## सप्तम संस्करण की भूमिका

तक का सप्तम संस्करण पाठकों के सामने है। हमारे लिए यह बड़ा ही हर्ष का वय है कि हम इस पुस्तक द्वारा विद्यार्थी वर्ग की कुछ सेवा कर पाये हैं। मुद्रा और का के क्षेत्र में नित्य नये नये परिवर्तन होते रहते हैं। बहुत सी दिशाओं रें पूर्णतया योग भी किये जा रहे हैं। ग्रर्थशास्त्र तथा वाणिज्य के किसी भी विपार्थी के व परिवर्तनों और प्रयोगों का समभना बहुत ही जरूरी है, मुख्यतया व मान शील युग में, जबिक संसार के ग्राधिक और राजनीतिक कले व वर्षा र तंन हो रहे हैं। भारत में ग्राधिक नियोजन के ग्रन्तगंत देश के ग्रीर परिगाम यह है कि वित्तीय समायोजन के इस काल में मौद्रिक इतिहास की नई परिगाम यह है कि वित्तीय समायोजन के इस काल में मौद्रिक इतिहास की नई भूमि तैयार हो रही है। सभी बातों को घ्यान में रखकर पुस्तक में जगह-जगह संशोधन ग्रावश्यक हो गये हैं। इसी ग्रावश्यकता को घ्यान में रखते हुए प्रस्तुत स्करणा में 'व्यापार एवं भुगतान संतुलन' तथा 'भारतीय तटकर नीति' नामक दो ध्याय प्रविष्ट कर दिये गए हैं तथा सभी ग्रावश्यक संशोधणीं को भी दर्शाने का पूर्ण गरत किया गया है।

पुस्तक के सुघार के सम्बन्ध में ग्रनेक सुफाव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तुत संस्करण में । त्र-योगी एवं ग्रावश्यक सुफावों को भी यथास्थान सम्मिलित कर दिया गया है। सभी महानुभावों के हम बहुत ग्राभारी हैं जिन्होंने हमें सुफाव दिये हैं प्राप्त

पुस्तक के विषय कम में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं और यथास्थान नये कड़े जोड़ दिये गये हैं और भाषा सम्बन्धी अनेक सुधार भी किये गये हैं। हमें पूरा वास है कि यह पुस्तक पाठकों के लिए उपयोगी और रुचिकर सिद्ध होगी।

## प्रथम संस्करण की मूमिका

ब्रध्यापको तथा विद्यार्थियों के सम्मुख यह छोटी सी पुस्तक प्रस्तुत करते हुए हमें ब्रत्यन्त हर्ष का अनुभव होता है। पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों लिखने की हमारे देश में एक परम्परा सी बन गई है। यह कहना तो कठिन है कि इस प्रकार की पुस्तकों लिखना कहाँ तक उचित है, परन्तु वर्तमान शिक्षा प्रणाली तथा विद्यार्थी वर्ग की सामान्य पृत्रृत्ति को देखते हुए किचित ऐसा करना हो पड़ता है। प्रस्तुत पुस्तक भी प्रधानतया जीगरा, बिहार तथा राजस्थान विश्वविद्यालयों के बी० ए० और बी० कॉम० पिक्षाञ्यक्रम के अनुसार लिखी गई है, परन्तु इसमें अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के विष्पाठ्यक्रम तथा उपयुक्त सम्बन्धित समस्याओं को भी ध्यान में रखा गया है।

मुद्रा, चलन एवं श्रिषकोषरा पर पाठ्य-पुस्तकों की कमी नहीं है श्रीर इस विशा में हिन्दी में भी कई सफल प्रयत्न किये गये हैं, परन्तु फिर भी इस पुस्तक की श्रावश्यकता इस कारण अनुभव की गई है कि विद्यार्थियों के सम्मुख एक समैबद्ध, वैज्ञानिक तथा रुचिकर विवेचना प्रस्तुत की जाय। यह विषय साधारणत्या कठिन होता है, जिसके कारण इसे समकाने की समस्या विशेष रूप में महत्त्वपूर्ण हो जाती है। लेखकों को इस सम्बन्ध में कहाँ तक सफलता मिली है, इसका निर्णय तो केवल पाठकगण ही दे सकते हैं। पुस्तक में मौलिकता तो नहीं है, परन्तु विवेचना की एक नई रीति अवश्य ग्रहण की गई है।

आशा है कि यह पुस्तक अध्यापक बन्धुओं को पसन्द आयगी। यदि पुस्तक विद्यार्थियों की कुछ भी सेवा कर सकी तो लेखक अपने परिश्रम को सफल ही समर्कों।

अपने प्रकाशकों के प्रति लेखकगए। आभारी हैं कि उन्होंने दो महीनों के अल्पकालीन समय में ही पुस्तक को इतने सुन्दर ढङ्ग से छाप कर पाठकों के सम्मुख रखा है।

व्यापार एवं भुगतान सन्तुलन	१ष्ठ संख्या
भारतीय तटकर नीति	₹८४—३८८
भारत का विदेशी व्यापार	३८८–४०६
विदेशी विनिम्ध	४१०-४५५
विनिमय नियन्त्रग्	४२६–४४६
A * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	४४७–४ <b>५</b> =
[चतुर्थ माना	
भारतीय चलन का इतिहास	
भारताय चलन का इतिहास	
भारतीय चलन का इतिहास (क्रमणः)	४४८–४६६
भारतीय चलन का इतिहास (क्रमशः)	४७०-४८ ई
भारतीय पत्र-चलन का इतिहास	४८२–४०६
भारत में दशमिक मुदग् की समस्या	५०७–५१६
	४१७–५२६
[पंचम भाग]	
भारतीय बैंकिंग / अग्रेश - 1	ARKET
ना रवाच वाक्या—उसका विकास गर्न जगरी जन्म	
भारतीय मुद्रा-बाजार रिजवं वेंक श्रॉफ इन्डिया	<b>५२६—५५३</b>
रिजव वैंक श्रॉफ इन्डिया	XXX-X03
समाशोधन-गृह श्रथवा निकासी गृह	४७४–४६=
भारत में मिश्रित पुँजी बैंक	४६६–६०४
इम्पीरियल बेंक एवं स्टेट बेंक श्रॉफ़ इन्डिया	8-88
भारत में विदेशी विनिमय बेंक	१२—२७ -
<u>श्रीरत</u> में देशी बेंकड़	२७–३७

गारताथ बाक्रा गरमानार -	MAKKET
भारतीय वैंकिंग उसका विकास एवं उसकी समस्यायें भारतीय मुद्रा-वाजार रिजवें बैंक श्रॉफ इन्डिया समाशोधन-गृह श्रथवा निकासी गृह भारत में मिश्रित पूँजी बैंक इम्पीरियल बैंक एवं स्टेट बैंक श्रॉफ इन्डिया भारत में विदेशी विनिमय बैंक भारत में देशी बेंकड आरत में ग्राम्य वित्त भारतीय सहकारी साख संगठन भारत में श्रीचोगिक वित्त भारत में श्रीचोगिक वित्त भारत में विदेशी पूँजी की समस्या भारत में बेंकिंग विधान [षष्ठम भाग]	\$ 0 5 - \$ 0 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
राष्ट्रीय घाय बचत, विनियोग भौर॰पूर्ण वृत्ति	१२२-१३१ १३२-१५४

कमलेश कुमार त्याभी

#### अध्याय १

# मुद्रा का आविष्कार

(The Invention of Money

### विनिमय का विकास—

प्रारम्भिक भ्रवस्था में मनुष्य का जीवन बड़ा सरल था। उसकी म्रावश्यकतार्ये सीमित यीं, जिन्हें वह साघारएातया भ्रपने ही प्रयत्न द्वारा भ्रथवा भ्रपने परिवार के भ्रन्य प्रदस्यों की सहायता से पूरा कर लेता था। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए ग्राधिक वावलम्बता थी श्रौर उसे दूसरों के परिश्रम पर निर्भर रहने की श्रावश्यकता न थी, ारन्तु ग्रार्थिक जीवन की यह प्रारम्भिक भ्रवस्था बहुत दिनों बनी न रह सकी । ग्रार्थिक ारिस्थितियों के परिवर्तन ने इस भङ्ग कर दिया। ग्राज के युग मे बहुत कम व्यक्ति (से मिलेंगे जो कि पूर्ण रूप से श्रात्म-निर्भर हों। लगुभग सभी मनुष्यों को श्रपनी-ग्रपनी श्रावश्यकताश्रों की सन्तुष्टि के लिए दूसरों पूर निर्भर रहना पड़ता है, क्छोंकि म्राज कोई भी व्यक्ति म्रपनी म्रावश्यकता की सभी वस्तुयें स्वयं निर्मारा नहीं कर पाता है । वह किसी एक धन्धे का ही विशेषज्ञ बनकर कार्य करता है तथा इस कार्य से उसे जो आय होती है उसका 'विनिमय' करके वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब तक किसी मनुष्य को विनिमय द्वारा दूसरे मनुष्यों की बनाई हुई वस्तुयें प्राप्त नहीं होतीं, तब तक उसकी ग्रावश्यकताएँ ग्रसन्तुष्ट ही रहती है। इस प्रकार विनि-मय की धुरी पर सम्पूर्ण समाज की ऋार्थिक व्यवस्था घूमती हे ऋौर विनिमय द्वारा ही उत्पादन ऋौर उपमोग एक डोरी में बंधे हुए हैं। जैसे जैसे सामाजिक जीवन उन्नति करता गया, वैसे-वैसे विनिमय का कार्य भ्रविक लाभदायक होता गया भ्रौर वीरे-घीरे विनिमय ने मानव-जीवन तथा मानव समाज में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया।

## वि नमय का अर्थ एवं इसके स्वरूप—

विनिमय एक आर्थिक क्रिया है और इस रूप में इसके निम्न लक्ष्मा पाये जाते हैं:—

- (१) इसमें धन का हस्तान्तरण होता है।
- (२) घन का यह हस्तान्तरम ऐच्छिक होता है। तथा
- ( ३ ) विनिमय की यह क्रिया वैधानिक ग्रौर पारस्परिक होती है।

ब्रतः उपरोक्त लैक्षणों के क्राघार पर यह कहा जा सकता है कि *विनिमय* 

(Exchange) दो पत्तों के बीच में होने वाला धन का ऐन्छिक, वैधानिक ऋौर पारस्परिक हस्तान्तरण है।

विनिमय दो प्रकार का होता है:—(१) 'प्रत्यक्ष विनिमय' या 'वस्तु-विनिमय' (Direct Exchange or Barter) तथा (२) 'परोक्ष विनिमय' या 'मुद्रा-विनिमय' (Indirect Exchange or Money Exchange)।

वस्तु-विनिमय में विनिमय का कार्य सरल होता है। एक वस्तु स्रथवा एक सेवा के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त कर ली जाती है। यदि एक व्यक्ति के पास गेहूँ है भ्रौर उसे कपड़े की भ्रावश्यकता है तो वह दूसरे व्यक्ति से, जिसके पास कपड़ा फालतू है भ्रौर जिसे गेहूँ की जरूरत है, गेहूँ के बदले में कपड़ा ले सकता है। विनिमय का यह कार्य इस कारण सरल तथा प्रत्यक्ष होता है कि दो व्यक्ति भ्रपनी फालतू वस्तुश्रों की भ्रापस में ही भ्रदला-बदली करके विनिमय के कार्य को सम्पन्न कर लेते हैं। शुरू-शुरू में इसी प्रकार का विनिमय प्रचलित था, परन्तु कालान्तर में जैसे-जैसे विनिमय का महत्त्व बढ़ता गया भ्रौर मनुष्य की भ्रार्थिक स्वावलम्बता घटती गई, वैसे-वैसे वस्तु विनिमय में कुछू किनाइयाँ भ्रनुभव होने लगों। इन किनाइयों को दूर करने के लिए ही 'मुद्रा' का भ्राविष्कार हुम्ना भ्रौर घीरे-घीरे 'वस्तु-विनिमय' का स्थान 'मुद्रा-विनिमय' ने ले लिया।

मुद्रा-विनिमय में एक माध्यम (Medium) की आवश्यकता पड़ती है और विनिमय का कार्य परोद्ध होता है। यदि गेहूँ के बदले में कपड़ा प्राप्त करना है तो पहले गेहूँ को मुद्रा में बदला जायगा और फिर इस मुद्रा के बदले में कपड़ा लिया जायगा। इस प्रकार विनिमय का कार्य दो भागों में बंट जाता है:— प्रथम, वस्तु अथवा सेवा के बदले मुद्रा प्राप्त करना, और दूसरे, मुद्रा के बदले में कोई अन्य वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करना। विशेषता यह है कि इन दोनों विनिमय कार्यों में से प्रत्येक में मुद्रा का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार पहले एक वस्तु के बदले में मुद्रा और फिर इस मुद्रा के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करके एक वस्तु का दूसरी वस्तु में परोक्ष रीति से विनिमय किया जाता है। वस्तु-विनिमय तथा मुद्रा-विनिमय दोनों के उद्देश्य में कोई अन्तर नहीं होता, अन्तर केवल विनिमय करने की रीति का है। मुद्रा-विनिमय वस्तु-विनिमय को अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होता है और यही कारण है कि घीरे-घीरे इसका चलन बराबर बढ़ता गया है।

### वस्तु-विनिमय की श्रसुविधाए-

ैयह तो हम पहिले ही देख चुके हैं कि वस्तु-विनिमय के बदले मुद्रा-विनिमय अधिक सुविधाजनक होता है। ग्रब हमें यह देखना है कि वस्तु-विनिमय की किठनाइयाँ कौन-कौन सी हैं। प्रमुख श्रसुविधायें निम्न प्रकार हैं:—

(१) ग्रावश्यकतात्रों के दोहरे पारस्परिक संयोग का ग्रभाव (Lack of Double Conicidence of Wants)—वस्तु-विनिमय की सफलता सबसे

पहिले इस बात पर निर्भर है कि ऐसे दो व्यक्ति मिल जाएँ जिनमें से प्रत्येक के पास ठीक वही वस्तु फालतू हो जिसकी दूसरे को ग्रावश्यकता है। यदि एक व्यक्ति गेहूँ को कपड़े में बदलना चाहता है तो वह विनिमय तभी कर सकेगा जबकि उसे कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा मिल जाय जिसके पास बदलने के लिए केवल कपड़ा ही फालतू न हो बिल्क जिसे साथ ही साथ गेहूँ की भी भ्रावश्यकता हो। वास्तविक जीवन में ऐसा केवल संयोग से ही हो सकता है, क्योंकि यह अवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति को गेहूँ की जरूरत है उसी के पास कपड़ा भी फालतू हो। यह भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति के पास कपड़ा फालतू है उसे वास्तव में गेहूँ के स्थान पर किसी भ्रन्य वस्तु की श्रावश्यकता हो। गुरू-गुरू में, जबिक मनुष्य की श्रावश्यकताएँ बहुत थोड़ी सी थीं श्रीर केवल कुछ ही वस्तुश्रों का उत्पादन करके पूरी हो सकती थीं, ऐसा बहुधा सम्भव हो जाता होगा, परन्तु जैसे-जैसे म्रावश्यकताम्रों ग्रौर उसके पूरा करने वाली वस्तुम्रों की संख्या बढ़ती गई, वैसे-वैसे इसमें निरन्तर ग्रधिक कठिनाई श्रनुभव होने लगी। जिस व्यक्ति के पास गेहूँ है उसके लिए यदि यह सम्भव भी हो जाता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोज निकाले जिसके पास बदलने के लिए कपड़ा है तो यह ग्रावश्यक नहीं है कि उस दूसरे व्यक्ति को गेहूँ की भी म्रावश्यकता हो। ऐसी दशा में विनिमय में भारी कठिनाई होगी। (मुद्रा के उपयोग द्वारा यह कठिनाई दूर हो जाती है, क्योंकि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसकी मावश्यकता सभी को होती है मौर इसलिए उसे दूसरी किसी भी वस्तु में भ्रासानी से बदला जा सकता है।)

(२) मूल्य के एक सामृहिक सूचक का ग्रभाव (Lack of a Common Denominator of Value)—वस्तु विनिमय की दूसरी कठिनाई वस्तुभ्रों की भ्रदल-बदल का पारस्परिक भ्रनुपात निश्चित करने के सम्बन्ध में है। एक मन गेहूँ के बदले में कितने गज काड़ा दिया जाय अथवा कितने सेर चीनी ली जाय, यह जान लेना वस्तु-विनिमय की सफजता के लिए बहुत जरूरी है। गेहूँ बेचने वाले तथा कपड़ा बेचने वाले दोनों ही व्यक्तियों को गेहूँ ग्रौर कपड़े की विनिमय दर का पता होना चाहिए, नहीं तो वे विनिमय करने में संकोच करेगे। स्रावश्यकता केवल इतनी ही नहीं है कि दोनों व्यक्ति गेहूँ ग्रौर कपड़े की विनिमय दर को जान लें। एक व्यक्ति विनिमय द्वारा एक वस्तु प्राप्त करके ही अपनी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट नहीं कर सकता । उसे भ्रनेक वस्तुम्रों के लिए विनिमय पर निर्भर रहना पड़ता है ग्रीर इसलिए भ्रनेक वस्तुर्घो की विनिमय दर जानने भ्रौर याद रखने की भ्रावश्यकता पड़त्री है। विकसित समाज में तो यह कठिनाई ग्रौर भी ग्रधिक हो जाती है। (यह कठिनाई ाद्रा के उपयोग से दूर हो जाती है। मुद्धा एक ऐसी वस्तु है जिसमे सभी वस्तुग्री पीर सेवाग्रों की कीमत ग्राँकी जा सकती है। एक रुपये में कितना गेहूँ मिलेगा ग्रथवा कतने गज कपड़ा मिलेगा, यह श्रासानी के साथ याद रखा जा सकता है श्रीर इतना गानने के पश्चात् गेहूँ और कपड़े के पारस्परिक विनिमय **श्र**तुपात **को ज्ञा**त करना

कठिन नहीं होता । इस प्रकार मुद्रा वस्तुस्रों ग्रौर सेवाग्रों के सामूहिक मूल्य सूचक का कार्य करती है।)

- (३) वस्तुम्रों की विभाजकता का म्रभाव (Lack of Divisibility of Commodities)—कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं कि जिनको दुकड़ों में बाँट देने से उनके मूल्य का काफी बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। उदाहरएएस्वरूप, एक घोड़े म्रीर एक मोटर कार को लीजिए। घोड़े को काट कर उसके मांस, हड्डी म्रादि के रूप में जो मूल्य प्राप्त होता है वह घोड़े के मूल्य से बहुत कम होता है। इसी प्रकार कार को तोड़ कर बेचने पर बहुत ही कम कीमत वसूल होती है। यदि किसी व्यक्ति के पास इस प्रकार की कोई वस्तु है म्रीर उसे विनिमय द्वारा म्रन्य कई वस्तुएँ प्राप्त करने की म्रावश्यकता है तो उसे वस्तु-विनिमय में भारी कठिनाई होगी, क्योंकि किसी एक ऐसे व्यक्ति का मिल जाना बहुत ही कठिन होगा जिसे घोड़े म्रथवा कार की म्रावश्यकता हो म्रीर साथ ही उसके पास विनिमय हेतु वे सभी वस्तुएँ मौजूद हों जिनकी घोड़े म्रयवा कार के स्वामी को म्रावश्यकता है। यही नहीं, घोड़े म्रयवा कार के टुकड़े करके वस्तुएँ प्राप्त करने में हानि होती है, इसलिए विनिमय बहुत म्रयुविघाजनक हो जाता है। (यह कठिनाई भी मुद्रा के उपयोग से दूर हो जाती है। घोड़े म्रयवा कार की कीमत मुद्रा में म्रांकी जा सकती है, म्रीर, क्योंकि मुद्रा में विभाजकता का ग्रुग होता है इसलिए घोड़े के बदले में प्राप्त होने वाली मुद्रा की म्रवान महता वस्तुएँ खरीदी जा सकती है।)
- (४) कयः शक्ति के संचय का अभाव (Lack of Store of Purchasing Power)—वस्तु विनिमय की प्रथा के समय कयःशक्ति का संचय वस्तुओं में होता था, और, क्योंकि वस्तुएँ शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं, इसलिये क्रयःशक्ति का संचय बहुत समय के लिये नहीं किया जा सकता था और बिना क्रयःशक्ति के संचय के देश की उन्नति नहीं हो सकती। यही कारण है कि वस्तु विनिमय के समय में देश इतने उन्नतिशील न थे जितने आजकल हैं, जबिक मुद्रा का उपयोग होता है।
- (५) मूल्य के हस्तान्तरण का अभाव (Lack of Transfer of Value)—प्राचीन काल में, जबिक वस्तु-विनिमय की प्रथा प्रचलित थी, मूल्य प्रथवा क्रयःशक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरित करना असम्भव सा ही था, जैसे—यदि एक मनुष्य का मकान आगरे में था और वह उसे छोड़कर जयपुर जाना चाहता था, तो वह अपने आगरे वाले मकान को जयपुर नहीं ले जा सकता था। मूल्य के हस्तान्तरण के अभाव के कारण सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति में काफी बाघा पड़ी। (आजकल आगरे के मकान को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जा सकती है और इस मुद्रा को जयपुर ले जाकर आसानी से दूसरा मकान बनवाया या खरीदां जा सकता है।)
- (६) स्थागत देय मान का ग्रभाव (Lack of a Standard of Deferred Payment)—बहुत से ऐसे लेन-देन होते हैं जिनका भुगतान तुरन्त

नहीं किया जाता है। बल्कि भविष्य के लिए स्थगित के जुझों का पता पहले लगा लिया के समय में वस्तुयें स्थगित भुगतानों का भुगतान करने के ज्या। अन्य रूपों में तो क्योंकि वस्तुय्रों की कीमत में स्थिरता नहीं होती है और उन

टिकाऊपन के गुरा भी अधिक नहीं होते।

#### वर्तमान समाज में वस्तु मुद्रा का स्थान-

ऋछ विद्वानों

उपरोक्त कठिनाइयों को देखने से पता चलता है कि वस्तु-विनिमय की म्वयं ही स्रिष्ठिक से अधिक अविकसित समाज में ही सम्भव है, जहाँ आवश्यकता पूर्ति की वस्तु-मिनी-चुनी हों। प्रारम्भिक अवस्था में ऐसा ही था। परन्तु आज का संसार बहुत आगे बढ़ चुका है। श्रम विभाजन अपनी उच्चतम सीमा पर पहुँच चुका है। मनुष्य की आवश्यकताओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। यही कारणा है कि कालान्तर में घीरे चीरे वस्तु-विनिमय प्रणाली समाप्त होती गई है और आधुनिक युग पूर्ण रूप में मुद्रा उपयोगी युग बन गया है।

वस्तु-विनिमय की संफलता की दशायें (Conditions for the Success of Barter)—

फिर भी वस्तु-विनिमय प्रणाली संसार से लुत नहीं हुई है। प्रत्येक वस्तु में दोषों के साथ-साथ गुण होते हैं। पिछड़े हुए देशों और जातियों के ग्रतिरिक्त सम्य समाजों तथा ग्रत्य विकसित ग्रर्थ-व्यवस्थाओं में भी वस्तु-विनिमय प्रणाली एक ग्रंश तक ग्रभी तक हो मौजूद है। वस्तु-विनिमय प्रणाली के इस प्रकार जीवित रहने का मुख्य कारण इस प्रणाली की सरलता है। यदि ग्रनुकूल दशायें उपलब्ध हों तो ग्र्यावहारिक जीविन में इससे विशेष सुविधा रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति को ग्रावह्यक वस्तु प्रत्यक्ष रीति से प्राप्त हो जाती है। कृषि उद्योग में मजदूरी चुकाने के लिए ग्रभी भी इस प्रणाली का काफी चलन है। विदेशी व्यापार में भी इसका उपयोग किया जाता है। मुद्रा के मूल्य की ग्राविश्वतता भी इस प्रणाली को बनाये रखने में सहायक रही है। ग्राधुनिक युग में तो इस प्रकार की ग्राविश्वतता बहुत काफी बढ़ गई है।

वस्तु विनिमय की सफलता निम्न दशाश्रों में सम्भव है:---

- (१) सीमित श्रावश्यकतायें जिस समाज की श्रावश्यकतायें सीमित होंगी वहाँ वस्तु विनिमय पर्याप्त ग्रेंश तक सफल हो सकता है, क्योंकि वस्तु-विनिमय की किठाइयाँ बहुत ग्रधिक नहीं। होंगी। पिछड़े हुए समाजों में क्रयः शक्ति के श्रभाव के कारण तथा श्रज्ञानता के कारण किसी समाज की श्रावश्यकतायें इतनी सीमित हो सकती हैं कि वस्तु-विनिमय बहुत श्रमुविधाजनक न हो।
- (२) सीमित क्षेत्रों में—वस्तु-विनिमय किसी ऐसे छोटे क्षेत्र में भी सफल हो सकता है जहां थोड़े से ही ऐसे लोग रहते हों जिनके बीच पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ट हो।

(३) यात्यात सुविधाओं का स्रभाव—यदि यातायात सुविधाओं के वाना के बार्च से दूसरे स्थान को माल भेजना कठिन है तो स्थानीय कार्य के बार्च के बीच का सम्पर्क वढ़ जायेगा। ऐसी दशा में वस्तु विनिमय की सम्पर्क वढ़ जायेगा।

४) मुद्रा के मूल्य की अनिश्चितता की दशा में — बहुत बार ऐसा में आता है कि कुछ कारणों से मुद्रा के मूल्य में तेजी के साथ परिवर्तन होने लगते हैं। अत्यधिक मुद्रा-प्रसार (Inflation) के काल में कुछ देशों में ऐसी परि-स्थितियाँ आ गई थीं कि समाज ने मुद्रा-विनिमय के स्थान पर वस्तु-विनिमय प्रणाली को ग्रहण किया था, क्योंकि ऐसी दशा में यह प्रणाली अधिक न्यायपूर्ण, निश्चित और सुविधाजनक हो जाती है।

(५) मुद्रा की मात्रा कम होने की दशा में—यदि किसी देश में मुद्रा की कुल मात्रा इतनी कम रहती है कि विनिमय सम्बन्धी सामान्य आवश्यकतायें उसके द्वारा पूरी नहीं की जा सकती हैं तो वस्तु-विनिमय प्रणाली का चलन बढ़ जायेगा।

#### मुद्रा का प्रारम्भ—

मुद्रा का आविष्कार कब और कैंसे हुआ, इस बात का निर्णय करना कठिन है। ग्रस्मरणीय काल से ही संसार में इसका उपयोग होता चला श्राया है। ऐसा ज्ञात होता है कि विभिन्न देशों तथा विभिन्न जातियों ने एक दूसरे से पूर्णतया स्वतन्त्र रूप में मुद्रा का आविष्कार कर लिया था, क्योंकि ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जिनका एक दूसरे से किसी भी प्रकार का सम्पर्क सम्भव नहीं हो सकता था, मुद्रा का उपयोग पाया जाता है। इससे यही सिद्ध होता है कि जैसे-जैसे विनिमय की ग्रावश्यकता ग्रौर कठिनाई बढ़ती गई वैसे-वैसे मुद्रा की खोज ग्रारम्भ हो गई। ग्रति प्राचीन भारत में ऋगु-वेद के युग में गाय को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। ग्रफ़ीका की जङ्गली जातियाँ अभी तक बकरी को मुद्रा के रूप में उपयोग करती हैं। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर विभिन्न वस्तुओं को इस रूप में उपयोग किया गया था । कौडियाँ मूँगे, मोती, कुछ वृक्षों के सूखे हुए फल, भूमि के ट्रकड़े ग्रादि ग्रनेक वस्तुग्रों से मुद्रा का काम लिया गया है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे मनुष्य का ज्ञान तथा उसकी शावश्यवतायें बढ़ती गई वैसे-वैसे अधिक अच्छी वस्तुओं को मुद्रा के रूप में उपयोग किया गया। गाय, वकरी ग्रौर कौड़ियों का स्थान घातु के सिक्कों ने ले लिया ग्रौर ज्यों-ज्यों सम्यता का ग्रीर श्रधिक विकास होता गया, त्यों-त्यों सिक्कों के स्थान पर पत्र-मुद्रा का चलन बढ़ता गया । आधुनिक संसार में सबसे अधिक चलन पत्र-मुद्रा का ही है ।

घातु के सिक्कों का ग्राविष्कार सबसे पहले किस देश में हुग्रा, इस सम्बन्ध में खोज की गई है। ऐसा पता चलता है कि सबसे पहिले मिस्र तथ्या लीडिया (Lydia) में सिक्कों का उपयोग हुग्रा था। विद्वानों का मत है कि लीडिया में इनका उपयोग

सबसे अधिक पुराना है। निश्चय ही जिन देशों ने धातुओं का पता पहले लगा लिया था, उन्होंने सिक्कों का उपयोग भी पहले ग्रारम्भ कर दिया था। ग्रन्य रूपों में तो मुद्रा का उपयोग और भी बहुत पहले से होता ग्रा रहा था।

#### मुद्रा के श्राविष्कार से सम्बन्धित विचारधारायें—

मुद्रा के ग्राविष्कार के सम्बन्ध में दो प्रकार की विचारधारायें हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि मुद्रा की किसी ने खोज नहीं की है, वह मनुष्य को स्वयं ही मिल गई। मुद्रा-उत्पत्ति के इस सिखान्त को हम मुद्रा का त्राक्तिमक जन्म सिखान्त (Theory of Spontaneous Growth) कह सकते हैं। स्पालिंड (Spalding) इसी सिखान्त के पक्षपाती हैं ग्रौर उनके विचार में यह सिखान्त ऐतिहासिक ग्रमुभव से भी सिद्ध होता है। जैसे-जैसे विनिमय का चलन बढ़ता गया, वैसे-वैसे सभी जातियों ने किसी न किसी विनिमय माध्यम का उपयोग करना गुरू कर दिया। जो भी वस्तु उपयुक्त प्रतीत हुई, घीरे-घीरे वही बिनिमय का माध्यम बनती गई ग्रौर जैसे-जैसे एक वस्तु दूसरी की ग्रपेक्षा ग्रधिक उपयुक्त जान पड़ी, उसने पुरानी मुद्रा का स्थान प्राप्त कर लिया। इससे सिद्ध होता है कि मुद्रा स्वयं मनुष्य के सम्मुख उपस्थित हुई, मनुष्य को उसे खोज करने की ग्रावश्यकता नहीं हुई।

दूसरी विचारधारा इस प्रकार हैं कि मुद्रा का आविष्कार वस्तु-विनिमय की किठनाइयों को दूर करने के लिए किया गया था। आरम्भ में सबसे बड़ी कठिनाई विनिमय के लिए विभिन्न वस्तुओं का मूल्य आँकने की थी, विनिमय के माध्यम की आवश्यकता इसके पश्चात् अनुभव हुई। यही कारण है कि आरम्भ में ही मूल्य के एक सामूहिक मापक की खोज की गई और इसके लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। गाय अथवा वकरी का उपयोग मूल्य के मापक के रूप में ही किया गया। प्रत्येक वस्तु की कीमत गाय अथवा वकरी की एक निश्चित संख्या में आँकी जाती थी। शुरू में इसी उद्देश्य से मुद्रा का उपयोग किया गया, यद्यिप धीरे-धीरे मुद्रा के अन्य कार्यों का महत्व भी बढ़ता गया।

उपरोक्त दोनों सिद्धान्तों के पद्म और विपद्म में काफी कहा जा सकता है, परन्तु इस सम्बन्ध में वाद-विवाद से कोई व्यावहारिक लाम नहीं निकलता। हमारे लिये तो इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि किसी न किसी भाँति मुद्रा का उपयोग ग्रारम्भ हुमा और कालान्तर में यह मानव समाज तथा ग्रर्थ-व्यवस्था का एक महत्त्व-पूर्य ग्रंग बन गई। गाय और बकरी मुद्रा के रूप में ग्रच्छी वस्तुएँ न थीं, क्योंकि उनमें मूल्य स्थिरता तथा टिकाऊपन के ग्रुग न थे। मवेशियों की बीमारी के काल में एक व्यक्ति का मुद्रा संचय ग्रकस्मात् ही बहुत घट सकता था और प्रजनन के काल में वह काफी बढ़ सकता था। इसके ग्रतिरिक्त सभी गायें ग्रथवा सभी बकरियां स्वास्थ्य और ग्रायु के दृष्टिकोण से समान नहीं होती हैं, इसलिये मान (Standard) के निर्धारण में कठिनाई, होती है कि किस गाय ग्रथवा बकरी को मूल्य ग्रांकने की इकाई माना जाय। संचय करने से भी गाय तथा बकरी की कीमत घटने लगती है। यही

कारण है कि इन वस्तुग्रों को मुद्रा के रूप में उपयोग करने का चलन धीरे-घीरे कम होता गया ग्रोर इनके स्थान पर कौड़ियाँ ग्रादि वस्तुयें, जिनमें इस प्रकार के दोष नहीं हैं, मुद्रा के रूप में उपयोग होने लगीं। तत्पश्चात् ये वस्तुएँ भी सन्तोषजनक सिद्ध न हो सकीं, क्योंकि इनमें एक ग्रोर तो दुर्लभता (Scarcity) का ग्रुए। न था ग्रौर दूसरी ग्रोर बोक्त के ग्रनुपात में इनका मूल्य बहुत ही कम था। घातुग्रों की खोज के पश्चात् इन वस्तुग्रों का चलन मिटता गया ग्रौर घातु के टुकड़ों तथा घातु से बने हुए सिक्तों को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा।

धातु-मुद्रा का उपयोग काफी लम्बे समय से होता ग्राया है ग्रौर ग्रभी तक भी इसका चलन बहुत है, परन्तु कुछ कारणों से घीरे-घीरे घातु-मुद्रा का भी महत्त्व घटता गया। जैसे जैसे व्यापार तथा वाणिज्य का विकास हुआ। मूद्रा की अधिक मात्रा में श्रावश्यकता हुई, परन्तु बहुमूल्य घातुमो की मात्रा सीमित ही थी, इसलिए ऐसी वस्तुश्रों की खोज शारम्भ हई जो मुद्रा काय में धातुग्रों का स्थान ले सकें। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि घात के सिक्के चलते-चलते घिमते रहते हैं और इस घिसावट के कारण घल की मात्रा नष्ट हो जाने के कारण पर्याप्त हानि होती है। इस प्रकार धीरे-धीरे पत्र-मुद्रा का श्राविष्कार हुआ। पत्र-मुद्रा मे यद्यपि बहुमूल्य होने का गुरा तो नहीं होता है, परन्तू बोभ में हल्की होने तथा घिसावट द्वारा हानि न होने के कारए वह काफी म्रच्छी होती है। शक्तिशाली तथा विश्वसनीय राज्यों की स्थापना मौर बेंकों के विकास ने तो पत्र-मुद्रा का चलन ग्रौर भी बढ़ा दिया है। बहुमूल्य घातुग्रों की कमी के कारण संसार के सभी देशों ने इसे ग्रपना लिया है। ग्राज के संसार में पत्र-मूद्रा ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भूद्रा है। अब तो देशों ने मूद्रा के उपयोग में इतनी प्रधिक प्रगति की है कि पत्र-मुद्रा के स्थान पर चैक, विनिमय बिल भ्रादि के रूप में साख मुद्रा का भी उपयोग होने लगा है। इन सबका विस्तृत वर्णन अगले ग्रध्यायों में किया जायगा।

#### **QUESTIONS**

- Discuss the advantages and disadvantages of 'Barter economy' and 'Exchange economy.' Is the world coming back to 'Barter economy'. (Raj., B. A., 1948)
- How did money originate? What are the different kinds of money? What functions does money perform? (Agra, B. A., 1956 Supp.)
- 3. Discuss the significance of the evolution of money in modern economy. What are its economic and social effects?

  (Patna, 1955 Supp.)
- 4. Explain how and to what extent, the use of money in exchange transactions removed the inconveniences of Barter(Kaj., B. Com., 1958)
- 5. What have been the economic effects of money द्वय)? Disuss. (Rai, B. A., 1958)

#### अध्याय २

# मुद्रा की परिभाषा, कार्य और महत्त्व

The Definition, Functions & Importance of Money)

#### परिभाषा की कठिनाई—

यद्यपि किसी भी वात को परिभाषा की निश्चित सीमा में बाँधना एक किठन कार्य है तथापि परिभाषा की ग्रावश्यकता तो होती ही है। सबसे पहला प्रश्न यह पैदा होता है कि 'परिभाषा' से क्या ग्राभिप्राय है तथा उसकी क्यों ग्रावश्यकता होती है? 'परिभाषा' किसी वस्तु का वह वर्गान है जिसे समभक्तर प्रत्येक व्यक्ति उस वस्तु को सरलतापूर्वक पहिचान सकता है। ग्राथीत, जिस वर्गान हारा कोई वस्तु बिना किसी किठनाई के पहिचानी जा सके, वही उस वस्तु की परिभाषा है। साधारणतया किसी वस्तु का जो सामान्य वर्गान किया जाता है वह एकसी ही कई वस्तु शों पर लागू हो सकता है, परन्तु परिभाषा का मुख्य गुगा यह है कि वह केवल वस्तु विशेष के ही सम्बन्ध में सही होती है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण के त्रानुसार एक सुन्दर एवं सफल परिभाषा में दो गुणों का होना परमावश्यक है:—(?) इसके द्वारा यह स्पष्ट विदित हो जाना चाहिए कि परिभाषित वस्तु किस वर्ग (Genus) के त्रान्तर्गत त्राती है तथा (२) वह कौन सा विशेष लद्मण (Differentia) है जिसके त्राधार पर उस वस्तु को उसी वर्ग की त्रान्य सजातीय वस्तुत्रों में से त्रालग करके त्रासानी से पहिचाना जा सकता है।

स्मरण रहे कि एक वर्ग में इहुत सी वस्तुएँ सम्मिलित हो सकती हैं। इन वस्तुश्रों में एक वर्ग के सदस्य होने के नाते बहुत सी समानतायें होंगी, परन्तु एक वर्ग की प्रत्येक वस्तु में कुछ ऐसी भिन्नताएँ भी अवश्य होती हैं जो वस्तु को उस वर्ग की दूसरी वस्तुश्रों से पृथक कर देती हैं। पिर्भाषा में इस प्रकार की भिन्नताग्रों का उल्लेख कर देना आवश्यक होता है। एक छोटे से उदाहरण से स्थिति स्पष्ट हो जायगी। तर्केशास्त्र में मनुष्य की परिभाषा इस प्रकार की गई है:—'मनुष्य एक विवेक्शील जानवर है।' ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि इस परिभाषा में जानवर मनुष्य का वर्ग है, क्योंकि मनुष्य भी एक प्रकार का जानवर ही है, परन्तु विवेकशील होना मनुष्य का विशेष गुण है। अन्य कोई भी जानवर इस गुण से परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जानवरों में समक्षते तथा याद रखने की शक्ति तो होती है, परन्तु उनमें विवेकशीलता (Rationality) नहीं होती है। इस प्रकार सभी मनुष्य उक्त परि-

भाषा के क्षेत्र में आ जाते हैं, परन्तु मनुष्य के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई जानवर श्रथवा वस्तु इसके क्षेत्र में नहीं आ सकती।

श्रिधकांश परिभाषात्रों में यह कठिनाई अनुभव होती है कि वे सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों ही दृष्टिकोण से समान रूप में सही नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए, रेखागि हास्त्र में एक सरल रेखा की परिभाषा इस प्रकार की जाती है:-- "सरल रेखा दो दिए हुये बिन्दुय्रों के बीच का न्यूनतम् अन्तर होती है।'' सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से इस परिभाषा के विरुद्ध कुछ भी कहना सम्भव नहीं है, परन्तु व्यावहारिक जीवन में जिस रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं वह सैद्धान्तिक दृष्टिकोए। से पूर्णतया ऐसी नहीं होती है। वह ग्रधिक से ग्रधिक 'लगभग' सरल रेखा होती है। व्यवहार में इससे काम तो चल जायगा, परन्तु वह तर्कशास्त्री को सन्तुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साधारण उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं की परिभाषा के सम्बन्ध में यही कठिनाई है। इसके अतिरिक्त जब भी हम किसी शब्द की परिभाषा करते हैं तो हमें परिभाषा में उपयोग किये हुये लगभग प्रत्येक शब्द की भी परिभाषा करनी होती है, क्योंकि साधारए। बोल-चाल में इन शब्दों का उपयोग भिन्न-भिन्न प्रथीं में किया जाता है। यहीं बस नहीं, विभिन्न ग्रर्थशास्त्रियों ने एक ही शब्द की ग्रलग-ग्रलग परिभाषाएँ की हैं। परिस्माम यह होता है कि किसी एक शब्द की परिभाषा करने के लिए शब्दों का चुनना भी कठिन हो जाता है। ग्रतः यह सम्भव है कि मुद्रा की एक साधारण सी परिभाषा देकर एक व्यापारी, उद्योगपति श्रथवा साहूकार को सन्तुष्ट किया जा सके, परन्तु एक तर्कशास्त्री ग्रथवा एक सैद्धान्तिक पाठक उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मुद्रा की परिभाषा के सम्बन्ध में यह स्नावश्यक है कि जो भी परिभाषा दी जाय वह सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों ही दृष्टिकोणों को सन्तुष्ट कर सके।

## मुद्रा की विभिन्न परिभाषायें

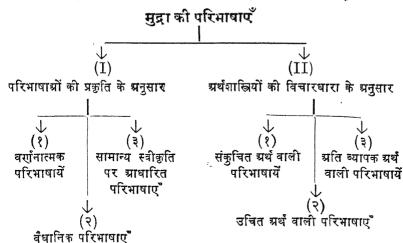
#### प्रारम्भिक-

शब्द गुत्पत्ति के अनुसार (Etymologically) अंग्रेजी भाषा का शब्द 'मनी' (Money), जिसके लिए हिन्दी में 'मुद्रा' शब्द है, लैंटिन भाषा के शब्द मोनिटा (Moneta) से बंना है। मोनिटा, देवी जूनो (Goddess Juno) का प्रारम्भिक नाम है, जिसके मन्दिर में रोम (Rome) की मुद्रा का निर्माण किया जाता था। इटली की प्राचीन कथाओं में जूनो स्वर्ग की रानी का नाम है। यही कारण है कि मुद्रा की कुछ लोगों ने स्वर्गीय आनन्द का प्रतीक माना है और इसीलिए शायद इस देवी के मन्दिर में मुद्रा बनाने का काम किया जाता था। लैंटिन भाषा में इस समय मुद्रा के लिए जो शब्द पाया जाता है वह 'पेक्यूनिया' (Pecunia) है। यह शब्द 'पेकस' (Pecus) से बना है, जिसका अर्थ पशु-सम्पन्ति से होता, है। ऐसा प्रतीत होता है कि रोम में भी किसी काल में, भारत की भांति, पशुआं को मुद्रा के रूप में उपयोग

किया जाता रहा होगा ग्रीर इस कारण मुद्रा तथा पशु-सम्पत्ति दोनों का एक ही ग्रर्थ लगाया गया है।

#### 'मुद्रा' की परिभाषात्रों का बाहुल्य श्रौर उनका वर्गीकरण —

अर्थशास्त्र के विषय में कीन्ज (Keynes) का कहना है कि इस विज्ञान ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट डाला है । इतनी परिभाषाएँ जमा हो गई हैं कि उनको पढ़ कर अर्थशास्त्र तथा उसकी प्रकृति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निश्चय कर लेना कठिन है, क्योंकि इन परिभाषाओं में भारी भिन्नताएँ हैं। कीन्ज का यह कथन मुद्रा पर भी पूर्णतया लागू होता है। इस शब्द की भी अनेक परिभाषाएँ हुई हैं, जिनमें इतना अधिक अन्तर पाया जाता है कि एक साधारण व्यक्ति उलक्षन में पड़ सकता है। बारबेरा ऊटन (Barbara Wootten) ने ठीक ही कहा है कि ''जब कभी छः अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं तो उनके सात अलग-अलग मत होते हैं।'' सौभाग्य से मुद्रा की परिभाषाओं में जो अन्तर हैं उनके आधार पर कुछ विशेष दृष्टिकोण बनाये जा सकतें हैं और विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई परिभाषाओं का इन दृष्टिकोणों के अनुसार निम्न प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता हैं:—



## (I) परिभाषात्रों की प्रकृति के त्रनुसार वर्गीकरण परिभाषात्रों की प्रकृति के ब्राधार पर उनके तीन वर्ग सम्भव हैं:—

- 1. "Political Economy is said to have strangled itself with definitions." J. N. Keynes: Scope and Methods of Political Economy, p. 153.
- 2. "Whenever six economists are gathered there are seven opinions." Barbara Wootten: Lament for Economics, p. 14

## (१) वर्णनात्मक परिभाषाएँ —

इस वर्ग में मुद्रा की उन सब परिभाषात्रों को सम्मिलित किया जाता है जो कि परिभाषा के स्थान पर वर्णन को ग्रिधिक महत्त्व देती हैं। ये परिभाषाएँ यह बताने के स्थान पर कि मुद्रा क्या है, मुद्रा की विशेषताग्रों का वर्णन करती हैं। इससे ये परिभाषाएँ व्यावहारिकता के दृष्टिकोगा से स्रिधिक उपयुक्त प्रतीत होती हैं। ऐसी सभी परिभाषात्रों को हम वर्णनात्मक परिभाषाएँ (Descriptive Definitions) कह सकते हैं। इस वर्ग के महत्त्वपूर्ण लेखक विदरस् (Hartley Withers), टामस (Thomas) तथा सिजविक (Sidgwick) हैं। उपरोक्त सभी लेखकों के श्रनुसार मुद्रा को समभने से पहले यह समभ लेना श्रावश्यक है कि मुद्रा की श्रावश्यकता किस लिए पड़ती है ग्रीर मुद्रा का उपयोग किन-किन कठिनाइयों को दूर करने तथा किन-किन भ्रावश्यकताभ्रों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इससे हमें यह पता चल जायगा कि मुद्रा के कार्य क्या हैं। तत्पश्चात् जो भी वस्तु श्रथवा पदार्थ इन कार्यों को सम्पन्न करेगा वह मुद्रा कहलाने का अधिकारी होगा । विदरस के अनुसार 'मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे।'' इसी प्रकार का दृष्टिकोए। सिजविक का भी है। टामस के ऋनुसार—''मुद्रा समुदाय के ऋन्य सभी सदस्यों के ऊपर एक प्रकार का श्रिधिकार, कुछ देने का एक प्रकार का श्रादेश श्रथवा वचन है, जिसे उसका स्वामी ऋपनी इच्छा से कभी भी प्रवृत्त करा सकता है । यह स्वयं 'साध्य' नहीं है, वरन् ग्रन्य व्यक्तियों की सेवाग्रों ग्रौर वस्तुग्रों पर ग्रधिकार जमाने का एक साधन मात्र है।"२

विदरस के अनुसार, मुद्रा के चार प्रमुख कार्य हैं:—विनिमय के माध्यम का कार्य करना, सभी वस्तुओं की कीमत को आँकना, मूल्य का संचय करना तथा उधार की लेन-देन में सुविधा प्रदान करना। जो कोई भी वस्तु इन चारों कार्यों को सम्पन्न करेगी वही मुद्रा कहलायेगी, चाहे उसके रूप और गुणा कुछ भी क्यों न हों।

#### दोष--

परन्तु यह दृष्टिकोगा तर्क की कसौटी पर सही नहीं उतरता, क्योंकि वर्णन तथा परिभाषा में भारी भ्रन्तर है। किसी वस्तु के गुगों तथा कार्यों की व्याख्या केवल

<sup>1. &</sup>quot;Money is what money does". Hartley Withers: The Meaning of Money.

<sup>2. &</sup>quot;Money is a kind of claim upon all other members of the community, a sort of order or promise to deliver which can be enforced whenever the owner pleases. It is a means to an end not for its own sake but as a means of obtaining other articles or of commanding the services of others." Thomas: Elements of Economics, p. 400.

उसका वर्णन हो सकती है, परिभाषा नहीं। परिभाषा में तो वर्ग (Genus) तथा विशेषक अन्तर (Differentia) का उल्लेख करना आवश्यक होता है। यदि मनुष्य के विषय में हम यह कहें कि यह चलता है, सोचता है तथा बात करता है तो निस्संदेह यह मनुष्य का 'वर्णन' तो हो जायगा, परन्तु उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। अतः तर्क के दृष्टिकोगा से विदरस् तथा सिजविक की परिभाषाएँ उपयुक्त नहीं हैं, यद्यपि ये परिभाषाएँ सरल हैं और व्यावहारिक जीवन में इनसे काम चल सकता है।

## (२) वैधानिक परिभाषायें—

दूसरे वर्ग में मुद्रा की उन सब परिभाषाग्रों को शामिल किया जाता है जो 'मुद्रा के राज्य सिद्धान्त' (State Theory of Money) पर ग्राधारित हैं। इस वर्ग की परिभाषात्रों को हम 'वैधानिक परिभाषाएँ' (Legal Definitions) कह सकते हैं। मुद्रा के राज्य सिद्धान्त के ग्रनुसार ग्राथिक सम्बन्धों में सबसे ग्रावश्यक चीज ऋ ए है, ग्रतएव मुद्रा वही वस्तु हो सकती है जो राज्य की ग्रोर से ऋ ए चुकाने का साधन घोषित कर दी जाय और यही कारण है कि विधान में मुद्रा का उल्लेख केवल ऋगु के ही सम्बन्ध में किया जाता है। जर्मन अर्थशास्त्री नैप (Knapp) तथा ब्रिटिश ग्रर्थशास्त्री हॉटरें (Hawtrey) मुद्रा की परिभाषा इसी दृष्टिकोगा से करते हैं। नैप के ऋनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा हो जाती है। \* नैप ने मुद्रा के सम्बन्ध में वैधानिक दृष्टिकोए। अपनाया है और मुद्रा के चालू रूप पर अधिक ध्यान दिया है। सभी जानते हैं कि आधुनिक जगत में मुद्रा का उत्पादन सरकार के हाथ में होता है ग्रौर कुछ वस्तुएँ सरकार की ग्रोर से मुद्रा घोषित कर दी जाती हैं। ये सभी वस्तुएँ मुद्रा के रूप में चालू रहती हैं। इनका स्वीकार करना कानून द्वारा ग्रनिवार्य कर दिया जाता है। जो व्यक्ति इनके रूप में भूगतान लेने से इन्कार करता है उसे राज्य दण्ड देता है। यही कारणा है कि बहुत सी ऐसी वस्तुएँ भी मुद्रा के रूप में चालू हो जाती हैं जिन्हें यदि सरकार मुद्रा घोषित न करती तो कोई भी स्वीकार न करता। उदाहरए। के लिए, एक सौ रुपये के नोट की वैसे तो कुछ भी कीमत नहीं हो सकती है, परन्तु सरकार द्वारा मुद्रा घोषित हो जाने के कारण उसकी कीमत इतनी अधिक हो जाती है। अतः जब सरकार कागज के नोटों का विमुद्रीकरण कर देती है, अर्थात् जब उनके पीछे से वैधानिक दबाव हटा लिया जाता है तो उन्हें कोई भी मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं करता। इन बातों से पता चलता है कि मुद्रा के भीतर सामान्य स्वीकृति का जो ग्रुग है वह राज्य द्वारा ही उत्पन्न किया गया है।

#### दोष--

वैघानिक दृष्टिकोए। के ग्रतिरिक्त व्यवहार में भी यह परिभाषा सही प्रतीत

See the English Translation of Knapp by Lucas and Bonar: The State Theory of Money, 1924.

होती है, परन्तु वास्तव में परिभाषा इतनी सही नहीं है। हॉटरे इसी परिभाषा के पक्षपाती थे, परन्तु बाद को कुछ किमयाँ देख कर उन्होंने परिभाषा में भ्रावश्यक परि-वर्तन करने की कोशिश की है। ऊपर से देखने में तो यही पता चलता है कि वास्तविक संसार में नैप का दृष्टिकोए। ही सही है, परन्तु स्वयं नैप के देश जर्मनी में ग्रसाधारए। परिस्थितियों के काल में इस परिभाषा की कमजोरी प्रकट हो गई थी। प्रथम महायुद्ध के पश्चात जर्मनी में भीषए। मुद्रा-प्रसार हुआ था। कारए। यह था कि युद्ध काल में ज़र्मन सरकार ने पत्र-मूद्रा की ग्रत्यधिक निकासी द्वारा ग्राय प्राप्त की थी। पत्र-मुद्रा इतनी अधिक हो गई थी और कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही थीं कि मुद्रा पर से जनता का विश्वास उठ गया था । परिएतम यह हुम्रा कि लोगों ने कागज के नोटों को स्वीकार करना बन्द कर दिया । हजारों नोटों के बदले में भी एक समय का भोजन प्राप्त करना कठिन हो गया था ग्रौर सभी विनिमय-कार्य वस्तु-विनिमय द्वारा होने लगे थे। जर्मन सरकार ने कड़े नियमों द्वारा मुद्रा की स्वीकृति को बनाये रखने का प्रयत्न किया। उसे स्वीकार न करने वाले के लिए मृत्यु दण्ड रखा गया, परन्तु फिर भी मुद्रा पर विश्वास न जम सका । अन्त में, जर्मन सरकार को यह घोषएा। करने पर बाध्य होना पड़ा कि सरकार पत्र-मुद्रा को भूमि के टुकड़ों में बदलने की गारन्टी देती है। इसके पश्चात् ही घीरे-घीरे मुद्रा में विश्वास पुनः स्थापित हुमा। इस उदाहरण से पता चलता है कि राज्य की सारी शक्ति मुद्रा के पीछे होते हुए भी राज्य द्वारा घोषित मुद्रा चालू न रह सकी । इससे स्पष्ट है कि मुद्रा की स्वीकृति यथार्थ में राज्य की घोषणा ग्रथवा उसकी शक्ति पर निर्भर नहीं होती, वरन् जनता के विश्वास पर निर्भर होती है। सरकार द्वारा घोषित वस्तु मुद्रा के रूप में तभी तक चल सकती है जब तक कि उस पर जनता का विश्वास है। इस विश्वास के उठते ही उसका चलन रुक जाता है। इसी विश्वास को वनाये रखने के लिए ही पत्र-मुद्रा के पीछे अनसर किसी न किसा प्रकार की बहुमूल्य घातु की स्नाड रखी जाती है।

नैप की परिभाषा का एक दोष और भी है। अर्थशास्त्र में केवल ऐसे हस्तान्तरण के कार्य को विनिमय कहा जाता है जोकि ऐच्छिक तथा स्वतन्त्र हो, परन्तु यि मुद्रा की स्वीकृति राज्य द्वारा अनिवार्य कर दी जाय तो फिर इससे विनिमय कार्य की स्वतन्त्रता ही समाप्त हो जाती है और ऐसा हस्तांतरण कार्य सच्चे अर्थ में विनिमय नहीं रहता। नैप ने अपनी परिभाषा इतिहास के आधार पर बनाई है और उसकी नियमितता पर अधिक जोर दिया है, परन्तु उसकी परिभाषा तक की कसौटी पर सही नहीं उत्तरती है। इन दोषों को ध्यान में रखते हुए हॉटरे ने अपनी परिभाषा में इस प्रकार परिवर्तन किया है कि ''मुद्रा के दो पहलू हैं:—प्रथम, यह लेखे की इकाई है और दूसरे यह विधि ग्राह्य (Legal Tender) है।'' इस प्रकार उन्होंने नैप के दृष्टिकोण के साथ-साथ मुद्रा द्वारा क्रयः शक्ति के रूप में किये जाने वाले कार्य को भी सिम्मिलत कर लिया है।

#### सामान्य स्वीकृति पर श्राधारित परिभाषायें

तीसरे वर्ग में वे परिभाषाएँ सिम्मिलित हैं जो मुद्रा की सामान्य स्वीकृति अथवा सर्वग्रहणीयता (General Acceptability) पर आधारित हैं। (इस वर्ग की परिभाषाओं में भी परस्पर काफी अन्तर है और दो प्रकार की परिभाषाएँ दृष्टिगोचर होती हैं । कुछ विद्वानों ने तो मुद्रा को संकुचित अर्थ में उपयोग किया है और कुछ ने उसके विस्तृत अर्थ लगाये हैं।) इस वर्ग की प्रमुख परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं—

(१) वाकर के अनुसार:—''मुद्रा वह है जो वस्तुएँ खरीदने के शोधन में तथा ऋगों का अन्तिम भुगतान करने में स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरित होती रहती है और इसे चुकाने वाले व्यक्ति के चिरत्र अथवा उसकी साख का ध्यान नहीं रखा जाता और साथ ही जो व्यक्ति इसे प्राप्त करता है उसका ऐसा विचार नहीं होता कि वह स्वयं इसका उपयोग करे, बिलक वह किसी न किसी समय उसे विनिमय द्वारा हस्तान्तरित कर देता है।''

(२) मार्शल के ऋनुसार:—"मुद्रा में वे सब वस्तुयें शामिल होती हैं जो (किसी समय विशेष ऋथवा स्थान विशेष में) बिना सन्देह ऋथवा विशेष जाँच के वस्तुऋों और सेवाऋों को खरीदने तथा खर्चों को चुकाने के साधन के रूप में साधारणतया चालू होती हैं।"

﴿ (३) रावर्टसन ने मुद्रा की परिभाषा इस प्रकार की है:—''मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुत्र्यों की कीमत चुकाने तथा ऋन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने के लिए विस्तृत रूप में स्वीकार किया जाता है ।''³

र्प(४) सैलिगमैन के ऋनुसार :—''मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो।''

ि ५ (५) कोल के विचार में :—''मुद्रा केवल कयःशक्ति है अर्थात् एक ऐसी वस्तु जिससे अन्य वस्तुयें खरीदी जा सकती हैं । यह ऐसी वस्तु है जो साधारणतया

- 1. Money is that which passes freely from hand to hand in full payment of goods in final discharge of indebtedness, being accepted equally without reference to the character or credit of the person tendering it, and without any intention on the part of the person receiving it himself to consume or otherwise use it than by passing it on, sooner or later, in exchange.
- 2. "Money includes all those things which are (at any given time or place) generally current without doubt or special enquiry as a means of purchasing commodities or services and of defraying expenses."—See, Marshall: Money, Credit and Commerce, p. 13.
- 3. "A commodity which is used to denote anything which is widely accepted in payment of goods, or in discharge of other business obligations." See Robertson: Money, p. 2.
  - 4. "Money is one thing that possesses general acceptability."

तथा विस्तृत रूप में शोधन के साधन के रूप में उपयोग की जाती है श्रीर साधारणतया ऋणों के भुगतान में स्वीकार की जाती है।"

﴿﴿ ६) प्रो॰ ऐली का मत है किः—''मुद्रा ऐसी कोई भी वस्तु है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरण होता है ख्रौर जो ऋणों के ख्रन्तिम सुगतान में सामान्य रूप में स्वीकार की जाती हैं।''

्र (७) काउथर का कथन है कि:—''यह (मुद्रा) वह चीज है जिसे साधा-रुगातः विनिमय माध्यम मान लिया गया हो, ऋथीत देना-पावना चुनान का जो साधन हो ऋौर साथ ही जो मूल्य की माप ऋौर उसके कोष का काम करती हो।''3

्रे (८) लार्ड कीन्ज के अनुसारः—''मुद्रा वह है जिसे देकर ऋग् के प्रसं-विदों (Contracts) तथा मूल्य के प्रसंविदों का भुगतान किया जा सकता है और जिसके रूप में सामान्य कथः शक्ति का संचय किया जाता है।"

(E) कैन्ट का कथन है कि:—''मुद्रा एक वस्तु है जिसे साधारणतया विनिमय के माध्यम अथवा मूल्य के मान के रूप में स्वीकार किया जाता है।''

1. "Money is simply purchasing power—something which buys things—it is anything which is habitually and widely used as a means of payment and is generally acceptable in the settlement of debts."—See G. D. H. Cole: What Everybody Wants to Know About Money, p. 21.

2. "Anything that passes freely from hand to hand as a medium of exchange and is generally received in final discharge of

debts."—See Ely: Elementary Principles of Economics.

3. See Geoffry Crowther मुद्रा की रूप रेखा, पृष्ठ २६।

4. "Money is that by the delivery of which debt contracts and price contracts are discharged and in the shape of which a store of general purchasing power is held." See J. M. Keynes: A Treatise on Money, vol. I.

5. "Money is anything which is commonly used and generally accepted as a medium of exchange or as a standard of value." See Kent: Money and Banking. p. 3.

6. "Money consists of those things which, within a society, are of general acceptability passing from hand to hand as a medium of exchange.......No commodity is however, acceptable and in this sense money is always local, it is money in some places and in other places it is not acceptable.

(११) हॉम के ऋनुसार :— "मुद्रा शब्द का उपयोग विनिमय माध्यम तथा मूल्य मान दोनों ही के लिए किया गया है। ""

उपरोक्त सभी परिभाषात्रों में भिन्नता होते हुए भी एक प्रकार की समानता है। सभी लेखकों ने सामान्य स्वीकृति को मुद्रा का एक ग्रावश्यक ग्रुण माना है, परन्तु इस सम्बन्ध में कीन्ज, क्राउथर तथा वाघ की परिभाषायें ग्रधिक उपयुक्त हैं। इन परिभाषाग्रों से मुद्रा के निम्न ग्रुणों का पता चलता है:—

- (१) मुद्रा की स्वीकृति स्वतन्त्र तथा ऐन्छिक होनी चाहिये। यदि किसी वस्तु को मुद्रा के रूप में दबाव ग्रथवा भय के कारण स्वीकार करना पड़ता है तो उसे हम मुद्रा नहीं कह सकते हैं। ग्रर्थशास्त्र में तो विनिमय स्वभाव से ही ऐन्छिक तथा स्वतन्त्र होता है। इस कारण मुद्रा का विनिमय के माध्यम के रूप में जो उप-योग होता है वह भी स्वेच्छा से ही होना चाहिए।
- (२) मुद्रा की स्वीकृति सामान्य होनी चाहिए। ग्रर्थात् सभी लोग उसे मूल्य तथा ऋणों के चुकाने में स्वीकार करते हों। इस सम्बन्ध में जैसा कि वाघ (Waugh) ने कहा है कोई कि भी वस्तु संसार में ऐसी नहीं है जिसे प्रत्येक स्थान में सर्व स्वीकृति प्राप्त हो। लगभग सभी वस्तुग्रों की स्वीकृति स्थानीय हुग्रा करती है। मुख्यतया एक देश की मुद्रा दूसरे देश में स्वीकृत नहीं होती। इस कारण सामान्य स्वीकृति का संकृचित ग्रर्थ लगाना ही ग्रधिक ग्रच्छा है। मुद्रा के लिए यह ग्रावश्यक है कि क्षेत्र विशेष में उसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, परन्तु क्षेत्र विशेष का काफी बड़ा होना ग्रावश्यक है। यदि दस मित्र मिल कर यह निश्चित कर लें कि ग्रमुक वस्तु मुद्रा के रूप में उपयोग की जायेगी तो इससे यह वस्तु मुद्रा नहीं हो सकती। स्वीकृति का क्षेत्र ग्राधिक दशाग्रों को देखते हुए समुचित रूप से विस्तृत होना चाहिए। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने मुद्रा के साथ सामान्य स्वीकृति के ग्रतिरिक्त 'विस्तृत' स्वीकृति का भी ग्रण जोड़ दिया है।
- (३) त्राधुनिक त्रार्थशास्त्र में मुद्रा-विनिमय का माध्यम तथा कीमतों का मान दोनों ही एक साथ मानी जाती है, मुद्रा को केवल विनिभय का माध्यम या केवल कीमतों का मान कहना ठीक नहीं है। हॉटरे (Hawtrey) भी यह मानते हैं कि वैद्यानिक महत्त्व के ग्रातिरिक्त लेखे की इकाई के रूप में भी मुद्रा का महत्त्व होता है।
- (४) उपरोक्त सभी परिभाषात्रों में मुद्रा के कार्यों की स्त्रोर भी संकेत किया गया है। मुख्यतया मुद्रा के निम्न चार कार्यों को विशेष महत्त्व दिया गया, है.

<sup>\* &</sup>quot;The word money has been used to designate the medium of exchange as well as the standard of value." See Halm: Monetary Theory, p. 3.

विनिमय का माध्यम, कीमतों का मान, ऋ गों के भुगतान का मान श्रौर कीमत का संचय।

(५) तर्कशास्त्र के दृष्टिकोण से भी ये परिभाषायें उपयुक्त हैं, क्योंकि इनमें मुद्रा का वर्ग स्रर्थात् वस्तु तथा मुद्रा के विशेष ग्रुण स्रर्थात् सामान्य स्वीकृति का उल्लेख कर दिया है। प्रत्येक वस्तु मुद्रा नहीं होती है। केवल वहीं वस्तुए मुद्रा है जिनमें पूर्व विशिष कार्य करने के ग्रुण पाये जाते है।

उपरोक्त गुणों को देखते हुए हम मुद्रा की एक सरल परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं—''मुद्रा वह वस्तु है जिसे एक विस्तृत च त्र में थिनिमय के माध्यम, कीमत के मान, ऋणों के भुगतान तथा कीमतों के संचय के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो।'' ऐसी वस्तु की प्रकृति तथा उसका रूप कुछ भी हो सकता है और वास्तविकता यह है कि विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न कालों में भ्रवग-भ्रवण वस्तुभों का मुद्रा के रूप में उपयोग हुम्रा भी है।

## (II) अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के श्रनुसार वर्गीकरण

ग्रर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की जो परिभाषाएँ दी हैं उनके ग्रध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वे दो सीमाग्नों—संकुचित भाव ग्रीर ग्रति विस्तृत भाव के बीच घड़ी के पेन्डुलम की तरह डोज रहे हैं। इस तरह मुद्रा की परिभाषा के सम्बन्ध में निम्न तीन विचारधारायें मिलती हैं:—

## (१) संकुचित ऋर्थ वाली परिभाषायें—

संकुचित ग्रर्थ में केवल घातु-मुद्रा को ही मुद्रा में सम्मिलित किया गया है।
मुद्रा का सम्पूर्ण उद्देश्य सिक्कों द्वारा ही पूरा होता है ग्रीर इसलिए कुछ विद्वानों (जैसे
राबर्टसन ग्रादि) ने विनिमय-माध्यम् के रूप में उन्हीं को मुद्रा स्वीकार किया है।

## (२) विस्तृत श्रर्थ वाली परिभाषायें—

विस्तृत ग्रथं में उन सभी वस्तुग्रों को मुद्रा में सम्मिलित किया जाता है जोकि विनिमय-माध्यम के रूप में चालू होते हैं, चाहे उनमें किसी प्रकार का निहित मूल्य (Intrinsic Value) हो या नहीं । इसी प्रकार यह भी ग्रावश्यक नहीं है कि वस्तु विशेष का मुद्रा के रूप में स्वीकार करना वैधानिक दृष्टिकोण से ग्रानवार्य हो । इस विचार के ग्रनुसार सोना, चाँदी, तांवे ग्रादि के सिक्के, कागज के नोट, चैक, हुण्डियाँ, विनिमय बिल (Bills of Exchange), बैंक नोट (Bank Note), पुस्तकीय साख (Book Credit) ग्रादि सभी मुद्रा होते हैं।

## (३) उचित ऋर्थ वाली परिभाषायें -

प्राधुनिक म्रर्थशास्त्री साधारएतया इन दोनों विचारघाराग्रों के बीच का मार्ग भ्रपनाते हैं। उनके म्रनुसार यह तो म्रावश्यक नहीं है-िक मुद्रा घातु की बनी हुई हो। मुद्रा केवल ऐसी होनी चाहिए कि उसे समाज या समुदाय में सामान्य स्वीकृति प्राप्त

गायद इसी कारएा

हो ग्रौर सभी मनुष्य उसे वस्तुग्रों तथा सेवाग्रों के मूल्य के रूप में स्वेच्च्च कम नहीं तरें। इस दृष्टिकोएा से केवल घातु मुद्रा तथा कागजी नोट ही मुद्रा हैं। चैक, का मुख्य बेल भ्रादि को मुद्रा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें सामान्य स्वीकृति प्राप्त 🌂 हैं। उनका स्वीकार करना या न करना व्यक्ति विशेष को स्वेच्छा पर निर्भर होता है

प्रौर स्वीकार करते समय बहुधा देने वाले की साख देख ली जाती है। निष्कर्ष ---

साराँश यह है कि केवल विधि-याह्य मुद्रा (Legal-tender money)

को ही मुद्रा में शामिल किया जाता है। यह तो निश्चय है कि किसी वस्तु के मुद्रा

बनने के लिये उसकी वैधानिक स्वीकृति की ग्रावश्यकता नहीं है. लेकिन ग्रधिकाँश

लेखक इस प्रकार की स्वीकृति का अनुरोध करते हैं। इस प्रकार का अनुरोध उचित नहीं है। मुद्रा के लिए सामान्य स्वीकृति का होना ही काफी है। वे बैंक नोट, साख-

पत्र तथा प्रतिभूतियाँ (Securities), जिन्हें इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त है,

मुद्रा ही हैं।

मुद्रा के कार्य

(The Functions of Money)

मुद्रा के कार्यों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है-

(१) मुख्य कार्य (Primary Functions)—इन्हीं को कभी-कभी

प्राधारभूत कार्य (Fundamental Functions), मौलिक कार्य (Original

Functions) अथवा आवश्यक कार्य (Essential Functions) भी कहा जाता है। मुख्य कार्यों की विशेषता यह है कि ये कार्य मुद्रा द्वारा आर्थिक विकास की

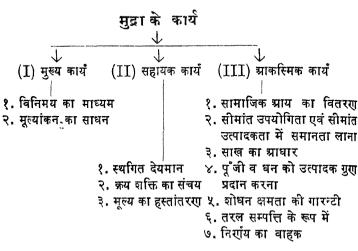
प्रत्येक ग्रवस्था में सम्पन्न किये जाते हैं। समय-समय पर विभिन्न वस्तुएँ मुद्रा के रूप में उपयोग की गई हैं, परन्तु उन सभी वस्तुश्रों ने कम से कम इन कार्यों को भ्रवश्य सम्पन्न किया है।

(२) सहायक कार्य (Secondary Functions)—इन्हें कभी-कभी मुद्रा के व्युत्पादित कार्य (Derived Functions) भी कहा जाता है। इन सब कार्यों की विशेषता यह है कि ये गौए। होते हैं धीर मुख्य कार्यों पर निभंर होते हैं।

मुद्रा द्वारा ये कार्य उसी अवस्था में सम्पन्न किये जाते हैं जबकि आर्थिक जीवन का एक ग्रंश तक विकास हो चुकता है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा के इन कार्यों का विकास ग्राधिक

विकास की उन्नति के पश्चात् होता है। (३) ग्राकस्मिक कार्य (Contingent Functions)—इन कार्यो का वर्णन प्रो० किनले (Kinley) ने किया है। उनका विचार है कि उपरोक्त कार्यों के ग्रतिरिक्त उन्नत देशों में, जहाँ ग्रार्थिक जीवन का विकास बहुत ग्रधिक हो जाता है. मुद्रा कुछ ग्रौर भी कार्य करती है, जिन्हें मुद्रा के ग्राकस्मिक कार्य कहा जाता है। जैस-

विनिमय का मान बंचय को जावन की उन्नति होती है, वैसे-वैसे इन कार्यों का महत्त्व बराबर बढ़ता संचय



## (I) मुख्य कार्य (Primary Functions)

# (१) मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है (Money is a Medium of Exchange)—

मुद्रा का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि वह विनिमय के कार्य को सरल बनाती है। इसकी सहायता से एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु सरलता से प्राप्त की जा सकती है। वस्तु-विनिमय में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं। जब तक दो व्यक्तियों की आवश्यकताओं में 'पारस्परिक मिलान नहीं होता है, विनिमय सम्भव नहीं हो पाता। परन्तु मुद्रा का उपयोग इस कठिनाई को दूर कर देता है। मुद्रा की सहायता से विनिमय कार्य प्रत्यक्ष न हो कर परोक्ष हो जाता है। पहले एक वस्तु मुद्रा में पिरविति की जाती है और फिर इस प्रकार प्राप्त होने वाली मुद्रा से दूसरी वस्तु खरीदी जाती है। इस प्रकार विनिमय का प्रत्येक कार्य दो भागों में विभाजित हो जाता है:—(१) वस्तु अथवा सेवा को मुद्रा में बदला जाता है और (२) फिर मुद्रा के बदले में वस्तुयें और सेवायूं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मुद्रा को सभी विनिमयों में स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए वह स्वयं भी वस्तुयों और सेवाय्रों के बदले में मुद्रा को निःसंकोच स्वीकार करता है। अतः वही मुद्रा सर्व स्वीकृत हो सकती है जो विनिमय सम्बन्ध इस आवश्यक कार्य को पूरा करे। जैसा कि कोल ने भी कहा है कि मुद्रा ही हमारी क्रयः शक्ति है।

विनिमय-माध्यम का यह कार्य मुद्रा को म्राधिक जीवन के विकास की प्रत्येक

भवस्था में करना पड़ता है। शुरू-शुरू में मुद्रा का भ्राविष्कार ही शायद इसी कारए। किया गया था ग्रौर ग्रार्थिक जीवन के विकास से भी इस कार्य का महत्त्व कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ता ही गया है। यही कारण है कि मुद्रा का यह कार्य उसकी मुख्य कार्यं कहा जाता है।

# (२) मूल्यमान अथवां मूल्याङ्कन का साधन (Standard of Values)—

मुद्रा का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि वह सब वस्तुग्रों के मूल्य को श्रांकने का कार्य करती है। सभी वस्तुश्रों की कीमत को मुद्रा में ही नापा जाता है, इसलिए मुद्रा कीमतों का सामूहिक सूचक होती है। कीमतों को नाप कर मुद्रा इन् वस्तुओं और सेवाओं के बीच विनिमय-अनुपात निर्धारित करती है। प्रत्येक विनिमय-

अनुपात की सही साप के लिए मुद्रा ही माप-दण्ड का कार्य करती है। वस्तु-विनिमय की दूसरी कठिनाई यह थी कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच विनिमय अनुपात निश्चित करना कठिन था, परन्तु जब प्रत्येक वस्तु अथवा सेवा की कीमत मुद्रा में नापी जाती है तो यह कठिनाई भ्रांप ही भ्राप दूर हो जाती है। इस सम्बन्ध में एक कठिनाई अवश्य है। एक गज अथवा एक मन की भाँति मुद्रा मूल्य नापने का पूर्णतया निश्चित मान नहीं है। कारण यह है कि समय-समय पर स्वयं मुद्रा की कीमत में भी परिवर्तन होते रहते हैं ग्रीर कीमतें बराबर घटती-बढ़ती रहती हैं, किन्तु कीमतों को नापने और विनिमय अनुपातों को निर्घारित करने के लिये मुद्रा से अच्छा

# मुद्रा के विनिमय माध्यम और मूल्यमान के कार्यों में मेल-

कोई दूसरा साधन नहीं है।

इस सम्बन्ध में यह याद रखना भ्रावश्यक है कि विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मान के रूप में मुद्रा के कार्यों का इतना घनिष्ट मेल है कि बहुचा यह निर्णाय करना कठिन होता है कि एक कार्य कहाँ पर समाप्त होता है और दूसरा कहाँ से भारम्भ होता है। अब तक विनिमय किये जाने वाली वस्तुओं की कीमत मुद्रा में नहीं श्रांक ली जाती है, तब तक मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता । विनिमय-माध्यम तथा मूल्य-मान का कार्य मुद्रा द्वारा लगभग साथ ही साथ

सम्पन्न किया जाता है, परन्तु कई बार ऐसा भी होता है कि मुद्रा को मूल्य-मान के रूप में तो उपयोग किया जाता है, परन्तु वस्तुओं को मुद्रा में बदला नहीं जाता । उदाहरण-स्वरूप, यदि एक किसान सहकारी भण्डार के पास जाता है ग्रीर ग्रपने पास से कुछ गेहूँ को देकर चीनी लेना चाहता है तो निस्सन्देह गेहूँ ग्रौर चीनी दोनों ही की कीमत मुद्रा में आँकी जाती है और विनिमय भी किया जाता है, परन्तु इस कार्य में मुद्रा का हस्तान्तरए। नहीं होता । इसी प्रकार लोग कई बार अपनी वस्तुओं की कीमत मुद्रा-में शाँकते हैं, परन्तु उनका इन वस्तुग्रों को विनिमय करने का कोई विचार नहीं होता। उदाहरण के लिये, एक मकान मालिक कह सकता है कि उसका मकान २०,००० रुपये का है, परन्तु साथ ही यह सम्भव है कि उसका ग्रपने मकान को इस कीमत पर

बेबने का कोई भी विचार न हो। वर्तमान व्यावसायिक संगठन में प्रत्येक फर्म (Firm) की लेन-देन का हिसाब मुद्रा में किया जाता है। भूमि, मकान मशीन आदि सभी चीजों को कीमत मुद्रा में सूचित की जाती है, यद्यपि इन सब चीजों को बेचने का तिनक भी विचार नहीं होता है। ऐसी दशा में मुद्रा केवल लेखे की इकाई (Unit of Account) के रूप में उपयोग की जाती है, विनिमय माध्यम के रूप में उसका उपयोग नहीं होता।

## च्या विनिमय-माध्यम तथा मूल्यमान वा ऋलग-ऋलग होना सम्भव है

विनिमय माध्यम तथा मूल्य-मान का सम्यन्ध इतना घनिष्ट है कि एक को दूसरे से अलग करना विठन है, परन्तु कुछ अश तक दोनों को अलग-अलग कर देना सम्भव होता है। आधुनिक जगत में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते है जिनमें किसी एक वस्तु को विनिमय के माध्यम के रूप-में उपयोग किया जाता है और किसी दूसरी वस्तु को मूल्य के मान के रूप में। इस विषय से सम्बन्धित कई उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। सन् १६२३ में जर्मनी में दो अलग-अलग मुद्रायें विनिमय माध्यम तथा मूल्यमान का काम कर रही थीं। इस काल में जर्मनी में भीषणा मुद्रा प्रसार फेला हुआ था। कीमतें निरन्तर ऊपर जा रही थीं और जर्मन मार्क (Mark) की कीमत में किसी भी प्रकार की स्थिरता न थी। इस काल में जर्मनी में साधारणतया प्रसंविदे (Contracts) सुइस फेंक (Swiss Franc) अथवा अमरीकन डालर में किए जाते थे (क्योंकि इन मुद्राओं के मूल्य में स्थिरता थी), परन्तु भुगतान जर्मन मार्क में ही किया जाता था। भुगतान के समय मार्क और फेंक अथवा डालर की विनिमय-दर के आधार पर मार्क की मात्रा निश्चित कर ली जाती थी। इस प्रकार चलन की इनाई तो मार्क ही था, परन्तु लेखे की इकाई डालर या फेंक होता था।

संयुक्त राज्य श्रमरीका में भी सन् १९३३ तक इसी प्रकार की स्थित थी। उस देश में मूल्य का मान तो स्वर्ण डालर था, परन्तु वास्तव में द्वेश में प्रचलन पत्र-मुद्रा और चाँदी, गिलट तथा ताँबे के सिक्कों का था। यही सब वस्तुए प्रत्यक्ष रूप में विनिमय माध्यम के रूप में प्रचलित थीं, परन्तु स्वर्ण डालर का इस रूप में उपयोग लगभग नहीं के बराबर था। इस प्रकार दो ग्रलग-ग्रलग मुद्रायों विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मान के रूप में उपयोग की जा रही थीं, परन्तु सरकार द्वारा यह गारन्टी दी गई थी कि प्रत्येक दशा में ग्रन्य सभी मुद्राग्रों की विनिमय-दर सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के ग्रनुसार रखी जाती थी। श्रतः दो मिच-भिच प्रकार की मुद्रायें विनिमय माध्यम तथा मूल्यमान के रूप में उपयोग में लाई जा सकती हैं। परन्तु यह तभी सम्भव होता है जबिक सरकार द्वारा दोनों मुद्राश्रों की विनिमय-दर कायम रखी जाती है। इस सम्बन्ध में प्री० बेनहाम (Benham) का कहना है कि यद्यिप साधारएतया चलन की इकाई (Unit of Currency) ग्र्यांत विनिमय-

भाध्यम तथा लेखे की इकाई (Unit of Account) में कोई अन्तर नहीं होता (क्योंकि मूल्य की माप ही विनिमय के लिए की जाती है) तथापि यह सम्भव है कि विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मान अलग-अलग हों, यदि दोनों के बीच के अनुपात को बनाए रखना सम्भव है।

## (II) गौग कार्य (Secondary Functions)

## (१) स्थगित देयमान (Standard for Deferred Payments)-

बहुत से लेन-देन ऐसे होते हैं जिनका भुगतान तुरन्त नहीं किया जाता है, बल्कि भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है। भ्राधुनिक जगत में तो भ्रधिकाँश व्याव-सायिक वार्य उधार ग्रथवा साख प्रणाली पर ही ग्राघारित होते हैं। कहा जाता है कि दूसरों के रायों से व्यवसाय करना ही आधुनिक व्यावसायिक संगठन की प्रमुख विशेषता है। मुद्रा का गुरा यह है कि वह तुरन्त के व्यावसायिक कार्यों के लिए ही मूल्य के मान का कार्य नहीं करती है, बलिक स्थिगित मुख्तानों का भी मान होती है। इसका कारण यह है कि मुद्रा में तीन ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो उसे इस कार्य के लिए उपयुक्त बना देती हैं। प्रथम तो ग्रन्य वस्तुश्रों की अपेक्षा मुद्रा की कीमत में स्थिरता अधिक होती है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन तो अवस्य होते रहते हैं, परन्तु साधारण-तया बहुत शीघ्रता से तथा बड़े म्रंश तक परिवर्तन कर्म होते हैं। यही कारण है कि स्थिगत भुगतानों का हिसाब मुद्रा में रखने से लेने वाले और देने वाले दोनों को ही हानि का भय कम रहता है । दूसरें, मुद्रा में सामान्य स्वीकृति, का गुण होता है, जिसके कारण उसकी मावश्यकता हर समय रहती है। तीसरे, मन्य वस्तुम्रों की म्रपेक्षा मुद्रा में टिकाजपन भी अधिक होता है। मुद्रा का स्थिगित भगतानों के मान के रूप में भारी महत्त्व है, क्योंकि इससे उधार लेने ग्रौर देने में सुभीता हो जाता है ग्रौर ग्रधिक उत्थान का मार्ग सरल हो जाता है। वैंकों की जमा, फर्मों के खातों श्रीर सरकार, रेल्वे. लोक उपयोगी सेवा कम्पनियों ग्रादि द्वारा निकाले हुए बाँड (Bonds) इन सभी प्रकार के ऋगों का हिसाब मुद्रा में ही रखा जाता है।

स्थिगित भुगतानों के मान के रूप में मुद्रा दोषों से खाली नहीं है | मुद्रा के इन दोषों के कारण बहुधा ऋण-दाताओं तथा ऋण-लेताओं को भारी कठिनाइयाँ होती हैं। कारण यह है कि स्वयं मुद्रा के मूल्य में भारी परिवर्तन होते रहते हैं, जो कभी ऋण-दाताओं को हानि पहुँचाते हैं और कभी ऋण-लेताओं को। इस कारण कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह सुभाव दिया है कि मुद्रा को स्थिगत भुगतानों का अधिक लोंचदार मान बनाने की आवश्यकता है। यदि इन अर्थशास्त्रियों के सुभाव को मान लिया जाय तो परिणाम यह होगा कि ऋणी वर्ग को उधार ली हुई क्रयः शक्ति के बराबर मूल्य लोटाना पड़ेगा और इस प्रकार चुकाई जाने वाली मुद्रा की मात्रा में मुद्रा की क्रयः शक्ति के परिवर्तनों के अनुसार अन्तर होगा।

## (२) क्रयः शक्ति का संचय (The Store of Purchasing Power)

जब मुद्रा का उपयोग विनिमय माध्यम के रूप में किया जाता है तो विनिमय का कार्य वास्तव में दो अलग-अलग कार्यों का एक सामूहिक परिगाम होता है। सर्व-प्रथम किसी वस्तु अथवा मेवा को मुद्रा में बेचा जाता है और फिर प्राप्त मुद्रा द्वारा अन्य वस्तु अथवा सेवा खरीदी जाती है। सभी प्रकार का विनिमय स्वभाव में वस्तु के बदले में वस्तुयें अथवा सेवायें प्राप्त करने की एक रीति होती है। मुद्रा को प्राप्त करने का उद्देश्य ही यह होता है कि उसके बदले में दूसरी वस्तुयें खरीदी जा सकें, परन्तु यह सम्भव है कि एक वस्तु को बेच कर जो मुद्रा प्राप्त की गई है उसे तुरन्त व्यय न किया जाय, बल्कि कुळ समय के लिए उसका व्यय स्थिगित कर दिया जाय। ऐसी दशा में मुद्रा एक और कार्य, अर्थात् कयः शिक्त का संचय करने का कार्य सम्मच करती है।

एक किसान को बैलों की श्रावश्यकता हो सकती है। रबी की फसल बेचकर वह मुद्रा प्राप्त करता है, परन्तु यदि बैलों की श्रावश्यकता जाड़ों में होगी तो इस मुद्रा को वह जाड़ों तक संचित रखेगा, ताकि समय श्राने पर उसे बैल खरीदने में कठिनाई न हो। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भावी श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ बचाकर रखना चाहता है। श्रव प्रश्न यह है कि बचत किस रूप में रखी जाय? सेवायें तो श्रित शीघ्र ही नाश हो जाने वाली वस्तुयें होती हैं, इसलिए उन्हें बचाकर रखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। श्रविकांश वस्तुश्रों में भी काफी समय तक टिकांऊ रहने का ग्रुग नहीं होता है श्रीर कुछ वस्तुश्रों, जैसे मवेशियों, में संचय करने से मूल्य का हास होता है। मुद्रा में टिकाऊपन होता है श्रीर उसके मूल्य में भी श्रपेक्षितन् पतन कम होता है, इसलिए क्रयः शक्ति के संचय के लिए मुद्रा ही श्रविक उपयुक्त होती है।

मुद्रा के इस कार्य का आरम्भ भी आर्थिक जीवन के विकास के परवात् ही हुआ है, परन्तु आधुनिक युग में इसका महत्त्व बहुत बढ़ गया है। बिना बचत के पूँजी का संचय सम्भव नहीं है और पूँजी के संचय के बिना आर्थिक उन्नति की आशा निमूल ही होगी। इस सम्बन्ध में यह भी बिना संकोच कहा जा सकता है कि मूल्य अथवा कयः शक्ति को संचित करने का सबसे सुरक्षित तथा सुविधाजनक साधन मुद्रा ही है।

## (३) मूल्य का हस्तान्तरण (Transfer of Value)—

मुद्रा के इस कार्य का महत्त्व भी ग्रायिक जीवन के विकास के साथ-साथ ही बढ़ा है। जैसे-जैसे ग्रायिक जीवन सुसंगठित होता गया, वैसे-वैसे विनिमय का क्षेत्र भी विस्तृत होता गया। वस्तुत्रों का क्रय-विक्रय दूर-दूर तक होने लगा ग्रौर इस प्रकार मूल्य ग्रथवा क्रयः शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरण करने की ग्राव- रियकता ग्रनुभव हुई। यह कार्य भी मुद्रा की सहायता से ग्रासानी के साथ होने लगा। ग्रापनी सामान्य स्वीकृति के कारण मुद्रा एक व्यक्ति को इस योग्य बना देती है कि वह एक स्थान पर त्रापनी सम्पत्ति को बेचकर दसरे स्थान पर नई सम्पत्ति ख़रीद सके।

इसके ऋतिरिक्त मुद्रा के ही रूप में रुपये का लेन-देन होता है और इस प्रकार कयः शक्ति का एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तान्तरण सम्भव हो जाता है।

इस कार्य का भी मनुष्य के सामाजिक तथा आधिक जीवन में भारी महत्त्व है। इस हस्तान्तरण के कारण कुछ व्यक्तियों के पास पड़ी हुई बेकार तथा फालतू क्रयः शक्ति का उत्पादक कार्यों में उपयोग सम्भव हो जाता है और आधिक विकास की सम्भावना दढ़ जाती है।

## ( III ) श्राकस्मिक कार्य (Contingent Functions)

प्रो० किनले ने मुद्रा के चार ग्राकस्मिक कार्यों का वर्णन किया है :--

#### (१) सामाजिक ग्राय का वितरण-

वर्तमान संसार में उत्पादन का कार्य साधारणतया प्रत्यक्ष उपभोग के लिये नहीं किया जाता है, बल्कि उत्पादित वस्तुम्रों को बाजार में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके म्रतिरिक्त म्राधुनिक उत्पादन सामूहिक रूप में म्रथवा सिम्मिलत रूप से किया जाता है। जो कुछ भी उत्पत्ति होती है वह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा न हो कर सारे समाज म्रथवा बहुत से व्यक्तियों द्वारा मिलकर की जाती है भौर इसलिए इस उत्पादन के वितरण की म्रावश्यकता पड़ती है। सुद्रा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वह इस सिम्मिलित उपज म्रथवा राष्ट्रीय लामांश (National Dividend) को बाँटने में सहायता देती है । पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली में वितरण की समस्या का भारी महत्त्व है, परन्तु यह निश्चय है कि मुद्रा के बिना वितरण कार्य लगभग म्रसम्भव ही रहेगा। मुद्रा की सहायता से बिना किसी कठिनाई के उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को उनके हिस्से प्रदान किये जा सकते हैं और प्रत्येक को उसकी म्रावश्यकता के म्रनुसार वस्तुए भीर सेवाए दी जा सकती है। कारण यह है कि मुद्रा सभी वस्तुम्रों की कीमत की माप का एक सामूहिक मान होती है म्रीर उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को ऐसे रूप में हिस्सा प्रदान करती है कि उसका म्रासानी से उपयोग हो सके।

(२) सीमान्त उपयोगिता और सीमान्त उत्पादकता में समान्ता लाना— मुद्रा के ग्राविष्कार से उपभोक्ताओं श्रीर उत्पादकों दोनों ही को बड़ा लाभ हुसा है। मुद्रा के उपयोग के कारणा- उपभोक्ता को यह अवसर मिला है कि वह अपने व्यय को इस प्रकार नियन्त्रित कर सके कि व्यय की प्रत्येक मद से समान् सीमान्त उपयोगिता प्राप्त करके अपने सन्तोष को अधिकतम् कर सके। इसका कारण यह है कि मुद्रा सामान्य कयः शक्ति है श्रीर उसका उपयोग किसी भी व्यस्तु को खरीदने के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार एक उत्पादक के लिए भी मुद्रा बड़ी लाभदायक है। उत्पादन को लाभदायक बनाने के लिए यह श्रावश्यक है कि उत्पाद के विभिन्न साधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाय कि प्रत्येक की सीमान्त उत्पादकता समान हो रहे मर्थात् प्रत्येक की म्रन्तिम इकाई से समान उपज प्राप्त हो। यह कार्य भी मुद्रा द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है, क्योंकि सभी उद्योगों में प्रत्येक साधन की सीमान्त उपज मुद्रा में नापी जा सकती है।

#### (३) साख का आधार-

श्राधुनिक युग में साख के महत्त्व से सभी परिचित हैं और विनिमय विलों, बैंक नोटों तथा अन्य साख पत्रों का चलन बहुत है। सभी प्रकार की आर्थिक उन्नित् साख की समुचित व्यवस्था पर निर्भर होती है, परन्तु बैंकों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा जिस साख का निर्माण किया जाता है वह मुद्रा पर आर्थारित होती है। नकद कीषों (Cash Reserves) के ग्राधार पर ही एक बैंक अपनी साख का विस्तार कर सकती है और वंक नोटों को निकाल सकती है। प्रत्येक बेंक अपने ग्राहकों की माँग को नकदी में पूरा करने का वचन देती है और इस वचन को पूरा करने में असमर्थ रहना उसके लिए घातक होता है। ऐसी दशा में जनता का बैंक पर से विश्वास उठ जाता है और साख का आधार ही समाप्त हो जाता है। पत्र-मुद्रा के प्रति विश्वास बनाये रखने में भी वह महत्त्वपूर्ण कार्य करती है।

(४) सभी प्रकार की पूँजी तथा सभी प्रकार के धन की उत्पादक गुण प्रदान करना—

ज़ब पूँजी को मुद्रा के रूप में रखा जाता है तो उसमें द्रवता (Liquidity) और गतिशीलता (Mobility) बहुत रहती है। परिणाम यह होता है कि पूँजी के निये तथा लाभपूर्ण उपयोग प्राप्त कर लेने में आसानी होती है। इस प्रकार मुद्रा के कारण उत्पादन बढ़ता है। पूँजी को मुद्रा के कारण जो उत्पादक गुण प्राप्त हो गया है वही वास्तव में वर्तमान आर्थिक उन्नति का सबसे बड़ा कारण है। अन्य कार्य—

मुद्रा के उपरोक्त नौ कार्य महत्त्वपूर्ण हैं, परन्तु कुछ विद्वानों ने मुद्रा के कुछ श्रोर भी श्राकस्मिक कार्यों का वर्णन किया है, जो निम्न प्रकार हैं :—

### (४) शोधन समता की गारन्टी-

मुद्रा का यह कार्य भी श्राष्ठ्रनिक युग में ही महत्त्वपूर्ण हुन्ना है। एक फर्म उसी समय दिवालिया हो जाती है जब वह अपने उत्तरदायित्व को मुद्रा में चुकाने में असमर्थ हो जाती है, यद्यपि यह सम्भव है कि उस समय भी फर्म की लेन उसकी देन से बहुत श्रिषक हो। भिविष्य में भुगतान करने का प्रत्येक वचन मुद्रा में भुगतान करने से सम्बन्धित होता है। स्त्रतः स्त्रपनी शोधन-दामता (Solvency) को बनाये रखने के लिए प्रत्येक व्यावसायिक फर्म तरल मुद्रा के रूप में कुन्न न कुन्न जमा स्त्रवस्य रखती है। ठीक इसी प्रकार देशों की सरकारों, बेंकों तथा व्यक्तियों को भी मुद्रा जमा करके शोधन-क्षमता बनाये रखने की आवश्यकता पड़ती है

#### (६) तरल सम्पत्ति के रूप में—

इस मुद्रा के कार्य को कीन्ज ने प्रधिक महत्त्व दिया है। यह कहा जाता है कि मुद्रा व्यवसायों की सबसे तरल सम्पत्ति (Liquid asset) है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, क्योंकि समाज के सभी सदस्य इसे पाने का प्रयत्त करते हैं। साधारणतया किसी व्यावसायिक फर्म के श्राय प्राप्त करने का समय निश्चित होता है, परन्तु खर्च की ग्रावश्यकता हर समय पड़ती रहती है। एक किसान को साधारणतया वर्ष में केवल दो बार ग्रर्थात् फसलों के तैयार होने पर ग्राय प्राप्त होती है, परन्तु व्यय साल भर बराबर होता रहता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा फर्म प्राप्त क्याः शक्ति के एक भाग को जमा करके ग्रपने पास रखता है, जिससे कि उसे ग्रावश्यकता के समय व्यय करने में कठिनाई न हो। इस काम के लिए मुद्रा सबसे उपयुक्त है क्योंकि एक ग्रोर तो इसमें टिकाऊपन तथा मूल्य की स्थिरता रहती है ग्रोर दूसरी ग्रोर इसमें तरलता का भी ग्रुण है। सम्पत्तियों की तरलता बनाये रखने के लिए कयः शिक्त को मुद्रा के ही रूप में संचित किया जाता है ज्योर यह तरलता विश्वास उत्पन्न करती है।

#### (७) निर्ण्य का वाहक (Bearer of Option)—

प्रो० ग्राहम (Graham) ने मुद्रा के इस कार्य पर विशेष जोर दिया है। उनका कहना है कि मुद्रा द्वारा कयः शक्ति का जो संचय सम्भव हो जाता है उससे एक लाभ यह भी होता है कि जमा करने वाले के लिए भविष्य में यह अवसर रहता है कि भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संचित कयः शक्ति का सबसे उत्तम उपयोग कर सके। भविष्य साधारणतया अनिश्चित होता है, इसलिए ग्रारम्भ में किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए कयः शक्ति जमा करना उपयुक्त नहीं होता। यह सम्भव है कि भविष्य में उद्देश्य ही बदल जाय, परन्तु यदि संचय मुद्रा में किया जाता है तो इस सम्बन्ध में कोई किठनाई नहीं होती है, क्योंकि मुद्रा को भविष्य में कोई भी वस्तु खरीदने के लिए काम में लाया जा सकता है। सारांश—

इस प्रकार मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा द्वारा अनेक महत्त्वपूर्णं कार्यं सम्पन्न िकये जाते हैं और आर्थिक विकास के साथ-साथ इन कार्यों की संख्या और इनका महत्त्व भी बढ़ता जाता है। आधुनिक संसार को देख कर तो यही पता चलता है कि शायद बिना मुद्रा के मनुष्य का आर्थिक और सामाजिक जीवन ही सम्भव न हो पायगा। वैसे तो मुद्रा के कार्य अनेक हैं, परन्तु अर्थशास्त्र में साधारणतया मुद्रा के चार कार्यों को ही अधिक महत्त्व दिया गया है अर्थात विनिमय का माध्यम भेल्य का

कार्यों को ही अधिक महत्त्व दिया गया है, अर्थात् विनिमय का माध्यम, भूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों का मान और मूल्य का संचय । अँग्रेजी भाषा का निम्न छन्द भी इसी श्रोर संकेत करता है:—

"Money is a matter of functions four: A medium, a measure, a standard, a store."

#### मुद्रा का महत्त्व

वर्तमान युग को 'मुद्रा का युग' कहा जाता है। इस संसार का जीवन-रक्त मुद्रा ही है। यदि संसार की तुलना एक विशाल मशीन से दी जाये तो यह कहना अनुचित न होगा कि जिस तेल से यह मशीन चालू है वह मुद्रा ही है। मुद्रा के बिना हमारा सामाजिक, आधिक अथवा राजनैतिक जीवन समुचित रूप में नहीं चल सकता है। आधुनिक संसार ने अनेक बार यह अनुभव किया है कि जब कभी किसी देश की मुद्रा अणाली बिगड़ जाती है तो उस देश का आर्थिक तथा सामाजिक जीवन ही नहीं, वरन् राजनैतिक जीवन भी चौपट हो जाता है और देश अवनित की ओर जाने लगता है। प्रत्येक देश यथासम्भव यही प्रयत्न करता है कि अपनी मुद्रा-प्रणाली को नियन्त्रित तथा व्यवस्थित रखे, क्योंकि इससे देश में सन्तोष और उन्नति के लिए अनुकूल दशायें उत्पन्न होती हैं। इसी उद्देश्य से लगभग सभी देश अपनी-अपनी मुद्रा व्यवस्था में उचित फेर-बदल करते रहते हैं।

वैसे भी यदि हम ग्रपने चारों ग्रोर दृष्टि डालें तो हमें प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ कार्य करता हुग्रा दिखाई देता है। कोई सड़क बनाता है, तो कोई कॉलिज में पढ़ता है, तो कोई दफ्तर में काम करता है, तो कोई दिन भर हथौड़ा चलाता है। यदि इन सब व्यक्तियों से पूछा जाय कि वे इस प्रकार दिन भर किस लिए जी तोड़ परिश्रम करते हैं तो उत्तर केवल यही होगा कि वे इस प्रकार काम करके रुपया कमाते हैं। दूसरे शब्दों में, उनका उद्देश्य मुद्रा प्राप्त करना है। मुद्रा का इतना ग्रधिक महत्त्व इस कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकतायों हुआ करती हैं, जिनका पूरा करना या तो उसके लिए आवश्यक होता है या उनको पूरा करने से उसे सुख मिलता है। मुद्रा आवश्यकता पूर्ति का सबसे उपयुक्त साधन है, क्योंकि मुद्रा द्वारा विनिमय का कार्य बड़ी ग्रासानी से किया जा सकता है। संसार की प्रत्येक वस्तु मुद्रा के बदले में प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान समाज में मुद्रा ही सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्रदान करती है। जिसके पास मुद्रा है उसे संसार के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में संसार का मुद्रा के पीछे दीवाना होना उचित ही दिखाई पड़ता है।

मुद्रा के गुण-

वर्तमान संसार में मुद्रा का महत्त्व ग्रथवा उसके लाभ निम्न प्रकार हैं:—
(१) मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों श्रोर श्रर्थ-विज्ञान चक्कर लगाता है—

पीग्र (Pigou) के अनुसार अर्थशास्त्र में प्रत्येक काम, घटना अथवा वस्तु को नापने का एकमात्र माप-दंड मुद्रा ही है। स्मरण रहे कि पीग्र का दृष्टिकोण व्यावहारिक है। यदि इस प्रकार के माप-दंड का उपयोग न किया जाय तो अर्थ-विज्ञान में न तो किसी प्रकार की निश्चितता ही आ सकती है और न किसी भी बात का ठीक-ठीक पता ही लगाया जा सकता है। विनिमय को सरल बना देने के कारण मुद्रा कला-कौशल, साहित्य. विज्ञान तथा उद्योग सभी के विकास में सहायक होती हैं। हम अपनी

उत्पादित वस्तुग्रों को मुद्रा में ही बेचते हैं ग्रीर ग्रपनी ग्रावश्यकता की सभी वस्तुएँ भी मुद्रा द्वारा ही खरीदते हैं। इसी प्रकार दूसरों की सेवाग्रों का मुल्य हम मुद्रा में चुकाते हैं ग्रीर ग्रपनी सेवाग्रों को भी मुद्रा में बेचते हैं। उधार का कार्य, व्यापार, वाणिज्य तथा, श्रम-विभाजन सभी मुद्रा के कारण सम्भव होते हैं। बिना मुद्रा के न तो सम्मिलित पूँजी कम्पनियाँ बन सकती हैं ग्रीर न सरकार ही ग्रपने कार्य को चला सकती हैं। सारांश यह है कि मनुष्य की सभी कियाग्रों का केन्द्र-बिन्दु मुद्रा ही है।

## (२) मुद्रा समाज की उन्नति का सूचक होती है-

जिस प्रकार किसी भी पुस्तक को पढ़ने और यह समभने के लिये कि उस पुस्तक में क्या चीज कहाँ पाई जायगी, उस पुस्तक की सन्दर्भ सूची (Index) हमारे लिये बहुत उपयोगी होती है, उसी प्रकार मुद्रा हमें किसी देश की आर्थिक प्रगृति समभने में भारी सहायता देती है। मानव विकास के इतिहास की प्रगृति मुद्रा के साथ ही सम्बन्धित है। इस संसार की जिटल आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने और उसकी स्थिरता को कायम रखने के लिये मुद्रा एक महत्त्वपूर्ण साधन है। यह समाज की उन्नित की सूचक होती है और सम्यता के विकास का सबसे बड़ा लक्ष्मण है। प्रचलित मुद्रा के रूप तथा मुद्रा की प्रगृति की स्थित को देखकर हम सरलतापूर्वक देश की आर्थिक उन्नित का पता लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं, वैसे-वैसे मुद्रा-प्रणाली में भी उसके अनुसार परिवर्तन होते जाते हैं।

## (३) पूँ जीवादी अर्थ व्यवस्था का आधार-

प्रत्येक स्माज में विशिधिकरण (Specialisation) तथा विनिमय सुविधा की सहायता से धन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, परन्तु इस विशिधिकरण के लिए श्रम विभाजन ग्रावश्यक होता है, जो विनिमय-विकास के बिना उन्नति नहीं कर सकता है, इसलिए मुद्रा का उपयोग बहुत ग्रावश्यक होता है। पूँजीवादी ग्रर्थ-व्यवस्था मुद्रा पर ही ग्राधारित है। ग्रुत्यधिक विशिधोकरण, व्यापार की उन्नति, वािण्ज्य और उद्योग तथा समस्त विनिमय प्रणाली मुद्रा पर ही निर्भर है।

## (४) मुद्रा वस्तु-विनिमय प्रणाली के सभी दोषों को दूर कर देती है—

इसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकताओं के पारस्परिक मिलान की आवश्यकता नहीं पड़ती, मुल्य की एक सामान्य तथा सामृहिक माप आसानी से हो जाती है, अविभाजीय वस्तुओं के विनिमय में कोई असुविधा नहीं होती है, किसी भी वस्तु के बदले में अन्य कोई वस्तु खरीदने में कठिनाई नहीं होती है और बिना किसी कठिनाई के मूल्य का संचय किया जा सकता है।

## (प्.) मुद्रा पूँजी को गतिशीलता ( Mobility ) प्रदान करती है—

इस गतिशीलता के अनेक लाभ हैं। गतिशीलता से आर्थिक विकास की नींव हढ़ होती है और सभी स्थानों तथा सभी प्रकार के उद्योगों के विकास की सम्भावना पैदा होती है। इसके अतिरिक्त मुद्रा-प्रगाली का विकास धन को थोडे से व्यक्तियों के पास केन्द्रित करने की प्रवृत्ति रखता है। इससे बचत को प्रोत्साहन मिलता है श्रीर बचत के एक बड़े श्रंश को पूँजी के रूप में उपयोग होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे श्रार्थिक जीवन उन्नत होता है। श्राधुनिक युग में रेलों, जल-मार्गी, गोदामों तथा विशालकाय उद्योगों का विकास मुद्रा का ही चमत्कार है।

## (६) मुद्रा सामाजिक स्वतन्त्रता प्रदान करती है-

जिस काल में मुद्रा का विकास नहीं हुया था और सभी प्रकार के भुगतान वस्तुओं और सेवाओं मे किये जाते थे तो श्रमिकों को पूरी तरह से भनी बगों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपनी इच्छानुसार स्थान तथा व्यवसाय का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। मुद्रा के उपयोग ने इस वर्ग को गतिशीलता तथा सामाजिक स्वतन्त्रता प्रदान की है और दासता की बेडियों को तोड़ दिया है।

## (७) मुद्रा ने राजनैतिक स्वतन्त्रता को भी बढ़ावा दिया है—

जब कर मुद्रा में चुकाये जाते हैं तो करदाता यह अनुभव करता है कि उसकी जेब से रुपया निकल रहा है। इससे करदाताओं में राजनैतिक जाग्रति ग्राती है। वे राज्य के संचालन-कार्य में ग्रधिक दिलचस्पी लेते हैं। इस प्रकार राजनैतिक स्वतन्त्रता की उन्नति होती है।

## (=) मुद्रा पृथकस्व को भङ्ग करती है-

विनिमय की सुविधा होने के कारण व्यापार की उन्नति होती है श्रीर मनुष्यों का पारस्परिक सम्पर्क बढ़ता है। पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ जाती है, जिसके कारण श्राधिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय मेल-मिलाप बढ़ता है।

## ( ह ) वर्तमान भौतिक सभ्यता का आधार-

यह स्पष्ट है कि हमारी वर्तमान भौतिक उन्नित का सबसे बड़ा कारण मुद्रा का विकास ही है। भौतिक सभ्यता के विकास में मुद्रा का महत्त्व बहुत ग्रधिक है। निष्कर्ष—

सारांश यह है कि आधुनिक संसार में मुद्रा का महत्त्व बहुत अधिक है। सामान्य रूप में मुद्रा ने आवश्यकताओं के प्रत्यक्ष और परोक्ष सन्तोष, अम-विभाजन, पूँजी तथा अम की गतिशीलता तथा उत्पत्ति के साधनों के संग्रह करने में सहायता दी है। मुद्रा का महत्त्व इससे भी स्पष्ट होता है कि मुद्रा प्रगाली की प्रत्येक गड़-बड़ का देश की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ता है। मुद्रा-प्रसार (Inflation) तथा अवसाद (Depression) के गम्भीर परिगामों से आज का संसार भली-भाँति परिचित है। पूँजीवादी प्रगाली की तो जान ही मुद्रा है और समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में भी कम से कम लेखे की इकाई (Unit of Account) के रूप में मुद्रा का उपयोग आवश्यक है। एक सुसंगठित समाज के लिए मुद्रा आवश्यक है। उपभोक्ताओं के हिण्डकोग से मुद्रा का महत्त्व इसलिए है कि मुद्रा का उपयोग उन्हें अपना निर्ग्य सूचित करने

श्रौर उसी के श्रनुसार वस्तृयें श्रौर सेवायें खरीदने में सहायता देता है। उत्पादक के हिष्टकोगा से भी यह लाभदायक है, क्चोंकि इससे उसे उत्पत्ति के साधनों को जुटाने, कचा माल खरीदने श्रौर पूँजी प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

मुद्रा के दोष-

- (I) मुद्रा के नैतिक दोष—साधारण बोलचाल में बहुषा ऐसा कही जाता है कि 'संसार की सभी बुराइयों की जड़ मुद्रा है।' यह मनुष्य में लालच तथा मोह उत्पच करके शोषण की प्रवृत्ति को जन्म देती है ज्ञौर मनुष्य को धोखेबाजी, बेईमानी तथा पाप के मार्ग पर ले जाती है। मुद्रा के पीछे चोरी, डकैती ग्रौर हत्या का होना एक साधारण सी घटना है। मानव समाज के पारस्परिक प्रेम को यह गहरी चोट पहुँचाती है। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि मुद्रा मनुष्य के लिए एक ग्रभिशाप बन गई है। इस सम्बन्ध में हमें याद रखना चाहिए कि ये दोष यथार्थ में मुद्रा के दोष नहीं हैं, बिलक मनुष्य के स्वभाव के दोष हैं। मुद्रा का ग्राविष्कार विनिमय की सुविधा के लिए हुग्रा था, ग्रतएव मुद्रा प्राप्त करने का उद्देश्य वास्तव में वस्तुए ग्रौर सेवाए प्राप्त करना होना चाहिए, जो मुद्रा की सहायता से ग्रासानी से प्राप्त की जा सकती हैं, परन्तु मनुष्य इस उद्देश्य को भूल जाता है ग्रौर मुद्रा-प्राप्ति स्वयं ग्रपना उद्देश्य बन जाती है। सारी बुराइयों की जड़ यही है, परन्तु मानव स्वभाव को देखते हुए इस बुराई को रोकना भी मुश्कल है।
- (II) मुद्रा के म्राधिक दोष—म्रार्थिक दृष्टिकोण से भी मुद्रा के त्रानेक दोष हैं:—
- मुद्रा उवार लेने तथा उचार देने की क्रियाओं को सरल बना देती है, जिसका परिगाम यह होता है कि उधार लेने की आदत को प्रोत्साहन मिलता है अग्रेर समाज में अपव्यय बढ़ता है। इसके अतिरिक्त उद्योग तथा व्यवसाय में यह प्रवृत्ति अति-पूँ जियन (Over-capitalisation) तथा अति-उत्पादन (Over-production) को बढ़ाती है, जिनके कारण समाज और अर्थ-व्यवस्था को भारी हानि पहुँचती है।
- (२) मुद्रा के मूल्य में स्थिरता नहीं रहती है। बीसवीं शताब्दी का अनुभव बराबर यही रहा है कि मुद्रा के मूल्य और कीमतों में बराबर परिवर्तन होते रहते हैं। मुद्रा के मूल्य के इन परिवर्तनों का समाज के विभिन्न वर्गों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है और कभी-कभी तो यह समाज के लिए घातक होता है। इन परिवर्तनों के कारएा आधिक जीवन में अनिध्वितता पैदा हो जाती है। जो व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योग की उन्नित के लिए अनुपयुक्त होती है।
- (३) मुद्रा के उपयोग ने ही पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली को जन्म दिया है। इस प्रणाली के ग्रन्तर्गत, उत्पत्ति के साधन केवल थोड़े से व्यक्तियों के पास इकट्ठे हो जाते हैं ग्रौर जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ता है, वैसे-वैसे धनी वर्ग ग्रौर ग्रधिक धनी

होता जाता है तथा निर्धन वर्ग की निर्धनता बढ़ती जाती है। इस प्रकार समाज में आय के वितरण की घोर असमानताएँ उत्पन्न होती जाती हैं, जिनके कारण सामाजिक तथा राजनैतिक असन्तोष बढ़ता है और कान्ति तथा आन्तिरक उपद्रव प्रोत्साहित होते हैं। अमिकों को तो विशेष हानि होती है। वर्तमान मजदूरी प्रणाली के सभी दोष एक प्रकार मुद्रा की ही देन हैं। बेरोजगारी तथा व्यापार चक (Business Cycles), जिन्होंने पूँजीवादी संसार में स्नातंक मचा रखा है, इसी के परिणाम हैं।

(४) मुद्रा मानव त्याग तथा सन्तोप की वास्तविक माप नहीं होती है। मुद्रा ऋौर कयः शिक्त एक ही चीज के दो नाम नहीं हैं। मुद्रा के पास में होते हुए भी यह ग्रावश्यक नहीं है कि एक मनुष्य उसके बदले वस्तुएँ ग्रौर सेवाएँ खरीद सके। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् मुद्रा-प्रसार के कारण जर्मनी में ऐसी स्थित उत्पन्न हो गई थी कि मुद्रा के बदले में कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता था।

(५) मुद्रा स्वयं सर्व शाकिमान बन जाती हैं। मुद्रा के मनुष्य का दास बनने के स्थान पर स्वयं मनुष्य मुद्रा का दास बनकर रह जाता है, जिससे मनुष्य का भारी पतन हो जाता है।

#### क्या इन दोषों के होते हुए भी मुद्रा का उपयोग करना चाहिए ?—

उपरोक्त दोषों को देखने के पश्चात् इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक ही है कि इतने दोषों के रहते हुए भी क्या हमें मुद्रा का उपयोग करना ही चाहिए ? क्या हम बिना मुद्रा के काम नहीं चला सकते हैं। याद रहे कि मुद्रा का परित्याग करने का ग्रर्थ केवल यही होता है कि हम फिर से वस्तु-विनिमय प्रणाली पर उतर ग्राएँ। म्राधुनिक युग में यह सफल हो सकेगी या नहीं, इसके सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ कहना कठिन है। जहाँ तक पूँ जीवादी ऋर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है, शायद बिना मुद्रा के काम न चल सके, क्योंकि वस्तु-विनिमय की कठिनाइयाँ काफी गम्मीर हैं, परन्तु नियन्त्रित त्र्रर्थ-व्यवस्था में वस्तु-विनिमय प्रणाली एक बड़े ऋंश तक सफल हो सकती है। समाजवादी रूस में ऋौर मुख्यतया चीन में इस समय भी इसका काफी महत्त्व है, परन्तु उपरोक्त देशों में भी वस्तु-विनिमय प्रणाली का उपयोग एक सीमित श्रंश तक ही किया गया है। चीन में वस्तु-विनिमय तथा मुद्रा-विनिमय एक दूसरे के विकल्प (Alternative) के रूप में प्रचलित हैं। समाजवादी देश भी मुद्रा के उपयोग के लाभों को भली भाँति समभते हैं ग्रीर मुद्रा का पूर्णतया परित्याग नहीं करते हैं। कम से कम लेखे की इकाई के रूप में तो इनके लिए भी मुद्रा का उपयोग श्रावश्यक है। सुद्रा के गुर्गों तथा दाषों की तुलना करने से भी यही पता चलता है कि दोषों की ऋपेद्मा लाभ ऋधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

### समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा का महत्त्व-

उपरोक्त विवेचन में हमने एक स्वतन्त्र ग्रथं व्यवस्था के दृष्टिकोगा से मुद्रा के महत्त्व पर प्रकाश डाखा है। कुछं विद्वानों का कहना है कि एक समाजवादी ग्रर्थ-

tender Money) भी सम्मिलित होती है। उपरोक्त स्पष्टीकरण से यह सिद्ध हो जाता है, यद्यपि सभी चलन मुद्रेष होता हैं, प्रन्तु सभी मुद्रा को चलन नहीं कहा जा सकता।

प्रो॰ रीड (Reed) के अनुसार—''मुद्रा एक दायित्त्व (देन) की द्रियिक कीमत को सूचित करती है, परन्तु चलन इस दायित्त्व को चुकाने का केवल एक साधन है। वास्तविकता यह है कि किसी देश की मुद्रा का केवल एक निश्चित भाग ही चलन होता है। मुद्रा की उन सब इकाइयों को चलन का नाम दिया जाता है जो विधानानुसार देश में मुद्रा के रूप में चालू होती हैं। कोई भी व्यक्ति इनमें सुगतान स्वीकार करने से इन्कार नहीं कर सकता। बहुधा सरकार की छोर से चलन में मुगतान न करने वालों के लिये दराड रखा जाता है।''

#### QUESTIONS

1. "Money is what money does." Explain this statement and briefly define money.

(Patna, 1953; Agra, B. Com., 1956 and 1949)

- द्रव्य की परिभाषा कीजिए श्रोर समक्ताइये कि द्रव्य तथा श्रन्य वस्तुश्रों में क्या श्रन्तर है। द्रव्य का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए।
  - (Agra, B.A., 1956 and 1958; Raj., B.A., 1954; Alld., B.A., 1956)
- 3. What do you understand by the term 'Money'? Explain the nature of the various forms of money circulating in India. (Agra, B. Com., 1957 Supp. and 1956 Supp.)
- 4. 'Money is what money does.' Explain fully the meaning of this statement. What will happen if money suddenly disappears from the country? (Agra, B. Com., 1956)
- 5. Define money critically. Discuss the importance of money as a liquid asset. (Agra. B. Com., 1951; Raj., B. Com., 1948)
- Money is a matter of functions four.

  A medium, A measure, A standard, A store.

  Explain fully the meaning of this statement.

(Agra, B. Com., 1958)

- 7. Explain the difference between-medium of exchange and a measure of value. (Agra, B. Com., 1955)
- 8. 'Money which is a source of many blessings to mankind

becomes also, unless we control it, a source of confusion and peril.' Comment. (Raj., B. Com., 1957)

- 9. What have been the economic effects of money? Discuss. (Raj., B. A., 1958)
- 10. ''मुद्रा एक श्रच्छा सेवक है, किन्तु बुरा स्वामी हैं।'' व्याख्या कीजिए। (Sagar, B. A., 1957)
- 11. मुद्रा का मानव जाति के आर्थिक विकास में क्या स्थान रहा है। इस पर प्रकाश डालिए और बतलाइये कि क्या अब मुद्रा की आवश्यकता समाप्त हो गई है? (Sagar, B. Com., 1954)
- 12. In what ways does money affect the economic system? Do you hold that money should have intrinsic value?

  [(Patna, B. A., 1957)]
- 13. Define 'money' critically and explain its nature carefully.
  मुद्रा की श्रालोचनात्मक परिभाषा करिये तथा उसकी प्रकृति सममाइये।
  (Agra, B. Com., 1959)
- 14. Discuss the role of money in the modern economic system.
  (Aligarh, 1956)
- 15. Critically discuss the functions said to be performed by money.

  Does money really perform all of them and can money alone perform them?

  (Raj., B. Com., 1956)
- 16. What have been the economic effects of money? Discuss. (Raj., B. A., 1958)

#### अध्याय ३

## मुद्रा का वर्गीकरण

(The Classification of Money)

विभिन्न लेखकों ने मुद्रा के वर्गीकरण की म्रलग-म्रलग रीतियाँ म्रपनाई हैं। प्रमुख वर्गी-करण निम्न प्रकार हैं: —

(I) वास्तिविक मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा (Actual Money and Money of Account)—

वास्तविक मुद्रा से हमारा अभिप्राय उस मुद्रा है होता है जिसका यथार्थ में देश के भीतर प्रचलन (Circulation) होता है। हिसाब की मुद्रा का प्रचलन नहीं होता है, परन्तु ऋगों, आदेयों तथा लेन-देन का हिसाब उसी में रखा जाता है। कीन्ज ने इन दो प्रकार की मुद्राञ्चों को मुख्य मुद्रा (Money Proper) तथा लेखे की मुद्रा (Money of Account) का नाम दिया है। प्रो॰ सैलिंगमैन (Seligman) ने इन्हें वास्तविक मुद्रा तथा आदर्श मुद्रा (Ideal Money) में विभाजित किया है और इसी प्रकार बेनहाम (Benham) ने इन्हें चलन की इकाई (Unit of Currency) तथा लेखे की इकाई (Unit of Account) बताया है।

वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय में वास्तिवक मुद्रा ही विनिमय माध्यम का कार्यं करती है। सभी प्रकार के भुगतान इसी मुद्रा में किये जाते हैं और इसी के रूप में क्रयः शक्ति का संचय किया जाता है। वास्तिवक मुद्रा और प्रचलित चलन (Currency) में कोई अन्तर नहीं होता। जितने भी प्रकार की मुद्रा प्रचलन में होती है वह सब की सब वास्तिवक मुद्रा होती है। भारत में १ पैसे से लेकर १ रूपये तक के जितने सिक्के हैं और १ रु० के नोट से लेकर १,००० रु० तक के जितने नोट हैं, वे सभी वास्तिवक मुद्रा हैं। हिसाब की मुद्रा से हमारा अभिप्राय उस मुद्रा से होता है जिसमें अप्टर्णों की मात्रा, कीमतें तथा क्रयः शिक्त को सूचित किया जाता है और जिसमें अप्टर्णों की मात्रा, कीमतें तथा क्रयः शिक्त को सूचित किया जाता है की ऐसी मुद्रा का वास्तव में प्रचलन हो ही। पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि एसी मुद्रा का वास्तव में प्रचलन हो ही। पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि सन् १६२३ में जर्मनी में मार्क चलन के रूप में प्रचलित था, परन्तु हिसाब की मुद्रा फें क अथवा डालर होती थी। इसी प्रकार अमरीका में सन् १६३३ तक हिसाब की मुद्रा स्वर्ण डालर था, यद्यपि प्रचलन केवल कागज के नोटों तथा गिलट और तांबे के सिक्कों का ही था। भारत में सभी प्रकार का हिसाब रुपये, आने और पाई में रखा

जाता रहा है यद्यपि पाई नाम के सिक्के का प्रचलन कभी का समाप्त हो चुका है। ठीक इसी प्रकार इङ्गलैण्ड में सोने का पौंड लेखे की इकाई है, यद्यपि काफी लम्बे काल से इस सिक्के का चलन मिट चुका है।

वास्तविकता यह है कि हिसाब की मुद्रा प्रचलित मुद्रा का सैंद्धान्तिक रूप है श्रीर वास्तविक मुद्रा उसका व्यावहारिक रूप है। यह सम्भव है कि व्यावहारिक जीवन में मुद्रा का रूप बदल जाय, परन्तु हिसाब-किताब के लिए उसका पुराना ही रूप बना रहे श्रीर इस प्रकार प्रचलित तथा हिसाबी रूप में श्रन्तर हो जाय, जिसके कारण वास्तविक श्रीर हिसाब की मुद्राएँ श्रलग-श्रलग हो जाती हैं।

कुछ लेखकों \* ने वास्तविक मुद्रा को भी दो और भागों में विभाजित किया

है—(अ) पदार्थ-मुद्रा (Commodity Money) तथा (ब) प्रतिनिधि मुद्रा (Representative Money) । पदाथ मुद्रा को ही कभी-कभी पूर्णकाय मुद्रा (Full-bodied Money) भी कहा जाता है । पदार्थ मुद्रा किसी न किसी धातु की बनी होती है और सिक्के पर लिखी हुई कीमत सिक्के की निहित कीमत अथवा उसके धातु-मूल्य के बराबर होती हैं । ऐसी मुद्रा में यह ग्रुग होता है कि इसे विनिमय-माध्यम के रूप में तो उपयोग किया जाता ही है, परन्तु साथ ही साथ मूल्य का संचय भी इसी में किया जाता है । इस मुद्रा का धातु के रूप में उतना ही मूल्य होता है जितना कि मुद्रा के रूप में ।

प्रतिनिधि मुद्रा वह है जिसका प्रचलन तो होता है और विनियय माध्यम के रूप में भी उपयोग किया जाता है, परन्तु उसमें मूल्य का संचय नहीं किया जाता। ऐसी मुद्रा को पदार्थ-मुद्रा में बदलने की सुविधा दी जाती है। इस कारण यद्यपि यह मुद्रा स्वयं मूल्य के संचय का कोर्य नहीं करती है, परन्तु मूल्य का सूचक प्रथवा प्रतिनिधि होती है, क्योंकि भ्रावश्यकता पड़ने पर इसे पदार्थ मुद्रा में बदला जा

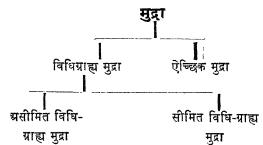
सकता है। सभी प्रकार की पत्र-मुद्रा प्रतिनिधि मुद्रा ही होती है। मूल्य के संवय के लिए उसे प्रक्षर धातु-मुद्रा में बदल लिया जाता है।

(II) विधि-ग्राह्म मुद्रा तथा ऐच्छिक मुद्रा (Legal tender money and Optional Money)—

विधि-प्राह्म मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे भुगतान के साधन के रूप में

Keynes—A Treatise on Mon ey, Vol. 1, p. 3.

सरकार तथा विद्यान द्वारा स्वीकार किया जाता है । इस मुद्रा में सभी प्रकार का भूगतान किया जा सकता है. चाहे वह वस्तुयों ग्रौर सेवाग्रों का मूल्य चुकाने से सम्बन्धित हो भ्रथवा ऋगों का भुगतान करने से । विघान के भ्रनुसार कोई भी व्यक्ति इस मुद्रा में भुगतान लेने ने इन्कार नहीं कर सकता है। इन्कार करने वालों को बहुधा सरकार द्वारा दण्ड दिया जाता है, क्योंकि यह मुद्रा सरकार द्वारा घोषित मुद्रा होती है। ऐसी मुद्रा की स्वीकृति वैघानिक हृष्ट्रि से अनिवार्य होती है। इसके विपरीत ऐन्छिक मुद्रा वह मुद्रा होती हैं जिसे वैसे तो सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है परन्तू कानूनन उसको स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होता । प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार होता है कि वह इसमें भगतान स्वीकार कर ले ग्रथवा इन्कार कर दे। साधाररातया जब ऐसी मुद्रा को स्वीकार किया जाता है तो देने वाले की साख देख ली जाती है, इसलिए ऐसी मुद्रा की स्वीकृति चुकाने वाले के विश्वास पर निर्भर होती है। यदि लेने वाले को देने वाले की साख में विश्वास नहीं है तो वह इसमें भुगतान स्वीकार नहीं करेगा। एक देश में लगभग सभी प्रकार का चलन विधिग्राह्य होता है, परन्तु चैक, बैंक-नोट, विनिमय विल, प्रतिज्ञा-पत्र (Promissory Notes), हुण्डी ग्रादि ऐच्छिक मुद्राएँ हैं । इन्हें विश्वास के कारएा स्वीकार किया जाता है । विश्वास का स्रभाव होते ही नेने से इनकार कर दिया जाता है।

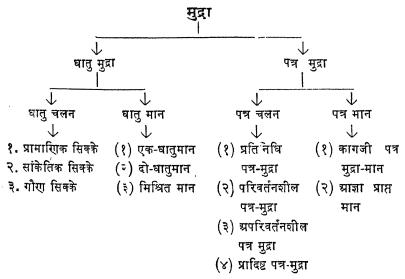


विधि-प्राह्म सुद्रा भी दो प्रकार की होती है—(१) ग्रसीसित विध-ग्राह्म सुद्रा (Unlimited Legal-Tender Money) तथा (२) सीमित विधि-ग्राह्म सुद्रा (Limited Legal-Tender Money)। यदि किसी सुद्रा के विषय में सरकार द्वारा यह नियम बना दिया जाता है कि उसमें मुगतान लेना अनिवार्य है, चाहे मुगतान की मात्रा कितनी हो क्यों न हो तो ऐसी सुद्रा को असीमित विधि-ग्राह्म सुद्रा कहा जाता है। भारत में एक रुपये और ग्रठकी के सिकके तथा सभी कीमतों के कागजी नोट ग्रसीमित विधि-ग्राह्म हैं। सीमित विधि-ग्राह्म सुद्रा वह सुद्रा होती है जिसकी अनिवार्य स्वीकृति की सरकार द्वारा सीमा निश्चित कर दी जाती है। एक निश्चित कीमत की मात्रा तक इस मुद्रा में भुगतान स्वीकार करना ग्रानवार्य होता है, परन्तु इस सीमा के ऊपर भुगतान स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। स्वीकार करना या न करना भुगतान पाने वाले की

इच्छा पर निर्भर होता है। भारत में चबन्नी तथा दुग्रन्नी के सिक्के १० रुपये तक विधि-ग्राह्य हैं। दो पैसे तथा एक पैसे के सिक्के केवल १ रुपये तक ही विधि-ग्राह्य हैं। इससे ऊपर की रकम का भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है, यद्यपि व्यावहारिक जीवन मे ऐसा बहुधा देखने में भ्राता है कि लोग इन सिक्कों में भी श्रिधिक मुक्त्या में भुगतान स्वीकार कर लेते हैं।

### श्रातु-मुद्रा तथा पत्र-मुद्रा (Metallic Money and Paper Money)—

मुद्रा का वर्गीकरण उस पदार्थ के ग्राघार पर भी किया जाता है जिसकी वह बनी हुई होती है। इस दृष्टिकोण से मुद्रा दो प्रकार की होती है: घातु मुद्रा तथा पत्र-मुद्रा। यद्यपि घातु तथा कागज के ग्रतिरिक्त ग्रन्य पदार्थ भी मुद्रा के रूप में उपयोग किये जाते हैं ग्रीर भूतकाल में किये गये हैं, परन्तु ग्राघुनिक युग में ग्रधिकांश चलन इन दोनों का ही है। घातु-मुद्रा से श्रमिप्राय उस मुद्रा का है जो किसी घातु की बनी हुई हो। इसे टंक या सिक्का (Coin) भी कहते हैं। पत्र-मुद्रा से श्रमिप्राय उस मुद्रा का है जो किसी सरकार या श्रिष्ठित संस्था के विशेष चिन्हों द्वारा (मागने पर निश्चित संस्था में धातु-मुद्रा देने के लिखित वायदे सहित या इसके बिना) कागज पर छापी गई हो।



भारत में दोनों ही प्रकार की मुद्रा प्रचलित हैं। घानु-मुद्रा एक रुपये, ग्रठकी, चवकी, दुग्रकी, इककी, दो पैसा तथा पैसे के रूप में पाई जाती है ग्रौर पत्र मुद्रा एक-रुपया, दो-रुपया, पाँच-रुपया, दस-रुपया तथा सौ-रुपया के नोटों के रूप में प्रचलित है। प्रथम अप्रैल सन् १६५७ से १, २, ५ ग्रौर १० पैसे ग्रौर १ रुपये की घानु-मुद्रा भी पुरानी घानु-मुद्रा के साथ चालू है। भूतकाल में देश में प्रचलित मुद्रा साधारए।तथा

सोने श्रौर चांदी के सिक्कों की होती थी। तुच्छ घातुश्रों, जैसे—गिलट, तांबा श्रादि के सिक्के केवल खेरीज की श्रावश्यकता को पूरा करते थे, परन्तु श्राधुनिक संसार में अविकाँग मुद्रा पत्र-मुद्रा श्रौर छोटी कीमत के तुच्छ घातुश्रों के सिक्कों के रूप में होती है।

धातु-मुद्रा को भी दो बड़े-बड़े भागों में बाँटा जाता है,:—(१) धातु-चलन (Metallic Currency) तथा (२) धातुमान (Metallic Standard)। धातु-चलन से हमारा अभिप्राय धातु के उन सिकों से होता है जिनका वस्तुओं और सेवाओं के कय-विकय में एक व्यक्ति से दूसरे के पास हस्तान्तरण होता रहता है। ये सिक्के वित्तमय-माध्यम के रूप में देश में चालू रहते हैं। धातु-मान से हमारा अभिप्राय उस धातु से होता है जो देश में मूल्य को नापने के लिए उपयोग की जाती है, ग्रर्थात् जिस वस्तु में अन्य सभी धातुओं और सेवाओं की कीमत आंकी जाती है।

इसी प्रकार पत्र-मुद्रा को भी दो भागों में बाँटा जाता है:—(१) कागजी नोट तथा (२) कागजी मान । जो कागजी मुद्रा विनिमय-माध्यम के रूप में चालू होती है उसे कागजी नोट कहते हैं। कागजी मान से हमास ऋभिप्राय एक ऐसे मुद्रा-मान (Monetary Standard) से होता है जिसमें किसी धातु को कीमतों के सामूहिक मापक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि कागजी मुद्रा में ही वस्तुत्रों श्रोर सेवाश्रों की कीमतें नापी जाती हैं। ग्राधुनिक अर्थभास्त्र में पत्र मुद्रा का एक ब्रोर भी रूप प्रचलित है, जिसे हम साख-मुद्रा (Credit Money) श्रथवा बेंक-मुद्रा का नाम देते हैं। इस प्रकार की मुद्रा साधारणतया बेंकों द्वारा उत्पन्न की जाती है श्रीर ऐन्छिक मुद्रा होती है। चैंक, हुण्डियां, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा-पत्र श्रादि इसके ग्रच्छे उदाहरण हैं। श्राधुनिक संसार में इनका भी चलन बहुत है।

### धातु चलन के रूप (The Forms of Metallic Currency)—

सभी प्रकार का घातु-चलन विधि-ग्राह्य होता है। ग्रन्तर केवल इतना होता है कि कुछ सिक्के ग्रसीमित विधि-ग्राह्य होते हैं और कुछ सीमित विधि-ग्राह्य। एक दूसरे दृष्टिकोएा से घातु के सिक्के तीन प्रकार के होते हैं:—

- (१) प्रामाणिक ग्रथवा पूर्णकाय सिक्के (Standard or Full-Bodied Coins)— इन सिंकों की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इन पर ग्रंकित कीमत सिक्के में लगी हुई धातु की कीमत के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में, इन सिकों की ग्रंकित कीमत निहित कीमत के बराबर होती है। यदि सिक्के को गला कर धातु के रूप में बेचा जाय तो कोई हानि नहीं होती है। ऐसे सिक्कों में चार मुख्य गुणा होते हैं:—
  - ( म्र ) म्रङ्कित मूल्य (Face Valve) निहित मूल्य म्रथवा धातु-मूल्य के बराबर होता है।

- (ब) यह सिका असीमित विधि-याह्य होता है।
- (स) इसी सिक्के में देश के भीतर सभी वस्तुश्रों ग्रौर सेवाग्रों की कीमत नापी जाती है। कीमतों की सापृहिक माप का सूचक यही सिका होता है।
- (द) इसका टङ्कन ग्रथवा इसकी ढलाई स्वतन्त्र होती है।

जब तक इङ्गलैंड में स्वर्णमान प्रगाली प्रचलित थी, ब्रिटिश सावरेन इङ्गलैंड का प्रामागिक सिका था, परन्तु सितम्बर सन् १६३१ में इङ्गलैंड ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया और तब से उस देश में कोई प्रामागिक सिक्श नहीं है।

### क्या भारतीय रुपया प्रामाणिक सिका है ?—

भारत में इस प्रकार का सिक्का लगभग कोई भी नहीं रहा है। महारानी विक्टोरिया के काल में रुपये में एक रुपये की कीमत की चाँदी रहती थी, इसलिए यह सिक्का पूर्णकाय सिक्का था। इस समय भी देश का प्रधान सिक्का रुपया ही है। इसमें असीमित विधि ग्राह्म होने का ग्रुण है और पूरे देश में इसी में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत नापी जाती है, अतएव यह देश की प्रामाणिक मुद्रा है, परन्तु भारतीय रुपया पूर्णकाय सिक्का नहीं है। घातु के रूप में इसकी कीमत ग्राङ्कित कीमत से बहुत कम होती है और इसकी ढलाई भी स्वतन्त्र नहीं है। इस प्रकार एक ज्योर तो भारतीय रुपया ग्रामाणिक सिक्का है और दूसरी और यह केवल एक सांकेतिक सिक्का है, क्योंकि धातु के रूप में रुपये की कीमत एक रुपये से बहुत कम है। यही कारण है कि कुछ लेखकों ने भारतीय रुपये को सांकेतिक मान (Token Standard) कहा है।

(२) सांकेतिक सिक्के (Token Coins)—सांकेतिक सिक्के वे सिक्के होते हैं जिनका श्रिक्कित मूल्य उनके निहित मूल्य से श्रिष्ठिक होता है। ऐसे सिक्कों में प्रामाणिक मुद्रा के विपरीत ग्रुण पाये जाते हैं:—(१) इनका धातु-मूल्य उनके मुद्रा-मूल्य से बहुत कम होता है। यही कारण है कि ऐसे सिक्कों को गलाया नहीं जाता, क्योंकि ऐसा करने से हानि होती है। (२) खेरीज (Small Change) के लिए जिन सिक्कों को रखा जाता है वे साधारणतया सांकेतिक ही होते हैं। (३) ऐसे सिक्के बहुधा सीमित विधि-ग्राह्म मुद्रा होते हैं, परन्तु भारतीय रुपये की स्थिति भिन्न है। वह सांकेतिक सिक्का होते हुए भी श्रसीमित विधि-ग्राह्म है। इन सिक्कों की ढलाई कभी भी स्वतन्त्र नहीं होती है। (४) ऐसे सिक्कों की कीमत उनके भीतर रहने वाली धातु-पर निभर नहीं होती है, बिल्क सरकारी श्रादेश द्वारा निर्धारित होती है। यही कारण है कि कुछ लेखकों ने इन्हें प्रादिष्ट सिक्के ग्रथवा प्रादिष्ट मुद्रा (Fiat Coins or Money) भी कहा है।

ऐसे सिकों की ढलाई साधारणतया दो कारूगों से की जाती है—(१) यदि सरकार के पास बहुमूल्य धातु की कमी है ऋौर मुद्रा को बढ़ाने की ग्रावश्यकता है तो वह सांकेतिक सिक्के तैयार करती हैं । इस प्रकार बहुमूल्य धातु के उपयोग में बचत हो जाती है ग्रीर घातु की थोड़ी भी मात्रा से ही ग्रधिक मुद्रा तैयार कर ली जाती है। (२) कभी-कभी जनता द्वारा सिक्कों के गलाने को रोकने के लिए भी उन्हें सांकेतिक बना दिया जाता हैं। सन् १६४० में भारतीय रुपये के सम्बन्ध मे एक भ्रजीब स्थिति पैदा हो गई थी। यद्यपि पहले से ही भारतीय रुपया एक सांकेतिक सिक्का थ' ग्रीर उसमे चाँदी की मात्रा केवल देने थी, परन्तु युद्ध-काल में चाँदी के दाम इतने चढ़ गये थे कि सन् १६४० में भारतीय रुपया एक पूर्णकाय सिक्का बन गया। जिसका परिग्णाम यह हुग्रा कि यह ग्रासंचित कोषों (Hoards) में गायब होने लगा। तुरन्त ही भारत सरकार ने इस रुपये का विमुद्रीक रण्ण कर दिया ग्रीर इसके स्थान पर नये रुपये के सिक्के चालू किए, जिनमें चाँदी की मात्रा केवल ने रखी गई। रुपया फिर सांकेतिक सिक्का बन गया। इस समय भी हमारा गिलट का रुपया एक सांकेतिक सिक्का ही है

### निष्कर्ष-

इसमें तो सन्देह नहीं है कि पूर्णकाय सिक्कों की तुलना में सांकेतिक सिक्के खराब मुद्रा होते हैं, क्योंकि इनके प्रति जनता का विश्वास उतना ऋधिक नहीं होता है जितना कि पूर्णकाय प्रामाणिक सिक्कों के प्रति, परन्तु वर्तमान संसार में ऐसे ही सिक्कों का चलन है और व्यावहारिक जीवन में इनसे कोई कठिनाई भी उत्पन्न नहीं होती हैं। कागजी मुद्रा से तो सांकेतिक सिक्के हर दशा में भ्रम्छे होते हैं, क्योंकि कागजी मुद्रा का तो लगभग कुछ भी निहित मूल्यं नहीं होता है। यदि सरकार समभदारी से काम लेती है तो इन सिक्कों पर से विश्वास उठ जाने का प्रश्न बहुत कम ही पैदा होता है।

- (३) गौरा सिक्के (Subsidiary Coins)— ऐसे सिक्कों की निकासी छोटी खेरीज की सुविधा के लिए की जाती है। इनकी प्रमुख विशेषतायें निम्न प्रकार हैं:—
  - ( ग्र ) ये साधारणतया थोडी कीमत के सिक्के होते हैं।
  - (ग्रा) इनका मुख्य कार्य कम कीमत की वस्तुत्रों श्रोर सेवाश्रों के विनिमय को सरल बनाना होता है।
  - (इ) ये सभी सिक्के सांकेतिक होते हैं।
  - (ई) इन सिक्कों का प्रामािशाक सिक्के से एक निश्चित सम्बन्ध रहता है।
  - (उ) इनकी ढलाई स्वतन्त्र नहीं होती है श्रीर इनकी निकासी सरकार द्वारा एक निश्चित मात्रा में ही की जाती है।
  - ( ऊ ) ये सिक्के सदा ही सीमित विधि-याह्य होते हैं।

भारत में चवनी, दुचानी, इकनी, दो पैसा तथा पैसा इसी प्रकार के सिक्के हैं।

### पत्र-मुद्रा के भेद

श्राधुनिक युग में लगभग सभी देशों में मुद्रा का श्रिधकांश भाग पत्र-मुद्रा के ही रूप में पाया जाता है। कुछ विशेष कारणों से पत्र-मुद्रा का उपयोग श्रिषक सुविधा-जनक होता है, क्योंकि एक तो, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में सुविधा रहती है और दूसरे, इसमें चलन के अन्तर्गत विसावट द्वारा भूल्य के ह्रास का भय नहीं रहता है। वर्तमान संसार की प्रधान सुद्रा पत्र-सुद्रा ही है और इसिलए हमारेंग युग आर्थिक भाषा में पत्र-सुद्रा का युग कहलाता है। पत्र-मुद्रा के दो प्रधान रूप होते हैं:—पत्र मुद्रा चलन (Paper Currency) तथा पत्र-मुद्रा मान (Paper Standard)। प्रस्तुत श्रष्ट्याय में हम केवल पत्र मुद्रा चलन का ही श्रष्ट्ययन करेंगे। पत्र-मुद्रा चार प्रकार की होती है:—

### पत्र-मुद्रा चलन के भेद-

# (१) प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा (Representative Paper Money)—

पत्र-मुद्रा में जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए सरकार ऐसी मुद्रा के पीछे किसी बहुमूल्य घातु की ग्राड़ ग्रथवा निधि (Reserve) रखती है। यह ग्राड़ साधाररणत्या सोने ग्रीर चाँदी के रूप में रखी जाती है। यदि पत्र-मुद्रा के पीछे उसके मूल्य का १००% सोना ज्रीर चाँदी निधि के रूप में रखा जाता है तो ऐसी पत्र-मुद्रा प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा कहलाती है। ऐसी मुद्रा का यह नाम इसलिए पड़ा है कि वास्तव में यह पत्र-मुद्रा उस सोने ग्रथवा चाँदी के प्रतिनिधि के रूप में प्रचलन में रहती है जो सुरक्षित कोष में रख दिया गया है। ऐसी पत्र-मुद्रा प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को यह ग्रधिकार होता है कि वह किसी भी समय कागज के नोट को सरकार से सोने ग्रथवा चाँदी में बदल ले। ऐसी मुद्रा के उपयोग का प्रमुख उद्देश्य सिक्कों की धिसावट की हानि को बचाना होता है।

#### गुग्-

प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा सबसे अच्छी पत्र-मुद्रा समफी जाती है, क्योंकि:—(१) इस मुद्रा पर जनता को अटल विश्वास होता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वह किसी भी समय अपने पास के कागज के नोट को सोना या चाँदी में बदल सकता है और सरकार के पास नोटों को बदलने के लिये काफी सुरक्षित कीष है। (२) ऐसी मुद्रा को अत्यधिक मात्रा में निकालने का तिनक भी भय नहीं रहता है, क्योंकि इस मुद्रा को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि ठीक उतनी ही कीमत का सोना और चाँदी कोषागरि में जमा किया जाय और क्योंकि चाँदी या सोना अत्यधिक मात्रा में मिलना कठिन होता है, इसीलिये मुद्रा की निकासी सीमित ही रहती है। (३) जब सिक्कों के स्थान में नोटों का प्रचलन होता है, बहुमूल्य धातुत्रों की बचत होती है। दोष—

परन्तु इन सब गुणों के होते हुए भी इस प्रकार की मुद्रा का चलन बहुत ही

कम रहा है, क्योंकि (१) यह मुंद्रा चलन प्रणाली को बेलोच बना देती हैं। बिना सोना चाँदी प्राप्त किये मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना सम्भव नहीं होता है। (२) राष्ट्रीय संकट के समय तो ऐसी पत्र-मुद्रा प्रणाली को भंग करना ग्रावश्यक हो जाता है, क्योंकि ऐसे काल में बहुमूल्य घातुग्रों का प्राप्त करना किन होता है, जबिक मुद्रा की मात्रा का बढ़ाना ग्रावश्यक होता है। (३) चूँ कि इस प्रणाली का ग्राघार मुख्यतः सोना है इस-लिए एक गरीब राष्ट्र इस प्रणाली को नहीं ज्रपना पाता। कुछ देशों ने इस सम्बन्ध में एक नई रीति ग्रपनाई थी। इङ्गलैण्ड में एक निश्चित मात्रा तक कागज के नोट बिना, किसी प्रकार की घातु ग्राड़ के निकाल दिए जाते थे ग्रीर तत्पश्चात् प्रत्येक नोट के पीछे १००% स्वर्ण निधि रखी जाती थी। बिना ज्राड़ की ऐसी निकासी को ज्रार्थ-शास्त्र में विश्वासाश्रित निकासी (Fiduciary Issues) कहा जाता है।

व्यावहारिक जीवन में इस प्रकार की मुद्रा का उपयोग बहुत ही कम हुआ है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमरीका के स्वर्ण तथा चाँदी प्रमाण-पत्रों (Gold and Silver Certificates) में मिलता है, जिनकी गारन्टी सरकार द्वारा उतनी कीमत का सोना और चाँदी सरकारी कोषागार में जमा करके दी जाती थी। भारत में ऐसी पत्र-मुद्रा का चलन नहीं रहा है, परन्तु सन् १६२७ के भारतीय चलन तथा वित्त के शाही आयोग ने स्वर्णपाट प्रमाण-पत्रों (Gold Bullion Certificates) के रूप में ऐसी पत्र-मुद्रा की निकासी का सुभाव दिया था।

(२) परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा (Convertible Paper Money)—
प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा में एक भारी दोष यह होता है कि मुद्रा-प्रशाली बेलोच

हो जाती है। प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा के सभी लाभों को प्राप्त करने ऋौर इस दोष को दूर करने के लिए परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का ऋाविष्कार किया गया।

### विशेषतायं-

इसकी विशेषतायें निम्न प्रकार हैं :---

- (अ) कागजी मुद्रा के पीछे सोने, अथवा चाँदी की आड़ रखी जाती है, परन्तु नोटों की कीमत से कम कीमत की निधि रखी जाती है।
- (ब) सरकार द्वारा यह गारन्टी दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति नोटों को सरकारी खजाने से सोना अथवा चाँदी में बदल सकता है।
- (स) सरकार विदेशी भुगतानों को चुकाने के लिए सोने या चाँदी का एक कोष रखती है।
- (द) सुरिच्चित निधि का एक भाग पूर्णाकाय सिक्कों, सांकेतिक सिक्कों तथा प्रतिभृतियों के रूप में रखा जाता है।
- (इ) सोने ऋौर चाँदी की कीमतें निर्घारित कर दी जाती हैं और सरकार इन कीमतों पर सोना और चाँदी खरीदने तथा बेचने को तैयार रहती है।

#### गुण-

इस प्रकार की पत्र-मुद्रा से कुछ विशेष लाभ प्राप्त होते हैं:—(१) धातु की ग्राड़ रहने के कारण इस पर जनता का विश्वास बना रहता है। (२) क्यों कि सरकार कागजी नोटों को सोने ग्रथवा चाँवी में बदलने का वचन देती है, इसजिए देशवासियों को घरेलू तथा विदेशी व्यापार के लिए सोना-चाँदी मिल जाती है। (३) पत्र-मुद्रा द्वारा सोने ज्योर चाँदी के उपयोग में बचत होती है। (४) थोड़ से सुरक्षित कोष के ग्राधार पर प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा की तुलना में कई ग्रनी ग्रधिक मुद्रा की निकासी की जाती है ग्रीर सुद्रा-प्रणाली लोचदार हो जाती है।

#### दोष-

परन्तु ऐसी पत्र-मुद्रा के कुछ गम्भीर दोष भी हैं:—(१) इस पत्र-मुद्रा के प्रित जनता का विश्वास इतना अधिक नहीं हो सकता हैं जितना कि प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा के प्रति । विश्वास की इस कमी के बहुवा घातक परिएगम होते हैं और संकट काल में मुद्रा के प्रचलन को बनाये रखना किठन हो जाता है। (२) इस प्रकार की सुद्रा-प्रएगाली का सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। बहुत बार ग्रासानी से अधिक ग्राय शात करने के लिए सरकार बिना सोचे-समभे पत्र-मुद्रा की निकासी करती जोती है। (३) परिवर्तनशील कागजी मुद्रा में इस प्रकार की निकासी की सम्भावना काफी ग्रधिक रहती है। इससे एक ग्रोर तो मुद्रा पर से जनता का विश्वास उठ जाता है ग्रीर दूसरी ग्रोर भीषण मुद्रा-प्रसार के कारण देश का सामाजिक, ग्राधिक तथा राजनैतिक जीवन चौपट हो जाता है।

### श्राश्रित निकासी और विश्वासाश्रित निकासी—

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् संसार के बहुत से देशों में ऐसी मुद्रा का प्रचलन रहा है। ऐसी मुद्रा प्रणाली में दो प्रकार की पत्र-मुद्रा होती है। कुछ पत्र-मुद्रा के पीछे तो १००% सोने छोर चाँदी की छाड़ होती है। मुद्रा की ऐसी निकासी को छाछित निकासी (Covered Issue) कहते हैं। रोष पत्र-मुद्रा के पीछे केवल कागजी प्रतिमृतियों की छाड़ रहती है छोर इसे विश्वासाश्रित निकासी (Fiduciary Issue) कहा जाता है। सन् १६२५ में इङ्गलैंड तथा फांस दोनों ही देशों ने यह पत्र-मुद्रा प्रणाली अपनाई थी। सन् १६२७ में शाही आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय पत्र-मुद्रा को परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा बना दिया गया था। सरकार द्वारा सोने की कीमत २१ रुपये ७ ग्राने १० पाई फी तोला निर्धारित की गई थी और सरकार ने इस दर पर प्रत्येक कागजी नोट के बदले सोना देने की गारन्टी दी थी, यद्यि प्रपनी सुविधा के लिए सरकार ने यह शर्त लगा दी थी कि कोई भी व्यक्ति ४०० श्रींस से कम सोना एक बार में सरकारी कोषागार से नहीं खरीद सकता था। यह प्रणाली सन् १६३१ तक चालू रही। स्वर्णमान पद्धित के अन्त के साथ-साथ इसका भी अन्त हो गया।

### (३) श्रपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा (Inconvertible Paper Money)-

प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा तथा परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का ग्राज के संसार में केवल सैंद्रान्तिक महत्त्व ही शेष रह गया है। वास्तिविक जीवन में चलन केवल ग्रपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा को फिसी धातु में बदला नहीं जा सकता है। यह पत्र-मुद्रा शासन की माख पर चालू रहती है। जितनी ही शासन की ग्राधिक हत्ता ग्रधिक होती है उतना ही इस मुद्रा पर जनता का विश्वास भी ग्रधिक होता है। किसी प्रकार का संचित कोष इस पत्र-मुद्रा के पीछे नहीं रखा जाता है। सरकार ग्रथवा मुद्रा ग्रधिकारी की ग्राज्ञानुसार इसका चलन होता है। शुरू में इस प्रकार की मुद्रा की निकासी साधारणत्या युद्ध-काल ग्रथवा ग्रन्य राष्ट्रीय संकट के समय में की जाती थी, परन्तु वर्तमान संसार में ऐसी मुद्रा का चलन एक बड़ी स्वाभाविक तथा साधारण घटना समभी जाती है।

### प्रमुख विशेषताएँ—

ऐसी पत्र-मुद्रा की प्रमुख विशेषतायें निम्न प्रकार हैं:---

- (क) पत्र-मुद्रा के पीछे किसी प्रकार की धातु की आड़ नहीं होती हैं। केवल सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्डस (Bonds) तथा कोषागार विपत्रों (Treasury Bills) की आड़ रहती है। इस प्रकार सुरक्षित कोष कागजी होता है।
- (ख) सरकार द्वारा कागजी नोटों को सोने या चाँदी में बदलने की गारन्टी नहीं दी जाती है। भारत सरकार ग्रपनी पत्र-मुद्रा को छोटी कीमत के कागजी नोटों तथा सांकेतिक रुपये के सिक्कों में ही बदलने का विक्वास दिलाती है।
- (ग) विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए सरकार देश की मुद्रा की विदेशी विनिमय दर निश्चित कर देती है। इस समय भारतीय रुपये की विदेशी विनिमय दर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित की जाती है।
- (घ) कागज के नोट प्रमाणित तथा श्रमीमित विधि-प्राह्म मुद्रा होते हैं। (४) प्रादिष्ट पत्र-मुद्रा (Fiat Money)—

यह पत्र-मुद्रा अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का ही एक रूप है। इसको कभी-कभी संकटकालीन मुद्रा (Emergency Money) भी कहा जाता है। अपरि-वर्तनशील पत्र-मुद्रा की भाँति इसके पीछे भी किसी प्रकार की सुरक्षित निधि धातु के रूप में नहीं रखी जाती है और इसे सोने अथवा चाँदी में बदलने की किसी प्रकार की गारन्टो भी नहीं दी जाती है, परन्तु इस पत्र-मुद्रा की निम्न विशेषताएँ इसे साधारण अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा से अलग करती हैं:—

( अ ) यह पत्र-मुद्रा संकट काला में निकाली जाती है।

- (ब) इसकी निकासीं सीमित मात्रा में की जाती है।
- (स) इसके पीछे कागजी त्राड़ भी नहीं होती है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, श्रपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के पीछे कागजी स्नाड़ स्रवश्य रहती है, परन्तु प्रादिष्ट मुद्रा के पीछे किसी भी प्रकार की स्नाड़ नहीं होती है।

इस मुद्रा को ग्रसाधारण पत्र मुद्रा कहना ग्रनुपयुक्त न होगा। किसी विशेष ग्राधिक परिस्थित का सामना करने के लिए सरकार इसे निकालती है। यह मुद्रा भी श्रसीमित विधि याह्य होती है। इस मुद्रा के प्रति जनता का विश्वास सबसे कम होता है। यही कारण है कि इसे थोड़ी मात्रा में निकाला जाता है ग्रीर संकट-काल का ग्रन्त होते ही सरकार इसे साधारण ग्रपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा में बदल देती है

कैन्ट के अनुसार प्रादिष्ट मुद्रा की तीन प्रमुख विशेषतायें होती है\*
प्रथम, पदार्थ के रूप में इसका लगभग कुछ भी मूल्य नहीं होता है। दूसरें, इस मुद्रा को किसी ऐसी वस्तु में बदलने की गारन्टी नहीं दी जाती है जिसका विश्ति मूल्य प्रादिष्ट मुद्रा के बराबर हो। तीसरें, इसकी क्रयः शक्ति को किसी अन्य वस्तु के समान नहीं रखा जाता है, इस कारण इस मुद्रा की कीमत स्वतन्त्र रूप में निर्धारित होती है।
गुण-दोष—

श्रिषकांश सरकारें श्रपनं। मुद्रा की प्रादिष्ट प्रकृति को स्वीकार करने में संकोच करती हैं, परन्तु श्राधुनिक-युग के बहुत से श्रथंशास्त्री प्रादिष्ट मान के पद्म में हैं। कहा जाता है कि ठीक नियन्त्रण द्वारा ऐसा मान श्राधिक तथा वित्तीय सुविधायें प्रदान कर सकता है। इसके विपरीत प्रादिष्ट मुद्रा के श्रालोचकों का कहना है कि इस मुद्रा के प्रचार से दो गम्मीर दोष उत्पन्न होंगे:—प्रथम, यदि संसार के सभी देश ऐसी मुद्रा-प्रणाली को ग्रहण कर लें तो श्रन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य में भारी उलक्षन पैदा हो जायगी। दूसरे, इस मुद्रा में श्रत्यिक निकासी का भय सदा हो बहुत रहता है। बड़ी कठिनाई यह है कि ऐसी मुद्रा की निकासी को नियन्त्रित रखने का कोई भी व्यवहारिक उपाय नहीं है। इसे राष्ट्रीय नीति का श्राधार बनाना संकट से खाली नहीं है।

प्रादिष्ट मुद्रा के प्रमुख उदाहरए फांस के एसाइनेट (Assignats), जो सन् १७६६ और सन् १७६६ के बीच चालू रहे, प्रमरीका के क्रान्तिकालीन कॉन्टीन टलस् (Continentals) तथा गृह-युद्ध के काल में ग्रीनबैक्स (Greenbacks) ग्रौर प्रथम युद्ध के उपरान्त जर्मनी के कागजी मार्क (Paper Marks) द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। इन सभी मुद्राग्रों में ग्रत्यधिक निकासी की ग्राम प्रवृत्ति थी। भारत में एक रुपये का नोट इसका ग्रच्छा उदाहरए है, यद्यपि ग्रब रिजर्व बैंक इसकी ग्रपरिवर्तनशील मुद्रा के रूप में फिर से निकासी कर रही है।

## टेकन, मुद्रण अथवा ढलाई (Coinage)—

मुद्रा के विभिन्न रूपों का भ्रष्टययन करने के बाद यह ग्रावश्यक मालूम होता है कि सिक्कों के मुद्रएा के विषय में भी थोड़ा सा बता दिया जाय । सिक्कों के उपयोग के साथ ही साथ उनकी ढलाई की समस्या उत्पन्न हुई ग्रौर विभिन्न देशों ने उनके मुद्रएा की कला का ग्राविष्कार किया । ऐतिहासिक खोज से पता चलता है कि सबसे पहिले लीडिया (Lydia) के देश में सिक्कों की ढलाई का काम ग्रारम्भ हुग्रा । मिस्र के निवासी भी इस कला से बहुत प्राचीन काल से परिचित थे । सिक्कों की ढलाई की कला को ही मुद्रएा त्राथवा टंकन (Coinage) का नाम दिया जाता है ।

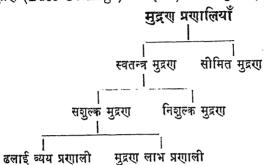
घातु के दुकड़ों को मुद्रा के रूप में उपयोग करते समय सबसे पहिली कठिनाईं यह पैदा हुई थी कि घातु के सभी दुकड़ों को एक ही वजन तथा एक ही शुद्धता का बनाना कठिन था। परिगाम यह होता था कि उनको स्वीकार करते समय प्रत्येक बार व्यापारियों तथा जन-साधारण को उनकी शुद्धता की जाँच करनी पड़ती थी और उनको तोलना पड़ता था। इसमें भारी अमुविधा थी और ठंगे जाने का भी भय रहता था। इन्हीं कठिनाइयों के कारण राज्य ने सिक्कों के निर्माण का काम शुरू किया। शुरू-शुरू में टंकन-कला में काफी शिल्प सुधार नहीं हो पाया था, परन्तु धीरे-धीरे सुधार होते गए और १८ वीं शताब्दी में ऐसे सिक्कों का निर्माण होने लगा, जो सभी हिष्टकोणों से सन्तोषजनक कहे जा सकते थे। आरम्भ में सिक्कों के निर्माण का कार्य अनेक व्यक्तिगत टकसालों तथा कारखानों द्वारा किया जाता था, परन्तु धीरे-धीरे टंकन राजकीय एकाधिकार बन गया और उसमें एकरूपता तथा समान शुद्धता उत्यन्न हो गई।

### मुद्रण के उद्देश्य-

मुद्रश् का उद्देश्य साधारशातया यही होता है कि समान वजन तथा समान शुद्धता के सिक्के तैयार किये जायें, जिससे घोखेबाजी और नकली सिक्कों का बनाना कम हो जाय। मुद्रश् के बहुत से उद्देश्य होते हैं:—(१) सिक्कों में से घातु को काट-कर अथवा गलाकर निकालने की अनुत्ति को रोकना। (२) सिक्कों में इतनी सख्ती अथवा इतना कड़ापन उत्पन्न करना कि प्रचलन के अन्तर्गत धिसायट द्वारा धातु नष्ट न होने पाये। इसके लिए बहुमूल्य घातुओं के सिक्कों को कड़ा करने के लिए उनमें थोड़ा टांका मिला दिया जाता है। (३) नकली तथा जाली सिक्कों को बनने से रोकना। इसके लिए सिक्कों पर सरकारी मुहर लगाई जाती है और उसकी ढलाई विधि ऐसी रखी जाती है कि अन्य व्यक्ति उन्हें बना न सकें। (४) सिक्कों को कलापूर्ण तथा सुन्दर रूप प्रदान करना, जिससे कि भविष्य में वे अपने काल के स्मर्ण चिह्न बन सकें। (४) आधुनिक युग में इन उद्देश्यों के अतिरिक्त सरकार टङ्कन द्वारा आय प्राप्त करने का भी प्रयत्न करती है।

### मुद्रग प्रगालियाँ

संसार में मुद्रण की दो प्रमुख प्रणालियाँ दिखाई पड़ती।हैं :—(१) स्वतन्त्र मुद्रण (Free Coinage) ग्रौर (२) सीमित मुद्रण (Limited Coinage)।



### (१) स्वतन्त्र मुद्रण-

स्वतन्त्र मुद्रण को कभी-कभी असीमित मुद्रण भी कहा जाता है। स्वतन्त्र मुद्रण प्रणाली में जनता को यह अधिकार होता है कि वह चातु पाट (Bullion) को सरकारी टकसाल पर ले जाकर सिक्कों में ढलवा सकती है। कभी-कभी तो यह कार्य सरकार द्वारा निःशुल्क किया जाता है, परन्तु बहुत बार सरकार इसके लिए शुल्क लेती है। दोनों ही दशाओं में जनता को घातुपाट को सिक्कों में ढलवाने की स्वतन्त्रता होती है। संसार के बहुत से देशों में भूतकाल में यही प्रणाली प्रचलित थी, मुख्यतया इङ्गलेंड, फांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में।

(२) सीमित मुद्रग् — सीमित मुद्रग् प्रगाली में सिक्के सरकारी लेखे पर ही तैयार किये जाते हैं । सरकार का मुद्रा उत्पादन का एकाधिकार होता है । वह स्वयं धातु खरीद कर मुद्रा बनाने का कार्य करती है । जनता को यह अधिकार नहीं होता कि वह सोने-चाँदी की सिलों को सिक्कों में ढलवा सके । इस समय संसार के सभी देशों में टक्कन की यही प्रगाली प्रचलित है । भारत में सन् १८६३ तक स्वतन्त्र मुद्रग् प्रगाली प्रचलित थी, परन्तु हरशैल (Herschell) समिति की सिफा-रिशों पर सन् १८६३ में भारत सरकार ने चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रग् बन्द कर दिया था । तब से भारत में सीमित मुद्रग् प्रगाली चालू है ।

#### स्वतुन्त्र मुद्रण के रूप-

स्वतन्त्र मुद्रण के दो रूप होते हैं — (ग्र) निःशुल्क मुद्रण (Gratuitous Coinage) तथा (ब) सःशुल्क मुद्रण (Non-gratuitous Coinage)। निशुल्क मुद्रण में सरकार ढलाई के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेती। ढलाई का काम मुक्त किया जाता है। ढलाई में जो व्यय होता है उसे सरकार अपनी साधारण भाय में से चुकाती है। इक्क्लैंड तथा अमरीका में भूतकाल में यही मुद्रण प्रणाली

प्रचलित थी। यह प्रणाली पूर्णकाय सिक्कों की ढलाई के लिए ग्रच्छी होती है। सःशुल्क मुद्रण प्रणाली में सरकार सिक्कों की ढलाई के लिए शुल्क लेती है। प्रत्येक व्यक्ति को घातु के ग्रतिरिक्त कुछ श्रधिक सरकार को देना होता है। इस प्रणाली के दो रूप देखने में ग्राते हैं:—

- (क) मुद्रगा व्यय प्रथवा ढलाई व्यय प्रगाली (Mintage or Brassage)—इस प्रगाली में सरकार मुद्रगा के व्यय को शुल्क के रूप में लेती है। मुद्रगा का व्यय सरकार उसी व्यक्ति से वसूल कर लेती है जो घातु को सिक्कों में ढलवाना चाहता है, परन्तु सरकार किसी प्रकार का लाभ नहीं कमाती। वह केवल ढलाई का वास्तविक व्यय वसूल करती है।
- (ख) मुद्रग् लाभ प्रगाली (Seigniorage)—इस प्रगाली में सरकार सिकों की ढलाई के लिए मुद्रग् व्यय से श्रिधक दाम वसूल करती हैं। व्यय से श्रिधक सरकार जो कुछ लेती है उसे 'मुद्रग् लाभ' कहते हैं। इस लाभ को प्राप्त कर ने की दो रीतियाँ हैं, या तो सरकार धातु में टाँका (Alloy) मिला देती है या वह प्रत्यक्ष रूप में शुल्क लेती है।

## कौनसी मुद्रा प्रणाली श्रेष्ठ है ?—

यह कहना कठिन है कि मुद्रण की कौनसी प्रणाली सबसे अधिक अच्छी है। स्वतन्त्र मुद्रण प्रणाली के पक्षपाती इस बात पर जोर देते हैं कि इसके द्वारा मुद्रा की अत्यधिक निकासी का भय मिट जाता है और मुद्रा-प्रसार की सम्भावना कम हो जाती है। सीमित मुद्रण प्रणाली में यह गुण बताया जाता है कि उसमें सरकार सांकेतिक सिक्के निकाल कर सोने और चांदी के उपयोग में बचत कर सकती है। निःशुल्क मुद्रण के समर्थकों का विचार है कि मुद्रण सरकार का ही कार्य है और उससे सम्बन्धित व्यय भी उसी पर पड़ना चाहिए। मुद्रण-लाभ प्रणाली के समर्थक इस प्रणाली को इस कारण उपयुक्त बताते हैं कि इसके कारण सिक्के की अङ्कित कीमत निहित कीमत से अधिक हो जाती है और इस प्रकार उसके गलाने का भय नहीं रहता है।

#### **QUESTIONS**

- 1. 'Metallic money has lost its importance in modern economic life.' Explain and amplify this statement.
  - (Agra, B. Com., 1957)
- 2. Distinguish between Convertible and Inconvertible paper currency. (Raj., B. A., 1956)
- 3. Define money and indicate its functions. Give a classifica-

tion of money which you consider the best, giving reasons for your choice. (Raj., B. A. 1955)

4. Write a note on Classification of money.

(Agra, B. A., 1954)

- 5. 'The Indian rupee is a curious mixture of a standard and token coin.' Explain. (Agra, B. Com., 1956)
- 6. Differentiate between :-
  - (a) Actual Money and Money of Account.
    - (b) Commodity Money and Representative Money.
    - (e) Legal tender money and Optional money.

(Raj., B. Com., 1960)

- 7. Explain the difference between the two—Standard Money and Token Money. (Agra, B. Com., 1958 and 1955)
- 8. Write short note on-Fiat paper money.

(Raj., B. Com., 1960)

### श्रध्याय ४

## उत्तम और हीन मुद्रा

(Good and Bad Money)

### निकृष्ट सिक्के (Debased Coins)—

जब किसी सिक्के के भीतर की घातु का वास्तिविक मूल्य उस सिक्के की नियम द्वारा निर्धारित घातु की प्रामाणिक कीमत से कम रह जाता है तो उस सिक्के को 'निकृष्ट सिका' कहा जाता है। भूतकाल में बहुत से राजा म्रावश्यकता के समय प्रचलित सिक्कों को निकृष्ट बनाकर म्रपनी म्राय बढ़ाने का प्रयत्न किया करते थे, परन्तु कुछ लोग घोखेबाजी करके लाभ कमाने के लिए भी सिक्कों को निकृष्ट बना देते हैं। इस कार्य के लिए कई तरीके म्रपनाये जाते हैं:—

- (१) किनारा काटना (Clipping)—सिक्के के सिरों में से सावधानी-पूर्वक थोड़ी थोड़ी धातु काट ली जाती है ग्रौर यह काम इतनी चतुराई से किया जाता है कि देखने वाले को ग्रासानी से पता न चले। इस व्यवहार को रोकने के लिए ग्राधु-निक सरकारें सिक्कों के किनारों में छोटे छोटे दाँते बना देती हैं, जिससे कि थोड़ी सी छिलाई का भी ग्रासानी से पता चल जाय।
- (२) सिक्के जलाई (Sweating)—तेजाब अथवा किसी दूसरे रसाय-निक पदार्थ में डालकर सिक्के पर से थोड़ी सी धातु उतार ली जाती है।
- (३) सिक्के घिसना (Abrasing)—सिक्कों को श्रापस में घिस कर अथवा रगड़ कर भी उनमें से थोड़ी सी घातु उतारी जा सकती है।
- (४) जाली सिक्के बनाना (Counterfeiting)—जाली श्रथवा नकली सिक्के बनाये जाते हैं, जिनमें बहुमूल्य घातु की मात्रा सरकारी सिक्कों की ग्रपेक्षा कम रखी जाती है। बहुत से सुनार तथा कारीगर ऐसे सिक्कों के बनाने में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं और बहुत बार ऐसे सिक्कों के बनाने के श्रौजार श्रीर यन्त्र पुलिस द्वारा बरामद किये गये हैं। सरकार जाली सिक्के बनाने वालों के लिए भारी दण्ड रखती है श्रौर इस बात का भरसक प्रयत्न करती है कि सिक्कों के ऐसे नमूने बनाये जायें जिनकी नकल न हो सके, परन्तु फिर भी जाली सिक्के बनाने का काम बराबर चलता ही रहता है।

बहुत सी दशात्रों में सरकार स्वयं देश के सिक्कों को निकृष्ट बना देती हैं। यह काम सिक्के में बहुमूल्य धातु की मात्रा कम करके किया जाता है। भूतकाल में सरकारें श्राय प्राप्त करने तथा सिक्कों के निर्यात को रोकने के लिए ऐसा किया करती

थीं। ग्राज कल की सरकारें मुद्रण नियमों में संशोधन करके ऐसा किया करती हैं। साधारणतया निकृष्टिकरण (Debasement) से सरकार का ग्रायिक मान कम हो जाता है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में ऐसा करने की प्रथा ग्रव लगभग सभी देशों में पाई जाती है। स्वयं भारत सरकार ने सन् १९४० में ऐसा किया था। भारतीय मुद्रण नियम सन् १९६० के ग्रनुसार भारतीय रुपये में कैई भाग चाँदी होनी चाहिए, परन्तु सन् १९४० में भारत सरकार ने उसे घटा कर ई कर दिया था।

### श्रवमूल्यत-मुद्रा (Depreciated Money)—

कागजी मुद्रा तथा अन्य मुद्रा की अत्यधिक निकासी के कारण यदि मुद्रा का मूल्य घट जाता है ( अर्थात् यदि यस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत बढ़ जाती है ) तो ऐसी दशा में मुद्रा का 'अयमूल्यन' हो जाता है । आधुनिक युग में ऐसा करने की प्रथा भी सभी देशों में पाई जाती है । युद्ध-काल में अथवा राष्ट्रीय संकट के काल में सभी सरकारें कागज के नोट छाप कर अपनी आय बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं । इससे मुद्रा का अवमूल्यन (Depreciation) हो जाता है और देश में मुद्रा-प्रसार फँलता है । ऐसी दशा में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तेजी के साथ बढ़ने लगती हैं । महायुद्ध के काल में भारत सरकार ने यही नीति अपनाई थी, जिसके फलस्वरूप पत्र-मुद्रा की मात्रा सन् १९३९ तथा सन् १९४५ के बीच लगभग २०० करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग १,३०० करोड़ रुपया हो गई थी।

मुद्रा का अवमूल्यन सदा ही बुरा नहीं होता है। संकट काल में सरकार के पास आय प्राप्त करने का बहुधा दूसरा कोई उपाय नहीं होता है और मुद्रा-अवमूल्यन देश की पराजय अथवा कह से बचा सकता है। कुछ सरकार आयातों को हतोत्साहित करने और निर्यातों को बढ़ाने के लिए भी इस नीति को प्रशुल्क-नीति (Fiscal Policy) का एक आवश्यक अङ्ग बनाती हैं।

## अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुरा (Qualities of a Good Money Material)-

हम देख चुके हैं कि मुद्रा द्वारा देश के आधिक जीवन में बहुत से महत्त्वपूर्णं कार्य किये जाते हैं। जो पदार्थ मुद्रा के रूप में इन कार्यों को भली-भाँति सम्पन्न कर सकता है उसे ही 'श्रच्छा मुद्रा-पदार्थं' कहा जाता है। एक श्रच्छा मुद्रा-पदार्थं बनने के लिए किसी वस्तु में निम्न गुर्णों का होना श्रावश्यक है:—

(१) उपयोगिता ग्रथवा सामान्य स्वीकृति (Utility or General Acceptability)—जिस वस्तु में सर्वमान्यता का ग्रुण नहीं है वह एक ग्रच्छी मुद्रा पर्दार्थ नहीं हो सकती है। यदि कोई वस्तु ऐसी है कि मुद्रा के ग्रतिरिक्त दूसरे कामों के लिए भी उसकी उपयोगिता बहुत है, तो निश्चय ही उसको सभी व्यक्ति सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। लोग किसी वस्तु को उसी दशा में स्वीकार करते हैं जबिक या तो वे यह जानते हैं कि ग्रन्थ व्यक्ति भी उसे बिना संकोच स्वीकार कर लेंगे ग्रथवा जब उन्हें यह ज्ञात होता है कि वस्तु विशेष के ग्रन्थ लाभदायक उपयोग हो सकते हैं। इन

हिष्टिकोगों से सोना और चाँदी अच्छे मुद्रा पदार्थं हैं, क्योंकि उन्हें हर कोई लेने को तैयार रहता है। कपड़ा एक अच्छा पदार्थं नहीं है, क्योंकि एक निश्चित मात्रा के परे उसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। कागज भी इस दृष्टिकोगा से अच्छा मुद्रा पदार्थं नहीं है, परन्तु कागज के नोटों को लोग इस कारण खुशी से स्वीकार कर लेते हैं कि उनमें सभी लोग भुगतान ले लेते हैं। वैसे मुद्रा के अतिरक्त कागज के नोट की कीमत लगभग कुछ भी नहीं होती है, परन्तु सोने और चाँदी का उपयोग और भी बहुत से कार्यों में किया जा सकता है।

- (२) वहनीयता (Portability)—एक ग्रच्छे मुद्रा पदार्थ में वहनीयता का भी ग्रुण होना चाहिए। इसके लिए किसी वस्तु में दो ग्रुणों का होना धावश्यक है—प्रथम, थोड़े बोभ में धिषक मूल्य का होना, ग्रीर दूसरे, टिकाऊपन होना। इस दृष्टिकोण से कोयला, दूष तथा गाय ग्रच्छे मुद्रा-पदार्थ नहीं हैं। पत्र-मुद्रा का सबसे बड़ा ग्रुण उसकी वहनीयता है। सोने ग्रीर चाँदी में भी यह ग्रुण भली भाँति पाया जाता है।
- (३) विभाज्यता (Divisibility)—वस्तु-विनिमय की एक बड़ी किठ-नाई यह है कि कुछ वस्तुग्रों को टुकड़ों में बाँटने से उनकी कीमत में भारी कमी थ्रा जाती है। ग्रच्छा मुद्रा-पदार्थ वही होगा जिसे मूल्य में किसी प्रकार की कमी किये बिना कितने ही टुकड़ों में बाँटा जा सके। इस दृष्टिकोगा में हीरे को एक ग्रच्छा मुद्रा-पदार्थ नहीं कहा जा सकता है, यद्यपि वह एक बहुमूल्य वस्तु है, क्योंकि टुकड़े कर देने से उसकी कीमत बहुत घट जाती है। यह गुगा सोने ग्रीर चाँदी में ही होता है कि उनके समान कीमत ग्रीर समान वजन के टुकड़े किये जा सकते हैं ग्रीर सभी टुकड़ों की सामू-हिक कीमत पूरी घानु की कीमत के बराबर होती है।
- (४) टिकाऊपन (Durability)—एक ग्रच्छे मुद्रा-पदार्थ में टिकाऊपन का भी ग्रेग होना चाहिए। मुद्रा का उपयोग क्यः शक्ति के संचय के लिए भी किया जाता है। यह संचय तभी सफल तथा लाभदायक होता है, जबिक मुद्रा में टिकाऊपन हो। गेहूँ ग्रथवा मवेशी इस दृष्टिकोग्रा से भी ग्रच्छे पदार्थ नहीं हैं, परन्तु सोने ग्रौर चांदी में ग्रन्य ग्रुगों के ग्रतिरिक्त यह ग्रुग भी मौजूद है।
- (५) परिचयता (Cognisability)—इस गुए। का ग्राशय यह होता है कि मुद्रा की इकाई को सरलतापूर्वक पहिचाना जा सके। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रचलन होता है ग्रीर वह एक व्यक्ति से दूसरे के पास ग्राती-जाती है, इसिलए यह ग्रावश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति उसे देखकर ही पहिचान सके, ग्रन्थथा मुद्रा विशेष को सामान्य स्वीकृति प्राप्त न होगी ग्रीर घोखेबाजी की सम्भावना काफी रहेगी। वर्तमान युग में सभी सिक्कों ग्रीर सभी प्रकार की पत्र-मुद्रा में इस ग्रुए। को वनाये रखने की ग्रोर विशेष ध्यान दिया जाता है। सोने ग्रीर चाँदी के सिक्के इस ग्रुए। से भी परिपूर्ण होते हैं।

- (६) अनुरूपता (Homogeneity)—-एक अच्छा मुद्रा पदार्थ वहीं होगा, जिसके सभी टुकड़ों में एक-रूपता हो। यदि ऐसा नहीं है तो समान वजन के टुकड़ों में समान कीमत नहीं रहेगी। मुद्रा की सभी इकाइयाँ सभी प्रकार एक जैसी ही होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी इकाई के ले लेने से किसी भी प्रकार का लाभ या किसी भी प्रकार की हानि न हो सके। इस दृष्टिकोएा से भी मवेशी तथा गेहूँ अच्छी मुद्रा नहीं बन सकते हैं, परन्तु सोने और चाँदी के टुकड़े सभी प्रकार एक जैसे हो सकते हैं।
- (७) सूल्य की स्थिरता (Stability of Value)—यह भी मुद्रा का अत्यावश्यक गुरा है। मुद्रा वा उपयोग मूल्य के मापक, स्थिगत शोधनों के मान तथा क्रयः शक्ति के संचय के लिए किया जाता है। यदि स्वयं मुद्रा के मूल्य में स्थिरता नहीं है तो वह स्थिगत शोधनों का अच्छा मान नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त संचित क्रयः शक्ति का भी मूल्य अनिश्चित रहेगा। इसी प्रकार यदि स्वयं स्थिगत साधनों के मान के मूल्य में परिवर्तन होते हैं तो ऋगुदाता और ऋगी में से किसी एक को हानि होगी।

श्राधुनिक संसार का यह अनुभव है कि मुद्रा की कीमत में भी स्थिरता नहीं रहती है, परन्तु इतना अवश्य है कि दूसरे पदार्थों की तुलना में सोने श्रीर चाँदी की कीमतों में परिवर्तन कम होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि संसार में इन दोनों धातुश्रों की एक सीमित मात्रा है, जिसमें वृद्धि अथवा कमी कठिनाई से होती है। यदि ठीक-ठीक नियन्त्रण रखा जाय, तो पत्र-मुद्रा के मूल्य को भी बड़े श्रंश तक स्थिर किया जा सकता है और उसकी अत्यधिक निकासी रोकी जा सकती है।

( द ) ढलन योग्यता (Malleability)— एक अच्छे मुद्रा-पदार्थ में यह भी गुएए होना चाहिए कि उसे गलाकर किसी भी रूप और वजन के सिक्के बनाये जा सकें। इसके अतिरिक्त सिक्कों पर ऐसी मुहरों का लगाना तथा चिन्ह बनाना भी आव- इयक है कि लोग जाली सिक्के तैयार न कर सकें।

#### निष्कर्ष-

इन सभी गुणों को देखने से पता चलता है कि सोने श्रौर चाँदी में ये गुण सब के सब मौजूद हैं। यही कारण है कि बहुत लम्बे समय से सोने श्रोर चाँदी के सिक ढाले जा रहे हैं श्रौर उन्हें मुद्रा के रूप में उपयोग किया जा रहा है। गिलट श्रौर-ताँबे के सिक्कों का भी प्रचार काफी रहा है, परन्तु ये दोनों घातुएँ श्रच्छे मुद्रा पदार्थं के सभी गुणों से सम्पन्न नहीं हैं। इनसे बने हुए सिक्के साधारणतया गौण सिक्कों के रूप में उपयोग किये गए हैं। सोने श्रौर चाँदी के सिक्कों में टाँका लगाने के लिए भी. इन घातुग्रों का उपयोग किया गया है। पत्र-मुद्रा में परिचयता, वहनीयता स्नादि के गुण तो होते हैं, परन्तु उसमें न तो टिकाऊपन होता है श्रौर न निहित मूल्य।

### ग्रेशम का नियम

#### (Greshams' Law)

एक ही समय में किसी देश में कई प्रकार की मुद्राएँ चालू हो सकती हैं। साधारणतया सोने, चाँदी और तुच्छ घातुओं के सिक्के तथा कागज के नोट एक ही साथ चालू रहते हैं। सिक्के प्रामाणिक तथा सांकेतिक हो सकते हैं और स्वयं पत्र-मुद्रा भी प्रतिनिधि, परिवर्तनशील श्रथवा प्रादिष्ट हो सकती है। घातु के सिक्के भी नये व पुराने हो सकते हैं। सभी सिक्के गुणों के दृष्टिकोण से एक जैसे नहीं होते, इसलिए उनकी प्राह्मता भी समान नहीं होती। कुछ मुद्राएँ तुलना में श्रच्छी होती हैं और कुछ बुरी।

'ऋच्छी मुद्रा' (Good money) से तात्पर्य नये व पूरे मूल्य के उन िक्कों से हैं जिनकी तोल श्रोर शुद्धता प्रमाणित होती है। पत्र मुद्रा के सम्बन्ध में 'श्रच्छी मुद्रा' का श्रभिप्राय उन नोटों से हैं जोकि परिवर्तनशील हैं, तथा नये व ठीक-ठीक हैं। इसके विपरीत 'बुरी मुद्रा' (Bad money) से तात्पर्य खोटे, जाली, मूल्य में कम श्रोर खराब सिक्कों तथा श्रपरिवर्तनशील व फटे पुराने नोटों से हैं।

ग्रेशम का नियम इङ्गलंड के व्यावहारिक ग्रथंशास्त्री सर टामस् ग्रेशम (Sir Thomas Gresham) के नाम से सम्बन्धित हैं। ग्रेशम महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पहले इङ्गलंड के शासकों ने बहुत से निकुष्ट सिक्के चालू किये थे। एलिजाबेथ प्रथम से पहले इङ्गलंड के शासकों ने बहुत से निकुष्ट सिक्के चालू किये थे। एलिजाबेथ चाहती थीं कि देश की मुद्रा में सुधार हो। इसके लिए उन्होंने नये पूर्णकाय सिक्के चालू किये। उनका विचार था कि धीरे-धीरे लोग पुराने ग्रीर निकुष्ट सिक्कों का परित्याग कर देंगे तथा नये सिक्कों को ग्रह्ण कर लेंगे, परन्तु ग्रनुभव ग्राशा के विपरीत रहा। यह देखने में ग्राया कि नए सिक्के चालू होते ही बाजार से गायब हो जाते थे ग्रीर पुराने तथा निकुष्ट सिक्के बराबर चालू रहते थे। महारानी को बड़ा विस्मय हुगा ग्रीर उन्होंने सर टामस ग्रेशम से इस घटना का कारण पूछा। ग्रेशम ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया:—"हीन मुद्रा में उत्तम मुद्रा को प्रचलन से निकाल देने की प्रवृत्ति होती हैं।" (Bad money drives good money out of circulation)। तब से यह प्रवृत्ति ग्रथंशास्त्र में ग्रेशम के नियम के नाम से प्रसिद्ध है। स्मरण रहे कि ग्रेशम से पूर्व भी लोगों को इसका ज्ञान था, परन्तु ग्रेशम ने इसे बड़ी सरल तथा स्पष्ट भाषा में व्यक्त किया.है।

प्रो॰ मार्शल ने इस नियम की परिभाषा बड़ी सावधानी से की है। ज़ुनका कथन है कि:—''यदि हीन मुद्राएँ परिमाण में सीमित नहीं हैं तो श्रच्छी मुद्राश्रों को प्रचलन से निकाल देती हैं।''\* मार्शल ने ''यदि परिमाण में

An interior currency, if not limited in quantity, will drive out the superior currency." See Marshall: Money, Currency and Credit.

सीमित नहीं हैं" वाक्य को जोड़ कर नियम की सीमा का भी उल्लेख कर दिया है। इस नियम का भ्राशय यही है कि यदि किसी देश में समान मूल्य की दो मुद्राएँ, जिनकी उत्तमता में भ्रन्तर है, एक ही साथ प्रचलन में हों तो हीन मुद्राएँ उत्तम मुद्राभ्रों को प्रचलन से बाहर निकाल देती हैं।

अर्थशास्त्र के अन्य नियमों की भाँति यह नियम भी केवल एक प्रवृत्ति को ही दिखाता है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दशा में नियम लागू हो हो, परन्तु साधारणतया ऐसा ही होने की सम्भावना रहती है। यह नियम मनुष्य की प्रकृति पर आधारित है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि जब उसे कोई चीज लेनी होती है तो वह सबसे अच्छी चीज छाँट कर लेता है और जब उसे कोई वस्तु देनी होती है तो वह सबं प्रथम सबसे खराब चीज को देने का प्रयस्त करता है। यदि सम्भव है तो वह अच्छे सिक्कों को प्राप्त करने और अपने पास रखने की चेष्टा करेगा और अपने पास के बुरे सिक्कों को दोने की कोशिश करेगा। वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदने के लिए तो हम बुरे सिक्के भी स्वीकार कर लेते हैं, यदि व इतने बुरे नहीं हैं कि दूसरे लोग उन्हें लेने से इन्कार कर दें, परन्तु संग्रह के लिए सबसे अच्छे सिक्कों को ही चुना जाता है। परिगाम यह होता है कि अच्छे सिक्के प्रथवा अच्छी पत्र-मुद्रा लोग अपने पास रख लेते हैं।

### नियम के लागू होने के कारण-

ग्रेशम के नियम में 'श्रच्छी' तथा 'बुरी' ये दोनों शब्द साधारण तथा तुलनात्मक श्रथं में उपयोग किये गये हैं। एक मुद्रा दूसरी की श्रपेक्षा श्रच्छी या बुरी हो सकती है श्रीर यदि ऐसी दोनों ही प्रकार की मुद्राएँ एक ही साथ प्रचलित हैं तो श्रच्छी मुद्रा का चलन साधारणतया बन्द हो जाता है। नियम के लागू होने के तीन प्रमुख कारण हैं:—

- (१) मुद्रा का संग्रह (Hoarding)—बहुत बार हम मुद्रा को जमा करते हैं, ताकि या तो उसे गाड़ कर रख सकें या अपने पास जमा करके रख सकें। इस कार्य के लिए हम सबसे उत्तम मुद्रा की खोज करते हैं। नये तथा पूर्णंकाय सिक्के तथा अच्छे कागजी नोट अथवा अच्छी किस्म की पत्र-मुद्रा जोड़ कर रखी जाती है। हीन मुद्रा हम शीघ्र से शीघ्र अपने पास से निकालने का प्रयत्न करते हैं।
- (२) सिक्कों को गलाना—इस कार्य के लिए नये तथा पूर्णकाय सिक्के चुने जाते हैं। घिसे हुए सिक्कों प्रथवा सांकेतिक सिक्कों को गलाने से तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है, इसलिए ऐसे सिक्कों को विनिमय माध्यम के रूप में उपयोग करना ही ग्रधिक लाभदायक होता है।
- (३) विदेशी भुगतान तथा निर्यात—विदेशों में हमारे देश की मुद्रा का प्रचलन नहीं होता, अतएव वे हमारे देश के चलन को मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं करते, बल्कि घातु के रूप में ही ग्रहण करते हैं। सिक्के साधारणतया तोल के हिसाब से लिये जाते हैं। यही कारण है कि विदेशी भुगतान अथवा निर्यात के लिए सबसे अच्छे सिक्के चुन लिए जाते हैं।

### निष्कर्ष-

जब संयह करने, गलाने श्रौर विदेशी मुगतान के लिये निर्यात करने में श्रच्छी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है तो श्रच्छी मुद्रा तो धीरे-धीरे चलन से लोप हो जाती है श्रौर हीन मुद्रा ही चलन में रह जाती है।

### नियम का चेत्र

श्रव हमें यह देखना है कि ग्रेशम का नियम विभिन्न परिस्थितियों में किस. प्रकार लागू होता है ? इसके लिए चार परिस्थितियों का ग्राच्ययन किया जाता है :—

### (१) एक-धातुमान प्रणाली में-

इस प्रएाली के अन्तर्गत देश में केवल एक ही घातु के सिक्के प्रचलित होते हैं, परन्तु इन सिक्कों में वजन, शुद्धता अथवा अन्य प्रकार के अन्तर होते हैं। एक-घातुमान की निम्न दशाएँ विचारणीय हैं:—

- ( श्र ) जबिक केवल प्रामािग्रिक सिक्के श्रथवा पूर्णकाय सिक्के प्रचिलित हैं, तो इन पूर्णकाय सिक्कों में से कुछ तो नये हो सकते हैं तथा कुछ पुराने श्रीर घिसे हुए । घिसे हुए सिक्कों नये सिक्कों की तुलना में 'हीन मुद्रा' होते हैं, इसलिए उनका प्रचलन बना रहता है, परन्तु नये सिक्के प्रचलन से निकल जाते हैं।
- (ब) जबिक पूर्णकाय तथा सांकेतिक सिक्के एक ही साथ प्रचलित हैं, तो इस दशा में सांकेतिक सिक्के बुरी मुद्रा होंगे और पूर्णकाय सिक्कों को प्रचलन से निकाल देंगे। सभी लोग संग्रह करने, गलाने तथा नियृति के लिए केवल पूर्णकाय सिक्कों का ही उपयोग करेंगे।

इसका उदाहरण भारत में उस समय मिला था जबिक रानी विक्टोरिया तथा सम्राट जार्ज षष्टम (George VI) के रुपये के सिक्के एक ही साथ चालू थे। विक्टोरिया के रुपयों में चाँदी की मात्रा ग्रिष्ठिक थी, इसिलए लोगों ने उनका संग्रह करना तथा गलाना ग्रारम्भ कर दिया था।

### (२) द्वि-धातुमान पद्धति में---

इस प्रगाली में दो घातुओं के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा तथा मूल्य-मान के रूप में एक ही साथ प्रचलित होते हैं। साधारणतया सोने श्रोर चाँदी के सिक्कों का इस प्रकार उपयोग किया जाता है। दोनों ही घातुओं के सिक्के श्रसीमित विधि ग्राह्म होते हैं श्रोर दोनों घातुओं के बीच विनिमय दर नियम द्वारा निश्चित कर दी जाती है। श्रागे चल कर ऐसा सम्भव है कि एक घातु की कीमत में दूसरी की श्रपेक्षा श्रधिक परिवर्तन हो जाय। ऐसी दशा में दोनों घातुओं की वास्तविक बाजारी विनिधय दर वैधानिक विनिमय दर से भिन्न हो जाती है, जिससे कि एक घातु के सिक्कों का श्रति-मूल्यन (Overvaluation) श्रोर दूसरी घातु के सिक्कों का श्रवमूल्यन (Under-valuation)

हो जाता है। श्रवमूल्यत मुद्रा श्रति-मूल्यत मुद्रा की श्रपेत्ता श्रधिक श्रच्छी होती है, श्रतएव श्रतिमूल्यत सिक्के श्रवमूल्यत सिक्कों को प्रचलन से बाहर निकाल देते हैं।

एक उदाहरण द्वारा इस सत्य को स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक देश में सोने और चाँदी के एक-एक तोले के पूर्णकाय सिक्के विधि-ग्राह्म सिक्कों के रूप में चालू हैं भौर सोने तथा चाँदी की इस समय की कीमतों के आधार पर सरवार उसमें १:२० का प्रमुपात निर्धारित करती है। यह सम्भव है कि भ्रागे चलकर चाँदी की कीमत बाजार में कम हो जाय श्रौर सोने की कीमत वही बनी रहे। मान लीजिए कि ऐसी दशा में बाजार में सोने श्रीर चाँदी की वास्तविक विनिमय दर १:२१ हो जाती है, जबकि नियमानुसार विनिमय दर ग्रभी भी १:२० ही रहती है। ऐसी परि-स्थिति में नियम द्वारा चाँदी को ग्रनुपात से श्रविक मूल्य प्रदान किया जायगा ग्रथवा श्राथिक भाषा में चाँदी के सिक्के का ग्रतिमूल्यन हो जायगा। इसके विपरीत सोने के सिक्हों को श्रनुपात से कम मूल्य मिलेगा और उनका श्रवमूल्यन हो जायगा। श्रतएव चौदी का सिक्झा हीन मुद्रा हो जायगा श्रीर सोने का सिक्झा श्रच्छी मुद्रा। लोग सोने के सिक्के को गलाना भ्रारम्भ कर देंगे, क्यों कि एक सिक्के को गला कर एक तोला सोना मिल जायगा ग्रौर बाजार में एक तोले सोने के बदले में २१ तोला चाँदी मिल जायगी, जबिक नियमानुसार एक तोले सोने के सिक्के के बदले में केवल २० चौदी के सिक्के, ग्रर्थात् २० तोला चाँदी मिलती है। जिस व्यक्ति को सोने का सिक्का मिल जायगा वह उसे छिपा लेगा. परन्तु चाँदी के सिक्कों का प्रचलन बराबर जारी रहेगा।

## (३) सिक्कों और पत्र-मुद्रा के एक साथ चलन में---

्यदि देश में घातु के सिक्के ग्रौर कागज के नोट एक साथ ही प्रचलित हैं तो घातु के सिक्के ग्रच्छी मुद्रा होंगे, संग्रह करने तथा गलाने के लिए उन्हों का उपयोग किया जायगा ग्रौर वे घीरे-धीरे प्रचलन से बाहर जाने लगेंगे। घातु के सांकैतिक सिक्के भी कागज के नोटों की तुलना में ग्रच्छी मुद्रा होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रथम महायुद्ध काल में जब इक्लेंड में पत्र-मुद्रा का ग्रत्यिक प्रसार हुग्रा, सोने की मुद्रायें प्रचलन से बाहर निकाल दी गई ग्रौर प्रचलन में ग्रधिकांश पत्र-मुद्रा ही रह गई।

### ४) पत्र-मुद्रा में—

पत्र-मुद्रा के चलन पर भी यह नियम लागू होता है। यदि देश में केवल कागज के नोट ही प्रचलित हैं, तो ग्रेशम का नियम निम्न प्रकार लागू होगा:——

- ( श्र ) यदि एक ही प्रकार की पत्र-मुद्रा प्रचिलत है, तो फटे-पुराने तथा सड़े श्रीर गन्दे नोट हीन सुद्रा होंगे | ग्रच्छे नोटों का संग्रह किया जायगा भ्रौर बुरे नोटों में उन्हें प्रचलन से निकाल देने की प्रवृत्ति बनी रहेगी।
- ( ब ) जबिक प्रतिनिधि तथा परिवर्तनशील पत्र मुद्रायें एक ही साथ चालू

होती हैं, तो प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा ऋच्छी मुद्रा होती है और परि-वर्तनशील पत्र-मुद्रा उसे प्रचलन से बाहर निकाल सकती है।

- (स) यदि परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा तथा ऋपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रायें एक ही साथ चालू हैं, तो हीन होने के कारण अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देगी।
- (द) यदि देश में केवल श्रपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का चलन है, परन्तु उनमें से एक प्रादिष्ट मुद्रा है, तो प्रादिष्ट मुद्रा पर विश्वास सबसे कम होने के कारण वह बुरी मुद्रा होगी और साधारण श्रपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकालने की प्रवृत्ति रखेगी।

### नियम के श्रपवाद श्रथवा सीमाएँ (Limitations of the Law)-

श्रव हमें यह देखना है कि क्या ग्रेशम का नियम सभी दशाश्रों में लागू होता है ? मार्शन ने नियम की परिभाषा करने में -सावधानी से काम लिया है । उनका विचार है कि यह नियम साधारणतया लागू होता है । यदि बुरी मुद्रा का प्रचलन सीमित रखा जाता है तो नियम के लागू होने की सम्भावना बहुत ही कम रहती है, परन्तु यदि ऐसी मुद्रा बिना किसी प्रतिबन्ध के ग्रच्छी मुद्रा के साथ साथ चलन में रहती है तो नियम श्रवहय लागू होता है । निम्न दशाश्रों में यह नियम लागू नहीं होता है :—

- (१) मुद्रा की कुल मात्रा कम होना—यदि देश में अच्छी शौर बुरी दोनों ही प्रकार की मुद्रा कुल मिलाकर देश की व्यापार, वाण्ज्य तथा व्यावसायिक आवश्यकता से भी कम है तो ग्रेशम का नियम लागू न होगा। बात यह है कि देश में विनिमय सम्बन्धी कार्यों को चलाने के लिए मुद्रा की एक न्यूनतम् मात्रा आवश्यक होती है। यदि मुद्रा की मात्रा इससे भी कम रह जाती है तो विनिमय में भारी असुविधा होने लगती है। विनिमय की यह असुविधा मुद्रा-संग्रह के लाभ की अपेक्षा अधिक हो सकती है, इसलिए अच्छी मुद्रा को प्रचलन से नहीं निकाला जाता है। यदि मुद्रा की मात्रा कम है, तो बाजार में उसकी माँग बढ़ जाने के कारण उसकी उपयोगिता भी बढ़ जायगी। मुद्रा के रूप में उपयोगिता बढ़ जाने के कारण उसे अन्य रूप में उपयोग करने का प्रलोभन ही नहीं रहेगा। मुद्रा की कमी के काल में ब्याज की दर भी उपर चढ़ जाती है, जो मुद्रा के अकारण संग्रह को रोक देगी।
- (२) ग्रत्यधिक हीन मुद्रा—यदि बुरी मुद्रा इतनी खराब हो चुकी है कि लोग उसे ग्रस्वीकार करने लगते हैं तो स्वयं उसी का चलन बन्द हो जाएगा। बहुत घिसे हुए सिक्के तथा बहुत खराब नोट खजाने को लौटा दिए जाते हैं ग्रौर स्वयं प्रचलन से निकल जाते हैं।
- (३) हीन मुद्रा का बहिष्कार—यदि सारा समाज बुरी मुद्रा के उपयोग के विरुद्ध है ग्रौर उसका बहिष्कार करता है तो वह ग्रच्छी मुद्रा को प्रचलन से नहीं हटा सकेगी। यदि कोई भी व्यक्ति हीन मुद्रा के लेने को तैयार नहीं है तो उसके प्रचलन (Circulation) का प्रश्न ही नहीं उठता है।

- (४) सांकेतिक सिक्के—यदि बुरी मुद्रा सांकेतिक सिक्कों के रूप में है श्रीर उसकी मात्रा सीमित है तो ग्रेशम का नियम लागू न होगा। कारण यह है कि एक श्रीर तो मात्रा की कभी के कारण लोग सभी भुगतान हीन मुद्रा में नहीं कर पायेंगे श्रीर उन्हें श्रच्छी मुद्रा में शोधन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दूसरी श्रीर, सरकार बुरी मुद्रा की निकासी पर नियन्त्रण रखती है श्रीर उसे श्रावश्यकता से श्रीधक प्रचलन में नहीं श्राने देती है।
- (प्र) बैंकिंग प्रथा की उन्नति—यदि देश में बैंकिंग प्रथा की इतनी उन्नति हो चुकी है कि सभी भुगतान चैंकों द्वारा होते हैं तो इस नियम के लागू होने का प्रश्न ही नहीं होगा।
- (६) भिन्न भिन्न उद्देश्य वाली मुद्रायें—प्रमाणित ग्रौर सांकेतिक सिक्के चलार्थं सम्बन्धी भिन्न-भिन्न प्रकार की माँग पूरी करते हों, तो सांकेतिक सिक्के निकृष्ट मुद्रा होने पर भी प्रमाणित सिक्कों को चलन से नहीं हटा पाते हैं।
- (७) अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान—कुछ विद्वानों का कहना है कि यदि विश्व के सभी देश द्विधातुमान को अपना लें तो क्षतिपूरक प्रभाव (Compensatory action) के कारण द्विधातुमान के अन्तर्गत ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि एक मुद्रा के अभाव की पूर्ति दूसरी मुद्रा के आधिक्य से हो जाती है। निष्कर्ष—

भूतकाल में ग्रेशम के नियम लागू होने के ग्रनेक ग्रवसर ग्राते थे। धातुमान ग्रोर विशेषकर दि-धातुमान के ग्रन्तगंत यह नियम बहुधा कार्यशील दिखाई पड़ता था। धातुमान का ग्रन्त हो जाने के पश्चात् नियम की कार्यशीलता बहुत ही कम रही है। प्रथम महायुद्ध के काल में लगभग सभी देशों ने ग्रपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा के रूप में हीन मुद्रा चालू की थी ग्रोर ग्रेशम के नियम के ग्रनुसार धातु मुद्राग्रों का चलन समास होने लगा था। दूसरे महायुद्ध के काल में भी ऐसी ही परिस्थिति श्राई थी। सन् १६४० में भारत में चाँदी के रुपयों का प्रचलन इसी नियम के ग्रन्तगंत समास होने लगा था।

#### **QUESTIONS**

- मुद्रा के विनिमय में मन्दी (Depreciation of Currency) पर नोट लिखिए। (Agra, B. A., 1958)
- 2. "Bad money drives good money out of circulation." Explain fully this statement. Is it always true?

(Raj., B. Com., 1949)

- 3. Give a critical estimate of Gresham's Law of money. Take necessary illustrations from the Indian Currency System.

  (Raj, B. Com., 1956)
- 4. Write short notes on—Gresham's Law-

(Agra, B. Com., 1956 and 1959)

5 Explain Gresham's Law giving its limitations and the occasions on which it will operate. (Patna, 1951)

#### अध्याय ४

### मुद्रा-मान

(Monetary Standards)

### मुद्रा-मान का अर्थ और मूल्यमान से उसका भेद-

ऊपर से देखने पर मुद्रा-मान (Monetary Standard) तथा मूल्य-मान (Standard of Value) में कुछ भी अन्तर दिखाई नहीं देता है। बहुत से अर्थशास्त्री भी कभी-कभी दोनों शब्दों के लगभग एक ही अर्थ लगाते हैं। परन्तु वास्तव में दोनों में काफी अन्तर होता है। मूल्य-मान से हमारा अभिप्रायः उस मुद्रा-इकाई से होता है जिसमें किसी देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत नापी जाती है। पींड, डालर, रुपया, रूबेल (Rouble), मार्क (Mark) आदि इसके उदाहरण हैं।

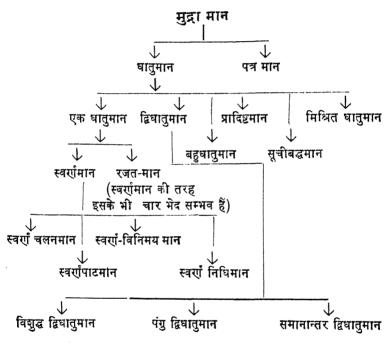
किन्तु मुद्रा-मान एक अधिक विस्तृत शब्द है, जिसमें मूल्य-मान के अतिरिक्त और भी बहुत सी वस्तुएँ सिमलित होती हैं। मुद्रा सम्बन्धी सभी प्रकार के नियम, सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ तथा सभी प्रकार के व्यवहार इसके क्ले त्र में आ
जाते हैं। सरकार को केश में प्रामाणिक मुद्रा के अतिरिक्त छोटी-छोटी कीमत के
सिक्ते निकालने पड़ते हैं, कागज के नोट छापने पड़ते हैं, साख-मुद्रा के विकास और
उसके नियन्त्रण के सम्बन्ध में नियम बनाने पड़ते हैं, बहुमूल्य धातुओं के खरीदने-बेचने
और उनके श्रायात-निर्यात की व्यवस्था करनी पड़ती है और देश की मुद्रा के मूल्य की
स्थिरता बनाये रखने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। ये सभी कार्य और
व्यवस्थाएँ मुद्रा-मान के क्षेत्र में श्रा जाते हैं। स्वयं मूल्य-मान भी मुद्रा-मान का ही
एक अंग होता है। सारांश यह है कि मुद्रा-मान में मुद्रा की नीति और व्यवहार
सम्बन्धी सभी बातों को सिम्मलित किया जाता है, परन्तु प्रत्येक देश का मुद्रा-मान
देश के मूल्य-मान पर श्राधारित होता है। मुद्रा-मान यदि शरीर है तो उसका प्राण
मूल्य-मान ही होता है।

### मुद्रामान के अध्ययन का महत्त्व

मुद्रा-मान के ग्रध्ययन का ग्रर्थशास्त्र में भारी महत्त्व है। किसी देश की ग्राधिक श्रीर सामाजिक उन्नति वहां के मुद्रा-मान पर ही निर्भर होती है। एक ग्रच्छा मुद्रा-मान कीमतों में स्थिरता लाकर ग्राधिक ग्रानिश्चितता को दूर करता है ग्रीर व्यापार, व्यवसाय तथा वाणिज्य के विकास के लिए ग्रनुकूल दशाएँ उत्पन्न करता है। मुद्रा-मान की ब्रुटियाँ ग्रनेक ग्राधिक ग्रुराइयों को जन्म देती हैं

### मुद्रामान के भेद

मुद्रा-मान दो प्रकार के होते हैं:—धातुमान (Metallic Standard) तथा पत्र-मान (Paper Standard) । प्रथम प्रकार के मुद्रा-मान में घातु का मूल्य-मान के रूप में प्रयोग किया जाता है, परन्तु दूसरे प्रकार के मान में पत्र,मुद्रा ही मूल्य के मान के रूप में प्रयोग की जाती है।



#### धातुमान के रूप-

धातुमान के कई रूप सम्भव हैं। प्रमुख रूप निम्न प्रकार हैं:---

### (१) एक-धातुमान (Monometallism) —

इस सुद्रा-मान में केवल एक ही धातु को मूल्य के मान के रूप में उपयोग किया जाता है। सैद्धान्तिक दृष्टिकोएा से तो किसी भी धातु को इस रूप में उपयोग किया जा सकता है, परन्तु व्यावहारिक जीवन में केवल सोने और चाँदी का ही उपयोग किया गया है। इङ्गलैंड ने सन् १६३१ तक और फांस ने सन् १६३६ तक सोने का मूल्य-मान के रूप में उपयोग किया है और चाँदी का उपयोग चीन के देश में हुआ है। सन् १८६३ तक भारत में भी रजत-मान (Silver Standard) था। सन् १६२७ और सन् १६३१ के बीच भारत में स्वर्णमान प्रचलित रहा है।

### एक-धातुमान के गुग्-

एक-घातुमान में सोने ग्रथवा चाँदी को मूल्य के मान के रूप में उपयोग किया गया है। सोने का उपयोग ग्रधिक सर्वव्यापी हुग्रा है। चीन, दक्षिणी ग्रमरीका के कुछ देशों ग्रोर भारत को छोड़ कर चाँदी का उपयोग बहुत ही कम हुग्रा है। बात यह थी कि सोने की ग्रपेक्षा चाँदी की पूर्ति ग्रधिक रही है ग्रोर इस कारण चाँदी का मूल्य ग्रपेक्षतन कम रहा है। एक-घातुमान संसार में विभिन्न रूपों में काफी लम्बे काल तक प्रचलित रहा है ग्रोर इस मान ने स्वर्णमान के ज्यन्तर्गत तो ज्यन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया था। इस मान के कई लाभ हैं, जिनमें से ग्रधिक महत्त्वपूर्ण निम्न प्रकार हैं:—

- (१) एक-घातुमान में सरलाता होती है, क्चोंकि केवल एक ही घातु को मूल्य के मान के रूप में उपयोग किया जाता है। ग्रतः लोगों की समभ में इसका चलन ग्रासानी से ग्रा जाता है। साथ ही, सोने ग्रौर चाँदी जैसी वहुमूल्य घातुग्रों का मुद्रा के रूप में उपयोग करने के कारण जनता का विश्वास भी ग्रधिक रहता है।
- (२) इस प्रणाली में एक ही घातु के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा होते हैं। यही कारण है कि येशम का नियम बहुत ही कम लागू होता है। दि-घातुमान में इस नियम के लागू होने का भय श्रधिक रहता है।
- (३) इस प्रगाली का सभी देशों द्वारा उपयोग होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा व्यवसाय में सुविधा रहती है। बड़े लम्बे समय तक स्वर्णमान ने संसार में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बनाये रखा है।

#### एक-धातुमान के दोष-

इन गुर्गों के साथ-साथ इस प्रगाली में कुछ महत्त्वपूर्ग दोष भी हैं। अनेक कारगों से एक-धातुमान श्रसन्तोषजनक है। प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं:—

- (१) संसार के सभी देश एक साथ इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्यों कि संसार में सोने ग्रथना चाँदी की कुल मात्रा सभी देशों का मुद्रा-मान बनने के लिए काफी नहीं है। कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि स्वर्ण-पाट-मान भी संसार के सभी देश ग्रहण नहीं कर सकते हैं।
  - (२) किसी भी मुद्रा-प्रगाली में लोच, ग्रर्थात् ग्रावश्यकता के समय मुद्रौ-विस्तार श्रथवा मुद्रा-संकुचन कर लेने का ग्रुगा बहुत महत्त्वपूर्गा होता है, परन्तु यदि सोने ग्रथवा चाँदी को मूल्य-मान के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसकी मात्रा में वृद्धि के बिना मुद्रा की पूर्ति को

बढ़ाना सम्भव नहीं हो सकता । संकट-काल में सोने अथवा, चाँदी को प्राप्त कर लेना कठिन होता है । यही कारण है कि प्रथम महायुद्ध के काल में अधिकाँश देशों को स्वर्णमान स्थिगित करना पड़ाथा।

(३) इस प्रणाली में कीमतों की स्थिरता को बनाये रखना कित होता है। किसी भी एक घातु की कीमत सदैव पूर्णतया स्थिर नहीं होती और जब मुद्रा-मान के ही मूल्य में स्थिरता न हो, तो फिर कीमतों की स्थिरता की ग्राशा करना निर्मुल है। संसार के ग्राधिक इतिहास से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न कालों में सोने ग्रीर चाँदी की कीमतों में भारी परिवर्तन होते रहे हैं। सन् १०० के ग्रास-पास ग्रीर प्रथम महायुद्ध के पश्चात् चाँदी की कीमतों काफी गिरी हैं। दूसरे कालों में चाँदी की कीमतों ऊगर चढ़ी हैं। कीमतों में स्थिरता बहुत ही कम रही है। सोने की कीमतों का इतिहास भी लगभग इसी प्रकार रहा है। प्रत्येक सोने की नई खान के पता लगने ग्रथवा खानों से सोना निकालने की नई विधि के ग्राविष्कार के साथ सोने की कीमतों गिरी हैं। इसी प्रकार सोने की किसी खान के समाप्त हो जाने ग्रथवा सोने के जहाजों के डूबने के साथ सोने की कीमतों ऊपर चढ़ी हैं।

### (२) द्वि-घातुमान (Bi-metallism)—

इस पद्धित में दो घातुत्रों को एक ही साथ प्रामाणिक घातुत्रों के रूप में उपयोग किया जाता है | वास्तव में संसार में सोने श्रौर चाँदी का ही इस प्रकार उपयोग किया गया है | दोनों घातुश्रों के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा तथा श्रसीमित विधिग्राह्य होते हैं और दोनों के बीच की विनिमय दर नियम द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। ऋण-दाता को यह श्रधिकार होता है कि वह ऋण का भुगतान सोने श्रथवा चाँदी किसी में भी कर सकता है।

सन् १००३ में फ्रांस ने द्वि-घातुमान ग्रहण किया था तथा सोने ग्रौर चाँदी के बीच १:१५ के का विनिमय अनुपात रखा था। सन् १८४६ तक तो यह पद्धित बिना किसी किठनाई के चालू रही, परन्तु सन् १८४६ ग्रौर सन् १८५० के बीच सोने की-बहुत सी ५ई खानों का पता चल गया था, जिसके कारण सोने की कीमतें गिर गई थीं। ग्रेशम के नियम की कार्यशीलता को रोकने के लिए फ्रांस को सोने ग्रौर चाँदी के अनुगत में परिवर्तन करना पड़ा था, परन्तु यह प्रयत्न बहुत सफल नहीं हो सका। सन् १८६५ में फ्रांस, इटली, बेल्जियम तथा स्विटजरलेंड ने सामूहिक रूप से द्वि-घातु-मान स्थापित करने का प्रयत्न किया था, परन्तु सन् १८७४ में चाँदी की कीमतों के तेजी से गिरने के कारण यह व्यवस्था भी हुट गई।

### (३) बहु-घातुमान (Multimetallism)—

बहु-धातुमान प्रणाली में कई घातुओं को एक ही साथ मूल्य-मान के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रत्येक घातु के सिक्कों की ढलाई स्वतन्त्र होती है और प्रत्येक घातु के सिक्कों की ढलाई स्वतन्त्र होती है और प्रत्येक घातु के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा तथा असीमित विधि-प्राह्म होते हैं। सभी घातुओं के बीच की विनिमय दर नियमानुसार निश्चित कर दी जाती है और ऋणदाता को किसी भी घातु में ऋण चुकाने का पूर्ण अधिकार होता है। व्यवहार में यह मुद्रा प्रणाली बहुत ही कठिन है, क्योंकि विभिन्न घातुओं की कीमतों में तुलनात्मक परिवर्तन होते रहने के कारण उनके बीच की विनिमय दरों को बनाये रखना कठिन होता है। यही कारण है कि ऐसा घातुमान किसी भी देश ने ग्रहण नहीं किया है, यद्यि इस मान में कीमतों की स्थिरता स्थापित करने तथा बनाये रखने की सम्भावना बहुत ग्रिषक होती है।

### ( ४ ) प्रादिष्ट मान (Fiat Standard)-

प्रत्येक प्रकार के घातुमान की यह विशेषता होती है कि प्रामाणिक हिक्के की कीमत घातु की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखी जाती है। उदाहरण के लिये, इङ्गलैण्ड में स्वर्णमान के अन्तर्गत ३ पौंड १७ शिलिंग और १० पैंस का मूल्य एक भ्रौंस सोने के बराबर था। भारत में २१ ६० ७ भ्राना १० पाई १ तोला सोने के बराबर होते थे। किन्तु, प्रादिष्ट मान में मुद्रा की इकाई की कीमत इस प्रकार स्वर्ण अथवा किसी अन्य घातु या घातुओं की एक निश्चित मात्रा के बराबर नहीं रखी जाती।

### प्रादिष्टमान की विशेषतायें—

श्री कैन्ट के अनुसार प्रादिष्ट मुद्रा की तीन विशेषतायें होती हैं—(१) वस्तु के रूप में इसका मूल्य लगभग न होने के बराबर होता है। (२) इसको ऐसी किसी वस्तु में नहीं बदला जा सकता है जिसकी कीमत उस मुद्रा की ग्रंकित कीमत के बराबर हो ग्रीर (३) इसकी क्रयः शक्ति को स्वर्ण ग्रथवा ग्रन्य किसी वस्तु की कीमत के बराबर नहीं रखा जाता है। किसी भी मुद्रा मान को प्रादिष्ट मान उस समय तक कहना किन होगा जब तक कि उसमें चलन की मुद्रा की कीमत स्वर्ण ग्रथवा ग्रन्य किसी धातु की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखी जाती है, यद्यपि वह स्वर्ण में परिवर्तनशील नहीं है। उदाहरण के लिये, सन् १६६२ तथा सन् १६७६ के बीच संयुक्त राज्य ग्रमरीका में प्रादिष्ट मान चालू रहा। ग्रमरीकन ग्रह-युद्ध के काल में जो ग्रीन-कैंक्स (Greenbacks) निकाल गये थे वे स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं थे ग्रीर न ही उनकी कीमत सोने की किसी निश्चत मात्रा के बराबर थी।

### प्रादिष्ट मान की स्थापना की रीतियां-

प्रादिष्ट मान की स्थापना दो प्रकार हो सकती है—(१) सरकार जानबूभ कर ऐसी मुद्रा की निकासी कर दे जिसका धातु-मूल्य बिल्कुल न हो या बहुत ही कस हो । ऐसी मुद्रा को निश्चित विनिमय दरों पर भ्रन्य किसी वस्तु में नहीं बदला जा सकता है भ्रौर इस प्रकार मुद्रा की इकाई का मूल्य दूसरी किसी भी वस्तु की कीमत से स्वतन्त्र रूप में निर्धारित होता है (२) साधारएतया ऐसा मान उस दशा में भी स्थापित हो जाता है जबकि एक-धातुमान वाला देश भ्रपनी मुद्रा की घातु में परिवर्तनशीलता समाप्त कर दे।

### प्रादिष्ट मान के लाभ-

साधारएातः प्रादिष्ट मान ग्रसाधारएा परिस्थितियों में स्थापित किया जाता है. परन्तु ग्राजकल के बहुत से भ्रर्थशास्त्रियों का विचार है कि इस मान को स्थायी रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस मत के पक्ष में प्रादिष्ट मान के निम्न लाभों का संकेत किया जाता है:--(१) घातुमान को ग्रपनाने में सरकारें कठिनाइयाँ श्रनुभव करती हैं। साथ ही, धातुमान में मुद्रा की धातु में परिवर्तन्शीलता केवल अम है, क्योंकि जब देश में ग्रसाथारए। परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो मुद्रा की परिवर्तनशीलता समाप्त हो जाती है। जनता का विश्वास भी घातु-कोष समाप्त हो जाने पर इस मुद्रा में से हट जाता है। ग्रतः ऐसी ग्रवस्था में यदि प्रादिष्ट मान को ही, जो कि ग्रसाधारण परिस्थितियों में भ्रपनाना पडता है, साधारण परिस्थितियों में भी भ्रपना लिया जाय तो कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा। (२) प्रादिष्ट मान को ग्रहरण करके मुद्रा और साख को इतनी मात्रा में उत्पन्न किया जा सकता है कि देश के मानव-साधनों को पूर्ण रोजगार प्रदान किया जा सके । अच्छे नियन्त्रण द्वारा प्रादिष्ट मुद्रा प्रणाली में धातु-मान की अपेद्धा अधिक लोच प्राप्त की जा सकती है। ग्रतः देश की ग्राधिक व्यवस्था को ग्रस्त-व्यस्त होने से बचाया जा सकता है। (३) इस मान में प्रबन्ध की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, क्योंकि एक देश की मौद्रिक ग्रौर ग्रायिक नीति किसी भ्रन्य देश पर निर्भर नहीं होती।

### प्रादिष्ट मान के दोष-

इस मान के विरुद्ध निम्न दो महत्त्वपूर्ण तर्क दिये गये हैं:—(१) यदि सभी देश इसे यहण कर लें, तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी उलमनें पैदा हो जायेंगी, क्योंकि विभिन्न देशों की मुद्राभ्रों का आपस में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने से उनके बीच विनिमय-दरों के परिवर्तन की कोई सीमा नहीं होती। (२) यह मय सदा ही रहता है कि प्रादिष्ट मुद्रा की अत्यधिक निकासी न हो जाय। यदि ऐसा हो गया, तो-देश की आर्थिक प्रणाली अस्त-व्यस्त हो जाती है, अशान्ति फैलती है और जनता का विश्वास मुद्रा में से हट जाता है।

### ( ५ ) सूचीबद्ध स्रथवा सूचक स्रंक मान (Tabular or Index Number Standard)—

इस प्रकार के मान का सुभाव फिशर (Fisher) ने दिया है। फिशर क विचार है कि एक ग्रच्छे मुद्रा-मान में देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत की स्थिरता बनाये रखने का गुण होना चाहिए। इस पद्धित के अनुसार एक आधार वर्ष चुन लिया जाता है और इस वर्ष की कीमतों के आधार पर देश में सामान्य कीमतों के निर्देशांक बनाए जाते हैं। इन निर्देशांकों के अनुसार भविष्य में मुद्रा का मूल्य नियत किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा का एक बार निश्चित किया हुआ मूल्य सदा के लिए स्थिर नहीं रहता। कीमतों के परिवर्तनों के साथ-साथ उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि स्थिगत शोधनों अथवा लेन-देन में समता बनी रहती है। ऋण-दाता अथवा ऋणी दोनों में से किसी को' भी हानि नहीं होती है।

उदाहरएास्वरूप, यदि कीमतों का निर्देशांक १०% ऊपर चढ़ जाता है तो इसका ग्रथं यह होगा कि मुद्रा ग्रथवा स्वर्णा की कीमतें १०% घट गई हैं। ऐसी दशा में सरकार सोने की नियम द्वारा निर्घारित कीमतों में १०% कमी कर देगी। फल-स्वरूप चलन की मात्रा घटेगी ग्रीर साख-मुद्रा में भी कमी ग्रा जायगी, जिसके कारएा मुद्रा की कीमत नीचे नहीं गिर सकेगी। इसी प्रकार कीमतों के घटने की दशा में मुद्रा की कीमत को ग्रावश्यक ग्रनुपात में बढ़ा देने से मुद्रा की कीमतों को ग्रीर ग्रागे घटने से रोका जा सकता है।

इस प्रगाली का महत्त्वपूर्ण गुण यही है कि मुद्रा के मूल्य तथा सामान्य कीमतों में स्थिरता लाई जा सकती है, परन्तु सब कुछ होते हुए भी यह व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि (१) सामान्य कीमतों के निर्देशांक (Index Numbers of General Prices) केवल भूतकालीन हो सकते हैं। वर्तमान ग्रथवा भविष्य के लिए उनका उपयोग केवल ग्रनुमानजनक फल ही दे सकता है, निश्चित फल नहीं दे सकता है; (२) इस मान में निर्देशांक मूल्य स्तर के परिवर्तनों को सूचित करते हैं, लेकिन यह सूचना गलत भी हो सकती है, क्योंकि निर्देशांक स्वयं ठीक नहीं बनाये जा सकते; ग्रौर (३) सरकार को निर्देशांक बार-बार बनाना पड़ता है, जिससे इस मान के प्रचलन में बहुत कठिनाई पड़ती है।

# (६) मिश्रित घातुमान (Symmetallism)—

इस घातुमान प्रणाली का सुकाव मार्शल की ओर से सन् १८५१ में रखा गया था। द्वि-घातुमान बहुधा ग्रेशम के नियम के लागू होने के कारण असफल रहता था, यद्यपि उस मान में अनेक गुण थे। मार्शन का यह सुकाव था कि (१) ऐसे घातुमान का निर्माण किया जाय जिसमें दो घातुओं को एक ही साथ मूल्यमान के रूप में उपयोग करके द्वि-घातुमान के सभी गुण प्राप्त किये जा सकें, परन्तु जिसमें ग्रेशम का नियम लागू न हो सकें, (२) देश की मुद्रा को सोने और चाँदी में बदल लेने की सुविधा नहीं रहनी चाहिए, और (३) ऐसी छड़ अथवा ऐसा पाँसा बत्यार होना चाहिए कि जिसमें सोने और चाँदी को एक निश्चित अनुपात में मिलाय। गया हो। देश की मुद्रा इसी छड़ या पाँसे में परिवर्तनीय होनी चाहिए इस प्रणाली के दो गुण हैं:—(१) सोने धौर चाँदी की कीमर्तों के तुलनात्मक परि-वर्तनों का मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और (२) क्योंकि एक ही सिक्का पाँसे के रूप में प्रामाणिक मुद्रा रहता है, इसलिए ग्रेशम का नियम लागू नहीं हो पाता।

इसमें तो सन्देह नहीं है कि इस प्रणाली में द्वि-धातुमान के सभी गुण होंगे और उसके दोष भी बड़े ग्रंश तक दूर हो जायेंगे, परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या यह व्यावहारिक है ? ग्रनुभव यह बताता है कि मार्शल का सुभाव केवल सैद्धान्तिक महत्त्व का है। किसी भी देश ने इस मान को उपयुक्त समभकर ग्रहण नहीं किया है।

(क) विशुद्ध द्वि-घातुमान (Bi-metallism)— द्वि-घातुमान भी संसार में काफी समय तक चालू रहा है, यद्यपि २० वीं शताब्दी के श्रारम्भ से किसी भी देश में इसका चलन दिखाई नहीं पड़ता। सन् १८०३ तक श्रमरीका में द्वि-घातुमान ही प्रचलित रहा है। फान्स ने सन् १८०३ तथा सन् १८७४ के बीच इसे प्रहण किया था। इस समय इस मान के पक्ष में बहुत ही कम लोग रह गये हैं। केवल संयुक्त राज्य अमरीका ने अपने चाँदी हितों की रक्षा के लिए सन् १६३४ तक द्वि-घातुमान को बनाये रखने का प्रयत्न किया था, परन्तु यह प्रयत्न सफल नहीं हो पाया था। श्रमरीका में भी सन् १६०० के पश्चात् द्वि-घातुमान को ग्रहण करना सम्भव नहीं हुआ।

## द्धि-धातुमान की विशेषताएँ —

द्वि-धातुमान की सफलता के लिए चार बातों की भारी आवश्यकता होती है — प्रथम, प्रत्येक द्वि-धातुमान देश को अपनी मुद्रा इकाई की कीमत सोने की निश्चित मात्रा के बराबर घोषित करनी पड़ती है और इसके साथ ही मुद्रा इकाई को चाँदी की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखना पड़ता है। उदोहरणस्वरूप, सन् १७६२ के अमरीकन मुद्रण नियम में एक डालर को २४'७५ ग्रेन सोने तथा ३७१'२५ ग्रेन चाँदी के बराबर घोषित किया गया था और इस प्रकार सोने और चाँदी की सरकारी विनिमय दर १:१५ रखी गई थी। दूसरें, सरकार को सोना और चाँदी दोनों के स्वतन्त्र मुद्रण तथा स्वतन्त्र वाजार (Free market) की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसा करने से देश के भीतर और देश के बाहर सोने और चाँदी दोनों ही के सिक्कों को अपरिमित विधि-ग्राह्य मुद्रा घोषित करना पड़ता है। चोथे, प्रत्येक प्रकार की पत्र-मुद्रा तथा साख-मुद्रा को सोने तथा चाँदी के सिक्कों में बदलने की गारन्टी देनी पड़ती है।

# द्वि-धातुमान के पच में एवं विपच में

## द्धि-धातुमान के पत्त में—

द्वि-घातुमान के समर्थंकों ने तीन कारणों से इस मान को एक-घातुमान की तुलना में अधिक उपयुक्त बताया है:—

(१) मुद्रा के सुरक्षित कोषों का विस्तार—जितना ही किसी मुद्रा के

पीछे घातु-कोष ग्रधिक होगा उतनी ही इसकी सुरक्षा भी ग्रधिक होगी। ग्रनुभव बताता है कि बहुत बार सोने के सुरक्षित कोषों की कमी के कारण एक-घातुमान वाले देशों को ग्रपनी मुद्रा की स्वर्ण परिवर्तनशीलता को स्थगित करना पड़ा है। यह निश्चय है कि यदि घातुमान तथा मुद्रा को घातु में बदलने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाता है, तो घातु-कोष काफी वड़े होने चाहिए। सोने ग्रौर चाँदी दोनों में से किसी भी एक घातु की मात्रा इस उद्देश्य के लिए काफी नहीं है, परन्तु दोनों घातुग्रों को सुरक्षित निधि बनाकर समस्या बड़े ग्रंश तक सुलक्षाई जा सकती है।

(२) की मतों में ग्रधिक स्थिरता—सोने के उत्पादन, ग्रासंचित कोषों भौर उपयोगों के प्रत्येक परिवर्तन का सोने की माँग भौर पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसकी कीमतों में भी परिवर्तन होते हैं। ठीक इसी प्रकार चाँदी की कीमतों पर भी उपरोक्त सभी कारगों का प्रभाव पड़ता है, परर्न्तु यह सम्भव है कि जिस समय सोने की कीमतें ऊपर चढ़ रही हैं, उस समय चाँदी की कीमतें नीचे गिर रही हों, श्रौर इसके विपरीत, जिस समय चाँदी की कीमतें ऊपर जा रही हैं, उस समय सोने की कीमतें नीचे गिर रही हों। ऐसी दशा में सोने और चाँदी के सामूहिक कोष की कीमत में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा। यदि एक ही घातु का कोष है तो सुरक्षित कोष की कीमत में भारी परिवर्तन होने का भय रहता है । जेवन्स(Jevons)ने इस सम्बन्ध में बड़ा ऋच्छा उदाहरणा दिया है। उनका कहना है कि यदि दो शराब के नशे में चूर व्यक्तियों को, जिनमें से एक दाई स्रोर को गिरता है स्रौर दूसरा बाई ग्रोर, ग्रापस में बाँध दिया जाय तो कम से कम कुछ समय तक दोनों के लिए सीधे खड़े होकर चलना सम्भव होगा, यद्यपि यह निश्चय है कि यदि दोनों व्यक्तियों में एक ही स्रोर गिरने की प्रवृत्ति है तो गिरना काफी भयंकर हो सकता है। इसी. प्रकार द्वि-धातु कोषों की मात्रा में उचावचनों (Fluctuations) की समभावना एक घातु के सुरक्षित कोषों की ग्रपेक्षा कम रहेगी, ग्रौर, क्योंकि मुद्रा के क्रूमूल्य निर्घारण में धातु-मुद्रा बड़ा महत्त्वपूर्ण काम करती है, पूर्ति की ग्रोर से मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का जोर कम रहेगा। इस दृष्टिकोगा से द्वि-घातुमान एक-घातुमान से ग्रच्छा है। द्वि-घातुमान के इस कार्य को हम उसका क्षयपूरक कार्य (Compensatory Action of the Double Standard) कहते हैं।

Action of the Double Standard) कहत है।

(३) विदेशी व्यापार की सुविधा—एक द्वि-घातुमान देश अपनी मुद्रा की कीमत सोने और चांदी में एक ही साथ निर्धारित करता है। इस कारण स्वर्णमान तथा रजत-मान दोनों ही प्रकार के देशों से देश की विदेशी विनिमय दर निश्चित करने और बनाये रखने में सुविधा होती है। यदि बहुमूल्य घातुओं के आयात और निर्यात पर किसी प्रकार के प्रतिदृत्य न लगाये जायें, तो एक बड़े अंश तक विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। साधारण दशाओं में एक-घातुमान के अन्तर्गत स्वर्णमान तथा रजतमान देशों के बीच विदेशी विनिमय दरों में भारी उच्चावचन होते रहते हैं। जब संसार में रजतमान देशों की संख्या काफी थी तो

उपरोक्त तर्क का महस्य काफी था, परन्तु रजतमान के संसार से बिदा हो जाने के पश्चात् भी यह कहा जा सकता है कि द्वि-घातुमान के कारणा सोना उत्पन्न करने वाले तथा चाँदी उत्पन्न करने वाले देशों के बीच विनिमय दरों की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।

(४) बैंकों को ग्रपने कोषों के संचालन में सुविधा—िद्व-घातुमान के ग्रन्तगँत बैंकों को ग्रपने कोषों (Reserves) के संचालन में बड़ी सरलता श्रोर किफायत हो जाती है, क्योंकि वे सोने या चाँदी किसी भी सिक्हे में ग्रपना कोष रख सकते हैं। साथ ही, मुद्रा की मात्रा ग्रधिक होने के कारण वे कम ब्याज पर व्यापारियों को रुपया उधार दे सकते हैं. जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है।

#### द्धि-धातुमान के विपच्च में-

द्वि-घातुमान के विपक्ष में तीन महत्त्वपूर्ण तर्क रखे जाते हैं :---

- (१) ग्रेशम के नियम की कार्यशीलता जब तक सारा संसार दि-घातु-मान को ग्रहण नहीं कर लेगा, तब तक किसी भी एक देश के लिए सोने ग्रीर चाँवी के विनिमय श्रनुपात को बनाये रखना सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी बाजारों में दोनों घातुग्रों की कीमतों में विपरीत दिशाग्रों ग्रथवा ग्रलग-ग्रलग ग्रनुपात में परिवर्तन होते रहेंगे। परिणाम यह होगा कि सोने ग्रीर चांदी के सरकारी विनिमय श्रनुपात तथा वास्तविक बाजारी ग्रनुपात में ग्रन्तर हो जायगा। एक घातु का दूसरी में ग्रितिमूल्यन हो जाता है ग्रीर ग्रेशम का नियम ग्रपनी पूरी शक्ति के साथ लागू होने लगता है। किसी भी एक घातु का ग्रायात ग्रथता निर्यात् लाभदायक हो जाता है, जिसके कारण देश में भी दोनों घातुग्रों की कीमतों में तुलनात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। विभिन्न कालों में दि-घातुमान देशों को इस प्रकार का ग्रनुभव हुग्रा है। ग्रेशम के नियम के कारण एक घातु के सिक्के बाजार से पूर्णंतया गायब हो सकते हैं ग्रीर इस प्रकार दि-घातुमान व्यवहार में एक-घातुमान ही रह जाता है।
  - (२) क्षितिपूरक कार्य में त्रृटि (Defect in the Compensatory Action of the Double Standard)—जब दो घातुग्रों को एक ही साथ मूल्य-मान के रूप में उपयोग किया जाता है तो इसके द्वारा कीमतों में जो स्थिरता ग्राती है वह द्वि-घातुमान के क्षयपूरक कार्य का परिएगाम होती है। एक घातु की कीमतों के गिरने के कारए। वस्तुग्रों ग्रौर सेवाग्रों की कीमतों में जो वृद्धि होने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वह इस कारए। इक जाती है कि दूसरी घातु की कीमत उसी समय बढ़ कर वस्तुग्रों ग्रौर सेवाग्रों की कीमतों को विपरीत दिशा में खींचती है। यही द्वि-घातुमान का क्षतिपूरक कार्य है। इसका महत्त्व हम द्वि-घातुमान के लाभों के सम्बन्ध में देख चुके हैं, परन्तु यह कार्य सदा ही सम्पन्न नहीं हो पाता। संसार के इतिहास में ऐसे ग्रनेक उदाहरए। मिलते हैं जबिक सोने ग्रौर चाँदी दोनों ही की

कीमतों में एक साथ एक ही दिशा में परिवर्तन हुए। ऐसी दशा में द्वि-घातुमान स्वयं

कीमतों में भारी उच्चावचन पैदा कर देता है। यह क्षतिपूरक कार्यं तभी सफल हो सकता है जबिक एक दि-घातुमान देश के पास दोनों घातुओं के इतने बड़े कोष हों कि भारी मात्रा में सोने अथवा चाँदी का निर्यान हो जाने पर भी किसी घातु की कमी अनुभव न हो। व्यवहारिक जीवन में किसी भी देश के पास दोनों घातुओं के इतने बड़े सुरक्षित कोषों का होना लगभग असम्भव ही होता है। यही कारण है कि यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर दि-घातुमान को स्थापित करने की ओर अनेक प्रयत्न हुए हैं, परन्तु सफलता कम ही रही है।

(३) व्यापारिक सौदों में गड़बड़ — द्वि-घातुमान में जब टकसाली अनुपात श्रीर बाजारी अनुपात में अन्तर हो जाता है, तो ऋ गदाता उस घातु में भुगतान लेना चाहते हैं, जिसका मूल्य चढ़ा हुआ है, जबिक ऋ गी उस घातु की मुद्रा में भुगतान देना चाहते हैं, जिसका मूल्य गिरा हुआ है। इस प्रकार लेन-देन के व्यवहारों में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

# द्वि-धातुमान के दोषों को दूर करने के उपाय—

द्वि-घातुमान का सबसे बड़ा दोष है ग्रेशम के नियम का लागू होना । इस दोष को दूर करने के लिये द्वि-घातुमान के समर्थकों ने निम्न उपाय सुभाये थे ग्रीर इन्हीं के प्राधार पर उन्होंने सन् १८७८ व सन् १८६२ के ग्रन्तेर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलनों में इस मान को ग्रन्तर्राष्ट्रीय ग्राधार पर ग्रपनाने का ग्राग्रह किया:—

- (१) जब कभी बाजार श्रीर टकसाली श्रनुपात में श्रन्तर हो तो टक-साली श्रनुपात में बाजार भाव के श्रनुसार परिवर्तन कर दिया जाय। इससे ग्रेशम का नियम लागू होने का ग्रवसर नहीं मिलेगा। वस्तुतः सन् १८४७—४२ में इसी उपाय का ग्रवलम्बन करके फ्रान्स ने ग्रपने यहाँ द्वि-घातुमान को स्थिर किया था।
- (२) यदि संसार के सभी मुख्य देशों में द्विधातुमान की स्थापना हो जाय तो येशम के नियम की कार्यशीलता को रोका जा सकता है, क्योंकि इस दशा में दिधातुमान की क्षतिपूरक क्रिया ग्रिधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करेगी, जिसके फन-स्वरूप सभी द्विधातुमान वाले देशों में बाजारी-श्रनुपात ग्रन्त में टकसाली ग्रनुपात के बराबर हो जायगा ग्रीर द्वि-धातुमान सफलतापूर्वक चलता रहेगा। निम्न उदाहरण से यह बात श्रिधिक स्पष्ट हो जायगी:—

मान लीजिये कि भारत में द्वि-घातुमान का चलन है तथा सोने और चांदी का टकसाली अनुपात व बाजारी अनुपात दोनों एक समान है और १:१५ हैं। यकायक चांदी की पूर्ति किसी कारण बढ़ जाती है। इसका परिग्णाम यह होगा कि सोने वै चांदी के बाजारी अनुपात में परिवर्तन हो जायगा। मान लीजिये कि यह बदल कर १:१६ हो गया। इस दशा में सोने का टकसाली मूल्य कम है, अतः लोग सोने के सिकों को पिघलाने लगेंगे और बाजार में इस सोने के बदले चांदी खरीद कर सिक्का ढलाई के लिये टकसाल भेजेंगे। इस प्रकार बाजार में चांदी की कमी और सोने की बहुतायत

हो जायगी, जिससे दोनों घातुग्रों का बाजार-श्रनुपात धीरे-धीरे कम होने लगता है श्रर्थात् १ इकाई सोने के बदले में बाजार में चाँदी धीरे-घीरे १६ इकाइयों से कम मिलने लगती है श्रीर ग्रन्त में इसका श्रनुपात टकसाली श्रनुपात के बराबर हो जाता है। बाजार से चाँदी का टकसाल को जानां श्रीर सोने का टकसाल से जाजार में लौटना द्विधातुमान का च्वतिपूरक प्रभाव है। यदि कोई श्रन्य शक्ति उसके मार्ग में बाधा न डा.वे तो यह प्रभाव तब तक कार्य करेगा जब तक बाजारी श्रनुपात श्रनुपात के बराबर न हो जाय।

किन्तु च्तिपूरक प्रभाव की कार्यशीलता के लिये यह आवश्यक हैं कि संसार के सभी देशों में सोने और चीदी का बाजारी अनुपात एक समान हो । जब द्विधानुमान अन्तरिष्ट्रीय आधार पर अपना लिया जायगा और सोने व चांदी का आयात-निर्यात स्वतंत्र होगा, तो किसी एक देश में सोने व चांदी के बाजारी अनुपात में परिवर्तन हो जाने पर विदेशों में इन धातुमों का आयात या निर्यात होने लगेगा और उक्त देश में फिर से बाजारी अनुपात टकसाली अनुपात के बराबर हो जायगा। जैसे मान लीजिये कि भारत में सोने का मूल्य अधिक हो गया, तो इस दशा में सारे संसार के बाजारों से सोना भारत को आने लगेगा और चांदी के सिक्के (चांदी के बदले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिमय होकर) विदेशों को जाने लगेंगे, जिससे भारत में सोने का मूल्य कम हो जायगा। इस प्रकार सब देशों के सहयोग से द्विधानुमान को सफलतापूर्वक कार्यशील रखा जा सकता है। परन्तु संसार के देश अपने व्यक्तिगत हितों की ओर ही अधिक देखने हैं, इसिलिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना कम रहती है।

#### निष्कर्ष-

श्राज के संसार में द्वि-घातुमान के समर्थंक बहुत ही कम हैं। वास्तविकता यह है कि स्वयं घातुमान ही संसार से उठ चुका है। संसार के लगभग सभी देशों में इस समय पत्र-मान ही प्रचलित है। घातुमान की स्थापना की ध्रोर किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न असफल ही रहे हैं। सन् १६४४ के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन में भी इस सत्य को स्वीकार कर लिया गया था। संसार घातुमान को ग्रहण करने में असमर्थ है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था के अन्तर्गत सोने को परोक्ष रूप में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में मूल्य का मापक तो स्वीकार कर लिया गया है, परन्तु प्रत्येक देश को पत्र-मुद्रा मान स्थापित करने तथा बनाए रखने की पूरी स्वतन्त्रता दी गई है। इम समय इस सम्बन्ध में यह विवाद कि एक घातु-मान तथा दि-घातुमान में से कौन सा अधिक उपयुक्त है, सारहीन है।

( ख ) पंगु द्वि-धातुमान (Limping Bi-metallism) ग्रथवा लंगड़ा -मान (Limping Standard)—यह द्वि-घातुमान की एक विशेष दशा होती है। यदि किसी देश में सोने त्रौर चाँदी दोनों के ही सिक्के त्रपरिमित विधि-याह्य रखे जाते हैं ऋौर दोनों के बीच की विनिमय दर निश्चित कर दी जाती है, परन्तु एक सिक्के की ढलाई स्वतन्त्र होती है ऋौर दूसरें की स्वतन्त्र नहीं होती है तो ऐसा मान 'लंगड़ा-मान' श्रथवा 'पंगु-मान' कहलाता है। इस प्रकार के मान का उदाहरण फांस से मिलता है। वहाँ सोने ऋौर चाँदी दोनों के ही सिक्के अपरिमित विधि-ग्राह्म थे, परन्तु चाँदी के सिक्कों की ढलाई स्वतन्त्र न थी। इस प्रकार को लंगड़ा मान इसलिए कहा जाता है कि जिस सिक्के की स्वतन्त्र ढलाई नहीं होती है वह कठिनाई के साथ चालू रहता है और केवल विसटता है। इस प्रकार मुद्रा-मान की एक टाँग बेकार रहती है।

(ग) व्यकल्पित या समानान्तर द्वि-धातुमान् (Parallel Bi-meta-llic Standard)—इस मान को समानिपाती माने पद्धित भी कहते हैं। यह पद्धित दि धातुमान का ही एक रूप है। इसमें भी धातुश्रों के सिक्के प्रचलन में रहते हैं श्रोर दोनों ही श्रामाणिक मुद्रा तथा श्रपरिमित विधि-प्राह्य होते हैं। दोनों धातुश्रों के सिक्कों की ढलाई भी स्वतन्त्र रहती है, परन्तु द्वि-धातुमान तथा व्यकल्पित मान में यह श्रन्तर होता है कि पहिले में तो दोनों धातुश्रों के बीच का विनिमय श्रनुपात नियमानुसार निश्चित कर दिया जाता है, जबिक दूसरे में ऐसा नहीं किया जाता। बाजारी कीमतों के श्राधार पर विनिमय श्रनुपात स्वयं निश्चित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार निर्वारत होने वाले श्रनुपात के श्राधार पर टकसाली विनिमय श्रनुपात निश्चित किया जाता है। यह टकसाली श्रनुपात स्थिर नहीं होता, बिक दोनों धातुश्रों की कीमतों के परिवर्तनों के साथ-साथ बदलता रहता है। इस प्रणाली में सबसे बड़ा दोष यही होता है कि दोनों धातुश्रों की टकसाली कीमत नियत नहीं की जाती, जिससे उसमें भारी परिवर्तन होते रहते हैं।

#### **QUESTIONS**

- 1. Write a note on-Bime allism.
  - (Agra, B. Com., 1957; Raj., B. A., 1955)
- Describe the essential features of bi-metallism and discuss whether prices are steadier under bi-metallism or under monometallism. (Agra, B. Com., 1955)
- 3. Discuss the essential features of bi-metallism and examine whether bi-metallic standards keep prices steadier than managementallic standards (Rai., B. Com., 1955)
- monometallic standards.

  4. What is meant by managed currency? Examine the advantages and disadvantages of the same. (Agra, B. A., 1956)

- 5. Write a note on the Compensatory Action of the Double Standard. (Agra, B. Com., 1956 Supp.)
  - 6. Distinguish between Monometallism and Bimetallism.

(Raj., B. A., 1956)

7. नोट लिखिए—प्रतिबन्धित चलार्थ (Sagar, B. A., 1957)

8. Write short note on—Parallel Standard.

(Raj., B. Com., 1940)

# .श्रध्याय ६ स्वर्णमान

(Gold Standard)

#### परिभाषा

एक-घातुमान का सबसे सुविख्यात तथा सबसे अधिक प्रचलित रूप स्वर्णमान रहा है। इस मान में सोने को मूल्यमान के रूप में उपयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र के अन्य शब्दों की भांति स्वर्णमान की भी अर्थशास्त्र में कई परिभाषाएँ की गई हैं। साधारण भाषा में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि किसी देश में देश की मुद्रा प्रत्यत्त अथवा परोद्या रीति से स्वर्ण में परिवर्तनशील घोषित की गई है तो देश का मुद्रामान स्वर्णमान है। नीचे कुछ प्रमुख लेखकों. द्वारा दी गई परिभाषाओं का उल्लेख किया जाता है:—

- (१) राबर्टसन—''स्वर्णमान वह ग्रवस्था है जिसमें कोई देश ग्रपनी मुद्रा की इकाई का मूल्य ग्रौर सोने की एक निश्चित मात्रा का मूल्य ऐक दूसरे के बराबर रखता है।''\*
  - ्री २) कालबोरन—''स्वर्णमान एक ऐसी व्यवस्था है जिसके ग्रन्तर्गत किसी

<sup>&</sup>quot;Gold Standard is a state of affairs in which a country keeps the value of its monetary unit and value of a defined weight of gold at an equality with one another." See: Robertson: Money, p. 97.

चलन की मुद्रा की प्रमुख इकाई निश्चित किस्म के सोने की एक निश्चित मात्रा में बदली जा सकती है न।" १

(३) कैमरर—"स्वर्णमान वह मौद्रिक व्यवस्था है जिसमें मूल्य की वह इकाई जिसमें कीमतों, मजदूरियों तथा ऋगों को व्यक्त किया जाता है तथा चुकाया जाता है, स्वतन्त्र स्वर्ण बाजार में सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर होती है।""

वास्तविकता यह है कि स्वर्णमान भी देश की घारा सभा द्वारा पास किये गये अन्य नियमों की माँति एक नियम है, जिसके अनुसार किसी मुद्रा अधिकारी का, चाहे वह केन्द्रीय बैंक हो स्रथवा कोषागार, यह उत्तरदायित्व रखा जाता है कि निश्चित दरों पर सोने को देश की मुद्रा में तथा देश की मुद्रा को सोने में बराबर बदलता रहे । उदाहरणस्वरूप, स्वर्णमान के अन्तर्गत प्रथम महायुद्ध से पहिले नियमानुसार बेंक भ्रॉफ इङ्गलेंड का यह उत्तरदायित्त्र था कि वह ४ २४०६ पौंड प्रति श्रोंस की दर पर प्रत्येक बेचने वाले से सोना खरीदे स्रौर ४ २४७७ पाँड प्रति स्रौंस की दर पर प्रत्येक खरीदने वाले को सोना बेचे। कभी-कभी देश की मुद्रा को स्वर्ण में परोद्धा रीति से भी बदला जाता है । मुद्रा भ्रघिकारी द्वारा देश की मुद्रा के बदले में एक निश्चित दर पर कोई ऐसी विदेशी मुद्रा दे दी जाती है कि जिसे निश्चित दरों पर सोने में बदला जा सकता है। सारांश यह है कि देश की मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तन-शीलता प्रत्वक्ष हो ग्रथवा परोक्ष, परन्तु प्रत्येक दशा में स्वर्णमान के ग्रन्तर्गत मुद्रा स्वर्ण में ग्रौर स्वर्ण मुद्रा में परिवर्तनशील होते हैं। ग्रतः हम यह कह सकते हैं कि स्वर्णमान वह मौद्रिक व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत देश की प्रचलित मुद्रा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रीति से स्वर्णं में परिवर्तनशील होती है ।<sup>3</sup>

# स्वर्णमान की विशेषतायें —

पूर्ण स्वर्णमान को स्थापित करने भ्रौर बनाये रखने के लिए एक देश के लिए नम्न कार्य करना ग्रावश्यक होता है:---

- (१) उसे ऋपने मुद्रामान ऋथवा ऋाधारमृत मुद्रा इकाई की कीमत सोने में परिभाषित करनी पड़ती है। इसके दो उपाय होते हैं: -(१) या तो मुद्रा इकाई में शुद्ध सोने की मात्रा का उल्लेख कर दिया जाता है,
- 1. "The Gold Standard is an arrangement whereby the chief price of money of a country is exchangeable with a fixed quantity of gold of a specific quality." See W. A. L. Coulborn: An Introduction to Money, p. 117.
- 2. Gold standard is a money system where the unit of value, in which prices & wages & debts are customarily expressed and paid, consists of the value of a fixed quantity of gold in a free gold market." Kemerrer: Gold and the Gold Standard, pp. 135-36.
- 3. Gold Standard is a monetary system in which the currency of a country is directly or indirectly convertible into gold.

जैसा कि इङ्गलैंड ने किया था, श्रीर (२) या सोने की टकसाली कीमत तय कर दी जाती है। श्रमरीका तथा भारत में दूसरी रीति श्रपनाई गई थी। श्रमरीका में १ श्रींस सोने की टकसाली कीमत ३५ डालर रखी गई थी श्रीर भारत में एक तोला सोने की सरकारी दर २१ रुपया ७ श्राने १० पाई।

- (२) मुद्रा ऋधिकारी को इस प्रकार निर्वारित कीमत पर यह सब सोना खरीदना चाहिए जो बेचने के लिए लाया जाता है।
- (३) मुद्रा श्रिधिकारी को इसी निश्चित कीमत पर श्रपरिमित मात्रा में सोना बेचने की व्यवस्था करनी चाहिए ।
- (४) देश में चालू मुद्रायें मुख्य मुद्रा में परिवर्तनशील होनी चाहिए। इसके लिए साधारणतया सभी मुद्राग्रों की ग्रापस में परिवर्तनशीलता रखी जाती है।
- (५) सोने के आयात और निर्यात की स्वतन्त्रता होनी चाहिए और उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए।

### स्वर्णमान के रूप (Forms of Gold Standard)—

स्वर्णमान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि देश की मुद्रा की कीमत सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखी जाय। मुद्रा की प्रत्येक इकाई की कीमत का, चाहे वह सोने के सिक्कों के रूप में हो अथवा अन्य धातुओं के सिक्कों के रूप में अथवा प्रन्य धातुओं के सिक्कों के रूप में अथवा पत्र-मुद्रा या साख-मुद्रा के रूप में, स्वर्ण इकाई से समुचित अनुपात होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा स्वर्णमान सम्बन्धी कुछ विशेष नियमों का बनाना आवश्यक होता है। साथ ही, सरकार को यह भी निश्चित करना होता है कि स्वर्णमान को किस रूप में प्रहर्ण किया जायगा।

स्वर्णमान के निम्न पाँच रूप सम्भव हैं। इन पाँचों में से प्रथम तीन रूपों में तो स्वर्णमान काफी लम्बे समय तक वास्तविक जीवन में प्रचलित रहा है, परन्तु चौथे रूप का ग्रविक महत्त्व भविष्य के लिए एक सम्भावना के रूप में ही श्रविक समभा जा सकता है। पाँचवाँ रूप सन् १९४६ से यारम्भ हुग्रा है, जबसे कि श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ग्रपना कार्य ग्रारम्भ किया।

## (I) स्वर्ण-चलन मान (Gold Currency Standard)

स्वर्णमान के इस रूप के कई नाम हैं, जैसे — स्वर्ण प्रचलन मान (Gold Circulation Standard), स्वर्ण टंक मान (Gold Coin Standard) तथा स्वर्णमान मुख्य (Gold Standard Proper)। प्रथम महायुद्ध से पहले यह मान इङ्गलैण्ड, संयुक्त राज्य प्रमरीका, फांस, जमंनी तथा यूरोप के अन्य देशों में प्रचलित था। अमरीका में सन् १६३३ तक इसका चलन रहा, यद्यपि सभी योरोपियन

ने प्रथम महायुद्ध के काल में इसका चलन बन्द कर दिया था श्रीर युद्ध के बाद मान को एक संशोधित रूप में ग्रहण किया था। इस मान की विशेषताएँ निम्न ार हैं:-

र्ण चलन मान की विशेषतायें -

(१) मुद्रा इकाई की कीमत सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर घोषित की जाती है। (२) सोने की ढलाई स्वतन्त्र होती है।

(३) भुगतान के लिए स्वर्ण मुद्रा अपरिमित विधि-याह्य होती है।

(४) देश में सोने के सिकों का प्रचलन होता है ग्रीर सभी गौए। सिक्के

तथा कागजी नोट जो देश के भीतर चालू होते हैं, स्वर्गा में परिवर्तन-शील होते हैं।

(५) सुभी प्रकार की साख-सुद्रा कीमत के ऋतुसार स्वर्गा में परिवर्तन-शील होती है। देश में प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा का चलन होता है, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रत्येक कागज के नोट के पीछे उसकी

कीमत का सोना भ्राड़ से रखा जाता है। (६) सोने के आयात और निर्यात पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं

होते हैं। (७) देश में चलन की मात्रा स्वर्ण निधि पर आधारित होती है। इसके घटने-बढ़ने के ग्रनुसार चलन की मात्रा में भी कमी या वृद्धि की जाती है।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सन् १६१४ से पहिले इङ्गलैण्ड में यही न प्रचलित था । सावरेन  $(\mathrm{Sovereign})$  के रूप में सोने के सिक्कों का प्रचलन था । ः सावरेन का वजन १२३<sup>.</sup>१७४४७ ग्रेन होता था श्रौर उसकी शुद्धता क्षेत्र होती थी। ाको अर्थ यह होता है कि सावरेन में ११३ हु<sup>नै</sup> च ग्रेन शुद्ध, सोना होता था और शेष

का। इस प्रकार ब्रिटिश मुद्रा में सावरेन की कीमत ३ पौंड १७ शिलिंग १०३ पैंस ती थी, परन्तु व्यवहार में एक ग्रौंस सोने के बदले में बैंक ग्रॉफ इङ्गलैंड केवल ३ ड १७ शिलिंग ६ पैंस ही देती थी, परन्तु यदि कोई व्यक्ति बैंक भ्रॉफ इङ्गलैण्ड से

ाना खरीदना चाहता था तो उसे एक ग्रौंस सोने के लिए ३ पौंड १७ शिलिंग १०<del>३</del> प्त देने पड़ते थे । इस व्यवस्था का परिगाम यह होता था कि ब्रिटिश सावरेन की ामत ११३ <sub>इ.च. उ</sub> ग्रेन सोने की कीमत के ग्रासपास ही बनी रहती थी।

स्वर्गामान की ऊगर दी गई विशेषताग्रों से स्वर्गा-चलन मान के कुछ महत्त्वपूर्ण णों का पता चलता है। प्रथम, क्योंकि मुद्रा की मात्रा सोने की मात्रा पर निर्भर ो, इस कारण इस स्वर्णमान में मुद्रा तथा साख की उत्पत्ति पर एक प्रभावशाली तिबन्ध रहता था भ्रौर विनिमय माध्यम की भ्रत्यधिक निकासी कठिन थी। ऐसी दशा

में पत्र-मुद्रा का उत्पादन निश्चित सीमा के भीतर ही रहता था। किसी भी केन्द्रीय सत्ता द्वारा व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा की पूर्ति पर जान-कर नियन्त्रण नहीं रखा जाता था। मुद्रा की पूर्ति को प्राकृतिक शक्तियों के स्वचालित नियन्त्रण पर छोड़ दिया जाता है और इन प्राकृतिक शक्तियों में सबसे अधिक महत्व स्वर्ण के उत्पादन ब्यय का था।

दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी ऐसा स्वर्णमान नियन्त्रण का कार्य करता विषा । जब तक संसार के विभिन्न देशों की मुद्राएँ स्वर्ण पर आधारित थीं, विदेशों विनिमय दरों के परिवर्तन स्वर्ण निर्यात तथा आयात व्यय की संकुचित सीमाओं के भीतर ही रहते थे । ऋणी देशों को विदेशों भुगतानों के लिए असीमित मात्रा में सोना भिल सकता था और सोना देकर वे अपने ऋणों को चुका भी सकते थे । महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि सोने के अथात और निर्यात के कारण सोने के कोषों में परिवर्तन होता रहता था । इसके द्वारा कीमतों में जो परिवर्तन हो जाते थे वे आगे चलकर व्यापाराशेष में परिवर्तन कर देते थे, जिससे सोने के आयात और निर्यात अपने आप ही रुक जाते थे ।

प्रथम महायुद्ध के काल में स्वर्ण-चलन-मान को बनाये रखना सम्भव न हो सका। प्रत्येक देश की सरकार को युद्ध-संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कागज के नोटों का छापना आवश्यक प्रतीत हुआ। यदि स्वर्ण-चलन-मान के नियमों का पालन किया जाता तो स्वर्ण-कोषों की वृद्धि के बिना कागज के नोटों का छापना सम्भव न था, परन्तु युद्ध काल में स्वर्ण-कोष कहाँ से आते? अतएव अधिकांश स्वर्ण देशों ने युद्ध-काल के लिए स्वर्णमान को स्थिगत कर दिया। युद्ध के पश्चात् यूरोप के जिन देशों ने स्वर्णमान को फिर से ग्रह्ण किया उनकी पत्र-मुद्रा युद्ध-काल में इतनी बढ़ाई जा चुकी थी कि उनके लिए पुराने ही रूप में स्वर्ण-मान को ग्रहण कर लेना असम्भव था। कठिनाई यह थी कि पत्र-मुद्रा की मात्रा के बढ़ जाने तथा सोने के स्टाकों के घट जाने के कारण यह सम्भव न था कि कागज के नोटों के पीछे उनकी कीमत के बराबर सोने की ग्राड़ रखी जा सके। इस कारण ग्रिधकाँश देशों को यह मान छोड़ना पड़ा था।

## स्वणं-चलन-मान के लाभ-

स्वर्ण-चलन-मान के समर्थकों ने इस मान के पक्ष में बहुत महत्त्वपूर्ण तर्क रखे हैं, इस मान के कुछ लाभ तो इस प्रकार के हैं कि कोई भी देश इस मान को स्थापित करके उन्हें प्राप्त कर सकता है, चाहे अन्य देश स्वर्णमान को ग्रह्ण करें ग्रथवा नहीं। इनके अतिरिक्त अन्य कुछ लाभ ऐसे हैं जो केवल उसी दशा में प्राप्त हो सकते हैं जबिक स्वर्णमान को अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर ग्रह्ण किया जाय। प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं:—

(१) जनता का विश्वास—स्वर्णमान के प्रहर्ण करने से देश की मुद्रा में जनता का विश्वास बना रहता है। इस विश्वास के कई कारण हैं—(१) स्वर्ण मुद्रा का निहित मूल्य (Intrinsic Value) भी ग्रंकित मूल्य के बराबर होता है और यही कारण है कि सभी व्यक्ति इसे सदा ही स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। (२) यदि मुद्रा के रूप में स्वर्ण मुद्रा की कीमत समाप्त हो जाय तो भी सिक्के की घातु का उपयोग किया जा सकता है। पत्र-मुद्रा में यह गुण नहीं होता। ग्रतः इसका विमुद्रीकरण हो जाय तो इसका कुछ भी मूल्य शेष नहीं रहता।(३) स्वर्ण चलन मान के ग्रन्तगंत जनता का यह विश्वास केवल सोने के सिक्कों के ही प्रति नहीं होता वरन पत्र-मुद्रा, तुच्छ धातु के सिक्कों तथा साख-मुद्रा पर भी होता है, क्योंकि इन्हें सोने में बदला जा सकता है, इसलिए वे भी विश्वासपद होती हैं।(४) विश्वास के बने रहने का एक कारण यह भी है कि मुद्रा की मात्रा स्वर्ण कोषों की मात्रा पर निर्भर होती है। बिना ग्रधिक सोना प्राप्त किए मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता। इस कारण पत्र-मुद्रा की ग्रद्रा की ग्रद्रा की नहीं उठता है।

(२) मुद्रा-प्रगाली की स्वचालकता (The Automatic Working of the Monetary System)—स्वर्ण-चलन-मान को स्वचालक मान कहा जाता है। प्रो० कैनन (Cannan) के शब्दों में यह मान 'मूर्स सिद्ध तथा मक्कार सिद्ध' (Fool-proof and Knave-proof) है। इसका अर्थ यह होता है कि स्वर्णमान देश की मूर्खता अथवा बेईमानी का भी इस मान के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मान को चालू रखने के लिए किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वयं अपना संचालन करता है। यदि किसी स्वर्णमान देश की सरकार गलती करती है या अन्य स्वर्णमान देशों को घोखा देना चाहती है तो भी स्वर्णमान के संचालन में गड़बड़ी नहीं पड़ती, क्योंकि यह मान गलती से उत्पन्न होने वालों स्थित को स्वयं सुधार लेता है और घोखेबाजी को फली- भूत नहीं होने देता। जो लोग इस सिद्धान्त में विश्वास करते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप सदा ही अनुचित होता है उनके दृष्टिकोग से तो यह मान बड़ा ही उपयुक्त है, क्योंकि इसमें मुद्रा की पूर्ति स्वर्णकोषों पर निर्भर होती है, न कि स्वर्णमान देश की सरकार की इच्छा पर। स्वर्ण कोषों को बढ़ाए बिना मुद्रा की मात्रा नहीं बढ़ाई जा सकती है।

स्वर्ण-चलन-मान में स्वचालकता लाने के लिए भी किसी विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार को विधान के अनुसार स्वर्ण-कोषों के सम्बन्ध में केवल कुछ नियम बना देने आवश्यक होते हैं और तत्पश्चात् इन नियमों का पालन करते रहने मात्र से ही स्वर्णमान अपने आप चलता रहता है। देखना केवल इतने ही पड़ता है कि देश की मुद्रा में स्वर्ण-कोषों की मात्रा के अनुसार परिवर्तन किए जायें और सोने के आयात-निर्यात पर से सभी प्रकार के प्रतिबन्ध हटा लिए जायें। इन दोनों नियमों का पालन करते रहने से स्वर्णमान में स्वचालकता आ जाती है।

- (३) देश में कीमत स्तर की स्थिरता— स्वर्ग-चलन-मान के पक्ष में सबसे अधिक बलशाली तर्क यह रखा जाता है कि इस मान द्वारा देश के भीतर कीमत-स्तर की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के घटने-बढ़ने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। इसका कारण यह वताया जाता है कि आर्थिक प्रणाली के अधिकांश दोप मुद्रा की कयः शक्ति के परिवर्तनों के ही परिणाम होते हैं। इन परिवर्तनों से देश का आर्थिक साम्य भद्ध हो जाता है और आर्थिक जीवन को गहरी चोट पहुँचती है; परन्तु जब सोने का मूल्यमान के रूप में उपयोग किया जाता है, तो कीमतों के घटने-बढ़ने का भय कम रहता है, क्योंकि कीमतें देश में सोने की मात्रा पर निर्भर होती हैं और सोने की मात्रा में बहुत ही कम परिवर्तन होते हैं और अन्य वस्तुओं की तुलना में उसकी कीमत में काफी स्थिरता रहती है। संसार की वार्षिक स्वर्ण उत्पत्ति संसार में सोने की कुल मात्रा की तुलना में इतनी कम है कि सोने की कीमतों में सामयिक (Seasonal) तथा अल्पनालीन परिवर्तन तो बहुत ही कम होते हैं।
- (४) विदेशी विनिमय दर की स्थिरता—स्वर्णमान का यह गुरू विदेशी व्यापार से सम्बन्धित है। विदेशी व्यापार विदेशी विनिमय दरों पर श्राधारित होता है। यदि इन विनिमय दरों में ग्रस्थिरता रहती है, तो विदेशी व्यापार का विस्तार नहीं हो पाता और अन्तर्शिय ऋण संसार के देशों को सीमित मात्रा में ही मिल पाते हैं। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् श्रीर मुख्यतया स्वर्णमान के परित्याग के पश्चात् विदेशी व्यापार में जो भारी कमी हुई है, वह विनिमय दरों की श्रास्थिरता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब सभी देशों में स्वर्णमान का चलन होता है और उनली मुद्राओं की कीमतें सोने की कीमतों पर श्राधारित होती हैं तो उनके बीच की पारस्पिक विनिमय दरों में स्वयं ही स्थिरता श्रा जाती है। यह स्वर्णमान वा एक ऐसा ग्रुण है जिसे सभी स्वीकार करते हैं। विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करने के श्रन्य सभी प्रयत्न पूर्ण त्या सफल नहीं हो पाए हैं। श्रन्य कोई भी उपाय विनिमय दरों के घटने-बढ़ने को नहीं रोक पाया है।

## स्वर्ण-चलन-मान के दोष-

प्रथम महायुद्ध के काल में तथा उसके बाद भी इस स्वर्णमान प्रणाली की काफी भ्रालीचना हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार के स्वर्णमान के लाभ काल्पनिक हैं। व्यवहार में इस मान के बहुत से दीप दृष्टिगोचर हुए हैं। भ्रभेरिका को छोड़ूकर सभी पाश्चात्य देशों को प्रथन महायुद्ध काल में इसे स्थिगत करना पड़ा था। वैसे भी इस मान की सफलता एक बड़े भ्रंश तक संसार के विभिन्न देशों के पारस्परिक सहयोग पर निभैर होती है, जो सरल नहीं है। प्रमुख दोषों की गंगना निम्न प्रकार की जा सकती है:—

(१) स्वर्ण-चलन-मान देश की मुद्रा प्रणाली को बेलोच बना देता है— बिना स्वर्ण-कोषों में बुद्धि किए चलन की मात्रा को बढ़ाना सम्भव नहीं होता, जबकि युद्ध अथवा अन्य राष्ट्रीय संकट के समय यह आवश्यक हो सकता है कि चलन की मात्रा को बढ़ाया जाय । ऐसी दशा में किसी देश के सम्मुख तीन ही मार्ग होते हैं :—प्रथम, देश को संकटों से निकालने का प्रयत्त ही न किया जाय, जिसे कोई भी देश पसन्द नहीं करेगा । दूसरे, स्दर्शमान के नियमों का उलंघन किया जाय, जिससे स्वर्शमान की स्वचालकता समाप्त हो जायगी और तीसरे, स्वर्शमान के संचालन को स्थगित कर दिया जाय, जिससे कि आवश्यकतानुसार मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जा सके । यही कारण है कि स्वर्शमान के आलोचकों ने इसे 'अनुकूत परिस्थित का मित्र' (Fair Weather Friend) कहा है । साधारण परिस्थितियों में तो यह मान ठीक रहेगा, परन्तु कठिनाई के समय यह साथ छोड़ देगा । आर्थिक संकट के काल में बहुबा इसे स्थगित कर देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ऐसे काल में मुद्रा की मात्रा में बिना स्वर्शनकों पर घ्यान दिए ही वृद्धि या वमी करना आवश्यक हो जाता है।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव-स्वर्ण-चलन-मान का एक भारी गुए। उसकी स्वचालन प्रकृति बताया जाता है। प्रथम महायुद्ध से पूर्व निस्सन्देह स्वर्ग्-मान स्वचालक ही था, परन्तु स्वर्णमान के समर्थक यह भूल जाते है कि यह गुरा तभी सम्भव हो सकता है. जबिक संसार के देशों के बीच सहयोग हो श्रीर सभी देश स्वर्ण-मान के नियमों का पालन करें। यदि कोई देश सोने के निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगाता है अथवा देश में चलन की मात्रा को स्वर्ण-कोषों की मात्रा के अनुपात में नहीं बदलता. तो यह स्वचालकता समाप्त हो जाती है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् सभी का यह अनुभव रहा है कि कोई भी देश स्वर्णमान के नियमों का पालन करने में अपना किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं समभता । कुछ कारणों से प्रथम महायुद्ध के पश्चात् कुछ देशों के लिए स्वर्णमान के नियमों का पालन करना सम्भव भी न था। कुछ देशों ने सोने के इतने बड़े कोष जमा कर लिये थे कि उनके अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ाने से भीषए। मूद्राप्रसार फैल सकता था. जिससे कीमतें काफी ऊँची चढ़ जातीं। इसके विपरीत कुछ देशों के पास सोना इतना कम रह गया था कि अनुपात में चलन को घटाने से भयङ्कर मुद्रा-संक्चन होने का भय था, जिससे कि कीमतें काफी नीचे गिरतीं ग्रौर बेरोजगारी बढती। दोनों ही दशाग्रों में स्वर्णमान की स्वचालकता पर देश की नौका को छोड देना घातक हो सकता था और इसीलिए प्रबन्धित (Controlled) मुद्रा-प्रगाली को ग्रहण करना ग्रावश्यक था।

(३) कीमतों की स्थिरता काल्पनिक है—कुछ झालोचकों का कहना है कि देश की मुद्रा के मूल्य को सोने की एक निश्चित मात्रा के मूल्य के बराबर रखने की नीति स्वयं कीमतों की स्थिरता को भंग कर देती है। ऐसी नीति का अपनीना श्रंघेरे में छलाँग लगाना है, क्योंकि यह निश्चय है कि सोने की कीमतों के प्रत्येक परिवर्तन के साथ-साथ अन्य वस्तुओं के कीमत-स्तर में भी अवश्य ही परिवर्तन होंगे भीर सोने की कीमतों अनेक कारगों से बदल सकती हैं। जैसे कि नई खान की खोज तथा पुरानी खान की समाति, सोने के निकालने की विधि में सुधार और सोने के

उपयोगों में परिवर्तन । इस प्रकार जब स्वयं सोने की कीमतें स्थिर नहीं रह पाती हैं तो फिर ग्रन्य कीमतें कैंसे स्थिर रहेंगी ?

- (४) स्वर्गा-कोषों का स्रसमान वितरगा—यद्यपि यह तो सभी जानते हैं कि सोने का वार्षिक उत्पादन संसार में सोने की कुल मात्रा की तुलना में बहुत ही कम है स्रोर सोने की कीमतों में साधारणतया ग्रन्य वस्तुओं की कीमतों की विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हैं, परन्तु सबसे बड़ी किनाई यह है कि स्वर्ण-कोषों का संसार के विभिन्न देशों के बीच बड़ा ही ग्रसमान वितरण है। इसके स्रतिरिक्त स्वर्ण के वार्षिक उत्पादन का संसार के विभिन्न देशों के बीच उनकी जन-संख्या, वाणिज्य प्रथवा मुद्रा श्रावश्यकतात्रों के अनुसार वितरण नहीं होता। इस समय संसार की सम्पूर्ण स्वर्ण मात्रा का दो-तिहाई से भी ग्रधिक भाग श्रकेले श्रमरीका के पास है। वितरण की यह श्रसमानता कीमत स्तर में स्थिरता उत्पन्न नहीं होने देती।
- ( ५ ) कीमतों तथा विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता के लिए स्वर्णा-मान आवश्यक नहीं है—बहुत से आलोचक इस बात पर भी जोर देते हैं कि यदि उद्देश्य यही है कि कीमत-स्तर में स्थिरता रहे और विदेशी विनिमय दरों में भारी परिवर्तन न होने पायें, तो इसके लिए प्रविन्धत मुद्रा-प्रणाली स्वर्णमान की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है, क्योंकि ऐसी प्रणाली में संसार के विभिन्न देशों के बीच मौद्रिक सहयोग स्वर्णमान की अपेक्षा अधिक सफल हो सकता है। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष बिना स्वर्णमान की स्थापना के ही आवश्यक काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि कीमतों की स्थिरता सभी दशाओं में लाभदायक नहीं होती है। एक अंश तक कीमत-स्तर में भी लीच का रहना आवश्यक होता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कीमतों को घटाया बढ़ाया जा सके। इस प्रकार स्वयं विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता भी दोषों से खाली नहीं है।

# (II) स्वर्ण-पाट-मान-ग्रथवा स्वर्णधातुमान (Gold Bullion Standard)

स्वर्ण-पाट-मान को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ—

यह मान स्वर्ण-चलन-मान का ही एक परिवर्तित रूप हैं। इशका आविष्कार प्रथम महायुद्ध के पश्चात हुआ था और अमरीका के अतिरिक्त अन्य सभी स्वर्णमान देशों ने इसे स्वीकार किया था। युद्ध के काल में यूरोप के देशों को चलन के विस्तार की आवश्यकता पड़ी थी, ताकि मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जा सके, परन्तु स्वर्णमान के स्थिमों का पालन करने के लिए उतनी ही कीमत का सोना सरकारी कोष में जमा करना आवश्यक था जितनी कीमत के कागज के नोट निकाल जाते थे और इसके लिए अधिकांश देशों के पास स्वर्ण-कोष काफी न थे, इसलिए स्वर्णमान को युद्धकाल के लिए स्थिगत कर दिया गया था। युद्ध के उपरान्त स्वर्णमान को पुनः स्थापित करने का प्रश्न उठा, परन्तु इङ्गलैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों के पास युद्धकाल में निकाली

गई समस्त चलन को १००% ग्राङ प्रदान करने के लिए काफी मात्रा में सोना न था। यह भी भय था कि यदि स्वर्ण-कोषों की प्राप्त मात्रा के अनुसार मुद्रा में कमी की गई तो भारी मुद्रा-संकुचन होगा. जिससे कीमते घटती ग्रीर उद्योग, व्यापार तथा मज-दूरियों में भारी मन्दी आ जाती। अधिकाँश देश यही चाहते थे कि मुद्रा की प्रस्तुत मात्रा में कमी किये बिना ही स्वर्णमान को पुनः ग्रहण कर लिया जाय। इस दशा में स्वर्ण-चलन-मान की स्थापना का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, ग्रतएव स्वर्णमान का एक नया रूप निकाला गया जिसमें अपेक्षतन थोड़े से स्वर्ण-कोषों की आवश्यकता पड़ती थी ग्रौर कीमतों में भारी उथल-पृथल किये बिना ही स्वर्गामान स्थापित हो जाता था । यही स्वर्ण पाट-मान था । इस मान की प्रमुख विशेषतायें निम्न प्रकार हैं-

# स्वर्ण पाट मान की विशेषतायें—

- (१) इस स्वर्णमान में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता है, देश के भीतर तुच्छ घातुश्रों के सिक्के श्रीर कागजी नोट चलते हैं. परन्तु इन सिक्तों तथा नोटों की कीमत स्वर्ण में सूचित की जाती है।
- (२) सोने की ढलाई स्वतन्त्र नहीं होती है। (३) कागजी नोटों के पीछे १००% स्वर्ग निधि ऋथवा ऋाड़ नहीं
  - होती । कुल पत्र-मुद्रा का एक निश्चित प्रतिशत, जैमे ३०% ग्रथवा ४०% ही सोने में रखा जाता है. परन्त सरकार सभी कागजों के नोटों को निश्चित कीमत पर सोने में बदलने का वचन देती है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह केन्द्रीय बेंक भ्रथवा
    - कोषागार से नोटों के बदले में सोना खरीद ले। शत-प्रतिशत स्वर्ण **ब्रा**ड़ न होते हुए भी नोटों की परिवर्तनशीलता इस कारण सम्भव हो जाती है कि किसी समय विशेष में कूल पत्र-मुद्रा का एक छोटा सा भाग ही स्वर्ण में बदलने के लिये लाया जाता है। मुद्रा श्रधिकारी पर जनता का विश्वास होने के कारण कागज के सभी नोट सोने में
- बदलने के लिए नहीं लाये जाते और वे भ्रपने भ्राप ही चालू रहते हैं। ( ४ ) सोने की कीमतें सरकार द्वारा निश्चित कर दी जाती हैं ऋौर इन नियत कीमतों पर सरकार असीमित मात्रा में सोना खरीदने और बेचने की व्यवस्था करती हैं। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो एक व्यक्ति सरकार से किसी भी मात्रा में सोना खरीद सकता है. परन्तू व्यवहार
  - में सरकारी प्रधिकारियों की सुविधा, मितव्ययिता तथा बार-बार सोना खरीदने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए एक न्युनतम् मात्रा निश्चित कर दी जाती है, जिससे कम मात्रा में एक बार सोना नहीं बेचा जाता । इङ्गलैंड में यह न्यूनतम् मात्रा ४०० श्रींस रखी गई थी ग्रौर भारत में १,०५६ तोले ग्रथवा ४०० ग्रौंस । उप-रोक्त मात्रा में सोने की छड़ें प्रथवा सिलें बेची जाती थीं।

(५) सरकार यह प्रयत्न करती है कि विदेशी भुगतानों के लिए सोनां प्राप्त करने में किसी को भी कठिनाई न हो । इस उद्देश्य से सरकार सोने के कोषों को जमा करती है। इन कोषों का उपयोग विशेषकर विदेशी भुगतान के लिए ही किया जाता है परन्तु ग्रावश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग ग्रन्थ प्रकार भी किया जा सकता है।

इस प्रकार स्वर्ण-पाट-पान में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता है। देश में सांकेतिक सिक्के तथा कागज के नोट चालू होते हैं, परन्तु सभी प्रकार की सुद्रा को सरकार द्वारा निश्चित दरों पर सोने की सिलां ख्रथ्या सोने की छड़ों में बदलने की गारन्टी दी जाती है। इक्क लैंड ने इस मान को सन् १६२५ में स्वीकार किया। उस देश में नोटों को ३ पाँड १७ शिलिक्स १०६ पेंस प्रति ध्राँस की दर पर चार-चार सो धाँस की सोने की सिलों में बदलने की व्यवस्था की गई थी। भारत ने यह मान सन् १६२७ में ग्रहण किया ध्रोर भारत। सरकार ने भी मुद्रा को २१ रुपये ७ ध्राने १० पाई फी तोला की दर पर ४००-४०० ध्राँस की सोने की सिलों में बदलने की गारन्टी दी थी। सन् १६३१ तक यह मान दोनों देशों में प्रचलित रहा, परन्तु इस वर्ष इक्स लैंड ने इसका परित्याग किया। भारत ने इक्स लैंड का ध्रनुकरण किया ध्रोर घीरे-घीरे संसार के सभी देशों ने स्वर्णमान प्रणाली तोड़ दी। संयुक्त राज्य ग्रमरीका ने सन् १६३३ तक स्वर्णमान चलाया। फांस ने सबसे ध्रन्त में इसका परित्याग किया ध्रोर सन् १६३६ के पश्चात् यह मान संसार से उठ खड़ा हुग्रा।

### स्वर्ण-पाट-मान के लाभ-

स्वर्ण-पाट-मान को कुछ लेखकों ने कुछ दिशाश्रों में स्वर्ण-चलन मान से भी श्रच्छा बताया है। कहा जाता है कि इस मान में स्वर्ण-चलन-मान के सभी ग्रुणों के श्रितिरिक्त कुछ श्रीर भी लाभ होते हैं।

- (१) स्वर्णा के उपयोग में मितव्ययिता—इसके अन्तर्गत सोने के सिकों का प्रचलन नहीं होता, जिसके तीन प्रत्यक्ष लाभ होते हैं: प्रथम, सिक्कों के मुद्रण का व्यय बच जाता है। दूसरे, प्रचलन के अन्तर्गत घिसावट द्वारा सोने का नाश नहीं होता है। तीसरे, सोने के उपयोग में बचत होती है और देश का सारा सोना सोने के राष्ट्रीय सुरक्षित कोषों के काम आ जाता है।
- (२) स्वर्णा का उपयोग सार्वजिनक हित के लिए—स्वर्ण-पाट-मान के समर्थक इस मान को इस कारण भी ग्रिधिक उपयुक्त बताते हैं कि इसमें सोना छोटे-छोटे व्यक्तिगत कोषों में जमा होने के स्थान पर सरकारी कोषागार ग्रथवा देश की केन्द्वीय बैंक में एक साथ जमा हो जाता है। इन लोगों का विचार है कि सोने के सिक्कों के प्रचलन ग्रौर उनकी व्यक्तिगत जोड़ से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। साधारण परिस्थितियों में सभी लोग पत्र-मुद्रा तथा सांकेतिक सिक्कों के ही उपयोग

को अधिक पसन्द करते हैं। केवल असाधारण परिस्थितियों में सोने के सिक्कों का उपयोग किया जाता है, परन्तु ऐसे काल में सरकारी कोष में ही सोने का जमा रहना अधिक अच्छा होता है। इससे एक ओर तो मुद्रा पर विश्वास बना रहता है और दूसरी और सोने के कोषों का व्यक्तिगत हितों के लिए उपयोग न होकर सामान्य तथा सार्वजनिक कल्याण के लिए उपयोग होता है।

- (३) मुद्रा पद्धित में लोच—यह मान मुद्रा-पद्धित में लोच उत्पन्न करता है, क्यों कि चलन और मुरक्षित कोषों के बीच के अनुपात में परिवर्तन कर देने से बिना सोना प्राप्त किये अथवा खोये भी चलन की मात्रा में परिवर्तन किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़े स्वर्ण-कोषों वाले देश भी बिना किठनाई के स्वर्णमान के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संसार के विभिन्न देशों के बीच स्वर्ण-कोषों के असमान वितरण के होते हुए भी इस पद्धित द्वारा स्वर्ण-मान को भली-भाँति चालू रखा जा सकता है। निश्चय ही इस प्रणाली में स्वर्ण चलन मान की तुलना में बहुत कम स्वर्ण कोषों से काम चल सकता है।
- (४) विनिमय दर की स्थिरता—विनिमय दरों की स्थिरता के लिए सोना प्रचलन में रहने की अपेक्षा मुद्रा-संचालक के पास निधि के रूप में होना अधिक उपयोगी होता है। इस दृष्टिकोण से भी स्वर्ण-पाट मान अधिक उपयुक्त है।
- ( १ ) स्वचालकता— स्वर्णं चलन मान पद्धित की भाँति स्वर्णं-पाट-मान में भी स्वचालकता का ग्रुण होता है। स्वर्णमान के नियमों का पालन करने से इस मान पर भी बाहरी हस्तक्षेप का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि जिस समय मुद्रा की माँग कम होती है, उस समय लोग सोना खरीदते हैं, जिसके कारण स्वर्णं-कोषों में कमी भ्रा जाती है भ्रौर चलन की मात्रा के घट जाने के कारण चलन की पूर्ति फिर उसकी मांग के बराबर हो जाती है। जिस काल में मुद्रा की माँग श्रीवक होती है, उस काल में लोग सोना बेचते हैं, जिससे स्वर्णं-कोषों में दृद्धि होती है भ्रौर चलन की मात्रा बढ़ जाने के कारण मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ जाती है। इस प्रकार मांग भ्रौर पूर्ति का समा-योजन हो जाने के कारण कीमत स्तर तथा विनिमय दरों की स्थिरता बनी रहती है भीर कोई भी त्रुटि स्वयं ही दूर हो जाती है।

### स्वर्ण-पाट-भान के दोष-

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् इसी मान को श्रादर्श मान समभा गया था, क्यों कि संसार में सोने की मात्रा इतनी नहीं थी कि युद्ध-कालीन मुद्रा विस्तार को बनाये रखते हुए भी स्वर्णमान को उसके पुराने रूप में ग्रहण किया जा सके। परन्तु इस मान में कुछ गम्भीर दोष भी हैं श्रीर शायद इन्हीं दोषों के कारण पुनः स्थापना के ६ वर्ष के भीतर ही स्वर्णमान पद्धति भङ्ग हो गई। प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं:—

(१) केवल ग्रनुकूल परिस्थितियों का मान - स्वर्ण-चलन मान की भाँति

यह मार्न भी साघारण परिस्थितियों के ही लिए उपयुक्त है। विशेष परिस्थितियों श्रथवा संकटकाल में इसे बनाये रखने में भी कठिनाई होती है।

- (२) जनता का कम विश्वास—इस मुद्रा-मान पर जनता का विश्वास स्वर्ण-चलन-मान की अपेक्षा कम होता है। देश की मुद्रा सोने से परोक्ष रूप में ही सम्बन्धित होती है। स्वर्ण-चलन मान की भांति सोना सामने उपस्थित नहीं होता। सामने तो कागज के नोट और सांकेतिक सिक्के होते हैं। केत्रल इन सिक्कों को बदल कर सोना प्राप्त किया जा सकता है।
- (३) सरकारी हस्तक्षेप की स्रावश्यकता—स्वर्ण-चलन-मान की अपेक्षा इस पढ़ित में सरकारी हस्तक्षेप की स्रावश्यकता भिष्ठिक पड़िती है, जिसके कारण भूत तथा घोले के लिए श्रिष्ठिक स्रवकाश रहता है और उनका प्रभाव भी पूर्ण रूप में दूर नहीं किया जा सकता है।
- (४) ग्रिधिक व्ययपूर्ण—यह प्रणाली ग्रिधिक व्ययपूर्ण होती है। एक श्रोर तो इसमें भी सोना सुरक्षित कोषों में बेकार पड़ा रहता है श्रोर दूसरी श्रोर साख-मुद्रा पर नियन्त्रण रखने तथा मुद्रा का प्रबन्ध करने के लिए काफी निरीक्षण तथा व्यय की ग्रावश्यकता पड़ती है।

स्वर्णमान के कुछ और भी रूप हो सकते हैं, जो इस प्रणाली की अपेक्षा अधिक मितव्ययी होते हैं और इससे भी कम स्वर्ण-कोषों की सहायता से चलाये जा सकते हैं, मुख्यतया स्वर्ण-विनिमय-मान (Gold Exchange Standard) एक ऐसा ही मान है।

स्वर्ण चलन-मान तथा स्वर्ण-पाटमान की तुलना— दोनों के प्रमुख भेद निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायेंगे :—

## स्वर्गा चलन-मान

- (१) सोने का उपयोग विनिमय माध्यम तथा मूल्यमान दोनों ही के रूप में किया जाता है।
- (२) सोने के सिक्के प्रचलित होते हैं ग्रौर सोने का मुद्रग्र स्वतन्त्र होता है।
- (३) देश में प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा का प्रच-लन होता है ग्रौर सरकार पत्र मुद्रा को प्रसीमित मात्रा में स्वर्ण में बदल देने की गारन्टी देती है। कोई

#### स्वर्गं-पाट-मान

- (१) सोने का उपयोग केवल मूल्य-मान के रूप में किया जाता है, वह विनिमय का माध्यम नहीं होता।
- (२) सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता है श्रौर जनकी स्वतन्त्र ढलाई का तो प्रवन ही नहीं उठता है।
- (३) देश में परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का चलन होता है, जिसे सरकार नियत कीमतों पर सोने में बदलने का वचन देती है, परन्तु व्यवहार में

भी व्यक्ति किसी भी मात्रा में सर-कार से सोना खरीद सकता है।

. (४) सोना घरेलू ग्रावश्यकता तथा विदेशी भुगतान दोनों ही के लिए मिल

सकता है।

(प्र) यह प्रगाली लगभग स्वचालक होती है ग्रोर बिना सरकारी हस्पक्षेप के चालू रह सकती है।

(६) इस पद्धित में देश के भीतर कीमतों की स्थिरता पर ग्रिधिक जोर दिया जाता है। सोने की एक न्यूनतम मात्रा निश्चित कर दी जाती है श्रीर उससे कम मात्रा में सरकार किसी भी व्यक्ति को सोना नहीं बेचती है।

(४) सैद्धान्तिक दृष्टिकोएा से किसी भी उद्देश्य के लिए सोना खरीदा जा सकता है, परन्तु व्यवहार में वह विदेशी भुगतानों के लिए ही दिया जाता हैं।

(५) स्वचालकता का गुएए एक ग्रंश तक इस प्रएाली में भी होता है, परन्तु सरकारी हस्तक्षेप बहुषा ग्रावश्यक होता है।

(६) इस प्रगाली में विनिमय दरों की स्थिरता पर ग्रिधिक जोर दिया जाता है।

## (III) स्वर्ण-विनिमय-मान (Gold Exchange Standard)

इस मुद्रा मान का प्रचलन भी प्रथम महायुद्ध के पश्चात् ही ग्रधिक रहा है, यद्यपि भारत तथा कुछ ग्रन्य देशों में इस प्रकार का स्वर्णमान २० वीं शताब्दी के ग्रारम्भ में ही स्थापित हो गया था। इस स्वर्णमान में केन्द्रीय बैंक ग्रथवा मुद्रा ग्रधि-कारी का यह उत्तरवायित्व नहीं होता कि वह देश के चलन को स्वर्ण में बदले। उसका उत्तरवायित्व केवल इतना होता है कि देश के चलन को किसी दूसरे ऐसे चलन में परिवर्तन करने का विश्वास दिलाया जाय जो कि स्वयं स्वर्ण में परिवर्तनशील हो। इस प्रकार स्वर्ण-विनिमय-मान से देश के चलन का सोने से कोई प्रत्यद्धा सम्बन्ध नहीं होता, परन्तु देश के चलन को एक निश्चित विनिमय दर पर किसी ऐसी विदेशी मुद्रा से जोड़ दिया जाता है जो स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है। सरकार का कर्ता व्य केवल यह होता है कि निश्चित विनिमय दर पर ऐसी विदेशी मुद्रा की सम्पूर्ण मांग को पूरा करती रहे। देश की सरकार देशी मुद्रा के बदले में सोना नहीं बेचती है, परन्तु देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदल कर उस मुद्रा के बदले में विदेश की केन्द्रीय बैंक से सोना खरीदा जा सकता है। इस प्रकार देश की मुद्रा परोद्दा रीति से सोने में बदली जा सकती है। यह मान साधारणतया निर्धन देशों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिनके पास सोना बहुत ही कम होता है।

स्वर्ण विनिमय मान के रूप-

स्वर्ण-विनिमय-मान के दो रूप संसार में दृष्टिगोचर हुए हैं—(१) कुछ देशों ने देश के भीतर स्वर्गा-कोष बिल्कुल नहीं रखे थे और वे अपनी स्वर्ग सम्बन्धी सम्पूर्णं ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति के लिए विदेशी स्वर्ण-कोपों पर निर्भर रहते थे। (२) इसके विपरीत कुछ देश भ्रपने सुरक्षित कोपों को विदेशी विनिमय श्रथवा विदेशी रोकों के रूप में विदेशों में रखते थे। दूसरे प्रकार के स्वर्णमान को कुछ अर्थ-शास्त्री स्वर्ण-विनिमय-मान स्वीकार करने से इन्कार करते हैं, परन्तु व्यवहार में दोनों को ही स्वर्ण-वितिमय-मान का नाम दिया जाता है। इस पद्धति की विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं:--

स्वर्ण-विनिमय-मान की विशेषतायें—

- (१) देश में न तो सोने के सिक्हों का प्रचलन होता है और न प्रतिनिधि तथा परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का । ग्रपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा, सांकेतिक सिक्के तथा तुच्छ घातुग्रों के सिक्के चलन में रहते हैं।
- (२) देश की प्रामाणिक मुद्रा को एक निश्चित दर पर किसी ऐसे देश की मुद्रा से जोड़ दिया जाता है जो स्वर्ण-चलन-मान म्रथवा स्वर्ण-पाट-मान को ग्रहरण करता है। इस प्रकार परोक्ष रूप में देशी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण द्वारा निर्घारित होता है।
- (३) सिद्धान्त में तो मुद्रा-नियन्त्रक देश की पत्र-पृद्रा को एक निश्चित दर पर सोने ग्रथवा विदेशी विनिमय में परिवर्तित करने का उत्तरदायी होता है, परन्तु व्यवहार में सोना केवल विदेशी भुगतानों के लिए ही दिया जाता है ग्रौर वह भी विदेशी विनिमय के ही रूप में।
  - (४) विदेशों से सोने में भ्रथवा किसी स्वीकृत विदेशी मुद्रा में भुगतान लिए जाते हैं।
  - (५) सोने का उपयोग न तो विनिमय माघ्यम के रूप में किया जाता है स्रोर न मूल्यमान के रूप में, परन्तु परोक्ष रूप में सभी प्रकार की वस्तुग्रों श्रीर सेवास्रों की कीमतें सोने की कीमतों द्वारा ही निश्चित होती हैं।

भारत ने सन् १६०० में इस मान को ग्रहरण किया था। भारतीय रुपए को ब्रिटिश पौंड से जोड़ दिया गया था भ्रौर भारतीय रुपए की विनिमय दर १ शिलिंग ४ पेंस प्रति रुपया रखी गई थी । सन् १६१७ तक यह मान सफलतापूर्वक चालू रहा था\_ यद्यपि सन् १६१४ के पञ्चात् भारत सरकार ने बड़ी कठिनाई के साथ इसे निभाया था । सन् १६१७ से सन् १६२० तक स्वर्ण-विनिमय-मान को स्थगित कर दिया गया था। सन् १६२० में २ शिलिंग प्रति रुपए की विनिमय दर पर भारत सरकार ने इस मान को फिर स्थापित करने का प्रयत्न किया, परन्तु यह प्रयत्न ग्रसफल रहा । भारत में स्वर्ण-विनिमय-मान की ग्रसफलता का प्रमुख कारण चाँदी की कीमतों का भारी उतार-चढ़ाव था । स्वर्गा-विनिमय-मान वाले ग्रन्य देशों में डेनमार्क का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है। इस देश ने भी अपने चलन को एक निश्चित विनिमय दर पर ब्रिटिश पौंड के साथ जोड़ रखा था।

स्वर्ण विनिमय मान तथा स्वर्ण-पाट-मान की तुलना-

निम्न तालिका दोनों प्रकार के मानों के भेद को स्पष्ट करती है: -

#### स्वरग-पाट-मान

- (१) इस मान में सोने के सिक्के तो प्रच-लन में नहीं होते हैं और सोना विनिमय के माध्यम का भी काम नहीं करता, परन्तु मूल्यमान के रूप में सोने का उपयोग अवस्य होता है।
- (२) देश की मुद्रा निर्घारित दरों पर सोने में परिवर्तनशील होती है अर्थात् देश में परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का प्रचलन होता है।
- (३) मुद्रा की स्वर्णं में परिवर्तनशीलता बनाये रखने के लिए सरकार सोने के संचित कोष रखती है, यद्यपि ऐसे स्वर्णं कोषों की कीमत कुल पत्र-मुद्रा की कीमत से कम होती है।
- (४) सरकार निश्चित कीमत पर ग्रसीमित मात्रा में सोना खरीदने ग्रौर बेचने की गारन्टी देती है।
- (५) प्रत्यक्ष रूप में देशी चलन स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है।

- स्वर्गं विनिमय मान
- (१) सोने का उपयोग न तो विनिमय के माध्यम के रूप में होता है ग्रौर न मूल्य-मान के रूप में। सोने के सिकों के प्रचलन का तो प्रक्त ही नहीं उठता है।
  - (२) देश की मुद्रा को सोने में बदलने की किसी भी प्रकार की गारन्टी सरकार नहीं देती है। देश में अपरि-वर्तनशील पत्र-मुद्रा का प्रचलन होता है।
  - (३) क्योंकि पत्र-मुद्रा को सोने में बदलने का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, इसलिए सरकार के लिए स्वर्गा कोषों का रखना भ्रावश्यक नहीं है। सरकार केवल इतनी गारन्टी देती है कि निश्चित विनिमय दर पर देश की मुद्रा एक ऐसे देश की मुद्रा से बदल दी जायगी जोकि स्वयं स्वर्गां में परिवर्तनशील हो।
  - (४) इस प्रकार की गारन्टी का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सरकार का सोना खरीदने ग्रौर बेचने का कोई भी उत्तरदायित्त्व नहीं है।
  - (५) देशी चलन केवल परोक्ष रूप में ग्रर्थात् किसी ग्रन्थ चलन के माध्यम से ही स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है।

#### स्वर्ण विनिमय मान तथा स्वर्ण चलन मान-

स्वर्णं विनिमय मान का उपयोग स्वर्णं चलन मान के उपयोग से बहुत पीछे आरम्भ हुग्रा था। वास्तविकता यह है कि उन देशों ने, जिनके सोने के कीप इतने कम थे कि वे स्वर्णं चलन मान तो क्या स्वर्णं-पाट मान भी स्थापित नहीं कर सकते थे, उन्होंने स्वर्णं विनिमय मान को ग्रयनाया। स्वर्णं चलन मान की तुलना में स्वर्णं विनिमय मान एक सस्ता परन्तु निम्न श्रेणी का स्वर्णमान है। दोनों के श्रन्तर निम्न प्रकार हैं:—

#### स्वर्गा चलन मान

- (१) सोने का उपयोग विनिमय माध्यम तथा मूल्य-मान दोनों ही रूपों में होता है।
- (२) सोने के सिक्के प्रचलन में होते हैं श्रोर इनका मुद्रग्र स्वतन्त्र होता है।
- (३) देश की पत्र-मुद्रा प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा होती है, जिसे श्रसीमित मात्रा में सोने में बदलने की गारन्टी दी जाती है।
- (४) यह प्रएाली बिना सरकारी हस्तक्षेप के चालू रहती है। इसमें स्वचाल-कता का महान् गुएा होता है श्रौर श्रुटियों को स्वयं दूर कर लेने की क्षमता होती है।
- (५) इस प्रएाली में देश के भीतर कीमतों की स्थिरता पर ग्रधिक जोर दिया जाता है।
- (६) मुद्रा प्रणाली पूर्णतया स्वतन्त्र होती है।

#### स्वर्गा विनिमय मान

- (१) सोने का उपयोग दोनों में रा किसी भी रूप में नहीं होता।
- (२) सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता।
- (३) देश में अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का प्रचलन होता है। सरकार न तो सोने के कोष जमा करती है और देश की मुद्रा को स्वर्गा के स्थान पर केवल किसी विदेशी मुद्रा में बदलने की गारन्टी देती है।
- (४) इस प्रणाली के चालू रखने के लिए सरकारी हस्तक्षेप भ्रावश्यक होता है। यह भ्रपनी त्रुटियों को स्वयं दूर नहीं कर पाती।
- (प्र) इस प्रगाली में केवल विनिमय दर की स्थिरता बनाये रखने का प्रयत्न किया जाता है।
- (६) मुद्रा प्रणाली म्राघार-देश (Planet Country) मर्थात् वह देश जिसकी चलन से देश की चलन जोड़ी गई है, की मुद्रा प्रणाली पर भ्राक्षित होती है।

#### स्वर्ण-विनिमय-मान के लाभ

स्वर्ण-विनिमय-मान को सबसे मितव्ययी स्वर्णमान कहा जाता है। इस मान के तीन प्रमुख लाभ हैं:

- (१) एक निधन दश के लिए भी उपयुक्त—एक निर्धन देश, जिसके पास सोना बहुत ही कम है, इसके द्वारा स्वर्णमान के सभी लाभ प्राप्त कर सकता है। किसी शक्तिशाली स्वर्ण-मुद्रा के साथ देश की मुद्रा को जोड़कर तथा विदेशी विनिमय दर पर नियन्त्रण रखकर विदेशी विनिमय दर की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही, यदि विदेशी मुद्रा को सावधानीपूर्वक चुना जाय, तो विदेशी भुगतानों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई का भय नहीं रहता।
- (२) मितव्ययितापूर्ण यह मान इस दृष्टिकोश से मितव्ययितापूर्ण है कि इसमें सोने के आयात और निय्ति का खर्च बच जाता है। सोना न तो बाहर भेजा जाता है और न बाहर से मँगाया जाता है, इसिलए सोने को पैक करने, उसके याता-यात तथा उसके बीमे का व्यय बच जाता है। इसी प्रकार क्योंकि देश में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता है, इसिलए सिक्कों की घिसावट द्वारा भी हानि का भय नहीं रहता। साथ ही, सोना सुरक्षित कोषों में व्यर्थ नहीं पड़ा रहता है, क्योंकि उसका उपयोग मुद्रा के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है।
- (३) सरकार को लाभ—देश की सरकार बहुधा इसके द्वारा लाभ भी कमाती है। विदेशों में जो निक्षेप रखे जाते हैं तथा जो विनिमय किये जाते हैं उनसे ब्याज प्राप्त होती है। देश की सरकार विदेशी विनिमय खरीदने तथा बेचने की दरों में अन्तर रखकर भी लाभ कमाती है। इसके अतिरिक्त स्वर्णमान संचालन सम्बन्धी सारी की सारी जिम्मेदारी विदेशी सरकार के ऊपर रहती है। देशी सरकार तो केवल विदेशी विनिमय दर की स्थिरता पर ही ध्यान देती है।

#### स्वर्ण विनिमय की कार्य विधि -

स्वर्ण-विनिमय-मान के संचालन की कार्य-विधि का संचिप्त वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है —

इस मान में संकुचित सीमाओं के भीतर विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन होने दिए जाते हैं। स्वर्ण-निर्यात बिन्दु (Gold Export Point) पर मुद्रा-नियन्त्रक विदेशी विनिमय खरीदता है और स्वर्ण-ग्रायात बिन्दु पर उसे बेचता है, यद्यपि दोनों ही दशाओं में स्वर्ण की बिक्री तथा खरीद ग्रसीमित होती है। जब विदेशी विनिमय खरीदा जाता है तो देशी चलन की मात्रा बढ़ती है और जब विदेशी विनिमय बेचा जाता है तो देशी चलन का संकुचन होता है, क्योंकि देशी मुद्रा के पीछे सबसे बड़ी आड़ विदेशी विनिमय कोषों की होती है। इस प्रकार देशी मुद्रा की पूर्ति में विदेशी व्यापर तथा विदेशी विनियोगों के परिवर्तनों के अनुसार कमी या वृद्धि होती

रहती है। सोने को भेजने और मंगाने का व्यय नहीं होता और विदेशी रोकों से श्राय प्राप्त होती है, श्रतः इस सम्बन्ध में भी व्यय कम होता है।

#### स्वर्ण-विनिमय-मान के दोष —

स्वर्ण-विनिमय-मान की सबसे बड़ी कभी यह होती है कि इसमें सोने के एक ही सुरक्षित कोष पर कई देशों की मुद्राएँ श्राचारित होती हैं। इस कारएा यह मान मितव्यियतापूर्ण तो श्रवश्य होता है, परन्तु भय यह रहता है कि कहीं सोने की यह सीमित मात्रा स्वर्णमान सम्बन्धी सभी कार्यों को सम्पन्न करने के लिए श्रपर्याप्त न हो। इसके श्रतिरिक्त इस मान के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं:—

- (१) देश के चलन की विदेशी चलन पर निर्भरता—स्वर्ण-विनिमय-मान के सफल संचालन के लिए विदेशों में लम्बी-चौड़ी रोकों की ग्रावश्यकता होती है। यह व्यवस्था वैसे तो सस्ती ग्रीर सुविधाजनक होती है, परन्तु यह संकट से खाली-नहीं होती। यदि ग्राधार देश (Planet Country) ही स्वर्णमान का परित्याग करता है तो उसके पीछे लगे हुए सभी देश कुछ भी नहीं कर सकते ग्रीर उनकी मुद्राग्रों की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। सन् १६३१ में इझलैंण्ड द्वारा स्वर्णमान के परित्याग के पश्चात् ऐसी ही स्थित उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार यह मान देश के व्यापार, विनियोग ग्रादि को विदेशी सरकार की नीति का दास बना देता है।
- (२) श्राघार देश की मुद्रा प्रणाली को खतरा—श्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह मान श्राघार देश (Planet Country) की मुद्रा-प्रणाली को असुरक्षित बना देता है। श्राघार देश के पास सोने का कीष तो सीमित ही होता है, परन्तु उस कोष पर श्राघार देश के अतिरिक्त उन सभी गौण देशों का भी श्रीधकार रहता है, जिन्होंने अपनी मुद्रा श्राघार देश की मुद्रा से जोड़ रखी है। ऐसी दशा में यह सम्भव है कि विभिन्न सूत्रों से सोने की माँग इतनी श्रीधक श्रा जाय कि श्राधार देश की मुद्रा-प्रणाली ही संकट में पड़ जाय।
- (३) अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के सन्तुलन में कठिनाई—इस मान के अन्तर्गत तरल आदेयों (Liquid Assets) का एक देश से दूसरे को उतनी सुगमता तथा उतनी मात्रा में हस्तान्तरए नहीं होता है जितना कि स्वर्णमान के अन्तर्गत सोने का होता है, जो सबसे तरल आदेय है। इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के सन्तुलन की स्थापना में कठिनाई होती है। यदि यह हस्तान्तरए ठीक-ठीक होता रहता है तो तरल साधनों का विभिन्न देशों के बीच ऐसा समुचित वितरए हो जाता है कि विभिन्न देशों की आन्तरिक कीमतों में साम्य स्थापित हो जाता है और वे एक दूसरे की लय में लय मिला कर बढ़ती-घटती हैं।

हिल्टन यंग च्यायोग ने भारत में स्वर्ण-िवनिमय-मान के व्यावहारिक कार्य-

वाहन की जाँच की थी, जिसके पश्चात् श्रायोग ने भारत में इस मान के निम्न दोष बताये थे :—

- (१) यह प्रणाली कठिन तथा अत्याधिक सैंद्धान्तिक है और जन-साधारण की समक्ष से बहुधा बाहर होती है। ऐसी प्रणाली के प्रौत जनता का विश्वास प्राप्त करना कठिन होता है। जनता मुद्रा-नियन्त्रक को सदा शंका की दृष्टि से देखती है और उसके साथ सहयोग नहीं करती है।
- (२) भारत में इस प्रणाली के अन्तर्गत कीषों की अधिकता थी। तीन प्रकार के सुरक्षित-कोष अर्थात् स्वर्णमान-कोष, पत्र-मुद्रा-कोष तथा भारत सरकार की रोकें, जो भारत और इङ्गलैण्ड दोनों में रखी जाती थीं।
- (३) यह प्रणाली स्वचालक नहीं होती है। इसका कार्यवाहन बड़े अंश तक मुद्रा-नियन्त्रक की इच्छा पर निर्भर रहता है।
- (४) इसमें लोच नहीं होती है। देश में चलन का विस्तार करने में तो विशेष कठिनाई नहीं होती है, परन्तु चलन का संकुचन लगभग असम्भव ही होता है।
- (५) एक गम्भीर दोष यह भी होता है कि देश का चलन विदेशी चलन पर ज्याश्रित हो जाता है और विदेशी सरकार की इच्छा, भूल तथा उसके दुर्भाग्य का देश को भी शिकार बनना पड़ता है।

## ( IV ) स्वर्ण-निधि-मान (Gold Reserve Standard)

यह मान स्वर्णमान का ही एक परिवर्तित का है, जो सन् १६३६ से लेकर सितम्बर सन् १६३६ तक कुछ देशों में प्रचलित रहा। सन् १६३६ में फ्रान्स ने भी स्वर्णमान का परित्याग कर दिया था। उस समय विनिमय दरों की स्थिरता को बनाये रखने के लिए बेल्जियम, फ्रान्स, इङ्गलेंड, हॉलैण्ड, स्विटरलैण्ड तथा संयुक्त राज्य ग्रमरीका के बीच एक समभौता हुग्रा, जिसके ग्राधार पर जो मुद्रा प्रगाली स्थापित हुई उसे 'स्वर्ण निधिमान' की संज्ञा दी जा सकती है। इस समभौते की प्रमुख

विशेषतायें निम्नलिखित थीं :--

- (१) सोने का ग्रायात-निर्यात केवल सरकार द्वारा—एक देश से दूसरे देश को सोने का ग्रावागमन हो सकता था। इन देशों में किसी भी प्रकार का स्वर्ण-मान चालू न था, ग्रतः यह ग्रावागमन केवल मुद्रा सम्बन्धी कार्यों में उपयोग होने वाले सोने का ही हो सकता था। व्यापारियों को सोना मँगाने ग्रथवा भेजने का ग्रधिकार न था। दूसरे शब्दों में, सोने के ग्रायात ग्रौर निर्यात का एकाधिकार केवल सरकारों के हाथ में था।
  - (२) विनिमय समानीकरण कोषों की स्थापना—सभी देशों ने विनि-

मय समानीकरए कोषों (Exchange Equalisation Funds) का निर्माण कर रखा था। इन कोषों को कभी कभी विनिमय समातुलन लेखे (Exchange Equalisation Account), विनिमय कोष (Exchange Funds) तथा 'नियन्त्रए।' (Control) भी कहा जाता था। विनिमय पर सरकारी एकाधिकार था। कुल विदेशी विनिमय को एक कोष में रखा जाता था और इस कोष का संचालन प्रत्येक देश की केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता था। प्रत्येक कोष के पास देश की मुद्रा क्वा एक भारी संचय होता था और इनमें से कुछ के पास सोना भी काफी मात्रा में रहता था। उद्देश्य यह था कि यदि किसी चलन की विदेशी विनिमय बाजार में ग्रसा-धारए एव में ग्रधिक माँग होती थी तो कोष विशेष उसे ग्रावश्यक मात्रा में देकर विनिमय दरों के परिवर्तन को रोक सकता था, परन्तु यदि कोष विशेष विदेशी मुद्राओं का ग्रत्यधिक संचय नहीं करना चाहता था तो व्यवस्था यह थी कि प्रत्येक कोष ग्रपने देश की मुद्रा के बदले में दूसरे कोष को सोना दे देता था।

इस प्रकार के कार्यं की ग्रावश्यकता निम्न उदाहरए। से स्पष्ट हो जायगी:— मान लीजिए कि ब्रिटिश कोष ऐसा अनुभव करता है कि उसका डालर संत्रय बहुत ग्रिधिक हो गया है तो ऐसी दशा में वह अमरीकन 'नियन्त्रए।' को सूचना दे देगा कि वह ग्रीर ग्रिधिक डालर का संचय नहीं करेगा। ग्रव क्यों कि विभिन्न समानीकरए। कोषों के प्रबन्धकों के बीच यह समफौता होता है कि प्रत्येक ग्रपने चलन के वदले में दूसरे कोष को सोना दे देता है तो ग्रमरीकन कोष डालर लेकर उसके बदले में ब्रिटिश कोष को उनकी कीमत का सोना दे देगा।

[ विनिमय समानीकरण कोषों में वह सोना जमा रहता है जो वे दूसरे कोषों से खरीदते थे। एक देश के कोष से दूसरे देश के कोष में सोने का हस्तान्तरण होता रहता था, इसलिए इस प्रणाली का नाम स्वर्ण-निधि पद्धति पड़ा।]

- (२) इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा ब्याज की दर में परिवर्तन किये बिना तथा देश की ज्ञान्तरिक ज्यर्थव्यवस्था में किसी प्रकार के हस्तत्त् प के बिना ही विदेशी विनिमय-दर की स्थिरता प्राप्त की जा सकती थी। जब तक यह प्रणाली चालू रही, विदेशी मुद्राग्नों में सोने का मूल्य स्थायी बना रहा। इस प्रणाली में ग्रण यह होता है कि देश के चलन में सोने की कीमतों को नियत करने की ग्रावश्यकता नहीं पड़ती है।
- ( ४-) जनता की यह पता नहीं चलती था कि कोई कीष क्या खरीद रहा है, ऋथवा क्या बेच रहा है ? यह भी एक रहस्य होता था कि समय विशेष में किसी कोष के पास विभिन्न मुद्राग्रों की कितनी-कितनी मात्रा रहती थी।

दूसरे महायुद्ध के आरम्भ तक तो यह प्रगाली सफलतापूर्वक चलती रही, परन्तु यह युद्ध की भीषण परिस्थितियों की चोट न सह सकी और टूट गई। युद्ध काल में विनिमय दरों की स्थिरता के लिए विनिमय-नियन्त्रण (Exchange

Control) की नीति को सफल बनाने के लिए नये-नये उपायों का अपनाना आव-श्यक हो गया।

#### ( पू ) स्वर्ण समता प्रणाली (Gold Parity Standard)—

इस प्रकार का स्वर्णमान सन् १६४६ से, जिस समय से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने अपना कार्य आरम्भ किया है, आरम्भ हुआ है। इस दृष्टिकोएा से हम इसे स्वर्णमान का नवीनतम् रूप कह सकते हैं। इस मान के अन्तर्गत देश की मुद्रा प्रणाली में स्वर्ण का स्थान इतना कम महत्त्वपूर्ण होता है कि रुद्धिवादी अर्थशास्त्री इस मान को स्वर्णमान स्वीकार करने में भी संकोच करते हैं, परन्तु शायद यह कहना अनुचित न होगा कि यह स्वर्णमान का आधुनिकतम रूप है और चाहे इसमें स्वर्ण का स्थान कितना ही कम महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, विभिन्न देशों की मुद्राओं की एक दूसरे में विनिमय दर स्वर्ण के माध्यम से ही स्थापित होती है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य देशों को अपने चलन की कीमत स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के बराबर घोषित करनी पड़ती है और इस अधार पर इन चलनों की पारस्परिक विनिमय दर निश्चित हो जाती है। इसके पश्चात् प्रत्येक देश का यह उत्तरदायित्व होता है कि स्वर्ण में देश के चलन की जो कीमत घोषित की गई है उसे बनाये रखे। इससे विनिमय दरों की स्थिरता बनी रहती है।

#### विशेषतायें—

(१) यह मान उन सभी देशों में प्रचलित समक्षा जाता है जो ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। (२) ऐसे मान में सोने के सिक्कों के प्रचलन का प्रक्त तो दूर रहा, स्वर्ण न तो मूल्य-मान के रूप में रहता है ग्रौर न विनिमय-माध्यम के रूप में। (३) इस मान को ग्रप्ताने वाले प्रत्येक देश को देश के ग्रन्दर मौद्रिक मामलों में पूरी स्वतन्त्रता होती है। (४) एक देश की मौद्रिक नीति का दूसरे देश की मौद्रिक नीति से कोई भी प्रत्यक्ष ग्रथवा परोक्ष सम्बन्ध नहीं होता है। मौद्रिक क्षेत्र सम्बन्धी सहयोग केवल विनिमय दरों की स्थिरता को बनाये रखने के लिए होता है। (५) यह मान वास्तव में एक बड़ा लोचदार मान है, क्योंकि ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियमानुसार सदस्य देशों को विशेष परिस्थितियों में विनिमय दरों में परिवर्तन करने का भी ग्रधकार प्राप्त है। (६) इसके ग्रतिरक्त स्वयं मुद्रा कोष भी विनिमय दरों की स्थिरता को बनाये रखने के लिए सदस्य देशों को ऋग्ण देता है। विस्तृत ग्रध्ययन के लिए ग्रध्याय २२ देखिए ।

### स्वर्शमान के नियम (The Rules of the Gold Standard)-

स्वर्णमान में स्वचालकता का ग्रुण बताया जाता है, परन्तु यह ग्रुण तभी प्राप्त होता है जबिक स्वर्णमान के कुछ नियमों का पालन किया जाय। इन नियमों को मू०च०प्र० (७) कभी-कभी खेल के नियम (Rules of the Game) भी कहा जाता है। ये नियम इस प्रकार हैं:—

- (१) स्वतन्त्र व्यापार नीति का ग्रपनाना—स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए यह म्रावश्यक है कि म्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध न लगाये जार्ये। संरक्षरा, म्राधिक राष्ट्रीयवाद, कोटा (Quota) तथा भ्रन्य व्यापारिक नियन्त्रगा इस मान के लिए ग्रहितकर हैं। वस्तुओं के ग्रायात ग्रीर निर्यात पर प्रतिबन्य लगाने का परिगाम यह होता है कि व्यापाराशेप में ठीक दिशास्रों में परिवर्तन नहीं होने पाते हैं, जिसके कारए। ग्रायात ग्रौर निर्यात के सन्तुलन में बाधा पड़ती है। स्वतंत्र ह्यापार का ग्रर्थ यह भी होता है कि प्रत्येक स्वर्णमान देश में सोने का भ्रायात ग्रीर निर्यात भी स्वतन्त्र होना चाहिए । इसका परिएाम यह होता है कि संसार के विभिन्न स्वर्णमान देशों के बीच सोने का वितरए इस प्रकार हो जाता है कि प्रत्येक को म्रावश्यकतानुसार सोना मिल जाता है। इसके म्रातिरिक्त व्यापारायोप की त्रुटियाँ भी स्वर्ण के श्रायात श्रीर निर्यात द्वारा ठीक हो जाती हैं। मुद्रा क+ विस्तार श्रथवा संक्चन स्वर्ण-कोषों की मात्रा पर निर्भर होता है और आयात-निर्यात द्वारा स्वर्ण कोषों में परिवर्तन हो जाने के कारण कीमत-स्तर इस प्रकार परिवर्तित हो जाता है कि विदेशी व्यापार का सन्तुलन बना रहे। इस प्रकार स्वर्णमान के इस नियम का पालन करने से विदेशी व्यापार का श्रसन्तुलन तथा सोने के वितरण की ग्रसमानता स्वयं ही ठीक हो जाते हैं।
- (२) स्वर्ण कोषों के अनुपात में मुद्रा को घटाना-बढ़ाना स्वर्णमान का दूसरा नियम यह है कि स्वर्ण के आवागमन के कारण देश के मूल्य-स्तर पर जो प्रभाव पड़ता है उसमें मुद्रा-नियन्त्रक को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यदि सोना देश से बाहर जाता है तो स्वर्ण कोप की कभी के अनुपात में मुद्रा की मात्रा को घटाकर कीमतों को गिरने देना चाहिये। यदि मुद्रा-संकुचन के भय से मुद्रा-संचालक कीमतों को गिरने से रोक देता है तो देश के निर्यातों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और आयातों के निर्यातों से अधिक रहने के कारण सोना देश से बरावर बाहर जाता रहेगा। ठीक इसी प्रकार यदि सोना बाहर से आ रहा है तो कीमतों को उसी के अनुपात में बढ़ने देना चाहिये, अन्यथा आयात-निर्यात सन्तुलन स्थापित नहीं हो पायेगा। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि मुद्रा-संचालक जनता को उसकी माँग के अनुसार सोना देने को तैयार रहे। इसी प्रकार जितना भी सोना देश के भीतर आता है उसे लेने के लिए और उसे चलन का आधार बनाने के लिए भी मुद्रा-संचालक को तैयार रहना चाहिये। स्वर्ण को मुद्रा में और मुद्रा को स्वर्ण में निर्वान्ध परिवर्तन-शील होना चाहिये।
- (३) राजनैतिक स्थिरता—देश में पूर्ण शान्ति रहनी चाहिए। देश के अन्दर के भगड़े लोगों में अशान्ति का वातावरण पैदा कर देते हैं। इस कारण बैंकों के काम में बाघा पड़ती है। लोग वहाँ से मुद्रा निकालने के लिए जाते हैं और

फिर मुद्रा को गाढ़ कर रखने की प्रवृत्ति हो जाती है। इससे स्वर्णमान को धका लगता है। इसलिए यह ग्रावश्यक है कि स्वर्ण-मान देश की सरकार शान्ति ग्रौर सुरक्षा बनाये रखे।

# स्वर्णमान पर एक ऐतिहासिक दृष्टि

१६ वीं शताब्दी में द्वि-घातुमान स्थापित करने के अनेक प्रयत्न किये गये, परन्तु इस सम्बन्ध में कठिनाइयाँ इतनी हुई कि ये प्रयत्न फलीभूत न हो सके। चांदी की कीमतों में परिवर्तन इतने अधिक हुए कि रजत-मान ग्रहण करना असम्भव हो गया। इस काल में स्वर्णमान का ही जोर अधिक रहा। इस शताब्दी में सोने की कीमतों की स्थिरता के कारण, सोने के अधिक मूल्यवान घातु होने के कारण, सोने की पूर्ति काफी होने के कारण और सोने के वार्षिक उत्पादन की कमी के कारण सोना ही मूल्यमान के रूप में अधिक उपयुक्त समभा गया था। संसार के सभी देशों की रुचि स्वर्णमान ग्रहण करने की ओर ही थी।

### सन् १६१४ से पूर्व का स्वर्गमान --

प्रथम महायुद्ध के पूर्व सभी स्वर्णमान देशों में स्वर्ण-चलन मान प्रहरा। किया गया था। इसके अन्तर्गत सोना विनिमय-माध्यम तथा मूल्य-मान दोनों ही का काम करता था। सोने के सिक्के प्रचलन में रहते थे। विदेशी विनिमय का आधार भी सोना ही था। विदेशी विनिमय दर दो चलनों की स्वर्ण खरीदने की शक्ति की समानता द्वारा निर्घारित होती थी ग्रौर यद्यपि इस विनिमय दर में परिवर्तन हो सकते थे, परन्तु इन परिवर्तनों की सीमायें छोटी सी थीं। विदेशी विनिमय दर स्वर्ण ग्रायात तथा स्वर्ण निर्यात बिन्द्रभ्रों (Gold Import and Export Points) के भीतर ही रहती थी। स्वर्णमान के अन्तर्गत दो नियमों का पालन किया जाता था:--(१) सोने के आयात-निर्यात स्वतन्त्र रखे जाते थे और (२) स्वर्ग्-कोषों की मात्रा में परिवर्तन होने पर उन्हीं के अनुपात में चलन की मात्रा में भी परिवर्तन कर दिये जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि इन नियमों का पालन करने के पश्चात यह मान स्वचालक हो जाता था। बिना किसी प्रकार के हस्तक्षेप के यह स्वयं ही चलता रहता था। यदि देश के स्वर्णं-कोषों में कमी आ जाती थी तो इसी कमी के अनुपार में देश में मुद्रा भी कम हो जाती थी, जिसके कारए। देश में वस्तुस्रों स्रौर सेवास्रों की म्रान्तरिक कीमतें गिर जाती थीं । इसके द्वारा म्रायात हतोत्साहित होते थे तथा निर्यात बढ़ते थे और स्रागे चलकर व्यापाराशेष में इस प्रकार के परिवर्तन हो जाते थे कि श्रायात-निर्यात के सन्तुलन के अतिरिक्त गया हुआ सोना फिर लौट आता था। इसी प्रकार निर्यातों के बढ़ने की दशा में देश में सोने का आयात होता था. मुद्रा-विस्ताः होता था, सामान्य कीमतें बढ़ती थीं श्रौर श्रायात प्रोत्साहित होते थे. जिसके फलस्वरू पुराना साम्य पुनः स्थापित हो जाता था। विदेशों से म्राया हुमा सोना उन देशों के पुनः लौट जाता था।

इसी काल में कुछ देशों में स्वर्ण-मान का एक दूसरा रूप भी प्रचिलत था, जिसे हम स्वर्ण-विनिमय-मान कहते हैं। इस पद्धित का उद्देश्य सोने के उपयोग में बचत करना होता था और यह साधारणतया ऐसे देशों द्वारा अपनाई जाती थी जिनके पास स्वर्ण-कोषों का अभाव था। इस प्रणाली में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता था। देश की मुद्रा को एक नियत दर पर किसी शक्तिशाली विदेशो मुद्रा से, जो स्वर्ण पर आधारित होती थी, जोड़ दिया जाता था। सरकार को देशी चलन, विदेशी चलन तथा सोने का एक कोष बनाना पड़ता था और विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए नियत दरों पर विदेशी विनिमय खरीदना और बेचना पड़ता था। यह प्रणाली भारत, जावा, हॉलेंड, डेनमार्क, आस्ट्रिया, हंगरी आदि देशों में प्रचलित थी। भारत में स्वर्ण-विनिमय-मान पद्धित सन् १६०७- में स्थापित की गई थी और यह सन् १६१७ तक चालू रही। उस समय भारत सरकार का यह वैधानिक उत्तरदायित्व था कि ऋणों का भुगतान सोने में करे। इस प्रणाली के अन्तर्गत आन्तरिक उपयोग के लिए चाँदी का रुपया प्रामाणिक मुद्रा थी, परन्तु विदेशी व्यापार ब्रिटिश स्टर्लिङ्क द्वारा किया जाता था और सरकार एक निश्चित दर, पर, अर्थात १ शिलिंग ४ पैंस प्रति रुपये के हिसाब से, रुपयों को स्टिलङ्क में बदल देती थी।

प्रथम महायुद्ध के आरम्भ काल तक स्वर्णमान विना किसी कठिनाई के चालू रहा। ग्रान्तरिक कीमत-स्तर तथा विदेशी विनिमय दरें स्थिर बनी रहीं ग्रीर विभिन्न देशों के बीच ग्राथिक परिस्थितियों की भिन्नता होते हुए भी पारस्परिक मौदिक सहयोग बना रहा, परन्तु युद्ध का आरम्भ होते ही इसमें विश्वनाइयाँ उत्पत्त होने लगीं ग्रीर ग्रिषकांश स्वर्णमान देशों ने सोने के सिक्के का मुद्रग्ण बन्द कर दिया तथा सोने के निर्यात् पर प्रतिबन्ध लगाने ग्रारम्भ कर दिये। प्रत्येक देश सोने का संचय करने लगा। सभी देशों ने स्वर्णमान को स्थिगत करके वित्तीय ग्रावश्यकता की पूर्ति के लिये बिना स्वर्ण-कोषों पर ध्यान दिये कागज के नोट छापने ग्रारम्भ कर दिये। ग्रापरिणाम यह हुआ कि स्वर्णमान व्यवस्था टूट गई।

युद्धोत्तर-कालीन स्वर्णमान (The Post-War Gold Standard)-

युद्ध का अन्त होते ही अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर स्वर्णमान को स्थापित करने का प्रयत्न फिर आरम्म हुआ । इसके लिये सन् १६२० में बूसेल्स (Brussles) में एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसने यह आदेश दिया कि जिन देशों ने स्वर्णमान को तोड़ दिया था वे उसे फिर से स्थापित कर दें। सन् १६२२ में एक अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ सम्मेलन हुआ, जिसने यह आदेश दिया कि आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सभी देशों की मुद्राओं के मूल्य में स्थिरता का बनाये रखना आवश्यक था। स्वर्णमान की स्थापना में सबसे पहला कार्य संयुक्त राज्य अमरीका ने किया और सन् १६१६ में ही सोने के आयात-निर्यात सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा दिये। इसके पश्चात सन् १६२४ में इङ्गलैण्ड तथा फ्रांस ने स्वर्णमान को पुनः

ग्रहरण किया। सन् १६२७ में भारत में भी यह मान स्थापित हुगा। स्वर्णमान को फिर से स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि युद्ध से पहले जैसी सामान्य परि-स्थितियाँ उत्पन्न की जायँ। इसके ग्रतिरिक्त युद्धोत्तर काल में जर्मनी तथा ग्रन्य यूरोपीय देशों ने भीषण मुद्रा-स्फीति के दुखद परिणाम देखे थे। उन्होंने भविष्य में इन परिणामों से बचने के लिए स्वर्णमान को पुनः स्थापित किया।

युद्ध के उपरान्त स्वर्णमान को पुनः स्थापित करने की समस्या विभिन्न देशों के सम्मुख विभिन्न रूपों में थी । अमरीका में सामान्य कीमतों में बहुत ही कम वृद्धि हुई थी, इसलिए उसने तो केवल स्वर्ण निर्यात सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटा कर स्वर्णमान को उसके प्राचीन अधार पर स्थापित कर दिया। इसी प्रकार उन देशों को भी स्वर्णमान स्थापित करने में कठिनाई नहीं हुई जिन पर युद्ध का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा था। स्विटजरलैण्ड, हॉलैण्ड, नार्वे तथा स्वीडन ऐसे ही देशों में से थे, परन्तु इङ्गलैण्ड तथा फांस की स्थिति भिन्न थी। वहाँ पत्र-मुद्रा का विस्तार बहुत हो गया था और इस कारण बिना भारी मुद्रा-संकुचन किये स्वर्ण-चलन-मान को स्थापित करना असम्भव था। इन देशों ने स्वर्ण-चलन-मान के स्थान पर स्वर्ण-पाट-मान को ग्रहण किया। इस प्रकार स्पेन को छोड़ कर सभी स्वर्णमान देशों ने युद्ध के पश्चात् स्वर्णमान को फिर ग्रहण कर लिया।

परन्तु पुनः स्थापित होने के पश्चात् स्वर्णमान की किंतनाइयों ने भीषण रूप धारण कर लिया | देशों के बीच पुराना मौदिक सहयोग समाप्त हो चुका था। प्रत्येक देश सोने का संग्रह करने का प्रयत्न कर रहा था और उचित अथवा अनुचित रीति से विदेशी व्यापार को स्वर्ण प्राप्ति तथा आर्थिक विकास का साधन बनाना चाहता था। इस काल में विदेशी व्यापार पर भी अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये। परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही स्वर्णमान फिर टूट गया। सितम्बर सन् १६३१ में इक्कलैण्ड ने स्वर्णमान को छोड़ दिया। सन् १६३३ में अमरीका ने भी इसे छोड़ दिया और अन्त में सन् १६३६ में फ्रांस ने स्वर्णमान को तोड़ कर इस मान को संसार से ही बिदा कर दिया।

#### स्वर्णमान का पतन और उसके कारण-

यह ऊपर ही बताया जा चुका है कि पुनः स्थापित होने के थोड़े ही समय परचात् स्वर्णमान समाप्त हो गया। युद्धोत्तर काल में ऐसे अनेक कारण उत्पन्न हो गये थे कि उन्होंने स्वर्णमान के चलन को असम्भव बना दिया। स्वर्णमान के दूट जाने के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं:—

(१) स्वर्णमान के नियमों का उलंघन (Violation of the Rules of Gold Standard)—सबसे पहला कारण यह था कि सभी स्वर्णमान देशों ने नियमों का उलंघन किया। स्वर्णमान के पहिले नियम को फ्रांस तथा श्रमरीका ने विशेषतया तोड़ा। इन देशों ने विदेशी श्रायातों तथा सोने के निर्यात पर

प्रतिबन्घ लगाने भ्रारम्भ कर दिए। स्वर्णमान के दूसरे नियम का भी फ्रांस तथा विटेन दोनों ने उलंघन किया । जब इङ्गलैंड ने स्वर्रामान को पुनः स्थापित किया तो अपनी मुद्रा का स्वर्ण में अति-मूल्यन (Over-valuation) कर दिया अर्थात् अपनी चलन को स्वर्ण में वास्तविक से ग्रधिक कीमत प्रदान की थी, जिसके फलस्वरूप उसका व्यापाराशेष प्रतिकूल हो गया और इङ्गलैण्ड से सोना वाहर जाने लगा। ऐसी दशा में स्वर्णमान के नियमानुसार इङ्गलैण्ड को मुद्रा की मात्रा श्रीर कीमतें घटानी चाहिए थीं, परन्तु मुद्रा संकूचन के भय के कारण इङ्गलैंड ने ऐसा नहीं किया, बल्कि प्रतिभूतियाँ (Securities) खरीद कर कीमतों को गिरने से बचाये रखा। परिगाम यह हम्रा कि इङ्गलैंड से सोना बराबर बाहर जाता रहा। फ्रांस ने श्रपनी मुद्रा को वास्तविक कीमत से कम कीमत पर स्वर्ण में परिवर्तनशील बनाया था। इसके काररा व्यापारा-शेष फ्रांस के पक्ष में रहा श्रौर विदेशों से फ्रांस में सोना ग्राने लगा, परन्तु फ्रांस ने इस प्रकार ग्राने वाले सोने को सुरक्षित कीषों में इस प्रकार बन्द करना ग्रारम्भ कर दिया कि उसके कारण मुद्रा की मात्रा बढ़कर कीमतें न बढ़ने पायें । *परिगाम यह हुन्ना कि* (Hoards) में जमा करना आरम्म कर दिया । अतएव सोने का संसार के देशों में समान वितरण न हो सका तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सन्तुलन में भारी बाधा उत्पन्न हो गई। इससे स्वर्णमान की स्व-संचालक प्रवृत्ति समाप्त हो गई।

- (२) म्राधिक राष्ट्रीयवाद का विकास (The Development of Economic Nationalism)—संसार के लगभग सभी देशों का युद्ध-कालीन अनुभव वहा दुखदायी था। युद्ध-काल में विदेशी व्यापार के स्थिगत होने म्रथवा उसकी मात्रा में भारी कमी हो जाने के कारण सभी देशों में उन वस्तुम्रों की गम्भीर कमी म्रमुभव हुई थी जिनके लिए वे विदेशी व्यापार पर निभंर रहते थे। जो देश खाद्यान्न तथा भ्रौद्योगिक कच्चे मालों के लिए भी विदेशों पर म्राध्रित थे उनके कष्ट की तो कोई सीमा ही नहीं रही थी। यह भी निश्चय था कि दूसरा महायुद्ध कभी न कभी म्रवश्य छिड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में कप्टों से बचने के लिए बहुत से देशों ने उद्योग-संरच्चण तथा ऋन्य क्षत्रिम रीतियों से देश में उद्योगों के विकास की थोजनगएँ बनाईं। स्रायातों का नियन्त्रण, ऋभ्यंश (Qnota) प्रणाली, निर्यात सहायता स्रादि प्रशुल्क नीति (Fiscal Policy) के प्रमुख स्त्राधार वन गये। ये सभी स्वर्णमान नियमों के विरुद्ध थे स्त्रोर इन्होंने स्नन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा स्वर्णमान के संचालन में भारी उलभन पैदा कर दी।
  - (३) स्वर्ण-कार्षों का अस्वस्थ वितरगा—युद्धकाल तथा युद्धोत्तर काल में संसार के स्वर्ण-कार्षों का विभिन्न देशों के बीच असमान वितरण हो गया। कुछ बड़े देशों के पास सोने की भारी कमी हो गई। जर्मनी तथा पूर्वी यूरोप के अधिकांश देशों के पास सोने की इतनी कमी थी कि उन्होंने सोने के प्रत्येक निर्यात् का रोकने

का प्रयत्न किया, ताकि देश की मुद्रा-व्यवस्था टूटने न पाये। सोने की कमी ने इन देशों को स्वर्णमान की स्वचालकता को भंग करने पर बाध्य किया। इसके विपरीत अमरीका तथा फ्रांस ने काफी सोना जमा करके कठिनाइयां उत्पन्न कर दीं।

- (४) स्वर्ण-चलन-मान का परित्याग—युद्धोत्तर काल में लगभग सभी देशों ने स्वर्ण-पाट-मान तथा स्वर्ण-विनिभय-मान को यहण किया। स्वर्णमान की भाँति इन दोनों मानों में स्वचालकता का ग्रण नहीं होता है। स्वर्णमान के ये रूप मूर्ख-सिद्ध तथा घोखा-सिद्ध नहीं हैं। परिणाम यह हुआ कि विभिन्न राष्ट्रों ने गलती श्रीर मकारी दोनों की श्रीर स्वर्णमान के संचालन को संकट में डाल दिया। स्वर्णमान का संचालन स्वाभाविक रूप में न हो सका। सरकारी हस्तक्षेप की भारी भावश्यकता पड़ी और विभिन्न सरकारों ने समभदारी और ईमानदारी से काम नहीं लिया।
- (५) वैंकिंग तथा साख-मुद्रा के नियन्त्रण की कठिनाई—२० वीं शताब्दी में वैंकिंग प्रणाली तथा साख-मुद्रा का ग्रत्यिक विकास हुआ था। कीमतों पर नियन्त्रण रखने के लिए चलन तथा साख-मुद्रा दोनों ही की मात्रा पर नियन्त्रण आवश्यक होता है, परन्तु अनुभव बताता है कि साख-मुद्रा पर नियन्त्रण रखने के लिए उपाय बहुत सफल न रह सके। यह नियन्त्रण ढीला ही रहा। वैंक दर, खुले बाजार ज्यवसाय तथा वैधानिक नियन्त्रण द्वारा साख-मुद्रा का नियन्त्रण सफल न हो सका।
- (६) शरगार्थी पूँजी का म्रातंक (The Havoc Caused by the Refuguee Capital)—प्रथम महायुद्ध के पूर्व से ही यह प्रथा चली म्रा रही थी कि बहुत से देश विदेशों में म्रल्पकालीन कोषों का विनियोग करते थे, परन्तु दोनों महायुद्धों के मध्य-काल में सभी देशों ने विदेशी पूँजी पर प्रतिबन्ध लगाने म्रारम्भ कर दिये। ब्याजों का भुगतान रोक दिया ग्रीर कुछ दशाम्रों में तो मूलबन भी लौटाना बन्द कर दिया गया। देश के चलन को विदेशी विनियय दरों में परिवर्तन करके भी विदेशियों को हानि पहुंचोंने का प्रयत्न किया गया। परिगाम यह हुम्मा कि ये म्रल्पकालीन विदेशी-कोष सुरद्धा की खोज में एक देश से दूसरे देश में मारे-मारे फिरने लगे। जिस देश में अधिक सुरद्धा दिखाई पड़ती थी, उसी को कोषों का हस्तान्तरग्र कर दिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षा की खोज में भटकने के कारग्र यह पूँजी शरगार्थी पूँजी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस पूँजी का एक देश से दूसरे देश को म्रावागमन इतना शीम्र तथा म्राकस्मिक होता था कि इसने म्रातङ्क मचा दिया भीर बहुत से देश इसके म्रावागमन के म्रनुसार कीमतों में परिवर्तन करने में म्रसम्भ रहे। मन्त में तंग म्राकर उन्होंने स्वर्णमान ही छोड़ दिया।
- (७) युद्धोत्तर-काल की राजनैतिक चालें—प्रथम महायुद्ध के उपरान्त विजयी तथा शक्तिशाली देशों ने जो नीतियाँ ग्रपनाई उन्होंने भी स्वर्णमान के तोड़ने में सहायता दी। ग्रमरीका ने पसस्त देशों से युद्ध का हर्जाना (Reparations)

वसूल करने की सन्धियाँ कीं ग्रीर कुछ देशों को युद्धकालीन ऋगों का भुगतान करने को बाध्य किया। इससे विदेशों में डालर की माँग चारों ग्रीर से बढ़ने लगी ग्रीर सोना तथा पूँजी खिंच-खिंच कर ग्रमेरिका को जाने लगे। बहुत से देश जैंसे जमानी इन ऋगों के भार को सहन न कर सके ग्रीर उन्हों विनिमय दर को बनाये रखने में कठि-नाई ग्रमुभव होने लगी। बाध्य होकर उन्होंने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया।

- (द) ग्राथिक ग्रौर राजनीतिक परिस्थितियों का परिवर्तन—युद्ध के परचात् संसार की ग्राथिक तथा राजनैतिक परिस्थितियाँ इस प्रकार बदल गई थीं कि स्वर्णमान के निर्वाच्ध उपयोग में बाधा होने लगी । यातायात ग्रौर कीमे के व्यय में कमी हो जाने के कारण सोने का ज्ञायात-निर्यात् ज्ञिधिक सुगम हो गया ज्ञौर विदेशी विनिमय दर के साधारण परिवर्तनों के कारण भी सोना एक देश से दूसरे देश को जाने लगा। ऐसी दशा में ग्रनिश्चित परिस्थितियों तथा सोने की कमी को देखते हुए धनहीन देशों ने सोने के ज्ञावागमन पर प्रतिबन्ध लगाना ज्ञारम्म कर दिया, जो स्वर्णमान पद्धित के लिए धातक था।
- (६) स्वर्णामान केवल ग्रनुकूल परिस्थिति मित्र है—स्वर्णमान पद्धित को एक ग्रनुकूल परिस्थिति मित्र कहा गया है। संकट के काल में यह साथ नहीं देती है। बहुत से देशों ने ग्राधिक किठनाइयों का निवारण न होते देखकर इस मान का परित्याग कर दिया।
- (१०) स्वर्णमान देशों की पारस्परिक दासता—स्वर्णमान की यह विशेष्यता है कि वह एक स्वर्णमान देश को अन्य सभी स्वर्णमान देशों की आर्थिक पिरिस्थितियों का दास बना देता है। यदि सरकारी नीति, गृह-युढ, उपद्रव अथवा प्राकृतिक कारणों से एक स्वर्णमान देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो कोई भी स्वर्णमान देश इसके प्रभाव से बच नहीं सकता है। प्रत्येक आधी, चाहे वह किसी भी देश में क्यों न आई हो, सभी स्वर्णमान देशों के आर्थिक वृद्धों को हिला कर ही जाती है। उदाहरणस्वरूप, यदि अत्यधिक बाढ़ के कारण अमेरिका में कीमतें बढ़ती है तो अमेरिका में भ्रायात प्रोत्साहित होंगे। अन्य स्वर्णमान देशों में भी वस्तुओं भ्रीर सेवाओं की माँग के बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ेंगी। इसी प्रकार यदि कोई देश जान-बूक्तकर मुद्रा प्रसार करता है तो इसी नीति का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता है। बहुत से देशों ने यह तर्क रखा कि ऐसे मुद्रामान को ग्रहण करने से क्या लाभ है जो सारे संसार की आपत्तियों और मक्कारियों का दण्ड उन्हीं को देता हो।
  - (११) संसार के देशों के बीच ग्रसहयोग स्वर्णमान की सफलता एक बड़े ग्रंश तक इस बात पर भी निर्भर रहती है कि संसार के स्वर्णमान देशों के बीच किस सीमा तक ग्राधिक, वित्तीय तथा राजनीतिक सहयोग रहता है। यह बहुत ही श्रावश्यक है कि विभिन्न देश मिल-जुल कर काम करें ग्रौर एक दूसरे की कठिनाइयों

को समभने का प्रयत्न करें। किन्तु दोनों महायुद्धों के बीच के काल में तो स्थिति बिलकुल बदल गई थी। प्रत्येक देश दूसरों को घोखा देकर अपना उल्लू सीघा करना चाहता था। सहयोग के स्थान पर शत्रुता की ग्रोर प्रवृत्ति ग्रिधिक तीव थी। ऐसी दशा में स्वर्णामान के सफल संचालन का प्रश्न ही नहीं उठता था।

(१२) महान् श्रवसाद का प्रभाव—स्वर्णमान पर श्रन्तिम, परन्तु सबसे कड़ा, श्राघात महान् श्रवसाद (Great Depression) ने किया। यह श्राधिक संकट सन १६२६ में श्रमरीका के वाल स्ट्रीट सङ्गट (Wall Street Crash) से श्रारम्भ हुश्रा श्रोर स्वर्णमान के चलन के कारण एक दम इसका प्रभाव संसार भर में फैल गया। सभी देशों में बैंक फेल होने लगीं, कीमतें तथा मजदूरियाँ गिरने लगीं श्रोर श्रति-उत्पादन (Over-production) के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। सन् १६३१ में इङ्गलैंड ने स्वर्णमान का त्याग कर दिया श्रोर शीद्र ही परित्याग की प्रवृत्ति ने विश्व-व्यापी रूप घारण कर लिया।

## स्वर्णमान के लाभ अथवा स्वर्णमान की आवश्यकता

स्वर्णमान के उपयोग का प्रधान महत्त्व देशी चलन के आधार के रूप में नहीं रहा है, बल्कि इसने एक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यमान तथा विनिमय माध्यम के रूप, में संसार की सेवा की है। कोई भी एक देश बिना स्वर्ण अथवा अन्य किसी घातु को अपने चलन का आधार बनाये केवल पत्र-मान द्वारा भी अपना काम चला सकता है, परन्तु अपरि-वर्तनशील पत्र-मुद्रा-मान को अपनाने से एक देश को विदेशों से वाणिज्यिक सम्बन्ध बनाये रखने में भारी कठिनाई हो सकती है। यद्यपि पत्र-मुद्रा को देश में स्वतन्त्र स्वीकृति प्राप्त होती है, परन्तु विदेशी लोग उसे अविद्वास की दृष्टि से देखते हैं। यही कारण है कि कठिनाइयों के रहते हुए भी संसार के देशों ने स्वर्णमान को वनाये रखने का बराबर प्रयत्न किया है। इस प्रकार स्वर्णमान का प्रमुख महत्त्व उसके अन्तर्राष्ट्रीय रूप से ही उत्पन्न होता है। इस रूप में स्वर्णमान के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है

## श्रन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के लाभ-

- (१) स्वर्ण अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय माध्यम तथा मूल्यमान का काम करता है— स्वर्ण को उपरोक्त दोनों कों में संसार के सभी देशों में सर्व-प्राह्मता प्राप्त होती है। इससे विनिमय में विशेष सुविधा होती है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के लिए उपयुक्त दशायें उत्पन्न हो जाती हैं। यदि किसी देश के पास सोने का संग्रह है तो उसके पास सभी देशों से वस्तुर्यें तथा सेवायें खरीदने के लिए क्रयःशक्ति होती है। इस प्रकार उसके लिए विदेशी व्यापार सरल हो जाता है।
- (२) विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता -- दूसरा प्रमुख लाभ वानमय दरों की स्थिरता होती है। इन दरों के उच्चावचन की सीमाएँ बहुत ही संकुचित होती हैं और विनिमय दर स्वर्ण आयात तथा स्वर्ण निर्यात बिन्दुओं के भीतर ही रहती है। कारण यह है कि विनिमय दरों में थोड़ा सा भी अधिक परिवर्तन होने से सोने के रूप

में भुगतान होने लगता है। ग्रायात-निर्यात व्यापारियों, विनियोगियों तथा बैंकों को एक प्रकार का संरक्षण प्राप्त हो जाता है, क्यों कि विनिमय दरों के परिवर्तनों के कारण उन्हें हानि नहीं होने पाती है।

- (३) कीमत स्तरों की समानता—अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्गमान एक ऐसा साधन उपलब्ध करता है जिसके द्वारा सभी स्वर्णमान देशों में मूल्य-स्तरों में समानता रहती है। इसके कारण प्रत्येक देश को समान आधार पर तथा समान लाभ प्राप्त करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य में भाग लेने का अवसर मिलता है। स्वर्ण-कोषों का आवाममन कीमतों में इस प्रकार के परिवर्तन करता है कि व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में सन्तुलन स्थापित हो जाता है। कोई भी देश स्थायी रूप से न तो लाभ में रह सकता है और न हानि में।
- (४) मुद्रा प्रसार की प्रवृत्ति पर रोक— चूँ कि मुद्रा स्वर्ण या स्वर्ण पर प्राधारित मुद्रा में परिवर्तनीय होती है, इसलिए मुद्रा की मात्रा बहुत कुछ सोने की मात्रा से सीमित होती है। जनता का विश्वास भी इस मान में प्रमुखतः इसी कारण होता है।

## श्चन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के दोष

म्रातर्राष्ट्रीय रूप में स्वर्णमान के निम्न दोष उल्लेखनीय हैं

- (१) ग्रान्तिरक ग्राधिक स्वतन्त्रता की समाप्ति—स्वर्णमान के श्रालोचकों का कहना है कि स्वर्णमान देश की ग्रान्तिरक ग्राधिक स्वतन्त्रता की समाप्त कर देता है। विदेशी विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखने के लिए देश को ग्रान्तिरक कीमत-स्तर का ग्रन्तर्राष्ट्रीय कीमत-स्तर के साथ समायोजन (Adjustment) करना पड़ता है। स्वर्णमान के ग्रन्तर्गत बिदेशी विनिमय दरों में तो भारी परिवर्तन हो ही नहीं सकते हैं, ग्रतः ग्रसन्तुलन की दशा में किसी भी देश को ग्रपने ग्रान्तिरक कीमत-स्तर में परिवर्तन करके विनिमय दर की स्थिरता कायम रखनी पड़ती है। यदि किसी एक स्वर्णमान देश में कीमतें गिरती हैं तो विनिमय दर की स्थिरता के लिए ग्रन्य स्वर्णमान देशों को भी कीमतें घटानी पड़ेगी। इस प्रकार विदेशी व्यापार के हितों की रक्षा के लिए ग्रान्तिरक ग्रयंव्यवस्था के हितों की बिल देनी पड़ती है।
- (२) स्वर्ण के म्रावागमन का प्रतिकूल प्रभाव स्वर्णमान के इस भवगुण के भी गम्भीर परिणाम होते हैं। स्वर्ण के मावागमन के कारण सभी प्रकार के माविक संकटों का प्रभाव तथा सभी प्रकार की ग्राधिक ग्रव्यवस्था एक देश से दूसरे देश को हस्तान्तरित हो जाती है। यदि एक देश मुद्रा प्रसार का मार्ग अपनाता है तो उस देश में म्रायात बढ़ते हैं और वहाँ से विदेशों को स्वर्ण का निर्यात होता है। विदेशों के स्वर्ण-कोषों में वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण उन देशों में भी कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक इसी प्रकार भ्रवसाद ग्रथवा ग्राधिक संकट के कारण कीमतों में जो कमी होती है वह एक देश से दूसरे देशों में फैल जाती है।

## स्वर्णमान का भविष्य

## क्या स्वर्णमान पुनः स्थापित किया जा सकता है ?—

इससे पहले कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय कि क्या स्वर्णमान को फिर से स्थ पित करना सम्भव है, संद्धों प में उन सब आवश्यकताओं का अध्ययन कर लेना अच्छा होगा, जिन पर स्वर्णमान की सफलता निर्भेर होती है। वे इस प्रकार हैं:—(१) स्वर्णमान की सफलता के लिए इसका एक ही साथ बहुत से देशों द्वारा ग्रहण कर लेना आवश्यक है।(२) संसार में स्वर्ण-कोष पर्याप्त होने चाहिए भौर उनका विभिन्न देशों में न्यायपूर्ण अथवा समान वितरण होना चाहिए।(३) क्यापार की स्वतन्त्रता होनी चाहिए भ्रौर उस पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं होने चाहिए।(४) सभी देशों द्वारा विधिपूर्वक स्वर्णमान के नियमों का पालन होना चाहिए।(५) आन्तरिक मुद्रा-प्रणाली में लोच होनी चाहिए।(६) अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों की मात्रा कम होनी चाहिए।(७) सभी देशों में राजनैतिक स्थिरता रहनी चाहिये श्रौर (०) विभिन्न देशों के बीच मौद्रिक सहयोग होना चाहिए।

उपरोक्त सभी बातों का उपलब्ध होना आधुनिक संसार में श्रसम्भव ही प्रतीत होता है, इसलिये स्वर्णामान की स्थापना की सम्भावना बहुत ही कम है। माधुनिक संसार में राष्ट्रीयवाद तथा निजी स्वार्थों का जोर इतना श्रधिक है कि स्वर्ण-मान की स्थापना बहुत ही कठिन मालूम होती है। "स्वार्थी व्यापारिक प्रणाली के सहारे चल कर किसी भी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली, चाहे वह राष्ट्र के हित में ही क्यों न हो, सफल नहीं हो सकती है।" कीन्ज तथा कैसला (Cassel) का विचार है कि भविष्य में स्वर्शमान की स्थापना लगभग श्रासम्भव है, क्योंकि मल्य की ऋस्थिरता के कारण स्वर्ण ने मौद्रिक चीत्रों में ऋपना महत्त्व नष्ट कर दिया है | इस कारण भविष्य में नियन्त्रित पत्र-मुद्रा-मान ही सम्भय है। इस प्रकार स्वर्णमान का भविष्य उज्जवल नहीं है। स्वर्णमान पर विचार इस समय इस कारण ही किया जाता है कि पत्र-मुद्रा प्रणाली में मुद्रा की अत्यधिक निकासी के कारण जनता के विश्वास को खो देने का भय रहता है भ्रौर साथ ही, इसमें भ्रन्तर्राष्ट्रीय भगतान में भी कठिनाई होती है। जब तक स्वर्श-कोषों का पुनर्वितरण नहीं होगा, मुद्रा-स्फीति की नीति नहीं छोड़ी जायगी और जब तक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित नहीं होगा, स्वर्णमान की स्थापना की कोई भी ऋाशा नहीं हो सकती है। साथ ही, सोना उत्पन्न करने वाले देशों को भी श्रपनी स्वर्ण-नीति में परिवर्तन करना त्र्यावश्यक होगा।

<sup>\* &</sup>quot;It is impossible to have an international financial system alongside a commercial system that is fiercely and jealously national." See G. Crowther: Outline of Money, p. 319.

श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष श्रीर स्वर्णमान (International Monetary Fund and Gold Standard)—

स्वर्णमान के टूट जाने के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा लेन-देन में जो भारी गड़बड़ उत्पन्न हो गई थी उसी को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा परिपद् की बैठक जुलाई सन् १६४४ में ब्रेटन बुड्स (Bretton Woods) में हुई थी और इस परिपद् ने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की एक योजना स्वीकार की थी। परिषद् ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुर्नानमांग्र और विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development) की स्थापना की योजना बनाई थी। इस योजना को कार्य रूप दे दिया गया है। इस योजना में स्वर्णमान की स्थापना नहीं की गई है, परन्तु सोने को कीमतों के अन्तिम मान के रूप में रख कर एक अंश तक सोने को अन्तर्राष्ट्रीय कीमत-स्तर तथा विनिमय दरों का आधार बनाया गया है। नई व्यवस्था में स्वर्ण का स्थान निम्न प्रकार है:—

- (१) प्रत्येक सदस्य देश को ग्रपने श्रभ्यंश का एक निश्चित प्रतिशत सोने में जमा करना होता है।
- (२) प्रत्येक देश को अपने चलन की कीमत सोने में परिभाषित करनी पड़ती है और इसी के आधार पर विदेशी विनिमय दरें निर्घारित की जाती हैं।
- (३) मुद्रा-कोष के पास किसी विशेष चलन की सामान्य कमी हो जाने की दशा में कोष ऐसे चलन को सोना देकर खरीद सकता है।

उपरोक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त सोने को और कुछ भी महत्त्व नहीं दिया गया। प्रत्येक देश को सांकेतिक सिक्कों के चलाने तथा पत्र-मुद्रा चलन प्रगाली स्थापित करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। आरम्भ में तो प्रत्येक सदस्य देश विदेशी व्यापार सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी बनाये रख सकता है।

## रजत-मान (Silver Standard)-

रजत-मान में मुद्रा इकाई का मूल्य चाँदी में नियत किया जाता है और निभाया जाता है। ऐसा करने के लिए चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण रखा जाता है और उसके एक निश्चित वजन तथा शुद्धता के सिक्के तैयार किये जाते हैं। चीन लम्बे समय तक रजत-मान का ही अनुयायी रहा है। भारत में सन् १८३५ से सन् १८६३ तक रजत-मान का चलन रहा है। रुपये का स्वतन्त्र मुद्रण होता था, उसना वजन १८० ग्रेन रखा गया था और उसकी शुद्धता ११/१२ थी। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार था कि वह सरकारी टकसाल से चाँदी की सिलों को रुपयों में ढलवा सकता था। इसी प्रकार जनता को रुपयों को गला कर धातु के रूप में बेचने का भी पूर्ण अधिकार था।

यह मुद्रा प्रणाली सन् १८७४ तक ठीक-ठीक चलती रही थ्रौर इसमें मुद्रा का विस्तार तथा संकुचन स्वयं ही होता रहता था, परन्तु सन् १८७४ से सोने में चाँदी की कीमतों तेजी के साथ गिरने के कारणा किनाइयाँ आरम्भ हो गईं। चाँदी की कीमतों के गिरने के कई कारणा थे:— चाँदी की पूर्ति बढ़ गई थी थ्रौर उसकी माँग अपेक्षतन कम हो गई थी। इसके विपरीत मुद्रा उद्देशों के लिए यूरोप के देशों में सोने की माँग अधिक बढ़ गई थी, जबिक सोने के उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई थी। भारत में तो चाँदी की कोमतों के इस पतन के गम्भीर परिगाम दृष्टिगोचर हुए । जनता के लिए यह लाभदायक हो गया कि वे सस्ते दामों पर बाजार से चाँदी खरीद कर उसे सरकारी टकसाल में रुपयों में ढलवा ले। इसके कारणा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई श्रौर वस्तुओं श्रौर सेवाओं की कीमतों बढ़ने लगीं। कीमतों की इस वृद्धि के कारण देश के आयात व्यापार में कठिनाई उत्पन्न होने लगी। इसी प्रकार गृह खर्ची (Home Charges) के भार में वृद्धि हो गई श्रौर भारत सरकार के लिए श्रपने बजट का सन्तुलन कठिन हो थ्या। श्रन्त में, हरशैल समिति (Herschell Committee) की सिफारिश पर सन् १८६३ में भारत ने चाँदी के स्वतन्त्र मुद्रण को समाप्त कर दिया।

व्यवहार में रजत-मान के नियम श्रोर उसका कार्यवाहन स्वर्णमान की ही भाँति होता है, परन्तु रजत-मान के स्थान पर स्वर्णमान को इस कारण श्रिधिक श्रच्छा समक्षा जाता है कि चाँदी की कीमतों की तुलना में सोने की कीमतों में साधारणतया कम परिवर्तन होते हैं।

#### **QUESTIONS**

- 1. Explain what you mean by 'Gold Standard' and state under what conditions it works smoothly. (Raj., B. A., 1958)
- 3. Examine critically the working of the Gold Exchange Standard. Discuss the position of gold under it. What are the objections against it? (Raj., B. Com., 1957)
- 3. Point out the characteristics of the various forms of Gold Standard. (Agra, B. A., 1956 Supp.)
- 4. "The case for the Gold Standard is a case for a strict de jure Gold Standard with each country following the rules so that no gold currency becomes distrusted." Explain and comment. (Agra, B. A., 1956)

(Agra, B. A., 1958)

5. स्वर्णमान पर नोट लिखिए

- स्वर्णामान के नियमों पर नोट लिखिए (Agra, B. A., 1957 Supp.) स्वर्णामान पद्धति का पूर्ण रूप से वर्णान कीजिए। (Agra, B. A., 1957)
- 6. Discuss the essential conditions which you think necessary for successful working of 'Gold Standard.' What led to the abondonment of Gold Standard by countries?

(Raj., B. A., 1957 and B. Com., 1958)

7. Write a note on-Gold Bullion Standard.

(Agra, B. Com., 1957 Supp.)

Gold Exchange Standard.

(Agra, B. Com., 1956 Supp. and B. A., 1959) Sterling Exchange Standard. (Agra, B. Com., 1956)

- 8. Discuss the limitations of Gold Standard in the context of an expansionist economy. What led to its breakdown in the
- inter-war period? Explain. (Raj. B. Com., 1955)

  9. Is it possible to have Gold Standard without Gold Currency?
  Give reasons for your answer and explain the merits and
- demerits of sash a standard. (Sagar, B. A., 1958)

  10. श्रान्तर्राष्ट्रीय स्वर्रा प्रमाप बिना किसी रुकावट के सरलातापूर्वक कार्य कर सके, इसके लिए कौनसी श्रानवार्य शर्तों का होना श्रावश्यक है, उनकी विवेचना कीजिए। उन कारणों की परीचा कीजिए जिनके फलस्वरूप सन् १६३१ में श्रान्तर्राष्ट्राय स्वर्ण प्रमाप समाप्त हो गया। " (Sagar, B. Com, 1954)
- 11. स्वर्ग प्रमाप की प्रमुख विशेषताएँ बताइये। (Jabalpur, B. A., 1958)
  12. Describe the different kinds of Gold Standard. Can Gold
- Standard secure stability of prices? (Bihar, B. A., 1958)

  13. 'Gold Standard failed primarily because it could not reconcile exchange stability with price stability.' Discuss.
- (Patna, B. A., 1957)
- 14. Write a note on—Gold Standard. (Raj., B. Com., 1954)
- 15. Examine critically the working of the Gold Standard. What were the reasons for its failure. स्वर्णमान के प्रयोग का श्रालोचनात्मक परांच्या करिए। उसकी विफलता के क्या कारण थे? (Agra, B. Com. 1959)
- 16. Distinguish between the gold exchange standard and the gold bullion standard proposed by the Hilton-Young Commission. State your views on the latter as a scheme of currency arrangement for the country. (Raj., B. Com., 1960)

#### अध्याय ७

## पत्र-चलन-मान

(Paper Currency Standard)

पत्र मुद्रा का प्रारम्भ (The Origin of Paper Money)—

पत्र-मुद्रा का इतिहास बहुत पूराना है। ऐसा अनुमान है कि कागज का आविष्कार सबसे पहिले चीन में हुया था। कागज को मुद्रा के रूप में भी सबसे पहिले चीन में ही उपयोग किया गया था। ऐतिहासिक खोज से पता चलता है कि ६ वीं शताब्दी के ग्रारम्भ में चीन में सम्राट हेसेनट्ड (Hsientung) के राज्य-काल में पत्र-मुद्रा चालू की गई थी। उस समय इस मुद्रा के चालू करने का प्रमुख उद्देश्य लोहे स्रीर ताँबे के भारी सिक्कों के ढोने की कठिनाई को दूर करना था। चीन के पश्चात् जापान श्रीर ईरान (Persia) में भी कागज के नोटों का चलन श्रारम्भ हुआ। चीन में १७ वीं शताब्दी के मध्य काल तक पत्र-मूद्रा को उपयोग बराहर होता रहा, यद्यपि बीच-बीच में कभी-कभी इसका उपयोग बन्इ भी कर दिया जाता था। चीनी सम्राटों की भांति मंगील सम्राटों ने भी पत्र-मुद्रा को चालू रखा। एशिया के परचात् यूरोप के देशों में भी कागज के नोट चलने लगे. यद्यपि ज्ञारम्भ में योरोपीय देशों में चमड़े के नोट चलाये गये थे। ऐसे नोटों का एक उदाहररा भारत में सम्राट हमायू के काल में भी मिलता है, जबिक बचा सक्ता ने चमड़े की मुद्रा चालू की थी। संसार के लगभग सभी उन्नित-शील देशों ने १७ वी शताब्दी के अन्तिम काल में परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का चलन म्रारम्भ हो गया था भौर १८ वीं शताब्दी में तो सरकारी म्रादेश पर अपरिवर्तनशील पत्र-मूद्रा भी चालू हो गई थी।

प्राचीन काल में नोटों का रूप वर्तमान नोटों जैसा नहीं था। श्रलग-स्रलग देशों में अलग-स्रलग रूप, रङ्ग ग्रीर नमूने के कागजी नोट चलते थे। कागजी नोटों के खलन को अत्यिक्षक प्रोत्साहन प्रथम महायुद्ध काल में मिला। इस काल में यूरोप की सरकारों को चन की ग्रीं कि ग्रावश्यकता थी। लगभग सभी देशों ने कागज के नोट छापकर आय प्राप्त की। इङ्गलैन्ड, फान्स, जर्मनी ग्रादि देशों के श्रतिरिक्त, जिनका युद्ध से प्रत्यक्ष सम्बन्ध था, तटस्थ देशों ने भी स्वर्णमान को स्थिगत कर दिया। इस काल में भारत में भी ग्रपिवतंनशील पत्र-मुद्रा चालू की गई थी। घीरे-घीरे पत्र-मुद्रा के प्रति जनता का विश्वास तथा परिचय-बढ़ता गया ग्रीर युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी पत्र-मुद्रा का चलन युद्ध-काल की भांति ही बना रहा। सन् १९३१ में स्वर्णमान फिर हूट गया ग्रीर संसार के अधिकांश देशों ने पत्र-मुद्रा को ही श्रपनी मुख्य-मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया। लगभग सभी देशों में पत्र-चलन-मान स्थापित हो गया। दूसरे महायुद्ध के

काल में पन्न-मुद्रा का और भी विस्तृत उपयोग हुन्ना है तथा उसकी मात्रा में आश्चर्य-जनक वृद्धि हुई है। निस्सन्देह न्नाज का संसार पन्न-मुद्रा से परिचित ही नहीं है, बिल्क वह इसे बड़ी महत्त्वपूर्ण मुद्रा समभता है। यह कहना तो किठन है कि पन्न-मुद्रा के उपयोग का प्रारम्भिक कारण क्या था, परन्तु यह निश्चय है कि कागजी नोटों के लाभों ने उनके प्रचलन को बढ़ाया है। यहाँ तक कि ग्राज का संसार धातु-मुद्रा को धीरे-धीरे भूल सा रहा है।

### पत्र-मुद्रा के लाभ-

जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है कि ग्रपने विशेष ग्रुएों के कारए ही पत्र-मुद्रा सर्व-ग्राह्य हुई। इस मुद्रा के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं:—

- (१) घातु-मुद्रा की बचत—पत्र-मुद्रा घातु के सिक्कों का स्थान ग्रहण कर लेती है, जिसके वारण उसके उपयोग से घातु-मुद्रा की ग्रावश्यकता कम हो जाती है। इस प्रकार बचा हुग्रा सोना ग्रीर चाँदी श्रौद्योगिक तथा कलात्मक कामों के लिए उपयोग किया जा सकता है। एडम स्मिथ ने कहा है: "कागज के नोट आकाश मार्ग की माँति हैं—उनके नीचे की भूमि भी काम में लाई जा सकती हैं और उस पर अन आदि उत्पन्न करके मनुष्य की अन्य आवश्यकताएँ पूरी की जा सकती हैं। 35%
- (२) वहनीयता—पत्र मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भ्रिष्ठिक सुविधा रहती है, क्योंकि मूल्य के अनुपात में कागज के नोट का बोभ बहुत ही कम होता है। पत्र-मुद्रा में वहनीयता का विशाल ग्रुए। है। सौ रुपये के सिक्कों की अपेक्षा सौ रुपये के एक नोट को ले जाने में किठनाई तथा व्यय बहुत ही कम होता है और सुरक्षा भी अधिक रहती है।
- (३) घातुम्रों के सिक्कों की घिसावट में बचत—कागज के नोट बहुमूल्य घातुम्रों के सिक्कों की घिसावट द्वारा होने वाली हानि से भी बचत करते हैं। प्रचलन के म्रन्तर्गत सिक्के घिस-घिस कर पुराने होते जाते हैं भौर उनमें से घातु की मात्रा धीरे-धीरे घटती जाती है। यदि सिक्कों के स्थान पर कागज के नोट चलाये जाते हैं तो यह हानि बच जाती है।
- (४) सस्ती एवं मितव्ययी—पत्र-मुद्रा सरकार के दृष्टिकोगा से बहुत सस्ती एवं मितव्ययी होती है। इसके उत्पादन का व्यय बहुत ही कम होता है। इसके विपरीत घातु मुद्रा के सम्बन्ध में खानों से घातु को निकालने, गलाने, साफ करने तथा उसे सिक्हों में ढलाने पर भी श्रिषक व्यय होता है। इस प्रकार कागज के नोटों का उपयोग करके श्रम श्रीर पूँजी की बचत की जा सकती है श्रीर उन्हें श्रन्य उपयोगी कार्यों में लगाकर श्रिषक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
  - (५) मुद्रा प्रगाली में लोच पत्र-मुद्रा, देश की मुद्रा प्रगाली में, लोच

उत्पन्न कर देती हैं, जो एक महत्त्वपूर्ण गुरा होता है। पत्र-मुद्रा की मात्रा शीघ्रतापूर्वः बिना भारी व्यय के घटाई-बढ़ाई जा सकती है और इस प्रकार मुद्रा की माँग औ पूर्ति में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। सोने और चाँदी के सिक्कों की मात्र को बढ़ाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इन घातुश्रों के स्टॉक कठिनाई से प्राप्त होते हैं।

- (६) सरकार को सुविधा—संकट काल के लिए पत्र-मुद्रा ही देश की हूबती हुई नौका का एक मात्र सहारा होती है। संकट काल में सरकार कागज के नोट छाप कर आय प्राप्त कर सकती है। युद्ध-काल में लगभग सभी सरकारों ने ऐसा ही किया था। यदि सरकार ऋगों द्वारा आय प्राप्त करने का प्रयत्न करती है तो प्रथम तो, सदा ही ऋगों का मिलना कठिन होता है और दूसरे, ऐसे ऋगों के ब्याज चुकाने और उनके प्रबन्ध पर सरकार को काफी व्यय करना पड़ता है।
- (७) प्रयोग करने में सुविधा—पत्र-मुद्रा को गिनने और उसका हिसाब करने में सुविधा होती है।
- ( ८ ) समानता एवं एकरूपता—पत्र-मुद्रा में समानता ग्रौर एकरूपता पाई जाती है। यह इस मुद्रा का विशेष गुरा है।
- ( ६ ) बैं किंग प्रवृत्ति का विकास—इस मुद्रा का उपयोग लोगों में बैंकिंग प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, जो कि देश के लिए बहुत ग्रावश्यक है, क्योंकि इससे बचत प्रोत्साहित होती है ग्रौर वाि्ए ग्रौर व्यापार की उन्नति होती है।
- (१०) घोखा-धड़ी की शीघ्र पकड़ यदि जाली नोट चलन में भ्रा जायें तो इनके नम्बरों को भ्रखबारों में छपवाकर प्रजा को इन्हें स्वीकार करने से मना किया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रगाली में घोखा शीघ्र पकड़ में भ्रा जाता है।

## पत्र-मुद्रा की हानियाँ—

यद्यपि पत्र-मुद्रा के ग्रनेक लाभ हैं ग्रौर वर्तमान संसार ने इसे स्थाई तथा सर्वे व्यापी रूप में स्वीकार भी कर लिया है, परन्तु इसके दोष भी गम्भीर हैं। प्रमुख हानियाँ निम्न प्रकार हैं:—

- (१) सरकार की इच्छा पर मूल्य की निर्भरता—पत्र-मुद्रा में कुछ भी निहित मूल्य (Intrinsic Value) नहीं होता है। यदि ऐसी मुद्रा का विमुद्रीकरण हो जाता है तो पदार्थ के रूप में इसका कुछ भी मूल्य शेष नहीं रहता है। इस मुद्रा का मूल्य अस्थिर तथा ग्रस्थाई होता है, क्योंकि यह सरकार की इच्छा पर निर्भं होता है। यही कारण है कि पत्र-मुद्रा के प्रति जनता का विश्वास धातु-मुद्रा की तुलना में बहुत कम होता है।
  - (२) अत्यधिक निकासी का भय-कागज के नोट सरकार अपनी

इच्छा के अनुसार किसी भी मात्रा में छाप सकती है। ऐसी मुद्रा की अत्यधिक निकासी का भय सदा ही बना रहता है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में इस प्रकार का भय नहीं रहता है, परन्तु परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा प्रणाली में निधि-अनुपात को घटाकर कागज के नोटों की संख्या में इच्छानुसार वृद्धि की जा सकती है। अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा तथा प्रादिष्ट मुद्रा में तो चलन के विस्तार पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं होते हैं। चलन के इस प्रकार के विस्तार के परिणाम काफी भयानक हो सकते हैं। इसके कारण कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होती है और भीपण मुद्रा-प्रसार के कारण जनता को घोर कष्ट होता है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् जर्मनी की दशा अत्यन्त खराब हो गई थी और मुद्रा-स्फीति की प्रचण्डता के कारण सारो अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी। दूसरे महायुद्ध के काल में भारत में मुद्रा विस्तार के कारण ही कीमतें बढ़ी थीं और युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में मुद्रा-प्रसार ने आतंक मचा दिया था।

- (३) शीघ्र खराब हो जाने का दोप—कागजी नोटों के फट जाने, गल जाने तथा तेल से खराब हो जाने का भय भी श्रिधिक रहता है। वैसे तो सरकार इस प्रकार के खराब नोटों को बदलने का श्राश्वासन देती है, परन्तु फिर भी जनता को इससे श्रमुविधा श्रवश्य होती है श्रीर नोटों के उपयोग में सावधानी से काम लेना पड़ता है।
- (४) चलन का सीमित क्षेत्र—पत्र-मुद्रा के चलन का क्षेत्र सीमित होता है। देश के बाहर कोई भी उसे स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि इन नोटों को केवल सरकार के विशेष कानून द्वारा मूल्य प्रदान किया जाता है। पाकिस्तानी नोट भारत में विधि-ग्राह्म नहीं हैं और यही कारण है कि लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं।
- (५) कीमतों की ग्रस्थिरता—पत्र-मुद्रा का मूल्य साधारणतया बहुत श्रिनिहचत तथा ग्रस्थिर होता है। उसमें अकस्मात ही घोर उच्चावचन (Fluctuations) हो सकते हैं। इसके कारण सभी वस्तुओं की कीमतों में तेजी से परिवर्तन होने लगते हैं। इस श्रिनिहचतता का देश के आन्तरिक कीमत-स्तर और देश की ग्रथं व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है और विदेशी विनिमय दरों में भारी उथल-पुथल होने लगती है। परिणाम यह होता है कि व्यापार और उत्पादन श्रीनयमित हो जाते हैं।
- (६) सरकार द्वारा दुरुपयोग—सरकार द्वारा आय प्राप्त करने के हेतु जो पत्र-मुद्रा निकाली जाती है वह करारोपएए की ही प्रकृति रखती है, परन्तु यह करारोपएए न्याय-विरुद्ध होता है और समाज के निर्धन वर्गों के लिए अत्यिधिक कष्टदाय्क होता है। वैसे भी इस प्रकार की मुद्रा-निकासी का आधार ही गलत होता है, क्योंकि चलन की निकासी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होती है, विल्क सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार होती है।
- ( ६) ग्रार्थिक जीवन में ग्रस्थिरता-पत्र-मुद्रा में सभी प्रकार की परिकल्पना (Speculation) को प्रोत्साहित करने का दोष होता है। साख-मुद्रा तो

विशेषतया भयद्भर होती है। पूँजीवादी देशों में व्यापार चक्रों (Trade Cycles) का एक महत्त्वपूर्ण कारण साख-मुद्रा तथा पत्र-मुद्रा की निकासी की अनियमितता तथा अनिश्चितता ही होती है। यही कारण है कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने पत्र-मुद्रा को एक प्रकार का गामाजिक घोखा (Social Fraud) कहा है। ''पत्र-मुद्रा किसी देश की सबसे भयद्भर महामारी है। कोई भयद्भर से भयद्भर बीमारी किसी व्यक्ति को जितना अधिक से अधिक कष्ट दे सकती है, उससे भी अधिक कष्ट पत्र-मुद्रा के कारण समाज को होता है।''

(८) जनता का कम विश्वास—जनता को इस मुद्रा में विश्वास कम होता है, क्योंकि उन्हें इस बात का भय रहता है कि सरकार कभी भी इस मुद्रा को ग्रमान्य घोषित कर सकती है।

### निष्कर्ष—

इस सम्बन्ध में यह निर्णय किठन है कि दोष पत्र-मुद्रा का है, ग्रथवा मनुष्य का । संसार में कोई भी वस्तु बुरी नहीं होती है । प्रत्येक वस्तु की ग्रच्छाई ग्रौर बुराई उसके उपयोग पर निर्भर होती है । पत्र-मुद्रा के विषय में तो उपरोक्त कथन ग्रौर भी भ्रधिक सही है । पत्र-मुद्रा में स्वयं तो कुछ भी बुराई नहीं होती । यह तो सरकार की इच्छा है कि वह उसे समाज ग्रौर राष्ट्र के कल्याण के लिए उपयोग करती है अथवा उसके विनाश के लिए । कागजी नोट निकाल कर समुचित नियन्त्रण द्वारा देश के त्रार्थिक नियोजन को सफल बनाया जा सकता है ज्रौर त्रार्थिक तथा सामाजिक जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जाया जा सकता है, परन्तु यह सब तभी सम्भव है जबिक सरकार समभदारी से काम लेती है ग्रौर राष्ट्रीय हितों को ही प्रधानता देती है । पत्र-मुद्रा के ग्रधिकाँ दोष मुद्रा-नियन्त्रक की मूर्खता, ग्रज्ञानता, संकुचित दिष्टकोण तथा स्वार्थरता के कारण उत्पन्न होते हैं ।

### पत्र-मुद्रा का वर्गीकरण-

पत्र-मुद्रा को दो बड़े-बड़े भागों में बाँटा जा सकता है:—पत्र मुद्रा-चलन (Paper Currency) तथा पत्र-मुद्रा-मान (Paper Standard) । इनमें से पत्र-मुद्रा-चलन का अध्ययन तूरे एक पिछले अध्याय में किया जा चुका है। प्रस्तुत विवेचना में केवल पत्र-मुद्रा-चलन का ही अध्ययन किया जायगा। पत्र-मुद्रा-मान की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि इस मान में किसी धातु को मुद्रा का आधार नहीं बनाया जाता है। देश में अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का चलन होता है और वहीं देश की प्रामाणिक मुद्रा होती है। कागज के नोटों के पीछे केवल कागजी प्रतिभृतियों की ही आड़ होती है।

पत्र-मुद्रा-मान, प्रवन्धित पत्र-चलन श्रथवा चलन-धिनिमय-मान (Paper Standard, Managed Paper Currency or Currency Exchange Standard)—

इस मुद्रा पद्धित में पत्र-मुद्रा ही ग्रामाणिक मुद्रा होती है। देश का मुद्रा-

नियन्त्रक पत्र-मुद्रा को स्वर्ण श्रथवा श्रन्य किसी धातु में परिवर्तित करने का उत्तर-दायित्व नहीं लेता । सन् १६२६ के महान् ग्रवसाद के पश्चात् संसार के बहुत से देशों को स्वर्णमान का परित्याग करने पर बाध्य होना पड़ा था । इन सभी देशों ने पत्र-मुद्रा मान ग्रह्ण कर लिया था । इस पद्धित में विनिमय-माध्यम का कार्य पत्र-मुद्रा ही करती है । पहले तो इस मान का उपयोग सङ्क्ष्ट-कालीन परिस्थितियों में किया जाता था, परन्तु श्रव इसका उपयोग विना संकोच किया जाता है । इस पद्धित की प्रमुख विशेष-ताएँ निम्न प्रकार हैं :—

## पत्र-मुद्रामान की विशेषतायें—

- (१) पत्र-मुद्रा देश में प्रामािग्कि तथा अपरिमित विधि-याह्य मुद्रा होती है।
- (२) पत्र-मुद्रा का मूल्य स्वतन्त्र रूप में निश्चित होता है। स्वर्ण श्रथवा श्रन्य किसी घातु द्वारा उसका मूल्य निश्चित नहीं होता है श्रोर पत्र-मुद्रा को घातु में बदलने की व्यवस्था नहीं की जाती है।
- (३) इस पद्धित में चलन का प्रवन्ध अथवा नियमन (Regulation) मुद्रा-नियन्त्रक द्वारा किया जाता है। उद्देश्य यह होता है कि कीमत-स्तर की स्थिरता बनी रहे, जिसके लिए मुद्रा-संचालक चलन की मात्रा को आवश्यक श्रंश तक बढ़ाता-घटाता रहता है। चलन की पूर्ति को उसकी माँग के बराबर बनाये रखकर कीमतों की स्थिरता प्राप्त की जाती है।
- (४) इस प्रणाली में भी विदेशी ऋगों के भुगतान के लिए स्वर्ण-कोपों की आवश्यकता पड़ती हैं, क्घोंकि विदेशी देश के चलन को स्वीकार नहीं करते हैं। इस कार्य के लिए सोना जमा किया जाता है, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना के पश्चात् श्रव अन्तर्राष्ट्रीय ऋगों के भुगतान में सोने की आवश्यकता नहीं रही है।

## भारत के वर्तमान चलनमान के उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण-

इस पद्धित के कार्यवाहन को समभने के लिए भारत सरकार के वर्तमान चलन-मान की विवेचना उपयुक्त होगी। स्वर्णमान के परित्याग के परचात भारत ने सन् १६३१ में स्टिलिङ्ग-विनिमय-मान स्थापित किया। भारतीय पत्र-मुद्रा ब्रिटिश पौंड स्टिलिङ्ग में परिवर्तनशील थी। जब तक स्टिलिङ्ग की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता बनी हुई थी, भारतीय कागजी नोटों के बदले में स्टिलिङ्ग के माध्यम से सोना प्राप्त किया जा सकता था, परन्तु जब स्टिलिङ्ग ही एक ऋपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा बन गया तो भारतीय मुद्रा-प्रणाली पत्र-मुद्रा-मान का ही एक रूप बन गई। भारत का मुद्रा-सञ्चालन रिजर्व बेंक ग्रॉफ इण्डिया द्वारा किया जाता था। रिजर्व बेंक रुपये की कीमत १ शिलिङ्ग ६ पैंस के बराबर रखती थी। इस उद्देश्य से रिजर्व बेंक १०,००० पाँड अथवा उससे अधिक कीमत का स्टर्लिङ्ग १ शिलिङ्ग ५ है पेंस प्रति रुपया की दर से खरीदती थी और १ शिलिङ्ग ६ है पेंस प्रति रुपया की दर से बेचती थी। भारत के इस मान को हम चलन-विनिमय-मान प्रणाली (Currency Exchange Standard) कह सकते थे, क्योंकि स्वयं स्टर्लिङ्ग स्वर्ण पर आधारित नहीं था। देश के भीतर रुपया ही विनिमय माध्यम तथा मूल्यमान का कार्य करता है। रुपये के बदले में केवल पत्र-मुद्रा तथा गौण सिक्के ही लिए जा सकते हैं, सोना नहीं। सन् १६४७ तक स्टर्लिङ्ग तथा भारतीय रुपया दोनों में से किसी का भी स्वर्ण से कोई सम्बन्ध न था, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की सदस्यता के कारण अब रुपये को स्वर्ण में एक निश्चित मूल्य दिया गया है। सन् १६४७ में रुपये का स्वर्ण मूल्य ० २६ ६० शाम रखा गया था। वैसे तो भारतीय रुपये तथा स्टर्लिङ्ग का वैधानिक गठबन्धन द अप्रैल सन् १६४७ से टूट चुका है, परन्तु व्यवहार में दोनों का यह सम्बन्ध अभी तक भी बना हुआ है।

## पत्र-मुद्रा-मान प्रणाली के गुण-

पत्र-मुद्रा-मान के निम्न गुरा बताये जाते हैं :---

- (१) मूल्यों में स्थिरता—मुद्रा ग्रधिकारी देश की ग्रावश्यकताग्रों के ग्रनु-सार पत्र-मुद्रा की मात्रा में घट-बढ़ करके देश में मूल्यों में स्थिरता ला सकता है ग्रौर इस कार्यं के लिए उसे कोई भी स्वर्ण-कोष रखना ग्रावश्यक नहीं है।
- (२) प्रबन्ध की स्वतन्त्रता—इस मान के अन्तर्गत मुद्रा की मात्रा किसी धातु पर निर्भर नहीं होती, अतः मुद्रा अधिकारी अपनी इच्छानुसार मुद्रा का प्रबन्ध-संचालन कर सकता है।
- (३) उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग—यह देखा गया है कि स्वर्ण-मान की प्रवृत्ति मुद्रा-संकुचन की श्रोर होती है। इससे देश में बेकारी रहती है श्रौर उत्पत्ति के साधनों का श्रच्छी तरह से उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन पत्र-मुद्रा के अन्तर्गत हर एक देश श्रपनी आवश्यकता के श्रनुसार मुद्रा-नीति का संचालन कर सकता है, जिससे देश में उत्पादन के साधनों का उपयोग हो सके। उसे भ्रन्य देशों पर निर्भर रहने या उनका अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार पत्र-मुद्रा-मान लोचदार होता है।

## पत्र-मुद्रा-मान प्रणाली के दोष-

पत्र मुद्रा-मान प्रणाली के अनेक दोष हैं। प्रमुख अवगुण निम्न प्रकार हैं:-

- (१) अरयधिक निकासी का भय—पत्र-मुद्रा के पीछे किसी प्रकार की धातु-निधि न होने के कारण मुद्रा की अरयधिक निकासी का भारी भय रहता है। इस प्रणाली में अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा के सभी दोष रहते हैं।
  - (२) कीमतों के परिवर्तनों की कोई सीमा नहीं—इस प्रणाली के ग्रन्त-

गंत कीमतों के परिवर्तनों की कोई भी सीमा नहीं होती है। पत्र-मुद्रा में निहित मूल्य कुछ भी नहीं होता, इसलिए उसके मूल्य-पतन की भी कोई ग्रन्तिम सीमा नहीं होती है। घातु-मुद्रा की कीमत तो सिक्के की निहित कीमत से नीचे नहीं कही जा सकती है, परन्तु पत्र-मुद्रा की कीमत की ऐसी कोई सीमा नहीं होती है। इसी कारण कीमतें किसी भी सीमा तक ऊपर जा सकती हैं।

- (३) विदेशी विनिमय दरों में उच्चावचन—देश की आन्तरिक कीमतों की भाँति विदेशी विनिमय दरों के परिवर्तनों की भी कोई सीमा नहीं होती है। पत्र-मुद्रा-मान में विनिमय दरों में ग्रपरिमित उच्चावचन हो सकते हैं। इससे विदेशी व्यापार में अनेक ग्रड़चनें पैदा होती हैं। सन् १६३१ के पश्चात् इस मान के सर्वव्यापी उपयोग के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी ऋणों की मात्रा में भारी कमी ग्रा गई है।
- (४) एक देश की आर्थिक अवस्था का दूसरे देश पर प्रभाव जिस प्रकार स्वर्णमान के अन्तर्गत एक देश की आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तनों का प्रभाव सभी स्वर्णमान देशों पर पड़ता है, इसी प्रकार यदि सभी देशों में पत्र-मुद्रा-मान का चलन है तो एक देश के आर्थिक सङ्कटों का प्रभाव दूसरों पर अवश्य पड़ेगा। परन्तु ऐसा तभी होगा जबकि ब्यापार स्वतन्त्र है, परन्तु अनुभव यह है कि पत्र-मुद्रा-मान का युग विदेशी व्यापार सम्बन्धी प्रतिबन्धों का भी युग होता है।

श्चन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा श्चन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण श्चौर विकास बैंक की स्थापना ने संसार में पत्र-सुद्रा-मान की कठिनाइयों को एक बड़े श्चंश तक दूर कर दिया हैं। प्रत्येक देश के चलन का मूल्य सोने में घोषित किया जाता है श्चौर विनिमय-दरों की स्थिरता के लिए मुद्रा-कोष की कुछ विशेष व्यवस्थाएँ हैं। यद्यपि मुद्रा-कोष सोने को मुद्रा का श्राघार बनाने पर विशेष बल नहीं देता है, परन्तु विदेशी मुद्राश्चों को बेच कर तथा उधार देकर यह कोष विनिमय दरों में स्थिरता लाता है श्चौर अन्तर्राष्ट्रीय ग्राधिक तथा मौद्रिक सहयोग के लिए ग्रनुकूल दशाएँ उत्पन्न करता है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का कार्य विदेशी पूँजी के ग्रावागमन में सहायता करना तथा ग्रन्तर्राष्ट्रीय ऋगों को प्रोत्साहित करके उनकी मात्राश्चों को बढ़ाना है।

## प्रादिष्ट-मान (Fiat Standard)-

इस मान को कभी-कभी नियन्त्रित पत्र-चलन-मान (Managed Paper Currency Standard) भी कहा जाता है। प्रामाणिक प्रादिष्ट मुद्रा को सरलता से पहिचना जा सकता है। कैन्ट के अनुसार इसकी तीन प्रमुख विशेषतायें होती हैं:— (१) पदार्थ के रूप में इसका निहित मूल्य लगभग कुछ भी नहीं होता है। (२) इसे किसी ऐसी वस्तु में नहीं बदला जा सकता है जिसका मूल्य प्रादिष्ट मुद्रा के ग्रिङ्कित मूल्य के बराबर हो ग्रीर (३) इसकी क्रयःशक्ति किसी भी वस्तु की क्रयःशक्ति के समान नहीं रखी जाती है।\*

इस प्रकार प्रादिष्ट मुद्रा साधारणतया ऐसी पत्र-मुद्रा होती है जो स्वर्ण अथवा अन्य किसी वस्तु में परिवर्तनशील नहीं होती और जिसकी कयःशिक स्वर्ण अथा अन्य किसी वस्तु द्वारा निश्चित नहीं की जाती है, अतः यदि कोई मुद्रा स्वर्ण में तो परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन इसके मूल्य को स्वर्ण की निश्चित इकाई की समानता में देखा जाता है तो हम ऐसी मुद्रा को प्रादिष्ट मुद्रा नहीं कहेंगे।

प्रादिष्ट मुद्रा का निमाण दो तरह से किया जा सकता है:—(?) ऐसी मुद्रा कभी-कभी तो सरकार द्वारा जानजूक कर निकाली जाती है, (२) परन्तु कभी-कभी देश में बैंक नोटों को प्रादिष्ट-मुद्रा बना दिया जाता है। प्रादिष्ट मान के गरा—

- (१) हाल के वर्षों में बहुत से ऋर्थशास्त्रियों ने यह विश्वास प्रकट किया है कि प्रसिट्ट-मुद्रा-मान को सरकारी नीति का एक स्थाई ऋाधार बनाना उपयुक्त होगा, यद्यपि साधारणतया भूत-काल में इसका उपयोग सङ्गटकालीन परिस्थितियों में हुआ है। कहा जाता है कि धातु-मुद्रा की परिवर्तनशीलता केवल एक भ्रम ही है और इसी प्रकार यह भी मिथ्या है कि धातु-कोष मुद्रा के प्रति विश्वास उत्पन्न करते हैं। अनुभव बताता है कि यै दोनों बातें केवल साधारण परिस्थितियों में ही सम्भव होती हैं और ऐसी परिस्थितियों में किसी प्रकार की मुद्रा समुचित रूप में चालू रह सकती है। सङ्गटकाल में यह व्यवस्था दूट जाती है भ्रौर धातु-मुद्रा की परिवर्तनशीलता तथा उसका विश्वास बनाये रखने की विशेषता समाप्त हो जाती है। प्रादिष्ट मुद्रा में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो फिर उसी को प्रामाणिक मुद्रा के रूप में क्यों न उपयोग किया जाय?
- (२) साधनों का उचित उपयोग श्रीर देश का उचित श्राधिक विकास किसी भी देश में मुद्रा की माँग न्यावसायिक कार्यों के परिमाण, श्रौद्योगिक संगठन, यातायात तथा सम्वादवाहन के विकास, बैंकिंग प्रणाली के रूप तथा साख श्रौर साख के साधनों के विकास पर निभंर होती है, परन्तु इनमें से किसी का धातु-कोष से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है। रॉबर्टमन का विचार है कि बहुत बार देश के भौतिक तथा मानव साधनों का पूर्ण उपयोग केवल इसी कारण नहीं हो सका है कि स्वर्ण-कोषों की कमी के कारण साख का समुचित विकास नहीं हो पाया था। \* इसलिए स्वचालक घातु-मान के स्थान पर एक नियन्त्रित प्राविष्ट-मान का उपयोग श्रीधक उपयुक्त हो सकता है। स्वर्णमान के खेल के नियमों के स्थान पर मानव नियन्त्रण का उपयोग श्रीधक लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि इससे श्रौद्योगिक समाज की श्रावश्यकतायों भी भली-भाँति पूरी होंगी।
- (२) एक नियन्त्रित प्रादिष्ट-मान वित्तीय सुविधात्रों को बढ़ाता है त्रीर त्रार्थिक त्रनियमितता को दूर करता है। इसके अन्तर्गत मुद्रा का विस्तार तथा

संकुचन इस प्रकार श्रायोजित किया जा सकता है कि देश के सभी साधनों का पूर्ण उपयोग हो सके । साथ ही, इसमें बदलती हुई श्राधिक दशाश्रों के श्रनुसार शीघ्रता-पूर्वक फेर-बदल की जा सकती है। इस प्रणाली में लोच भी बहुत होती है।

## प्रादिष्ट मान के दोष-

- (१) विनिमय दरों में ग्रस्थिरता ग्रौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कठिनाई—क्योंकि इसमें मुद्रा की इकाई का किसी भी वस्तु के मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं होता है, इसलिये विभिन्न देशों के बीच विनिमय-दरों के निर्धारण में कठिनाई होती है। वे स्थिर नहीं रह सकती हैं ग्रौर उनके उच्चावचनों की कोई सीमा नहीं होती है। ऐसी दशा में उधार पर किये गये विदेशी व्यवसायों की मात्रा में भारी कमी म्ना जायगी, जिससे ग्रन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य में उलभन पैदा हो जायगी।
- (२) प्रादिष्ट मुद्रा की ऋत्यधिक निकासी का भय बहुत ऋधिक रहता हैं। इस ऋत्यधिक निकासी से सारी आर्थिक प्रणाली छिन्न-भिन्न हो सकती है और इस प्रकार यह मान स्वयं अपने उद्देश्य को ही समाप्त कर सकता है। घातुमान में भ्रत्यधिक निकासी के विरुद्ध कुछ न कुछ उपचार भ्रवश्य किये जा सकते हैं, परन्तु प्रादिष्ट मुद्रा-मान प्रणाली में कोई व्यावहारिक रोक-थाम सम्भव नहीं होती है।

पत्र-मुद्रा का संचालन कौन करे (Who should issue the paper currency)—

## भूमिका-

पत्र-मुद्रा का निर्गमन कौन करे ?— ग्रारम्भ से ही यह प्रश्न विवादग्रस्त रहा है कि नोटों की निकासी सरकार द्वारा की जाय, ग्रथवा बेंकों द्वारा । साथ ही, इस विषय में भी सभी का एक मत नहीं है कि यदि बेंकों को नोटों की निकासी का ग्रिधिकार दिया जाता है तो यह एक बेंक को मिलना चाहिये ग्रथवा एक ही साथ बहुत सी बेंकों को । ऐसे ग्रथं शास्त्रियों की कमी नहीं है जो इस बात के पक्ष में हैं कि नोट निकासी का एकाधिकार सरकार के पास रहना चाहिये । इसके विपरीत बहुत से ग्राधिक पण्डित यह ग्रधिकार बेंकों को देना चाहते हैं। वर्तमान-काल में यह वाद-विवाद समाप्त नहीं हुग्रा है, यद्यपि नोटों की निकासी पर सरकारी नियन्त्ररण के सिद्धान्त को ग्रब सभी ने स्वीकार कर लिया है।

## सरकार द्वारा नोट निर्गमन का कार्य-

सरकार द्वारा नोटों की निकासी के पक्ष में ग्रनेक तर्क रखे जाते हैं, जिनमें से मुख्य-मुख्य निम्न प्रकार हैं:—

(१) जनता का विश्वास — सरकार द्वारा निकाली हुई पत्र-मुद्रा पर जनता का विश्वास सबसे अधिक रहता है, क्योंकि जब तक जनता का सरकार के प्रति विश्वास बना रहेगा, इस मुद्रा पर अविश्वास का प्रश्न नहीं उठेगा। इसके अतिरिक्त भले ही ऐसी पत्र-मुद्रा के पीछे कोई घातु की ग्राड़ न हो, राष्ट्र की सारी सम्पत्ति श्रौर सरकार की सारी प्रतिष्ठा ग्राड़ का काम करती है।

(२) मुद्रा-प्रगाली के सम्बन्ध की सरलता—राज्य को एक बहुत बड़े संगठन की सेवाएँ प्राप्त होती हैं भ्रौर वह समाज की मौद्रिक माँगों का विशेषज्ञों द्वारा

सगठन की सेवाएँ प्राप्त होती हैं भ्रोर वह समाज की मौद्रिक माँगों का विशेषज्ञी द्वारा पता लगा सकता है। इसके भ्रतिरिक्त उसके हाथ में नियम श्रौर कानून बनाने की भारी शक्ति होती है, जिसके कारण वह मुद्रा श्रौर साख के उत्पादन की प्रत्येक भ्रवस्था

पर समुचित नियन्त्रण रख सकता है। इसी कारण आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा की मात्रा को घटाने-बढ़ाने में अन्य सभी संस्थाओं की अपेक्षा राज्य को अधिक सुविधा

तथा अधिक सामर्थ्य प्राप्त होती है।
(३) लाभ का उपयोग सार्वजनिक हितों की उन्नति में—पत्र-मुद्रा की

(३) लाभ का उपयोग सार्वजिनक हितों की उन्नित में—पत्र-मुद्रा की निकासी से लाभ ग्रिधिक होता है, परन्तु यह लाभ समस्त जनता के विश्वास के कारण पैदा होता है इसलिए यह ग्रावश्यक है कि इस लाभ का उपयोग भी जनता ग्रथवा

पैदा होता है, इसलिए यह ब्रावश्यक है कि इस लाभ का उपयोग भी जनता ब्रथना समाज के हितों को उन्नत करने के लिये ही किया जाय। इस लाभ के सरकारी कोषागार में जाने से इसके सार्वजनिक हितों की उन्नति में व्यय होने की सम्भावना

भ्रधिक रहती है। (४) सरकार का वैंक के पत्र-मुद्रा निर्गमन में सदा ही बहुत हस्तक्षेप रहा है—श्रनुभव बताता है कि उन देशों में भी जहाँ पत्र-मुद्रा की निकासी व्यक्तिगत

रहा है—अनुभव बताता है कि उन देशों में भी जहाँ पत्र-मुद्रा की निकासी व्यक्तिगत बैंकों द्वारा की जाती है, मुद्रा-नीति के निर्माण में सरकार का हाथ प्रमुख रहता है। मौद्रिक नीति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णाय सरकार द्वारा ही किया जाता है। फिर

सरकार इस काम को स्वयं ही क्यों न करे।

(प्र) ऐतिहासिक महत्त्व—ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी मुद्रा-निर्माण का कार्य राज्य द्वारा ही होता चला ग्राया है।

(६) अनुपयुक्त नीति के घातक परिगामों से रक्षा—पत्र-मुद्रा के सम्बन्ध में अनुपयुक्त नीति अपनाने के परिगाम बहुवा इतने गम्भीर होते हैं कि इस कार्य को किसी ऐसी संस्था पर छोड़ देना घातक हो सकता है जो राष्ट्रीय हितों की

सम्बन्ध में श्रनुपयुक्त नीति ग्रपनाने के परिगाम बहुधा इतन गम्भार हात है कि इस कार्य को किसी ऐसी संस्था पर छोड़ देना घातक हो सकता है जो राष्ट्रीय हितों को ग्रपेक्षा ग्रपने ही स्वार्थ पर ग्रिधिक व्यान दे। वैंक द्वारा नोट निर्गमन का कार्य—

इसके विपरीत व्यक्तिगत बैंक ग्रथवा बैंकों को यह ग्रधिकार सौंपने के पक्ष में

भी बहुत से महत्त्वपूर्ण तर्क रखे जा सकते हैं:—
(१) चलन में लोच का ग्रभाव—सरकारी विभागों का व्यापार, उद्योग

तथा व्यवसाय से कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं रहता है । उनका ग्रार्थिक तथा वागािज्य जगत में भी विशेष सम्बन्ध नहीं होता है । इस कारण सरकार द्वारा चलाई गई मुद्रा-प्रगािली में लोच का ग्रभाव होता है, क्योंकि वह व्यावसाियक ग्रावश्यकताग्रों पर ग्राधा-रित नहीं होती है । इसके विपरीत वैंकों का देश के व्यापार-वागािज्य ग्रौर उद्योग से घनिष्ट सम्बन्ध रहता है जिससे वे देश की मौद्रिक आवश्यकताओं का सुगमद्भा से पता लगा सकते हैं और तदनुसार मुद्रा-मात्रा में प्रसार या संकुचन करते रह सकते हैं। इससे चलन में लोच आ जाती है।

- (२) बैंक द्वारा पत्र-मुद्रा के निर्गमन का सुव्यवस्थित कार्य— सरकारी काम में ढील-ढाल रहती है ग्रौर बहुवा विलम्ब भी होता है। किसी नाम का निश्चित समय पर हो जाना कठिन होता है। मुद्रा की ग्रावश्यकता ग्रधिक होते हुए भी उसकी वृद्धि में कष्टदायक एवं हानिकारक विलम्ब होता है। किन्तु बैंक के विशेषज्ञ कर्मचारी सदा जागरूक रहते हैं, क्योंकि तिनक सी भी बृटि उनके बैंक को संकट में डाल सकती है ग्रौर उन्हें भी मालिकों की ग्रोर से निकाले जाने का डर रहता है, ग्रतः वे सब काम समय पर निपटाते हैं।
- (३) स्वस्थ आर्थिक विचारों पर आधारित मौद्रिक नीति—
  राज्य द्वारा पत्र-मुद्रा के संवालन में यह भी भय रहता है कि मौद्रिक नीति स्वस्थ
  आर्थिक विचारों के स्थान पर राजनैतिक तथा वित्तीय आयश्यकताओं से प्रभावित हों।
  प्रत्येक राजनैतिक दल अपने मत-पक्ष को निभाने का प्रयत्न करता है और र्जनता तथा
  करदाताओं से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए करारोपण के स्थान पर पत्र-मुद्रा की
  निकासी द्वारा सरकारी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करता है।
  इससे राजनैतिक अधाचार को प्रोत्साहन मिलता है। इसके विपरीत जब बैंक द्वारा
  नोटों का निर्गम किया जाता है तो वह विशुद्ध आर्थिक विचारों से प्रभावित होता है।
  राजनैतिक दलबन्दी के लिथे कोई स्थान नहीं है।
- (४) बैं किंग के नियमों का पालन—भूतकालीन अनुभव स्पष्ट रूप से यह बताता है कि अधिकाँश सरकारें अपनी पत्र-मुद्रा की परिवर्तनशीलता बनाये रखने में भी असमर्थ रही हैं। बजट की हानि को पूरा करने के लिये नोट छाप कर आय प्राप्त करने की प्रवृत्ति अधिक व्यापक रही है और उसके कारण समाज को मुद्रा-प्रसार के भारी कष्ट उठाने पड़े हैं। इसके विपरीत एक बैंक सदा नोटों का निर्गम करते समय बैंकिंग के नियमों का पालन करता है, जिससे चलनाधिक्च का भय नहीं रहता।
- (५) स्वतन्त्र उपक्रम में, राज्य द्वारा मुद्रा-संचालन की प्रथा स्वतन्त्र उपक्रम के विरुद्ध है। यह ग्राशा करना भूल होगी कि एक ग्रच्छा राजनीतिज्ञ ग्रच्छा बेंकर भी होगा।
- (६) लाभ का अधिकाँश भाग सार्वजिनिक हित में व्यय—जब बैंक पत्र-मुद्रा का प्रकाशन करता है, तो उसको होने वाले लाभ का अधिकांश भाग सरकार करों द्वारा लेकर सरकारी खजाने में जमा कर लेती है तथा वहाँ से वह सार्वजिनिक कार्यों में व्यय होता रहता है। बिचारे शेयरहोल्डरों की जेब में तो थोड़ा ही लाभ पहुँचने पाता है।

### निष्कर्ष

उपरोक्त सभी बातों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद नोटों की निकासी के लिये राज्य की अपेत्ता बैंक ही अधिक उपयुक्त संस्थाएँ हैं। उनका ज्यापारी एवं व्यवसायिक जगत से सीधा और घिनष्ट सम्बन्ध होता है और उन्हें सुद्रा तथा साख सम्बन्धी व्यवहारिक तथा विशेषज्ञ ज्ञान भी प्राप्त होता है। ये संस्थाएँ सुद्रा-प्रगाली में आवश्यक लोच उत्पन्न कर सकती हैं। जहां तक जनता के विश्वास का प्रश्न है, बैंक द्वारा निकाले हुये नोटों की प्रतिष्ठा सरकारी नोटों से कम नहीं होती है और यदि सरकार नोट-निकासी के लिए समुचित विधान बना दे तथा बैंक द्वारा निकाले हुए नोटों की परिवर्तनशीलता की गारन्टी ले ले तो फिर अविश्वास का प्रश्न भी नहीं उठता है। चलन की निकासी से बैंकों को जो भारी लाभ होता है, उसका अधिकाँश भाग सरकार करों के रूप में ले सकती है। इस प्रकार देंक द्वारा पत्र-मुद्रा की निकासी की व्यवस्था अधिक उपयुक्त तथा मितव्ययी होगी।

## एक अथवा अनेकों बैंकों द्वारा पत्र-मुद्रा-निर्गम (Single Note Issue Vs. Multiple Note Issue System)—

इस निर्ण्य के पश्चात् कि नोटों की निकासी का कार्य बैंक द्वारा होना चाहिए, इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक ही है कि यह कार्य किसी एक बैंक द्वारा सम्पन्न किया जाय, अथवा इसमें बहुत सी बैंक सामूहिक रूप में हिस्सा लें। दूसरे शब्दों में, नोट निर्णम की एकाकी निर्णम प्रणाली (Single Issue System) को अपनाया जाय, अथवा बहुबाही निर्णम प्रणाली (Multiple Issue System) को । मृतकाल में अधिकांश देशों में बहुत सी बैंकों द्वारा नोटों की निकासी का काम किया जाता था, परन्तु आधुनिक प्रवृत्ति एकाकी निर्णम प्रणाली की ओर विशेष रूप से हैं। इस प्रणाली से अनेक लाम हैं।

- (१) घातु-निधि का मितव्ययी एवं लाभपूर्ण उपयोग—इस प्रणाली में देश के घातु-कोषों को एक ही बैंक में एकत्रित कर दिया जाता है, जिसके कारण उनका ग्रधिक सप्रभाविक, मितव्ययी तथा लाभपूर्ण उपयोग हो सकता है।
- (२) पत्र-मुद्रा में एकरूपता—ग्रलग-ग्रलग बैंकों द्वारा निकःले हुए नोट भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। प्रत्येक बैंक की साख में भी ग्रन्तर होता है, इसलिए जनता के लिए ग्रन्छी ग्रौर बुरी मुद्रा में भेद करना कठिन हो जाता है। वैसे भी ऐसी ब्यवस्था में भंभट ग्रौर उलभन का भय रहता है।
- (३) मुद्रा प्रगाली के नियन्त्रगा में सुविधा—एकाकी प्रगाली में सर-कार का नियन्त्रगा भी ग्रधिक सप्रभाविक तथा व्यापक हो सकता है।
- (४) प्रतियोगिता का स्रभाव इस प्रणाली में बैंकों की पारस्परिक प्रति-योगिता का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(५) जनता का ग्रधिक विश्वास—जब नोटों की निकासी का एकाधिकार एक ही बैंक के पास होता है ग्रौर सरकार इन नोटों की गारन्टी देती है तो नोटों के प्रति विश्वास बहुत ग्रधिक रहता है।

इस प्रकार यही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है कि नोट निकासी का एकाधिकार एक ही बैंक के पास रहे, परन्तु यह बैंक कौन सी होनी चाहिए ? निस्संदेह अन्य बैंकों की अपेद्या देश की केन्द्रीय बैंक इस कार्य के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इङ्गलैण्ड, भारत, फांस, जर्मनी भ्रादि देशों में नोट की निकासी का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक के ही पास है। श्रमरीका तथा जापान में उपरोक्त देशों की भाँति केन्द्रीय बैंक तो नहीं हैं, परन्तु वहाँ पर भी एकाकी प्रसाली का ही एक दूसरा रूप प्रचलित है।

## ोट निर्गम के सिद्धान्त (Principles of Note-issue)

नोटों की निकासी के सम्बन्ध में दो विपरीत विचारधाराएँ हैं और दोनों ही के समर्थक अपने-अपने सिद्धान्तों को सही बताते हैं। इन सिद्धान्तों को चलन सिद्धान्त (Currency Principle) तथा बैंकिंग अथवा अधिकोषण सिद्धान्त (Banking Principle) के नाम से पुकारा जाता है। दोनों सिद्धान्तों में आधारभूत भिन्नता है, इसलिये दोनों को ठीक-ठीक समभ लेना आवश्यक है। दोनों की व्याख्या नीचे दी जाती है:—

## (१) चलन सिद्धान्त या सुरत्ता सिद्धान्त-

यह सिद्धान्त इस मान्यता पर श्राधारित है कि कागजी नोटों की निकासी का उद्देश्य केवल यही होता है कि बहुमूल्य धातुओं के सिक्कों के कम खर्च वाले स्थानापच (Substitutes) निकाले जायँ, जिससे मुद्रा के हस्तान्तरण में सुविधा हो श्रीर प्रचलन के कारण धातु नष्ट न होने पाये। इस कारण नोटों को बहुमूल्य गातुओं में पूर्ण रूप में परिवर्तनशील होना चाहिये श्रीर मुद्रा-नियन्त्रक को उनके शिश्ठे १०० प्रतिशत सोने-चाँदी की श्राड़ रखनी चाहिए। इस सिद्धान्त के श्रनुसार रेश की पत्र-मुद्रा की मात्रा देश में स्थित स्वर्ण श्रयवा श्रन्य बहुमूल्य घातुओं के कोषों र निर्भर रहती है। यदि देश में बहुमूल्य घातु का ग्रायात होता है तो घातु-कोष की वृद्धि के श्रनुपात में पत्र-मुद्रा स्वयं ही बढ़ जायगी। ठीक इसी प्रकार बहुमूल्य घातु के निर्यात के श्रनुपात में पत्र-मुद्रा की मात्रा घट जायगी। जन-विश्वास को बनाये रखने के लिए यह श्रावश्यक है कि स्वर्ण श्रयवा श्रन्य किसी बहुमूल्य घातु के कोष पर ही पत्र-मुद्रा की निकासी हो। यदि ऐसा किया जाता है तो पत्र-मुद्रा पर जनता को पूरा विश्वास होगा श्रीर इस मुद्रा के श्रति निर्णम (Over-issue) की सम्भावना नहीं रहेगी। इस प्रकार इस सिद्धान्त के श्रन्तर्गत प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा का प्रचलन रहना चाहिए, जो सबसे श्रिषक विश्वसनीय पत्र-मुद्रा होती है।

#### गुग्-

- (i) सुरक्षा—मुद्रा-चलन पूरी तौर से सुरक्षित रहता है, क्योंकि नोटों के पीछे १००% बहुमूल्य घातु की म्राड़ होती है।
- ( ii ) जनता का विश्वास—नोट सदा घातु में परिवर्तनीय होते हैं; इसलिए इस प्रगाली में जनता का विश्वास रहता है।

#### दोष--

- (i) साख की उपयोगिता की उपेक्षा—इसमें तो सन्देह नहीं है कि इस सिद्धान्त ने सुरक्षा को भारी महत्त्व दिया है, परन्तु इसमें साख की उपयोगिता तथा उसकी भावश्यकता पर ध्यान नहीं दिया गया है। केवल सुरक्षा होने से ही काम नहीं चल सकता।
- (ii) मुद्रा प्रगाली में लोच का होना भी आवश्यक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर चलन की मात्रा का बढ़ाना और घटाना सम्भव हो सके। लोच के बिना व्यापार और उद्योग के विकास में भारी बाधा पड़ जायगी।
- (iii) प्रमित्वयिता—इसके प्रतिरिक्त इस पद्धित में काफी मात्रा में सोना और चाँदी सुरक्षित निधि के रूप में बेकार पड़ा रहता है। इस प्रकार ऐसी प्रशाली मित्वयी नहीं होगी।

#### वैंकिंग सिद्धान्त-

यह सिद्धान्त इस बात पर जोर देता है कि मुद्रा द्वारा विनिमय माध्यम का कार्य सफलत। पूर्वक सम्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा-प्रणाली में लोच हो । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रचलित नोटों की कीमत का केवल एक भाग ही सोने अथवा चाँदी के रूप में सुरिद्धात कोषों में रहना चाहिए । सौ प्रतिशत कीमत का इस प्रकार रखना आवश्यक नहीं है । बैंकों को पत्र-मुद्रा की निकासी के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता रहनी चाहिए, क्योंकि यदि वे आवश्यकता से अधिक नोट निकालती हैं तो फालतू नोट नकदी में बदलवाने के लिए बैंक के पास लौट आयेंगे और यदि वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही नोटों की निकासी होती है तो अति-निर्गमन का भी भय नहीं रहेगा और नोटों की परिवर्तनशीलता भी बनी रहेगी । परिवर्तनशीलता के लिए १०० प्रतिशत धातु-निधि की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अपने अनुभव द्वारा बैंक को यह ज्ञात होता है कि एक निश्चित काल में कुल नोटों का केवल एक निश्चित भाग ही सोने अथवा चांदी में बदलने के लिए प्रस्तुत किया जाता है । यदि केवल इस भाग के लिए धातु-कोष की समुचित व्यवस्था की जाती है तो जनता के विश्वास के हूट जाने अथवा नोटों के बदले में धातु न दे सकने का भय नहीं रहता है।

#### गुग्-

( i ) लोच-इस प्रकार इस सिद्धान्त पर श्राधारित मुद्रा-प्रगाली का सबसे

महत्त्वपूर्ण गुरा लोत्र होता है ग्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्रावश्यकताओं के ग्रनुसार चलन की मोत्रा को बढ़ाना ग्रौर घटाना सदा ही सम्भव होता है।

- (ii) सोने व चाँदी के उपयोग में बचत—इसके म्रातिरिक्त सोने म्रीर चाँदी के उपयोग में भी बचत होती है दोष—
- (१) सुरक्षा की कमी—परन्तु ऐसी मुद्रा-प्रणाली में सुरक्षा कम रहती है, क्यों कि नोटों की निकासी के पीछे शत-प्रतिशत घातु नहीं रखी जाती।
- (२) सुरक्षा की कमी---- उक्त कारणों से इसमें पूर्ण सुरक्षा का भी प्रायः अभाव रहता है।

## दोनों में से कौन सी प्रणाली श्रच्छी है ?—

श्राधुनिक युग में यह निर्णय करना कठिन नहीं है कि व्यापारिक हिष्टकोण से दोनों में से कौनसी प्रणाली ग्रधिक उपयुक्त है। चलन-सिद्धान्त के श्राधार पर सुद्रा-प्रणाली का निर्माण करना तो श्राज के संसार में सम्मव ही नहीं है। स्वर्ण कोषों की कमी तथा सोने के विभिन्न देशों के बीच ग्रसमान वितरण के कारण अधिकांश देशों के लिए नोटों को १०० प्रतिशत सोने की ग्राड़ प्रदान करना भी सम्भव नहीं है। चाँदी की ग्राड़ भी लगभग ग्रसम्भव ही है। इस कारण बैंकिंग सिद्धान्त के श्राधार पर ही मुद्रा-प्रणाली का निर्माण किया जाता है। ऐसी प्रणाली में घातु-निधि तथा ग्रन्य साधनों की व्यवस्था करके सुरक्षा का ग्रण भी प्राप्त किया जा सकता है। एक ग्रादर्श-मुद्रा प्रणाली वही होगी जिसमें सुरक्षा तथा लोच के दोनों ग्रणों का समावेश हो ग्रीर जो इसके साथ ही साथ व्यावहारिक भी हो। समुचित नियन्त्रण द्वारा बैंकिंग सिद्धान्त में ये सभी ग्रण प्राप्त किये जा सकते हैं ग्रीर इसी कारण वर्तमान संसार में इसका चलन है।

## नोट निर्गम की पद्धतियाँ (The Methods of Note issue)

नोट निगंम के सिद्धान्तों का ग्रध्ययन करने के पश्चात् नोटों की निकासी की विभिन्न रीतियों का ग्रध्ययन भी आवश्यक है। नोट की निकासी की सात रीतियाँ महत्त्वपूर्ण हैं:—(१) निश्चित विश्वासाश्रित निगंम प्रणाली, (२) अधिकतम् विश्वासाश्रित निगंम प्रणाली, (३) अनुपातिक निधि पद्धति, (४) साधारण निधि प्रणाली, (५) आंशिक निधि पद्धति, (६) न्यूनतम् निधि पद्धति ग्रौर (७) कोषागार-विपत्र निधि प्रणाली।

(१) निश्चित विश्वासाश्चित निर्गम प्रणाली (Fixed Fiduciary System)—

इस प्रणाली में मुद्रा-नियंन्त्रक को यह ऋधिकार दिया जाता है कि वह

एक निश्चित मात्रा तक, बिना किसी प्रकार की धातु-निधि के, नोटों की निकासी कर ले, परन्तु इस निश्चित मात्रा के उपर प्रत्येक कागजी नोट के पीछे १०० प्रतिशत धातु-निधि रखी जाती है। जो पत्र-मुद्रा बिना धातु-निधि के निकाली जाता है, उसके पीछे सरकारी प्रतिभूतियों की ग्राड़ होती है ग्रौर ऐसे निगंम को विश्वासाश्रित निगंम (Fiduciary issue) कहा जाता है। इस प्रणाली का प्रमुख उद्देश पत्र-मुद्रा की धातु में परिवर्तनशीलता बनाये रखना होता है।

इङ्गलैण्ड में यह प्रगाली काफी लम्बे काल तक चालू रही है। सन् १८४४ के बैंक चार्टर एक्ट के अनुसार बैंक आंफ इङ्गलैण्ड को १४० लाख पौंड की कीमत के नोटों को विश्वासाश्रित निर्गम का अधिकार दिया गया था, परन्तु स्वर्ग-कोषों की कमी और मुद्रा-विस्तार की आवश्यकता के कारण ऐसे निर्गम की मात्रा सन् १६२६ में बढ़ा कर २६ करोड़ पौंड कर दी गई थी। सन् १६३६ में यह सीमा ३,००० लाख पौंड कर दी गई थी। सन् १६४६ में यह १४,४०० लाख पौंड थी, परन्तु जनवरी सन् १६४० में यह केवल १३,००० लाख पौंड रह गई थी। इङ्गलैण्ड के अतिरिक्त जापान तथा नारवे ने भी कुछ संशोधनों के साथ इसी प्रगाली को अपनाया था। सन् १६६ और सन् १६२० के बीच भारत में भी यही प्रगाली चालू थी।

#### गुग-

- (१) सुरक्षा—इस प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि इसमें पत्र-मुद्रा के बदले में सोना मिलना निश्चय होता है। कुछ मूल्य के नोट ऐसे अवश्य होंगे जिनके पीछे स्वर्ण-निधि नहीं रहेगी, परन्तु क्चोंकि सभी नोट सोने में बदलने के लिए प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, इसलिए नोटों की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता सदा बनी रहती है।
- (२) ग्रति निर्गमन का भय नहीं—इसके ग्रतिरिक्त पत्र-मुद्रा से ग्रति-निर्गमन का भय नहीं रहता है, क्योंकि नोटों की प्रत्येक ग्रगली निकासी के लिए समान कीमत का सोना कोष में रखा जाता है।
- (३) जनता का विश्वास—जनता का विश्वास भी इस प्रकार की पत्र-मुद्रा-प्रगाली के प्रति अधिक होता है।

### दोष--

(१) लोच का स्रभाव—किन्तु इस प्रणाली का प्रमुख दोष लोच का स्रभाव है। यदि राष्ट्रीय संकट के काल में स्रिष्ठिक मुद्रा की स्रावश्यकता पड़ती है तो उसे प्राप्त करने के दो ही उपाय हो सकते हैं:—या तो विदेशों से सोना मंगाया जाय, जो लगभग असम्भव होता है या प्रणाली के नियमों को तोड़ा जाय, जो प्रणाली के प्रति स्रविश्वास उत्पन्न कर देगा। इङ्गलैण्ड में इस प्रणाली का इतिहास यह स्पष्ट कर देता है कि उस देश को समय-समय पर विश्वासाश्रित निर्गम की मात्रा में काफी परिवर्तन करने पड़े हैं और स्रनेक बार इससे सम्बन्धित नियमों को तोड़ना पड़ा है।

सोना खरीदने में मुद्रा-नियन्त्रक को इस कारणा भी कठिनाई होती है कि चलन की माँग बढ़ने पर सोने की कीमत भी बढ़ जाती है।

(२) व्ययपूर्ण—इसके अतिरिक्त यह प्रणाली व्ययपूर्ण है भ्रौर केवल उन्हीं देशों में सफल हो सकती है, जहाँ सोना अधिक मात्रा में उपलब्ध है तथा जहाँ साख-मुद्रा का इतना अधिक प्रचार हो चुका है कि उसके उपयोग के कारण चलन की माँग में समय-समय पर भारी परिवर्तन नहीं होता है। इङ्गलैण्ड में इसकी सफलता का मुख्य कारण यही रहा है। भारत में चलन की माँग में समय-समय पर इतने अधिक परिवर्तन होते रहते हैं कि सन् १६२० के पश्चात् इसके अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठा है।

# (२) श्रधिकतम् विश्वासाश्रित निर्गम प्रणाली (The Fixed Maximum Fiduciary System)—

इस प्रणाली के अन्तर्गत विधान द्वारा पत्र-मुद्रा की एक अधिकतम् मात्रा निश्चित कर दी जाती है। इस निर्धारित सीमा तक मुद्रा-नियन्त्रक बिना किसी प्रकार के धातु-कोष के ही नोटों की निकासी कर सकता है, परन्तु निश्चित अधिकतम् सीमा के परे मुद्रा-नियन्त्रक को नोट निकालने का अधिकार नहीं होता है, चाहे उसके लिए १०० प्रतिशत स्वर्ण-कोषों की ही व्यवस्था क्यों न हों। कितना सोना चलन की आड़ में रखा जाय, इसका निर्ण्य मुद्रा-नियन्त्रक स्वयं करता है। इस प्रणाली में विश्वासाश्रित निर्गमन की अधिकतम् सीमा निश्चित करने में सावधानी वर्ती जाती है। देश की वाणिज्यिक तथा व्यवसायिक ग्रावश्य-कताग्रों का ठीक-ठीक प्रनुमान लगाकर देश में चलन की माँग निश्चित की जाती है। विश्वासाश्रित निर्गमन की मात्रा साधारणतया इतनी रखी जाती है कि देश की चलन सम्बन्धी साधारण ग्रावश्यकताएँ बिना किसी कठिनाई के पूरी होती रहें। इन ग्रावश्यकताग्रों में परिवर्तन होने की दशा में समय-समय पर निश्चित ग्रधिकतम् विश्वासाश्रित निर्गम की मात्रा में भी परिवर्तन कर दिये जाते हैं।

सन् १६२८ तक फांस में यही प्रणाली प्रचलित थी। इङ्गलैंड में भी मैंकिमिलन सिमिति ने इसी के ग्रहण करने की सिफारिश की थी। फांस में जब कभी भी पत्र-मुद्रा की मात्रा ग्रधिकतम् सीमा के निकट पहुँचती थी तो सरकार मुद्रा-प्रणाली में लोच बनाये रखने के लिए सीमा को आगे बढ़ा देती थी। समय-समय पर सरकार बैंक आफ फांस की साख नीति की जाँच करती रहती थी और उसे आवश्यक चेतावनी भी देती रहती थी, परन्तु सन् १६२६ में फांस ने इसे छोड़ दिया।

#### गुग-

(१) इसी प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें स्वर्ण को स्त्रानवश्यक रूप में कोषागारों में बन्द करके रखने की स्त्रावश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर्ण-निधि की मात्रा का निर्णय बैंक की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

(२) मुद्रा प्रगाली में लोच—दूसरा गुग्ग यह है कि सरकार सोच-समभ कर देश की व्यापारिक तथा वाणिज्यिक आवश्यकताओं के अनुसार पत्र-चलन की निकासी निश्चित करती है। इससे मुद्रा-प्रगाली में आवश्यक लोच बना रहती है और आवश्यकता से अधिक निकासी का भय नहीं रहता है।

## दोष—

- (१) सरकार द्वारा दुरुपयोग की संभावना—परन्तु यह प्रणाली भी दोषों से विमुक्त नहीं है। सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है। केवल आय प्राप्त करने के लिए निश्चित अधिकतम् सीमा का विस्तार किया जा सकता है, जिसके कारण चलन की मात्रा व्यापार और व्यवसाय की आवश्यकता से अधिक हो जाती है और अति-निर्णम के सभी परिणाम दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इस प्रणाली में मुद्राप्तार के विरुद्ध किसी प्रकार की रुकावट नहीं है।
- (२) लोच का स्रभाव—यदि सरकार नोट निकासी की स्रधिकतम् सीमा में परिवर्तन न करे, तो यह पद्धित देश में बढ़ते हुये व्यापार की माँग को पूरा नहीं कर सकती है। इस दृष्टि से यह पद्धित कम लोचदार कही जा सकती है।
- (३) रूढ़िवादी प्रगाली —यह प्रगाली नोट-निर्गमन के बैंकिंग सिद्धान्त की अपेक्षा करैन्सी सिद्धान्त पर भ्रधिक जोर देती है। यही कारगा है कि इसे एक रूढ़िवादी प्रगाली माना जाता है।

# (३) श्रनुपातिक निधि प्रणाली (The Proportional Reserve System)—

इस पद्धित में नोटों की सम्पूर्ण निकासी के पीछे घातु की आड़ रखी जाती है, परन्तु यह आड़ १०० प्रतिशत नहीं होती है, बल्कि नियम द्वारा १०० प्रतिशत से कम नियत की जाती है, जैसे २०% अथवा ४०%। सभी मुत्र-मुद्रा के पीछे ग्राड़ रहती है श्रौर विश्वासाश्रित निगंम नहीं होता है। पत्र-मुद्रा के जिस भाग के पीछे स्वर्ण निधि नहीं होती है उसकी ग्राड़ में प्रतिभूतियाँ रखी जाती हैं। इस प्रकार पत्र-मुद्रा निगंम का एक निश्चित प्रतिशत ही धातु-निधि के रूप में रखा जाता है।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् यह पद्धित काफी लोकप्रिय हुई थी। सन् १९२६ में फांस ने निश्चित अधिकतम् विश्वासाश्चित प्रणाली को त्याग कर इसी पद्धित को अपनाया था। संयुक्त राज्य अमरीका के फैंडरल रिजर्व सिस्टम ने भी इसी पद्धित को अपनाया है। हिल्टन-यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर सन् १९२७ में भारत सरकार ने भी इसे ग्रहण किया था और सन् १९३४ के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में इसे स्थान दिया था।

#### ग्र्ग-

- (१) लोच इस प्रणाली का एक मात्र गुण इसकी लोच है। यदि पत्र-मुद्रा के पीछे २५% स्वर्णं-निधि रखी जाती है तो खजाने में एक सोने के सिक्के के स्नाते ही चार कागज के नोट निकाले जा सकते हैं। इसके श्रातिरिक्त श्रावश्यकता पड़ने पर स्वर्णं-निधि का प्रतिशत घटाकर पत्र-चलन का स्नावश्यक विस्तार किया जा सकता है।
- (२) परिवर्तनशीलता—साथ ही, यदि सरकार सोच-समभ कर काम करती है तो नोटों की स्वर्णं में परिवर्तनशीलता बराबर बनी रहती है। दोष—

## परन्तु इस पद्धति के अनेक दोष हैं:--

- (१) मुद्रा-संकुचन में किठनाई—इसमें मुद्रा का विस्तार करना तो सरल होता है, परन्तु मुद्रा-संकुचन में किठनाई होती है। सुरक्षित निधि से सोने का एक सिक्का निकलने पर तीन-चार नोटों को रद्द करना पड़ता है, जबिक अन्य प्रणालियों में ऐसी दशा में केवल एक नोट को रद्द कर देने से काम चल जाता है।
- (२) सोना कोष में बेकार पड़ा रहता है—इस प्रणाली में भी काफी मात्रा में सोना बेकार ही सुरक्षित-कोषों में बन्द पड़ा रहता है।
- (३) नोटों की परिवर्तनशीलता केवल सैंद्धान्तिक—इस प्रणाली में नोटों की परिवर्तनशीलता को बनाये रखना कठिन भी होता है। इस सम्बन्ध में व्यवहारिक कठिनाई यह है कि एक नोट के भुनाने में एक सोने का सिक्का दिया जाता है, परन्तु एक सिक्के के निकल जाने के कारण सोने की मात्रा कानूनी ध्रुनुपात से कम रह जाती है, इसलिए बिना श्रुनुपात सम्बन्धी कानून को भङ्ग किये नोटों के बदले में सोना दे देना सम्भव नहीं होता है। इस प्रकार इस पद्धति में नोटों की परिवर्तनशीलता सैद्धान्तिक ही रहती है।

## ( ४ ) साधारण निधि प्रणाली (Simple Deposit System)—

इस पद्धति में नोटों की कीमत के बराबर सोना ग्रौर चांदी घातु-निधि के रूप में रखना ग्रावश्यक होता है। सम्पूर्ण पत्र-मुद्रा के पीछे १०० प्रतिशत घातु-निधि होती है ग्रौर इस प्रकार केवल प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा का ही चलन होता है।

## गुग्-दोष—

विश्वास के दृष्टिकोण से ता यह प्रणाली सबसे उत्तम है, परन्तु इसमें मितव्यियता तथा लोच का स्त्रमाव होता है ग्रौर इसे चलाने के लिए लम्बे-चौड़े स्वर्ण कोषों की ग्रावश्यकता पड़ती है।

## ( पू ) त्रांशिक श्रनुपात निधि प्रणाली (The Percentage Method)—

यह प्रणाली अनुपातिक निधि पद्धति का ही एक सुधरा हुआ रूप है। इसमें भी कुल पत्र मुद्रा का एक निश्चित भाग ही सोने और चाँदी के रूप में रखा जाता है,

परन्तु निधि का एक भाग विदेशी बैंकों में विदेशी मुद्राम्रों, विनिमय बिलों म्रथवा ग्रन्थ म्रलपकालीन विनियोगों के रूप में रखा जा सकता है। विधान के म्रनुसार भारत सरकार की पत्र मुद्रा का ४०% निधि के रूप में रखना म्रावश्यक होता है, परन्तु इस निधि का ६०% विदेशी विनियय तथा म्रल्पकालीन विदेशी विनियोगों में रखा जा सकता है।

### गुण-दोष-

इस प्रणाली का मुख्य गुण यह है कि सोने श्रौर चाँदी के उपयोग में बचत होती है श्रौर साथ ही साथ मुद्रा-प्रणाली में लोच बनी रहती है। परन्तु विदेशी विनिमय का जमा करना, विदेशों में कोषों का रखना तथा विनियोग करना भी भय से सुरक्षित नहीं है। वैसे भी यह प्रणाली स्वर्ण-विनिमय मान का ही पत्र-मुद्रा स्वरूप है श्रौर उसके सभी दोष इसमें पाये जाते हैं।

## (६) न्यूनतम् निधि प्रणाली (Minimum Reserve System)—

इस पद्धित में कानून द्वारा घातु-निधि की एक न्यूनतम् मात्रा निश्चित कर दी जाती है। मुद्रा नियन्त्रक का कर्तं व्य केवल इतना होता है कि वह निश्चित कीमत की घातु निधि को ग्रपने पास बनाये रखे। इसके पश्चात पत्र-चलन की निकासी की मात्रा पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं होती है। कम से कम निधि रख कर बैंक कितनी भी मात्रा में नोट छाप सकती है।

#### गुग-दोष-

इस प्रगाली में लोच, मितव्ययिता तथा परिवर्तनशीलता के गुगा हैं, परन्तु यह प्रणाली केवल ग्रमिवृद्धि (Prosperity) के काल में ही सफल होती है, जबिक व्यवसायिक वर्ग को मुद्रा की ग्रावश्यकता श्रधिक होती है। संकट-काल में उपरोक्त उद्देशों की पूर्ति नहीं होने पाती है। जब निधि की मात्रा नोटों के बदले में सोना देने के कारगा घट कर न्यूनतम् मात्रा के बराबर रह जाती है तो केन्द्रीय बैंक नोटों की परिवर्तनशीलता स्थिगत कर देती है। न्यूनतम सीमा के बढ़ाये जाने के भय के कारगा भी बहुवा केन्द्रीय बैंक न्यूनतम कीमत से ग्रधिक कीमत का सोना बेकार ही ग्रपने पास रखती है।

## (७) कोषागार-विपन्न निधि प्रणाली (The Bonds Deposit System)-

इस पद्धित में बैंक को पत्र-मुद्रा के लिए घातु-निधि नहीं रखनी पड़ती है। पत्र-मुद्रा का निर्गम कोषागार विपत्रों ( ${\rm Treasury\ Bills}$ ) के ग्राधार पर हो सकता है। यह विपत्र सरकार के ग्रल्पकालीन प्रतिज्ञा-पत्र ( ${\rm I.\ O.\ Us.'}$ ) होते हैं। सरकार द्वारा कोषागार विपत्र बैंक को दे दिये जाते हैं, जो उन्हें प्रतिभूति मान कर उनकी कीमत की पत्र-मुद्रा की निकासी कर देती है। वैसे तो इन कोषागार विपत्रों पर सरकार को ब्याज मिलती है, परन्तु उद्देश्य ग्राय कमाना न होकर पत्र-मुद्रा की सुव्यवस्था करना होता है।

## गुग-दोष-

इस प्रणाली में अति-निर्गम का भय कम रहता है, क्योंकि बैंक सरकारी प्रति-भूतियों को खरीदे बिना पत्र-चलन में वृद्धि नहीं कर सकती है। यदि बैंक ग्रधिक नोट निकालना चाहती है तो उसे ग्रधिक प्रतिभूतियाँ खरीदनी पड़ेंगी, जिससे उनकी कीमत बढ़ जायगी ग्रीर बैंक को लाभ के स्थान पर हानि होगी, परन्तु इस प्रणाली में लोच का। अत्यधिक अभाव होता है। साथ ही, सोना देने के लिए प्रतिभूतियों का तिक्रय करना होता है ग्रीर जब भारी संख्या में प्रतिभूतियाँ बेची जाती हैं तो मुद्रा-नियन्त्रक को हानि होती है, क्योंकि प्रतिभूतियों को कीमत गिर जाती है।

भारत सरकार ने सन् १६०२ के पश्चात् इस प्रकार का प्रयोग किया था और स्वर्ण-निधि को सरकारी प्रतिभृतियों के रूप में लन्दन में रखना ग्रारम्भ किया था, सन् १६०५ के विदेशी विनिमय सङ्कृट के काल में प्रतिभृतियाँ बहुत सस्ती कीमत पर बिकी थीं और भारत सरकार को ग्रधिक हानि हुई थी। संयुक्त राज्य ग्रमरीका ने भी सन् १६१३ से पहले इस प्रणाली का उपयोग राष्ट्रीय बैंक नोटों के सम्बन्ध में किया था। कुछ बैंकों को एक निर्धारित ग्रधिकतम् मात्रा में कुछ प्रकार के सरकारी बौंडों पर नोट निकालने का ग्रधिकार दिया गया था।

नोट निर्गम की प्रणालियाँ	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , ,
निश्चित विश्वासाश्रित प्रणाली	ग्रधिकतम् विश्वासाश्रित निर्गम प्रगाली
$({ m The\ Fixed\ Fidu}$	(The Fixed Maximum
ciary System)	Fiduciary System)
1	<u> </u>
ग्रनुपातिक निधि प्रणाली	साघारए। निधि प्रएाली
(The Proportional	(The Simple
Reserve System)	Deposit System)
<u> </u>	<u> </u>
श्रांशिक ग्रनुपात निधि प्रगाली	न्यूनतम् निघि प्रगाली
(The Percentage	(The Minimum
System)	Reserve System)
	<u> </u>
कोषागार विपत्र निधि प्रगाली	
(The Bonus Deposit	
System)	

नोट निकासी श्रीर उसके नियन्त्रण का सबसे सही सिद्धान्त क्या है ?— ऊपर हमने नोट निर्गमन की अनेक रीतियों का उल्लेख और उनके गुणों और दोषों का भी अध्ययन किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि नोटों की निकासी है:—पहला प्रश्न तो यह उठता है कि क्या घातु-निधि तथा पत्र-मुद्रा के बीच किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध रह्ना चाहिए ? दूसरा प्रश्न यह है कि पत्र-चलन के निर्गमन के लिए किसी देश को सोने ग्रथवा चाँदी का कितना कोष रखना चाहिए ? पहले प्रश्न के उत्तर के लिए हमें पहले तो यह ज्ञात करना ग्रावश्यक है कि पत्र-मुद्रा के पीछे घातु-निधि रखने का क्या उद्देश्य होता है ? निस्सन्देह नोटों की सोने-चाँदी में परिवर्तनशीलता इसलिए रखी जाती है कि नोटों के प्रति जनता का विश्वास बना रहे ग्रीर विदेशी भुगतानों का स्वर्ण में भुगतान किया जा सके । घातु-निधि का उद्देश विश्वास की बनाय रखना है । ऐसी दशा में यह ग्रावश्यक प्रतीत नहीं होता है कि पत्र-मुद्रा के निर्गमन को किसी भी प्रकार सौने की मात्रा के साथ सम्बन्धित किया जाय । दूसरे शब्दों में, देश में पत्र-चलन की मात्रा स्वर्ण-कोषों की मात्रा से स्वतन्त्र रूप में निश्चित होनी चाहिए । नोटों की निकासी के सम्बन्ध में केन्द्रीय बैंक पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना ग्रावश्यक प्रतीत नहीं होता है । स्वर्ण-निधि का नोटों के चलन के साथ किसी प्रकार का गठ-न्धन नहीं होना चाहिए । ऐसा सोचना भूल होगी कि केन्द्रीय बैंक ग्रपनी जिम्मेदारी को नहीं निभायेगी । यदि हम केन्द्रीय बैंक को साख मुद्रा के

का सही सिद्धान्त क्या होना चाहिए ? इस समस्या कों दो भागों में बाँटा जा सकता

जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, उसके विषय में हम यह कह सकते हैं कि यदि मुद्रा का मान स्वर्णमान हो तो सोने का उपयोग विदेशी भुगतानों में विनिमय माध्यम के रूप में ही हो सकता है। इस कारण यह ग्रधिक उपयुक्त है कि स्वर्ण-कोष की मात्रा नोटों के निर्णम पर निर्भर न रह कर विदेशी भुगतानों की मात्रा पर निर्भर रहे। स्वर्ण कोषों में इतना सोना रहना चाहिए कि केन्द्रीय बैंक ग्रल्पकालीन भुगतानों को शीघ्र चुका सके, क्योंकि दीर्घकाल में तो व्यापाराशेष के सन्तुलन के ग्रनेक उपाय किये जा सकते हैं। स्वर्ण-कोषों की मात्रा का यही ग्राधार होना चाहिए।

नियन्त्रण का अधिकार दे सकते हैं तो फिर चलन के संचालन में कौन सी बात है।

एक ग्रच्छी चलन पद्धित वही है जिसमें, मितव्यियता, लोच, परिवर्तनशीलता तथा ग्रित-निर्गम के विरुद्ध सुरक्षा हो। ग्रच्छा यही है कि पत्र-मुद्रा का निर्गमन पूर्णंतया केन्द्रीय बेंक को सौंप दिया जाय ग्रीर उसे चलन की मात्रा तथा धातु-निधि का प्रबन्ध करने की स्वतन्त्रता दे दी जाय। यदि सरकारी हस्तक्षेप की ग्रावश्यकता ही हो तो वह दो दिशाग्रों में होना चाहिए:—प्रथम, सरकार को न्यूनतम स्वर्ण-निधि की मात्रा निश्चित कर देनी चाहिए ग्रीर दूसरे, पत्र-मुद्रा की निकासी की ग्रधिकतम् सीमा भी निश्चित कर देनी चाहिए। ऐसी मात्रा तथा ऐसी सीमा में समय-समय पर ग्रावश्यकतानुसार परिवर्तन ग्रावश्यक होंगे। इस प्रकार एक ग्रच्छी मुद्रा-प्रणाली निश्चित ग्राविकतम् विश्वासाश्रित प्रणाली तथा न्यूनतम् निधि प्रणाली का एक मिश्रित एवं संशोधित रूप है।

## एक अच्छी चलन प्रणाली के गुण

(Essentials of a good currency system)

एक ग्रच्छी चलन प्रगाली में, चाहे वह घातु-मुद्रा पर श्राघारित हो श्रथवा पत्र-मुद्रा पर, निम्न ग्रुगों का होना श्रावश्यक होता है:—

- (१) लोच—लोच का अर्थ यह होता है कि चलन प्रणाली में शीझतापूर्वक प्रसार तथा संकुचन का गुण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आवश्यकता पड़ने पर चलन की मात्रा में वृद्धि अथवा कमी करना सम्भव ही नहीं, सरल भी होना चाहिए। यदि चलन-प्रणाली में लोच का अभाव है तो संकट-काल में उसके कारण बड़ी कठिनाई होगी। लोच की आवश्यकता इस कारण भी है कि उद्योग तथा व्यापार की आवश्यकताओं के अनुसार चलन की मात्रा को बदला जा सके।
- (२) मितव्ययिता—यह भी चलन-प्रगाली का एक आवश्यक गुगा है। इसका अर्थ यह होता है कि चलन-प्रगाली के संचालन पर बहुत व्यय नहीं होना चाहिए। एक अञ्छी प्रगाली में सोने और चाँदी के उपयोग में बचत होगी और संचालन-व्यय कम रहेगा। एक व्ययपूर्ण प्रगाली अञ्छी होते हुए भी राष्ट्र के लिए भार बन जाती है। निर्धन देशों के लिए तो मितव्ययिता का महत्त्व और भी अधिक होता है, क्योंकि उनके पास स्वर्ण-कोषों तथा अञ्छी प्रतिभूतियों का अभाव होता है।
- (३) परिवर्तनशीलता एक अच्छी चलन प्रगाली का यह भी उद्देय होना चाहिए कि उसमें पत्र-मुद्रा की सोने ग्रथवा चाँदी में परिवर्तनशीलता बनी रहे। परिवर्तनशीलता के दो उद्देश होते हैं प्रथम तो, इसके कारण चलन के प्रति जनता का विश्वास बना रहता है। दूसरे, इसके द्वारा विदेशी भुगतानों में सुविधा होती है। वर्तमान संसार में मुद्रा का प्रचलन साधारणतया सरकार की साख पर निर्भर होता है, इसलिए देश की आन्तरिक आवश्यकताओं के लिए स्वर्ण नहीं दिया जाता है। विदेशी भुगतानों में भी प्राय: यही प्रयत्न किया जाता है कि यथासम्भव सोना न दिया जाय, परन्तु व्यापाराशेष की अल्पकालीन प्रतिकूलता को दूर करने के लिए सोने का उपयोग कभी कभी आवश्यक होता है, इसलिए सरकार को इतना स्वर्ण-कोष अवश्य रखना चाहिये कि इस सम्बन्ध में कठिनाई उत्पन्न न हो। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना ने तो स्वर्ण में भुगतान करने की सम्भावना वो और भी न्यून कर दिया है।
- (४) सरलता—श्रच्छी चलन-प्रणाली सरल भी होनी चाहिये। प्रणाली के सम्बन्ध में जटिलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जटिलता प्रबन्ध के व्यय को बढ़ा देती है और इसमें अकुश्लता का भी भय रहता है। साथ ही साथ, चलन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि आर्थिक विशेषज्ञ, उद्योगपति, व्यापारी तथा जन-साधारण सभी उसे भली भाँति समक्ष लें। इससे प्रणाली के प्रति विश्वास की वृद्धि होगीं और मुद्रा-नियन्त्रक को समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त होगा।
  - ( ५ ) स्थिरता—चलन प्रणाली में यह भी गुण होना चाहिए कि उसके द्वारा

मुद्रा की ग्रान्तिरिक तथा बाहरी कीमतों में स्थिरता लाई जा सके। देश के भीतर कीमतों के ग्रत्यधिक उच्चावचन ग्रच्छी चलन-प्रणाली के लक्षण नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार विदेशी व्यापार के विकास के लिए विनिमय-दरों की स्थिरता ग्रावश्यक होती है। स्थिरता निश्चितता को उत्पन्न करके विकास ग्रीर उन्नति की ग्रमुकूल दशाएँ उत्पन्न करती है। स्थिरता तभी सम्भव है जबिक चलन प्रणाली में ग्रत्यधिक निकासी का भय न हो। इसके लिए सरकारी नियन्त्रण की ग्रावश्यकता होती है ग्रीर मुद्रा-संचालक का यह कर्त्तंच्य होता है कि वह ग्रपनी मुद्रा-निर्गमन-नीति केवल ग्राधिक परिस्थितियों पर ही ग्राघारित करे।

- (६) निश्चितता—मुद्रा-प्रगाली में की प्रत्येक बात विधान द्वारा स्पष्ट होनी चाहिये। यदि उसमें ग्रनिश्चितता का क्षेत्र है, तो सरकार उस सम्बन्ध में मनमानी करेगी तथा जनता का भी प्रगाली में विश्वास कम हो जायगा।
- (७) स्वयं संचालकता—सबसे उत्तम मुद्रा-प्रणाली वह है जिसमें स्वयं संचालकता का गुण भी हो ग्रर्थात् उसमें व्यापार-वाणिज्य व उद्योग की ग्रावश्यकता के ग्रनुसार स्वयं घटने-बढ़ने की प्रवृत्ति हो तथा सरकार का कम से कम हस्तक्षेप रहे। भारत की वर्तमान चलन पद्धति कहाँ तक उक्त गुणों का समावेश करती है?—

भारत की मुद्रा-प्रगाली में गुग अधिकाँशतः पाये जाते हैं। वह पर्यात रूप से मितव्ययो, सुनिश्चित एवं लोचदार है। चूं कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है, इसलिये चलन-पद्धित में परिवर्तनशीलता का गुग होना कोई खास जरूरी नहीं रहा है। हाँ, यह प्रगाली सरल नहीं है, क्योंकि साधारण जनता इसे समफ नहीं पानी है। यही नहीं बाह्य मूल्य-स्तर कायम रखने के प्रयत्न में आन्तरिक मूल्य-स्तर की स्थिरता को भुला दिया जाता है।

#### **QUESTIONS**

- 1. What are the tests of a good monetary system? How far are these satisfied in India? (Agra, B. A., 1956 Supp)
- 2. What is meant by managed currency? Examine the advantages and disadvantages of the same.

  (Agra, B. A., 1956)
- 3. What are the criteria of a good monetary system? How far does the Indian currency system satisfy these criteria.

(Raj., B, Com., 1948; Agra, B. Com, 1953)

- 4. Discuss the essentials of a good currency system. Does the Indian currency system satisfy the test of a good currency system? (Agra, B. Com., 1957) 15. নীট লিভিए—সনিষ্ট বৰাৰ্থ (Sagar, B. A., 1957)
- 6. Write a note on—Fiduciary Note Issue.
  (Agra, B. Com., 1958; Jabalpur, B. A., 1958)
  - 7. Explain the difference between Paper money and Bank money. (Agra, B. Com., 1957)
     8. "Metallic money has lost its importance in modern eco-
    - "Metallic money has lost its importance in modern economic life." Explain and amplify this statement.

      (Agra, B. Com., 1957)
  - 9. Discuss clearly the main features of the Fiduciary issue system and the minimum reserve method of note issue as adopted by India. Give your arguments in support of them-भारत की विश्वासाश्रित पत्र मुद्रा संचालन एवं न्यूनतम् कोष-पद्धति की विशेषतात्र्यों का विवेचन करिये। उनकी पृष्टि के लिए अपनी युक्तियाँ दीजिये।
- (Agra, B. Com., 1959)
  10. Why was the 'propotional reserve system' of note issue
- changed to the minimum reserve system in India in 1956? What was its effect on Indian currency? भारत में १६५६ में नोट जारी करने की विधि "श्रनुपातिक कोष-प्रथा" से बदलकर ''निश्चित कोष-प्रणाली" क्यों की गई थी? भारत के चलार्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ा?
- 11. Write short note on:—
  Fiat Paper Money. (Raj., B. Com., 1960)
- 12. Discuss the different methods for the regulation of note-issue. Which of them do you prefer and why?

  (Calcutta, B. Com. 1946; B. A., 1957)
- 13. Explain what is meant by a "monetary system" and enunciate the essential features of a sound and satisfactory monetary system. (Calcutta, B. A., 1954)

#### श्रध्याय =

## मुद्रा का मृल्य अथवा मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त

(The Value of Money or the Quantity Theory of Money)

## मुद्रा के मूल्य का ऋर्थ—

'मुद्रा के मूल्य' का अर्थशास्त्र में अलग-अलग अर्थ लगाया गया है। वास्तव में मुद्रा के मूल्य का ठीक-ठीक अर्थ बताना किंठन होता है। किसी भी बाजार में जब हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं तो बदले में जितने रुपये दिये जाते हैं, वही इन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सूचित करते हैं। साधारण बोलचाल में मूल्य का यही अर्थ लगाया जाता है, परन्तु क्या मुद्रा भी खरीदी और बेची जाती है? यदि ऐसा है तो मुद्रा को किस वस्तु में बेचा जाता है? रुपयों को रुपयों में बेचने का तो कुछ भी अर्थ नहीं होता है। यही कारण है कि मुद्रा के मूल्य का अर्थ समफने में थोड़ी कठिनाई होती है।

कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि वस्तु बाजार की भाँति मुद्रा का भी बाजार होता है और जिस प्रकार वस्तुएँ खरीदी और बेची जाती हैं, ठीक उसी प्रकार मुद्रा-बाजार में मुद्रा का भी कय-विक्रय होता है । अन्तर केवल इतना है कि साधा-रण वस्तुएँ मुद्रा में बेची जाती हैं, परन्तु मुद्रा की बिक्री मुद्रा को फिर लौटा देने की प्रतिज्ञा (Promise to pay) के बदले में होती है। इस सम्बन्ध में मुद्रा के मूल्य की माप भी मुद्रा में ही की जा सकती है। जब किसी व्यक्ति को लौटाने की प्रतिज्ञा पर मुद्रा दी जाती है तो उससे ब्याज लिया जाता है। उधार देने का प्रत्येक कार्य मुद्रा की बिक्री का ही कार्य होता है और ब्याज की रकम इस प्रकार बेची हुई मुद्रा की बाजारी कीमत होती है। यही कारण है कि कुछ अर्थशास्त्री ब्याज को ही मुद्रा के मूल्य का नाम देते हैं। मुद्रा बाजार के सम्बन्ध में मुद्रा के मूल्य की यह परिभाषा सही भी है।

कुछ अर्थशास्त्री मुद्रा के मूल्य का दूसरा ही अर्थ लगाते हैं जिनका अभि-प्राय मुद्रा के बाहरी मूल्य (External Value) से होता है। इस अर्थ में मुद्रा के मूल्य का अर्थ विदेशी विनिमय दर से होता है। एक देश की मुद्रा की एक निश्चित इकाई के बदले में किसी दूसरे देश की मुद्रा की जितनी मात्रा मिलती है वही उसका मूल्य कहलाती है। विदेशी व्यापार तथा विदेशी विनिमय में मुद्रा के मूल्य का यही म्राशय होता है।

इसी प्रकार एक तीतरे अर्थ में, मुद्रा के मूल्य का अभिप्राय मुद्रा की कयः

शिक्त से होता है। जिस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की कीमत मुद्रा में नापी जाती है, ठीक इसी प्रकार मुद्रा का मूल्य उसकी एक निश्चित इकाई के बदले में प्राप्त होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में सूचित किया जा सकता है, किन्तु इस सम्बन्ध में एक बड़ी किटाई यह होती है कि जबिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को नापने के लिए तो मुद्रा के रूप में एक सामृहिक तथा सामान्य इकाई होती है, मुद्रा का मूल्य नापने के लिए कोई ऐसी इकाई उपलब्ध नहीं है। मुद्रा का मूल्य स्वयं मुद्रा ही में नापा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई एक वस्तु अथवा कोई एक सेवा मुद्रा का मूल्य नापने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि मुद्रा तो स्वयं ही सामृहिक मापक का कार्य करती है। इस कारण मुद्रा की कीमत अथवा उसकी क्रयःशक्ति सामान्य रूप में वस्तुओं और सेवाओं में नापी जाती है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा का मूल्य नापने के लिए हमें वस्तुओं और सेवाओं के एक सामान्य संग्रह को मूल्य-मापक के रूप में उपयोग करना पड़ता है।

मुद्रा का मूल्य निकालने के लिए हमें मुद्रा की सामान्य कयः शक्ति (General Purchasing Power) को ज्ञात करना पड़ता है। इसी बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हमें सामान्य कीमतों (General Prices) को निश्चित करना पड़ता है। वास्तव में मुद्रा की सामान्य क्रयःशक्ति और सामान्यं कीमत दोनों एक ही वस्तु के दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से दो अलग-अलग नाम हैं-प्रथम मुद्रा के दृष्टिकोण से श्रीर दूसरा वस्तुश्रों श्रीर सेवाश्रों के दृष्टिकोण से। यहां पर इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक ही है कि सामान्य कीमत किसे कहते हैं। इस प्रकार की कीमत एक प्रकार से देश में उपलब्ध सभी वस्तुओं और सेवाओं की भौसत कीमत होती है। सामान्यं कीमत निकालने के लिए हम ठीक उन्हीं उपायों का उपयोग करते हैं जिनका कि निर्देशांक बनाने के सम्बन्ध में किया जाता हैं | इनका विस्तृत अध्ययन एक अगले अध्याय में दिया जायेगा। ] यह निश्चय है कि देश की सारी वस्तुओं श्रीर सेवाग्रों की कीमत का श्रीसत निकालना कठिन होता है, इसलिए कुछ वस्तुएँ ग्रौर सेवाएँ सभी वस्तुग्रों ग्रौर सेवाग्रों की प्रतिनिधि स्वरूप चुन ली जाती हैं और फिर इन चुनी हुई वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत को सामान्य कीमत कहा जाता है। उदाहरगास्वरूप, मान लीजिये कि हमने २५० वस्तुग्रीं भौर ५० सेवाओं को देश की सभी वस्तुओं और सेवाओं का प्रतिनिधि स्वरूप चुना। मान लीजिये कि इन २५० वस्तुओं की कीमतों का जोड़ २२५ रुपया है और इसी प्रकार ५० निर्वाचित सेवाग्रों की कीमत का जोड़ १७५ रुपया है। इस प्रकार २५० वस्तुओं 🕂 ५० सेवाओं ( कुलं ३०० इकाइयों ) की सामूहिक कीमत २२५ 🕂 १७५ = ४०० रुपया होगी। ऐसी दशा में वस्तुओं श्रीर सेवाश्रों की सामान्य कीमत ४०० - ३०० अर्थात् १६ रुपया होगी अर्थवा मृद्रा की १ इकाई की सामान्य कयः शक्ति 🔮 इकाई वस्तुएँ भ्रौर सेवाएँ होगी।

## मुद्रा के मूल्य श्रीर सामान्य कीमतों का सम्बन्ध—

इस अर्थ में मुद्रा के मूल्य की महत्त्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि मुद्रा का मूल्य वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों की विपरीत दशा में घटता-बढ़ता है। यदि सामान्य कीमतों बढ़ती हैं तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, क्योंकि उस दशा में मुद्रा की एक निश्चित मात्रा के बदले में पहले की अपेक्षा कम वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदी जा सकती हैं। इसके विपरीत यदि सामान्य कीमतों घटती हैं तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि अब मुद्रा की प्रत्येक इकाई पहले की अपेक्षा अधिक वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदती है। स्मरण रहे कि मुद्रा के मूल्य का सम्बन्ध वस्तुओं की कीमत से होता है, उनके मूल्य से नहीं होता। यदि सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों एक ही साय एक ही अनुपात में बढ़ती हैं तो निस्सन्देह मुद्रा का मूल्य घट जायगा, परन्तु ऐसी दशा में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कुछ भी अन्तर नहीं होगा, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय अनुपात में कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

होता है। प्रो॰ सेलिंगमैन ने लिखा है: — "मुद्रा का मूल्य मुद्रा की कयःशिक्त होती है और इसे वस्तुओं के सामान्य कीमत-स्तर से जाना जा सकता है। जब तक मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब तक वस्तुओं के सामान्य कीमत-स्तर में भी कोई फेर-बदल नहीं हो सकती है।" परन्तु स्मरण रहे कि मुद्रा के मूल्य का सम्बन्ध सामान्य कीमत-स्तर से होता है, न कि किसी वस्तु विशेष की कीमतों के परिवर्तन से। यह सम्भव है कि किसी समय विशेष में एक देश में कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के घटने के कारण सामान्य कीमत-स्तर में कुछ भी परिवर्तन न हो। ऐसी दशा में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में फेर-बदल होते हुए भी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा।

इस प्रकार मुद्रा के मूल्य श्रीर वस्तुश्रों की कीमत में पारस्परिक सम्बन्ध

# मुद्रा का मूल्य कैसे निर्धारित होता है ? (Determination of the Value of Money)

मुद्रा के मूल्य के सम्बन्ध में यह प्रश्न बड़ा महत्त्वपूर्ण है कि यह मूल्य किस प्रकार निश्चित होता है? मूल्य का सामान्य सिद्धान्त हमें यह बताता है कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का मूल्य उसकी माँग और पूर्ति द्वारा निश्चित होता है। एक ग्रोर तो वस्तु विशेष की माँग होती है, जिसके बढ़ने के कारण वस्तु की कीमत भी बढ़ने लगती है ग्रीर जिसके घटने के साथ-साथ उसकी कीमत में भी गिरने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। दूसरी ग्रोर पूर्ति की शक्ति होती है, जिसका वस्तु की कीमत पर विपरीत दिशा में प्रभाव पड़ता है। पूर्ति के बढ़ने से वस्तु की कीमत गिरती है और घटने के कारण कीमत बढ़ती है। इस प्रकार माँग ग्रीर पूर्ति की शक्तियों में किसी भी वस्तु की

कीमत भी इसी प्रकार निश्चित होती है, परन्तु मुद्रा के सम्बन्ध में पुराने श्रार्थशास्त्रियों ने एक महत्त्वपूर्ण मान्यता को स्वीकार किया था। उन्होंने यह मान लिया था कि मुद्रा की माँग सदा के लिए यथास्थिर होती हैं श्रोर इस माँग में किसी भी कारण परिवर्तन नहीं होते हैं। उनका विचार था कि मुद्रा की माँग किसी समाज में, किसी निश्चित काल में, इस ग्रंश तक ग्रपरिवर्तनशील होती है कि वह कीमतों के परिवर्तन पर भी नहीं बदलती है। चाहे वस्तुए सस्ती हों ग्रथवा मेंहगी, सभी उत्पादित वस्तुए बेची जायेंगी। इस कारण यदि मुद्रा की मात्रा तीन-चार गुनी भी हो जाती है तो भी बिकने वाली वस्तुग्रों की मात्रा यथास्थिर ही रहेगी। यह मान्यता कहां तक सही है, इसका ग्रध्ययन ग्रागे किया जायगा। इस समय केवल इतना ही जानना पर्याप्त होगा कि यह मान्यता काफी महत्त्वपूर्ण है।

इस मान्यता के आधार पर इन अर्थशास्त्रियों ने यह तर्क रखा है कि अपनी स्थिरता के कारण मुद्रा की माँग उसके मूल्य को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं कर सकती है। मूल्य-निर्धारण में उसका कार्य इतना निष्क्रिय (l'assive) है कि उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु मुद्रा के पिगाण के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसमें कभी और वृद्धि बराबर होती रहती है और मुद्रा के मूल्य-निर्धारण में वह सिक्क्य (Active) होता है। मुद्रा के मूल्य-निर्धारण में इसी का महत्त्वपूर्ण हाथ होता है और उसके परिवर्तन तो निर्मित रूप में मुद्रा के मूल्य को भी बदलते रहते हैं। अत्राप्य इन अर्थशास्त्रियों ने ऐसा बताया है कि मुद्रा का मूल्य केवल उसके परिमाण द्वारा ही नियत होता है और इसी कारण मुद्रा के मूल्य का सिद्धान्त मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है। यह सिङान्त बहुत पुराना है श्रीर क्योंकि बड़े लम्बे काल तक सभी प्रसिद्ध श्रर्थशास्त्रियों ने इसका समर्थन किया है, इसलिए इसने श्रर्थशास्त्र में प्रतिष्ठित सिद्धान्त का रूप घारण कर लिया है। संद्यों प में, यह सिद्धान्त यह बताता है कि सुद्रा का मूल्य तथा उसके मूल्य के परिवर्तन सुद्रा के परिमाण द्वारा निश्चित किये जाते हैं। विस्तारपूर्वक समभाने के लिए सिद्धान्त के तीन श्रङ्कों को श्रलग-श्रलग प्रस्तुत किया जा सक्ता है:—

- (१) मुद्रा का मूल्य मुद्रा के परिमाण द्वारा निर्घारित होता है।
- (२) सामान्य कीमत-स्तर में मुद्रा के परिमारा के परिवर्तनों के काररा फेर-बदल होती है।
- (३) सामान्य-कीमत स्तर के परिवर्तन मुद्रा के परिमागा के समदिशाई तथा अनुपाती (Direct and Proportional) होते हैं।

## कुछ विद्वानों के विचार—

(१) परिमाण सिद्धान्त के सम्बन्ध में रिकाडों (Ricardo) का कथन

है कि "मुद्रा की माँग उसके मूल्ये की अनुपाती होती है। यदि स्वर्ण की कीमत हुगुनी हो जाय तो उसकी आधी मात्रा प्रचलन में पहले के बराबर काम कर देगी और यदि स्वर्ण की कीमत आधी रह जाय तो उसकी दूनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार मुद्रा के परिमाण तथा उसकी क्रयःशिक का गुणनफल यथा-स्थिर ही रहता है।"

(२) भिल (Mill) के अनुसार मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त हमें यह बताता है कि ''यदि श्रन्य वातें यथास्थिर रहें तो मुद्रा के मूल्य में उसके परिमाण की विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हैं; परिमाण की प्रत्येक वृद्धि मूल्य को उसी श्रनुपात में घटाती है श्रौर परिमाण की प्रत्येक कमी उसे उसी श्रनुपात में बढ़ाती है।'' २

इसी सत्य को प्रो॰ टाउजिंग (Taussig) ने इस प्रकार व्यक्त किया है—
"मुद्रा के परिमाण को दुगुना कर दीजिए और यदि श्रन्य बातें समान रहती हैं
तो कीमतें पहले से दुगुनी हो जायेंगी और मुद्रा की कीमत पहले की श्राधी रह
जायेंगी । मुद्रा के परिमाण को श्राधा कर दीजिए और यदि श्रन्य बातें समान रहें
तो कीमतें पहले की श्राधी रह जायेंगी और मुद्रा का मूल्य दुगुना हो जायेगा।"

विकसेल (Wicksell) के शब्दों में हम संक्षेप में मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं:—''मुद्रा के मृत्य अथवा मुद्रा की कयःशक्ति में उसके परिमाण के उल्टे अनुपात में परिवर्तन होते हैं, जिस कारण मुद्रा के परिमाण की प्रत्येक वृद्धि अथवा कमी, यदि अन्य बातें समान रहें, वस्तुओं और

<sup>1. &#</sup>x27;For money the demand is exactly proportional to its value. If gold were of double the value half the quantity would perform the same functions in circulation, and it were half the value, double the quantity would be required—The quantity of money multiplied by its purchasing power remains constant." Vide Works edited by Maculloeh, p. 114.

<sup>2. &</sup>quot;The value of money, lother things being the same, varies inversely as its quantity, every increase of quantity lowers the value and every dimunation raising it in a ratio exactly equivalent."—J. S. Mill. Political Economy, Vol. II 1862, p. 15.

<sup>3. &</sup>quot;Double the quantity of money, and other things being equal, prices will be twice as high as before, and the value of money one-half. Halve the quantity of money and other things being equal, prices will be one-half of what they were before and the value of money double."—F. W. Taussig: Principles of Economics, Vol. I.

सेवात्रों में उसकी कयःशिक्त में त्र्नुपातिक कमी त्रथवा वृद्धि उत्पन्न करेंगी त्रौर इस प्रकार वस्तुत्रों की कीमतों में वसी ही वृद्धि त्रथवा कमी होगी।""
परिमाण सिद्धान्त का समीकरण—

सरलता तथा बोधगाम्यता के लिए मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को प्राचीन काल से ही एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत करने की प्रथा चली थ्राई है। इस समीकरण में मुद्रा के परिमाण, वस्तुओं की मात्रा तथा सामान्य कीमतों के पारस्परिक सम्बन्ध को दिखाया जाता है। विभिन्न कालों में परिमाण सिद्धान्त के समीकरण ने अलग- अलग रूप धारण किये हैं। वर्तमान ग्रर्थशास्त्री पुराने सिद्धान्त को पूर्णतया ध्रसन्तोष-जनक बताते हैं, परन्तु मुद्रा के मूल्य सम्बन्धी सिद्धान्त को श्रभी तक भी समीकरण के ही रूप में रखा जाता है।

(१) प्राचीन अर्थशास्त्री मुद्रा के परिमाण का अर्थ देश में प्रचलित चलन की कुल मात्रा से ही लगाते थे। जैसा कि विदित है, साख-मुद्रा का महत्त्व आधुक निक काल में ही अधिक बढ़ा है। पुराने अर्थशास्त्री इसको मुद्रा प्रणाली का एक बड़ा ही तुच्छ अंग समस्ते थे और इसी कारण उन्होंने इसे मुद्रा की मात्रा में सिम्मिलित करना आवश्यक नहीं समस्ता था। उस काल में बैंकों तथा अन्य साख संस्थाओं का विकास लगभग नहीं के बराबर था। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का सबसे प्राचीन समीकरण निम्न प्रकार था:—

$$\frac{H}{a} = \pi$$
 ग्रथवा  $\frac{M}{T} = P$ 

इस समीकरण में म (M) समय विशेष में देश में प्रचलित चलन की मात्रा को सूचित करता है, व (T) उसी समय देश में प्रस्तुत वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा को दिखाता है और क (P) सामान्य कीमत-स्तर को। इस समीकरण में व को मान्यता के रूप में यथास्थिर माना गया है, जिसका स्पष्ट ग्रथं यह होता है कि क के सभी परिवर्तन म के परिवर्तनों के परिणाम होंगे। इसके अतिरिक्त म तथा क में एक ही दिशा में एक ही साथ परिवर्तन होंगे और क के परिवर्तनों का ग्रंश म के परिवर्तनों का ग्रनुपातिक होगा। एक-श्रङ्कीय उदाहरण से उपरोक्त समीकरण को स्पष्ट किया जा सकता है। यदि म और व की कीमत क्रमशः १०० और २० है तो समीकरण का रूप निम्न प्रकार होगा:—

'The value or purchasing power of money varies in inverse proportion to its quantity, so that an increase or decrease in the quantity of money, other things being equal, will cause a proportionate decrease or increase in its purchasing power in terms of other goods, and thus a corresponding increase or decrease in all commodity prices."—Knut Wicksell: Lectures on Political Economy.

यह निश्चय है कि इस समीकरएं में यदि म की कीमत दो ग्रुनी अर्थात् २०० हो जाती है, परन्तु व की कीमत २० ही रहती है तो क की कीमत बढ़कर दो ग्रुनी अर्थात् १० हो जायगी। इस प्रकार क के परिवर्तन म के समदिशाई तथा अनुपातिक होंगे।

(२) ग्रागे चलकर कुछ ग्रर्थशास्त्रियों ने उपरोक्त समीकरण को दोषपूर्ण बताया, क्योंकि उनका विचार था कि इसमें मुद्रा के परिणाम के सम्बन्ध में एक ग्रावश्यक सत्य को भुला दिया गया है। इनका कथन था कि यह समम्मना भूल होगी कि मुद्रा का परिणाम केवल देश में प्रचलित चलन की मात्रा पर ही निर्मेर होता है। व्यावहारिक जीवन में चलन की प्रत्येक इकाई का एक से श्रिधिक बार विनिमय माध्यम श्रथवा वस्तुश्रों के खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है। वस्तुर्थे खरीदते समय कोई एक नोट ग्रथवा सिक्का एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दे दिया जाता है। दूसरा व्यक्ति ठीक इसी प्रकार वस्तुर्थे खरीद कर इसे तीसरे व्यक्ति को देता है ग्रीर इस प्रकार मुद्रा की एक इकाई का बार-बार हस्तान्तरण होता रहता है। इस हस्तान्तरण के कारण मुद्रा की प्रत्येक इकाई, एक नहीं वरन् ग्रनेक बार,वस्तुर्थे ग्रीर सेवाएँ खरीदती है। मुद्रा की प्रत्येक इकाई विनिमय का कार्य ठीक उत्तनी ही बार करती है जिद्दनी बार उसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास हस्तान्तरण होता है। इस प्रकार के हस्तांतकरण की बारम्बारता को ग्रथंशास्त्र में प्रचलन-वेग(Velocity of Circulation) ग्रथवा गति-सामर्थ कहा जाता है।

श्रतएव मुद्रा का परिमास केवल चलन की कुल मात्रा द्वारा सूचित नहीं होता, बिल्क चलन की कुल मात्रा तथा चलन के प्रचलन-वेग के ग्रुसानफल द्वारा सूचित होता है। इस दृष्टिकोस के अनुसार परिमास सिद्धान्त के समीकरस में निम्न संशोधन किया गया था:—

$$\frac{H}{q} = \pi$$
 ग्रथवा  $\frac{M}{T} = P$ 

इसी समीकरण में च (V) प्रचलन वेग को दिखाता है और इस प्रकार मुद्रा का परिमाण में च द्वारा सूचित होता है। के के सभी परिवर्तन में च के परिवर्तनों के अनुसार होंगे और उनक अनुपाती भी। यदि केवल प्रचलन वेग में वृद्धि होती है तो चलन की कुल मात्रा में वृद्धि हुये बिना भी सामान्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है। प्रचलन वेग वैसे तो स्वयं भी चलन की मात्रा पर निर्भर होता है, क्योंकि जैसे जैसे चलन की मात्रा बढ़ती है, व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है और वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय अधिक तेजी के साथ होने लगता है, परन्तु वस्तुओं के विनिमय की तेजी और भी बहुत से कारणों से हो सकती है। कुछ भी हो, चलन की मात्रा तथा उनका प्रचलन वेग दोनों ही मिलकर मुद्रा के परिमाण को निश्चित करते हैं।

(३) उपरोक्त समीकरण में भी एक गम्भीर दोष है। चलन ही विनिमय माध्यम के रूप में उपयोग नहीं होती है, बैंक-मुद्रा अथवा साख-मुद्रा का भी इस रूप में उपयोग होता है। मुद्रा की कुल मात्रा में उसको भी सम्मिलित करना श्रावश्यक है । सभी जानते हैं कि बेंकों द्वारा चालू किये चैक, विनिमय बिल तथा सभी प्रकार के साख-पत्र वस्तुएँ खरीदने के काम स्राते हैं। वे भी विनिमय माध्यम के रूप में मुद्रा का काम करते हैं। ग्राधूनिक संसार में तो इस प्रकार की मुद्रा का महत्त्व बहुत ही बढ़ गया है। साथ ही, चलन मुद्रा की भौति साख-मुद्रा की प्रत्येक इकाई भी एक से श्रधिक बार वस्तुयें खरीदने के काम श्रा सकती है। उसका भी प्रचलन-वेग होता है। एक चैक के पीछे किये गये हंस्ताक्षरों की संख्या से यह पता श्रासानी से लगाया जा सकता है कि भुगतान के लिए बैंक में श्राने से पहले वह कितने हाथों से गुजर चुका है ग्रीर उसने कितनी बार विनिमय-कार्य सम्पन्न किया है। इस प्रकार मुद्रा की कुल मात्रा में चलन तथा उसके प्रचलन वेग के गुए। नफल के प्रतिरिक्त साख-मुद्रा तथा उसके प्रचलन-वेग का गुए। नफल भी सम्मिलित होता है। यही दोनों मिलकर मुद्रा के परिमाण को निश्चित करते हैं। विना साख-मुद्रा तथा उसके प्रच-लन-वेग पर विचार किये मुद्रा के मूल्य के सम्बन्ध में जो भी समीकरण बनाया जायेगा उससे प्राप्त फल वास्तविक तथा व्यावहारिक नहीं हो सकता हैं।

## फिशर का परिमाण सिद्धान्त का समीकरण-

प्रसिद्ध ऋथैशास्त्री प्रो० फिशर ने उपरोक्त सभी वातों को ध्यान में रखते हुए मुद्रा-मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में पुरान समीकरण में ऋावश्यक परिवर्तन किये हैं | उनका समीकरण, जिसे मुद्रा परिमाण सिद्धान्त का फिशर का समीकरण कहा जाता है, निम्न प्रकार है:—

$$\frac{\mathbf{H} \cdot \mathbf{W} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{V}}{\mathbf{q}} = \mathbf{q}, \quad \mathbf{M} \cdot \mathbf{V} + \mathbf{M}' \cdot \mathbf{V}' = \mathbf{P}$$

इस समीकरण में भी पहले की ही भाँति में चलन की कुल मात्रा को बतात है और च उसके प्रचलन वेग को। इसी प्रकार प देश में दस्तुओं की मात्रा को दिखात है और क सामान्य कीमतों को। से साख-मुद्रा की कुल मात्रा को सूचित करता है और के सामान्य कीमतों को। से साख-मुद्रा की कुल मात्रा को सूचित करता है और च उसका प्रचलन वेग है। इस समीकरण के अनुसार मुद्रा का परिमाण में चे में में के बराबर है। इस कुल मात्रा में जो परिवर्तन होते हैं उन्हों के अनुसार के में भे परिवर्तन होंगे। में च में स्वी में परिवर्तन होंगे। में च में स्वी में परिवर्तन में, च, से तथा च किसी के भी परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, परन्तु निस्सन्देह इस सम्बन्ध में में का महत्त्व बहुत अधिक है।

## फिशर की मान्यता—"ग्रन्य बातें स्थिर रहें"—

मुद्रा के प्रतिष्ठित परिमाण सिद्धान्त का स्त्रन्तिम रूप यही है। प्रो० फिश का विचार है कि ग्रल्पकाल में वे चे तथा चा यथास्थिर रहते हैं तथा में ग्रोर

में एक निश्चित अपरिवर्तनीय अनुपात बना रहता है, जिसके कारण के में केवल <sup>7</sup>में के परिवर्तनों के कारए। फेर-बदल होती है। दूसरे शब्दों में, क्योंकि चलन ग्रीर साख दोनों का प्रचलन वेग तथा वस्तुष्रों की मात्रा ग्रल्पकाल में श्रपरिवर्तनीय होती है श्रीर चलन तथा तथा साख-मूद्राश्रों के बीच एक निश्चित श्रनुपात रहता है, इसके कारए। सामान्य कीमतों में केवल चलन की मात्रा में परिवर्तन होने से ही परिवर्तन हो जाते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि अल्पकाल में मुद्रा का परिमागा केवल देश में प्रचित चलन की मात्रा पर ही निर्भर होता है। फिशर का विचार है:--''त्र्यत्पकाल में व्यवसाय त्र्यथवा मुद्रा द्वारा किया हुत्र्या कार्य यथास्थिर रहता है, क्योंकि इस काल में जन-संख्या में परिवर्तन नहीं होते हैं, प्रति व्यक्ति उत्पादन नहीं बदलता है त्र्योर उत्पत्ति का जो प्रतिशत उत्पादकों द्वारा उपयोग किया जाता है, वह भी यथास्थिर रहता है। वस्तु-विनिमय तथा मुद्रा-विनिमय का त्र्रानुपात भी नहीं बदलता है ऋौर वस्तुऋों के प्रचलन वेग में भी परिवर्तन नहीं होते हैं। इस काल में उत्पादन की रीतियाँ तथा लोगों की उपभोग सम्बन्धी स्रादतें भी लगभग निश्चित होती हैं। इस प्रकार मुद्रा की माँग स्थिर रहती है। " उप-रोक्त कारणों से चलन की मात्रा तथा वस्तुः श्रोर सेवाश्रों की सामान्य कीमतों में प्रत्यन्त तथा ऋतुपाती परिवर्तन होते हैं।

जपरोक्त सभी बातों को देखते हुए ग्रब हमारे लिये मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की एक स्पष्ट तथा सही परिभाषा देना सम्भव है। यह सिद्धान्त बताता है किः— ''यदि ग्रन्थ बातें समान रहें तो सामान्य कीमत-स्तर के सभी परिवर्तनों का मुद्रा के परिमाण के परिवर्तनों से प्रत्यक्त तथा ग्रनुपातिक सम्बन्ध होता है।'' इस परिभाषा में 'ग्रन्थ बातें समान रहें' यह वाक्य महत्त्वपूर्ण है।

### 'श्रन्य बातें स्थिर रहने' का श्रर्थ एवं महत्त्व—

यहाँ ग्रन्य बातों के यथास्थिर रहने का ग्रिभिप्राय निम्न प्रकार है:---

- (१) व्यापार की मात्रा का यथास्थिर रहना—िकसी भी देश में मुद्रा की मांग देश में होने वाले व्यापार की मात्रा द्वारा निश्चित की जाती है। यदि व्यापार की मात्रा स्थिर है तो मुद्रा की माँग भी यथास्थिर रहेगी।
- (२) निहिच्त वस्तु-विनिमय व्यवसाय—विनिमय का कार्य बिना मुद्रा के उपयोग के अर्थात् वस्तु-विनिमय आधार पर भी किया जा सकता है। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के सम्बन्ध में ऐसे विनिमय से सम्बन्धित वस्तुओं को कुल वस्तुओं की मात्रा में सम्मिलित नहीं किया जाता है। निस्सन्देह यदि वस्तु-विनिमय के क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो कुल वस्तुओं धर्यात् ये की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है

इसलिए सिद्धान्त के सही होने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु-विनिमय व्यवसाय की मात्रा यथास्थिर रहे ।

- (३) साख-मुद्रा तथा चलन का अनुपात—साख-मुद्रा भी विनिमय माध्यम का कार्य करती है और उसकी मात्रा में भी समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, परन्तु साख-मुद्रा सदा ही चलन पर आघारित होती है। बेंक साख-मुद्रा का निर्माण अपने नकद कोषों के ही आधार पर करती हैं और ये नकद कोष चलन के रूप में होते हैं। साधारणतया अधिक नकद कोष चलन की अधिक निकासी द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में लोगों की आय बढ़ती है और वे बेंक में अधिक रुपया जमा करते हैं। नकद कोषों तथा निक्षेपों का अनुपात बेंक की स्वेच्छा पर निर्भर होता है, यद्यपि कभी-कभी सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियम बना दिये जाते हैं। मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त इस बात पर आधारित है कि आय का केवल एक निश्चित प्रतिशत ही बेंकों में जमा किया जाता है तथा नकद कोषों और निक्षेपों का अनुपात यथास्थिर रहता है।
- (४) प्रचलन वेग—परिमाण सिद्धान्त की एक मान्यता यह भी है कि चलन तथा साख-मुद्रा दोनों के ही प्रचलन वेग स्थिर रहें। (म च + स चा) की मात्रा में, यदि स और म के परिवर्तन अनुपातिक हैं, केवल उसी दशा में म के परिवर्तनों के अनुपात में फेर-बदल होगी जबिक च तथा चा में किसी प्रकार की घटत-बढ़त नहीं होती है। प्रचलन-वेग की स्थिरता के लिए कई बातें आवश्यक होती हैं, इसलिए परिमाण सिद्धान्त की ये मान्यताएँ होती हैं कि देश में जन-संख्या, लोगों की उपभोग सम्बन्धी रुचियों, प्रति व्यक्ति उत्पादन आदि में परिवर्तन नहीं होगा। इन सब बातों के स्थिर रहने पर प्रचलन-वेग में स्थिरता आ जाती है।

उपरोक्त सभी मान्यतात्रों को देखने से पता चलता है कि वे व्यवहारिक नहीं हैं। मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त इतना अधिक मान्यता-जटित कर दिया गया है। श्रोर ये मान्यताएँ भी इतनी अवास्तिविक हैं कि सिद्धान्त का केवल सैद्धान्तिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व ही शेष रह गया है। सिद्धान्त की अधिकांश आलोचनाएँ इन अव्यवहारिक मान्यताओं के कारण ही उत्पन्न होती हैं।

मुद्रा का प्रचलन वेग किन-किन बातों पर निर्भर होता है (Factors Determining the Velocity of Circulation of Money)?—

यह हम पहले ही बता चुके हैं कि मुद्रा का परिमाण केवल मुद्रा की कुल मात्रा पर ही निर्भर नहीं होता है, परन्तु उसके प्रचलन-वेग पर भी निर्भर होता है। मुद्रा के प्रचलन-वेग का ऋथे यह होता है कि मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित काल में विनिमय हेतु कितनी बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। यदि एक पाँच रुपये का नोट एक महीने में १५ बार विनिमय माध्यम के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो उसका मासिक प्रचलन-वेग १५ होगा। मुद्रा के प्रचलन-वेग पर बहुत सी बातों का प्रभाव पड़ता है। इसमें से मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:—

(१) मुद्रा की मात्रा—मुद्रा का प्रचलन-वेग स्वयं उसकी मात्रा पर निर्भर होता है। देश के आर्थिक जीवन को सुचार रूप में चलाने के लिए विनिमय-कार्यों के लिए मुद्रा की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। यदि मुद्रा की निकासी कम है तो उसका प्रचलन अधिक तेजी के साथ होने लगेगा। इसके विपरीत मुद्रा की पूर्ति अधिक होने की दशा में उसका प्रचलन-वेग कम रहेगा।

(२) जनता की बचत सम्बन्धी श्रादतें—श्राय के एक भाग को उप-भोगीय वस्तुश्रों को खरीदने पर व्यय किया जाता है, परन्तु दूसरे भाग की बचत कर लीं जाती है। वास्तव में मुद्रा की उतनी ही मात्रा तुरन्त काल में विनिमय माध्यम के रूप में उपयोग की जाती है जितनी कि उपभोग हेतु रखी जाती है, श्रतएव मुद्रा का प्रचलन वेग इस बात पर भी निर्भर होता है कि जनता समस्त श्राय का कौनसा भाग उपभोग के लिए रखती है।

(३) जनता की नकदी में माल खरीदने की ग्रादत—यदि माल उघार खरीदा जाता है तो तीन महीने, छः महीने भ्रथवा साल भर का हिसाब एक ही साथ चुकाया जाता है। ऐसी दशा में मुद्रा का प्रचलन वेग कम होता है। नकद सौदों में थोड़ा-थोड़ा भ्रुगतान निरन्तर होता रहता है, जिसके कारण मुद्रा का प्रचलन बराबर बना रहता है।

(४) स्थिगित भुगतानों को कितनी बार चुकाया जाता है—यदि देश में सामान्य रिवाज स्थिगित भुगतानों (ऋगों) को साल में एक-दो बार चुकाने का है ग्रीर भुगतान बड़ी मात्रा में किया जाता है तो मुद्रा का प्रचलन-वेग कम होगा। यदि बार-बार तथा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में भूगतान किये जाते हैं तो प्रचलन-वेग बढ़ जायगा।

(५) लोगों की द्रवता पसन्दगी (Liquidity Preference)—व्यव-सायिक वर्ग दिन प्रति दिन के कार्यों को चलाने के लिए जितना बड़ा नकद कोष रखता है उतना ही मुद्रा का प्रचलन-वेग कम होता है।

(६) मजदूरी प्रगाली का रूप — मजदूरी वाषिक, मासिक, साप्ताहिक ग्रथवा दैनिक ग्राघार पर बांटी जा सकती है। यदि मजदूरी लम्बे काल के पश्चात् मिलती है तो दैनिक ग्रावश्यकताग्रों को पूरा करने के लिए मुद्रा का संचय ग्रधिक बड़ा रखा जाता है, जिसके कारण मुद्रा का प्रचलन-वेग कम रहता है। इसके विपरीत जितनी ही मजदूरी बार-बार दी जायगी उतनी ही मुद्रा की प्रत्येक इकाई विनिमय माध्यम के रूप में ग्रधिक बार उपयोग होगी।

(७) यातायात तथा संचार साधनों की उन्नात—इसके द्वारा विनिमय का क्षेत्र विस्तृत कर दिया जाता है ग्रौर वस्तुग्रों का क्रय-विक्रय ग्रधिक तेजी से होने लगता है ग्रौर ये दोनों ही मुद्रा के प्रचलन-वेग को बढ़ा देते हैं।

- ( ८ ) ऋगा प्राप्ति की सुविधाएँ ऐसी सुविधाएँ उधार को प्रोत्साहन देकर प्रचलन-वेग के ग्रंश को घटाती हैं।
- (६) ग्राय-व्यय तथा कीमतों का भावी ग्रनुमान—निस्सन्देह इसी भनुमान के श्राघार पर विनिमय कार्यों की गृति तेज ग्रथवा धीमी की जाती है। यदि भविष्य में कीमतों के चढ़ जाने का धनुमान है तो व्यापार श्रधिक तेजी से होने लगेगा ग्रोर मुद्रा का प्रचलन-वेग भी बढ़ जायगा।
- (१०) सामान्य आर्थिक उन्निति मुद्रा का प्रचलन-वेग देश की आर्थिक उन्निति की दशा पर भी निर्भर होता है। एक विकसित समाज में वस्तु-विनिमय का ग्रंश कम होता है, इस कारण अधिक मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु ऐसे समाज में साख-मुद्रा का ग्रत्यधिक विकास हो जाता है। उधार की प्रथा काफी विस्तृत रूप धारण कर लेती है, मजदूरियों का भुगतान अधिक शी घ्रतापूर्वक होने लगता है ग्रौर यातायात के साधनों के विकास के कारण वस्तुओं का विनिमय दूर-दूर तक तथा अधिक तीव्रता के साथ होने लगता है। व्यापार की अनिश्चित स्थित में तथा सङ्कट-काल में मुद्रा का प्रचलन-वेग कम होता है। इसी प्रकार कृषि-प्रधान देशों में शौद्यो- गिक तथा व्यापारी देशों की तुलना में मुद्रा का प्रचलन-वेग कम रहता है। साधारण-तया बढ़ती हई कीमतें तथा आर्थिक जीवन का विकास प्रचलन-वेग को दढ़ा देते हैं।
- (११) साख की गतिशीलता—चलन की भांति साख-मुद्रा का भी प्रचलन बना रहता है धौर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उसका भी हस्तान्तरण होता है, परन्तु साख के प्रचलन-वेग को जमा राशि की गतिशीलता (Mobility of Balances) कहना ही अधिक उपयुक्त है। जितनी जल्दी-जल्दी पैसे का एक व्यक्ति के लेखे से दूसरे व्यक्ति के लेखे में हस्तान्तरण होता है उतना ही साख मुद्रा का प्रचलनवेग भी अधिक होता है। साख-मुद्रा की गतिशीलता साधारणतया देश में वैंकिंग के विकास और उसकी उन्नति पर निर्भर होती है।

### परिमाण सिद्धान्त की श्रालोचनाएँ -

परिमाग् सिद्धान्त की आलोचनाओं को हम दो भागों में बाँट सकते हैं— (ग्र) कुछ आलोचकों ने इस सिद्धान्त का आधार ही गलत बताया है और (ब) इसके विपरीत कुछ धर्यशास्त्रियों का विचार है कि इसका आधार तो ठीक है, किन्तु यह सिद्धान्त मुद्रा के मूल्य-निर्धारण का सही सिद्धान्त नहीं है। कुछ त्रुटियां तथा मान्यताएँ इस सिद्धान्त को धवास्तविक बना देती हैं।

## ( अ ) सिद्धान्त के स्राधार सम्बन्धी आलोचनायें-

पहले वगं की प्राबोचनायें इस प्रकार हैं :--

(१) तर्क की विधि उल्टी है—इस सिद्धान्त में मुद्रा की मात्रा के परि-वर्तनों को सामान्य कीमत-स्तर के परिवर्तनों का कारण माना गया है, जो ठीक नहीं है। वास्तव में कीमत-स्तर के परिवर्तनों के कारण मुद्रा की मात्रा घटती-बढ़ती है, ग्रतएव कीमत-स्तर के परिवर्तन मुद्रा के परिमाण के परिवर्तनों के परिणाम नहीं होते हैं. बल्कि उनके कारए। होते हैं।

ग्रालोचकों का यह तर्क ठीक नहीं है। ग्रनुभव बताता है कि पहले मुद्रा की मात्रा बढ़ती है श्रीर तत्पश्चात् कुछ समय पीछे कीमतें बढ़ जाती हैं। प्रो० फिशर ने लिखा है:--''कीमत-स्तर को मुद्रा की मात्रा घटने-वढ़ने का कारण समभना बडी

भारी भूल होगी । निस्सन्देह ऐसा ग्रवश्य होता है कि एक स्थान का मूल्य-स्तर दूसरे स्थान के मूल्य-स्तर पर अपना प्रभाव डालता है।" यदि किसी स्थान पर कीमतें

बढ़ती हैं तो वहाँ मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, बिल्क इसके विपरीत मुद्रा

उस स्थान से हट कर दूसरे ऐसे स्थान को जाने लगती है जहाँ उसकी कय: शक्ति ग्रिधिक होती है, ग्रर्थात् जहाँ कीमतें नीची होती हैं। ठीक इसी प्रकार मुद्रा की मात्रा के घट जाने के का रस ऊँची कीमतों वाले स्थान में कीमतें घटने लगती हैं धौर यदि

मुद्रा की गतिशीलता में कोई बाघा नहीं है तो प्रन्त में दोनों स्थानों का कीमत-स्तर बराबर हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि कीमत-स्तर के परिवर्तन तो मूद्रा परिमाण के परिवर्तनों पर निभर होते हैं, परन्तु स्थिति इसके विपरीत नहीं है।

(२) मुद्रा की कीमत मुद्रा की माँग श्रीर पूर्ति दोनों पर निर्भर होती है - कुछ श्रालोचकों का कहना है कि मूल्य के सामान्य सिद्धान्त के श्रनुसार सभी वस्तुमों की कीमत उनकी माँग और पूर्ति पर निर्भर होती है और उनका निर्घारण उन्हीं के द्वारा होता है। ठीक इसी प्रकार मुद्रा की कीमत भी उसकी माँग ग्रीर पृति पर निर्भर रहती है। मुद्रा की मात्रा ग्रकेले में (एकाकी रूप में) कीमत-स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है।

प्रो० फिशर ने इस म्रालोचना के विरुद्ध बताया है कि माँग म्रीर पूर्ति का सिद्धान्त किसी एक वस्तु की कीमत का पता लगाने के लिए तो उपयुक्त होता है. परन्तु इससे सामान्य कीमत का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सामान्य माँग

तथा सामान्य पृति का पता नहीं लग सकता है। हम किसी वस्तु की माँग तथा उसकी पूर्ति भीर इन दोनों के सन्तूलन का पता तो लगा सकते हैं. परन्तु वस्तुभों भीर सेवाभों की सामान्य माँग ग्रीर सामान्य पूर्ति का लगशग कुछ भी अर्थ नहीं होता है। ग्रतएव माँग ग्रीर पूर्ति का सिद्धान्त सामान्य कीमत-स्तर के निर्घारण के लिये उपयुक्त नहीं है। जिस प्रकार विभिन्न लहरों की ऊँचाई द्वारा समुद्र-स्तल का पता नहीं लगाया जा

सकता है, परन्तु समुद्र-स्तल के द्वारा लहरों की स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ठीक इसी प्रकार धलग-धलग वस्तुधों भीर सेवाग्रों की कीमर्ते सामान्य कीमत की

सकती है।

सूचक नहीं होती हैं, परन्तु सामान्य कीमतें व्यक्तिगत कीमतों की स्थिति का ज्ञान भवश्य करा देती हैं। सामान्य कीमत तो केवल मुद्रा की मात्रा द्वारा ही जानी जा (३) यह सिद्धान्त महत्त्वहीन सत्य को वताता है—प्रो॰ निकलसन (Nicholson) का कहना है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त एक साधारण सत्य है, जिसका उल्लेख करने से न तो किसी महत्त्वपूर्ण वात का पता चलता है और न किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। यह तो सभी जानते हैं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ाने से कीमतें बढ़ जाती हैं। तो फिर इसको सिद्धान्त का नाम देने से कौन सी नई बात का पता चलता है। इस ग्रालोचना के उत्तर में प्रो॰ फिशर ने कहा है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त इतना सरल नहीं है जितना कि निकलसन समभते हैं, परन्तु यदि यह सरल भी है तो इसकी वैज्ञानिक विवेचना के विरुद्ध फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

### निष्कर्ष--

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्धान्त के विरुद्ध जो आधारभूत आलोचनाएँ की गई हैं वे यथार्थ में ठीक नहीं हैं। आलोचकों ने मुद्रा के परिमाएा सिद्धान्त और उसके महत्त्व को ठीक-ठीक समभा ही नहीं है। शायद यह कहना गलत न होगा कि इस सिद्धान्त का आधार तो सही है, परन्तु जिस रूप में यह सिद्धान्त फिशर द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसके विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा सकता है।

## ( व ) त्रुटियों एवं मान्यता सम्बन्धी आलोचनाएँ-

ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि मुद्रा के मूल्य के प्रतिष्ठित सिद्धान्त में कुछ भारी त्रुटियाँ हैं, जिनके कारण यह सिद्धान्त गलत ही नहीं हो जाता है, बिलक अध्यवहारिक तथा अवास्तिविक भी हो जाता है। वास्तिविकता तो यह है कि अर्थ-शास्त्र के अन्य सिद्धान्तों की भाँति यह भी अनेक मान्यताओं पर आधारित है, परन्तु ये मान्यतायें ऐसी हैं कि इनके आधार पर तर्क करना केवल कल्पना के जगत में चक्कर लगाना है। प्रमुख आलोचनाएँ निम्नु प्रकार हैं:—

(१) ग्रवास्तिविक मान्यतायें इस सिद्धान्त की मान्यताएँ ग्रवास्तिविक हैं। सबसे पहले तो यह मान्यता ही गलत है कि मुद्रा की माँग यथास्थिर रहती हैं। श्रनुभव बताता है कि देश में विनिमय साध्य वस्तुग्रों ग्रौर सेवाग्रों की मात्रा में बराबर परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के ग्रनेक कारण हो सकते हैं, जैसे — उत्पादन की वृद्धि, वस्तुग्रों के प्रचलन-वेग की तेजी, इत्यादि। यदि किसी कारण देश में जन संख्या के ग्राकार ग्रथवा उसकी कुशलता में वृद्धि हो जाती है ग्रथवा उत्पादन विधियों के सुधार, नये ग्राधिक साधनों की खोज ग्रादि के कारण उत्पत्ति बढ़ती है तो यह मान्यता गलत हो जाती है। ग्रनुभव बताता है कि संसार के सभी देशों में उत्पादन की कुल मात्राग्रों में वार्षिक तथा सामयिक (Seasonal) परिवर्तन होते ही रहते हैं। इसके ग्रीतिरक्त स्वयं सामान्य कीमत स्तर की वृद्धि भी वस्तुग्रों के उत्पादन की मुद्धि में सहायक होती है। यदि कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादकों को लाभ ग्रधिक होता है, नयोंक बिक्री ग्रधिक होती है ग्रौर कीमतों की तुलना में उत्पादन-व्यय कम रहता

है। उत्पादन के अधिक लाभदायक हो जाने के कारण उत्पादन में वृद्धि की जाती है और मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के समीकरण में ये की कीमत बढ़ जाती है। इसी प्रकार सामान्य कीमतों के गिरने के काल में उत्पादकों को हानि होती है, जिससे उत्पत्ति घटती है और ये की कीमत घटती है। इस प्रकार व को यथास्थिर मान लेना गलत है।

केवल पूर्ण वृत्ति बिन्दु (Full Employment Point) पर ही वस्तुओं ग्रीर सेवाग्रों की कुल मात्रा यथास्थिर रहती है ग्रीर वह भी थोड़े से ही समय तक। यदि कोई देश बराबर मुद्रा-प्रसार की नीति को बनाये रखता है स्रौर थोडे-थोडे समय पश्चात् चलन की मात्रा बढ़ाता रहता है तो घीरे-घीरे कीमतें बढ़ती रहती हैं ग्रीर उत्पादन का विस्तार होता रहता है. परन्त्र उत्पादन के विस्तार के साथ ही वृत्ति (Employment) का भी विस्तार होता जाता है. क्योंकि ग्रधिक उत्पत्ति करने के लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को म्रधिक मात्रा में उपयोग करने की म्रावश्यकता पड़ती है। यदि इस प्रकार चलन की मात्रा बढ़ाने का क्रम चलता ही रहे तो अन्त में एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि उत्पत्ति के सभी साधनों की पूर्ण वृत्ति मिल जाती है. अर्थात् जब कोई भी साधन तिनक भी बेकार नहीं रहता है। यही पूर्ण वृत्ति की अवस्था है। यहाँ पर चलन की मात्रा में वृद्धि कर देने पर तथा कीमतों के बढ़ने के कारण उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी ग्रौर वस्तुग्रों की कुल मात्रा यथास्थिर हो जायेगी । इस दशा में मुद्रा का परिमाग सिद्धान्त पूर्णतया सही होगा और कीमत स्तर में मुद्रा के परिमाण के परिवर्तनों के अनुपात में परिवर्तन होंगे. परन्तू पूर्ण वृत्ति बिन्दु पर भी थोड़े ही समय तक यह बात सत्य होती है। मनोवैज्ञानिक कारगों की कार्यशीलता के कारए। शीघ्र ही कीमतें मुद्रा के परिमाए। से ग्रधिक तेजी के साथ बढने लगती हैं।

इसी प्रकार ये मान्यताएँ भी गलत हैं कि चलन तथा साख-मुद्रा तथा वस्तुओं का प्रचलन वेग यथास्थिर रहता है | कीमतों में थोड़ी सी भी वृद्धि होने पर माल जल्दी-जल्दी खरीदा थ्रौर बेचा जाने लगता है । वस्तुओं ग्रौर मुद्रा की इकाइयों का हस्तान्तरण ग्रधिक तेजी के साथ होने लगता है । इसी प्रकार ऋतु के परिवर्तन तथा सट्टा बाजार की प्रवृत्तियों के ग्रनुसार भी प्रचलन वेग बदलता रहता है । इस वेग को यथास्थिर मान लेना ग्रवास्तिवक है । ग्रन्य मान्यताओं के विषय में भी हम ऐसा ही कह सकते हैं । कम से कम इस संसार में तो यह सम्भव नहीं है कि ग्रन्य बातों में परिवर्तन न हो ।

(२) प्रचलन वेग का सही-सही पता लगाने की कठिनाई—फिशर द्वारा दिए गए समीकरण में च तथा चा दो ऐसे तथ्य है जिनकी कोई भी निश्चित माप सम्भव नहीं है। ग्रल्पकालीन दृष्टिकोण से तो चलन तथा साख-मुद्रा के प्रचलन वेग को नापने की ग्रावश्यकता नहीं है, क्यों कि फिशर ने उन्हें यथास्थिर मान लिया है, परन्तु दी घंकालीन दृष्टिकोण से इनको कैसे नापा जाय? साँ ख्यिकी में कोई भी ऐसी रीति

नहीं है कि जिसके द्वारा मुद्रा के प्रचलन वेग का सही-सही पता लगाया जा सके। इस सम्बन्ध में यह भी जानना जरूरी है कि वस्तुश्रों का भी प्रचलन वेग होता है, जिसके कारण वस्तुश्रों का कुल परिमाण उनकी मात्रा तथा विनिमय के लिए होने वाले प्रचलन वेग पर निभंर होता है। सरलता लाने के लिए फिशर के समीकरण में वस्तुश्रों के प्रचलन वेग को सम (Unity) मान लिया गया है, जो ठीक नहीं है।

- (३) केवल दीर्घकालीन प्रवृत्ति का सूचक—यह सिद्धान्त केवल एक दीर्घकालीन प्रवृत्ति को ही दिखाता है। मान्यताग्रों की ग्रवास्तविकता की छोर जब फिशर का घ्यान दिलाया गया तो उन्होंने यही उत्तर दिया था कि ग्रन्य बातें केवल अल्पकाल ग्रथवा मध्य के काल में ही ग्रस्थिर होती हैं। दीर्घकाल में वे लगभग यथा-स्थिर ही रहती हैं। फिशर के सिद्धान्त से केवल इतना ही स्पष्ट होता है कि बहुत सी बातों के समान रहने की दशा में मुद्रा के मूल्य की प्रवृत्ति इस सिद्धान्त के ग्रनुसार रहती है, परन्तु जैसा कि कीन्ज ने कहा है, दीर्घकाल के ग्रव्ययन से क्या लाभ है ? दीर्घकाल में तो हम सभी मर जाते हैं। मुद्रा सम्बन्धी घटनाग्रों के ग्रल्पकालीन परि-एगम भी घातक हो सकते हैं, इसलिए उनके सम्बन्ध में जो भी सिद्धान्त बनाए जायें वे ग्रल्पकालीन होने चाहिए।
- (४) संचित मुद्रा—कीन्ज ने इस सिद्धान्त को एक और दृष्टिकोग् से भी असन्तोषजनक बताया है। उनका विचार है कि चलन अथवा साख मुद्रा की सारी की सारी मात्रा वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने पर व्यय नहीं की जाती है। सभी व्यवसायी हर समय तरल मुद्रा के रूप में चलन तथा साख मुद्रा का एक निश्चित सचय रखते हैं, जिसका ग्राकार समय समय पर बदलता रहता है। केवल यही संचय वस्तुए और सेवाए खरीदने पर व्यय किया जाता है। चलन तथा साख-मुद्रा का एक भाग तो आसंचित कोषों (Hoards) में गायब हो जाता है। यह भाग कीमतों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए मुद्रा-परिमाग् में से हमें मुद्रा की ऐसी मात्रा को निकाल देना चाहिए।
- (१) वस्तुय्रों के प्रचलन-वेग का महत्त्व—इस सिद्धान्त की ग्रालोचना इस ग्राधार पर भी की जा सकती है कि जिस प्रकार चलन-मुद्रा ग्रौर साख-मुद्रा का प्रचलन-वेग होता है ठीक उसी प्रकार वस्तुग्रों का भी प्रचलन-वेग हो सकता है। अर्थात् जिस प्रकार मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित समय-ग्रविध में एक से ग्रधिक बार वस्तुएँ ग्रौर सेवाएँ खरीदने के काम ग्रा सकती है ठीक इसी प्रकार वस्तु की एक इकाई भी उस समय ग्रविध में एक से ग्रधिक बार खरीदी ग्रौर बेची जा सकती है। मुद्रा के मूल्य को निकालते समय वस्तुग्रों के प्रचलन-वेग को भी ध्यान में रखना ग्रावश्यक है, परन्तु फिशर के समीकरण में इस बात को बिल्कुल भुला दिया गया है।
- (६) समय-विलम्ब के महत्त्व की उपेक्षा—इस सिद्धान्त में समय-विलम्ब (Time lag) के महत्त्व को नहीं समभा गया है। मुद्रा के परिमाण के परिवर्तनों

का प्रभाव कीमत-स्तर पर एक दम नहीं पड़ता है, इसमें विलम्ब होता है। यदि श्राज मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है तो महीनों के बाद कीमत-स्तर पर इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। इस काल में ग्रन्य बातों में परिवर्तन हो सकते हैं, जिनके कारण कीमत के परिवर्तनों ग्रीर मुद्रा-परिमाण के परिवर्तनों का पारस्परिक सम्बन्ध सिद्धान्त के ग्रनुसार नहीं रह पाता है।

- (७) यह सिद्धान्त यह स्पष्ट नहीं करता है कि मुद्रा के परिमाण के परिवर्तन किस प्रकार कीमत-स्तर पर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसा कि काउथर, हेयक (Hayek) तथा हॉटरे (Hawtrey) का मत है, मुद्रा-परिमाण के परिवर्तन कीमत-स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। सर्वप्रथम, उनका प्रभाव ब्याज की दरों पर पड़ता है भौर बाद में ब्याज की दरों के परिवर्तन, कीमतों तथा उत्पादन की मात्रा को बदल देते हैं। यही कारण है कि मुद्रा के मूल्य सिद्धान्त का उद्देश्य केवल मुद्रा-परिमाण तथा कीमतों के पारस्परिक सम्बन्ध का उल्लेख करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे सम्बन्धित सारी बातों का स्पष्टीकरण करना होना चाहिए।
- (क) कीमत-स्तर के कुछ परिवर्तनों को समभाने में श्रसफल-यह सिद्धान्त कीमत-स्तर के उन परिवर्तनों को समभाने में श्रसफल रहता है जो व्यापार-चक्रों के कारण उत्पन्न होते हैं। इस सिद्धान्त के श्रनुसार कीमतों के घटने-बढ़ने का कारण केवल मुद्रा की मात्रा की कमी या वृद्धि होती है, परन्तु श्रनुभव बताता है कि श्रवसाद के काल में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर देने पर भी कीमतें नहीं बढ़ती हैं।
- (६) माँग श्रौर पूर्ति के सिद्धान्त का ही एक संशोधित रूप— श्रश्वंशास्त्रियों का विचार है कि यह सिद्धान्त मुल्य के माँग श्रौर पूर्ति सिद्धान्त का ही एक संशोधित रूप है, जिसमें मुद्रा की पूर्ति को श्रावश्यकता से श्रधिक महत्त्व दे दिया गया है। वास्तव में ऐसा ही है। ग्रन्य वस्तुश्रों की भाँति मुद्रा का मूल्य भी उसकी माँग श्रौर पूर्ति द्वारा निश्चित किया जाता है, परन्तु इस सिद्धान्त में व्यर्थ की मान्य-ताश्रों के श्राधार पर केवल मुद्रा की पूर्ति को मुद्रा के मूल्य-निर्धारण का श्राधार मान लिया गया है।

### सिद्धान्त की उपयोगिता—

मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त काफी दोषपूर्ण है। कीन्ज के अनुसार यह सिद्धान्त अधूरा है। उनके विचार में इसके द्वारा मुद्रा की कुल क्रय: शक्ति का सही-सही और पूरा-पूरा अनुमान प्राप्त नहीं होता है, बिल्क केवल नकद क्रय-विक्रय (Cash Purchases & Sales) का ही अनुमान प्राप्त होता है। मुद्रा के द्वारा होने वाले अधिकांश लेन-देन उद्योग, व्यापार अथवा वित्त से सम्बन्धित होते हैं, जिन पर यह सिद्धान्त विचार नहीं करता है। स्वयं फिशर ने भी यह स्वीकार किया है कि संक्रांति काल (Transitional Period) में मुद्रा की मात्रा तथा कीमत-स्तर में

कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है। इस काल में मुद्रा की मात्रा के घटने-बढ़ने के ग्रितिरिक्त भ्रन्य कारणों से भी कीमत-स्तर में परिवर्तन हो सकते हैं।

निष्कर्ष-

सब कुछ होते हुए भी इस सिद्धान्त का कुछ महत्त्व श्रवश्य है। (i) कीमत स्तर के परिवर्तनों के वैसे तो बहुत से कारण होते हैं, परन्तु इन सब में सबसे महत्त्वपूर्ण कारण मुद्रा की मात्रा ही है। कीमतों के परिवर्तनों का कारण बत ने के नाते सिद्धान्त का कुछ महत्त्व श्रवश्य है। (ii) व्यावहारिक जीवन में भी इस सिद्धान्त का उपयोग श्रवेक बार दृष्टिगोचर होता है। कीमत स्तर पर नियन्त्रण रखने के लिए इस सिद्धान्त का उपयोग किया जाता है। चलन की मात्रा को बढ़ाकर कीमतों को बढ़ाने तथा चलन की मात्रा को घटा कर बढ़ती हुई कीमतों की नीचे गिराने का उपाय काफी विस्तृत रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से मुद्रा की मात्रा के परिवर्तनों के श्रवुपाती परिवर्तन तो कीमत स्तर में नहीं होते हैं, परन्तु कम से कम एक श्रंग तक कीमत स्तर को परिवर्तित श्रवश्य किया जा सकता है। यह सिद्धान्त हमें कम से कम कीमतों के नियन्त्रण का एक श्रच्छा उपाय तो बताता हो है। राबर्टसन ने कहा है:—''मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त मुद्रा का मूल्य समक्तन के लिए एक विचित्र सत्य है। यह एक ऐसा सत्य है कि जिसका समक्ता वास्तविक जीवन में मुद्रा की मात्रा श्रीर वस्तुश्रों की कीमत में सम्पर्क स्थापित करने के लिए श्रावश्यक है।'' ध्रिरागण सिद्धान्त में सत्यता का श्रंश— धरिमाण सिद्धान्त में सत्यता का श्रंश—धरिमाण सिद्धान्त में सत्यता का श्रंश—

परिमाण सिद्धान्त को अपूर्ण, किल्पत एवं दोषपूर्ण वताया गया है। यह आलोचना बहुत कुछ सही भी है, किन्तु यह स्मरणीय है कि जब माँग तथा पूर्ति के सिद्धान्त को मुद्रा पर लाग्न किया जाता है, तो वस्तुओं की तरह मुद्रा की माँग व पूर्ति में जो परिवर्तन समय-समय पर होते रहते हैं तथा इन परिवर्तनों के फलस्वरूप मुद्रा के मूल्य में जो परिवर्तन होते हैं उनका स्पष्टीकरण यह सिद्धान्त कर देता है। इस सम्बन्ध में फिशर ने कई उदाहरण दिये हैं:—

- (१) अमेरिका में चाँदी की खानों का पता लगने पर, स्पेनिश खोज करने वालों ने उसे योरोप को भेजना प्रारम्भ कर दिया, जिससे वहाँ सामान्य मूल्य-स्तर बढ़ गया। बाद में जैसे-जैसे जन-संख्या बढ़ती गई (मुद्रा की माँग बढ़ी या अमेरिक से चाँदी का आयात कम होने लगा) वैसे-वैसे वस्तुओं की कीमतें कम होती गई।
- (२) ग्रास्ट्रेलिया ग्रीर कैलीफोरिनयां से सन् १८४४ के लगभग बड़ी मात्रा में सोने का ग्रायात स्वर्णमान देशों में हुग्रा, जिससे उन देशों में वस्तुग्रों के मूल्य बढ़ गये। जब उक्त खानों से सोना निकलना बन्द हो गया, तो इन देशों में मूल्य-स्तर भी गिर गया।
- (३) मैक्सीको में चाँदी की खानें मिल जाने से भारत व ग्रन्य रजतमान देशों में सन् १८७३ के लगभग वस्तुग्रों के मूल्यों में वृद्धि हो गई थी।
- (४) द्वितीय महायुद्ध और इसके पश्चात् भारत व अन्य देशों में कागजी नोटों के आधिक्य के कारण वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य बढ़ गये थे।

स्पष्ट है कि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन के फलस्वरूप मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान होता है। हाँ, इससे इन दोनों में कोई संख्यात्मक सम्बन्ध स्थापित नहीं होता। शायद प्रोफेसर फिशर का भी यह ग्रिभिप्राय न था। उन्होंने गिणितात्मक समीकरण का प्रयोग केवल एक प्रवृत्ति को दिखलाने के लिए किया है।

## (II) कैम्ब्रिज का मुद्रा का परिमाण विद्धान्त (The Cambridge Quantity Theory of Money)

कैम्ब्रिज सिद्धान्त के निर्माण का श्रेय मार्शल, पीगू, हॉटरे, कैनन ग्रौर राबटंसन जैसे प्रसिद्ध ग्रर्थशास्त्रियों को है। इन्होंने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को एक नये समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

- (१) प्रत्येक समाज में लोग अपनी आय के एक निश्चित भाग को चलन के रूप में जमा करना अच्छा समक्षते हैं। फिशर ने अपने समीकरण में मुद्रा की माँग को कुल सौदों के मूल्य के बराबर (M=P.T.) माना था अर्थात् मुद्रा का स्वयं कोई उपयोग नहीं होता। वह केवल विनिमय के काम में भ्राता है। लेकिन ध्यानपूर्वंक विश्लेषण करने से प्रतीत होगा कि जमा करने के हेतु भी लोग मुद्रा की माँग करते हैं, क्योंकि अनेक बार व्यावहारिक जीवन में भ्राय और खर्च का पूरा संयोग नहीं बैठता। यदि कभी खर्च करना चाहते हैं, तो आमदनी नहीं होती और यदि कभी आमदनी है लो-खर्च कम है। प्रायः आमदनी कम और खर्च अधिक होता है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति, संस्था अथवा सरकार अपने पास दैनिक खर्चों की पूर्ति के लिये कुछ न कुछ घन नगदी के रूप में जमा रखती है। वह कुल मद्रा जो विभिन्न व्यक्ति, संस्थायें और सरकार अपने पास दैनिक खर्चे चलाने के लिये रखते हैं, मुद्रा की कुल माँग कहलाता है।
- (२) मुद्रा की मांग लोगों की द्रव्यता पसन्दगी (Liquidity Preference) पर निर्भर होती हैं। मनुष्य ग्रपना धन कई प्रकार से विनियोग कर सकता है। कुछ विनियोग इतने सरल हैं कि उनको तत्काल मुद्रा में बदला जा सकता है, जब कि ग्रन्य में ऐसी सुविधा नहीं होती है। उदाहरण के लिये, वस्तुग्रों की ग्रपेक्षा शेयरों में ग्रधिक द्रवता होती है। ग्रतः जिन लोगों में द्रवता पसन्दगी ग्रधिक है उनकी मुद्रा सम्बन्धी मांग (ग्रर्थात् मुद्रा को ग्रपने पास चलन के रूप में रखने की मांग) ग्रधिक होती है ग्रौर जिन लोगों में द्रव्यता पसन्दगी कम होती है उनकी मुद्रा सम्बन्धी माँग भी कम होती है।
- (२) मुद्रा की माँग पर अन्य अनेक बातों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आय प्राप्त होने की अवधि, वस्तु का मूल्य, जन संख्या, धन का वितरण, व्यवसाय

प्रो॰ कैनन के राब्दों में ''जिस प्रकार मकान की वास्तविक मांग मकान में रहने वाले लोगों की होती है (मकानों के खरीदने-बेचने वालों की नहीं) उसी प्रकार मुद्रा की गस्तविक मांग वह है जिसे मनुष्य अपना खर्च चलाने के लिये अपने पास रखते हैं।''

की दशा, लेन-देन में चैंक व ग्रन्य साख-पत्र प्रयोग करने की ग्रादत, मुद्रा की चलन गित । यदि ग्रामदनी देर से प्राप्त होती। है, वस्तुग्रों का मूल्य ग्रधिक है, जन-संख्या ग्रधिक है, घन का समान वितरण है, व्यवसाय में कम लाभ होता है, साख-पत्रों का उपयोग ग्रधिक किया जाता है, मुद्रा की चलन गित कम है, तो जनत। के पास नगद ख्पया बहुत होता है, ग्रर्थात् मुद्रा की मांग ग्रधिक होगी विपरीत दशाश्रों में मुद्रा की मांग कम होगी।

### निष्कर्ष—

स्पष्ट है कि कैंम्ब्रिज समीकरए के अनुसार मुद्रा की मांग किसी देश के व्यापारिक सौदों की मात्रा पर निर्भर नहीं होती, वरन् जनता की मुद्रा की मांग पर निर्भर होती है, क्योंकि जनता अपनी आय का कुछ भाग नगद रूप में अपने पास बचा कर रखना चाहती है। फिशर के विपरीत इस सिद्धान्त में मुद्रा की मांग पर अविक बल डाला गया है, इसलिये इसे मुद्रा की मांग का सिद्धान्त (Demund Theory of Money) भी कहा गया है।

कैम्ब्रिज समीकरण-

(१) कैम्ब्रिज समीकरण के ग्राघारमूत विचार को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं:—प्रत्येक समाज में लोग ग्रपनी ग्राय के एक निश्चित भाग को चलन के रूप में जमा करना ग्रच्छा समभते हैं! इस प्रकार चलन को जमा कर लेने से व्यवसाय में बड़ी सुविधा होती है, परन्तु इस प्रकार चलन को जमा करने से हानि भी होती है, क्योंकि यह पैसा बेकार पड़ा रहता है ग्रौर किसी भी प्रकार की ग्राय उत्पन्न नहीं कर पाता है। इस सम्बन्ध में एक व्यक्ति इस प्रकार जमा किये हुए चलन के लाभों ग्रौर उसकी हानियों की बड़ी समभदारों के साथ तुलना करता है ग्रौर तत्पश्चात् यह निश्चय करता है कि कुल ग्राय के कौन से भाग को इस प्रकार जमा करके रखा जाय। यदि किसी देश के लोग कुल ग्राय के कै की इस रूप में जमा कर लेना उपयुक्त समभते हैं तो ऐसी दशा में देश के चलन की सामूहिक कीमत समाज की ग्राय के कै के बराबर होगी। यदि समाज की वार्षिक वास्तविक ग्राय र (I?) द्वारा मूचित की जाती है ग्रौर ग्रा (K) ग्राय के उस ग्रनुपात को दिखाता है जो कि जनता चलन के रूप में रखती है तो ग्रा र (K) मुद्रा की कुल मात्रा, ग्रर्थात् म (M) के मूल्य के बराबर होगा। इस प्रकार मुद्रा की एक इकाई का मूल्य में ग्रथात् K K के बराबर होगा। इस प्रकार मुद्रा की एक इकाई का मूल्य में ग्रथात् K K के बराबर होगा।

श्रौर क्योंकि सामान्य कीमत-स्तर मुद्रा के मूल्य का उल्टा होता है इसलिए क $=\frac{\mu}{2\pi}$ 

ग्रथवा  $P = \frac{M}{KR}$  ही सही समीकरण होगा, जिसमें क (P) पहले समीकरण की भांति सामान्य कीमत-स्तर को सूचित करता है

From Marshall quoted by Keynes: A Treatise on Money,

उपरोक्त विचारधारा के अनुसार मुद्रा केवल वस्तुएँ ही खरीदने का ही एक मात्र साधन नहीं है। बल्कि वस्तुओं के मृल्य का संचय भी इसी में किया जाता है। देश में व्यापार की तेजी और मन्दी के कारण मुद्रा की मांग में वृद्धि अथवा कमी होती रहती है। साधारणतया मन्दी के काल में जनता मुद्रा का सञ्चय करती है, जिसके कारण मुद्रा की मांग बढ़ती है, उसका मूल्य बढ़ता है और कीमतें गिरती हैं। तेजी के काल में व्यवसायी वगं मुद्रा को नये-नये उपक्रमों में लगाना चाहता है, अतएव मुद्रा की पूर्ति इसकी मांग से भी अधिक हो जाती है। इससे मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमतें ऊपर चढ़ जाती है, अतः यह पता चलता है कि मुद्रा की माँग व्यापारिक सौदों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि जनता की माँग पर निर्भर होती है, जो उसका सञ्चय करना चाहती है।

फिशर की विचारधारा और कैम्ब्रिज की विचारधारा में अन्तर—

फिशर की विचारधारा और कैम्ब्रिज विचारधारा का इन्तर संक्षेप में इस प्रकार है:—(i) फिशर का सिद्धान्त उस सब मुद्रा पर आधारित है जो देश में व्यापार के लिए आवश्यक है, परन्तु कैम्ब्रिज विचारधारा अपने अध्ययन को उस नकदी पर आधारित करती है जो समय विशेष में जनता द्वारा भविष्य के लिए जमा की जाती है। (ii) फिशर का सिद्धान्त दीर्घकालीन है और एक अधि (Period) की ओर संकेत करता है, परन्तु कैम्ब्रिज सिद्धान्त अल्पकालीन है और एक च्ता (Moment) का ही अध्ययन करता है। इन दोनों सिद्धान्तों को एक दूसरे के विरोधी तो नहीं कहा जा सकता है, परन्तु ये दोनों एक ही समस्या के दो विभिन्न रूपों का अध्ययन अवश्य करते हैं।

### कैम्ब्रिज समीकरण में कीन्ज द्वारा संशोधन

कैम्ब्रिज समीकरण को कुछ संशोधज्ञों के साथ दो ग्रौर रूपों में भी व्यक्त किया गया है। जैसा कि स्पष्ट है कि उपरोक्त समीकरण में केवल चलन की मात्रा पर ही विचार किया गया है, साख-मुद्रा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उसको सिम-लिए करते हुए कीन्ज ने समीकरण को इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

न=क (श्र+र आ) अथवा 
$$n=p (k+r k')$$
\*

इस समीकरण में कैम्बिज समीकरण से कोई भी आधारभूत अन्तर नहीं है। न (n) समस्त चलन की मात्रा को दिखाता है, क (p) सामान्य कीमत को, आ (k) उन उपभोग की इकाइयों (Consumption Units) को जिनके लिये चलन के रूप में क्रय: शक्ति संचय की जाती है, र (r) बेंकों के नकद कोषों तथा निक्षेपों का अनुपात है और आ (k) उन उपभोग की इकाइयों की मात्रा है जिनके लिए साख-मुद्रा में क्रय: शक्ति का संचय किया जाता है। कीन्ज के समीकरण की विशेषता यह है कि साख-मुद्रा के महत्त्व तथा प्रभाव को भी आवश्यक स्थान दे दिया गया है। कीन्ज

का यह समीकरण उनके द्रवता पसन्दगी सिद्धान्त पर श्राघारित है, जिसका उपयोग उन्होंने ब्याज के निर्घारण के सम्बन्ध में किया है। इस समीकरण में श्रासिद्धत कोषों के प्रभाव से मुद्रा के मूल्य को विमुक्त कर दिया गया है।

### पीगू का संशोधन-

पीगू ने इस सम्बन्ध में जो समीकरण दिया है वह निम्न प्रकार है :—  $\pi = \frac{\pi}{H} \left\{ \pi + \varepsilon(? - \pi) \right\}$  ग्रथवा  $P = \frac{K}{M} \left\{ c + h(1 = c) \right\}$ 

### कैम्ब्रिज समीकरण की श्रालोचना —

फिशर के समीकरण को नकद-व्यवसाय (Cash Transaction) समीकरण का नाम दिया जाता है श्रौर इसके विपरीत के मित्रज समीकरण का रूप नकद-शेष (Cash-balance) से सम्बन्धित है, परन्तु इस समीकरण की सहायता से भी पुराने समीकरण की भाँति मुद्रा की क्यः शक्ति का पता लगाना कठिन है। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो समीकरण सही प्रतीत होता है, परन्तु व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह श्रमुपयुक्त है। कीन्ज के समीकरण में श्र श्रौर श्रा (k and k') तथा पीयू द्वारा दिये गये समीकरण में स श्रौर ह (c and h) की कोई भी निश्चित माप सम्भव नहीं है। इसी प्रकार मार्शल ने जिस समीकरण को दिया है उसमें श्र (K) का पता लगाना लगभग श्रसम्भव है।

## (III) बचत और विनियोग का सिद्धान्त (The Saving and Investment Theory)

गह सिद्धान्त भी कीन्ज के नाम से सम्बन्धित है, यद्यपि इस पर हेयक (Hayek), हेवरलर (Heberler), क्राउथर ग्रादि ग्रनेक विद्वानों ने काम किया है। कीन्ज का विचार है कि मुद्रा का मूल्य जनता की ऋाय तथा उसके बचाने की शाकि तथा बचत और विनियोग के सम्बन्ध पर निर्भर होता है, मुद्रा के परिमाण पर नहीं।

परिमाण सिद्धान्त के श्रालोचकों का विचार है कि यद्यपि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त यह तो बता देता है कि एक समय विशेष में कीमत-स्तर एक निश्चित बिन्दु पर क्यों होता है ? परन्तु यह सिद्धान्त उन रीतियों को स्पष्ट नहीं करता है श्रौर उस क्रम को नहीं बताता है कि जिनके कारण कीमत-स्तर में परिवर्तन पैदा होते हैं। बचत

श्रीर विनियोग सिद्धान्त के समर्थकों का कहना है कि उनके सिद्धान्त की सहायता से कीमत-स्तर तथा उसके परिवर्तनों का सभी प्रकार की श्राधिक घटनाश्रों, जैसे — द्रव्यिक श्राय (Money Income), व्यय, उत्पादन, बचत, विनियोग, मुद्रा का संचय, मुद्रा की निकासी श्रादि से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है।

इस सिद्धान्त के प्रमुख ग्राघार निम्न प्रकार हैं :---

- (१) किसी निश्चित काल में मुद्रा का मूल्य एक श्रोर तो द्रव्यिक श्राय तथा व्यय के सम्बन्ध पर निर्भर होता है श्रोर दूसरी श्रोर वास्तविक श्राय श्रथवा बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत की हुई वस्तुश्रों की मात्रा पर। इसमें से द्रव्यिक ग्राय तो मुद्रा की मात्रा तथा उससे मिलने वाली श्राय श्रथवा उसके प्रचलन वेग पर निर्भर होती है श्रीर वस्तुशों की मात्रा—पूँजी की मात्रा, लाभ की सम्भावना श्रादि पर निर्भर होती है।
- (२) किसी देश में उपलब्ध मुद्रा की मात्रा बहुत सी बातों पर निर्भर होती है, जैसे— देश का मुद्रा-मान, नकद कोषों तथा सुरक्षित कोषों संबंधी नियम, बैंक प्रणाली का रूप इत्यादि। इसके विपरीत आय अथवा मुद्रा का विनियोग वेग (Circuit Velocity) साहसी वर्गों द्वारा लाभ की आशा, उत्यादन के अन्तर्गत व्यय होने वाले समय तथा आय प्राप्त करने वालों के इस निर्णय पर भी निर्भर होता है कि आय का उपयोग किस प्रकार किया जायगा।
- (३) एक निश्चित काल में द्रव्यिक ग्राय की मात्रा उस काल में उत्पादित वस्तुओं की भौद्रिक कीमत के बराबर होती है, परन्तु यह सम्भव है कि नवीन उत्पादित वस्तुओं के खरीदने के लिए बाजार में जितनी मुद्रा प्रस्तुत की जाती है वह ग्रासंचन (Hoarding), मुद्रा-निर्माण ग्रथवा मुद्रा विनाज्ञ के कारण उसी काल की द्रव्यिक ग्राय से कम ग्रथवा ग्रधिक हो।
- (४) बचत का ग्रभिप्राय यह होता है कि द्रव्यिक ग्राय समय विशेष में नई उपभोग की वस्तुग्रों पर व्यय नहीं की जाती है ग्रौर विनियोग का ग्राशय द्रव्यिक ग्राय को पूँजी की नई वस्तुग्रों पर व्यय करना होता है। कुल द्रव्यिक ग्राय उपभोग तथा पूँजी दोनों प्रकार की वस्तुग्रों पर किये जाने वाले व्यय से कम या ग्रिविक हो सकती है, जिसका कारण संचित कोषों का जमा करना ग्रथवा खाली करना होता है।
- (१) इस प्रकार किसी काल में बचत श्रीर विनियोग का बराबर होना श्रावश्यक नहीं होता है, ज्याज की वास्तविक दरें उनके बीच संतुलन

स्थापित नहीं करती हैं। मुद्रा के विनाश ग्रथवा ग्रासंचन के कारण बचत विनियोग से ग्रधिक हो सकती है ग्रौर इसी प्रकार मुद्रा के निर्माण ग्रथवा व्यर्थ जमा के टूटने के कारण विनियोग बचत से ग्रधिक हो सकता है।

(६) जिस दशा में बचत विनियोग से श्रिष्ठिक होती है, कीमतें नीचे गिरती हैं ग्रौर जिस काल में विनियोग बचत से ग्रिष्ठिक होता है, कीमतें ऊार चढ़ जाती हैं। साम्य की स्थिति वही होती है जिसमें बचत ग्रौर विनि-योग दोनों बराबर होते हैं।

बहुत ही सरल भाषा में उपरोक्त सिद्धान्त यह बताता है कि उपभोग की वस्तुओं श्रौर पूँ जी की वस्तुओं (Consumption Goods and Capital Goods) की कीमतें और इसलिए मुद्रा का मूल्य, श्राय प्राप्त करने वालों के इस निर्णय पर निर्भर होता है कि वे उस श्राय का कौनसा भाग वस्तुयें खरीदने के लिए प्रस्तुत करते हैं। जिस स्थिति में वस्तुयें खरीदने के लिए प्रस्तुत की हुई श्राय घटती है, परन्तु वस्तुओं की मात्रा यथास्थिर रहती है, श्रथवा वस्तुओं की मात्रा बढ़ती है, लेकिन श्राय का वह भाग यथास्थिर रहती है जो वस्तुएँ खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है तो सामान्य कीमतें गिरती हैं। इसके विपरीत उस दशा में सामान्य कीमतें बढ़ेंगी जबिक या तो वस्तुओं की मात्रा में कमी हुए बिना वस्तुएँ खरीदने के लिए प्रस्तुत किया हुशा श्राय का प्रवाह (Flow of Income) बढ़ता है, श्रथवा जबिक श्राय की मात्रा के यथास्थिर रहते हुए भी वस्तुओं की मात्रा घटती है।

इस सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य कोन्ज ने किया है। उनका विचार है कि वचत ग्रौर विनियोग सदा ही ग्रौर ग्रावश्यक रूप में एक दूसरे के बराबर होते हैं। कि कीन्ज ने ग्रपना तर्क निम्न तीन समीकरणों द्वारा प्रस्तुत किया है:—

का 
$$=$$
 उ $+$  वि  $=$  श्रथवा  $Y = C + I$   $=$  श्रथवा  $S = Y - C$  श्रयत्व  $=$  वि  $=$  श्रथवा  $S = I$ 

उपरोक्त समीकरणों में  $q_I(Y)$  कुल श्राय को सूचित करता है, g(C) उपभोग को, g(I) विनियोग को तथा बg(I) वचत को। पूरे समाज को जो श्राय प्राप्त होती है, श्रर्थात का, वह या तो उपभोगीय वस्तुश्रों g(I) का उत्पादन करके होती है, श्रथवा विनियोग की वस्तुयों g(I) उत्पन्न करके। इसी प्रकार g(I) चg(I) परन्तु g(I) जो उपभोग की वस्तुश्रों को उत्पन्न करने की श्राय को सूचित करता है, श्राय की इस मात्रा के बराबर होगा जो उपभोग की वस्तुएँ खरीदने पर व्यय की जाती है, क्योंकि इन दोनों में वास्तव में कोई श्रन्तर नहीं होता है। इसी प्रकार g(I) मुद्रा की

उस मात्रा को दिखाता है जो विनिमय की वस्तुग्रों ग्रथवा पूँजी की वस्तुग्रों पर व्यय की जाती है। इससे यह पता चलता है कि समाज की कुल बचत व, का—उ के बराबर होनी चाहिए ग्रौर क्योंकि विभी का—उ के बराबर है, ग्रतएव a=1, ग्रथित बचत ग्रौर विनियोग वराबर होंगे।

एक उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—
इस सिद्धान्त को अधिक स्पष्ट करने के लिए और यह दिखाने के लिए कि
मुद्रा की मात्रा के परिवर्तनों का बचत तथा विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम
एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि मुद्रा संचालक मुद्रा की मात्रा (ऋण
योग्य कोष) को बढ़ाता है। इससे ब्याज की दरें नीचे गिरेंगी, जिसके फलस्वरूप
साहसियों द्वारा ऋण लेने तथा विनियोजन को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे आगे चलकर
मौद्रिक आय बढ़ेगी, जिसका कारण पहले मुद्रा की मात्रा की वृद्धि हो जाना होगा।
कीन्ज के अनुसार विनियोग बचत से कम या अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि विनियोग के लिए जिस मुद्रा का सृजन होता है वह तुरन्त किसी न किसी की आय को
बढ़ाती है और यदि इस आय का उपभोग नहीं होता है तो इसकी बचत ही की
जायगी। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा के परिवर्तनों की दशा में भी ब्याज की दरों के
परिवर्तनों द्वारा बचत और विनियोग बरावर ही रहेंगे। यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ाई
जाती है और अतिरिक्त मुद्रा के एक भाग का आसंचन (Hoarding) भी कर लिया

जाता है तो भी उपरोक्त निष्कर्ष में कोई त्रुटि उत्पन्न नहीं होती है। यह निश्चय है कि आसंचित आय न तो उपभोग पर व्यय हुई है और न विनियोग पर। ऐसी दशा में वस्तुओं और सेवाओं की माँग घटेगी, कुछ माल बिना बिके रह जायगा, कीमतें नीचे गिरेंगी और भविष्य में आय घट जायगी, जिसका उपभोग, बचत और विनियोग तीनों

वस्तुएँ खरीदने के काम म्राती है म्रौर न उत्पत्ति की वस्तुयें खरीदने के लिए। इस कारण उपभोग की वस्तुएँ म्रौर पूँ जीगत माल बिना बिके रह जायगा म्रौर इस प्रकार रहे हुए माल को विनियोग ही गिना जायगा। म्रतः म्रासंचन की दशा में भी बचत भ्रौर विनियोग बराबर होते है।

पर प्रभाव पड़ेगा। कीन्ज का कथन है कि क्यों कि आसंचित आय न तो उपभोग की

कीनज के सिद्धानत के दोष-

कीन्ज के इस दिष्टकोरा के कई दोष है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :--

(१) बचत श्रीर विनियोग प्रत्येक दशा में समान नहीं हैं —कोन्ज ने बचत श्रीर विनियोग जैसे एक से तथ्यों को बराबर बनाने का प्रयत्न किया है। इससे कुछ पारिभाषिक कठिनाइयाँ पैदा हो जाती है। लेवन्तीफ (Leontief) का विचार है कि बचत श्रीर विनियोग को प्रत्येक दशा में समान दर्शाने से एक सैद्धान्तिक सन्तोष के श्रीतिरक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।\*

W. Leontief: Implicit Theoriving—a Mathematical Criticism of the Neo-Cambridge School, Quarterly Journal of Economics, Vol. 51, p. 337.

(२) व्यावहारिक महत्त्व का प्रभाव—खुट्ज का विचार है कि कीन्ज ने बचत और विनियोग की जो परिभाषायें दी हैं वे प्रवेगिक परिवर्तनों अथवा साख नीति के अध्ययन में बेकार हैं। ऐसी दशा में कीन्ज के मत का व्यावहारिक महत्त्व कुछ भी नहीं होगा। \*

## "मुद्रा की माँग की लोच 'इकाई' है"-

परिमाण सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा की मात्रा हूनी कर देने से मूल्य-स्तर दूना श्रीर मुद्रा की मात्रा ग्राघी कर देने से मूल्य-स्तर ग्राघा हो जाता है। इस कथन से यह आशाय निकलता है कि मुद्रा की माँग की लोच 'इकाई' (Unity) के बराबर है। है। किन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि मुद्रा की माँग की लचक इकाई के बराबर नहीं होती है। इसका कारण यह है कि व्यात्रहारिक जीवन में मुद्रा के पूर्ति के अनुसार मूल्य-स्तर में अनुपातिक परिवर्तन नहीं हुआ करते, जैसा कि उक्त कथन में बताया गया है। उदाहरण के लिए, प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी में जर्मन मार्क में जैसे-जैसे वृद्धि हुई वैसे वैसे वस्तुश्रों का मूल्य भी बढ़ता गया श्रीर यह मूल्य वृद्धि अनुपात से कहीं श्रीक हुई, क्योंकि जनता का मुद्रा से विश्वास उठ गया था। श्रतः मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन से मूल्य-स्तर में उसी अनुपात में परिवर्तन नहीं होते श्रीर इसलिए मुद्रा की माँग की लोच भी 'इकाई' के बराबर नहीं हो सकती है।

# मुद्रा की मात्रा की बृद्धि का कीमत स्तर पर प्रभाव (Effect of Increased Money Supply on the Price-level)—

मुद्रा, कीमत तथा ब्याज की दर के पारस्परिक सम्बन्ध में प्रतिष्ठित ग्रथंशास्त्री टाउजिंग ने इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है: "ग्रधिक मुद्रा कीमतों को ऊँचा उठाती है, परन्तु ब्याज की दर को नीचे नहीं गिराती है।" यही विचारधारा मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त तथा ब्याज के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त (Marginal Productivity Theory) पर ग्राधारित है। कीन्ज ने ग्रपनी जनरल थ्योरी (General Theory) में इस प्रतिष्ठित विचारधारा को स्वीकार किया है कि मुद्रा की मात्रा की वृद्धि साधारणतया कीमतों की भी वृद्धि उत्पन्न करती है; परन्तु इस सम्बन्ध में कीन्ज का विचार पृथक है कि कीमतों की यह वृद्धि किसी प्रकार उत्पन्न होती है।

कीन्य का विचार है कि मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि का ग्रारम्भिक प्रभाव यह होता है कि ब्याज की दरें नीचे गिरती हैं। कारण यह है कि ग्रब लोगों के पास मुद्रा उससे प्रधिक मात्रा में हो जाती है जितनी कि ये रखना चाहते हैं, जिसके कारण उधार दिये जाने वाले कोषों की मात्रा बढ़ती है। किन्तु ब्याज की दर के घटने से विनियोग (Investments) प्रोत्साहित होते हैं ग्रीर विनियोगों के बढ़ने के कारण रोजगार में वृद्धि हो

<sup>\*</sup> F. A. Lutz: The Outcome of the Saving-Investment Discussion, Quarterly Journal of Economics, Vol. 52, p. 613.

जाती है। रोजगार की यह वृद्धि निम्न तीन कारणों से कीमतों को बढ़ा देती है:—(<)
मजदूरी व्यय बढ़ जाता है, क्योंकि श्रमिकों की माँग बढ़ जाती है श्रीर साथ ही श्रमिकों
की मिलमालिकों से सौदा करने की शक्ति (Bargaining Power) भी बढ़ जाती
है; (२) साधारणतया श्रल्पकाल में क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है; जिसके
कारण उत्पादन व्यय बढ़ जाता है श्रीर (३) उत्पादन के विस्तार के मार्ग में श्रमेक
बाधाएँ (Bottlenecks) उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उत्पत्ति के सभी साधनों की
माँग पूर्ण ह्रप में लोचदार नहीं होती है।

कीन्ज के मतानुसार यद्यिप मुद्रा की मात्रा के बढ़ने से रोजगार और कीमतें दोनों बढ़ते हैं, किन्तु आरम्भ में रोजगार की वृद्धि का ही महत्त्व होता है, परन्तु घीरे-घीरे जैसे-जैसे पूर्ण रोजगार (Full Employment) की स्थिति समीप आती जाती है तो कीमतों की वृद्धि अधिक महत्त्वपूर्ण होती जाती है। जब पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती है तो रोजगार के आगे बढ़ने की सम्भावना समाप्त हो जाती है और अब मुद्रा की मात्रा की वृद्धि का प्रभाव कीमतों की ही वृद्धि पर ही पूर्ण रूप में पड़ने लगता है।

कीन्ज के अनुसार संशोधित रूप में मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: "जब तक बेरोजगारी है, रोजगार का परिवर्तन उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है; और जब पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती है तो कीमतें उसी अनुपात में बदलती हैं जिसमें कि मुद्रा की मात्रा।" यह विचाराधारा निम्न मान्यताओं पर आधारित है:—

(१) बेरोजगारी भ्रयवा भ्रांशिक बेरोजगारी के काल में उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है।

(२) पूर्णं रोजगार की दशा में उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति पूर्णंतया बेलोच हो।

(३) सप्रभाविक माँग की श्वृद्धि उसी श्रनुपात में होती है जिसमें कि मुद्रा की मात्रा की वृद्धि ।

श्रलग-श्रलग वस्तुमों की कीमतों में उनके उत्पादन व्यय के परिवर्तनों के श्रनुसार परिवर्तन होते हैं श्रौर उत्पादन व्यय के परिवर्तन उत्पादन की मात्रा पर निर्भर होते हैं। मुद्रा की मात्रा का परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप में उत्पादन व्यय पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, किन्तु परोक्ष रूप में ब्याज की दर, विनियोग के ग्रंश, श्राय तथा रोजगार के परिवर्तन के कारएा उत्पादन व्यय में भी परिवर्तन श्रा, जाते हैं।

"So long as there is unemployment, employment will change in the same proportion as the quantity of money; and when there is full employment, prices will change in the same proportion as the quantity of money." Vide Keynes: General Theory.

जब कीमतें तथा उत्पादन की मात्रा बढ़ते हैं तो व्यवसाय के लिए श्रधिक मुद्रा की श्रावश्यकता होती है, जिसके कारण मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। इस प्रकार कीमत-स्तर तथा उत्पादन की मात्रा की वृद्धि श्रधिक मुद्रा के निर्माण का कारण बूनती है। इस प्रकार श्रधिक मुद्रा के कारण कीमतें ऊँची नहीं होतीं, बिल्क ऊँची कीमतों के कारण मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। यह क्रम उसका बिल्कुल उल्टा है जैसा कि प्रतिष्ठित परिमाण सिद्धान्त में दर्शाया गया है।

#### QUESTIONS

- द्रव्य की परिभाषा दोजिए श्रौर समम्माइये कि द्रव्य तथा श्रन्य वस्तुश्रों में क्या श्रन्तर है १ द्रव्य का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए।
   (Agra, B. A., 1958)
- 2. क्या श्राप द्रव्य के परिमारा सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं ? (Agra, B. A., 1957 Supp.)
- 3. मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा की माँग की विस्तृत रूप में व्याख्या कीजिए। (Agra, B. A, 1957)
- 4. The Quantity Theory has been widely criticised. With the qualification 'Other things remaining the same' it is a useless truism. "Examine the statement and give the main weeknesses of the Theory. (Agra, B. A., 1954)
- 5. Critically examine Quantity Theory of Money and explain how far it falls short of giving correct explanation of variation in price-level. (Raj., B. A., 1957)
- 6. What is meant by the Quantity Theory of Money? How far does it afford a true explanation of the rise and fall of prices? (Agra, B. Com., 1958)
- 7. What do you understand by the Quantity Theory of Money? What are its limitations?

(Agra, B. Com., 1954, 1956)

- 8. Explain what is meant by 'value of money' and show how is it measured? (Raj., B. Com., 1958)
- 9. Explain the Quantity Theory of Money as propounded by Keynes- How does it mark an advance upon Fisher's Theory?
  (Raj., B. Com., 1956)
- 10. मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त समकाइये। (Sagar, B. A., 1957)

सुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की श्रालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मुद्रा की चलन-पति के कौन-कौन से मुख्य कारक हैं। (Sagar, B. Com., 1957)

What is meant by value of money? How is the value of money determined? (Alld., B. A., 1955)

What do you understand by velocity of circulation of money? Discuss the factors that determine it.

(Patna, B. A., 1957)

सुद्रा (Money) क्या है, बताइये। सुद्रा-मात्रा सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) समभाइये। (Jabalpur, B. A., 1958)

Discuss critically the Quantity Theory of Money.

मुद्रा मात्रा-सिद्धान्त की तर्क पूर्णे व्याख्या कीजिये। (Agra, B. A., 1959)

### अध्याय ६

# मुद्रा-स्फीति, मुद्रा-संकुचन तथा मुद्रा-संस्फीति

(Inflation, Deflaton and Reflation)

### प्रारम्भिक--

पिछले श्रघ्याय में हम यह देख चुके हैं कि मुद्रा के मूल्य श्रथवा कीमत-स्तर में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। पूँजीवादी देशों में एक निश्चित क्रम के अनुसार श्रिमवृद्धि ग्रथवा वैभव (Boom or Prosperity) तथा श्रवसाद श्रथवा मन्दी (Depression or Slump) के काल ग्राते रहते हैं श्रौर इनके श्रनुसार ही ग्राधिक जगत में उथल-पुथल होती रहती है। तेजी श्रौर मन्दी के इस क्रम को ग्रथंशास्त्र में व्यापार चक्र श्रथवा व्यवसायिक चक्र (Trade Cycles or Business Cycles) के नाम से पुकारा जाता है। व्यवसायिक चक्रों के कारण उत्पन्न होने वाले कीमतों के परिवर्तनों ने संसार में काफी ग्रातंक मचा रखा है श्रौर पूँजीवादी संसार इनसे बहुत भयभीत है। किठनाई यह भी है कि इनके निवारण का कोई पूर्णतया सफल उपाय श्रथंशास्त्र के पण्डित नहीं निकाल पाए हैं। कीमतों के इस प्रकार के उच्चावचनों का श्रघ्ययन श्रथंशास्त्र में एक नितान्त ग्रावश्यक विषय बन गया है। प्रस्तुत श्रघ्याय में उच्चावचनों के विभिन्न रूपों, उनके कारणों श्रौर उनकी प्रकृति का श्रघ्ययन किया जायगा।

## मुद्रा-प्रसार श्रथवा मुद्रा-स्फीति

(Inflation)

### मुद्रा प्रसार का ऋर्थ (Mening of Inflation)

लगभग प्रत्येक लेखक ने मुद्रा-प्रसार ग्रथवा मुद्रा-स्फीति की अपनी ग्रलग ही परिभाषा दी है। परिगाम यह हुगा है कि इस शब्द के सही ग्रथं समभने में बड़ी कि िताई होती है, परन्तु मुद्रा-स्फीति शब्द बहुधा भय से सम्बन्धित होता है। एक निश्चित श्रवस्था पार कर लेने के पश्चात् मुद्रा-स्फीति देश की ग्रथंव्यवस्था को पूर्णत्या चौपट कर देती है। इस कारण ग्रावश्यकता इस बात की है कि इस शब्द के सही-सही ग्रथं समभ लिये जायें। इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों के विचार प्रस्तुत किये जाते हैं—

(१) क्राउथर ने लिखा है कि:—''सबसे सरल तथा सबसे उपयोगी परिभाषा यह लगती है कि स्फीति वह स्थिति है जिसमें रुपए का मूल्य गिरता रहता है, ग्रर्थात् पदार्थों के मूल्य बढ़ते रहते हैं।

परन्तु यह परिभाषा पूर्णतया सन्तोषजनक नहीं है। इसके अनुसार सामान्य कीमतों की प्रत्येक वृद्धि मुद्रा-स्फीति होती है और यदि स्फीति कोई भयानक चीज है तो कीमतों की प्रत्येक वृद्धि से डरना चाहिए, परन्तु यह ठीक नहीं है। कीमतों की प्रत्येक वृद्धि समाज के लिए कष्टदायक नहीं होती है। अवसाद के पश्चात् जब घीरे-धीरे उद्धार (Recovery) के अन्तर्गत कीमतों बढ़ती हैं तो वे लाभदायक ही होती हैं। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, कीमतों की प्रत्येक वृद्धि मुद्रा स्फीति नहीं होती। यह शब्द केवल एक विशेष प्रकार की कीमत वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है।

- (२) केमरर (Kemmerer) का विचार है:— "यदि मुद्रा की मात्रा प्रिधिक हो और वस्तुग्रों की मात्रा उत्पादन घटने के कारण कम हो जाय तो मुद्रा-स्फीति होती है।" इस परिभाषा के अनुसार कीमतों का बढ़ना प्रत्येक दशा में मुद्रा-स्फीति नहीं होती है, परन्तु यदि कीमतें इस कारण बढ़ गई हैं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ गई है और वस्तुग्रों की मात्रा घट गई है तो यह मुद्रा-स्फीति हो कहलायेगा। केमरर का विचार है कि यदि देश की जन-संख्या के बढ़ने के कारण या व्यापार के बढ़ जाने के कारण मुद्रा बढ़ाई जाती है तो यह मुद्रा स्फीति उत्पन्न नहीं करेगी, यद्यि इसके फलस्वरूप कीमतें बढ़ सकती हैं। मुद्रा-स्फीति केवल उसी दशा में होगी जबिक मुद्रा की मात्रा इतनी ग्रधिक बढ़ जाय कि वह व्यापार एवं उद्योगों की ग्रावश्यकता से ग्रधिक हो जाय और उसकी कयः शक्ति कम होने लगे, ग्रथवा जबिक मुद्रा की मात्रा तो यथास्थिर रहे, परन्तु उत्पादन किसी कारण इतना कम हो जाय कि कीमतें बढ़ जायें। दूसरे शब्दों में, यदि उत्पादन की तुलना में मुद्रा की मात्रा ग्रधिक होने के कारण कीमत बढती हैं तो यह मद्रा-स्फीति है।
  - 1. See G. Crowther : मुद्रा की रूप रेखा Hindi Edition, p. 138.
  - 2. See Kemmerer A.B.C. of Inflation, p. 46.

यह परिभाषा बहुत ग्रंश तक सन्तोषजनक है, क्योंकि इसमें मुद्रा-स्कीति के ग्राघारभूत कारण को स्पष्ट किया गया है। मुद्रा-स्कीति की ग्रवस्था तभी उत्पन्न होती है जबिक मुद्रा की निकासी ग्रावश्यकता में ग्राधिक मात्रा में हो जाती है, ग्रथवा उत्पादन इतना घट जाता है कि उसकी तुलना में मुद्रा की प्रस्तुत मात्रा ही ग्रावश्यकता से ग्राधिक हो जाती है। परन्तु इस परिभाषा का भारी दोष ग्रस्पष्टता है। ग्रावश्यकता से ग्राधिक मात्रा में मुद्रा के होने का कोई निश्चित ग्रर्थ नहीं होता है ग्रीर यदि होता भी है तो उसकी पहिचान क्या है? यदि कीमतों की वृद्धि को मुद्रा के ग्रावश्यकता से ग्राधिक होने का लक्षण मान लिया जाता है तो उस दशा में कीमतों की प्रत्येक वृद्धि मुद्रा-स्फीति को गूचित करेगी, परन्तु केमरर स्वयं इस विचार के विरुद्ध हैं।

कुछ लोगों का विचार है कि भ्रावश्यकता से श्रिष्ठिक मात्रा में मुद्रा के होने का यह श्रथं होता है कि मुद्रा की पूर्ति उसकी माँग से श्रिष्ठिक हो। निस्सन्देह उत्पादित वस्तुएँ, व्यापार भ्रौर उद्योग की स्थिति भ्रादि मुद्रा की माँग को सूचित करती हैं भ्रौर मुद्रा की पूर्ति विभिन्न रूपों में मुद्रा की मात्रा भ्रौर उसके प्रचलन वेग द्वारा सूचित होती है। यदि पूर्ति के माँग से श्रिष्ठिक हो जाने के कारण मुद्रा की क्रयः शक्ति घटती है भ्रौर कीमतें बढ़ती हैं तो यही मुद्रा-स्फीति होगी।

परन्तु मुद्रा-स्फीति की यह परिभाषा भी श्रसन्तोषजनक है। इस परिभाषा में दो किठनाइयाँ हैं:— प्रथम, मुद्रा की माँग श्रौर पूर्ति का ठीक-ठीक पता लगा लेना किठन होता है। किसी भी देश से सम्बन्धित व्यापार तथा उद्योग की श्रावश्यकता का प्रत्येक श्रनुमान श्रनिश्चित होता है। ठीक इसी प्रकार मुद्रा के प्रचलन-वेग का सही श्रनुमान न लगने के कारण भी मुद्रा की पूर्ति का ठीक-ठीक पता लगाना कठिन होता है। दूसरे, किसी भी वस्तु के मूल्य के परिवर्तन उसकी माँग श्रौर पूर्ति के तुलनात्मक पृश्चित्तेंनों के परिणाम होते हैं। कीमतों की वृद्धि केवल उसी दशा में होती है जबिक मुद्रा की माँग उसकी पूर्ति से कम होती है। ऐसी दशा में कीमतों की प्रत्यैक वृद्धि मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से श्रधिक होने के कारण उत्पन्न होगी।

(४) मुद्रा-स्फीति की सबसे ग्रच्छी परिभाषा पीगू ने की है। उनका विचार है कि — ''मुद्रा-स्फीति की ग्रवस्था तब होती है जबिक मौद्रिक ग्राय उत्पादन-क्रिया की तुलना में ग्रधिक तेजी से बढ़ रही हो।'' एक दूसरे स्थान पर पीगू ने फिर लिखा है:—''मुद्रा-स्फीति उस समय होती है, जबिक उत्पादक साधनों द्वारा किये गये काम की तुलना में, जिनको भुगतान के रूप में मौद्रिक ग्राय प्राप्त होती है, मौद्रिक ग्राय ग्राधिक तेजी के साथ बढ़ रही हो।'' इस परिभाषा के ग्रनुसार कीमतों की वृद्धि

<sup>1.</sup> Inflation exists when money income is expanding more than in proportion to income-earning activity. See Pigou: Types of War Inflation, Economic Journal, Dec. 1941, p. 439,

<sup>2.</sup> Inflation is taking place when money income is expanding relatively to the output of work by productive agents for which it is the payment. See Pigou: The Veil of Money, p. 14.

मुद्रा स्फीति का ग्रावश्यक लक्षरा है, परन्तु कीमतों की प्रत्येक वृद्धि मुद्रा-स्फीति नहीं होती है । यदि कीमतें इस कारएा बढ़ रही हैं कि समाज को प्राप्त होने वाली मौद्रिक श्राय उसके द्वारा किये जाने वाले उत्पादन की श्रपेक्षा श्रघिक तेजी के साथ बढ़ रही है तो यह मुद्रा-स्फीति होगी । कीमतों के बढ़ने की निम्न दशायें मुद्रा-स्फीति को दिखायंगी: - MV and I bethere is onighed Tal a greater reate

(१) जबिक मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं, परन्तु मौद्रिक

श्चाय उत्पादन की श्रपेक्षा श्रधिक तेजी के साथ बढ़ती है।
(२) जबकि मौद्रिक श्चाय बढ़ती है, परन्तु उत्पादन यथास्थिर रहता है।
(३) जबकि मौद्रिक श्चाय बढ़ती है, परन्तु उत्पादन घटता है।
(४) जबकि मौद्रिक श्चाय यथास्थिर रहती है, परन्तु उत्पादन घटता

जाता है। MV met both declar , had E de pealer - ale ( १५) जबिक मौद्रिक ग्राय तथा उत्पादन दोनों ही घटते हैं, परन्तु उत्पादन मौद्रिक ग्राय की ग्रपेक्षा ग्रधिक तेजी के साथ घटता है।

# मुद्रा स्कीति के रूप (Types of Inflation)-

कारएों तथा उद्देश्यों के श्राधार पर ग्रर्थशास्त्रियों ने मुद्रा-स्फीति के विभिन्न रूपों को ग्रलग-ग्रलग नाम दे दिए हैं।

- (१) मुद्रा स्फीति—कीन्ज के अनुसार एक साधारण प्रकार के सुद्रा-प्रसार को, जिसमें वस्तुत्र्यों की कीमतें बढ़ती हैं, 'वस्तु-स्फीति' (Commodity Inflation) कहा जा सकता है।
- (२) ब्ललन स्फीति—यदि स्फीति का कारए। यह है कि सङ्कट काल में वित्तीय ग्रावश्ये 📶 ग्रों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा त्र्यत्यधिक मात्रा में कागज के नोट छाप कर बकीमतों को बढ़ा दिया जाता है तो इसको 'चलन-स्पीति'  $(Currency\ Inflation)$  का नाम दिया जाता है। युद्धकालीन मुद्रा-स्कीति का साधारणतया यही रूप होता है।
- (३०) लाभ स्फीति—कीन्ज का विचार है कि अनेक बार ऐसा भी देखने में ग्राता है जबकि उत्पादन व्यय घटता है तो उसके फलस्वरूप कीमतों में नीचे गिरने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, परन्तु सरकार कृत्रिम उपायों से कीमतों की स्थिरता बनाये रखती है। ऐसी दशा में कीमतें बढ़ती तो नहीं हैं, परन्तु ये उन कीमतों की ग्रपेक्षा ऊँची रहती हैं जो कि उस दशा में रहतीं जबकि सरकार उनके गिरने पर किसी प्रकार का नियन्त्रण न लगाती। ऐसी ग्रवस्था को कीन्ज ने 'लाभ-स्फीति' (Profit Inflation) ना नाम दिया है। इस प्रकार की स्फीति में कीमतें पुराने कीमत-स्तर पर ही बनी रहती हैं।
  - (४) पूर्ण स्फीति ग्रौर (५) ग्राँशिक स्फीति—पीग्र ने पूर्ण-स्फीति (Full Inflation) तथा ग्रांशिक स्फीति (Partial Inflation) में भी भेद

ादया है। उनका विचार है कि साधारणतया कीमतों के बढ़ने के कारण उत्पादन की भी वृद्धि होती है और उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ उत्पत्ति के साधनों की वृत्ति का भी विस्तार होता है। इसके फलस्वरूप अन्त में ऐसी अवस्था आ सकती है कि पूर्ण वृत्ति स्थापित हो जाय, अर्थात् देश में उत्पत्ति के सभी साधनों को पूर्ण रूप में रोजगार मिल जाय। ऐसी अवस्था में यदि मौद्रिक आय के तेजी के साथ बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ती हैं तो इसे 'दूर्ण स्फीति' कहा जाता है, परन्तु पूर्ण वृत्ति के पूर्व भी मौद्रिक आय का विस्तार उत्पत्ति के विस्तार से अधिक तेजी के साथ हो सकता है। ऐसी दशा में कीमतों की वृद्धि 'आँशिक स्फीति' होती है।

- (६) घाटा प्रात्साहित स्फीति—ग्राधुनिक युग में मुद्रा-स्फीति उत्पन्न किये बिना युद्ध के लिए वित्तीय-व्यवस्था करना लगभग ग्रसम्भव होता है। यदि जनता करों तथा ऋगों के रूप में लड़ाई के खर्चों के लिए काफी रकम नहीं दे पाती है तो सरकार को नई मुद्रा का निर्माण करके बजट के घाटे को पूरा करने पर बाघ्य होना पड़ता है। इस प्रकार बजट के घाटे को पूरा करने के लिए जो मुद्रा-प्रसार किया जाता है उसे 'घाटा ग्रथवा होनार्थं प्रोत्साहित स्फीति' (Deficit-induced Inflation) कहा जाता है।
- (७) मजदूरी प्रोत्साहित स्फीति—इसी प्रकार यदि श्रम-संबों के जोर पर सेवायोजकों (Employers) को ग्रधिक मजदूरियाँ देने पर बाध्य होना पड़ता है, परन्तु उत्पत्ति की मात्रा न इड़ने के कारण कीमत बढ़ जाती है तो ऐसी दशा में 'मजदूरी प्रोत्साहित स्फीति' (Wage-induced Inflation) उत्पन्न होती है।
- (प) स्वतन्त्र मुद्रा-स्फीति कुछ लेखकों के अनुसार मुद्रा-स्फीति स्वतन्त्र अथवा निष्कंटक (Open) तथा शमन (Suppressed) भी हो सक्ती है। यदि ऊँची मौद्रिक आय और उसके व्यय पर किसी प्रकार के नियन्त्रण नहीं लगाये जाते और मुद्रा-स्फीति का निष्कंटक विकास होता है तो ऐसी अवस्था के 'स्वतन्त्र स्फीति' (Open Inflation) होती है।
- ( ६ ) शमन स्थिति—परन्तु यदि नियन्त्रण द्वारा जनता की ग्राय के स्वतन्त्र व्यय को रोक दिया जाता है, तो स्फीति का परिणाम कीमतों की वृद्धि के विपरीत उपभोग की कमी, नकदी की जोड़ तथा वें कों की जमा के बढ़ने के रूप में प्रकट होता है। ऐसी ग्रवस्था में शमन-स्फीति होती है।
- (१०) अत्यधिक स्फीति—स्वतन्त्र स्फीति के विकास पर यदि कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है तो यह प्रचण्ड रूप धारण कर सकती है और कीमतें बेहिसाब बढ़ने लगती हैं। मुद्रा की मात्रा में तिनक सी बुद्धि होते ही कीमतें कई गुनी बढ़ सकती हैं। एक-एक सप्ताह में कीमतों में १,०००% की वृद्धि होने के उदाहरण संसार में मिलते हैं। मुद्रा-स्फीति के इस रूप को 'अत्यधिक, अतिरिक्त अथवा सरपट दौड़ने वाली स्फीति' (Hyper, Super of Galloping Inflation) कहा जाता है।

## मुद्रा-स्फोति की तीन श्रवस्थाएँ—

मुद्रा-स्फीति को देश के आर्थिक जीवन का क्षय रोग (Tuberculosis) कहा गया है। आर्थिक विद्वानों का मत है कि मुद्रा-स्फीति के विकास की तीन अवस्थाएँ होती है: (i) अवस अवस्था में स्फीति का निवारण सम्भव होता है और उपयुक्त अपाय करके इसे पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है। (ii) क्षय रोग की भाँति दूसरी अवस्था में भी गम्भीर प्रयत्नों द्वारा इसका निवारण हो सकता है, यद्यपि सफलता एक ग्रंश तक सन्देहपूर्ण ही होती है। (iii) परन्तु तीसरी अवस्था में किसी भी प्रकार मुद्रा-प्रसार को नहीं रोका जा सकता है। उसका अन्तिम परिणाम यहीं होता है कि देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है।

### उदाहरण-

इन तीनों श्रवस्थाग्रों को एक उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सरलता के लिये हम यह मान लेते हैं कि कीमतों की वृद्धि का एक मात्र कारण सरकार द्वारा चलन की मात्रा की वृद्धि है। ऐसी दशा में जब तक कीमतों चलन की वृद्धि के श्रनुपात से कम तेजी के साथ बढ़ेंगी, मुद्रा-स्फीति श्रपनी पहली श्रवस्था में रहेगी, जब चलन की वृद्धि तथा कीमतों की वृद्धि की दर एक ही हो जायगी तो दूसरी श्रवस्था रहेगी श्रीर जब कीमतों चलन के विस्तार से भी श्रिष्टक तेजी के साथ बढ़ने लगेंगी ती स्फीति की तीसरी श्रथवा श्रन्तिम श्रवस्था ग्रारम्भ हो जायगी।

ग्रारम्भ में यह मान लीजिये कि चलन में १०% की वृद्धि की जाती है। इसके फलस्वरूप कीमतें भी कुछ समय परचात् लगभग इसी अनुपात में बढ़ जायेंगी, परन्तु कीमतों की वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन ग्रधिक लाभदायक हो जायगा ग्रौर उसका भी विस्तार होगा। हो सकता है कि उत्पादन में १०% ग्रथवा इससे भी ग्रधिक वृद्धि हो जाय, अतएव वस्तुओं की मात्रा के बढ़ जाने के कारएा कीमतें फिर गिर कर भ्रपने पुराने स्तर पर भ्रा जायेंगी। कुछ दशास्रों में वह पहिले से भी नीचे गिर सकती है। इस प्रकार कीमतों की वृद्धि ग्रस्थाई रहेगी, परन्तु यदि फिर उसी प्रकार चलन की मात्रा में १०% वृद्धि कर दी जाती है। तो कीमतें फिर बढ़ेंगी श्रीर उत्पत्ति का फिर विस्तार होगा । यदि यह कम बराबर बना रहता है तो कुछ समय पश्चात् वस्तुश्रों के उत्पादन का विस्तार चलन के विस्तार की अपेक्षा कम तेजी के साथ होने लगेगा। कारए। यह है कि उत्पादन के विस्तार के साथ-साथ उत्पत्ति के साधनों के रोजगार का भी विस्तार होता है ग्रीर कुछ समय पश्चात इन साधनों की दुर्लभता अनुभव होने लगती है। क्रमगत उत्पत्ति ह्यास नियम की कार्यशीलता के कारण उत्पत्ति की वृद्धि की गति धीमी पड़ जाती है। ऐसी दशा में उत्पादन की वृद्धि चलन-विस्तार की अपेक्षा कम होगी। पीगू के शब्दों में मौद्रिक श्राय, श्राय उत्पादन की क्रियाओं की अपेक्षा श्रधिक वेग से बढ़ने लगेगी । यहीं से मुदा-स्फीति का ग्रारम्भ हो जायगा, परन्तु क्योंकि श्रभी उत्पादन में वृद्धि सम्भव है। इसलिये कीमतें चलन विस्तार की श्रपेक्षा कम तेजी के साथ बढ़ेंगी। यह मुद्रा-स्फीति की पहली श्रवस्था है।

यदि चलन के विस्तार का क्रम ग्रंब भी बराबर बना रहता है। तो घीरें-घीरे ऐसी ग्रंबस्था ग्रा जायगी जबिक उत्पत्ति के सभी साधनों को पूर्ण वृत्ति प्राप्त हो जायगी। उत्पत्ति को ग्रीर ग्रंधिक बढ़ाने के लिये ग्रंब कोई भी साधन शेष नहीं रहेगा। यह पूर्ण वृत्ति (Full Employment) की ग्रंबस्था होगी। यहाँ पर साधनों के पूर्ण रूप में काम पर लगे रहने के कारगा उत्पादन का विस्तार रुक जायगा। वस्तुत्र्यों की मात्रा यथास्थिर रहने के कारगा कीमतों में उसी वेग त्र्यथा त्रानुपात में वृद्धि होने लगेगी, जिस त्रानुपात में चलन का विस्तार किया जाता है। यही मुद्रा स्मीति की दूसरी त्रवस्था है।

पूर्ण वृत्ति बिन्दू के पश्चात् भी यदि चलन के विस्तार का क्रम बना रहता है श्रौर थोड़े-थोड़े समय के बाद उसकी मात्रा में १०% वृद्धि होती रहेगी तो कुछ समय तक तो कीमतें चलन विचार के अनुपात में ही बढ़ती रहेंगी.परन्त कुछ समय बाद पत्र-मुद्रा की मात्रा इतनी बढ़ जायगी कि उस पर से जनता का विश्वास उठने लगेगा। जनता में भय की मनोवृत्ति उत्पन्न हो जायगी। यह मनोवृत्ति इतना प्रचएड रूप धारण कर लेगी कि कीमतों की वृद्धि की कोई सीमा ही न रहेगी। वे चलन-विस्तार की ग्रपेक्षा बहुत ग्रधिक तेजी से बढ़ने लगेंगी। चलन में १०% वृद्धि होने पर कीमतें २०, ३०, १०० भ्रथवा १,०००% के हिसाब से भी बढ़ सकती हैं। यहाँ पर चलन के विस्तार को बन्द कर देने पर भी कीमतों का बढना बराबर बना रह सकता है। यही मुद्रा स्कीति की ग्रन्तिम ग्रवस्था है, जिसके बहुत ही गम्भीर परिगाम होते हैं। सन् १६२३ में जर्मनी में ऐसी ही प्रचण्ड मुद्रा-स्फीति हुई थी, जिसके फलस्वरूप देश में मुद्रा-विनिमय के स्थान पर वस्तु-विनिमय का प्रचलन हो गया थां, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जर्मन सरकार द्वारा निकाले गये कागजी नोटों को लेने के लिये तैयार न था। इस प्रकार की मुद्रा स्कीति को अर्थशास्त्र में बड़े भयङ्कर शब्दों में वर्णित किया जाता है। यही दौड़ती हुई स्फीति (Runaway or Galloping Inflation) है। कुछ लेखकों ने तो इसे स्फीति का भयङ्कर राक्षस (The Hydra-headed Monster of Inflation) भी कहा है।

## मद्रा-स्फीति के कारण (The Causes of Inflation)-

मुद्रा-स्फीति दो प्रकार के कारणों से उत्पन्न होती है:—(१) मौद्रिक ग्राय के विस्तार के कारण ग्रीर (२) उत्पादन की कमी के कारण। ग्रब हमें यह देखना है कि मौद्रिक ग्राय का विस्तार किन बातों पर निभंर होता है ग्रीर किस प्रकार किया जाता है ग्रीर इसी प्रकार हमें यह भी देखना है कि कौन से कारण वस्तुग्रों की उत्पत्ति में कमी कर देते हैं ? देश में मुद्रा की मात्रा की वृद्धि, जिसके कारण कीमतें बढ़ने की सम्भावना पैदा हो जाती है, निम्न प्रकार होती हैं:—

## (१) मौद्रिक त्राय के विस्तार को प्रभावित करने वाली बातें—

- (i) सरकारी नीति के फलस्वरूप—बहुत बार सरकार जान-बूक्त कर चलन की मात्रा को बढ़ाकर तथा साख-विस्तार को प्रोत्साहन देकर कीमतों को बढ़ाती है । इसका उद्देश यह होता है कि मुद्रा की कथः शक्ति को कम करके ऋणी वर्ग के ऋँण भार को कम किया जाय, प्रथवा धनहीन ऋषक वर्ग के उन कष्टों को दूर किया जाय जो कीमतों के पतन के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके प्रतिरिक्त इस नीति के और भी बहुत से उद्देश्य होते हैं, जैसे—देश की विकास योजनाओं के लिए धन प्राप्त करना। इन उद्देश्यों से सरकार केवल चलन की मात्रा का ही विस्तार नहीं करती है, बिल्क बैंक दर को घटा कर तथा अन्य रीतियों से बैंक मुद्रा के विस्तार को भी प्रोत्साहन देती है। साख-मुद्रा के विस्तार का भी स्कीतिक प्रभाव होता है और इसे ग्राधिक भाषा में कभी-कभी साख-स्कीति (Credit Inflation) कहा जाता है। उपरोक्त सभी रीतियाँ ऐच्छिक ग्रथवा कृत्रिम स्कीति (Deliberate Inflation) को उत्पन्न करती हैं।
- (ii) हीनार्थ-प्रबन्धन (Deficit Financing)—बहुत बार सरकारें घाटे के बजट बनाती हैं। व्यय की मात्रा ग्राय से ग्रधिक रखी जाती है ग्रौर सरकार प्रतिभूतियाँ निकाल कर बैंकों से ऋण लेती है। इन प्रतिभूतियों के ग्राधार पर बैंक ग्रपने निक्षेपों को बढ़ाती हैं ग्रौर इस प्रकार साख-मुदा का विस्तार होने के कारण मुद्रा-प्रसार फैलता हैं। श्री ग्राधुनिक युग में सरकारों द्वारा ऐसा करने के ग्रनेक उदाहरण मिलते हैं। जब सरकार की साख इतनी कम होती है कि उसे खुले बाजार में ग्रावश्यक मात्रा में ऋण नहीं मिलते हैं, ग्रथवा जब सरकार ग्रौर ग्रधिक करारोपण द्वारा जनता को ग्रसन्तुष्ट करना नहीं चाहती है तो होनार्थ-प्रबन्धन द्वारा ग्राय प्राप्त की जाती है।
- (iii) प्राकृतिक कारण, जैसे स्वर्ण की मात्रा में वृद्धि—कभी-कभा प्राकृतिक कारणों द्वारा भी मुद्रा-स्फीति फैलती है। यदि किसी ऐसे देश में जहाँ स्वर्णं को चलन का ग्राधार बनाया गया है, ग्रकस्मात् ही किसी कारण से बहुत ग्रधिक मात्रा में स्वर्णं ग्रा जाता है तो उस देश में मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बहुमूल्य घातुग्रों का भारी ग्रायात भी मुद्रा-प्रसार का कारण वन सकता है।
- (iv) चलन तथा साख-मुद्रा के प्रचलन-वेग में वृद्धि वर्तमान काल में यह कारण बहुत महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। मुख्यतया साख-मुद्रा के प्रचलन वेग की वृद्धि के कारण मुद्रा की कुल मात्रा में काफी वृद्धि हो जाती है ग्रीर कीमतों में स्फीतिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। सम्पन्नता (वैभव) के काल में बैंकों के निक्षेपों की मात्रा श्रीर साख-मुद्रा का प्रचलन-वेग बढ़ने से स्फीति के विकास की श्रनुकूल दशायें उत्पन्न हो जाती है।

उत्पादन को कम करने वाली बातें-

साधारणतया उपरोक्त सभी कारण उत्पत्ति के विस्तार को भी प्रोत्साहित

करते हैं। कीमतों की वृद्धि साधारगतया ग्रिषक माँग तथा ग्रिषक बिकी का सूचक होती है। इसके ग्रितिस्त कच्चे माल की कीमतें तथा मजदूरियाँ भी तैयार माल की तुलना में नीची रहती हैं। ये सभी परिस्थितियाँ उत्पादक के लाभ को बढ़ाती हैं ग्रौर उत्पाद दन के विस्तार का कारग बनती हैं, परन्तु यह सम्भव है कि उत्पादन की वृद्धि मौद्रिक ग्राय के विस्तार की तुलना में कम रहे। ऐसी दशा में वस्तुग्रों श्रौर सेवाग्रों की एक तुलनात्मक कमी ग्रनुभव होने लगती है। ग्रनेक कारगों से उत्पत्ति की मात्रा घट भी सकती है, जो उस काल में भी सम्भव है जबिक मुद्रा की मात्रा यथास्थिर रहती है। उत्पादन की कमी के प्रमुख कारगा निम्न प्रकार हैं:—

- (i) कुछ उत्पत्ति के साधनों की दुर्लभता, जिसके कारण उत्पत्ति क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम के ग्रन्तर्गत होने लगती है।
- ( ii ) ऋौद्योगिक कगड़े, जिनके कारण काम बहुघा वन्द रहता है।
- (iii) प्राकृतिक स्त्रापत्तियाँ, जैसे-भूचाल, बाढ़, सूखा, महामारी इत्यादि ।
- (iv) शिल्प सम्बन्धी परिवर्तन (Technological changes), जो कुछ काल के लिए उत्पादन कार्यों को स्थगित करा देते हैं।
- ( v ) सरकार की व्यापार तथा प्रशुल्क नीति, जिसके अन्तर्गत विदेशों को इतना अधिक निर्यात कर दिया जाता है कि देश में वस्तुओं की कमी पैदा हो जाती है, अथवा जिसके अन्तर्गत आयातों पर नियन्त्रण लगा कर उसकी मात्रा सीमित रखी जाती है और देश में वस्तुओं का अभाव उत्पन्न हो जाता है।

### मद्रा-प्रसार के परिणाम (The Effects of Inflation)—

मुद्रा-प्रसार के प्रभाव श्राधिक जीवन के सभी श्रङ्कों पर पड़ते हैं, यद्यपि यह सत्य है कि श्रलग-अलग दिशाओं में इसके प्रभाव भी अलग-अलग होते हैं। समाज के कुछ वर्गों के लिए मुद्रा-स्फीति एक प्राकृतिक श्राशीर्वाद के रूप में श्राती है, परन्तु समाज के कुछ वर्गों को इसके कारए। श्रपार कष्ट होता है। साधारए। मुद्रा-स्फीति के परिएगाम इतने गम्भीर होते हैं कि लोग इसे दोषपूर्ण ही समफते हैं, परन्तु सभी दशाओं में मुद्रा-स्फीति हानिकारक नहीं होती। नियन्त्रित स्फीति के विषय में तो यह कहा जाता है कि इसकी सहायता से देश के श्राधिक जीवन के विकास तथा देश के भौतिक और मानव साधनों के पूर्ण उपयोग की योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है। श्राधुनिक श्रर्थशास्त्री कीमत-स्तर की धीरे-धीरे ऊपर उठती हुई प्रवृत्ति को बनाये रखना देश की मौद्रिक नीति का श्रावश्यक श्राधार समफते हैं।

श्राधिक विनियोजन तथा युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था के प्रबन्ध में तो मुद्रा स्फीति का महत्त्व सभी स्वीकार करते हैं। आर्थिक नियोजन द्वारा एक पिछुड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था को भी उन्नत बनाया जा सकता है और देश के बेकार पड़े हुए साधनों का उपयोग करके देश में उपभोग-स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है, परन्तु नियोजन को सफल बनाने के लिए सरकार को भारी मात्रा में पुँजी व्यय करना पड़ता है। साधारए साघनों, जैंसे— करारोपर्ग, लोक ऋग् स्नादि, द्वारा इस व्यय को पूरा करना किन होता है। इस कारण सरकार होनार्थ प्रवन्ध द्वारा स्रथवा कागज के नोट छाप कर इस व्यय को पूरा करने का प्रयत्न करती है। इससे मुद्रा-प्रसार तो स्रवश्य होता है, परन्तु यह इसलिए उचित होता है कि भविष्य में उत्पत्ति बढ़ने के कारण वर्तमान र्झाधिक कष्टों का पूर्ण रूप में बदला मिल जाता है। इसके स्रतिरिक्त मुद्रा-प्रसार के कारण देश के साधनों का पुर्नावतरण हो जाता है, जिससे र्झाधिक नियोजन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त साधन मिल जाते हैं। इसी प्रकार युद्धकालीन मुद्रा-प्रसार भी इस कारण उचित होता है कि इसके द्वारा सरकार रक्षा व्यय के लिए स्रावश्यक धन प्राप्त कर लेती है। मुद्रा-स्फीति के कारण जो कष्ट होता है वह देश की पराजय तथा दासता की तुलना में कुछ भी नही होता है। स्राधुनिक संसार का स्रनुभव यही है कि युद्ध की तैयारी तथा युद्ध के सफल संचालन के लिए मुद्रा-स्फीति स्नावश्यक ही है।

इस प्रकार मुद्रा-स्फीति के भी अपने लाभदायक उपयोग होते हैं, परन्तु जन-साधारण के दृष्टिकोण से मुद्रा-स्फीति अस्यन्त बुरी होती है। प्रो॰ वकील ने मुद्रा-स्फीति की तुलना एक डांकू से की है, जो वैसे तो सारे राष्ट्र को लूटता है, परन्तु अदृश्य रहता है। लोगों को साधारणतया यह पता भी नहीं चल पाता है कि उन्हें कौन लूट रहा है और किस प्रकार? "मुद्रा प्रसार की तुलना एक डांकू से की जा सकती है। दोनों ही कोई न कोई वस्तु छीनते हैं, लेकिन अन्तर यह है कि जबिक एक डांकू दृष्टिगत होता है, मुद्रा-प्रसार अदृष्ट्य रहता है; डांकू का शिकार एक ही समय पर एक या कई व्यक्ति होते हैं। लेकिन मुद्रा-प्रसार का शिकार समस्त जनता होती है; डांकू को न्यायालय में उपस्थित किया जा सकता है, लेकिन मुद्रा-प्रसार कानूनी होता है; उसे न्यायालय में इस प्रकार नहीं घसींटा जा सकता है।"\*

## समाज के विभिन्न वर्गों पर मुद्रा-स्फीति का प्रभाव—

मुद्रा-स्फीति के सामाजिक प्रभाव का ग्रध्ययन करने के लिए कीन्ज ने समाज को ५ वर्गों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं:—(I) विनियोगी वर्ग (The Investors), (II) उत्पादक वर्ग (The Producers), (III) श्रमिक वर्ग (The Wage-earners), (IV) उपभोक्ता वर्ग (The Consumers) ग्रोर (V) ऋग्गी वर्ग तथा साहूकार वर्ग (The Debtors and Creditors)। स्पष्ट तथा विस्तृत ग्रध्यैयन के लिए प्रत्येक वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव का ग्रध्ययन ग्रलगम्बलग किया जायगा। यह निश्चय है कि इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे से पूर्णतया ग्रलग नहीं किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति एक साथ विनियोगी, उत्पादक

Inflation may be compared to robbery. Both deprive the victim of some possession with the difference that the robber is visible, intfation is invisible; the robber's victim may be one or a few at a time, the victims of inflation are the whole nation, the robber may be dragged to a court of law, inflation is legal. See C. N. Vakil Financial Burden of War on India.

श्रमिक, उपभोक्ता तथा ऋगी और साहूकार सभी कुछ हो सकता है। यहाँ पर केवल यह देखने का प्रयत्न किया जायगा कि इन विभिन्न रूपों में समाज के सदस्यों पर मुद्रा-प्रसार का अलग-अलग प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? यह सम्भव है कि एक रूप में एक व्यक्ति को लाभ हो और दूसरे रूप में हानि।

- (I) विनियोगी वर्ग—विनियोगी वर्ग से हमारा ग्रिभिप्राय उन लोगों से होता है जो उद्योग ग्रोर व्यवसाय में रुपया लगाते हैं ग्रोर इस प्रकार लगाये हुए रुपए से ग्राय प्राप्त करते हैं। यही वर्ग साहसी का काम करता है ग्रीर उत्पत्ति सम्बन्धी जोखिम को उठाता है। इस वर्ग को दो भागों में बाँटा जा सकता है:—(१) वे विनियोगी जिन्हें निश्चित ग्राय प्राप्त होती है ग्रौर (२) वे विनियोगी जिनकी ग्राय परिवर्तनशील होती है।
  - (१) निश्चित आय वाले विनियोक्ता—प्रथम वर्ग के विनियोगियों का व्यवसाय के लाभ और हानि से कोई निकट सम्बन्ध नहीं होता है। चाहे व्यवसाय को अत्यधिक लाभ हो या हानि उन्हें तो पूर्व निश्चित राशि ही मिलती है। एक सम्मिलित पूँजी कम्पनी के ऋगा-पत्रधारी (Debenture Holders) इसी प्रकार के विनियोगी होते हैं। इन व्यक्तियों को कम्पनी को उधार दी गई राशि पर एक निश्चित दर पर ब्याज मिलती है। व्यवसाय की सम्पन्नता अथवा कठिनाई का ब्याज की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वर्ग को मुद्रा-स्फीति के काल में हानि होती है, क्योंकि इसकी आय तो स्थिर रहती है, परन्तु मुद्रा की अयः शक्ति कम हो जाने के कारण इस आय की वास्तविक कीमत घट जाती है। पहिले के बराबर आय से अब पहले से कम वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदी जा सकती हैं।
  - (२) परिवर्तनशील ग्राय वाले विनियोक्ता—परिवर्तनशील ग्राय वर्ग के विनियोगी वे लोग होते हैं जिनकी ग्राय निश्चित नहीं होती, वरन व्यवसाय के भाग्य पर निर्भर होती है। यदि व्यवसाय को र्जाधक लाभ होता है तो इस वर्ग को भी लगभग उसी अनुपात में बड़ी हुई ग्राय प्राप्त होती है। व्यवसाय को हानि होने की दशा में यह भी सम्भव होता है कि इस वर्ग को कुछ भी ग्राय प्राप्त न हो। मुद्रा-स्फीति का समय व्यवसायों के लिए सम्पन्नता का काल होता है। बिकी ग्रिधिक होती है, ग्रच्छी कीमतें मिलती है ग्रीर व्यापार तेजी के साथ होता है। लाभ का ग्रंश ग्रिधक ग्राय प्राप्त होती है। सम्मिलित पूँजी कम्मनी के साधारण ग्रंशवारी ऐसे ही विनियोगा होते है। इस प्रकार

इस वर्ग की मौद्रिक स्राय बढ़ती है, परन्तु क्योंकि कीमतें भी बढ़ जाती हैं, इसलिए वास्तविक स्राय उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती है। कुल मिलाकर इस वर्ग के विनियोगियों को लाभ ही होता है।

- (II) उत्पादक वर्ग—इस वर्ग में हम उन सभी व्यक्तियों को सिम्मिलत करते हैं जो उत्पादन के कार्यों में लगे रहते हैं। उद्योगपित, क़षक, खानों के मालिक, माहीगीर च्यादि सभी प्रकार के उत्पादक इसी वर्ग में सिम्मिलित किये जाते हैं। हमें यह देखना है कि मुद्रा-प्रसार का इस वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है ? मुद्रा-स्फीति में ऐसा होता है कि जनता के पास क्रयः शक्ति का विस्तार देश में उत्पादन की अपेक्षा अधिक तेजी से होता है। सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें निरन्तर ऊपर चढ़ती जाती हैं। सामान्य रूप में इस वर्ग के व्यक्तियों को मुद्रा-स्फीति के काल में लाम होता है। उत्पादक के लामों के निम्न तीन कारण होते हैं:—
- (१) कीमतों की वृद्धि साधारणतयां माँग की वृद्धि के कारण होती है। इसका ग्रर्थ यह होता है कि वस्तुग्रों ग्रीर सेवाग्रों की विक्री तेजी के साथ होती है। माल तैयार होते ही विक जाता है, जिसके फलस्वरूप एक ग्रोर तो श्रविक विक्री के कारण लाभ ग्रविक होता है ग्रीर दूसरे, तैयार माल को जमा करके रखने, उसकी लागत पर ब्याज देने तथा माल का विज्ञापन करने पर व्यय कम होता है, तीसरे, कोई मशीन तथा कारखाना वेकार नहीं रहता है।
- (२) कीमतों की तुलना में उत्पादन व्यय निम्न स्तर पर रहता है। कारण यह है कि उत्पादन में समय लगता है। यदि ग्राज कचा माल तथा ग्रौजार खरीदे जाते हैं। पूँजी उघार ली जाती है, ग्रथवा श्रमिकों को भर्ती किया जाता है तो दो-चार महीने पीछे तैयार माल निकल पाता है ग्रौर हो सकता है कि माल को बेच कर कीमत प्राप्त करने में ग्रौर भी ग्रधिक समय लगे। उपरोक्त सभी खर्चे, जो उत्पादन व्यय के ग्रंग होते हैं, वर्तमान कीमत-स्तर के श्रनुसार होंगे, परन्तु इस बीच में कीमतें बढ़ जाती हैं तो तैयार माल की बिक्री ऊँचे कीमत-स्तर के श्रनुसार ग्र्यांत् ऊँची कीमतों पर होगी। इससे उत्पादक के लिए लाभ का ग्रंग बढ़ जाता है।
- (२) मजदूरी में भी उत्पादक को बचत होती हैं। यह अर्थशास्त्र में एक साधारण सी बात है कि मजदूरियाँ कीमत-स्तर से पीछे ही रहती हैं। कीमतों के बढ़ने की दशा में मजदूरियों की दरें भी अवश्य बढ़ती हैं, परन्तु उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से कि कीमतें बढ़ती हैं। इस प्रकार मजदूरी का एक भाग भी उत्पादक के लाभों में सम्मिलित हो जाता है। जिन उद्योगों में मजदूरी उत्पादन-व्यय का एक वड़ा भाग होती है उन्हें तो विशेष रूप में लाभ होता है।

इस प्रकार मुद्रा-स्फीति के काल में उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन का विस्तार करके धौर ग्रधिक लाभ कमाने का प्रयत्न किया जाता है। व्यापारी वर्ग को भी उत्पादकों में ही सम्मिलित किया जा सकता है। इस वर्ग को

साधारणतया ग्रौर भी ग्रधिक लाभ होता है। रखे-रखे माल के दाम बढ़ते रहते हैं ग्रौर प्रत्येक वार माल को कम कीमत पर खरीद कर ग्रधिक कीमत पर बेच दिया जाता है। ग्राहकों को दूँढ़ने तथा ग्राकपित करने की ग्रावश्यकता भी कम पड़ती है।

(TII) श्रमिक वर्ग—इ। वर्ग में हम उन सब व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जो अपनी सेवाओं अथवा अपने श्रम को बेचकर आय प्राप्त करते हैं। इस वर्ग में कारखानों और कृषि में काम करने वाले मजदूर, वेतनभोगी व्यक्तियों तथा अन्य प्रकार के श्रमिकों को शामिल किया जाता है।

यदि कीमतें बढ़ती हैं तो हैएक दिशा में तो इस वर्ग को लाभ होता है, परन्तु दूसरी दिशा में हानि रहती है। बात यह है कि मुद्रा-स्फीति के काल में, उत्पत्ति, व्यापार तथा व्यवसाय का विस्तार होता है। इस सारे विस्तार के लिए प्रधिक श्रमिकों की ग्रावश्यकता पड़ती है, जिससे रोजगार की वृद्धि होती है। श्रम की माँग प्रधिक होने के कारण श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति भी वढ़ जातो है श्रीर वे कार्य की ग्रधिक ग्रच्छी दशाएँ प्राप्त कर लेते हैं। रोजगार के विस्तार के कारण श्रमिक वर्ग सुखी रहता है, परिवार के ग्रधिक सदस्यों को रोजगार मिल जाने के कारण श्राय में वृद्धि हो जाती है, परन्तु दूसरी दिशा में श्रमिक वर्ग को हानि होती है। मजदूरियों तथा वेतनों की यह सामान्य प्रकृति है कि वे कीमत-स्तर से बहुत पीछे रहती है। मुद्रा-स्प्रीति के काल में मजदूरियों त्योर वेतन बढ़ते तो हैं, परन्तु कीमतों की त्रप्रेष्ता कम तेजी के साथ बढ़ते हं, इसिलए श्रमिक की वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है। बढ़ी हुई मजदूरी भी पहले की ग्रपेक्षा कम वस्तुएँ ग्रीर सेवाएँ खरीद सकती है, जिससे श्रमिकों का जीवन-स्तर नीचे गिर जाता है। उन्हें विशेष किताई ग्रनुभव होती है ग्रौर वे संगठन करके ग्रधिक मजदूरियों, मँहगाई के भत्तों तथा जीवन निर्वाह व्यय के भत्तों की माँग करते हैं।

यह काल श्रम संघों के संगठन श्रीर विकास का काल होता है। सामूहिक रूप में श्रमिक ग्रधिक मजदूरियों की माँग करते हैं। श्रम संघों की सदस्यता बढ़ती है श्रीर श्रमिकों का संगठन हढ़ होता है। यह काल हड़तालों का भी काल होता है, जिसके कारण श्रीद्योगिक श्रशान्ति फैलती है। श्रमिक वर्ग यह जान लेता है कि इस समय उत्पादन को बन्द करना उत्पादक के हित में नहीं है, इसलिए वह हड़ताल की धमकी श्रथवा हड़ताल करने पर श्रमिकों की कुछ न कुछ माँगों को अवश्य पूरा करेगा। इसी काल में श्रीद्योगिक शान्ति स्थापित करने की नई-नई रीतियों श्रीर नये-नये उपायों का श्राविष्कार किया जाता है श्रीर श्रमिकों को सन्तुष्ट रखने के विशेष प्रयत्न किये जाते हैं।

(IV) उपभोक्ता वर्ग—समाज के सभी सदस्य उपभोक्ता होते हैं। चाहे हम ब्याज पर रुपया देकर ग्राय प्राप्त करें, कोई उद्योग ग्रथवा व्यवसाय चलायें ग्रथवा मजदूरी करें, ग्रपनी ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति के लिए हमें उपभोग ग्रवश्य करना

पड़ता है। उपभोक्तात्रों के दृष्टिकोण से मुद्रा-स्फीति का काल विशेष रूप में कप्टदायक होता हैं। उपभोक्ताग्रों की ग्राय की तुलना में कीमतें बराबर बढ़ती जाती हैं। जीवन की नितान्त ग्रावश्यक वस्तुग्रों की कीमतें सबसे ग्रधिक बढ़ती हैं। वस्तुए ग्रीर सेवाए दुर्लभ हो जाती हैं ग्रीर उपभोक्ताग्रों को उपभोग की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। इस कारण उपभोक्ताग्रों में भारी ग्रसन्तोष फैलता है। उन्हें कुछ ग्रावश्यकताग्रों की सन्तुष्टि तो पूर्णतया स्थिगत करनी पड़ती है ग्रीर कुछ को केवल ग्रांशिक रूप में ही पूरा करने पर वाध्य होना पड़ता है। उपभोक्ताग्रों की ग्रीर से सहकारी सिमितियाँ स्थापित करने तथा कीमतों पर नियन्त्रण रखने की माँग की जाती है। दूसरे महायुद्ध के काल तथा युद्धोत्तर काल में उपभोक्ताग्रों के कष्टों से सभी परिचित हैं।

(V) ऋग्गी तथा साहूकार वर्ग—इस वर्ग में उधार लेने और देने वाले व्यक्तियों को सिम्मिलित किया जाता है। ग्राधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति ऋगों ग्रथवा साहूकार है और कभी-कभी तो वह दोनों एक ही साथ होता है। ऋगों के सम्बन्ध में बहुधा ऐसा होता है कि ऋगा एक निश्चित काल के लिए दिया जाता है भीर देते समय उसके व्याज की दर निश्चित कर ली जाती है। इसके पश्चात कीमतों की घटा-बढ़ी का इस पहिले से तय की हुई व्याज की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(१) मुद्रा-स्फीति के काल में ऋगी वर्ग को लाभ होता है। कारण यह है कि उसे एक पूर्व निश्चित मात्रा में मूलधन तथा ब्याज चुकाना होता है। कीमतों के बढ़ जाने के कारण भुगतान की इस राशि की वास्तविक कीमत कम रह जाती है। इस प्रकार ऋण का वास्तविक भार बहुत कम रह जाता है, परन्तु इस काल में साहु-कार वर्ग को हानि होती है। मूलधन तथा ब्याज के रूप में इस वर्ग को जो राशि प्राप्त होती है उसकी वास्तविक कीमत उस समय की अपेक्षा बहुत कम रह जाती है जबिक ऋगा दिया गया था प्रमुदा-स्फीति के काल में उत्पत्ति के बढ़ने के कारण ऋगों की माँग अधिक होती है और ब्याज की दरें ऊपर चढ़ती हैं। इस काल में बेंकों द्वारा अधिक सख का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग का विकास भी होता है। बैंकों के नकद कोषों और उनकी निक्षेपों का पारस्परिक अनुपात कम हो जाता है।

एक दूसरे दृष्टिकोण से मुद्रा-स्कीति के काल में साहूकार वर्ग को लाम होता है और ऋणी वर्ग को हानि होती है। बढ़ती हुई कीमतों के काल में बहुधा उत्पादन का विस्तार किया जाता है। इसके लिए ग्रधिक ऋणों की ग्रावश्यकता पड़ती है। इसके ग्रातिरक्त ऐसे समय में व्यापार भी ग्रधिक तेजी के साथ होने लगता है। इससे भी ग्रह्मकालीन ऋणों की माँग बढ़ जाती है। दोनों ही कारणों से ऋणों की माँग बढ़ जाती है, जिससे एक श्रोर तो ब्याज की दर बढ़ जाती है श्रोर दूसरी श्रोर साहूकार के पास धन बेकार नहीं पड़ा रहता है। यह स्थित साहूकार के लिए

निसन्देह लाभपूर्ण रहेगी। इसके विपरीत ऋगी को हानि होगी, क्योंकि एक ऋार तो ऋगों की माँग बढ़ जाने के कारण ऋग मिलने में कठिनाई होगी ऋोरै दूसरी ऋोर ब्याज की दरें ऊँची उठ जायेंगी।

स्मरण रहे कि मुद्रा-स्कीति के उपरोक्त सभी परिणाम मुद्रा-स्कीति की पहली और दूसरी अवस्थाओं से सम्बन्धित हैं। अन्तिम अवस्था में तो उसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। जर्मनी में सन् १६२३ में विनिमय व्यवस्था पूर्णतया वस्तु विनिमय आधार पर आ गई थी। नोटों के बदले में कुछ भी प्राप्त कर लेना सम्भव न था। अत्यिक मुद्रा-प्रसार सरकार पर से जनता का विश्वास उठा देता है। बहुत बार यह सामाजिक और राजनैतिक क्रान्ति को जन्म देता है। चीन की कॉमिटाँग सरकार की पराजय का कारण साम्यवादी फोजों की शक्ति के अतिरिक्त वह भीषण मुद्रा-स्कीति भी थी जो उसके राज्य-काल में चीन भर में फैल गई थी।

#### मुद्रा-स्फीति के अन्य आर्थिक प्रभाव-

समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले उक्त प्रभावों के ग्रतिरक्त मुद्रा-प्रसार के निम्न ग्राधिक प्रभाव भी उल्लेखनीय हैं:—

- (१) करों में बृद्धि—मुद्रा प्रसार के दिनों में नये कर बहुत लगाये जाते हैं ग्रौर पुराने करों में वृद्धि हो जाती है।
- (२) ऋगों में वृद्धि—व्यापारी वर्ग तो श्रिषकाधिक ऋग लेकर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करता ही है, साथ ही सरकार भी श्रिषक ऋग लेती है, जिससे उसके बजट में घाटे की पूर्ति हो सके।
- (३) बैंकिंग ग्रौर बीमा—नये-नये बैंक व बीमा कम्पिनयों की स्थापना होने लगती है ग्रौर पुरानी निष्प्राण संस्थायें भी गतिशील हो उठती हैं।
- (४) नियमित आर्थिक प्रगाली—सरकार स्वतन्त्र श्राध्यक प्रगाली का परित्याग करके नियन्त्रित आर्थिक प्रगाली की नीति अपनाती है, जो देश का आर्थिक विकास करने में सहायक होती है और लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठता है। राश-निंग, मूल्य नियन्त्रग्ण आदि नियन्त्रित आर्थिक प्रगाली के ही अङ्ग हैं।
- (५) रक्षा-व्यय में सुविधा—युद्ध काल में मुद्रा-प्रसार के द्वारा सरकार देश की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यय करने में समर्थ हो जाती है, यद्यपि नागरिकों को थोड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन देश की स्वतन्त्रता के सामने उसकी कोई गिनती नहीं है।
- (६) ग्रायात उत्साहित ग्रौर निर्यात हतोत्साहित होते हैं, जिससे निदेशी निनमय दर बढ जाती है ग्रौर व्यापार-सन्तुलन देश के प्रतिकूल रहता है।
- (७) बचत की भावना को ठेस—मुद्रा-प्रसार होने पर मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। ग्रतः लोगों ने जो बचत की है उसका मूल्य भी (क्रय शक्ति कम हो जाने से. कम हो जाता है, जिससे लोगों में बचत की भावना कुंठित हो जाती है।

- (८) करदाताश्रों को लाभ होता है, क्योंकि मुद्रा-प्रसार के दिनों में उन्हें कर के रूप में कुछ श्रधिक रुपया देना पड़ता है, लेकिन वास्तव में वस्तुश्रों के रूप में वे श्रपेक्षत: कम भुगतान करते हैं।
- ( ६ ) धन का वितर्ग मुद्रा-प्रसार एक ऐसा अन्धा इन्जन है जो एक का धन लूटकर दूसरे को और दूसरे का धन लूट कर तीसरे को देता है। जिन्होंने परिश्रम से कमाया है और जिन्होंने बिना परिश्रम के कमाया है वे सब ही लूटे जाते हैं। यह कुछ लोगों को फायदा और कुछ को नुकसान पहुँचाता है।
- (१०) समाज का नैतिक पतन मुद्रा-प्रसार के दिनों में श्रिधिक से श्रिष्ठक लाभ कमाने के प्रयत्न में ज्यापारी चोरबाजारी, मिलाबट, मनाफाखोरी जैसे धनैतिक कमें करने लगते हैं तथा यह रोग सरकारी कर्मचारियों में भी फैल जाता है। वे भी रिश्वत लेकर व्यापारियों को ध्रमैतिक कर्मों की छूट दे देते हैं।

#### सारांश-

उपरोक्त विवेचना से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मुद्रा-प्रसार ऋनेक ऋार्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं नैतिक वुराइयों की जड़ है ऋौर ऋन्त में सारे राष्ट्र को भयंकर हानि सहनी पड़ती है।

### मुद्रा-संकुचन श्रथवा मुद्रा विस्फीति (Deflation)

# मुद्रा संकुचन का अर्थ (Meaning of Daflation)—

मुद्रा-संकुचन मुद्रा-स्फिति की विपरीत प्रवृत्ति है। वैसे तो बहुत से लोग कीमतों के प्रत्येक पतन को मुद्रा-संकुचन का नाम दे देते हैं, परन्तु जिस प्रकार कीमतों की प्रत्येक वृद्धि स्फीतिक नहीं होती है ठीक उसी प्रकार कीमतों का प्रत्येक पतन विस्फीतिक भी नहीं होता है। कुछ लोगों का विचार है कि यदि मुद्रा की पूर्ति ग्रथवा उसकी मात्रा, मुद्रा की माँग ग्रथांत् उसकी व्यापार, व्यवसाय ग्रथवा ग्रन्य विनिमय कार्यों सम्बन्धी ग्रावश्यकता से, कम होती है तो मुद्रा की क्रयः शक्ति बढ़ जाती है तथा वस्तुमों भौर सेवाग्रों की सामान्य कीमतें गिरती हैं, यही विस्फीति हैं जैसा कि हम मुद्रा-स्फीति के सम्बन्ध में देख चुके हैं कि मुद्रा की माँग ग्रौर पूर्ति का कोई निश्चत ग्रतुमान सम्भव नहीं होता है, इसलिए मुद्रा-विस्फीति के सम्बन्ध में यह दिव्दकीए। सन्तोषजनक नहीं है। मुद्रा-संकुचन की भी सबसे उपयुक्त परिभाषा पीगू ने ही की है। उनके ग्रनुसार मुद्रा-विस्फीति कीमतों के गिरने की वह स्थिति है, जो उस समय उत्पन्न होती है, जबकि वस्तुग्रों ग्रौर सेवाग्रों का उत्पादन मौद्रिक ग्राय की ग्रपेक्षा ग्रिष्क तेजी से बढ़ता है। इस प्रकार कीमतों का प्रत्येक पतन मुद्रा-संकुचन नहीं होता है। उसकी केवल एक विशेष दशा ही मुद्रा-स्फीति को सूचित करती है। निम्न दशाओं में कीमतों का गिरना विस्फीतिक होता है

- (१) यदि मौद्रिक ग्राय घटती है, परन्तु उत्पादन यथास्थिर रहता है।
- (२) यदि मौद्रिक स्राय तथा उत्पादन दोनों घटते हैं, परन्तु मौद्रिक स्राय स्रपेक्षतन स्रधिक तेजी से घटती है।
- (३) यदि उत्पादन बढ़ता है, परन्तु मौद्रिक ग्राय यथास्थिर रहती है।
- (४) यदि उत्पादन तथा मौद्रिक म्राय दोनों बढ़ते हैं, परन्तु उत्पादन म्रिविक तेजी से बढ़ता है।
- ( प्र ) यदि उत्पादन बढ़ता है और मौद्रिक आय घटती है।

#### मुद्रा-संकुचन के कारण-

मुद्रा-संकुचन प्रचलित चलन तथा साख-मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक कमी करके किया जाता है। कभी-कभी जब मुद्रा-स्फीति के कारण कीमतें बहुत ऊँची हो जाती हैं तो सरकार उन्हें कम करने के लिए मुद्रा-संकुचन की नीति अपनाती है, परन्तु प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार है कि संकुचन का कम भी एक बार आरम्भ होकर फिर रुकता नहीं है और कीमतें नीचे ही गिरती जाती हैं। मुद्रा-संकुचन साधारणतया निम्न प्रकार होता है:—

- (१) भारी करारोप्गा—सरकार भारी करारोप्ण द्वारा या बलात् ऋगों (Forced Loans) द्वारा देश में मुद्रा की प्रचलित मात्रा घटा देती है।
- (२) सुद्रा की मात्रा में कमी—सरकार देश में प्रचलित अपरिवर्तनशील नोटों तथा प्रादिष्ट-सुद्रा को रद्द करके देश में सुद्रा की मात्रा में कमी कर सकती है।
- (३) वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि—प्रचलित मुद्रा की मात्रा यथास्थिर रहते हुए यदि ग्रकस्मात् ही वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है तो कीमतें गिर सकती हैं।
- (४) बैंक दर में बृद्धि—केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक दर को ऊँचा उठाकर भी मुद्रा-संकुचन कर सकती है। इस नीति का परिग्णाम यह होता है कि अन्य बैंकों को ऋगा मिलने में कठिनाई होती है और अधिक ब्योज देना पड़ता है, जिसके कारण वे साख के उत्पादन को घटा देती हैं।
- (५) केन्द्रीय बैंक की अन्य नीतियाँ—केन्द्रीय बैंक और भी कई रीतियों से मुद्रा-संकुचन कर सकती है, जैसे—जनता से प्रत्यक्ष रूप में ऋण लेकर अथवा अपनी खुले बाजार कियाओं (Open Market Operations) द्वारा। इसी प्रकार केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेच कर भी जनता से चलन को अपने पास खींच लेती है। इसके अतिरिक्त बहुत बार सरकार साख निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा देती है। मुद्रा-संकुचन के परिणाम (Effects of Deflation)—

विस्कीति कीमत-स्तर को नीचे गिराती है। स्फीति के विपरीत यह देश के जीवन को अवनित की ओर ले जाती है। विस्कीति के काल में कीमतें, मजदूरियां, उत्पादन, ब्याज की दरें तथा रोजगार सभी नीचे की ओर जाते हैं। देश में अति-

उत्पादन दृष्टिगोचर होने लगता है। व्यवसायिक भविष्य निराशाजनक होता है श्रीर समाज के लगभग सभी वर्गों को भारी कष्ट होता है।

मुद्रा-स्फीति की भाँति विस्फीति का भी समाज के विभिन्न वर्गों पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव निम्न प्रकार होंगे:—

- (I) विनियोगी वर्ग—इस वर्ग के उस भाग को लाभ होगा जिसकी आय निश्चित होती हैं, क्योंकि कीमतें घट जाने के कारण इस आय की वास्तविक कीमत दढ़ जाती है। परिवर्तनशील आय वर्ग के विनियोगियों की आय घटती हैं। कारण यह है कि विस्फित के काल में बहुत से उद्योग और व्यवसाय बन्द हो जाते हैं और शेष को साधारणत्या हानि होती है। भूमिपतियों और जमींदारों को लाभ होता है, क्योंकि ये लोग निश्चित आय वर्ग के होते हैं।
- (II) उत्पादक वर्ग-इस वर्ग को सामान्य रूप में हानि हे ती है। (i) कारएा यह है कि कीमतें गिरना मांग के गिरने का सूचक होता है, इस कारएा विस्फीति के काल में बिकी कम होती है। कारखानेदारों, व्यापारियों ग्रौर दूकानदारों के पास बिना विके माल के स्टॉक जमा हो जाते हैं। मन्दी इतनी हो जाती है कि माल को बेचने में भारी कठिनाई होती है। (ii) दूसरे, कीमतों की तुलना में उत्पादन व्यय ऋधिक रहता है, जिससे हानि की सम्भावना ग्रीर बढ़ जाती है। माल के तैयार होने से पहले ही कचा माल खरीदा जाता है, मजदूर रखे जाते हैं, ग्रीजार तथा ग्रन्य सामान खरीदे जाते हैं, रुपया ब्याज पर लिया जाता है और फैक्टरी का लगान तय किया जाता है, परन्तु यदि माल तैयार होने के काल तक कीमर्ते गिर जाती हैं तो उपरोक्त सभी वस्तुएँ उस कीमत-स्तर की तुलना में महिगी रहती हैं जिस पर माल को बेचा जाता है। इस प्रकार माल को बेचकर उत्पादन व्यय को पूरा करना भी कठिन हो जाता है। (iii) तीसरे. विस्फीति के काल में मजदूरियाँ घटती तो ऋवश्य हैं, परन्तु कीमत-स्तर की तुलना में कम तजी के साथ घटती हैं । परिएाम यह होता है कि मजदूरियों ार प्रस्तुत कीमत-स्तर की तुलना में ग्रधिक व्यय होता है। इन सब बातों के फलस्व-ह्म उत्पादकों को हानि होती है ग्रीर वे उत्पादन को बन्द करना ग्रथवा उत्पत्ति की मात्रा को घटाना ग्रारम्भ कर देते हैं।

कृषकों को इस काल में और भी अधिक हानि होती हैं। साधारण अनुभव बताता है कि विस्फीति के काल में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कृषि-उगज की कीमतें अधिक नीचे गिर जाती हैं। किसानों को लगान के रूप में तो एक पूर्व निश्चित राशि देनी पड़ती हैं, परन्तु कीमतों के गिर जाने और मुद्रो की क्रयः शक्ति वढ़ जाने के कारण इस राशि का वास्तविक भार बढ़ जाता है। इस प्रकार ऋण का भार और भी बढ़ जाता है।

व्यापारी वर्ग को भी भारी हानि होती है। एक ग्रोर तो माल की बिक्री नहीं होने श्राती है, जिससे घाय घटती है। दूसरे, मुद्रा या रुपये का फेर न बँबने के

कारण पूँजी की कमी अनुभव होती है और तीसरे, रखे हुए माल की कीमत गिरतीं जाती है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन तथा ग्राहकों की सन्तुष्टि के लिये भी विशेष प्रयत्न करना पड़ता है।

(III) श्रमिक वर्ग—इस वर्ग को विस्फीति के काल में भारी कष्ट होता है, यद्यपि एक दिशा में इस वर्ग को लाभ भी होता है। विस्फीति के काल में उत्पादन घटाया जाता है, ब्हुत से उद्योग और व्यवसाय बन्द हो जाते हैं और व्यापारी लोग माल का क्रय-विक्रय वम करते हैं। इन सभी कारणों से बेरोजगारी फैलती है। श्रमिकों को काम नहीं मिलता है और उनके मूखों मरने की नौबत आ जाती है। श्रमिक वर्ग में भारी निराशा फैलती है। इस काल में हड़तालों के स्थान पर ताला-बन्दी का जोर होता है। श्रत्येक श्रमिक ग्रपने काम पर जमा रहना चाहता है। श्रम-सङ्घों की सदस्यता कम हो जाती है और उनका कार्य तो बहुत ही संकुचित हो जाता है।

इसके विपरीत उन श्रमिकों को लाभ होता है जिनका कि रोजगार बना रहता है। कारण यह है कि यद्यपि इस काल में मजदूरियाँ घटती हैं, परन्तु वे कीमतों की तुलना में ऊँची रहती हैं और इस प्रकार वास्तविक मजदूरी ऊँची हो जाती है। वेतनभोगी वर्ग (Salaried classes) को विशेष रूप से लाभ होता है, क्योंकि वेतनों के घटने की सम्भावना कम होती है, परन्तु कीमतों के घट जाने के कारण इन वेतनों की क्यः शक्ति बढ़ जाती है। उन श्रमिकों को हानि होती है जिन्हें वस्तुग्रों के रूप में मजदूरी मिलती है, जैसे—कृषि उद्योग के श्रमिक।

(IV) उपभोक्ता वर्ग—विस्कीति का काल उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण् से आनन्द का काल होता है। सभी वस्तुओं और सेवाओं की प्रचुरता दृष्टिगोचर होती है। वास्तिविकता यह है कि वस्तुओं के खरीदने वाले ही नहीं मिलते हैं। कीमतों के गिरने के कारण उपभोग के स्तर को ऊँचा करना सरल हो जाता है। जो आवश्य-कताएँ लम्बे काल से पूरी नहीं हो रही थीं वे भी अब सरलतापूर्वंक पूरी हो जाती हैं। सभी ओर हर्ष और सन्तोष का संचार होता है।

( V ) ऋगी तथा साहूकार—विस्मीति के काल में ऋगी वर्ग को हानि होती है, क्योंकि मूलधन तथा ब्याज के रूप में इस वर्ग को जो रकम लौटानी पड़ती है उसका वास्तविक मूलय इस कारण बढ़ जाता है कि मुद्रा की क्यः शक्ति बढ़ जाती है। परिगाम यह होता है कि ऋगों का भार लगभग असहनीय हो जाता है। कृषक वर्ग पर तो इस काल में और भी ऋग लद जाता है। पिछले ऋगों को चुकाना तो लगभग असम्भव हो जाता है। परन्तु एक दूसरे दृष्टिकोण से इस वर्ग को लाभ भी होता है। इस काल में माँग घट जाने के कारण ऋग सरलता से मिल जाते हैं और उन पर ब्याज की दर भी घट जाती है।

साह्कारों को इस काल में लाभ होता है। बात यह है कि मुद्रा की क्रयः शक्ति बढ़ जाने के कारण ब्याज तथा मूलधन के रूप में मिलने वाली राशि की वास्ट विक कीमत बढ़ जाती है, परन्तु एक दूसरे रूप में इस वर्ग को थोड़ी सी हानि भी होती है, क्योंकि व्यापार तथा उत्पादन के संकुचन के कारएा ऋएों की मांग काफी घट जाती है और ब्याज की दरें नीचे गिर जाती हैं।

### मुद्रा संकुचन के ग्रन्य प्रभाव—

डक्त वर्गीय प्रभावों के श्रतिरिक्त मुद्रा-संकुचन के निम्न श्रन्य प्रभाव भी होते हैं:—

- (१) करों के भार में वृद्धि—विस्फीति के काल में करदाताग्रों को हानि होती है। यद्यपि रुपयों में उन्हें श्रपेक्षतः कम कर देना पड़ता है, तथापि वस्तुग्रों के रूप में उनका कर-भार बढ़ जाता है।
- (२) ऋराों में वृद्धि मुद्रा की क्रयः शक्ति बढ़ जाने से सरकार पर ऋरा का भार बढ़ जाता है। उसकी ग्राधिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। घाटे को पूरा करने तथा बेकारी की रोकथाम करने के लिये भी उसे ऋरा लेने पड़ते हैं।
- (३) ब्रैंकिंग का पतन—विस्फीति काल में दुर्वल बैंक श्रौर बीमा कम्पनियाँ टूटने लगती हैं।
- (४) ग्रायात हतोत्साहित व निर्यात प्रोत्साहित होता है—क्चोंकि देशे में मूल्य-स्तर गिर जाता है। इससे देश का व्यापार-सन्तुलन श्रनुकूल हो जाता है।
- (५) नैतिक दुष्परिगाम—विस्फीति के काल में कल-कारखाने बन्द होने लगते हैं, मजदूरों की छँटनी की जाती है, श्रम वर्ग व कल-स्वामी में भगड़े प्रारम्भ हो जाते हैं। बेरोजगारी के कारण देश में श्रशान्ति रहती है व व्यापारी निराश होने लगते हैं।

#### सारांश—

र्श्रतः सुद्रा-स्फोति समाज के लिये हानिकारक श्रधिक है, लाभ-प्रद कम । कुछ विद्वानों को मत है कि सुद्रा-प्रसार की तुलना में सुद्रा-संकुचन श्रधिक हानि-कारक है। वास्तव में दोनों की श्रपेत्ता मूल्य स्थिरता की दशा संबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके कारणा श्रर्थ-व्यवस्था में सन्तुलन बना रहता है।

### मुद्रा-स्कीति श्रेष्ठ है या मुद्रा-संकुचन ? (Which is better—Inflation or Deflation)—

उपरोक्त अध्ययन में मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-विस्फीति के उन प्रभावों का अध्ययन किया है जो समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ते हैं। हमने देखा है कि स्फीति के काल में उत्पादकों, कुछ प्रकार के विनियोगियों, ऋगा-दाताग्रों तथा कुछ दिशाश्रों में श्रमिकों को लाभ होता है। इसके विपरीत श्रधिकांश विनियोगियों, श्रमिकों, उपभोक्ताश्रों और साहूकारों को हानि होती है। विस्फीति के काल में निश्चित ग्राय वर्ग के विनियोगियों, उपभोक्ताग्रों तथा साहूकारों को लाभ होता है, परन्तु ग्रन्य विनियोगियों

उत्पादकों, श्रमिकों ग्रीर ऋ एवाताभों को हानि होती है। विस्फीति के काल में उप-भोक्ताग्रों को ग्रानन्द मिलता है, परन्तु व्यवसाय बन्द हो जाते हैं ग्रीर बेकारी फैलती है। स्फीति के काल में उत्पादक ग्रीर व्यापारी चैन से रहते हैं तो उपभोक्ताग्रों को घोर कष्ट होता है ग्रीर ग्रीद्योगिक ग्रज्ञान्ति फैलती है।

दीनों ही ग्राधिक ग्रीर सामाजिक दृष्टिकीण से घातक होते हैं। लार्ड कीन्ज ने लिखा है:—''मुद्रा-स्फीति ग्रन्यायपूर्ण है ग्रीर मुद्रा-संकुचन ग्रनावश्यक ग्रथवा ग्रनुप-युक्त है।'' शो० सेलिगमैन ना भी ऐसा ही मत है, उनके ग्रनुसर—''चढ़ती ग्रीर गिरती हुई कीमतों के कारण देश के ग्राधिक ढाँच में एक ऐसी ग्रस्थिरता ग्रा जाती है जिससे कृषि, व्यापार तथा उद्योग की स्थिति डाँवाडोल हो जाती है ग्रीर समाज में विभिन्न वर्गों को ग्रलग-ग्रलग ग्रनुपात में लाभ ग्रीर हानि होती है। उँची तथा नीची कीमतों के कारण इतना नुकसान नहीं होता जितना कि कीमतों के बराबर चढ़ते-उतरते रहने के कारण होता है भें' कीमतों में निरन्तर होने वाले उच्चावचन देश के ग्राधिक जीवन में ग्रनिश्चितता ग्रीर ग्रस्थिरता पैदा कर देते हैं, जिसके कारण उन्नति के मार्ग में भारी ग्राधाएँ उपस्थित होती हैं। इनके कारण विदेशी व्यापार का ग्राधार समुचित तथा स्थाई नहीं हो पाता है ग्रीर राज्य को देश की ग्राधिक तथा सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए भारी प्रयत्न करने पड़ते हैं।

मुद्रा-स्फीति श्रन्यायपूर्ण है ?— मुद्रा-स्फीति को श्रन्थायपूर्ण इस कारण कहा जाता है कि यह प्रकृति में एक प्रकार का श्रदृश्य करारोपण होती है । सरकार कागज के नोट छाप कर ग्रथवा

एक प्रकार की श्रष्टश्य करारापण हाती है। सरकार कागज के नाट छाप कर श्रथवा घाटे के बजट बनाकर स्फीति उत्पन्न करती है श्रीर इस प्रकार वस्तुश्रों को जनता के उपभोग से छीनकर सरकारी कार्यों में उपयोग करती है। यही कारण है कि प्रो॰ वकील ने इसे श्रहश्य डकैती कहा है। राजस्व के सिद्धान्तों के श्राधार पर भी यह श्रन्यायपूर्ण इसलिए होती है कि इस ग्रहश्य करारोपण का बोभ उन्हीं कन्धों पर सबसे श्रधिक पड़ता है जो उसे उठाने के लिए सबसे कम बलवान होते हैं। कीमतों की वृद्धि के कारण गरीब लोग ही श्रधिक पिसते हैं, क्योंकि सबसे श्रधिक वृद्धि जीवन-निर्वाह सम्बन्धी वस्तुश्रों की ही कीमत में होती है।

एक दूसरे दृष्टिकोण से भी मुद्रा-स्फीति श्रान्यायपूर्ण है। इसके द्वारा कृतिम सम्पन्नता उत्पन्न की जाती है, जो थोड़े ही काल तक बनी रहती है। घीरे-घीरे श्रीम-वृद्धि का काल श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच कर टूट जाता है। कीमतों के निरन्तर बढ़ते रहने का परिणाम श्रन्त में यही होता है कि श्रिभवृद्धि समाप्त हो जाती है। कीमतों तेजी के साथ गिरने लगती हैं श्रीर मुद्रा-संकुचन के सभी दुष्परिणाम उपस्थित हो जाते हैं।
मुद्रा-संकुचन श्रनुपयुक्त हैं!—

. सुद्रा<u>-</u>संकुचन को ऋनुपयुक्त इसलिए कहा गया है कि इसके द्वारा किसी भी

<sup>&</sup>quot;Inflation is unjust and deflation is inexpedient.

स्थाई लाभ की आशा नहीं की जा सकती है। मुद्रा-स्फीति का उपयोग तो देश के आर्थिक जीवन का उत्थान करने, युद्धकालीन अर्थ-ज्यवस्था को चालू रखने अथवा पूर्ण वृत्ति की अवस्थाएँ उत्पन्न करने के लिए भी किया, जा सकता है, परन्तु मुद्रा-संकुचन एक प्रतिगामी किया है। उससे लाभ के स्थान पर हानि की सम्भावना ही अधिक रहती है। देश में बेरोजगारी का फैलना, उत्पादन तथा ज्यापार का घटना और आर्थिक जीवन का पतन की और जाना, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है। मुद्रा-मंकुचन की नीति अधिक से अधिक मुद्रा-प्रसार का अन्त करने के लिए ही उपयुक्त हो सकती है, परन्तु कठिनाई यह है कि विस्फीति का क्रम एक बार आरम्भ होकर रकता नहीं है और देश के आर्थिक ढाँचे को खोखला कर डालता है। कीन्ज ने ठीक ही कहा है कि वैसे तो मुद्रा-प्रसार और सन्तुक्तन दोनों ही चुरे हैं, परन्तु दोनों में संकुचन अधिक हानिकारक है और विना नितान्त आवश्यकता के सरकार को इसे अपनी नीति का आधार नहीं वनाना चाहिए।

### मुद्रा-संस्फीति (Reflation)

### मुद्रा संस्फीति का अर्थ -

मुद्रा-स्फीति से ही मिलता-जुलता एक ग्रौर शब्द मुद्रा-संस्फीति भी है। कोल के शब्दों में:—''जब ग्रवसाद के प्रभाव को दूर करने के लिए जान बुभ कर मुद्रा-प्रसार किया जाता है तो उसे हम मुद्रा-संस्फीति कहते हैं।'' मुद्रा संस्फीति एक छोटे पैमाने की नियन्त्रित मुद्रा-स्फीति ही होती है। जब कभी मुद्रा-संकुचन इतना ग्रिष्क हो जाता है कि कीमतें बहुत ही नीचे गिर जाती हैं तो ग्राधिक जीवन की रक्षा के लिए सरकार कोई ऐसी नीति ग्रवनाती है जिससे घीरे-घीरे कीमतों को फिर से ऊपर उठाया जा सके, यही संस्फीति है। यह उद्धार-काल (Period of Recovery) में होती है ग्रौर इसके द्वारा कीमतों को फिर सामान्य-स्तर पर लाया जाता है।

### मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-संस्फीति का भेद-

मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-संस्फीति दोनों ही स्वभाव में एक सी ही होती हैं। कीमतों की वृद्धि दोनों का ही लक्ष्मण होता है ग्रौर दोनों में मुद्रा की मात्रा का विस्तार होता है, परन्तु दोनों के बीच निम्न प्रकार भेद हैं:—

- भ्रे ) मुद्रा-स्फीति प्राकृतिक हो सकती है अथवा ऐच्छिक, परन्तु मुद्रा-संस्फीति सदा ही ऐच्छिक अथवा कृत्रिम होती है।
  - (२) मुद्रा-संस्फीति उद्धारकाल में होती है भ्रीर उसका उद्देश्य कीमत को

<sup>&</sup>quot;Reflation may be defined as inflation deliberately undertaken to relieve a depression." See G. D. H. Cole: What Everybody Wants to Know About Money.

सामान्य-स्तर पर लाना होता है। यह उसी समय तक रहती है जब तक कीमतें सामान्य-स्तर पर नहीं ब्रा जाती हैं। इसके विपरीत मुद्रा-स्फीति का ब्रारम्भ ही तब होता है जबिक कीमतें सामान्य कीमत-स्तर से ऊपर उठ जाती हैं।

- (३) मुद्रा-स्फीति के परिगाम घातक हो सकते हैं, परन्तु मुद्रा संस्फीति का चहेश्य देश को मन्दी की खाई से निकाल कर पुनर्जीवन प्रदान करना होता है। मुद्रा-संस्फीति निर्मागात्मक होती है, परन्तु स्फीति विनाश-कारी हो सकती है।
- (४) मुद्रा-संस्फीति में कीमतें घीरे-घीरे ही बढ़ती हैं, परन्तु मुद्रा-प्रसार में वे बहुत तेजी के साथ बढ़ सकती हैं।

एक लेखक ने कहा है कि बेकार पड़ी हुई पूँजी और वृत्तिहीन श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से जो मुद्रा-प्रसार किया जाता है उसे हम मुद्रा-संस्फीति कहते हैं, परन्तु यदि इस उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात् भी मुद्रा-प्रसार होता है तो उसे मुद्रा-स्फीति कहा जायेगा।

### मुद्रा-श्रपस्फीति (Disinflation)

#### मुद्रा-ग्रस्कीति का ग्रर्थ-

इस शब्द का उपयोग अर्थशास्त्र में थोड़े ही काल से आरम्भ हुआ है, परन्तु युद्ध-काल तथा युद्धोत्तर-काल में यह शब्द बड़ा लोकप्रिय था। आरम्भ में तो इस शब्द का उपयोग बड़े अस्पष्ट तथा विभिन्न अर्थों में किया जाता था, परन्तु घीरे-घीरे इसके उपयोग में स्पष्टता आ गई है। मुद्रा-अपस्फीति मुद्रा-स्फीति को दूर करने की नीति होती है। जब किसी देश में मुद्रा-स्फीति प्रचण्ड रूप धारण करने लगती है तो सरकार उसकी प्रचण्डता को कम करने तथा उसके दोषों को दूर करने के लिए जो नीति अपनाती है वही मुद्रा-अपस्फीति की नीति होती है। इस प्रकार इस शब्द द्वारा वे सभी कियायों, नीतियाँ तथा उपाय सूचित होते हैं जो स्फीति के वेग को रोकने के लिए किये जाते हैं। इन उपायों की आवश्यकंता इसलिए पड़ती है कि एक निश्चित सीमा के परे मुद्रा-स्फीति विशेष दुखदायी हो जाती है।

### मुद्रा अपस्कीति और मुद्रा संकुचन में भेद-

परन्तु यह समभाना भूल होगी कि मुद्रा-म्रपस्फीति तथा मुद्रा-संकुचन एक ही चीज के दो अलग-अलग नाम हैं। वास्तव में दोनों में लगभग वैसा ही अन्तर होता है जैसा कि मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-संफीति के बीच होता है। कुछ दिशाओं में तो मुद्रा-भ्रपस्फीति तथा विस्फीति समान अवस्य होती हैं, क्चोंकि दोनों का उद्देय कीमतों को

नीचे गिराना होता है ग्रौर दोनों के कारण लगभग एक से ही होते हैं, परन्तु वास्तव में दोनों में भेद होता है ।

- (1) मुद्रा-विस्फीति बहुत बार विना सरकार की इच्छा के ही होती है, परन्तु अपस्फीति सदा ही कृत्रिम होती है।
- (ii) इसके अतिरिक्त अपस्फीति कीमतों को कम करने का उपाय है और इसके अन्तर्गत कीमतें घटा कर सामान्य कीमत-स्तर तक लाई जाती है। मुद्रा-संकुचन में कीमतें सामान्य-स्तर से काफी नीचे तक जा सकती हैं।
- (iii) मुद्रा-संकुचन मन्दी की दशाएँ उत्पन्न करता है, परन्तु मुद्रा अपस्फीति केवल आर्थिक जीवन की श्रसाधारणता को दूर करती है।

#### **QUESTIONS**

- मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा संकुचन में क्या घ्यन्तर है, स्पष्ट कीजिए। देश की आर्थिक उन्नित के लिए किन परिस्थितियों में मुद्रा-प्रसार लाभदायक हो सकता है, सममाइये। (Agra, B. A., 1958)
- 2. इन्य के मूल्य में परिवर्तनों का उत्पादन और वितरण पर गम्भीर प्रभाव पढ़ता है और ये परिवर्तन अधिक सामाजिक महत्त्व रखते हैं। न्याख्या कीजिए। (Agra, B, A., 1957)
- 3 ''मुद्रा एक श्रन्छा सेवक है, परन्तु बुरा स्वामी है।'' व्याख्या कींजिए।
   (Sagar, B. A., 1957)
- 4. मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने का क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है, इसकी विवेचना कीजिए और बताइये कि यदि इन परिवर्तनों को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता तो कम किस प्रकार किया जा सकता है।

(Sagar, B. Com., 1954, 1957)

 ''मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्ग है और मुद्रा-संकोच अनुपयुक्त है। इन दोनों में आपस में मुद्रा-संकोच सबसे बुरा है।'' इस उक्ति का विवेचन कीजिए।

(Sagar, B. Com., 1958)

- 6. मुद्रा-स्फीति (Inflation) की परिभाषा कीजिए छोर बतलाइये कि इसके आर्थिक परिसाम क्या हैं ? (Jabalpur, B. A., 1958)
- 7. मुद्रा स्फीति की परिभाषा दीजिए। इसके श्रार्थिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। (Alld., B. A., 1956)
- 8. "Inflation is unjust and deflation is inexpedient. Of the two perhaps deflation is worse." Elucidate.

(Raj., B. Com., 1955, 1957)

What is Inflation? How does inflation effect the mill-9. owners, cultivators and labourers. How can the evil effects (Raj., B. A, 1954) of inflation be reduced?

10.

करिये।

- Distinguish clearly between-Inflation and Deflation. (Raj., B. A., 1956; Agra, B. A., 1956)
- Explain inflation, deflation, disinflation and reflation. Exa-11. mine the effects of inflation and deflation on production and (Raj, B. Com., 1954) employment.
- What are the effects of Inflation? How can inflation be 12. (Bihar, B. A., 1958) controlled?
  - What is inflation? Analyse the effects of war-time inflation
  - (Alld., B. A, 1954) on Indian agriculture.
- 13. 'Deficit-financing leads to inflation.' Discuss. How can 14. (Patna, B. A., 1957) you control inflation? Discuss the economic effects of 'Inflation' and 'Deflation' 15. of currency. (Raj., B. A., 1957) Discuss the causes of inflation in our country during and 16.
  - after the Second World War and indicate the measures adopted by the State in controlling it. (Agra, B. Com., 1959) अपने देश में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय और उसके पश्चात मुद्रा स्फीति के कारणों का विवेचन करिये। राज्य द्वारा किये गये उसके नियन्त्रण के उपायों का संज्ञिप्त वर्णान

#### अध्याय १०

# मौद्रिक नीतियाँ

(Monetary Policies)

## मुद्रा-प्रसार को रोकने की रीतियाँ

मुद्रा-प्रसार के सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रध्ययन यही है कि उसे कैंसे दूर किया जाय । जैसा कि विदित है कि मुद्रा की मात्रा का विस्तार तथा उत्पादन का घटना यही मुद्रा-प्रसार के दो प्रमुख कारण होते हैं, ग्रतः मुद्रा-प्रसार को रोकने के उपाय भी दो प्रकार के होते हैं  $\mathbf{i}$ — $(\mathbf{I})$  वे उपाय जिनके द्वारा मुद्रा के विस्तार को रोका जाता है ग्रौर  $(\mathbf{II})$  वे उपाय जिनके द्वारा उत्पत्ति की मात्रा को बढ़ाया जाता है । एक तीसरे प्रकार के उपाय ऐसे हो सकते है कि जिनके द्वारा बिना मुद्रा की मात्रा को घटाये तथा बिना उत्पत्ति को बढ़ाए कीमतों को बढ़ने से रोक दिया जाता है ।

#### (I) मुद्रा की मात्रा को कम करने के उपाय--

मुद्रा की मात्रा को कम करने के उपाय निम्न प्रकार हैं :---

- (१) देश में किसी विशेष प्रकार की मुद्रा को रह कर दिया जाय, अथग नई मुद्रा चालू कर दी जाय और पुराने चलन को नये चलन की कम मात्रा में परिवर्तनशील रखा जाय। युद्ध के उपरान्त यह रीति रूस ने अपनाई थी।
- (२) वेतनों, मजदूरियों, बैंकों में जमा की हुई राशि स्त्रादि में स्त्रिनिवार्य तथा बलात् कमी करना । यह एक बड़ा सप्रभाविक परन्तु क्रान्तिकारी उपाय है।
- (३) नए-नए करों द्वारा जनता से क्रयः शक्ति को वापिस लेना ।
- (४) सरकार द्वारा जनता से ऋगा लेना ।
- (५) सरकार द्वारा सोना, प्रतिभूतियाँ तथा अन्य स्वीकृत वस्तुयें बेचना और प्राप्त राशि की कीमत की मुद्रा को प्रचलन से निकाल देना।
- (६) कम्पनियों के लाभाँश बाँटने पर प्रतिबन्ध लगाना।
- (७) चलन की निकासी को बन्द करना और सन्तुलित बजटों (Balanced Budgets) को तैयार करना।
- ( 5 ) बैंकों की साख-निर्माण शक्ति को कम करना, जिसके लिए बैंक दर का ऊँचा उठाना, केन्द्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार व्यवसाय करना, वैद्यानिक नियन्त्रण ग्रादि उपाय किए जाते हैं।

#### (II) उत्पादन की बढ़ाने के उपाय-

देश में वस्तुम्रों ग्रीर सेवाम्रों की मात्रा बढ़ाने के उयाय निम्न प्रकार हैं :---

- (१) स्त्रायातों को प्रोत्साहन देना स्त्रीर निर्यातों को कम करना, जिससे कि देश के भीतर वस्तुम्रों भीर सेवाम्रों की मात्रा बढ़ जाय।
- (२) देश के भीतर कृषि तथा उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देना, जिसके लिए ग्राधिक सहायता, करों में छूट, कच्चे मालों, कारीगरों तथा मशीनों की ब्यवस्था ग्रादि ग्रनेक उपाय हो सकते हैं।
- (३) सरकार द्वारा स्वयं उत्पादन आरम्भ करना, जिसके लिए सरकारी खेती करना तथा सरकारी उद्योगों का खोलना भ्रावश्यक होता है।

#### (III) श्रन्य उपाय---

इनके अतिरिक्त कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए कीमतों पर श्रंकुश (Control) लगा दिये जाते हैं, उपज के ृनियन्त्रित वितरणा की व्यवस्था की जाती है, सरकारी दुकानें खोली जाती हैं। रार्शानग व्यवस्था लागू की जाती है, व्यवसायों के लाभ की सीमा निश्चित कर दी जाती है और चोर बाजारी को रोकने के लिए कड़े नियम बनाये जाते हैं।

### मुद्रा-संकुचन को दूर करने के उपाय

मुद्रा-संकुचन देश में क्रयःशक्ति ग्रथवा मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाने से पैदा होता है, परन्तु कभी-कभी ग्रित-उत्पादन के कारएा भी कीमतें गिरती हैं। संकुचन को दूर करने के उपाय साधारणतया मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने से सम्बन्धित होते हैं। यद्यपि बहुत बार वस्तुच्यों च्योर सेवाच्यों के उत्पादन को भी कम किया जाता है। प्रमुख उपाय निम्न प्रकार हैं:--

- (१) सरकारी व्यय को बढ़ाया जाता है। केन्द्रीय और स्थानीय सरकारें राष्ट्रीय विकास की योजनाएँ बनाकर अधिक रोजगार उत्पन्न करने तथा जनता के हाथ में अधिक क्यःशक्ति पहुँचाने का प्रयत्न करती हैं। महान् अवसाद के पश्चात् न्यू डील (New Deal) नीति के अनुसार अमरीका में जंगलों और दलदलों को साफ करने, सड़कें बनाने, सिचाई की व्यवस्था करने आदि के बहुत से कार्य किये गये थे, जिनसे राष्ट्रीय जीवन के उद्धार और कीमतों के ऊपर उठाने में काफी सहायता मिली थी।
- (२) केन्द्रीय बैंक साख विस्तार नीति को अपनाती है। इसके लिए बैंक दर को कम किया जाता है, जिससे कि अन्य बैंकों को सस्ते ब्याज पर ऋगा मिल सकें। प्रतिभूतियों को जनता से खरीदा जाता है, ताकि जनता के हाथ में अधिक क्रयः शक्ति पहुँच जाय और उधार देने के सम्बन्ध में अधिक उदार नीति अपनाई जाती है।
  - (३) स्त्रायातों को रोका जाता है और निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाता मु॰च॰भ्र॰ (१३)

है, जिससे कि माल की बिक्री होने के कारएा कारखाने फिर से चालू होने लगें ग्रीर व्यापार तथा यातायात सेवाग्रों को भी प्रोत्साहन मिले ।

- (४) करों तथा भूमि के लगान में छूट दी जाती है ब्रौर पिछले ऋगों का भुगतान किया जाता है।
- (५) कभी-कभी कीमतों को ऊपर उठाने के लिये पहिलों से उत्पन्न की हुई वस्तु ह्यों को नष्ट कर दिया जाता है।
- (६) उद्योगों को काम चालू रखने के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि उनकी हानि पूरी हो सके।
- (७) पुराने ऋरुणों का भुगतान करके भी मन्दी की दशास्रों को दूर किया जाता है।

### मूल्य-वृद्धि, मूल्य-हास तथा श्रवमूल्यन

मुद्रा क भूल्य के सम्बन्ध में इन तीनों शब्दों का भी उपयोग किया जाता है :- (१) मूल्य वृद्धि (Appreciation); (२) मूल्य हास (Depreciation) ग्रीर (३) ग्रवमूल्यन (Devaluation)।

- (१) मूल्य-वृद्धि का ग्रभिप्राय— मूल्य-वृद्धि का श्रभिप्राय यह होता है कि मुद्रा का मूल्य श्रथवा उसकी कयः शिक्ष बढ़ जाय । ऐसी दशा में मुद्रा की प्रत्येक इकाई के बदले में पहिले से अधिक मात्रा में वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त होंगी। दूसरे शब्दों में, मुद्रा की मूल्य-वृद्धि के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घट जायेंगी। व्यवहार तथा परिणाम में मुद्रा संकुचन तथा मूल्य-वृद्धि में कोई भी श्रन्तर नहीं होता है। दोनों में कीमतें घटती हैं ग्रौर दोनों के उत्पन्न होने के कारण भी एक से ही होते हैं। मूल्य-वृद्धि ग्रपने ग्राप उत्पन्न हो सकती है, जैसे—ग्रवसाद के काल में ग्रथवा यह सरकारी नीति के फलस्वरूप भी उत्पन्न हो सकती है।
- पूल्य-ह्रास का अभिप्राय— मूल्य-ह्रास, मूल्य-वृद्धि के बिल्कुल विपरीत होता है। मुद्रा के मूल्य अथवा उसकी कयःशक्ति के घटने और परिणामस्वरूप सामान्य कीमतों के बढ़ने को मूल्य-ह्रास कहा जाता है। यदि मुद्रा की प्रत्येक इकाई के बदले में पहले की अपेक्षा कम वस्तुयें और सेवाएँ प्राप्त होती हैं तो ऐसी दशा में हम कहते हैं कि मुद्रा का मूल्य-ह्रास हो गया है। मुद्रा-स्प्रीति के काल में सदा ही मुद्रा का मूल्य-ह्रास भी हो जाता है। मूल्य-ह्रास तथा मुद्रा-स्प्रीति दोनों में लगभग कुछ भी अन्तर नहीं होता है। दोनों में एक सी दशाएँ उत्पन्न होती हैं और दोनों को उत्पन्न करने तथा दूर करने के लिये एक जैसे ही उपाय किये जाते हैं। दोनों ही या तो प्राकृतिक हो सकते हैं और या सरकारी नीति का परिणाम हो सकते हैं। अन्तर केवल इतना है कि मुद्रा स्प्रीति एक कारण अथवा नीति होती हैं और मूल्य-ह्रास उसका परिणाम होता है।
  - (३) मुद्रा अवसूल्यन का अर्थ-- नुद्रा अवसूल्यन का अर्थ थोड़ा भिन्न होता

है। मूल्य-वृद्ध तथा मूल्य-ह्रास दाना का ही सम्बन्ध देश की ग्रान्तरिक कीमतों से होता है। इन दोनों में ही देश की चलन की कीमत में परिवर्तन होते हैं, परन्तु चलन की वास्तव में दो कीमतों होती हैं—ग्रान्तरिक कीमत (Internal Value) तथा बाह्य कीमत (External Value)। चलन की ग्रान्तरिक कीमत वस्तुग्रों ग्रीर सेवाग्रों में नापी जाती है ग्रीर वह देश के ग्रान्तरिक कीमत-स्तर द्वारा सूचित की जाती है। बाह्य कीमत चलन की एक निश्चित इकाई के बदले में प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्राग्रों की मात्रा में नापी जाती है ग्रीर वह विदेशी विनिमय दर द्वारा सूचित की जाती है। श्रव-मूल्यन का श्राश्य देश के चलन की बाह्य कीमत को कम करने से होता है। अवमूल्यन की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं-यह देश की मुद्रा की बाह्य कीमत को कम करने की एक विचारयुक्त नीति है। यह स्त्रावश्यक नहीं है कि स्त्रवमूल्यन के साथ-साथ चलन की स्त्रान्तरिक कीमत भी कम की जाय, यद्यपि कभी-कभी स्त्रवमूल्यन तथा मूल्य-हास दोनों एक ही साथ किये जाते हैं।

### अवमूल्यन के उद्देश्य-

अवमूल्यन के उद्देश्य कई प्रकार के हो सकते हैं:-

- (i) भूल सुधार—यदि किसी देश ने भूल ग्रथवा ग्रन्य किसी कारण से देश की मुद्रा को ग्रावश्यकता से ग्रधिक वाह्य कीमत देरखी है तो इसके फलस्वरूप ग्रायात बढ़ जायेंगे ग्रौर निर्यातों में कमी हो जायगी। ऐसी दशा में ग्रवमूल्यन द्वारा इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है।
- (ii) शोधनाशेष का ग्रसन्तुलन—ग्रवमूल्यन का उद्देश्य बहुवा शोधनाशेष (Balance of Payments) के ग्रसन्तुलन को दूर करना होता है। यदि कोई देश ऐसा ग्रनुभन करता है कि उसका विदेशी व्यापार सम्बन्धी घाटा बराबर बना रहता है श्रीर वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी ऋणों, स्वर्ण ग्रायात ग्रथवा ग्रन्य उपायों द्वारा उसे दूर करना सम्भव नहीं है तो वह ग्रवमूल्यन द्वारा देश की विदेशी विनिमय दर को घटाकर इस घाटे को दूर कर सकता है। ग्रवमूल्यन का परिणाम यह होता है कि विदेशों में ग्रवमूल्यन करने वाले देश के माल की कीमतें घट जाती हैं श्रीर देश के भीतर विदेशी माल की कीमतें बढ़ जाती हैं। इससे निर्यात प्रोत्साहित होते हैं श्रीर ग्रायातों की मात्रा घटती है। इस प्रकार शोधनाशेष का सन्तुलन फिर से स्थापित हो जाता है।
- (iii) उद्योग संरक्षरा कुछ देशों में धवमूल्यन का उपयोग उद्योग-संरक्षरा (Protection) के लिए भी किया जाता है।
- (iv) ऋगा-भार की कमी—अवमूल्यन का उपयोग विदेशों को दिये हुये ऋगों के भार को कम करने के लिये भी किया जा सकता है, परन्तु ऐसा करने से स्वयं अवमूल्यन करने वाले देश को हानि होती है।

### मुद्रा-हास तथा मुद्रा-अवमूल्यन—

परिशाम के दृष्टिकोश से मुद्रा-ह्रास तथा मुद्रा-श्रवमूल्यन म काइ ावशष ग्रन्तर नहीं होता है, परन्तु दोनों की कार्य-विधि ग्रलग-ग्रलग होती है। मूल्य-ह्रास में देश की मुद्रा की ज्ञान्तरिक कीमत में कभी की जाती है, परन्तु ज्ञवमूल्यन में उसकी बाह्य कीमत में। इसमें तो सन्देह नहीं है कि मुद्रा की ग्रान्तरिक कीमत को कम कर देने से कुछ समय परचात उसकी बाह्य कीमत भी कम हो जाती है, परन्तु मूल्य-ह्रास का उद्देश्य ऐसा करना नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार ग्रवमूल्यन के वारण मुद्रा की ग्रान्तरिक कीमत भी घट सकती है, क्योंकि इसका परिशाम देश में वस्तुशों की कमी उत्पन्न करना तथा उनकी कीमतों को बढ़ाना होता है। इससे देश की मुद्रा की ग्रान्तरिक कीमत भी कम हो जाती है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक दशा में मुद्रा की ज्ञान्तरिक ज्ञोर बाह्य दोनों ही कीमतें एक ही साथ घटती हैं, परन्तु ह्रास तथा ज्ञवमूल्यन ज्ञलग-ज्ञलग रीतियों से इस कार्य को सम्पन्न करते हैं।

## भारत में मुद्रा अवमूल्यन

स्मरण रहे कि अवमूल्यन का सदा ही यह अर्थ नहीं होता है कि देश की मुद्रा की कीमत सभी विदेशी मुद्राओं में घटा दी जाय । ऐसा साधारणतया बहुत ही कम किया जाता है। अक्सर देश की मुद्रा की बाह्य कीमत साधारणतया एक या कुछ विदेशी मुद्राओं में घटा दी जाती है। अवमूल्यन का एक अच्छा उदाहरण भारतीय रुपये के अवमूल्यन से मिलता है। सितम्बर सन् १६४६ में इज़्लेंड ने स्टिलिज़ का अवमूल्यन किया था, जिसके द्वारा डालर में पींड की कीमत ३०.५% घटा दी गई थी। स्टिलिज़ का अवमूल्यन होते ही स्टिलिज़ क्षेत्र के सभी देशों ने अपनी-अपनी मुद्राओं का डालर में अवमूल्यन किया था। कनाडा ने १०% और भारत, लङ्का और बर्मा ने ३०.५% के अनुपात में अपनी मुद्रा की कीमतें घटाई थीं। स्टिलिज़ क्षेत्र में केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश था, जिसने अवमूल्यन नहीं किया था। आगे चल कर सन् १६५५ में पाकिस्तान ने भी अपने रुपये का अवमूल्यन कर दिया था।

# अवमूल्यन क्यों किया गया ?—

भ्रवमूल्यन के पश्चात् भारतीय रुपये की कीमत ३० सेन्ट (Cents) से घटकर २१ सेन्ट रह गई। स्टिलिङ्ग के अवमूल्यन के पश्चात् भारत सरकार के सामने अकस्मात् ही यह समस्या उठ खड़ी हुई थी कि अब क्या किया जाय ? अवमूल्यन न करने से यह भय था कि रुपये और स्टिलिङ्ग का परम्परागत सम्बन्ध हुट जायगा और स्टिलिङ्ग क्षेत्र के देशों से व्यापार में किठनाई उत्पन्न हो जायगी और साथ ही, देश के पौंड पावना ऋगों की कीमत भी कम हो जायगी। इसके विपरीत अवमूल्यन द्वारा मुद्रा स्फीति के और अधिक बढ़ने तथा आयातों की पहले से अधिक कीमत चुकाने का भय था, परन्तु सब कुछ सोव-विचार कर भारत सरकार ने मुद्रा अवमूल्यन को ही अधिक उचित समका।

भारत सरकार के निर्णय पर मुख्यतया इस बात का प्रभाव पड़ा कि कई वर्षों से भारत का व्यापाराशेष डालर देशों के साथ प्रतिकूल ही चल रहा था। भारत सरकार ने डालर की बचत करने का भरसक प्रयत्न किया था और सम्पूर्ण अधिकृत ऋएा राशि मुद्रा-कोष (I.M.F.) से उधार भी ली थी, परन्तु डालर का घाटा पूरा नहीं हो रहा था। ग्रान्तरिक कीमत-स्तर डालर देशों की तुलना में ऊँ वा था, जिसके कारण निर्यातों में भारी कठिनाई होती थी, परन्तु साथ ही साथ, खाद्यान्न, मशीनरी तथा पूँजीगत माल के लिए भारत को डालर देशों से ग्रायातों का लेना ग्रावश्यक था। अवमूल्यन द्वारा भारत सरकार ने डालर देशों को अधिक निर्यात करने की बात सोची थी। बाद की घटनात्रों ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत सरकार का निर्णय ठीक था। निस्सन्देह ही इसके कारण भारत के शोधनाशेष की गड़बड़ काफी ग्रंश तक दूर हो गई थी, यद्यपि इसने भारत ग्रीर पाकिस्तान के व्यापार सम्बन्धों में काफा उलफनें पैदा कर दी थीं।

## मौद्रिक नीतियाँ (Monetary Policies)

इसमें तो सन्देह नहीं है कि मुद्रा के ग्राविष्कार ने मानव समाज का काफी कर्त्याण त्या है, परन्तु मुद्रा के मूल्य के उच्चावचनों के फल कभी-कभी इतने दुखदायी होते हैं कि मुद्रा के मूल्य पर नियन्त्रण रखने की ग्रावश्यकता पड़ती है। मौद्रिक नीति का त्राभिप्राय एक ऐसी नीति से होता है, जिसमें मुद्रा के मूल्य को त्रावश्यक सीमा के भीतर नियन्त्रित रखा जाय।

### मौद्रिक नीति के उद्देश्य

मौद्रिक नीति के तीन घलग-घलग उद्देश्य हो सकते हैं:—(१) कीमत स्थिरता (Price stabilization), (२) मुद्रा की तटस्थता (Neutrality of Money) और (३) साधनों का ग्रधिकतम् उपयोग। इसमें से ग्रन्तिम उद्देश सबसे ग्रधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राधिक सन्तुलन, पूर्ण वृत्ति, राष्ट्रीय ग्राय को ग्रधिकतम् अनाना ग्रादि सभी इसके ग्रन्तर्गत ग्रा जाते हैं।

#### (१) कीमतों की स्थिरता—

मौद्रिक नीति के सम्बन्ध में सबसे लोकप्रिय मत यही है कि इस नीति का उद्देश्य कीमतों की स्थिरता को बनाये रखना होना चाहिये | यदि मुद्रा को मूल्यमान के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह म्रावश्यक है कि उसके मूल्य में स्थिरता रहे। इसके म्रतिरिक्त कीमतों में भारी उथल-पुथल के भयंकर परिग्णामों से भी संसार परिचित है।

परन्तु कीन्ज जैसे महान् ग्रर्थशास्त्रियों का मत है ग्रौर व्यवहारिक जीवन में यह सत्य भी है कि एक घीरे-घीरे ऊपर उठता हुग्रा कीमत-स्तर वृत्तिहीनता को दूर

करने तथा देश में बेकार पड़े हुए साधनों को काम में लगाने के लिए स्थिर कीमत-स्तर की श्रपेक्षा ग्रधिक उपयुक्त होता है।

कीमतों की स्थिरता बनाये रखने की नीति तीन कारगों से भ्रनुपयुक्त होती है:—

- (i) कौन सी कीमतों में स्थिरता होनी चाहिये पहली किठनाई यह है कि कौनसी कीमतों में स्थिरता लाई जाय— थोक कीमतों को स्थिर किया जाय, अथवा खेरीज की कीमतों को, अथवा मजदूरियों में स्थिरता लाई जाय? इसके अतिरिक्त कीमतों के सामान्य परिवर्तनों का देश के आर्थिक जीवन पर इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उनके तुलनात्मक परिवर्तनों का, अतः सामान्य कीमतों की स्थिरता के स्थान पर तुलनात्मक कीमतों की स्थिरता अधिक उपयुक्त है; परन्तु यह सम्भव नहीं है।
- (ii) कीमतों की स्थिरता से लाभ की स्राशा नहीं —कीमतों के परिवर्तन स्रार्थिक जीवन की स्रस्थिरता के लद्दारण होते हैं, उसके कारण नहीं होते | कीमतों की स्थिरता रहते हुए भी उत्पादन तथा द्रार्थिक सम्बन्धों में काफी उथल-पुथल हो सकती है। कीमतों की उथल-पुथल से बहुत पहले ही ग्रार्थिक जीवन में ग्रस्थिरता ग्रा चुकती है, इसलिये कीमतों की स्थिरता से किसी भी लाभ की ग्राशा नहीं हो सकती है।
- (iii) कीमतों के सभी परिवर्तन बुरे नहीं—इस नीति में कीमतों के सभी परिवर्तनों को बुरा समका जाता है, परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। मुद्रा की मात्रा के परिवर्तनों से सम्बन्धित कीमतों के उच्चावचन तो बुरे होते हैं, परन्तु यदि ये उच्चावचन उत्पादन के वास्तविक व्यय से सम्बन्धित हैं तो पूर्ण तथा स्थिर वृत्ति की दशाएँ उत्पन्न करने के लिए इनका होना ग्रावश्यक होता है।
- (iv) स्थिरता कैसे लाई जाय?—इस सम्बन्ध एक व्यवहारिक कठिनाई यह भी है कि कीमतों में स्थिरता कैसे लाई जाय? इसके लिए दो उपाय बताये जाते हैं:—प्रथम, मुद्रा की मात्रा को स्थिर रखना और दूसरे, मौद्रिक व्यय की दर को यथास्थिर रखना। प्रथम के सम्बन्ध में यह कठिनाई है कि मुद्रा की मात्रा को यथास्थिर रखने से कीमतों में स्थिरता नहीं आ सकती। मुद्रा की मात्रा को व्यापार तथा व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार घटाना-बढ़ाना आवश्यक होता है। इसलिए दूसरी रीति अधिक उपयुक्त है।

#### (२) तरस्थ मुद्रा-

कुछ स्रयंशास्त्रियों का विचार है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य तटस्थ मुद्रा की स्थापना होना चाहिए। इस नीति के श्रन्तर्गत वस्तुस्रों की पूर्ति के परिवर्तनों की दशा में सुद्रा की मात्रा में परिवर्तन नहीं करने चाहिए। वस्तुस्रों की मात्रा में कमी स्रोर वृद्धि के कारण सामान्य कीमत-स्तार में होने वाले परिवर्तनों को रोकना ठीक

नहीं होता है। इस नीति के समर्थकों का विचार है कि आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में सबसे दु:खदायी परिवर्तन मुद्रा की मात्रा के परिवर्तनों के ही कारण उत्पन्न होते हैं। प्रो॰ हेयक इसी नीति के समर्थक हैं। आ॰ हेयक इसी नीति के समर्थक हैं।

(३) प्रो॰ हैनसेन (Hansen) ने इस नीति की ग्रालोचना इस ग्राघार पर की है कि एकाधिकार तथा त्रौद्योगिक संघों के इस वर्तमान युग में यह नीति व्यवहारिक नहीं है। कोई भी केन्द्रीय बैंक एकाधिकारों द्वारा उत्पादित वस्तुग्रों की कीमतें घटाने में सफल नहीं हो सकती है। (ii) इसके ग्रातिरिक्त मुद्रा की मात्रा को यथास्थिर रख कर तटस्थ मुद्रा का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता है। वस्तुत्रों त्रौर मुद्रा की मात्रा के त्रमुपात को बंनाये रखने के लिए मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन त्रावश्यक होते हैं। (iii) विनियोगों की वृद्धि के काल में भी मुद्रा का त्रिधिक संचार त्रिनिवार्य होता है, इस कारण निर्वाधावादी नीति से काम नहीं चल सकता है। (iv) मुद्रा-नियन्त्रक के लिए देश के उत्पादन की वृद्धि को घ्यान में रखना भी त्रावश्यक होता है।

#### कीन्ज का मत-

लार्ड कीन्ज ने राष्ट्रीय ग्राय को ग्रविकतम् करने के लिये मौद्रिक नीति का उपयोग करने पर जोर दिया है। अ उनका विचार है कि वृत्तिहीनता को दूर करने का सबसे उपयुक्त उपाय यही है कि जब तक पूर्ण वृत्ति की दशायें उत्पन्न न हो जायें, सुलभ मुद्रा नीति (Cheap Money Policy) द्वारा कीमत-स्तर को बराबर ऊपर उठाया जाय। इस मत के पक्ष में कीन्ज ने यह बताया है कि:—(१) मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के कारण मुद्रा के व्यय में वृद्धि होगी, क्योंकि इसके द्वारा नकद शेषें बहेंगी, बैंकों की साख-निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी ग्रीर ब्याज की दरें

नीचे गिरेंगी। (२) मुद्रा की मात्रा के बढ़ने के कारए। कीमतें बढ़ेंगी ग्रीर (३) कीमतों

में इस प्रकार होने वाली वृद्धि ग्राय को बढ़ायेगी।

इस मत के अनुसार जब तक किसी भी ग्रंश तक वृत्तिहीनता शेष रहती है, मौद्रिक विस्तार द्वारा घीरे-धीरे ऊपर उठते हुये कीमत-स्तर को बनाये रखना आव-श्यक होता है। व्यापार चक्र के विरुद्ध कीन्ज ने यही उपाय बताया है कि ब्याज की दरों को नीचे रखना ही उपयुक्त होता है, ताकि वैभव (Boom) को एक आभास स्थाई (Quasi-Permanent) रूप दिया जा सके। उस मौद्रिक नीति को अच्छा नहीं कहा जा सकता है जो देश में मन्दी की दशाएँ बनाये रखने का प्रयत्न करे। अच्छी नीति वही है जो अवसाद को आने ही न दे और आधिक जीवन को हल्की तेजी की अवस्था में रखे। इस दृष्टिकोएा से मौद्रिक नीति का उद्देश्य कीमतों की स्थिरता बनाये रखने के स्थान पर उन्हें घीरे-धीरे ऊपर उठाना होना चाहिए।

See Keynes: The General Theory of Employment, Interest and Money, The Chapter on Monetary, Policy.

## भारत में मुद्रा-स्फीति

दूसरें महायुद्ध के काल में तथा युद्धोत्तर काल में भारत में मुद्रा-स्फीति का जोर रहा है; यद्यपि सन् १६४ म से पहले भारतीय राजनीतिज्ञों का घ्यान इस ग्रोर ग्राक्षित नहीं हुग्रा था। भारतीय मुद्रा-स्फीति के सम्बन्ध में एक हास्यरस लेखक ने बहुत ही ग्रच्छा लिखा है। उनका कथन है कि "युद्धकाल में सभी काम तेजी के साथ हो रहे थे। सबकी देखा-देखी भारतीय रुपये ने भी तेजी से दौड़ना ग्रारम्भ कर दिया, परन्तु श्रकस्मात ही १५ ग्रगस्त सन् १६४७ को ग्रङ्करेज लोग भारत से भाग खड़े हुए। रुपये को इस परिवर्तन का पता न चल सका, क्योंकि ग्रङ्करेज राजा की मुहर उस पर ग्रभी तक भी मौजूद थी ग्रौर वह दौड़ता ही रहा। इस काल में भारत निवासी एक-दूसरे को लूटने-काटने तथा सभी जगहों पर भण्डे लहराने में व्यस्त रहे। इससे ऊब जाने पर उन्होंने देखा कि रुपया तेजी से दौड़ रहा था, बस एक दम उन्होंने इसे मुद्रा-स्फीति का नाम दे डाला।" इस हास्य में कटु सत्य छिपा है। भारत सरकार इतने लम्बे समय तक इस समस्या के प्रति उदासीन रही है कि शायद थोड़ा सा ग्रौर विलम्ब देश की ग्रर्थ-व्यवस्था के लिए घातक हो सकता था।

इस सम्बन्ध में थोड़ा मतभेद रहा है कि भारत में मुद्रा-स्फीति का ग्रंश कहाँ तक पहुँच गया था। प्रो० राव का विचार है कि सन् १९४५ के प्रथम छः महीनों में भारत में कीमतों की वृद्धि लगभग १२% थी, जबिक इसी काल में चलन का विस्तार केवल ४.७% ही था। निस्सन्देह इससे यही पता चलता है कि मुद्रा-प्रसार की तीसरी ग्रवस्था ग्रारम्भ हो गई थी। प्रो० वकील ने भी डा० राव का समर्थन किया है। इसके विपरीत श्री घनश्यामदास बिड़ला का कथन है कि भारत में मुद्रा-स्फीति थी ही नहीं। कीमतों की वृद्धि केवल मुद्रा-संफीति के कारण हुई थी। सत्य इन दोनों मतों के बीच है। देश में मुद्रा-स्फीति काफी वढ़ गई थी, परन्तु स्त्रभी तीसरी स्त्रवस्था स्त्रारम्भ नहीं हुई थी।

भारत में मुद्रा-स्फीति के कारण-

मुद्रा-स्फीति के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं:—

- (१) सबसे महत्त्वपूर्ण कारण देश में चलन तथा साख-मुद्रा का विस्तार है—सन् १६३६ तथा सन् १६४८ के बीच चलन की मात्रा १७६ करोड़ से बढ़कर १,३१० करोड़ रुपया हो गई ग्रीर साख-मुद्रा १२६ करोड़ से बढ़कर ४४४ करोड़ रुपया। चलन की इस ग्रत्यधिक वृद्धि का प्रमुख कारण यह था कि युद्ध से सम्बन्धित खचों को चलाने के लिए सरकार ने पत्र-मुद्रा छाप कर आय प्राप्त की थी। कीमतों के बढ़ाने का उद्देश्य यह भी था कि वस्तुग्रों ग्रीर सेवाग्रों की कीमत बढ़ा कर उनके नागरिक उपभोग को कम किया जाय। इस प्रकार चलन की मात्रा में वृद्धि होने के कई कारणा थे:—
  - ( i ) स्टर्लिङ्ग निधि में बृद्धि—इङ्गलैंड की सरकार ने भारतीय बाजार से

काफी माल खरीदा था। इसके लिए स्टॉल इसे मुगतान किया गया था, जो इक्जलैंड की सरकार को फिर से ऋगा के रूप में दे दिया गया था, परन्तु इस प्रकार जिन स्टॉल इस प्रतिभूतियों अथवा हुण्डियों का निर्माग हुआ था उनको निधि के रूप में रख कर रिजर्व बैंक ने कागज के नोट छाप दिए थे, जिनमें भारत के ज्यापारियों को इक्जलैंड द्वारा खरीदी हुई वस्तुओं और सेवाओं की कीमत चुका दी गई थी।

- (ii) डालरों का स्टॉलंड्स में परिशात होना—भारत निर्यात व्यापांर द्वारा अमरीका से जो डालर प्राप्त करता था वे साम्राज्य डालर कोष (Empire Dollar Pool) में जमा कर दिए जाते थे और ब्रिटिश सरकार उनके बदले में रिजर्व बैंक को स्टॉलंड्स प्रतिभृतियाँ देकर कागज के नोट छपवाती रहती थी। इस प्रकार युद्ध के यन्त में भारत का इङ्गलैंड पर लगभग १,६०० करोड़ रुपये ऋगा हो गया था।
- (iii) वेतनों ग्रौर मँहगाई भत्तों की वृद्धि—युद्ध-काल तथा उसके पश्चात् वेतनों ग्रौर मँहगाई के भत्तों में जो वृद्धि हुई थी उसके कारण भी भारत सरकार को मुद्रा-स्फीति द्वारा ग्राय प्राप्त करने पर बाध्य होना पड़ा था। करों की वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही हो सकती थी ग्रौर सरकार की लोक ऋण प्राप्त करने की नीति ग्रसफल रही थी, इसलिए सरकार के पास कागज के नोट छाप कर ग्राय प्राप्त करने के ग्रितिरिक्त दूसरा कोई चारा न था।
- (iv) हीनार्थ-प्रवन्धन—इसी प्रकार सरकार की हीनार्थ प्रबन्धन (Deficit financing) नीति के कारण साख-मुद्रा का विस्तार हुग्रा।
- ( v ) बैंकों की लाभ प्रवृत्ति—विनियोग ग्रौर व्यापार की वृद्धि ने भी बैंकों को ग्रधिक साख निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया था। बैंकों को साख-वृद्धि करके लाभ कमाने का ग्रच्छा ग्रवसर मिल गया था।
- (२) दस्तुस्रों की सामान्य दुर्लभता ने कीमतों को ऊँचा उठा दिया— इस दुर्लभता का एक कारण तो यह था कि स्नायातों की मात्रा युद्धकालीन कठिनाइयों के कारण बहुत ही सीमित रह गई थी सौर दूसरे, विभिन्न कारणों से देश में उत्पादन का विस्तार मुद्रा के विस्तार की तुलना में कम रहा था। खाद्यान्न की कमी ने तो भयंकर रूप घारण कर लिया था। लड़ाई से पहिले भारत को वर्मा, मलाया, स्याम तथा हिन्द-चीन से काफी चावल मिल जाता था, परन्तु जापानी श्रिधकार के पश्चात् इन देशों से स्नायात बन्द हो गये थे। देश के भीतर खाद्यान्न उत्पादन वरावर घट रहा था सौर भारत सरकार लंका, दक्षिणी स्नफीका तथा मध्य-पूर्व युद्ध-क्षेत्रों को स्ननाज भेज रही थी। खाद्यान्न की इस भारी कमी का परिगाम सन् १९४३ के बंगाल दुर्भिक्ष के रूप में प्रकट हुस्रा। युद्ध के उपरान्त पाकिस्तान के निर्माग ने। भारत की खाद्य स्थिति स्नौर भी खराब कर दी। सिन्य तथा पश्चिमी पंजाब के स्नधिक सन्न उपजाऊ

क्षेत्र पाकिस्तान के पास चले गए । निर्मित वस्तुत्र्यों की कमी का प्रमुख कारण

आयातों की कमी थी, परन्तु आवश्यक मशीनों और कच्चे मालों की कमी के कारण भी देश के भीतर उत्पादन में समुचित वृद्धि न हो सकी । सन् १६४२-४३ में ही आयात सन् १६३६-३६ का केवल ३७.६% थे। साथ ही, भारतीय उत्पादन का बहुत बड़ा भाग युद्धकालीन उद्देश्यों के लिए खरीद लिया गया। युद्ध के काल में लगभग २,००० करोड़ रुपये का माल इस प्रकार खरीदा गया था।

- (३) सट्टों की प्रवृत्ति भी काफी बलवान हो गई थी श्रौर वस्तुश्रों को जमा करने की मनोवृत्ति बहुत बढ़ गई थी—सट्टों बाजार के विकास ने श्रकारण ही कीमतों को बढ़ाना श्रारम्भ कर दिया। दुर्लभता के कारण केवल दूकानदारों श्रौर ज्यापारियों ने भी लाभ कमाने के लिए माल जमा करना लाभदायक नहीं समभा, बिल्क यह प्रवृत्ति सर्वज्यापी हो गई। पूर्ति के श्रिनिश्चित रहने के कारण सभी ने स्टॉक् जमा करना शुरू कर दिया था।
- (४) यातायात सम्बन्धी किठनाइयों तथा वस्तुओं के असन्तोषजनक वितरण ने भारी भय की स्थिति उत्पन्न कर दी—सैनिकों और सैनिक सामानों के यातायात ने रेलों को व्यस्त रखा। इसके अतिरिक्त पैट्रोल आदि की कमी के कारण अन्य यातायात सेवाओं से पूरा-पूरा लाभ न मिल सका। स्थानीय दुर्लभताएँ बराबर बनी रहीं, जिसके कारण आसंचन (Hoarding) तथा नफाखोरी को रोकना किंक हो गया।
- (५) कीमत नियन्त्रगा तथा राशनिंग की सरकारी नीति एक बड़े ख़ंश तक ग्रसफल ही रही थी— शासन की श्रकुशलता तथा भ्रष्टाचार के कारण चोर-बाजारी को प्रोत्साहन मिला। राशन व्यवस्था कुछ थोड़े से शहरों तथा कुछ थोड़ी सी वस्तुश्रों पर ही लागू की गई थी, जिसके कारण कीमतों की वृद्धि रुक न सकी। वैसे भी श्रिधकांश दशाश्रों में राशन की मात्रा इतनी कम रखी गई थी कि लोगों को चोर वाजार से माल खरीदने पर बाध्य होना पड़ा था।
- (६) युद्धोत्तर-काल में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की हीनार्थ प्रबन्धन रीति तथा विकास योजनाग्रों के संचालन ने कीमतों को गिरने नहीं दिया है इसके ग्रतिरिक्त सन् १९४७ के उपद्रव तथा शरणार्थी समस्या ने सरकार को व्यस्त रखा। सितम्बर सन् १९४६ में भारत सरकार ने रुपये का श्रवमूल्यन कर दिया, जिसके कारण मुद्रा-स्फीति को एक बार फिर बल प्राप्त हो गया।

#### भारत सरकार के मुद्रा-स्फीति विरोधी उपाय-

सन् १६४२ में ही भारत सरकार ने कीमत नियन्त्रण तथा राशनिंग द्वारा स्फीति का सामना किया था। इसके भ्रतिरिक्त कुछ वस्तुग्रों की कीमतों में सट्टा बन्द कर दिया गया था, करों में वृद्धि की गई थी ग्रौर सरकार ने जनता से ऋगा लिए थे। साथ ही, रक्षा बचत योजना लागू की गई ग्रौर लोगों को बचत करने के लिए उत्साहित किया गया। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए 'ग्राधिक ग्रन्न उपजाग्रो ग्रान्दो-

लन' ग्रारम्भ किया गया. परन्तु ये सब उपाय बहुत सफल सिद्ध न हो सके। स्वतन्त्रता के पश्चात् जनवरी सन् १६४८ में राष्ट्रीय सरकार ने ग्रपनी मुद्रा-स्फीति विरोधी नीति

की घोषणा की। इस नीति के दो प्रमुख ग्रावार थे—(1) प्रचलित मुद्रा की मात्रा को

ग्रीर (II) उत्पादन को बढ़ाना । (I) मुद्रा की मात्रा को कम करने के लिए निम्न उपाय किये गये थे:—

(१) करों में वृद्धि करना—राज्य सरकारों को ५०० रुपया प्रति वर्ष से ऊपर की भ्राय पर कृषि भ्राय कर लगाने का भ्रधिकार दिया गया। (२) ऊँची ब्याज देकर जनता से ग्रधिक ऋगा प्राप्त करना।

(३) चलन के विस्तार को बन्द कर देना।

(४) हीनार्थ-प्रबन्धन की नीति का परित्याग कर देना। (५) शासन के व्यय कों कम करके तथा विकास योजनाम्रों के कार्यवाहन

को घीमा करके सरकारी व्यय में कमी करना। (६) कम्पनियों द्वारा लाभांश के वितरण पर ६% की सीमा लगाना। (७) तीन वर्ष के लिए जमींदारों को मुग्रावजे तथा दूसरे भुगतानों को

रोक देना। (II) उत्पत्ति को बढाने के लिए सरकार ने निम्न प्रयत्न किये:—

(१) बीजों, खादों, तथा सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाकर 'म्रिधिक मन

उपजाम्रो म्रान्दोलन' को म्रधिक सफल बनाने का प्रयत्न किया गया। (२) म्रधिक भूभाग पर खेती करके कपास, पटसन तथा गन्ने का उत्पादन बढ़ाया गया।

(३) पहले तीन वर्ष के लिए नये उद्योगों को ग्राय-कर से छूट दी गई। (४) निजी विनियोगों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योगों का राष्ट्रीयकरएा १० वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया।

( १ ) खाद्यान्न तथा निर्मित वस्तुम्रों के म्रायात बढ़ाये गये। (६) अपव्यय को दूर करने के नियम बनाये गये और खाद्य पदार्थों के स्रक्षित संचय की स्विधाएँ प्रदान की गईं।

(७) सरकारी सहायता द्वारा उद्योगों की स्थापना की गई। ( = ) मुल्य-नियन्त्रए तथा रार्ज्ञानग सम्बन्धी नियमों को कडा किया गया

ग्रौर उनका पालन कराने पर ग्रधिक जोर दिया गया। म्रारम्भ में तो सरकारी नीति को म्रधिक सफलता नहीं मिली थी, परन्तु धीरे-

घीरे कीमतों की वृद्धि की गति शिथिल होती गई। सन् १९५१ में भारत सरकार ने देश में प्रथम पंच-वर्षीय योजना लागू की । अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन हो गया कि ग्रब कीमतें उठने के स्थान पर नीचे की ग्रोर जाती हुई दिखाई

पड़ने लगीं। कुछ समय तक भारत सरकार उल्टा यह प्रयत्न करती रही कि कृषि उपज की कीमतों को नीचे न गिरने दिया जाय, ताकि कृषक वर्ग की हालत बिगड़ने न पाये। दूसरे पंच-वर्षीय श्रायोजन में कृषि उपज की कीमतों की स्थिरता को ही श्रार्थिक नीति का श्राधार बनाया गया था।

### दूसरी पंच-वर्षीय योजना के काल में कीमतों की वृद्धि-

विगत वर्षों में एक महत्त्वपूर्ण घटना यह हुई है कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना के काल में कीमतें फिर ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। पथम पंच-वर्षीय योजना के काल में कीमतें कुछ नीचे ग्रा गई थीं। प्रथम योजना के ग्रन्त में कीमतें उसके म्रारम्भ से भी १३ $\frac{9}{10}$  नीची थीं। कूछ दिनों तक तो भारत सरकार इस टिशा में प्रयत्नशील रही कि कृषि की उपज की कीमतों को किसी प्रकार ग्रौर नीचे गिरने से रोका जाय श्रीर यथासम्भव उन्हें स्थिर कर दिया जाय। प्रथम योजना पर २.००० करोड़ रुपये के लगभग व्यय हो जाने पर भी कीमतों में नीचे गिरने की प्रवृत्ति निस्सन्देह एक ग्राश्चर्यजनक बात थी। जिस समय दूसरी पंच-वर्षीय योजना की रूप-रेखा तैयार की गई थी उस समय कीमतें काफी स्थिर सी थीं. बल्कि उनमें गिरने की ही प्रवृत्ति थी। किंचित इसी कारएा भारत सरकार ने दूसरी योजना के लिए १,२०० करोड़ रुपए के हीनार्थ-प्रवन्धन (Deficit-financing) का कार्यक्रम रखा था। सरकार का विश्वास था कि इतने ग्रिधिक हीनार्थ-प्रबन्धन के रहते हुए भी योजना काल में मुद्रा-प्रसार का भय न था। परन्तु वास्तविक अनुभव भ्राशा के विपरीत रहा है। म्रप्रैल सन् १९५६ से ही कीमतों ने ऊपर उठना म्रारम्भ किया, मुख्यतया खाद्याचों की कीमतों ने। घीरे-घीरे सभी वस्तुश्रों की कीमतें ऊपर जाने लगीं। यहाँ तक कि दिसम्बर सन् १९५६ में ही राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) को स्थिति पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। ऐसा अनुभव किया गया था कि खाद्यान्न उत्पादन सम्बन्धी स्थिति फिर बिगड़ गई थी ग्रौर भारी मात्रां में हीनार्थ-प्रबन्धन के दुष्परिगाम सामने ग्रा गये थे। हीनार्थ-प्रबन्धन को कम करने तथा खाद्य पदार्थों के भण्डारों को बढ़ाने के प्रयत्न ग्रारम्भ हुए, किन्तु मुद्रा प्रसार का विस्तार रुक न सका। सन् १६५७ में दूसरी पंच-वर्षीय योजना के लच्यों को नीचा करने की भी बात चली । ऐसा अनुमान है कि कीमतों की वृद्धि के कारए। दूसरी योजना के लद्द्यों को पूरा करने के लिए ४,५०० करोड़ रुपये के स्थान पर लगभग ५.५०० करोड़ रुपये के व्यय की आवश्यकता पड़ेगी और यह भी तब जबिक कीमतें मार्च सन् १९५० के स्तर से ऊँची नहीं जाती हैं। इस प्रकार एक बार फिर मुद्रा-प्रसार का राक्षस हमारे सामने उपस्थित है। कीमतों की वृद्धि की यह प्रवृत्ति ग्राज भी स्पष्टतया सामने है, किन्तु हमें इस ऐच्छिक मुद्रा-प्रसार से डरना नहीं चाहिए ।

दूसरी योजना के निर्माण के समय कीमतों की वृद्धि की सम्भावना पर विचार न किया गया हो, ऐसी बात नहीं है। सरकार का विचार था कि खाद्यान्न तथा सूती कपड़े का उत्पादन बढ़ाकर इन दोनों की कीमतों यथास्थिर रखी जायेंगी ग्रौर इस प्रकार यदि मुद्रा-प्रसार होता भी है तो उसका जन-साधारण पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तविकता यह है कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम ग्रसफल

रहा है श्रीर कपड़ा श्रीर श्रनाज दोनों की कीमतें बढ़ी हैं। परिग्णाम यह हुआ है कि बढ़ती हुई कीमतें दुखदायी हो गई हैं। करारोपण तथा लोक ऋगा के पर्याप्त विस्तार के द्वारा भी सरकार अभी तक भी स्थिति को बदल नहीं सकी है।

#### QUESTIONS

- 1. What is inflation? What are its causes? What are its effects upon the economy of a country? Discuss it with regard to Indian conditions. (Raj., B. Com., 1944)
- 2. What is inflation? What are its evils? What are the possible methods of controlling inflation?

(Bombay, B. Com., 1948)

- 3. Discuss the measures for combating inflation.
  (Bombay, B, Com., 1947)
- 4. लगातार बढ़ने हुए मूल्य-स्तर के दुष्परिशामों को स्पष्ट कीजिए। बढ़ते हुए मूल्य-स्तर को स्थिर करने के लिए आप क्या समाव देंगे। (Sagar, B. Com., 1957)
- 5. What are the effects of inflation? How can inflation be controlled? (Bihar, B. A., 1958)
- 6. What is inflation? Analyse the effects of war-time inflation on Indian agriculture? (Alld, B. A., 1954)

### ग्रध्याय ११

# निर्देशांक

(Index Numbers)

#### प्रारम्भिक-

मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों का भ्रध्ययन करने के पश्चात् श्रब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि कीमत-स्तर के उच्चावचनों को किस प्रकार नापा जाता है। यह काम निर्देशांकों ग्रथवा सूचक ग्रङ्कों की सहायता से किया जाता है, इसलिए प्रस्तृत ग्रध्याय में निर्देशांकों का ही ग्रध्ययन किया जायगा। स्मरण रहे कि मुद्रा की क्रयः शक्ति के परिवर्तनों को नापना कई दृष्टिकोएों से महत्त्वपूर्ण होता है :-(i) एक पिछले ग्रध्याय में हम यह देख ही चुके हैं कि इन परिवर्तनों का देश के सामाजिक ग्रौर ग्रार्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी वर्ग को लाभ होता है और किसी को हानि। (ii) इसके अतिरिक्त विभिन्न ग्राथिक घटनाग्रों के बीच समायोजन भी इन्हीं परिवर्तनों के द्वारा होते हैं। (iii) मूल्य-यन्त्र (Price Mechanism) को पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली की संचालक शक्ति कहा जाता है। किस वस्तु का उत्पादन होगा ग्रौर कितनी मात्रा में, कौन-कौन से उत्पत्ति के साधनों को रोजगार मिलेगा और किस अंश तक, देश के भीतरी ग्रीर बाहरी व्यापार का क्या रूप होगा. देश का ग्रार्थिक विकास किस सीमा तक होगा भीर किन-किन दिशाओं में भीर देश में भ्राय भ्रथवा क्य: शक्ति के वितरए। का क्या रूप होगा, ये सभी बातें कीमत स्तर ग्रौर उसके परिवर्तनों पर निर्भर होती हैं। (iv) यही नहीं, समाज के विभिन्न वर्गों के पारसारिक सम्बन्ध, उनके बीच का सहयोग श्रौर उनके पारितोषण की मात्राएँ भी इन्हीं परिवर्तनों द्वारा निर्घारित होती हैं। कोई भी ऐसा उपाय जिसके द्वारा इन परिवर्तनों को निश्चित रूप में नापा जा सके. ऋर्थशास्त्र में काफी महत्त्वपूर्ण होगा ।

### निर्देशांक क्या होते हैं ?—

जिन वस्तुओं ग्रौर सेवाग्रों पर मुद्रा का व्यय किया जाता है उनकी कीमतों के ग्रौसत को हम कीमत-स्तर कहते हैं ग्रौर कीमत-स्तर की एक सूची (Series) को निर्देशांक ग्रथवा सूचक ग्रंक कहा जाता है। इस प्रकार निर्देशांक कीमत-स्तर के ग्रङ्कों की एक सूची होती है, जिन्हें एक तालिका के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि मुद्रा के मूल्य के उच्चावचनों को सूचित करने के उद्देश्य से वस्तुग्रों ग्रौर सेवाग्रों की सामान्य कीमत के परिवर्तनों को दिखाया जा सके। यदि एक निश्चित समय की तुलना में निर्देशांक ऊँचा है तो इसका ग्रथं है कि सामान्य कीमतें ऊँची उठ गई हैं

श्रोर मुद्रा का मूल्य कम हो गया है। इसके विपरीत जब सामान्य कीमत-स्तर का निर्देशांक गिरता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। श्रतएव जब निर्देशांक वृद्धि दिखाते हैं तो मुद्रा का मूल्य गिरता है श्रोर जब निर्देशांक पतन दिखाते हैं तो मुद्रा का मूल्य ऊपर उठता है।

इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में एक ही साथ एक ही दिशा में परिवर्तन नहीं होते हैं। यद कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तो कुछ की नीचे गिरती हैं। इसके विपरीत विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन का ग्रंश भी ग्रंलग-ग्रंलग होता है। किन्तु कीमतों के इन सभी परिवर्तनों की एक सामान्य दिशा भी होती है। विविधता के साथ-साथ उनमें एक ग्रंश तक अनुरूपता भी रहती है। व्यक्तिगत कीमतों के परिवर्तन प्रतिविरोधी हो सकते हैं, परन्तु उनके बीच की एक सामान्य प्रवृत्ति का पता लगा लेना सम्भव होता है। विर्देशांक का उद्देश्य इसी प्रकार की केन्द्रीय प्रवृत्ति की त्रोर संकेत करना होता है। दूसरे शब्दों में, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि निर्देशांकों का व्यक्तिगत कीमतों से कोई प्रत्यक्ष ग्रथवा निकट सम्बन्ध नहीं होता है। उनका सम्बन्ध तो केवल कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति से होता है, यद्यपि यह सत्य है कि स्वयं सामान्य प्रवृत्ति भी कीमतों के व्यक्तिगत परिवर्तनों पर ही निर्भर होती है। एक बात और ध्यान देने योग्य है। निर्देशाङ्क कीमतों के परिवर्तन के तुलना-त्सक रूप को ही दिखाते हैं। उनका उद्देश्य सामान्य कीमत के दो विभिन्न कालों के बीच होने वाले तुलनात्मक परिवर्तनों को सूचित करना होता है। वे मुद्रा के मुल्य के

त्मक रूप को ही दिखाते हैं। उनका उद्देश्य सामान्य कीमत के दो विभिन्न कालों के बीच होने वाले तुलनात्मक परिवर्तनों को सूचित करना होता है। वे मुद्रा के मूल्य के निरपेक्ष (Absolute) मापक नहीं हैं। यह कहने का लगभग कुछ भी अर्थ नहीं होता है कि निर्देशांक अब ७५ अथवा ६५० है। इसका कुछ अर्थ तभी हो सकता है जबिक यह बता दिया जाय कि किस वर्ष, मास, सप्ताह अथवा दिवस की तुलना में वह इतना है। निर्देशांक केवल दो विभिन्न कालों के कीमत-स्तर की तुलना करने के लिये उपयोग किये जा सकते हैं।

ऊपर की सारी विवेचना में हमने यह मान लिया है कि निर्देशांक केवल मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों को नापने के लिये ही उपयोग किये जाते है, परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। प्रत्येक प्रकार का ग्राधिक परिवर्तन निर्देशांक द्वारा सूचित किया जा सकता है। निर्देशांक तो ग्राधिक घटनाग्रों के तुलनात्मक परिवर्तनों को नापने की विधि है। ये ग्राधिक घटनायें किसी भी प्रकार की भी हो सकती है। सामान्य कीमतों के निर्देशांकों की निर्माण विधि—

सामान्य कीमतों के निर्देशांक श्रौसत कीमतों पर श्राधारित होते हैं। सैढ़ान्तिक दृष्टिकोएा से इन निर्देशाङ्कों के बनाने में देश में उपलब्ध समस्त वस्तुशों ग्रौर सेवाग्रों की कीमतों का ग्रौसत निकालना चाहिए, परन्तु व्यवहार में ऐसा करना किठन होता है। इसलिये कुछ वस्तुशों ग्रौर सेवाग्रों को प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया जाता है ग्रीर उन्हीं की ग्रौसत कीमत को देश की सभी वस्तुशों ग्रौर सेवाग्रों की ग्रौसत कीमत

के रूप में ग्रह्ण कर लिया जाता है। स्मरण रहे कि निर्देशाकों का बनाना यथार्थ में सांख्यिकी (Statistics) की एक समस्या है भ्रौर सांख्यिकी की सहायता से सही- सही परिणाम निकालना विशेषज्ञों का काम होता है। ऐसा कहा जाता है कि म्रङ्क विज्ञान की सहायता से इच्छानुसार कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। यही कारण है कि निर्देशाँकों के बनाने तथा उनका उपयोग करने में विशेष सावधानी की म्रावश्य- कता है। तम्न सावधानियां महत्त्वपूर्ण हैं:—

(¸४ ) ग्राधार वर्ष का चुनाव—निर्देशांक साघारणतया वार्षिक म्राघार पर बनाये जाते हैं, परन्तु सभी वर्षों की ग्रौसत प्रचलित कीमतों की तुलना किसी एक निश्चित वर्ष की कीमतों से की जाती है। ऐसे वर्ष को ग्राधार वर्ष (Base Year) कहा जाता है। निर्देशांक बनाने से पहले ग्राघार वर्ष को सावधानीपूर्वक चुनना बड़ा म्रावश्यक होता है। सबसे वड़ी भ्रावश्यकता यह होती है कि किसी ऐसे वर्ष को स्राधार वर्ष के रूप में चुना जाय जो कि सभी दृष्टिकोगों से एक साधारण वर्ष (Normal Year) हो I दूसरे शब्दों में, केवल ऐसे वर्ष को श्राधार बनाना उपयुक्त होता है जिसमें कीमतें न तो बहुत ऊँची रही हों ग्रौर न बहुत नीची। एक छोटे से उदाहरएा द्वारा ऐसे चुनाव के महत्त्व को स्रष्ट किया जा सकता है। मान लीजिये कि हम यह जानना चाहते हैं कि एक कक्षा में विद्यार्थियों का सामान्य बुद्धि-स्तर कैसा है। श्रव यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी की बुद्धिमानी की तुलना कक्षा के सबसे तेज बुद्धि वाले विद्यार्थी से करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि कक्षा श्रत्यन्त बुद्धिहीन है। इसी प्रकार यदि किसी ऐसे विद्यार्थी को ग्राघार के रूप में उपयोग किया जाता है, जो मूर्ख है तो तुलना करने पर यही ज्ञात होगा कि कक्षा का बुद्धि-स्तर बहुत ही ऊँचा है। कक्षा की सही योयग्ता का पता लगाना दोनों ही दशाश्रों में कठिन होगा । सही श्रनुमान लगाने के लिये हमें एक ग्रौसत दर्जे के बुद्धिमान विद्यार्थी को ग्राघार स्वरूप मानना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार कीमतों के निर्देशांक बनाने के लिये एक ग्रसाघारण श्रार्थिक परि-स्थितियों वाला वर्ष उपयुक्त नहीं हो सकता है । संसार के लगभग सभी देशों में सन् १६३६ को ब्राघार के रूप में उपयोग किया गया है, क्योंकि उसकी सहायता से युद्ध तथा युद्धोत्तर-कालीन कीमतों के परिवर्तनों का एक लाभदायक अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार सन् १९५० को भी एक ऐसा ही वर्ष कहा जा सकता है।

(२) वस्तुओं और सेवाओं का निर्वाचन — ग्राघार वर्ष को निश्चित करने के पश्चात् उन वस्तुओं श्रौर सेवाओं के निर्वाचन की समस्या उत्पन्न होती है जिनकी कीमतों का श्रौसत निकालना है। सभी वस्तुओं श्रौर सेवाओं की कीमतों का श्रौसत निकालना न तो सम्भव ही है श्रौर न ग्रावश्यक ही, परन्तु वस्तुओं श्रौर सेवाओं को इस प्रकार सावधानीपूर्वक चुन लेना ग्रावश्यक होता है कि वे देश की सभी वस्तुओं श्रौर सेवाओं की सामान्य प्रकृति को दिखा सकें। यह श्रत्यावश्यक है कि वस्तुओं श्रौर सेवाओं का निर्वाचित समूह समस्त वस्तुओं श्रौर सेवाओं का प्रतिनिधित्त्व करे। साथ ही,

यह भी घ्यान में रखना आवश्यक है कि निर्वाचित वस्तुओं और सेवाओं की संख्या बहुत कम न हो।

(३) कीमतों का निर्वाचन — वस्तुग्रों ग्रोर सेवाग्रों के चुन लेने के पश्चात् कीमतों का चुनना ग्रावश्यक है। निर्देशां कों के उद्देश्य के अनुसार इस प्रकार चुनी हुई कीमतें अलग-अलग प्रकार की होनी चाहिए। कीमतें थोक भी हो सकती हैं ग्रोर फुटकर भी। मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों को दिखाने के लिए थोक कीमतें ग्रधिक सही अनुमान दे सकती हैं ग्रोर उनका एकत्रित करना भी सुविधाजनक होता है, परन्तु जीवन निर्वाह व्यय के निर्देशांक बनाने के लिए फुटकर कीमतों का चुनना ग्रधिक उपयुक्त होता है। इस निर्णाय के पश्चात् कि कौन सी कीमतों एकत्रित की जायंगी, यह निश्चित करना होता है कि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक ग्रथवा ग्रन्य किसी समय से सम्बन्धित कीमतों को लिया जायगा। इस निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता है। यह निर्देशांक के उद्देश्य, निर्माणकर्त्ता की सुविधा तथा कीमतों की उपलब्धता पर निर्भर होता है श

(४) ग्रौसत का निर्धारण —यह भी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय होता है, क्योंकि ग्रौसत अनेक प्रकार के होते है ग्रौर प्रत्येक से एकसा ही फल प्राप्त नहीं होता है। श्रिधिक चलन गिणित या समानान्तर श्रौसत (Arithmetic Average) के उपयोग का होता है, परन्तु यदि विभिन्न मदों के ग्रन्तर बहुत ही विशाल होते हैं तो ग्रुणोत्तर ग्रौसत (Geometrical Average) ग्रधिक विश्वासजनक फल देता है। इस प्रकार विभिन्न दशाओं में ग्रलग-ग्रलग ग्रौसत महत्त्वपूर्ण होते हैं।

इन सब सावधानियों के पश्चात् निर्देशांकों का बनाना सरल होता है। चुनी हुई वस्तुम्रों की कीमतें ग्राधार वर्ष के नीचे क्रमशः रख दी जाती हैं ग्रौर ग्राधार वर्ष की प्रत्येक कीमत को १०० के बराबर मान लिया जाता है। जिस वर्ष का निर्देशांक निकालना है उसके नीचे भी चुनी हुई सभी वस्तुम्रों की कीमतें उसी क्रम में रख दी जाती हैं ग्रौर ग्राधार वर्ष की कीमत को १०० मान कर वर्ष विशेष की कीमत का सम्बन्धित मूल्य निकाला जाता है। यह मूल्य कीमत-सम्बन्धी (Price-relative) कहलाता है। इस प्रकार सभी कीमत-सम्बन्धियों द्वारा यह पता चल जाता है कि ग्राधार वर्ष की तुलना में वर्ष विशेष की कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुम्रा है। ग्रन्त में कीमत सम्बन्धियों को जोड़ कर मदों ग्रयवा वस्तुम्रों की सख्या से भाग दे देते हैं ग्रौर इस प्रकार ग्रावश्यक निर्देशांक निकल ग्राता है। नीचे की तालिका में इस क्रम को दिखाया गया है

मु०च०ग्र० (१४)

एक उदाहरण—साधारण निर्देशांक— तालिका

वस्तुएँ १६३६ मूल्य	सम्बन्धी	\$ \$ \$ 3 \$	मूल्य सम्बन्धी
चावल (प्रतिमन) ६ रुपया	१००	१८ रुपया	300
गेहूँ (,,) ५ ,,	800	२० ,,	४००
ৰাল ( <sub>,,</sub> ) দ ,,	१००	१६ ,,	, २००
कपड़ा (प्रति गज) ६ ग्राना	१००	१ रुपया २ स्राना	३००
कोयला (प्रति मन) 🖒 🔒	१००	२ रुपया	800
दूघ (प्रतिसेर) ३ ,,	१००	६ ग्राना	₹00
	₹00	ŧ	8 8600
	१००		३१६,६

परिवर्तन 🕂 २१६ ६

उपरोक्त तालिका यह स्पष्ट करती है कि सन् १६३६ के आधार पर सन् १६५३ का निर्देशांक ३१६ है। सन् १६३६ की तुलना में सन् १६५३ में कीमत स्तर में २१६ ६% की वृद्धि हो गई है। स्मरण रहे कि सूचक अङ्क कीमतों के केवल श्रीसत परिवर्तन को ही दिखाता है। निर्वाचित वस्तुओं में से किसी की भी कीमत में इतना परिवर्तन नहीं हुआ है। उपरोक्त उदाहरण में हमने केवल ६ कस्तुओं को चुना है, परन्तु एक सन्तोषजनक निर्देशांक के निर्माण में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त हमें इस बात का भी ध्यान। रखना चाहिए कि दोनों वर्षों में एक वस्तु की (जिसके ग्रुण अथवा परिमाण में अन्तर न हो) एक सी ही कीमतों को लिया जाय।

#### साधारण एवं समार निर्देशांक—

तालिका नं० १ में निकाला गया निर्देशांक साधारणा स्त्रोसत द्वारा तैयार किया गया है। इस प्रकार के निर्देशांक को साधारणा निर्देशांक (Simple Index Number) कहते हैं। इसका सबसे बड़ा दोष यह होता है कि सम्मिलित की हुई प्रत्येक वस्तु को समान ही महत्त्व दिया जाता है, परन्तु वास्तविकता यह है कि समाज पर किसी ग्रावश्यक वस्तु, जैसे—गेहूँ ग्रथवार चावल की कीमतों के थोड़े से भी परिवर्तन का दूघ, सिगरेट ग्रादि कम ग्रावश्यक वस्तुओं की कीमत के ग्रत्यिक परिवर्तन की तुलना में बहुत ग्रधिक प्रभाव पड़ता है। इस कारण निर्देशांक द्वारा दिखाया गया कीमत परिवर्तन समाज के लिए उसके महत्त्व का सही ग्रनुमान प्रस्तुत नहीं करता है।

इस कठिनाई को इस प्रकार दूर किया जा सकता है कि निर्देशांक बनाते समय प्रत्येक कीमत परिवर्तन को आवश्यक भार (Weight) दे दिया जाय। ये भार वस्तु विशेष के तुलनात्मक महत्त्व पर निर्भर होंगे। पारिवारिक बजटों के अध्ययन द्वारा समुचित भारों का सरलता से पता लगाया जा सकता है। कीमत सम्बन्धियों को इन भारों से ग्रुणा किया जाता है और श्रौसत कीमत-स्तर को निकालने के लिए योग को भारों की कुल संख्या से भाग दे दिया जाता है। मान लीजिए कि तालिका नं० १ चावल, गेहूँ, दाल, कपड़ा, कीयला तथा दूध को क्रमशः १२, १०, ४, ६, ४ और ३ भार दिए गये हैं तो इस दशा में सभार निर्देशांक (Weighted Index Number) का निर्माण निम्नं प्रकार होगा:—

तालिका २ ——
सभार निर्देशांक का उदाहरए

व्यय सम्बन्धी मूल्य सम्बन्धी वस्तुएँ भार 3=3.8 १६५३ 3838 300 3,500 चावल 800 ३०० १२ १,२०० गेहूँ 800 १० १,००० 8,000 >00 800 ሂ 200 १,००० दाल 200 २,५०० 5 कपडा १०० 300 १,६०० 600 कोयला ४ १०० 800 .з 003 दूघ 800 300 300 १३,५०० ४२ ४,२०० याग 003.8 کرہ بخ ग्रोचन ३१६.६ 800 358.8

परिवर्तन + २२१ ४

इस दशा में सभार निर्देशांक ३२१'४ है ग्रौर कीमत में २२१'४% की वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट है कि साधारण तथा सभार निर्देशांक तथा उनके द्वारा सूचित कीमत परिवर्तनों में पर्याप्त ग्रन्तर है।

उत्पर की दोनों तालिकाओं में निर्देशांक बनाने के लिए हमने समानान्तर औसत (Arithmetic Average) का ही उपयोग किया है। सरलता के कारए। यही श्रौसत श्रधिक लोकप्रिय है, परन्तु इस प्रकार के निर्देशांक पूर्णंतया सन्तोषजनक नहीं होते है, यद्यपि भारों का उपयोग करके उनकी उपयोगिता काफी बढ़ाई जा सकती है। यह श्रौसत कीमतों की वृद्धि श्रयवा उनके पतन को वास्तविक से श्रधिक दिखाने की प्रवृत्ति रखता है। इस दोष को दूर करने के लिए ग्रुगोत्तर श्रयवा ज्योमीतिक श्रौसत (Geometric Average) का उपयोग किया जाता है, परन्तु इस श्रौसत में भी यह दोष बताया जाता है कि यह पारवर्तनों के श्रंश को वास्तविक से भी कम दिखाता है। विभिन्न सांख्यिकिक विशेषज्ञों ने श्रलग-श्रलग प्रकार के श्रौसतों के उपयोग की सलाह दी है, किन्तु वास्तविकता यह है कि यद्यपि प्रत्येक श्रौसत कुछ दृष्टिकोगों से सही फल प्रदान करता है, परन्तु कुछ दिशाशों में यह दोषपूर्ण श्रवस्य रहता है।

### निर्देशांक के प्रक्रार (Types of Index Numbers)—

- (१) मुद्रा की कयः शक्ति निर्देशांक—यह तो हम देख ही चुके हैं कि प्रिष्ठकांश निर्देशांकों का उद्देश्य मुद्रा के मूल्य के तुलनात्मक परिवर्तनों को दिखाना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनके बनाने में उन सभी मदों को सिम्मिलित करना चाहिए जिनका ग्रन्तिम दृशा में उपभोग किया जाता है ग्रीर फिर इन मदों को प्रत्येक पर व्यय की गई ग्राय के ग्रनुपात में भार दिए जाने चाहिए। कठिनाई यह है कि व्यवहारिक जीवन में उपभोग की सभी वस्तुत्रों ग्रीर सेवात्रों को सिम्मिलित कर लेना सम्भव नहीं होता है, ज्ञतः भारी संख्या में प्रतिनिधि स्वरूप वस्तुत्रों ग्रीर सेवात्रों को सिम्मिलित करके ही सन्तोष कर लिया जाता है। ऐसे निर्देशांक को उपभोग निर्देशांक (Consumption Index Number) ज्रथवा जीवन निर्धाह व्यय निर्देशांक (Cost of Living Index Number) कहा जाता है। ऐसे सभी निर्देशांकों में यह दोष रहता है कि व्यक्तिगत सेवाग्रों पर किए गए व्यय को कम महत्त्व दिया जाता है। वास्तिवकता यह है कि निर्देशांकों द्वारा मुद्रा की क्रयः शक्ति का पूर्णत्या निश्चत ग्रनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
- (२) स्राय निर्देशांक (Earning Index Number)— जबिक उपभोग निर्देशांक वस्तुओं और सेवाओं के सम्बन्ध में मुद्रा की कयः शक्ति को नापने का प्रयत्न करता है, स्त्राय निर्देशांक मुद्रा की कयः शिक्त को मानव प्रयत्न की इकाइयों में नापता है। यद्यपि इस दशा में किया हुआ प्रयत्न लाभदायक होता है, परन्तु किताई यह है कि विभिन्न प्रकार के मानव की तुलना करने के लिए कोई सामूहिक माप की इकाई उपलब्ध नहीं होती है। कुछ ग्रंश तक तो दक्षता तथा चतुराई के अनुसार भार निश्चित करना सम्भव हो सकता है, परन्तु यह विधि बहुत दूर तक नहीं ले जाई जा सकती है।
- (३) श्रमिक वर्ग जीवन व्यय निर्देशांक (Working Class Cost of Living Index Numbers)—ये निर्देशाँक उन प्रमुख वस्तुझों की खेरीज कीमतों पर आधारित होते हैं जो श्रमिकों के उपभोग में साधारणतया सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार के निर्देशांकों में उपभोग निर्देशांकों से यह भेद होता है कि इनमें सेवाग्रों की कीमतों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इन निर्देशांकों के निर्माण में उपभोग की विभिन्न मदों को समुचित भार अथवा प्रभाव देना आवश्यक होता है। भारों की मात्राएँ किसी विशेषज्ञ मण्डल द्वारा सावधानीपूर्वंक निश्चत की जाती हैं। अतरों की मात्राएँ किसी विशेषज्ञ मण्डल द्वारा सावधानीपूर्वंक निश्चत की जाती हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश श्रम मन्त्रालय ने सरकारी निर्देशांकों में इस प्रकार भार निश्चत किये हैं:—भोजन ६०, किराया और भाड़ा १६, वस्त्र १२, ई धन और रोशनी द और विविध ४। इन निर्देशांकों को मजदूरियों के निश्चत करने तथा उनमें परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांकों के अनुपात में ही मजदूरियों को भी बदलने का प्रयत्न किया जाता है।

(४) थोक कीमतों के निर्देशांक (The Wholesale Price Index

Numbers)—इस प्रकार के निर्देशाङ्क आधारभूत वस्तुओं की थोक कीमतों पर

श्राधारित होते हैं। इन वस्तन्त्रों में साधारणतया कच्चे मालों की कीमतों को ही

सिमालित किया जाता है। वस्तुम्रों को या तो खाद्य सामग्री तथा भ्रन्य वस्तुम्रों में

विभाजित किया जाता है. ग्रथवा कृपक ग्रीर श्रकृषक वस्तुग्रों में । पूराने समय में इन

निर्देशांकों में भारों का उपयोग कद्भने का चलन या तो था ही नहीं. या भारों का

निर्घारण वैज्ञानिक रीति से नहीं किया जाता था, परन्त ग्रब थोक कीमतों को राष्ट्रीय श्चर्य-व्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं के तुलनात्मक महत्त्व के ग्राघार पर भार दिया जाता है। ग्रमरीकन श्रम विभाग द्वारा थोक कीमतों का जो निर्देशांक तैयार किया जाता है

वह एक प्रकार ग्रादर्श स्वरूप होता है। यह ५५० वस्तुओं की कीमतों पर ग्राधारित

होता है श्रौर उसमें भारों को वैज्ञानिक रीति से निश्चित किया जाता है।

मुद्रा की क्रयः शक्ति के परिवर्तनों को नापने के लिए बहुघा थोक कीमतों के निर्देशांकों का ही उपयोग किया जाता है। परन्तु इस दृष्टिकोए। से इन निर्देशांकों में कुछ गम्भीर दोष होते हैं। प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं:--

(१) इन निर्देशांकों में केवल त्रानिर्मित वस्तुत्रों की कीमतों को सम्मि-लित किया जाता है. परन्तु अनिर्मित वस्तुओं का आधिक जीवन में जो महत्त्व होता है उसका निर्मित अवस्था में भी बना रहना आवश्यक नहीं होता है।

(२) थोक कीमतों के निर्देशांकों में व्यक्तिगत सेवान्त्रों तथा बिक्री व्यय को सम्मिलित नहीं किया जाता है. यद्यपि उपभोक्ता के व्यय का काफी बड़ा भाग इन मदों पर खर्च होता है।

(३) ऐसे निर्देशांकों में परिवर्तनों का ऋंश ऋधिक रहता है, क्योंकि उपभोग निर्देशांकों की तुलना में इनकी मदें ग्रधिक विशिष्ट होती हैं।

उपरोक्त सभी कारगों से थोक कीमतों के निर्देशाँक मुद्रा की कयः शक्ति के पारवतनों का पूर्णतया विश्वासजनक ग्रनुमान नहीं दे पाते हैं।

निर्देशांकों के निर्माण में कठिनाइयाँ— निर्देशांकों के निर्माण में कुछ भारी कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। इन

कठिनाइयों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं :—(i) सैंद्धान्तिक कठिनाइयाँ एवं (ii) व्यवहारिक कठिनाइयां।

सैद्धान्तिक कठिनाइयाँ कई प्रकार की होती हैं—(i) भारों के निर्घारण में तथा ग्रौसतों के चुनने में भारी सावधानी की ग्रावश्यकता पड़ती है। कितना भी

प्रयत्न क्यों न किया जाय, प्रत्येक दशा में भार तथा श्रौसत का चुनाव अनुमानजनक ही रहता है। ऐसा देखने में आता है कि भारों तथा श्रौसतों के परिवर्तनों के कारए। एक सी ही कीमतों से भ्रलग-भ्रलग निर्देशांक प्राप्त होते हैं। (ii) वस्तुम्रों की मात्राम्रों क ानवाचन में भी कठिनाई होती है। यदि ग्राघार वर्ष में निहिचत की गई मात्राग्री का ही उपयोग किया जाता है तो परिस्ताम ठीक ही निकलते हैं, परन्तु यदि किसी निश्चित वर्ष की मात्रास्रों के स्नाधार पर भूतकालीन वर्ष के लिए निर्देशांक बनाये जाते हैं तो दूसरा ही परिखाम प्राप्त होता है। (iii) निर्देशांकों के बनाने में वस्तुम्रों श्रीर सेवाग्रों के एक पूर्व निश्चित महत्त्व को लिया जाता है, परन्तु रुचियों के परिवर्तन के काररा उपयोग की वस्तुएँ तथा उनके महत्त्व के ग्रंश रहते हैं। कितनी ही पुरानी वस्तुएँ समाप्त हो जाती हैं भ्रौर पूर्णातया नई वस्तुएँ उत्पन्न हो जाती हैं. जो भ्राधिक जीवन में महान् महत्त्व प्राप्त कर सकती हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मार्शल ने श्रृङ्खलाकारी निर्देशांक (Chain Index) के उपयोग का सुफाव दिया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष की कीमतों की उससे अगले वर्ष की कीमतों से तुलना की जाती है। इस तुलना में ऐसी वस्तुग्रों की कीमतों को सम्मिलित नहीं किया जाता है जो दोनों वर्षों के उपभोग में सिम्मलित नहीं होती हैं। उपभोग के परिवर्तनों के अनुसार प्रति वर्ष भारों की मात्राओं में भी आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं। किसी दिये हुए वर्ष की कीमतें उससे पिछले वर्ष की कीमतों से सम्बन्धित की जा सकती हैं। उपभोग सम्बन्धी परिवर्तनों को घ्यान में रखते हुए निर्देशांक वनाने की सबसे उपयुक्त विधि यही हो सकती है, परन्तु यह प्रएाली भी दोष-विमुक्त नहीं है। यह प्रगाली इस मान्यता पर ग्राधारित है कि खरीददारी (क्य) के वार्षिक परिवर्तन लगभग ग्रर्थहीन होते हैं, जबिक कालान्तर में उन परिवर्तनों का सामूहिक परिशाम काफी महत्त्वपूर्ण होता है।

व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी अनेक हैं—(i) आधार वर्ष का चुनाव ही कठिन होता है, क्योंकि सामान्य भ्राधिक परिस्थितियों के भ्रतिरिक्त इस वर्ष में विभिन्न वस्तुओं की कीमतों के बीच सामान्य सम्बन्ध भी होना चाहिए। (ii) हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन वस्तुओं की कीमतों की तुलना की जा रही है वे सभी प्रकार समान हों। वस्तु का नाम ही पर्यात नहीं होता है। एक ही नाम की वस्तुओं में विभिन्न कालों में भारी भिन्नता हो सकती है और वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन तो बरावर होते ही रहते हैं। (iii) ठीक इसी प्रकार कीमतों का निर्वाचन भी सरल नहीं होता है।

#### सारांश—

स्पष्ट है कि निर्देशांक इनाने में अनेक सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयाँ पड़ती हैं, जिससे सच्चे निर्देशांक तैयार नहीं हो पाले और फल यह होता है कि मूल्य-परिवर्तनों को ठीक ठीक नहीं नापा जा सकता। राबर्टसन के शब्दों में:—"मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों को ठीक ठीक नाप लेना न तो सैद्धान्तिक दृष्टि से ही सम्भव है और न व्यवहार में ही। इतना अवश्य है कि यदि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होते हैं और काफी सावधानी बर्ती जाती है तो प्रत्यक्ष उपयोग के लिए उसकी माप ठीक रीति से

की जा सकती है। '' प्रो० मार्शन ने भी कहा है: — "क्रय शक्ति की निश्चित माप केवल ग्रसम्भव ही नहीं है, बिल्क ग्रविचारणीय भी है।' कि निश्चेंशांक बहुवा ग्रनुमान-जनक होते हैं ग्रौर क्योंकि वे सामान्य प्रकृति को सूचित करते हैं, व्यवहारिक जीवन में उनको बहुत ग्रधिक महत्त्व देना ठीक न होगा। ये श्रङ्क केवल श्रस्पष्ट रूप में ही हमारा ध्यान श्रार्थिक परिवर्तनों की केन्द्रीय प्रवृत्ति की श्रोर श्राक्षित करते हैं। वास्तव में ग्राधिक जीवन का कलेवर बड़ा जिंदल है ग्रौर उसको निर्देशांक जैसी सरल विधि से पूर्णतया समक्ष लेना किन होता है।

# निर्देशांकों के उपयोग अथवा लाम-

निर्देशांकों को ऋार्थिक जगत का दबाव नापने का यन्त्र (Economic Barometer) कहा जाता है। इनकी सहायता से सभी आर्थिक घटनाओं के जोर को नापा जा सकता है। इनके लाभ निम्न प्रकार हैं:—

- (१) जीव न-स्तर का सूचक—इनके द्वारा हम मुद्रा की क्रयः शक्ति के घटने-बढ़ने का एक सामान्य परन्तु व्यवहारिक अनुमान लगा सकते हैं, जिसकी सहायता से देश में समाज के जीवन-स्तर का पता लगाया जा सकता है और उसकी उन्नति के उपाय सोचे जा सकते हैं।
- (२) श्रौद्योगिक शान्ति की स्थापना में सहायक—जीवन निर्वाह व्यय सम्बन्धी निर्देशांकों की सहायता से यह पता लगाया जा सकता है कि देश में वास्तिक मजदूरी घट रही है श्रथवा बढ़ रही है श्रौर किस श्रमुपात में। इसके द्वारा मजदूरों के श्रसन्तोष को दूर किया जा सकता है, श्रौद्योगिक शान्ति स्थापित की जा सकती है श्रौर श्रमिक की कार्य-कुशलता बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि श्रावश्यकता के श्रमुसार मजदूरी श्रौर जीवन निर्वाह व्यय के बीच समायोजन किया जा सकता है।
- (३) उद्योगों की उन्नति—उत्पादन सम्बन्धी निर्देशांक यह बता देते हैं कि कौन से उद्योग उन्नति कर रहे हैं और कौन-कौन से उद्योगों को प्रोत्साहन भ्रथवा आर्थिक सहायता देने की भ्रावश्यकता है।
- (४) मौद्रिक नीति की सफलता—मौद्रिक नीति को सफल बनाने में भी इनसे अधिक सहायता मिलती है।
- ( ध्र ) ऋगों के भुगतान में सुविधा—स्थगित भुगतानों ग्रथवा दीर्घकालीन ऋगों के भुगतानों में भी इनके द्वारा न्यायशीलता, समता तथा सन्तुलन स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि क्रयः शक्ति के परिवर्तनों का सामान्य रुख जाना जा सकता है।
- (६) व्यापारी के लिए उपयोगिता—विदेशी व्यापार से सम्बन्धित निर्देशांकों से विदेशी व्यापार के शोधनाशेष के सन्तुलन में सहायता मिलती है।

<sup>\* &</sup>quot;A perfectly exact measure of purchasing power is not only unattainable but even unthinkable."

### व्यापारी के लिए उपयोगिता—

प्रो० फिशर ने ठीक ही वहा है:— "वस्तुओं का कीमत-स्तर स्थाई रखने तथा व्यापार में स्थिरता और स्थाईपन स्थापित करने के लिए निर्देशांक बहुत ही उपयोगी हैं। इनकी सहायता से ग्राथिक, व्यापारिक तथा वित्त सम्बन्धी सभी समस्याओं के समभूते में ग्रासानी होती है।" हम सरलतापूर्वक यह जान लेते हैं कि व्यापार का क्या रख है। पूँजी की गतिशीलता का क्या हाल है ग्रीर लाभ-हानि सम्बन्धी स्थिति किस प्रकार है? एक व्यापारी के लिए ये बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि व्यवसायिक वर्ग का मुद्रा की क्या शक्ति के परिवर्तनों से ग्रत्यधिक घनिष्ट सम्बन्ध होता है। इसी वे उत्पर उसका लाभ, उसकी हानि तथा उसकी व्यवसायिक नीति ग्राधारित होती है मजदूरों के साथ भगड़े निबटाने में भी इनसे सहायता मिलती है, क्योंकि वास्तविव मजदूरों के परिवर्तनों को भली भाँति जाना जा सकता है। दो विभिन्न कालों तथ स्थानों में होने वाले लाभों की तुलना करने में भी ये उपयोगी होते हैं। सट्टा बाजा के तो निर्देशांक प्राणा ही होते हैं। सट्टा बाजार का संगठन ही कीमतों के परिवर्तनं के ग्राधार पर होता है।

# राजनीतिज्ञ और सरकार के लिए उपयोगिता—

एक राजनीतिज्ञ के लिए भी निर्देशांक ग्रधिक उपयोगी होते हैं। इनकी सहा यता से देश की ग्राधिक स्थिति को समभा जा सकता है ग्रौर सरकार की ग्राधिक नीति की रचनात्मक ग्रालोचना की जा सकती है। सरकार को भी इनके द्वारा देश कं ग्राधिक स्थिति के परिवर्तनों का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मुद्रा के मूल्य जीवन निर्वाह व्यय ग्रौर उत्पादन व्यय के ग्राधार पर राज्य की कर नीति का निर्मार होता है। सरकार जब ग्राधिक नियोजन के सम्बन्ध में सोचती है तो उसे निर्देशांव से ग्रत्यधिक सहायता मिलती है। निर्देशांक देश के ग्राधिक जीवन की भूतकालीन तथ वर्तमान स्थिति का ज्ञान करा कर योजनाबद्ध विकास के लिए उपयुक्त मार्ग दर्शांते हैं निर्देशांक ग्राधिक परिवर्तनों का ज्ञान दिला कर समाज के सभी वर्गों की सेव करते हैं।

# निर्देशांकों की सीमायें—

ग्रत्यन्त उपयोगी होते हुए भी निर्देशांकों के कुछ महत्त्वपूर्ण दोष सीमार्थे हैं:—

- (१) अन्तर्राष्ट्रीय तुलना सम्भव नहीं है—निर्देशांकों के ब्राघार अल अलग देशों में अलग अलग होते हैं, अतः इनकी सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय तुलना कर सम्भव नहीं होता।
- (२) समय का अन्तर—समय का अन्तर हो जाने पर निर्देशांकों । सहायता से तुखना करना कठिन हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के उपभोग की आह सदा बदलती रहती हैं, जैसे कुछ वर्ष पहले टाई का साधारण रिवाज था, लेकिन इ

वह बहुत कम हो गया है। ग्रतः पुरानी उपभोग वस्तु ग्रों के ग्राधार पर बने निर्देशां को की तुलना उन निर्देशांकों से करना उचित नहीं होता. जो कि नवीन उपभोग वस्तुओं के आधार पर बनाये गये हों।

(३) सीमित उपयोग - निर्देशांक प्रायः किसी विशेष उद्देश्य को लेकर बनाये जाते हैं। श्रतः उनका उपयोग किन्हीं श्रन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जा सकता, वरना घोला होने का भय है। जैसे म्राध्यापकों की म्राधिक स्थिति का पता लगाने के हेतु बनाये गए निर्देशांकों से मजदुरों की आर्थिक दशा का अनुमान नहीं लग सकता।

(४) बिल्कुल सत्य परिगाम का सभाव - निर्देशांकों में गींगत जैसी शुद्धता नहीं पाई जाती, किन्तू 'समीपता' का ग्र्ण अवश्य होता है अर्थात् निर्देशांकों के परिगाम केवल 'लगभग सत्य' ही होते हैं।

(४) भार देने का दोष—सभार निर्देशांकों में भार देने का कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं है। भारों की ठीक-ठीक जानकारी न होने से निर्देशांक भी सही परिगाम प्रस्तुत नहीं करते हैं।

(६) फूटकर मूल्य निर्देशांकों का ग्रभाव—प्रायः निर्देशांक थोक मूल्यों के ग्राधार पर बनाये जाते हैं, क्योंकि इनकी जानकारी सरलता से उपलब्ध होती है। लेकिन व्यावहारिक जीवन में फुटकर मृत्य पर बनाये गए निर्देशांकों की ग्रावश्य-कता भी पड़ती है। फुटकर मूल्यों की जानकारी में बहत कठिनाई होने से थोक मुल्य वाले निर्देशांकों से काम चलाया जाता है, जिससे परिस्माम भ्रमात्मक होने का भय रहता है।

इतनी कठिनाइयों व सीमाग्रों के होते हुयै भी यह मानना पड़ेगा कि मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों को नापने का इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है। तिनक सावधानी रखने पर इनके दोष काफी सीमा तक दूर हो सकते हैं।

#### QUESTIONS

1. Write a note on-Index Numbers.

सारांश-

- (Agra, B. A., 1958, 57, 55 Supp. and 55; B. Com., 1959;
- Raj., B. A., 1954; Jabalpur, B. A., 1958; Alld., B. A., 1955) What are Index Numbers and how are they prepared? Show 2. how Index Numbers can be used to measure changes in the yalue of money?

(Agra, B. A., 1956 Supp:)

# २१८ ]

- 3. What are simple Index Numbers? How are they constructed? Give their uses. (Agra, B. A., 1954)
- 4. Explain the nature, construction and uses of Index Numbers of prices. (Agra, B. Com., 1957)
- 5. Explain the purpose and method of preparing Index Number. What is 'weighted index number' and why is it prepared?

  (Agra, B. Com., 1956 Supp.)
- 6. Discuss the importance and purpose of weighting in constructing Index Numbers (स्चनांक या निदंशांक) and indicate the practical difficulties in the way. (Raj., B. Com., 1958)
- 7. What is an Index Number (स्चनांक या निर्शांक)? Examine the difficulties experienced in measuring changes in the value of money with the help of Index Numbers.

(Raj., B. Com, 1956)

- 8. What do you understand by Index Number? How are they prepared? Explain their uses in the study of economic problems. (Sagar, B. A., 1958)
- 9. देशनांक क्या हैं ! सामान्य देशनांक श्रनुगणन करने की विधि (Method of Constructing) समभाइये। (Alld., B. A., 1956)
- 10. What do you mean by the General Price Level? How do you measure changes in it? (Bihar, B. A., 1951)

### अध्याय १२

# बैंक और उसके कार्य

(Bank and its Functions)

# BANK AND ITS FUNCTIONS

# वैंक की परिभाषा-

बैंक एक ऐसा शब्द है जिससे दैनिक जीवन में हम सभी परिचित हैं, परन्तु प्रन्य साधारएं शब्दों की भाँति इसकी परिभाषा में भी अनेक कठिनाइयाँ हैं। इस शब्द की भी अर्थशास्त्र में बहुत सी परिभाषाएँ प्रचलित हैं। श्रेंग्रेजी का बैंक शब्द जर्मन शब्द बैंक (Back) से बना है, जिसको इटेलियन भाषा में बैंको (Banco) कहा जाता है।

- (१) श्रॉक्सफोर्ड शब्द-कोष के श्रनुसार:—''बैंक एक ऐसा कार्य-ग्रह है जो श्रपने ग्राहकों से प्राप्त श्रयवा उनकी श्रोर से घन का संरक्षण करता है। इसका मुख्य कार्य उनके द्वारा बैंक पर निकाले हुये श्रादेशों का शोधन करना होता है। इसके लाभ उस घन के उपयोग [द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसका बैंक के ग्राहक उपयोग नहीं करते हैं।''
- (?) सेयर्स ( $S_{ayers}$ ) के विचार में :—''बैंक वह संस्था है जिसके ऋगों को दूसरे व्यक्तियों के पारस्परिक भुगतान में विस्तृत मान्यता प्राप्त हो।''
- (३) बेंक शब्द की परिभाषा सर्वं प्रथम इङ्गलेंड के विनिमय दिल विधान सन् १८८२ में की गई थी, जो संशोधित रूप में इस प्रकार है—''वेंक शब्द में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी को सिम्मिलित किया जाता है जिसके पास ऐसा व्यवसाय स्थान है जहाँ पर निक्षेप अथवा मुद्रा संग्रहणा द्वारा साख खोली जाती है और जिसका भुगतान विकर्ष, धनादेश अथवा आदेश द्वारा होता है अथवा जहाँ स्कन्ध आदि की आड़ पर मुद्राएँ अथवा ऋगा दिए जाते हैं।''

(अ) भारतीय वैंकिंग कम्पनीज एक्ट सन् १९४६ में बैंक की परिभाषा

<sup>1. &#</sup>x27;An establishment for the custody of money received from or on behalf of its customers. Its essential duty is to pay their drafts on it; its profits arise from the use of the money left unemployed by them.'—The Shorter Oxford English Dictionary.

<sup>2. &#</sup>x27;In a Bank, we include every person, firm or company having a place of business where credits are opened by deposits or collection of money or currency, subject to be paid or remitted on drafts, cheques or orders or money as advanced or loaned on stocks, etc.'

नम्न प्रकार की गई है—-''बैंकिंग कम्पनी वह कम्पनी है जो बेंकिंग का कार्य करती

वैकिंग का अभिप्राय जनता से उधार देने के लिए अथवा विनियोग करने के लए मुद्रा के निक्षेपों का स्वीकार करना है, जो माँग पर अथवा किसी अन्य प्रकार ।नादेश, विकर्ष, आदेश आदि द्वारा शोधनीय होते हैं।"

- (५) इसी प्रकार टाउजिंग का मत है—''बैंक विनियोगों तथा बचतों के ांग्रह के ग्राढ़ितयों का काम करती हैं, वे विनिमय के माध्यम के एक भाग का निर्माण रती हैं।''
- (६) हार्ट के अनुसार :—''बैंकर वह व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यवसाय के अन्तर्गत लोगों का रुपया जमा करता है, जिसे वह उन व्यक्तियों के घनादेशों का धुगतान करके चुकाता है जिन्होंने यह रुपया जमा किया है, अथवा जिनके खाते में यह स्पया जमा किया गया है।'' र
- (७) किनले ने बेंक की परिभाषा इस प्रकार की है:—''बैंक एक ऐसी तंस्था है जो ऋगा की सुरक्षा को घ्यान में रखते हुये ऐसे व्यक्तियों को रुपया उधार देती है जिन्हें उसकी आवश्यकता है और जिसके पास व्यक्तियों द्वारा अपना फालतू हपया जमा किया जाता है।''<sup>3</sup>
- ( द ) सबसे विस्तृत परिभाषा जोन पेजेट ने की है। उनका विचार है
  "कोई भी व्यक्ति ग्रथवा संस्था तब तक वैंकर कहलाने का ग्रधिकारी नहीं है जब तक
  कि वह:—(१) निक्षेप खाते स्वीकार नहीं करता है, (२), चालू खाते में राया जमा
  नहीं करता है (३) धनादेशों की निकासी ग्रीर ग्रपने ऊपर लिखे हुये धनादेशों का
  भुगतान नहीं करता है, (४) ग्रपने ग्राहकों की ग्रीर से रेखाँकित (Crossed) ग्रीर
  बिना रेखाँकित धनादेशों का रुपया एकत्रित नहीं करता है—ग्रीर शायद यह कहना
  ग्रमुपयुक्त न होगा कि यदि किसी व्यक्ति ग्रथवा संस्था द्वारा उपरोक्त सभी कार्य किए
  जाते हैं तो उसका उस समय तक वैंकर होना ग्रावश्यक नहीं है जब तक कि वह निम्न
  शतें पूरी न करता हो:—(१) बैंकिंग उसका ज्ञात व्यवसाय हो, (२) जनता के
  सम्मुख वह ग्रपने बैंकर ग्रथवा बैंक होने की घोषणा करे ग्रीर जनता उसे इसी रूप में
- 1. "The accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public repayable on demand or otherwise and withdrawable by cheque, draft, order or otherwise."—
  The Indian Banking Companies Act, 1949.
- 2. "A banker is one who, in the ordinary course of his business, receives money which he repays by honouring cheques of persons from whom or on whose account he receives it."—Hart
- 3. "Bank is an establishment which makes to individuals such advances of money as may be required and safely made and to which individuals entrust money when not required by them for use."

  -Kinlay

समभती हो, (३) इस प्रकार के व्यवसाय से उसका घनोपार्जन का इरादा हो, (४) यह व्यवसाय उसका गौए। व्यवसाय न हो, बल्कि मुख्य व्यवसाय हो। '' "

- ( ६ ) गाटियर नामक एक दूसरे ग्रथंशास्त्री ने बंक की एक लम्बी-चौड़ी परि-भाषा की है। उनके मनुसार:—''बंक शब्द द्वारा ऐसा व्यवताय सूचित होता है जिसमें दूसरों की ओर से जमा ग्रौर भुगतान करना, सोने ग्रौर चाँदी की मुद्रा, विनि-मय विपत्र ग्रौर विकर्ष (Drafts), सार्वजनिक प्रतिभूतियाँ ग्रौर ग्रौद्योगिक उपक्रमों के ग्रंशों—सारांश में—इस प्रकार की सभी देनों का बेचना ग्रौर खरीदना सम्मिलित है जो राज्य, समाज ग्रथवा व्यक्तियों द्वारा साख के उपयोग से पैदा होती हैं।'' श
- (१०) फिन्डले शिराज के अनुसार "बैंकर वह व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी है जिसके पास कोई ऐसा व्यापार स्थान हो जहाँ मुद्रा अथवा चलन की जमा द्वारा साख का कार्य किया जाता है और जिसकी जमा का ड्राप्ट, धनादेश अथवा आदेश द्वारा भुगतान किया जाता हो अथवा जहाँ स्टॉक्, बांड, घातु तथा विपन्नों पर मुद्रा उधार दी जाती हो अथवा जहाँ प्रतिज्ञा-पत्र बट्टे पर अथवा बेचने हेतु लिए जाते हों।" विककर्ष—

इसी प्रकार बैंक की और भी बहुत सी परिभाषाएँ दी गई हैं। सभी परि-भाषाओं के देखने से पता चलता है कि इनमें परिभाषा के स्थान पर वर्णन को अधिक महत्त्व दिया गया है। प्रत्येक लेखक ने उन कार्यों अथवा उन व्यवसायों को गिन-

- 1. "No one and nobody, corporate and otherwise, can be a banker who does not:—(i) take deposit account, (ii) take current accounts, (iii) issue and pay cheques drawn upon himself, (iv) collect cheques crossed and uncrossed for his customers—and it might be said that even if all the above functions are performed by a person or body corporate, he or it may not be a banker or bank unless he or it fulfils the following conditions: (i) banking is his or its known occupation, (ii) he or it may profess to be a banker and the public takes him or it as such, (iii) has an intention of earning by doing so, (iv) this business is not subsidiary."—John Paget
- 2. "The word bank expresses the business which consists in effecting on account of others receipts and payments, buying and selling either money or gold and silver or letters of exchange and drafts, public securities and shares in industrial enterprises—in a word—all the obligations whose creation has resulted from the use of credit on the part of states and societies and individuals."
- -Gautier

  3. "A banker is a person, firm or company having place of business where credits are opened by the deposit or collection of money or currency, subject to be paid or remitted upon draft, cheque, order or where money is advanced or loaned on stocks, bonds, bullion and B/E and P/N are received for discount and sale."

  Findlay Shirras

वाने का प्रयत्न किया है जो एक बैंकर ग्रथवा बैंक के लिए ग्रावश्यक हैं। ग्रधिकाँ व परिभाषाओं कों जिटलता भी है, जिसके कारण बेंक जैसी साधारण श्रीर सर्व-परिचित संस्था का समक्तना भी किठन हो जाता है। तर्क के दृष्टिकोण से भी ग्रधिकां ज परिभाषायें दोषपूर्ण हैं। ग्रावश्यकता इस बात की है कि बेंक की कोई ऐसी परिभाषा दी जाय जिससे उसे सरलता के साथ पहिचाना जा सके ग्रीर साथ ही उसकी प्रमुख विशेषतायें भी स्पष्ट हो जायें।

र्वैंक की एक सरल परन्तु सही परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं :-''वैंक उस व्यक्ति अथवा संस्था को कहते हैं जो मुद्रा ऋौर साख में व्यवसाय करती है। 23 % इस परिभाषा में मुद्रा ग्रीर साख के व्यवसाय का ग्रर्थ समभ लेना ग्रावश्यक है। जब हम यह कहते हैं कि ग्रमुक व्यक्ति ग्रमुक वस्तु में व्यवसाय करता है तो हमारा श्रभिप्राय यह होता है कि वह व्यक्ति इस वस्तु को खरीदता ग्रौर बेचता है, परन्तु क्या मुद्रा तथा साख को भी इस प्रकार खरीदा भ्रौर बेचा जा सकता है ? मुद्रा के बेचने ग्रथवा खरीदने का ग्रथंशास्त्र में एक विशेष ग्रथं होता है। मुद्रा के बेचने का ग्रथं उसका ऋगा देना होता है ग्रौर इसी प्रकार मुद्रा को खरीदने का ग्रभिप्राय उसके ऋगा लेने से होता है। दोनों ही दशाग्रों में मुद्रा की कीमत ब्याज के रूप में चुकाई जाती है। इस प्रकार बैंक का कार्य ऋ गों का लेना ग्रीर उनका प्रदान क्रना होता है। परन्तु ऋगा तो लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा लिए-दिए जाते हैं तो फिर क्या सभी व्यक्ति बैंक हैं ? वास्तव में बात ऐसी नहीं है । बैंक की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता साख का कय-विकय करना होती है । यह तो हम एक ग्रगले भ्रध्याय में देखेंगे कि बैंक किस प्रकार साख का निर्माण करती है। यहाँ हमारा सम्बन्ध केवल इस महत्त्वपूर्ण सत्य से है कि बैंक भ्रपने ग्राहकों की साख को खरीदती है भ्रौर भ्रपनी साख उन्हें बेच देती है। इसी कारण यह कहा जाता है कि वैंक का भ्रावश्यक कार्य भ्रपनी साख का भ्रपने ग्राहकों की साख में हस्तान्तरण करना होता है। साख के व्यवसाय का यही अर्थ होता है।

यह कार्य इस कारण होता है कि बैंक द्वारा दिया गया प्रत्येक ऋण निक्षे पों को भी उत्पन्न करता है (Loans create deposits)। जब कोई बैंक ऋण देती है. तो अपनी साख उत्पन्न करती है, इन ऋणों द्वारा जिन निक्षेपों का निर्माण होता है वे ऋण लेने वालों अर्थात् बैंक के प्राहकों की साख का निर्माण करती हैं। जब कोई निक्षेपधारी बैंक के उत्पर धनादेश लिखता है और जब धनादेश भुगतान के लिए बैंक को प्रस्तुत किया जाता है तो ग्राहक की साख को बैंक की साख म बदला जाता है और इसी प्रकार साख का हस्तान्तरण होता है।

# वैंक श्रौर साधारण साहकारों में भेद—

स्मरण रहे कि साख व्यवसाय बैंक का एक विशेष गुण है। सभी महाजन अथवा साहूकार मुद्रा में व्यवसाय करते हैं, क्योंकि वे ऋण लेते भी हैं स्रोर देते भी

Dank is an institution dealing in money and credit.

हैं, परन्तु वे साख का क्रय-विक्रय नहीं कर सकते है। साख का क्रय-विक्रय वैंक की ही विशेषता हैं। इस प्रकार वेंक तथा साधारण साहूकारों में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर होता है। इस यह तो कह सकते हैं कि प्रत्येक वेंक साहूकार का काम करती है, परन्तु प्रत्येक साहूकार को वैंकर नहीं कहा जा सकता है। वेंक की विशेषता जमा को स्वीकार करना है, जो उसकी कम्पंवाहक पूँजी का एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग होती है। साख में व्यवसाय करना वेंक की प्रमुख विशेषता होती हैं।

# श्राधुनिक वैंकों के कार्य तथा सेवायें—

सामान्य रूप में एक ग्राधुनिक बैंक के प्रमुख कार्यों को निम्न प्रकार बताया जा सकता है:—

- (१) निक्षेपों को स्वीकार करना अथवा ऋगा लेना (Acception of Deposits)—यह प्रत्येक आधुनिक बैंक का महत्त्वपूर्ण कार्य है। अपने अंशों की निकासी करके तथा विभिन्न प्रकार के निक्षेप स्वीकार करके बैंक व्यक्तियों तथा फर्मों के फालतू घन को अपने पास जमा करने का प्रयत्न करती है। व्यवसायिक क्रिय में एक बैंक का मान साधारणतया इसी बात पर निर्भर होता है कि उसकी अध्या अथवा निक्षेप प्राप्त करने की शिक्त कितनी हैं अंशों की बिक्री तथा निक्षेपों की स्वी कृति के अतिरिक्त बैंक विनिमय बिल भुना कर, बैंक नोट निकाल, कर बाँड निकाल कर, ऋण-पत्र तथा रोक प्रमाण पत्र जारी करके भी घन प्राप्त करती हैं, परन्तु बैंकों के अधिकाँश ऋण निक्षेपों के ही रूप में होते हैं। भारत में ऐसे निक्षेप विशेषकर पाँच प्रकार के होते हैं—निश्चितकालीन निक्षेप, सेविंग बैंक निक्षेप, चालू निक्षेप, अनिश्चितकालीन निक्षेप तथा गृह बचत खाता।
- (क) निश्चितकालीन निक्षेप—ऐसे निक्षेपों का ग्रभिप्राय उन निक्षेपों से होता है जिनका भुगतान केवल एक निश्चित ग्रविध के पश्चात जो तीन मास से ५ वर्ष तक की होती है, हो सकता है, परम्तु ग्रपने ग्राहकों की सुविधा के लिए कटौती काट कर बैंक ऐसे निक्षेपों को समय से पहले निकाल लेने की भी ग्राज्ञा दे देती है। ऐसे निक्षेपों के लिए बैंक द्वारा रसीद दी जाती है, जो विनिमय' साध्य (Negotiable) नहीं होती है, ग्रयीत जिसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं भुनाया जा सकता है। ऐसे निक्षेपों पर ब्याज की दर साधारणतया ऊँची होती है, क्योंकि बैंक को एक निश्चित ग्रविध तक उनके निकाल जाने की चिन्ता नहीं होती है।
- (ख) सेविंग बैंक निक्षेप—यह जमा साधारणतया उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होती है जो कभी-कभी पैसा जमा करना चाहते हैं और वह भी छोटी-छोटी मात्राओं में। निक्षेपदाता जमा तो कभी भी कर सकता है, परन्तु उसे एक सप्ताह में केवल एक या दो बार रुपया निकालने का अधिकार होता है। ऐसे निक्षेपों के लिये जमा करने वाले को 'पास बुक' ( $Pass\ Book$ ) दी जाती है, जो उस पर अथवा

धनादेश द्वारा रुपया निकाल सकता है। ऐसी जमा पर निश्चितकालीन जमा की अपेक्षा कम ब्याज दिया जाता है।

- (ग) चालू निक्षेप—ऐसी जमा की विशेषता यह होती है कि जमा करने वाला अपनी इच्छानुसार कभी भी अपने खाते में रुपया जमा कर सकता है, अथवा उसमें से रुपया निकाल सकता है। रुपया चैंक द्वारा निकाला जा सकता है। ऐसी जमा पर अच्छी बेंक साधारएतया कुछ भी ब्याज नहीं देती हैं, बिल्क बहुत बार तो उल्टा प्रबन्ध का व्यय ग्राहक से वसूल किया जाता है, परन्तु कभी-कभी बहुत कम दर पर ब्याज भी दिया जाता है। ऐसी दशा में बेंक बहुधा यह अनुरोध करती है कि जमा की मात्रा एक निश्चित राशि से नीचे न गिरने पाये। जमा के इस राशि से कम हो जाने की दशा में अन्तर पर ब्याज लिया जाता है।
- (घ) ग्रिनिश्चितकालीन निक्षेप—यह जमा बहुत लोकप्रिय नहीं है ग्रौर बैंक के व्यवसायिक जीवन में इसका महत्त्व कम ही रहता है। इसके ग्रन्तगंत जो रुपया जमा किया जाता है वह कुछ विशेष दशाग्रों को छोड़कर कभी भी निकाला नहीं जा सकता है, केवल उसके ब्याज की राशि को ही निकालना सम्भव होता है। इस जमा पर ब्याज की दर सबसे ऊँची होती है, क्यों कि बैंक जमा की गई राशि का दीर्घ-कालीन तथा स्थायी विनियोग कर सकती है।
- (ङ) गृह बचत खाता (Home Saving Account)—इसका वलन थोड़े ही काल से लोकप्रिय हुआ है। इसके अनुसार बैंक जमा करने वाले के घर पर एक गुल्लक (Safe) रख देती है, जिसमें वह समय-समय पर अपनी छोटी-छोटो बचत को डालता है। समय-समय पर सेफ को बैंक में ले जाया जाता है, जो उसे खोलती है और एकत्रित राशि को जमा करने वाले के खाते में जमा कर देती है। यह बचत को प्रोत्साहन देने की एक अच्छी विधि है। ऐसी जमा पर ब्याज नाम-मात्र ही होती है।
- (२) ऋगों का प्रदान करना—बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ऋगों प्रथवा ग्रिप्रमों (Advances) का देना है। साधारणतथा बैंक्क नकद ऋगा नहीं देती है। बैंक ऋगों को एक निश्चित सीमा तक चैंक द्वारा बैंक से घन निकालने का ग्रिष्वकार दे देती है। ऋगों से ही बैंक को ग्रपनी ग्राय ग्रथवा लाभ का ग्रिष्वकाँग भाग प्राप्त होता है। एक बैंक की योग्यता भी साधारणतया इसी बात पर निर्भर होती है कि वह ग्रपने ऋगा व्यवसायों को किस प्रकार चलाती है। ऋगों के सम्बन्ध में गलत नाति ग्रपनाना बैंक के लिये घातक हो सकता है ग्रीर ऐसी दशा में बैंक के फेल होने का भय रहता है। भारतीय बैंक्क कभी तो स्पष्ट अग्रिम (Clean advances) प्रदान करती हैं, जो व्यक्तिक ग्रतिभृति (Personal Securities) पर दिये जाते हैं, परन्तु अधिकतर ऋगा उपगुक्त तथा बिक्री-साध्य प्रतिभृतियों पर दिये जाते हैं। भारतीय बैंकों के ऋण साधारणतया निम्न चार छपों में होते हैं—

- (श्र) नकद साख (Cash Credit)—यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बंक अपने ग्राहक को बांड अथवा अन्य प्रतिभूतियों के ग्राधार पर एक निश्चित मात्रा तक ऋगा लेने का अधिकार देती है। भारतीय व्यवसायी ऋगा लेने की इस प्रगाली को ग्रिधिक पसन्द करते हैं, क्यों कि इसमें ऋगा की सारी राशि को एक दम निकाल लेने की ग्रावश्यकता नहीं होती है। आवश्यकतानुसार समय समय पर ऋगा लेने वाला ग्रावश्यक राशि निकालता रहता है। इस व्यवस्था में साधारणतया एक निश्चित समय के लिए बैंक ग्राहक की ऋगा सम्बन्धी ग्रावश्यकता का ग्रनुमान लगा कर उसको पूरा करने के लिए ग्रावश्यक धन रखती है, इसलिये बैंक को उस राशि पर ब्याज की हानि होती है जो ग्राहक द्वारा नहीं निकाली जाती है। इस हानि से बचने के लिये वैंक बहुधा बिना खर्च की हुई राशि पर भी ग्राहक से पूरी या ग्राधी दर पर ब्याज लेती है।
- ्(ब) अधि-विकर्ष (Over-draft)—यह सुविधा वैंक द्वारा अपने निक्षेप-दाताओं को अल्पकालीन अग्निम के रूप में दी जाती है। चालू खाते में ग्राहक का जितना रुपया जमा है उससे भी कुछ प्रधिक राशि , निकालने का अधिकार ग्राहक को दे दिया जाता है, यद्यपि इसके लिये उचित प्रतिभूति ली जाती है। ग्राहक समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार इस अधि-विकर्ष सुविधा का लाभ उठाता रहता है और उसे एक ही बार सारा ऋगा निकाल लेने की आवश्यकता नहीं होती है। नकद साख और अधि-विकर्ष अग्निमों में वेवल इतना अन्तर होता है कि अधि-विकर्ष सुविधा अल्प-कालीन होती है, जो केवल रुपया जमा करने वालों को ही दी जाती है, परन्तु नकद साख प्रगाली का बहुत विस्तृत उपयोग होता है और बैंक का कोई भी ग्राहक इसका लाभ उठा सकता है।
- (स) ऋर्गे—यदि बेंक एक मुश्त रुपया उधार देती है, जिसे पूर्ण रूप में चुकाये बिना ऋरण का ग्रन्त नहीं होता और पूरा चुकाने पर ऋरण का पूर्णतया ग्रन्त हो जाता है तो उसे ऋरण कहा जाता है। स्मरण रहे कि ऋरण कभी भी चालू नहीं रहता है। यदि ऋरणी उसके एक भाग को चुका कर फिर से उधार लेना चाहता है तो यह तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक कि बेंक एक दूसरा ऋरण देना स्वीकार न कर ले। ऐसे ऋरणों पर बेंक के लिए ब्याज की हानि उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए साधारणतया ऋरणों पर ग्रग्निमों की ग्रपेक्षा ब्याज की दर कम रहती है। इसके ग्रतिरिक्त बेंक के लिए ऋरण खातों का सञ्चालन व्यय भी कम हो जाता है।
- (द) विनिमय विलों का भुनाना—वैंक द्वारा ऋग तथा अग्रिम प्रदान करने की यह भी एक महत्त्वपूर्ण विषि है। वैंक विनिमय विलों को भुना कर ऋग दे सकती है। ऐसे ऋग अलाकालीन होते हैं और समुचित प्रतिभूतियों पर विए जाते है। ऐसे ऋगा भी स्पष्ट (Clean) अथवा पुस्तकीय ऋगा (Book Credit) हो सकते

हैं। स्पष्ट ऋण ग्राहर्त्ता (Drawer) ग्रीर ग्राहार्यी (Drawee) के हस्ताक्षरों पर ही दे दिये जाते हैं, परन्तु पुस्तकीय ग्राग्रिमों के लिए वस्तुग्रों की उपस्थिति के किसी प्रमाण-पत्र की प्रतिभूति ग्रावश्यक होती है। विनिमय बिल की परिपक्कता ग्रविध से पूर्व ही यदि उसकी राशि की ग्रावश्यकता पड़ती है तो उसे बैंक से भुनाया जा सकता है, जिस दशा में बेंक शेष ग्रविध का ब्याज काट लेती है ग्रीर परिपक्कता पर बिल की राशि वसूल कर लेती है। यह बैंक का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है, जो व्यापारियों को भारी सुविधा देता है ग्रीर साथ ही बैंक के ग्रादेयों को भी तरल रखता है।

- (३) ग्रभिकत्ती सम्बन्धी सेवाएँ ग्रपने ग्राहकों के ग्रभिकर्ता (Agent) के रूप में बैंक ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएँ सम्पन्न करती है। इसमें से मुख्य-मुख्य निम्न प्रकार हैं:—
  - (क) साख-पत्रों के भुगतान का संग्रह ग्राहकों की स्रोर से घनादेशों, विनिमय बिलों, प्रतिज्ञा-पत्रों स्रादि का भुगतान एकत्रित करना।
  - (ख) ग्राहकों की ग्रोर से भुगतान—ग्राहकों के सभी प्रकार के भुगतान सम्बन्धी ग्रादेशों को पूरा करना, जैसे—उनकी ग्रोर से ऋएों की किश्तें, ब्याज, चन्दे, बीमे की किश्तें, कर ग्रादि चुकाना। इनके लिए बैंक साधारण सा कमीशन लेती है।
  - (ग) ग्राहकों की ग्रोर से भुगतान संग्रह करना—ग्राहक की ग्रोर से उसके ग्रादेशानुसार विभिन्न प्रकार के भुगतानों को प्राप्त करना, जैसे —लाभांश, ऋण की राशि, ब्याज श्रादि एकत्रित करना। ये कार्य बैंक कमींशन के ग्राधार पर करती है।
  - (घ) ग्राहकों की ग्रोर से उनके ग्रादेशानुसार प्रतिभूतियों का खरी-दना ग्रौर बेचना—इस कार्य के लिए वैंक ग्राहक से कमीशन नहीं लेती है, बल्कि सट्टे के दलालों से दलाली कमीशन का एक हिस्सा प्राप्त करती है। इससे ग्राहकों को लाभ रहता है।
  - (ङ) एक शाखा से दूसरी शाखा तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को कीषों का हस्तान्तरएा करना—इस सम्बन्ध मे प्राहकों को यह सुविधा दे दी जाती है कि वे एक शाखा या स्थान में रुपया जमा करके दूसरी शाखा अथवा स्थान पर भुगतान ले सकें।
  - (च) भ्रपने ग्राहकों के श्रभिकत्ता श्रथवा प्रतिनिधि के रूप में श्रन्य प्रकार के कार्य करना।
  - (छ) ग्राहकों की ग्रोर से रिक्थ-पत्रों (Wills), ट्रस्ट श्रथवा श्रादेशित संस्थाग्रों का प्रबन्ध ग्रौर वित्तीय ग्रायोजन करना।
  - (४) बैंक नोटों का निकालना यह भी बैंक का एक महत्त्वपूर्ण कार्य रहा है। मुतकाल में यह अविकार सभी बैंकों को प्राप्त था, परन्तु ग्राजकल नोट-निर्गम

का एकाधिकार केवल देश की केन्द्रीय बैंक के ही हाथ में होता है। भारत में रिजर्व बैंक श्रॉफ इण्डिया के निकाले हुए नोट चालू हैं श्रोर विधि-ग्राह्म मुद्रा हैं।

- (१) अन्य उपयोगी सेवाएँ एक आधुनिक वैंक को व्यवसायी वर्ग के लिए और भी बहुत सी उपयोगी सेवाएँ सम्पन्न करनी पड़ती हैं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है:—
  - ( अ ) बहुमूल्य धातुश्रों, जैसे—हीरे जवाहरात, प्रतिभूति, आवश्यक पत्र, इत्यादि का सुरक्षित संरक्षरा—इस कार्य के लिए बैंक्क के पास सुरक्षित कमरे तथा विशेष प्रकार की मजबूत अलमारियाँ होती हैं, जिनमें बहुमूल्य वस्तुएँ जमा कर दी जाती हैं और इन अलमारियों की चाबी जमा करने वाले को दे दी जाती हैं। बैंक्क इन वस्तुओं के सुरक्षित संरक्षरा का उत्तरदायित्त्व लेती है। इस कार्य के लिए बैंक एक विशेष कमीशन अथवा पारितोपरा लेती है, परन्तु जमा करने वाले के दृष्टिकोसा से बैंक्क की यह सेवा काफी लाभदायक होती है।
  - (व) साख प्रमाग पत्रों (Letters of Credit) का प्रदान करना— इससे ग्राहकों को दूसरे स्थानों तथा विदेशों से माल खरीदने में सुविधा रहती है। इन पत्रों के ग्राधार पर पत्रधारी की साख वनती है। ग्रज्ञात व्यापारी तथा व्यवसायी भी इसकी साख से परिचित हो जाते हैं ग्रीर साधारणतया उधार माल देने में संकोच नहीं करते हैं, विशेपकर यदि प्रमाग्-पत्र किसी ग्रच्छी बैंद्ध ने दिया है।
  - (स) ग्राहक की ग्रोर से विनिमय विल को स्वीकार करना—इससे काफी लाभ होता है, क्योंकि बिल पर बैंक का नाम देख कर ऋगु-दाता ग्रथवा माल का विक्रता ग्राहक की साख पर सरलतापूर्वक विश्वास कर लेता है। इस प्रकार विनिमय बिल पर बैंक के हस्ताक्षर हो जाने से दूसरों के द्वारा उसके स्वीकार हो जाने की सम्भावना बढ़ जाती है श्रौर ग्राहक को माल उवार मिलने में सुविधा रहती है।
  - (द) ग्राहकों, को एक दूसरे की साख के सम्बन्ध में सही तथा विश्वसनीय सूचना देना—यह सूचना बेंक बड़ी सावधानी के साथ एकत्रित करती है, परन्तु इसके द्वारा बैंक के ग्राहक को यह पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति के साथ वह व्यवसाय करना चाहता है. उसकी साख कैसी है।
  - (य) व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी सूचनाश्रों श्रौर श्राँकड़ों का इकट्ठा करना—यह सेवा बड़ी-बड़ा बैंकों द्वारा प्रतिपादित की जाती है श्रौर इस प्रकार की सचना पूछने पर ग्राहक को दे दी जाती है श्रथवा

- (फ) सरकार तथा व्यापार प्रमण्डलों के ऋगों का ग्रभिगोपन (Underwriting)—इससे इन ऋगों के प्राप्त होने में सुविधा होती है, क्योंकि ऋग-पत्रों पर बैंक के हस्ताक्षर हो जाने के कारण विश्वास उत्पन्न हो जाता है।
- (६) विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय— बेंक विदेशी मुद्राम्रों के क्रय-विक्रय द्वारा विदेशी व्यापार को भारी सहायता देती है। वैसे तो साधारणतया यह कार्य एक विशेष प्रकार की बैंकों म्रर्थात् विदेशी विनिमय बैंकों द्वारा किया जाता है, परन्तु भारत में कुछ व्यापार बैंक भी दूसरे कार्यों के साथ-साथ विभिन्न देशों की मुद्राम्रों में व्यवसाय करती हैं। विदेशी विनिमय व्यवसाय का म्रर्थ एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना होता है।
- (७) स्रान्तरिक तथा विदेशी व्यापार का सर्थ-प्रवन्ध यह भी बैंक का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। यह कार्य साधारणतया विनिमय बिलों को खरीद कर किया जाता है। हुण्डियों धौर विदेशी विनिमय बिलों की खाड़ पर भारतीय बैंक भ्रत्मकालीन भ्रप्रिम देती रहती हैं। यदि किसी व्यापारी के पास ऐसा विनिमय बिल हैं जिसकी परिपक्कता का समय दो महीने पीछे भ्रायगा, परन्तु व्यापारी को तुरन्त धन की भ्रावश्यकता होती है तो यह व्यापारी इस बिल को बैंक से भुना सकता है। बाजार दर पर दो महीने का ब्याज काट कर बिल का शेष रुपया बैंक बिल भुनाने वाले को दे देती है भ्रौर परिपक्कता का समय भ्रा जाने पर बिल की राशि का भ्रुगतान लिखने वाले से प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार बिल को भुनाने का यह परिणाम होता है कि एक भ्रोर तो व्यापारियों को भ्रावश्यकता के समय धन मिल जाता है भ्रौर दूसरी भ्रोर बैंक के लिए लाभ कमाना सम्भव हो जाता है।

#### तिष्कर्ष—

ऊपर बैक की सेवाग्रों का जो संक्षिप्त वर्णन किया गया है उससे ग्राधुनिक बैंक के महत्त्व का सही ग्रमुमान नहीं लगता है। वास्तविकता यह है कि व्यापार ग्रौर व्यवसाय सम्बन्धी लगभग कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता है जो एक ग्राधुनिक बैंक ग्रपने ग्राहकों के लिए सम्पन्न नहीं करती हैं। बैंक का कार्य सलाह देने से ग्रारम्भ होकर ग्रभिकर्ता, मित्र, प्रमाणक ग्रधिकारी तथा ऋग्-दाता तक फैला रहता है। यही कारण है कि ग्राधुनिक युग में बैंकिंग का समुचित विकास ग्राधिक उन्नति की प्रथम ग्रावश्यकता समभा जाता है, क्योंकि देश की ग्राधिक सम्पन्नता की नींव बैंकिंग के समुचित विकास पर ही रखी जा सकती है।

# वैंकिंग का आरम्भिक इतिहास—

संसार में बैंकिंग प्रणाली काफी पुरानी है। ऐतिहासिक खोज से पता चलता है कि ग्रब से लगभग २,००० वर्ष पूर्व भी बैंकिंग का व्यवसाय होता था। बेबीलोन, भारत, यूनान ग्रीर रोम चारों ही देशों में प्राचीन काल में बैंकिंग के विकास के प्रमाण मिलते हैं। बैंकिंग प्रथा के ग्रारम्भ के विषय में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले यह कार्य सराफों ग्रीर मुनारों ने ग्रारम्भ किया था। जिन लोगों के पास फालतू घन होता था वे इस घन को ग्रपने पास न रखकर सराफों ग्रथवा मुनारों के पास जमा कर देते थे, क्योंकि इससे रुपया सुरक्षित रहता था ग्रीर कुछ दशाग्रों में ब्याज के रूप में भी कुछ मिल जाता था। ये सराफ साधारएतया एक राज्य ग्रथवा स्थान की मुद्रा को दूसरे राज्य ग्रथवा स्थान की मुद्रा में बदलने का काम करते थे। जमा किये हुए रुपये के लिए ये जमा करने वालों को जमा की रसीद देते थे, क्योंकि इनका कार्य सन्देह से परे होता था ग्रीर ऊँची साख होने के कारएा जनसाधारए का इन पर विश्वास होता था, इसलिए ये रसीदें भी विनिमय साध्य (Negotiable) होती थीं ग्रीर बहुत बार ऋएों को चुनाने के लिए घन के स्थान पर उपयोग की जाती थीं। घीरे-घीरे यह प्रथा बढ़ती गई ग्रीर जमा की रसीदें ग्राधुनिक वैंक-नोटों की भाँति चलने लगीं। जमा स्वीकार करने वाले साहूकारों ने भी ग्रनुभव द्वारा यह जान लिया कि एक निश्चत काल में कुल जमा का केवल एक भाग ही जमा करने वालों द्वारा निकाला जाता था ग्रीर शेष उनके पास ऐसे ही पड़ा रहता था, ग्रतएव इन्होंने फालतू पड़े हुए जमाधन को ब्याज पर उठाना ग्रारम्भ कर दिया।

इस कार्य में सराफों को भी लाभ होने लगा और उन्होंने जमाघन अधिक मात्रा में एकतित करने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने जमा राशि पर ब्याज देकर और अधिक जमा आर्कापत करना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार ब्याज पर रुपया जमा करना और ब्याज पर रुपया उघार देना, इनका मुख्य व्यवसाय हो गया। साघारणतया जमाधन पर नीची दर पर ब्याज दिया जाता था, जिसका प्रमुख कारण सराफ की ऊँची साख थी। इसके विपरीत ऋणों पर ऊँचा ब्याज लिया जाता था। ब्याज की दर के इस अन्तर के कारण सराफ को लाभ होता था। कालान्तर में घीरे-घीरे इन सराफों ने और भी बहुत से सम्बन्धित कार्य आरम्भ कर दियै। चैक की प्रथा के विकास के पश्चात् तो इन कार्यों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई। स्मरण रहे कि ये प्राचीन साहूकार वास्तविक अर्थ में बैंकर न थे, क्योंकि वे केवल रुपया उघार देते थे और ब्याज खाने वाले महाजन थे।

सबसे पहले बैंकिंग प्रणाली ने बेबीलोन में उन्नित की । वहाँ साहूकारों के अतिरिक्त जन-साधारण भी रुपये के लेन-देन का व्यवसाय करता था। बेबीलोन की अति प्राचीन इजिबी बेंक (Igibi Bank) कुछ दिशानों में उतनी ही विकसित थी जितनी कि १६ वीं शताब्दी की आधुनिक बेंक। बेबीलोन से यह प्रथा यूनान में पहुँची और यूनान से रोम में। तत्पश्चात् बैंकिंग की सबसे अधिक उन्नित इटली में हुई। यूरोप के सभी देशों में इसकी उन्नित का श्रीय यहूदी जाति के लोगों को है। इटली में इसके विकास के प्रमुख केन्द्र वेनिस, मिलन और जेनोआ रहे हैं। इटली के लम्बंड व्यापारियों ने अधिकोषण के विकास में विशेष ख्याति प्राप्त की और उनमें से कुछ ने इङ्कलेंड जाकर लन्दन नगर में इस व्यवसाय को आरम्भ किया। अब से २,१५०

वर्ष पूर्व की राज्याज्ञा का इटली में प्रमाण मिलता है, जिसके अनुसार बेंकों को यह आदेश दिया गया था कि उन्हें अपने कार्यालय स्थापित करने और कार्य-प्रणाली के निर्माण में कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि उस काल में भी रोम का बैंकिंग व्यवसाय काफी विकसित अवस्था में था।

तत्पश्चात् कई शताब्दियों तक बैंकिंग के विकास में शिथिलता हिष्टिगोचर होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सध्य-युग (Middle Ages) की अराजकता और निरन्तर युद्धों के कारण साहू कारों का व्यवसाय पनपने नहीं पाता था। धार्मिक और सामाजिक विचारधारा भी ब्याज लेने के विरुद्ध थी। प्रसिद्ध यूनानी विद्वान ग्ररस्तु के अनुसार रुपया रुपये को जन्म नहीं दे सकता। पूँजी स्वभाव से ही बाँभ (Sterile) है। इस कारण ब्याज का लेना अनुचित है। ब्याज लेने का अर्थ यह होता है कि किसी निर्धन अथवा आवश्यकताग्रस्त भाई की दीन अवस्था से अनुचित लाभ उठाया जाय। इसी प्रकार लगभग सभी धर्मों में ब्याजखोरी को निन्दनीय बताया गया है। यहूदियों के अतिरिक्त सभी लोग धन को उधार पर चलाना ग्रस्वाभाविक तथा अनैतिक (Immoral) समभते थे। यहूदियों के लिए तो ब्याज लेने के विरुद्ध कोई धार्मिक दबाव न था। यही कारण है कि बैंकिंग क्षेत्र में यहूदियों का ही सबसे अगला हाथ रहा है।

धीरे-धीरे विचारधारा फिर बदली श्रोर व्याज लेने की वाँछनीयता स्वीकार की जाने लगी। इस परिवर्तन का प्रमुख कारण यह था कि घीरे-थीरे ऐसे ऋणों की मात्रा बढ़ती जा रही थी जो उत्पादक थे, ग्रर्थात् जिनका उपयोग करके ऋणी ग्राय प्राप्त करता था। इस प्रकार प्राप्त ग्राय में से ऋण-दाता द्वारा एक हिस्सा लेना ग्रनुचित नहीं हो सकता था। कालान्तर में बड़े-बड़े व्यापार ग्रहों ग्रीर बैंकिंग ग्रहों की स्थापना हुई। ये व्यापारी ग्रह जनसाधारण से जमा स्वीकार करते थे ग्रीर ग्रपने ऋण दक्तानदारों, साहूकारों तथा कुछ दक्ताग्रों में राजाग्रों तक को देते थे। राजात्रों को त्रप्रण देना एक महत्त्वपूर्ण तथा लाभदायक धन्धा था, परन्तु इसके कारण श्रमेक व्यापार गृहों को श्रपना व्यवसाय बन्द करने पर बाध्य होना पड़ा। राजा द्वारा ऋण चुकाने से इन्कार करने का ग्रर्थ केवल यही नहीं होता था कि उधार की राशि मारी जाय। वास्तविकता यह है कि ऐसी दशा में सारे व्यवसाय को बन्द कर देना पड़ता था। परिणाम यह हुग्रा कि १७ वीं शताब्दी तक ये व्यापार-ग्रह समाप्त ही गये, जिसके कारण बैंकिंग के विकास में भारी शिथिलता ग्राई।

तुरन्त ही १७ वीं शताब्दी में एक नये युग का आरम्म हुआ । इस काल में यूरोप में भौद्योगिक क्रान्ति हुई थी और अनेक नये-नये देशों तथा उपनिवेशों की खोज की गई थी। जलयान यातायात का भारी विकास हुआ और यूरोप के व्यापार का भारी विस्तार हुआ। इसके अतिरिक्त नई-नई व्यापार कम्पनियों की वित्तीय व्यवस्था तथा उपनिवेशों के विकास के लिए भी धन की भारी आवश्यकता पड़ी थी। वैसे भी यूरोप के विभिन्न देशों के बीच काफी प्रतियोगिता थी और प्रत्येक दूसरों से आगे बढ़

कर व्यापार और वािराज्य के भ्रधिक विस्तृत भ्रधिकार प्राप्त करना चाहता था। ऐसे काल में बेंकिंग का विकास भी स्वाभाविक ही था, भ्रतः इस ह्वें त्र में भी भारी उचिति हुई।

किंचित यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि आधुनिक प्रकार की सबसे पहली बैंक सन् १४०१ में स्पेन देश के वारिसलोना नगर में स्थापित हुई। तत्पश्चात् सन् १६०७ में हॉलैंड में बैंक ऑफ एमस्टरडम और सन् १६१६ में बैंक ऑफ हेम्बर्ग जर्मनी में स्थापित हुई। यह क्रम बराबर चलता रहा और स्वीडन तथा अन्य योरोपीय देशों में बैंक खौली गईं। इस काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना सन् १६६४ में बैंक ऑफ इङ्गलेएड की स्थापना थी। इसके पश्चात् चैंक प्रथा आरम्भ हुई और सिम्मिलित-पूँजी बैंकों का अधिक विकास हुआ।

### भारत में आधुनिक वैंकिंग का विकास—

वैसे तो भारत में बैंकिंग का विकास बहुत ही प्राचीन काल में हो चुका था, परन्त देश में त्राधिनिक वैंकिंग का विकास बहुत पुराना नहीं है। इसके ब्रारम्भ का श्रीय यूरोप के लोगों को है। १८ वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने कलकत्ता श्रीर बम्बई में त्र्राभिकर्त्ता-गृह (Agency Houses) खोले थे, जो इङ्गलैंड के व्यापारियों की म्रोर से भारत में उनके व्यवसाय की देख-भाल करते थे। इस कार्य के ग्रतिरिक्त ये गृह ैंकिंग का कार्य भी करते थे। *बैंकिंग की दिशा में इनका प्रमुख कार्य ऋपनी ऋोर से* हैंक-नोट निकालना था | १६ वीं शताब्दी के मध्यकाल में इन गृहों पर श्रार्थिक संक**ट** म्राया भीर ये एक-एक करके ठप्प होने लगे। यद्यपि ये गृह कुछ बैंकिङ्ग सम्बन्धी कार्यं करते थे, परन्तु सच्चे ग्रर्थ में इन्हें बैङ्क नहीं कहा जा सकता था। उनके ठए हो जाने के पश्चात् वास्तविक ऋर्थ में देश में वैङ्किंग का विकास ऋरम्भ हुऋा । इस कार्य का श्रीगरोश प्रेसीडेन्सी बैङ्कों की स्थापना से हुन्ता। सर्व प्रथम सन् १८०६ में बैङ्क ग्रॉफ बङ्गाल स्थापित किया गया । ४० वर्ष पश्चात् सन् १८४६ में बैंक श्रॉफ बॉम्बे खुला श्रीर उसके तीन वर्ष पीछे सन् १८४६ में बैंक ग्रॉफ मद्रास । ग्रारम्भ में इन बैंकी को सरकार की म्रोर से नोटों की निकासी का म्रिवकार दिया गया था, परन्तु एक बैंक के नोट एक निश्चित क्षेत्र में ही विधि-ग्राह्म होते थे। सन् १८६२ में नोट निर्गम का म्रिधिकार छीन लिया गया, क्योंकि सरकार ने ऐसा मनुभव किया था कि उस समय तक भारतवासी बैङ्क प्रणाली से भली-भाँति परिचित हो चुके थे। धीरे-धीरे भारत में स्रब सम्मिलित पूँ जी बैंकों का खुलना आरम्म हो गया था। सम्मिलित पूँ जी बैंक्कों में से सर्वप्रथम सन् १८८१ में 'श्रवध कॉर्माशयल बैंक' स्थापित हुई, जो एक भारतीय बैंक थी। इसी काल में विदेशी पूँजी की सहायता से 'इलाहाबाद बैंक' तथा 'एलायंस बेंक ग्रॉफ शिमला'भी खुलीं। १६ वीं शताब्दी की एक बड़ी महत्त्वपूर्ण बैंक सन् १८६४ में स्थापित 'पंजाब नेशल बैंक' भी थी।

२० वीं शताब्दी का त्र्यारम्भ होते ही वैंकों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगी । सन् १६०१ में ही 'दी पीपल्स वैंक ग्रॉफ इण्डिया' खुल गई ग्रौर तत्प- क्वात सन् १६१३ तक एक के बाद दूसरी बैंक बराबर खुलती गई। बैंक इतनी तेजी के साथ खुलती गई कि बैंकिंग का विकास भ्रारोग्य न रह सका। सन् १६०६-०७ के ग्राधिक संकट के काल में बहुत सी बैंक फैंत हो गई, परन्तु संख्या की वृद्धि की गित रक न सकी। विकास इतना श्रिष्ठक परन्तु इतना कमजोर हुग्रा था कि भारतीय बैंड्रिंग प्रगाली प्रथम महायुद्ध की चोट न सह सकी। श्रिधकाँश बैंड्रिंग के पास पूँजी की कमी थी श्रीर वे श्रिपने कार्यवाहन में भी समुचित नियमों का पालन नहीं करती थीं। श्रिधकाँश बैंड्रिंग घन के लिए जमाधन पर ही निर्भर रहती थीं श्रीर परस्पर एक दूसरी से होड़ करती थीं। ऋगा लम्बे काल के लिए दे दिये जाते थे, जिसके कारगा श्रादेयों की तरलता नहीं रहती थी। इस वारण भ्रादेयों का मूल्य भ्रष्टिक रहते हुए भी कुछ बैंक भ्रपनी देन को चुकाने में भ्रसमर्थ रहने के कारण फेल हो जाती थीं। वैसे भी बैंकों का संचालन साधारगतया भ्रनुभवहीन भ्रौर स्वार्थी संचालकों (Directors) के हाथ में होता था। यही कारगा है कि देश में भ्रष्टिकाँश ऐसी बैंड्रिंग संस्थाएँ स्थापित हुई जिनकी कमर पहले से ही बलहीन थी ग्रौर जो थोड़ी सी भी चोट न सह सकीं। भ्राधिक संकट की एक ही भपट में वे टूट गई।

सन् १६१३ में ही 'पीपल्स बैंक ग्रॉफ इण्डिया' फेल हो गई थी ग्रीर उसके पश्चात् बैङ्कों के पेल होने की एक लहर सी दिशा भर में फेल गई। ऐसा ग्रनुमान लगाया गया है कि सन् १६१३ ग्रीर सन् १६१७ के बीच में ही ८७ बैङ्क फेल हो गई थीं ग्रीर प्रथम महायुद्ध के समाप्त हो जाने पर भी संकट का ग्रन्त न हो सका था। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने पता लगाया है कि ग्रन्य कारणों के ग्रितिरक्त देश में केन्द्रीय बैंक के न होने के कारणा भी बैंक ग्रधिक संख्या में फेल होती गई थीं। युद्धोत्तर काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना सन् १६२० का इम्पीरियल बैङ्क ग्रॉफ इण्डिया एक्ट था, जिसके ग्रनुसार सन् १६२१ में तीनों प्रेसीडेन्सी बैङ्कों को मिला कर इम्पीरियल बैङ्क ग्रॉफ इण्डिया स्यापित किया गथा था। इस बैंक को ग्रांशिक रूप में केन्द्रीय बैंङ्क सम्बन्धी कुछ ग्रधिकार भी दिये गये थे।

प्रथम महायुद्ध के अन्तिम वर्षों में देश के वािराज्य और व्यवसाय की दशा कुछ अंश तक सुघर गई थी, क्यों कि व्यापारियों और उद्योगपितयों को खूव लाभ हुआ था। परिगामस्वरूप बैंडूों के जमाधन में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। युद्धोत्तर काल में देश की बैंडूग प्रगाली एक बार फिर से संगठित की गई। बैंड्रों के खुलने की फिर से बाढ़ सी आने लगी। इस काल की प्रमुख विशेषता यह थी कि औद्योगिक वित्त का आयोजन करने और औद्योगिक बैंड्र खोलने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त बड़ी-बड़ी बैंकों ने अपनी शाखाएँ खोल कर व्यवसाय बढ़ाने का प्रयत्न किया। नई बैंक भारी संख्या में खोली गई। उन्नित का यह युग सन् १६३६ तक चलता रहा, यद्यि सन् १६२६ के महान् अवसाद ने संकट की दशाएँ उत्पन्न कर दी थीं। सन् १६३१ में भारत सरकार ने बैंड्र प्रगाली के दोषों की जांच करने और सुभाव देने के लिए केन्द्रीय बैंड्र जांच समिति नियुक्त की। इस समिति ने केन्द्रीय बैंड्र की स्थापना पर

प्रसे पूर्वं सन् १६२६ में हिल्टन-यंग ग्रायोग ने भी इसी प्रकार का सुभाव । । सन् १६३४ में भारत सरकार ने रिजर्व वैङ्क ग्रॉफ इण्डिया एक्ट ग ग्रीर १ ग्रप्रैल सन् १६३५ को रिजर्व वैङ्क ग्रॉफ इण्डिया का, जो बैङ्क है, उद्घाटन हुग्रा था, परन्तु थोड़े समय बाद ही सन् १६३६ का रिम्भ हुपा ग्रीर देश में सैंकड़ों की संख्या में बैङ्क फेत्र हो गईं।

ाहायुद्ध के काल में देश की बेंकिंग प्रणाली पर बहुत तनाव पड़ा, परन्तु इतनी प्रधिक थी और चलन के विस्तार के कारण जनता के पास कयः गई थी कि बैंकों के जमाधन का भारी विस्तार हुआ था। युद्ध के सेवाओं का विकास हुआ और साख-मुद्रा की अत्यधिक वृद्धि हुई। ोने के पश्चात् सन् १९४७ में देश का विभाजन हुआ, जिसके कारण इाल की बहुत सी बेंक फेल हो गईं। युद्धोत्तर काल की महत्त्वपूर्ण ९४५ में रिजर्व बैंक और सन् १९५५ में इन्पीरियल बैंक का राष्ट्रीय-काल में भारतीय बैंकिंग कम्पनीज एक्ट सन् १९४९ भी पास हुआ है।

हर∙.

ायुनिक समाज के वित्त तथा साख संगठन का एक महत्त्वपूर्ण साधन ।।र, वाणिज्य और व्यवसाय का धमनी केन्द्र (Nerve Centre) बैंक । युग में साख का महत्त्व सभी जानते हैं। साख का सुजन वर्तमान जिर बैंक द्वारा ही किया जाता है। वैसे भी, बैंक के कार्यों पर दृष्टि सका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। बैंक अपनी साख को अपने ग्राहकों की देती है। ऐसा कहा जाता है कि औद्योगिक विकास की कोई भी योजना कास के सफल नहीं हो सकती है। ये समाज के फालतू धन को एकत्रित और व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। कालान्तर में में निरन्तर वृद्धि हो हुई है। अभिकर्त्ता और प्रतिनिधि के रूप में बैंक म्पन्न करती है। किसी भी देश का आन्तरिक और विदेशी व्यापार इसी है। यहीं नहीं, बैंक एक अच्छे वािणिज्यक और व्यवसायिक सलाहकार रती है। बैंक के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार होते हैं:—

पूँजी की उत्पादकता में वृद्धि— बैंक समाज के उन व्यक्तियों तथा मा करती है जिनके लिए वह ग्रनावश्यक ग्रथवा कम उपयोगी है ग्रौर हो उन व्यक्तियों के पास हस्तान्तरित कर देती है जो इसका उत्पादक ग्रपना ही नहीं देश भर का भला करते हैं।

वित्तीय साधनों का संरक्षरा—वैंक देश के वित्तीय साधनों का है तथा उनका लाभदायक और हितकारी वितरए करती है। इसके यक जीवन में सन्तुलन ग्राता है ग्रीर उसकी जड़ें हढ़ हो जाती हैं। कोषों के हस्तांतरए। की सुविधा - वैंक कोषों के एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने का सस्ता, सुरक्षित श्रौर सुविधाजनक साधन उपलब्ध करती हैं।

- (४) भुगतान करने में सुविधा— बैंक चैंकों (धनादेशों) के उपयोग को बढ़ाती है। यह बहुत सुविधा-जनक होता है, क्योंकि इसमें गिनने, जाँच करने तथा हस्तान्तरित करने की सरलता होती है। यह रीति सुरक्षित भी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त चैंक के भुगतान में यह प्रमाण भी प्राप्त हो जाता है कि धन अमुक व्यक्ति को दिया गया है।
- (५) संरक्ष्मण सेवाएँ बैंक बहुमूल्य घातुम्रों म्नौर वस्तुम्रों का संरक्षण करके प्रपने ग्राहकों को काफी लाभ पहुँचाती है।
- (६) साख मुद्रा के लाभ—साख-मुद्रा के ग्रिधिकांश लाभ बेंक की सेवाग्नों के ही परिग्णाम होते हैं।
- (७) मुद्रा प्रगाली में लोच—वेंक देश की मुद्रा प्रगाली में लोच उत्पन्न कर देती है। साख-मुद्रा की मात्रा के परिवर्तन द्वारा विनिमय-माध्यम की मात्रा घटाई-बढ़ाई जा सकती है।
- (८) सरकारी म्रर्थ-प्रबन्ध की सुविधा— बैंकों का सरकारी म्रर्थप्रबन्ध में भी भारी महत्त्व होता है। सरकारी रोको का संरक्षण, सरकारी ऋणों का प्रबन्ध तृथा म्रावश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करना, ये सब कार्य बैंक द्वारा ही किए जाते हैं। बैंकों का वर्गीकरण—

बैंकों को उनके विशेष कार्यों के ग्राधार पर निम्न प्रकार से वर्गित किया जा सकता है:—

- र् ) व्यापारिक वैंक (Commerical Banks), जोकि मुख्य रूप से व्यापारियों को भ्रत्यकालीन ऋण उपयुक्त तरल प्रतिभूतियों के भ्राधार पर देते हैं।
- (२) श्रौद्योगिक वेंक (Industrial Banks) वे हैं जो भ्रौद्योगिक वित्त का प्रबन्ध करते हैं। ये बेंक प्रायः दीर्घकालीन जमा प्राप्त करके उद्योग-धन्धों को दीर्घकालीन ऋए। दिया करते हैं।
- (२) विदेशी विनिमय बैंक (Foreign exchange Banks) विदेशी बिलों का क्रय-विक्रय करके विदेशी भुगतान में सहायता पहुँचाते हैं।
- (४) कृषि बैंक (Agricultural Banks) कृषि की ग्रर्थ व्यवस्था के लिये विशेष रूप में स्थापित किये जाते हैं। कृषि के ग्रर्थ-प्रबन्धन की समस्या ग्रपने ढंग की निराली है, क्योंकि ऋग लेने के हेतु जमानत स्वरूप किसानों के पास कोई ठोस प्रतिभूति नहीं होती है, जिससे उनको ऋग देने में जोखिम ग्रधिक होती है। ये वैंक प्रायः दो प्रकार के होते हैं—सहकारी बैंक (ग्रथवा सहकारी साख समितियाँ) ग्रीर भूमि-बन्धक वैंक।

- (५) पोस्ट ऋॉफिस सेविंग बैंक (Post Office Savings Bank), जिनका संगटन डाक विभाग द्वारा, झल्प आय वाली जनता में बचत की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए किया गया है।
- (६) देशी वैकर (Indigenous Bankers), जिनके अन्तर्गत महा-जन व साहूकार आते हैं, जोकि मुख्यतः आन्तरिक व्यापार और कृषि कार्य के लिए वित्तीय सुविधा देते हैं।
- (७) के-द्रीय बेंक (Central Bank), जो प्रायः प्रत्येक देश में केवल एक ही हुमा करता है। इसे नोट निकालने का म्रिष्टिकार होता है। यह बेंकों का बेंक भ्रीर सरकार वा बेंक कहलाता है। इस पर ही देश की बेंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी होती है।

भारत में श्रौद्योगिक बेंकों श्रौर विदेशी विनिमय बेंकों की कमी है। श्रौद्योगिक वेंकों का कार्य इस समय तो विभिन्न श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल कर रहे हैं। विदेशी विनिमय का काम श्रीवकतर विदेशी वेंकों के हाथ में है, जिनके प्रमुख कार्यालय विदेशों में हैं। ये बेंक राष्ट्रीय हित में काम नहीं करते।

#### QUESTIONS

Give the main functions of Commercial Banks and show how they create credit? (Agra, B. A., 1955 Supp.)

Briefly discuss the functions of commercial banks. How far Indian commercial banks perform these functions?

(Raj., B. A., 1957)

Explain the role which joint-stock banks play in the economic development of a nation. (Agra, B. A., 1955)

What is a bank? Discuss the services it renders to industry and trade and point out the sources of its profits.

(Agra, B. Com., 1957 Supp.)

Briefly discuss the importance of a Commercial Bank (ब्यापारिक बेंक) to modern trade and state how far they help trade and commerce. (Raj., B. A, 1958)

व्यापारी बैंकों (Commercial Banks) के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए और बताइये कि किसी देश की श्रीद्योगिक उन्नति में ये किस प्रकार सहायक हैं।

(Jabalpur, B. A, 1958)

"Banking consists of receiving other people's money and lending it out again to the people who deposited it. The banker really borrows the depositor's money, usually for nothing, and then lends the same money back again on interest." Comment on this statement.

(Agra, B. A., 1955 Supp.)

Briefly discuss the functions of a modern bank and explain the main considerations that guide a banker in investing his funds.

(Rai, B. Com., 1958)

# अध्याय १३

# साख-मुद्रा तथा साख-पत्र

(Credit Money and Credit Instruments)

साख किसे कहते हैं ?—

श्रंग्रेजी भाषा में साख शब्द के स्थान पर क्रेडिट ( $\operatorname{Credit}$ ) शब्द का उपयोग किया जाता है और वह क्रेडो (Credo) शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मैं विश्वास करता हैं (I Believe)। म्रतः साख शब्द का मर्थ विश्वास, भरोसा म्रथवा यकीन (Trust or Confidence) से होता है। साधारण बोलचाल में साख शब्द जिस अर्थ में उपयोग किया जाता है वह काफी विस्तृत होता है, क्यों कि सभी प्रकार का विश्वास सास हो सकता है। ग्रर्थशास्त्र में इस शब्द का उपयोग ग्रधिक संकृचित ग्रर्थ में होता है। यहाँ साख का ग्रभिप्राय केवल देनदारी ग्रथवा शोधनक्षमता के विश्वास से होता है। जब हम यह कहते हैं कि बाजार में ग्रमुक व्यक्ति की साख बहुत है तो इसका ग्रर्थ यह होता है कि लोग उस व्यक्ति की देनदारी पर ग्रधिक विश्वास रखते हैं, ग्रथीत उस व्यक्ति को सरलता के साथ पर्याप्त उधार मिल जाता है। साख शब्द का संम्बन्ध सदा ही उधार की लेन-देन ग्रथवा स्थिगत शोधनों से होता है। विनिमय का एक पक्ष दूसरे पक्ष को मुद्रा, वस्तुएँ ग्रथवा सेवाएँ उघार देता है ग्रौर उनको भविष्य में कुछ निश्चित शर्तों पर लौटाने का वचन ले लेता है। यही साख व्यवसाय है श्रीर इसका श्राधार यह है कि प्रस्तृत सेवाग्रों तथा वस्तुग्रों का भावी वायदे के साथ विनिमय किया जाता है। यह इसी कारण होता है कि ऋगी व्यक्ति की शोधनक्षमता पर विश्वास किया जाता है। साख की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है - साख वर्तमान काल में हस्तान्तरित किए गये माल के बदले में माँगने पर अथवा किसी निश्चित भावी तिथि पर भुगतान प्राप्त करने का ऋधिकार ऋथवा भुगतान देने का उत्तर-दायित्व है । इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों के विचार नीचे दिये गये हैं :---

- (१) प्रो॰ जाइड (Gide) के अनुसार "साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो कुछ समय पश्चात् अर्थात् भुगतान कर देने पर पूरा हो जाता है।"
- (२) प्रो॰ टामस (Thomas) के अनुसार "साख शब्द का अभिप्राय किसी व्यक्ति की उस शोधनक्षमता तथा देनदारी के विश्वास से होता है जिसके कारण उस व्यक्ति पर यह विश्वास कर लिया जाता है कि किसी दसरे व्यक्ति की बद्रमल्य वस्त

उसे सींपी जा सके, वह बहुमूल्य वन्तु मुद्रा, वस्तुएँ, सेवायँ अथवा स्वयं साख हो सकती है, जैसे कि उस दशा में जबकि एक व्यक्ति दूसरे को अपनी व्यवसायिक ख्याति अथवा अपने नाम के उपयोग का अधिकार देता है।"\*

#### साख का श्राधार-

अब हमें यह देखना है कि किसी व्यक्ति की साख किन बातों पर निर्भर होती है ? इस सम्बन्ध में आधिक विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। कुछ लोगों का विचार है कि साख का आधार विश्वास है। यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास नहीं है कि ऋए की राशि लौटा दी जायगी तो वह ऋएा प्रदान करने का विचार भी नहीं करेगा। वेवल दान अथवा मित्रता के हेलु ही वह उधार दे सकता है। इसके विगरीत कुछ लेखकों का कहना है कि साख का आधार विश्वास नहीं सम्पत्ति है और उसी को देख कर ऋएा दिये जाते हैं। कुछ और व्लेखकों ने ऋएग लेने वाले के चिरत्र को साख का वास्तविक आधार माना है और कुछ ने चिरत्र, पूँजी तथा अमता तीनों को। वास्तव में व्यक्ति तथा सम्पत्ति दोनों ही पर साख निर्भर होती है। प्रायः साख के निम्न आधार माने जाते हैं:—

- (१) विश्वास—कुछ लेखकों का मत है कि विश्वास ही साख का श्राधार है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को रुपया उधार लेने वाले मनुष्य के बारे में यह विश्वास नहीं है कि वह उसके ऋण को लोटा देगा, तो वह ऐसे मनुष्य को कभी ऋण नहीं देगा। हाँ, यह बात मित्रता व प्रेम के सम्बन्धों में लागू नहीं होती है।
- (२) चरित्र यदि किसी व्यक्ति को ऐसी ख्याति प्राप्त होती है कि भूत-काल में उसने ग्रपने सभी ऋगों को ठोक-ठोक चुकाया है, ग्रथवा यदि उसका सामान्य चरित्र निष्कलङ्क तथा विश्वसनीय है तो उसको साख भी ग्रधिक होगी। इसके विपरीत यदि भूतकाल में किसी व्यक्ति का चरित्र सन्देहयुक्त रहा है तो उसे ऋगा देने से पहले उसकी शोधनक्षमता पर विचार किया नायगा।
- (३) क्षमता—यह दूसरी ग्रावश्यकता है। केवल चरित्र से ही काम नहीं चलता। ऋए देने वाले को यह भी विश्वास होना चाहिए कि ऋएा लेने वाले के पास भुगतान के लिए पर्याप्त साधन भी विद्यामान हैं। कुछ दशाग्रों में स्वयं चरित्र ही क्षमता का ग्राधार हो सकता है। यदि चरित्र विश्वसनीय है ग्रीर व्यक्ति विशेष को पर्याप्त ग्रामुभव, शिक्षएा तथा योग्यता प्राप्त है तो ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि कुछ समय पश्चात् यह ऋएा को चुकाने के लिए ग्रावश्यक साधन भी जुटा ही लेगा। फिर भी लेने वाले के पास लौटाने की सामध्यं को देखा ग्रवश्य जाता है।

<sup>\* &</sup>quot;The term credit is now applied to that belief in a man's probity and solvency which will permit of his being entrusted with something of value belonging to another whether that something consists of money, goods, services or even credit itself as when one man entrusts to another the use of his good name and reputation." See S E. Thomas: Elements of Economics, p. 398.

- (४) पूँजी ग्रौर सम्पत्ति—उपरोक्त दोनों ग्राधारों पर छोटी-छोटी रकम के ऋएा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। बड़े-बड़े ऋएाों के लिए बैंकों पर निभंर रहना पड़ता है, परन्तु बैंक ऋएा देने से पहले ही यह देख लेती है कि ऋएा लेने वाले के पास उपयुक्त प्रतिभूति है या नहीं। साधारएतया जितनी ही किसी व्यक्ति के पास पूँजी भ्रथवा सम्पत्ति ग्रधिक होती है उतने ही उसे ग्रधिक ऋएा मिल सकते हैं ग्रौर उतनी ही उसकी साख भी ग्रधिक ऊँवी होती है।
- (५) प्रतिभूतियों अथवा आदेयों की तरलता—प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति साख के आधार के दृष्टिकोण से समान रूप में उपयुक्त नहीं होती है। यदि ऋण लेने वाले के पास तरल आदेय हैं और उसका व्यवसाय सरलतापूर्वक चल रहा है तो उसकी साख अधिक होगी। यदि आदेय अचल सम्पत्ति और अबिक्री-साध्य प्रतिभूतियों के रूप में हैं तो ऋण देने वाले को संकोच होगा।
- (६) साख की ग्रविध—साख देना या न देना इस बात पर भी निर्भर होता है कि वह कितने समय के लिए माँगी जा रही है। प्रायः दीर्घकालीन साख देने में बहुत संकोच किया जाता है, क्योंकि इस बीच ग्राहक की परिस्थितियों में ग्रन्तर होने से रुपया लौटने की सम्भावना समाप्त हो सकती है।

# साख की विशेषताएँ —

उपरोक्त सभी बातों के देखने से साख की तीन विशेषताओं का पता चलता है:—सर्वप्रथम तो, साख की राशि का उल्लेख आवश्यक होता है। अनिश्चित मात्रा में ऋरा का कोई भी अर्थ नहीं है। दूसरे, साख की समय-अवधि भी निश्चित होती है। यह स्पष्ट रूप में बताया जाता है कि साख कितने समय के लिए है, अर्थात् ऋरा कितने समय पश्चात् शोधनीय है। साख की तीसरी विशेषता विश्वास है। बिना विश्वास के साख उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त कितनी मात्रा में तथा कितने समय के लिए साख प्रदान की जाती है, यह भी इसी बात पर निर्भर होता है कि ऋरा दाता को ऋरा पर कितना विश्वास है।

# साख का वर्गीकरण

साख का वर्गीकरण करने की कई रीतियाँ हैं। भ्रनेक बार तो ऋगा लेने वाले की स्थिति के भ्रनुसार साख का वर्गीकरण किया जाता है भ्रौर बहुत बार ऋण देने गले की स्थिति के भ्रनुसार । कभी-कभी साख प्रदान करने की समय-भ्रविध को भी गर्गीकरण का भ्रावार माना जाता है, परन्तु भ्रधिक प्रचलित रीति साख को उसके उपयोग के भ्रनुसार वर्गीकृत करने की है—

(१) व्यक्तिगत तथा सार्वजिनक साख (Private and Public Credit)—सावाररातया सरकारी प्रयीत सरकार द्वारा इस वायदे पर प्राप्त की हुई वस्तुधों और सेवाधों को, कि उनकी कीमत का भुगतान् भविष्य में कर दिया जायगा, सार्वजिनक अथवा लोक साख कहा जाता है। आधुनिक युग में सरकार द्वारा

ऋणों का लेना एक बड़ी साधारण सी घटना है। लोक ऋण लोक साख को जन्म देते हैं। सरकार के ग्रतिरिक्त भ्रन्य सभी व्यक्तियों भ्रौर संस्थाओं की साख होती है। म्राथिक ग्रध्ययन में व्यक्तिगत साख का ही महत्त्व ग्रधिक होता है। इस व्यक्तिगत साख के भी कई रूप होते हैं।

- (२) वैंक साख (Bank Credit) यह भी एक प्रकार की व्यक्तिगत साख ही होती है। प्रथंशास्त्र में यह दो प्रथों से उपयोग की जाती है: संकुचित तथा विस्तृत । संकुचित प्रथंशास्त्र में वैंक साख का ग्राग्य केवल व्यापार वेंकों की ग्रभियाचन निक्षेपों (Demand Deposits) से होता है, परन्तु विस्तृत ग्रथं में यह शब्द वैंकिंग संस्थाग्रों की सभी प्रकार की भुगतान सम्बन्धी प्रतिज्ञाग्रों को सूचित करता है, जिसमें वैंकों के ग्रभियाचन निक्षेप, समय निक्षेप (Time Deposits), रोक साख-पत्र (Cash Letters of Credit), ऋरण-पत्र (Debentures), बाँड (Bonds), नोट तथा वेंकरों की स्वीकृतियाँ (Banker's Acceptances) सम्मिलित होते हैं । वैंक साख शब्द को साधारणतया इन दोनों ही ग्रथों में निःसंकोच जपयोग किया जाता है । वैंक साख की ही एक शाखा केन्द्रीय वेंक की साख होती है । इसमें केन्द्रीय वेंक द्वारा चालू किए हुए नोट तथा केन्द्रीय वेंक के निक्षेप उत्तरदायित्त्व (Deposit Liabilities) सम्मिलित होते हैं ।
- (३) विनिमय साख (Investment Credit)—इस प्रकार की साख व्यवसायों की दीर्घकालीन ऋए। सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती है। यदि व्यवसाय का स्वामी भूमि, मकान तथा मशीन आदि के लिए अपने ही पास से पर्याप्त पूँजी उपलब्ध नहीं कर सकता है तो उसे इन कार्यों के लिए दीर्घकाल ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ऋणों को चुकाने का एक मात्र उपाय यही होता है कि उन विनियोगों के लाभ से प्राप्त होने वाली राशि में से उनका भुगतान किया जाय, जिनके लिए वे लिए गये हैं, परन्तु इस प्रकार इनके भुगतान में समय लगता है। इस कारण ऐसे ऋणों को प्राप्त करने के लिए एक विशेष साख-पत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे प्राधि बाँड (Mortgage Bonds) कहते हैं। इस पत्र में ऋणी निर्देशित शर्तों पर मूलधन को लौटाने का वचन देता है और प्रतिभूति के रूप में अपनी सम्पत्ति का एक भाग ऋणदाता के पास गिरवी रख देता है, जिसका अधिकार कुछ निश्चित दशाओं में ही ऋणदाता को प्राप्त हो सकता है। यदि ऋणी प्राधि-पत्र की शर्तों को यथा-समय ठीक ठीक पूरा करता रहता है तो सम्पत्ति पर उसका स्वतन्त्र अधिकार रहता है। ऐसे प्राधि-बाँड द्वारा निर्मित साख वाणिज्यिक भाषा में विनियोग साख कहलाती है।
- (४) वाग्णिज्य साख (Commercial Credit) इस साख का सम्बन्ध भी व्यवसाय से होता है। जिस प्रकार व्यवसाय को दीर्घकालीन ऋगों की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार समय-समय पर उसके लिए अल्पकालीन ऋगा भी आवश्यक होते हैं। वाग्णिज्य सोख से हमारा अभिष्राय अल्पकालीन ऋगों से ही होता है। इस

प्रकार की साख व्यवसायों की निर्माण तथा बिक्री सम्बन्धी अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए प्रवान की जाती है। कच्चे मालों के खरीदने, मजदूरियाँ देने, करों को चुकाने तथा विज्ञापन आदि करने के लिये व्यवसाय को ऋणों की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि व्यवसायों को उस समय तक आय प्राप्त नहीं होती है जब तक कि वह माल बेचकर उसकी कीमत वसूल नहीं कर लेता है। ऐसे कार्यों को सम्पन्न करने के लिये ही वाणिज्य अथवा अल्पकालीन साख की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी समय अविध अधिक से अधिक ६ मास अथवा एक वर्ष तक होती है। ऐसे ऋणों को भी व्यवसाय से प्राप्त शुद्ध आय में से ही चुकाया जाता है, परन्तु इन ऋणों के पीछे कच्चे माल, तैयार माल आदि के तरल आदेशों की आड़ रहती है।

(५) उपभोक्ताओं की साख तथा उत्पादकीय साख Consumer's Credit and Producr's Credit)—साख को उपभोक्ताओं की साख तथा उत्पादकों की साख में भी विभाजित किया जाता है। उपभोक्ता की साख में उपभोक्ताओं को क्रयः शक्ति प्रथवा वस्तुओं के ऋएा दिये जाते हैं। इन ऋएों की विशेषता यह होती है कि इनसे ऋएों को कोई ग्राय प्राप्त नहीं होती है और इसलिए इनके पूलघन तथा ब्याज को चुकाने की व्यवस्था व्यक्तिगत ग्राय में से की जाती है। ऐसे ऋएा केवल उपभोग के हेतु लिए जाते हैं। 'उपभोक्ता-साख में दूकानदारों द्वारा दिया गया उघार, साहूकार तथा बेंकों द्वारा दिये गये व्यक्तिगत ऋएा ग्रादि सम्मिलत किये जाते हैं। इसके विपरीत उत्पादकीय साख में उन सब ऋएों को सम्मिलत किया जाता है जो विभिन्न व्यक्तियों, फर्मों, कम्पनियों ग्रथवा सरकार को उत्पादन कार्यों के लिए दिये जाते हैं। ऐसे ऋएों की विशेषता यह होती है कि उनसे ऋएों को ग्राय प्राप्त होती है श्रीर कम से कम ब्याज का भुगतान तो ऋएा की राशि के उपयोग से प्राप्त ग्राय में से ग्रवश्य किया जा सकता है। ऐसे ऋएा दीर्घकालीन ग्रथवा विनियोग ऋएा, व्यकालीन ग्रथवा ग्रल्पकालीन या वािए ज्यिक ऋएा हो सकते हैं। ग्राधुनिक जगत में से ही ऋएों की प्रधानता है।

# गख की मात्रा किन बातों पर निर्मर होती है ?-

किसी देश में साख का विस्तार बहुत सी बातों पर निर्भर होता है। साख की । वश्यकता व्यवसायों के सम्बन्ध में पड़ती है। ग्राधुनिक व्यवसायिक सगठन की जान ो साख है, क्योंकि दूसरों के रुपयों से व्यवसाय करना ही ग्राधुनिक व्यापार की वशेषता है। सामान्य रूप में हम यह कह सकते हैं कि किसी देश के ग्राधिक, ग्रौद्योगिक, व्यापारिक तथा वैंकिंग जीवन का जितना ही ग्रधिक विकास होगा उतना ही वहाँ । खि के विस्तार की सम्भावना भी ग्रधिक होगी। साख की मात्रा इस बात पर भी नेभर होती है कि ऋणदाता किस ग्रंश तक ऋण देने को तैयार है ग्रोर ऋण लेने वाले केतना ऋण लेना चाहते हैं। निम्न कारणों का प्रभाव साख की मात्रा पर विशेष भ पे पहता है:—

- (१) लाभ की मात्रा—विनियोगों पर जितना ही श्रविक लाभ प्राप्त होगा और जितने ही ये विनियोग श्रविक सुरक्षित होंगे उतनी ही ऋगों की माँग भी श्रविक होगी श्रौर उन्हें देने की तत्परता भी उतनी ही श्रविक होगी।
- (२) व्यापार की दशाएं व्यापार की दशाग्रों का भी साख की मात्रा से घिनष्ट सम्बन्ध होता है। वैभव (Boom) के काल में चारों ग्रोर तेजी रहती है। व्यापार ग्रीर व्यवसायों का विस्तार होता है ग्रीर विनियोगों पर ग्रधिक लाभ प्राप्त होता है। इस काल में ब्याज की दरें भी ऊपर उठती हैं, क्योंकि व्यवसायों के विस्तार के साथ-साथ ऋगों की माँग बढ़ती जाती है। बैंक तेजी के साथ ग्रपनी साख का विस्तार करती हैं। इसके विपरीत मन्दी के काल में उत्पादन घटता है ग्रीर व्यवसायों को हानि होती है, जिसके कारण ऋगों की माँग बहुत कम होती है। भविष्य के उज्जवल न होने के कारण विनियोगी वर्ग जोखिम उठाने से घवराता है। निश्चय ही ऐसे काल में साख का उत्पादन कम होता है 1
- (३) सट्टा बाजार की प्रवृत्ति—सट्टे बाजी के कारण भी साख की मात्रा का विस्तार प्रथवा संकुचन हो सकता है। जब भविष्य में कीमतों के बढ़ने की श्राशा की जाती है तो सट्टा बाजार बड़ी तेजी से चालू होता है। नये-नये सौंदे खरीदे जाते हैं और ऋणों की माँग बढ़ने के कारण साख का विस्तार होता है। यदि सट्टा बाजार में मन्दी है तो ऋणों की माँग घटने के कारण साख का संकुचन होता है। बहुत बार तो सट्टे बाज प्रकारण ही कीमतों में तेजी प्रथवा मन्दी उत्पन्न करके ऋणों की माँग घटा-बढ़ा देते हैं और साख के निर्माण को प्रोत्साहित कर देते हैं।
  - (४) देश की राजनीतिक दशाएँ—राजनीतिक स्थिरता म्राथिक जीवन स्थायीपन उत्पन्न करके उसके विकास के लिए उपयुक्त दशाएँ उत्पन्न कर देती है, ससके कारण ऋगों की माँग बढ़ती है भौर साख का विस्तार होता है। यदि राज-।तिक वातावरण भ्रानिश्चित है तो भ्राथिक विकास हतोत्साहित होता है भौर साख का संभूचन होता है।
  - (५) सरकार तथा केन्द्रीय बैंक की नीति—साल नियन्त्रण के दृष्टिकोण इसका भारी महत्त्व होता है। यदि केन्द्रीय बैंक सुलभ मुद्रा नीति (Cheap Ioney Policy) अपनाती है और कम ब्याज पर ऋण देने की अधिक सुविधाएँ दान करती है तो साल का विस्तार होता है परन्तु यदि केन्द्रीय बैंक, बैंक दर को जैंचा करके अथवा अन्य रीतियों से ऋणों को हतोत्साहित करती है तो साल का कुंचन होगा।
  - (६) चलन की दशाएँ (Currency Conditions)—साख की गात्रा पर देश की चलन व्यवस्था का भारी प्रभाव पड़ता है। यदि देश की मुद्रा के पूल्य हास का भय है अथवा यदि सरकार की चलन सम्बन्धा नीति अनिश्चित है तो मृज्व०अ० (१६)

साख का संकुचन होगा। इसके विपरीत एक समुचित चलन प्रणाली के अन्तर्गत साख के विस्तार की सम्भावना अधिक होगी।

(७) बैंकों का विकास तथा बैंकों की सामान्य नीति — आधुनिक संसार में साख के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन बैंक हैं, क्योंकि देश की अधिकाँश साख का निर्माण उन्हों के द्वारा किया जाता है, अतः जितना ही किसी देश में बैंकिंग का विकास अधिक होगा उतनी ही साख के विस्तार की सम्भावना भी अधिक होगी। साथ ही, बैंकों की साख सम्बन्धी नीति तथा देश में साख-मुद्रा के उपयोग की प्रथा पर भी साख विस्तार की सीमा निर्भर रहती है।

# क्या साख पूँजी हैं (Is Credit Capital) ?—

यह विषय विवादग्रस्त है कि क्या साख पूँ जी हैं, ऋर्थात् क्या साख के द्वारा उपयोगिता का सुजन होता है ? स्मरए रहे कि पूँजी मनुष्य की पिछली कमाई का वह भाग होती है जिसे ग्रौर ग्रविक उत्पत्ति करने के लिए उपयोग किया जाता है । इस हिंछकोरासे साखन तो पूँजी है और न उत्पत्ति का ही साधन है। मैकलौड का विचार है:—''साख वास्तविक ग्रर्थ में पूँजी है। मुद्रा ग्रौर साख दोनों ही पूँजी हैं। व्यापारिक साख को एक प्रकार की व्यापारिक पूँजी ही कहा जा सकता है।" १ परन्त यह विचार ठीक नहीं है। वास्तविकता यह है कि साख उत्पत्ति का साधन नहीं है. वह तो एक उत्पादन विधि मात्र है। जिस प्रकार श्रम-विभाजन तथा विनिमय .. उत्पादन करने की रीतियाँ हैं ग्रौर दोनों के ही द्वारा उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है. ठीक इसी प्रकार साख भी केवल एक रीति है, जो किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ा ु देती है। मैकलौड के विरुद्ध मिल तथा रिकार्डो जैसे महान् ग्रर्थ-शास्त्रियों का मत है कि साख को पूँजी कहना भूल होगी। मिल के श्रनुसार साख द्वारा केवल पूँजो का हस्तान्तरण होता है, उसका सुजन नहीं होता है। उन्होंने लिखा है:---''केवल उधार देने से नई पूँजी का निर्माण नहीं हो सकता है, ऐसी दशा में तो केवल उस पूँजी का जो पहले से ही ऋ एा-दाता के पास थी, ऋ एा को हस्तान्तर एा होता है। साख तो केवल दूसरे की पूँजी को उपयोग करने का ग्रधिकार है, इसके द्वारा उत्पत्ति के साधनों की वृद्धि नहीं होती, उनका केवल हस्तान्तरए। ही होता हैं।''े ठीक इसी प्रकार रिकार्डों ने भी कहा है :— ''साख पूँजी का सृजन नहीं करती है, वह तो केवल

1. "Money and credit are both capital. Mercantile credit is mercantile capital. See Macleod: Elements of Banking. Chap. IV.

<sup>2. &#</sup>x27;New capital is not created by the mere fact of lending, only the capital that was in the hands of the lender is now transsion to use the capital of another person. The means of production cannot be increased by it but only be transferred." See J.S. Mill: Principles of Political Economy.

यह निश्चित करती है कि पूँजी का उपयोग कौन करेगा।" प्रतः (i) साख-पत्र (Credit Instruments) केवल पूँजी के प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं, वे स्वयं पूँजी नहीं होते। वे तो केवल उस पूँजी का, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को या एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तान्तरणा ही करते हैं। एक व्यवसायी के लिए वे पूँजी पर ग्रधिकार पाने का ग्रच्छा साधन होते हैं। (ii) यद्यपि साख द्वारा पूँजी का जो हस्तान्तरण होता है वह उत्पादक होता है। परन्तु यह उत्पादकता हस्तान्तरण द्वारा उत्पन्न हुई है। साख को उत्पत्ति का एक स्वतन्त्र साधन कहना उपयुक्त नहीं हो सकता है। साख की लेन-देन से पूँजी की गतिशीलता ग्रौर उसकी उत्पादकता बढ़ती है। परन्तु पूँजी की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। (iii) साख द्वारा पूँजी का ऐसे व्यक्तियों के पास हस्तान्तरण हो जाता है जो उसे ग्राधिक विकास के लिए ग्रधिक उपयुक्त रीति से उपयोग कर सकते हैं। इससे किसी नई पूँजी का निर्माण नहीं होता। साख तथा की सत-स्तर (Credit and Prices)—

यह प्रश्न भी विवाद-प्रस्त है कि साख और कीमतों के बीच किस प्रकार का सम्बन्ध है। वाकर (Walker) का मत है कि साख का कीमतों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका विचार है कि साख में क्रयः शक्ति तो होती है, परन्तु निस्तारण शक्ति (Liquidating Power) नहीं होती है। सभी प्रकार के विनिमय तथा ऋण व्यवसायों का ग्रन्तिम निस्तारण नकद भुगतानों द्वारा ही होता है। इसके ग्रांतिरक्त साख-मुद्रा के द्वारा जो क्रय-विक्रय होता है उसमें एक क्रिया का दूसरी से सन्तुलन हो जाता है ग्रीर इस प्रकार साख को लेन-देन का वस्तुग्रों के कीमत-स्तर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है।

इसके विपरीत मिल तथा उनके समर्थकों का विचार है कि साख के निर्माण् का कीमतों पर ठीक उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है जैसा कि चलन की उत्पत्ति का, क्योंकि चलन की भाँति साख-मुद्रा भी कयः शक्ति होती है और उसके द्वारा भी वस्तुओं और सेवाओं का कय-विक्रय होता है। मुद्रा का परिमाण चलन तथा साख-मुद्रा दोनों का ही सामूहिक योग होता है और इस पर साख-मुद्रा की मात्रा के परिवर्तनों का भी उसी प्रकार प्रभाव पड़ता है जिस प्रकार कि चलन की मात्रा के परिवर्तनों का। सरकार तथा केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियन्त्रण की जो नीति अपनाई जाती है उसका कीमतों पर काफी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। साधारणतया साख पर दी जाने वाली राशि इस उद्देश्य से दी जाती है कि उसकी सहायता से वस्तुओं का उत्पादन किया जाय और उत्पादित कीमत में से उसका भुगतान कर दिया जाय, परन्तु उत्पादन कार्य में समय लगता है और इस वीच में साख मुद्रा क्रयः शक्ति का विस्तार करके कीमतों को बढ़ा सकती है।

whom capital should be employed." See Ricardo: Principles of Political Economy and Taxation.

सकते तो उनका कीमतों पर ठीक वही प्रभाव पड़ता जो कि चलन का पड़ता है, परन्तु साख-पत्र उतना विश्वास उत्पन्न नहीं करते हैं जितना कि चलन मुद्रा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ग्रन्तिम दशा में सभी साख-पत्रों का निस्तारएा नकदी में ही किया जाता है। साख निर्माएा के हेतु वैंकों को नकद कोष भी जमा करके रखने पड़ते हैं ग्रीर साख का ग्रीर अधिक विस्तार केवल नकद कोषों की वृद्धि करके ही किया जा सकता है। जब साख का विस्तार होता है तो नकद कोषों में जमा की हुई चलन मुद्रा को प्रचलन में से निकाला जाता है। परिएाम यह होता है कि लगभग कभी भी कीमतें साख-विस्तार के ग्रनुपात में नहीं बढ़ पाती हैं, परन्तु क्योंकि साख-मुद्रा के पीछे शत-प्रतिशत नकदी नहीं रखी जाती है, इस कारएा साख विस्तार में स्फीतिक प्रवृत्ति ग्रवश्य रखी जाती है। साख विस्तार के कारएा उत्पत्ति की जो वृद्धि होती है वह भी वस्तुग्रों की कुल मात्रा को बढ़ाकर कीमतों को नीचे गिरने की सम्भावना उत्पन्न कर सकती है। कीमत-स्तर साख-मुद्रा के प्रभाव से पूर्णतया विमुक्त नहीं होता है। श्रिधिक इतना कहा जा सकता है कि चलन की तुलना में साख-मुद्रा का कीमतों पर कम प्रभाव पड़ता हैं।

# साख-पत्र श्रौर उनके भेद (Credit Instruments and their Kinds): साख-पत्रों का श्रर्थ—

साख-पत्रों से हमारा श्रिमिप्राय उन सभी नोटों, परचों या पुजों श्रीर साधनों से होता है जिनका साख मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। साख-पत्र भी वस्तुग्रों ग्रीर सेवाग्रों के कय-विकय में विनिमय-माध्यम का कार्य करते हैं ग्रीर इस कारण विस्तृत प्रथं में उन्हें भी मुद्रा में ही सिम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु मुद्रा के रूप में सिक्कों तथा नीटों श्रीर साख-पत्रों में यह मेद होता है कि साख-पत्र चलन मुद्रा की माँति विधिग्राह्य नहीं होते हैं। उनकी ग्राह्यता लेने वाले की इच्छा पर निर्भर होती है। यही कारण है कि उनका प्रचलन ग्रिपेक्षतन ग्रियक सीमित रहता है। क्रयः शक्ति का लगभग सभी प्रकार का संचय सिक्कों ग्रीर नोटों में ही किया जाता है। ग्रियिग्राह्य होने तथा विश्वास की कमी के कारण साख-पत्र इस कार्य के लिए उप-प्रक्ति नहीं होते हैं। इस मुद्रा का न तो कोई निहित मूल्य ही होता है श्रीर न इसके पीछे किसी प्रकार का कानूनी बल ही होता है।

## साख-पत्रों के भेद-

साख-पत्र कई प्रकार के होते हैं। साख-मुद्रा के प्रमुख भेद निम्न प्रकार हैं:---

(१) चैक (Cheque)—चैक साख-मुद्रा का एक सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। यह सबसे अधिक प्रचलित साख-पत्र है। भारतीय विनिभय-साध्य विपत्र एक्ट (Indian Negotiable Instruments Act) के अनुसार :—"चैक, बेंक में रुपया जमा करने वाले का अपनी बेंक के लिए ही एक लिखित आदेश है,

जिसके द्वारा उसके खाते में से ग्रादेश प्राप्त करने वाले को ग्रथवा ग्रन्य व्यक्ति या संस्था को, जिसका कि श्रादेश में नाम लिखा हुआ है, श्रादेशानुसार ग्रंकित रुपया दिया जाता है।" चैक सदा ही बैंक के लिए लिखा जाता है ग्रीर इसका भुगतान बैंक को माँग पर तुरन्त ही करना पड़ता है। चैक में तीन पन्न होते हैं ग्रथीत ग्राहर्ता (Drawer), जोकि ग्रादेश देता है, ग्राहार्यी (Drawee) ग्रथीत जिसको कि ग्रादेश दिया जाता है ग्रीर ग्रादाता (Payee), जिसको कि भुगतान किया जाता है। चैक की प्रमुख विशेष-ताएँ इस प्रकार है:—(१) यह सदा ही एक लिखित ग्रादेश होता है, (२) इसके भुगतान पर किसी प्रवार की शर्त नहीं लगाई जाती, (३) यह सदा ही किसी बैंक के लिए लिखा जाता है, (४) इसमें भुगतान की राशि का स्पष्ट रूप में उल्लेख किया जाता है, (५) इसका भुगतान बैंकों को माँग पर तुरन्त ही करना होता है, (६) चैक का भुगतान निर्देशित व्यक्ति ग्रथवा उसके ग्रादेश के ग्रनुसार ही किया जाता है ग्रीर (७) चैक पर ग्राहर्ता (Drawer) के हस्ताक्षर ग्रावश्यक होते हैं।

चैंक म्रनेक प्रकार के होते हैं, जैसे—वाहक [चैंक (Bearer Cheque) भ्रादेश चैंक (Order Cheque), खुला चैंक (Open Cheque), रेखाङ्कित चैंक (Crossed Cheque), प्रमाणित चैंक (Marked Cheque) तथा उत्तर-तिथीय चैंक (Post-dated Cheque)।

- (i) वाहक चैंक उस चैंक को कहते हैं जो निर्देशित व्यक्ति श्रथवा श्रग्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को शोधनीय होता है जो उसे बैंक में प्रस्तुत करता है। इस चैंक पर श्रादाता के हस्ताक्षर श्रावश्यक नहीं होते, यद्यपि सुरक्षा के दृष्टिकोग से बैंक श्रादोता के हस्ताक्षर पर श्रनुरोध करती है। ऐसा चैंक पूर्ण रूप में हस्तान्तरीय (Transferrable) होता है।
- (ii) त्र्यादेश चैंक वह चैंक होता है जिस पर उस व्यक्ति को ही भुगतान मिल सकता है जिसका नाम चैंक में लिखा है। ऐसा चैंक लिखे अनुसार हस्तांतररा-शील अथवा अहस्तान्तरएाशील (Non-transferrable) हो सकता है। ऐसे चैंकों के भुनाने के लिए आदाता के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।
- (iii) रैखांकित चैंक के ऊपर ब्राड़ी रेखा खींचकर ब्रंग्रेजी में '& Co.' लिख दिया जाता है। ऐसे चैंक द्वारा बैंक से नकदी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसकी ब्रिङ्कत रकम ग्रादाता के खाते में ही हस्तान्तरित की जा सकती है। इस प्रकार के चैंक दो प्रकार के होते हैं:—सामान्य रेखांकित चैंक तथा विशिष्ट रेखांकित चैंक। दूसरे प्रकार के चैंक में '& Co.' ब्रथवा 'Not Negotiable' के ब्रतिरिक्त यह भी ब्रिङ्कत किया जाता है कि किस विशेष बैंकर को चैंक का भुगतान होना चाहिए। इस लिखाई का ब्राश्य यह तो नहीं होता है कि चैंक का हस्तान्तरण नहीं हो सकता है। ब्रभिप्राय केवल यही होता है कि हस्तान्तरण करने वाला केवल उसी प्रकार के ब्रिधिकार का हस्तान्तरण कर सकता है जैसा कि स्वयं उसको प्राप्त है।

- (iv) खुले चैकों का अभिप्राय उन चैकों से होता है जिन्हें किसी भी व्यक्ति हारा वेंक के काउण्टर (Counter) पर प्रस्तुत करके भुगतान लिया जा सकता है। ऐसे चैकों की चोरी और खो जाने का भय बहुत होता है।
- (v) प्रमाणित चैंक वह चैंक होता है जो ग्राहार्यी बैंक द्वारा इस प्रकार प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान कर दिया जायगा। यह ग्रादाता के विश्वास के लिए किया जाता है।
- (vi) उत्तर-तिथि चैं कों में केवल इतनी विद्वोषता होती है कि उन पर एक भावी तिथि डाल दी जाती है और उस तिथि से पहिले उनका भुगतान नहीं लिया जा सकता है।
- (२) विनिमय बिल (Bill of Exchange)—भारतीय विनिमय साघ्य विपत्र एक्ट की घारा ५ के अनुसार:—"विनिमय बिल एक लिखित पत्र होता है, जिसमें लिखने वाले की ग्रोर से विना कोई शर्त लगाये किसी व्यक्ति को ऐसा ग्रादेश दिया जाता है कि वह किसी व्यक्ति को ग्रथवा उसके ग्रादेशानुसार ग्रथवा इस पत्र को प्रस्तुत करने वाले को एक निश्चित राशि का भुगतान कर दे।" इस प्रकार विनिमय बिल एक प्रकार का ग्रादेश-पत्र होता है, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मिद्धित राशि चुकाने का ग्रादेश देता है। ऐसा कहा जाता है कि एक सही विनिमय बिल में ५ बार्ते निश्चित होनी चाहिए:—(१) ग्राहर्त्ता, (२) ग्रादेश, (३) ग्राहार्यों, (४) ग्रादाता ग्रोर (५) राशि।

विनिमय विल साधारणतया दो प्रकार के होते हैं:—(i) देशी विनिमय बिल (Inland Bill of Exchange) तथा (ii) विदेशी विनिमय बिल (Foreign Bill of Exchange)। जो बिल देश के ही किसी व्यापारी के ऊपर लिखा जाता है, वह देशी विनिमय बिल कहलाता है, परन्तु यदि बिल का आहर्ता अथवा आहार्यों दोनों में से कोई भी एक विदेशी है तो वह विदेशी विनिमय बिल होगा। प्रथा के अनुसार विनिमय बिल तीन मास की अविध का होता है, अर्थात् बिल लिखने की तिथि के ६० दिन पीछे उसका भुगतान करना आवश्यक होता है, परन्तु कभी-भी दर्शनी बिल (Demand Bills) भी लिखे जाते हैं, जिनका भुगतान माँगने पर तुरन्त ही किया जाता है। ऐसे बिलों पर टिकट (Revenue Stamp) की आवश्यकता नहीं होती है, अन्यथा सभी विनिमय बिलों पर राशि के अनुपात में टिकट लगाये जाते हैं। कोई भी विनिमय बिल उस समय तक विनिमय साध्य या वैध नहीं होता जब तक कि आहार्यी उसे स्वीकार करके उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देता है। यदि निश्चित तिथि पर आहार्यी बिल का भुगतान नहीं करता है तो बिल का अनादर (Dishonour) हो जाता है। ऐसी दशा में भुगतान का उत्तरदायित्त्व लिखने वाले पर होता है।

विनिमय बिल का व्यापार, वाि्एज्य तथा लेन-देन के जगत में भारी महत्त्व होता हैं। (i) इसकी सहायता से एक व्यवसायी नकदी में तुरन्त भुगतान किये बिना ही माल खरीद सकता है। बिल की परिपक्कता (Maturity) के समय तक माल को बेचकर घन प्राप्त किया जा सकता है ग्रीर माल की कीमत का भुगतान किया जा सकता है। (ii) विदेशी व्यापार में तो इससे बहुत ही लाभ होता है, क्योंकि निर्यात व्यापारी को ग्रपने देश की ही मुद्रा में भुगतान मिल जाता है। (iii) इसके कारण बहुमूल्य घातुओं के यातायात ग्रीर बीमे का व्यय बच जाता है। विदेशों को भेजे हुए माल के दाम देश में ही मिल जाते हैं। (iv) विनियोगी वर्ग के लिए यह एक विनियोग का तरल तथा सुविधाजनक साधन उपलब्ध करता है, क्योंकि विनिमय बिल को परिपक्कता से पहले भी ग्रावश्यकता पड़ने पर तुरन्त भुनाया जा सकता है। (v) विनियय बिल उसके स्वामी को निश्चित समय ग्रीर स्थान पर निश्चित राशि का भुगतान प्राप्त करने का ग्रधिकार प्रदान करता है ग्रीर क्योंकि यह विनिमय साध्य (Negotiable) होता है, इसलिए इसे सरलता से खरीदा ग्रीर बेचा जा सकता है। परिपक्कता से पहले रुपये की ग्रावश्यकता पड़ने पर बिल को बैंक द्वारा भुनाया जा सकता है।

(३) बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft)—ड्राफ्ट में चैंक तथा विनिमय बिल दोनों के ही ग्रुएए पाये जाते हैं। बैंक ड्राफ्ट उन विनिमय बिलों को कहते हैं जो एक बैंक द्वारा उसकी अपनी शाखाओं पर लिखे जाते हैं। भारत में ड्राफ्टों पर ठीक उसी प्रकार के नियम लागू होते हैं जैसे कि चैंकों पर। ड्राफ्ट रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का बड़ा सस्ता तथा सुविधाजनक साधन होते हैं। इस कारएए व्यापार के अर्थ-प्रबन्धन में इनका भारी महत्त्व होता है। यदि एक व्यक्ति आगरे से कलकत्ते को १,००० रुपया भेजना चाहता है तो वह स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया की आगरा शाखा से उसकी कलकत्ता शाखा पर १,००० रुपये का ड्राफ्ट खरीद सकता है और फिर इस ड्राफ्ट को कलकत्ते में उस व्यक्ति के पास भेज सकता है जिसे भुगतान होना है। वह व्यक्ति ड्राफ्ट को स्टेट बेंक को कलकत्ता शाखा पर प्रस्तुत करके भुगतान ले सकता है। ठीक इसी प्रकार किसी भारतीय बेंक की लन्दन शाखा पर ड्राफ्ट खरीद कर लन्दन में भुगतान लिया जा सकता है।

(४) प्रतिज्ञा-पत्र ग्रथवा प्रग्-पत्र (Promissory Note)—यह वह लिखित पत्र होता है जिसमें उसका लिखने वाला उसमें लिखी हुई राशि उसमें लिखित व्यक्ति को ग्रथवा उसके ग्रादेशानुसार ग्रथवा उसके वाहक को बिना किसी शतंं के देने की प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञा-पत्र तीन प्रकार के होते हैं:—(?) बैंक प्रतिज्ञा-पत्र (Bank Promissory Note) वह प्रतिज्ञा-पत्र होता है जो साधारणतया देश की केन्द्रीय बैंक द्वारा चालू किया जाता है ग्रौर उसका भुगतान वाहक को माँग पर तुरन्त किया जाता है। भारत में एक रुपये के कुछ नोटों को छोड़कर ग्रन्य सभी नोट रिजर्व बैंक के ऐसे ही प्रतिज्ञा-पत्र हैं। (२) चलन प्रतिज्ञा-पत्र (Currency Promissory Note) तथा बैंक प्रतिज्ञा-पत्रों में केवल इतना ही ग्रन्तर होता है

कि ये देश की सरकार अथवा देश के मुद्रा-संचालक की ग्रांर से चालू किए जाते हैं। ग्रन्य सभी बातों में दोनों समान ही होते हैं। (२) व्यापारिक प्रतिज्ञा-पत्र (Commercial Promissory Note) सरकार तथा बैंक द्वारा नहीं जिल्ला जाता है। प्रकृति तथा रूप में यह विनिमय बिल की भाँति ही होता है। श्रन्तर यह होता है कि इसको देनदार लिखता है श्रीर हस्ताच्तर करके लेनदार को देता है। इसमें ग्राह्मा श्रीर ग्राह्मा दोनों एक ही व्यक्ति होता है। इसके विपरीत विनिमय बिल को लेनदार लिखता है ग्रीर स्वीकृति के पश्चात् देनदार उसे लेनदार के पास भेज देता है। उसमें ग्राह्मा, ग्राह्मा तथा श्रादाता तीनों साधारएतया श्रलग-ग्रलग व्यक्ति ही होते हैं। प्रतिज्ञा-पत्र सदा ही मुद्दती होता है ग्रर्थात् इसका भुगतान एक निश्चित समय-ग्रवधि के पश्चात् ही मिल सकता है।

(४) हुन्डी (Hundi)—यह भारतवर्ष का एक विशेष साख-पत्र है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग एक हजार वर्ष पहले से भारत में यह साख-पत्र प्रचलित है। स्मरण रहे कि विनिमय बिल, प्रतिज्ञा-पत्र तथा अन्य साख-पत्रों को वैद्यानिक स्वीकृति प्राप्त होती है, परन्तु हुन्डियों का चलन रीति-रिवाज पर आधारित है। ये साधारणतया स्थानीय भाषा में लिखी जाती हैं और भारतीय देशी बैंकों, व्यापारियों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उपयोग की जाती हैं। विनिमय बिलों की भाँति इन पर भी टिकट लगाया जाता है। प्रकृति में ये विनिमय बिलों की ही भाँति होती हैं। भुगतान के पश्चात् हुन्डी को खोखा कहा जाता है।

हुन्डियाँ कई प्रकार की होती हैं, परन्तु सबसे ग्रधिक प्रचलन दर्शनी तथा मुद्दी हुन्डियों का होता है। (i) दर्शनी हुन्डी का भुगतान माँग पर तुरन्त ही किया जाता है, (ii) परन्तु मुद्दती हुन्डी का भुगतान एक निश्चत ग्रंकित ग्रवधि के पश्चात होता है। हुन्डियाँ ग्रोर भी बहुत से प्रकार की होती है, जैसे—(iii) देखनहार हुन्डी जिसका भुगतान उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को ही कर दिया जाता है। (iv) धनी जोग हुन्डी का भुगतान केवल निश्चत पाने वाले को ही हो सकता है ग्रौर (v) नाम जोग ग्रथवा फरमान जोग हुन्डी वह होती है जिसका भुगतान पाने वाले के ग्रादेशानुसार किया जाता है ग्रौर जिसमें वेचान (Endorsement) की ग्रावश्यकता होती है। वेचान का ग्रथं यह होता है कि हुन्डी में लिखित व्यक्ति यह स्पष्टतया लिखता है कि हुन्डी की राशि का कि किस व्यक्ति को भुगतान होना है। (iv) इसी प्रकार शाहजोग हुन्डी वह होती है जिसका भुगतान किसी ग्रावरणीय व्यापारी को ही हो सकता है।

(६) साख प्रमाण-पत्र (Letters of Credit)—साख प्रमाण-पत्र एक व्यक्ति, फर्म अथवा बैंक द्वारा लिखा हुआ एक प्रकार का पत्र होता है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति अथवा बैंक से यह प्रार्थना की जाती है कि वे पत्र में अंकित व्यक्ति को एक निश्चित् मात्रा के भीतर किसी भी अंश तक साख प्रदान कर दें। बहुषा इस पत्र में एक तिथि का उल्लेख कर दिया जाता है और जिसके नाम पत्र लिखा जाता है उससे इस तिथि तक ही साख प्रदान करने की प्रार्थना की जाती है। ऐसे प्रमाण-पत्र साधारणतया बेंकों द्वारा ही चालू किए जाते हैं। ये प्रमाण-पत्र भी दो प्रकार के होते हैं: (i) साधारण साख-प्रमाण-पत्र तथा (ii) चलायमान साख प्रमाण-पत्र (Circular Letters of Credit)। एक साधारण पत्र केवल एक ही बैंक ग्रथवा फर्म के नाम लिखा जाता है, परन्तु चलायमान पत्र एक ही साथ जारी करने वाली बैंक वी ग्रनेक शाखाग्रों, ग्रभिकर्ताग्रों तथा ग्रन्य सम्बन्धित बेंकों को लिखा जाता है। सभी साख-पत्रों के ग्राधार पर ऋण नकदी में प्राप्त किये जा सकते हैं ग्रथवा विनिमय बिलों के रूप में। इस प्रकार प्राप्त ऋणों को पत्र की पीठ पर ग्रंकित करना ग्रावस्थक होता है।

- (७) यात्री धनादेश (Traveller's Cheque)—ये चैंक यात्रियों के लिए बड़े उपयोगी होते हैं, क्योंकि इनको प्रस्तुत करके यात्री चैंक निकालने वाली वैंक की किसी भी शाखा, श्रिभिक्ती श्रिथवा सम्बन्धित संस्था से रुपया ले सकता हैं। जितनी ही ऐसी शोधन संस्थायों की संख्या श्रिषक होती है उतनी ही यात्री को सुविधा भी श्रिषक रहती है। प्रत्येक चैंक के बदले में उस पर छुपी हुई राशि मिलती है श्रीर यात्री को भुगतान करने वाली बेंक के सामने अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। वैसे भी चैंक प्रदान करने वाली बेंक श्रुपने सामने यात्री से उन पर हस्ताक्षर करा लेती है श्रीर यह हस्ताक्षर नमूने (Specimen) के रूप में उपयोग होते हैं। इस प्रकार चैंक के खो जाने श्रुथवा घोखेबाजी के कारण हानि होने का भय नहीं रहता है।
- ( ८ ) कोषागार विपत्र (Treasury Bills)—कोषागार विपत्र सरकार के अल्पकः लीन ऋगों के सूचक होते हैं। इन पत्रों की निकासी तीन, छः, नौ अथवा बारह महीनों की अविध के लिए की जाती है। वात यह है कि सरकार की आय प्राप्ति का समय बहुधा निश्चित होता है, परन्तु आय प्राप्ति के समय से पहले सरकार को धन की आवश्यकता पड़ सकती है। इस काल के लिए सरकार कोषागार विपत्रों के द्वारा ऋगा प्राप्त करती है। ये ऋगा इस आशा पर लिए जाते हैं कि आय प्राप्त होते ही इनका भुगतान कर दिया जायगा। इन पत्रों की निकासी के लिए सरकार निविदा (Tenders) माँगती है, जिसमें निविदा देने वालों से उस ब्याज का ब्योरा माँगा जाता है जिस पर वे ऋगा देने को तैयार हैं। ऐसे निविदे एक निश्चित राशि के लिए ही माँगे जाते हैं और फिर उस निविदे को स्वीकार किया जाता है जिसमें सबसे कम ब्याज माँगा जाता है। भुगतान निश्चित राशि में से ब्याज की राशि वाट कर लिया जाता है और भुगतान के समय विपत्र में अंकित पूरी राशि लौटा दी जाती है।
- (६) पुस्तकीय साख (Book Credit)—जब कोई व्यापारी उधार माल बेचता है अथवा जब कोई बेंक ऋण देती है और उधार की राशि को अपनी खाता बही में दिखाती है तो इस प्रकार के उधार को पुस्तकीय साख कहते हैं। इस प्रकार की खाता पुस्तकों के हिसाब को वैधानिक रूप में उधार मान लिया जाता है। यद्यपि यह ग्रावश्यक नहीं है कि उन पर ऋणी के हस्ताक्षर हों। इस प्रकार

का पुस्तकीय साख बहुत प्रचलित है और एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारियों तथा एक बैंक द्वारा दूसरे बैंकों को प्रदान किया जाता है। बहुधा उधारों का एक बड़ा भाग ग्रापसी ऋगों के समायोजन से ही चुकती हो जाता है। शेष के लिये नगदी में भुगतान कर दिया जाता है। बैंकों के लिए इस प्रकार के समायोजन का कार्य समाशोधन-गृहों (Clearing Houses) द्वारा किया जाता है।

(१०) अनुग्रह बिल (Accomodation Bill)—यह बिल प्रकृति तथा रूप में विनिमय बिल की ही भाँति होता है। अन्तर केवल इतना होता है कि विनिमय बिल प्राप्त मूल्य के आधार पर लिखा जाता है, परन्तु यह बिना किसी मुआवजे के लिखा और स्वीकार किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल पारस्परिक साख का प्रदान करना होता है। अनुग्रह बिल को बैंक द्वारा भुनाकर दोनों ही दलों को साख प्राप्त हो जाती है। ऐसे बिल साख प्राप्त करने का एक अच्छा और उपयोगी साधन होते हैं।

उपरोक्त साख-पत्रों के ग्रतिरिक्त बाँड्स (Bonds), ऋगा-पत्र (Debentures), जो कि सम्मिलित पूँजी कम्पनियों द्वारा निकाले जाते है, ग्रादि ग्रौर भी बहुत से साख- पत्र होते हैं, जो विनिमय साध्य होते हैं ग्रौर काफी लोकप्रिय भी हैं।

# साख के कार्य श्रौर उसके लाभ-

पूँजीवादी ग्राधिक प्रणाली में साख व्यवस्था का ग्रधिक महत्त्व है। यह तो सत्य है कि साख पूँजी का निर्माण नहीं करती है, परन्तु यह पूँजी में गतिशीलता उत्पन्न करके उद्योग ग्रौर व्यापार की बड़ी सेवा करती है। ग्राजकल का बाजार विश्वव्यापी है ग्रौर संसार के सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर हैं ग्राज का संसार ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर ग्राधारित है ग्रौर उत्पत्ति काफी बड़े पैमाने पर होती है। इस विशालकाय ढाँचे को चलाने के लिए साख की भारी ग्रावश्यकता होती है। केवल व्यक्तिगत रूप में ही मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाता है, वरन् सामूहिक रूप में भी वह इस पर ग्राश्रित है। इसके प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं—

- (१) पूंजी की उत्पादक शक्ति में वृद्धि—साख पूँजी में गतिशीलता उत्पन्न करके उसकी उत्पादन-शक्ति को बढ़ा देता है। इसके द्वारा बेकार पड़ी हुई पूँजी का उन व्यक्तियों के पास हस्तान्तरए। हो जाता है जो उसे उत्पादन कार्य में लगा कर अपना ही नहीं वरन् समाज और राष्ट्र का भी भला करते हैं।
- (२) बहुमूल्य घातु की बचत—साख-पत्रों का उपयोग विनिमय माध्यम के रूप में भी होता है। इससे एक स्रोर तो विनिमय माध्यम की मात्रा बढ़ जाने के कारण व्यापार श्रौर व्यवसाय में सुविधा होती है ग्रौर दूसरी ग्रोर बहुमूल्य धातुग्रों के उपयोग में बचत होती है।
- (३) व्यापार की उन्नित में सहायता—साख से व्यापार की उन्नित में भारी सहायता मिलती है। यदि बैंकों की सहायता से विभिन्न देशों के व्यापारी एक दूसरे

से परिचित न हों तो व्यापार का भ्राधार ही समाप्त हो जाय। सारा ही जाता ही विनिमय बिलों, ड्राफ्टों भ्रादि पर भ्राधारित होता है। बिना समुचित सार्थ जाता है के भ्राधुनिक म्रन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य की कलाना भी नहीं की जा सकती है।

(४) दूर-दूर के स्थानों तक भुगतान में सुविधा—बड़ी-बड़ी राशियों के भुगतान के लिए साख-पत्र ग्रधिक सुरक्षित, सस्ता तथा सुविधाजनक साधन होते हैं श्रीर इनसे दूर-दूर धन भे जने में भी सुविधा होती है।

(४) ग्रार्थिक विकास की सुविधा—उधार ग्रथवा स्थगित शोधनों के लिए तो साख प्रारातुल्य होती है ग्रोर उधारों की सुविधा, ग्राधिक, व्यवसायिक ग्रौर वार्गिज्यक उन्नति का प्रतीक होती है।

(६) बचत को प्रोत्साहन—साख से बचत तथा पूँजी के संचय को प्रोत्साहन मिलता है। बैंक जैसी साख संस्थाएँ छोटी-छोटी बचतों को भी जमा कर लेती हैं। ब्याज का लोभ लोगों को ग्रधिक बचत करने के लिए प्रेरित करता है।

(७) मूल्यों में स्थिरता—साख पर समुचित नियन्त्रण रखने से देश में कीमत-स्तर की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है, जिसके अनेक लाभ होते हैं।

( ८ ) मुद्रा-प्रगाली में लोच - साख निर्माण बहुषा बैंकों द्वारा किया जाता है, जो व्यापार ग्रौर व्यवसाय की ग्रावश्यकताग्रों के ग्रनुसार उसका विस्तार ग्रथवा संकुचन करती है। इससे देश की मुद्रा-प्रगाली में लोच बनी रहती हैं।

(६) उत्पत्ति के साधनों का अधिकतम उपयोग —साख क्रयःशक्ति और सरकारी आय में वृद्धि करके सरकार को देश के मानव और भौतिक साधनों के अधिक भ्रच्छे उपयोग का भ्रवसर देती है।

(१०) ग्रार्थिक संकटों का मुकाबिला—साख की सहायता से सरकार को संकट-कालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए ग्रावश्यक घन प्राप्त हो जाता है ग्रौर वह ग्रपनी प्राप्त ग्राय के व्यय को समुचित रूप में नियन्त्रित कर सकती है।

#### साख की हानियाँ (Dangers of Credit)-

अनुभव बताता है कि साख का दुरुपयोग भी सम्भव है। एक सेविका के रूप में तो इसकी सेवायें सराहनीय होती हैं, परन्तु एक स्वामिनी के रूप में यह देश के आधिक जीवन को इतना दूषित कर सकती है कि समाज की हानियों की कोई सीमा ही न रहे। साख के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं:—

(१) ग्राय का ग्रसमान वितरगा—साख तथा पूँजीवादी उत्पादन-प्रगाली दोनों का ही एक साथ विकास होता है। पूँजीवाद का विकास करके साख देश के भीतर ग्राय के वितरगा में घोर ग्रसमानताएँ उत्पन्न करती है। सारा घन ग्रौर सारी ग्रायिक शक्ति थोड़े से ही हाथों में एकत्रित हो जाती है। इससे समाज के एक वर्ग

को दूसरे का शोपण करने का भ्रवसर मिल जाता है भ्रौर सामाजिक भ्रशान्ति बढती है।

- (२) ग्रपव्यय का भय-ऋगों के सुगमता के साथ प्राप्त हो जाने के कारण समाज में अपव्यय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे समाज का नैतिक स्तर नीचे गिर जाता है :
- (३) श्रकुशल व्यवसायों का पोषगा—उधार मिलने की श्रत्यधिक सुविधा ग्रयोग्य तथा अकुशल व्यवसायों को जन्म देती है ग्रौर जब ये व्यवसाय ठप्प होते हैं तो राष्ट्र का भारी अनहित होता है।
- (४) सट्टो को प्रोत्साहन—साख सट्टो को प्रोत्साहित करती है, जिससे बुग्रारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है ग्रौर कीमतों में ग्रकारण ही भारी उच्चावचन पैदा होते हैं।
  - (४) साख के ग्रत्यिक प्रसार का भय—साख का एक गम्भीर दोष यह भी है कि तेजी के समय इसका ग्रधिक विस्तार होता है ग्रीर मन्दी के काल में भारी संकुचन भी। इस प्रकार स्फीति तथा विस्फीति दोनों ही की प्रवृत्तियों को श्रौर भ्रघिक बल मिल जाता है। भारी कठिनाई यह है कि साख मानव नियन्त्रगा पर भ्रवलम्बित है ब्रौर यदि ऐसा नियन्त्ररा कुशल नहीं है तो यह गम्भीर दोष उत्पन्न कर सकती है।
  - (६) एकाधिकार संस्थाग्रों की स्थापना—साख प्रगाली में पूँजी का कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रीयकरएा हो जाता है, जिससे देश में एकाधिकारिक -संस्थाम्रों की स्थापना होने लगती है। ये संस्थायें जनता का शोषण करती हैं श्रीर भौका मिलते ही राजनैतिक सत्ता को भी हथियाने की चेष्टा करने लगती हैं। चेंक साख का निर्माण किस प्रकार करती है ?—

साख-निर्माण की सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था बैंक है। बेंक साख का निर्माण दो प्रकार करती हैं:---

(१) बैंक नोटों की निकासी साख उत्पादन की ही एक विधि है। भूतकाल में प्रत्येक बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार होता था, परन्तु इस समय यह एकाधिकार केवल देश की केन्द्रीय बैंक के पास होता है। जितने नोटों का निर्गम बैंक द्वारा किया जाता है उन सबके पीछे धातु निधि नहीं रखी जाती है। जिन देशों में बैंक नोटों की वातु-मुद्रा में बदलने का वचन देती है वहाँ भो नोटों के केवल एक भाग को ही <mark>घात</mark>ु-निधि के रूप में रखा जाता है. शेष के पीछे प्रतिभृतियाँ रखी जाती हैं; क्योंकि अनुभव द्वारा वैं कि को यह ज्ञात होता है कि कूल नोटों के एक छोटे से भाग को ही जनता द्वारा घातु में बदला जाता है। जब तक बैंक के ऊपर विश्वास रहता है, ये नोट बिना किसी बाधा के चलते हैं। इस प्रकार नोट चालू करने वाली बेंक साख उत्पन्न करती है श्रौर इस साख द्वारा व्यवसायों को क्रयः शक्ति प्रदान की जाती है।

(२) बैंक द्वारा साख निर्माण की दूसरी रीति ऋणों को देना और उनके लिए निन्ने पों का उत्पन्न करना है। जो घन किसी बैंक के पास जमा किया जाता है उसको बैंक श्राय कमाने तथा श्रपने साख संगठन निर्माण के लिये उपयोग करती है, परन्तु बहुधा ऐसा होता है कि यदि बैंक में जमा केवल १०,००० रुपया की है तो बैंक श्रासानी से ४०,००० या ४०,००० रुपया उधार दे देगी। ऊपर से देखने पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह श्रसम्भव है, परन्तु वास्तव में बैंक सदा ही ऐसा करती है श्रीर यही बैंक के लाभ का प्रमुख साधन है। श्रनुभव द्वारा बैंक को यह ज्ञात होता है कि जो ऋण उसके द्वारा दिये जाते हैं उनके एक छोटे से भाग के लिए ही नकदी की माँग की जाती है। श्रिधकाँश ऋणा तो विभिन्न याहकों के लेखों में श्रावश्यक समायोजन करने से बिना नकदी दिए ही सुलक्ष जाते हैं। इसका कारण यह है कि एक बैंक के विभिन्न ग्राहक श्रापस में भी एक-दूसरे के ग्राहक होते हैं श्रथवा श्रन्य किसी ऐसी बैंक के ग्राहक होते हैं जिसकी बैंक विशेष से लेन-देन है। ऐसी दक्षा में विभिन्न ग्राहकों द्वारा एक-दूसरे को जो भुगतान किए जाते हैं वे साधारणतया एक-रूसरे को ग्राहकों द्वारा एक-दूसरे को जो भुगतान किए जाते हैं वे साधारणतया एक-रूसरे को रहते हैं। एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायगा:—

मान लीजिये कि एक बैंक के पास नकदी में केवल १०,००० रुपये हैं ग्रौर उसके क, ख, ग, घ, ङ पाँच ग्राहक हैं. जिनमें से प्रत्येक को वह द-द हजार रुपए का ऋण देती है । इन पाँच ग्राहकों की ग्रापस में भी लेन देन है ग्रौर इनका हिसाब भी वैंक द्वारा ही रखा जाता है। मान लीजिए कि क ५,००० रुपए का चैक लिखता है ग्रौर बैंक को यह ग्रादेश देता है कि यह राशि ख को चुका दी जाय। बैंक तुरन्त इतनी राशि क के खाते से निकाल कर ख के खाते में जमा कर देगी। इसी प्रकार ख इतनी ही राशि का चैक ग के लिए लिख सकता है, ग फिर घ के लिए और घ ग्रागे चलकर ङ के लिए। श्चन्त में ङ इसी राशि का चैक क के लिए लिख सकता है। प्रत्येक बार जब चैक बैङ्क को भेजा जाता है तो बैंक को विभिन्न ग्राहकों के खातों में जमा-घटी करनी पड़ती है, परन्तु जैसा कि स्पष्ट है कि उपरोक्त लेन-देन में बैंक को वास्तव में नकदी में कुछ भी देने की ग्रावश्यकता नहीं पड़ती है, केवल लेखों में समायोजन करने से ही काम चल जाता है । इस प्रकार यद्यपि दिखाने के लिए ५ बार पाँच-पाँच हजार रुपये का भुगतान करके बैंक ने २५,००० रुपये का भुगतान किया है, परन्तु उसे नकदी में कुछ भी नहीं देना पड़ा है। इस प्रकार २५,००० रुपये की राशि का साख निर्माण हुग्रा। बेंकों की ऋगा-दान विधि यह होती है कि प्रत्येक ऋगा लेने वाले को निक्षेपदाता की भाँति समभा जाता है । जितनी राशि उसको उघार दी गई है उतने का खाता उसके नाम में खोल दिया जाता है, जिसमें से एक साधारण निक्षेपधारी की भाँति वह चैक से रुपया निकाल सकता है। यही कारण है कि बहुधा यह कहा जाता है कि वैंक के ऋगु उसके निद्धा पों को पैदा करते हैं (Loans Create Deposits)। इस प्रकार बैंक के निक्क्षेप दो प्रकार के होते हैं: -- प्रथम, वे जो निक्षेपघारियों ने रुपया

जमा करके उत्पन्न किए हैं ग्रौर दूसरे वे जो ऋ एा लेने वालों ने ऋ एा लेकर उत्पन्न किये हैं।

विद्रस् (Withers) का विचार है कि बैंक के सभी ऋण इस प्रकार निद्धे पों को उत्पन्न करके साख का निर्माण करते हैं। बैंक के प्रधिकाँश निक्षेपधारी नकदी में भुगतान नहीं माँगते है, यद्यपि बैंक ऐसे भुगतान से कभी इन्कार नहीं करती है। प्रधिकांश भुगतान चैकों द्वारा किये जाते हैं, जो या तो उसी बैंक में जमा हो जाते हैं जिस पर वे लिखे गये हैं प्रथवा किसी भ्रन्य बैंक में जमा होकर नए निक्षेप उत्पन्न करते हैं। विभिन्न बैंकों की भ्रन्योन्य लेन-देन चलती रहती है, जिसका समायोजन समाशोधन गृहों द्वारा कर दिया जाता है। नकदी के भुगतान बहुत ही कम होते हैं।

लीफ (Leaf) तथा कैनन ने बैंकों द्वारा इस प्रकार साख निर्माण की कड़ी आलोचना की है। उनका विचार है कि साख निर्माण का कार्य निद्धिप-धारियों द्वारा आरम्भ किया जाता हैं, न कि बैंक द्वारा। बैंक ऋणों के प्रदान करने में इसी कारण सफल होती है कि निक्षेपधारी अपनी निक्षेपों के अधिकांश भाग का भुगतान नकदी में नहीं लेते हैं। यहाँ लीफ तथा कैनन ने बैंक के वार्य को समम्भने में भूल की है, क्योंकि बैंक तो साधारणतया उन्हों निक्षेपों को ऋणों के रूप में देती है जो निकाली नहीं जाती है।

## साख की सीमायें (Limits of Credit)—

इस सम्बन्ध में यह प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण है कि बेंक किस सीमा तक साख का विस्तार कर सकती है। ऋ शों के कुछ न कुछ भागों की नकदी में मांग अवश्य की जाती है। इस सम्बन्ध में बेनहाम ने बैंकों की साख निर्माश शिक्त की तीन सीमाएँ बताई हैं, जो निम्न प्रकार हैं:—

- (१) देश में रोक (Cash) की कुल मात्रा—स्मरण रहे कि वेवल रोक के भाषार पर ही साख का निर्माण हो सकता है। जितनी ही देश में रोक अथवा विविधाह्य मुद्रा अधिक होगी उतनी ही अधिक मात्रा में साख का निर्माण हो सकेगा। किसी देश में रोक की मात्रा केन्द्रीय बैंक द्वारा निश्चित की जाती है, जो साख के विस्तार तथा संकुचन के हेतु उसे घटा-बढ़ा सकती है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक की नीति साख की सीमा निर्घारित करती है।
- (२) जनता द्वारा रोक का उपयोग—यदि किसी देश में चैकों के स्थान पर नकदी के उपयोग की ही प्रथा है तो जैसे ही बैंक द्वारा साख प्रदान किया जायगा, ऋगी चैंक की सहायता से नकदी प्राप्त कर लेगा। नकद कोषों में कमी होते ही बैंक की साख निर्माण शक्ति भी घट जायगी। भारत में ऐसी ही प्रथा है श्रीर इसी कारण बैंक कम मात्रा में साख का निर्माण कर पाती हैं। इसके विपरीत जिन देशों में चैंकों का ही विस्तृत उपयोग होता है वहाँ बैंकों की साख निर्माण शक्ति श्रीषक होती है।

इस प्रकार जनता की रोक उपयोग सम्बन्धी ग्रादतें साख के निर्माण की सीमाएँ निश्चित करती हैं।

(३) कुल दायित्त्वों के साथ नकद कोष का अनुपात—तीसरी सीमा बैंकों के नकद कोषों के उनके निक्षेपों के अनुपात द्वारा निश्चित की जाती है। कुछ देशों में तो यह अनुपात वैधानिक रूप में निश्चित कर दिया जाता है, परन्तु अन्य देशों में इसका आधार परम्परागत होता है और आदेयों की तरलता के उस अंश पर निर्भर होता है, जिसे बैंक की सुरक्षा के लिए आवश्यक समक्षा जाता है। यह तो स्पष्ट ही है कि जब भी बेंक द्वारा कोई नया ऋगा दिया जाता है अथवा कोई नया निक्षेप उत्पन्न किया जाता है तो बेंक की देन में वृद्धि होती है और उसके साथ ही साथ बेंक के नकद कोषों और उनके निक्षेपों का अनुपात भी घटता है, परन्तु क्योंकि बेंक भुगतानों को नकदी में चुकाने की गारन्टी देती है और नकदी में भुगतान न कर पाने की दशा में बैंक के विश्वास खो देने तथा ठप्प हो जाने का भय होता है, इसलिए बैंक नकद कोषों को निक्षेपों के एक निश्चित न्यूनतम् प्रतिशत से नीचे नहीं गिरने देती हैं। जिन देशों में नकद कोषों तथा निक्षेपों के अनुपात को नियमानुसार निश्चित नहीं किया जाता है वहाँ भी अनुभव के आधार पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैंकों द्वारा नकद कोषों की न्यूनतम् सीमा निश्चत कर ली जाती है। नकद कोषों तथा निक्षेपों का यह अनुपात साख के विस्तार की सबसे महत्त्वपूर्ण सीमा है।

#### श्रन्य सीमायें—

उक्त सीमाग्रों के ग्रलावा बेंकों द्वारा साख-सुजन की निम्न सीमार्थे भी हैं—
(i) बैंक को केन्द्रीय बैंक के पास अपने दायित्त्वों का कुछ भाग रिक्तत कोषों के रूप में जमा करना पड़ता है, जिसमें दायत्त्वों की घट-बढ़ के साथ-साथ परिवर्तन होता रहता है। यह कोष भी बेंक की साख-सुजन की शक्ति को सीमित कर देती है।
(ii) केन्द्रीय बैंक की खुले बाजार की कियाओं व बैंक दर नीति आदि का भी बेंक द्वारा साख का प्रसार करने पर ग्रंकुश रहता है। (iii) जमाकत्तीओं की बैंकों में आपना द्रव्य रखने की इच्छा पर भी साख का सुजन निर्भर होता है, क्योंकि यदि जमाकत्ती (Depositor) बेंक में हपया कम जमा करायें, तो बेंक साख का ग्रधिक सुजन नहीं कर सकेंगे। (iv) जमानतों की श्रेष्ठता पर भी साख का ग्रधिक या कम निर्माण होना निर्भर रहता है, क्योंकि बेंक ग्रन्थ प्रतिभूतियों के ग्राधार पर ही ऋण दिया करते हैं।

- 2. What is credit and how do commercial banks create credit? (Raj., B. A., 1954; Agra, B. A., 1959)
- 3. How does a bank create credit? Examine the limitation's on the power of banks to create credit.

(Agra, B. A., 1956)

4. What are the different ways in which bank deposits arise? How do loans create deposits?

(Agra, B. Com., 1958)

- 5. 'Every loan creates a deposit'. How does it happen.
  (Agra, B. Com., 1956)
- 6. बेंक साख कैसे उत्पन्न करते हैं ? साख उत्पन्न करने में बेंक की शिक्त कैसे सीमित है ? (Sagar, B. A., 1957)
- 7. 'ऋषा साख का निर्माण करते हैं' (Loans create credit)। इस मत की व्याख्या की जिए और बताइये कि बैंकों या अधिकोषों द्वारा साख निर्माण कर सकने की क्या सीमाएँ हैं? (Sagar, B. Com., 1954)
- 8. Criticise the view that a bank can credit to the extent of several times the amount of its cash resources.

(Bombay, B. Com., 1950)

9. 'Loans create credit'. Discuss this statement and point out the limitations on the power of banks to create credit.

(Agra, B. Com., 1945; Raj., B. Com., 1950)

10. Write a note on :-Bill of Exchange.

(Raj., B. A., 1955)

#### अध्याय १४

## बैंक की कार्य-प्रणाली

(The Banking Operations

#### श्रारमिभ ह--

पिछले अघ्याय में हमने बैंक और उसके कार्यों का अघ्ययन किया था। प्रस्तुत अघ्याय में हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि बैंक अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को किस प्रकार सम्पन्न करती है। बैंक का प्रमुख कार्य रुपये की लेन-देन करना होता है। बैंक लोगों से ब्याज पर रुपया लेती है और फिर उसी रुपये को उघार पर चलाती है। वास्तिवक जीवन में बैंक ऋगा के रूप में प्राप्त राशि से भी अधिक रुपया उघार दे सकती है, जिसका कारण यह होता है कि बैंक साख का निर्माण करती है और यह साख-मुद्रा भी नकद रुपये की भाँति उघार दे दी जाती है। एक साधारण व्यवसायी की भांति बैंक को भी अपना व्यवसाय चलाने के लिए घन अथवा पूँजी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बैंक की कार्य-प्रणाली का अध्ययन बड़े ऋंश तक इस बात का अध्ययन होगा कि बैंक किस प्रकार पूँजी प्राप्त करती है और फिर इस प्राप्त पूँजी का उपयोग करके किस प्रकार लाभ कमाती है।

## वैंक द्वारा पूँजी प्राप्त करना—

एक बैंक द्वारा पूँजी प्राप्त करने के साधन निम्न प्रकार होते हैं:--

(१) ग्रंश पूँजी (Share Capital)—ग्रामुनिक बैंकों का संगठन सम्मिलित पूँजी कंपनियों (Joint-stock Companies) की भाँति होता है। वे भी मिश्रित पूँजी संस्थायें होती हैं। बैंक का संचालक-मण्डल यह निश्चय कर लेता है कि बैंक कुल कितनी पूँजी से व्यवसाय ग्रारम्भ करेगी ग्रथवा उसकी ग्रधिकृत पूँजी (Authorised capital) कितनी होगी। तत्पश्चात् इस ग्रधिकृत पूँजी को ग्रंशों में बाँट दिया जाता है, जिनमें से प्रत्येक बरावर मूल्य का होता है। इन ग्रंशों को बाजार में वेचने के लिए उपस्थित किया जाता है! संचालक-मण्डल द्वारा बहुधा यह भी निश्चय कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति ग्रधिक से ग्रधिक कितने ग्रंश खरीद सकता है। इसके विपरीत कभी-कभी एक व्यक्ति को किसी भी सीमा तक ग्रंश खरीद की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। ग्रंश खरीदने वाला व्यक्ति बैंक का ग्रशधारी (Share-holder) कहलाता है। ग्रशों की बिक्री से प्राप्त राशि बैंक की पूँजी होती है ग्रीर कुछ दशाग्रों में तो बेंक की कुल पूँजी का काफी बड़ा भाग ग्रश पूँजी के रूप में ही होता है। साथारसत्या ग्रारम्भ में ही यह निश्चण कर दिया जाता है कि क्रितनी

स्रंश पूँजी प्राप्त करेगी, यद्यपि यह स्रावश्यक नहीं है कि इस प्रकार निर्धारित पूँजी की पूर्ण मात्रा प्राप्त हो ही जाय।

- (२) निक्षेप अथवा जमाधन (Deposits) यह बैंक की पूँजी का दूसरा साधन है। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, बैंक जनता से रुपया उधार लेकर अपने व्यवसाय में लगाती है । बैंक के ऋगा साधारगातया निक्षेप अथवा जमाधन के रूप में होते हैं। लोगों को यह अधिकार होता है कि निश्चित शर्तों पर वे अपना रुपया बैंक में जमा कर सकते हैं। इस प्रकार यह रुपया सुरक्षित ही नहीं रहता, बल्कि म्राधिकाँश दशास्रों में बैंक इस जमा पर ब्याज भी देती है। निक्षेपधारी को बिना किसी शर्त के अथवा कुछ शर्तो पर जमा किया हुआ रुपया निकालने का अधिकार दिया जाता है। निक्षेप कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे—चालू जमा, निश्चितकालीन जमा, ग्रि-िश्चितकालीन जमा, सेविंग बैंक जमा, गृह बचत जमा, इत्यादि । प्रत्येक प्रकार की षमा में जमाधारी ग्रौर बैंक के ग्रिधिकारों में भ्रन्तर होता है ग्रौर प्रत्येक के लिए भ्रलग-ग्रलग प्रकार के खाते खोले जाते हैं। इन खातों में छोटी से छोटी राशि से लेकर बड़ी से बड़ी राशिभी जमा की जा सकती है। यह यथार्थ में बैंक का एक बड़ा ही महत्त्व-पूर्ण कार्य है; क्योंकि इसी के द्वारा जनता के पास फालतू पड़े हुये घन का लाभपूर्ण लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। जिस प्रकार बूँद बूँद पानी जमा होते-होते कुछ समय पश्चात् तालाव भर जाता है, ठीक इसी प्रकार थोड़ी-थोड़ी बचत के इकट्टा हो जाने से देश के लिए पर्याप्त पूँजी जमाही सकती है। वैसे भी एक ग्रच्छी बैंक की पहिचान इसी से होती है कि उसे कितना जमाधन प्राप्त हुम्रा है।
- (३) ऋरण (Loans)—जमाधन भी एक प्रकार का ऋरण ही होता है, जो बैंक द्वारा जन-साधारण से लिया जाता है, परन्तु जमाधन के अतिरिक्त एक बैंक प्रत्यक्ष रूप में भी ऋरण ले सकती है। ऐसे ऋरण साधारणतया व्यक्तियों से नहीं लिए जाते हैं, बिल्क अन्य वैकों, केन्द्रीय बैंकों अथवा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं से लिए जाते हैं। वैसे तो एक बैंक किसी भी काल में ऋरण ले सकती है, परन्तु साधारण परिस्थितियों में बहुधा अंश पूँजी तथा जमाधन से ही काम चलाया जाता है। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ऋरणों की शरण ली जाती है। जब किसी बंक के निक्षेत्रधारी इतनी अधिक मात्रा में नकदी की मांग करने लगते हैं कि बैंक किसी भी प्रवार अपने साधनों में से इस माँग को पूरा नहीं कर पाती है तो बैंक देश की केन्द्रीय बैंक अथवा किसी दूसरी बैंक से ऋरण ले सकती है। ऐसे ऋरण साधारणतया थोड़े काल के लिए ही लिये जाते हैं और संकट वाल का अन्त होते ही लौटा दिये जाते हैं।
- (४) साख का निर्माण (Creation of Credit) बैंक के इस कार्य का विस्तृत अध्ययन एक पिछले अध्याय में किया जा चुका है। साख का निर्माण करना और इस प्रकार निर्मित साख में व्यवसाय करना बैंक की एक प्रमुख विशेषता

है। बैंक की देनदारी पर लोगों का विश्वास होने के कारण बैंक लगभग सदा ही उससे बहुत श्रिष्क मात्रा में ऋण दे सकती हैं जितना कि उनके पास नकद कोष है। अपने पास केवल ४,००० रुपये नकद रहते हुए भी वैंक २४,००० रुपये तक के ऋण दे सकती है। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि बैंक ऋण लेने वालों के खाते खोल देती है, जिसमें से वे धीरे-धीरे आवश्यकतानुसार ऋण की अधिकृत राश्चि निकाजते रहते हैं। ऋण की सारी राश्चि की नकदी में माँग नहीं की जाती है। अधिकांश भुग-तान केवल विभिन्न खातेदारों के खातों में आवश्यक समायोजन करके ही सम्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि एक वैंक के विभिन्न ग्राहक या तो आपस में एक दूसरे के ग्राहक होते हैं या किसी दूसरी वैंक के ग्राहक होते हैं, जिससे पहली बैंक की लेन-देन होती रहती है।

श्राधुनिक युग में बैंकों के साख निर्माण-कार्य का महत्त्व बहुत ही बढ़ गया है श्रीर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि वैंक श्रीष्ठक मात्रा में साख का निर्माण कर सकती है, यद्यपि उसे इस सम्बन्ध में अपनी सुरक्षा का ध्यान श्रवस्य रखना पड़ता है। निम्न चार कारणों ने बैंक की साख-निर्माण-शक्ति में गृद्धि की हैं:—

- (क) ग्राधितिक संसार में नकदी के स्थान पर चैक द्वारा भुगतान करने की प्रथा ग्रधिक लोकप्रिय हो गई है, जिसके कारण बैंक से नकदी की माँग कम ही रहती है।
- (ख) लोग पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में बैंक से व्यवसाय करने लगे हैं। केवल बैंकिंग प्रणाली की लोकप्रियता में ही वृद्धि नहीं हुई है, वरन् बैंक के प्रति विश्वास भी ६ढ गया है।
- (ग) समाशोधन गृहों (Clearing Houses) के विकास ने यह सम्भव बना दिया है कि विभिन्न बैंकों की अन्योन्य लेन-देन नकदी में होने के स्थान पर खातों के समायोजन द्वारा होती रहे। इसका परिग्णाम यह होता है कि नकदी में भुगतानों की आवश्यकता बहुत ही कम रहती है।
- (घ) जनता में बैंकिंग ग्रादत भी बढ़ती जा रही है। बैंक को निरन्तर ग्रधिक संख्या में ग्राहक मिल रहे हैं और इन ग्राहकों की तत्काल नकदी में भुगतान लेने की ग्रातुरता भी घट रही है।
- (५) सुरक्षित कोष (Reserve Fund)—अपने व्यवसाय के अन्तर्गत बैंक आय कमाती है। इस आय ना एक भाग तो कार्यवाहन व्यय को पूरा करने में खर्च हो जाता है और शेष लाभ के रूप में प्राप्त होता है। एक वैंक अपने लाभ का भी दो प्रकार उपयोग करती है—लाभ का एक भाग लाभाँश (Dividend) के रूप में अंशवारियों में बांट दिया जाता है और दूसरा भाग सुरक्षित कोष में डाल दिया जाता है। साधाररणतया सुरक्षित कोष की व्यवस्था लाभाँश बाँटने से पहिले की जाती है और घोषित लाभाँश को निश्चित सीमा के ही भीतर रखा जाता है। सुरक्षित कोष बहुत सी दशाओं में तो बेंक के कुल विनियोग घन का काफी महत्त्वपूर्ण भाग होता

है और कालान्तर में कोष का ग्रावार बढ़ता ही जाता है, परन्तु पूँजी का यह साधन बेंक को कुछ समय परचात ही प्राप्त होता है, क्योंकि घीरे-घीरे व्यवसाय के लाम में से सुरक्षित कोष बनाया जाता है। नये विधान के अनुसार भारत में बैंकों के लिए सुरक्षित कोषों का जमा करना ग्रावश्यक हो गया है। प्रत्यैक बैंक को ग्रापने लाभों (Profits) का २०% भाग सुरक्षित कोष में तब तक स्थानान्तरित करना ग्राविवार्य कर दिया है जब तक कि वह दत्त पूँजी (Paid-up Capital) के बराबर न हो जाय।

## बैंक के घन का विनियोग (Investment of Funds)

वैंक के लाभ उसके विनियोगों द्वारा ही पैदा होते हैं। अंश पूँजी, जमाधन, ऋग की राशि तथा अन्य कोषों का विनियोजन करके बेंक लाभ कमाती है। कुल पूँजी को कुछ निश्चित उपयोगों तथा विनियोगों में बाँटा जाता है, जैसे— नकद कोष, मृत स्कन्ध, तरल आदेय, अतरल आदेय और लाभपूर्ण विनियोग। एक बेंक किस प्रकार अपनी कुल पूँजी को विभिन्न विनियोगों में बांटती है, इसका कोई निश्चित नियम तो नहीं हो सकता है, परन्तु समुचित विनियोजन नीति के सम्बन्ध में कुछ सामान्य नियम अवश्य बनाये जा सकते हैं। ये नियम बेंक की सुरक्षा, जनता के विश्वास और विनियोगों की लाभपूर्णता पर आधारित होंगे। प्रमुख नियम निम्न प्रकार हो सकते हैं।

# बंक की समुचित विनियोग नीति के सिद्धान्त (Principles of a Sound Banking Investment Policy)—

एक बेंक की सफलता बड़े श्रंग तक इस बात पर निर्भर होती है कि वह अपने कोपों का किस प्रकार विनियोजन करती है। इस सम्बन्ध में एक गलत नीति का अपनाना बेंक के लिए घातक हो सकता है। जैसा कि एक पिछले अध्याय में स्नष्ट किया जा चुका है कि बेंक के पास नकदी की उन समस्त भाँगों की तुलना में जो उसके ऊपर की जा सकती हैं, नकद कोष बहुत ही कम होते हैं। बैंक अनुभव द्वारा यह जान लेती है कि नकदी की माँग साधारएतया कितनी रहती है और उसी के अनुसार वह नकद कोष रखती है अथवा अपनी निक्षेपों का विस्तार करती है, परन्तु कभी-कभी विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। यदि बैंक ग्राहकों की नकदी की माँगों को पूरा करने में श्रस्कत रहती है तो जनता का उस पर से विश्वास उठ जाता है और फिर उसके ठप्प होने में समय नहीं लगता है। बैंक की समुचित विनियोग नीति के आधारसृत सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं:—

(१) सुरक्षा (Safety)—वैंक की अग्निम तथा विनियोग नीति के सम्बन्ध में यह सबसे पहली आवश्यकता है, क्योंकि सुरक्षित विनियोगों के न होने से स्वयं बैंक का जीवन ही संकट में पड़ जाता है। अधिक लाभ कमाने के लिए सुरक्षा पर ध्यान

न देना घातक हो सकता है। इस कारण ऐसा कहा जाता है कि बिना उपयुक्त प्रित्मूित के बैंक को ऋण नहीं देना चाहिए। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो यही उपयुक्त है, परन्तु अन्य बैंकों की प्रतियोगिता के कारण बैंक को बहुत बार व्यक्तिक अथवा कम विश्वसनीय प्रतिभृतियों पर भी ऋण देना पड़ जाता है। ऐसी दशाओं में बेंक के प्रबन्धक को बहुत सोच-विचार कर तथा सावधानीपूर्वक काम करना चाहिए। व्यवसाय में लोच बनाये रखने के लिए यदि कम सुरक्षित विनियोग आवश्यक होते हैं तो उन्हें सावधानी से चुनना चाहिए।

(२) तरलता (Liquidity)—यह उपयक्त विनियोग नीति की दूसरी म्रावश्यकता है। विशेष परिस्थितियों में वैंक को नकदी की म्रधिक म्रावश्यकता पड सकती है। इस के लिए बैंक को ऐसे भादेयों को रखना चाहिए जिन्हें सरलतापूर्वक शीघ्र ही नकदी में बदला जा सके। इस दृष्टिकोगा से बैंक के लिये थोड़े काल के लिए ऋगों का देना अधिक उपयक्त होता है. जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त ही घन प्राप्त किया जा सके । यदि वैंक अतरल आदेयों जैसे - भू-सम्पति, अविकी-साध्य प्रतिभूतियों अथवा दीर्घकालीन भौद्योगिक तथा कृ.प ऋगों में अपना धन फँसा देती है तो यह धन काफी समय तक के लिए एक जायगा और आदेयों पर तरलता समाप्त हो जायगी। इस सम्बन्ध में यह कहा जाता कि एक सचा वैंकर वही है जो विनिमय बिल तथा प्राधि के ग्रन्तर को समभता है। अबात यह है कि विनिमय बिल एक म्रत्पकालीन साख-पत्र होता है, जिसकी परिपक्कता म्रश्विक से मधिक ३ महीने की होती है, परन्तु ग्रावश्यकता पड़ने पर उसे केन्द्रीय बैंक से भी भुनाया जा सकता है, श्रथवा श्रन्य किसी बैंक के हाथ वेचकर तुरन्त नकदी प्राप्त की जा सकती है। प्राधि (Mortgage) में यह बात नहीं होती। वह तो एक बड़ा ही अतरल आदेय है। यह सम्भव है कि बैंग के पास बहुत काफी ग्रतरल ग्रादेय रहते हुए भी उसका दिवाला निकल जाय, यदि वह अपनी नकदी सम्बन्धी माँगों को तत्काल पूरा करने में असफल रहती है। एक ग्रच्छी बैंक के लिए तरल ग्रादेयों में घन का ग्रधिक मात्रा में लगाना बहत ही भ्रावश्यक है।

(३) जोखिम की विविधता (Diversification of Risk)—यह भी बहुत ग्रावश्यक है कि बैंक ग्रपना सारा या ग्रधिकाँग धन एक ही प्रकार के ऋराों, प्रतिभूतियों, व्यवसायों ग्रथवा विनियोगों में न लगाये, बल्कि उसका विभिन्न प्रकार के ग्रादेयों में वितरण करे। इसका महत्त्व इस कारण है कि ऐसी दशा में एक व्यवसाय में मन्दी ग्राने ग्रथवा एक प्रकार की प्रतिभूतियों की तरलता घट जाने या उनकी कीमतों के गिरने का बैंक की साख पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि सभी ग्रण्डे एक ही टोकरी में रखे जाते हैं तो उनके टूटने का भय ग्रधिक रहता है। इस दृष्टिकोण से यह भी ग्रधिक उपयुक्त है कि बैंक कुछ थोड़े से उद्योगों ग्रथवा व्यापारियों को बड़े-

A true banker is one who understands the difference between a mortgage and a bill of exchange.

बड़े ऋगा देने के स्थान पर छोटे-छोटे अथवा मध्यम प्रकार के ऋगा बहुत से उद्योगों अमेर व्यक्तियों को दे। इसका यह लाभ होता है कि एक समय में कुछ व्यक्तियों द्वारा भुगतान न होने से उत्पन्न होने वाली जोखिम कम हो जाती है और बैंक के लिए नकदी का एक ऐसा प्रवाह बना रहता है कि उसे ग्राहकों की नकदी की माँग पूरा करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है।

- (४) उत्पादकता (Productivity)—प्रत्येक बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। बैंक यही देख कर ऋग देने का निर्णय करती है कि उससे किस ग्रंश तक लाभ प्राप्त होगा। जितनी ही विनियोग ग्रथवा ग्रादेय की उत्पादकता ग्रधिक होगी उतना ही उसे ग्रधिक पसन्द किया जायगा। बैंक बहुधा स्वयं ऋग लेकर विनियोग करती है। यदि ऋग प्राप्त करने की ब्याज की दर भौर ऋग प्रदान करने की ब्याज की दर में ग्रधिक ग्रन्तर है तो ऋग देना ग्रधिक लाभदायक होता है। बिना समुचित लाभ की ग्राशा के विनियोग का प्रदन ही नहीं उठता है।
- (५) प्रतिभृतियों की बिकी-साध्यता (Marketability of Securities)—यह भी सुरक्षा के हिष्टकोए से किया जाता है। जिन प्रतिभृतियों में बेंक विनियोग करती है वे ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें शीघ्रतापूर्वक बेचकर नकदी प्राप्त की जा सके। विनिमय साध्य साख-पत्रों, तैयार माल प्रथवा अच्छी कम्पनियों के ग्रंशों भौर ऋएा-पत्रों पर जो ऋएा दिए जाते हैं उनमें तरलता तथा सुरक्षा दोनों ही रहते हैं, क्योंकि ये सभी प्रतिभृतियाँ पूर्णतया बिकी-साध्य हैं, परन्तु अचल सम्पत्ति में लगाया हुआ धन इतनी ग्रासानी से नहीं निकाला जा सकता है। एक बैंक इस सम्बन्ध में जितनी ही ग्रधिक सावधान रहती है उतना ही उसके इबने का भय कम रहता है। कोषों के विनियोजन की मदें—

एक बैंक को अपने कोषों को साधारणतया दो प्रकार के विनियोगों में लगाना पड़ता है:—(१) लाभदायक विनियोग और (२) बिना लाभ के विनियोग। दोनों ही प्रकार के विनियोग ग्रावश्यक होते हैं ग्रौर एक बैंक को बड़ी चतुराई के साथ यह निर्णय करना होता है कि इन दोनों प्रकार के विनियोगों में कोषों का वितरण किस अनुपात में किया जाय। सुरक्षा तथा तरलता के दृष्टिकोणों से लाभदीन विनियोग ग्रावश्यक होते हैं, परन्तु उत्पादकता के दृष्टिकोण से लाभदायक विनियोगों का चुनना ग्रावश्यक होता है। एक बैंक को दो बातों को एक ही साथ ध्यान में रखना पड़ता है:—प्रथम, तो ग्रंशघारियों को समुचित लाभ प्रदान किया जा सके और दूसरे, बैंक की विफलता का भय उत्पन्न न होने पाये। स्मरण रहे कि बैंक का प्रारम्भिक उद्देश्य ग्रंशघारियों के लिए लाभ कमाना होता है। इसके लिए लाभदायक विनियोग ही ग्राविक पसन्द किए जाते हैं, परन्तु इस स्वार्थी नीति के कारण बहुत सी बैंकों का दिवाला निकल जाता है। इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि बैंक का उत्तर-दायित्व केवल उसके ग्रंशघारियों के ही प्रति नहीं होता है, समाज तथा राष्ट्र के प्रति

भी उसका कुछ कर्त्तव्य हुम्रा करता है। बेंक की विफलता से म्रंशधारियों को तो हानि होती है, परन्तु समाज ग्रौर राष्ट्र का भी ग्रनहित होता है। यही कारएा है कि सरकार बहुधा बेंक, की विनियोग नीति में हस्तक्षेप भी किया करती है। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य बहुधा यह होता है कि ग्रधिक लाभ के लोभ में बेंक ग्रादेगों की तरलता को न खोने पाये।

बैंक के लाभदायक विनियोगों में ऋगा, प्रियम, नकद साख, प्रधिविकर्ष प्रादि सिम्मिलित होते हैं भौर उसके लाभहीन विनियोग नकद कोषों भौर मृत स्कन्ध (Dead Stock) के रूप होते हैं। लाभहीन म्रादेयों में सबसे बड़ा महत्त्व नकद कोषों का होता है। नकदी से म्रधिक तरलता किसी भी म्रादेय में नहीं होती है मौर प्रत्येक बैंक समय-समय पर की जाने वाली अपने ग्राहकों की नकदी की माँग को पूरा करने के लिए नकदी का संचय रखती है। म्रारम्भ में वैंक के नकद कोषों का मर्थ केवल उस संचय से होता था जो वैंक अपने कोष में देश के चलन के रूप में रखती थी, परन्तु वर्तमान वैंकिंग पद्धित में यह शब्द म्रधिक विस्तृत मर्थ में उपयोग किया जाता है। नकद कोषों में वैंक द्वारा संचित चलन के म्रातिरिक्त उस जमा को भी सिम्मिलित किया जाता है जो बैंक विशेष अन्य वैंकों तथा केन्द्रीय वैंक में रखती है। ये कोष बैंक की सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन होते हैं।

यह कहना कठिन है कि एक बैंक को ग्रपने कुल निक्षेपों का कौनसा भाग नकद कोषों के रूप में रखना चाहिए। इस सम्बन्ध में सुरक्षा ग्रौर लाभ दोनों ही दृष्टिकोणों के बीच समायोजन तथा सन्तुलन करना पड़ता है।

#### (१) नकद कोष--

बैंक के दैनिक व्यवसाय में नकद कोषों का भारी महत्त्व है। वैसे तो प्रति दिन ही बेंक के पास कुछ न कुछ नकद रुपया ग्राता रहता है, जिसमें से वह ग्रपने ग्राहकों की नकदी की माँगों को पूरा करती रहती है, परन्तु फिर भी यह सम्भव है कि किसी दिन नकदी की मांग उसकी प्राप्ति से ग्राधिक हो। यदि बैंक इस मांग को पूरा करने में ग्रासमर्थ रहती है तो उसकी साख हटती है और बैंक की सामर्थ्यहीनता की थोड़ी सी भी ग्रफवाह बैंक के लिए भारी कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। यही कारग्रा है कि प्रत्येक बैंक यथेष्ठ नकद कोष रखना ग्रावश्यक समभती है।

इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते हैं कि बैंक के लिए कम से कम ग्रथवा ग्रधिक से ग्रधिक कितने बड़े नकद कोष ग्रावश्यक होते हैं। ग्रलग-ग्रलग विद्वानों के इस सम्बन्ध में ग्रलग-ग्रलग मत हैं। वैसे भी विभिन्न परि-स्थितियों में ग्रलग-ग्रलग मात्रा में नकद कोषों की ग्रावश्यकता पड़ती है। इस सम्बन्ध में केवल ग्रनुभव तथा सामान्य बुद्धिमानी ही सबसे उपयुक्त सहारा हो सकते हैं।

## (१) नकद कोषों सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नियम-

यद्यपि नकद कोषों की मात्रा के विषय में पूर्णतया निश्चित नियम तो नहीं

बनाए जा सकते हैं, परन्तु कुछ सामान्य बातें अवश्य बताई जा सकती हैं। इन बातों को घ्यान में रखने का परिग्णाम यह होता है कि बैंक को यथासमय नकदी में भुगतान करने में विशेष कठिनाई नहीं होती है। ये नियम निम्न प्रकार बताये जा सकते हैं:—

- (i) वैधानिक ग्रावश्यकता— कुछ देशों में नकद कोषों की न्यूनतम् सीमा नियम द्वारा निश्चित कर दी जाती है। उदाहररास्वरूप, भारत में उन सभी अनुस्चित वैंकों को जिन्हें रिजर्व वैंक की ग्रनुस्चित २ (Second Schedule) में सम्मिलित किया गया है, ग्रपने माँग दायित्व (Demand Liabilities) का ५% श्रीर अपने समय दायत्व (Time Liabilities) का २% रिजर्व वैंक में हर समय जमा करके रखना पड़ता है। इसी प्रकार अन्य वैंकिंग कम्पनियों को नियमानुसार अपने पास ग्रथवा रिजर्व वैंक्क में जमा के रूप में, ग्रथवा कुछ ग्रपने पास ग्रीर कुछ रिजर्व वैंक्क में, ग्रपने माँग दायत्त्व का कम से कम ५% ग्रीर समय दायत्त्व का २% नकद कोपों में रखना होता है। जहाँ नकद कोषों की न्यूनतम् सीमा इस प्रकार निश्चित कर दी जाती है, वहाँ कम से कम उतने नकद कोष रखने पड़ते हैं।
- (ii) ग्राहकों की मनोवृत्ति तथा क्षेत्र विशेष की व्यवसायिक दशाएँ— यदि लोगों में चैक (धनादेश) द्वारा भुगतान करने की प्रथा ग्रधिक प्रचलित है तो साधारएतया कम नकद कोषों से काम चल जाता है। भारत जैसे देश में, जहाँ अधिकाँश भुगतान नकदी में ही होते हैं, नकदी को ग्रधिक मात्रा में रखना ग्रावश्यक होता है। इसके ग्रतिरिक्त यदि स्थानीय क्षेत्रों में ग्रौद्योगिक तथा व्यापारिक व्यवसाय हैं, जिसके कारएा विनिमय का कार्य काफी जल्दी तथा ग्रधिक मात्रा में होता है तो नकदी की ग्रावश्यकता ग्रधिक रहेगी। कृषक क्षेत्रों में बैंक नकद कोषों से ही ग्रपना कार्य चला सकती है।
- (iii) व्यवसाय की प्रकृति (Nature of the Business)—नकद कोपों की मात्रा इस बात पर भी निर्भर होती है कि बैंक किस प्रकार के विनियोग करती है। यदि कोई बैंक्क अपने घन का अधिकाँश भाग विनिमय बिलों, विनिमय-साध्य प्रतिभूतियों तथा अल्पकालीन ऋगों में लगाती है तो उसे अपेक्षतन कम नकद कोषों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसके अधिकाँश आदेय तरल रूप में होते हैं, जिनका किसी भी समय निस्तारण करके तत्काल नकदी प्राप्त की जा सकती है। इसके विपर्रात यदि बैंक के अधिकाँश विनियोग ऋगों में अथवा अतरल आदेयों के रूप में हैं, तो उसे अविक मात्रा में नकद कोष रखने पड़ते हैं।
  - (iv) वैंकरों के निकासी गृहों का होना (The Presence of Banker's Clearing Houses).—निकासी गृह का कार्य यह होता है कि ये विभिन्न वैंकों की अन्योन्य लेन-देन का समायोजन करते हैं। ऐसी दशा में प्रत्येक बैंक को उन सभी धनादेशों का नकदी में भुगतान नहीं करना पड़ता है, जो इसके अवर

लिखे गये हैं ग्रौर दूसरी बैंकों में जमा कर दिए गए हैं। उसे केवल उन चैकों की राशि जो कि दूसरे वैंकों पर लिखे गए हैं ग्रौर उनके पास जमा हैं तथा उन घनादेशों की राशि जो ग्रन्य वैंकों के पास हैं ग्रौर उसके ऊपर लिखे गए हैं, का ग्रन्तर ही नकदी में देना पहता है। निकासी ग्रह के न होने की दशा में प्रत्येक चैंक का नकदी में भुगतान करना ग्रावश्यक होता है। भारत में निकासी ग्रहों के ग्रभाव के कारण ग्रधिकाँश वैंकों को ग्रधिक बड़े नकद कोष रखने पड़ते हैं।

- ( v ) खातों की प्रकृति—नकद कोषों की मात्रा इस वात पर भी निर्भर होती है कि बैंक में खोले हुए विभिन्न प्रकार के खाते कैसे हैं। यदि खाते इस प्रकार के हैं कि उनमें ते गी के साथ धन ग्राता-जाता रहता है तो बैंक के लिए ग्रधिक मात्रा में नकदी का रखना ग्रावश्यक होता है। दलालों तथा सोने-चाँदी के व्यापारियों के खाते इसी प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार यदि चालू खातों की ही ग्राधिकता है तो बड़े नकद कोषों की ग्रावश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार वे वड़ी वड़ी बैंक, जिनमें स्थानीय छोटी-छोटी बैंकों की जमा रहती है, छोटी वैंकों की ग्रावश्यक नकदी रखती हैं। इसके विपरीत यदि निश्चितकालीन जमा के खाते ग्रधिक हैं तो छोटे नकद कोषों से भी काम चल सकता है।
- ( vi ) निक्षेपों का स्राकार (Size of the Deposits)—वेंक के नकद कोषों की स्रावश्यकता उसके प्राहकों की संख्या पर भी निभंर होती है। यदि वेंक के थोड़े से ही प्राहक हैं, जिनके वड़े-बड़े खाते खुले हुए हैं तो नकदी की स्रावश्यकता स्रिष्ठक रहेगी, किन्तु यदि वेंक के छोटे-छोटे खातों वाले बहुत से प्राहक हैं तो नकदी की माँग, वम होगी। कारण यह है कि वेंक के ग्रिष्ठकाँश प्राहक स्रापस में भी एक-दूसरे के प्राहक होते हैं स्रोर उनके खातों में स्रावश्यक समायोजन करके ही स्रिष्ठकाँश भुगतान चुका दिए जाते हैं, सतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जितना ही बेंक का व्यवसाय विस्तृत होगा उतना ही स्रिपेक्षतन कम नकद कोषों से काम चल जायगा।
- (vii) अन्य बैंकों की नकद कोष नीति—व्यवसायिक मनोवृत्ति भेड़ की सी मनोवृत्ति होती है। सभी बैंक एक दूसरे की देखा-देखी अपने अपने नकद कोषों को घटाती बढ़ाती हैं। यदि किसी क्षेत्र में वहुत सी ऐसी बैंक हैं जो नकद कोष अधिक मात्रा में रखती हैं तो दूसरी बैंकों को यह भय होने लगता है कि इन बैंकों पर जनता का विश्वास अधिक हो जाने के कारण इनकी प्रतियोगिता शक्ति अधिक हो जायगी और वे अन्य बैंकों के ग्राहकों को तोड़ लेंगी। इस कारण दूसरी बैंक भी अधिक नकद कोष रखने लगती हैं।

उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर ग्रौर सामान्य ग्रनुभव ग्रौर बुद्धिमानी से काम लेकर एक बेंक यह निश्चित करती है कि उसे ग्रपनी कुल निक्षेपों को कौनसा प्रतिशत नकद कोष के रूप में रखना चाहिए। कुछ देशों में नकद कोष का न्यूनतम् प्रतिशत विधानानुसार भी निश्चित कर दिया जाता है, जिसे हम विधानतः रोक निधि

(Statutory Cash Reserve) कहते हैं। इस व्यवस्था का ग्रमित्राय यह होता है कि इस प्रकार निश्चित प्रतिशत से नीचे कोई भी बैंक ग्रपने नकद कोषों को नहीं घटा सकती है, यद्यपि कोई भी बैंक इससे ग्रधिक मात्रा में नकद कोष रखने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र होती है। विधानानुसार भारत में प्रत्येक व्यापारिक बैंक को ग्रपने चालू ख'ते का ५% और सावधि जमा (Time Deposits) का २% नकदी के रूप में रिजर्व बैंक में रखना ग्रनिवार्य है। व्यवहार में यह नकद कोष बहुत कम है, इसलिए सभी बैंक इसके ग्रतिरिक्त ग्रीर भी नकद कोष ग्रपने पास रखती हैं।

### (२) मृत स्कन्ध (Dead Stock)-

नकद कोपों के परचात् यह बैंक का दूसरा लाभहीन म्रादेय होता है। बैंक को म्राप्ती इसारत, भूमि, फर्नीचर (Furniture), फिटिंग तथा म्रन्य स्थिर म्रादेयों पर भी व्यय करना पड़ता है। इन सबकी व्यवस्था व्यवसाय के संचालन के लिए म्रावस्थक होती है, यद्यपि इनसे कोई भी म्राय प्राप्त नहीं होती है। इन म्रादेयों (Assets) को मृत स्कन्य इस कारण कहा जाता है कि इन्हें सरलतापूर्वंक वेचा नहीं जा सकता है। ये सरलतापूर्वंक विनिमय साध्य नहीं होते हैं भीर इन्हें बेचने से बैंक के मान को हानि पहुँचती है, जो उसके व्यवसाय के लिए घातक है। इनको केवल उसी समय बेचा जाता है जबकि बैंक ठप हो जाती है म्रीर उसके सभी प्रकार के म्रादेयों को बेच कर लेनदारों का भुगतान किया जाता है। साधारणतया मृत स्कन्धों पर बैंकों को काफी व्यय करना पड़ता है और प्रत्येक बेंक म्रारम्भ में ही इस व्यय के लिए धन का प्रबन्ध करती है। म्रारम्भ में व्यय कर देने के परचात् म्रागे चलकर इस मद पर प्रति वर्ष बहुत हो कम व्यय की म्रावस्थकता पड़ती है। इसी कारण बेंक के चालू व्यय में मृत स्कन्य व्यय का बहुत ही कम महत्त्व रहता है।

मृत स्कन्घों का रखना भी बैंक के लिए ग्रावश्यक है। इनके बिना कार्य-स्थान की समुचित व्यवस्था कठिन होती है। बैंक को ग्रपना दिन प्रति दिन का काम ठीक-ठीक चलाने के लिए ही नहीं, बल्कि ग्रपनी प्रतिष्ठा के लिए भी समुचित कार्य-स्थान तथा फर्नीचर ग्रादि की ग्रावश्यकता पड़ती है।

## बैंक के लाभदायक आदेय-

वैंक के लाभदायक ब्रादेयों में याचना राशि (Call Money), विनियोग (Investments), ब्रिग्रम (Advances), ऋरा, नकद-साख, ब्रिघि-विकर्ष (Overdraft), विनिमय बिलों को भुनाना, स्वीकृतियाँ (Acceptances) ब्रादि सम्मिलित होते हैं। इनमें से प्रत्येक का ब्रलग-ब्रलग वर्रान नीचे किया जायेगा।

# (१) याचना राशि श्रथवा श्रत्य सूचनार्थं ऋग् (Money at Short Notice)—

इसमें वे सब ऋरण सिम्मिलित होते हैं जो थोड़े काल का नोटिस देकर वसूल किये जा सकते हैं। ऐसे ऋरणों में मुद्रा-बाजार, बिल के दलालों तथा स्टॉक एक्स- चेन्ज के व्यापारियों को दिये हुए ऋगा सिम्मिलित होते हैं। प्रत्येक बैंक इस प्रकार की कुछ जमा ग्रवश्य रखती है, जिसे बिना सूचना ग्रथवा कुछ समय की सूचना पर तुरन्त निकाला जा सकता है। सुरक्षा के दृष्टिकोगा से नकद कोषों के बाद बैंक के ग्रादेयों में दूसरा नम्बर इन्हीं का ग्राता है, परन्तु नकद कोषों की ग्रपेक्षा ये इस कारगा ग्रधिक श्रच्छे होते हैं कि सुरक्षा के साथ-साथ इनसे ग्राय भी प्राप्त होती है।

इज़्लेंड ग्रादि देशों में इसी प्रकार के ऋण विल के दलालों, डिस्काउन्ट गृहों (Discount Houses) ग्रीर स्टॉक एक्सचेन्ज (Stock Exchange) के ग्राढ़-तियों ग्रीर दलालों को दिये जाते हैं ग्रीर इन्हें बहुत बार केवल एक ही घन्टे का नोटिस देकर वसूल किया जा सकता है। भारत में बिलों को भुनाने वाले गृह तथा निगंम गृह (Issue Houses) नहीं हैं, इसलिए हमारे देश में याचना राशि को एक बैंक द्वारा दूसरी बैंकों को ही देने की प्रथा ग्रधिक प्रचलित है। परिग्णामस्वरूप तरल ग्रादेयों की प्राप्ति कम ग्रंश तक ही हो पाती है।

#### (२) बिलों का भुनाना—

लाभदायक विनियोग में दूसरा नम्बर बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों के भूनाने का श्राता है। बैंक बिलों को भूनाती है श्रीर उन्हें खरीद कर भी रख लेती है। बिलों की परिपक्ता अविध साधाररातया ६० से ६० दिन तक की होती है. यद्यपि बिल को बेच कर भ्रथवा केन्द्रीय बैंक से भुनवा कर इससे पहले भी घन प्राप्त किया जा सकता है। यही बात प्रतिज्ञा-पत्रों भ्रौर कोषागार विपत्रों (Treasury Bills) के ऋय-विक्रय के सम्बन्ध में भी की जा सकती है। भारतीय बैंक प्रतिज्ञा-पत्रों में व्यवसाय कम करती हैं और उन पर साधारणतया जमानत भी माँगती हैं। कोषागार विपत्रों अथवा सरकारी हिण्डियों में रुपया लगाना ग्रच्छा समभा जाता है। इसमें जोखिम कम रहती है, सुरक्षा भ्रधिक रहती है ग्रौर इन हुण्डियों को सरलता से बेचा जा सकता है। इन हुण्डियों की परिपक्तता अविध भी अधिक से अधिक एक वर्ष की होती है। परन्तू अन्य ग्रल्पकालीन विनियोगों की भाँति इन पर भी ब्याज की दर कम रहती है। भारत में बिल बाजार का समुचित विकास न होने के कारण ग्रीर उनके क्रय विक्रय में कठिनाई होने के कारण बिलों में लगाये हुए धन वी मात्रा सीमित ही रहती है। यह भारतीय मुद्रा-बाजार का एक गम्भीर दोष है, जिसे की घ्रा ही दूर करने की ग्रावश्यकता है। बिल बाजार के विकास से आदेयों की तरलता और लाभपूर्णता दोनों एक ही साथ प्राप्त हो सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों से रिजवं बैंक ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न ग्रारम्भ भी किये हैं।

## (३) विनियोग—

ये बेंक के तीसरे लाभदायक ग्रादेय हैं। विनियोगों के सम्बन्ध में बेंक सुरक्षा, विनियय साध्यता, मूल्य स्थिरता तथा उत्पादकता को विशेषकर देखती है। ग्रच्छी बेंक ग्रपने कोषों का एक काफी बड़ा भाग परम प्रतिभूतियों (Guilt-edged Securi-

ties) में लगाती है। विनियोग सोने ग्रीर चांदी में भी किये जा सकते हैं। श्रेष्ठता के दृष्टिकोए। से सबसे उत्तम प्रतिभूतियाँ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ होती है। इसके पश्चात् ग्रद्ध-सरकारी लोक ग्रिष्ठकारियों, जैसे—नगरपालिकाग्रों, जिला बोर्डों तथा ग्रन्य लोक संस्थाग्रों की प्रतिभूतियों का नम्बर ग्राता है। इसके ग्रातिरक्त ग्रीर भी बहुत सी प्रकार की प्रतिभूतियों में धन लगाया जा सकता है, जैसे—रेलों के ग्रंग, ऋएा-पत्र, बाँड ग्रादि, लोक उपयोगी सेवाग्रों (Public Utility Services) की प्रतिभूतियाँ, सरकारी ऋएा, ग्रौद्योगिक कम्पनियों के ग्रंश, ऋएा-पत्र, बांड ग्रादि। भारतीय वैंक सरकारी हुण्डियों में धन लगाना ग्रिष्ठक पसन्द करती हैं, क्योंकि देश में ग्रन्य प्रकार की प्रतिभूतियाँ कम संख्या में प्राप्त होती हैं।

## (४) ऋण तथा अग्रिम—

ऋएा तथा श्रग्रिम विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और इनकी सम्बन्धित प्रतिभृतियां भी श्रलग-श्रलग प्रकार की होती हैं। श्रिम साधारएतिया ऋएा, नकद साख तथा श्रधि-विकर्ष का रूप लेते हैं। ऐसे श्रिम व्यक्तिगत प्रतिभृतियों, गारन्टी श्रथवा श्रम्य उपयुक्त प्रतिभृतियों के श्राधार पर दिये जा सकते हैं। व्यक्तिगत प्रतिभृति पर दिए हुए ऋएा साधारएतिया श्ररक्षित श्रिम (Unsecured advances) होते हैं और प्रतिज्ञा-पत्रों पर दिये जाते हैं, परन्तु साधारएतिया व्यक्तिगत प्रतिभृति के साथ कोई सहायक प्रतिभृति (Collateral Security) भी ली जाती है। ऐसी प्रतिभृतियाँ स्टॉक एक्सचेन्ज प्रतिभृति, विनिमय-साध्य साख-पत्र, माल के श्रधिकार-पत्र (Titles), बीमा पॉलिसी, श्रचल सम्पत्ति श्रादि के रूप में होती हैं।

## बैंक की ऋण दान नीति

यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि ऋगों का प्रदान करना बैंक का महत्त्वपूर्ण कार्य है भ्रौर उसकी भ्राय का भी प्रमुख साधन है। साधारणतया बैंक के ऋग्रय तीन प्रकार के होते हैं:—

- (१) साधारण ऋ ए तथा ग्रमिम,
- (२) अधि-विकर्ष (Over-draft) ग्रीर
- (३) नकद-साख (Cash-credit)।
- (१) साधारण ऋगा तथा अग्रिम—साधारण ऋगों को प्रदान करने की रीति यह होती है कि बैंक ऋगा लेने वाले का खाता अपने यहाँ खोल लेती हैं। इस प्रकार व्यवहार में वेंक के ऋगी और उसके जमावारी में अन्तर नहीं होता है। ऋग की राशि को ऋगी एक साधारण जमाधारी की भाँति चैंक द्वारा कभी भी निकाल सकता है, परन्तु कोई भी ऋग देने से पहले बैंक प्रार्थी की आधिक स्थित और उसकी साख की भली-भाँति जाँच कर लेती है। वेंक ऋगा के लिये समुचित जमानत का भी अनुरोध करती है। ब्याज की दर पहले से ही निश्चित कर ली जाती है, जिसमें ऋगा के भुगतान की अवधि के अनुसार अन्तर होता है। ऋगी को उधार की सारी

राशि पर ब्याज देना पड़ता है, चाहे वह उपयोग एक दम करता है अथवा धीरे-घीरे, परन्तु ग्रधिकांश बैंक बिना उपयोग की हुई राशि पर नीची दर पर व्याज लेती हैं। प्राथी की साख का पता लगाने के लिए बैंक के पास अनेक साधन होते हैं। प्रमुख साधन निम्न प्रकार हैं:—

- (१) कुछ संस्थाएँ ऐसी होती हैं जो विभिन्न व्यापारियों की आर्थिक स्थिति और साख सम्बन्धी सूचनात्रों को एकत्रित करती हैं। बैंक इन संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करती है। यूरोप के सभी देशों में ऐसी संस्थाएँ बहुत हैं और विश्वसनीय भी होती हैं, परन्तु भारत में इनकी कमी है।
- (२) उन व्यापारियों झौर संस्थाझों से पूछताछ की जाती है जिनसे प्रार्थी का लेन-देन रहता चला आया है।
- (३) एक बैंक दूसरी बैंक को भी इसी प्रकार की सूचना देती रहती है श्रौर ग्रपने ग्राहक की साख दूसरी बैंक को बता देती है।
- (४) प्रार्थी फर्म के वार्षिक चिट्ठे के निरीक्षण से भी उसकी साख का ग्रनुमान लगाया जा सकता है।
- (४) प्रार्थी फर्म के वार्षिक ग्रंकेक्षण विवरण (Andit Report) को देख कर।
- (६) ग्रपने कर्मचारियों ग्रौर विशेषज्ञों को भेज कर जानकारी प्राप्त करके।
- ( ७ ) यदि प्रार्थी बैंक का ही पुराना ग्राहक है तो उसकी लेन-देन का पिछला इतिहास देखकर।
- (२) ग्रिधि-विकर्ष ग्रिधि-विकर्ष की सुविधा केवल बैंक के जमाधारी को ही दी जाती है। रुपया जमा करने वाले को यह सुविधा दी जाती है कि वह ग्रावश्यकता पड़ने पर जमा की राशि से कुछ ग्रिधिक रुपया भी खाते में से निकाल सकता है। यह सुविधा चालू खातों पर ही दी जाती है। जमाधारी से केवल उतनी ही राशि पर ब्याज लिया जाता है जितनी वह दिन प्रति निकालता रहता है। साधा-रण्तया ग्राधि-विकर्ष की सीमा निश्चित कर दी जाती है ग्रीर इस प्रकार के ऋष्ण के लिए कोई जमानत नहीं माँगी जाती है, यद्यपि कभी-कभी बैंक जमानत का भी ग्रानुरोध करती है।
- (३) नकद साख नकद साख की सुविधा भी साधारएतया ग्राहकों ग्रथवा खातेषारियों को ही दी जाती है, यद्यपि कभी-कभी यह ग्रन्य व्यक्तियों को भी दी जा सकती है। इस प्रकार के ऋएों के लिए प्रत्येक दशा में जमानत ली जाती है और वह भी माल ग्रथवा सम्पत्ति की। व्यक्तिगत जमानत ग्रथवा प्रतिज्ञापत्र पर ऐसे ऋएा नहीं दिये जाते हैं। ऋएी माल ग्रथवा सम्पत्ति को बैंक के गोदाम में जमा कर देता है, ग्रथवा ग्रपनी फसल, धन, तैयार माल ग्रादि को गिरवी रखता है। जैसे-जैसे ऋएी रूपया चुकाता जाता है, बैंक उसके माल को छोड़ती रहती है। साधारएतया ग्रचल तथा ग्रक्रय

प्रतिभूति पर ऐसे ऋगा नहीं दिये जाते हैं। श्रधि-विकर्ष की भाँति ऐसे ऋगों में भी केवल उसी राशि पर ब्याज लिया जाता है जिसका ऋगी द्वारा वास्तव में उपयोग किया जाता है। विना निकाली हुई राशि पर ब्याज नहीं लिया जाता है।

## ऋग्ण की प्रतिभूतियाँ श्रथवा जमानतें (Securities)

दो प्रकार की प्रतिभूतियाँ—

वेंक द्वारा सभी प्रकार के ऋगा किसी न किसी प्रकार की जमानत पर दिये जाते हैं। इन जमानतों को ग्राधिक भाषा में प्रतिभूति कहा जाता है। प्रतिभूतियों को दो भागों में बाँटा जा सकता है:—(I) व्यक्तिगत प्रतिभूतियाँ, (Personal Securities) ग्रीर (II) सहायक प्रतिभूतियाँ (Collateral Securities)।

## (I) व्यक्तिगत प्रतिभूतियाँ—

व्यक्तिगत प्रतिभूति किसी ऐसी जमानत को कहते हैं जो स्वयं पाहक के व्यक्तित्त्व द्वारा प्रस्तृत की जाती हैं । बैंक ऋण लेने वाले व्यक्ति की ग्राधिक स्थिति. साख, चरित्र, व्यवसाय प्रगाली ग्रौर व्यापार कुशलता को देखती हैं ग्रौर यदि ये सभी विश्वसनीय है तो इन्हीं के आधार पर बिना किसी प्रकार की जमानत लिये ऋगा दे सकती हैं। ऐसे ऋगों के देने में विशेष सावधानी बर्ती जाती है और बेंक बिना सम्-चित जाँच के ऋगा नहीं देती हैं। इस प्रकार दिये हुये ऋगों की संख्या और मात्रा भी सीमित ही रहती है। यह सुविधा साधारणतया उन ग्राहकों को दी जाती है जो काफी समय से बैंक के साथ व्यवसाय करते चले खाये हैं ख्रौर जिन्हें बैंक भली भाँति जानती है। भारत में इस प्रकार दिये जाने वाले ऋगों का सबसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण अधि-विकर्षे है, जिसमें बैंक अपने ग्राहक को बिना किसी जमानत के उसके खाते में जमा की हुई राशि से अधिक धन निकाल लेने का अधिकार दे देती है। व्यक्तिगत प्रतिभृति पर दिये जाने वाले ग्रन्य ऋए। वे होते हैं जिनमें ऋए। से प्रतिज्ञा-पत्र लिखवा लिया जाता है ग्रौर उस पर जमानत के रूप में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। इस प्रकार की जमानत के दो रूप हो सकते हैं:—(१) विशेष (Specific), जिसमें जमानत देने वालों के हस्ताक्षर किसी विशेष ऋगा के ही लिए स्वीकार किये जाते हैं ग्रौर (२) चालू (Current), जिसमें जमानती हस्ताक्षरों को ऋए। लेने वाले के प्रत्येक अगले ऋए। के लिए भी मान लिया जाता है।

## ( II ) सहायक प्रतिमूतियाँ—

इसी प्रकार की जमानतें किसी वस्तु की ग्राड़ के रूप में ली जाती हैं। बैंक बहुषा व्यक्तिगत प्रतिज्ञा-पत्र ग्रथवा जमानती हस्ताक्षरों पर ऋगा नहीं देती हैं, बिक माल, सम्पत्ति, सोना, चांदी ग्रादि को ग्राड़ में रखकर ऋगा देती हैं। ये जमानतें भौतिक वस्तुग्रों के रूप में होती हैं। तीन प्रकार की भौतिक जमानतें ज्राधिक प्रच-

लित हैं—(१) यह शाधिकार (Lien), जिसमें ग्राड़ में रखी हुई वस्तु वैंक के पास रखी जाती है, परन्तु ऋ ग का भुगतान न होने की दशा में वैंक वस्तु को उस समय तक नहीं बेच सकती है जब तक कि वह न्यायालय से कुर्की का ग्रादेश प्राप्त नहीं कर लेती है (२) जिसमी (Pladae) जिसमें ग्राह में रखी हुई वस्तु को बेचने के

कर लेती है, (२) गिरवी (Pledge), जिसमें ग्राड़ में रखी हुई वस्तु को बेचने के लिए न्यायालय की ग्राज्ञा की ग्रावश्यकता नहीं पड़ती है, वैंक द्वारा ऋगी को समुचित सूचना देना ही पर्याप्त होता है ग्रौर (३) ग्राधि श्रथवा रहन (Mortgage),

सूचना दना ही पर्याप्त होता है ग्रोर (३) प्राधि श्रथवा रहन (Mortgage), जिसमें म्रङ्कित शर्त के ग्रनुसार ग्राड़ में रखी हुई वस्तु पर ऋगी का ही ग्रधिकार रहता है, ग्रथवा उसके स्वामित्त्व का बैंक को हस्तान्तरगा हो सकता है।

#### सहायक प्रतिभृतियों के प्रकार—

भारत में साधारएतया पाँच प्रकार की सहायक प्रतिभृतियों का चलन है:—
(१) स्टॉक एक्सचेंज में बिकने वाले पत्र, (२) विनिमय बिल, (३) माल ग्रथवा माल
के ग्रधिकार पत्र (४) जीवन दीमा पत्र ग्रीर (५) ग्रचल सम्पत्ति ।

## (१) स्टॉक एक्सचेंज में विकने वाले पत्र—

इन पत्रों में सरकारी हुण्डियाँ, कम्पनियों के ग्रंश, ऋग्य-पत्र, प्रतिज्ञा-पत्र तथा ग्रन्य प्रकार के विनिमय-साध्य साख-पत्र सिमिलित होते हैं। ऐसी प्रतिभूतियों को बैंक बहुत पसन्द करती है। इनके प्रमुख गुग्ग निम्न प्रकार होते हैं:—(१) इन्हें ग्राव-रयकता पड़ने पर सरलतापूर्वक तत्काल बेच कर नकदी प्राप्त की जा सकती है। (२) इनकी बाजार कीमत का पता सरलता से तथा शीध्र लग जाता है। (३) बिक्री-साध्य होने के कारण इनके स्वामित्व में किसी प्रकार का भगड़ा नहीं होता है। (४)

इनकी कीमत बिना कठिनाई के बसूल की जा सकती है। (१) इनकी कीमतों में काफी स्थिरता रहती है। इन्हें केन्द्रीय बैंक तथा अन्य बैंक भी ऋगों की जमानत के रूप में स्वीकार कर लेती हैं। इन्हें भी अपनिस्तियों के कुछ दोष भी होते हैं:—(१)

श्रंशों को सावधानी के साथ देख-भाल कर खरीदना श्रावश्यक होता है, क्योंकि यदि श्रंशधारी पर कम्पनी का कुछ ऋरा शेष है तो कम्पनी उसे श्रंश में से वसूल कर लेती है, जिस दशा में ऐसे श्रंश को प्राप्त करने वाली बैंक को हानि हो सकती है। (२) बैंक को यह देखना पड़ता है कि श्रंश विशेष की पूरी रकम चुका दी गई है या नहीं।

यदि सावधानी से काम नहीं लिया जाता है तो अशोधित रकम बैंक को चुकानी पड़ती है। (३) कुछ साख-पत्र पूर्णतया विनिमय-साध्य नहीं होते हैं, इसलिए न्न्हें प्राप्त करने के पश्चात् बेंक बेचने में कठिनाई अनुभव कर सकती है। उपरोक्त सभी दोषों से केवल यही सिद्ध होता है कि इन प्रतिभूतियों के स्वीकार करते समय सावधानी की आवश्य-कता होती है।

व्यवहारिक जीवन में तीन प्रकार की सावधानी रखने से वैंक के लिए हानि का भय कम रह जाता है:—(१) प्रतिभृतियों की कीमतों में परिवर्तन की सम्भावना रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रतिभूति की कीमत से कम के ऋगु दिए जायेँ। (२) ऐसे अंश अथवा अन्य पत्र न खरीदे जायेँ जिनका पूरा भुगतान नहीं हो पाया है। (३) बैंक को ऐसे साख-पत्र नहीं खरीदने चाहिए जो स्वतन्त्रता-पूर्वक विनिमय-साध्य (Negotiable) नहीं हैं।

## (२) विनिमय विल-

विनिमय बिलों को बैंक द्वारा श्रच्छी प्रतिभूति समका जाता है। एक व्यापारी विनिमय बिल को बैंक से भुनवा कर ऋ ए प्राप्त कर सकता है। ऐसी दशा में उसे बिल की परिपक्कता ग्रविष के शेष भाग के लिए ही बैंक को ब्याज देना पड़ता है। परिपक्कता पर बैंक बिल को लिखने वाले व्यापारी के पास प्रस्तुत करती है और श्रंकित राशि वसूल कर लेती है। श्रावश्यकता पड़ने पर बैंक भी बिल को दुबारा भुनवा सकती है। यह कार्य केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। विनिभय बिल एक बिक्री-साध्य साख-पत्र होता है और बैंक के श्रव्यकालीन विनियोग को सूचित करता है। इस प्रकार की प्रतिभृति के प्रमुख लाम निम्न प्रकार हैं:—

- (१) इसके मूल्य में परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता है।
- (२) इसके वेचने तथा दुबारा भुनवाने में कठिनाई नहीं होती है, इसलिए यह एक बहुत तरल आदेथ होता है।
- (३) इसकी ग्राड़ पर ऋगा मिल सकते है।
- (४) यदि विनिमय बिल सावधानीपूर्वक चुना जाता है तो इसकी राशि के वसूल होने में सन्देह नहीं होता है।

इस प्रतिभृति का एक-मात्र दोष यही होता है कि यदि स्वीकार करने वाला पक्ष भुगतान देने से इन्कार कर देता है तो बैंक को काफी कठिनाई होती है। इसके लिए यह ग्रावश्यक है कि बैंक विनिमय बिल के स्वीकार करने वाले की साख की सावधानी के साथ जाँच करे। स्वीकार करने वाले पक्ष की साख का देख लेना ग्रावश्यक होता है। साथ ही, बेंक के लिए यह भी ग्रावश्यक है कि वह गिरवी (Pledge) के रूप में विनिमय बिल को स्वीकार न करे, क्योंकि ऐसी दशा में भी काफी कठिनाई हो सकती है।

श्राधिनिक व्यवसायिक जगत में बैंक द्वारा बिल के स्वीकरण का भारी महत्त्र हैं। बैंक द्वारा बिल के स्वीकरण का ग्रामित्राय यह होता है कि बैंक ग्रपने ग्राहक की ग्रोर से बिल पर हस्ताक्षर करके उसे स्वीकार कर लेती है। यह बिल लिखने वाले ग्रायांत माल बेचने वाले के विश्वास के लिए किया जाता है। यदि बैंक का ग्राहक किसी व्यापारी से माल खरीदता है तो ग्राहक की साख ग्रज्ञात होने के कारण व्यापारी माल उवार देने में संकोच करता है। वह ग्राहक पर बिल लिखने में इसलिए डरता है कि कहीं घन डूव न जाय। ऐसी दशा में विक्रेता के विश्वास के लिए ग्राहक ग्रपनी बैंक पर बिल लिखने का ग्रादेश दे सकता है। बिल बैंक पर लिखने में विक्रेता के मिवश्वास का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस बिल को ग्रपने ग्राहक की ग्रोर से बैंक द्वारा

स्वीकार किया जाता है। परिपक्कता पर विक्रेता बैंक से रुपया पा लेने का अधिकारी होता है और क्योंकि बैंक अपने ग्राहकों की साख से परिचित होती है, वह भी इस प्रकार के बिल के भुगतान का उत्तरदायित्व ले लेती है। परिपक्कता पर बैंक ग्राहक से बिल की राशि ले लेती है और इसके अतिरिक्त कमीशन के रूप में अपनी सेवा का पारितोषण भी ले लेती है। इस स्वीकरण से विक्रेता, ग्राहक और बैंक तीनों को ही लाभ होता है। विक्रेता को धन डूबने का भय नहीं रहता है, ग्राहक को उधार माल मिल जाता है और बैंक अपना कमीशन पा जाती है।

बैंक विलों का स्वीकरण भी सोच-विचार के पश्चात् करती है। प्रत्येक व्यक्ति को यह सुविधा नहीं दी जा सकती है। केवल कुछ विश्वसनीय व्यापारियों तथा बैंक के अपने ग्राहकों की ओर से ही विल स्वीकार किये जाते हैं। प्रत्येक दशा में बैंक दो वातों पर ध्यान देती हैं:—(१) उस व्यक्ति की साख और आधिक स्थिति जिसकी ओर से विल स्वीकार किया जा रहा है और (२) अपनी स्वयं की शोधनक्षमता। यदि ग्राहक की साख सन्देहपूर्ण है अथवा यदि उसकी आधिक स्थिति बिगड़ने वाली है तो बैंक उसकी ओर से विल को स्वीकार करने से इन्कार कर सकती है। ठीक इसी प्रकार यदि बैंक को यह भय है कि विल को स्वीकार करने से उसकी अपनी आधिक दशा के विगड़ने की सम्भावना है तो बैंक स्वीकरण नहीं करेगी। स्मरण रहे कि विल के भुनाने (Discounting) तथा उसके स्वीकरण (Acceptance) में अन्तर होता है, यद्यपि दोनों में ही बैंक लाभ कमाती है। भुनाने की दशा में तो बैंक एक पहले से स्वीकार करती है। युनाने की दशा में तो बैंक एक पहले से स्वीकार करती है।

## (३) माल श्रौर उसके श्रधिकार-पत्र-

इस प्रकार की प्रतिभूति माल की वास्तिविक जमा ग्रथवा माल की जमा की रसीदों के रूप में होती है। बैंक ग्रपने गोदामों में गिरवी माल को जमा करा सकती है ग्रथवा माल ऋगी के ही गोदामों में रह सकता है, परन्तु गोदाम की चाबी बैंक के पास रहती है। इन दोनों ही दशाग्रों में बैंक के सामने माल की भौतिक उपस्थित श्रावश्यक होती है, परन्तु सभी दशाग्रों में बैंक ऐसी उपस्थित का ग्रनुरोध नहीं करती है। वह माल के ग्रधिकार-पत्रों (Document of Titles) को भी ग्राड़ में रख कर ऋगा दे सकती है, जैसे—जहाजों की रसीदें, डाक की रसीदें, रेलों की रसीदें, स्वीकृत गोदामों की माल जमा की रसीदें, इत्यादि। प्रतिभृति के रूप में ऐसे श्रिधिकार-पत्रों के दो लाम होते हैं:—(१) माल का मूल्य ग्रासानी से जाना जा सकता है ग्रौर (२) घन डूबने का भय नहीं रहता, क्योंकि ग्राड़ में रखे हुए माल की बिक्री पर तुरन्त रुपया मिल जाता है। व्यापारी द्वारा रुपए न देने की दशा में बैंक माल को नीलाम करके रुपया वसूल कर सकती है, परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ व्यवहारिक कठि-

नाइयां हैं ग्रौर बेंक को सावधान रहने की ग्रावश्यकता है। प्रमुख कठिनाइयाँ निम्न प्रकार हैं:---

- (१) बेंक को गोदाम का प्रबन्ध करना पड़ता है। उसे या तो अपनी स्रोर से गोदाम बनाने पड़ते हैं या ऐसे गोदामों को खोजना पड़ता है जो सुरक्षित तथा विश्वस-नीय हों।
- (२) यह भय सदा ही रहता है कि रखे-रखे माल के दाम घट जाने के कारए। प्रतिभृतियों का मूल्य कम न हो जाय।
- (३) गोदामों में माल के खराब हो जाने अध्यवा नष्ट हो जाने का भय रहता है।
- (ˈ४) ग्रिधिकार-पत्रों द्वारा सूचित माल के खो जाने ग्रथवा नष्ट हो जाने का भय रहता है।
  - ( ५ ) माल के सही मूल्य का आंकना कठिन होता है।
- (६) ग्रिधिकार-पत्र भूठे हो सकते हैं। घोखेबाजी की काफी सम्भावना रहती है।
- (७) ऋगी ऋग की राशि धीरे-घीरे किश्तों में चुकाता जाता है श्रौर श्रपना माल भी गोदाम से घीरे-घीरे निकालता रहता है। इसमें बैंक को काफी श्रसु-विधा रहती है श्रौर गलती होने का भी डर रहता है।
- ( = ) यदि ऋ गा माल नहीं छुड़ाता है श्रीर बैंक उसे एक दम नीलाम करती है तो कम की मत वसूल होती है, परन्तु बैंक के लिए रुक जाना भी जोखिम उठाने के बराबर होता है, इसलिए माल को नीची की मत पर ही बेचना पड़ता है।

इस सम्बन्ध में घोले तथा हानि से बचने के लिए बैंक के लिए निम्न प्रकार की सावधानियाँ त्रावश्यक होती हैं :---

- (१) जितना ऋरा दिया जाता है उससे ग्रधिक मूल्य का माल ग्राड़ में रखा जाय, ताकि माल के दाम गिरने ग्रथवा उसके नीलाम करने की दशा में हानि का भय न रहे।
- (२) मालं के मूल्य का पता लगाने, उसके सुरक्षित रखने तथा उसे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में निकालने का हिसाब रखने के लिए ग्रलग कर्मचारी रहने चाहिए।
- (३) माल रखने से पहिले उसकी किस्म और उसके खराब हो जाने की सम्भावना की जाँच होना चाहिए। यदि माल ऋगी के ही गोदामों में रखा है तो भी जाँच ग्रावश्यक है।
- (४) गोदाम सुरक्षित होने चाहिए भ्रोर समय-समय पर माल की देख-भाल होनी चाहिए, ताकि दीमक, चूहा भ्रोर पानी से माल खराब न होने पाये।
- (५) माल के ग्रधिकार-पत्रों को सावधानीपूर्वंक देख लेना ग्रीर उनके असली स्वामी का पता लगा लेना ग्रावश्यक है।

- (६) जिन ग्रधिकार-पत्रों की कई प्रतिलिपियाँ होती हैं उनकी सभी प्रति-लिपियाँ बैंक को प्राप्त कर लेनी चाहिए।
  - (७) यह देखना भ्रावश्यक है कि माल बिक्री योग्य है या नहीं।

#### (४) जीवन बीमा-पत्र--

जीवन बीमा पत्र (Life Insurance Policy) पर ऋ ए देने की प्रथा भारत में बहुत कम है, क्योंकि स्वयं बीमा कम्पनियाँ इनकी प्रतिभूति पर ऋ ए दे देती हैं, परन्तु कुछ दशाभ्रों में वैंक भी उनकी जमानत पर ऋ ए दे देती हैं। ऋ ए देने से पहले बेंक बीमा कम्पनी की आधिक स्थिति की जाँच कर लेती है और साधारए-तया बीमा-पत्र के अध्यपूर्ण मूल्य (Surrender Value) से अधिक ऋ ए नहीं देती है। इन दोनों बातों को देखने के पश्चात् बीमा-पत्र की आड़ पर ऋ ए दिये जा सकते हैं।

#### गुग-

प्रतिभूति के रूप में बीमा-पत्र के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं—(१) ग्राध्य-पूर्ण मूल्य का पता लगाने में कठिनाई नहीं होती है। (२) यदि बीमा कम्पनी विश्वसनीय है तो भुगतान न होने का भय नहीं रहता है। जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीय-करण के पश्चात् तो भारत में जीवन बीमा निगम पूर्णतया विश्वसनीय हो गया है। (३) जैसे-जैसे बीमे की ग्रीर किश्तें चुकाई जाती हैं, प्रतिभूति की कीमत बढ़ती जाती है। (४) इन पत्रों का हस्तान्तरण हो सकता है ग्रीर ये दूसरी बेंकों को बेचे जा सकते हैं। (५) बीमा कम्पनी से पूछ कर स्वामित्त्व का सही पता लगाया जा सकता है।

#### दोष-

इस प्रतिभूति के दोष इस प्रकार हैं:—(१) बीमा-पत्र में त्रुटि रहने की दशा में बीमा कम्पनी भुगतान देने से इन्कार कर सकती है। (२) बीमा-पत्र के हस्तान्तररण की दशा में बीमा कम्पनी सर्वप्रथम सूचना देने वाले के ही ग्रधिकार को स्वीकार करती है। इसमें बेंक को घोखा होने का भय रहता है। (३) बीमा कराने वाले की ग्रायु का प्रमाण-पत्र न होने की दशा में वसूली कठिन होती है। (४) प्रतिभूति के मूल्य को बढ़ाने के लिए कभी-कभी बैंक को स्वयं किस्त चुकानी पड़ती है, जिससे बैंक का व्यय बढ़ता है।

#### सावधानियाँ--

(i) दिन दोषों से बचने के लिए बैंक को ग्रध्यपूर्ण मूल्य से कुछ कम राशि ही का ऋरण देना चाहिए। (ii) यह भी आवश्यक है कि बैंक बीमा कराने वाले की श्रायु के प्रमाण-पत्र, श्रधिकार तथा बीमा चुकाने की स्थिति को देखती रहे और समुचित रूप में जाँच कर ले और बीमा-पत्र प्राप्त करते ही कम्पनी को उसकी सूचना तुरन्त दे दे। (iां) व्यवहार में बैंक ग्रामरण बीमे (Whole life Insurance) की ग्रपेक्षा निश्चित ग्रविघ बीमे (Endowment) को ग्रधिक पसन्द करती हैं।

## (५) सम्पत्ति-

सम्पत्ति दो प्रकार की होती हैं:—चल (Movable) और अचल (Immovable)—दोनों ही अकार की सम्पत्ति को गिरवी रखा जा सकता है। चल सम्पत्ति तो सोने, चाँदी, जेवरात, अनाज आदि के रूप में होती है। इनके अतिरिक्त माल के अधिकार-पत्र, हुन्डियाँ, विनिमय बिल आदि भी चल सम्पत्ति ही होते हैं। इस प्रकार की सम्पत्ति का स्थानान्तरण सम्भव होता है और इसके कय-विक्रय में भी सुविधा रहती है। ऐसी सम्पत्ति को आड़ में लेकर बैंक आसानी से ऋण दे देती है। सावधानी केवल इतनी बर्ती जाती है कि ऋण की रकम सम्पत्ति की कीमत से कम रखी जाती है, ताकि सम्पत्ति के मूल्य के नीचे गिरने की दशा में भी हानि का भय न रहे। ऐसी जमानतों पर ५० से ७०% की कीमत के ऋण दिये जाते हैं। ऐसी प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा लाभ उनकी बिक्री-साध्यता होती है। ऋणी द्वारा समय पर भुगतान न होने की दशा में बैंक तुरन्त इन्हें बेचकर धन प्राप्त कर लेती है। इस दृष्टिकोण से कम्पनियों के अशों और ऋण-पत्रों को उत्तम प्रतिभूति पाना जाता है। इसी प्रकार सरकारी हुण्डियाँ और कोषागार विषत्र भी परम प्रतिभूति (Gilt-edged Securities) होते हैं। भारत में अंश बाजार के अभाव के कारण सरकारी हुन्डियों का ही इस रूप में अधिक चलन है।

श्रवल सम्पत्ति से हमारा श्रमिश्राय ऐसी सम्पत्ति से होता है जिसका स्थानान्तरण सम्भव नहीं होता है, जैसे—जमीन, मकान, इत्यादि । साधारणतया बैंक ऐसी सम्पत्ति की जमानत लेने में संकोच करती है। कभी-कभी बैंकों पर ऐसी सम्पत्ति को ग्राड़ में न लेने का वैद्यानिक प्रतिबन्ध भी लगा दिया जाता है। ऐसी ग्राड़ का स्वीकार करना जोखिम से विमुक्त नहीं होता है, क्योंकि एक ग्रोर तो ग्रचल सम्पत्ति को तत्काल वेचकर धन प्राप्त कर लेना कठिन होता है और दूसरी ग्रोर ऐसी सम्पत्ति का स्वामित्त्व प्राप्त करने में ग्रधिक भगड़ा रहता है। इस प्रकार की प्रतिभृतियों का एक मात्र गुण् यह होता है कि बहुत से ऐसे व्यक्तियों को भी ऋण् मिल जाता है जिनके पास ग्रन्य प्रकार की जमानत नहीं है ग्रौर फिर जो केवल व्यक्तिगत साख पर ऋण् नहीं प्राप्त कर सकते हैं।

प्रतिभृति के रूप में अचल सम्पत्ति के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :--

- (१) ऐसी सम्पत्ति के सही-सही स्वामित्त्व का पता लगाना कठिन होता है।
- (२) सम्पत्ति का ठीक मूल्य केवल विशेषज्ञ ही ग्राँक सकते हैं 🖥
- (३) ऐसी सम्पत्ति के मूल्य में अधिक'अंश तक परिवर्तन होते रहते हैं।
- (४) ऐसी सम्पत्ति के प्रवन्ध ग्रौर निरीक्षणा पर काफी व्यय होता है ग्रौर उसे एक दम बेच देना भी सम्भव नहीं होता है।
- (५) स्वामित्त्व के हस्तान्तरस्य के लिए लम्बी-चौड़ी श्रदालती कार्यवाही की श्रावश्यकता पड़ती है।

उपरोक्त कारणों से ऐसी जमानत को स्वीकार करने में संकोच किया जाता है। अचल सम्पत्ति की आड़ पर अप्टर्ण देने वाली वैंक को वड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है:—(१) बैंक को चाहिए कि सम्पत्ति के स्वामित्त्व ग्रीर ग्रिष्कार का ठीक-ठीक पता लगाए।(२) सम्पत्ति को गिरवी रखने के लिए वैधा-

निक प्राधि (Mortgage) ग्रावश्यक होता है। (३) हस्तान्तरित करने वाले के स्वामित्त्व ग्रौर ग्रधिकार की भली-भाँति जाँच होनी चाहिए। (४) सम्पत्ति की कीमत से ऋएा की राशि काफी कम रखनी चाहिए।

इस प्रश्न का उत्तर कठिन है कि ऋगा देते समय किसी बैंक को कौन-कौन

#### उधार देने के सम्वन्ध में सावधानियाँ—

दिये जा सकते है :---

समस्याएँ ग्रलग-ग्रलग होती हैं। सभी बैंक समान रूप में व्यापार कुशल भी नहीं हो सकती हैं ग्रीर सभी ग्राहक भी समान रूप में विश्वासप्रद नहीं होते हैं। इस सम्बन्ध में सबसे ग्रधिक महत्त्व बेंक के अनुभव का है। ग्रपने कार्यवाहन के ग्रन्तर्गत बैंक यह जान लेती है कि किन ग्राहकों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाय। इसके ग्रतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों श्रीर कालों की समस्याएँ भी श्रलग-ग्रलग हो सकती हैं। ऋगों के सम्बन्ध में सबसे ग्रधिक ध्यान ऋगी के चरित्र, उसकी ग्राधिक स्थिति श्रीर उसके ऋगा के लेने के कारण की ग्रीर देना चाहिए। यद्यपि प्रत्येक बैंक की ऋगा दान नीति में ग्रन्तर हो सकता है, परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ सामान्य सुभाव निम्न प्रकार

सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रलग-ग्रलग बेंकों ग्रीर ग्रलग-ग्रलग ग्राहकों की

- (१) आदेयों की तरलता—आदेयों की तरलता और वैंक की अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ही लम्बे काल के लिए ऋएा देना अनुपयुक्त होता है।
- (२) जोखिम का ग्रधिकतम् वितरएा—जोखिम का यथासम्भव ग्रधिक से ग्रधिक वितरएा होना चाहिए। इस दृष्टिकोएा से कुछ थोड़े से व्यक्तियों को बड़े-बड़े ऋएा देने की ग्रपेक्षा बहुत से व्यक्तियों को छोटे-छोटे ऋएा देना ग्रधिक ग्रच्छा होता है। इसी प्रकार एक क्षेत्र में ऋएा देने ग्रथवा एक ही प्रकार के व्यापारियों को ऋएा देने की ग्रपेक्षा बहुत से क्षेत्रों ग्रौर ग्रनेक प्रकार के व्यापारियों को ऋएा देना ग्रच्छा होता है।
- (३) ऋगों की उत्पादकता—ग्रधिकांश ऋग उत्पादक होने चाहिए, ताकि ऋगी उनसे प्राप्त ग्राय में से ब्याज ग्रीर मूलधन चुका सके। उपभोग ग्रथवा सट्टे के लिए दिए हुए ऋगा श्रच्छे नहीं होते हैं।
- (४) उपयुक्त जमानत—जमानत लेने में सावधानी की ग्रावश्यकता है। बैंक को प्रतिभूतियों की तरलता पर ग्रनुरोध करना चाहिए। ग्रचल सम्पत्ति की ग्राड़ पर कम ऋरण देने चाहिए।
  - ( ५) पर्याप्त मार्जिन रखना—बैंक को चाहिए कि ऐसी नीति अपनाये कि

ऋरण की राशि प्रतिभूति के मूल्य से काफी कम रहे। इससे जोखिम बच जाती है स्रौर हानि का भय नहीं रहता। ऐसी दशा में स्वयं ऋरणी भी शीध्र भुगतान करके अपने माल को छुड़ाने के लिए उत्सुक रहता है।

- (६) ऋगा की वसूली में नियमितता—ऋग के वसूल करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि ऋगी को बार-बार ऋगा को बदलने अधवा उसका नवीनी-करण (Renewal) करने की सुविधा दी जाती है तो वह भुगतान करने में उत्सुकता नहीं दिखाता है और भुगतान की अविध बढ़ जाती है।
- (७) ऋरण की मात्रा का निर्धारण्—ऋरण की कुल मात्रा सोच-समफ्तकर निश्चित करनी चाहिए। प्रत्येक ऋरण निक्षेप उत्पन्न करता है और नकद कोष को कम करने की सम्भावना उत्पन्न करता है। नकद कोषों की तुलना में निक्षेपों के बहुत बढ़ जाने से बेंक के फेल हो जाने का डर रहता है।
- (८) ऋरगी के सम्बन्ध में जानकारी—ऋगी का चरित्र ही ऋग के भुगतान की सबसे बड़ी गारन्टी होती है, इसलिए इस सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्राप्त किये बिना ऋगा नहीं देना चाहिए।

## वैंक का चिट्ठा श्रथवा बैलेन्स शीट (The Balance Sheet)

बैंक के स्थिति विवरण का श्रर्थ—

किसी भी बैंक की वास्तविक ग्रार्थिक स्थिति का सही ग्रनुमान उसके चिट्टे द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक बैंक की सम्पूर्ण लेनदारी श्रीर देनदारी का विस्तृत विवर्षा होता है। किसी भी बैंक के चिट्टे के श्रध्ययन से निम्नलिखित लाभ होते हैं:--(i) कोई भी व्यक्ति चिट्ठे को देख कर बैंक की पूँजी. विनियोग नीति तथा उसकी व्यापार-कुशलता का पता लगा सकता है। (ii) चिट्ठा वार्षिक म्राघार पर बनाया जाता है। दो वर्षों के चिट्ठों की तुलना करने से यह भी सरलता से जाना जा सकता है कि बीच के काल में बैंक की स्थित किस ग्रंश तक सूधर गई है अथवा बिगड़ गई है। (iii) जनता में बैंक के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिए भी चिट्ठे का भारी मह<del>स्य होता है। पुराने काल में ग्र</del>पनी ग्रार्थिक स्थिति को सूहढ़ दिखाने के लिए बैंक के कर्मचारी चिट्टे को जान-बूफ कर इस प्रकार बनाते थे कि बैंक को स्थिति ग्रच्छी दिखाई पड़े। वैसे भी ग्रलग-ग्रलग बैंकों की चिट्ठा बनाने की विधि म्रलग-म्रलग थी। इससे घोलेबाजों की काफी सम्भावना रहती थी स्रौर विभिन्न बेंकों की म्रार्थिक स्थिति की तुलना करने में भी कठिनाई होती थी। बैंक की समुचित प्रगति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता था। भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में सन् १९४६ के बैंकिंग कम्पनी विधान में चिद्वा बनाने की एक रीति निर्धारित कर दी है और ग्रब सभी भारतीय बैंक उसी के ग्रनुसार चिट्ठा तैयार करती हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोगा से भी श्राधुनिक बैंक चिट्ठे में जान-बूभ कर परिवर्तन करना

उचित नहीं समक्तीं, क्योंकि इसका उनकी साख पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उपरो नियम के श्रनुसार भारत में बैंकों के वार्षिक चिट्ठे का निम्न रूप होता है:— वैंक को वार्षिक चिट्ठे का नमूना

পক্ষ বাপেক বস্তু কা ননুবা (Specimen of Bank Balance Sheet)

पूँजी और देनदारी (Liabilities)
(१) पूँजी: अधिकृत अथवा परिदत्त

(Capital : Authorised

or Paid-up) : (क) पूर्वाधिकार ग्रंग

(Preference Shares) (ভ) साधारण ग्रंश

(Ordinary Shares)

(ग) ग्रस्थगित ग्रंश

(Deferred Shares) (२) सुरक्षित कोष एवं अन्य जमा

(Reserves and Funds)

(३) जमाघन तथा ग्रन्य खाते(Deposits and other

Accounts):

Accounts): (क) सावधि जमा (Fixed

Deposits)

(ख) सेविंग बैंक जमा

(ग) चालू जमा (Current Account)

(४) ग्रन्य वेंकों, ग्रिभकर्ताग्रों ग्रादि के ऋगः

(क) भारत के भीतर

(ख) भारत के बाहर

(খ) গাঘনীয় বিল (Bills Payable)

(६) ग्रन्य बिल (Bills of Collection, etc.)

(७) ग्रन्य देन (Other Liabilities) लेनदारी ग्रौर ग्रादेय (Assets)

(१) नकदी:

(क) हाथ की नकदी

(Cash in hand) (ख) रिजर्व वेंक में जमा

(ग) स्टेट बैंक में घरोहर

(घ) ग्रन्य बैंकों के पास, चालू खातों में जमा

(२) याचना राशि (Money at

Call & Short Notice)

(३) भुनाये श्रोर खरीदे हुए बिल
 (४) विनियोग (Investments):

(क) केन्द्रीय श्रीर राज्य सरका की हुण्डियाँ श्रीर कोषागा विपत्र

(ख) ग्रंश:

์ (ग्र.) पूर्वाधिकार

(ग्रा) साधारण (इ) ग्रस्थगित

(ग) ऋगा-पत्र ग्रौर बाँड

(Debentures and Bonds)

(घ) स्वर्ण

(ङ) ग्रन्य विनियोग

(५) ऋग तथा ग्रग्रिम

(Loans and Advanc including Over-dra

and Cash-Credit) : (क) पूर्णतया सुरक्षित ऋग (Fully secured Debt

- (६) स्वीकृतियाँ, बेचान तथा इसी प्रकार की ग्रन्य देन (Acceptances, Endorsements and such other Obligations) (१) लाभ ग्रीर हानि खाता
- (Profit and Loss A/c.)
- (१०) सामयिक ग्रथवा ग्रांकस्मिक देन (Contingent Liabilities)

- (ख) व्यक्तिगत जमानत पर दिये हुए ऋरण (Loans on
- Personal Security)
  (ग) ऋग, जिन पर व्यक्तिगत
  जमानत के ग्रतिरिक्त ग्रौर
  व्यक्तियों की भी व्यक्तिगत
  जमानत है।
- (Unsecured or Doubtful Loans) (ङ) बेंक के संचालकों ग्रथवा

(घ) बिना जमानती ऋगा

- श्रिषकारियों को दिये गये ऋण (Loans to the Directors and Officers of the Bank)
- (च) ऐसी कम्पनियों ग्रथना फर्मों को दिये हुए ऋगा जिनसे बेंक के संचालक सम्बन्धित हैं।

  (Loans to Companies or Firms with which the Directors
- connected)
  (छ) कुल ऐसे ऋगों का योग जो
  बैंक के संचालकों, मैंनेजर
  तथा भ्रन्य भ्रधिकारियों को
  दिए गए हैं।

of the Bank are

- (ज) कुल ऐसे ऋगों का योग जो उन कम्पनियों तथा फर्मों को दिये गये हैं जिनसे बेंक के संचालक किसी प्रकार सम्बन्घित हैं।
- (क) ग्रन्य बैंकों पर ऋग (Dues from other Banks)

- (६) वसूनी के लिए प्राप्त बिल (Bills acquired for collection)
- (७) स्वीकृतियाँ, वेचान म्रादि (Acceptances, Endorsements, etc.)
- (द) कार्य-स्थान (Premises minus depreciation
- (६) फर्नीचर श्रोर अन्य सामान
- (१०) ग्रन्य ग्रादेय
- (११) गैर-बैंकिंग आदेय
- (१२) लाभ ग्रौर हानि

योग

योग

## चिट्ठे का विश्लेषण-

चिट्ठा ठीक इसी प्रकार तैयार किया जाता है जिस प्रकार कि बही खाते का एक पृष्ठ । इसमें दाहिनी भ्रोर देनदारी दिखाई जाती है भ्रीर बाईं भ्रोर लेनदारी । दोनों तरफ की मदों का योग भ्रन्त में बराबर हो जाता है भ्रौर बैलेन्सजीट का सन्तुलन हो जाता है । बैलेन्सजीट को ठीक-ठीक समभने के लिए हम देनदारी की प्रमुख मदों को एक-एक करके लेते हैं।

(१) पूँजी - बैंक अपनी पूँजी को चिट्ठे में विशेष रीति से दिखाती है। प्रारम्भन से पूर्व ही यह घोषित कर दिया जाता है कि बैंक कितनी पूँजी से ग्रपना व्यवसाय म्रारम्भ करेगी। ऐसी घोषणा बैंक के स्मारक-पत्र (Memorandum of Association) में कर दी जाती है और इसी के आधार पर बैंक अपले अंश निकालती है। ऐसी पूँजी को ग्रधिकृत पूँजी (Authorised Capital) कहा जाता है। कोई बेंक ग्रिवकृत पूँजी से ग्रिविक कीमत के ग्रंश नहीं निकाल सकती है, यद्यपि यह म्रावश्यक नहीं है कि सम्पूर्ण प्रधिकृत पूँजी के ग्रंश बेचे जायें। प्रधिकृत पूँजी के जिस भाग के श्रंश वास्तव में निकाले जाते हैं श्रीर बेचने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं उसे निर्गमित पूँजी (Issued Capital) कहा जाता है। यदि सम्पूर्ण अधिकृत पूँजी के ग्रंश निकाले जाते हैं तो निर्गमित ग्रौर ग्रधिकृत पूँजी बराबर होगी। यह भी म्रावश्यक नहीं है कि सभी निकाले हुए ग्रंश खरीद लिये जायें। जितने मूल्य के ग्रंश जनता द्वारा खरीदे जाते हैं उसे प्राथित पूँजी (Subscirbed Capital) कहते हैं। इस सम्बन्ध में यह भी याद रखना ग्रावश्यक है कि बैंक बहुधा ग्रपने ग्रंश का सारा मुल्य एक ही साथ नहीं लेती है। १०० रुपये के ग्रंश पर ग्रारम्भ में ५० रुपए लिये जा सकते हैं और आगे आवश्यकता पड़ने पर घीरे घीरे अंश की कीमत का शेष रुपया ले लिया जा सकता है। प्राधित पूँजी का वह भाग जो बैंङ्क को वास्तव में चुका दिया

जाता है, परिदत्त पूंजी ( $Paid-up\ Capital$ ) कहलाती है। यह श्राबश्यक है कि चिट्ठे में पूंजी को दिखाते समय चारों प्रकार की पूँजी को श्रलग-श्रलग दिखाया जाय।

- (२) सुरक्षित कोष तथा ग्रन्य जमा—इस मद में वह कुल राशि दिखाई, जाती है जो बेंक लाभांश घोषित करने से पहले सुरक्षित कोष में डालती रहती है। इस प्रकार की समस्त जमा इस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाई जाती है।
- (३) जनाधन तथा अन्य खाते—इस शीर्षक में विभिन्न व्यक्तियों और फर्मों द्वारा बेंक में जमा की हुई राशि को दिखाया जाता है। प्रत्येक प्रकार की जमा का अलग-अलग दिखाना आवश्यक होता है।
- (४) अन्य बैंद्धों के ऋर्ग इस शीर्षक में दूसरी बेंकों से लिया हुन्रा उचार दिखाया जाता है। देश के भीतर और देश के बाहर की बेंद्कों के ऋर्गों को अलग-अलग दिखाना आवश्यक होता है।
- ( १) शोधनीय बिल—इस मद में उन सब बिलों की राशि का जोड़ लिखा जाता है जिनका भुगतान करने का बैंक ने उत्तरदायित्व लिया है।
- (६) अन्य बिल—यह शीर्षंक उन बिलों की राशि की दिखाता है जिन्हें बैंक ने अपने ग्राहकों की भ्रोर से एकत्रित करने के लिए जमा किया है। यह रूपया एकत्रित हो जाने के परचात् ग्राहकों को लौटा दिया जाता है, इसलिए ऐसे बिलों की राशि को लेन और देन दोनों के रूप में दिखाया जाता है। वसूली से पहले यह बैंक की लेन होती है और वसूली के परचात् उसकी देन बन जाती है।
- (७) स्वीकृतियाँ तथा बेचान—इस शीर्षक में उस राशि को दिखाया जाता है जिसकी कीमत के विनिमय बिल बैंक ने भ्रपने ग्राहकों की भ्रोर से स्वीकार कर लिए हैं। स्वीकार किए हुए विल का घन ग्राहक से मिल जाता है भ्रोर इस घन से बिल का भ्रगतान कर दिया जाता है, परन्तु जब तक बिल का भ्रगतान नहीं होता है, यह बैङ्क की देन ही रहती है।
- ( ८ ) सामयिक अथवा आकस्मिक देन—इस शीर्षंक की राशि को देन-दारी के योग में नहीं जोड़ा जाता है। बैंक अपनी ऐसी देनदारी को इस मद में दिखाती है, जो केवल अनुमानजनक है और किसी प्रकार निश्चित नहीं है। आकस्मिक देनों के लिए, जो अज्ञात हैं, पहले से ही कुछ न कुछ व्यवस्था कर ली जाती है।

## लेनदारी अथवा आदेय (Assets)-

विहिनी ग्रोर के खानों में बेंक की लेनदारी ग्रथवा उस राशि का ब्यौरा दिया जाता है जो बेंक को प्राप्त होनी है। इस ग्रोर के प्रमुख शीर्षकों की विवेचना निम्न प्रकार है:—

(१) नकदी—भारतीय बैंक अपने पास ग्राहकों की माँग को पूरा करने

के लिए सदा ही नकदी का संचय रखती हैं। इसके य्रतिरिक्त समय ग्रौर माँग देन का एक निश्चित प्रतिशत विधानानुसार रिजर्व बैंक में जमा किया जाता है। एक बैंक स्टेट बैंक ग्रॉफ इन्डिया तथा ग्रन्य बैंकों में भी धरोहर रख सकती है, ताकि भ्रावस्य-कता पड़ने पर नकदी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके।

- (२) याचना राशि—इस शीर्षंक में उन सब धनों को सम्मिलित किया जाता है, जो माँगने पर तुरन्त मिल जाते हैं। ऐसी राशि वैंक द्वारा श्रधिक से श्रधिक एक सप्ताह के भीतर वसूल की जा सकती है।
- (३) भुनाये और खरीदे हुए बिल—उन सव बिलों की कीमत इस शीर्षक में दिखाई जाती है जो या तो बेंक ने खरीद लिए हैं अथवा भुना दिये हैं। परिपक्कता पर इनका रुपया बेंक को मिल जाता है, परन्तु परिपक्कता अविध के आने से पूर्व आवश्यकता पड़ने पर इन्हें बेचा जा सकता है, अथवा रिजर्व बेंक से भुनवा लिया जाता है।
- (४) विनियोग—विनियोगों में बैंक के लाभदायक म्रादेयों को सिम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के विनियोग की राशि म्रलग-म्रलग दिखाई जाती है। म्रल्पकालीन मौर दीर्घकालीन तथा सरकारी मौर गैर-सरकारी हुण्डियों के विनियोग का विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है।
- ( प्र ) ऋगा तथा श्रग्रिम—इस शीर्षंक में दूसरों को उघार दी गई राशि चिट्ठे में दिखाये हुए क्रम के श्रनुसार लिखी जाती है।
- (३) स्वीकृतियाँ—इस मद में उन बिलों का सारा मूल्य दिखाया जाता है जिन्हें बेंक ने ग्राहकों की ग्रोर से स्वीकार किया है। यह राशि देनदारी में भी दिखाई जाती है।
- (७) कार्य-स्थान—इसके अन्तर्गत बेंक की समस्त अवल सम्पत्ति का मूल्य दिखाया जाता है। ऐसी सम्पत्ति में बेंक के कार्यालय की बिल्डिङ्ग, बेंक का फर्नीचर तथा उसके कार्य-स्थान से सम्बन्धित अन्य स्थिर सामानों की कीमत को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार की सम्पत्ति बेंक के मृत स्कन्ध होते हैं। इन्हें उसी समय बेचा जाता है जबिक बेंक फेन होती है और उसका निस्तारण (Liquidation) करके लेनदारों को भुगतान किया जाता है।

#### **QUESTIONS**

1. What are the tests of the soundness of a bank? Is there any necessary relation between the size of a bank and its soundness? (Agra, B. A., 1956 Supp.)

#### २८४ ]

- Briefly discuss the functions of a modern bank and explain the main considerations that guide a banker in investing his funds. (Raj., B. Com., 1958)
- 3. Describe the functions of a Commercial Bank. What are the sources of its profits and what considerations guide the investment of its funds? (Agra, B. Com., 1956 Supp.)
- 4. Explain the functious of a Commercial Bank and discuss in this connection the importance of cash reserves and investment policies. (Agra, B. Com., 1955 Supp.)
- एक अधिकोष का काल्पनिक स्थिति विवरण (Balance Sheet) बना कर यह बताइये कि उसके भिन्न-भिन्न पदों का क्या महत्त्व है ? (Sagar, B. Com. 1958)
- ६. 'एक श्रच्छी बैंक को चाहिए कि वह तरलता और लाभदायकता के बीच सन्तुलन बनाए रक्खे।' व्याख्या कीजिए। (Sagar, B. Com., 1955)
- 7. Write short notes on:

  Money at Call and Short Notice. (Agra, B. Com., 1955)

  Liquid Assets of a Bank. (Agra, B. Com., 1957 & 1954)

## अध्याय १५

## बेंक और ग्राहक का सम्बन्ध

(The Relation Between the Bank and the Customer)

## 'वैंकर' श्रौर 'ग्राहक' की परिभाषायें—

बेंक ग्रीर ग्राहक के सम्बन्ध को समभने से पहले दोनों के सही-सही ग्रर्थं समभ लेना म्रावश्यक है। एक पिछले मध्याय में हम देख चुके हैं कि वैंक की बिल्कूल सही परिभाषा करना कठिन है। साधारए। रूप में हम बैंकर उस संस्था अथवा व्यक्ति को कहते हैं जो मुद्रा श्रीर साख में व्यवसाय करे। दूसरे शब्दों में, रुपये की लेन-देन श्रीर साख का कय-विक्रय बैंक की प्रमुख विशेषताएँ होती हैं। घनादेशों द्वारा भगतान करने की प्रणाली के विकास के कारण अधिकांश भुगतान धनादेशों पर ही किये जाते हैं. म्रतएव डा॰ हार्ट ने बैंक की परिभाषा इस प्रकार की है:-- ''एक वैंकर वह व्यक्ति है जो श्रपने साधारण व्यवसाय के श्रन्तर्गत ऐसे धनादेशों का भुगतान करता है जो उन व्यक्तियों द्वारा लिखे गये हैं जिनके लिये ऋथवा जिनकी ऋोर से उसके पास चाल खाते में रुपया जमा किया गया है ।" इस प्रकार घनादेशों पर भुगतान करना ही आधूनिक बैंक की प्रमुख विशेषता है और यह भुगतान उस घन में से किया जाता है जो ग्राहकों ने बैंक में जमा कर रखा है। कूछ लोगों से घन जमा के रूप में स्वीकार करके बैंक दूसरे व्यक्तियों को ऋगा के रूप में दे देती है। साख का निर्माग भी इस प्रकार की जमा के ही ग्राघार पर किया जाता है। इस कारए। किंचित यह कहना अनुपयक्त न होगा कि बैंक एक प्रकार अपने विभिन्न ग्राहकों के बीच लेन-देन का सम्बन्ध स्थापित कराने में मध्यस्थ का कार्य करती है।

स्रव ग्राहक शब्द का सही स्रथं समभने की स्रावश्यकता है। साधारण बोल-चाल में ग्राहक का स्रभिप्राय खरीदार से होता है, जो किसी वस्तु स्रथवा सेवा को खरीदता है। बैंक के सम्बन्ध में भी ग्राहक के लगभग यही स्रथं होते हैं, परन्तु बैंकिंग के सम्बन्ध में खरीदने का विशेष स्रथं होता है। बैंक के सम्बन्ध में ग्राहक का स्रभिप्राय ऐसे व्यक्ति, फर्म स्रथवा संस्था से होता है जिसने बैंक में घन जमा करके स्रपने नाम का खाता खुलवाया है सौर इस खाते में से वह बिना पूर्व सूचना के घनादेश द्वारा घन निकाल सकता है। यह स्रावश्यक नहीं है कि व्यक्ति विशेष स्रधिक समय से बैंक के साथ व्यवसाय करे। ग्राहक ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका बैंक में इस प्रकार का खाता है कि उसमें से घनादेश द्वारा घन निकाला जा सकता है। इस का उठना म्रावश्यक है कि क्या उस व्यक्ति को बेंक का ग्राहक नहीं कहा जायगा जो वेंक में रुपया जमा करने के स्थान पर उलटा बेंक से रुपया उधार लेता है? व्यवसायिक जगत में ऋणी और जमाधारी दोनों ही को बेंक का प्राहक कहा जाता है। वात यह है कि बेंक से ऋण लेने वाले तथा बेंक में धन जमा करने वाले के बीच वेंक के व्यवसायिक दृष्टिकोण से कोई भी म्रन्तर नहीं होता है। ऋण भी जमा को उत्पन्न करते हैं; बेंक की धन उधार देने को रोति यह है कि ऋण की राशि का ऋणी के नाम बेंक में खाता खोल दिया जाता है, जिसमें से वह धनादेशों द्वारा भुगतान ले सकता है, म्रतः बेंक का ऋणी भी ऐसा ही व्यक्ति होता है जिसके खाते में बेंक में रुपया जमा रहता है और धनादेशों द्वारा निकाला जा सकता है। इस प्रकार बेंक का प्रत्येक ग्राहक उसका जमाधारी होता है।

#### ग्राहकों के प्रकार-

वेंक का याहक व्यक्ति, फर्मे, कम्पनी, संस्था, समा, संघ श्रादि कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार एक ग्रधकारी ग्रथवा संघ का मन्त्री भी सभा की ग्रोर से खाता खोज सकता है। किसी व्यक्ति ग्रथवा संस्था को ग्राहक बना लेने के पश्चात् वेंक को उससे सम्बन्धित कर्त्तंथों को पूरा करना ग्रावश्यक होता है, इसलिए ग्राहक बनाते समय वेंक श्रपने भावीं ग्राहक के सम्बन्ध में पूरी जानकारी ग्राप्त करने का प्रयत्न करती है। किसी भी व्यक्ति के नाम का खाता खोलने से पहले उसके चरित्र, उसकी साख, उसकी ईमानदारी, उसकी व्यवसायिक ख्याति तथा उसकी ग्राधिक स्थिति का पता लगाया जाता है। यही कारण है कि वेंक नये ग्राहक से हवाला ग्रथवा परिचय माँगती है। ऐसे व्यक्ति के विषय में दूसरी बेंकों तथा पुराने ग्राहकों से ग्रप्त जांच की जाती है ग्रीर व्यक्तिगत भेंट द्वारा बेंक का व्यवस्थापक वास्तविक स्थिति का पता लगाने का प्रयत्न करता है। सुरद्धा के लिए ग्राहक के हस्ताद्धरों के नमूने लिए जाते हैं ग्रीर बेंक इस बात पर ग्रनुरोध करती है कि प्रत्येक धनादेश पर नमूने के ग्रनुसार ही हस्ताक्षर होने चाहिए। नमूने के हस्ताक्षर सुरक्षित रखे जाते हैं।

## याहक श्रौर बैंकर का पारस्परिक सम्बन्ध

एक बेंकर और उसके ग्राहक के बीच तीन प्रकार के सम्बन्ध होते हैं---

- (१) साहूकार तथा ऋ गो का सम्बन्ध (Creditor and Debtor)।
- (२) म्रिभिकत्तां म्रथवा प्रतिनिधि मौर प्रधान का सम्बन्ध (Agent and Principal)।
- (३) घरोहर-वारी और घरोहर-वर्ता अथवा अमानत लेने वाले और अमा-नत देने वाले का सम्वन्च (Bailee and Bailer)।

## साहुकार श्रीर ऋणी—

बैंकर ग्रौर ग्राहक के बीच का ग्राघारभूत सम्बन्ध ऋगी ग्रौर साहूकार का ही

है। जब कोई व्यक्ति बैंक में अपना रुपया जमा करके खाता खुलवाता है तो जमाधन की मात्रा के अनुसार बैंक जमा करने वाले अर्थात् ग्राहक की ऋणी हो जाती है। यह बैंक का उत्तरदायित्व होता है कि वह निश्चित वार्तों पर ग्राहक की माँग पर उसका घन लौटा दे। इसके विपरीत कुछ दशाओं में बेंकर साहकार होता है और ग्राहक उसका ऋणी होता है। वैंकर अपने ग्राहक को घन उधकर देता है, जो अधिविक्ष, नकद साख, ऋण, अग्रिम आदि किसी भी रूप में दिया जा सकता है। घन का लौटाना ग्राहक का उत्तरदायित्व होता है। इस प्रकार कभी ग्राहक ऋणी होता है और और कभी बैंकर। बैंकर और ग्राहक के इस सम्बन्ध की कुछ विशेषताएँ होती हैं, जो साधारणतया अन्य साहूकारों और ऋणी व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों में नहीं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं की गण्याना निम्न प्रकार की जा सकती हैं:—

- (१) ऋगा का भुगतान करने की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध—स्वभाव में ग्राहक द्वारा जमा की गई राशि एक ऐसे सामान्य ऋगा की भाँति होती है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दिया जाता है। ग्राहक श्रथवा जमाधारी को वैङ्क के विरुद्ध वही प्रधिकार प्राप्त होते हैं जो एक साहकार को ऋगी पर प्राप्त होते हैं। यदि वैङ्क का दिवाला निकल जाता है तो जमाधारी को अपनी जमा के प्रमाण देने पड़ते हैं और तभी उसका दावा सचा माना जाता है, परन्तु एक साधारण व्यापारिक ऋरण भौर बैंड्ड की जमा में अन्तर होता है। जो राशि बैंड्ड में जमा की जाती है वह बैंड्ड के पास ग्रमानत ग्रथवा घरोहर के रूप में नहीं होती है, बल्कि यह राशि ऋएा के रूप में होती है. जिसे बैङ्कर ग्रावश्यकता पड़ने पर किसी भी प्रकार उपयोग कर सकता है, परन्तु यद्यपि एक साधारण कर्जदार ऋण की राशि को कभी भी चुका सकता है श्रौर चुकाने के सम्बन्ध में कोई समय अविध अथवा शर्त नहीं लगाई जाती है, बैङ्क ऐसा नहीं कर सकती है। वह अपनी ओर से घन का भुगतान करके ऋगा से निवटारा नहीं पा सकती है। ग्राहक का खाता केवल ग्राहक की प्रार्थना पर ही बन्द किया जा सकता है। बिना माँग के बैङ्क भूगतान नहीं कर सकती है। इस प्रकार सोधारण ऋगी के विप-रीत भुगतान की प्राथमिकता साहकार अर्थात् ग्राहक की स्रोर से ही होती है, स्वयं ऋगी सर्थात बैङ्क की स्रोर से नहीं।
- (२) ऋरण का उपयोग करने की स्वतन्त्रता—वैद्धर को उसके पास जमा किये हुए घन के उपयोग का पूरा-पूरा अधिकार होता है। एक साधारण ऋरणी किसी निश्चित उद्देश्य से ऋरण लेता है और प्राप्त राशि का उपयोग निर्धारित शर्तों के अनुसार करता है, परन्तु बैद्ध के ऊपर इस प्रकार का कोई उत्तरदायित्त्व नहीं होता है। वह जमाधन का इच्छानुसार विनियोग कर सकती है। बैद्धर का केवल इतना दायित्व रहता है कि जमाधन को यदि वह चालू खाते में है तो माँग पर तुरन्त चुका दे और वह सावधि जमा में है तो निर्धारित अवधि के पश्चात् चुका दे। इससे आगे घन के उपयोग पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता है।

- (३) ऋगादाता (ग्राहक) की ग्राज्ञानुसार रुपयों का भुगतान—एक साधारण ऋगा तो ऋगादाता द्वारा निश्चित भ्रवधि के पहले वापिस नहीं लिया जा सकता है, किन्तू वैद्ध के ग्राहक को यह ग्रधिकार होता है कि वह पहले से निर्घारित की गई शर्तों के अनुसार घनादेश द्वारा अपनी रकम की वापिस ले ले और विधान के अनुसार वैङ्क के लिए यह अनिवार्य है कि यह ग्राहक की आज्ञानुसार उसके खाते में से भगतान करती रहे। वैङ्क का यह उत्तरदायित्व है कि जैसे ही धनादेश प्रस्तुत किया जाता है, तूरन्त भूगतान कर दे। यदि चैक में किसी प्रकार की श्रनियमितता नहीं है श्रीर चैक लिखने वाले के खाते में पर्याप्त धन है तो बैङ्क भुगतान करने से इन्कार नहीं कर सकती है। यदि कोई बैङ्कः विना समुचित कारण के चैक का अनादर अथवा तिरस्कार (Dishonour) करती है तो इसका बैंड्झ की साख पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यही नहीं इससे चैक लिखने वाले के आर्थिक मान और उसकी प्रतिष्ठा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति द्वारा लिखे हुए चैंक का ग्रनादर हो जाता है उसे लोग शङ्का की दृष्टि से देखने लगते हैं और उसके साथ व्यवसाय करने में संकोच करते हैं। ग्राहक को यह भी ग्रधिकार है कि यदि बैङ्क ने ग्रकारण चैक का ग्रनादर किया है तो वह बैङ्क पर मान-हानि का दावा करके मुग्रावजा प्राप्त कर ले। न्यायालय बैङ्क को हर्जाना देने पर बाध्य करते हैं।
- (४) ग्राहक के खातों की गोपनीयता ग्रौर पूछ-ताछ—एक साधारण ऋरणदाता के लिये यह ग्रनिवार्य नहीं है कि वह ग्रपने ऋरणी की ग्राधिक ग्रवस्था को ग्रुप्त रखे या उसके बारे में किसी भी प्रकार की पूछ-ताछ का उत्तर दे। किन्तु बैंङ्कर के लिए यह ग्रावश्यक है कि वह ग्रपने ग्राहक के खाते से सम्बन्धित सभी बातों को ग्रुप्त रखे। वह ग्रन्य पक्षों को ग्राहक के सम्बन्ध में कोई बात उस समय तक नहीं बता सकती है जब तक कि ऐसा करना या तो ग्रावश्यक न हो ग्रौर या उग्युक्त। प्रत्येक बार जब बैंक ग्रपने ग्राहक की ग्राधिक स्थिति की सूचना ग्रन्य व्यक्तियों को देती है तो वह एक प्रकार की जोखिम उठाती है। यदि बैङ्क के ऐसा करने से ग्राहक के मान की हानि होती है तो ग्राहक बैङ्क के ऊपर क्षय-पूर्ति का दावा कर सकता है। वैसे भी बैङ्क की ऐसी कार्यवाहियों का परिग्णाम यह होगा कि बैङ्क श्रपने ग्राहकों को खो बैठेगी। केवल निम्न दशाग्रों में ग्राहक की ग्राधिक स्थिति का रहस्य खोलना उचित हो सकता है।
  - (क) जबिक किसी न्यायालय के आर्देशानुसार ग्राहक की आर्थिक स्थिति का बताना आवश्यक है।
  - ( ख ) यदि ऐसा करना राष्ट्र, समाज ग्रथवा व्यवसायिक उन्नति के लिए ग्रावश्यक है।
  - (ग) जबिक ग्राहक स्वयं रहस्य खोलने की ग्राज्ञा देता है।
  - (घ) जविक ग्राहक वैङ्क का हवाला देता है श्रीर संदर्भ (Reference) के लिए बैङ्क को ग्राहक की ग्राधिक स्थित बताना पड़ती है।

# (ङ) यदि ग्राहक की आर्थिक स्थिति बताना स्वयं वेंक की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

उपरोक्त दशायों में भी जब कभी भी ग्राहक के खाते ग्रौर उसकी साख की सूचना दी जाती है तो बेंक को सावधानी से काम लेना चाहिए। यदि वेंक की ग्रसावधानी के कारए। ग्राहक की साख को ठेस पहुँचती है तो इससे वेंक ग्रौर ग्राहक दोनों हो को हानि होती है।

#### श्रमिकर्त्ता और प्रधान-

वेंक ग्रौर ग्राहक का दूसरा सम्बन्ध ग्रीभिकर्ता ग्रौर प्रधान का होता है। बेंक का प्रमुख कार्य तो रुपए का जमा करना ग्रौर उधार देना ही है, परन्तु श्राधुनिक वेंक को श्रपने प्राहक के प्रतिनिधि श्रथवा श्रीभिकर्ता के रूप में भी श्रनेक सेवाएँ सम्पन्न करनी पड़ती हैं। इन सेवाग्रों का व्यापार ग्रौर वाि एज्य जगत में भारी महत्त्व है। इनसे ग्राहक को विशेष सुविधा होती है ग्रौर क्योंकि बेंकर ग्रपनी सेवाग्रों का पारितोषण लेता है, इसलिए उसकी भी ग्राय में वृद्धि होती है। श्रीभिकर्ता के रूप में वेंकर के निम्न कार्य महत्त्वपूर्ण हैं:—(१) ग्राहक के चैकों का भुनाना, (२) ग्राहक की ग्रोर से विनिम्य बिलों को स्वीकार करना ग्रौर एकत्रित करना, (३) ग्राहक का ग्रोर से विनिम्य बिलों को स्वीकार करना ग्रौर एकत्रित करना, (३) ग्राहक का श्रोर से ग्रंशों, ऋण पत्रों, प्रतिज्ञा-पत्रों, स्टॉक ग्रादि को खरीदना ग्रौर बेचना, (५) ग्राहक की ग्रोर से ब्याज, मूलधन, लाभाँग ग्रादि एकत्रित करना ग्रौर चुकाना, (६) ग्राहक की ग्रोर से बीमा, ब्याज, ऋण ग्रादि की किश्तों का चुकाना, (७) ग्राहक की ग्रोर से ग्रन्य ग्रादेशित कार्य करना, इत्यादि।

इन कार्यों की संख्या और उनका महत्त्व ग्राधुनिक संसार में बराबर बढ़ता ही जा रहा है। ये सभी कार्य ग्राहक के ग्रादेशानुसार बेंक उसके प्रतिनिधि के रूप में करती है ग्रीर यिद बेंक अपने प्राहकों की आज्ञानुसार कार्य करती है तथा अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करती है तो बेंक के कार्यों के लिए प्राहक उत्तरदायी होता है। इस सम्बन्ध में ग्राहक और बैंक के पारस्परिक सम्बन्ध पर भारतीय प्रसंविदा विधान (Indian Law of Contracts) की व्यवस्थाएँ लागू होती हैं। जब तक बैंक की लापरवाही, श्रधिकार से बाहर काम करना ग्रथवा बेईमानी सिद्ध नहीं होती है, ग्राहक बैंक की उन सभी कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी होता है जो उसने उस ग्राहक की ग्रोर से की हैं।

### घरोहरं-धारी और घरोहर-धर्ता-

बेंकर तथा ग्राहक के बीच तीसरी प्रकार का सम्बन्ध प्रन्यासी (Trustee) तथा लाभवारी (Beneficiary) का होता है। आधुनिक वैङ्क अपने प्राहकों की बहुमूल्य वस्तुओं के लंरकाण का भी कार्य करती हैं। एक ग्राहक जेवबात, हीरे, मु०च०ग्र० (१६)

बहुमूल्य प्रतिभूतियाँ ग्रौर पत्र-वैंक के संरक्षण में छोड़ सकता है। इस संरक्षण के लिस वैङ्क शुल्क अथवा कमीशन लेती है, परन्तु बैंक घरोहर को सुरक्षित रखने ग्रीर लौटाने की गारन्टी देती है। घरोहर के खो जाने ग्रथवा नष्ट हो जाने की दशा में वैंक को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। विधान के अनुसार घरोहर के प्रति बैङ्क को इतनी ही सावधानी वर्तनी पड़ती है जितनी वह निजी माल के सम्बन्ध में रखती है। यदि वैंक की किसी भी प्रकार की ग्रसावधानी के कारण ग्राहक को हानि होती है तो वैंक को उसकी क्षय-पूर्ति करनी पड़ती है।

व्यवहार में बेंक इस प्रकार की घरोहर को मुहर लगे हुए लिफाफों ग्रथवा मुहर लगे हुए तालाबन्द सन्दूकों में लेती है श्रीर बैंक यह जिम्मेदारी लेती है कि माँगने पर घरोहर-वर्ता को उसी प्रकार बिना मुहर टूटे घरोहर लौटा दी जायगी । परन्तु ऐसी वस्तु के लौटाने में सावधानी की ग्रावश्यकता होती हैं। यदि यह किसी ग्रनाधिक्त (Unauthorised) व्यक्ति को लौटा दी जाती तो बैंक उत्तरदायी होती हैं। कुछ देशों में इस प्रकार का नियम है कि यदि घरोहर रखने के लिए पारितोषण नहीं लिया जाता है ग्रोर बैंक की घोर लापरवाही सिद्ध नहीं होती है तो बैंक घरोहर की क्षय-पूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। मारत का नियम इस सम्बन्ध में अधिक कड़ा हैं। यहाँ प्रत्येक घरोहर पर बैंक्क की असावधानी सिद्ध होने पर क्तय-पूर्ति आवश्यक होती है, चाहे उसके संरक्षण के लिए बैंक ने कमीशन लिया है या नहीं।

जड़ बैंक बहुमूल्य वस्तुओं के संरक्षण श्रौर सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व लेती है तो वह एक प्रन्यासी (Trustee) के रूप में कार्य करती है। इसी प्रकार जब बैंक निश्चित शर्तो पर जमा स्वीकार करती है श्रौर उसका हिसाब जमा करने वाले को देती रहती है तो भी बैंक प्रन्यासी हो रहती है।

## ब्राहकों के प्रति बैंक की विशेष जिम्मेदारियाँ—

उपरोक्त सम्बन्धों के अतिरिक्त व्यवहारिक जीवन में बैंक के उसके ग्राहकों के प्रित कुछ विशेष उत्तरदायित्त्व होते हैं, जिनका निभाना बैंक के लिए आवश्यक होते हैं। ये उत्तरदायित्त्व निम्न प्रकार हैं:—

- (i) धनादेशों का भुगतान करना— बैंक के लिए उसके ग्राहकों द्वारा उस पर लिखे हुए बनादेशों का ग्रादर करना ग्रावश्यक होता है। जब तक ग्राहक के खाते में प्रयक्ति धन है ग्रीर धनादेश के विषय में कोई ग्रन्य प्रकार की त्रुटि नहीं है, बेंक को उस पर लिखे हुए सभी चैंकों का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- (ii) बैंकर का साधारण ग्रह्णाधिकार (General lien)—यदि कोई विरोधी समभौता नहीं हुन्ना है तो प्रतिभूति के रूप में बैंक किसी भी ऐसी सम्पत्ति को रोक सकती है जो उसके संरक्षण में रखी हुई हो।
  - ( iii ) खातों की गोपनीयता—बैंक का यह महान् उत्तरदायित्व होता है

कि वह अपने ग्राहक के खाते को ग्रुप्त रखे। दहुत बार ग्राहक की द्याधिक स्थिति के खुल जाने से उसकी साख तथा उसके व्यवसाय को काफी हानि पहुँच सकती है, अत-एव जब तक नियम, लोक हित अथवा ग्राहक की स्वीकृति के कारण ऐमा करना आवश्यक नहीं होता है, बेंक अपने ग्राहक की आधिक स्थिति छुपाकर ही रखती है, परन्तु बेंक अपने ग्राहकों को एक दूसरे की आधिक स्थिति के सम्बन्ध में गोपनीय रिपोर्ट दे सकती है।

- (iv) आनुषांगिक व्यय लेने का अधिकार—वैंक को अपने ग्राहकों से आनुषांगिक व्यय (Incidental Charges) वसूल करने का अधिकार होता है और ग्राहक उन्हें देने से इन्कार नहीं कर सकता है।
- (  $\nabla$  ) चक्रवर्ती व्याज लगाने का अधिकार—वैंक को चक्रवर्ती व्याज लगाने का अधिकार होता है।
- ( vi ) समय-सीमा की छूट— वैंक ऐसी गारन्टी देती है कि निक्षेपदाताग्रों द्वारा जमा की हुई राशि पर समय सीमा (Time Limitation) लाग्न नहीं होती है। यदि निक्षेपदाता को तीन साल से भी अधिक समय रुपया जमा किए हुए हो जाता है ग्रीर समय सीमा विद्यान (Limitation Law) के अनुसार ऋरण के ब्रशोघनीय हो जाने की श्रवस्था उत्पन्न हो जाती है, परन्तु फिर भी बैंक उसे चुकाने से कभी भी इन्कार नहीं करती है।

## बैंकर और ग्राहक के सम्बन्ध की कुछ विशेष दशाएँ —

चार महत्त्वपूर्ण परिस्थितियों में, जो नीचे दी जाती हैं, वैंक को विशेष रूप में सावधानी से काम करना पड़ता है:—

- (१) ग्राहक के धनादेशों का भुगतान—वैसे तो ग्राहक के घनादेशों का भुगतान करने के लिए बैंक उत्तरदायी है ग्रीर ग्रकारणा भुगतान न करने पर बैंक को मान-हानि की क्षय-पूर्ति करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, परन्तु इस सम्बन्ध में भी थोड़ी सी सावधानी की ग्रावश्यकता होती है। यदि बैंक को इस प्रकार की सूचना मिल चुकी है कि ग्राहक पागल हो गया है, उसका दिवाला निकल चुका है, ग्राहक ने घनादेश विशेष का भुगतान न करने का लिखित ग्रादेश दे दिया है, ग्रथवा ग्राहक ने घनादेश के खो जाने की सूचना दे दी है तो बैंक को चाहिए कि वह ग्राहक के घनादेश का भुगतान न करे। यदि सब कुछ जानते हुए भी बैंक भुगतान करती है तो वह हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी होती है।
- (२) म्रल्पवयस्क ग्राहक के प्रति—ग्रल्पवयस्क ग्रथवा नावालिग (Minor) के साथ व्यवसाय करने में बड़ी सावधानी की ग्रावश्यकता है। विधान के श्रनुसार श्रत्यवयस्क के साथ किए हुए प्रसंविदे (Contracts) ग्रमान्य होते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति ऋगा लेता है, श्रध-विकर्ष प्राप्त करता है, श्रथवा बिल को स्वीकार करता है तो उससे धन वसूल नहीं किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के नाम का खाता खोलते

समय बैंक को इन सब वातों का घ्यान रखना पड़ता है। व्यवहार में बैंक इस बात पर अनुरोध करती है कि ऐसे व्यक्ति की ओर से उसके संरक्षक के नाम पर खाता खोला जाय और उसे जमाधन से अधिक घन निकालने का अधिकार न दिया जाय।

- (३) सम्मिलित हिन्दू परिवार का खाता—सम्मिलित हिन्दू परिवार की भ्रोर से उसका प्रवन्धकर्ता सभी बातों के लिए उत्तरदायी होता है। परिवार के अन्य सदस्यों के वैधानिक अधिकार सीमित होते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे खाते से सम्बन्धित सभी धनादेशों पर प्रवन्धकर्ता के हस्ताक्षर रहें। साभेदारी फर्म में सभी साभेदारों का सामृहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, इसलिए किसी भी साभेदार के हस्ताक्षर अथवा आदेश पर भुगतान किया जा सकता है, परन्तु सम्मिलित हिन्दू परिवार में यह बात नहीं होती है।
- (४) संस्था की ग्रोर से खोला हुआ खाता—फर्मों की भाँति संस्थाओं ग्रथवा विभागों की ग्रोर से भी खाते खोले जा सकते हैं। इन खातों पर संस्थाओं ग्रौर विभागों के ग्रधिकारियों द्वारा धनादेश लिखे जाते हैं ग्रीर बहुधा चैकों पर दो या उससे ग्रधिक हस्ताक्षर ग्रावश्यक होते हैं। इसके ग्रितिरक्त यह भी बेंक को पहले से ही बता दिया जाता है कि ग्रमुक खाते से धन निकालने का ग्रधिकार किसको है। बेंक के लिए यह ग्रावश्यक है कि सभी धनादेशों की समुचित जाँच के पश्चात् ही भुगतान करे श्रोर सन्देह को दशा में बिना प्रमाए। के भुगतान न करे।

#### **QUESTIONS**

- 1. Discuss the relationship between a banker and his customer. (Agra, B. Com., 1953; Raj., B. Com., 1956, 1952, 1960, 1949)
- What is a banker and who is his customer? Examine the relationship between the two. (Agra, B. Com., 1957)
- 3. What precaution should the banker take in opening accounts with:—
  - (a) a miner, (b) a married purdanashin woman, (c) joint-stock company, (d) an illiterate person. (Raj., B. Com., 1950)
- 4. How is the banker's position as a drawer with regard to endorsement on cheques; if the banker makes payment in due course of a cheque bearing a forged endorsement, can be see over the amount as money paid under mistake?

(Agra, B. Com., 1957)

#### अध्याय १६

# आधुनिक बैङ्किङ्ग के प्रकार

(The Types of Modern Banking)

#### व्यापार वैंकिंग के प्रकार—

देश की प्रचलित मुद्रा साधारएतिया बेंकिंग मुद्रा ही होती है और यह वैंक मुद्रा व्यापार वैंकों द्वारा निर्मित होती है। विभिन्न देशों में व्यापार वैंकों के संगठन और उनकी कार्य-विधियों में भारी अन्तर पाया जाता है, परन्तु व्यापार वैंकिंग प्रधा को हम दो बड़े-बड़े भागों में बाँट सकते हैं:—(१) ब्रिटेन की शाखा वैंकिंग प्रणाखी (Branch Banking System) तथा (२) अमरीका की इकाई वैंकिंग पद्धति (Unit Banking System)। सबसे पहले हम बैंकों की इस कार्य-विधि के अन्तर का ही अध्ययन करेंगे।

## शाखा चैंकिंग प्रणाली (Branch Banking)

#### शाखा बैंकिंग का अर्थ-

शाखा वैङ्किंग से अभिप्राय वैङ्किंग की उस प्रणाली का है जिसमें वैङ्किंग कम्पनी की अनेक शाखायें सारें देश में या देश के एक बहुत बड़े भाग में फैली हैं। इस प्रकार की वैंकिंग प्रणाली का सबसे घच्छा उदाहरण इङ्गलण्ड में मिलता है, जहाँ व्यापार वैंक साधारणतया एक विशालकाय संस्था होती है, जिसकी शाखाएँ देश भर में फैली रहती हैं। ग्रन्य बहुत से देशों में भी, जिनमें भारत भी सम्मिलित है, यह प्रणाली प्रचलित है। इङ्गलण्ड की कुल १०,५७४ वैंकिंग संस्थाओं में से ६७,७१७ पर पाँच बड़ी-बड़ी वैंकों का, जिन्हें 'महान् पाँच' (Big Five) कहा जाता है, माधिपत्य है। इसी प्रकार जर्मनी ग्रीर फ्रान्स में भी ग्रधिकांश वैंकिंग व्यवसाय कुछ थोड़ी सी ही बैंकों के हाथ में है।

### शाखा बैंकिंग प्रणाली के लाभ-

इस प्रकार की वैंकिंग प्रणाली के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं :--

(१) बड़े पैमाने की उत्पत्ति श्रीर श्रम-विभाजन के लाभ—शाखा बैंकिंग को बड़े पैमाने की उत्पत्ति तथा श्रम-विभाजन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। एक ही बैंक का विशाल संगठन होता है श्रौर उसके पास पूँजी तथा श्रन्य साधन भी श्रिषक मात्रा में होते हैं। ऐसी बैंक बैंक-कार्यों के संचालन के लिये विशेषज्ञ रख

सकती है और इम प्रकार प्रपने व्यवसाय का वैज्ञानिक तथा कुशल प्रवन्ध कर सकती है। छोटी-छोटी वैंकों के लिए धनाभाव के कारण यह सम्भव नहीं है कि वे ऊँचा वेतन देकर विशेषज्ञों को रख सकें।

- (२) सुरिक्षित कोष में बचत—इस प्रणाली में निधि की बच्चत होती है। एक विशाल वैंक के लिए यह सम्भव हो सकता है कि वह प्रत्येक शाखा में थोड़ी-थोड़ी मुरिक्षित निधि रखे, क्योंकि ग्रावश्यकता पड़ने पर एक शाखा से दूसरी शाखा को नकद कोषों का हस्तान्तरण किया जा सकता है, परन्तु यदि बैंक की शाखाएँ नहीं हैं तो उसे ग्रधिक बड़ा सुरिक्षित कोष रखना पड़ता है, जिससे कि ग्रावश्यकता पड़ने पर किठनाई न हो। इस प्रकार व्यवसाय के विस्तार की तुलना में इकाई वैंकिंग की प्रपेक्षा शाखा वैंकिंग में कम सुरिक्षत कोषों की ग्रावश्यकता पड़ती है।
- (३) धन के हस्तांतरए। में मितव्ययिता एवं सरलता—शाखा बैंकिंग के लिये विश्रेय व्यवसाय (Remittance Business) अर्थात् धन का एक स्थान से दूसरे को हस्तान्तरए। सस्ता और सरल होता है, क्योंकि बैंक की एक शाखा से दूसरी को घन का हस्तान्तरए। हो सकता है। यही कारए। है कि ऐसी बैंकों के कारए। देश के विभिन्न भागों के लिए व्याज की दरों में समानता आ जाती है।
- (४) व्यवसायिक जोखिम का भौगोलिक वितरण शाखा बैंकिंग में व्यवसायिक जोखिम का भौगोलिक वितरण हो जाता है। कुल सम्पत्ति अथवा कुल व्यवसाय एक ही क्षेत्र में केन्द्रित न होकर कई स्थानों पर फैला हुआ होता है। इस प्रकार एक स्थान की हानियों का एक दूसरे स्थान के लाभों से समायोजन होता रहता है। यदि एक स्थान पर मन्दी भी आती है तो भी बैंक सरलतापूर्वंक उसके दुष्परिणामों को सहन कर सकती है।
- (४) बैंकिंग सेवाफ्रों में वृद्धि—इस पद्धति द्वारा देश के सभी नगरों, अविकसित क्षेत्रों और ग्रामीए क्षेत्रों तक में बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध की जा सकती है। इस प्रकार इसके द्वारा देश के उन भागों को भी बैंकिंग सेवाफ्रों के लाभ प्राप्त हो जाते हैं जहाँ स्वतन्त्र रूप में बैंक खोलने का विचार भी नहीं किया जा सकता है।
- (६) प्रतिभूतियों का कुशल विनियोग शाखा बैंकिंग प्रणाली के ग्रन्त-गंत वैंकों के कर्मचारी योग्य एवं कुशल होते हैं, ग्रौर उनके पास विनियोग के लिए धन भी काफी होता है। ग्रतः वे उपयुक्त व सुरक्षित प्रतिभूतियों में घन का विनियोग करने में सफल रहते है।
- (७) कर्मचारियों की ट्रोनिंग में भी सुविधा हो जाती है, क्योंकि शाखा वैंकिंग के ग्रन्तर्गत वैंकों का काम बहुत विस्तृत होता है, जिससे कर्मचारियों को वैंकिंग कारोबार के प्रत्येक पहलू की ट्रोनिंग प्राप्त करने का ग्रवसर मिलता है।

## शाखा बैंकिंग पद्धति के दोष-

यह प्रगाली श्राधुनिक श्राधिक विकास प्रगाली के श्रनुकूल तो श्रवस्य है,

परन्तु म्राष्ट्रिक उत्पादन प्रणाली के सभी दोप भी इसमें पाये जाते हैं। प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं:—

- (१) प्रबन्ध व निरीक्षण की कठिनाई—इस प्रणाली में बड़े पैमाने की उत्पत्ति के सभी दोष होते हैं। विदालकाय सगठन के कारण प्रवन्य, निरीक्षण भीर नियन्त्रण की गम्भीर समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं।
- (२) प्रारम्भन-प्रेरणा, लोच व रुचि-म्रनुकूलता का म्रभाव—एक बैंक के लिए दो बातों की भारी म्रावश्यकता होती है: एक तो यह कि जिस क्षेत्र में वह स्थित है उस क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों ग्रौर प्राहकों की रुचियों के ग्रनुसार कार्य-विधि निश्चित की जाय ग्रौर दूसरे, उसके कार्य में लोच तथा प्रारम्भन प्रेरणा (Initiative) रहे। शाखा बैंकिंग द्वारा ये दोनों बातें कठिनाई से पूरी होती हैं, क्योंकि प्रत्येक बात प्रधान कार्यालय से पूछ कर उसकी निर्वारित नीति के ग्रनुसार की जाती है। यही कारण है कि ऐसी प्रणाली को व्यक्तिगत सम्पर्क के लाभ बहुत ही कम प्राप्त होते हैं ग्रौर बहुत बार उसका कार्य स्थानीय परिस्थितियों के भ्रमुकूल नहीं रह पाता है।
- (३) व्ययपूर्ण प्रगाली शाखा बैंकिंग प्रणाली साधारणतया व्ययपूर्ण होती है। प्रत्येक नई शाखा की स्थापना पर अलग-अलग व्यय करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त जैसे-जैसे शाखाओं की संख्या बढ़ती है और उनका फैलाव बढ़ता है वैसे-वैसे समचय (Coordination), नियन्त्रण (Control) तथा निरीक्षण (Supervision) का व्यय बढ़ता जाता है।
- (४) म्रनावश्यक व प्रतियोगी विकास का दोष —यह पद्धित बैंकिंग सेवाम्रों के म्रनावश्यक तथा प्रतियोगी विकास को प्रोत्साहन देती है। प्रत्येक नगर भौर क्षेत्र में प्रत्येक बैंक म्रपनी-म्रपनी शाखाएँ खोलने का प्रयत्न करती है। इससे सेवाम्रों की दोबारगी (Duplication) होती है भौर विभिन्न बैंकों के बीच हानिकारक प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है।
- (५) एक शाखा के दोषों का ग्रन्य शाखाश्रों पर प्रभाव—एक शाखा की भूल का सारी शाखाश्रों पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी एक क्षेत्र में संकट ग्रथवा मन्दी श्राती है तो सारी की सारी बेंकिंग प्रणाली का ढाँचा हिलने लगता है।
- (६) एकाधिकार को बढ़ावा -- शाखा बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत अत्यधिक केन्द्रीयकरण हो जाता है। इसके फलस्वरूप आधिक सत्ता कुछ इने-गिने व्यक्तियों के हाथों में पहुँच जाती है, जिसका दुरुपयोग होने का भय है।

## इकाई चैंकिंग (Unit Banking)

इस प्रकार की बैंकिंग प्राणाली का चलन मुख्यतया संयुक्त राज्य अमरीका मे

है। इसके अन्तर्गत एक वेंक का कार्य साधार एतया एक ही कार्यालय तक सीमित होता हे, यद्यपि यह सम्भव हे कि कुछ बैंकों को एक सीमित च्रित्र के भीतर शासाय लालने का भी अधिकार हो। इस प्रणालों में प्रतिनिधि बैंकिंग पद्धित द्वारा काम किया जाता है। घनों के हस्तान्तर ए तथा कार्य की सुविधा के लिए विभिन्न बैंकों को एक-दूसरे से सम्बन्ध रखना पड़ता है। इकाई वैंकिंग प्रणाली इस आधार भूत विचार के अनुसार ठीक समभी जाती है कि एक वैंक का प्रारम्भन स्थानीय समाज द्वारा ही होना चाहिए और उसका स्वामित्त्व भी उसी के पास रहना चाहिये। ऐसी बैंक का व्यवसाय साधार एतिया आस-पास के उद्योगपितयों, व्यापारियों तथा कृषकों से ही सम्बन्धित होता है। ऐसी प्रणाली में वेंक के कार्य का स्थानीय, आर्थिक और सामाजिक संगठन के साथ एकी करण होता है। ऐसी पद्धित में जन-संख्या के अनुपात में बैंकों की संख्या अधिक होती है। अमरीका में हजारों छोटी-छोटी स्वतन्त्र और स्यक्तिगत वेंक है, जिनका स्वामित्त्व भी स्थानीय होता है। एकाधिकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अमरीकन सरकार वेंकों के कार्य क्षेत्र को सीमित रखने का प्रयत्न करती है।

## इकाई वैंकिंग के गुण-

इस प्रणाली के समर्थक इसे विभिन्न कारणों से ग्रविक उपयुक्त बताते हैं-

- (i) स्वतन्त्र व्यवसाय सिद्धान्त के अनुकूल—यह कहा जाता है। इकाई-बेंकिंग स्वतन्त्र व्यवसाय (Free Enterprise) सिद्धान्त के प्रधिक अनुकूल है।
- (ii) स्थानीय कल्यागा का विशेष ध्यान—इसमें स्थानीय कल्यागा का विशेष ध्यान स्थानीय कल्यागा का विशेष ध्यान रखा जाता है। शाखा बैंकिंग स्वभाव से ही ऐसी होती है कि अपने लाभ के पीछे स्थानीय जन-संख्या के हितों का ध्यान नहीं रख सकती है। बैंक का स्थानीय जन-संख्या से प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत सम्पर्क रहता है और उसका संचालन तथा उसकी कार्य-विधि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होती है।
- (iii) एकाधिकारी संस्थाओं के विकास पर रोक—यह प्रणाली एका-धिकारी बेंकिंग के विरुद्ध एक अच्छा प्रतिबन्ध है, क्योंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत बैंक छोटे-छोटे होते हैं, जिससे बड़ी एकाधिकारी संस्थाओं के निर्माण का डर नहीं होता।
- ( iv ) कार्य में शीझता एकाकी बैंकिंग-प्रगाली के ग्रन्तगंत कार्य शीझता से समय पर किया जाता है । ग्रधिकारीगग्ग दिन प्रति दिन की समस्याग्रों का यथोचित निर्णय कर लेते हैं जिससे दीर्घसूत्रता (Red Tapism) की हानियाँ नहीं होने पाती हैं ।
- ( v ) अनुशल बैंकों की समाप्ति—जब कि शाख बेंकिंग के अन्तर्गंत एक बैंक की अनुशब शाखा अन्य कुशल शाखाओं के बल पर जीवित रहती है, इकाई बैंकिंग अर्णावी के अन्तर्गंत ऐसा होना सम्भव नहीं है, क्योंकि एक अकुशल बैंक अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता।

( vi ) प्रवन्ध में सुविधा रहती है, क्यों कि इस पद्धति के अन्तर्गत देश भर में शाखाओं का जाल सा नहीं विछा होता।

#### श्रालोचना—

इस प्रणाली के विरुद्ध भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। जोखिम का फैलाव न होने के कारण इस प्रणाली में स्थिरता कम होती है ग्रीर बेंकों की विफलता का भय अधिक रहता है। (ii) कोपों में गतिलशीता नहीं रहती ग्रीर उनका हस्तान्तरण किन ग्रीर ज्ययपूर्ण होता है। (iii) ज्यवसाय का पैमाना छोटा होने के कारण प्रवन्ध की कुशलता तथा कार्य-विधियों के सुधार सम्बन्धी लाभ कम ही प्राप्त होते हैं। (iv) ऐसी प्रणाली में छोटे-छोटे नगरों तथा ग्रामीण हो तों में वैंकिंग सेवाएँ उपस्थित करने में किठनाई होती हैं, क्योंकि एक स्वतन्त्र वेंक की स्थापना शाखा खोलने की ग्रपेक्षा अधिक किठन होती है ग्रीर नये क्षेत्रों में ग्रारम्भ में ज्यवसाय भी कम ही मिलता है। (v) सरकारी नियन्त्रण तथा निरीक्षण के हिएकोण से भी इकाई वैंकिंग शाखा बैंकिंग की तुलना में श्रच्छी नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक वैंकिंग इशाइ पर ग्रलग-ग्रलग नियन्त्रण रखना ग्रावश्यक होता है।

#### इकाई वैंकिंग प्रणाली में सधार—

इकाई बैंकिंग प्रणाली के दोषों को देखते हुए ग्रमरीकन बैंकिंग पद्धति में कुछ ग्रावश्यक सुष्ठार किये गये हैं। (i) कुछ बैंकों को थोड़ी-थोड़ी शाखाएं खोलने का अधिकार दिया गया है। (ii) इसके ग्रातिरक्त वहाँ शृङ्खलाकारी अथवा वर्गीय (Chain or Group), बैंकिंग पद्धित को प्रोत्साहन दिया गया है। इसके ग्रन्तर्गत बहुत सी बैंकों पर एक ही साथ एक ही व्यक्ति ग्रथवा कुछ थोड़े से व्यक्तियों का सामू-हिक स्वामित्त्व रहता है, यद्यपि वैसे प्रत्येक बैंक की पूँजी, प्रवन्ध तथा कर्मचारी ग्रवग ग्रवग होते हैं। (iii) साथ ही ऐसी भी व्यवस्था पाई जाती है कि प्रामीण चें त्रों तथा छोटे-छोटे नगरों की बैङ्क बड़े-बड़े लगरों की बैङ्कों में अपने साते खोलाती हैं, जिससे कि विभिन्न बैंकिंग इकाइयों का एक-दूसरे से धनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। (iv) बड़े-बड़े नगरों की बैङ्क छोटी-छोटी बेङ्कों को व्यवसायिक सलाह देती है। उनके फालतू घन को एक से दूसरी के पास हस्तान्तरित करती है ग्रोर ग्रावश्य-कता के समय उन्हें ग्राथिक सहायता भी देती है।

#### निष्कर्ष—

यह निर्णय करना थोड़ा किठन है कि भारत में इन दोनों में से कौन सी
प्रणाली ग्रिंघक उपयुक्त है। इस सम्बन्ध में टामस् (Thomas) ने कहा है कि
"यद्यपि दोनों ही प्रणालियाँ अपूर्ण हैं, परन्तु दोनों की कार्य पद्धति को देखने से
पता चलता है कि शाखा बैङ्किंग प्रणाली अधिक उत्तम हे ।" वास्तविकता यह है
कि ग्रमरीका जैसे धनी देश में तो जहाँ जन-साधारण की ग्राय काफी ऊँची है ग्रौर
जहाँ व्यवसायों का काफी विस्तार हो चुका है, इकाई बैंकिंग प्रणाली ठीक हो सकती

है, यद्यपि वहाँ पर भी उसके सफल संचालन के लिए उसमें समय-समय पर परिवर्तन आवश्यक होते हैं। भारत में पूँजी की कमी है, आय की कभी के कारए। बचत कम होती है, बेंकिंग प्रशाली का विकास बहुत ही कम हुआ है और प्रस्तुत बेंकों के पास पर्याप्त व्यवसाय नहीं है, इसलिए यहाँ इकाई बेंकिंग प्रशाली उपयुक्त नहीं हो सकती है। हमारे लिए तो शाखा बैंकिंग ही अधिक अच्छी है, परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि एक बेंक की अलग-अलग शाखाएँ स्थानीय दशाओं के अनुसार अपनी अपनी नीति और कार्य-प्रशाली का निर्माण करें, ताकि बैंक और स्थानीय व्यवसायिक वगं के बीच निरुटतम् सम्बन्ध बना रहे।

ग्रमेरिका ने इकाई बैंकिंग पद्धित को ग्रपनाया था, लेकिन सन् १६२६-३३ की महान् मन्दी में इस प्रणाली के बैंक संकटों का सामना न कर सके और टूट गए, जबिक इक्नलैंड के शाखा प्रणाली के बैंक इन संकटों को फोल गये। ग्रपनी अनिगनती शाखाओं के बल पर उन्होंने संकटों का सामना कर लिया। इस कारण ही ग्रमेरिका ग्रब घीरे-घीरे शाखा बैंकिंग की ग्रोर बढ़ रहा है। भारत ने इक्नलैंड का ग्रनुसरण करते हुये शाखा बैंकिंग पद्धित को ग्रपनाया है।

## वैंकों का वर्गीकरण (The Classification of Banks)-

बेंक साधारएतया निम्न प्रकार की होती हैं :--

(१) केन्द्रीय बैंक (Central Bank) -यह देश की राष्ट्रीय बैंक होती है। ऐसी देश में साधारणतया एक ही बैंक होती है, यद्यपि इसकी अनेक शाखाएँ हो सकती हैं। भारत की केन्द्रीय बैंक। रिजर्व बैंक ग्रॉफ इण्डिया है। लगभग सभी केन्द्रीय बेंकों की दो प्रमुख विशेषताएँ होती हैं :--प्रथम, ऐसी बेंक को देश में नोट निर्गम का एकाधिकार बात होता है और दूसरे, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर उसे जनता से प्रत्यक्ष व्यवसाय करने का ग्रविकार नहीं होता है। केन्द्रोय बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य सम्पन्न करती है। सरकारी धन की लेन-देन और उसका हिसाब-किताब केन्द्रीय बैंक ही रखती है और यह बैंक आवश्यकता पड़ने पर सरकार को ऋएा भी देती है। दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय बैंक सरकार की बैंकर होती है। सरकारी रोकों का संरक्षण और सरकारी ऋणों का प्रबन्घ भी इसी के हाथ में होता है। इसके अतिरिक्त यह वेंक विभिन्न रीतियों से देश की चलन तथा साख व्यवस्था पर नियन्त्रण रखती है, सरकार को श्रार्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक मामलों में सलाह देती है श्रीर इन विषयों से सम्बन्धित आवश्यक सूचना और आँकड़े एकत्रित करती है । बुँकिंग प्रणाली के दृष्टिकीए। से भी केन्द्रीय वेंक कई प्रकार के महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। यह वेंकों की बेंक होती है। बैंकों को विभिन्न रूपों में ऋ एों, ग्रग्रिमों तथा उनके द्वारा भुनाए हुए विनिमय बिलों को पुनः मुनाकर ग्रायिक सहायता देती है, उनके समुचित संचालन की देख रेख करती है और सरकार को वैंकिंग विधान के सम्बन्ध में सुफाव देती है। आधुनिक युग

में तो मौद्रिक साख, विनियोग तथा वित्तीय समस्याग्रों की जटिलता के कारए। केन्द्रीय बैंक का महत्त्व वरावर ग्रौर भी बढ़ता जा रहा है।

(२) व्यापारिक वैंक (Commercial Banks)—भारत की ग्राध-काँश सम्मिलित पूँजी बैंक (Joint-stock Banks) इसी प्रकार की हैं। इन बैंबों का प्रमुख कार्य व्यापार की वित्तीय व्यवस्था में सहायता देना होता है। इन वैंकों की विशेषता यह होती है कि वे ग्रल्पकालीन ऋगा और ग्रग्निम प्रदान करती हैं। भारत में ऐसी बैंक साधारएातया ३ महीने तक के लिए ही ऋएा देती है. यद्यपि कुछ दशाश्रों में ग्रधिक से ग्रधिक १ वर्ष के लिए भी ऋगा दे दिए जाते हैं। ये ग्रग्रिम वैयक्तिक प्रतिभूतियों, विनिमय विलों भ्रथवा बाँड की भ्राड़ पर दिये जाते हैं, परन्तु तैयार माल, जो गोदामों में रखा गया है, फसलें, कृषि की उपज, ग्रन्य उपयुक्त तरल ग्रादेय तथा चल सम्पत्ति को भी वैंकों द्वारा श्रच्छी प्रतिभृति समभा जाता है। प्रतिज्ञा-पत्रों पर साधारणतया किसी दूसरे सम्मानित दल के हस्ताक्षरों का भी अनुरोध किया जाता है। विधानानुसार ऐसी वेंक भ्रचल सम्पत्ति की ग्राड़ पर तथा दीर्घकालीन ग्रौद्योगिक कार्यों के लिए ऋगा नहीं देती हैं. परन्तु भारत की कुछ व्यापार बैंक व्यापारिक वित्त के ग्रतिरिक्त ग्रौर भी बहत सी सेवाग्रों को अपने कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं। ऐसी बैंक लगभग सभी प्रकार की निक्षेपों को स्वीकार करती हैं ग्रीर वैंक सम्बन्धी भ्रन्य सामान्य सेवाग्रों को भी सम्पन्न करती हैं। बहुत बार ये बैंक विदेशी विनिमय व्यवसायों में भी भाग लेती हैं। Hadusing many.

(३) श्रौद्योगिक बैंक (Industrial Banks) — ये वैंक व्यापार के स्थान पर ग्रीद्योगिक वित्त की व्यवस्था करती हैं। इन वैंकों के तीन कार्य महत्त्वपूर्ण होते हैं :- प्रथम, जमा का प्राप्त करना-व्यापार बेंकों की भाँति ग्रौद्योगिक बेंक भी जमा स्वीकार करती हैं. परन्तू ये साधारगातया निश्चित तथा अनिश्चितकालीन निक्षेपों ग्रयात् दीघंकालीन जमा ही स्वीकार करती हैं, क्यों कि इन्हें ऋगा भी लम्बे काल के लिए देने पड़ते हैं। दूसरे, ये बैंक दीर्घकालीन भीद्योगिक ऋरा प्रदान करती हैं। उद्योगों को दो प्रकार के ऋगों की म्रावश्यकता होती है: - मशीनरी, बिव्डिङ्ग तथा फर्नीचर म्रादि के लिए दीर्घकालीन ऋए। म्रावश्यक होते हैं, परन्तु मजदूरी चुकाने, कचा माल खरीदने और तैयार माल की विक्री के लिए श्रत्पकालीन ऋ एों से काम चल जाता है। दूसरी प्रकार के ऋए। तो व्यापार वैंकों से मिल जाते हैं, परन्तु प्रथम प्रकार के ऋए। भौद्योगिक बैंकों से मिलते हैं। इस सम्बन्ध में भौद्योगिक बैंक ऋए। लेने वाले उद्योग की साख और वित्तीय स्थिति की सूद्म जाँच करती है और नियन्त्रण तथा सुरक्षा के लिए फर्म के प्रबन्ध में सिक्तय हिस्सा लेती है। तीसरे, ये बैंक भीर भी बहुत सी फुटकर सेवाएँ सम्पन्न करती हैं, जैसे — श्रीद्योगिक फर्मों को विनियोग सम्बन्धी सलाह देना. श्रीद्योगिक कम्पनियों के ग्रंशों को खरीदना ग्रीर वेचना. ग्रीद्यो-गिक फर्मों के लिए विज्ञापन करना, इत्यादि।

भारत में ऐसी बैंक लगभग न होने के बराबर हैं, परन्तु जर्मनी धीर जापान में उनका चलन बहुत है। भारत में ध्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल (Industrial Finance Corporation) तथा राज्य औद्योगिक वित्त प्रमण्डल इसके प्रच्छे उदाहरए। हैं। कुछ देशों में मिश्रित बैंक पद्धित भी प्रचलित है। जर्मनी की ध्रौद्योगिक बैंक व्यापार बैंकों का भी कार्य करती हैं ग्रौर ग्रमेरिका में व्यापार बैंक ग्रौद्योगिक बैंक भी होती हैं।

इन बैंकों का प्रौद्योगिक विकास में भारी महत्व होता है, क्योंकि ये स्थिर यंत्र (Plant), विल्डिंग, मशीनरी ग्रादि की प्रतिभूतियों पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं। ये वैंक भी साधारणतया मिश्रित पूँ जी बैंक होती हैं और इनकी पूँ जी कई मदों से प्राप्त होती है:—प्रथम, ग्रंशों की विक्री से पूँ जी मिलती है—इन बैंकों की परिदत्त पूँ जी (Paid-up Capital) व्यापार बैंकों की ग्रपेक्षा ग्रधिक होती है। दूसरे, इनकी पूँ जी का दूसरा साधन दीर्घकालीन जमा होती है। तीसरे, ये बैंक बीमा कम्पनियों से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करती हैं। ग्रन्त में, ये बैंक ऋण-पत्र (Debentures) निकाल कर पूँ जी प्राप्त करती हैं।

(४) विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Banks)— इन बैंकों का मुख्य कार्य विदेशी बिलों की खरीद और बेच द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन को मुलभाना होता है। स्मरण रहे कि प्रत्येक देश के व्यापारी अपने ही देश के चलन में भुगतान लेना पसन्द करते हैं, इसलिए किसी ऐसी संस्था की आवश्यकता पड़ती है जो एक देश की मुद्रा को दूसरे देशों की मुद्राओं में बदलने का कार्य करती हो। इन बैंकों को विभिन्न देशों की मुद्रायें रखनी पड़ती हैं और इनकी शाखायें भी देश-विदेश में फैली रहती हैं। इन वैंकों को कभी-कभी केवल 'विनिमय बैंक' भी कहा गया है।

हन वेंकों की कार्य-विधि यह होती है कि विनिमय बेंक की एक देश की शाखा बिल खरीदती है और कीमत चुकाती है और फिर दूसरे देश की शाखा इसी बिल को बेचती है और घन वसूल करती है। इस प्रकार विना घन का हस्तान्तरएा किये अन्तर्हाण्य लेन-देन सुगमतापूर्वक वैसे ही तय हो जाता है। ये , बेंक विदेशी व्यापार की सहायता करके उसके प्रोत्साहन में भी सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त इन बेंकों के अन्य कार्य अन्तर्राष्ट्रीय ऋएगें का भुगतान, प्रतिभूतियों का आयात-निर्यात, अग्रिम या भावी विनिमय व्यापार (Forward Exchange) भी हैं। ये बेंक विनिमय दरों के आकस्मिक उच्चावचनों को रोक कर आयात-निर्यात व्यापारियों को अनिश्चितता तथा उससे सम्बन्धित जोखिम से बचा देती हैं। इन कार्यों के साथ-साथ विनिमय बेंक बेंकों के और भी लगभग सभी प्रकार के सामान्य कार्य सम्पन्न करती हैं।

मारत में पूर्णतया भारतीय विनिमय बैंक कोई भी नहीं है। श्रविकाँश विनिमय बैंक विदेशी बैंकों की ही शाखायें हैं, परन्तु श्राधुनिक काल में कुछ ऐसी प्रवृत्ति देखने को श्राती है कि एक ही बैंक एक ही साथ कई प्रकार की बैंकों के कार्य करती

है। व्यापार बैंक बिदेशी विनिमय व्यवसाय करती हैं और विनिमय बैंक व्यापार बैंकों के भी कार्य करती हैं। इस कारण एक बैंक को उसके प्रधान कार्य के अनुसार ही व्यापार अथवा विनिमय बैंक का नाम दिया जाता है। यदि किसी बैंक का मुख्य कार्य विदेशी विनिमय व्यवसाय है तो उसे विनिमय बैंक का नाम दिया जाता है।

(५) कृषक वैंक (Agricultural Banks)—कृषि की समस्याएँ व्यापार तथा निर्माण उद्योगों से भिन्न होती हैं। कृपक व्यापारियों तया उद्योगपितयों की भाँति ऐसी प्रतिभूतियाँ नहीं दे सकते हैं जो व्यापार तथा खाँद्योगिक वैंकों को मान्य हों। इसके अतिरिक्त कृषि की वित्तीय आवश्यकताएँ दो प्रकार की होती हैं:—बीज, खाद तथा फसलों की बिक्री के लिए अल्पकालीन ऋगों की आवश्यकता होती है, परन्तु भूमि में स्थायी सुधार के लिये दीर्घकालीन ऋगों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे भी कृषि में सामयिक वित्त (Seasonal Finance) का काफी महत्त्व होता है। इसी कारण कृषि की वित्तीय व्यवस्था के लिये अलग प्रकार की ही वैंकों की आवश्यकता पड़ती है।

कृषि सम्बन्धी वित्तीय ग्रावश्यकता की पूर्ति के लिए दो प्रकार की बैंक होती हैं :—एक तो, सहकारी बैंक, जो साधारणतया ग्रत्पकालीन ऋण देती हैं ग्रौर दूसरी, भू-प्राधि ग्रथवा भूमि-बन्धक बैंक (Land Mortgage Banks), जो दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करती हैं। भारत में दोनों ही प्रकार की बेंक हैं, परन्तु सहकारी बेंकों का चलन ग्रधिक है ग्रौर ये बेंक बहुत बार दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान कर देती है।

(६) सहकारी बैंक (Co-operative Banks)—भारत में दस या दस से अधिक व्यक्ति मिलकर एक सहकारी साख समिति खोल सकते हैं और उसका पंजीयन (Registration) भी करा सकते हैं। ऐसी समितियाँ केन्द्रीय बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों से सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इनका उद्देश्य पारस्परिक साख का निर्माण करना तथा कृषकों को कम ब्याज पर अल्पकालीन ऋगों का प्रदान करना होता है। सहकारी साख समितियों में उतरदायित्त्व सीमित अथवा असीमित हो सकता है, परन्तु भारत में ग्रामीण साख समितियों का संगठन साधारणतया असीमित उत्तर-दायित्त्व (Unlimited Liability) आधार पर ही किया जाता है। इन सिमितियों पर राज्य सहकारी संस्थाओं का तामान्य निरीक्षण रहता है।

एक साधारण सहकारी बैंक अथवा साख सिमिति की पूँजी प्रवेश शुल्क (Entrance Fee), अंशों की बिक्री, जनता तथा सदस्यों द्वारा जमा किये हुए निक्षेपों, सुरक्षित कोषों, सरकारी सहायता और केन्द्रीय तथा राज्य सहकारी वैंकों से लिये हुये ऋगों से प्राप्त होती हैं। कुछ काल से भारत में सहकारी धान्दोलन के रूप में परिवर्तन किया जा रहा है और सहकारी साख सिमितियों के स्थान पर बहुमुखी सिमितियाँ (Multi-purpose Societies) खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है,

जो साख सुविधा के ब्रितिरिक्त एक ही साथ और भी अनेक प्रकार की सेवाएँ सम्पन्न करने का प्रयत्न करती हैं।

(७) भूमि-वन्यक बैंक (Land-Mortgage Banks)—ये वैंक कृषि उद्योग को दीर्घकालीन ऋगा. अर्थात ५ से लेकर २० वर्ष के काल के लिये ऋगा प्रदान करती हैं। ये ऋगा खेतों में स्थायी सुधार के लिए दिए जाते हैं और भूमि को गिरवी रख कर प्राप्त किये जाते हैं। खेतों में कुँए खुदवाने, मवेशी खरीदने, बाढ़ को रोकने का प्रवन्ध करने आदि के सम्बन्ध में ये ऋगा लिए जाते हैं। इनका भुगतान बहुधा किश्तों में किया जाता है, जो एक निश्चित समय के पश्चात् आरम्भ होती हैं।

कुछ समय से भारत में भू-प्राधि बैंकों को खोलने का काफी प्रयत्न किया जा रहा है ग्रौर साधारएतया ऐसी बैंकों को मिश्रित पूँजी बैंकों के रूप में खोला जा रहा है। कभी-कभी भू-प्राधि बैंक सहकारी भूमि-बंधक बेंक भी होते हैं ग्रौर कभी-कभी उनको ग्राभास-सहकारी भू-प्राधि बैंक (Quasi-Cooperative Land Mortgage Bank) के रूप में खोला जाता है। ऐसी बैंकों के सदस्य ऋएा लेने वाले तथा देने वाले दोनों हो सकते हैं, लेकिन इनमें उत्तरदायित्व सीमित होता है। एक श्रच्छी बैंक प्रशाली की श्रावश्यक विशेषताएँ—

किसी भी देश के ग्राधिक जीवन में बैंकों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। बैंकों से समाज को ग्रनेक लाभ होते हैं: -(i) ये देश में दचत को प्रोत्साहन देकर पूँजी के निर्माण में सह यक होती है। (ii) ये बचत करने वालों तथा निनियोगियों के बीच मध्यस्य का कार्य करके दोनों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कर देती हैं। (iii) साख का निर्माण श्रधिकतर इन्हीं के द्वारा किया जाता है, इस कारण इनके द्वारा साख पद्धति के सभी लाभ प्राप्त हो जाते है। श्राधुनिक युग में बिना बैंकिंग का समुचित विकास किये श्रौद्योगिक तथा वािणाज्यिक उन्नति की ग्राशा निमूष्त है।

परन्तु अपनी सेवाओं का सरलतापूर्वक प्रतिपादन करने के लिए बैंक प्रथा में कुछ विशेषतात्रों का होना आवश्यक होता है। ये विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं:—

- (१) वैंक प्रणाली ऐसी हो कि वह समाज के सभी वर्गों की आवश्यकता पूरी करें। इसका अर्थ यह होगा कि बैंक प्रणाली देश की आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल हो। एक कृषि प्रधान देश में सहकारी तथा भू-प्राधि बैंकों की प्रधानता रहेगी और एक व्यवसायिक देश में व्यापार बैंकों की। इसी प्रकार विदेशी व्यापार के लिये विनिमय बेंकों का होना आवश्यक होता है।
- (२) वचत को संग्रह करने में सुविधा—यह म्रावश्यक है कि बैंकिंग प्रणाली का इस प्रकार संगठन किया जाय जिससे कि समाज के घनी तथा निधंन दोनों ही वर्गों की वचत को एकत्रित किया जा सके।
  - (३) साख पर समुचित नियन्त्रण्—क्योंकि साख का म्रत्यधिक निर्माण

देश के लिए घातक होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे िशा साख-मुद्रा की जिससे बैंक प्रसालि पर समुचित नियन्त्रसा रखा जा सके और वह स्यकतानुसार साख की मात्रा को घटाती-बढ़ाती रहे। कार्य-विधि

(४) समन्वित वै किंग प्रगाली—यह ग्रावश्यक है कि वैकिंग प्रस्हिर भी विभिन्न ग्रङ्कों के बीच समुचित समन्वय ग्रथवा समचय (Co-ordination) में को रहे। इससे एक ग्रोर तो सेवाग्रों की दोबारगी (Duplication) नहीं होने पाये ग्राये दूसरी ग्रोर ग्रनाथिक प्रतियोगिता समात हो जायगी। इसके ग्रतिरिक्त वैकिंग संगठन के पूरे-पूरे लाभ भी उसी दशा में प्राप्त होते हैं जबिक वैंकर सेवाग्रों का विकास समचयपुक्त (Co-ordinated) होता है।

#### **QUESTIONS**

 Explain fully the difference between Commercial and Central Banking and state the functions of a Commercial Bank,

(Sagar, B, A., 1958)

केन्द्रीय बैंक श्रीर व्यापार वैंक के कार्यों का श्रन्तर सममाइये ?

(Sagar, B. A, 1957)

- 3. Explain the difference between the Unit and Branch banking. Which one will you prefer and why?
- 4. Explain clearly the various types of modern banking institutions.

# र्ग्यस्याय १७ केन्द्रीय बैंड्सिंग (Central Banking)

#### मूामका--

केन्द्रीय बैंक से हमारा ग्रिमिप्रायः देश की उस बैंक से होता है जो प्रधानतया देश में बैंकिंग तथा साख पर नियन्त्रण रखती है। ऐसी बैंक को हम केन्द्रीय बैंक इस कारण कहते हैं कि इसका देश की मुद्रा भीर साख व्यवस्था में केन्द्रीय स्थान होता है। इस बैंक को कुछ ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जो अन्य बैंकों को या तो प्राप्त ही नहीं होते या बहुत ही कम ग्रंश तक उपलब्ध होते हैं। इन अधिकारों के कारण केन्द्रीय बैंक देश की मौद्रिक और साख नीति को अधिक ग्रंश तक प्रभावित कर सकती है। केन्द्रीय बैंक की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं:—"यह वह बैंक है जो देश की साख और मौद्रिक नीति का जन-साधारण के कल्याण के लिए प्रवन्ध करती है।" केन्द्रीय बैंक की और भी परिभाषाएँ देखने में आती हैं। लगभग सभी परिभाषाओं में केन्द्रीय बैंक के कार्यों का उल्लेख करने का प्रयत्न किया गया है। प्रमुख परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं:—

# परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं :— प्रमुख परिभाषाएँ —

- (१) ''केन्द्रीय बैंक वह संस्था है जो देश में जन-साधारण के हितों को ध्यान में रखकर मुद्रा और साख के बीच सम्बन्ध स्थापित करती है, देश के हित में मुद्रा और साख पर नियन्त्रण रखती है और इस प्रकार देशो और विदेशो कीमतों में स्थिरता स्थापित करती है और बैंकिंग तथा बैंकिंग व्यवस्था का विकास तथा संगठन करती है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक वह संस्था है जो देश के भीतर आर्थिक स्थिरता (Economic Stability) स्थापित करती है।"
- (२) ''केन्द्रीय वेंक वह संस्था है जो अन्य बैंकों तथा साख संस्थाओं की मुद्रा और साख सम्बन्धो आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बैंकों को वेंक होती है, सरकारी बैंक का कार्य करती है, राष्ट्र के आर्थिक हितों की रक्षा करती है और देश की मुद्रा और साख प्रगालियों का इस प्रकार नियन्त्रग रखती है कि देश के भीतर की मत-स्तर और देश की मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता (Stability) बनी रह सके, देश में बृत्तिहीनता (Unemployment) दूर हो और देशवासियों के वास्तविक आय-स्तर की वृद्धि हो। इस प्रकार, केन्द्रीय बैंक वह संस्था है जो केन्द्रीय बैंक के कार्य करे।"

(२) ''केन्द्रीय बैंक वह बैंक है जो देश में चलन तथा साख-मुद्रा की । ।त्रा का नियमन करे ।''\*

वर्तमान युग में ऐसी वैंक का विधान, उसके कार्य और उसकी कार्य-विधि भी साधारण वैंकों से भिन्न होते हैं। ऐसी वैंक के अपने सिंडान्त तथा व्यवहार भी गलग होते हैं। केन्द्रीय बैंक को इस योग्य बनाने के लिए कि वह अपने कार्यों को मुचित रूप में पूरा कर सके, सरकार द्वारा कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जैसे— त्र-मुद्रा निर्गम का एकाधिकार, सरकारी घन का संरक्षण, चलन निधि को रखना, त्य बैंकों की जमा को रखना और अन्य बैंकों को संकट काल में सहायता देना, त्यादि। इन विशेष अधिकारों के कारण केन्द्रीय बैंकिंग के सिद्धान्त एवं व्यवहार त्य बैंकों से अलग होते हैं और इसीलिए केन्द्रीय बैंकिंग का एक पृथक दिषय के प में अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

एक साधारणा व्यापार बैंक के विरुद्ध केन्द्रीय बैंक का कार्य देश की बैंकिंग ाणाली पर इस प्रकार नियन्त्रण रखना होता है कि राज्य की सामान्य मौद्रिक नीति हो सफल बनाया जा सके । इसका श्रभिप्राय यह होता है कि:-(i) केन्द्रीय वैंक हा उद्देश्य व्यापार की भाँति अपने स्वामियों अथवा अंशधारियों के लिए अधिकतम् ताभ कमाना नहीं होता है। ( ii ) केन्द्रीय वैंक के पास व्यापार वैंकों पर नियन्त्रएा एखने के कुछ उपाय श्रथवा साधन होते हैं। ( iii ) केन्द्रोय बैंक सदा ही राज्य के प्रादेशानसार कार्यं करती है। कुछ ऐसी परम्परा बन गई है कि सभी देशों में. चाहे ाहाँ की शासन प्रणाली का रूप कूछ भी क्यों न हो, सरकार कुछ इस प्रकार के नियम भ्रवश्य बनाती है जिनके द्वारा केन्द्रीय बैंक पर नियन्त्रण रखा जा सके । भ्रिधि-काँश दशाओं में तो केन्द्रीय बैंक एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में कार्य करती है, परन्तु जिन देशों में वह व्यक्तिगत ग्रंशधारियों की बैंक होती है वहाँ भी सरकार इसके प्रबन्ध में भाग लेती है, इसकी नीति का निर्धारण करती है ग्रीर इसके कार्यवाहन पर नियन्त्रण रखती है। ( iv ) केन्द्रीय बैंक का मुख्य कार्य मौद्रिक प्रणाली का संरक्षण करना होता है। इस उद्देश्य से ही उसे नोट निर्गम का एकाधिकार दिया जाता है ग्रीर ग्रन्य बेंकों पर इसका म्राधिपत्य स्थापित किया जाता है। ( v ) इसके म्रितिरिक्त केन्द्रीय बेंक सरकार तथा देश की अन्य बैंकों के बैंकर के रूप में भी कार्य करती है। केन्द्रीय वेंक की श्रावश्यकता-

(१) साख के निर्माण पर नियन्त्रण—वैंकों का एक महत्त्वपूर्ण कार्यं साख का निर्माण है और साख के इस निर्माण से समाज और राष्ट्र को काफी लाभ होता है, परन्तु ग्रपने लाभों को बढ़ाने के लिए बैंक साख के निर्माण को एक निश्चित सीमा से बाहर ले जा सकती है। ऐसी दशा में साख राष्ट्र की सेविका न रह कर उल्टा उसके लिए अभिशाप बन जाती है। इस कारण आवश्यकता इस बात की है कि देश के हितों को घ्यान में रखते हुए साख के निर्माण पर नियन्त्रण रखा जाय, जिससे उनकी निकासी एक सीमा के ही भीतर रहे, परन्तु प्रश्न यह उठता हैं कि बैंकिंग पर इस प्रकार का नियन्त्रए। कीन रखे ? प्रत्येक बैंक को भी अपनी सुरक्षा का घ्यान रखना पडता है, इसलिए वह स्वयं भी अपने कार्यवाहन को इस प्रकार नियन्त्रित करती है कि उसके पास नकद कोषों की कमी न होने पाये और संकट काल में सरलता से घन प्राप्त करके ग्राहकों की नकदी की माँग को पूरा करने में कठिनाई न हो। व्यवहार में लगभग सभी वेंक अपनी माँग देन (Demand Liabilities) का १५-२० प्रतिशत नकदी के रूप में रखती हैं। वास्तव में ग्रपने श्रनुभव द्वारा बैंक यह जान लेती है कि उसे कितना नकद कोष रखना चाहिए, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि नकद कोपों के रखने के सम्बन्ध में बैंक को पूरी-पूरी स्वतन्त्रता दे दी जाय। बात यह है कि अधिक लाभ कमाने के लिए बैंक अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। वेंक की ऐसी नीति से बेंक ग्रौर उसके ग्रंशधारियों की तो हानि होती है, परन्तु देश की सारी ग्रर्थव्यवस्था पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि किसी वाहरी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा साख का नियन्त्रण त्र्यावश्यक हो जाता है। यह संस्था कोई वैंक ही होनी चाहिए, क्योंकि उसी को जनता की साख सम्बन्धी आवश्यकता का ठीक-ठीक पता रहता है। इसके स्रतिरिक्त सास के नियन्त्रए। के लिए भारी योग्यता तथा तान्त्रिक क्षमता की म्रावश्यकता होती है, जो किसी एक व्यक्ति ग्रथवा सरवारी ग्रिधकारी को प्राप्त नहीं हो सकती है। इस कार्य के लिए देश की केन्द्रीय बैंक ही सबसे उपयक्त संस्था हो सकती है।

- (२) वैंकों की आर्थिक सहायता—यही नहीं, केन्द्रीय बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य वैंकों को अपने पास से आर्थिक सहायता भी देती है, जिससे कि संकट के काल में उन्हें डूबने से बचाया जा सके।
- (३) सरकार की मौद्रिक नीति को सफल बनाने में सहायता एक केन्द्रीय बैंक देश की बैंकिंग संस्थाओं पर इस प्रकार नियन्त्रण रखता है कि जिससे राज्य को अपनी मुद्रा-नीति कार्यान्वित करने में सुविधा होती है। एक केन्द्रीय बैंक के कठोर नियन्त्रण के कारण ही उसे अपनी नीति में सफलता मिलती है।

केन्द्रीय बैंकिंग की म्रावश्यकता यथार्थं में उसके कार्यों से सिद्ध होती है। सन् १६२० की नु सेल्स की अन्तर्राष्ट्रीय वित्त परिषद ने कहा था—"जिन देशों में केन्द्रीय वैद्ध नहीं हैं वहाँ शीघ्र ही ऐसी बैंक स्थापित की जायें।" ऐसा समभा गया था कि वित्तीय और मौद्रिक ग्रावार को सुदृढ़ बनाने के लिए यही ग्रावश्यक है। दूसरे महायुद्ध के पश्चात् संसार के सभी देशों में केन्द्रीय बैंकिंग के महत्त्व को समभा जाने लगा। सन् १६२६ में हिल्टन यङ्ग म्रायोग ने भारत में भी केन्द्रीय बैंक

की स्थापना का सुफाव दिया, यद्यपि ऐसी बैंक सन् १६३५ में ही स्थापित हो पाई थी। केन्द्रीय बैंक देश में पूँजी की गतिशीलता को भी बढ़ाती है।

केन्द्रीय वैंकिंग के सिद्धान्त (Central Banking Principles)—

केन्द्रीय बैङ्क तथा साधारण बैंकों की कार्य-पद्धित में बड़ा अन्तर होता है। बास्तव में केन्द्रीय बैंक एक अलग ही प्रकार की संस्था होती है, यद्यपि बहुत बार केन्द्रीय बैंक साधारण बैंकिंग सम्बन्धित कुछ प्रकार के कार्य को सम्पन्न कर सकती है। केन्द्रीय बैंकिंग के प्रमुख सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं:—

- (१) राष्ट्रीय कल्याण की भावना—एक साधारण वेंक मुख्यतया लाभ के लिए कार्य करती है, जबिक इसके विपरीत केन्द्रीय वेंक का प्रमुख उत्तर-दायित्व देश के आर्थिक और वित्तीय स्थायित्व की रत्ता करना होता है। डी॰ कौक के अनुसार—'केन्द्रीय बैंक का निर्देशक सिद्धान्त यह है कि वह केवल लोक हित और समस्त देश के कल्याण के लिए ही कार्य करे और लाभ को अपना प्रारम्भिक उद्देश्य न समभे।'' इसका यह अर्थ तो नहीं है कि केन्द्रीय बैंक लाभ नहीं कमाती है, परन्तु लाभ कमाना केवल एक गौण उद्देश्य होता है और राज्य ऐसी बेंक को अत्यधिक जोखिम वाले उपक्रमों में भाग लेने से रोकता है। इसका परिणाम यह होता है कि केन्द्रीय बैंक अधिक समभवारी से कार्य करती है और अन्य बेंकों से प्रतियोगिता नहीं करने पाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य देश की समस्त बैंकिंग प्रणाली की शोधनक्षमता बनाये रखना होता है। इसलिए अपने आदेयों को तरलतम् रूप में रखना इसके लिए अत्यन्त आवश्यक होता है।
- (२) साख का भण्डार—केन्द्रीय बैंक साख का भण्डार होती है। अन्य सभी बैंक तथा दूसरी वित्तीय संस्थाएँ इससे आवश्यकता के समय ऋण् की आशार्ये रख सकती है, यद्यपि केन्द्रीय बैंक भी ऋणों पर ब्याज लेती है, किन्तु स्वयं केन्द्रीय बैंक किसी से ऋण की ब्राशा नहीं कर सकती है।
- (३) मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता—केन्द्रीय बैंक को देश के मौद्रिक श्रीर वित्तीय जीवन में सिक्रिय (Active) भाग लेना चाहिए। जब भी देश की साख प्रणाली में कोई श्रुटि उत्पन्न होती है तो बैंक को उसे पूरा करने के लिए सिक्रिय उपाय करने होते हैं। इसके लिए केन्द्रीय बैंक के शस्त्र-भण्डार में श्रनेक शस्त्र होते हैं, जिनका विस्तृत वर्णन श्रागे किया जायगा।
- (४) कार्य संचालन के लिए विशेष व्यवस्थायें—अपने कार्यों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए केन्द्रीय बैंक के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएँ की जाती हैं। उदाहररास्वरूप, इसे नोट निर्गम का एकाधिकार दिया जाता है, यह सरकारी बैंकों की बैंक होती है और बैंकों की बैंक के रूप में भी कार्य करती है।

<sup>\* &</sup>quot;The guiding principle of a Central Bank int hat it should act only in the public interest and for the welfare of the country as a whole and without regard to profit as a primary consideration."—De Kock—Central Banking.

(५) राजनैतिक प्रभाव का अभाव—केन्द्रीय बैंक पर किसी भी राज-नीतिक दल का आधिपत्य नहीं रहना चाहिये | इस प्रकार किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव अथवा प्रभाव नहीं रहना चाहिए, ताकि यह देश और समाज के हित में निःसंकोच तथा स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर सके । किन्तु साथ ही केन्द्रीय बैंक और सरकार के बीच पूर्णतया सहयोग रहना चाहिए।

केन्द्रीय वैंक के स्वामित्व का प्रश्न (The Question of the Ownership of the Central Bank)—

बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि केन्द्रीय बैंक 'स्वतन्त्र' होनी चाहिये, परन्तु 'स्वतन्त्र' शब्द के निश्चित अर्थ समभने में किनाई होती है। यदि स्वतन्त्र होने का अर्थ यह है कि केन्द्रीय बैंक पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होना चाहिए तो यह अनुपयुक्त है, क्योंकि मौद्रिक इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है। केन्द्रीय बैंक पर किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण अवश्य रहता है, यद्यपि अलग-अलग देशों में तथा अलग-अलग कालों में नियन्त्रण के अंश में अन्तर रहा है। कुछ दशाओं में तो सरकार केवल इतना कर देती है कि चलन की कीमत को स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के वरावर घोषित कर देती है और मौद्रिक प्रणाली के प्रबन्ध का शेष कार्य बैंक पर छोड़ देती है, परन्तु कुछ दशाओं में सारा अधिकार सरकार के पास होता है और केन्द्रीय बैंक को सभी मामलों में सरकार की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। दोनों ही प्रकार के सरकारी नियन्त्रण के उदाहरण संसार में मिलते हैं।

केन्द्रीय बैंक के स्वामित्त्व का प्रश्न भी सरकारी नियन्त्ररा से ही सम्बन्धित है । सरकारी स्वामित्त्व भी एक प्रकार का सरकारी नियन्त्रए ही है । जिन देशों में केन्द्रीय बैंक की स्वतन्त्रता को महत्त्व दिया जाता है वहाँ उसको जन-साधारण अथवा व्यापार वैंकों के स्वामित्त्व में रखा जाता है। इसके विपरीत जिन देशों में सरकारी म्राघिपत्य को म्रधिक महत्त्व दिया जाता है वहाँ केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण को म्राव-श्यक बताया जाता है। १६ वीं शताब्दी में जब सबसे पहले केन्द्रीय बेंक की स्नावश्यकता म्रनुभव की गई तो इस बात पर जोर दिया गया था कि ऐसी बैंक की स्वतन्त्रता को वनाये रखना स्रावश्यक था। यह कहा गया था कि केन्द्रीय बैंक पर किसी भी प्रकार राज्य का नियन्त्रण नहीं होना चाहिए, अन्यया उसका राजनीतिक शोषण होगा और वह सरकार की वित्त-सम्बन्धी मनमानी नीति का साधन बन जायगी । इस व्यवस्था के श्रन्तर्गत केन्द्रीय बैंक की व्यक्तिगत ग्रंशवारियों की बैंक बनाया जाता था. परन्तु स्मरण रहे कि लगभग कभी भी केन्द्रीय बैंक को ग्रपने लाभों को इच्छानुसार बाँटने का ग्रधि-कार नहीं दिया जाता था। इन लाभों में राज्य का हिस्सा अवश्य रहता था। जो लोग केन्द्रीय वैंक के राष्ट्रीयकः ए। के समर्थक है उनका विचार है कि केन्द्रीय वैंक के संचा-लन के लिये राजकीय निर्देशन तथा नियन्त्रए। आवश्यक होता है और इसके लिए केन्द्रीय वेंक के राष्ट्रीयकरण से अच्छा उपाय कोई भी नहीं है । स्वामित्त्व के दृष्टिकोण् से केन्द्रीय वेंक सात ऋलग-ऋलग प्रकार की हो सकती हैं :—(i) उसकी कुल

पुँजी सरकारी हो सकती है, ( ii ) जन-साधारण प्रथवा साधारण व्यक्तिक धारियों की हो सकती है, (iii) व्यापार वैंकों द्वारा प्रसादित की जा सकती (iv) जन-साधारण तथा सरकार द्वारा मिलकर दी जा सकती है. (v) सरकी तथा व्यापार बैंकों की मिली-जुली पूँजी हो सकती है, ( vi ) सरकार, जन-साधारण तथा व्यापार बैंक तीनों द्वारा मिलकर उपलब्ध की जा सकती है, ग्रथवा ( vii ) जन साधारण तथा व्यापार बेंकों की सम्मिलित पूँजी हो सकती है। वर्तमान युग में बहुमत केन्द्रीय बेंक के राष्ट्रीयकरण के ही पक्ष में है। दूसरे महायुद्ध के पश्चात् वैंक भ्रॉफ इङ्गलैण्ड, बैंक भ्रॉफ फांस तथा रिजर्व वैंक भ्रॉफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। वैसे तो ऋलग-ऋलग देशों में केन्द्रीय वैंक का रूप ऋलग-ऋलग होता है, परन्त कुछ विशेषतायें ऐसी श्रवश्य हैं जो किसी न किसी श्रंश में लगभग सभी केन्द्रीय बैंकों में पाई जाती हैं। (i) ऐसी संस्थायें साधार एतया लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं की जाती हैं। उनका अधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को उन्नत करना होता है। ( ii ) इन वैंकों पर सरकारी नियन्त्रण तथा निरीक्षण काफी रहता है। (iii) ऐसी संस्थायें साधारएातया जनता के साथ प्रत्यक्ष व्यवसाय नहीं करती हैं। (iv) इन संस्थायों को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं जो अन्य किसी. भी बैंक को प्राप्त नहीं होते हैं। वैसे भी ये शक्तिशाली संस्यायें होती हैं। केन्द्रीय बैंक के कार्य (The Functions of the Central Bank)-

केन्द्रीय बैंक के कार्यों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं :—
(१) नोट निर्गम का एकाधिकार—ग्रारम्भ में नोटों की निकासी का भ्रिष्ठकार राज्य का ही एक विशेष भ्रष्ठकार समक्ता जाता था, परन्तु व्यापार बैंकों के

विकास के पश्चात् यह ध्रिषकार उन्हें सौंप दिया गया था। यह व्यवस्था भी बहुत सफल न रह सकी और ऐसा अनुभव किया गया कि राज्य तथा व्यापार बैंक दोनों ही इस कार्य के लिए अनुपदुक्त थे। धीरे-धीरे यह अधिकार केन्द्रीय बैंक को सौंप दिया गया, क्योंकि ऐसी आशा की गई थी कि यह बैंक इस कार्य को राष्ट्रीय हित के दृष्टि कोए से अधिक सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकेगी। लगभग सभी देशों में नोट निर्गम का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक के पास है। इसके मुख्य कारए। निम्न प्रकार हैं:—
( i ) नोट निर्गमन में अनुरूपता—प्रत्येक देश ने ऐसा अनुभव किया है

कि नोट निर्गम में अनुरूपता लाने तथा उस पर सरकारी नियन्त्रण् तथा निरीक्षण को हढ़ता के साथ बनाये रखने के लिए उसका एकाधिकार केन्द्रीय बैंक को ही देना ठीक था।

(ii) साख निर्माण पर नियन्त्रण —वर्तमान युग में व्यापर वैंकों द्वारा निकाली हुई साख-मुद्रा के प्रचलन के बढ़ जाने के कारण इस साख पर समुचित नियन्त्रण रखने की समस्या काफी महत्त्वपूर्ण हो गई है। इस सम्बन्ध में ऐसा अनुभव किया जाता है कि केन्द्रीय वैंक को नोट निर्गम का एकाधिकार देने से एक श्रंश तक नियन्त्रण की समस्या

सुलभ जाती है, क्योंकि साख-मुद्रा की प्रत्येक वृद्धि के लिए चलन की वृद्धि की ग्रावश्यकता पड़ती है। केन्द्रीय बैंक चलन की मात्रा निय-नित्रत करके साख-मुद्रा के विस्तार को सीमित कर सकती है। ग्रतः साख-मुद्रा पर नियन्त्रण रखने के लिए भी केन्द्रीय बैंक की ग्रावश्यकता पड़ती है।

- (iii) जनता का विश्वास ऐसा भी अनुभव किया गया है कि किसी ऐसी बैंक को नोट निर्गम का अधिकार देने से जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त है, नोटों के प्रति जनता के विश्वास को काफी ऊँचा रखा जा सकता है।
- (iv) राज्य को लाभ की प्राप्ति—नोट निर्गम एक लाभदागक व्यवसाय है। एक ही बैंक के पास नोट निर्गम का एकाधिकार रहने की दशा में राज्य को निर्गम लाभों को प्राप्त करने में भारी सुविधा रहती है, क्योंकि केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण अथवा उनके लाभों पर कर लगाकर सरकार के लिए इन लाभों को प्राप्त कर लेना सरल होता है।
- ( v ) आन्तरिक श्रीर बाह्य मूल्य में स्थिरता—नोट निर्गम के एकाधि-कार द्वारा केन्द्रीय बैंक को मुद्रा की श्रान्तरिक तथा बाह्य कीमत का स्थायत्व बनाये रखने में काफी सफलता मिलती है। इसका परिग्णाम यह होता है कि विदेशी विनिमय दर में उच्चावचन कम होते हैं श्रीर देश के भीतर भी कीमतों में परिवर्तन कम ही हो पाते हैं।
- (vi) मुद्रा-प्रगाली में लोच जब व्यापारिक बैंकों द्वारा नोटों का निर्गम किया जाता है, तो वे नोटों का निर्गम व्यापारिक आवश्यकता के अनुसार नहीं कर पाते, लेकिन केन्द्रीय बैंक ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसकी देश की व्यापारिक आवश्यकताओं से निकट जानकारी होती है। इससे मुद्रा प्रगाब्री में लोच आ जाती है।
- है। इससे मुद्रा प्रणाख्नी में लोच ग्रा जाती है।

  (२) सरकारी बैंकर यह केन्द्रीय बैंक का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य है।

  (i) केन्द्रीय बैंक सरकार का एजेन्ट तथा बैंकर के रूप में कार्य करता है—इस रूप में केन्द्रीय बैंक सरकारी कोणों का संरक्षण करती है ग्रीर विभिन्न सरकारी विभागों के खातों तथा हिसाबों को रखती है। सरकारी करों की राशि केन्द्रीय बैंक में ही जमा होती है ग्रीर ग्रावश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय बैंक सरकार की ग्रात्यक्रता मुद्राभी तथा प्रतिभृतियों को खरीदती ग्रीर बेचती भी है, सरकारी मुद्राभी तथा प्रतिभृतियों को खरीदती ग्रीर बेचती भी है, सरकारी मृद्राभी का प्रवन्ध करती है ग्रीर लगभग सभी ग्राधिक मामलों में
  - ( ii ) केन्द्रीय वैंक सरकार का ग्राधिक सलाहकार होता है—मौद्रिक

सरकारी अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है।

तथा बैंकिंग मामलों में सरकार केन्द्रीय वैंक से सलाह भी लेती है। सरकारी घन केन्द्रीय वैंक में ही जमा किया जाता है श्रौर सरकारी देनों का भुगतान भी वही करती है।

(३) बैंकों की बैंक— केन्द्रीय बैंक का देश की अन्य बैंकों से लगभग उसी प्रकार का सम्बन्ध होता है जैसा कि एक साधारण बैंक का अपने प्राहकों से होता है । विधान अथवा परम्परा के अनुसार सभी बैंकों को अपनी रोक निधि (Cash Reserves) का एक भाग केन्द्रीय बैंक में जमा करना पड़ता है। इससे कई महत्त्वपूर्ण लाभ होते हैं:—(') साख प्रणाली में लोच उत्पन्न हो जाती है और (ii) साख-मुद्रा के नियन्त्रण की समस्या सरल हो जाती है। (iii) इसके अतिरिक्त बैंकों की बैंक के रूप में केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देती है। (iv) उन्हें आवश्यक व्यवसायिक सलाह देती है तथा उनकी पारस्परिक लेन-देन का समायोजन भी करती है। ( $\nabla$ ) केन्द्रीय बैंक ही साधारणतया देश में निकासी गृह (Clearing House) खोलने का कार्य करती है।

बेंकों की बैंक के रूप के केन्द्रीय बेंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बेंकों को ऋण तथा ग्रियम प्रदान करना होता है। केन्द्रीय बेंक को ग्रम्तम म्हण्णदाता (Lender of last resort) कहा जाता है। जब किसी बैंक को ग्रम्य किसी भी सूत्र से ऋण प्राप्त नहीं होता है तो वह केन्द्रीय बेंक से सहायता ले सकती है। व्यापार बेंकों द्वारा भुनाये हुये बिलों को दुबारा भुनाकर ग्रथवा उपयुक्त स्वीकृत प्रतिस्तियों पर ऋण देकर केन्द्रीय बेंक संकट ग्रथवा ग्रावश्यकता के काल में बेंकों की इहुत सहायता कर सकती है। संकट के काल में तो बेंकिंग प्रणाली का जीवन ही केन्द्रीय बेंक पर निर्भर होता है। एक दूसरे दृष्टिकोण से भी केन्द्रीय बेंक सरकार ग्रथवा जन-साधारण को भी ऋण दे सकती है। खुले बाजार प्रतिभूतियां खरीद कर केन्द्रीय बेंक साख का विस्तार करती है ग्रीर ग्राधिक कठिनाई को बड़े ग्रंश तक दूर कर देती है।

- (४) राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय चलन संचय की संरक्षक स्वर्ण तथा सभी प्रकार के विदेशी विनिमय संचयों का संरक्षण केन्द्रीय बेंक ही करती है। यह केन्द्रीय बेंक का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि देशी चलन की बाह्य कीमत को बनाये रखना केन्द्रीय बेंक का ही कर्त्तंव्य होता है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए केन्द्रीय बेंक विदेशी मुद्राश्रों का संचय रखती है।
- (५) साल-मुद्रा का नियन्त्ररा मिघन्त्ररा ग्रंथिकांश ग्रंथिशास्त्री ग्रौर वैंकर साख-मुद्रा के नियन्त्ररा को ही केन्द्रीय वैंक का प्रधान कार्य मानते हैं। इस कार्य में केन्द्रीय वैंकिंग नीति सम्बन्धी लगभग सभी विषय सम्मिलित होते हैं। केन्द्रीय वैंक के लगभग सभी कार्यों का ग्रन्तिम उद्देश्य मुद्रा की मात्रा पर समुचित नियन्त्ररा रखना होता है ग्रीर इसके लिए साख नियन्त्ररा एक प्रारम्भिक ग्रावश्यकता है। वर्तमान ग्राधिक व्यव-

स्थाओं में साख मुद्रा महत्त्वपूर्ण सेवाएँ कर सकती है। ये सेवाएँ ग्रच्छी ग्रीर बुरी दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। यही कारण है कि ग्राधुनिक युग में साख नियन्त्रण की ग्रावश्यवता को सभी स्वीकार करते हैं। यद्यपि यह विषय विवाद-ग्रस्त है कि साख नियन्त्रण का सही उद्देश्य क्या होना चाहिए—इसके द्वारा देश में ग्रान्तरिक कीमतों की स्थिरता स्थापित की जाय ग्रथवा विनिमय दरों की स्थिरता—परन्तु साख नियन्त्रण के महत्त्व से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है। साख नियन्त्रण के कई उगय होते हैं, जैसे—वैंक दर ग्रथित केन्द्रीय वैंक की ब्याज की दर में परिवर्तन करना, केन्द्रीय वैंक द्वारा खुले बाजार व्यवसाय करना, वैङ्कों पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगाना इत्यादि। केन्द्रीय वैंक इनमें से पहले दो उपाय ही कर सकती है। इन उपायों का विस्तृत विवेचन ग्रागे किया जायगा।

- (६) स्लाहकारी कार्य—केन्द्रीय वैंक राज्य के ग्राधिक ग्रीर वित्तीय सलाहकार का भी कार्य करती है। वह सरकार को ग्राधिक तथा वित्तीय मामलों में भावश्यक सलाह देती है ग्रीर सरकार किसी भी उलकी हुई समस्या के सम्बन्ध में इससे विचार-परामर्श कर सकती है। इसके ग्रातिरिक्त मुद्रा, साख, विदेशी विनिमय तथा लोक ऋगु सम्बन्धी नियम साधारणतया केन्द्रीय बैंक की ही सिफारिश के ग्रनुसार बनाये जाते हैं। भारत में बैंकिंग विधान सम्बन्धी सलाह सदा ही रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत की जाती है। राजकीय ग्राथंप्रबन्ध में भी इसकी सलाह उपयोगी होती है।
- (७) सूचनाओं श्रीर श्राँकड़ों का एकत्रित करना—यह भी केन्द्रीय बैंक का एक लगभग श्रावश्यक कार्य ही बन गया है। मुद्रा, श्रविकोषण तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी श्रावश्यक श्राँकड़ें केन्द्रीय बैंक ही एकत्रित करती है। इन श्राँकड़ों की सहायता से देश की श्राधिक प्रगति का वेग जाना जा सकता है। विधान की श्रावश्यकता स्पष्ट हो जाती है श्रीर श्राधिक नियोजन के श्राधार को हढ़ किया जा सकता है। इन श्राँकड़ों की सहायता से विभिन्न देशों की स्थित का भी तुलनात्मक श्रनुमान लगाया जा सकता है।

#### निष्कर्ष-

उपरोक्त सभी कार्य लगभग सभी केन्द्रीय बेंकों द्वारा किये जाते हैं, परन्तु इन कार्यों की गएाना कर देने से यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि इससे केन्द्रीय बैंक के सभी कार्य समाप्त हो जाते हैं। केन्द्रीय बैंक के कार्यों का निरन्तर विस्तार हो रहा है और विभिन्न प्रर्थशास्त्री इस सम्बन्ध में सहमत नहीं हैं कि केन्द्रीय बैंक के कार्यों की सीमा किस स्थान पर निर्धारित कर दी जाय। प्री० स्प्रेग (Sprague) का मत है कि—"केन्द्रीय बैंकों के विशेष कार्यों का उल्लेख तीन भागों में किया जा सकता है। वे सरकार के ग्राधिक ग्रभिकर्त्ता का कार्य करती हैं, नोट निर्गम के एकाधिकार के कारए। उनका चलन पर विस्तृत नियन्त्रए। रहता है ग्रौर ग्रन्त में, क्योंकि इनके पास

म्रत्य बेंकों की निधि का काफी बड़ा भाग रहता है, वे समस्त साख-कलेवर के आधार के लिए प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी होती हैं। अन्तिम कार्य केन्द्रीय बेंक का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य होता है।" <sup>9</sup>

यह विषय विवाद-अस्त है कि केन्द्रीय वैंक का सबसे आवश्यक कार्य क्या है। हाटरे (Hawtrey) का विचार है। कि केन्द्रीय वैंक मुस्यतया अन्तिम ऋरण-दाता होती है। बेरा स्मिथ (Vera Smith) ने नोट निर्गमन के एकाधिकार को अधिक महत्त्व दिया है, शॉ (Shaw) का विचार है कि साख नियन्त्रण ही केन्द्रीय बेंक का एक मात्र वास्तविक, किन्तु-पर्याप्त कार्य है। किश और एलिकिनस् ने मौदिक मान के स्थायित्त्व को बनाये रखना ही केन्द्रीय बेंक का आवश्यक कार्य बताया है। किन्तु किसी एक कार्य को केन्द्रीय बेंक का आवश्यक कार्य कहना शायद उपयुक्त नहीं है। डी कौक (De Kock) ने निम्न आउ कार्यों को केन्द्रीय वैंकिंग कार्य बताया है—

- (१) पत्र-मुद्रा का निर्गम, जिसका इसे पूर्ण भ्रथवा श्रांशिक एकाधिकार प्राप्त होता है।
- (२) राज्य के बेंकिंग तथा ग्रभिकर्ता सेवाएँ सम्पन्न करना,
- (३) व्यापार बैंकों के नकद कोषों का संरक्षरा,
- (४) राष्ट्र की घातु-निधि का संरक्षण,
- (प्र) विनिमय बिलों, कोषागार विपत्रों तथा ग्रन्य उपयुक्त विपत्रों का फिर से भुनाना,

ग्रन्तिम ऋगादाता का उत्तरदायित्त्व स्वीकार करना, विभिन्न बेंकों की पारस्परिक लेन-देन का निबटाना, ग्रौर व्यवसायिक ग्रावश्यकताग्रों तथा राज्य द्वारा घोषित मौद्रिक मान की स्थिरता को ध्यान में रख कर साख-मुद्रा प्रर नियन्त्रण रखना।

सन् १९२६ के भारतीय चलन- श्रीर वित्त श्रायोग के सम्मुख बैंक श्रॉफ इङ्गलैंड के गवर्नर ने केन्द्रीय बैंक के निम्न कार्यों का वर्णन किया था:—"इसे

d. "The special functions of the Central Banks may be grouped under three heads: They serve as fiscal agents of Governments; they have large powers of control over currency through the more or less complete monopoly of note issue; and finally, since they hold a large part of the reserves of other banks, they are directly, responsible for the foundation of the entire structure of credit. This last is by far the most important function of the Central Bank."—Sprague.

<sup>2, &</sup>quot;.....the one true, but at the same time all—sufficing function of a central bank."—Shaw.

<sup>3.</sup> Kisch and Elkins: Central Banks, p. 74.

<sup>4.</sup> De Kock: Central Banking, p. 15.

नोट निर्गम का एकाधिकार होना चाहिए, विधि-प्राह्म मुद्रा की निर्गम तथा उसके प्रचलन से हटाने का एकमात्र सूत्र यही होना चाहिए। सरकार की सभी शेषें (Balances) तथा देश की ग्रन्य वैंकों ग्रौर उनकी शाखाग्रों की सभी शेषें इसी के पास रहनी चाहिए। यह एक ऐसी ग्रभिकर्त्ता का कार्य करे जिसके द्वारा देश के ग्रान्तिक ग्रौर विदेशी ग्राधिक कार्य सम्पन्न किए जार्य। केन्द्रीय वेंक का यह भी कर्त्व्य होना चाहिये कि देश के चलन की ग्रान्तिक ग्रौर बाह्म कीमत की स्थिरता को यथा-सम्भव बनाये रखने हुये चलन प्रणाली में उपयुक्त विस्तार तथा संकुचन करे। ग्रावश्यकता के समय प्रथवा संकट के काल में यह ऋण का ग्रन्तिम साधन होनी चाहिये, जो कि स्वीकृत विलों को दुबारा भुनवाकर ग्रग्निम के रूप में ग्रथवा सरकारी हुण्डियों की जमानत पर मिल सके

# केन्द्रीय बैंक <u>श्रीर मौद्रिक नीति</u> (साख-नियन्त्रण)

#### (Central Bank and the Monetary Policy)

मौद्रिक नीति का अर्थं एक पिछले अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है। कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह बहुवा आवश्यक समभा जाता है कि देश में चलन और साख-मुद्रा की कुल मात्रा का आवश्यकतानुसार विस्तार और संकुचन किया जाय। वर्तमान युग में तो इस बात का महत्त्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आधुनिक सरकारें वित्तीय और मौद्रिक विषयों के नियन्त्रण द्वारा ही आर्थिक और वाणिज्यिक नीतियों को फलीभूत करने का प्रयत्न करती हैं। इस सम्बन्ध में चलन की मात्रा पर नियन्त्रण रखना अपेक्षतन सरल होता है, क्योंकि अधिकाँश चलन पत्र-मुद्रा के रूप में होता है, जिसके निर्गमन का एकाधिकार केन्द्रीय बेंक के पास रहता है। प्रमुख समस्या साख के नियन्त्रण की होती है, क्योंकि साख का निर्माण अनेक बेंकों

<sup>\* &</sup>quot;It should have the sole right of note-issue, it should be the channel, and the only channel, for the output and intake of legal-tender currency. It should be the holder of all the Government balances, the holder of all the reserves of other banks and the branches of banks in the country. It should be the agent, so to speak, through which the financial operations at home and abroad of the Government would be performed. It would further be the duty of the Central Bank to effect, as far as it could, suitable contraction and suitable expansion, in addition to aiming at general stability, and to maintain that stability within as well as without. When necessary it would be the ultimate source from which necessary credit might be obtained in the form of rediscounting of approved bills or advances on approved short securities or Gevernment paper."—Governor, Bank of England—Vide Report of the Royal Commission on Indian Currency and Finance, 1926.

द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति के सम्बन्ध में केन्द्रीय वैंक का प्रमुख कार्य साख के विस्तार ग्रीर संकुचन को नियन्त्रित करने से ही सम्बन्धित होता है। घीरे-घीरे इस दिशा में केन्द्रीय बैंक के कार्य का काफी विकास हुन्ना है। यहाँ तक कि वर्तमान केन्द्रीय बैंक सारे मुद्रा-बानार के संगठन, विकास ग्रीर नियन्त्रण का भार ग्रपने ऊपर ले लेती है।

### साख नियन्त्र ग् के उद्देश्य (Objects of Credit Control)—

यहाँ पर इस प्रश्न का उठना भी स्वभाविक ही है कि साख नियन्त्रण क्यों किया जाय। निश्चय है कि साख नियन्त्रण का अभिप्राय देश की व्यानार, वाणिज्य तथा जन-साधारण सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार साख की मात्रा को घटाने-बढ़ाने से होता है। कारण यह है कि यदि मुद्रा की मात्रा का उसकी आवश्यकता के साथ समायोजन नहीं किया जाता है तो समाज को मुद्रा-प्रसार अथवा मुद्रा-संकुचन के कहों को भोगना पड़ता है। साख नियन्त्रण के उद्देश्यों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं, अर्थात् ऋणात्मक उद्देश्य तथा धनात्मक उद्देश्य (Negative and Positive Objects)। प्रथम प्रकार के उद्देशों में आधिक जीवन की अस्थिरता को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है, जबिक दूसरी प्रकार के उद्देशों में किसी निर्धारित लच्च की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है। ऋणात्मक उद्देश्यों में से अधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:—

- (१) मुद्रा-प्रसार श्रथवा मुद्रा-संकुचन की स्थिति को सुधारना—यित किसी कारण से देश में मुद्रा-प्रसार श्रथवा मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो साख की मात्रा का संकुचन श्रथवा विस्तार करके सामान्यता स्थापित की जा सकती है। साख की मात्रा घटाने से कीमतें गिरती हैं श्रौर उत्पादन की वृद्धि का क्रम क्क जाता है। इसके विपरीत साख की मात्रा के बढ़ने से मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कीमतें ऊपर उठती हैं श्रौर उत्पादन तथा रोजगार का विकास होता है।
- (२) विदेशी विनिमय दरों के पतन स्रथवा उठान को रोकना—व्यापाराशेष के परिवर्तनों, सट्टे बाजार की कार्यवाहियों स्रथवा स्रन्य कारगों से विदेशी विनिमय दरों में स्रधिक उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। विनिमय दर के इन परिवर्तनों का देश की स्रान्तरिक सर्थव्यवस्था स्रौर देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन परिवर्तनों से देश की सर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए साख के विस्तार पर नियन्त्रगा रखना स्रावश्यक हो सकता है। विदेशी विनिमय की पूर्ति का उसकी मांग से समायोजन करने के लिए उसकी मात्रा का नियमन किया जाता है।
- (३) बेरोजगारी की वृद्धि ग्रौर उत्पादन के पतन को रोकना-ग्रवसाद के कारण ग्रथवा ग्रन्य कारणों से देश में उत्पादन घट सकता है। उत्पादन के घटने के साथ-साथ रोजगार सम्बन्धी स्थिति विगड़ जाती है। उद्योग ग्रौर व्यवसायों के बन्द हो जाने के कारण श्रमिक ग्रधिक संख्या में बेकार होने लगते हैं। ऐसे काल में

साख का विस्तार कीमतों श्रौर उत्पादन के पतन को रोक कर बेरोजगारी को बढ़ने से रोक सकता है।

#### धनात्मक उद्देश्य-

71400

इस प्रकार के उद्देश्यों में निम्न विशेषतया महत्त्वपूर्ण हैं:--

- (१) देश में कीमत-स्तर में स्थायित्व स्थापित करना (Stability of the Internal Price-level)—कीमत-स्तर के ग्रत्यिक परिवर्तन बहुवा ग्रान्तरिक ग्रथंव्यवस्था के समुचित विकास में वाधक होते हैं। वे ग्राधिक जीवन में ग्रानिश्चितता उत्पन्न कर देते हैं। लगभग प्रत्येक ग्राधुनिक सरकार इस बात का प्रयत्न करती है कि कीमतों में यथासम्भव कम से कम परिवर्तन हों। ग्रनुभव बताता है कि एक उपयुक्त साख नीति द्वारा ऐसे परिवर्तनों को न्यूनतम किया जा सकता है ग्रीर इस प्रकार देश के ग्राधिक विकास के लिए उपयुक्त दशाएँ उत्पन्न की जा सकती हैं।
- (२) विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्त्व लाना (Stability of Exchange Rates)—साख नियन्त्रण का दूसरा उद्देश्य विनिमय दरों में स्थिरता लाना हो सकता है। विदेशी विनिमय दरों के परिवर्तन भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता उत्पन्न करके उसके विकास को रोक देते हैं। साख की मात्रा के नियमन द्वारा विनिमय दरों की स्थिरता स्थापित करने का अच्छा अवसर मिलता है। यह विषय विवादग्रस्त है कि देश की सरकार को विनिमय दरों की स्थिरता स्थापित करने पर अधिक व्यान देना चाहिए अथवा आन्तरिक कीमत-स्तर के स्थायित्व पर। इस प्रश्न का उत्तर कठिन है। आज के संसार में अधिकांश देश आन्तरिक कीमतों की स्थिरता को अधिक महत्त्वपूर्ण समक्षते हैं, यद्यपि उन देशों के लिए जिनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतया विदेशी व्यापार पर निर्भर होती है, विनिमय दरों की स्थिरता अधिक महत्त्वपूर्ण होती है।
- (३) रोजगार श्रौर उत्पादन में स्थायित्व लाना (Stability of Production and Employment)—देश में उत्पादन की मात्रा श्रौर रोजगार के ग्रंश के परिवतन भी साधारणतया श्रच्छे नहीं समभे जाते हैं। मन्दी श्रौर तेजी के निरन्तर श्रोते रहने से समाज को ग्रत्यधिक कष्ट होता है। साख के विस्तार श्रौर संकुचन द्वारा रोजगार श्रौर उत्पादन के उच्चावचनों को रोका जा सकता है।
- (४) म्रार्थिक नियोजन की सफलता (Success of Economic Planning)—देश में म्रार्थिक नियोजन की सफलता के लिए भी उपयुक्त सास नीति म्रावश्यक होती है। बहुवा नियोजन की सफलता के लिए मुद्रा की मात्रा का विस्तार तथा होनार्थ-प्रवन्धन (Deficit financing) म्रावश्यक होते हैं। वैसे भी एक निरन्तर किन्तु घीरे-घीरे ऊपर उठता हुमा कीमत-स्तर उत्पादन मौर रोजगार के विकास में, जो म्रायिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं, सहायक होता है।

(१) युद्ध का तयारा तथा दश का रक्षा (Preparation for War and the Defence of the Country)—साख नियन्त्रए का उद्देश्य मुद्रा की मात्रा की वृद्धि द्वारा देश को युद्ध के लिए तैयार करना अथवा गत्रुओं से देश की रक्षा करना हो सकता है। आधुनिक युद्ध इतने मेंहगे होते हैं कि बिना साख और मुद्रा के विकास के कोई भी देश उनका अर्थ प्रवन्ध नहीं कर सकता है। दूसरे महायुद्ध के काल में संसार के सभी देशों ने साख के विस्तार को युद्ध की तैयारी का एक महत्त्व-पूर्ण साधन बनाया था।

## साख नियन्त्रण की रीतियाँ (Methods of Credit Control)

केन्द्रीय बैंक का एक महत्त्वपूर्ण कार्य देश में मुद्रा भ्रौर साख के विस्तार पर नियन्त्रण रखना होता है, जिससे कि सरकार की मौद्रिक नीति को सफल बनाया जा सके। इसके लिए कई प्रकार के उपाय किये जाते हैं। कुछ उपाय तो सीधे सरकार द्वारा किये जाते हैं भौर कुछ केन्द्रीय बैंक द्वारा, परन्तु सभी प्रकार के उपायों को केन्द्रीय बैंक द्वारा ही कार्य-रूप दिया जाता है। प्रमुख उपाय वैंक दर भौर खुले वाजार व्यवसाय हैं, यद्यपि इनके श्रतिरिक्त और भी बहुत सी रीतियों से इस कार्य को सम्पन्न किया जाता है। इस प्रकार के अलग-अलग उपायों से निश्चित तथा सप्रभाविक परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुधा उनका सामूहिक रूप में भी उपयोग किया जाता है। विशेषतया भ्राधुनिक सरकारें तो किसी एक उपाय पर कभी भी निर्भर रहने का प्रयत्न नहीं करती हैं। श्रव हम इन सब उपायों की सविस्तार जाँच करेंगे:—

## ( श्र ) वैङ्क दर <u>नीति</u> (Bank Rate Policy)

## बैङ्कर की नीति का अर्थ व इसका प्रभाव-

बैद्ध दर से हमारा श्राभिप्राय व्याज की उस न्यूनतम दर से होता है जिस पर देश की केन्द्रीय बैंक श्रन्छी श्रे शी के बिलों को फिर से मुनाने (Rediscounting) श्रथवा स्वीकृत प्रतिभृतियों पर ऋण या श्रिम देने का तैयार रहती है। दूसरे शब्दों में, यह केन्द्रीय बैंक द्वारा निश्चित व्याज की दर होती है। इक्ष्णेंड में बैद्ध दर का श्राश्य सरकार द्वारा प्रकाशित उस दर से होता है जिस पर बैद्ध श्रांक इद्धलैंड एक विशेष प्रकार के तीन मासीय बिलों को भुनाने को तैयार रहती है। इस सम्बन्ध में बैद्ध दर तथा 'बाजार दर' (Market Rate) के श्रन्तर को समम लेना श्रावश्यक है। वाजार दर से हमारा श्राव्य बाजार में प्रचलित व्याज की दर श्रांत व्याज की उस दर से होता है जिस पर सिमालित पूँ जी बैंक, डिस्काउन्ट ग्रह श्रादि स्वीकृत विनिमय दिलों को भुनाते हैं। परन्तु बैंक दर तो केन्द्रीय बैंक की डिस्काउन्ट दर होती है। इसका श्रर्थ यह नहीं है कि बैंक दर तथा बाजार दर में

कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है। यह अवश्य सही है कि केन्द्रीय बैंक साधारणतया बिलों को भुनाने का कार्य नहीं करती है और बैंक दर ब्याज की बाजार दर से साधारणतया ऊँची रहती है। केन्द्रीय बैंक से ऋण लेने का प्रश्न तभी उठता है जबिक ऋण प्राप्ति के अन्य साधन समाप्त हो चुकते हैं। एक प्रकार बैंक दर एक दण्ड के रूप में होती है। यदि कोई बैंक अपनी साख का अत्यिधिक विस्तार कर देती है तो उसे ऊँचे ब्याज पर केन्द्रीय बैंक से ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि वाजार दर भी ऊपर उठकर बैंक दर के बराबर हो जाती है, परन्तु सब कुछ होते हुए भी बैंक दर ब्याज की बाजार दर से सम्बन्धित होती है। जिन देशों में केन्द्रीय बैंक की व्याज की दर महत्त्वपूर्ण होती है वहाँ ब्याज की बाजारी दर भी बैंक दर के ही अनुसार बदलती रहती है।

वैंक दर नीति का संचित्र इतिहास—

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम यह कह सकते हैं कि सन् १९१४ से पूर्व स्वर्ण-मान प्रशाली के अन्तर्गत वेंक दर केन्द्रीय वैंक के साख नियन्त्रशा का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रस्त्र होती थी। ग्रन्य जो भी उराय किए जाते थे वे बैंक दर नीति के सहायक प्रथवा गौए। के रूप में ही काम में लाये जाते थे। प्रथम महायुद्ध के काल में सरकार ने बैंक दर नीति का उपयोग वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा तथा साख-विस्तार को सम्पन्न करने के उद्देश्य से किया ग्रौर युद्ध के पश्चात् भी यही प्रवृत्ति बनी रही। सन् १६२५ में स्वर्णमान की पुनर्स्थापना के पश्चात् बैंक दर को साख नियन्त्रण के साधन के रूप में उपयोग करने का जम फिर आरम्भ हुआ, परन्तु इस काल में साख नियन्त्र एा की ग्रन्य रीतियों की तुलना में इसका महत्त्व घट गया था। दूसरे महायुद्ध के पश्चात् इस नीति का महत्त्व फिर बढ़ता हुम्रा दृष्टिगोचर होता है, यद्यपि वर्तमान युगुमें इसको सःख नियन्त्र भी केवल एक सहायक अथवा गौगा रीति के रूप में ही अपनाया जाता है। सन् १६५० से संसार के अधिकांश देशों में बैंक दर की वृद्धि का मुद्रा-।सार विरोधी नीति के रूप में विस्तृत उपयोग हुम्रा है। सर्वप्रथम २५ ग्रगस्त सन् १९५० को संयुक्त राज्य ग्रमरीका ने ग्रपनी बैंक दर को १ ५०% से बढ़ाकर १ ५५% किया था। तत्परचात् फरबरी सन् १९५१ में तुर्की ने उसमें १% की वृद्धि की । अप्रैल सन् १९५१ में हालैण्ड ने भी बेंक दर को १% बढ़ाया। इसी वर्ष जुलाई में वेल्जियम ने ० २५%, म्बद्दबर में जापान ने ० ७३%, फ्रान्स ने ० ५०%, नवम्बर में ब्रिटेन ने ० ५०%, फांस ने १.०% तथा भारत ने ०.४०% ग्रीर दिसम्बर में ग्रास्ट्रेलिया ने १.४०% तथा फिनल्रैंण्ड ने  $\circ$  २५% से ग्रपनी बैंक दरों को बढ़ाया । बैंक दरों की वृद्धि का यह क्रम सन् रि९५२ में भी चालू रहा। २२ जनवरी सन् १९५२ को हॉलैंड ने अपनी बैंक दर में ० %०% कमी कर दी, परन्तु १२ मार्च सन् १९५२ को इङ्गलैंड ने ग्रपनी बैंक दर में १ ५% की फिर वृद्धि की, यद्यपि मार्च सन् १६५८ में इसमें फिर १% की कमी कर दी गई थी। अभी हाल में संयुक्त राज्य अमरीका ने २८ मई सन् १६५६ की बैंक दर को ३% से बढ़ाकर ३३% कर दिया है।

बैंक दर नी ते का सिद्धान्त (The Theory of Bank Rate Policy)-

बैंक दर नीति का सिद्धान्त इस आधार पर स्थित है कि बैंक दर के परि-वर्तनों के फलस्वरूप सभी प्रकार की मौद्रिक दरों में परिवर्तन होन हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यदि बैंक दर ऊँची कर दी जाती है तो सभी प्रकार की ब्याज की दरें ऊपर उठती हैं, ऋगों का लेना कम लाभदायक हो जाता है और इस प्रकार साख का संकुचन होता है। इसके विपरीत यदि बैंक दर घटाई जाती है तो ब्याज की दरों के घटने के कारण ऋगों को प्रोत्साहन मिलता है ग्राँर साख का विस्तार होता है।

कीन्ज के अनुसार बैंक दर नीति के परम्परागत सिजान्त के सम्बन्ध में तीन प्रकार की विचारधाराएँ हैं। इस इनमें से प्रथम विचारधारा के अनुसार वेंक दर केवल के सुद्रा को नियन्त्रित करने का ही एक साधन हें। इस इण्टिकोग्रा में प्रचलित मुद्रा की मात्रा का संकुचन करने के लिए वेंक दर की वृद्धि आवश्यक होती है, पर नु इस सिद्धान्त का दोष यह है कि वैंक दर तथा वैंक मुद्रा की पूर्ति में कोई स्थायी सम्बन्ध नहीं है। यदि बैंक दर अपना प्रभाव डालने में सफल भी होती है तो अभिवृद्धि (Boom) के काल में यह आवश्यक नहीं है कि वैंक दर की वृद्धि का साख के विस्तार पर कोई प्रभाव पड़े ही। इसी प्रकार मन्दी अथवा अवसाद के काल में बैंक दर के घटाने पर भी बहुधा साख का विस्तार सम्पन्न नहीं हो पाता है।

दूसरी विचारधारा के अनुसार बैंक दर का कार्य विदेशी ऋरों के व्याज की दर को नियन्त्रित करके देश के स्वर्ण-कोषों की रज्ञा करना होता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के अन्तर्गत यदि एक स्वर्णमान देश अपनी बेंक दर में बृद्धि करता है तो इससे केवल स्वर्ण का देश से बाहर जाना ही नहीं एक जाता है, अपितु उँचे व्याज के लालच में विदेशी ऋरोों के रूप में सोना देश में आने लगता है। इस प्रकार उपरोक्त विचारधारा के अनुसार बैंक दर विनिमय दरों को प्रतिकूल हो जाने से रोकती है और देश के स्वर्ण-कोषों की रक्षा करती है।

तीसरी विचारधारा के अनुसार बैंक दर का प्रभाव विनियोग दरों (Investment Rates) पर पड़ता है और इससे बचत और विनियोग के पारस्परिक अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। बैंक दर की प्रत्येक वृद्धि बचत की तुलना में विनियोगों को हतोत्साहित करती है और इसके विपरीत बैंक दर की कमी के कारण बचत की तुलना में विनियोग अधिक प्रोत्साहित होते हैं। इस सम्बन्ध में यह कहना अनुग्युक्त न होगा कि यद्यपि बैंक दर और बचत में तो एक प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट सम्बन्ध रहता है, परन्तु बैंक दर तथा विनियोगों का सम्बन्ध इतना स्पष्ट नहीं है। यह तो सभी स्वीकार करते हैं कि बैंक दर का देश के आर्थिक जीवन और देश की आर्थिक क्रियाओं पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, परन्तु यह विषय विवाद-ग्रस्त है कि बैंक दर के परि

<sup>\*</sup> See J. M. Keynes: A Treatise on Money.

वर्तनों का म्रायिक क्रियाम्रों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। इस सम्बन्ध में कीन्ज भ्रौर हॉटरे (Hawtrey) की दो विरोधी विचारधारायें हैं:—हॉटरे का विचार है कि वैंक दर के परिवर्तनों के प्रभाव का मुख्य स्रोत व्यवसायों पर पड़ने वाले ब्याज की म्रल्पकालीन दरों के प्रभाव होते हैं। वैंक दर के परिवर्तनों का दूकानदारों की तैयार तथा मर्द्ध नैयार वस्तुम्रों के स्टॉक जमा करने की प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। यदि मल्पकालीन ब्याज की दरें घटती हैं तो स्टॉकों को रखने के व्यय में भी कभी म्रा जाती है भ्रौर दूकानदार स्टॉकों को बढ़ाने लगते हैं। निर्माणकर्ताम्रों को माल मँगाने के म्रिषक म्रादेश प्राप्त होते हैं भ्रौर वे उत्पत्ति को बढ़ाते हैं, जिसके फलस्वरूप रोजगार तथा मौद्रिक म्राय का भी विस्तार होता है। परन्तु यह तर्क दो बातों पर म्राश्रित है—(१) इस बात पर कि ब्याज की दर तथा स्टॉक रखने के व्यय में क्या सम्बन्ध है भ्रौर (२) इस बात पर कि स्टॉक जमा करने की सुविधा की माँग की लोच कितनी है। व्यवहारिक जीवन में न तो इस सम्बन्ध का ही ठीक-ठीक पता लगाया जा सकता है म्रोर न स्टॉक जमा करने की सुविधा की माँग की ही किसी निश्चित् रूप में नापा जा सकता है। इसलिए बैंक दर के परिवर्तनों के प्रभाव के परिगामों की कोई निश्चत माप सम्भव नहीं होती है।

कीन्ज का विचार है कि बैंक दर का आगन्ति अर्थ-व्यवस्था पर मुख्य प्रमाव दीर्घकालीन व्याज की दरों के परिवर्तन द्वारा ही पड़ता है। यदि बैंक दर ऊँ वी की जाती है तो दीर्घकालीन प्रित्मूतियों से प्राप्त होने वाली आय की तुलना में ऋगा प्राप्त करने का व्यय बढ़ जाता है। जो व्यक्ति अथवा फर्में पहिले बेंकों से ऋगा लेकर व्यवसाय करते थे, अब उसके स्थान पर इन दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को बेच कर घन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार प्रतिभूतियों को बेचने की आग्रहपूर्णता बढ़ती है, परन्तु दूसरी ओर, जिन व्यक्तियों अथवा फर्मों के पास फालतू घन होता है वे उसे प्रतिभूतियों की अपेक्षा निक्षेत्रों में लगाना अधिक लाभदायक समभते हैं, क्योंकि इसमें लाभ अधिक होता है। इस प्रकार प्रतिभूतियों की माँग घटती है। दोनों ही कारणों से दीर्घकालीन प्रतिभूतियों की कीमतों का पतन होता है। प्रतिभूतियों को कीमतों के गिरने का अर्थ यह होगा कि उनसे प्राप्त आय बढ़ेगी और इस प्रकार अल्यकालीन व्याज की दर की प्रत्येक वृद्धि से दीर्घकालीन ब्याज की दरें भी ऊपर उठ्छ जायोंगी और इसके विपरीत अल्पकालीन दरों का पतन दीर्घकालीन दरों को भी गिरा देगा।

साहसियों की विनियोग नीति पर दीर्घकालीन ब्याज की दरों का ही सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। उसी को देखकर वे यह निश्चय करते है कि व्यवसायों में पूँजी का विस्तार किया जाय अथवा नहीं। यदि व्याज की दीर्घकालीन दरें नीची हैं तो प्रतिभूतियों की कीमत ऊँची होगी और साहसी के लिए अश तथा ऋग् पूँजी का प्राप्त करना सरल होगा। इसी काल में स्टॉकों को बदलने और नए करने का

कार्य भी तेजी के साथ होता है। इस प्रकार बैंक दर वास्तव में दीर्घकालीन व्याज की दरों को प्रभावित करके अपना प्रभाव दिखाती है। बैंक दर के परिवर्तनों के उहे श्य (Objectives of the Change in the Bank Rate)

बेंक दर के परिवर्तनों का प्रमुख उद्देश्य साख-मुद्रा का नियन्त्रणा होता है। इस प्रकार के परिवर्तन साधारणतया निम्न कारणों से किए जाते हैं:

- (१) विनिमय दर की अनुक्तलता अथवा प्रतिक्तलता दूर करने के लिए—जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, विनिमय दर के परिवर्तनों पर साख के विस्तार और संकुचन का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वेंक दर का उपयोग विनिमय दर की अनुक्तलता अथवा प्रतिक्तलता दूर करने अथवा सम्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।
- (२) स्वर्ण कोषों की रक्षा— वैंक दर के परिवर्तनों का उद्देश्य देश से स्वर्ण कोषों का बाहर जाना हो सकता है। बैंक दर के बढ़ जाने से देश में सभी प्रकार के ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं। ऐसी दशा में विदेशी देश में लगाई हुई पूँजी को देश से बाहर निकालना बन्द कर देते हैं। बिल्क यह भी सम्भव है कि देश में उल्टा पूँजी का ग्रायात होने लगे। इस प्रकार स्वर्ण कोषों का देश से बाहर जाना रुक जाता है।
- (३) सट्टा बाजार पर श्रंकुश—सट्टो बाजार की कार्यवाहियों के फल-स्वरूप कीमतों में भारी उचावचन उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे देश के श्रायिक जीवन में श्रानिश्चितता श्रा जाती है। साख नियन्त्रण द्वारा सट्टो बाजार को मिलने वाले ऋगों को घटाकर सट्टा व्यवसाय पर प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं।
- (४) मुद्रा-बाजार में धन के अभाव को दूर करना—बहुत बार मुद्रा-बाजार में घन की कमी उत्पन्न हो जाती है, जिससे उद्योगों और व्यवसायों को आव-स्यकतानुसार ऋगा नहीं मिल पाते हैं। ऐसी दशा में बैंक की दर कम करके बेंकों की साख निर्माण करने तथा ऋगा देने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है।
- (५) मुद्रा की माँग में बृद्धि करना—व्यवसायिक मन्दी के काल में बहुवा ऐसा अनुभव किया जाता है कि ऋरों की माँग ही घट जाती है और वैंकों तथा व्यापारियों के पास बहुत-सा घन फालतू पड़ा रहता है। ऐसी दशा में वैंक दर को घटाने से ऋरों की माँग में वृद्धि की जा सकती है और व्यवसायिक मन्दी की स्थिति को दूर किया जा सकता है।
- (६) विदेशी पूँजी के स्रायात श्रीर निर्यात के लिए—बेंक दर के घटने से देश में सभी प्रकार के ब्याज की दरें घटती हैं। इससे पूँजी के निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है श्रीर ग्रायात हतोत्साहित होते हैं। इसके विपरीत बेंक दर के ऊँचा उठा देने से पूँजी के श्रायात श्राकांषत होते हैं श्रीर निर्यात घटते हैं।

मु०च०ग्र० (२१)

(७) प्रतिशोध (Retaliation)—कैंक दर में इसलिए भी परिवर्तन किये जा सकते हैं कि ग्रन्य देशों द्वारा ग्रपनी कैंक दरों में किए हुए परिवर्तनों से देशी ग्र्यं व्यवस्था की रक्षा की जा सके । विदेश में बैंक दर के बढ़ जाने से उस देश को पूँजी का निर्यात होने लगता है, जिसे रोकने के लिए देश को भी देवेंक दर ऊपर उठानी पड़ती है, ताकि दोनों देशों के बीच ब्याज की दरों का ग्रन्तर मिट जाय।

#### वैंक दर के परिवर्तनों का प्रभाव-

बैंक दर के परिवर्तनों का प्रभाव एक देश की ऋान्तरिक ऋर्थव्यवस्था पर तीन रूप में पड़ता है: - दो प्रकार के प्रभाव तो प्रत्यक्ष रूप में देशी अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित होते हैं, परन्तु तीसरी प्रकार का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय शोधनाशेष के परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होता है। जहाँ तक श्रान्तरिक प्रभावों का सम्बन्ध है, उन्हें हम मुख्य तथा गौरा दो भागों में बाँट सकते हैं: (i) बैंक दर की वृद्धि का मुख्य प्रभाव यह होता है कि यदि देश में लोगों की ग्राय यथास्थिर रहती है तो बचत की मात्रा बढ़ती है श्रौर स्थिर पूँजीगत वस्तुश्रों की कीमत घट जाती है। ( ii ) परन्तू उपरोक्त प्रभाव का गौए। प्रभाव यह होगा कि बैंक दर के बढ़ने के कारए। पूँजीगत माल की कीमतों में जो कमी उत्पन्न हो जाती है उसके कारण उस माल का उत्पादन भी घटता है। पुँजीगत माल उत्पन्न करने वाले व्यवसायों में बेरोजगारी बढ़ती है, जिसके कारगा ग्राय घटती है और ग्रन्त में उपभोगीय वस्तु उद्योगों (Consumer goods industries) के माल की भी कीमतें घटती हैं। इस प्रकार सारी अर्थ-व्यवस्था पर मन्दी छा जाती है। सर्वप्रथम पूँजीगत माल बनाने वाले उद्योगों में लाभ घटने लगते हैं। फिर-घीरे-घीरे सभी उद्योगों में लाभ समाप्त हो जाते हैं और चारों ओर व्यवसायिक मनदी फैल जाती है। इसके विपरीत बैंक दर के गिर जाने से भी स्रौर तेजी की दशाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि इससे सभी व्यवसायों को विस्तार करने का प्रोत्सा-हन मिलता है।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोए से यदि स्वर्णमान का चलन है तो बैंक दर की वृद्धि के कारए स्वर्ण निर्यात रुक जायेंगे अगर हा सकता है कि विदेशों से पूँ जी का आयात होने लगे। इसके कारए विदेशी विनिमय दर अनुकूल हो जायगी। दूसरे क्योंकि बैंक दर की वृद्धि के कारए देश में कोमतें तया मौद्रिक आय घटती है इस कारए विदेशी आयात कम हो जाते हैं, क्योंकि देशी माल की तुलना में विदेशी माल के दाम ऊँचे हो जाते हैं। इसके विपरीत विदेशों में देशी माल के दाम घट जाने के कारए निर्यात प्रात्साहित होते हैं। इस प्रकार व्यापाराशेष की प्रतिकूलता अनुकूलता में वदल जाती है। अन्त में कीमतों और मौद्रिक आय के घटने के कारए रोजगार तथा मजदूरियों में भी कमी आ जाती है, जिसके कारए उत्पादन व्यय घटता है और देशी अर्थ-व्यवस्था का असन्तुलन दूर हो जाता है। देशी उद्योगों की प्रतियोगिता शक्ति बढ़ती है और निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। जब बैंक दर इस अन्तिम

उद्देश्य को पूरा कर चुकती है तो राष्ट्रीय ऋर्थ-व्यवस्था के ग्रसन्तुलन का दोप पूर्णतया दूर हो जाता है, परन्तु यह फल देर में प्राप्त होता है। इस प्रकार ग्रल्प तथा दीर्घ दोनों ही कालों के दृष्टिकोएा से बैंक दर नीति का विदेशी व्यापार के ग्रर्थप्रवन्त्र में भारी महत्त्व होता है।

वेंक दर के परिवर्तन विदेशी विनिमय दर को तीन रीतियों अथवा तीन साधनों द्वारा प्रभावित करते हैं—अल्पकालीन मौद्रिक बाजार को प्रभावित करके, दीर्घकालीन पूँजी बाजार के परिवर्तनों द्वारा और व्यापाराशेष के परिवर्तनों द्वारा। जब देश के सामने विनिमय दर के पतन की समस्या आती है, स्वर्ण का निर्यात होता है और स्वर्ण-कोष तेजी के साथ घटने लगते हैं तो वेंक दर को ऊँचा कर देने से देश की भीतरी कीमतों और व्याज की दरों पर इस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं कि बिना स्वर्ण निर्यात के ही शोशनाशेष का असन्तुलन दूर हो जाता है, क्योंकि अल्पकालीन कोषों का देश में आयात होने लगता है। विदेशी अधिक व्याज कमाने के लिए अपने ऋगों का भुगतान लेना स्थिगत कर देते हैं, विल्क और अधिक ऋगा देने लगते हैं और देशवासियों द्वारा विदेशियों को दिए गए ऋगा वापिस मँगा लिए जाते हैं। स्वर्ण-ऋगा तथा कोषों के देश के भीतर इस प्रवाह के कारण देश के चलन की मांग वढ़ जाती है और विनिमय दर देश के लिए अनुकूल हो जाती है।

कुछ समय पश्चात् बैंक दर के परिवर्तनों का प्रभाव दीर्घंकालीन प्रतिभृतियों की ब्याज की दर पर भी पड़ने लगता है। इस वृद्धि के कारण ऋणों की मांग घटती है। प्रतिभृतियों की कीमत घटने के कारण उनसे प्राप्त ग्राय बढ़ जाती है श्रौर क्योंकि विदेशों में ऋण की मांग घट जाती है, इस कारण स्वर्ण, पूँजी ग्रौर कोपों का देश से बाहर जाना रुक जाता है। इसके फलस्वरूप विदेशों विनिमय बाजार में देश के चलन की पूर्ति कम हो जाती है ग्रौर श्रन्य मुद्राग्रों में देश की मुद्रा की मूल्य वृद्धि हो जाती है।

दीर्घनाल में बंक दर की वृद्धि के परिएगाम ग्राथिक जीवन की ग्रन्य शाखाओं में भी दृष्टिगोचर होंगे। विनियोगों में कमी होगी ग्रीर व्यवसायिक कार्य का संकुचन होगा। विस्फीतिक प्रवृत्तियों के कारएग उत्पादन व्यय तथा मौद्रिक ग्राय दोनों में ही कमी ग्रा जायगी। फल यह होगा कि निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा ग्रीर ग्रायात घटते जायेंगे, जिसके कारएग व्यापाराशेष भी श्रनुकूल हो जायगा। व्यापाराशेष की यह ग्रनुकूलता विनिमय दरों को भी श्रनुकूल बना देगी। बैंक दर के नीचा कर देने के सभी दिशाग्रों में विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। व्यापाराशेष प्रतिकूल हो जाता है ग्रीर उसके साथ ही साथ विनिमय दर भी प्रतिकूल हो जाती है।

संक्षेप में, हम ऐसा कह सकते हैं कि बैंक दर के परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव निम्न प्रकार होते हैं:—

(१) इसके फलस्वरूप साख की मात्रा का विस्तार ग्रथवा संकुचन होता है।

- (२) देश का ग्रान्तरिक कीमत-स्तर (Internal Price-level) या तो ऊपर उठ जाता है ग्रथवा नीचे गिर जाता है ग्रथवा उसके नीचे या ऊपर जाने की प्रवृत्ति रुक जाती है।
- (३) पूँजी के विनियोग या तो घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं। प्रथम दशा में पूँजी का देश से निर्यात होने लगता है और दूसरी दशा में देश में पूँजी का आयात होता है। दोनों दशाओं में देश में उपलब्ध पूँजी की मात्रा में परिवर्तन होते हैं अथवा पूँजी का निर्यात अथवा आयात रुक जाता है।
- (४) विनिमय दरों की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता बढ़ जाती है अथवा अनुकूलता या प्रतिकूलता की प्रवृत्ति रुक जाती है।

#### बैंक दर नीति के महत्त्व की कमी—

वर्तमान संसार में साख नियन्त्रक साघन तथा व्यापाराशेष के ग्रसन्त्रलन को दूर करने का उपाय दोनों ही के रूप में बैंक दर का महत्त्व बहुत घट गया है। इस कमी के तीन कारण हैं—प्रथम, वर्तमान युग में मुद्रा-बाजार तथा ग्राथिक व्यवस्था में इतने गम्भीर परिवर्तन हो गए हैं कि बैंक दर का ग्रस्त्र पूर्णतया सफल नहीं हो रहा है। इसरे अधिक प्रत्यक्ष परिएामों के कारएा ग्रन्य उपायों का उपयोग बढ़ गया है और तीसरे, वर्तमान संसार ने सुलभ मुद्रा नीति (Cheap Money Policy) को लोक नीति का ग्रावश्यक ग्राधार मान लिया है। स्वर्णमान के पतन के पश्चात् स्वर्णं कोषों के आवागमनों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से तो बैंक दर का कोई महत्त्व ही नहीं रह गया है। साख नियन्त्रण की इतनी कठोर तथा सप्रभाविक रीतियों का श्रव संसार में श्राविष्कार हो गया है कि बैंक दर के श्रध्ययन का लगभग ऐतिहासिक महत्त्व ही शेष रह गया है। इसके साथ ही साथ, ऐसा श्रनुभव किया जाता है कि बैंक दर के परिवर्तनों द्वारा शोधनाशेष का जो संतुलन स्थापित किया जाता है वह देश के लिये काफी मेँहगा पड़ता है, क्योंकि उसके कारएा बेरोजगारी श्रौर मानव कष्ट दोनों बढ़ते हैं। इस कारए। विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए म्रान्तरिक ग्रर्थ-व्यवस्था की स्थिरता को खो देना बुद्धिमानी नहीं समभी जाती है। वर्तमान सर-कारें विनिमय ह्रास तथा विनिमय नियन्त्रण जैसे प्रत्यक्ष उपायों द्वारा विनिमय दरों की स्थिरता स्थापित करना मुद्रा-संकुचन श्रीर उसके दुष्परिएगामों की तुलना में कहीं ग्रच्छा समभती हैं. क्योंकि इनका ग्रान्तरिक अर्थ-व्यवस्था पर इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और इनकी सफलता भी अधिक निश्चित होती है।

विगत वर्षों मैं बैंक दर नीति के महत्त्व के घट जाने के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं:—

(१) अर्थ-व्यवस्था में लोच का अभाव—प्रथम महयुद्ध के पश्चात् विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में वह लोच नहीं रह पाई है जो पहले थी। परिगाम यह हुआ है कि बेंक दर का परिवर्तन सारी अर्थ-व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालने में असमर्थ रहता है।

- (२) अन्य वैंकों की केन्द्रीय वैंकों पर निर्भरता में कमी—वंक दर की सप्रभाविकता उसी दशा में सम्भव होती है जबिक सभी बैंक आवश्यकता के समय ऋएए के लिए केवल केन्द्रीय वैंक पर ही निर्भर रहें, परन्तु आधुनिक युग में ऐसी प्रथम श्रेणी की बहुत सी बैंक हैं जो दूसरी बैंकों की केन्द्रीय वैंक पर आश्रिता दूर कर देती हैं। काफी समय तक इम्पीरियल बैंक एक इसी प्रकार की बैंक रही है। ऐसी दशा में बैंक दर के परिवर्तनों का अन्य बैंकों पर कोई भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ने पाता है।
- (३) नकद साख व अधिविकर्ष का अधिक उपयोग—आधुनिक जगत में आन्तरिक व्यापार का अर्थ-प्रवन्ध नकद साख तथा अधि-विकर्ष ऋगों द्वारा किया जाता है। विनिमय बिलों की आड़ पर प्राप्त ऋगों और उनसे सम्वन्धित बैंक दर का महत्त्व घट गया है। इससे स्वयं ही बैंक दर नीति की सप्रभाविकता कम हो गई है, क्योंकि बिलों को केन्द्रीय बैंक से दुवारा भुनवाने की आवश्यकता कम हो गई है।
- (४) अन्य प्रभावपूर्ण रीतियों का आविष्कार—सांख नियन्त्रण के भिषक सफल और सप्रभाविक उपायों के आविष्कार ने वेंक दर का महत्त्व घटा दिया है।
- (५) राष्ट्रों की सुलभ मुद्रा नीति—आर्थिक नियोजन के इस वर्तमान संसार के सभी देशों की नीति सस्ती अथवा सुलभ मुद्रा नीति है, जिसके अन्तर्गत बैंक दर को नीचा रखना ही आर्थिक नीति का स्थायी आधार माना जाता है।
- (६) स्रादेयों की तरलता में बृद्धि—ग्राधुनिक काल में बेंकों के आदेयों की तरलता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण केन्द्रीय बेंक से ऋण लेने की आवश्यकता घटती जा रही है। इस कारण बेंक दर के परिवर्तनों का बेंकों की साख निर्माण नीति पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ पाता है।
- (७) मुद्रा बाजार पर देर से प्रभाव पड़ना—बैंक दर के परिवर्तनों का मुद्रा बाजार पर कुछ समय पश्चात् ही प्रभाव पड़ता है। परन्तु मौद्रिक क्षेत्र में वही नीति लाभदायक हो सकती है जिसका ग्रत्पकाल में प्रभाव पड़ सके। बैंक दर इसके लिए ग्रंधिक उपयक्त नहीं है।
- (८) अन्य बैंकों द्वारा अपनी जमाओं पर अधिक व्याज देना—वैंक दर की वृद्धि के प्रभाव को एक बैंक अपनी निक्षेपों पर अधिक व्याज देकर दूर कर सकती है। अधिक निक्षेप प्राप्त हो जाने के कारण केन्द्रीय बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। वर्तमान काल में यह प्रवृत्ति बराबर बलवान होती जा रही है और ऋण के अन्तिम प्रदानकर्त्ता के रूप में केन्द्रीय बैंक का महत्त्व घटता जा रहा है।

#### वैंक-दर नीति की सीमाएँ —

विगत वर्षों में साख-नियन्त्रए। के दृष्टिकोए। से बैंक-दर नीति के महत्त्व का

घट जाना इस बात को स्पष्ट कर देता है कि यह नीति सभी दशाओं में भ्रावश्यक श्रंश तक सफल नहीं होती है। वास्तव में इस नीति के उपयोग की दो महत्त्रपूर्ण सीमायें हैं, जो निम्न प्रकार हैं:—

- (१) वैंक दर में परिवर्तन होने पर अन्य ब्याज दरों में भी परिवर्तन होना—देश में प्रचलित सभी प्रकार की ब्याजों की दरों से बैंक-दर का ऐसा सम्बन्ध होना चाहिए कि बैंक-दर का प्रस्थेक परिवर्तन उत्तमें भी वैसा ही परिवर्तन उत्पन्न कर सके। ऐसा सम्बन्ध तभी सम्भव हो सकता है जबिक मुद्रा-बाजार पूर्णतया संगठित (Organised) हो। केवल उसी दशा में जबिक सभी प्रकार की ब्याज की दरें स्वयं ही बैंक दर के परिवर्तनों के अनुसार बदल जाती हैं, साख की मात्रा में बैंक-दर के परिवर्तनों के अनुसार और संकुचन हो सकेगा। जिन देशों में ऐसी स्थिति नहीं है वहाँ बैंक-दर साख-नियन्त्रगण का सप्रभाविक उपाय नहीं हो सकती है।
- (२) ग्रर्थ-व्यवस्था में लचीलायन होना—देश के ग्राधिक कलेवर में काफी लचीलायन (Flexibility) होना चाहिए, जिससे कि साख की मात्रा के परिवर्तनों का उत्पादन, कीमत, मजदूरी, व्यापार, भाड़ों तथा मौद्रिक ग्राय पर ग्रावश्यक प्रभाव पड़ सके। इस प्रकार की लचक संयोग से कहीं मिलती होगी।

वास्तविक जीवन में इन दोनों शातों का पूरा होना कठिन होता है । शायद इक्ज़ लैंड ही एक ऐसा देश है जहाँ का मुद्रा-बाजार बहुत सुसंगठित है और जहाँ आधिक कलेवर में लचीलापन भी काफी है। यही कारए। है कि उस देश में बैंक-दर नीति को अधिक सफलता मिली है। अनुकूल परिस्थितियां न रहने के कारए। संसार के दूसरे देशों में यह नीति बहुत ही कम सफल हो पाई है। भारत में संगठित मुद्रा-बाजार और आर्थिक कलेवर की लचक दोनों ही का अभाव है। यहाँ तो इस नीति से सफलता की आशा बहुत ही कम हो सकती है।

कीन्ज का विचार है कि सामान्य भ्राधिक स्थायित्व के लिए बचत और विनियोग का सन्तुलन भ्रावश्यक है। इस प्रकार का स्थायित्व बैंक दर नीति तथा साख नियन्त्रण के भ्रन्य उपायों द्वारा ही स्थापित नहीं किया जा सकता है, बिल्क इसके लिए राज्य को प्रत्यक्ष रूप में विनियोगों की व्यवस्था करनी चाहिए भौर भ्रवसाद के काल में लोक कार्यों (Puelic Works) का विकास करना चाहिए। कीन्ज के अनुसार बैंक दर नीति साख नियन्त्रण का एक बड़ा ही धिसा हुआ तथा रूदिवादी उपाय है।\*

किन्तु इस सम्बन्ध में यह जानना भ्रावश्यक है कि बैंक दर नीति का उपयोग पूर्णंतया समाप्त भ्रभी भी नहीं हुन्ना है, केवल उसका महत्त्व ही घट गया है। अभी तक भी मुद्रा की माँग और पूर्ति के बीच समायोजन करने का यह एक लोकप्रिय

J. M. Keynes: General Theory of Employment, Interest and Money, p. 164,

उपाय है। यह कहना तो कठिन है कि प्राधिक ग्राधिक जीवन पर वेंक दर का प्रभाव ग्रत्मलालीन ब्याज की दरों के परिवर्तन द्वारा पड़ता है ग्रथवा दीर्घकालीन ब्याज की दरों के परिवर्तन द्वारा पड़ता है ग्रथवा दीर्घकालीन ब्याज की दरों के परिवर्तन द्वारा। किन्तु इस प्रकार का प्रभाव पड़ता ग्रवस्य है ग्रीर क्योंकि ग्राधिक जीवन पर ब्याज की दरों के परिवर्तनों के ग्रतिरिक्त ग्रीर भी ग्रनेक वातों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए केवल वेंक दर के परिवर्तनों द्वारा स्थिति दो पूर्णतया सुघार लेना सम्भव नहीं हो पाता है।

#### विगत वर्षों में वैङ्क-दर के परिवर्तन-

यद्यपि श्रव बेंक-दर नीति का पहला सा महत्त्व शेप नहीं रह गया है, परन्तु सन् १६४५ के पश्चात् संसार के श्रविशां देशों में इसका उपयोग फिर बढ़ता हुग्रा दिखाई देता है। श्रविकांश देशों ने मुद्रा-प्रसार से उत्पन्न होने वाली स्थिति का सामना बेंक-दर में परिवर्तन करके करने का प्रयत्न किया है, यद्यपि साथ में ग्रन्य उपाय भी किए गये हैं। बेंक-दर में वृद्धि करने की प्रवृत्ति विश्वव्यापी होती गई है। निम्न तालिका में इस परिवर्तन के कम को दियाया गया है:—

देश	वर्तमा दर	न परिवर्त तिर्ी		परिवर्तन से पूर्व की दर	ग्रन्तर
१. भारत	8.00	जनवरी	१९५	७ ४.४	+0.10
२. ग्रास्ट्रे लिया	¥.00	दिसम्बर	१९५	१ ३•५०	十 6.16。
३. फिनलैंड	४.००	दिसम्बर	ं१९५	४ ५.७४	¥७ <b>:</b> ० —
४" फ्रान्स	३'००	दिसम्बर	१९५	४७°३	بە•°ە −
५ तुर्की	४.४०	जून	१८५	χ 3:00	+8.80
६॰ बेल्जियम	३'००	श्रगस्त े	४, १६५	४ २ ७४	+०'२५
७ जापान	७•३०	ग्रगस्त	१८५	५ ५.२८	<del>+</del> १.४६
<ul> <li>संयुक्त राज्य ग्रमरीका</li> </ul>	े ३•४०	मई	१९५	oo.£ 3	十0.70
६. नीदरलैण्डस <u>्</u>	₹.००	फरबरी ६	, १९५	६ २ ५०	十0.10
१० ब्रिटेन	४.४०	मार्च	१९५	द ४.४०	<b>− १.00</b>
<b>११.</b> रूस	8,00	जुलाई १	, <b>१</b> ६५	€ 8.00	-8.00
१२, इटली	४.४०				****
१३. दक्षिगी स्रफीका	३•५०		•••		****
१४. नार्वे	२.४०		•••		****
१५. स्वीडन	२•५०		•••		****
१६. कनाडा	६.५०		•••		****
१७, स्विट्जरलैंड	१:५०		•••		****
१८. न्यूजीलैंड	१-५०		•••		****

## (ब) खुले बाजार क्रियाएँ (Open Market Operations)

खुले वाजार की कियाओं का अर्थ-

साघारणतया, कैन्द्रीय बैंक को व्यक्तिगत फर्मों तथा जन-साघारण के साथ व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होता है, परन्तु विशेष परिस्थितयों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है कि साख नियन्त्रण हेतु केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों के प्रतियोगी के रूप में जन-साधारण से व्यवसाय करने लगती है । इसी को केन्द्रीय बैंक की खुले बाजार किया कहा जाता है। 'खुले बाजार किया अ में इसका उपयोग केन्द्रीय बैंक द्वारा किसी भी प्रकार के बिलों अथवा प्रतिभृतियों के खरीदने और बेचने से होता है, (ii) परन्तु संकुचन अर्थ में इसका अभिप्राय केवल सरकारी प्रतिभृतियों के कय-विक्रय से होता है। साख नियन्त्रण की इस रीति का प्रचलन पिछले २०-३० वर्षों से अधिक बढ़ गया है। प्रकृति में यह नीति केन्द्रीय बैंक द्वारा साख के निर्माण तथा रद्द करने की एक विधि होती है। प्रतिभृतियों के क्य-विक्रय द्वारा केन्द्रीय बैंक प्रत्यक्ष रूप में एक दम देश में चलन की मात्रा तथा बैंकों के नकद कोषों को घटा-बढ़ा देती है और इस प्रकार अन्य बैंकों की साख निर्माण शिक्त में परिवर्तन कर देती है। खुले बाजार की कियाओं का साख व चलन प्रणाली पर प्रभाव—

यदि केन्द्रीय वैंक प्रतिभूतियों को खरीदती है तो चलन की ग्रधिक मात्रा जनता के हाथ में चली जाती है। जनता की मौद्रिक स्राय बढ़ती है स्रौर उसके साथ ही साथ कीमतें भी ऊपर को जाने लगती हैं। जनता को जो अधिक मात्रा में अप्य प्राप्त होती है उसका एक भाग उसके द्वारा बैंकों में भी जमा किया जाता है और इस प्रकार बैंकों के नकद कोषों का विस्तार होता है। साख-मुद्रा की ग्रधिक मात्रा में निकासी होने लगती है, कीमतों की वृद्धि के कारए। उत्पादन भी ग्रुधिक लाभदायक हो जाता है भीर साल-मुद्रा की माँग बढ़ने लगती है। इस प्रकार प्रतिभृतियों के कय की नीति का परिशाम यह होता है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है त्रीर साख का विस्तार होता है | इसके विपरीत यदि केन्द्रीय बैंक्क प्रतिभूतियाँ बेचती है तो क्चोंकि केन्द्रीय बेंक पर ग्रन्य सभी बेंकों की ग्रपेक्षा ग्रधिक विश्वास रहता है, लोग ग्रपनी-ग्रपनी बेंकों से रुपया निकाल कर. अधिक बचत द्वारा तथा अपने दिये हुए ऋगों को वापिस लेकर इन प्रतिभूतियों को खरीदते हैं। इस प्रकार नकदी केन्द्रीय बैंक को लौट जाती है ग्रौर प्रचलित मुद्रा की मात्रा घटती है, जिससे बेंकों के नकद कोषों में कमी आ जाती है। नकद कोषों में कमी हो जाने के कारए। बैंकों को साख-मुद्रा का संकूचन करने पर बाध्य होना पड़ता है। मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाने के कारए। कीमतों में गिरने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण व्यवसाय हतोत्साहित होते है। स्रातः प्रतिः

<sup>\*</sup> कुछ लेखकों ने इन्हें ''विरृत विपिए कियायें'' भी कहा है।

मृतियाँ बेचने की नीति को स्पष्ट परिशाम साख-संकुचन के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि वैंकों की साख निर्माश शक्ति और साख-मुद्रा की माँग दोनों ही में कमी आ जाती है।

#### खुले बाजार की क्रियाओं भी नीति को अपनाने की दशायें—

खुले बाजार की क्रियाओं वाली नीति का प्रयोग प्रायः निम्न दशाओं में किया जाता है—

- (i) स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण के आयात और निर्यात के प्रभाव को विफल करने के लिये यह नीति अपनाई जाती है। स्वर्ण का आयात होने पर प्राय: स्वर्ण-मान देश में मुद्रा का प्रसार हो जाता है और मूल्य-स्तर बढ़ने लगते हैं। यदि मूल्य वृद्धि देश-हित में न हो, तो केन्द्रीय वैंक प्रतिभूतियाँ वेंचकर देश में मुद्रा की मात्रा को कम कर लेता है, जिसमें मूल्य वृद्धि पर रोक लग जाती है। इसके विपरीत जब स्वर्ण का निर्यात होता है तो उस पर आधारित मुद्रा की मात्रा घट जाती है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है वस्तुओं के मूल्य गिरने लगते हैं यदि यह गिरावट देश के अनुकूल न हो तो केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियाँ खरीद कर प्रचलित मुद्रा में वृद्धि कर देती है, जिससे मूल्य गिरने बन्द हो जाते हैं।
- (ii) पूँजी के निर्यात को रोकने के लिये केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियाँ बेच कर मुद्रा बाजार से भ्रतिरिक्त राशि को खींच लेती है। इससे विदेशों को पूँजी का निर्यात होना रुक जाता है।
- (iii) बैंकों पर दौड़ रोकने के लिये—संकट काल में जब बैंकों पर जनता रूपया निकालने के लिये दौड़ पड़ती है तो मुद्रा बाजार में जनता का विश्वास स्थापित करने के लिये केन्द्रीय बैंक बैंकों की हुन्डियों ग्रौर ग्रन्य पत्रों को भुनाने लगती है तथा जनता से प्रतिभृतियाँ खरीद कर उन्हें ग्रावश्यक मात्रा में नकद घन देने लगती है, इससे बैंकों का संकट दूर हो जाता है।
- (iv) बैंक दर के असफल होने पर—जब कभी बैंक दर के बढ़ने पर मुद्रा बाजार की अन्य संस्थायें अपनी ब्याज दरें नहीं बढ़ाती हैं, क्योंकि उनके पास काफी नकद कोष हैं तो केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ बेच कर बैंक की इस अति-रिक्त राशि को घटा देता है, जिससे ये संस्थायें ब्याज-दर बढ़ाने पर विवश हो जाती हैं।
- (v) सुद्रा बाजार में सुद्रा की कमी को दूर करने के लिये भी केन्द्रीय बेंक प्रतिभूतियां खरीदने लगता है। इससे बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है भ्रौर समाज के भ्राधिक व्यवहारों में समता बनी रहती है।

वैंक दर नीति श्रेष्ठ है या खुले बाजार की कियात्रों की नीति ?— इस नीति का उपयोग बहुवा बेंक-दर नीति के साथ ही साथ उसे प्रविक सप्रभाविक बनाने के लिए किया जाता है, परन्तु स्वतन्त्र रूप में भी इसका उपयोग हुग्रा है। वैंक दर के परिवर्तनों का ब्याज की दीर्घकालीन दरों पर केवल परोक्ष ही प्रभाव पड़ता है, परन्तु खुले बाजार कियाग्रों द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित किया जा सकता है। इसके ग्रतिरिक्त बैंक दर का प्रभाव तत्काल तो केवल ब्याज की ग्रह्मकालीन दरों पर ही पड़ता है, दीर्घकालीन दरों पर वह काफी समय पश्चात् प्रकट होता है, परन्तु खुले बाजार व्यवसाय का दीर्घकालीन तथा ग्रह्मकालीन दोनों ही प्रकार की ब्याज की दरों पर एक ही साथ प्रभाव पड़ता है श्रीर वह भी तत्काल ही। यही कारएा है कि इस नीति के फल प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर होते हैं।

#### खुले बाजार किया नीति की सीमाएँ -

खुले बाजार क़िया नीति की सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रच-लित मुद्रा मात्रा तथा व्यापार बैंकों के नकद कोषों में खुले बाजार व्यवसाय की प्रकृति और विस्तार के ही अनुसार परिवर्तन हों, व्यापार बैंक अपने नकद कोषों की मात्रा के अनुपात में ब्याज की दरों को घटाने-बढ़ाने के लिए तैयार हो और वैंक-साख की माँग ब्याज की प्रत्येक वृद्धि और कमी के साथ घट-बढ़ जाय। साधारणतया व्यवहारिक जीवन में उपरोक्त मान्यताएँ सत्य होती हैं, यद्यपि कुछ परिस्थितियां इससे भिन्न भी हो सकती हैं।

यह नीति निम्न कारणों से कभी-कभी श्रसफल रहती है:-

- (१) परिस्थितियों की अनुकूलता—यह सम्भव है कि केन्दीय बैंक द्वारा प्रितिभूतियाँ खरीदने पर भी प्रचलित मुद्रा तथा व्यापार बैंकों के नकद कोषों की मात्रा न बढ़ सके। विशेष का से यदि उसी काल में पूँजी का निर्यात होता है, व्यापाराशेष प्रितिकून है अथवा जनता पत्र-मुद्रा को जमा करके रखने लगती है। इसी प्रकार केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियां बेचने पर मुद्रा संकुचन का होना आवश्यक नहीं है, यदि व्यापाराशेष अनुकूल है अथवा यदि लोग अपने आसंचित कोषों (Hoards) को खाली करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यह नीति भी केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही सफल होती है। प्रत्येक दशा में इसकी सफलता भी सन्देह-पूर्ण ही रहती है।
  - (२) नकद कोषों के रखने के सम्बन्ध में कड़ी नीति का पालन—साख के आधार प्रयात नकद कोषों को विस्तृत प्रथवा संकुचित कर देने के फलस्वरूप साख की मात्रा में उसी के अनुपात में विस्तार अथवा संकुचन होना आवश्यक नहीं है, जब तक कि वैंक नकद कोषों के बनाये रखने में एक कड़ी नीति नहीं अपनाती है। इङ्गलैंड में तो बैंकों की नीति यही है, परन्तु इसके विपरीत अमरीका की बैंक नकद कोषों की वृद्धि का उपयोग साधारणतया संघ निधि प्रणाली (Federal Reserve System) के ऋण चुकाने के लिए ही करती है। इसके अतिरिक्त नकद कोषों की वृद्धि के आधार पर साख का विस्तार करने के लिए बैंक को और भी बहुत सी व्यवसायिक

बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इस कारण यह आवश्यक नहीं है कोषों के बढ़ने की प्रत्येक दशा में साख का विस्तार ही किया जाय और नकेंद्र कापा की वृद्धि के अनुपात में साख का विस्तार तो किंचित ही हो पाता है।

- (३) ऋरुगों की मांग की आग्रहपूर्णता—यह भी सम्भव है कि नकद कोषों के बढ़ने पर भी बेंक साख का विस्तार न कर सकें, क्यों कि साख विस्तार ऋरुगों की मांग पर निर्भर होता है। यदि ऋरुगों की मांग ही नहीं है तो साख के विस्तार का प्रश्न ही नहीं उठेगा। अवसाद के काल में बहुवा ऐसी ही स्थिति उत्तन्न हो जाती है। इसके विपरीत अभिवृद्धि के काल में ब्याज की दर के ऊँचा हो जाने के काररण नकद कोषों की कमी भी साख के विस्तार की प्रवृत्ति को रोकने में असमर्थ ही रहती है, क्यों कि ऊँचे ब्याज पर भी ऋरुगों की मांग वहुत होती है। अतः ऋरुगों की मांग की आग्रहपूर्णता भी साख के विस्तार और संकुचन की सीमाएँ निर्धारित करती है।
- (४) प्रतिभूतियों को खरीदने-वेचने की शक्ति ग्रसीमित होनी चाहिये— खुले बाजार व्यवसाय नीति की सफलता इस बात पर भी निर्भर होती है कि केन्द्रीय बैंक के पास बेचने के लिए कितनी प्रतिभूतियाँ हैं और वह कितनी प्रतिभूतियाँ खरीद सकती है। दोनों ही दिशाओं में भारी सीमितता होती है, जिसके कारण ग्रनेक व्यवहा-रिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। वास्तिवक जीवन में न तो केन्द्रीय बैंक के पास पूंजी की हो प्रचुरता रहती है ग्रीर न उसके पास विक्री साव्य प्रतिभूतियाँ ही ग्रसीमित मात्रा में होती हैं। केन्द्रीय बैंक सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय भी नहीं कर सकती है। इस प्रकार इस नीति का कार्य-क्षेत्र भी सीमित रहता है।

इन सीमाओं के रहते हुए भी यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय वैंक द्वारा प्रित्मित्वाँ खरीदने ग्रीर बेचने तथा बैंक द्वारा साख के संकुचन तथा विस्तार के बीच पर्याप्त सम्बन्ध होता है। खुले बाजार क्रियाओं की सफनता के लिए यह ग्रावव्यक है कि ग्रल्पकालीन तथा दीर्घंकालीन दोनों ही प्रकार की सरकारी हुण्डियों के क्रय-विक्रय के लिए विस्तृत तथा सिक्रय मण्डी हो। इस प्रकार की मण्डियाँ ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य ग्रमरीका में ही हैं ग्रीर इसी कारण इन्हीं देशों में इस उगाय को ग्रधिक सफलता मिली है। ब्रिटेन में तो बैंक दर नीति की सप्रभाविकता बढ़ाने के लिए एक सहा-यक उपाय के रूप में इसका बहुत उपयोग हुग्रा है।

#### (स) साख-नियन्त्रण की ऋन्य रीतियाँ (Other Methods of Credit Control)

बैंक दर तथा खुले बाजार किया के ग्रितिरक्त और भी बहुत सी रीतियों से साख-नियन्त्रण के उद्देश को पूरा किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जो उपाय किये जाते हैं उनका ग्रलग-ग्रलग अथवा कई को एक साथ मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। ग्रन्थ प्रमुख उपाय निम्न प्रकार हैं:—

- (१) व्यापार बैंकों की न्यूनतम् नकद निधि को बदलना (Variation n the Bank Reserve Ratios)—केन्द्रीय बैंक व्यापार बैंकों द्वारा उसके एस जमा की हुई न्यूनतम् नकद निधि के अनुपात में परिवर्तन करके साख-नियन्त्रण हा उपाय कर सकती है। यह रीति सर्वप्रथम सन् १६२३ में अमरीका में अपनाई गई शी, परन्तु इसके परचात् संसार भर में इसका विस्तृत उपयोग हुआ है। बैंकों द्वारा एखी हुई सुरक्षित निधि के अनुपात को बढ़ाने से साख का विस्तार रोका जा सकता है और इसके विपरीत उसे कम कर देने से साख का विस्तार हो सकता है। अमरीका ने ओ बैंक दर नीति के साथ-साथ इस उपाय को भी कितनी ही बार अपनाया है, परन्तु यह रीति भी पूर्णतया दोष-विमुक्त नहीं है। सभी बैंकों के बीच नकद कोषों का समान वितरण नहीं होता है, इसकिये इसके फलस्वरूप कुछ बैंकों को दूसरों की अपेक्षा अधिक कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त यह एक कठोर रीति है, जिसका प्रभाव सभी व्यापार बैंकों पर पड़ता है, न कि केवल उन बैंकों पर जो साख निर्माण के सम्बन्ध में गलत नीति अपनाती हैं। इसलिए केन्द्रीय बैंक को इसका उपयोग सावधानीपूर्वक करना पड़ता है।
- (२) साख की राशनिङ्ग (Rationing of Credit)—यह एक भत्यिषक कठोर उपाय है और इसका उपयोग साधारणतया तानाशाही शासन प्रणाली में ही अधिक विस्तृत रूप में हुआ है। इसके अन्तर्गत व्यवसायिक आवश्यकताओं को देखते हुए साख के निर्माण की एक अधिकतम सीमा निश्चित कर दी जाती है और उसमें से विभिन्न बेंकों तथा विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए अभ्यंश निश्चित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार साख का विस्तार अथवा संकुचन नहीं हो पाता है। उसकी मात्रा पहले से ही निश्चित कर दी जाती है। कोई भी वैंक निर्धारित अभ्यंश (Quota) से कम या अधिक साख उत्पन्न नहीं कर सकती है। यह वैंसे तो एक बड़ी सप्रभाविक रीति है, परन्तु इसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ बहुत हैं, क्योंकि केन्द्रीय बेंक को विभिन्न व्यवसायों की ऋण आवश्यकताओं और उनसे सम्बन्धित साख के निर्माण की मात्रा का सही सही अनुमान लगाना पड़ता है और फिर सभी बेंकों के अलग-अलग अभ्यंश निर्धारित करने पडते हैं।
- (३) सीधी कार्यवाही (Direct Action)—सीधी कार्यवाही का अभिप्राय प्रतिविरोधी कार्यों से होता है। यदि कोई वैंक केन्द्रीय वेंक द्वारा निर्धारित साख नीति का पालन नहीं करती है तो केन्द्रीय वेंक उसके विरुद्ध अनेक प्रकार की कार्यवाहियाँ कर सकती है, जैसे—उसके बिलों को भुनाने से इन्कार करना, उसे ऋए न देना अथवा उससे मौद्रिक दण्ड वसूल करना। कठोर रूप में इसके अन्तर्गत वेंक विशेष के वेंकिंग अधिकार भी छीने जा सकते हैं। सीधी कार्यवाही की सैद्धान्तिक वांछनीयता यही है कि इस प्रणाली में वेंक-साख का अधिक अच्छा गुणात्मक वितरण हो जाता है, जबकि अन्य साधारण उपायों का प्रभाव केवल साख की मात्रा के वितरण पर ही पड़ता है, परन्तु यह रीति भी सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी

रचनात्मक कार्य सम्पन्न नहीं होता है। यह तो केवल एक प्रकार का प्रतिकार है, जिसका उद्देश्य केवल वेंक विशेप की प्रस्तुत साख नीति में परिवर्तन करना होता है श्रीर उसे केन्द्रीय बैंक के आदेशों को मानने पर बाध्य किया जाता है।

√४) समभाना (Persuasion)—यह भी एक प्रकार की सीची कार्य-वाही ही है, परन्तु इसमें किसी प्रकार का भय नहीं दर्शाया जाता है, विक एक प्रकार सोचन-समभने के आधार पर प्रार्थना की जाती है और वैंक विशेप के सम्मुख उसकी नीति के दुष्परिणाम स्पष्ट कर दिये जाते हैं। इस उपाय का आधार यह है कि केन्द्रीय वैंक देश की बैंकों का एक प्रकार से नेतृत्व करती है और इस नाते उसे सलाह देने तथा पथ-प्रदर्शन करने का अधिकार होता है। यह प्रणाली इसलिए अच्छी है कि इसका उपयोग सीधी कार्यवाही की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है, परन्तु उसको केवल उसी देश में अधिक सफलता मिलती है जिसमें थोड़ी सी ही संख्या में बड़ी-बड़ी वैंक हों, जिनसे केन्द्रीय बैंक का घनिट सम्बन्ध रहे। भारत में यह नीति बहुत सफल नहीं रह सकती है, क्योंकि रिजर्व बैंक के लिए प्रत्येक बैंक को अलग-अलग समभाना कठिन है।

(अ) प्रतिभूति ऋगों की य्यावश्यकता सीमा में परिवर्तन (Changes in Margin Requirements on Security Loans)—यह भी साख के गुणात्मक नियन्त्रण का ही एक उपाय है ग्रीर इसका उपयोग साधारणतया उस साख के नियन्त्रण हेतु किया जाता है जो सट्टा प्रतिभूतियों के लिए निर्मित किया जाता है। इस प्रणाली का ग्राविष्कार भी ग्रमरीका में हुग्रा था। इस प्रणाली में केन्द्रीय वैंक को ऐसे वैधानिक ग्रधिकार दे दिये जाते हैं कि वह बेंकों द्वारा सट्टा बाजार को दियं जाने वाले ऋगों की मात्रा के सम्बन्ध में नियम बना सके, जिससे कि उस बाजार के लिए नियन्त्रित मात्रा में ही साख मिल सके। यह सट्टा बाजार पर नियन्त्रण रखने का एक सप्रभाविक उपाय है।

प्रभोक्ता साख का नियमन (Regulation of Consumer Credit)—इस रीति का उपयोग सर्वप्रथम दूसरे महायुद्ध के काल में अमरीका में रक्षा-उद्देश्य से किया गया था। केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली को यह अधिकार दिया गया था कि वह ऐसे नियम बनाये कि जिनके आधार पर उपभोक्ताओं को किश्तों पर थोड़ी-थोड़ी करके साख सुविधाएँ दी जा सकें। युद्ध के पश्चात् कनाडा ने इस प्रणाली को अपनाया। ऐसी व्यवस्था की गई कि बैंकों को स्थायी उपभोगीय वस्तुओं की १०% कीमत नकदी में देनी पड़ती थी। परिणाम यह होता था कि प्रत्येक ऋण का एक भाग अनिवार्य रूप में नकदी में चुकाना आवश्यक था और साख विस्तार एक निश्चित सीमा के परे नहीं हो पाता था।

(७) विज्ञापन तथा प्रचार (Publicity)—यह भी समभाने का ही एक उपाय है। इसका आधार यह है कि वर्तमान युग में किसी भी नीति के प्रति एक

सप्रभाविक जनमत तैयार करके उसकी सफलता को अधिक अंश तक निश्चित किया जा सकता है। केन्द्रीय वैंक प्रचार द्वारा यह दिखाने का प्रयत्न करती है कि राष्ट्रीय पूर्य-व्यवस्था के हितों को देखते हुये साख सम्बन्धी कौनसी नीति अधिक उपयुक्त है और कौन कौनसी बैंक्क उस नीति का पालन नहीं करती हैं।

( ८ ) अन्य उपाय—विगत वर्षों में युद्धकालीन मुद्रा-प्रसार के विरुद्ध साख नियन्त्रण को और भी कई रीतियों का उपयोग किया गया है। उदाहरणस्वरूप, कुछ देशों ने विदेशी ऋगों को प्राप्त करके मुद्रा-प्रसार को रोकने का प्रयत्न किया हैं। लङ्की की केन्द्रीय बैङ्क ने व्यापार बैङ्कों को प्राप्त विदेशी आदेय कम मात्रा में बाहर भेजने की सलाह दी है। कनाडा ने लचीली (Flexible) विनिमय दरों को ग्रहण किया है और अनुसूचित बैंकों को निक्षेप प्रमाण-पत्र (Deposit Certificates) दिये हैं।

इस प्रकार साख नियन्त्रण के उपाय अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इनमें कुछ तो तुरन्त फल प्रदान करते हैं और कुछ थोड़े समय पश्चात्, कुछ कठोर होते हैं और कुछ उदार : प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता और अर्थ-व्यवस्था की स्थिति के अनुसार उपायों को चुनता है। इस सम्बन्ध में केवल इतना कहा जा सकता है कि प्रत्येक उपाय का उपयोग सोच-समक्ष कर करने की आवश्यकता है। यह अविवेचक (Indiscriminate) नहीं होना चाहिये।

#### साख नियन्त्रण की कठिनाइयाँ (Difficulties of Credit Control)-

विभिन्न उपायों का उपयोग करके भी यह ग्रावश्यक नहीं है कि देश में साख की मात्रा पर ग्रावश्यक ग्रंश तक नियन्त्रए। रखा जा सके । साख नियन्त्रए। के मार्ग में भ्रनेक कठिनाइयाँ हैं:—

- (१) साख के विभिन्न रूपों पर नियन्त्रण रखने की किठनाई—केन्द्रीय वैंक केवल बैंक साख (Bank Credit) को ही नियन्त्रित करने का प्रयत्न करती है, परन्तु बैंक साख ही साख का एक मात्र रूप नहीं है। इसके अतिरिक्त पुस्तकीय साख, विनिम्य बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों आदि के रूप में वाणिज्य साख भी होती है। ये भी वैंक साख की माँति मुद्रा होते है। किन्तु इन पर केन्द्रीय बैंक का नियन्त्रण नहीं होता है।
- (२) सभी वैंकों पर नियन्त्रण का अभाव—वैङ्क साख पर केन्द्रीय वैङ्क का पूर्ण नियन्त्रण नहीं हो सकता है, क्यों कि देश की सभी वैंकों का केन्द्रीय वैंक से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है। अमरीका में लगभग आधी व्यापार वैंक केन्द्रीय वैंक के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर हैं। भारत में भी लगभग सभी देशी बैंकर रिजर्व वैंक से किसी प्रकार सम्बन्धित नहीं हैं।
- (३) सहयोग प्राप्त करने में किठनाई—यदि व्यापार बैङ्क केन्द्रीय बैङ्क से प्रत्यक्ष रूप में सम्वन्धित है तब भी यह ग्रावश्यक नहीं है कि वे केन्द्रोय बैंक को सह-

योग दें भ्रौर जब तक केन्द्रीय वैङ्क को अन्य वैङ्कों का सहयोग प्राप्त न होगा, वह साख नियन्त्ररण में सफल न हो सकेगी।

- (४) गैर-वित्तीय संस्था श्रों का प्रभाव देश के वित्तीय कलेवर में कुछ ऐसी गैर-वित्तीय संस्थायें भी होती हैं जो साख तथा वैंकों की साख निर्माण नीति पर बहुत प्रभाव डालती हैं, किन्तु इन पर केन्द्रीय बैंक्क का किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं हो सकता है।
- (५) साख के म्रन्तिम उपयोग पर नियन्त्रग् का म्रभाव केन्द्रीय बैंक साख के म्रन्तिम उपयोग पर नियन्त्रग् नहीं रख सकती है। यदि सट्टे के लिए ऋग् नहीं दिये जाते हैं तो यह सम्भव है कि वाणिज्य कार्यों के हेतु लिए हुए ऋग् सट्टा बाजार को हस्तान्तरित हो जायें।

#### QUESTIONS

- 1. केर्न्द्रीय बैंक किसे कहते हैं ? मुद्रा श्रीर साख को यह बैंक किस प्रकार नियन्त्रित करती है, बंतलाइये। (Agra, B. A., 1958)
- 2. What are the functions of a Central Bank? How does it control the volume of currency and credit.

(Agra, B. Com., 1957)

- What are the main functions of the Central Bank? How does it co-ordinate currency and credit. (Alld., B., A., 1955)
- 4. What are the functions of a central bank? How does it control commercial banks? (Bihar, B. A., 1958)
- 5. How does a central bank control the volume of currency and credit in a country? (Sagar, B. A., 1958)
- 6. Show how the central bank of country controls credit? Point out the limitations on its power of controlling credit.

(Agra, B. A., 1956)

- 7. Explain Bank Rate and discuss its effects on the external and the internal situations of a country. Can it operate effectively in India? (Raj., B. Com., 1954)
  - 8. Write short note on: Bank Rate

(Agra, B. A., 1956 & 1955 Supp.; Raj., B. Com., 1956; (Agra, B. Com., 1958, 1956 & 1954)

Open Market operations (Agra, B. A., 1956 Supp.)

9. What is Bank Rate? Discuss the effects of changes of such a rate on industry and trade in a country.

(Agra, B. Com., 1957, 1956 Supp. & 1955)

- 10. केन्द्रीय अधिकोष देश की मुद्रा एवं साख नीति का नियंत्रण किस प्रकार करता है? (Sagar, B. Com., 1958)
- 11. केन्द्रीय अधिकोष के मुख्य कार्य क्या होते हैं ? केन्द्रीय अधिकोष व्यापारी अधिकोषों द्वारा निर्मित साख को राशि को कैसे नियंत्रित करता है।

(Sagar, B. Com., 1957)

- 12. केन्द्रीय बैंक से त्राप क्या सममते हैं ? उसके द्वारा साख का नियंत्रण किस प्रकार होता है ? (Jabalpur, B. A., 1958)
- 13. Examine the comparative importance of discount rate and open market operations as methods of credit control. State the reasons why the discount rate policy is less important today than what is was under the gold standard. (Agra, B. Com., 1953)
- .14. Enumerate the main difficulties in the way of and limitations to the central bank's power of controlling oredit.

(Bombay, B. Com., 1956)

- 15. How does a modern central bank control the quantity and quality of credit? (Bombay, B. Com., 1955)
- 16. Describe the chief functions of a central bank. Explain the methods by which the central bank controls the volume of credit. (Agra, B. Com., 1949; Raj., B. Com., 1952)
- 17. Discuss the objects and methods of credit control employed by a central bank.

किसीं केन्द्रीय श्रिधिकोष के साख नियंत्रण के उद्देश्यों एवं पद्धतियों की विवेचना की जिए। (Agra, B. Com., 1959)

18. केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णान कींजिए और बतलाइये कि यह साख का नियन्त्रण (क) बाजार में खुले रूप से कार्य करके तथा (ख) बैंक दर के द्वारा किस प्रकार करता है ? (Agra, B. A., 1950)

#### अध्याय १८

## अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

(The International Monetary Fund)

#### प्रारम्भिक-

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् संसार के प्रायः सभी देशों को माँद्रिक तथा विनिमय दर सम्बन्धी अस्थिरता का कटु अनुभव हुआ था। युद्धकालीन मुद्रा-प्रसार के कारण सभी देशों की आधिक व्यवस्था बिगड़ गई थी। विदेशी व्यापार में अनेक असुविधायें और बाधायें उत्पन्न हो गई थीं, जिससे उसकी मात्रा काफी ग्रंश तक घटं चुकी थी। कीमतों की उथल-पुथल के कारण केवल विदेशी व्यापार में ही नहीं, राष्ट्रों के आन्तरिक व्यापार में भी कठिनाइयाँ थीं। प्रत्येक देश दूसरे देशों के हितों पर ध्यान दिए बिना स्वार्थी आर्थिक नीति को अपनाता था। विनिमय अवमृत्यन तथा विनिमय नियन्त्रण सभी देशों की आर्थिक नीति के आवश्यक अंग वन गए थे और एक-दूसरे की देखा-देखी सभी देश एक-दूसरे का गला काटने पर तैयार थे देश काल में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के स्थान पर पारस्परिक स्पर्धा का ही जोर था और प्रत्येक देश दूसरों को घोखा देकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का गला घुटता जाता था और ग्रान्तरिक ग्रर्थ-व्यवस्था अस्थिरता के थपेड़ों से व्याकुल थी।

विस्तिन्देह ऐसी व्यवस्था का बना रहना राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हितों के लिए घातक था। श्रारम्म से ही कुळ देश अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की किसी समुचित योजना द्वारा इस समस्या को सुलमाने का प्रयत्न कर रहे थे, परन्तु दूसरे महायुद्ध के काल में तो इस दिशा में विशेष प्रयत्न किया गया। सभी जानते थे कि युद्धकालीन विष्वंस के कारण युद्धोत्तर-काल में आर्थिक पुनर्वासन तथा पुनिनर्माण की ऐसी गम्भीर समस्यायें उत्पन्न होंगी जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, विदेशी व्यापार के विकास तथा विभिन्न देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों के समुचित प्रवाह के बिना हल करना सम्भव न था। साथ ही, ऐसा भी अनुभव किया गया था कि आधुनिक युद्ध आर्थिक कारणों के ही परिणाम होते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के आर्थिक विकास-स्तरों में समानता लाए बिना तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की किसी समुचित योजना के कार्यरूप दिये बिना भविष्य में युद्ध की सम्भावना का अन्त करना सम्भव न था। युद्ध के काल में ही अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की योजनाओं

का निर्माण घ्रारम्भ हुग्रा । ब्रिटिश कोषागार, ग्रमरीकन सरकार तथा कनाडा ने इस सम्बन्घ में ग्रपनी-ग्रपनी योजनायें संसार के सम्मुख रखीं।

## अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना—

समस्या पर विचार करने के लिए जुलाई सन् १६४४ में अमरीकन सरकार ने ब्रेटन वुड्स (Bretton Woods) नामक स्थान पर एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा परिषद् वुलाई। इस परिषद् में ४४ मित्र राष्ट्रों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। परिषद् ने एक योजना को स्वीकार किया। परिषद् के सुभाव दो भागों में बाँटे गए हैं:—(i) पहले भाग में एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष, जिसे संक्षेप में मुद्रा-कोष (I. M. F.) भी कहा जाता है, की स्थापना का प्रस्ताव था। (ii) दूसरे भाग में इसी प्रकार एक अन्तर्राष्ट्रीय पुर्नीनर्माण तथा विकास बैंक, जिसे संक्षेप में विश्व बैंक (World Bank) भी कहा जाता है, की योजना प्रस्तुत की गई थी।

## **ब्रान्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य**—

कोष सम्बन्धी समभौते की घारा १ के अनुसार मुद्रा-कोष के उद्देश्यों को निम्न प्रकार बताया गया है:—

- (१) ''एक स्थाई संस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्नति करना....।
- (२) ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार ग्रौर संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना ग्रौर इस प्रकार सभी सदस्य देशों में रोजगार के ऊँचे स्तरों को स्थापित करना ग्रौर बनाये रखना......
- (३) विनिमय स्थिरता को उत्पन्न करना, सदस्यों के बीच नियमित विनिमय मय व्यवस्थाओं का बनाए रखना और प्रतियोगी विनिमय भ्रवमूल्यन को रोकना .....।
- (४) सदस्यों के बीच चालू व्यवसायों के सम्बन्ध में बहु-देशीय भुगतान प्रगाली की स्थापना करना तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटाने में उनकी सहायता करना.....
- (५) समुचित सुरक्षा के अन्तर्गत सदस्य देशों के लिए कोष के साधनों को उपलब्ध करके उनमें विश्वास उत्पन्न करना और इस प्रकार उन्हें, ऐसे उपायों को किए बिना, जो राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय वैभव को नष्ट करते हैं, अपने शोधनाशेष की अटियों को दूर करने का अवसर देना.....
- (६) उपरोक्त व्यवस्थाओं के अनुसार सदस्यों के अन्तर्राष्ट्रीय शोधनाशेष के असन्तुलन की अविध और उसके अंश को कम करना।"

#### श्रभ्यंश और चन्दे—

कोष के कुल साधनों का योग १,००० करोड़ डालर नियत किया गया है।

इसमें से विभिन्न सदस्य देशों के अभ्यंश निश्चित किये गये हैं। बड़े-बड़े देशों के अभ्यंश (Quotas) निम्न प्रकार हैं:—

	(करोड़ डालर में)		(करोड़ डालर में)	
संयुक्त राज्य श्रमरीका	२७४	चीन	ሂሂ	
ब्रिटेन	१३०	फांस	५२.५५	
रूस	१२०	भारत	४०	
कनाडा	, <b>₹</b> 0	ग्रास्ट्रे लिया	२०	
दक्षिणी ग्रफीका	१०	पाकिस्तान	१०	

इसी प्रकार अन्य सम्मिलित होने वाले देशों के चन्दे भी निश्चित कर दिये गए थे। जो देश परिषद् में सिम्मिलित नहीं हुए थे उनको वाद में मुद्रा-कोप की योजना में सिम्मिलित होने का अधिकार दिया गया था और उनका चन्दा मुद्रा-कोष निश्चित करता है। प्रत्येक ५ वर्ष पश्चात कूँ बहुमत से मुद्रा कोष किसी भी देश के अभ्यंश को बदल सकता है, परन्तु इसके लिए सदस्य देश की अनुमित आव- स्यक होती है। सदस्य की प्रार्थना पर भी चन्दे में परिवर्तन किए जा सकते हैं। प्रत्येक देश को अपने चन्दे का कुँ अथवा सरकारी स्वर्ण तथा डालर जमा का नैन्द्र सोने में देना होता है और शेष वह अपनी मुद्रा में दे सकता है। स्वर्ण के अतिरिक्त शेप चन्दा मुद्रा कोष के अभिकर्त्ता के रूप में सदस्य देश की केन्द्रीय वंक के पास ही रखा जाता है।

#### कोष का विधान तथा प्रवन्ध-

घारा १२ के अनुसार कोष के कार्य-संचालन के लिए एक गर्वनर मगडल (Board of Governors), कार्यकारिगी संचालक (Executive Director), प्रबन्धक डायरेक्टर तथा स्टॉफ होगा। कोष का दिन प्रति दिन का कार्य कार्यकारिगी संचालक समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति के १२ सदस्य होते हैं, जिनमें से ५ स्थाई और ७ अस्थाई होते हैं। प्रथम ५ उन पाँच बड़े-बड़े राष्ट्रों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जिनके अभ्यंश सबसे अधिक हैं, २ को नियुक्ति लेटिन अमरीका के देशों द्वारा की जाती है और शेष का अन्य सदस्य देशों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्त्व प्रणाली के अन्तर्गत निर्वाचन होता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य को २५० में प्रत्येक १ लाख डालर अभ्यंश या उसके भाग के साथ एक और मत का अधिकार होता है। आरम्भ में अमरीका, ब्रिटेन, रूस, चीन तथा फांस को स्थाई सदस्य नियुक्त करने का अधिकार था, किन्तु रूस के सदस्यता छोड़ने के पश्चात् भारत पाँचवे नम्बर पर आ गया है। कोई भी सदस्य देश साधारण सूचना देकर कोष की सदस्यता छोड़ सकता है। कोष का प्रधान कार्यालय अमरीका में हैं, परन्तु इसकी शाखारें सदस्य देशों में स्थापित की जा सकती हैं। संचालक समिति एक-मत प्रस्ताव द्वारा कोष के कार्य को अधिक से अधिक १२० दिन के लिए स्थिगत भी कर सकती है।

कोप का कार्यालय तथा संग्रहालय (Office and Depositories of the Fund)—

विघान के अनुसार कोष का प्रधान कार्यालय उस सदस्य देश में रहेगा जिसका अभ्यंश ( $Q_{ROM}$ ) सबसे अधिक है, अर्थात् संयुक्त राज्य अमरीका । शाखाएँ किसी भी सदस्य देश में खोली जा सकती हैं । मुद्रा-कोष के पास जो स्वर्ण रहता है उसका आघा ऐसे संग्रहालय (Depository) में जमा रहेगा जो सबसे बड़े अभ्यंश वाले देश द्वारा सूचित किया जायगा । शेष आधे का 50% अर्थात् कुल का ४०% उन चार देशों में रखा जायगा जिनके कोटे सबसे बड़े हैं ।

#### विभिन्न करैन्सियों की समता दरों का निर्धारण-

समभौते की घारा ४ के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश को अपने चलन की कीमत स्वर्ग अथवा अमरीकन डालर में ( जैसा कि वह १ जुलाई सन् १९४४ को था ) परि-भाषित करनी होती है। इस प्रकार प्रत्येक देश के चलन का स्वर्ण मुल्य निश्चित हो जाने के पश्चात विनिमय दरों के निर्घारण में कोई कठिनाई नहीं रहती है। इस प्रकार 🧺 टन वुड्स योजना के ग्रनुसार स्वर्ण के द्वारा विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की करैन्सियों के विनिमय की सम-मूल्य दर (Par values) निश्चित हो जाती है। किसी सदस्य द्वारा स्वर्ण के क्रय-विकय के लिये कोष इस तुल्यता (Parity) से एक अधिकतम और एक निम्नतम सीमा तय कर देता है, जिनके बीच में ही सदस्य अपनी करैन्सियों का ग्रवमूल्यन या अधिमूल्यन कर सकते हैं। इस प्रकार प्रतियोगी ग्रुवमूल्यन का भय दूर हो गया है और विनिमय दरों में अधिक स्थिरता आ गई है। एक बार निर्घारित की गई विनिमय दर में सदस्य देश की प्रार्थना पर १०% तक का परिवर्तन किया जा सकता है । इसमें कोष को इन्कार करने का अधिकार नहीं है। इसके पश्चात् कोष से श्राज्ञा लेकर सदस्य विनिमय दर में ग्रौर भी १०% का परिवर्तन कर सकता है, परन्तु कोष के लिए भ्राज्ञा लेना भ्रनिवार्य नहीं है। २०% से ऊपर के प्रत्येक परिवर्तन के लिए सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की अनुमति आवश्यक होती है। इस नियम का पालन करने पर कीय सदस्य देश की कीय के साधनों का उपभोग करने से रोक सकता है अथवा सदस्यता से हटा सकता है। अतः स्पष्ट है कि कींप ने विभिन्न राष्ट्रों को भ्रपनी भ्राधिक सामाजिक तथा ग्रन्य घरेलू समस्याभ्रों को हल करने के लिए समय-समय पर, ग्रपनी करेन्सी के विनिमय मूल्य में घटा-बढ़ी करने की आजादी दे रखी है ग्रोर प्रायः वह इस प्रकार की घटा-बढ़ी करने में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, किन्तु किसी भी देश को यकायक लाभ प्राप्ति अथवा किसी अन्य उहे इय को पूरा करने के लिए परिवर्तन करने का अधिकार न होगा। इस प्रकार अब स्पर्धात्मक विनिमय श्रवमूल्यन (Competitive Exchange Depreciation) की सम्मावना बहुत कम हो गई हैं। इस योजना का उद्देश्य ही यह है कि किसी देश की विनि-मय दर में परिवर्तन केवल उसके आन्तरिक मूल्य और आमदनी के स्तर के अनु-सार ही हो।

श्चारम्भ में भारत ने श्चपने रुपये का स्वर्णं मूल्य ०'२६ ६०१ ग्वाम विशुद्ध स्वर्णं निश्चित किया था। डालर में उसका मूल्य ३०'२५ सेन्ट रखा गया था। सन् १६४६ में उसने कोष की सहमति से श्चपनी करेन्सी में ३०'५% का श्रवमूल्यन किया था, जिससे रुपये का स्वर्णं मूल्य व डालर मूल्य क्रमशः ०'१ ६६६२१ ग्राम विशुद्ध सोना और २१ सेन्ट हो गया है।

#### सदस्यों को कोष से विदेशी विनिमय क्रयः श्रधिकार—

मुद्रा कोष के सदस्यों को कोष से विदेशी विनिमय खरीदने का अधिकार है। कोष के लिए यह ग्रनिवार्य है कि वह सदस्य देश की माँग होने पर उसकी मुद्रा ग्रौर स्वर्गा के बदले किसी अन्य देश की मूद्रा का प्रबन्ध करे। परन्तु इस सम्बन्ध में एक शर्त है। किसी भी समय कोष के पास उस सदस्य की मुद्रा की मात्रा उसके कोटे से २००% से भ्राधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी देश का २००% मि० डालर का कोटा है, जिसमें से उसने ५० मि० डालर का सोना व १५० मि० डालर की अपनी मुद्रा कोष को प्रदान की है। ग्रब यह देश मुद्रा कोप से २५० मि० डालर से ग्रधिक की मुद्रा नहीं ले सकेगा ( ४०० --- १५० = २५० )। इस प्रकार २५० मि० डालर की विदेशी मुद्रा के बढ़ने के बदले. जो कोष उस देश को देता है, कोप के पास उस देश की ४०० मि० (२५० + १५०) डालर की मुद्रा + ५० मि० डालर का सोना रहता है। सदस्य देश को यह लाभ है कि उसे केवल ५० मि० डालर का सोना रख कर ही २५० मि० डालर की विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाती है। इस क्रय के वारे में एक अन्य शर्त यह भी है कि कोई देश बारह महीनों के भीतर कोष से अपने चलन ( मुद्रा ) के बदले में अपने कोटे के २५% से अधिक नहीं खरीद सकता है। ऊपर दिये गये उदाहरण में वह देश किसी एक वर्ष में ५० मि० डालर से ग्रधिक विदेशी मुद्रा नहीं खरीद सकता । ये प्रतिबन्ध इसलिए लगाये गये हैं ताकि (i) कोष में अल्प मुदायें जल्दी समाप्त न हों ग्रौर (ii) सदस्य देश स्वयं ग्रपनी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न भी करें। किन्तू संकट या ग्रत्यधिक ग्रावश्यकता के काल में ये शतें ढीली की जा सकती हैं।

इस दृष्टिकोण से कि कोई भी सदस्य बिना त्रावश्यकता त्रथ्यना वार-बार कोष से विदेशी विनिमय न खरीदे, ऐसी व्यवस्था की गई है कि जैसे-जैसे मुद्रा-कोष का त्रष्टणा बढ़ता जाता है, त्रष्टणी सदस्य को निरन्तर बढ़ती हुई दूरों पर व्याज देना पड़ता है। यह दर है% से ब्रारम्भ होकर २ है% तक जाती है। कोष इस बात में बड़ा सतर्क रहता है कि उससे लिए गये ऋगों का उपयोग किसी ऐसे कार्य के लिए न किया जाय जोकि कोष के उद्देश्यों के विरुद्ध हो।

#### श्रन्य मुद्रायें—

आरम्भ में ही ऐसा अनुमान लगा लिया गया था कि युद्धोत्तर काल में कुछ मुद्राएँ दुर्लभ हो जायँगी और इस प्रकार ऐसी सम्भावना उत्पन्न हो जायगी कि मुद्रा कोष अपने ही साधनों द्वारा ऐसी मुद्राश्रों की माँग पूरी न कर सके । डालर के विषय में ऐसा अनुमान बहुत पहले से किया जा सकता था। इस स्थिति के लिए यह व्यवस्था की गई है कि जिस मुद्रा की मांग को कोष अपने साधनों में से पूरा नहीं कर सकता है उसे वह देश विशेष से उधार ले सकता है। यदि उधार नहीं मिलता है तो वह उसे सोना देकर खरीद सकता है, परन्तु यदि फिर भी मांग को पूरा करना सम्भव नहीं है तो कोष सदस्य देशों को मुद्रा विशेष की दुर्लभता के कारएगें की सूचना देकर उसकी प्राप्त पूर्ति का राशन कर सकता है और आँशिक रूप में सबकी थोड़ी-थोड़ी माँग पूरी कर सकता है।

#### कोष के साधनों की तरलता-

इस बात की सम्भावना रहती है कि ऋगी देश श्रपनी मुद्रा के बदले में श्रन्य मुद्रा खरीदते चले जायें, जिससे कोष के पास ऐसी मुद्राश्रों की पूर्ति बढ़ जाय, जिनकी माँग नहीं है और ऐसी मुद्राश्रों की पूर्ति समाप्त हो जाय जिनकी माँग बहुत है। यदि ऐसा हुश्रा, तो कोष एक रक्षित कोष का कार्य नहीं कर सकेगा। श्रतः साधनों में तरलता रखने के उद्देश्य से तीन उपाय रखे गये हैं:—(i) जो सदस्य देश स्वर्ण के बदले कोई विदेशी मुद्रा खरीदना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। (ii) यदि किसी सदस्य देश की मुद्रा कोष के पास उसके कोटे से श्रिषक है, तो वह देश श्रपनी श्रतिरक्त मुद्रा को कोष से सोना देकर खरीद सकता है। (iii) प्रत्येक सदस्य देश प्रति वर्ष स्वर्ण या परिवर्तनीय मुद्रा के बदले कोष के पास जितनी उसकी मुद्रा है उसका कुछ भाग पुनः खरीदेगा। इस पुनः खरीदने के नियम द्वारा ही कोष के साधन तरल श्रवस्था में बने रहते हैं।

#### . सदस्यों पर प्रतिबन्ध-

मुद्रा कोष इस विषय में बड़ा सतर्क रहता है कि उससे उघार ली हुई राशि का समुचित उपयोग हो और साथ ही कोष के अन्य उद्देशों की भी पूर्ति हो। इस बात को घ्यान में रखकर सदस्यों पर निम्न प्रतिबन्ध लगाए गये हैं:—(i) कोष से आज्ञा प्राप्त किए बिना कोई भी सदस्य देश अपनी मौद्रिक नीति को नहीं बदल सकता है। (ii) कोई भी सदस्य देश केवल कोष द्वारा निर्धारित दरों पर ही स्वर्ग खरीद अथवा वेच सकता है। (iii) प्रत्येक देश केवल कोष द्वारा निर्धारित विनिमय दरों पर ही विदेशी विनिमय व्यवसाय कर सकता है। (iv) सदस्य देशों को चालू अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के सम्बन्ध में भुगतान सम्बन्धी किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार नहीं है। ( $\nabla$ ) कोष से उधार ली हुई राशि का उपयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता है कि वह कोष के उद्देश्य के विपरीत हो।

#### मुद्रा कोष में स्वर्ण का स्थान-

े किसी भी सदस्य देश को स्वर्णमान स्थापित करने पर बाध्य नहीं किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को केवल भ्रपने चलन का स्वर्ण-मूल्य घोषित करना होता है। स्वर्ण

कीमतों के सामूहिक मापक का कार्य करता है और प्रत्येक देश को निश्चित कीमतों पर सोने को खरीदने और बेचने का वायदा करना पड़ता है। मुद्रा-कोप की व्यवस्था के स्वर्ण से तीन सम्बन्ध हैं:—(i) प्रत्येक सदस्य को अपने अभ्यंश का एक भाग स्वर्ण में देना होता है। (ii) प्रत्येक सदस्य देश को चलन का प्रारम्भिक मूल्य स्वर्ण में निर्धारित करना होता है और (iii) किसी मुद्रा की दुर्लभता की दशा में उसे स्वर्ण में खरीदने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त कोप नियत दरों पर सोना खरीदने को सदा तैयार रहता है।

क्या कोष का निर्माण स्वर्णमान पर वापिस त्राना है ? कुछ ग्रर्थशास्त्रियों ने कोष का निर्माण स्वर्णमान पर वोपिस म्राना (Return to Gold Standard) कहा है: क्योंकि कोष योजना ग्रीर स्वर्णमान में निम्न समानतायें हैं:—(i) स्वर्ण-मान वाले देशों की तरह ही इस कोष में भी दिभिन्न देशों की करैन्सियों के मध्य प्रारम्भिक विनिमय दर स्वर्ण के ग्राधार पर ही तय की जाती है। (ii) कोप की योजना में भी स्वर्ण का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है (ऊपर पिंड्ए), ग्रतः इस योजना में स्वर्ण का श्रमुद्रीकरण (Demonetisation) नहीं किया गया है। (iii) स्वर्णमान में एक देश ग्रपनी लेन-देन की बाकी का संतुलन सारे संसार से एक बार में ही करता है। इसी तरह कीष प्रगाली भी प्रत्येक देश से अलग-अलग समन्वय कराके बहुपक्षी भूगतान पद्धति को बढ़ावा देती है, क्योंकि कोष द्वारा निश्चित सम-मूल्य दरों पर मद्राभ्रों को बदला जा सकता है। (iv) वह देश जो कोष से भ्रन्ततः विदेशी मुद्राभ्रों का खरीदने वाला है उसकी अवस्था स्वर्णमान में एक स्वर्ण खोने वाले देश के समान होती है, जबिक कोष को अन्ततः अपनी मुद्रा बेचने वाले राष्ट्र की स्थिति स्वर्णमान में स्वर्ण प्राप्त करने वाले देश के समान होती है। विदेशी मुद्रा खरीदने वाले देश में मुद्रा संकूचन के और अपनी मुद्रा बेचने वाले देश में मुद्रा प्रसार के लक्षरा प्रगट होने लगते हैं। (▽) स्वर्णमान के ग्रन्तर्गत तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के ग्राघार पर व्यापार होता है. जिसमें कोई विशेष बाघा नहीं पड़ती है, किन्तु योजना के अन्तर्गत फिलहाल परिवर्तनकाल में विनिमय नियन्त्रणों से विदेशी व्यापार में रुकावट पड़ेगी, किन्तु कोष को म्राशा है कि विभिन्न राष्ट्र इन नियन्त्रणों को शीघ्र हटा लेगें भ्रौर तव विदेशी व्यापार तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त से ही कम ग्रधिक मात्रा में नियन्त्रित होने लगेगा ।

यद्यपि कोष योजना में स्वर्णमान के अनेक गुरा हैं तथापि वह पूर्ण रूपेण स्वर्णमान नहीं है और यह कहा जा सकता है कि कोष का निर्मारा स्वर्णमान पर आना है, क्योंकि इस योजना में स्वर्णमान के दोष नहीं हैं, जैसे—(i) स्वर्णमान में विनिमय दर अत्यन्त निश्चित (Rigid) सी होती है और उसे स्वर्ण के आयात-निर्यात द्वारा कायम रखा जाता है, लेकिन कोष योजना के अन्तर्गत परिस्थिति बदलने पर विभिन्न राष्ट्र कुछ सीमा तक विनिमय दर बदल सकते हैं। (ii) स्वर्णमान में प्रत्येक देश को अपना आन्तरिक मूल्य-स्तर अन्य देशों के समान रखना पड़ता है और स्वर्ण

के आयात निर्यात द्वारा परस्पर लेनी-देनी का सन्तुलन रखा जाता है, जिससे साख संकुचन एवं साख प्रसार का सिलसिला चलता है, लेकिन कोष योजना के अन्तर्गत प्रत्येक देश अपनी आन्तरिक आर्थिक नीति के बारे में स्वतन्त्र रहता है और कोष की सहायता से, अपनी साख व्यवस्था को प्रभावित किये बिना, अन्य देशों से अपनी लेना-देना नियत कर लेता है।

#### श्राय का वितरग-

मुद्रा कोष को जो ग्राय प्राप्त होती है उसका २% उन देशों में बाँट दिया जाता है जिनकी चलन के दूसरे देशों द्वारा उधार लिए जाने के कारण कोष के पास उनकी चलन का संचय उनके ग्रम्यंश के ७५% से कम रह गया हो। शेष ग्राय सदस्य देशों के बीच उनके ग्रम्यंशों के ग्रनुपात में बाँट दी जाती है। मुद्रा-कोष प्रत्यैक सदस्य देश को लाभ का हिस्सा देश विशेष के ही चलन में चुकाता है।

#### कोष का कार्य-त्तेत्र--

मुद्रा-कोष को निजी संस्थाओं तथा व्यक्तियों के साथ व्यवसाय करने का अधिकार नहीं दिया गया है। एक सदस्य देश कोष के साथ केवल अपनी केन्द्रीय बेंक, स्थिरता कोष (Stabilization Fund) अथवा अन्य किसी मौद्रिक संस्था के द्वारा ही व्यवसाय कर सकता है और इसी प्रकार मुद्रा कोष भी इन्हीं संस्थाओं के द्वारा व्यवसाय कर सकता है। कोष को शोधनाशेष के सन्तुलन के लिये सदस्य देश की भीतरी अर्थव्यवस्था में हस्तद्धीय करने का अधिकार नहीं है। कोष अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की एक अच्छी संस्था है और यह सदस्य देशों को ऋण के रूप में सहायता देकर उनके शोधनाशेष के घाटे को दूर करता है, परन्तु कोष केवल अल्प-कालीन अप्टण ही दे सकता है और वे भी केवल व्यापाराशेष के अस्थाई असंतुलन को दूर करने के लिए।

# संक्रान्तिकालीन सुविधायें (Facilities during the Transitional Period)—

श्र-तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष विदेशी विनिमय तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी सभी प्रतिवन्धों के विरुद्ध है, परन्तु सदस्य देशों को संक्रातिकाल में विनिमय नियंत्रण, संरच्चण तथा श्रन्य प्रतिबन्धों के बनाने रखने का श्रिधकार दिया गया है, यद्यपि यह ग्राज्ञा प्रकट की गई है कि प्रत्येक सदस्य इन्हें शीघ्र से शीघ्र हटाने का प्रयत्न करेगा। संक्रान्तिकाल के ग्रन्त की घोषणा पर सदस्य देशों को ग्रनिवार्य रूप में सभी प्रतिबन्ध हटाने होंगे। प्रत्येक देश को यह ग्रधिकार है कि प्रत्येक प्रतिबन्ध की भावस्यकता ग्रथवा वाँछनीयता कोष के सम्मुख रखे ग्रीर नियन्त्रण के सम्बन्ध में ग्रपने विचार प्रस्तुत करे। किन्तु कोष तथा सदस्य के बीच नियन्त्रण के सम्बन्ध में मतभेद होने की दशा में सदस्य देश को सदस्यता छोड़नी पड़ेगी।

#### सदस्यता का परित्याग—

कोई भी सदस्य देश किसी भी समय लिखित सूचना देकर कोप की सदस्यता का परित्याग कर सकता है। कोष को त्याग-पत्र ग्रस्वीकार करने का ग्रधिकार नहीं है। त्याग-पत्र उसी समय से कार्यशील समका जायगा जबिक वह कोंप को प्राप्त हुआ है। कोष के नियमों का पालन न करने श्रथवा आदेशों का उलंघन करने की दशा में सदस्यता समाप्त भी की जा सकती है।

#### कोष व बैंकिंग कोष—

जिस प्रकार किसी देश का केन्द्रीय बैंक वहाँ की अन्य सब बैंकों का बैंक होता है उसी प्रकार विश्व की समस्त केन्द्रीय बैंकों का बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। केन्द्रीय बैंक में भ्रन्य बैंकों के रक्षित कोष एकत्रित रखे जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी सदस्य देशों के केन्द्रीय बैंक के साधनों को एक जगह एकत्र कर लेता है। किन्तु कोष और केन्द्रीय बैंकों में निम्न अन्तर भी हैं:—(i) केन्द्रीय बैंक तो एक ही प्रकार की (स्वदेशी) मुद्रा एकत्र करता है, लेकिन मुद्रा कोप विभिन्न देशों की मुद्राओं का कोष रखता है। (ii) मुद्रा कोष केन्द्रीय बैंकों की तरह किसी नई मुद्रा का निर्माण नहीं कर सकता है। (iii) मुद्रा कोष का अपने सदस्य देशों की आन्तरिक आधिक नीति का निर्धारण करने में कोई हाथ नहीं होता है, जबिक केन्द्रीय बैंक सदस्य व्यापा-रिक बैंकों की साख नीति पर पूर्ण नियन्त्रण रखती हैं।

#### मारत श्रौर मुद्रा कोष—

ञ्चन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा परिषद् में भारत ने ञ्चपनी ञ्चोर से ही दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे:—(i) यह कि भारत को मुद्रा-कोष की कार्यकारिगाी में स्थाई स्थान दिया जाय ग्रौर ( ii ) यह कि भारत के पौंड-पावना ऋ गों को मुद्रा-कोप के कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित किया जाय। ये दोनों ही प्रस्ताव ग्रस्वीकार कर दिए गए थे इसलिए भारत ने सदस्यता प्राप्त करने में भारी संकोच किया। बाद को रूस के निकल जाने के कारण भारत की पहली माँग स्वयं ही पूरी हो गई ऋौर दूसरी मॉॅंग के सम्बन्ध में भी बिटेन से सन्तेषजनक समभौता हो गया। प्रक्टबर सन १९४६ में भारत ने कोष की प्रारम्भिक सदस्यता प्राप्त कर ली। कोप की योजना में सम्मिलित होने से भारत को लाभ ही हुम्रा है। कोष की सदस्यता के द्वारा उसे विश्व बैंक की भी सद्स्यता प्राप्त हो गई, जिसने उसकी विकास योजनाम्रों को काफी सहायता दी है। सन् १६४ द-४६ में भारत का व्यापाराशेष सम्बन्धी घाटा बहुत था। मार्च सन् १९४८ ग्रौर मार्च सन् १९४९ के बीच में भारत ने कोष से ६.२ करोड़ डालर का ऋगा लिया था। अप्रैल सन् १९४९ में उसने अपना समस्त अधिकृत डालर ऋगा प्राप्त कर लिया था ग्रीर एक विशेष संकट के ग्राधार पर कोष से शर्तों को ढीला करने की प्रार्थना की थी। कोष ने यह प्रार्थना भी स्वीकार कर ली थी। वास्तविकता यह है कि भारत ने कोष की सुविधात्रों का त्र्यधिकतम् उपयोग करने की ख्याति प्राप्ति की है। कोष की सदरयता के पश्चात् भारत ने रुपये-स्टर्लिङ्ग का वैद्यातिक गठवन्यन तोड़ दिया है और द अप्रैल सन् १६४७ को रुपये की कीमत स्वर्णं में नियत कर दी गई है। कोष ने इङ्गलैण्ड की भांति भारत को भी सन् १६४६ में अवमूल्यन की आज्ञा दे दी थी। अवमूल्यन के पश्चात् हमारे व्यापाराशेष में काफी सुवार हुआ है और हमने अपना ऋगा काफी ग्रंश तक चुका दिया है। भारत को केवल यही भय था कि कोष की सदस्यता के कारणा शायद उसे अपनी उद्योग-संरद्मण नीति को छोड़ना पड़े, परन्तु संकान्ति काल में मुद्रा कोष ने व्यापारिक प्रतिवन्धों को लगाने की त्राज्ञा दे दी है।

मारत समय-समय पर श्रान्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋ्राण लेता रहा है। दूसरी योजना के काल में कुछ कारणों से कोधनाशेष का घाटा बहुत बढ़ गया है, अतः भारत ने जनवरी सन् १६५७ में कोष से १२'७५ करोड़ डालर के ऋण की बात तय की। पिछले साल में भारत ने मुद्रा-कोष से निम्न प्रकार ऋण लिए हैं:— जनवरी से मार्च सन् १६५७ के ३ महीनों में ६०'७ करोड़ रुपये के ऋण और अप्रैल से जून सन् १६५७ के ३ महीनों में ३४'५ करोड़ रुपयों के ऋण। उसके बाद अभी और ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जनवरी और मार्च सन् १६५७ में ६ करोड़ रुपये के ऋण का भारत ने भुगतान भी किया था।

कोप का सदस्य होने के नाते भारत के रुपये का सम-मूल्य (Par value) स्वर्ण तथा डालर में कमशाः ०'१८६६२१ ग्राम विशुद्ध सोना तथा २१ सेन्ट रखा गया है । प्रवमूल्य से पूर्व यह मूल्य क्रमजाः ०'२६६६१ ग्राम स्वर्ण तथा ३०'२५ सेन्ट था। ग्रव रिजर्व वैंक को कोष द्वारा निर्धारित विनिमय दरों पर विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय २ लाख रुपये से कम राजि का नहीं हो सकता है।

#### भारत को कोष से लाम-

भारत को कोष का सदस्य बन जाने से निम्न लाभ हुए हैं :--

- (१) भारत को आवश्यकतानुसार विदेशी मुद्रायें मिलने लगी हैं, जिससे वह अपने आधिक विकास के लिए आवश्यक पूँजीगत सामान विदेशों से ने सकता है।
- (२) रुपया स्टिलिङ्ग की परम्परागत दासता से मुक्त हो गया है। उसका सम्बन्ध स्वर्ण से हो जाने पर वह किसी भी देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार अब ग्र-स्टिलिङ्ग क्षेत्रों से भी व्यापार में सुविधा हो गई है।
- (२) भारत कोष की नीति के निर्धारण में भाग लेता है, क्योंकि रूस द्वारा सदस्यता ग्रस्वीकार कर देने से संचालन मंडल में पाँचवाँ स्थान भारत को मिल है।
  - (४) त्रान्तरिक त्रार्थिक समस्यात्रों पर भी कोष से परामर्श मिलता

रहता है, जैसे स्रभी हाल में पंचवर्षीय योजनास्रों की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में कोष ने भारत को महत्त्वपूर्ण सुभाव दिये थे।

(५) भारत ऋन्तर्राष्ट्रीय वैंक का सदस्य भी वन सका है और इस वैंक से भारत को विकास कार्यों के लिये ऋगा प्राप्त हये।

कुछ लोगों ने कोष की सदस्यता से भारत को कितपय हानियों का भी उल्लेख किया है, जैसे—(i) कोष ने भारतीय पौंड पावनों के भुगतान के लिए सुविधा नहीं दी है।(ii) भारत का कोटा उसकी प्राप्त होने वाले लाभ से ग्रधिक रखा गया है ग्रीर (iii) भारत बिना जनता या विधान मण्डलों की स्वीकृति के कोष का सदस्य बना है। किन्तु ये श्राक्षेप लाभों को देखते हुए ग्रमहत्त्वपूर्ण है।

#### मुद्रा-कोष की त्रालोचनाएँ —

कोष की सन् १६५० की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि कोप के कार्यों का बराबर विस्तार हो रहा है, परन्तु इस समय कोष से पहिले की तुलना में कम ऋरण लिए जा रहे हैं, अधिकाँश ऋरण डालर में लिए गये हैं। सन् १६५४-५५ में सदस्य देशों ने केवल ४'६ करोड़ डालर के ऋरण लिये थे, यद्यपि इसी वर्ष में ७'६ करोड़ डालर के पुराने ऋरणों का भुगतान किया गया था। रिपोर्ट में वताया गया था कि मार्च सन् १६४७ से लेकर, जबिक कोष ने कार्य आरम्भ किया था, सन् १६५४-५५ के अन्त तक कोष में से कुल ११६'७ करोड़ डालर के ऋरण लिये गये थे, जिनमें से ६०'६ करोड़ डालर का भुगतान हो चुका था। साधारणतया कोष का कार्यवाहन सन्तोषजनक ही रहा है और इसने व्यापाराशेष के घाटे को दूर करने में काफी सहा-यता दी है।

इसमें तो सन्देह नहीं है कि कोष की सफलता की सूची काफी लम्बी है, परन्तु सैंद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दोनों ही हिष्टकोगों से कोष की काफी ग्रालोचना की जा सकती है। कोष की प्रमुख ग्रालोचनायें निम्न प्रकार हैं:—

'(१) मुद्रा कोष का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है—कोप केवल चालू सौदों से सम्बन्धित विदेशी विनिमय की समस्याओं को सुलक्षाने का प्रयास करेगा। युद्ध ऋएा, पूँजी का ग्रायात-निर्यात, समावरुद्ध स्टींलग (Blocked Sterling) ग्रादि के भुगतान के सम्बन्ध में राष्ट्रों को ग्रन्य उपाय करने होंगे। इस प्रकार कोष की उपयोगिता कम हो जाती है। [किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोष को ग्रारम्भ से ही इन जटिल समस्याओं को सुलक्षाने का कार्य सौंप दिया गया होता, तो कोष-योजना बहुत शीघ्र ही ग्रसफल हो जाती। ग्रतः उक्त ग्रालोचना सही नहीं है।]

'(२) मुद्रा कोष का चन्दा किसी भी वैज्ञानिक ग्राधार पर निश्चित नहीं किया गया है—चन्दा या तो विभिन्न देशों की विदेशी व्यापार की मात्रा के ग्राधार पर हो सकता था या व्यापाराशेष की स्थिति के ग्राधार पर ग्रीर या विदेशी विनिमय की ग्रावश्यकता के ग्राधार पर, परन्तु इनमें से किसी को भी ग्राधार नहीं बनाया गया है। ऐसा मालूम होता है कि अंग्रेजों श्रीर अमरीकनों के आधिक श्रीर राजनैतिक स्वार्थों को घ्यान में रख कर चन्दा निर्धारित किया गया है। इसका परिगाम शीघ्र ही रूस के त्याग-पत्र के रूप में सामने आया है और कोष को समाजवादी राष्ट्रों की सदस्यता प्राप्त नहीं हो सकी है।

- (३) ऋगों के प्रदान करने और आवश्यक सुविधाओं के देने में कोष ने भेद-भाव किया है—फान्स द्वारा कोष की आज्ञा के विरुद्ध अवसूल्यन करने पर भी कोई कड़ी सजा उसे नहीं दी गई है। यह सन्देह है कि मुद्रा-कोष अमरीकन सरकर की कठपुतली है।
- (४) मुद्रा-कोप की कार्यकारिगाी की सदस्यता दोषपूर्ग है—मुद्रा-कोष की कार्यकारिगाी की सदस्यता इस प्रकार रखी गई है कि ग्रमरीकन हितों की रक्षा होती रहे, इसीलिए लेटिन ग्रमरीका के देशों के लिए दो स्थान सुरक्षित रखे गये हैं।
- (५) कम उन्नत देशों पर पिश्चमी देशों के दबाव का भय—भय यह है कि भविष्य में पिश्चमी देश अपने आधिक हितों की उन्नति के लिए व्यापारिक प्रतिबन्धों को तोड़ने पर जोर देंगे। कम उन्नत देशों के लिए यह लाभदायक न होगां और इस कारण दोनों में खींच-तान रहेगी। शायद कम उन्नत देशों को कोष की सदस्यता ही छोड़नी पड़े।
- ' (६) डालरों की अल्पता की सम्भावना—इसका कारण स्पष्ट है कि अमेरिकन निर्यात के लिए कोष के डालर जायेंगे, लेकिन अमेरिकन आयातकर्ताओं को दिये जाने वाले डालर कोष को नहीं मिलेंगे। अतः जो देश अमेरिका को माल भेजेंगे वे कोष के वाहर बहुत अधिक मात्रा में डालर एकत्र कर लेंगे, क्योंकि वहाँ के निर्यातकर्ता स्वदेश की मुद्रा के बजाय डालर में ही बीजक बनावेंगे। इस तरह डालर की अल्पता होने के कारण कोष को अपने कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ भी यह स्मरणीय है कि डालरों की समाप्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के दृष्टिकोण से ही कोष के विधान में यह आयोजन किया गया है कि वह डालरों का पुनः क्रय कर सकता है और राशनिंग की योजना अपना सकता है, जिससे योजना चलती रहे, टूटे नहीं। सद्भा-कोष की सफलताएँ—

मुद्रा कीप की स्थापना से निम्न लाभ हुए हैं :—

- (१-) इसके द्वारा बहुपद्ती व्यापार बहुपद्ती मुगतान की व्यवस्था सम्भव हो सकी है, जिससे विदेशी व्यापार ग्रौर विनियोग के लिए पूँजी के ग्रावागमन को बढ़ावा मिला है।
- (२) कोष के पास विभिन्न देशों की मुद्राश्चों का रिक्तित कोष रहता है, जिससे वह इनका क्रय-विक्रय करके सदस्य देशों की ग्रावश्यकतानुसार विदेशी विनिमय की पूर्ति करता रहता है, और उन्हें बराबरी के ग्रावार पर ग्रपने शोधनाधिक्य के असन्तुलन को दूर करने का ग्रवसर देता है।

- (३) विनिमय दर में ऋव ऋपेताऋत ऋधिक स्थायित्त्व रहने लगा है, ग्रस्थाई कारणों से घटा बढ़ी नहीं होने पाती है तथा म्रान्तरिक नीतियों में भी हस्तक्षेप नहीं होता ।
- (४) कोष के निर्माण से विश्व को स्वर्णमान की स्थापना के विना स्वर्ण-मान के लाभ प्राप्त हो गये हैं।

#### QUESTIONS

Write a note on :- International Monetary Fund.

(Agra, B. A., 1958, 57; Raj., B. Com., 1958; Alld., B. A., 1955)

- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष को स्थापना किन उद्देश्यों से की गई थी ? इस मुद्रा-कोष के कार्यों का विवेचन कीजिए। (Agra, B. A., 1957 Supp.)
- India's admission to the International Monetary Fund marks the inauguration of a new currency standard for India. Explain carefully and examine the existing Indian currency (Agra, B. A., 1956) system.
- What are the principal objectives of the International Monetary Fund and how does the Fund seek to accomplish (Agra, B. A., 1955 Supp.)
- Briefly discuss the working of International Monetary Fund' (अन्तर्राष्ट्रीय मुदा-कोष) and explain how far it has succeeded in its objects. (Raj., B. A., 1958, 57)
- Explain the objects and functions of International Monetary Fund. How does the Fund seek to stabilise foreign (Raj., B. Com., 1954) exchange rates? Explain.
- श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (I. M. F.) पर एक संन्निप्त तथा परिपूर्ण टिप्पणी लिखिए और उसकी तुलना अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ग-प्रमाप से कीजिए। (Sagar, B. Com., 1955)
- What is the International Monetary Fund and how does it function? Show what benefit India has derived from this Fund.

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है ? और यह किस प्रकार कार्य करता है ? इस कोष से भारत को क्या लाभ हुआ है समकाइये। (Agra, B. A, 1959)

#### अध्याय १६

## अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक

(International Bank For Reconstruction and Development)

#### उद्देश्य---

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा परिषद् की रिपोर्ट के दूसरे भाग की घारा १ के अनुसार विश्व बेंक के उद्देश्य निम्न प्रकार है:—

- (१) राष्ट्रों का पुर्नीनर्माग् व म्राधिक विकास—युद्ध विष्वंसित सदस्य देशों की म्रर्थ-व्यवस्थाम्रों के पुर्नीनर्माग् तथा विकास में सहायता देना, युद्धकालीन म्रर्थ-व्यवस्था में शान्तिकालीन समायोजनों को सफल बनाना म्रौर म्रविकसित देशों के विकास में सहायता प्रदान करना।
- (२) पूंजी के विनियोग को बढ़ावा देना—ऋगों की गारन्टी लेकर अथवा उनमें सम्मिलत होकर व्यक्तिगत विदेशी ऋगों का विस्तार करना और यदि व्यक्तिगत ऋग उपलब्ध नहीं हैं तो उत्पादन कार्यों के लिए समुचित शर्तों पर अपने पास से ऋग देना।
- (३) दीर्घकालीन श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना—विदेशी व्यापार की दीर्घकालीन सन्तुलित उन्नति की व्यवस्था करना श्रौर इस प्रकार सदस्य देशों में उपज, जीवन-स्तर तथा श्रीमकों की कार्य-दशाओं को उन्नत करना।
- (४) शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्था स्थापित करना—युद्धोत्तर काल में अन्तर्राष्ट्रीय विनियोगों को बढ़ाना और शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्था के लिए समुचित दशाएँ उत्पन्न करना।

#### विश्व बैंक के चन्दे-

बैंक की ग्रिधिकृत पूँजी १,००० करोड़ डालर है। इस पूँजी को १-१ लाख डालर के ग्रंशों में बाँटा गया है। प्रमुख देशों के ग्रभ्यंश निम्न प्रकार हैं:—

भ्रमरीका २४३'५ करोड़ डालर फ्राँस ४५ करोड़ डालर इङ्गलैंड १००'० ,, भारत ४० ,, चीन ६०'० ,,

प्रत्येक देश के चन्दे को दो भागों में बाँटा गया है :—२०% चन्दा माँगने पर तुरन्त ही देना पड़ता है। शेष ५०% उस समय देना पड़ता है । शेष ५०%

पड़ने पर बैंक उसे माँगती है। अभ्यंश का २% स्वर्ण अथवा अमरीकन डालर में लिया जाता है और शेष १६% सदस्य देश अपनी मुद्रा में दे सकता है। जब और अधिक चन्दे की माँग की जाती है तो सदस्य देश को यह अधिकार होता है कि वह उसे स्वर्ण, डालर अथवा बैंक द्वारा आदेशित किसी अन्य मुद्रा में चुका दे। ऐसी मुद्रा की बैंक समय-समय पर घोषग्णा करती रहती है।

#### वैंक का कार्य--

बैंस को व्यक्तियों श्रोर व्यक्तिगत संस्थाश्रों के साथ प्रत्यक्त व्यवसाय का श्रिषिकार नहीं हैं। वह केवल सदस्य देश की सरकार द्वारा ही व्यवसाय कर सकती हैं। स्मरण रहे कि मुद्रा-कोष की भाँति विश्व वैंक में सदस्यों को प्राप्त होने वाले ऋणों की मात्रा उनके चन्दों पर निर्भर नहीं होती है। चन्दे तो केवल उत्तर-दायत्त्वों तथा शासन शक्तियों की ही सीमाएँ निहिचत करते हैं। बैंक का उद्देश्य यह भी नहीं हैं कि व्यक्तिगत विदेशी ऋणों के स्थान पर अपनी श्रोर में ऋणा दे। इसके विपरीत यह तो व्यक्तिगत ऋणों को प्रोत्साहन देती है। अपने पास से तो बेंक केवल उसी दशा में ऋण देती है जबिक व्यक्तिगत ति व्यक्तिगत ऋणों की गारंटी ली जाती है उन पर भी जे सिम उठाने का कमीशन लिया जाता है। गारंटी ली जाती है उन पर भी जे सिम उठाने का कमीशन लिया जाता है। गारंटी लेने से पहले बेंक यह देख लेती है कि ऋण लेने वाले की माँग कहाँ तक वास्तविक है और देने वाले की शतें कहाँ तक उचित प्रथवा न्यायपूर्ण हैं। ऋणों की गारंटी श्रथवा उनके प्रदान करने के सम्बन्ध में बेंक की शतें निम्न प्रकार होती हैं:—

- (१) जबिक बैंक को यह सन्तोष है कि प्रस्तुत दशाग्रों में ऋएा लेने वाले के लिए ग्रन्य सूत्रों से ऐशी शर्तों पर ऋएा मिलने की सम्भावना नहीं है जो बैंक के दृष्टिकोएा से उचित हैं।
  - (२) जबिक वही देश जिसकी सीमा में ऋगा का उपयोग होता है, स्वयं ऋगा नहीं लेता तो सदस्य देश अथवा उसकी केन्द्रीय बैंक को ऋगा के मूलघन, ब्याज तथा अन्य खर्चों के चुकाने की गारन्टी देनी पड़ती है।
  - (३) जबिक बैंक द्वारा नियुक्त की हुई कोई उपयुक्त सिमिति ऋगा देने के प्रस्ताव का समर्थन करती है।
  - (४) यदि बेंक के विचार में ब्याज की दर तथा ग्रन्य शतें उचित हैं ग्रौर उसके तथा मूलधन के चुकाने की रीति उपयुक्त है।
  - (१) गारन्टी देते समय बैंक ऋएा लेने वाले, ऋएा देने वाले तथा समस्त सदस्यों के हित को देखती है।
  - (६) बैंक द्वारा दिये गये भ्रथवा गारन्टी किये गये ऋरण कुछ विशेष दशाभ्रों

को छोड़कर केवल पुनर्तिर्माण अथवा विकास योजनाओं पर ही व्यय किये जा सकते हैं।

विश्व बैंक बहुदंशीय निकासी तथा व्यापार के आघार पर कार्य करती है। प्राप्त ऋगों के द्वारा किसी भी देश से माल खरीदा जा सकता है। प्रत्येक सदस्य को अनुकूलतम् बाजार से माल खरीने का अवसर मिलता है। इसी प्रकार जब तक ऋगा का उपयोग बैंक के उद्देशों के विरुद्ध नहीं किया जाता है, सदस्य द्वारा ऋगा के व्यय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है।

#### विधान श्रौर प्रवन्ध-

बंक के प्रबन्ध के लिए (i) एक गर्वनर मग्डल, (ii) एक कार्यकारिगी सिमिति, (iii) एक अध्यक्त त्या (iv) अन्य कर्मचारी होते हैं। बेंक का संचालन अधिकार गर्वनर मण्डल के हाथ में होता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य का एक-एक प्रतिनिधि रहता है। दिन प्रति दिन का कार्य कार्यकारिगी सिमिति करती है, जिसमें १२ सदस्य होते हैं। ५ सदस्य पाँच बड़े-बड़े अभ्यंश वाले देशों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और शेष ७ मुद्रा कोष की भाँति प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं, जिसमें प्रत्येक सदस्य को २५० मत तथा १ लाख डालर चन्दे के पीछे एक और मत प्राप्त होता है। कार्यकारिगी सिमिति अध्यक्ष को नियुक्त करती है, जो कि न तो कार्यकारिगी का सदस्य हो सकता है और न गवर्नर मण्डल का। इसके अतिरिक्त गवर्नर सिमिति कम से कम सात सदस्यों की एक (v) सलाहकार सिमिति का भी निर्वाचन करती है। जब किसी ऋगा का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होता है तो समुचित जांच के लिए बेंक एक विशेषज्ञ सिमिति नियुक्त करती है। कोई भी सदस्य मुद्रा-कोष की सदस्यता को त्याग कर अथवा लिखित त्याग-पत्र देकर बैंक की सदस्यता को छोड़ सकता है। स्मरण रहे कि केवल वही देश विश्व बैंक का सदस्य बन सकता है जिसने पहले मुद्रा-कोष की सदस्यता प्राप्त कर ली हो।

#### भारत और विश्व बैंक-

भारत ने विश्व बैंक की प्रारम्भिक सदस्यता प्राप्त कर ली थी। वैंक की सदस्यता से भारत को काफी लाभ हुआ है। अब तक भारत को विश्व बैंक से नौ ऋए प्राप्त हुए हैं। अगस्त सन् १६४६ में भारत को रेलवे विकास के लिए ३'४ करोड़ डालर का ऋए। मिला था। तत्पश्चात् सितम्बर सन् १६४६ में कृषि विकास के लिए १ करोड़ डालर और अप्रैल सन् १६५० में १'६५ करोड़ डालर का ऋए। नदी-घाटी योजनाओं के लिए प्राप्त हुआ। इसके बाद दामोदर घाटी योजना के लिए भी एक और ऋए। प्रदान किया गया। इन ऋए।ों में से ४'२ करोड़ डालर भारत ने सन् १६५१-५२ से पूर्व ही निकाल लिया था। शेष को कोलम्बी योजना में सम्मिलित कर लिया गया था। सन् १६५५ तक भारत को विश्व बैंक से १२'५० करोड़ डालर का ऋए। मिल खुका है, जिसमें से लगभग आधी राशि भारत निकाल चुका है। विश्व बैंक के ऋए।ों

के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई यह है कि ऋएा की रकम केवल उसी निश्चित उद्देश के लिए व्यय की जा सकती है जिसके लिए वह ली गई है। वेंक का एक विशेषज्ञ मण्डल ग्रप्रैल सन् १६५६ में भारत की दूसरी पंच-वर्षीय योजना के लिए ऋएा के प्रार्थना-पत्र पर भारत का दौरा कर गया था। भारत ने प्रार्थना की थी कि उसे निश्चित उद्देश्य (Specific) ऋएा के स्थान पर सामान्य ऋएा (Block Loan) दिया जाय, जिसका उपयोग किसी भी काम में किया जा सके। पहले ऐसा ऋएा मास्ट्रेलिया को दिया जा चुका था। भविष्य में भारत को शीघ्र ही ग्रौर भी ऋएा मिलने की ग्राशा की जाती है।

भारत को विश्व बैंक से निम्न नौ ऋगा प्राप्त हुए हैं :--

- (१) रेलों के विकास के लिए ऋगा—पहला ऋगा ३'४ करोड़ डालर का अगस्त सन् १६४६ में मिला था, जो रेल-मार्गों की उन्नति के लिए दिया गया था। ऋगा १५ वर्ष के लिए है और इस पर ३% ब्याज और १% कमीशन प्रति वर्ष दिया जाता है। इसमें से भारत ने केवल ३'२५ करोड़ डालर प्राप्त किया है। ऋगा का भुगतान अगस्त सन् १६५० से आरम्भ हो गया है।
- (२) कृषि विकास के लिए ऋगा—दूसरा ऋगा १ करोड़ डालर का सितम्बर सन् १६४६ में कृषि विकास के लिए लिया गया था। यह ७ वर्ष के लिए है और इस पर २५% ब्याज और १% कमीशन है। इसमें से भारत ने केवल ७५ लाख डालर लिये हैं। ऋगा का भुगतान जून सन् १६५२ से आरम्भ हो गया है।
- (३) दामोदर घाटी योजना ऋगा—तीसरा ऋगा १'=४ करोड़ डालर का भ्रप्रैल सन् १९४० में दामोदर घाटी योजना के लिए लिया गया था। यह २० वर्ष के लिए है भ्रौर इस पर ३% ब्याज तथा १% कमीशन दिया जाता है। १ अप्रैल सन् १९४४ से भुगतान आरम्भ हो गया है।
- (४) लौह व स्पात के लिए ऋगा—चौथा ऋग सन् १६५३ में इण्डियन ग्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के लिए लिया गया है, जो कि १ ३५ करोड़ डालर का है। यह एक निजी व्यवसायिक संस्था को मिलने वाला ऋग है, यद्यपि इस पर भारत सरकार की गारन्टी है।
- (५) पाँचवाँ ऋगा सन् १६५३ में दामोदर घाटी योजना के लिए लिया गया है। इसकी राशि १-९५ करोड़ डालर है।
- . (६) विद्युत योजनाम्रों के लिए ऋग्ग-छठा ऋग १ ६२ करोड़ डाल र का सन् १६५४ में टाटा ग्रुप को बम्बई में बिजलीघर के विकास के लिए प्राप्त हुम्रा है।
- (७) ग्रौद्योगिक साख व विनियोग प्रमण्डल के लिए ऋरा—सातवां ऋरा सन् १६५५ में १ करोड़ डालर की राज्ञि का भारतीय ग्रौद्योगिक साख ग्रौर विनियोग प्रमण्डल को मिला है।

मु०च०ग्र० (२३)

( ६ ) ग्राठवाँ ऋगा सन् १६५६ में प्राप्त हुग्रा है, जो १५० करोड़ रुपये

का है।

(१) बन्दरगाहों के विकास व सुधार के लिए ऋग् — १६ अप्रैल सन्
१९५८ को विश्व बैंक ने दो ग्रीर ऋगों के देने की घोषणा की है, जिनकी सामूहिक
राशि ४ ३ करोड़ डालर है। २ ६ करोड़ डालर कलकत्ते की बन्दरगाह के सुधार के
लिए हैं ग्रीर शेप मद्रास की बन्दरगाह के लिए।

(१०) सन् १६५ में विश्व बैंक ने ५ ५ करोड़ डालर का एक ऋ ए देना भ्रौर स्वीकार किया है। यह ऋ ए भारतीय रेलों के सुधार और विकास की योजना के भ्रन्तर्गत दिया गया है। इस सुधार और विकास के लिए विदेशी विनिमय की समस्त भ्रावश्यकता इस ऋ ए से पूरी हो जाने की स्राशा है।

भारत को जो ऋग् प्राप्त हुए हैं उनके सम्बंध में निम्न श्रालोचनायें की गई हैं:— (?) ये ऋग् केवल निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलते हैं, जबिक भारत सामान्य ऋग भी चाहता है, जिनका प्रयोग किसी भी कार्य के लिए किया जा सके। (२) ब्याज की दर ऊँची है। भारत जैसे ग्रविकसित और निर्धन राष्ट्रों के लिए २.५% से ४.७५% तक ब्याज-दर बहुत भारस्वरूप है, जिससे विवश होकर उन्हें सस्ती साख के ग्रन्य स्रोत तलाशने पड़ते हैं। (३) भारत को बैंक से बहुत कम ऋग मिला है। भारत की ग्रौद्योगिक एवं विकास योजनाग्रों की ग्रावश्यकताग्रों को देखते हुए जो ऋग मिला है वह बहुत नगण्य है। इन दोषों के कारण ही भूतपूर्व ग्रथं मन्त्री श्री जॉन मथाई ने यह मत प्रगट किया था कि भारत को बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, वरन ग्रपने देश में ही वैयक्तिक पूँजी को निकालने के साधन ढूँढ़ने चाहिए। श्रन्तर्रोध्हीय मौद्धिक समक्तीते पर एक श्रालोचनात्मक दृष्ट—

भ्रान्तरां द्रीय मुद्रा-कोष का कार्य काफी सराहनीय रहा है। इसकी उपयोगिता का पता इसी बात से चल जाता है कि मार्च सन् १६४७ तथा अभ्रेल सन् १६५२ के पाँच वर्षों में ही इसने ५५ ७६ करोड़ डालर विभिन्न देशों को वेचा था, जिसमें से ६२ लाख डालर सोने में वेचा गया था और शेष विभिन्न सदस्यों के चलन के बदले में। ३० अभ्रेल सन् १६५२ को कोष के पास ५१ ४३ करोड़ डालर की कीमत का चलन संचय था, जिसमें से १२ ५३ करोड़ अमरीकन डालर थे और २२ ५ करोड़ अमरीकन डालर की कीमत का कनाडा का डालर था।

विश्व वेंक का कार्य तो छोर भी छाधिक शानदार रहा है। (i) अपने जीवन-काल के प्रथम ५ वर्षों में ही इसने ६० ऋरा दिए, जिनकी कीमत १४१'२ करोड़ डालर के बरावर थी। इसमें से केवल १३ करोड़ डालर का इस काल में भुगतान हुआ छौर शेष १३०'२ करोड़ डालर का विभिन्न देशों पर ऋरा बना रहा। (ii) ऋराों के प्रतिरिक्त दिश्व बेंक ने दक्षिगी अमरीका के राज्यों, मिश्र, भारत, ईराक, ईरान, लेबेनन तथा फिलीपाइन्स को शिल्प सहायता भी दी। (iii) बेंक ने विभिन्न सदस्य देशों की वित्तीय दशाओं को सुघारने के लिए लाभदायकं उपाय भी बताये हैं।

उपरोक्त बातों से यही पता चलता है कि ये दोनों संस्थायें मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रों में काफी लाभदायक कार्य कर रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का आधार काफी हड़ हो जायगा और भावी विकास की मजबूत नींव पड़ जायगी, परन्तु दोनों संस्थाओं की निष्पद्धता पर बहुधा सन्देह किया जाता है । राजनीतिक हास्टिकोग्गों पर आर्थिक सहायता का आधार बनाया जाता है । सारी कार्यवाहियों के पीछे साम्राज्यशाही डालर का प्रमुत्त्व साफ दिखाई पड़ता है । यदि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थों के ही लिए किया जाता है तो निस्सन्देह उसका जीवन काल लम्बा नहीं हो सकता है । दोनों ही संस्थाओं ने पक्षपात किया है, जो उनकी सफलता पर सन्देह उत्पन्न करता है ।

जहाँ तक मुद्रा-कोष का सम्बन्ध है उसमें प्रभ्यंशों का निर्धारण ग्राधिक ग्राधारों पर नहीं किया गया है, जिससे कि समस्त शक्ति ग्रमरीका ग्रौर उसके पीछे चलने वाले देशों के ही हाथ में केन्द्रित रहती है। ऐसे देशों द्वारा ग्रवैध कार्य करने पर भी कोष ने कोई दण्ड नहीं दिया है। इसका परिणाम ग्रौर भी गम्भीर प्रतीत होता है, जबिक हम जानते हैं कि मुद्रा-कोण की सदस्यता के विना विश्व वैंक की सदस्यता भी प्राप्त नहीं हो सकती है।

विश्व बैंक के ऊपर भी दो ब्रारोप लगाये जाते हैं :-प्रथम, यह कहा जाता है कि उसका कार्य विलाभवपूर्ण होता है । यह विलाभव ऋगा लेने वाले देश के लिए बड़ा ब्रसुविधाजनक होता है। दूसरे, इसका कार्य भी भेद-भाव से पूर्णतया विमुक्त नहीं है।

जहाँ तक भविष्य का सम्बन्ध है, इन दोनों संस्थाय्रों की उपयोगिता वड़े ग्रंश तक राजनीतिक तथा श्राधिक शान्ति ग्रौर स्थिरता पर निर्भर होगी, परन्तु वर्तमान संसार में इनकी ग्राशा कम है। भारत को दोनों संस्थाय्रों के विषद्ध कुछ भी कहने को गुन्जाइश शायद नहीं है, परन्तु हमारे लिए केवल अपने ही हितों की ग्रोर देखना बहुत ग्रन्छ। नहीं हो सकता है।

#### QUESTIONS

1. Give the constitution and functions of the International Bank for Reconstruction and Development.

(Agra, B. A., 1954)

2. Give a brief evaluation of the working of the International Bank for Reconstruction and Development.

(Agra. B. A., 1955)

- 3. पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक पर एक नीट लिखिए। भारत ने इस बैंक की सेवाओं से क्या लाभ उठाया है ? (Agra, B. A., 1957)
- Describe the aims and constitution of International Bank for Reconstruction and Development. Discuss its value to different countries in general and to India in particular. (Agra, B. Com., 1951)

5. Explain the economic purposes for which the World Bank was established. To what extent has India benefitted? (Agra, B. Com., 1950)

# श्रध्याय २० अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

### म्रान्तरिक तथा म्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषायें—

एक देश के व्यापार को दो भागों में बाँटा जा सकता है:—ग्रान्तरिक, देशी ग्रथवा घरेलू व्यापार तथा विदेशी ग्रथवा ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार । ग्रान्तरिक व्यापार से हमारा श्रमिप्राय उस व्यापार से होता हैं जो एक ही देश के विभिन्न क् त्रों ग्रथवा स्थानों के बीच होता रहता है । इसको कभी-कभी ग्रन्तस्थानीय व्यापार (Interregional Trade) ग्रथवा क्षेत्रवर्ती व्यापार भी कहा जाता है । इसके विपरीत ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से हमारा ग्राशय उस व्यापार से होता है जो दो ग्रलग-ग्रलग देशों या राष्ट्रों के बीच होता है । उदाहरणस्वरूप, यदि दिल्ली ग्रीर ग्रमुतसर के व्यापारी ग्रापस में क्य-विक्रय करते हैं तो उसे भारत का ग्रान्तरिक व्यापार कहा जायगा, परन्तु यदि श्रमुतसर के व्यापारी लाहौर के व्यापारियों के साथ व्यापार करते हैं तो यह भारत का विदेशी व्यापार होगा । कारण यह है कि दिल्ली ग्रीर ग्रमुतसर ये दोनों तो एक ही देश में स्थित हैं, परन्तु लाहौर एक दूसरे देश में स्थित हैं । फीमैन (Freeman) के ग्रमुतार:—"राष्ट्र भू-भाग का वह लगातार भाग है जिसके रहने वाले एक सी ही भाषा बोलते हैं तथा एक ही राज्य के शासन के भीतर ग्राते हैं ।" इसी प्रकार बेजहोट (Bagehot) के ग्रमुतार:—"राष्ट्र उत्पादकों का एक ऐसा

समूह है जिसके बीच श्रम श्रीर पूँजी की स्वतन्त्र गतिशीलता होती है।" स्मरण रहे कि फीमैन की परिभाषा राजनैतिक हिष्टकोरण से है श्रीर वेजहोट की श्रायिक हिष्टकोरण से, परन्तु क्योंकि एक देश की श्रायिक श्रीर राजनैतिक सीमाएँ प्रायः समान होती हैं, श्रतः दोनों परिभाषाश्रों में लगभग कुछ भी अन्तर नहीं है।

#### श्रान्तरिक तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का भेद-

ऊपर से देखने पर किसी देश के म्रान्ति तथा म्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ भी भेद दृष्टिगोचर नहीं होता है। दोनों का म्राघार विनिमय द्वारा ऐसी वस्तुमों मौर सेवामों के बदले में जो कि स्थान विशेष में फालतू म्रथवा प्रचुर हैं, ऐसी वस्तुमों मौर सेवामों का प्राप्त करना होता है जो या तो उपलब्ध ही नहीं हैं म्रथवा दुर्लभ हैं। दोनों का उद्देश्य इस प्रकार विनिमय द्वारा म्रधिकतम् म्रावश्यकतामों को पूर्ण करके म्रधिकतम् सन्तोष प्राप्त करना ही होता है। जिस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न कार्यं करने की विशेषता म्रथवा योग्यता होती हैं इसी प्रकार प्राकृतिक तथा म्रन्य कारणों से विभिन्न देश मलग-मलग वस्तुमों मौर सेवामों के उत्पादन के लिए म्रधिक उपयुक्त होते हैं। यही कारण है कि जिस प्रकार विनिमय द्वारा विनिमय करने वाले दोनों व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है ठीक उसी प्रकार विदेशी व्यापार, उसमें सम्मिलत होने वाले सभी देशों के लिए हितकारी होता है। स्वभाव में म्रान्तिक व्यापार तथा मन्तर्रिष्ट्रीय व्यापार एक से ही होते हैं, क्योंकि दोनों का ही म्राधारभूत उद्देश्य विनिमय द्वारा लाभ कमाना होता है, परन्तु म्राधिक विद्वानों ने निम्न कारणों से इन दोनों के बीच भेद करने का प्रयत्न किया है।

### अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये एक भिन्न सिद्धान्त की आवश्यकता क्यों ?—

ग्रान्तरिक ग्रौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इतनी समानता होते हुए भी दोनों व्यापारों में कुछ ग्रन्तर की बातें पाई जाती हैं, जिनके ग्राघार पर विद्वानों ने ग्रन्त-र्राष्ट्रीय व्यापार के लिये एक पृथक सिद्धान्त की ग्रावश्यकता बतालाई है। ये ग्रन्तर निम्नलिखित हैं:—

(१) श्रम श्रौर पूंजी की गतिशीलता—एक देश के भीतर साधारणतया श्रम श्रौर पूँजी में गतिशीलता होती है। इसका परिग्णाम यह होता है कि देश
के सभी स्थानों पर मजदूरी श्रौर ब्याज की दरें समान ही रहती हैं श्रौर उत्पादन-व्यय
भी लगभग समान रहता है। श्रम श्रौर पूँजी की गतिशीलता के इस श्रभाव के अनेक
कारण होते हैं। ऐसा देखने में श्राता है कि विदेशों में काफी ऊँचे वेतन मिलने पर
भी लोग अपने देश को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कारण यह है कि विभिन्न देशों में
भाषा, धर्म, श्राचार-विचार, रीति-रिवाज, खान-पान, सामाजिक श्रौर श्राधिक जीवन
श्रादि के श्रधिक श्रन्तर हैं। जहाँ तक पूँजी का प्रश्न है, वह श्रम की अपेक्षा श्रिषक
गतिशील होती है, परन्तु लाग अपनी बचत का भी अपने ही देश में श्रिषक विनियोग
करने की इच्छा करते हैं। विदेशियों को ऋग्ण देते समय प्रतिभृति सम्बन्धी शर्ते श्रिषक

कड़ी रखी जाती हैं ग्रौर ब्याज भी ग्रधिक माँगा जाता है। लोगों का कुछ ऐसा विश्वास है कि देशी विनियोग विदेशी विनियोगों की ग्रपेक्षा ग्रधिक सुरक्षित होते हैं।

गितशीलता के इस अन्तर का प्रभाव यह होता है कि विभिन्न देशों में एक सी ही वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व्यय में समानता नहीं आने पाती है। इस प्रकार विभिन्न देशों को अलग-अलग वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक लाम प्राप्त होने लगते हैं और उत्पादन का इस प्रकार विशिष्टीकरण (Specialisation) हो जाता है कि विभिन्न देशों के बीच स्पर्धा नहीं हो पाती है। पातिशीलता के इस ग्रभाव का एक और भी महत्त्वपूर्ण ग्राधिक परिणाम होता है। दीर्घकाल में प्रत्येक वस्तु के मूल्य में उसके उत्पादन व्यय के बराबर हो जाने की प्रवृत्ति होती है, किन्तु विभिन्न देशों के धीच एक वस्तु के उत्पादन व्यय में ग्रन्तर होने के कारण उसके मूल्यों में भी ग्रन्तर बना रहता है।

कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि जिस तरह एक देश की सीमा में श्रम और पूँजी पूर्ण गतिशील नहीं होते उसी तरह वे भिन्न-भिन्न देशों भें भी पूर्ण प्रगतिशील नहीं होते, क्योंकि अब चमत्कारिक यातायात-साधनों व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के फलस्व-रूप आधिक और राजनैतिक दूरियों का महत्व कम हो गया है। अतः उक्त विद्वानों के अनुसार आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में केवल मात्रा का भेद (Difference of Degree) ही होता है।

- (२) उत्पादन सम्बन्धी नियम—एक देश के भीतर उत्पादन सम्बन्धी नियम सभी स्थानों पर एक से ही होते हैं। उत्पादन के सम्बन्ध में सरकारी नीति भी समान ही रहती है। शार्थिक और सामाजिक संस्थाओं में भी अनुरूपता रहती है। एक देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय कर भी एक से होते हैं। उनके लिए स्वास्थ्य, सफाई, कारखानों में काम करने की दशाओं और सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नियम एक से रहते हैं, यातायात और लोक-सेबाएँ एक सी होती हैं, औद्योगिक सम्बन्धों और अम-संघों के लिए एक से ही नियम रहते हैं और व्यवसायिक कार्य-प्रणाली में भी अन्तर नहीं होता। परन्तु अलग-अलग देशों में इन सब दिशाओं में भारी विविधता रहती है, जिसके कारण उत्पादन सम्बन्धी सुविधाओं में अन्तर रहता है और व्यय में भिन्नता आ जाती है। विभिन्न देशों के बीच आर्थिक घटनायें अपना प्रमाव स्पष्ट व स्वतन्त्रतापूर्वक स्पष्ट नहीं कर पाती हैं।
- (३) प्राकृतिक साधनों ग्रौर भौगोलिक दशाग्रों में भिन्नता— विभिन्न देशों के बीच भूमि की बनावट, जलवायु तथा प्राकृतिक साधनों की उपलब्बता के भी गम्भीर ग्रन्तर हो सकते हैं। इनका परिगाम भौगोलिक श्रम विभाजन तथा उद्योगों के स्थानीयकरण के रूप में प्रकट होता है। कुछ देशों को खनिज पदार्थों के लाभ प्राप्त होते हैं तो कुछ को उपयुक्त भूमि ग्रौर ग्रच्छी जलवायु के। इन लाभों का एक देश से दूसरे देश को हस्तान्तरण या तो ग्रक्षम्भव होता है या बहुत ही व्ययपूर्ण, यद्यि

देश के भीतर इसमें कोई बाघा नहीं होती है ! इन लाभों के कारएा भी दो देशों के बीच किसी वस्तु के उत्पादन व्यय में अन्तर हो जाता है !

- (४) मुद्रा प्रगाली में भिन्नता—प्रत्येक देश की मुद्रा-प्रगाली ग्रनग-ग्रवण होती है। देश के भीतरी व्यवसाय में विदेशी विनिमय ग्रव्यात एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में वदलने की समस्या नहीं होती है, परन्तु विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में इस समस्या का ग्रधिक महत्त्व होता है। यह समस्या ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जटिलता लाती है और उसके निष्कंटक संचालन में ग्रनेक बाबायें उपस्थित करती है। यत्येक देश की मुद्रा देश के मुद्रा-नियन्त्रक की नीति के श्रनुसार चलती है श्रार मुद्रा-नियन्त्रक की नीति के श्रत्येक परिवर्तन का श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर पर्यात श्रमाय पड़ता है।
- (५) वस्तुओं के आयात-निर्यात में बाधायें—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसे स्वतन्त्र देशों के बीच होता है, जो आयात-निर्यात, विनिमय नियन्त्रण आदि के सम्बन्ध में अपनी अलग-अलग नीतियों के अनुसार कार्य करते हैं। साधारणतया देश के भीतर वस्तुओं के आवागमन पर किसी प्रकार के प्रतिवन्च नहीं होते हैं, परन्तु विदेशी व्यापार में ऐसे प्रतिबन्ध लगभग सभी देशों में लगाये जाते हैं।

#### निष्कर्ष-

इस स्राघार पर स्रर्थशास्त्रियों का ऐसा विचार है कि स्रान्तिरक व्यापार तथा सन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्यायें एक दूसरे से पूर्णत्या पृथक हैं और इसलिए साधारण विनिमय सिद्धान्त स्नन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके लिए एक स्रलग ही सिद्धान्त की स्नावश्यकता है। परन्तु दोनों प्रकार के व्यापार के स्नन्तरों को व्यान-पूर्वक देखने से पता चलता है कि वे स्नाधारभूत नहीं है। मेद केवल ऋंश का है। यद्यपि यह तो सत्य हैं कि विभिन्न देशों के बीच श्रम स्रौर पूँजी की गतिशीलता का भारी स्रभाव होता है, परन्तु यह समक्तना भी भूल होगी कि स्वयं देश के भीतर ये साधन पूर्ण रूप में गतिशील होते हैं। एक देश के भीतर भी स्नलग-स्नलग स्थानों में भाषा, धर्म, रीति-रिवाज स्नादि के गम्भीर स्नन्तर हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार देश के भीतर पूँजी का स्नावागमन भी पूर्णत्या स्वतन्त्र नहीं होता है। स्निक से स्निक हम इतना ही कह सकते हैं कि देश के भीतर दो स्नलग-स्नलग देशों के बीच की तुलना में श्रम श्रौर पूँजी की गतिशीलता स्रधिक होती है। कभी-कभी तो यह भी सम्भव है कि दोनों दशाशों में गतिशीलता का स्नश समान ही रहे।

ठीक इसी प्रकार एक देश के भीतर भी उत्पादन सम्बन्धी नियमों में अन्तर हो सकता है। स्वयं भारत में कुछ नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये जाते हैं और कुछ राज्य सरकारों द्वारा। विभिन्न राज्यों द्वारा बनाये हुए नियमों में विभिन्नता का रहना कोई आश्चर्यं की बात नहीं है। साथ ही, एक देश के अलग-अलग भागों में प्राकृतिक साधन तथा भौगोलिक दशाएँ भी एक सी नहीं होती हैं। भारत इसका प्रत्यक्ष उदा-हरण है, जहाँ लगभग सभी प्रकार की भूमि तथा सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती

है। कुछ लोग तो इसी कारएा भारत को एक छोटा-सा महाद्वीप कहते हैं। इसी प्रकार कभी-कभी तो यह भी देखने में म्राता है कि देश के भीतर एक से म्रधिक प्रकार की मुद्राएँ चालू होती हैं मौर माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी रुकावटें रहती हैं।

इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि भ्रान्तरिक तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई मौलिक भेद तो नहीं है, परन्तु कुछ महत्त्वपूर्ण बातों ऐसी भ्रवश्य हैं जो भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की भ्रपेक्षा भ्रान्तरिक व्यापार में भ्रधिकता से पाई जाती है। इनके कारण भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्णत्या भ्रलग प्रकार का तो नहीं हो जाता है, परन्तु उसमें विशिष्टता भ्रवश्य भ्रा जाती है। स्रोहिलन (Ohlin) ने ठीक ही कहा है—"अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्नन्तर्स्थोनीय व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है।"

# श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है ?—

यह प्रक्त भी महत्त्वपूर्ण है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों और किन दशाओं में सम्भव होता है ? इस प्रश्न का उत्तर वैसे तो बड़ा ही सरल है । बात यह है कि जिस प्रकार प्रत्येक विनिमय कार्य से विनिमय करने वाले दोनों पत्तों को लाभ होता है ठीक इसी प्रकार ऋन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी उसमें सम्मिलित होने वान दोनों देशों के लिए लाभदायक होता है। अब हमें यह देखना है कि किन दशाओं में तथा किन कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लाभदायक हो जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय भाषार पर प्रादेशिक श्रम विभाजन को प्रोत्साहन देता है। इसके कारए। उत्पादन का इस प्रकार विशिष्टीकरण हो जाता है कि प्रत्येक देश ऐसी ही वस्तुम्रों का उत्पादन करता है जिनका उत्पादन व्यय उसके लिए न्यूनतम् होता है। यही कारए है कि भारत पटसन का उत्पादन करता है, बर्मा चावल का, इङ्गलैंड ऊनी कगड़े का श्रीर जापान सूती कपड़े का । इससे निस्सन्देह लाभ होता है, क्योंकि प्रत्येक देश को अन्त-र्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा बाहर के देशों से न्यूनतम् कीमतों पर वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ इस काग्या प्राप्त होता है कि विभिन्न देशों में एक वस्तु के उत्पादन-व्यय श्रीर मुल्य में श्रन्तर होते हैं । ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का ग्राधार उत्पादन-व्यय तथा मूल्यों का यह ग्रन्तर ही है। वैसे म्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए भी हो सकता है कि एक देश दूसरे देश से कोई ऐसी वस्तु प्राप्त करे जिसे वह स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता है, परन्तु व्यवहार में इस कारण होने वाला व्यापार कम ही रहता है। श्रिधिकाँश दशाश्रों में विदेशों से वही वस्तुएँ मंगाई जाती हैं जिन्हें हम स्वयं उत्पन्न तो कर सकते हैं. परन्तु हमारा उत्पादन-व्यय विदेशों से ऊँचा होता है।

regional trade." See Ohlin: Inter-regional and International Trade, p. 3.

# श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लागतों में श्रन्तर—

उत्पादन व्यय के अन्तर को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—(१) लागत का निरपेक्ष (Absolute) अन्तर और (२) लागत का तुलनात्मक अन्तर (Comparative Difference)।

(१) निरपेक्ष अन्तर (Absolute Difference)—एकाविकार प्राप्त हो जाने के कारण किसी देश को कुछ वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो सकता है। कुछ देशों पर कुछ दशाओं में प्रकृति की विशेष उदारता होने के कारण वहाँ पर कुछ वस्तुओं का उत्पादन बहुत ही कम लागत पर हो सकता है। इसके कारण कुछ विशेष खनिज पदार्थों का मिलना अथवा विशेष प्रकार की जलवायु अथवा पृथ्वी की बनावट हो सकते हैं। दक्षिणी अफ्रीका को संसार भर में हीरे के उत्पादन का एकाधिकार प्राप्त है। भारत को जूट, जावा को चीनी और ब्राजील को कहवे के सम्बन्ध में विशेष सुविधायें हैं। ऐसे देशों में इन वस्तुओं का उत्पादन व्यय काफी कम होता है और दूसरे देशों को इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उपरोक्त देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार के व्यापार को जन्म देने वाली दशा को लागतों का निरपेद्त अन्तर कहते हैं। नीचे का उदाहरण इसे स्पष्ट करता है—

भारत २ इकाई १ इकाई ) एक दिन के श्रम का उत्पादन । बर्मा १ ,, २ ,,

यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि पटसन के उत्पादन में भारत को श्रेष्ठता प्राप्त है। प्रत्येक देश उसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्ठीकरण प्राप्त करेगा जिसमें उसे श्रेष्ठता प्राप्त होगी और उसी में दूसरे राष्ट्रों से व्यापार करेगा। इससे दोनों ही देशों को लाभ होगा। यदि व्यापार नहीं किया जाता है तो भारत अथवा बर्मा को तीन दिन के श्रम के फलस्वरूप केवल २ इकाई पटसन + २ इकाई चावल प्राप्त होता है, परन्तु व्यापार होने की दशा में इतने ही श्रम के फलस्वरूप ३ इकाई पटसन तथा ३ इकाई चावल मिल सकता है। श्रम लागत के आघार पर पटसन और चावल का विनिमय अनुपात निम्न प्रकार होगा:—

भारत— चावल की एक इकाई = पटसन की दो इकाई | बर्मा— चावल की एक इकाई = पटसन की है इकाई |

भारत और बर्मा के बीच का व्यापार उस समय तक वरावर लाभदायक रहेगा जब तक कि भारत को पटसन की २ इकाइयों के बदले में चावल की एक से अधिक इकाई मिलती रहेगी। ठीक इसी प्रकार उस समय तक व्यापार बर्मा के लिए भी लाभदायक होगा जब तक कि उसके फलस्वरूप चावल की एक इकाई के बदले में पटसन की ग्राधे से अधिक इकाई मिलती रहेगी। इस उदाहरण में हमने यह मान लिया है कि व्यापार के सम्बन्ध में यातायात तथा बीमे का व्यय नहीं होता है। परन्तु यातायात, बीमा ग्रादि के व्यय को जोड़ देने पर भी लाभ की इस स्थित में

अन्तर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रभाव भारत और वर्मा दोनों पर समान रूप में पड़ेगा। इस प्रकार भारत तथा वर्मा का पारस्परिक व्यापार लाभदायक होगा।

(२) सापेक्ष अन्तर (Relative Difference)—उपरोक्त उदाहरण में हमने यह देखा है कि एक देश को ऐसी वस्तुओं का निर्यात करने में लाभ होता है जो वहाँ पर निरपेक्ष रूप में श्रीर कम लागत पर उत्पन्न की जा सकती हैं और उन वस्तुओं के भ्रायात से लाभ होता है जिनकी लागत अधिक बैठती है, परन्तु लागत के निरपेक्ष अन्तर साधारणतया कम ही होते हैं । वैसे तो प्रत्येक देश में लगभग सभी वस्तुएँ किसी न किसी प्रकार उत्पन्न की जा सकती हैं, परन्तु किसी-किसी वस्तु का उत्पादन व्यय कभी-कभी इतना ऊँचा हो सकता है कि वस्तु का उत्पादन ही भ्रनाधिक हो जाय । युद्धकाल में जर्मनी ने रसायनिक पैट्रोल (Sinthetic Petrol) को अधिक मात्रा में उत्पन्न किया था, परन्तु उसका उत्पादन व्यय प्राकृतिक पैट्रोल की तुलना में बहुत ही अधिक था। लागत के निरपेक्ष अन्तर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को निरसन्देह लाभदायक बनाते हैं, परन्तु व्यवहारिक जीवन में उनका महत्त्व कम ही रहता है।

एक देश के लिये विदेशों से ऐसी वस्तुओं का मँगाना भी लाभदायक हो सकता है जिन्हें वह स्वयं विदेशों की अपेचा कम लागत पर उत्पन्न कर सकता है। यह इस कारण होता है कि माल मँगाने वाला देश अन्य वस्तु के उत्पादन का विशिष्टीकरण करके और भी अधिक लाम प्राप्त कर सकता है। ऐसी दशा में दोनों के बीच लागत में निरपेच्च अन्तर नहीं होता, बल्कि तुलनात्मक अथवा सापेच्च अन्तर होता है। एक कॉलेज का प्रोफेसर घर के कामों को एक नौकर की अपेक्षा अधिक कुशनतापूर्वक कर सकता है, परन्तु उसके लिए नौकर रखना इसिलए अधिक लाभदायक हो सकता है कि इस प्रकार समय की जो बचत होती है उसका और भी अधिक लाभपूर्ण उपयोग सम्भव होता है। बिल्कुल यही बात एक देश के विषय में भी ठीक हो सकती है। वह एक वस्तु को दूसरे देश से केवल इसी कारण मँगा सकता है कि देश में उस वस्तु का उत्पादन बन्द करने से जिन साधनों की जो बचत होती है उनका और भी अधिक लाभदायक उपयोग सम्भव होता है।

परन्तु लागत के सापेच्न अन्तर दो प्रकार के हो सकते हैं :—(?) समान अन्तर और (२) तुलनात्मक अन्तर। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उसी दशा में लाभदायक होता है जबिक लागत के सापेक्ष अन्तर तुलनात्मक होते हैं। समान अन्तर रहने की दशा में लाभ की कोई सम्मावना नहीं रहती और इसिलिये व्यापार का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। भारत और बर्मा के उपरोक्त उदाहरण में थोड़ा सा परिवर्तन कर देने से स्थित बदल जायगी।

	पटसन	चावल	
भारत	२ इकाई	२ इकाई	एक दिन के श्रम का
बर्मा	१ इकाई	१ इकाई	<b>े</b> उत्पादन

उपरोक्त उदाहरए। समान सापेक्ष अन्तर को स्पष्ट करता है। जैसा कि विदित है कि भारत को वर्मा की तुलना में पटसन और चावल दोनों ही के उत्पादन में कम लागत लगानी पड़ती है, परन्तु यदि दोनों के बीच व्यापार नहीं होता है तो भारत में पटसन और चावल का विनिमय अनुपात १: १ होगा और ठीक यही अनुपात वर्मा में भी रहेगा। यदि भारत केवल पटसन का ही उत्पादन करता है और अपनी चावल की आवश्यकता वर्मा से चावल मेंगा कर पूरी करता है तो भी उसे कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि वर्मा में भी चावल और पटसन का विनिमय अनुपात वही है जो कि भारत में। ऐसी दशा में व्यापार करना उल्टा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वाहर से माल मैंगाने में माल की कीमत के अतिरिक्त यातायात सम्बन्धी लागत और भी देनी पड़ेगी।

परन्तु दो देशों में लागत के तुलनात्मक अन्तर भी हो सकते हैं। ऐसे अन्तरों की दशा में, जैसा कि जिम्न उदाहरण से सिद्ध हो जायगा, व्यापार लाभ-दायक होगा और यही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उपयुक्त दशा होगी:—

 चाय
 मसाले

 भारत
 २ इकाई
 १ इकाई
 एक दिन के श्रम का

 जावा
 २ इकाई
 २ इकाई
 उत्पादन

उपरोक्त उदाहरण में यदि भारत श्रीर जावा के वीच व्यापार नहीं होता है तो दोनों देशों में चाय श्रीर मसालों के विनिमय श्रनुपात इस प्रकार होंगे:—भारत—१ इकाई चाय = १ इकाई मसाला, परन्तु यदि भारत केवल चाय का ही उत्पादन करता है श्रीर जावा केवल मसालों का श्रीर दोनों ही दूसरी वस्तु व्यापार द्वारा प्राप्त करते हैं तो दोनों को लाभ होगा। भारत चाय की एक इकाई को जावा में भेजकर उसके बदले में जावा के विनिमय श्रनुपात के श्राचार पर १ इकाई मसाला प्राप्त कर सकता है श्रीर ठीक इसी प्रकार जावा १ इकाई मसाले को भारत भेजकर बदले में २ इकाई चाय ले सकता है। इस प्रकार यह व्यापार दोनों ही देशों के लिए लाभद्यक है। स्मरण रहे कि जावा में चाय का उत्पादन व्यय ठीक छतना ही है जितना कि भारत में, परन्तु फिर भी जावा को भारत से चाय को खरीदने में श्रधिक लाभ होता है। व्यवहारिक जीवन में ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ साधारणतया इसो प्रकार उत्पन्न होते हैं श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होने की सामान्य दशा यही होती है। इसी को श्रर्थशास्त्र में तुलन;त्मक लागत का सिद्धान्त कहा गया है।

# तुलनात्मक लोगत का सिद्धान्त (The Doctrine of Comparative Cost)

प्रतिष्ठित विचारधारा — ग्रर्थशास्त्र में तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का उपयोग सबसे पहले रिकाड़ों ने किया था। उनका विचार था कि एक देश के भीतर श्रम श्रीर पूँजी की गतिशीलता के कारण विभिन्न व्यवसायों में लाम का ऋंश समान रहने की प्रवृत्ति होती हे, परन्तु दो देशों के वीच ऐसा नहीं हो पाता है। व्यवहारिक जीवन से एक उदाहरण लेकर रिकार्डों ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था कि यद्यपि पुर्तगाल कपड़ा तथा जराब दोनों ही इक्कलैंड की अपेक्षा कम कीमत पर उत्पन्न कर सकता था, परन्तु पुर्तगाल के लिए यही अधिक लाभदायक था कि वह जराब के उत्पादन पर अधिक व्यान दे और कपड़े का इक्कलैंड से आयात करे, क्योंकि उसे शराब के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ अधिक था। इस सम्बन्ध में रिकार्डों ने यह भी बताया था कि विदेशी विनिमय दरों की सीमाएँ भी तुलनात्मक लागत द्वारा ही निर्धारित होती हैं।

रिकाडों के सिद्धान्त में मिल ने आवश्यक सुधार किये। उनका विचार था कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार तो तुलनात्मक लागत का अन्तर ही था और उसके लाम भी इसी के कारण उत्पन्न होते हैं, परन्तु इस लाम का अंश इस बात पर निर्मर है कि तुलनात्मक दृष्टिकीण से एक देश में दूसरे देश के माल की माँग कितनी आयहपूर्ण है। साम्य की दशा में आयातों तथा निर्यातों का मूल्य वरावर होता है, परन्तु यह साम्य इस प्रकार स्थापित होता है कि अधिक कीमत का माल मेंगाने वाला देश बहुमूल्य धातुओं का निर्यात करके वस्तुओं के निर्यात की कमी को पूरा करता है और इस प्रकार अपने अधिक आयातों का मूल्य चुकाता है।

मिल तथा रिकार्डो दोनों ने ही इस मान्यता पर इस सिद्धान्त का निर्माण किया था कि एक देश के भीतर श्रम श्रीर पूँजी दोनों ही पूर्ण रूप में गतिशील होते हैं, परन्तु दो ग्रलग-ग्रलग देशों के बीच उनमें गितशीलता बिल्कुल भी नहीं होती है। कैरनीज (Cairnes) नामक ऋर्थशास्त्री ने इस मान्यता की ऋालोचना की है। उनका विचार है कि एक देश के भीतर भी श्रम श्रौर पूँजी की गतिशीलता पूर्ण नहीं होती है ग्रीर इसके विपरीत यह भी सत्य नहीं है कि विभिन्न देशों के बीच उनकी गतिशीलता का पूर्णतया ग्रभाव होता है। वास्तविकता केवल यह है कि देश के भीतर श्रीर देश के वाहर श्रम ग्रीर पूँजी की गतिशीलता में श्रन्तर होता है, परन्तू कैरनीज का मत था कि रिकार्डो ग्रौर मिल की मान्यता को हटा देने से भी तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त गलत नहीं हो जाता है। साधनों की गतिशीलता की ग्रधिकता के कारए। एक देश के भीतर लाभों में समानता था जाने की प्रवृत्ति ग्रधिक तीव होती है, परन्तू विभिन्न देशों के बीच यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार, जबिक देश के भीतर वस्तुयों का विनिमय अनुपात उसके उत्पादन व्यय द्वारा निश्चित होता है, विभिन्न देशों के बीच यह ग्रन्योन्य मांग (Reciprocal Demand) ग्रर्थात् एक देश के भीतर दूसरे देश की उत्पादित वस्तु की मांग की ग्राग्रहपूर्णता द्वारा ही निर्घारित होता है। कीन्ज ने भी निष्कर्ष रूप में रिकार्डो ज्रीर मिल के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है, यद्यपि उन्होंने इसकी विवचना की प्रथक रीति ऋपनाई है।

### प्रतिष्ठित विचाराधारा में श्राधुनिक सुधार—

तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को आधुनिक अर्थशास्त्री भी स्वीकार करते हैं, परन्तु उन्होंने इसमें तीन महत्त्वपूर्ण सुधार किए हैं:—

- (i) लागत का माप श्रम के वजाय मुद्रा में—प्रतिध्ठित ग्रथंशास्त्रियों ने रिकार्डों का अनुकरण करते हुए लागत की माप निर्माण में क्यय होने वाले श्रम की मात्रा में की थी, परन्तु ग्राधुनिक ग्रथंशास्त्री उसकी माप मुद्रा में करते हैं। इसका कारण यह है कि ग्राधुनिक ग्रथंशास्त्रियों ने मूल्य के श्रम सिद्धान्त (Labour Theory of Value) को ग्रस्वीकार कर दिया ग्रौर फिर वस्तुग्रों के उत्पादन में श्रम के ग्रलावा ग्रन्य साधन भी स्तैमाल किये जाते हैं। ग्रतः ग्राजकल मूल्य सिद्धान्त सीमान्त उत्पादन व्यय के रूप में प्रगट किया जाता है। कहा जाता है कि एक देश उन वस्तुग्रों का निर्यात करता है जिनका उत्पादन ग्रथंशतन ग्रधिक प्रचुर साधनों द्वारा किया जाता है, ग्रथ्यां जिनका सीमान्त उत्पादन-व्यय कम होता है ग्रौर इसके विपरीत उन वस्तुग्रों का ग्रायात करता है जिनका उत्पादन-व्यय तुलना में ग्रधिक होता है, ग्रथंवा जो ग्रयंक्षतन ग्रधिक दुर्लभ साधनों द्वारा उत्पादन-व्यय तुलना में ग्रधिक होता है, ग्रथंवा जो ग्रयंक्षतन ग्रधिक दुर्लभ साधनों द्वारा उत्पादन-व्यय तुलना में ग्रधिक होता है,
- (ii) उत्पत्ति-वृद्धि स्रौर उत्पत्ति ह्रास नियमों को सम्मिलित करना प्राचीन स्रर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त की विवेचना केवल इस स्राधार पर की थी कि उत्पादन क्रमगत उत्पत्ति स्थिरता नियम (Law of Constant Returns) के अन्तर्गत होता है स्रौर विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में होने वाले यातायात व्यय का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्तमान स्थंशास्त्रियों ने इन मान्यतास्रों को स्रावश्यक नहीं समक्षा है। उन्होंने यातायात व्यय तथा उत्पत्ति ह्रास नियम की कार्यशीलता के साधार पर इस सिद्धान्त का विवेचन किया है स्रौर इस प्रकार इस सिद्धान्त में व्यवहारिकता उत्पन्न कर दी है। जब उत्पत्ति क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियमों के अन्तर्गत होती है, तो पूर्ति में वृद्धि होने से लागत प्रति इकाई कम हो जाती है, जिससे विदेशी व्यापार में तुलनात्मक लाभ का क्षेत्र बढ़ जाता है श्रौर विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है, परन्तु जब उत्पत्ति ह्रास नियम के अन्तर्गत की जाती है, तो पूर्ति बढ़ाने से लागत प्रति इकाई बढ़ जाती है, जिससे तुलनात्मक लाभ का क्षेत्र कम हो जाता है श्रौर प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हतोत्साहन होता है।
- (iii) माँग की लोच का प्रभाव—रिकार्डो श्रौर उनके समर्थकों ने यह तो बताया था कि सिद्धान्त के ग्राधार पर किन-किन वस्तुश्रों में व्यापार करना लाभ-दायक होगा, परन्तु वे यह निश्चित नहीं कर पाये थे कि लाभ की मात्रा किन बातों पर निर्भर होगी। इस सम्बन्ध में ग्राधुनिक ग्रर्थशास्त्रियों का विचार है कि लाभ का ग्रंश इस बात पर निर्भर होता है कि एक देश में दूसरे माल की माँग की लोच कितनी है। जिस देश में दूसरे देश के माल की तुलनात्मक माँग की लोच श्रिषक होगी उसी को ब्यापार से लाभ भी ग्रपेक्षतन ग्राधक ही होगा। जिस देश में अन्य देश की वस्तु की

तुलनात्मक माँग की लोच ग्रधिक होगी, उस देश के लिये व्यापार की शतें ग्रधिक ग्रमुकूल होंगी ग्रौर जिस देश में ग्रन्य देश की वस्तु की तुलनात्मक माँग की लोच कम होगी उस देश के लिये व्यापार की शतें कम श्रमुकूल होंगी।

#### सिद्धान्त का वर्तमान रूप-

ऊपर की व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केवल इस कारण सम्भव होता है कि विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के उत्पादन-व्यय में अन्तर होते हैं। ये अन्तर तीन प्रकार के हो सकते हैं:—(१) निरपेक्ष अन्तर, (२) समान अन्तर और (३) तुलनात्मक अन्तर। इनमें से केवल पहिली और तीसरी दशाओं में ही व्यापार हो सकता है। समान अन्तरों की दशा में व्यापार से कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है, इसलिए पहिलो और तीसरी दशाओं का ही विस्तृत अध्ययन लाभदायक है।

(१) निरपेक्ष अन्तर—सबसे पहिले हम निरपेक्ष अन्तर को लेते हैं :— प्रति मन सीमान्त व्यय (रुपयों में )

चावल कपास भारत **द १**२ पाकिस्तान १२ **5** 

क्योंकि दीर्घकाल में कीमत सीमान्त उत्पादन व्यय के बराबर होती है, भारत में १ मन कपास का १३ मन चावल में विनिमय होगा और पाकिस्तान में १ मन चावल का १३ मन कपास में । इस प्रकार भारत में चावल श्रीर कपास का विनिमय अनुपात २ : ३ होगा और पाकिस्तान में ३ : २ । यहाँ पर यह स्पष्ट है कि भारत को चावल के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है ग्रीर पाकिस्तान को कपास के उत्पादन में। भारत को कपास का उत्पादन छोड़कर केवल चावल का ही उत्पादन करने में लाभ होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ व्यापार करके उसे १ मन चावल के बदले में 🖁 मन से ग्रधिक कपास मिल जायगी, जबिक कपास को स्वयं उत्पन्न करने की दशा में १ मन चावल के बदले में केवल है मन कपास मिलती है। इसी प्रकार पाकिस्तान के लिए कपास का उत्पादन ग्रधिक लाभदायक होगा. क्योंकि वह भी भारत से १ मन कपास के बदले में 🕏 मन से अधिक चावल प्राप्त कर सकता है, जबिक स्वयं उत्पन्न करके उसे भी केवल है मन चावल मिलता है। भारत को वास्तव में १ मन चावल के बदले में कितनी कपास मिलेगी श्रीर पाकिस्तान को १ मन कपास के बदले में कितना चावल मिलेगा, यह दो बातों पर निर्भर होगा :--(१) यह कि यातायात पर कितना व्यय होता है और (२) यह कि भारत और पाकिस्तान में क्रमशः कपास और चावल की अन्योन्य माँग (Reciprocal Demand) की तुलनात्मक लोच का ग्रंश कितना है। जब तक भी भारत को एक मन चावल के बदले में 🚉 मन से अधिक कपास मिलती रहेगी, वह व्यापार करने को तैयार रहेगा। इसी प्रकार जब तक पाकिस्तान १ मन कपास के बदले में हु मन से अधिक चावल प्राप्त करता रहेगा. उसे व्यापार से लाभ ही होगा और वह भी व्यापार करता रहेगा।

(२) तुलनात्मक अन्तर—ठीक इसी प्रकार हम उत्पादन व्यय के तुलनात्मक अन्तर का भी उदाहरण दे सकते हैं। नीचे का उदाहरण इसी प्रकार का है:—

प्रति मन सीमान्त उत्पादन व्यय ( रुपयों में )

	पटसन	<u>चावल</u>
भारत	હ	₹.१४
वर्मा	e <sub>e</sub>	<b>*</b> 4

इस उदाहरण में बर्मा पटसन तथा चावल दोनों को ही भारत की अपेक्षा कम कीमत पर उत्पन्न करता है, परन्तु वर्मा को चावल के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ ग्रधिक है। इसके विपरीत बर्मा की तुलना में भारत में दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन व्यय ग्रधिक है, परन्तु पटसन के उत्पादन में उसकी तुलनात्मक हानि कम है। इस प्रकार भारत में १ मन पटसन = है मन चावल ग्रीर वर्मा में १ मन पटसन = है मन चावल विनिमय अनुपात होंगे । भारत के लिए पटसन के उत्पादन में विशेषता प्राप्त करना लाभदायक होगा और वर्मा के लिए चावल के उत्पादन में । व्यापार द्वारा जब तक भारत को एक मन पटसन के बदले में है मन से ग्रधिक चावल मिलेगा, उसे लाभ ही होगा। इसी प्रकार जब तक बर्मा को १ मन चावल के बदले में हूँ मन से अधिक पटसन मिलता रहेगा, उसे भी लाभ ही होगा। दोनों देशों के बीच पटसन ग्रौर चावल का विनिमय अनुपात कहीं पर इन दोनों अनुपातों के बीच निश्चित होगा. अर्थात् एक मन पटसन के बदले में जितना चावल मिलेगा वह है मन तथा हूँ मन के बीच में ही रहेगा । चावल और पटसन के इस विनिमय अनुपात पर ३ बातों का प्रभाव पड़ेगा :--(१) यातायात व्यय, (२) ग्रन्योन्य माँग की तुलनात्मक लोच और 📢 उत्पत्ति का वह नियम जिसके अन्तर्गत उत्पादन हो रहा है। इस सम्बन्ध में इतना कह देना ही पर्यात होगा कि क्रमगत उत्पत्ति वृद्धि नियम व्यापार के लाभ में और भी वृद्धि कर देता है, क्योंकि उसके ग्रन्तर्गत उत्पत्ति को प्रत्येक वृद्धि के साथ सीमान्त उत्पादन व्यय घटता जाता है । क्रमगत उत्पत्ति स्थिरता नियम का व्यापार की लाभदायकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उत्पादन के बढ़ने पर भी सीमान्त उत्पादन व्यय ज्यों का त्यों ही रहता है, परन्तु यदि उत्पादन क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम के ग्रन्तर्गत होता है तो उत्पत्ति के बढ़ने से सीमान्त उत्पादन व्यय भी बढ़ जाता है ग्रौर इसके कारण व्यापार के लाभों का ग्रंश घटता जाता है। ग्रन्त में एक ऐसी स्थिति ग्रा सकती है, जिवक वह पूर्णतया समाप्त हो जाय। यहाँ पर व्यापार लाभदायक नहीं रहता है।

(३) समान ग्रन्तर—उपरोक्त दोनों उदाहर एों से स्पष्ट होता है कि उत्पादन व्यय के निरपेक्ष ग्रौर तुलनात्मक दोनों प्रकार के ग्रन्तर श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को लाभ-दायक बना देते हैं ग्रौर दोनों ही दशाग्रों में पारस्परिक व्यापार दोनों देशों के लिए हितकारी होता है। श्रब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि उत्पादन व्यय के समान भ्रन्तरों का परिगाम क्या होगा। नीचे का उदाहरण इस प्रकार के भ्रन्तरों को दिखाता है:—

प्रति मन	सीमान्त उत्पादन	न्यय	(रुपयों मे)
चाय			चीनी
भारत	980		٧o

चीन १२० ३०

इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि चीन को भारत की तुलना में चाय और चीनी दोनों के उत्पादन में श्रीष्ठता प्राप्त है। दोनों का ही उत्पादन व्यय भारत की तुलना में नीचा है, किन्तु भारत में चाय और चीनी का अनुपात १ मन चाय = ४ मन चीनी रहेगा और इसी प्रकार चीन में भी दोनों का यही अनुपात रहेगा। यदि भारत दोनों का उत्पादन स्वयं करता है तो ४ मन चीनी के बदले में एक मन चाय प्राप्त होगी और यदि केवल चीनी का उत्पादन करके चाय चीन से मंगाता है तो भी ४ मन चावल के बदले में १ मन चाय ही मिलती है (यदि हम यह मान लेते हैं कि यातायात व्यय नहीं होता है)। ठीक यही बात चीन के विषय में भी कही जा सकती है और उसे भी भारत को चाय अथवा चावल भेजकर कोई लाभ नहीं होता है। भय उल्टा यह है कि यातायात व्यय के कारण व्यापार में हानि हो सकती है। निश्चय है कि ऐसी दशा में आपस में व्यापार का प्रश्न नहीं उठता है। इस प्रकार लागत के समान अन्तरों की दशा में दो देशों के बीच व्यापार नहीं होगा।

#### विदेशी व्यापार के लाभ-

देशी ट्रियापार की भाँति विदेशी व्यापार भी इसलिए किया जाता है कि उससे लाभ होता है। विदेशी व्यापार के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं:—

- (१) प्रादेशिक श्रम विभाजन—इसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच प्रादेशिक श्रम विभाजन सम्भव होता है। ग्रलग-ग्रलग देश केवल ऐसी वस्तुश्रों के उत्पाटन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं, जिनके उत्पादन में ग्रधिकतम् योग्यता ग्रथवा कुशलता प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक देश ऐसी वस्तुश्रों का उत्पादन करता है जिन्हें वह न्यूनतम् लागत पर उत्पन्न कर सकता है। इसके फलस्वरूप संसार भर में उत्पत्ति ग्रनुकूलतम् दशाश्रों के ग्रन्तर्गत होती है श्रौर मानव कल्याण की वृद्धि होती है।
- (२) उपभोक्ताम्रों को सस्ती वस्तुयें मिलना—विदेशी व्यापार द्वारा उपभोक्ताम्रों को यह सुविधा मिलती है कि वे उन बाजारों से प्रपनी ग्रायश्यकता की बस्तुयें खरीदें जहाँ वे सबसे कम मूल्य पर मिलती हैं। इससे संसार भर में मानव समाज का उपभोग-स्तर ऊँचा उठता है। साधारगृतया विदेशों से माल मँगाया ही इसलिए जाता है कि वह देश में तैयार होने वाले वैसे ही माल की तुलना में सस्ता

होता है। इसके श्रतिरिक्त इस व्यापार द्वारा बहुत सी ऐसी वस्तुएँ भी प्रान्त हो जाती हैं जो अपने देश में उत्पन्न ही नहीं हो सकती हैं।

- (३) म्राथिक संकट काल में सहायता—ग्राथिक संकटों के कहों को भी विदेशी व्यापार की सहायता से काफी कम किया जा सकता है। कहा जाता है कि ग्राधुनिक दुर्भिक्ष ग्रनाज या वस्तुओं के ग्रभाव से उत्पन्न नहीं होते है, वितक क्रयः शक्ति के ग्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे संकट के काल में दूसरे क्षेत्रों से ग्रन्न तथा दूसरी ग्रावश्यक वस्तुएँ मँगाई जा सकती हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार ग्राधिक कहों को कम करता है।
- (४) वस्तुश्रों श्रौर सेवाश्रों के मूल्यों में समानता की प्रवृत्ति—विदेशी व्यापार के कारण संसार भर में लगभग सभी वस्तुश्रों श्रौर सेवाश्रों की कीमतों के समान रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। सभी देशों में श्रर्थ-व्यवस्था के विकास श्रौर उपभोग-स्तरों में समानता श्रा जाती है। इससे मजदूरियों तथा कार्य की दशाश्रों में भी समानता श्राती है, जिसके कारण लागत के तुलनात्मक अन्तरों के लाभ श्रौर भी सरलता से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- (५) उत्पादन विधि में सुधार को बढ़ावा—विदेशी प्रतियोगिता का भय देशी उत्पादकों को सुधार की ग्रोर कार्यशील रखता है। वे उत्पादन विधियों में इस प्रकार के सुधार करते रहते हैं कि उत्पादन व्यय कम से कम रहे। इसके ग्रितिरक्त इससे प्रवन्व की कुशलता में भी उन्नति होती है। परिग्णाम यह होता है कि उपभोक्ताग्रों को कम से कम मूल्य पर वस्तुएँ ग्रीर सेवाएँ प्राप्त हो जाती हैं।
- (६) कच्चे माल की उपलब्धता—विदेशी व्यापार की सहायता से आव-श्यक कच्चे माल, मशीनरी तथा शिल्प योग्यता विदेशों से मंगाकर देश के औद्योगी-करण को आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे देश के साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है।
- (७) सांस्कृतिक सम्बन्ध व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग—सामाजिक दृष्टिकोरा से विदेशी व्यापार संसार के विभिन्न देशों के बीच सम्पर्क स्थापित करके अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना का विस्तार करता है।

#### विदेशी व्यापार की हानियाँ—

लाभों के साथ-साथ विदेशो व्यापार के कुछ गम्भीर दोष भी है, जो कुछ ग्रंश तक इन लाभों के ग्रन्छे परिगामों को नष्ट कर देते हैं। श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के श्रिध-कांश लाभ तभी प्राप्त होंने हैं जबिक विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक सद्भावना हो श्रीर व्यापार पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध न हों, परन्तु श्राधुनिक संसार में न तो पारस्परिक सद्भावना ही है श्रीर न श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का मार्ग निष्कंटक ही है । विदेशी व्यापार की प्रमुख हानियाँ निम्न प्रकार है:—

मु॰च॰ग्न॰ (२४)

- (१) कच्ची सामग्री की समाप्ति—विदेशी व्यापार द्वारा देश के बहुत से ऐसे साधन समाप्त हो सकते हैं जिनका प्रतिस्थापन भी सम्भव होता है। बहुत से देशों में कोयला, पैट्रोल तथा ग्रन्य भूगर्भ स्थित पदार्थ इसी प्रकार समाप्त होते जा रहे हैं। भारत की मैंगनीज ग्रीर ग्रवरक की खान बराबर खाली होती जा रही हैं ग्रीर देश को इन ग्रावश्यक घातुग्रों का समुचित मूल्य भी नहीं प्राप्त हो रहा है। यदि इन घातुग्रों का उपयोग देश के ग्रन्दर ही ग्रीचोंगिक मालों के तैयार करने में किया जाता तो एक ग्रीर तो इनके उपयोग में बचत की जा सकती थी ग्रीर दूसरी ग्रीर इसका ग्राधिक लाभपूर्ण उपयोग हो सकता था।
- (२) विदेशी प्रतियोगिता के घातक प्रभाव—विदेशी व्यापार देश के उद्योगों के लिए विदेशी प्रतियोगिता उपस्थित करता है। इसके द्वारा विकसित देशों को तो लाभ होता है, परन्तु अविकसित देशों में उद्योग-घन्धे या तो स्थापित ही नहीं हो पाते हैं या स्थापित होने के पश्चात् पनपने नहीं पाते हैं।
- (३) देश का एकांगी विकास—विदेशी व्यापार देश के ग्राधिक विकास को एक-दिशायी करके देश के लिए भारी समस्यायें उत्पन्न करता है। संकटकाल में ऐसे विकास के दुष्परिएगम भयंकर रूप में प्रकट होते हैं। दोनों महायुद्धों के काल का अनुभव यह स्पष्ट करता है कि जो देश खाद्य-पदार्थों अथवा अन्य ग्रावश्यक वस्तुओं के लिए विदेशी व्यापार पर निर्भर रहते हैं, युद्धकाल में उनके कष्टों की कोई भी सीमा नहीं रहती है। विदेशी व्यापार के इसी दोष ने बीसवीं शताब्दी में ग्राधिक राष्ट्रीयवाद को जन्म दिया है। उत्पत्ति के विशिष्टीकरए। के कारए। देश के कितने ही साधन बेकार पड़े रहते हैं, रोषगार का समुचित विकास नहीं होने पाता है और देश के ग्राधिक जीवन की स्थिरता भी संकट में पड़ जाती है।
- (४) विदेशों पर निर्भरता—विदेशी व्यापार विभिन्न देशों की ग्रथं-व्यवस्थाग्रों को एक दूसरे पर श्रवलम्बित कर देता है। यह निर्भरता सदा श्रच्छी नहीं होती है, क्योंकि किसी एक देश में ग्राने वाले ग्राधिक संकट का प्रभाव संसार भर में व्यास हो जाता है।
- (५) म्रादतों पर स्थायी प्रभाव—विदेशी व्यापार देश की उपभोग सम्बन्धी म्रादतों में भी हानिकारक परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है। दीर्घकाल तक चीन के निवासी म्रफीम खाने के म्रादी बने रहे हैं, यद्यपि उस देश में म्रफीम का उत्पादन विल्कुल नहीं होता है।
- (६) अन्तर्राष्ट्रीय द्वेष—विदेशी व्यापार के कारण प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा अवश्य मिला था, लेकिन आजकल यह अन्तर्राष्ट्रीय द्वेष और युद्ध का आघार बना हुआ है। विदेशी व्यापार बढ़ाने की भावना ने उपिनवेश-विद्या को जन्म दिया और अनेक राष्ट्र गुलाम बना कर शोषित किये जा रहे हैं।
  - (७) राशिपातन का भय-यह देखा गया है कि विदेशी बाजार को हथि-

याने के लिए कुछ देश प्रारम्भ में वहाँ ग्रिति कम मूल्य पर वस्तुयें वेचते है ग्रीर जब देशी उद्योग नुकसान उठाकर वन्द हो जाते हैं तब मनमाना मूल्य चार्ज करके जनता का शोषएा करने लगते हैं।

- ( प्र ) जीवन-स्तर में गिरावट—देश के व्यापार ऊँचे मूल्य पर वस्तुएँ बेचकर लाभ श्रर्जन करने के हेतु वस्तुश्रों का निर्यात कर देते हैं, जिससे कभी-कभी स्वदेश में वस्तुश्रों की कभी हो जाती है तथा नागरिकों का जीवन-स्तर गिर जाता है।
- ( ६ ) खेतिहर देशों को हानि—जब एक खेतिहर देश किसी ग्रौद्योगिक देश से विदेशी व्यापार करता है, तो उसे हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि वह ऐसी वस्तुएँ भेजता है जोकि वढ़ती हुई लागत के नियम के ग्रन्तगंत पैदा की जाती हैं ग्रौर ऐसी वस्तुयें मंगाता है जोकि घटती हुई लागत के नियम के ग्रन्तगंत पैदा की जाती हैं।

इस प्रकार विदेशी व्यापार की अनेक हानियाँ हैं। २० वी शताब्दी में भी इसके अनेक गम्भीर परिगाम हिंछगोचर हुए हैं। पारस्परिक सद्भावना के स्थान पर इसने अन्तर्राष्ट्रीय द्वेष तथा भगड़ों को प्रोत्साहन दिया है। इसने देशों को दासता की बेड़ियों में जकड़ दिया है और यह उनके अर्थिक और राजनैतिक शोपगा का भारी कारगा रहा है, परन्तु फिर भी किचित यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि विदेशी व्यापार के लाभ हानियों की अपेक्षा अधिक हैं।

# अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ की सीमाएँ —

यहाँ पर हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ का अंश किन वातों पर निर्भर होता है। टाउजिंग (Taussig) का विचार है कि किसी देश को विदेशी व्यापार से होने वाला लाम दो बातों पर निर्भर होता है— अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय अथवा व्यापार की शतें और निर्यात की वस्तुयें उत्पन्न करने में देश की उत्पादन चमता। इन दोनों का अलग-अलग विवेचन निम्न प्रकार है—

(१) व्यापार की शर्ते (Terms of Trade)—इन शर्तों का अभिप्राय उस अनुपात से होता है जिस पर दो देशों में उत्पादित वस्तुओं का आपस में
विनिमय होता है। यदि हम भारत और बर्मा का उदाहरण लेते हैं और व्यापार
न होने की दशा में भारत में १ मन पटसन के बदले में केवल है मन चावल प्राप्त होता
है, परन्तु व्यापार द्वारा बर्मा से कै मन चावल प्राप्त किया जा सकता है तो भारत का
लाभ कै—हे अर्थात किया विनेष्ण मन चावल होगा। इसी प्रकार बर्मा में यदि देश के भीतर
चावल और पटसन का अनुपात १: है है, परन्तु भारत से १ मन चावल के बदले में
है मन पटसन मिल सकता है तो बर्मा का लाभ है—हे अर्थात है मन पटसन होगा,
परन्तु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि यह विनिमय अनुपात दोनों देशों में एकदूसरे की उपज की प्रति-माँग (Reciprocal Demand) की स्थित पर निभंद
होता है। इसी माँग की आग्रहपूर्णता के अनुसार व्यापार की शर्तों में भी परिवर्तन

होते रहते हैं। प्रति-माँग की सापेक्ष स्रथवा तुलनात्मक लोच व्यापार की शर्तों स्रथवा सन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ की मात्रा को निश्चित करती है।

साम्य की दशा में विनिमय का अनुपात ऐसा होगा कि उस पर किसी देश के निर्यातों की कीमत उसके आयातों की कीमतों के बराबर हो जाय। इस प्रति माँग का प्रभाव व्यापार की शतों पर ही नहीं, बिल्क व्यापार के लाभों पर भी पड़ता है। टाउजिंग के अनुसार:—''उस देश को सबसे अधिक लाभ होता है जिसके निर्यातों की माँग सबसे अधिक होती है और जिसमें आयातों (दूसरे देशों के निर्यातों) औ माँग केवल थोड़ी सी होती है। उस देश को सबसे कम लाभ होता है जिसमें अन्य देशों की उपजों की माँग बहुत अधिक होती है।''

(२) उत्पादन क्षमता— अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों पर दूसरा प्रभाव निर्यात की वस्तुम्रों के उत्पादन में देश के श्रम की कुशलता का पड़ता है। वास्त-विकता यह है कि दो व्यापारी देशों के बीच लागत के अन्तरों का मूल कारण श्रम की कुशलता ही होती हैं। श्रम की कुशलता के बढ़ने से सापेच्च अथया तुलनात्मक लागतों का अन्तर बढ़ जाता है और लाभपूर्ण व्यापार का च्रित्र मी बढ़ जाता है। जिस देश में श्रमिकों की कार्य-कुशलता अधिक होगी उसके निर्यातों की माँग भी अधिक रहेगी, देश में जनता की मौद्रिक तथा वास्तविक दोनों ही प्रकार की मजदूरियाँ उँची रहेंगी व्यापार से भी ऐसे देश को लाभ अधिक होगा, क्योंकि वह अपनी निर्यात वस्तुम्रों का अधिक उत्पादन करके विनिमय में बहुत अधिक वस्तुम्रों को प्राप्त कर सकेगा।

किसी देश के अन्तर्राष्ट्रीय लाभ की मात्रा का अनुमान उसकी मौद्रिक आय (Money Income) से लगाया जा सकता है, क्योंकि देश को मौद्रिक आय के रूप में ही लाभ प्राप्त होता है। जिस देश की वस्तुओं की माँग विदेशों में बहुत व निरन्तर रहती है उस देश की मौद्रिक आय का स्तर ऊँचा होता है, क्योंकि वहाँ निर्यात उद्योग उन्नत हो जाते हैं, उनमें मजदूरी की दर भी अधिक हो जाती है और अन्य उद्योगों की मजदूरी भी बढ़ जाती है (क्योंकि श्रमिक अधिक मजदूरी वाले उद्योगों में जाने लगते हैं)।

#### **QUESTIONS**

उत्तनात्मक सापेच लागत के सिद्धान्त को विवेचना सिंहत समभाइये अर बतलाइये कि वास्तव में यह अन्तर्राष्ट्रीय अम-विभाजन को कहाँ तक स्पष्ट करता है ?

(Agra, B. A., 1958)

 श्र-तर्राष्ट्रीय व्यापार का श्रध्ययन द्यांतरिक व्यापार से विभिन्न किस त्राधार पर किया जाता है ? सममाकर लिखिए।

(Agra, B. A., 1957 Supp.)

- Discuss the principle of comparative costs and examine the criticisms against it. (Agra, B. A., 1955, 1956; Raj., B. A., 1956; Raj., B. Com., 1954; Jabalpur, B. A., 1958; Allahabad, B. A., 1958; Bihar, B. A., 1958)
- 4. Discuss the main factors that give rise to a separate theory of International Trade and describe briefly the advantages and disadvantages of foreign trade. (Agra, B. A., 1954)
- 5. "There is no essential difference between domestic and international trade and consequently no place for a special theory regarding international trade." Examine this statement carefully.

  (Rai., B. Com., 1957)
- 6. Discuss the advantages of International Trade.

(Rai., B. Com., 1957)

- 7. Distinguish between domestic and international trade and point out the advantages arising from the participation in International Trade. (Sagar, B. A., 1958)
- श्रुंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक परिव्यय नियम से आप क्या समम्मते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सदा इस नियम पर क्यों आधारित नहीं होता ?

(Sagar, B. A., 1957)

- 9. Examine fully the principle of comparative costs as an explanation of international trade. (Alld., B. A., 1958)
- 10. Explain the theory of comparative cost underlying international trade. (Aligarh, B. A., 1956)
- 11. Write short notes on :—
  International Trade Organisation श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ
  (Agra, B. A., 1959)

#### अध्याय २१

# मुक्त व्यापार एवं संरच्नण

(Free Trade and Protection)

व्यापार नीतियाँ (Trade Policies)—

इस ग्रघ्याय में हम इस बात का ग्रध्ययन करेंगे कि व्यापार नीतियाँ कितने प्रकार की होती हैं ग्रौर उनके क्या-क्या लाभ ग्रौर दोष होते हैं ? ग्रारम्भ में इतना बता देना मावश्यक प्रतीत होता है कि व्यापार नीति का त्राःशय देश द्वारा किये हुए उन सब कार्यों से होता है जो उस देश के वैदेशिक ऋार्थिक सम्बन्धों की व्यवस्था करने के लिए किए जाते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में इस सम्बन्ध में दो नीतियाँ महत्त्वपूर्ण रही हैं—( i ) मुक्त ग्रथवा स्वतन्त्र व्यापार ग्रौर ( ii ) संरक्षरा । मुक्त व्यापार का श्रभिप्राय अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की स्वतन्त्रता से होता है। एडम स्मिथ (Adam Smith) के शब्दों में, मुक्त व्यापार का अभिप्राय उस व्यापारिक नीति से है जिसमें घरेलू और विदेशो वस्तुओं में कोई अन्तर नहीं समभा जाता है और न किसी एक को बुरा समभा जाता है ग्रीर न दूसरे को विशेष ग्रधिकार दिये जाते हैं। इस व्यवस्था के ग्रन्तर्गत विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं श्रौर सेवाग्रों के ग्रावागमन पर किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती है श्रीर अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय अपनी स्वाभाविक गति से स्वत-न्त्रतापूर्वक चलता रहता है। संरद्धारा की नीति में व्यापारिक प्रतिबन्ध ऋनिवार्य होते हैं | वस्तुओं, सेवाओं श्रौर पूँजी के स्वतन्त्र श्रावागमन पर रोक लगाई जाती है श्रौर देश की ग्रान्तरिक ग्रर्थ-व्यवस्था को विदेशी ग्राधिक प्रभाव से मुक्त करने का प्रयत्न किया जाता है। साधाररातया संरक्षरा का उद्देश्य देश के उद्योगों की विदेशी स्पर्धा से रक्षा करना होता है। वस्तुओं के ग्रायात पर पूर्णतः ग्रथवा ग्राँशिक रोक लगा दी जाती है, जिससे कि गृह-उद्योगों को उन्नति तथा विकास का श्रवसर मिलता रहे। संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य तो यही होता है, किन्तु अनेक बार हस्तक्षेप के सभी कार्य, चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी क्यों न हों. जिनके कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्वा-भाविक ग्रथवा कृत्रिम बाघाएँ उत्पन्न होती हैं, संरक्षिण में सम्मिलित किये जाते हैं।

अब हम इन दोनों नीतियों का इस प्रकार अध्ययन करेंगे कि इनमें से कौन सी नीति अधिक उपयुक्त है। विशेष रूप में, हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि आर्थिक क्रियाओं के इस घ्येय को कि सामाजिक उत्पादन अधिकतम् हो, इन दोनों नीतियों में से प्रत्येक किस अंश तक पूरा करती है।

### मुक्त व्यापार के लाभ-

प्रतिष्ठित ग्रर्थशास्त्री सब के सब मुक्त व्यापार के पक्ष में थे त्रौर विदेशी व्यापार सम्बन्धी सभी बाधाग्रों को ग्रनुचित समभते थे। उन्होंने मुक्तं व्यापार की वांछनीयता को साधारणतया इसी कारण महत्त्वपूर्ण समभा था कि इससे श्रम विभाजन के सभी महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो जाते हैं। इसके पक्ष में निम्न तर्क रखे जाते हैं—

- (१) संसार में उत्पत्ति के साधनों का अनुकूलतम वितरण्—निर्वाधनावी नीति का परिणाम यह होता है कि उसके द्वारा उत्पत्ति के साधनों का संसार भर में अनुकूलतम् वितरण् होता है और इस प्रकार प्रस्तुत साधनों से अधिकतम् लाभ उठाया जा सकता है। अनियन्त्रित स्पर्धा के कारण् प्रत्येक देश ऐनी वस्तुओं के उत्पादन में विशेषता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है किनमें उसे प्राकृतिक अथवा अन्य कारणों से अधिकतम् लाभ अथवा सुविधा प्राप्त होती है। सारे संसार तथा प्रत्येक राष्ट्र की म्राय को अधिकतम् करने की रीति यही हो सकती है कि प्रत्येक देश में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाय जो वहां न्यूनतम् मूल्य पर उत्पन्न की जा सकती हैं।
- (२) अनुशाल एवं व्ययपूर्ण व्यवसायों की समाप्ति—अनियन्त्रित प्रतियो-गिता के कारणा अनुशाल तथा व्ययपूर्ण व्यवसाय कुछ ही समय पश्चात् ठप्प हो जाते हैं। केवल ऐसे ही उद्योग चालू रहते हैं जो कम लागत पर उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए उपभोक्ताओं को सभी स्थानों पर कम से कम कीमत पर वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त हो जाती हैं। इससे संसार भर में लोगों की वास्तिवक आय में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त मुक्त-व्यापार एकाधिकारों तथा औद्योगिक संघों को बनने से रोकता है, क्योंकि यह प्रतियोगिता पर आधारित होता है।
- (३) पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना—स्वतन्त्र व्यापार संसार के देशों को एक-दूसरे पर निर्भर बना कर उनके बीच पारस्परिक सद्भावना एवं सहानुभूति पैदा करता है। इसके द्वारा सभी देशों को यह ज्ञात हो जाता है कि उनमें से प्रत्येक का हित एक-दूसरे के हित तथा सभी के सामृहिक हित पर निर्भर है।
- (४) भौगोलिक स्थानीयकरण को प्रोत्साहन स्वतंत्र व्यापार के अन्त-गंत हर एक देश केवल वही वस्तुयें उत्पन्न करता है जिनके लिये उस देश में प्राकृतिक सुविधायें प्राप्त हों। इस प्रकार उद्योगों के भौगोलिक स्थानीयकरण को बढ़ावा मिलता है तथा श्रम विभाजन के लाभ प्राप्त होते हैं।
- (५) एकाधिकारी संघों पर रोक —पारस्परिक प्रतियोगिता के कारण एकाधिकारी संघों के विकास पर रोक लगती है ग्रीर वस्तुग्रों के मूल्य बहुत ऊँचे नहीं होने पाते हैं।
- (६) बाजार के क्षेत्र का विस्तार—स्वतन्त्र व्यापार में विदेशी व्यापार की वस्तुओं का क्रय-विक्रय दूर-दूर तक अनेक देशों से होने लगता है। इस प्रकार

उनका बाजार बहुत विस्तृत हो जाता है, वस्तुओं के मूल्य भी कम हो जाते हैं (विशेषत: तब जब कि उनका उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत किया जा रहा है)। इससे देशों को निरपेक्ष लाभ श्रौर तुलनात्मक लाभ श्रिधक मिलने लगते हैं।

# संरत्त्रण की वांछनीयता (Arguments for Protection)—

यद्यपि मुक्त-व्यापार के लाभ महत्त्वपूर्ण हैं, परन्तु इसमें कुछ ऐसे गम्भीर दोष भी हैं जिनके कारण ब्राधुनिक संसार के सभी देशों ने इस नीति का परित्याग कर दिया है। १६ वीं शताब्दी में इक्कलैंड तथा ब्रन्य बड़े-बड़े देश मुक्त व्यापार के भारी समर्थक थे, परन्तु प्रथम महायुद्ध के पश्चात् इसका संसार से अस्तित्व ही मिट गया है। साधारणतया संरक्षण का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों को घ्यान में रखते हुए राष्ट्रीय उद्योगों की उन्नति करना होता है, परन्तु ब्राधिक कारणों के ब्रतिरिक्त ब्रनेक बार राज्नैतिक कारण भी संरक्षण को प्रोत्साहन देते हैं। संरक्षण का वास्तिविक ब्राधार मनुष्य का स्वार्थ है। वह स्वभाव से ही प्रतियोगिता से घृणा करता है। संरक्षण के पक्ष में ब्रनेक तर्क रखे जाते हैं, परन्तु जैसा कि हम ब्रागे की विवेचना में देखेंगे कि कुछ तर्क तो मान्य हैं, परन्तु ब्रधिकाँश तर्क केवल कृत्रिम हैं। प्रमुख तर्क निम्न प्रकार हैं—

(१) शिशु-उद्योग तर्क (The Infant Industries Argument)-संरक्षण के पक्ष में यह तर्क सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस तर्क के जन्म-दाता जर्मनी के प्रसिद्ध राष्ट्रीयवादी ग्रर्थशास्त्री फ्रोडरिक लिस्ट (Frederich List) हैं । इस तर्क को इतना महत्त्वपूर्ण माना गया है कि मुक्त-व्यापार के महान् समर्थकों ने भी इसको स्वीकार किया है। शिशु-उद्योग तर्क का आधार यह है कि संसार के सभी देशों में ग्रार्थिक विकास की ग्रवस्था एक सी नहीं होती है। विभिन्न कारणों से कुछ देश श्रौद्योगीकरण का ग्रारम्भ शीझ कर देते हैं ग्रौर कुछ देश इस दिशा में पीछे रह जाते हैं। कालान्तर में विकसित देशों के उद्योगों को अनुभव पैमाने के विस्तार तथा शिल्प ज्ञान के कारए। कुछ विशेष सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं, जिनके कारए। उनकी प्रतियोगी शक्ति बढ़ जाती है। जिन देशों में उद्योगों का विकास देर में होता हैं वहाँ के उद्योग शिशु अवस्था में ही होते हैं, जो विकसित देशों के वयस्क उद्योगों की प्रतियोगिता की समता नहीं रखते हैं। इसमें तो सन्देह नहीं है कि यदि इन उद्योगों को उन्नति और विकास का अवसर दिया जाय तो कुछ समय पश्चात् ये भी प्रतियोगिता कर सकने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु यदि मुक्त-व्यापार नीति का ऋनुकरण किया जाता है तो विकसित देशों के उद्योग इन्हें फलने-फूलने से पूर्व ही नष्ट कर सकते हैं। इन शिशु उद्योगों को संरत्त्रण प्रदान करना श्रावश्यक होता है । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो विकसित देश अविकसित देशों का विकास ही नहीं होने देंगे। इस तर्क का श्राघार तो ठीक है, किन्तु इसके सम्बन्घ में यह कठिनाई है कि यह निर्एाय बहुघा कठिन होता है कि शिशु उद्योग को कैसे पहिचाना जाय ? ग्रनेक देशों ने इस तर्क के ग्राघार पर किसी भी उद्योग को शिशु उद्योग घोषित करके संरक्षण की नीति को उचित बताया है, परन्तु ग्राधुनिक ग्रथंशास्त्रियों का विचार है कि केवल उसी उद्योग को शिशु त्र्यवस्था में कहा जा सकता है, जिसे उद्योग सम्बन्धी सभी प्रकार की त्र्यान्तिर वचत तो प्राप्त हों, परन्तु त्र्यभी वाह्य वचत उपलब्ध न हो सकी हों। स्वयं लिस्ट ने कहा कि केवल निम्नलिखित तीन दशाग्रों में ही संरक्षण मिलना चाहिए:—

- (क) संरक्त्या का उद्देश्य राष्ट्र को श्रोद्योगिक शिक्ता प्रदान करना होना चाहिए। ऐसे देशों में संरक्षण नहीं होना चाहिए जहाँ पर श्रोद्योगिक उन्नति पहले से ही पर्याप्त हो चुकी है, अथवा जहाँ उद्योगों को उन्नति की कोई सम्भावना ही नहीं है।
- (ख) संरक्ष्ण त्र्यस्थाई होना चाहिए। यह केवल उन्हीं देशों के लिए लाभदायक हो सकता है जहाँ विदेशी प्रतियोगिता के कारण राष्ट्रीय उद्योगों की अवनित हो रही है। उद्योगों का समुचित विकास होते ही संरक्षण हटा लेना चाहिए। संरक्षण केवल शिशु अवस्था के लिए ही उपयुक्त होता है।
- (ग) कृषि उद्योग को संरच्न्या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ग्रन्य उद्योगों की उन्नति स्वयं ही उसकी भी उन्नति कर देगी।

शिशु उद्योग के ग्राघार पर बनाई गई संरक्षण-नीति में निम्न दोप हैं:—(i) शिशु उद्योग की पहिचान कठिन है। (ii) नये उद्योग को प्रदान किये गये संरक्षण में स्थायी होने की प्रवृत्ति रहती है प्रथात् जब उद्योग युवावस्था में भी पहुँच जाता है, तो सम्बन्धित उद्योगपित ग्रपने स्वार्थ-वंश संरक्षण को हटवाने के लिए तैयार नहीं होते। (iii) संरक्षण काल में उपभोक्ताग्रों को हानि होती है, क्योंकि उन्हें वस्तुग्रों का ग्रिषक मूल्य देना पड़ता है।

(२) बेकार साधन सम्बन्धी तर्क (The Idle Rosources Argument)—यह तर्क शिशु उद्योग तर्क से थोड़ा सा भिन्न है। इसका प्रान्तग यह है कि ऐसे देश को संरक्षण से लाभ होगा जिसमें बहुत से साधन वेकार पड़े हुए हैं। विदेशी प्रायातों के सुगमतापूर्वक तथा कम मूल्यों पर प्राप्त हो जाने के कारण यह सम्भव है कि देशवासी देश के साधनों का समुचित उपयोग ही न करें। ऐसी दशा में देश में साधनों की प्रचुरता होते हुए भी जनसाधारण में दिरद्रता हो सकती है। संरक्षण केवल शिशु उद्योगों को ही बढ़ने का अवसर नहीं देता है, उसके द्वारा पूर्णतया नये उद्योगों को खड़ा करके देश के साधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है श्रीर इस प्रकार देश में धन के उत्पादन को बढ़ा कर सामान्य उपभोग-स्तर को ऊँचा

(३) उद्योग विविधता का तर्क (The Diversification of Industries Argument)—यह तर्क भी सर्व प्रथम लिस्ट ने ही प्रस्तुत किया था।

किया जा सकता है।

उनका मत था कि एक देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का रहना ही प्रविक प्रच्छा होता है। यदि बहुत से ग्रण्डों को एक ही टोकरी में रख दिया जाता है तो उनके टूटने का ग्रधिक भय रहता है। इसी प्रकार यदि देश के समस्त साधनों को एक या दो-चार उद्योगों में ही लगा दिया जाता है तो इन उद्योगों में कुछ भी विष्क उत्पन्न होने से सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था ही अस्त-व्यस्त हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि देश की एक ही उद्योग पर निभरता दूर करने के लिए नये-नये उद्योगों को संरक्षण प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाय। ऐसा करने से दो मुख्य लाभ प्राप्त होंगे:—एक ग्रोर तो देश में सन्तुलित ग्रर्थ-व्यवस्था स्थापित करना सम्भव हो जायगा ग्रौर दूसरी ग्रोर देश के विविध प्रकार के सम्पूर्ण साधनों का उपयोग हो सकेगा, परन्तु इस तर्क के सम्बन्ध में हमें इतना ग्रवश्य स्मरण रखना चाहिए कि इसमें विशिष्टीकरण के लाभों का विस्मरण कर दिया गया है।

- (४) ग्राधार उद्योग तर्क (Key Industry's Argument)— इस तर्क के भ्रमुसार प्रत्येक देश को भ्रपने भ्राधार उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। देश का ऋार्थिक विकास ऋाधार उद्योगों की ही उन्नति पर निर्मर होता है। ऐसे उद्योग वे होते हैं जिनका तैयार माल ऋन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। लोहा श्रौर इस्पात उद्योग, रासायनिक पदार्थ उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग भ्रादि ऐसे ही उद्योग हैं।
- (५) रक्षा तर्क (Defence Argument)—यद् तर्क इस विश्वास पर धाघारित है कि देश की रक्षा और उसकी स्वतन्त्रता को स्थिर रखना अन्य सभी बातों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होता है, इसिलये देश की सैनिक शक्ति को बढ़ाने और बनाये रखने के लिये रक्षा उद्योगों को संरक्षण देना आवश्यक होता है। सैनिक उद्योग तथा वे उद्योग जो सेना के संगठन के लिये आवश्यक होते हैं, संरक्षण के अधिकारी हैं। आज के संसार में, जबिक प्रति दिन युद्ध के काले बादल मंडराते रहते हैं, इस तर्क का महत्त्व अधिक है।
- (६) वृत्ति सम्बन्धी तर्क (The Employment Argument)— इस तर्क का सार यह है कि यदि किसी देश में बेरोजगारी काफी ऋधिक है तो उसे दूर करने के लिए संरक्षण की नीति ऋधिक उपयुक्त होगी। संरक्षण का रोजगार पर दो दिशाओं में प्रभाव पड़ता है। श्रायातों के घट जाने से वर्तमान उद्योगों की उत्पादन शक्ति के विस्तार द्वारा रोजगार की वृद्धि होती है श्रीर श्रायातों के श्रभाव के कारण जो माँग श्रसन्तुष्ट रहती है उसकी पूर्ति के लिए नए-नए उद्योग खुल सकते हैं।
  - (७) घरेलू साधनों के रक्षण सम्बन्धी तर्क (Conservation of Domestic Resources' Argument)—स्वतन्त्र व्यापार द्वारा अनेक बार देश के साधनों का व्ययपूर्ण उपयोग होता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वतन्त्र व्यापार ने ब्रिटेन की कोयले की खानों को खाली कर दिया है। इसी प्रकार भारत के मैंगनीज

भीर भवरक के खनिज भण्डार का इसके कारए पर्याप्त उपयोग किया जा चुका है। स्मरण रहे कि इन वस्तुओं को प्रकृति ने केवल सीमित मात्रा में ही प्रदान किया है। इन बहुमूल्य धातु ओं को देश के अन्दर निर्भाण उद्योगों में उपयोग करके काफी अधिक लाभ कमाया जा सकता है। यदि कोई देश इन वस्तुओं के बचाव के लिये संरच्छा ीति को घहण करता है तो यह उचित ही होगा।

(द) प्रतिकारी ग्रथवा राशिपातन विरोधी तर्क (Retaliation or Anti-dumping Argument)—इस तर्क के यनुसार प्रतिकार के रूप में संरक्षण करों का लगाना उचित बताया जाता है। यदि कोई देश हमारे देश से आने वाले माल पर प्रतिबन्ध लगाता है तो हमें भी उस देश से आने वाले माल पर प्रतिबन्ध लगाता है तो हमें भी उस देश से आने वाले माल पर प्रतिबन्ध लगाने में संकोच नहीं करना चाहिए। राशिपातन के विरुद्ध संरक्षण कार्यवाही करना तो स्वतन्त्र व्यापार के पक्षपाती भी उचित समभते है, क्योंकि राशिपातन का उद्देश्य उत्पादन व्यय से भी कम कीमत पर माल वेचकर देशी उद्योगों को समाप्त करना होता है, जिससे कि भविष्य में एकाधिकारी द्वारा उसी माल का उन्चा मूल्य प्राप्त किया जा सके।

(६) राष्ट्रीय स्वावलम्बता तर्क (National Self-sufficiency Argument)— यह तर्क प्रथम महायुद्ध के परचात् प्रधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसके श्रनुसार देश को अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुयें स्वयं ही उत्पन्न करनी चाहिए। अधिकांश देशों का सामान्य अनुभव यही रहा है कि युद्धकाल में विदेशों से माल नहीं मंगाया जा सकता है, जिसके कारण एक और तो रक्षा व्यवस्था वलहीन हो जाती है और दूसरी और जनता को अधिक कष्ट होता है, अतः जब तक संसार से लड़ाई का भय पूर्णतया नहीं मिट जाता है, प्रत्येक देश को आवश्यकता की सभी वस्तुएँ देश में ही उत्पन्न करनी चाहिए।

(१०) द्रव्य को देश में रखने तथा गृह बाजार का तर्क (Keeping Money at Home Argument or the Home Market Argument)—यह तर्क ग्रमरीका की ग्रोर से ग्रनेक बार प्रस्तुत किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यद हम विदेशों से माल नहीं मंगाते हैं तो देश का द्रव्य देश में ही रहता है, परन्तु यह तर्क इस कारण निराधार है कि यदि हम श्रायात नहीं प्रहण करते हैं तो निर्यात भी नहीं कर पायेंगे। ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में द्रव्य के खोने या पाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ग्रन्तिम दशा में ग्रायातों ग्रीर निर्यातों का सन्तुलन होना ग्रावश्यक होता है। इसी तर्क से मिलता-जुलता तर्क गृह बाजार तर्क भी है। ऐसा कहा जाता है कि संरद्धाण द्वारा उद्योगों का विस्तार करके श्रियंक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है श्रीर इस प्रकार गृह-ावाजार का भी विस्तार सम्भव होता है, परन्तु इस सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है कि श्रायातों के साथ-साथ निर्यात भी घटेंगे श्रीर गृह-बाजार के विस्तार की दशा में विदेशी बाजार का संकुचन होगा।

(११) मजदूरी तर्क (Wage's Argument)—इस तर्क के अनुसार एक ऐसे देश को जिसमें मजदूरी की दरें ऊँची हैं, ऐसे देश से माल के आने पर प्रतिवन्ध लगाने चाहिए जहाँ मजदूरियाँ बहुत कम हैं, क्योंकि ऐसा देश सदैव ही नीचे मूल्यों पर वस्तुएँ वेच सकता है।

#### संरत्नण विरोधी तर्क-

संरक्षण एक अमिश्रित आशीर्वाद नहीं है। अनेक बार उसके राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। संरक्षण नीति आर्थिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप की नीति होती है, इस कारण सरकार उसके परिणामों का व्यानपूर्वक अध्ययन करती है और यथासम्भव उससे उत्पन्न होने वाले दोषों को दूर करने का प्रयत्न भी करती है। संरक्षण के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं:—

- (१) अकुशल और सारहीन उद्योगों का पालन—संरक्षण बहुषा देश में ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करता है जो आर्थिक दृष्टिकोण से देश के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। कहा जाता है कि संरक्षण की ऊँची दीवारों के पीछे पूर्णतया अकुशल तथा सारहीन उद्योग भी पलते रहते हैं। ऐसे उद्योग एक विशेष समस्या उत्पन्न करते हैं। यदि उनका संरक्षण बन्द कर दिया जाता है तो प्रतियोगिता के कारण वे ठप्प हो जाते हैं और देश को पर्याप्त हानि होती है। इसके विपरीत यदि उन्हें निरन्तर संरक्षण के द्वारा ही जीवित रखा जाता है तो वे सदा के लिए देश पर एक प्रकार का भार बनु जाते हैं।
- (२) विशिष्टीकरण में बाधा श्रौर साधनों का श्रनार्थिक उपयोग— संरक्षण के कारण साधन ग्ररक्षित उद्योगों से हटकर रक्षित उद्योगों में जाने लगते हैं। इससे एक श्रोर तो विशिष्टीकरण के मार्ग में बाधा पड़ती है, जिससे कीमतें ऊँची ही बनी रहती हैं श्रौर दूसरी श्रोर साधनों का श्रनार्थिक उपयोग होता है। दोनों ही दशाश्रों में उपभोक्ताश्रों को हानि होती है। विशिष्टीकरण न होने के कारण उत्पादन-व्यय तथा मूल्य नीचे नहीं गिरने पाते हैं श्रौर श्रायातों के न रहने से मूल्य उपर चढ़ते हैं। उपभोक्ताश्रों द्वारा ऊँची कीमतों के का में जो श्रदृश्य कर दिया जाता है, वह भी सरकारी खजाने को नहीं जाता, बिल्क रक्षित उद्योगों के मालिकों के लाभों में वृद्धि करता है।
- (३) स्राय के वितरए। में स्रसमानता—संरक्षण बहुवा देश में स्राय के वितरए। की स्रसमानतास्रों में वृद्धि करता है। यह निर्धन वर्गों पर घनियों के लाभ के लिए स्रहश्य कर लगाकर उन्हें स्रोर भी घनहीन बना देता है।
- (४) श्रौद्योगिक संघों व एकाधिकारों को जन्म—विदेशी प्रतियोगिता को समाप्त करके संरक्षण देश में श्रौद्योगिक संघों श्रौर एकाधिकारों को उत्पन्न करता है।
  - (५) उद्योगों में शिथिलता-संरक्षण उद्योगों में शिथिलता उत्पन्न करता

है। प्रतियोगिता का भय न रहने के कारए। वे सुधार तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध की ग्रोर कम ही व्यान देते हैं।

- (६) राजनैतिक भ्रष्टाचार—बहुत बार संरक्षण द्वारा देश में निहित हित (Vested Interests) उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे राजनैतिक भ्रद्वाचार फैनता है।
- (७) राष्ट्रों में मन मुटाव —जब एक देश संरक्षण की नीति अपनाता है, तो दूसरा देश उसका प्रतिकार (Retaliation) करता है, जिससे परसार वेचैनी व मनमुटाव बढ़ता है और युद्ध तक छिड़ जाता है।
- (८) विदेशों व्यापार में कमी—संरक्षण के कारण विदेशों से ग्रायात व्यापार घट जाता है ग्रौर साथ ही निर्यात व्यापार भी, क्योंकि विदेशी सरकार भी प्रतिकार करती हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार का ह्रास होता है।
- (६) संरक्षरण के स्थायी होने की प्रवृत्ति एक वार संरक्षरण मिल जाने पर उद्योगपित अपने स्वार्थ वश उसे आवश्यक न होने पर बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं।
- (१०) उपभोक्ताग्रों को हानि होती है, क्योंकि उन्हें संरक्षित वस्तुग्रों के ग्रिषक मूल्य देने पड़ते हैं।

संरत्त्रण की रीतियाँ—

संरक्षण प्रदान करने की अनेक रीतियाँ होती हैं, परन्तु निम्न रीतियाँ अधिक प्रचलित हैं:—

- (१) संरक्षरा प्रशुल्क (Protective Tariffs)—यह रीति सबसे प्रिषक प्रचलित है। इसमें आयातों को रोकने के लिए उन पर आयात कर लगाये जाते हैं। व्यवहार में ऐसे कर अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे—यथामूल्य कर, जो मूल्य के एक निश्चित अनुपात के रूप में लगाया जाता है; प्रमाणिक कर, जो अलग-अलग दरों में लगाया जाता है, इत्यादि। इन करों का प्रभाव यह होता है कि विदेशों से आने वाले माल की कीमत बढ़ जाती है, जिसके कारण देश में उसकी खपत कम हो जाती है।
- (२) स्रायात स्रभ्यंश (Import Quotas)—यह संरक्षण की एक स्रिष्ठक सप्रभाविक रीति है। इसके स्रन्तर्गत विदेशों से स्राने वाले माल की स्रिष्ठिक तम् मात्रा निश्चित कर दी जाती है। कभी-कभी तो कुल स्रायात का स्रभ्यंश निश्चित कर दिया जाता है, परन्तु साधारणतया स्रन्ग-स्रन्य देशों में स्रभ्यंश पृथक-पृथक नियत किए जाते हैं। इस प्रकार स्रम्यंश निश्चित करके वस्तु विशेष की पूर्ति को नियन्त्रित किया जाता है और देश में उसके उत्पादन के लिए समुचित स्रवकाश रखा जाता है।
- (३) सरकारी म्राधिक सहायता इस रीति के त्र्यनुसार व्यापारियों श्रीर उद्योगपतियों को विशेष छूट, श्रनुदान, ऋग्ण त्र्रथवा स्त्रन्य प्रकार की

अप्रधिक सहायताएँ प्रदान की जाती हैं। देश के उद्योगपितयों को करों में छूट देकर, कम ब्याज प्रथवा दिना ब्याज पर ऋण देकर अथवा निर्यातों पर आर्थिक सहा-यता देकर देश में उत्पादन की वृद्धि की जाती है।

- (४) विनिमय नियन्त्रगा (Exchange Control)—इस प्रणाली में विदेशी विनिमय पर नियन्त्रगा लगा दिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आयातों पर प्रतिबन्ध लग जाते हैं।
- (१) निषेध (Prohibition)—इसके अन्तर्गत कुछ मालों का आयात अथवा निर्यात पूर्णतया वर्जित कर दिया जाता है।
- (६) स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्ध—यह संरक्षण की एक अनुठी रीति है। इसमें देश में आने वाले माल को कुछ विशेष रीतियों से रोग-मुक्त किया जाता है, जिससे उनके मुल्य बढ जाते है और प्रतियोगिता शक्ति का ह्यास हो जाता है।
- (७) विनिमय ह्रास अथवा अवस्त्यन—इसका विस्तृत अध्ययन एक पिछले अध्याय में किया जा चुका है। यहाँ पर केवल इतना हो बता देना पर्यात है कि इसके द्वारा विदेशों में निर्यात की कोमत घट जाती है और देश में आयातों की कीमत बढ़ जाती है, अतः आयात हतोत्साहित होते हैं एवं निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है।

#### निष्कर्ष—

संरक्षण की इन विभिन्न रीतियों के सम्बन्ध में यह निर्णय देना कठिन है कि इनमें से कौन सी रीति सबसे अधिक उपयुक्त है। प्रत्येक प्रणाली के अपने ही अलग-अलग गुण और दोष होते हैं। संसार में अधिक प्रचलन आयात प्रशुक्त का है, क्योंकि इसके द्वारा सरकार को भी आय प्राप्त हो जाती है और आयात करों के भार को एक अंश तक विदेशियों पर भी डाला जा सकता है, परन्तु आयात कर संरक्षण का एक बहुत ही शक्तिशाली उनाय नहीं है। अभ्यंश प्रणाली द्वारा संरक्षण का उद्देश्य पूर्ण रूप में पूरा हो जाता है, परन्तु यह बहुवा प्रतिकार (Retaliation) को जन्म देती है और भारी आधिक और राजनैतिक उलक्त उत्यन्न कर देती है। ठीक यही बात संरक्षण की अन्य रीतियों के विषय में भी कही जा सकती है। वास्तविकता यह है कि संरन्तुण की प्रत्येक रीति अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के विरुद्ध होती है।

### स्वतन्त्र व्यापार, उचित व्यापार एवं संरच्या—

स्वतन्त्र व्यापार वह व्यापार है जिसमें विभिन्न देशों के मध्य वस्तुत्रों का विनिमय बिना किसी बाघा के होता है, जबिक संरक्षण वह व्यापारिक नोति है जिसके अन्तर्गत स्वदेशी उद्योगों की लाभ-दृष्टि से विदेशी वस्तुत्रों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। दोनों ही नीतियाँ दोषपूर्ण हैं। किन्तु इनके बीच का एक मार्ग और है, जिसे अपनाकर दोनों नीतियों के लाभ प्राप्त करते हुए दोपों से बचा जा सकता है। यह मार्ग है उचित व्यापार की नीति अपनाने का। उचित व्यापार वह व्यापार है जिसमें प्रति-बन्ध विदेशियों के बनावटी लाभ के अनुचित प्रभाव को समाप्त करने के लिए लगाये जाते हैं। इस नीति का उद्देश्य यह है कि स्वृदेश के उत्पादक भी अपनी वस्तुओं को विदेशी उत्पादकों के साथ ही साथ बेच सकें। अतः उचित व्यापार में कर केवल इतना लगाया जाता है कि देशी व विदेशी वस्तुओं का मूल्य बरावर हो जाय।

#### QUESTIONS

- 1. "Protection must not be protection of excessive costs, inefficient methods and obsolete equipment, nor should it encourage the practice of relying on signs, cartels, tariffs and guaranteed marked rather than on efficient production." In the light of the above statement, examine the obligations of protected industries in India. (Agra, B. A., 1956 Supp.)
- 2. Discuss the arguments in favour of protection (संरच्या). Do you think India should adopt a policy of protection? What do you understand by Discriminating protection?

(Raj., B. A., 1958)

- 3. What are the arguments in favour of a 'policy of protection'?

  What is meant by a policy of 'discriminating protection'?

  (Raj. B. A., 1957)
- 4. नीट लिखिए—विवेचनात्मक संरत्न्य (Discriminating Protection). (Jabalpur, B. A., 1958; Agra, B. A., 1959)
- 5. Discuss critically the main arguments in support of free trade in the present condition of world trade.

(Agra, B. A., 1959)

संसार की वर्तमान व्यापारिक दशा में स्वतन्त्र व्यापार के पत्त में तर्कपूर्ण सुकाव दीजिए।

#### अध्याय २२

# व्यापार एवं भुगतान सन्तुलन

(Balance of Trade and Payments)

### व्यापार संतुलन का अर्थ-

वर्तमान काल में प्रत्येक देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में संरक्षण की नीति को अपनाता है। विभिन्न रीतियों द्वारा आयातों को घटाने व निर्यातों को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि व्यापार सन्तुलन देश के पक्ष में रहे। व्यापार सन्तुलन (Balance of Trade) का अर्थ आयात और निर्यात के अन्तर से होता है। यह अन्तर दो प्रकार का होता है:—

- ( म्र ) म्रनुकूल व्यापार सन्तुलन—जब निर्यात म्रिक्षिक भ्रौर भ्रायात कम होते हैं तो इस भ्रन्तर को भ्रनुकूल व्यापार सन्तुलन ( $Favourable\ Balance$  of Trade) कहते हैं । प्रत्येक देश यही प्रयत्न करता है कि उसका व्यापार संतुलन उसके पक्ष में रहे ।
- ( ब ) प्रतिकूल व्यापार संतुलन—जब ग्रायात ग्रधिक ग्रौर निर्यात कम होते हैं तो इन ग्रायातों व निर्यातों के ग्रन्तर को 'प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन' (Unfavourable Balance of Trade) कहते हैं। प्रत्येक देश इस बात का प्रयत्न करता है कि उसके देश का व्यापार सन्तुलन इस प्रकार का न रहे।

### भुगतान सन्तुलन का अर्थ-

वर्तमान काल में वस्तुग्रों के श्रनावा सेवाग्रों का भी ग्रावागमन भिन्न-भिन्न देशों के बीच में होता है। वस्तुग्रों के ग्रावात ग्रौर निर्यात के ग्रन्तर को, जैसा कि उपर समभाया जा चुका है, व्यापार सन्तुलन कहते है, परन्तु वस्तुन्त्रों व सेवान्रों न्नादि तथा देश के कुल निर्यातों व न्नावा जाता है। यह विवरण बहीसाते के एक पृष्ठ की भाँति प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें वायीं न्नार तो समस्त निर्यातों व जनकी कीमतों का व्यौरा दिया जाता है न्नीर दाहिनी न्नोर न्नायातों का सविस्तार वर्णन होता है। इस प्रकार एक न्नोर तो उन शीर्षकों को दिखाया जाता है जिन पर विदेशियों से भुगतान प्राप्त होते हैं न्नोर दूसरी न्नोर जन शीर्षकों को जिनके निमित्त विदेशियों को भुगतान किए जाते हैं। इन दोनों शीर्षकों के न्नुल न्नार को भुगतान सन्तुलन (Balance of Payment) कहते हैं। शीर्षकों के ग्रनुसार भुगतान सन्तुलन का विवरण निम्न प्रकार का होता है:—

विदेशियों से नीचे लिखे हुये कारगों से भुगतान प्राप्त किये जाते हैं:—

- (१) वस्तुम्रों के निर्यात,
- (२) सेवाग्रों के निर्यात,
- (३) विदेशी ऋगों तथा विनियोगों से प्राप्त होने वाली ख्राय, जिसमें मूलघन का लौटाना, ब्याज तथा लाभ सम्मिलित होते हैं.
- (४) विदेशी यात्रियों द्वारा देश में किया जाने वाला व्यय.
- (५) विदेशियों से प्राप्त होने वाले मुम्रावजे, युद्ध व्यय, दान, दण्ड म्रादि,
- (६) म्रन्य प्रकार के शोधन, जो विदेशियों से प्राप्त होते हैं।

विदेशियों को नीचे लिखे हुए कारणों से भुगतान किए जाते हैं:—

- (१) वस्तुग्रों के ग्रायात,
- (२) सेवाम्रों के म्रायात.
- (३) विदेशियों की ऋरण के चुकाने, ब्याज, लाभ आदि के रूप में किये जाने वाले शोधन,
- (४) देश के यात्रियों द्वारा विदेशों में किया जाने वाला व्यय,
- (५) विदेशियों को दिये हुये मुम्रावजे, दान, जुमीने इत्यादि,
- (६) विदेशियों को दिये जाने वाले भ्रन्य प्रकार के शोधन ।

भुगतान सन्तुलन बहुधा वार्षिक आधार पर बनाया जाता है और इसमें आयातों अर्थात् दाहिनी ओर के शीर्षकों की कीमत एक पूर्व निश्चित विनिमय दर के आधार पर लगाई जाती है, क्योंकि वैसे तो उनकी कीमत विभिन्न चलनों (Currencies) में होती है।

# भुगतान सन्तुलन श्रौर व्यापार सन्तुलन में भेद-

भुगतान संतुलन शब्द से ही मिलता-जुलता शब्द व्यापार सन्तुलन है। यह भी एक ऐसा विवरण होता है जिसमें भ्रायातों व निर्यातों का विस्तृत विवरण रहता है, परन्तु भ्रायात व निर्यात दो प्रकार के होते हैं, ग्रर्थात् हश्य (Visible) व ग्रहश्य (Invisible) । भुगतान सन्तुलन में तो इन दोनों ही प्रकार के भ्रायातों व निर्यातों को सम्मिलत किया जाता है, परन्तु व्यापार सन्तुलन में केवल हश्य निर्यातों व भ्रायातों (Visible Exports and Imports) को ही ज्ञामिल किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि भुगतान सन्तुलन का तो सदा ही सन्तुलन होता है, जबिक व्यापार सन्तुलन का सन्तुलन भ्रावद्यक नहीं होता है। भ्रायातों की मात्रा निर्यातों की तुलना से कम भी हो सकती है भ्रीर भ्रायक भी।

व्यापार सन्तुलन प्रतिकृल होने के कारण-

भारतवर्ष के पिछले कुछ वर्षों के विदेशी व्यापार की महत्त्वपूर्ण घटना व्यापार

सन्तुलन का भारत के विपक्ष में होना है। इस व्यापार के सन्तुलन के विपक्ष में होने के निम्नलिखित कारण हैं:—

- (१) भारत में मुद्रा प्रसार के कारण भिन्न-भिन्न उद्योगों की उत्पादन दर बढ़ रही है, जिसके कारण भारतीय माल विदेशों को सस्ते मूल्य पर नहीं भेजा जा सका है।
- (२) भारतीय माल भ्रधिक मात्रा में विदेशों को नहीं भेजा जा सका है, क्योंकि देश का उत्पादन घट गया है, विशेष तौर पर जूट निर्यातों का।
- (३) भारतीय उपभोक्ता विदेशी वस्तुश्रों का उपभोग श्रधिक करने लगे हैं, ग्रतः श्रायात बढ गया।
- (४) देश की ग्रौद्योगिक उन्नति करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की मशीनें ग्रायात की गई।
- (५) पाकिस्तान सरकार ने भारत के द्वारा किये गये लगभग सभी समभौतों को तोड़ा है और भारत से पाकिस्तान जाने वाले माल पर कर लगाये हैं, जिनके कारण भारत का पाकिस्तान को निर्यात कम हुआ।
- (६) खाद्य सामग्री भारत में इतनी पैदा न की जा सकी जो भारतवासियों के लिए पर्याप्त होती, अतः इसे भी विदेशों से आयात करना पड़ा है।
- (७) भारतीय व्यापारी माल में मिलावट करके विदेशों को भेजते हैं। भारतीयों की इस व इसी प्रकार की ग्रन्य वेईमानियों के कारणा विदेशों में भारत के माल की माँग कम हो गई है।
- ( प ) स्वेज नहर (Swez Canal) द्वारा व्यापार कुछ समय के लिए बन्द हो जाने के कारए। भी भारत के विदेशी व्यापार को घक्का लगा। इस नहर पर मिस्र की सरकार ने अपना कब्जा किया। नहर के राष्ट्रीयकरए। होने के कारए। जहाजों का आवागमन इसके द्वारा न हो सका।
- ( ६ ) देश की श्रौद्योगिक उन्नति के कारएा जो कच्चा माल व उत्पादन संबंधी माल भ्रौर वस्तुयें बाहर मेजी जाती थीं उनकी खपत श्रव भारत में ही होने लगी है, इसलिये देश के निर्यात कम हो गये हैं।
- ( १० ) कुछ राजनैतिक कारण भी देश के विदेशी व्यापार को प्रतिकूल बनाने के लिए उत्तरदायी है।

प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन को ठीक करने की रोतियाँ—

यदि व्यापार सन्तुलन अनुकूल है तो यह देश के लिए अच्छा ही समभा जाता है, क्योंकि विदेशियों को स्वर्ण अथवा वस्तुओं के निर्यात बढ़ाकर इसका भुगतान करना पड़ता है, परन्तु यदि व्यापार सन्तुलन देश के प्रतिकूल है तो इसके कारण देश के सम्मुख काफी गम्भीर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। स्वर्ण का निर्यात व बिदेशी ऋषण एक निश्चित सीमा के परे नहीं हो पाते हैं। ऐसी दशा में प्रतिकूलता को दूर करने के लिए निम्न उपाय किये जाते हैं

- (१) निर्यातों को बढ़ाना—इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्यात व्यापा-रियों को विदेशों में कम कीमत पर माल वेचने के लिए तथा घाटे को पूरा करने के हेतु अनुदान, ऋरण, निर्यात करों की छूट ग्रादि दिए जा सकते हैं और कच्चे माल सस्ते मूल्य पर निर्यात करने वाले उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि उत्पा-दक वस्तुओं का लागत मूल्य कम हो ग्रीर वे विदेशों में प्रतियोगिता करने के योग्य हो सकों।
- (२) श्रायातों पर प्रतिवन्ध—भिन्न-भिन्न रीतियों द्वारा ऐसी वस्तुश्रों के ग्रायातों पर प्रतिवन्ध लगाना चाहिए जो भारत में उत्पादित की जाती है ग्रीर जिनके उपभोग के बिना देशवासियों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुँचेगी । देशवासियों में देशी माल प्रयोग करने की भावनाएँ जागृत करने के लिए सभी सम्भव उपाय श्रपनाने चाहिए।
- (३) सूल्य ह्रास—इस रीति के अनुसार सरकार देशी चलन की वाह्य अथवा विदेशी विनिमय की कीमत में कमी करती है। इसका परिगाम यह होता है कि विदेशों में देशी माल की कीमतों गिर जाती हैं और इसके विपरीत आयातों की कीमतों ऊँची हो जाती हैं। देश के निर्यातों की विदेशों में माँग बढ़ने और देश में आयातों की माँग घटने से व्यापाराशेप फिर से सन्तुलित हो जाता है।
- (४) मुद्रा-स्फीति (Inflation)—बहुत बार ऐसा होता है कि एक देश अपने चलन की बाह्य कीमत में कमी करना नहीं चाहता। ऐसी दशा में व्यापाराशेय की त्रुटियों को दूर करने के लिए वह देश में मुद्रा संकुचन कर सकता है। इसका परि-एगाम यह होता है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घट जाती हैं और इसके विपरीत देशी माल विदेशियों को कम कीमत पर मिल जाता है, जो उसे अधिक मात्रा में मंगाने लगते हैं।
- (१) विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control)—यह व्यापार सन्तुलन की प्रतिकूलता को रोकने की एक व्यापक तथा विस्तृत विधि है। साधारण-तया मुद्रा संकुचन (Deflation) नीति के फलस्वरूप देशी ग्रर्थ व्यवस्था पर बुरे ग्रसर पड़ते हैं। ग्रवमूल्यन तथा हास के कारण देश के सम्मान को ठेस पहुँचती है और प्रशुल्क कर, ग्रम्थंश (Quotas) ग्रांदि प्रतिकार को जन्म देते हैं, इसिलए इन सभी उपायों को सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाता है। उपरोक्त नीतियों के दुष्परिणामों से बचने के लिए विनिमय नियन्त्रण किया जाता है। इसके ग्रन्तगंत ग्रायातों और निर्यातों पर इस प्रकार का नियन्त्रण लगाया जाता है कि वे सरकारी ग्राज्ञा के बिना नहीं किये जा सकते हैं। निर्यातकर्ताग्रों को सारा का सारा विदेशी विनिमय सरकार को सौंपना पड़ता है, जो उसे ग्रायातकर्ताग्रों में बाँट देती है। इसका परिणाम यह होता है कि ग्रायातों की कीमत कि भीतर ही रहती है।
- (६) सन् १६४६ में गोरवाला निर्यात प्रगति समिति (Gorwala Export Promotion Committee) की नियुक्ति भारत सरकार ने की थी।

इस कमेटी ने जो भी सुभाव निर्यात ्बढ़ाने के लिए भारत सरकार को दिये हैं, उन्हें भारत सरकार ने मान लिया है। इस कमेटी के सुभावों में से कुछ सुभाव नीचे दिये जाते हैं:—

- ( ग्र ) निर्यात व्यापार में सरकार कम हस्तक्षेप करे।
- (ब) जो माल निर्यात किये जाते हैं उन पर कर कम कर दिये जायेँ ग्रीर कूछ कर बिल्कुल नहीं लगने चाहिए, जैसे—बिक्री कर।
- (स) देश के खाद्य उत्पादन को बढ़ाना चाहिए, ताकि खाद्य वस्तुओं ना ग्रायात कम हो।
- (द) जो देश भारत से मनमुटाव रखते हैं उनके साथ भी भारत सरकार को ग्रपने व्यापारिक सम्बन्ध स्थिर रखने चाहिये।
- (य) भारतीय वस्तुयें भ्रच्छी किस्म की होनी चाहिए, ताकि विदेशी बाजारों में उन देशों के बने मालों के साथ प्रतियोगिता में ठहर सकें।
- (र) उत्पादकों को कच्चे माल प्राप्त करने की सुविधा देनी चाहिए, जिससे देश का उत्पादन बढ़े।
- (ल) निर्यात वस्तुग्रों में किये जाने वाले सट्टों को बन्द करना चाहिए, विशेष तौर पर जूट में।
- (व) भारत में कुछ ऐसे संगठनों की भी स्थापना करनी चाहिए जो कि देशवासियों में निर्यात बढ़ाने की भावना पैदा कर सकें।

#### **QUESTIONS**

- व्यापार-संतुत्तन श्रौर पावना लेखा (शोधनाधिक्य) में क्या भेद है ! इस भेद का क्या महत्त्व है ?
- 2. What is 'Balance of Payments'? How may disequilibrium arise in a country's balance of payments and how may such disequilibrium be corrected?

# अध्याय २३ भारतीय तटकर नीति

(Indian Fiscal Policy)

#### प्राक्कथन-

विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में यह सिद्धान्त मान्य कर लिया गया है कि राष्ट्रीय सरकार भौद्योगिक विकास में प्रगतिशील एवं सिक्तय भाग ले। प्रत्येक देश की सरकारी भौद्योगिक नीति का यह प्रमुख भाग रहा है कि सरकार अपने राष्ट्रीय साधनों के अनुसार एवं देश की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊगर लेती है। देश के औद्योगीकरण को गति देने में सरकार की तटकर नीति महत्त्वपूर्ण होती है। इसी दृष्टि से भारतीय औद्योगिक नीति की घोषणा में प्रशुक्क नीति को भी स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार—"सरकार की प्रशुक्क नीति (Tariff Policy) ऐसी रहेगी, जिससे अनुचित विदेशी प्रतियोगिता का अन्त होकर देश के उपलब्ब लोतों का पूर्णतम् उपयोग हो सकेगा तथा उपभोक्ताओं पर अनुचित प्रभार भी नहीं रहेगा।" परन्तु इसके पहिले भारत सरकार की नीति क्या थी, यह देखना आवश्यक है।

# सन् १६२१ के पूर्व की तटकर नीति-

सन् १६२१ से पूर्व भारत पर विदेशी सत्ता का केवल राजनैतिक ही नहीं, ध्रिपतु आधिक पंजा भी था। भारत की आधिक एवं व्यापारिक नीति का संचालन इज़्लेंड में बैठकर भारत सचिव करता था। तत्कालीन आधिक नीति की विशेषता भारत का आधिक शोषएा कर अंग्रेजी उद्योगों को बल देने में थी, इसलिए उस समय भारत जैसा विशाल बाजार इज़्लेंड के उद्योगों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि भारत केवल कच्चे माल का निर्यात करने वाला देश बना रहे तथा यहाँ का औद्योगिक विकास न हो, फलतः भारतीय शासन की मुक्त-व्यापार नीति रही, जिसमें विदेशी निर्माता मजे से भारतीय उद्योगों का गला घोंट सकते थे। भारत में जिस पूर्णारूपेण मुक्त-व्यापार नीति का अवलम्ब किया गया, वह सन् १८६२ तक रही। इस अविघ में किसी भी प्रकार के आयात अथवा निर्यात-कर नहीं लगाए जाते थे। कारण भारत से अधिकतर कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता था तथा अंग्रेजी माल का आयात होता था।

सन् १८६४ में परिस्थिति बदली, एक ओर तो भारतीय रुपए का अवमूल्यन हो रहा था और दूसरी और भारत सरकार की आर्थिक आवश्यकताएँ बढ़ रही थीं, भतः सरकार को आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिसम्बर सन् १८६४ में ५% श्रायात कर लगाना पड़ा, परन्तु रेल्वे के लिए श्रावश्यक सामान एवं यन्त्र-सामग्री श्रायात कर से मुक्त थी श्रोर लोहा एवं इस्पात के श्रायात पर १% श्रायात कर था। इस ग्रायात कर के लगाते ही लंकाशायर एवं मैनचेस्टर के मिल मालिकों ने हायतोबा मचाया, इसलिए भारत सरकार ने २० नम्बर सूत एवं इससे श्रच्छी किस्म के सूत पर तथा भारतीय कपड़े के उत्पादन पर ५% उत्पादन कर लगा दिया, जिससे ग्रायात कर का लाभ भारतीय निर्माताश्रों को न मिले। यह मुक्त-व्यापार नीति सन् १६१६ तक इसी प्रकार चालू रही तथा उसका पालन भी कड़ाई के साथ किया गया था।

सन् १९१४ में प्रथम विश्व युद्ध यारम्भ हुआ, जिससे भारत सरकार की यावश्यकताएँ बढ़ीं। इनकी पूर्ति के लिए सन् १९१६ में आयात कर ५% से ७५% कर दिया गया, परन्तु उत्पादन कर में वृद्धि नहीं हुई। इस प्रकार एक ओर तो आयात करों की वृद्धि तथा युद्ध के कारएा विदेशी आयात की कमी तथा दूसरी ओर युद्ध-जन्य माँग की अधिकता से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। इसी प्रकार भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर भी (जैसे—चमड़ा, चाय, कॉफी पटसन आदि पर) निर्यात कर लगाए गये एवं उनमें वृद्धि की गई।

युद्ध-काल में भारत का पर्याप्त श्रौद्योगिक विकास न होने के कारण शासकों को अनेक कठिनाइयाँ प्रतीत हुई । दूसरे, भारत में सन् १६०५ से स्वदेशी श्रान्दोलन की जड़ें मजबूत होनी लगीं, जिससे श्रंग्रे को भारत सम्बन्धी नीति की कड़ी श्रालोचना हो रही थी। तीसरे, जमनी के श्रनुभव से जहाँ उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देकर श्रौद्योगिक विकास हुआ था, उसके श्राधार पर संरक्षण नीति जापान श्रादि देशों में श्रपनाई गई थी। चौथे, युद्ध काल में श्रौद्योगिक दृष्टि से भारत पिछड़ा होने के कारण जो अनुभव शासकों को हुये उससे उनको मुक्त व्यापार नीति के दोषों का श्रनुभव हुशा। पांचवे, सन् १६१६ के श्रौद्योगिक श्रायोग ने भारत के श्रौद्योगिकरण के सम्बन्ध में छानबीन कर जो निर्णय दिया, उसमें कहा—"भविष्य में देश के श्रौद्योगिक विकास में सरकार को सिक्रय भाग लेना चाहिए, जिससे भारत मनुष्य एवं सामग्री की दृष्टि से श्रात्म-निर्भर हो सके।"

भारत में जो राजनैतिक परिवर्तन एवं जागृति हो रही थी उससे अंग्रेज शासकों को भारत के प्रति रुख में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया, अतः अगस्त सन् १६१७ में माँटेम्यू-चेम्सफोर्ड सुघारों की घोषणा हुई। इसमें भारतीयों को 'स्वयं-निर्णय' का अधिकार मिला। सन् १६२१ में ब्रिटिश सरकार ने वित्तीय कन्वेन्शन (Fiscal Autonomy Convention, 1921) के सुभाव स्वीकार कर लिए, जिनके अनुसार वित्तीय नीति के निर्घारण में, कुछ सीमाओं के अन्दर, भारत को स्वतन्त्रता दी गई।

# तटकर आयोग सन् १६२१ (Fiscal Commission)

श्रायोग की सिफारिश-विवेचनात्मक संरज्ञण-

इस ग्राथिक स्वतन्त्रता का परिचय तव मिला, जब ७ ग्रगस्त सन् १६२१ को भारत की तटकर नीति के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए तटकर आयोग की नियुक्ति हुई । इस श्रायोग के सभापति सर ग्रवाहीम रहिमत उल्ला थे । इस श्रायोग ने ग्रपनी रिपोर्ट सन् १९२२ में सरकार की प्रस्तृत की, जिसमें भारतीय उद्योगों की विवेकात्मक संरक्षरा देने की नीति की सिफारिश थी। म्रायोग ने भारतीय उद्योगों की जाँच करने के पश्चात् यह निर्णय दिया कि भारत कृषि प्रधान देश होते हुये भी इसमें उद्योगों के विकास के लिए प्राकृतिक स्विधाएँ बहुत हैं। कच्चे माल की विपुलता, सस्ता एवं पर्याप्त श्रम तथा श्रीद्योगिक विकास के लिए ग्रावश्यक विद्युत-शक्ति के निर्माण के साधन भी उपलब्ध हैं। इसी प्रकार पटसन तथा वस्त्र उद्योग ने जो विकास किया उससे यह स्पष्ट है कि भारत भ्रपने प्राकृतिक साधनों का पूर्ण लाभ उठाने में समर्थ है। ऐसी स्थिति में भारतीय उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। ग्रायोग ने यह भी सिफारिश की कि उपभोक्ताग्रों, जन-साधारण, कृषि, श्रौद्योगिक विकास के हित से तथा व्यापार सन्त्लन को अनुकूल रखने के लिए कुछ चुने हुए उद्योगों को संरक्षरा देना चाहिए, जिससे संरक्षण का भार जनता पर ग्रधिक न पड़े। सारांश में उद्योगों में विवेकात्मक संरक्षण की नीति अपनाई गई, जिससे केवल उन्हीं उद्योगों को संरक्षण दिया जा सकता था, जो ग्रावश्यक शर्ते पूरी करते हों। ये शर्ते निम्न प्रकार हैं:-

- (१) नैस्रिंगिक लाभ उद्योग ऐसा होना चाहिए, जिसको नैस्रिंगिक लाभ प्राप्त हों, चैसे कच्चे माल का विपुल प्रदाय, सस्ती शक्ति, श्रम का पर्याप्त प्रदाय प्रथवा विस्तृत घरेलू बाजार । भारतीय उद्योगों को संरक्षरण देने के पूर्व उसे प्राप्त होने वाली नैस्रिंगिक सुविधायों का विश्लेषरण किया जाय, जिससे किसी भी ऐसे उद्योग को संरक्षरण न मिल सके, जो समाज पर स्थायी रूप से भार बन जाय।
- (२) स्रावश्यक सहायता—उद्योग ऐसा होना चाहिये, जिसका विकास संरक्षण के ग्रभाव में होना ग्रसम्भव हो ग्रथना देश के हित की दृष्टि से उसका विकास जितनी शीं घ्रता से होना चाहिए वह न हो सके।
- (३) विश्व-प्रतियोगिता करने योग्य—संरक्षण ऐसे उद्योग को दिया जाय जो श्रन्ततः संरक्षण के बिना विश्व-प्रतियोगिता करने योग्य हो।

संरक्षण के इस त्रिमुखी (Triple) सिद्धान्त के म्रलावा तटकर म्रायोग ने संरक्षण की म्रन्य कुछ शर्तों की म्रोर भी संकेत किया है, जो कम महत्त्वपूर्ण हैं। संरक्षण देते समय जिन उद्योगों का उत्पादन-व्यय कम हो सकता है म्रथवा जो बहुप्रमाण उत्पादन कर सकते हों तथा देश की सम्पूर्ण माँग की पूर्ति निश्चित समय में कर सकते हों, ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिये। सुरक्षा के लिए म्रावश्यक उद्योग तथा

श्राघारभूत उद्योगों को किसी भी दशा में संरक्षण देने की सिफारिश श्रायोग ने की है। इसी प्रकार ग्रायोग ने ऐसे विदेशी माल पर जिसका राशि-पातन (Dumping) होता हो ग्रथवा जिनके निर्यात को विदेशों से ग्रार्थिक सहायता मिलती हो ग्रथवा जो देश प्रतिस्पर्धात्मक ग्रवमूल्यन (Depreciation) से निर्यात करते हों, ऐसे माल के श्रायात से होने वाली हानि से सुरक्षा के लिए संरक्षण देने की सिफारिश की। प्रत्येक प्रार्थी उद्योग के संरक्षण के सम्वन्ध में ग्रावश्यक जाँच करने के लिए प्रशुल्क-सभा की नियुक्ति करने की सिफारिश ग्रायोग ने की थी। यह सभा उद्योग के संरक्षण के सम्बन्ध में सरकार को ग्रावश्यक सलाह देगी।

# विवेकात्मक संरत्त्रण नीति कार्य रूप में--

ग्रायोग की सिफारिशों के ग्रनुसार भारत सरकार ने फरवरी सन् १६२३ से संरक्षण की नीति ग्रपनाई। संरक्षण के लिये सबसे पहिले माँग करने वाला लोहा एवं इस्पात-उद्योग था, परन्तु साथ ही ग्रन्य उद्योग भी थे। इस सम्बन्ध में ग्रावश्यक जाँच करने एवं संरक्षण की सिफारिश करने के लिए जुलाई सन् १६२३ में प्रशुल्क-सभा की नियुक्ति की गई।

सन् १६२३ से सन् १६३६ तक प्रशुल्क सभा ने ५१ उद्योगों की जाँच की, जिनमें नए प्रार्थी उद्योग तथा संरक्षणा की पुन: प्राप्ति के लिए आवेदन तथा अन्य तान्त्रिक जाँचों ना समावेश है। इन विविध जाँचों के फलस्वरूप ३५ वर्तमान उद्योगों को संरक्षण दिया गया, परन्तु १० को संरक्षण नहीं दिया तथा ६ उद्योगों को संरक्षण देने से इन्कार किया गया।

#### विवेकात्मक संरच्चण नीति की श्रालोचना-

तटकर ब्रायोग ने विवेकात्मक संरक्षण की जो त्रिमुखी सिद्धान्त बिस्तुत किया था, उसका हेतु केवल इतना ही था कि तीन में से कोई भी एक शर्त यदि उद्योग पूरी करता है, तो वह संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु वास्तविक व्यवहार में इस सिद्धान्त का अत्यन्त कठोरता से पालन किया गया, जिससे इस विवेकपूर्ण संरक्षण नीति का उपयोग विवेकहीनता से हुआ। संरक्षण को ब्राधिक विकास का साधन न सम-भिते हुए उसे केवल ऐसा साधन समभा गया, जिससे कुछ उद्योगों को संरक्षण द्वारा विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने को शक्ति प्रदान की जाय। ब्रध्यत् उद्योगों का महत्व देश के हित की हिंद से कभी भी नहीं ब्राँका गया। इस कारण देश का असन्तुलित भौद्योगिक विकास हुआ। भारतीय उद्योगों के कच्चे माल की विपुलता के सम्बन्ध में लगाई गई शर्त भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि जब इङ्गलैण्ड ब्रौर जापान के वस्त्र उद्योग देश में रुई की पर्याप्त उपज न होते हुए भी इतने सुदृढ़ हो सके तो भारतीय उद्योगों पर ही ऐसी शर्त क्यों लगाई जाय?

इसी प्रकार तटकर आयोग ने स्थायी प्रशुल्क सभा की नियुक्ति की सिफारिश की थी, परन्तु सरकार ने स्थायी प्रशुल्क सभा नियुक्त न करते हुए प्रत्येक उद्योग के लिए अलग-अलग सभायें नियुक्त कीं, जिनके सभासदों में भी समय-समय पर परिवर्तन होता रहता था। इस कारण प्रजुक्क सभा कोई भी दीर्घकालीन नीति नहीं अपना सकी, जिसका अस्थायी रूप से अनुकरण होता, जो इस नीति का सबसे बड़ा दोष था।

इस प्रकार विवेकात्मक संरक्षण नीति ने:— ''ग्रक्षि तथा श्रवहेलना से उद्योगों को जो निरुत्साहित सहायता दी जाती थी, उससे उद्योगों को उसके भाग्य पर छोड़ने के श्रलावा किसी भी प्रकार से उनकी सुरक्षा नहीं की। साधारणतः प्रशुक्क कार्य-प्रणाली तथा सरकार की विलम्बकारी नीति से जो संरक्षण मिलता भी था वह बेकार साबित होता था।''

# संरत्त्रण नीति का मूल्यांकन-

संरक्षण नीति का मूल्यांकन तभी न्यायोचित रीति से हो सकता है, जब देश की ग्रायिक स्थिति संरक्षण की ग्रविष में ग्रविषत रही हो। भारत की ग्रायिक स्थिति पर सन् १६२५ से सन् १६३१ तक मन्दी का प्रभाव रहा ग्रीर दूसरे प्रत्येक देश में राष्ट्रवाद का विकास तेजी से हो रहा था, जिसका परिणाम भारतीय ग्रर्थ-व्यवस्था पर हुए बिना नहीं रहा। फिर भी इस नीति के विरोध में जो ग्राक्षेप हैं तथा जिस ग्राथिक परिस्थिति से भारत जा रहा था, उसके होते हुए भी भारतीय उद्योगों ने संरक्षण की ग्रविष में काफी प्रगति की है। भारत का लोहा एवं इस्पात तथा शक्कर उद्योग भारत को स्वयं निर्भर बनाने में सफल हुए हैं, जिसका प्रमुख कारण संरक्षण ही था।

सन् १६२६ की ग्राधिक मन्दी में जब ग्रम्य देशों में उत्पादन गिर रहा था, उस समय भी भारत के प्रमुख उद्योगों का उत्पादन स्थिर रहा ग्रौर कुछ उद्योगों का बढ़ा भी। ग्रौद्योगिक उत्पादन की यह स्थिरता संरक्षण के कारण ही रही। इससे मन्दी के दुष्परिणामों से भारतीय उद्योगों की रक्षा हुई तथा विकास तीत्र गित से होता गया। इस्पात, कागज, दियासलाई ग्रादि संरक्षित उद्योगों ने ग्रपनी उत्पादन शिक्त बढ़ाकर देश में होने वाले ग्रायात वम किए। इससे देश के विदेशी विनिमय की बचत हुई। ग्रन्त में, ग्रौद्योगिक विकास के लिए ग्रावश्यक कच्चा माल ग्रादि की पूर्ति (जैसे — रुई, बांस एवं बांस की लुगदों, गन्ना ग्रादि) ग्रावश्यकतायें बढ़ने से कृषकों को लाभ हुग्रा तथा देश में रोजगारों के ग्रवसर बढ़े। साथ ही, संरक्षित उद्योग-क्षेत्र में नए-नए कारखाने खोले गये तथा उनसे सम्बन्धित सहायक उद्योगों का विकास भी हुग्रा। ये लाभ विवेकात्मक संरक्षण नीति की सफलता के परिचायक हैं। हाँ, इतना ग्रवश्य कहा जा सकता है कि यदि सरकार उद्योगों को संरक्षण देने में इतनी कड़ी शर्तें न रखती तो सम्भवतः देश में ग्राधारभूत उद्योगों का विकास तीत्र गित से होता, परन्तु यह साम्राज्यवादी नीति के विरोध में था ग्रौर भारत सरकार केवल सीमित क्षेत्र में ही कार्यं कर सकती थी।

# क्या संरत्त्रण जनता पर एक भार है?

जनता पर संरक्षण का भार जानने के लिए ग्रायात-कर एवं संरक्षण करों में भेद करना ग्रनिवार्य है। ग्रायात-कर सरकार की श्रायिक ग्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगाये जाते हैं तो संरक्षण कर उद्योग की सुरक्षा के लिए तथा विदेशी प्रति-योगिता के निवारण के लिए होते हैं। संरक्षण करों से जो वस्तु आज १) में मिलती है, वह जिस परिगाम में संरक्षण कर लगाये जाते हैं, उसी परिगाम में महिगी हो जाती है। यदि देश में संरक्षित उद्योग का उत्पादन व्यय वही रहता है, श्रर्थात् संरक्षण करों का भार जनता पर पडता है, परन्तु कितना ? इस सम्बन्ध में भारतीय ग्रथं-शास्त्रियों ने अनुमान लगाने के प्रयत्न किए, परन्तु उसका विश्वसनीय परिग्णाम नहीं निकल सका, क्योंकि "संरक्षण के भार में कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिनका सही निर्घारण ग्रसम्भव होता है। संरक्षण से संरक्षित उद्योग की उत्पादन कीमतों में क्या परिवर्तन हुमा. यह हम जान सकते हैं. परन्तु जब तक इस बात का भ्रनुमान न लगा लिया जाय कि किस हद तक विदेशी निर्माताग्रों ने भारतीय बाजार में मूल्यों को कम किया है अथवा संरक्षण के अभाव में भारतीय संरक्षित उद्योग के उत्पादन की क्या कीमतें होंगी, तब तक संरक्षण के भार का हम सही अनुमान नहीं लगा सकते। † फिर भी "भारतीय प्रशुल्क व्यवस्था में जिन उद्योगों को संरक्षरण दिया गया है, उनके स्वरूप से यह कहने का साहस किया जा सकता है कि संरक्षण का प्रमुख भार घनी लोगों पर ही पड़ा है । †

फिर भी संरक्षण का प्रभार विशेष रूप से उपभोक्ताग्रों पर ही पड़ता है, परन्तु वह किस हद तक पड़ेगा, यह संरक्षण की ग्रविध तथा संरक्षण की राशि पर निर्भर रहेगा। संरक्षण से संरक्षित उद्योग के वस्तुग्रों के मूल्य तो बढ़ेंगे ही, परन्तु वे कितने बढ़ेंगे, यह विदेशी निर्यातों की मूल्य-नीति तथा संरक्षित उद्योग की उत्पादन क्षमता पर निर्भर रहेगा। साथ ही, संरक्षण से समाज को होने वाले लाभों को भी देखना होगा, जंसे—रोजगारी में वृद्धि, उद्योगों का विकास एवं नवीन उद्योगों की स्थापना, लाभ, ग्राय-कर तथा राष्ट्रीय ग्राय में वृद्धि। इन सब घटकों को देखने से यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि संरक्षण का तत्कालीन भार उपभोक्ताग्रों पर होता है, परन्तु उद्योग की कायंक्षमता वढ़ने से घीरे-धीरे वह भार कम हो जाता है। इस हिंद से विवेकात्मक संरक्षण नीति से भारत को लाभ ही हुग्रा है।

# द्वितीय-विश्व युद्ध में एवं युद्धोत्तर संरक्तण नीति-

सन् १६३६ में द्वितीय विश्य युद्ध छिड़ते ही आयात कम हो गये तथा भारतीय उद्योगों पर युद्ध-जन्य माँग की पूर्ति करने की जिम्मेवारी आ गई। इससे युद्ध-काल में तत्कालीन उद्योगों का तो विकास हुआ ही, परन्तु नये उद्योगों की स्थापना भी हुई। युद्ध के कारण आयात बन्द हो जाने से एवं माँग बढ़ जाने से भारतीय उद्योगों को

<sup>†</sup> Tariffs & Industry—Dr. John Mathai.

प्रोत्साहन मिला, जिससे संरक्षण की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। युद्ध-काल में भारतीय उद्योग युद्ध के सफल संचालन में अधिकतम् गोग दे सकें, इसलिए भारत ने सन् १९४० में यह आश्वासन दिया कि युद्धोत्तर-काल में वर्तमान उद्योगों तथा युद्ध-काल में स्थापित नये उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता का भय होने पर सरकार संरक्षण प्रदान करेगी, परन्तु जो उद्योग युद्ध के समय संरक्षण पा रहे थे उनका संरक्षण चालू रहा।

हितीय विश्व युद्ध के अनुभव से जिससे सुरक्षा के खतरे वढ़ गये थे तथा युद्ध के स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ, उससे देश का औद्योगीकरण अनिवार्य हो गया। इसी दृष्टि से युद्धोत्तर औद्योगिक नीति की घोषणा अप्रैल सन् १६ ४ में हुई। इस नीति के अनुसार नवम्बर सन् १६४५ में युद्धकालीन प्रमून उद्योगों की जाँच के लिए २ वर्ष के लिये एक प्रशुक्क सभा का पुनर्गठन किया गया तथा उस पर नई जिम्मेवारियाँ लाशी गईं। यह जाँच तीन सूत्रों को घ्यान में रख कर होनी थी:— (१) उद्योग समुचित ज्यापारिक नीति पर स्थापित एवं कियाशील हैं अथवा नहीं। (२) समुचित समय तक संरक्षण देने के बाद क्या उद्योग सरकारी सहायता अथवा संरक्षण के अभाव में चालू रहेगा? (३) यदि उद्योग राष्ट्रीय हित की दृष्टि से आवश्यक है तो संरक्षण का भार समाज पर अधिक तो नहीं होगा?

इस सभा ने सन् १६४५ से झगस्त सन् १६४७ तक के १ ने वर्ष में ४२ उद्योगों की जाँच की, "परन्तु सन् १६४७ में राजनैतिक परिवर्तन हुए, उससे देश का आर्थिक ढाँचा बदल गया, इसलिए अक्टूबर सन् १६४७ में प्रशुत्क सभा का पुर्नीनर्भाएं तीन वर्ष के लिये हुझा, जिससे अन्तरिम अविध में स्थायी तटकर-नीति को अपनाया जा सके तथा इस नीति को लागू करने की स्थायी-शासन व्यवस्था हो। प्रशुत्क सभा पर पहिले कार्यों के अलावा अन्य निम्न कार्य एवं दायित्व और दिया गया—

- (१) ऐसे पूर्व स्थापित उद्योगों को जिनकी संरक्षरा अविध ३१-३-१६४७ को समाप्त'होती थी, उन्हें इस तिथि के बाद संरक्षरा देने के सम्बन्ध में जांच करना।
- (२) देश में निर्भित वस्तुग्रों के उत्पादन-मूल्यों की जाँच करना तथा उनकी कीमतें निश्चित करना।
- (३) संरक्षित उद्योगों की जाँच द्वारा देखरेख करना, जिससे संरक्षण करों ग्रथवा ग्रन्य सहायता का प्रभाव मालूम हो सके । ऐसे संरक्षण करों ग्रथवा सहायता में संशोधन करने की ग्रावश्यकता के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना तथा जिन शर्तों पर संरक्षण दिया है, उनकी पूर्ति पूर्णतः हो रही है एवं उनका प्रबन्ध कार्यक्षम है, यह निश्चित करना।

Hindustan Year Books.

(४) ग्रन्य कार्यं, जैसे: — मूल्यानुसार एवं निश्चित करों का विभिन्न वस्तुग्रों पर लगाये गये प्रशुक्क करों का मूल्यांकन एवं विदेशों को दी गई प्रशुक्क-सुविधाग्रों का ग्रध्ययन करना। साथ ही, संयोग, प्रन्यास, एकाधिकार तथा ग्रन्य व्यापारिक प्रतिबन्धों का संरक्षित उद्योगों पर होने वाला प्रभाव देखना।

## अस्थाई प्रशुल्क सभा की आलोचना-

ग्रस्थाई प्रशुलक सभा की कार्य नीति से स्पष्ट है कि विभिन्न उद्योगों के संरक्षण का माधार विवेकात्मक संरक्षण नीति से किसी प्रकार अच्छा न था। इस नवीन नीति में संरक्षण पाने वाले उद्योग का संगठन व्यापारिक आधार पर होना आव-रयक था। इससे कोई भी नवीन स्थापित उद्योग प्रशुल्क सभा के विचार क्षेत्र में नहीं मा सकता था भीर न कोई उद्योग ही संरक्षण की माँग कर सकता था. जिसकी पूर्णं रूप से स्थापना न हुई हो। संरक्षण की दूसरी शर्त के अनुसार उसी उद्योग को संरक्षरा दिया जा सकता था, जो प्राकृतिक एवं ग्रार्थिक सुविधाग्रों तथा लागत की दृष्टि से निश्चित समय में ग्रपना विकास कर सकेगा तथा संरक्षण की आवश्यकता न रहेगी। यह शर्त इतनी विचित्र है कि इस सम्बन्ध में पहिले से ही कोई निश्चित मत नहीं बनाया जा सकता था। इसी प्रकार सूरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के लिए स्रावश्यक उद्योगों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में यह शर्त थी कि संरक्षण देते समय यह देखना होगा कि जनता पर संरक्षण का भार ग्रधिक न पड़े, परन्तु किसी भी ग्रवस्था में संरक्षण का भार जनता पर तो पडेगा ही स्त्रीर उसके साथ ही संरक्षण से होने वाले लाभों से जनता को भी लाभ होगा. इसलिए ऐसा एकांकी विचार अनुपयक्त था। तीसरे, ग्रस्थाई प्रशुल्क सभा तीन वर्ष से ग्रविक ग्रविष के लिए संरक्षरा की सिफारिश नहीं कर सकती थी। इससे उद्योग को संरक्षण से आशातीत लाभ होगा. यह अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तो संरक्षरा के सम्बन्ध में ग्रनिश्चित भविष्य होने से उद्योगों को प्रोत्साहन का स्रभाव रहता था और साथ ही इतनी थोड़ी स्रविध में संरक्षरा के परिणामों की जांच भी ठीक रीति से नहीं हो सकती थी, परन्तु सन् १९४७ के पुनर्गठित प्रशुल्क सभा से संरक्षण का क्षेत्र व्यावक हो गया. क्योंकि इस सभा ने ग्रायात सरक्षक करों से संरक्षण देना पर्याप्त नहीं समभा । प्रस्तुत कुछ उद्योगों की सहायता के लिए विकास कोष (Development Funds) के निर्माण से सहायता देने की सिफारिश भी की । इस प्रकार भारतीय स्वतन्त्रता के पश्चात् की संरक्षण नीति व्यापक एवं देशी उद्योगों के लिए पोषक है।

# भारतीय तटकर-श्रायोग (Indian Fiscal Commission), १६४६-४०-

सन् १६४८ की श्रौद्योगिक नीति की घोषगा में भारत सरकार ने श्रपनी तटकर नीति स्पष्ट की थी। इसका उद्देश्य सरकार की श्रार्थिक नीति, भारत का जनरल एग्रोमेंट ग्रॉन ट्रेड एण्ड टेरिफ (सन् १६४७) तथा हॅबाना चार्टर का उत्तर- दायित्व देखते हुए भावी प्रशुल्क नीति निश्चित करना एवं उसकी कार्यवाही के लिए स्थायी व्यवस्था करना था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने ग्रप्रैल सन् १६४६ में भारतीय-तटकर ग्रायोग की नियुक्ति की।

श्रायोग का कार्यं निम्न बातों को ध्यान में रख कर प्रगुलक नीति निश्चित करना था:—

- (१) पिछले आयोग की नीति, उसके परिशाम एवं कियाओं की जाँच करना।
- (२) भविष्य में उद्योगों को संरक्षण देने की नीति निश्चित करना :— (ग्र) इस नीति को व्यवहार में लाने के लिए सुभाव देना। (ब) इस नीति की कार्यवाही से सम्बन्धित ग्रन्थ सुभाव देना।
- (३) भारत की विदेशी ग्राधिक जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में विचार करना।
- (४) श्रायोग को सिफारिशें करते समय यह देखना था कि उसकी सिफारिशें भारतीय संविधान एवं भारत सरकार की सन् १९४८ की श्रौद्योगिक नीति की घोषणा से विसंगत न हों।

इस श्रायोग ने श्रपना कार्य २५ जून सन् १६४६ को श्रारम्भ किया श्रोर २५ मई सन् १६५० में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की । आयोग ने सरकारी नीति को घ्यान में रख कर यह मान लिया है कि भारत में योजना-बद्ध अर्थ व्यवस्या होगी । इसी श्राघार पर आयोग ने अपनी सिफारिशें की हैं। इस श्रायोग ने प्रशुत्क संरक्षण को भारत के आर्थिक विकास का प्राथमिक साधन मान लिया है तथा यह संरक्षण आर्थिक विकास की योजना के अनुष्ट्य होगा । संरक्षण के लिए निम्न सिद्धान्तों की सिफारिश की है:—

- (१) योजनाबद्ध चेत्र के उद्योगों को तीन समूहों में बाँटना चाहिए:--
  - ( अ ) सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षात्मक (Strategic) उद्योग ।
  - (ब) ब्राघारभूत एवं मूल उद्योग (Basic & Key Industries)।
  - (स) ग्रन्य उद्योग।

पहिले समूह के उद्योगों को किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय महत्त्व की दृष्टि से संरक्षण देना चाहिए, फिर उसका जनता पर भार कितना ही क्यों न हो। दूमरे समूह के उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुक्त अधिकारियों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे ऐसे उद्योगों को दिये जाने वाले संरक्षण का स्वरूप एवं उसका परिमाण, ऐसी सहायता अथवा संरक्षण सम्बन्धी शर्तें एवं प्रतिबन्धों का निर्णय करें तथा किस हद तक संरक्षित उद्योग इन शर्तों को पूरा करते हैं, यह देखें। तीसरे समूह के उद्योगों को संरक्षण देते समय निम्न बातों पर ध्यान दिया जाय: (अ) उद्योग को प्राप्त आर्थिक सुविधायें, (आ)

उद्योग की वास्तिविक घ्रथवा संभवनीय लागत, (इ) उद्योग का समुचित समय में विकास होने की सम्भावना तथा (ई) संरक्षण के जिना उसके सफल संचालन की सम्भावना । इसके साथ ही यदि उद्योग को राष्ट्रीय हित की हिष्ट से संरक्षण अथवा सहायता देना वाँछनीय है तथा अन्य सुविधाओं को देखते हुए उसके संरक्षण का भार जनता पर अधिक न होता हो तो ऐसे उद्योग को संरक्षण देना चाहिए।

- (२) ऋन्य उद्योग जो किसी मान्य योजना के ऋंतर्गत नहीं ऋाते, उनके संरक्ष्मण का विचार उपरोक्त सिङान्तों के ऋाधार पर करना चाहिये।
- (२) त्रायोग का यह भी मत है कि संरच् एा के लिए किसी एक शर्त को ही त्रावश्यक न समका जाय, जैसे—कच्चे माल की स्थानीय प्राप्ति प्रथवा उद्योग की सम्पूर्ण देशी माँग की पूर्ति करने की शक्ति। यदि उसे अन्य आधिक सुविधायें प्राप्त हैं तो उसे संरक्षण दिया जा सकता है, इसलिए आयोग ने सिफारिश की है:—
  - (म्र) कचा माल किसी उद्योग को उपलब्ध नहीं है, किन्तु स्रन्य प्राधिक स्विधायें उपलब्ध हैं, जैसे—देशी बाजार, सस्ता एवं पर्यात श्रम।
  - (व) किसी भी उद्योग को संरक्षण देते समय वह सम्पूर्ण देशी माँग की पूर्ति करे, यह साधारणतः अपेक्षित नहीं है।
  - (स) उद्योग के संरक्षण सम्बन्धी विचार करते समय अपेक्षित (Potential) निर्यात बाजार का विचार करना चाहिए।
  - (द) संरक्षित उद्योगों के उत्पादन का कच्चे माल की भाँति उपयोग करने वाले उद्योग को क्षित-पूरक (Compensatory) संरक्षण मिलना चाहिए। इसका परिमाण निश्चित नहीं किया जा सकता है तथा वह कच्चे माल के स्वरूप, उपभोक्ताओं पर प्रभाव, उत्पादन (Finished-Products) की मांग ग्रादि वातों के ग्रनुसार निश्चित होना चाहिये।
  - (य) जो उद्योग प्रारम्भिक स्थिति में हैं अथवा नये हैं उनको संरक्षण मिलना चाहिए। विशेषतः ऐसे उद्योगों को जिनके निर्माण की लागत अधिक है अथवा जिनके संचालन के लिए उद्य कोटि के विशेषज्ञों की अधिक ग्रावश्यकता है।
  - (फ) राष्ट्रीय हित की दृष्टि से कृषि-उत्पादन को संरक्षरण दिया जा सकता है, परन्तु इनकी संख्या एवं संरक्षरण ग्रविध यथासम्भव कम होनी चाहिए, जो किसी भी स्थिति में ५ वर्ष से ग्रविक न हो।

श्रायोग का यह विचार है कि संरक्षित उद्योग पर उत्पादन कर लगाना उचित नहीं है। ऐसे कर केवल उसी दशा में लगाये जायँ, जब बजट के स्रोतों के लिए श्राव-श्यक हों तथा अन्य साधन उपलब्ध न हों। इसी प्रकार संरक्षित उद्योगों के कच्चे माल की कीमतें भी श्रावश्यकता के समय विधान द्वारा निश्चित की जा सकती हैं। उद्योग को संरक्षरा देने का स्वरूप एवं पद्धति ग्रिधिकाँगतः उत्पादित वस्तु के स्वरूप पर निर्भर होना चाहिए।

त्र्यायोग की ऋन्य सिफारिशों ये हैं:— (१) संरक्षरा-करों से जो वार्षिक ग्राय हो ज

(१) संरक्षरा-करों से जो वार्षिक म्राय हो, उसके कुछ भाग से एक विकास-कोप बनाया जाय । इस कोप का उपयोग उद्योगों को सहायता (Subsidy) देने के लिए हो ।

(२) उद्योगों को तीत्र गित से विकास करने की सुविधायें देने के लिए एक संगठन (After-care Organisation) बनाया जाय!

(३) एक स्थायी प्रशुक्त प्रायोग का निर्माण किया जाय, जिसके सभापति सहित ५ सदस्य हों। इस सभा का निम्न कार्य हो—

(ग्र) संरक्षण सम्बन्धी जाँच। (ब) राशिपातन (Dumping) सम्बन्धी मामलों की जाँच।

(स) संरक्षण कर तथा आयात करों के परिवर्तन सम्बन्धी जाँच।

(द) व्यापार समभौते के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रतुत्क-मुविधाओं की जाँच।

जनरल एग्रीमेंट ग्रॉन ट्रेंड एन्ड टेरिफ में भारत की सदस्यता के सम्बन्ध में ग्रायोग ने कहा है कि इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित निर्णय नहीं दिया जा सकता। फिर भी जब तक ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (I. T. O.) का भविष्य निश्चित नहीं

होता, तब तक भारत को जी० ए० टी० टी० की सदस्यता छोड़ना लाभकर न होगा, ग्रतः प्रशुक्क सुविधाओं के म्रादान-प्रदान सम्बन्धी सरकारी नीति उचित है, यह निर्णाय ग्रायोग ने दिया । भावी प्रशुक्क व्यवहारों के सम्बन्ध में ग्रायोग का मत है कि भारत को जो प्रशुक्क सुविधाएँ प्राप्त हों, उनके विषय में सरकार को निम्न वातों की ग्रोर

ध्यान देना चाहिये:—
(१) वस्तुएँ ऐसी हों जिनमें तत्सम् वस्तुग्रों के साथ विश्व-बाजारों में प्रतियोगिता है।

(२) वस्तुएँ ऐसी हैं जिनको विश्व-बाजारों में अन्य देशों की प्रतिवस्तुग्रों (Substitutes) की प्रतियोगिता का भय है।

(३) कच्चे माल की अपेक्षा निर्मित वस्तुओं को ऐसी सुविधार्ये मिलती हैं। इसी प्रकार प्रशुल्क सुविधाएँ देते समय भारत का लच्य:—
( i ) पूँजीगत वस्तुओं पर,

( ii ) श्रन्य यन्त्र एवं सामग्री पर, ( iii ) श्रावश्यक कच्चे माल पर केन्द्रित होना चाहिए।

इन सिफारिशों के ग्रनुसार स्थायी प्रशुल्क सभा के निर्माश के लिए १२ सितम्बर सन् १९५१ को प्रशुल्क स्रायोग अधिनियम स्वीकृत हुग्रा। इसके स्रनुसार २१

स्थायी प्रशुल्क सभा—

जनवरी सन् १६५२ को स्थाई प्रशुक्त सभा की नियुक्ति हुई, जिसका नाम प्रशुक्त आयोग (फिस्कल कमीशन) है। इस आयोग के तीन सदस्य हैं, जिनमें से एक सभा-पित है। अधिनियम के अन्तर्गत आयोग में न्यूनतम् एवं अधिकतम् सदस्यों की संख्या ३ व ५ है। विशेष कार्यों के लिए दो अतिरिक्त सदस्यों से अधिक सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। जनता के लिए आयोग की सभाएँ सामान्यतः खुली हैं, परन्तु विशेष मामलों में उस पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। आयोग के कार्य पहिली प्रशुक्त सभाओं से अधिक व्यापक हैं। इसी प्रकार सरकार को किसी भी उद्योग की जाँच आयोग को सौंपने का तथा उस सम्बन्ध में आयोग से रिपोर्ट माँगने का अधिकार है. जैसे:—

- (१) किसी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये संरक्षरण देना।
- (२) किसी उद्योग के संरक्षण के लिये कस्टम तथा ग्रन्य करों में परिवर्तन।
- (३) किसी वस्तु के राशिपातन के सम्बन्ध में तथा संरक्षित उद्योग द्वारा संरक्षगा का दुरुपयोग होने की दशा में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
- (४) रहन-सहन का व्यय तथा मूल्य-स्तर पर संरक्षण का परिणाम ।
- (प्र) व्यापार एवं वािराज्यिक समभौतों के ग्रन्तगंत दी जाने वाली सुविधाग्रों का किसी निश्चित उद्योग के विकास पर होने वाला प्रभाव।
- (६) संरक्षण के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली कोई श्रव्यवस्था। स्रायोग के कार्य—
  - (१) पूर्व स्थापित उद्योगों के अलावा ऐसे उद्योगों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में विचार करना, जिनकी स्थापना न हुई हो, परन्तु संरक्षण मिलने पर उनकी स्थापना हो सकती है।
  - (२) भ्रायोग भ्रपनी भ्रोर से संरक्षित एवं भ्रसंरक्षित उद्योगों की जाँच कर सकता है। इसी प्रकार सरकारी भ्रादेश पर वह किसी उद्योग को प्राथमिक संरक्षण (Initial Protection) देने तथा विशेष वस्तुश्रों की कीमतों के सम्बन्ध में जाँच कर सकता है। भ्रपनी भ्रोर से भ्रायोग ऐसी जाँच नहीं कर सकता।
  - (३) संरक्षरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में सामयिक जाँच कर रिपोर्ट देना।
  - (४) ब्रायोग को संरक्षण की दरें, संरक्षण अविध तथा संरक्षित उद्योग के उत्तरदायित्व सम्बन्धी शर्तें निश्चित करने का पूर्ण अधिकार है।

ं सन् १६५१ में ही सरकार ने इस ग्रिधिनियम में संशोधन किये, जिसने सरकार को यह ग्रिधिकार मिला कि वह किसी भी स्थिति में उद्योग को संरक्षण देने के लिए तटकर लगा सकती है। इसका उद्देश्य देश की कीमतों तथा विदेशी कीमतों के भन्तर का लाभ उठाने के लिए सट्टेबाजी का जोर न बढ़े, यह है।

#### जाँच के सिद्धान्त-

किसी भी उद्योग के संरक्षण का विचार करते समय ग्रायोग निम्न बातों की ग्रीर ध्यान देगा:—

- (१) भारत एवं प्रतियोगी देशों में उस वस्तु की उत्पादन लागत।
- (२) प्रतियोगी वस्तुओं का ग्रायात-मूल्य।
- (३) प्रतिनिधिक उचित बिक्री-मूल्य।
- (४) माँग, स्थानीय उत्पादन तथा ग्रायात का स्तर।
- (५) कुटीर, लघु तथा अन्य उद्योगों पर किसी उद्योग के संरक्षिण का प्रभाव।

जिस समय आयोग ने अपना कार्य आरम्भ किया, उस समय कुल ५३ मामले विचारार्थ थे, जिनमें से ५ संरक्षरा के, ३ कीमतों के तथा ४२ संरक्षित उद्योगों की जाँच के थे। यह कार्य अधिक होने के कारए। सरकार ने २६ संरक्षित उद्योगों के संरक्षरा की अविध एक वर्ष से बढ़ा दी। इस प्रकार आयोग ने संरक्षरा सम्बन्धी जो कार्य किया है, उसकी कल्पना अध्याय के अन्त के परिजिष्ट से हो सकती है।

#### वर्तमान संरच्या नीति-

वर्तमान संरक्षण नीति तथा युद्ध-पूर्व विवेकात्मक संरक्षण नीति युद्धोत्तर नीति से अधिक अच्छी है, जो देश के श्रीद्योगीकरण के लिये पोपक है। पहिले तो वर्तमान ग्रायोग का कार्य एवं श्रधिकार दोनों ही व्यापक हैं, जो पहली नीति में नहीं थे. जिस कारएा प्रज़लक सभाएँ चाहते हुए भी कुछ न कर सकती थीं। दूसरे, उद्योग को संरक्षण देने के लिए किसी भी एक शर्त पर जोर देना स्नावश्यक नहीं रहा. केवल यह देखना है कि वह उद्योग देश के हित में है ग्रथवा नहीं। तीसरे. सुरक्षात्मक एवं भ्राधारभूत उद्योगों को संरक्षण देने के लिये कोई भी वर्त नहीं है। उनको तो संरक्षण मिलेगा ही, जो देश की सुरक्षा, श्रौद्योगीकरण तथा स्वयं निर्भरता की दृष्टि से नीति में ग्रिधिक उपयुक्त परिवर्तन है। चौथे. युद्धोत्तर संरक्षण नीति में केवल तीन वर्ष के लिये संरक्षण दिया जायगा. इस सम्बन्ध में निर्ण्य देने के लिए प्रशुल्क ग्रायोग स्वतन्त्र है, जो प्रत्येक उद्योग की म्रावश्यकताम्रों एवं विशेषताम्रों पर निर्भर रहेगा। पाँचवें, पहिले प्रशुल्क सभा की सिफारिशों पर कार्यवाही करने के सम्बन्य में कोई समय निश्चित नहीं था. जिससे देर ही होती थी. परन्तु ग्रब सरकार की प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या कार्य किया गया, इसकी रिपोर्ट तीन मास के अन्दर संसद को देनी होगी और यदि विलम्ब होता है तो विलम्ब के कारगों को स्पष्ट करना होगा। इस प्रकार वर्तमान नीति स्वतन्त्र भारत की स्वतन्त्र एवं प्रशुल्क आर्थिक नीति की परि-चायक है, जिससे भारत की ग्राधिक व्यवस्था की उन्नति तेजी से हो सकेगी।

# भारत की व्यापारिक नीति (Commercial Policy of India)

'शाही म्रिधमान' की विचारधारा काफी पुरानी है, जिसका भारत में श्रीगरोश सन् १६०२ में हम्रा। शाही अधिमान का यह म्रर्थ है—''साम्राज्य का व्यापार वढाने के हेत् साम्राज्य के विभिन्न सदस्य देशों के बीच प्रशुल्क रुकावटों को यथासम्भव कम करना।" शाही अधिमान को अपनाने वाले देशों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे अपनी स्वतन्त्र प्रशुल्क नीति न अपनावें। कोई भी देश अपनी स्वतन्त्र प्रशुल्क नीति अपना सकता था तथा विदेशी आयात पर संरक्षण कर लगा सकता था. परन्त साम्राज्य के देशों से होने वाले ग्रायात पर कुछ तटकरों में ग्रिथमान देना होगा, ग्रर्थात उनसे अन्य देशों की अपेक्षा कम तटकर लिए जायेंगे। इस प्रकार संरक्षरण एवं शाही म्रिघमान दोनों को ही एक साथ कार्यशील रखना सम्भव था। यह नीति सर्व प्रथम कनाडा ने सन् १८९७ में अपनाई तथा ब्रिटिश माल को आयात करों में छूट दी। सन् १८६८ में उसने इसी प्रकार की सुविधाएँ अन्य देशों को देना भी स्वीकार किया. यदि श्रन्य देशों से कनाडा को समान सुविधाएँ मिलें, परन्तु संयुक्त राज्य (U. K.) से कनाडा को कोई भी सुविवाएँ नहीं मिलती थीं, क्योंकि उस समय इङ्गलैंड में मक्त-व्यापार-नीति होने से इङ्गलैंड ऐसी सुविधायें किसी भी देश को नहीं दे सकता था । इसके बाद सन् १६०२ में एक श्रीपनिवेशिक (Colonial) परिषद् हुई, जिसमें भ्रधिमान नीति का समर्थन किया गया तथा सामाज्य के उपनिवेशों को सिफारिश की गई कि वे इस नीति को अपनावें। सन् १९१७ में शाही युद्ध सम्मेलन (Imperial War Conference) तथा सन् १६२३ में शाही ग्राधिक सम्मेलन (Imperial Economic Conference) में इस नीति का समर्थन किया गया। फलस्वरूप सन् १९२२ में साम्राज्य के लगभग २६ देशों में यह नीति ग्रपनाई जा रही थी। इन सब सम्मेलनों एवं सुविधाग्रों के कारण तथा इङ्गलैंड में मुक्त-व्यापार नीति का परि-त्याग सन् १६३२ में होने के कारण, सन् १६३२ के बाही आर्थिक सम्मेलन, ग्रोटावा में इस नीति को साम्राज्य के अधिक देशों ने अपनाया। इस सम्मेलन में ही श्रोटावा समभौते पर भारत और इङ्गलैंड ने हस्ताक्षर किये तथा परस्पर माल के म्रायात-निर्यात पर प्रशुल्क सुविधायें देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया।

## भारत और शाही अधिमान—

सन् १६०३ में जब यह प्रश्न भारत के सामने सर्व प्रथम श्राया तब भारत ने इस नीति को अपनाने का विरोध किया। सन् १६१७ में यह प्रश्न फिर से उपस्थित हुआ, भारत ने इस नीति को अपनाने से इन्कार किया, परन्तु सन् १६२२ के तटकर आयोग को जब इम्पीरियल प्रीफरेंस को भारत में लागू करने के सम्बन्ध में विचार करने के लिए कहा गया तब इस आयोग ने 'सवार्त वाही श्रिधमान' (Conditional Preference) अपनाने के सम्बन्ध में सिफारिश की और मत दिया कि भारत की

ग्रौद्योगिक प्रगति उसके विशाल साधन एवं जन-संख्या की दृष्टि से बहुत कम है, ग्रतः वह शाही ग्रिधमान नीति सामान्य सिद्धान्तों पर नहीं ग्रपना सकता। 'सशतं शाही ग्रिधमान' के श्रन्तर्गत निम्न शर्ते होनी चाहिए:—

- (१) किसी वस्तु के सम्बन्घ में प्रशुत्क-सुविघाएँ देने के विषय में भारतीय संसद की राय ली जाय ।
- (२) भारतीय उद्योगों को दिया हुम्रा संरक्षरण ऐसी प्रशुल्क सुवि**घाम्रों से** कम न हो ग्रौर न प्रभावित हो।
- (३) भारत को ऐसी सुविघाएँ देने से सम्भावित लाभ की तुलना में किसी प्रकार उल्लेखनीय हानि न हो।
- (४) इङ्गलैंड के सम्बन्ध में यह ग्रधिमान ऐच्छिक हो तथा ग्रन्य देशों के लिए परस्पर ग्राधार (Reciprocity) पर हो ।

इस सिफारिश के होते हुए भी भारत सरकार को साम्राज्यवादियों की चाल में ग्राना ही पड़ा, जिससे सन् १६२७ में ब्रिटिश इस्पात, सन् १६३० में ब्रिटिश सूती वस्त्र के ग्रायात तथा सन् १६३३ में ब्रिटिश उगम की वस्तुग्रों के ग्रायात पर प्रशुल्क सुविधाएँ दी गईं। इसके पहले भी भारत से ब्रिटिश माल के ग्रायात पर ग्रन्य देशों के माल की ग्रापेक्षा ग्रायात करों में छूट मिलती थी, जैसे—सन् १६१६ में चाय के निर्मात करों में छूट, सन् १६१६ में चमड़े (Hidest & Skins) के निर्यात करों में १०% की छूट ग्रावि, परन्तु ग्रन्त में सन् १६३२ में भारत ग्रीर ब्रिटेन में ग्राटावा समभौता हुन्ना, जिससे भारत में शाही ग्रधिमान को ग्रपना लिया गया।

#### वर्तमान स्थिति-

दितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की ग्रापिक स्थिति में जो महान् परिवर्तन हुए उससे ग्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्राणीवि, ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सङ्घ ग्रादि विभिन्न संस्थाग्रों का विकास हुग्रा। ऐसी स्थिति में तथा दितीय विश्वयुद्ध में इङ्गलैंड की जो ग्राथिक हानि हुई तथा ग्रमरीका का महत्त्व ग्राधिक क्षेत्र में बढ़ा, उससे इङ्गलैंड को ग्रमरीकी पूँजीवाद की दासता माननी पड़ी, फलतः शाही ग्रधिमान नीति को घक्का लगा तथा विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के जो ग्रनेक सम्मेलन हुए, उनमें ग्रमरीका ने इस नीति का घोर विरोध किया। यह नीति ग्राज राष्ट्रसंव ग्रधिमान (Commonwealth Preference) के रूप में कार्य कर रही है। इसी प्रकार व्यापारिक समभौतों द्वारा धुभी एक-दूसरे देशों को प्रशुल्क-ग्रधिमान दिए जा सकते है। इस प्रकार के ग्रधिमान भारत ने सन् १६५१-५२ में ५२ करोड़ रुपयों के ग्रायातों पर दिए तथा भारत के २०५ करोड़ के निर्यातों पर ग्रधिमान प्राप्त हुए। इस सम्बन्ध में उद्योग मन्त्री श्री टो० टी० कृष्णामाचारी ने कहा — 'ग्रधिमान सम्बन्ध यह चित्र स्थिर न रहते हुए प्रति वर्ष एवं प्रति मास बदलता रहता है, किन्तु

वर्तमान स्थिति में यह चित्र भारत के लिए हानिकर नहीं है।" इसी सम्बन्ध में भावी नीति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा—''वर्तमान समय में हमारा विचार संयुक्त राज्य को ग्रिवमान देने की नीति परित्याग करने का नहीं है, क्योंकि उससे होने वाले लाभ हमारे पक्ष में हैं। ये ग्रिविक न हों, परन्तु निश्चित हैं, इसलिए में यह विश्वास दिलाता हूँ कि वर्तमान समय में यदि हम शाही ग्रिविमान नीति को बनाए रखते हैं तो भी भारत के हित बिल्कुल सुरक्षित हैं।" इससे स्पष्ट है कि जब यह नीति भारत के विपक्ष में होगी, उसमें ग्रवश्य ही देश हित में परिवर्तन होगा।

# फिर पहले विरोध क्यों ?—

किसी भी देश को शाही अधिमान लाभकर है अथवा हानिकर, यह उस देश में ग्रायात एवं उस देश से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर निर्भर रहता है। सन् १६०३ में जिस समय सर्व प्रथम इस नीति को श्रपनाने का प्रस्ताव रखा गया, उस समय भारत में उद्योगों की बाल्यावस्था थी एवं वे उद्योग ग्रच्छी तरह से संगठित नहीं थे। दूसरे भारत निर्मित वस्तुग्रों का ग्रायात तथा कच्चे माल का निर्यात करता था; इस कारण भारत के ग्रौद्योगिक विकास के लिए किसी भी प्रकार का ग्रिधमान देना हानिकर था। तीसरे भारत के म्रायात-निर्यातों का यदि विश्लेषण किया जाय तो भारत में लगभग ७०% म्रायात साम्राज्य के देशों से होता था, इसके विपरीत लगभग ६०% निर्यात साम्राज्य के बाहरी देशों को होता था। ऐसी स्थिति में यदि भारत साम्राज्य के देशों को किसी प्रकार का अधिमान देता तो अन्य देश भारत के प्रति विरोधी नीति अपनाते। यह भारत के विदेशी व्यापार, विशेषतः निर्यात व्यापार के लिए हानिकर होता । चौथे ग्रिधिमान से देश की ग्रायात करों से होने वाली ग्राय कम हो जाती तथा ग्रन्त में किसी भी प्रकार का साम्राज्य देशों को ग्रिधमान देने से भारतीय उद्योगों को मिलने वाले संरक्षरा का प्रभाव कम हो जाता। भारत यदि ग्रधिमान नीति ग्रपनाता तो निश्चित था कि भारत का विदेशी व्यापार ग्रधिकतर साम्राज्य के देशों से ही होता तथा ग्रन्य देशों से विदेशी व्यापारिक सम्बन्ध न बढ़ते। इन कारणों से उस समय भारत ने विरोघ किया ग्रीर साथ ही इङ्गलैंड स्वयं जब यह नीति नहीं ग्रपना रहा था, भारत को बाध्य न होना पड़ा, परन्तु सन् १९३० में इङ्गलैंड की न्यापारिक नीति में परि-वर्तन होते ही भारत को भी साम्राज्यवादी नीति के सामने भूकना ही पडा। इसके परिसाम स्पष्ट हैं कि भारतीय मुद्रा का स्टलिङ्ग देशों से म्राज भी गठबन्धन है, जिस कारण उसे रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। यदि ऐसा न होता तो भारत का विदेशी व्यापार जो लगभग ६०% स्टर्लिङ्ग देशों के साथ था, वह प्रभावित होता. परन्तू भारत अब अपनी स्वतन्त्र नीति अपना रहा है तथा द्विपक्षीय समभौते से उस नीति में सुटढ़ता स्राती जा रही है तथा हमारा विदेशी व्यापार स्टर्लिंग देशों के स्रलावा स्रन्य देशों से पर्याप्त मात्रा में बढ़ रहा है । भविष्य में यदि हमारे निर्यात व्यापार का

Loksabha Debate on 25-9-54.

अनुपात स्टर्लिंग क्षेत्रों की अपेक्षा अन्य क्षेत्र के साथ बढ़ जायगा तब निश्चय ही अधिमान नीति का त्याग होगा।

# द्धि-पत्तीय व्यापारिक समभोते (Bilateral Trade Agreements) —

जब दो देशों के बीच में कोई व्यापारिक समभौता अल्पकाल के लिए किया जाता है तो इसे द्वि-पक्षीय व्यापारिक समभौता कहने हैं। अल्प काल से यहाँ आशय एक वर्ष या उससे कम अविध से है। एक वर्ष या वह समय समात हो जाने के बाद जिसके लिए समभौता किया गया था, समभौते को बढ़ाने या उसमें कुछ परिवर्तन करने का दोनों पक्षों में समभौता होता है। ये समभौते अस्थाई होते हैं। इन्हें करने में अधिक समय नहीं लगता है। इन समभौतों से दुनियाँ के देशों के मध्य स्वतन्त्र व्यापार में बाधा पड़ती है। यही कारण है कि इन समभौतों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति में हानिकारक माना जाता है।

भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद अपने व्यापार को वढ़ाने के हिष्टिकोरा से भिन्न-भिन्न देशों के साथ दि-पक्षीय व्यापारिक समभौते किये हैं, जैसे—भारत व आस्ट्रिया, भारत व जैकोस्लोवेकिया, भारत व मिन्न, भारत व फिनलेंड, भारत व पाकिस्तान, भारत व पश्चिमी जमांनी, भारत व पोलेंड, भारत व वलगेरिया, भारत व यूगोस्लोविया, भारत व रूस, भारत व नार्वे, भारत व स्वीडन, भारत व ईराक, भारत व इन्डोनेशिया आदि के साथ किए गए दि-पक्षीय समभौते।

### बहु-पत्तीय व्यापारिक समसौते (Multilateral Trade Agreements)-

जो व्यापारिक समभौते ग्रनेक देशों के मध्य किये जाते हैं ग्रौर दीघं काल के लिए होते हैं, बहु-पक्षीय समभौते कहे जाते हैं। इन समभौतों का महत्त्व उस समय तक बना रहेगा जब तक भिन्न-भिन्न देशों के उत्पादन के साधन ग्रसमान रहेंगे। मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह ग्रपनी ग्रावश्यकताग्रों को सस्ते से सस्ते वाजार में पूरा करता है। बहु-पक्षीय व्यापार में मनुष्यों की यह प्रवृत्ति पूरी होगी ग्रौर ऐसा करने से समाज ग्रपने जीवन-स्तर को ऊँचा करने में सुविधा ग्रनुभव करेगा। इन समभौतों से बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं. जिनका विवरण सूदम में नीचे दिया जाता है:—

- (ग्र) ग्रन्तर्राष्ट्रीय विधान बनाने के लिए द्वि-पक्षीय समभौतों द्वारा काफी सहायता मिलती है।
- (ब) इनके द्वारा विदेशी ब्यापार की स्थाई नीति बनाई जा सकती है। बहुत सी विदेशी समस्यायें ऐसी हैं जो दो देशों के बीच के व्यापारिक समभौते से हल नहीं हो सकतीं। उन्हें इसी समभौते द्वारा हल किया जा सकता है।
- (स) सब देशों के बीच निश्चित् नियमों के साथ व्यापार होने के काररण ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति होती है, जिससे सभी देशों को लाभ प्राप्त होता है।
  - (द) भिन्न-भिन्न देशों में एक दूसरे के प्रति प्रेम व सद्भावना पैदा होती

हैं ग्रौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय एकता स्थापित होती है, जो कि युद्ध टालने के लिए ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है।

(य) वास्तव में द्वि-पक्षीय विदेशी व्यापारिक समभौतों के कारएा ही भिन्न-भिन्न देशों में विशिष्टीकरएा (Specialisation) व श्रम विभाजन होता है, जिससे विश्व में उत्पादन बढ़ता है।

## बहु-पन्नीय व्यापारिक समभौतों में कठिनाइयाँ—

- (ग्र) भिन्न-भिन्न देशों की भाषा, रीति-रिवाज, ग्रार्थिक संगठन व कानूनों झादि में भिन्नता होने के कारए। इन समभीतों का किया जाना कठिन है।
- ( व ) दुनियाँ के भिन्न भिन्न देशों में राजनैतिक गुटबन्दियाँ हैं। जैसे कुछ देश कम्यूनिस्ट हैं, कुछ सोशलिस्ट हैं, कुछ ग्रन्य प्रकार के गुट बनाये हुए हैं। इन गुटबन्दियों के कारण बहु-पक्षीय व्यापारिक समभौते सम्भव नहीं हैं।
- (स) इन समभौतों के करने में काफी समय व्यय होता है, क्योंकि भिन्न-भिन्न देशों के प्रतिनिधि एक स्थान पर जमा होते हैं ग्रौर ग्रपने-ग्रपने दृष्टिकोए। रखते हैं। सब प्रतिनिधियों को एक राय पर पहुँचने में काफी समय लगता है। इतनी मेह-नत के बाद किये हुये समभौते का बहुत समय तक चलना भी कठिन है।
- (द) बहुत से देशों में पुराना द्वेष चला भ्रा रहा है, श्रतः ये देश उन सम-भौतों के होने में ग्रड्चनें डालते हैं।

#### द्वि-पक्षीय श्रौर बहु-पक्षीय समभौतों में श्रन्तर द्धि-पक्षीय बहु-पक्षीय (१) बहुत से देशों के बीच व्यापा-(१) दो देशों के बीच में व्यापारिक रिक समभौता होता है। समभौता होता है। (२) यह समभौता ग्रल्पकालीन (२) यह समभौता दीर्घ हालीन होता है। होता है। (३) दो देशों के बीच समभौता (३) ये समभौते शीघ्र सम्भव नहीं शीघ्र सम्भव होता है। होते हैं। (४) यह समभौता एक स्थाई नीति (४) यह समभौता एक ग्रस्थायी के अनुसार होता है। व्यवस्था है। (५) ये निष्पक्ष भाव से किये जाते हैं। (५) ये समभौते पक्षपातपूर्ण होते हैं। (६) इन समभौतों का क्षेत्र ब्यापक (६) इन समभौतों का क्षेत्र सीमित होता है। होता है।

#### हैवाना चार्टर-

पिछले दो महायुद्धों के कारए। भिन्न-भिन्न देशों को काफी हानिया उठानी पड़ीं, परन्तु इन युद्धों से एक लाभ यह हुआ कि सब देशों ने यह अनुभव किया कि सभी देशों की आर्थिक उन्नति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों द्वारा हो सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बहु-पक्षीय समभौते के अनुसार करने के दृष्टिकोगा से ब्रेटनबुड्स में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए कई सुभाव विये । इन्हीं सुभावों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (International Trade Organisation) के विधान का एक चार्टर बनाया और इसे स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न देशों को भेजा। इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ, इङ्गलैंड व अमेरिका आदि ने हल करने के अनेक प्रयत्न किये। अन्त में मार्च सन् १६४६ में हैवाना में एक विधान बनाया गया, जिसे हैवाना चार्टर कहा जाता है। इस विधान पर ५३ देशों ने सहमति दी थी, जिसमें से भारत भी एक था।

## हैवाना चार्टर के उद्देश्य-

इसका मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन स्थापित करना था, ताकि विश्व के व्यापार को स्वतन्त्रतापूर्वक वड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सके और सभी देशों की व्या-पारिक व आधिक उन्नति हो। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित कठिन समस्याओं को सुविधा से हल करना, विभिन्न देशों को किसी भी ऐसे काम को करने से रोकना जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अड़चनें आवें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिवन्धों को हटाना, सभी देशों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी वस्तुयें वेचने का समान अवसर देना, पिछड़े हुए देशों की आधिक उन्नति में सहायता करना और अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी की गतिशीलता बढ़ाना आदि कार्य ही हैवाना चार्टर के मुख्य लच्य थे।

इसमें भिन्न-भिन्न देशों की ग्राधिक उन्नति के लिए विदेशी विनिमय व विनियोग सम्बन्धी सभी समस्याओं का विस्तारपूर्वक विवरण है। जो भी देश ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का सदस्य होगा, ग्रपने यहाँ संरक्षण (Protection) की नीति को तब तक नहीं ग्रपना सकेगा जब तक कि उस देश की सहमित न ले ले जिस पर कि संरक्षण का प्रभाव पड़ेगा। ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए व सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रशुल्क नीति व संरक्षण नीति से सम्बन्धित विदेशी विनियोग तथा ग्रापस के विदेशी भुगतानों ग्रादि से सम्बन्धित लगभग सभी ग्रावश्यक नियम इस चार्टर में बनाये गये हैं। वास्तव में ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए हैवाना चार्टर ने जो कार्य किया है बह ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास में ग्रमर रहेगा।

व्यापार और प्रश्चटक सम्बन्धी सामान्य समसौता ('G. A. T. T.' General Agreement on Trade and Tariff)—

संयुक्त राष्ट्र घ्रमेरिका व २३ घ्रन्य देशों ने मिलकर घ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रशुल्क व संरक्षण सम्बन्धी प्रतिवन्धों के हटाने के लिए एक समभौता कियां। इस समभौते में यह तय किया गया कि यदि एक देश किसी दूसरे देश को प्रशुल्क में कुछ छूट देता है तो उसे यह छूट घ्रन्य सदस्य देशों को भी देनी पड़ेगी, प्रार्थात् सदस्य देश किसी भी देश के साथ पक्ष गतपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। घ्रमे-

sation)-

रिका व अन्य २३ देशों में जो समभौता हुआ उसे G. A. T. T. में समावेश किया गया। इस समभौते के अनुसार निम्नलिखित लच्च रखे गये थे:—

- (१) भिन्न-भिन्न देशों में ग्रापस के भेदभाव को हटाकर मित्रता की भावना पैदा करना।
- (२) भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्न-भिन्न देशों द्वारा श्रायातों पर लगे हुए करों को हटवाकर व्यापार की उन्नति करना।
  - (३) व्यापार की उन्नति के लिए सभी सम्भव नियमों को बनाना।
- (४) G. A. T. T. के बारे में बहुत समय पहिले से विभिन्न देशों के बीच बातचीत होती चली थ्रा रही थी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, हैवाना चार्टर व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलनों में एक इस प्रकार के समभौते की बातचीत थी जिससे कि भिन्न-भिन्न देशों की प्रशुल्क-नीतियों में उचित सुधार किया जाय, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उन्नति के शिखर पर पहुँचे।

प्रारम्भ में इस समभौते में २३ सदस्य थे, परन्तु बाद में कुल सदस्यों की संख्या ३६ हो गई। इसके अनुसार भिन्न-भिन्न देशों के बीच १४७ द्वि-पक्षीय समभौते हुए और सभी सदस्यों ने अपने प्रशुल्क में भिन्न-भिन्न प्रतिशत में कमी की। ब्रिटेन, अमेरिका व अन्य देशों ने अपने प्रशुल्क में इतनी कमी की कि अन्त में वह निम्नतम् सीमा पर पहुँच गई। इस समभौते से अन्य समभौतों की अपेक्षा बहुत कम सफलता मिली, परन्तु कुछ भी हो, इस प्रकार के समभौते से यह सिद्ध होता है कि सभी देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के पक्ष में हैं।

१० अप्रैल और ३० अक्टूबर सन् १६४७ के बीच इस समफौते के लिए जिनेवा में वार्ता प्रारम्भ हुई। इसमें भिन्न भिन्न देशों ने भाग लिया। यह समफौता १ जनवरी सन् १६४६ के बागू हुआ था। २७ अप्रैल सन् १६४६ को अनेकी में इसका दूसरा सम्मेलन हुआ। जो भी देश इस समफौते का सदस्य बनता था वह तीन साल से पहिले अलग नहीं हो सकता था और अलग होने के लिए ६ महीने का नोटिस देना पडता था।

# भारत और जी० ए० टी० टी० (India and G. A. T. T.)—

१ जुलाई सन् १९४ में भारत ने इस समभौते के अनुसार करों में छूट देना चुरू किया! भारत को निम्नलिखित वस्तुओं पर कर की छूट इसी समभौते के अनुसार मिली है:—सूती कपड़ा, चमड़ा, नारियल की चटाइयाँ, मसाले, जूट का सामान, अभ्रक, काजू, कालीन आदि। भारत ने निम्न देशों के साथ इसी समभौते के अनुसार व्यापारिक समभौते किये हैं—चीन, जैंकोस्लोवेकिया, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, लेबनान, सीरिया, क्यूबा, न्यूजीलेंड, इटली, स्वीडन, फिनलेंड, डेनमार्क आदि। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ ('I. T. O.' International Trade Organi-

१४ मगस्त सन् १९४१ को एटलांटिक चार्टर के साथ इस संघ की नींव पड़ी

थी। इस सब का मुख्य उद्देश अन्तर्राष्ट्रीय ज्यापार को बढ़ावा देना है। अमरीका श्रीर इक्षलैंड इस संघ के कर्मठ सदस्य हैं, जो भी देश इसके सदस्य हैं उन्हें अपनी ज्यापार सम्बन्धी सूचना व श्राँकड़े इस संघ के पास भेजने पड़ते हैं। इस संघ के अन्य कार्य निम्नलिखित हैं:—

- (१) विदेशी वस्तुओं का विरोध करना।
- (२) व्यापार को भिन्न-भिन्न प्रकार के स्रायात व निर्यात के स्नुचित करों से स्वतन्त्र करना।
- (३) ऐसे सामान्य नियमों को बनाकर प्रचार करना जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति हो।
  - (४) राशिपातन (Dumping) को रोकना ।
- (१) भिन्न-भिन्न देशों द्वारा लगाए जाने वःले करों की नीति को अधिक स्रल बनाना।
  - (६) देशों के बीच मित्रता की भावनाएँ बढ़ा कर व्यापार को बढ़ाना।

२६ नवम्बर सन् १६४६ को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ से सम्बन्धित विचारों पर विचार-विनिमय करने के लिए लन्दन में एक सभा हुई। फिर २५ जनवरी सन् १६४७ को न्यूयाक में एक सम्मेलन हुआ। अन्त में, २२ अगस्त सन् १६४७ को जिनेवा में एक महत्त्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। इन भिन्न-भिन्न स्थानों पर सम्मेलनों को करके इस बात का प्रयत्न किया गया कि दुनियां के देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की स्थापना में सहायक हों, ताकि सब देशों की आर्थिक उन्नति हो सके।

सन् १६६ में इन्हीं बातों पर विचार करने के लिए हैवाना में एक बैठक हुई। इस बैठक में पास हुए प्रस्ताव पर दुनियां के देशों ने हस्ताक्षर किये। ग्राशा की जाती है कि इस प्रकार के संघ ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने में ग्रत्यन्त सहायक होंगे।

#### **QUESTIONS**

- 1. Discuss the arguments in favour of protection. Do you think India should adopt a policy of protection? What do you understand by a policy of Discriminating Protection?
- 2. Write a note on (a) Imperial Preference, (b) Bilateral Trade Agreements.
- 3. What do you know of the objectives of the International Trade Organisation?

#### अध्याय २४

# भारत का विदेशी व्यापार

(The Foreign Trade of India)

वर्तमान संसार में किसी भी देश के आर्थिक विकास श्रौर उसकी सम्पन्नता के लिए विदेशी व्यापार की उन्नति ग्रावश्यक है। राष्ट्रीय स्वावलम्बता का युग पहले से ही समाप्त हो चुका है। कितनी ही वस्तुएँ तो ऐसी हैं कि एक देश उन्हें उत्पन्न ही नहीं कर सकता है श्रौर बहुत सी वस्तुएँ ऐसी हैं जिन्हें प्राकृतिक श्रथवा ग्रन्य कारणों से देश में बहुत ही श्रधिक लागत पर उत्पन्न किया जा सकता है। दोनों ही दशाशों में विदेशी व्यापार लाभदायक होता है, क्योंकि ऐसी वस्तुएँ कम मूल्य पर मिल जाती हैं। विशिष्टीकरण तथा विनिमय दोनों ही के श्राधिक लाभों को प्राप्त करने के लिए विदेशी व्यापार का विकास ग्रत्यन्त ही आवश्यक है। इसके श्रतिरक्त विदेशी व्यापार देशों की पारस्परिक मित्रता श्रौर सहयोग के लिए ग्रावश्यक है। इसके द्वारा सभी देशों को दूसरों को सहायता से ग्रपनी ग्रर्थव्यवस्था के विकास ग्रौर उपभोग-स्तर को ऊँचा उठाने का ग्रवसर प्राप्त होता है।

# विदेशी व्यापार का प्राचीन इतिहास

## (१) प्रथम मेहायुद्ध के प्रारम्भ तक—

ऐतिहासिक खोज से पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत का विदेशी व्यापार पर्याप्त विस्तृत एवं महत्त्वपूर्ण था। अस्मरणीय काल से जल और थल दोनों ही मार्गों से भारत के विदेशियों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध थे। अब से ४,००० वर्ष पूर्व भी भारत का वेबिलोन से व्यापार होता था। ऐसा पता चलता है कि भारतीय व्यापारियों के पास बड़े बड़े जहाजी बेड़े थे और वे सुदूर-पूर्व तथा मध्य-पूर्व के देशों के साथ नियमित रूप में व्यापार करते थे। पिरचम में मिस्न, यूनान, अरव और ईरान से लेकर पूर्व में चीन तक भारत का माल जाता था। ढाके की मलमल और कालीकट के सूती कपड़े को संसार भर में ख्याति प्राप्त थी। निर्यात् की वस्तुओं में सूती कपड़े, घातु के सामान, हाथी दाँत, रंग, मसाले, हथियार और अनेक कलात्मक सामान सम्मिलत थे और घातुओं, पीतल, टीन, शराब, घोड़े आदि का आयात होता था।

मुसलमानों के निरन्तर ग्राक्रमणों ने देश की राजनैतिक दशाग्रों में ग्रनिश्चितता उत्पन्न करके व्यापार में भारी कमी कर दी। परिणाम यह हुग्रा कि समुद्री व्यापार घट गया, परन्तु मुस्लिम काल में थल-मार्गीय व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई। साथ ही, ग्रान्तरिक व्यापार की भी उन्नति हुई, जिसका प्रमुख कारए। थल मार्गों का विकास था। मोरलैंड (Moreland) के अनुसार लाहौर ग्रौर काबुल तथा मुल्तान और कन्धार के बीच बराबर नियमित क्य से व्यापार होता रहता था। यही थल मार्गे काबुल और कन्धार से चीन तथा ईरान को जाने थे और इनके द्वारा भारत का माल यूरोप तक पहुँचता था। इस काल में भी ग्रायात और निर्यात की वस्नुएँ पहले जैसी ही थीं।

योरोपीय व्यापारियों ने म्राते ही देश के विशसित व्यापार से लाभ उठाना म्रारम्भ किया। डच, फान्सीसी तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने देश के उद्योगों को प्रोत्साहर देकर व्यापार में वृद्धि की, परन्त यह स्थिति प्रधिक समय तक बनी न रह सकी। 'श्रौद्योगिक क्रान्ति' के पश्चात दशाएँ बदल गईं श्रौर १८ वीं शताब्दी में जैसे-जैसे इङ्गलैंड तथा अन्य योरोपियन देशों के उद्योगों का विकास हुआ, उन्होंने भारतीय माल के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने आरम्भ कर दिये। इङ्गलैंड ने ऐसा म्रनुभव किया कि भारत से कचा माल मँगाना ग्रौर ग्रपने उद्योगों की उपज को भारत में वेचना देश के लिए अधिक लाभदायक था। अतः कचे मालों, के आयातों को प्रोत्साहन दिया गया ग्रीर भारत में इङ्गलैंड की ग्रीद्योगिक उपज के लिए वाजारों का विकास करने का प्रयत्न किया गया। इस काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना स्वेज नहर का निर्माण थी। इसके फलस्वरूप समुद्र के रास्ते से भारत ग्रीर इङ्गलेंड का अन्तर ५,५०० मील से घट गया ग्रीर यूरोप के बाजार भारत के लिए खुल गये। मुक्त-व्यापार नीति के फलस्वरूप भी व्यापार के विस्तार में सुविधा हुई । सन् १५६४-६६ तथा सन् १८६९-१६०४ के बीच विदेशी व्यापार का वार्षिक मूल्य ६६ कोड़ रुपये से बढ़कर २१० करोड़ रुपया हो गया ग्रौर सन् १६०६-१४ में यह ३७६ करोड़ रुपये तक पहुँच गया।

### (२) प्रथम महायुद्ध श्रीर उसके उपरान्त-

सन् १६१४ में प्रथम महायुद्ध म्रारम्भ हुम्रा। युद्ध के कारण यातायात सम्बन्धी किठनाइयाँ बढ़ गईं। साथ ही, यूरोप के देश युद्ध-कार्य में इतने तल्लीन हो गए कि वे ग्रपने विदेशी व्यापार को बनाए न रख सके। युद्ध-काल में भारत में निर्यात मौर म्रायात दोनों ही में कमी हुई। सन् १६१३-१४ स्रौर सन् १६१५-१६ के बीच निर्यात ३२४ करोड़ रुपए से घट कर केवल १६० करोड़ रुपया रह गये। इसी काल में स्रायात १६३ करोड़ रुपये के स्थान पर केवल ६३ करोड़ रुपया रह गए थे। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत के विदेशी व्यापार में कुल मिलाकर लगभग ५०% की कमी हो गई थी। शत्रु देशों के साथ तो व्यापार पूर्णतया बन्द हो गया था, परन्तु मित्र देश भी माल मैंगाने ग्रौर भेजने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे। ग्रायातों के घटने का परिणाम यह हुम्रा था कि युद्ध-काल में देश के उद्योगों को प्राकृतिक संरक्षण मिल गया था।

### (३) प्रथम महायुद्ध के बाद का काल (द्वितीय महायुद्ध तक)—

युद्धोत्तर काल में भारत के विदेशी व्यापार में एक दम तेजी आई। यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्थाएँ युद्ध के कारण चौपट हो गई थीं, इसिलए उन्हें आयातों की भारी आवश्यकता थी। भारत के लिए निर्यातों को बढ़ाने और ऊँची कीमत प्राप्त करने का अच्छा अवसर था, परन्तु यातायात की कठिनाइयों तथा ऊँची विनिमय दर के कारण भारत इस तेजी का पूरा-पूरा लाभ न उठा सका। सन् १६२०-२१ में तेजी का यह कम टूट गया और विदेशी व्यापार में फिर मन्दी आ गई, परन्तु २ वर्षों के पश्चात सन् १६२२-२३ में फिर उद्धार-काल आरम्भ हुआ। सन् १६२४-२५ तक दशाएँ काफी सुधार गई। अभिवृद्धि का यह कम निरन्तर आगे ही बढ़ता रहा, केवल सन् १६२६-३० के बीच महान् अवसाद के कारण यह टूट गया था। सन् १६१६-२० तथा सन् १६२६-३० के बीच व्यापार की स्थिति निम्न प्रकार थी:—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	निर्यात	ग्रायात	व्यापाराशेष
09-3838	३३६	<b>२२२</b>	+ 888
<b>१</b> ६२०–२१	२६७	३४७	- 50
<b>१</b> ६२ (–२२	२४६	₹=₹	— 3×
१६२२–२३	३१६	२४६	+ 90
<b>१</b> ६२६–३०	३१५	388	+ 48

युद्धोत्तर काल में उद्धार का तत्काल कारण यह था कि घीरे-घीरे सभी योरोपीय देशों की मुद्राश्रों की कीमतों में स्थिरता था गई थी। इन देशों की साल में वृद्धि हो गई थी और युद्ध के हर्जानों (Reparations) का प्रश्न सुलफ गया था। सन् १६२६ में महान् अवसाद आरम्भ हुआ। इसके प्रथम चिन्ह संयुक्त राज्य अमरीका में दृष्टिगोचर हुए थे, परन्तु घीरे-घीरे संसार के लगभग सभी देश इसकी जकड़ में आ गए। अवसाद का प्रमुल कारण कच्चे मालों और निर्मित वस्तुओं का अति-उत्पादन, संसार के अधिकांश स्वर्ण का अमरीका में एकत्रित हो जाना, विभिन्न देशों की मुद्रा-संकुचन नीति और कुछ देशों की राजनैतिक अशान्ति थे। युद्धोत्तर काल में आधिक राष्ट्रीयवाद की भावना भी तीत्र हो गई थी, जिसके अन्तर्गत सभी देशों ने विदेशी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिए थे और विदेशी व्यापार को अधिक संकुचित कर दिया था। विभिन्न देशों के द्वारा स्वर्ण-मान परित्याग, मुद्रा-अवमूल्यन, आयात अभ्यंश नीति आदि ने भी विदेशी ब्यापार के मार्ग में अनेक बाघायें उपस्थित कीं। अवसाद का सबसे बुरा प्रभाव कृषि प्रधान देशों पर पड़ा, क्योंकि ऐसे काल में कृषि उपज और कच्चे माल के मूल्यों में ही सबसे अधिक पतन होता है। भारत के निर्यात व्यापार को भारी घक्का लगा। साथ ही, जनता के पास क्रयः शक्ति की कमी, राजनैतिक अशान्ति

तथा देशी उद्योगों के विकास ने जिसे संरक्षरण नीति ने प्रोत्साहित किया था, आयातों को भी पर्याप्त मात्रा में घटा दिया था।

भारत में ग्रायातों की तुलना में निर्यातों का पतन ग्रधिक हुग्रा था, जिसकी मुख्य कारण यही था कि देश का निर्यात व्यापार कच्चे मालों से सम्बन्धित था, जिनकी कीमतें बहुत नीचे गिर गई थीं। इस काल में भारत ने काफी ग्रधिक मात्रा में स्वर्ण का निर्यात किया और इसी कारण निर्यातों में कमी होने पर भी व्यापाराशेष अनुकूल ही बना रहा। सन् १६३० तथा सन् १६३८ के बीच भारत ने ३५० करोड़ रुपये की कीमत के सोने का निर्यात किया। ग्रवसाद के सबसे बुरे वर्ण ग्रायांत् सन् १६३२-३३ में भी हमारा व्यापाराशेष ग्रनुकूल ही था, जिसकी मात्रा ३ करोड़ रुपया थी। यह इसी कारण सम्भव हुग्रा था कि हम ग्रन्य प्रकार के निर्यातों की कमी को विदेशों को सोना भेज कर पूरी कर रहे थे।

भ्रवसाद सन् १६३३ में समात हुआ भीर सन् १६३३-३४ से उद्धार की प्रवृत्ति फिर स्रारम्भ हो गई। भारत के माल की विदेशों में माँग वढ़ने लगी। इस उद्धार के अनेक कारए। थे:--सर्वप्रथम तो, अमरीका और फांस ने कृत्रिम उपायों द्वारा उद्धार का क्रम आरम्भ किया था। दूसरे, इसी काल में संसार के देशों ने दूसरे महायुद्ध की तैयारी आरम्भ कर दी थी। तीसरे, ओटावा समभौते के कारण भारत ग्रीर राष्ट्रमण्डल देशों के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। इसी काल में सन् १६३४ भारत-जापान समभौता भी हुआ, जिसने भारतीय व्यापार के विस्तार में सहायता दी । सन् १६३५-३६ तक व्यापार का विस्तार होता गया, परन्तु सन् १६३६-३७ में फिर मन्दी आई, जो सन् १६३६ तक चलती रही और अन्त में दूसरे महायुद्ध के आरम्भ होने पर फिर तेजी आरम्भ हुई। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि महान भ्रवसाद के पश्चात भारतीय व्यापार का विशेष विस्तार नहीं हो सका था। इसका प्रमुख कारए। यह था कि युद्ध का ग्रारम्भ होने के भय के कारए। व्यावसायिक वर्ग भयभीत था। इसके म्रितिरक्त चीन-जापान युद्ध के कारण पूर्व की मण्डियों से बहुत व्यापार सम्भव न था। सन् १६३६-४० में प्रथम बार तेजी प्रकट रूप में आई क्योंकि युद्ध की तैयारी के लिए विभिन्न देशों ने शस्त्र उद्योगों के विकास और स्टॉकों के जमा करने पर अधिक व्यय करना आरम्भ कर दिया था. जिससे भारतीय निर्यातों की मांग एवं उसके मूल्य दोनों में वृद्धि हुई थी।

# (४) दूसरा महायुद्ध श्रौर उसके उपरान्त-

सन् १६३६ में दूसरे महायुद्ध का ग्रारम्भ होते ही विदेशी व्यापार में तेजी के साथ वृद्धि हुई। कच्चे माल ग्रौर निर्मित वस्तुएँ दोनों ही की विदेशी माँग पर्याप्त बड़ी ग्रौर यद्यपि बहुत से देशों को शत्रु घोपित करके उनके साथ व्यापार विजत कर दिया गया था, तथापि भारतीय व्यापार निरन्तर विस्तृत ही होता गया। निम्न ग्राँकड़े इस वृद्धि का कुछ, ग्रनुमान प्रदान करते हैं, यद्यपि वे पूर्णतया सन्तोषजनक नहीं हैं,

क्चोंकि उनमें विटिश सरकार द्वारा खरीदे हुए माल तथा उधार-पट्टा (Lend-lease) प्रसाली द्वारा प्राप्त माल की कीमत नहीं दिखाई गई है:—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	निर्यात	ग्रायात	कुल व्यापार
\$5.00,38	१८७	१५७	३४४
<b>१</b> ६४:-४२	२३७	१७३	४१०
88-583 <b>8</b>	१ट७	११०	२८७
884-88	338	११=	<b>३१</b> ७
\$E88-84	२१०	२०४	४१४

युद्धकाल में सन् १६४२-४३ के वर्ष को छोड़ कर बराबर विदेशी व्यापार का विस्तार ही हुग्रा है। इस वर्ष में व्यापार की मात्रा के घटने के कई कारण थे:— (i) जापान के युद्ध में सम्मिलित हो जाने के कारणा सुदूर-पूर्व (Fareast) का व्यापार समाप्त हो गया था। (ii) विनिमय नियन्त्रणा प्रणाली को कड़ा कर दिया गया था, जिससे व्यापारियों को भारी ग्रमुविधा थी। (iii) ग्रायात तथा निर्यात व्यापारियों को ग्रनुज्ञोपित कर दिया गया था। बाद को इन सब बाधाओं ने नियमितता धारण कर ली ग्रौर इनके रहते हुए भी व्यापार का विस्तार होता रहा। (iv) युद्ध की प्रगति के साथ जलयानों के मिलने में कठिनाई होती गई ग्रौर इसका विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। (v) कुछ देशों को तो शत्रु घोषित कर दिया गया था ग्रौर उनके साथ व्यापार वर्जित था, परन्तु मित्र देश भी युद्ध कार्यों में इतने व्यस्त थे कि वे भी सैनिक सामानों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य माल भेजने में ग्रसमर्थ थे, (vi) साम्राज्य डालर कोष के कार्यवाहन ने ग्रमरीका से माल मैंगाना कठिन बना दिया। (vii) शत्रु की कार्यवाहियों के कारणा यातायात में ग्रधिक कठिनाई हुई। (viii) युद्धकाल की प्रमुख विशेषता यह थी कि निर्यातों की ग्रपेक्षा ग्रायातों में ग्रियक कमी हुई थी।

## युद्धोत्तर काल में विदेशी व्यापार—

युद्ध का अन्त होने पर आयात स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ। युद्धकाल में आयातों के रुक जाने तथा भूल्यों के ऊपर उठने पर भी देशी उद्योगों का समुचित विकास न हो सका, जिसका कारण पूँजीगत माल और आवश्यक कच्चे मालों का अभाव था। युद्ध-कालीन तनाव कम होते ही आयातों में बृद्धि हुई, जलयानों की कमी के कारण कठिनाई बनी रही। आरम्भ में सबसे अधिक वृद्धि उन वस्तुओं के आयातों में हुई जिनकी सैनिक कार्यों के लिए आवश्यकता थी, परन्तु तत्पश्चात् खाद्यान्न तथा पूँजीगत माल के भी आयात बढ़े। आयातों में इतनी तेजी के साथ वृद्धि हुई कि युद्धोत्तरकाल व्यानाराशेष भारत के लिए प्रतिकूल हो गया। निम्न आँकड़ों द्वारा स्थिति स्पष्ट हो जाती है:—

(करोड़ रुपयों में )

वर्ष	निर्यात तथा पुनर्निर्यात	ग्रायात	व्यापाराशेप
१६४४	355	२३२	<del></del> ₹
१९४६	२६६	२६२	२६
११४७	३२०	२३४	— १४
१६४८	४२८	४५१	<del></del> २३
१६४६	४२३	ሂሄ፥	—-१२०

युद्धोत्तर काल में आयातों की अत्यधिक वृद्धि के अनेक कारण थे :—( i ) घीरे-घीरे भारत सरकार ने आयात सम्बन्धी प्रतिबन्धों को ढीला कर दिया था, (ii) जलयान यातायात की पूर्ति बढ़ गई थी, (iii) देश में मुद्रा-प्रसार के दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा था, (iv) खाद्यान्न आयातों में अधिक वृद्धि हुई थी, और (v) भारत सरकार ने खुले सामान्य अनुज्ञापन (Open General Licenses) नीति के अन्तर्गत आयातों के सम्बन्ध में उदारता को अपनाया था।

#### देश का विभाजन-

सन् १६४७ में भारत के दो भाग कर दिये गये—पाकिस्तान और हिन्दुस्तान। इस विभाजन के वई कुप्रभाव हुये—(i) मखाद्यान्न की बहुत कभी हो गई और (ii) कच्चा माल बनाने वाले क्षेत्र भारत से निकल गये। फलतः एक और तो खाद्यान्न अधिक आयात करना पड़ा और दूसरी ओर रुई व जूट के निर्यात में बहुत कभी आ गई। रुई व जूट के सम्प्रन्थ में पाकितान से अनेक समभौते किये गये, जिनका उसने पालन नहीं किया। फलतः हमारा निर्यात व्यापार बहुत घट गया और कच्ची सामग्री के लिए हमें विदेशियों पर निर्भर होना पड़ा। इस प्रकार देश के दिभाजन ने हमारे विदेशी व्यापार का स्वरूप बदल दिया। व्यापार का सन्तुलन हमारे देश के अधिकाविक प्रतिकृत होता चला गया और अन्त में इसे ठीक करने के लिए भारत सरकार को कृत्रिम उपाय करने पड़े।

#### रुपये का अवसूल्यन-

युद्धोत्तर-काल में इङ्गलैंण्ड तथा स्टॉलङ्ग क्षेत्र के अन्य देशों का व्यापाराशेष डालर क्षेत्र के साथ प्रतिकूल ही बना रहा। कुछ काल तक इङ्गलैंड ने मुद्रा-कोष तथा अमरीका से ऋगा लेकर डालर की कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया, परन्तु जब किसी भी प्रकार घाटा पूरा न हो सका तो सितम्बर सन् १६४६ में स्टॉलङ्ग का अवस्थित कर दिया गया। इससे डालर में स्टॉलङ्ग को कीमत ४०३ से घटकर २ ५० रह गई। इङ्गलैंड का अनुकरण करते हुए पाकिस्तान को छोड़कर स्टॉलङ्ग क्षेत्र के सभी देशों ने अपनी अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर दिया। डालर में रुपये की कीमत ३०२२५ सेन्ट से घट कर केवल २१ सेन्ट रह गई। अवमूल्यन एक आर्थिक आव-

श्यकता थी। सन् १६४५ तक डालर क्षेत्र से भारत का व्यापार अनुकूल था, परन्तु सन् १६४६ में स्थिति बदलने लगी। सन् १६४८-४६ में तो उदार आयात नीति के फलस्वरूप भारत के डालर क्षेत्रीय व्यापार में १२० करोड़ रुपये का घाटा था। भारत में भी 'डालर समस्या' उत्पन्न हो गई थी। अवमूल्यन ने इस स्थिति को कुछ अंश तक सुधार दिया था।

#### व्यापारिक सन्तुलन-

निम्न तालिका में अवमूल्यन के पश्चात् की व्यापाराशेष स्थिति दिखाई गई है:—

वर्ष	निर्यात तथा पुनर्निर्यात	ग्रायात	व्यापाराशेष
38-288	४२३	४४३	<u> </u>
9888-40	४५१	४१४	309-
१६५०–५१	६०१	६२३	२२
१ <i>६</i> ५१–५२	७३३	<b>£</b> 83	२१०
8 x x 3	<u> </u>	६७०	<i>₹3</i> —
8EX3-X8	<b>५३१</b>	५७२	— <b>8</b> 8
१९५४-५५	<i>488</i>	६५६	६३
<b>१</b> ९५ <b>५—</b> ५६	६०६	४०७	— EX
१६५६–५७	६३७	१,०६७	<b>−</b> ₹80
<u>१६४७–५</u> ८ ( ६	मास) २६७	६२२	<b>३</b> ४४

### व्यापाराशेष (Balance of Trade)-

व्यापाराशेष के इस सुघार के कारण अवसूल्यन के अतिरिक्त और भी थे।
(i) सरकार ने डालर आयातों पर प्रतिबन्ध लगाकर देश की आयात मांग को स्टिलिङ्ग क्षेत्र से ही पूरा करने का प्रयत्न किया था। (ii) कोरिया युद्ध के आरम्भ होने पर सभी देशों ने सैनिक तैयारी तथा स्टॉकों का जमा करना आरम्भ कर दिया था, जिससे देश के पर्याप्त व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। (iii) व्यापार की शर्ते भारत के अनुकूल होती गईं। सन् १६५०-५१ तक यही प्रवृत्ति बनी रही, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय तक अवसूल्यन के लाभ समाप्त हो चुके थे। सरकार ने भी अपनी निर्यात नीति में परिवर्तन किया और देशी उपजों को देशी उद्योगों में अधिक मात्रा में उपयोग करना आरम्भ कर दिया था। सन् १६५३ के आरम्भ में व्यापार की शर्ते प्रतिकूलता के पुराने स्तर से भी नीचे पहुँच गई थीं, तत्पश्चात् कुछ सुघार हुआ था और मार्च सन् १६५४ तक व्यापाराशेष का घाटा केवल ४१ करोड़ रुपया रह गया था। सन् १६५४-५५ में स्थिति और भी बिगड़ गई थी और सन् १६५६-५७ में आयातों में

ग्रिषिक तीत्रता के साथ वृद्धि हुई और घाटा ३४० करोड़ तक पहुँच गया। चालू वर्ष के ६ महीनों में अर्थात् सितम्बर सन् १६५७ तक ३५५ करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। स्थिति को समभने के लिए शायद यह ज्ञात करना भी आवश्यक है कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना काल में हमारी विदेशी विनिमय जमा निरन्तर घटती गई है और दूसरी योजना काल में यह और भी तेजी के साथ घटी है। मार्च सन् १६५६ में रिजर्व के की विदेशी विनिमय जमा ४४६ करोड़ रुपया थी, जो सितम्बर सन् १६५६ तक केंवल २४३ करोड़ रुपया रह गई है। ६ महीनों में इस जमा में से २०३ करोड़ रुपये का निकल जाना चिन्ता की बात थी, यद्यपि यह सत्य है कि दूसरी पञ्च वर्षीय योजना के सञ्चालन के लिए हमारी आयात आवश्यकता बढ़ गई है।

## युद्धोत्तर काल में भारत के विदेशी व्यापार की विशेषतायें—

ये विशेषतायें निम्नलिखित हैं :--(१) युद्ध के पूर्व भारत इङ्गलैंड का कर्जदार था लेकिन युद्ध के बाद वह उसका लेनदार बन गया। उसने इङ्गलैंड पर १,७०० करोड रुपए का ऋएा (Sterling Balances) चढ़ा दिया। ब्रिटेन की ग्रायिक कठिनाइयों के कारण भारत उसका मनचाहा उपयोग नहीं कर सका। (२) डालर की अल्पता के कारए। निर्यातों को (विशेषतः डालर क्षेत्र के देशों के लिए) बहुत श्रोत्साहन दिया जा रहा है। (३) विदेशी व्यापार के मूल्य (Value) ग्रौर मात्रा (Volume) दोनों में घीरे-घीरे बहुत वृद्धि हो गई है। सन् १६४८ में कूल व्यापार १२६ करोड रु० काथा जो सन् १९५६ में बढ़ कर १,४०० करोड़ रु० का हो गया। (४) देश के व्यापारिक संतूलन में बरावर घाटा रहा है। यदि किसी वर्ष कम तो किसी वर्षं ग्रिधिक परन्तू घाटा रहा ग्रवश्य है। स्थिति में सुवार करने के लिये सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। (५) भारत ने सन् १९४९ में अपनी मुद्रा का डालर में ३० ५ % अवमूलन कर दिया। (६) आर्थिक योजनाओं के कारण मशीनों व औजारों व कुछ कच्चे मालों का बहुत ग्रायात किया गया है ग्रीर इन ग्रायातों का भुगतान करने के लिए सरकार निर्यातों को भरसक प्रोत्साहन दे रही है। (७) विदेशी विनिमय की कठिनाई को हल करने के लिये सरकार ने विलम्बित भुगतान (Deferred Payment) की नीति ग्रहण की है तथा विश्व वैंक ग्रीर ग्रन्य संस्थाग्रों से उवार ्लेकर दशा सुघारने का प्रयास किया है। (८) भारत के विदेशी व्यापार पर वैज्ञानिक ढंग से नियन्त्रण करने के लिये सन् १९५६ में स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना भी की गई थी।

# विदेशी व्यापार त्रौर पंचवर्षीय योजनायें योजना त्रायोग की सिफारिशें—

योजना ग्रायोग ने विगत वर्षों में भारतीय व्यापार की दिशाओं ग्रौर समस्याओं का सिवस्तार ग्रध्ययन करने के पश्चात् विदेशी व्यापार नीति के सम्बन्ध में पाँच मु०च०ग्र०, (२७)

सिद्धान्तों का निर्माण किया है :— (१) व्यापार नीति का उद्देश्य पंच वर्षीय योजनाम्रों के उत्पत्ति म्रौर उपभोग लच्यों को पूरा करना होना चाहिये। (२) निर्यात-स्तर को ऊँचा रखने के लिये निर्यात व्यापार का प्रोत्साहन म्रावश्यक है। (३) व्यापाराशेष के घाटे को यथासम्भव विदेशी विनिमय कमाई में से ही पूरा करना चाहिये। (४) म्रायात म्रौर निर्यात नीति सरकार की सामान्य वित्त नीति के म्रनुसार रहनी चाहिए ग्रौर (५) सरकार की व्यापार नीति स्पष्ट तथा समुचित रहनी चाहिए।

श्रायोग का अनुमान था कि प्रथम योजना काल में श्रायातों में १०% की वृद्धि होगी, इसके कारण व्यापाराशेष का घाटा श्रोर भी बढ़ जायगा और इसी कारण विदेशी व्यापार पर किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण अवश्य रहना चाहिए। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि प्रथम योजना-काल में विदेशी विनिमय कमाई में १३३ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और उसकी माँग में १०८ करोड़ रुपये की, परन्तु विदेशी विनिमय श्रावश्यकता का श्रनुमान अधूरा था, क्योंकि सभी मदों को सम्मिलित नहीं किया गया था, इसलिए व्यापाराशेष स्थित में विशेष परिवर्तनों की श्राशा नहीं थी। श्रायोग के श्रनुसार योजनाकाल में विदेशी व्यापार पर दो बातों का प्रभाव पड़ेगा :— (१) देश में कच्चे माल, खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुश्रों का उत्पादन और (२) प्रस्तावित लच्च पूरा करने के लिए मशीनरी तथा श्रावश्यक कच्चे माल का श्रायात।

दूसरे पंच-वर्षीय आयोजन के निर्माताओं का विचार है कि इस योजना काल में भी निर्यातों को बढ़ाकर और श्रिष्ठक विदेशों विनिमय प्राप्त करना किन ही होगा, क्योंकि हमारे निर्यात प्रकृति में वेलोच हैं। श्रीद्योगीकरण की योजना की सफलता के लिये भी निर्यातों को बहुत बढ़ाना उपयुक्त न होगा। इसके श्रितिरक्त दूसरे श्रायोजन में पूँजीगत माल के श्रायात की श्रावश्यकता बढ़ जाने के कारण श्रायात बढ़ेंगे। केवल पूँजीगत माल के श्रायात के लिए १,६०० करोड़ रुपये की कीमत के विदेशों विनिमय की श्रावश्यकता पड़ेगी। योजना कमीशन का सुकाव है कि इसके लिये निर्यातों को श्रोत्साहन देने, खाद्यात्र, चीनी, रुई और पँट्रोल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये विदेशों सहायता और पाँड-पावना भुगतान की श्रिष्ठक श्रावश्यकता होगो। कमीशन ने श्रनुमान लगाया है कि सभी प्रकार के उपाय कर लेने के पश्चात् भी विदेशों व्यापार में योजना के ५ वर्षों में लगभग १,१२० करोड़ रुपये का घाटा रहेगा, इसीलिये कमीशन ने निर्यातों की श्रिष्ठक से श्रिष्ठक वृद्धि करने का सुकाद दिया है। निम्न तालिका में दूसरी पंच-वर्षीय योजना के काल में श्रनुमानित व्यापारशेष स्थिति दिखाई गई है :-

					(	, , , , , ,
o	8 & 4 & * & 9	<b>የ</b> ደ ኣ ७ – ኣ ฅ	1845-48	8848-80	\$ 3-033 3	<b>कुल</b>
१. निर्यात	५७३	४८३	५६२	६०२	६१५	२,६६५
२. भ्रायात	७८३	दद६	033	द्ध	७६६	४,३४०
३. व्यापाराशेष	- २१०	- 303	<b>—</b> ३६	- २६३	- 202	- 8,300
४. ग्रहश्य व्यापार	+ ६२	+ 44	+ 48	+ 88	+ 88	+ २४४
४. कुल चालू खाता शेष	— १४ द	- २४६	<del> ३४७</del>	<del>- २४७</del>	<b>- १३</b> 0	- १,१२०

#### भारत में विदेशी विनिमय संकट-

पिछले तीन वर्षों के श्रायातों श्रीर निर्यातों के मूल्य एवं व्यापाराशेय के घाटे को देखने से ज्ञात होता है कि देश में विदेशी विनिमय संकट उपस्थित है। श्रायातों का कार्यं कम दूसरी योजना में निर्यारित लच्यों से श्रीधक तीव्रता के साथ बढ़ा है। दूसरी योजना के श्रथम वर्ष श्रर्थात् सन् १६५६—५७ में ही श्रायातों की कुल कीमत १,०७० करोड़ रुपया थी, जबिक दूसरी योजना का श्रनुमान केवल ७८३ करोड़ रुपये का था। इस कारण इस वर्ष में ३४० करोड़ रु० का घाटा रहा था। सन् १६५७-५८ के पहले ६ महीनों में श्रायातों की कीमत ६२२ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी, जबिक योजना का साल भर का श्रनुमान केवल ८८६ करोड़ रुपया था। पहले ६ महीनों में ही ३५५ करोड़ रुपया था। पहले ६ महीनों में ही ३५५ करोड़ रुपए का घाटा रहा है, जो श्रगले ६ महीनों में श्रीर भी बढ़ गया है।

दूसरी योजना में शोघनाशेष सम्बन्धी घाटे का अनुमान पाँच वर्षों के लिए १,१०० करोड़ अर्थात् लगभग २२० करोड़ रुपया प्रति वर्ष रखा गया था, जिसमें से २०० करोड़ रुपये का घाटा पौंड पावना शेषों में से पूरा करने की योजना बनाई गई थी। तत्पश्चात् ऐसा ज्ञात हुआ कि एक और तो योजना में पूँजीगत माल के आयात के अनुमान नीचे रखे गये थे और दूसरी और आयातों के मूल्यों में वृद्धि हो गई थी। इस प्रकार घाटे में ५०० करोड़ रुपये की और वृद्धि हो गई थी। इस के अतिरिक्त खाद्य आयात और रक्षा आवश्यकतायों भी अनुमान से ऊँचे रहे थे। इस कारण यह अनुमान लगाया गया था कि घाटे में २०० करोड़ रुपए की और वृद्धि होने का अनुमान है। इस प्रकार पौंड पावना शेषों के उपयोग के अतिरिक्त ६०० १ ५०० १ २०० अर्थात् लगभग १,६०० करोड़ रुपये के घाटे का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। इसने निस्सन्देह विदेशो विनिमय संकट उपस्थित कर दिया है।

जनवरी सन् १९५ म से यह निराशाजनक स्थिति कुछ परिवर्तन की श्रोर दृष्टि-गोचर होती है। दिसम्बर सन् १९५७ तक ४८० करोड़ रुपए की विदेशी सहायता दूसरी योजना के लिए प्राप्त हो चुकी थी श्रीर सन् १९५८ में लगभग ३२६ करोड़ रु० भौर मिल चुकने की आशा है। इसके अतिरिक्त २२० करोड़ रुपया संयुक्त राज्य अम-रीका तथा १५० करोड़ रु० विश्व बेंक से मिलने के वचन पूर्ण हो चुके हैं। इस कारण शायद हम संकट का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ हो सर्कों। एक आशाजनक बात और भी है। योजना में निर्यातों के अनुमान भी वोस्तविक से कम निकले हैं। दूसरी योजना में सन् १९५६-५७ के लिए निर्यातों के मूल्य का लच्य केवल ५७३ करोड़ रुपया था, जबिक उनका वास्तविक मूल्य ६३७ करोड़ रु० रहा है। सन् १९५७-५८ के प्रथम ६ महीनों में निर्यातों का मूल्य २६७ करोड़ रुपया रहा था, जबिक योजना का साल भर का अनुमान केवल ५८३ करोड़ रुपये था। इस प्रकार निर्यातों के बढ़ने के कारण भी स्थित के सुधरने की कुछ आशा अवश्य है।

## भारत में विदेशी व्यापार का रूप—

दूसरे महायुद्ध का प्रभाव सबसे ग्रधिक भारतीय व्यापार के रूप के परिवर्तन में दृष्टिगोचर होता है। इस परिवर्तन का ग्रनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है:—

	35-2838	१९४३-४४	१६४४-४५
	कुल का $\%$	कुल का $\%$	कुल का $\%$
म्रायात—			
खाद्यान्न	१५.७	६"०	8.8
कच्चा माल	२१•७	<b>48.8</b>	५५'३
निर्मित सामान	६०"=	३८"२	३१"=
निर्यात—			
ৰাহ্যান্ন	२३-३	३२:६	3.05
कचा माल	४७*१	२४.६	२५.६
निर्मित सामान	३०"०	४०.४	५१•५

व्यापार के रूप के परिवर्तन की यह प्रवृत्ति युद्धोत्तर काल में भी बनी रही है। सन् १६४६ में खाद्यान्न, कच्चे माल और निर्मित सामान कुल ग्रायात के क्रमशः १६६६ में ४३% से बढ़ कर सन् १६४६ में ४६.२% तक पहुँच गया था। युद्धोत्तर काल में कच्चे माल और तैयार माल के निर्यात की कभी का प्रमुख कारण पाकिस्तान का निर्माण था, जिसने कच्चे माल के निर्यात तथा देशी खपत दोनों में कभी कर दी। सन् १६४६ के परचात् भारत सरकार के प्रयत्नों के फ़लस्वरूप खाद्यान्न का ग्रायात घटा है। प्रथम पंच-वर्षीय योजना में सन् १६५६ के ग्रन्त तक ३० लाख उन खाद्यान्न के ग्रायात का अनुमान लगाया गया था, परन्तु ग्रन्तिम दो वर्षों में खाद्य उत्पादन की वृद्धि ग्रनुमान से भी ग्रिक्क रही थी, इसलिए ग्रायात और घटे थे। निर्मित माल के ग्रायात की वृद्धि का

प्रमुख कारण मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति थी, जिसके भ्रन्तर्गत ग्रायात नियन्त्रण ढीलः कर दिया गया था।

# व्यापार की दशाएँ (Direction of Trade)—

जहाँ तक भारत के व्यापार में विभिन्न देशों के महत्त्व का प्रश्न है, २० वीं शताब्दी में ब्रिटेन ग्रौर साम्राज्य तथा राष्ट्रमण्डल देशों के साथ व्यापार में निरन्तर वृद्धि हुई है। सन् १६०६-१४ में इन देशों का भाग केवल ४१% था, जो सन् १६४४-४५ में ६४% तक पहुँच गया था। दूसरे महायुद्ध के पश्चात् देश का व्यापार साम्राज्य तथा ग्रन्य देश के साथ लगभग समान सा रहा है। नीचे के श्रांकड़े इस सम्बन्ध में उपयोगी होंगे:—

#### निर्यात-प्रतिशत

साम्राज्य देश	<b>११-</b> 32 <b>9</b> <b>१</b> ४	35-253 <b>\$</b> <b>44</b>	१६४५ ६०	१६४=	१९५४-५५ ३१
भ्रन्य देश	४६	४६	४०	५०	इ.ह
	3	गयात-प्रतिशत	1		
	१६०६-१४	१६३५-३६	१६४५	१६४५	१६५४-५५
साम्राज्य देश	७०	४=	३७	४६	२३
ग्रन्य देश	30	∨9	c a	25.7	1010

जपरोक्त आँकड़ों से पता चलता है कि साम्राज्य देशों के बाहर से अधिक मात्रा में आयात लेने की प्रवृत्ति है, यद्यपि देश के आयात व्यापार में अब भी ब्रिटेन का अधिक महत्त्व है। विगत वर्षों में भारत का व्यापार गैर-साम्राज्य देशों के साथ अधिक रहा है। अमरीका, बेल्जियम, चैकोस्लोवेकिया और जापान से पूँजीगत माल आ रहा है और बर्मा, पाकिस्तान, अर्जेनटाइना, रूस और अमेरिका से खादान ।

# भारत की व्यापार नीति

दूसरे महायुद्ध के काल में भारत सरकार ने देश के ज्यापार पर कड़ा नियन्त्रण रखा था। इसका उद्देश्य विदेशों से प्रधिक से प्रधिक सैनिक सामान खरीदना ग्रीर देश की विदेशों विनिमय कमाई के उपयोग में बचत करना था। युद्ध का ग्रन्त होने पर भी नियन्त्रण को हटाया न जा सका। युद्धोत्तर काल में देश में ग्रन्न का ग्रभाव था। ग्रीद्योगिक विकास के लिए मशीनों की ग्रावश्यकता थी ग्रीर साथ ही, देश की निर्यात क्षमता भी सीमित थी। खाद्यान्न, ग्रावश्यक कच्चा माल तथा पूँजीगत माल के ग्रायात की ज्यवस्था करने के लिए ज्यापार नियन्त्रण ग्रावश्यक हो गया। सन् १६४७ के ग्रायात-निर्यात सन्नियम के ग्रन्तर्गत सरकार ने ज्यापार नियन्त्रण के विस्तृत ग्राधिकार प्राप्त कर लिये।

(I) ग्रायात .नियन्त्रण नीति —वाणिज्य मन्त्री की भ्रष्यक्षता में सन्

रहिष्ठ में एक ग्रायात सलाहकार परिषद् का निर्माण किया गया । परिषद् ग्रायात के लिए अनुज्ञापन प्रदान करती है, जिसके लिये ग्रायात की वस्तुग्रों को तीन भागों में बाँटा गया है—(१) ऐसा माल जिसके लिए अनुज्ञापन नहीं दिये जा सकते हैं, (२) ऐसा माल जिसके ग्रायात के लिये केवल सीमित ग्रंश तक ही अनुज्ञापन दिये जाते हैं ग्रीर (३) ऐसा माल जो खुले सामान्य अनुज्ञापन के भीतर ग्राता है। ग्रायात के लिए परिषद् कच्चे माल, मशीन तथा स्टालङ्ग क्षेत्र के माल को प्राथमिकता देती है।

सन् १६५० में सरकार ने एक ब्रायात नियन्त्रण जाँच समिति नियुक्त की थी। समिति ने सुकाव दिया है कि ब्रायात नियन्त्रण नीति के तीन उद्देश्य होने चाहिये:—(१) ब्रायातों की मात्रा को विदेशी विनिमय कमाई के भीतर रखना, (२) विदेशी विनिमय का इस प्रकार वितरण करना कि उपभोक्ताओं के ब्रधिकतम् सन्तोप के साथ-साथ देश में ब्रायोजित विकास की उन्नति हो और (३) यथासम्भव कीमतों के उन्नावचनों को रोकना। समिति की प्रमुख सिफारिशों निम्न प्रकार हैं:—

- (१) केवल वास्तविक उपभोक्ताग्रों, स्थापित ग्रायातकर्ता फर्मों ग्रोर समु-चित नये व्यापारियों को ही ग्रनुज्ञापन दिये जायें।
- (२) अनुज्ञापन प्रदान करने की नीति इतनी उदार होनी चाहिए कि अन्त में सभी वस्तुएँ उसमें आ जायेँ।
- (३) समिति ने प्रस्तुत प्राथमिकता क्रम में संशोधन का सुभाव दिया था श्रीर निम्न क्रम की सिफारिश की थी:—(क) श्रावश्यक कच्चा माल, (ख) मशीनों के पुर्जे, (ग) कृषि यत्र, (घ) प्रस्तुत उद्योगों के लिए मशीनरी, (ङ) श्रावश्यक उपभोक्ता माल, (च) वर्तमान उद्योगों के विस्तार के लिए मशीनें, (छ) नये उद्योगों के लिए मशीनें श्रीर (ज) श्रन्थ श्रावश्यक सामान।
- (४) खुले सामान्य अनुज्ञापन (Open General Licences) की सूची का उस समय तक विस्तार नहीं होना चाहिए जब तक कि इस व्यवस्था की दीर्घकाल तक बनाये रखना सम्भव न हो।
  - (५) व्यापार नियन्त्रक शासन को कुशलता में वृद्धि होनी चाहिए।

सरकार ने सिमिति की सिफारिशें मान ली हैं, परन्तु प्राथमिकता का नवीन क्रम निम्न प्रकार निश्चित किया है:—

- (१) (क) ग्रावश्यक कचा माल।
  - (ख) पुरानी मशीनों के पुर्जे ग्रौर भाग।
  - (ग) वे उपभोग की वस्तुएँ जो जीवन ग्रथवा स्वास्थ्य के लिए ग्रावश्यक हैं।
- (२) अन्य कचा माल और मशीनरी।
- (३) अन्य आवश्यक सामान।
- (४) भ्रनावश्यक माल ।

समय-समय पर सरकार ने जो ग्रायात नीति ग्रपनाई है उसकी निम्ने चनायें की गई हैं—(१) इसमें इतनी जल्दी-जल्दी परिवर्तन होता रहता है कि देश में व्यापारिक श्रनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो गया है। इस श्रनिश्चितता के कारण उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को हानि हो रही है।(२) सरकार की ग्रायात नीति का ग्राघार विदेशी विनिमय की उपलब्धता है, जबिक देश की ग्रायिक ग्रीर ग्रौद्योगिक ग्रावश्यकताग्रों को ग्राघार बनाना चाहिए था।(३) ग्रायात सम्बन्धी नियन्त्रणों की कार्यविधि ग्रपनी जिटलता ग्रौर ग्रवैज्ञानिकता के कारण वेईमानी को जन्म देती है। इघर इस दिशा में कुछ सुवार हुग्रा है, परन्तु ग्रव भी स्थिति ग्रमन्तोष-जनक ही बनी हुई है।

(II) निर्यात नियन्त्रण नीति—भारत सरकार की ग्रोर से ग्रनेक बार यह घोषणा की गई है कि सरकार की निर्यात नीति का ग्राघार निर्यात नियन्त्रण नहीं है, बिल्क निर्यात प्रोत्साहन है। इस उद्देश्य से एक निर्यात सलाहकार परिषद् नियुक्त की गई है। निर्यात की वस्तुग्रों को क, ख, ग ग्रौर घ चार वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग क में उन वस्तुग्रों को सम्मिलत किया जाता है जिनकी पूर्ति सीमित है ग्रौर जिनके लिए निर्यात अनुज्ञापन नहीं दिये जाते हैं। वर्ग ख में खाद्य पदार्थों को सम्मिलत किया जाता है, जिन पर खाद्य मन्त्रालय का ग्राधकार है। वर्ग ग में वे सभी माल सम्मिलत हैं जिनकी सरकार ग्रथवा देशी उद्योगों के लिए ग्रावश्यकता है। ग्रन्य सभी वस्तुग्रों को वर्ग घ में सम्मिलत किया जाता है ग्रौर उन पर वाित्यव्य मन्त्रालय का नियन्त्रण रहता है।

(III) व्यापार नियन्त्रण का भविष्य—भारत संयुक्त-राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का सदस्य है और यह संगठन व्यापारिक प्रतिबन्धों को ढीला
करने के पक्ष में है। भारत सरकार भी घीरे-घीरे प्रतिबन्धों की नीति को समास
करने के पक्ष में है। मुद्रा-कोष ने भी केवल संक्रान्ति काल के लिए ही ऐसे प्रतिबन्धों
की आज्ञा दी है, परन्तु भारत सरकार हैवाना चार्टर (Havana Charter) और
गेट (General Agreement on Trade and Tariffs) की सिफारिशों को
पूर्ण रूप में पूरा करने में असमर्थ है। विगत वर्षों में भारत सरकार ने व्यापारिक
समभौतों द्वारा अपनी व्यापार नीति को सफल बनाने का प्रयत्न किया है। ऐसे
समभौते ब्रिटेन, पाकिस्तान, जापान, जर्मनी, बर्मा, इन्डोनेशिया, रूस, अफगानिस्तान
आदि अनेक देशों के साथ हुए हैं।

### व्यापाराशेष सम्बन्धी स्थिति—

सन् १९५ में भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता उसकी कमी रही है। मूल्य की दृष्टि से आयात में २२% और निर्यात में १५% की कमी हुई है। गत वर्ष जनवरी से अगस्त तक ५१२ ७६ करोड़ रुपये का आयात हुआ और ३५४ ५० करोड़ कपये का कुल निर्यात हुआ, जबकि सन् १९५७ की इसी अविध में ये आँकड़े

्हें ४० दि ५६ १११ करोड़ रुपये और ४१४ २६ करोड़ रुपए थे। इस प्रकार व्यापार सन्तुलन के घाटे में ६६ ६६ करोड़ रुपये की कमी हो गई। इसका प्रमुख कारण सरकार की अधिक कठोर आयात नीति है, जिससे आयात में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट आई है। मूल्य के अतिरिक्त व्यापार के परिमाण में भी कमी हुई है। जनवरी-जून सन् १६५६ में निर्यात् का परिमाण सम्बन्धी निर्देशांक (आधार वर्ष १६५२-५३ = १००) ६६ तथा आयात का १२६ रहा, जबिक सन् १६५७ की इसी अविध में कमशः ११७ तथा १५० था। स्थिति निम्न प्रकार रही है:—

(करोड़ रुपयों में )

	जनवरी-म्रगस्त	जनवरी-ग्रगस्त	५७ की अपेक्षा ५ में
	१६५८	१६५७	हुई गुद्ध घट-बढ़
श्रायात	५१२ <b>"७६</b>	६५ <b>६</b> ' <b>१</b> १	- १४६·३५
निर्यात	३४६"०१		- ६२·३९
पुर्नानर्यात	34.8.2	२' <i>५६</i>	+       २.६०         -       ४६.४६         -       = १.८०
कुल निर्यात	53.6.48	४१४'२६	
व्यापार सन्तुलन	33.6.48	२४४' <i>५</i> २	

जहाँ तक व्यापार की शिक्षा का प्रश्न है, हमारा लगभग ग्राघा व्यापार तीन देशों ग्रायांत् ब्रिटेन, संयुक्त राज्य ग्रामरीका तथा पश्चिमी जर्मनी के साथ है, जिनके साथ क्रमशः कुल का २७, १४ ग्रीर ६% व्यापार रहा है, विगत वर्षों में ब्रिटेन का महत्त्व बराबर घटता जा रहा है ग्रीर संयुक्त राज्य ग्रामरीका, पश्चिमी जर्मनी, जापान, इटली, रूस तथा पश्चिमी ग्रीर पूर्वी एशिया के देशों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। व्यापार के रूप को नीचे की तालिका में दिखाया गया है:—

सन् १६५७ में भारत के व्यापार का रूप

(करोड़ रुपयों में)

शीर्षंक	कुल निर्यात	कुल ग्रायात	व्यापाराशेष
खाद्य सामग्री	१७६:३४	६५"८७	+ 57.80
पेय तथा तम्बाकू	१२•=६	३,५८	<b>-</b>
श्रखाद्य पदार्थं	<b>१</b> २४ <b>°</b> ६४	<b>११</b> २•१६	<b>+ १२</b> '४५
घातुएँ, ईंघन ग्रादि	१२ ६३	१०७"५८	— ६५'५५
चर्बी, तेल, इत्यादि	१२"६९	५.६२	<b>⊕ ६</b> "७७
रसायनिक पदार्थ	४.६०	७इ:६७	- 65.50
निर्मित वस्तुएँ	२७२"४३	२८६'५४	— ३० <b>५</b> ०७
मशीनरी तथा यातायात सामान	३"७१	ই০ন'ডন	७०"४० <i>६</i> —
विविष निर्मित वस्तुएँ	£*£X	२२ ४४	— <b>१२</b> '६०
भ्रन्य वस्तुए	ह-प्रद	७•३६	- २.५५
योग	<b>\$</b> 87'5¥	१,०२५'5२	- ३=२:६७

## भारत के विदेशी व्यापार का भावष्य-

देश की पंच-वर्षीय योजनाश्चों को सफल वनाने के लिये भारत सरकार को आजकल की तरह भविष्य में भी आयोजित व्यापार (Planned Trade) की नीति अपनानी पड़ेगी। भविष्य में हमें पहले से श्रीवक विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी, ताकि आवश्यक पूँजीगत माल व औद्योगिक कच्ची सामग्री का आयात कर सकें। अतः हमें निर्यातों में अधिक से अधिक वृद्धि और आयातों में अधिक से अधिक कमी करनी पड़ेगी, ताकि अगतान सन्तुलन हमारे अनुकूल रहे। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन विदेशी व्यापार को बढ़ाने में पर्याप्त योग दे रहा है, किन्तु इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार होना चाहिये। निर्यात प्रोत्साहक कार्जन्सलों ने निर्यात-वाजार की खोज में विदेशों को प्रतिनिधि मण्डल भेजे हैं। अभी अन्य वस्तुओं के लिये भी निर्यात प्रोत्साहन कार्जन्सलें स्थापित करने की आवश्यकता है। भविष्य में सरकार को ऐसी निर्यात नीति प्रहरण करनी पड़ेगी जिससे भारत उन वस्तुओं के निर्यात में विशेषता प्राप्त कर ले जिनमें उसे तुलनात्मक लाभ अधिक है और भारतीय वस्तुयें विदेशी वाजारों में स्पर्धा कर सकें।

# QUESTIONS

- भारतीय विदेशी व्यापार में सन् १६४७ के उपरान्त क्या मुख्य परिवर्तन हुए हैं.
   स्पष्ट कीजिये और सममाइए कि क्या ये परिवर्तन देश के लिए हितकर सिद्ध हुए हैं १
   भारतीय विदेशी व्यापार में सम्भाइए कि क्या ये परिवर्तन देश के लिए हितकर सिद्ध हुए हैं १
- 2. Describe the changing direction and pattern of India's foreign trade since 1939. (Agra, B. A., 1956 Supp.)
- हिन्दुस्तान के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सन् ११४७ के बाद और सन् ११३६ से पहले के समय में क्या और क्यों अन्तर हुआ ? (Agra, B. A., 1957 Supp.)
- 4. "In any event, the balance of trade does not tell the whole story." Examine this statement from the point of view of the position of India and England. (Agra, B. A., 1956)
- 5. अन् १६४७ से भारतीय विदेशो व्यापार की प्रमुख प्रगतियों का वर्गान कीजिये। (Allahabad, B. A., 1955, 1956)
- 6. Account briefly for the deterioration in India's Balance of Trade after the Second World War. What measures would you suggest to remedy the situation? (Alid, B. A., 1954)

# <sup>श्रध्याय</sup> २४ विदेशी विनिमय

Foreign Exchange

# विदेशी विनिमय का अर्थ-

विदेशी विनिमय शब्द का उपयोग ग्रर्थशास्त्र में कई ग्रर्थों में किया जाता है:—

- (१) विस्तृत ग्रर्थ में कुछ लेखकों का विचार है कि विदेशी विनिमय का भ्रमिप्राय उस सारी किया से होता है जिसके द्वारा दो व्यापारियों द्वारा ग्रयने विदेशी दायिन्दों का भुगतान किया जाता है। यह इस शब्द का बड़ा ही विस्तृत ग्रयं है, क्यों कि इस ग्रर्थ में वे सब संस्थाएँ जो विदेशी भुगतानों में सहायता करती हैं, वे सब रीतियाँ जिनके द्वारा विदेशी भुगतान किये जाते हैं, वे सभी उपाय जिनका इस सम्बन्ध में उपयोग किया जाता है तथा वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है, सबके सब विदेशी विनिमय में सिम्मिलित हो जाते हैं।
- (२) संकुचित ग्रर्थ में विदेशी विनिमय का उपयोग संकुचित ग्रर्थ में भी किया जाता है। (क) इस सम्बन्ध में कुछ लोग तो विदेशी विनिमय का ग्रर्थ उन सब सुविधाओं से लगाते हैं जो विदेशी भुगतानों के चुकाने से सम्बन्धित होती हैं। (ब) कुछ इसका ग्रर्थ विदेशी मुद्राओं के कय-विकय से लगाते हैं ग्रीर (ग) कुछ इसके द्वारा उस अनुपात अथवा दर को सूचित करते हैं जिस पर विभिन्न देशों की मुद्रा की ग्रदल-बदल होती है।

## निष्कर्ष —

त्रागे के सारे त्रध्ययन में हम इस शब्द का उपयोग संकुचित ऋथे में ही करेंगे । विदेशी विनिमय की एक सरल परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि विदेशी विनिमय का ऋभिप्राय उन प्रपत्रों, रीतियों ऋथवा साधनों से होता है जिनके द्वारा विदेशी सुगतान चुकाये जाते हैं।

### विदेशी विनिमय की समस्या-

विदेशी विनिमय की समस्या इस कारण उदय होती है कि अलग-अलग देशों के चलन अलग-अलग होते हैं और प्रत्येक देश के निवासी अपने देश के चलन में भुगतान स्वीकार करते हैं। उदाहरणस्वरूप, भारतीय व्यापारी विदेशों को मेजे हुये माल की कीमत स्पयों में चाहते हैं। इसी प्रकार भ्रमरीकन व्यापारी डालर

में ही भुगतान लेंगे, ब्रिटिश व्यापारी पौंड में और जापानी व्यापारी यैन में। यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रत्येक व्यवसाय में हमें अपने देश के चलन को अन्य देशों के चलन में बदलना पड़ता है। विदेशी चलनों के क्रय-विक्रय तथा एक देश के चलन के दूसरे देश के चलन में होने वाले विनिमय अनुपात को ही हम विदेशी विनिमय का नाम देते हैं। प्रस्तुत विवेचना में हम विदेशी विनिमय को विदेशी विनिमय दर के अर्थ में उपयोग करेंगे और हमारा प्रयत्न मुख्यतया इसी दर से सम्बन्धित बातों का अध्ययन करना होगा। विदेशी व्यापार में आन्तरिक व्यापार की तुलना में साधारणतया इसी कारण जटिलता आ जाती है कि उसमें देश के चलन को विना विदेशी चलनों में बदले कोई व्यवसाय नहीं हो सकता है।

## विदेशी विनिमय द्रों का निर्धारण-

विनिमय दर केवल दो देशों के चलनों के विनिमय अनुपात को सूचित करती है। यदि एक पींड के बदले में १३'३ रुपये मिल सकते हैं तो रुपया और पींड की विनिमय दर १ पींड = १३'३ रुपया होगी। इसी प्रकार यदि विदेशी विनिमय वाजार में १ रुपये के बदले में २१ सेन्ट प्राप्त होते हैं तो रुपये और डालर की विनिमय दर १ रुपया = २१ सेन्ट अथवा १ डालर = ४'७३ रुपया होगी। स्मर्ग्ग रहे कि विनिमय दर सदा के लिए स्थिर नहीं रहती है। इसमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, जिनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था दोनों पर प्रभाव पड़ता है। यही कार्ग्ण है कि विनिमय दर तथा उसके परिवर्तनों के अध्ययन का देश के आर्थिक जीवन में भारी महत्त्व होता है।

विनिमय दरों के निर्घारण की समस्या का दो ग्रलग-ग्रलग रूपों में ग्रध्ययन किया जा सकता है: -(I) स्वर्णमान प्रणाली के ग्रन्तर्गत ग्रौर (II) स्वतन्त्र चलन प्रणाली ग्रथवा पत्र-चलन-मान के ग्रन्तर्गत । इन दोनों प्रणालियों में विनिमय दरों के निर्घारण के सम्बन्ध में कोई मौलिक भेद तो नहीं होता है, परन्तु क्योंकि स्वर्णमान में स्वर्ण के रूप में सभी देशों के जिए कीमतों का एक सामुहिक मापक विद्यमान होता है, इस कारण विनिमय दर के निर्घारण में सरलता रहती है ।

# (I) स्वर्णमान में विनिमय दर का निर्धारण—

प्रिविद सभी देशों में स्वर्णमान हो और सोने के आयात और निर्यात पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध न हों तो विनिमय दरों का निर्धारण काफी सरल होता है । बात यह है कि प्रत्येक स्वर्णमान देश का चलन सोने की एक निश्चित मात्रा में परिवर्तनीय होता है । हेबरलर (Haberler) ने कहा है कि यदि व्यापारी देशों में स्वर्णमान है और सोने के आयात-निर्यात अनियन्त्रित हैं तो उनके चलन का सम्बन्ध काफी दृढ़ होगा । ऐसे देशों के बीच की विनिमय दर उनके चलनों की सोना खरीदने की शिक्त में समानता स्थापित करके प्राप्त की जाती हैं । उदाहरणस्वरूप, यदि भारत में एक औंस सोने की कीमत २२५ रूपया है और इक्नलेंड में उसकी कीमत

१५ पौंड है तो रूपये घ्रौर पौंड की विनिमय दर १५ पौंड=२२५ रूपया ग्रथवा १ पौंड = १५ रूपया होगी। इसी प्रकार यदि ग्रमरीका में ४५ डालर के बदले में १ ग्रौंस सोना खरीदा जा सकता है तो रूपये ग्रौर डालर की विनिमय दर २२५ रूपये =४५ डालर ग्रथवा १ डालर बराबर ५ रूपया होगी। इसी ग्राघार पर पौंड ग्रौर डालर की विनिमय दर १ पौंड = ३ डालर होगी। स्मरण रहे कि उपरोक्त सभी विनिमय दर प्रत्येक चलन की उसके ग्रपने देश के भीतर स्वर्ण क्यः शक्ति की समानता द्वारा प्राप्त की गई हैं। १ पौंड के बदले में इक्क्लैंड में ठीक उतनी ही मात्रा में सोना खरीदा जा सकता है जितना कि ३ डालर के बदले में ग्रमरीका में, ग्रथवा १५ रूपये के बदले में भारत में। स्वर्ण क्यः शक्ति की समानता द्वारा जो विनिमय दर प्राप्त होती है उसे त्राधिक भाषा में विनिमय की टकसाली दर (Mint Par of Exchange) त्रथवा 'स्वर्ण मूल्य समानता दर' (Gold Par of Exchange) कहा जाता है। स्वर्णमान देशों के बीच विनिमय दर की दीर्घकालीन प्रवृत्ति इसी की त्रोर होती है, यद्यपि समय-समय पर वास्तविक विनिमय दर इसके थोड़ी सी भिन्न भी हो सकती है।

# स्वर्णमान में विनिमय दरों के उद्यावचन-

स्वर्णमूल्य समानता दर विनिमय दरों की सामान्य प्रवृत्ति को ही दिखाती है। वास्तविक दर का इसके बराबर होना सदा ही स्रावश्यक नहीं होता है। व्यापाराशेष का प्रत्येक परिवर्तन इस दर में भी कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य कर देता है। मान, लीजिये कि इङ्गलेंड भ्रौर भ्रमरीका दोनों ही स्वर्णमान देश हैं भ्रौर दोनों के बीच की स्वर्णभूल्य विनिमय दर १ पौंड = ३ डालर है, परन्तु मान लीजिए कि किसी एक वर्ष में इक्कलैंड ग्रमरीका से ग्रधिक माल मँगाता है ग्रौर उसकी तुलना में ग्रमरीका को कम माल भेजता है। इसका परिग्णाम यह होगा कि इङ्गलैंड के लिए डालर की माँग बढ़ जायगी, क्योंकि इङ्गलेंड के लिए अपने आयातों की कोमत को डालर में चुकाना म्रावश्यक होता है । इसके विपरीत म्रमरीका में ब्रिटिश ब्यापारियों को भुगतान करने के लिए पौंड की माँग अपेक्षतन कम होगी। मांग का साधारएा नियम हमें यह बताता है कि जिस वस्तु की बाजार में माँग बढ़ जाती है उसकी कीमत ऊपर चढ़ जाती है श्रीर इसके विपरीत जिस वस्तु की माँग घट जाती है उसकी कीमत नीचे गिर जाती है । डालर की माँग बढ़ जाने के कारएा विदेशी विनिमय बाजार में उसकी कीमत बढ़ जायगी और इसके विपरीत पौंड की कीमत में कमी हो जावगी, ग्रतः १ पौंड की कीमत ३ डालर से कम रह जायगी, ग्रर्थात् एक पौंड के बदले में तीन से कम ही डालर प्राप्त होंगे।

स्मरण रहे कि स्वर्णमान में एक देश के व्यापारियों के लिये विदेशियों को भुगतान करने के दो उपाय होते हैं :—या तो विदेशी विनिमय बाजार से, जिसकी प्रमुख संस्था विनिमय बैंक होती है, विदेशी चलन को खरीद कर भुगतान किया जा सकता है अथवा सोना विदेश को भेज कर उसके बदले में वहाँ की केन्द्रीय

बैंक श्रथवा वहाँ के मुद्रा-संचालक से विदेशी चलन खरीदा जा सकता हैं | दोनों ही रीतियां उपयोग में लाई जाती हैं, परन्तु समय विशेष में किस रीति द्वारा भुगतान किया जायगा, यह इस बात पर निर्भर होता है कि कौन सी रीति अधिक लाभदायक है। सोने का निर्यात !करने में खर्ची पडता है, उसके पैकिंग, यातायात तथा वीमं पर व्यय होता है। इस कारण इस नीति से स्वर्ण-मृल्य दर पर विदेशी विनिमय प्राप्त नहीं होता है। उज्ञहरू के लिये मान लीजिए कि इङ्गलैंड से १ पींड की कीमत का सोना ग्रमरीका को भेजने के सम्बन्ध में '०२ डालर का खर्चा बैठता है। इस दशा में १ पींड का सोना अमरीका को भेज कर केवल २'६८ डालर प्राप्त किये जा सकते हैं. क्योंकि '०२ डालर तो स्वर्गा निर्यात व्यय के रूप में निकल जाता है। यदि विदेशी विनिमय वाजार में १ पींड के बदले में २.६८ डालर से अधिक मिल जाता है तो इङ्गलेंड के व्यापारी अमरीका को सोना भेज कर डालर प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, परन्तु जब विदेशी विनिमय बाजार से भी एक पौंड के बदले में इतना ही डालर मिलता है तो ब्रिटिश व्यापारी इस सम्बन्ध में तटस्थ रहेंगे कि डालर को विदेशी विनिमय वाजार से खरीदा जाय प्रथवा स्वर्ण निर्यात द्वारा प्राप्त किया जाय। यदि विनिमय वैंक १ पौंड के बदले में २'६ द डालर से थोड़ा सा भी कम डालर देने का प्रयत्न करती है तो उससे डालर नहीं खरीदा जायगा, बल्कि स्वर्ण निर्यात द्वारा डालर प्राप्त किया जायगा । इस प्रकार १ पौंड के बदले में कम से कम २ ६ द डालर अवस्य प्राप्त किये जा सकते हैं। इङ्गलैंड के दृष्टिकोण से विनिमय दर इससे नीचे नहीं गिर सकती है। इस बिन्दु पर विनिमय दर के त्राते ही इङ्गलैंड से सोने के निर्यात त्रारम्म हो जायेंगे, त्रातः इस विनद को इङ्गलैंड का 'स्वर्ण निर्यात विन्दु' (Gold Export Point) कहा जाता है। श्रमेरिका के दृष्टिकोए। से विनिमय दर के इस बिन्दु पर श्राते ही स्वर्ण श्रायात त्रारम्म हो जायँगे त्रीर यह उसके लिए 'स्वर्ण त्रायात विन्दु' (Gold Import Point) होगा। स्वर्णमान के ऋन्तर्गत विनिमय दर में इससे ऋधिक परिवर्तन नहीं हो सकेंगे।

श्रव एक दूसरी स्थिति को लीजिये। मान लीजिये कि किसी वर्ष में इङ्गलैंड श्रमेरिका को श्रिधक माल भेजता है श्रौर उसकी तुलना में वहाँ से कम माल मैंगता है। इस दशा में व्यापाराशेष इङ्गलैंड के पक्ष में हो जायगा। श्रमरीका में पौंड की माँग बढ़ेगी श्रौर उसके विपरीत इङ्गलैंड में डालर की माँग कम हो जायगी। विदेशी विनिमय बाजार में पौंड की डालर में कीमत बढ़ जायगी ग्रौर इस प्रकार एक पौंड के बदले में ३ से श्रधिक डालर प्राप्त हो जायेंगे, परन्तु श्रमेरिकन व्यापारी भी पौंड को या तो विनिमय बैंक से खरीद कर प्राप्त कर सकते हैं या इङ्गलैंड को सोना भेज कर खरीद सकते हैं। यदि तीन डालर का सोना भेजने पर कुल खर्च '०२ डालर होता है तो श्रमेरिकन व्यापारियों को सोने के निर्यात द्वारा ३ डालर के स्थान पर इं०२ डालर में १ पौंड प्राप्त होगा। जब तक विनिमय बैंक ३'०२ डालर के बदले में १ पौंड से

श्रिषक देती रहेगी, श्रमरीका द्वारा स्वर्ण निर्यात का प्रश्न ही नहीं उठेगा, परन्तु यि बाजार में विनिमय दर १ पौंड = ३ ०२ डालर के बराबर हो जाती है तो श्रमरीका से स्वर्ण निर्यात श्रारम्भ हो जायगा। यही श्रमरीका के लिए स्वर्ण निर्यात बिन्दु होगा श्रीर इङ्गलैंड के लिए स्वर्ण श्रायात बिन्दु। पौंड की कीमत ३ ०२ डालर से ऊपर नहीं जायगी।

स्वर्ण आयात और स्वर्ण निर्यात बिन्दुओं को सामूहिक रूप में स्वर्ण बिन्दु (Gold Points), धातु बिन्दु (Specie Points) अथवा पाट बिन्दु (Bullion Points) कहा जाता हैं। ये दोनों बिन्दु स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय दर के चढ़ाव और उसके पतन की सीमायें निश्चित करते हैं। हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि स्वर्णमान में विदेशी विनिमय दर पूर्णतया स्थिर रहती है, परन्तु इतना अवस्य कह सकते हैं कि स्वर्णमान में विनिमय दरों के उच्चावचन स्वर्ण बिन्दुओं द्वारा निश्चित की गई संकुचित सीमाओं के ही भीतर रहते हैं। उनमें अत्याधिक उच्चावचन नहीं हो पाते हैं।

स्मरण रहे कि स्वर्णमान सम्बन्धी उपरोक्त ग्रवस्था तभी सम्भव होती हैं जबिक स्वर्ण के ग्रावागमन पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाए जाते हैं। यदि कोई देश स्वर्ण के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाता है तो विनिमय दरों के उच्चावचनों का रुक जाना ग्रावश्यक नहीं होता है। उस दशा में विदेशी विनिमय दर में विदेशी विनिमय की माँग ग्रीर पूर्ति के ग्रनुसार किसी भी ग्रंश तक परिवर्तन हो सकते हैं।

## (II) स्वतन्त्र चलन अथवा पत्र-चलन प्रणाली में विनिमय दर-

ऐसी चलन प्रगाली में एक देश के चलन का दूसरे देश के चलन में किछ भी सम्बन्ध नहीं होता है। विभिन्न देशों की मुद्राएँ स्वर्गा ग्रथवा ग्रन्य किसी एक धातु में परिवर्तनशील नहीं होती हैं। इसके कारण विभिन्न चलनों के मूल्यों का कोई सामूहिक मापक नहीं होता है। इस सम्बन्ध में विनिमय दर के निर्धारण का सबसे महत्त्व-पूर्ण सिद्धान्त कयः शिक्त समानता सिद्धान्त (Purchasing Power Parity Theory) है। सबसे पहले हम उसी की विवेचना करेंगे।

# क्रयः शिक समानता सिद्धान्त

इस सिद्धान्त का निर्माण स्वीडन के प्रसिद्ध प्रथंशास्त्री गस्टाव कैसल (Gustav Cassel) ने किया या ग्रार इसो कारण इसे कैसल का क्रयः शिल समानता सिद्धान्त (Cassel's Purchasing Power Parity Theory) कहा जाता है। यह सिद्धान्त एक बड़े ग्रश तक विनिमय दरों के निर्मारण की ठीक वैसी ही व्याख्या करता है जैसी कि हमने स्वर्णमान के ग्रन्तर्गत की थी। जब दो व्यापारी देशों में स्वर्णमान का चलन नहीं होता तो निस्सन्देह सोने में उनके चलनों की क्रयः शिक्त की समानता द्वारा विनिमय दर का निर्मारण नहीं होता है, परन्तु स्वर्ण के स्थान पर किसी दैनिक उपयोग की वस्तु में दोनों चलनों की क्रयः शिक्त का पता

गगया जा सकता है और इस क्रयः शक्ति की समानता द्वारा विनिमय दर को निश्चित किया जा सकता है। मान लीजिए कि इङ्गलैंड में १ पौंड द्वारा ठीक उतनी ही मात्रा में हूँ खरीदा जा सकता है जितना कि ग्रमरीका में ४ डालर के बदले में। ऐसी दशा में कि ग्रीर डालर की गेहूँ खरीदने की शक्ति में समानता उत्पन्न करके पौंड ग्रीर डालर हा विनिमय अनुपात १: ४ होगा।

 परन्तु उपरोक्त रीति बहुत लाभदायक नहीं है, क्योंकि स्वतन्त्र पत्र-चलन । एगाली में कोई भी एक वस्तु ऐसी नहीं होती है जिसे चलन की क्रय: शक्ति के मापक रूप उपयोग किया जा सके । कैसल का विचार है कि विनिमय दर के निर्धारण ६े लिए हमें किसी एक वस्तु में चलन की कयः शक्ति को नहीं नापना चाहिये, रन्त् यदि हम दो मुद्रात्र्यों की सामान्य कयः शक्ति (General Purchasing Power) में समानता कर देते हैं तो विनिमय दर का पता ऋवश्य लग ायगा | मान लीजिये कि इङ्गलैंड में १ पौंड की सामान्य क्रयः शक्ति उतनी ही है जतनी कि ग्रमरीका में ४ डालर की तो इङ्गलैंड ग्रीर ग्रमरीका के बीच की विनिमय र १ पौंड = ४ डालर होगी। सामान्य क्रयः शक्ति से हमारा ग्रिभिप्राय मुद्रा की ाधारसा रूप में वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त करने की शक्ति से होता है। एक छोटे से । बाहरए। द्वारा उपरोक्त सिद्धान्त को समभने में सहायता मिलेगी। मान लीजिए कि म १,५६० वस्तुओं ग्रोर सेवाग्रों को इङ्गलैंड की वस्तुग्रों ग्रौर सेवाग्रों के प्रतिनिधि हरूप में चुन लेते हैं। मान लीजिये कि वस्तुओं ग्रीर सेवाओं के इस विशाल समूह ी कीमत इङ्गलैंड में ५२० पौंड है, जिसका ग्रर्थ यह होगा कि पौंड की सामान्य क्रय: ाक्ति ३ है। ग्रब मान लीजिए कि वस्तुग्रों ग्रौर सेवाग्रों के इसी विशाल समूह की ीमत अमरीका में २,०८० डालर है, जिसके अनुसार डालर की सामान्य क्रयः शक्ति होगी। इसका स्पष्ट ग्रर्थ यह होता है कि १ पौंड की सामान्य क्रयः शक्ति ४ डालर ी सामान्य क्रयः कक्ति के बराबर होगी. अतः पौंड और हालर का विनिमय अनुपात ः ४ होगा स्रौर यही दोनों के बीच की विनिमय दर होगी ।

क्यारेक्त विवेचन में हमने केवल यह बताने का प्रयत्न किया है कि कैसल के मनुसार विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार होता है, परन्तु कैसल का सिद्धान्ता । स्तव में तीनों बातों को बताता हैं—(१) विनिमय दर किस प्रकार निश्चित विते हैं, (२) विनिमय दर में क्यों परिवर्तन होते हैं और (३) विनिमय दर परिवर्तनों की दिशा और उनका अश क्या होता है ? कैसल का विचार है कि क) दो देशों के चलनों का विनिमय अनुपात उन चलनों की सामान्य कथः शक्ति की मानता द्वारा निश्चित होता है, (ख) उसमें इस प्रकार की कथः शक्ति के तुलनात्मक रिवर्तनों के कारण परिवर्तन होते हैं और (ग) इन परिवर्तनों को दिशा तथा उनका श सामान्य कथः शक्ति के तुलनात्मक परिवर्तनों के अनुसार होता है। क्रयः शक्ति मानता सिद्धान्त का यही अन्तिम रूप है।

💪 श्री एस॰ ई॰ टॉमस (S. E. Thomas) ने इस सिद्धान्त को इन शब्दों में

व्यक्त किया है—''एक देश की करेन्सी का मूल्य दूसरे देश की करेन्सी के रूप में किसी समय विशेष पर, बाजार की माँग और पूर्ति की दशाओं द्वारा निर्घारित होता है; दीर्घ काल में यह मूल्य उन दोनों देशों की मुद्राओं के सापेक्षिक मूल्यों द्वारा निर्घित होता है, जैसा कि उन देशों की करेंसी की क्रयः शक्ति अपने अपने देशों की वस्तुओं और सेवाओं के रूप में होती है। अन्य शब्दों में, विनिमय दर में उसी बिन्दु पर स्थिर होने की प्रवृत्ति होती है जहाँ दोनों देशों की मुद्राओं की क्रयः शक्ति समान होती है। इस बिन्दु को ही 'क्रयः शक्ति समता' कहते हैं।''

यहाँ पर यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चलन की सामान्य कयः शक्ति और उसके तुलनात्मक परिवर्तनों का अर्थ स्पष्ट कर दिया जाय । साम्रान्य कयः शक्ति चलन विशेष की वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदने की औसत क्षमता की ओर संकेत करती है। यह इस बात को सूचित करती है कि एक निश्चित काल में चलन की एक इकाई औसतन कितनी वस्तुएँ और सेवाथ की श्रीसत कीमत निकालते हैं। यदि हम भारत में ५०० प्रतिनिधि वस्तुओं और सेवाओं की श्रीसत कीमत निकालते हैं (इस प्रकार की कीमत इन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के योग को इनकी संख्या से भाग देकर निकल आयेगी) और मान लीजिये कि वह २ रुपया निकलती है तो ऐसी दशा में २ रुपए की सामान्य क्रयः शक्ति एक वस्तु होगी अथवा इस प्रकार कहिये कि रुपये की क्रयः शक्ति के बराबर होगी। इसी प्रकार सभी चलनों की उनके अपने देश में सामान्य क्रयः शक्ति ज्ञात की जा सकती है।

किसी चलन की सामान्य क्रयः शक्ति के तुलनात्मक परिवर्तन का अभिप्राय् यह होता है कि किसी दूसरी चलन की सामान्य क्रयः शक्ति को तुलना में चलन विशेष की क्रयः शक्ति में विस अंश तक परिवर्तन हुआ है। उदाहरणस्वरूप, मान लीजिये कि सन् १६३६ = १०० के आघार पर सन् १६४२ में इक्जलैंड में सामान्य कीमतों का सूचक अंक ३०० हो जाता है अर्थात् पौंड की सामान्य क्रयः शक्ति एक-तिहाई रह जाती है, किन्तु इसी काल में अमरीका में सामान्य कीमतों का सूचक अंक २०० होता है अर्थात् डालर की सामान्य क्रयः शक्ति एकी दशा में डालर की तुलना में पौंड की सामान्य क्रयः शक्ति है। निश्चय है कि ऐसी दशा में डालर की तुलना में पौंड की सामान्य क्रयः शक्ति में अधिक कमी हुई है। जब एक चलन की सामान्य क्रयः शक्ति में दूसरे चलन की सामान्य क्रयः शक्ति से कम अधवा अधिक परिष्वर्तन होते है तो चलनों की क्रयः शक्ति में तुलनात्मक परिवर्तन हो जाते हैं।

<sup>\*</sup> While the value of the unit of one currency in terms of another currency is determined at any particular time by the market conditions of demand and supply, in the long run that value is determined by the relative values of the two currencies as indicated by their relative purchasing power over goods and services (in their respective countries). In other words, the rate of exchange tends to rest at that point which expresses equality between the respective purchasing powers of the two currencies. This point is called the Purchasing Power Parity."

—S. E. Thomas.

इस प्रकार सामान्य कयः शक्ति के तुलुनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप निश्चित विनिमय दरों में परिवर्तन हो सकते हैं। क्रयः शक्ति के परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं - समान तथा तुलनात्मक । समान परिवर्तनों के फलस्वरूप विनिमय दरों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होंगे, किन्तु यदि परिवर्तन तुलनात्मक हैं भ्रयात् यदि एक चलन की कयः शक्ति में दूसरी चलन की क्रयः शक्ति की अपेक्षा अधिक परिवर्तन होते हैं तो विनिमय दर में भी उसी अनुपात में तथा उसी दिशा में पर्वितंन हो जायेंगे 1 यदि भौंड की सामान्य क्रयः शक्ति डालर की क्रयः शक्ति की तुलना में २०% घट जाती है तो पौंड की कीमत भी डालर में ठीक इसी अनुपात में घट जायगी। दूसरे शब्दों में, यदि अमरीका की तुलना में इङ्गलैंड में कीमतों का सामान्य कीमत-स्तर दढ़ जाता है तो पौंड की विदेशी कीमत डालर में उसी अनुपात में बढ़ जायगी। एक उपयुक्त उदाहरणा से यह सत्य स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिये कि मुद्रा-प्रसार के कारण इङ्गलैंड ग्रोर ग्रमरीका दोनों में ही सामान्य कीमतों का सूचक-ग्रंक सन् १६३६ = १०० के आधार पर सन् १६५२ में क्रमशः २१० ग्रीर २१० हो जाता है तो इस दशा में यद्यपि पौंड तथा डालर दोनों ही की क्रयः शक्ति घट जाती है, परन्तु क्यः शक्ति में तुलनात्मक परिवर्तन नहीं होते. क्योंकि दोनों ही चलनों की कीमत एक ही अनुपात में घटती है। यह अवस्था कयः शक्ति के समान परिवर्तन की है और इसके कारण विनिमय दर में परिवर्तन नहीं होंगे।

दिसके विपरीत यदि ऐसा होता है कि इङ्गलेंड में मुद्रा-प्रसार का ग्रंश ग्रमरीका की ग्रपेक्षा ग्रधिक रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ की मतों की वृद्धि ग्रमरीका की तुलना में ग्रधिक होती है तो स्थित बदल जायगी। यदि इङ्गलेंड में सन् १६३६ = १०० के ग्राधार पर की मतों का सूचक-ग्रङ्क सन् १६५४ में २०० है, परन्तु ग्रमरीका में वह केवल १५० है तो इस दशा में पौंड की क्रयः शक्ति डालर की क्रयः शक्ति की तुलना में ग्रधिक ग्रंश तक घट जायगी। क्रयः शक्ति में तुलनात्मक परिवर्तन होगे ग्रौर उन्हीं के ग्रनुसार विनिमय दर भी बदल जायगी। कैंसल के ग्रनुसार नई विनिमय दर का पता लगाने के लिए ग्राधार वर्ष की दर में प्रत्येक चलन को देश विशेष के निर्देशांक से ग्रुणा कर देना चाहिए। यदि सन् १६३६ में विनिमय दर १ पौंड = ४ डालर थी तो सन् १६५४ में यह निम्न समीकरण से प्राप्त होगी:—

पाँड  $\times$  इङ्गलेंड का निर्देशांक = डालर  $\times$  भ्रमेरिकन निर्देशांक भ्रथांत् १ पाँड  $\times$  २०० = ४ डालर  $\times$  १५० भ्रथवा १ पाँड = ३ डालर

स्मरण रहे कि पाँड की क्रयः शक्ति में कमी हो गई थी और इसी कारण स्मकी विनिमय दर (डालर खरीदने की शक्ति) भी कम हो गई है। ४ डालर के स्थान पर भ्रव १ पाँड के बदले में केवल ३ डालर ही मिलते हैं। साथ ही, पाँड की क्रयः शक्ति में, डालर की तुलना में, उपरोक्त उद्भूहरेंग के अनुसार ३०६० विकास मृ०च० भ्र० (२८) २५% की कमी होती है, अतः क्रयः शक्ति का तुलनात्मक परिवर्तन २५% है और ठीक यही परिवर्तन पौंड की विदेशी विनिमय दर में भी हुआ है, क्योंकि १ पौंड ४ डालर के स्थान पर केवल ३ डालर के बराबर रह गया है। इस प्रकार क्रयः शक्ति समानता सिद्धान्त विनिमय दर के निर्घारण तथा उसके परिवर्तन के विषय में सशुचित ज्ञान प्रदान करता है।

क्रयः शक्ति समानता सिद्धान्त की ग्रालोचनाएँ —

कैसल के क्रयः शक्ति समानता सिद्धान्त की अनेक आलोचनाएँ हुई हैं। घ्यान-पूर्वक देखने से पता चलता है कि यह सिद्धान्त विनिमय दर के निर्धारण तथा उसके परिवर्तनों की सन्तोषजनक विवेचना नहीं करता है। सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएँ निम्न प्रकार हैं:—

- ्र) यह मुद्राओं की प्रति माँग का विवेचन नहीं करता, ग्रतः इसका स्पष्टीकरण ग्रध्रा है—यह सिद्धान्त यह तो बताने का प्रयत्न करता है कि विनिमय दरों में क्यों और किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, परन्तु इस सिद्धान्त द्वारा किया गया स्पष्टीकरण ग्रध्रा है। वास्तव में विनिमय दर की समस्या कीमत निर्धारण की ही समस्या है और जिस प्रकार देश के चलन की मांन्तरिक कीमत देश के भीतर चलन की मांग और पूर्ति पर निर्भर होती है, ठीक उसी प्रकार उसकी बाह्य कीमत ग्रथवा विनिमय दर भी विदेशी विनिमय बाजार में उसकी माँग श्रीर पूर्ति पर निर्भर होगी। विनिमय दर का सन्तोषजनक सिद्धान्त वही हो सकता है जो दो मुद्राञ्चों की विदेशी विनिमय बाजार की श्रन्योन्य माँग और पूर्ति (Reciprocal demand and supply) की समुचित विवेचना करें, परन्तु क्रयः शक्ति समानता सिद्धान्त का सम्बन्ध तो केवल चलनों की क्रयः शक्ति सम्बन्धी विवेचना से ही है, उनकी प्रतिमाँग की विवेचना से नहीं है। यही कारण है कि सिद्धान्त द्वारा की गई विवेचना अधूरी है।
- (२) विनिमय दर मान कर चलता है उसका निर्धारण नहीं करता— यह सिद्धान्त विनिमय दर का निर्धारण नहीं करता है, ऋषितु उसे मान कर ऋषे बढ़ता है। कयः शक्ति की समानता दिखाने से पहिले ही एक प्रकार, ग्रहश्य मान्यता के रूप में, विनिमय दर स्वीकार कर ली जाती है। इसके बिना दो चलनों की क्रयः शक्ति की समानता दिखाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
- (३) क्रयशक्ति के नापने का साधन ठीक नहीं है—यह धिवेचना प्रत्येक देश के कीमत निर्देशांकों (Price Indices) पर आधारित होती हैं। इसके दो दोष हैं:—(i) निर्देशांक सदा ही मृतकाल से सम्बन्धित होते हैं। वे वर्तमान अथवा भविष्य के सम्बन्ध में पूर्णयया निश्चित अनुमान प्रस्तुत नहीं करते हैं। इस कारण प्रस्तुत तथा भावी विनिमय दर का निर्धारण केवल अनुमानजनक ही रहता है। ब्यवहारिक जीवन में सिद्धान्त का यह गम्भीर दोष होता है। (ii) दूसरी कठिनाई

यह है कि निर्देशांकों में ऐसी वस्तुत्रों की कीमतों की भी गएाना होती है जिनका विदेशी व्यापार से कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है। कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो देश में ही उत्पन्न की जाती हैं, देश में ही उनका विनिमय होता है ग्रीर देश में ही उनका उपभोग भी हो जाता है ( जैसे लकड़ी, पत्थर, ईंट झादि )। विदेशी व्यापार भ्रथवा विदेशी विनिमय पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। विदेशी विनिमय दरों के निर्घारए के लिए तो उन्हीं वस्तुओं की कीमतों को सिम्मलित करना चाहिए जिनका कि स्रायात-निर्यात होता रहता है ( जैसे गेंहूँ, कपास, जूट, मशीनें, मादि )। चूँ कि निर्देशांक दोनों ही वर्ग की वस्तुओं के ग्राघार पर बनाये जाते हैं इसीलिये वे एक ऐसी विनिमय दर सूचित करते हैं जो कि वास्तविक विनिमय दर से मेल नहीं रखती है। किन्तु यदि हम केवल ऐसी वस्तुत्रों को सूची में सम्मिलित करें, जिनका विदेशों से सम्बन्ध है, तो भी समस्या हल नहीं होती है, क्योंकि (i) ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं के मूल्य सब देशों में लगभग समान रहते हैं। यदि इनके मूल्यों में परिवर्तन होता भी है, तो तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ही कम, जिससे विनिमय दरों में ठीक ठीक परिवर्तन मालूम करना कठिन हो जाता है। (ii) देश में भ्रन्य उत्पादित वस्तुग्रों के मूल्य का प्रभाव दूसरी वस्तुश्रों के मूल्यों पर पड़ता है। ग्रतः निर्देचत की र्गाई विनिम्रय दर श्रौर वास्तविक विनिमय दर में श्रन्तर पाया जायेगा ।

(४) विनिमय की दर में परिवर्तन का मूल्य-स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है—यह सिद्धान्त ऐसा समभता है कि विनिमय दरों के परिवर्तन देशों के भ्रान्तरिक कीमत-स्तरों के परिवर्तनों के परियाम होते हैं, किन्तु इसके विररीत यह भी देखाँ जाता है कि विनिमय दर के परिवर्तन स्वयं भी कीमत-स्तर में परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लो कि इज़्लेंड से फांस को बहुत पूँजी जा रही है। इसके कारण पींड का मूल्य फॉक में कम हो जायगा। यदि इज़्लेंड फांस से कच्चा माल मँगाया करता है, तो अब कच्चा माल उसे महिगा मिला करेगा, जिससे इनके द्वारा बनने वाली वस्तुयें महिगी हो जायेंगी। स्पष्ट है कि विनिमय दर के परिवर्तन से मूल्य-स्तर में भी परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार अवमूल्यन में मुद्रा-प्रसार की भी प्रवृत्ति होती है। बहुषा ऐसा देखने में आता है कि जब देश की सरकार देश की चलन की विनिमय दर को घटाती है तो इसके फलस्वरूप देश के भीतर चलन की सामान्य क्रयः शक्ति भी घट जाती है।

(५) विनिमय दर पर प्रभाव डालने वाले मनेक कारणों को छोड़ दिया गया है—इस सिद्धान्त में क्रयः शक्ति के परिवर्तनों को विनिमय दरों के परिवर्तनों का एक मात्र कारण माना गया है, परन्तु विनिमय दरों पर वास्तव में मनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है, जैसे—सट्टा, पूँजी का स्थानान्तरण, व्यापार का विस्तार मादि। इससे सिद्धान्त का व्यवहारिक महत्त्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि विनिमय दरों के परिवर्तनों का मध्ययन करते समय इन सभी कारणों पर विचार करना चाहिए।

- (६) माँग की लोच सम्बन्धी गलत मान्यता पर आधारित यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि देश के माल के लिए विदेशों की माँग की लोच सम (Unity) के बराबर है, अर्थात कीमतों के परिवर्तनों के ही अनुपात में यह माँग घटती-वहती है, परन्तु यह मान्यता सही नहीं है, क्योंकि यह सम्भव है कि यदि एक देश में कीमतों बढ़ती है तो दूसरे देश में उसके माल को माँग न घटे।
- (७) लगभग सभी प्राचीन सिद्धान्तों की भाँति यह सिद्धान्त भी दीर्घकालीन विवेचना ही करता है—यह अधिक से अधिक विनिमय देशों की वीर्घकालीन प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। व्यवहारिक जीवन में मुद्रा अथवा विदेशी विनिमय सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्त का कुछ भी महत्त्व नहीं होता है जो कि अल्पकालीन विवेचना न करता हो। कारए। यह है कि मौद्रिक कारए। अल्प काल में ही इतना उपद्रव मचा देते हैं कि दीर्घकाल की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है।
- ( द ) सामान्य अनुभव इस सिद्धान्त के विरुद्ध है—व्यवहार में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, जिससे यह पता चल जाय कि विनिमय-दर क्रय शक्ति तुल्यता सिद्धान्त द्वारा तय होती है। ग्रतः व्यवहारिक जीवन में इसका कोई महत्त्व नहीं है। सच तो यह है कि गत कुछ वर्षों में ऐसे उदाहरण सामने आये हैं जिनमें विनिमय दर क्रय शक्ति तुल्यता सिद्धान्त के द्वारा तय नहीं हुई थी। अमेरिका ने भारी संरक्षण नीति अपना कर अपना आयात व्यापार बहुत कम कर दिया, जिसके फल-स्वरूप अन्य देशों की मुद्राओं के लिए उसकी माँग बहुत कम होगई, जबिक उसकी मुद्रा (जीवर) के लिए अन्य देशों की माँग पूर्ववत बनी रही। ग्रतः डालर का बाह्य मूल्य बहुत ऊँचा हो गया जबिक डालर का आन्तरिक मूल्य लगभग पहले के समान है। यह अनुभव क्रय शक्ति तुल्यता सिद्धान्त के विरुद्ध है।

### निष्कर्ष—

श्रनेक दोप होते हुये भी कय शिक्ष तुल्यता सिद्धान्त बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि (i) ईस सिद्धान्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश के श्रान्तरिक मूल्य-स्तर श्रीर उसकी विनिमय दर में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। श्रतः प्रत्येक देश अपनी मुद्रा निर्धारित करते समय इस ज्ञान का लाभ उठा सकता है। (ii) यह सिद्धान्त सब प्रकार की चलन पद्धितयों पर लागू होता है। (iii) इसकी सहायता से यह मालूम कर सकते है कि किसी समय व्यापार का रुख क्या होगा। (ो√) इसके द्वारा मुद्रा के अवमूल्यन श्रीर श्रुधिमूल्यन का विनिमय दर व विदेशो व्यापार पर प्रभाव जाना जा सकता है।

विदेशी विनिमय का भुगतान संतुलन सिद्धान्त (The Equilibrium Theory of Foreign Payments)—

यह सिद्धान्त आन्तरिक व्यापार के सिद्धान्त पर बनाया गया है। इसके अनु-सार हम विदेशियों को न तो उससे कम देते हैं और न उससे अधिक जो हमें उनसे प्राप्त होता है। उदाहरए।स्वरूप. यदि क ग्रीर ख देशों के बीच वस्तु शों ग्रीर सेवाग्रों का विनिमय होता है तो साम्य की दशा में क व्यापार तभी करेगा जबिक उसे ख से खरीदे हए माल के लिए वही देना पड़े जो कि उसे ख से उसके हाथ अपना माल बेच-कर प्राप्त होता है। इस सिद्धान्त को बहुधा इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है कि श्रायात निर्यातों का भुगतान करते हैं (Imports pay for the exports)। परन्तू इस सम्बन्ध में कभी-कभी ऐसा कहा जाता है कि जब तक हमें विनिमय दर का पता न होगा. हम यह वह ही नहीं सकते हैं कि देश क अथवा ख़ की प्राप्ति और भुग-तान बराबर हैं। कारण यह है कि का श्रायातों की कीमत ख के चतन में चुकाता है भीर निर्यातों की कीमत अपने चलन में प्राप्त करता है। इस प्रकार लेन और देन दो ग्रलग-ग्रलग मुद्राग्नों में होती है ग्रौर जब तक विदेशी विनिमय दर पहले से ही मालूम नहीं है, इन दोनों की तुलना करने अथवा बरावर होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि हमें विनिमय दर पहले से ही ज्ञात है तो हम क के ग्रायातों ग्रौर निर्यातों की कीमत को क के ही चलन में नाप कर यह देख सकते हैं कि दोनों की कीमत बराबर है या नहीं। जिस विनिमय दर पर यह वरावर होती है, साम्य की दशा में वही विनि-मय दर चालु होगी। यदि आयातों और निर्यातों की कीमत समान नहीं है तो यह ग्रसन्तुलन की दशा होगी। इसके कारण किसी एक व्यापारी देश को लाभ अथवा हानि हो सकती है और उसके कारण आयात और निर्यात में आवश्यक कमी अथवा वृद्धि भी होगी । दीर्घकाल में साम्य वहीं पर स्थापित होगा जहाँ पर कि त्रायातों की कीमत निर्यातों की कीमत के बराबर हो, ऋतः स्थायी विनिमय दर केवल वही होती है जिस पर श्रायातों श्रीर निर्यातों का सन्तलन हो जाय। इस कथन के सत्य होने में कोई सन्देह नहीं है। वास्तविकता यह है कि यह केवल एक सत्यता ही है कि ज्रायातों ज्रौर निर्यातों की कीमत बराबर होती है।

हाती है जिस पर श्रायाता श्रीर नियाता का सन्तुलन हा जाय।

इस कथन के सत्य होने में कोई सन्देह नहीं है। वास्तिवकता यह है कि यह
केवल एक सत्यता ही है कि श्रायातों श्रीर निर्यातों की कीमत बराबर होती है।
यदि एक देश उससे अधिक कीमत का माल मँगाता है जितना कि उसने बाहर भेजा है
तो उसके लिए दो ही उपाय हैं:—या तो वह विदेशी चलन को दूसरे देश से उधार
ले या अपने निर्यातों को बढ़ाकर आयातों की कीमत चुकाए। इनमें से दूसरी दशा में
तो आयात-निर्यात का सन्तुलन हो ही जाता है, परन्तु पहली दशा में सन्तुलन तुरन्त
न होकर कुछ समय पश्चात होता है। उधार सदा के लिए नहीं मिलता है और फिर
उसकी भी एक सीमा होती है। अन्तिम दशा में एक देश के लिए निर्यातों को बढ़ाकर
आयातों की पूरी कीमत का चुकाना आवश्यक होता है, अतः इस कथन की सत्यता में
सन्देह नहीं है कि आयातों का निर्यातों के बराबर होना आवश्यक है, परन्तु इससे
विनिमय दर का पता नहीं चलता है। निर्यातों और आयातों की कीमत उस समय
तक तुलना करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, जब तक कि विनिमय दर पहले से
ही ज्ञात न हो। साथ ही, यह भी निश्चय है कि आयातों श्रीर निर्यातों की मात्राश्रों
में परिवर्तन होने के कारणा ही विनिमय दर में परिवर्तन नहीं होते हैं। स्वयं विनि-

मय दर के परिवर्तन भी आयातों और निर्यातों की मात्रा को घटा-बढ़ा देते हैं।

# शोधनाशेष अथवा चुकती सन्तुलन (The Balance of Payments)-

वर्तमान काल में प्रत्यैक देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में संरक्षण नीति को अपनाता है। विभिन्न रीतियों द्वारा आयातों को घटाने तथा निर्यातों को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि व्यापाराशेष अथवा चुकती का सन्तुलन स्थापित किया जाय। यदि कोई देश किसी कारण अपने आयात द्वारा निर्यातों का मूल्य नहीं चुका पाता है तो दीर्घकाल में उसके लिये यही आवश्यक होगा कि वह अपने आयातों को घटा कर आयातों और निर्यातों के बीच सन्तुलन स्थापित करे।

### शोधनाशेष का अर्थ-

शोधनाशेष से हमारा श्रिभेपाय किसी देश के श्रायातों श्रौर निर्यातों तथा उनके मूल्य का सम्पूर्ण विवरण (Complete Statement) होता है। यह विवरण बही-खाते के एक पृष्ठ की माँति प्रस्तुत किया जाता हैं, जिसमें बाई श्रोर तो सभी निर्यातों श्रौर उनकी कीमतों का विस्तारपूर्वक व्यौरा दिया जाता है श्रौर दाहिनी श्रोर श्रायातों का सविस्तार विवरण होता है। इस प्रकार एक श्रोर तो उन शीर्षकों को दिखाया जाता है जिन पर विदेशियों से भुगतान प्राप्त होते हैं श्रौर दूसरी श्रोर उन शीर्षकों को जिनके निमित्त विदेशियों को भुगतान किये जाते हैं। शीर्षकों के श्रनुसार शोधनाशेष का विवरण निम्न प्रकार होता है:—

Control of the Contro			
	लेन		देन
(१)	वस्तुग्रों के निर्यात ।	(१)	वस्तुओं के श्रायात।
(२)	सेवाग्रों के निर्यात ।	(२)	सेवाग्रों के ग्रायात।
(₹)	विदेशी ऋगों तथा विनियोगों से प्राप्त होने वाली ग्राय, जिसमें मूल-घन का लौटाना, ब्याज तथा लाभ सम्मिलित होते हैं।	(₹)	विदेशियों को ऋगा के चुकाने, ब्याज, लाभ ग्रादि के रूप में किये जाने वाले शोधन।
(x)	विदेशी यात्रियों द्वारा देश में किया जाने वाला व्यय ।	(8)	देश के यात्रियों द्वारा विदेशों में किया जाने वाला व्यय।
(X)	विदेशियों से प्राप्त होने वाले मुग्रावजे, युद्धं-व्यय, दान, दण्ड ग्रादि ।	(খ)	विदेशियों को दिये हुए मुकावजे, दान, जुर्माने, इत्यादि।
(६)	ग्रन्य प्रकार के शोधन, जो विदे- शियों से प्राप्त होते हैं।	(६)	विदेशियों को किये जाने वाले अन्य प्रकार के शोधन।

न्यापाराशेष बहुवा वार्षिक श्राधार पर बनाया जातो है श्रीर इसमें श्रायातों अर्थात् दाहिनी श्रोर के शीर्ष को की कीमत एक पूर्व निश्चित विनिमय दर के श्राधार पर लगाई जाती है, क्योंकि वैसे तो उनकी ग्रलग ग्रलग कीमत विभिन्न चलनों में होती है।

#### शोधनाशेष और व्यापाराशेव —

बोधनाशेष से ही मिलता-जुनता दूसरा शब्द व्यापाराशेप है। यह भी एक ऐसा विवरण होता है जिसमें आयातों और निर्धातों का विस्तृत व्योरा रहता है, परन्तु आयात और निर्धात दो प्रकार के हाते हैं, अर्थात् हर्य और अहर्य (Visible and Invisible)। शोधनारोप में तो इन दोनों ही प्रकार के आयातों और निर्धातों को सम्मिलित किया जाता है, परन्तु व्यापारारोप में केवल हर्य निर्धातों और आयातों को ही सम्मिलित किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि शोधनाशेध का तो सदा ही सन्तुलन हो जाता है, जबिक व्यापारा-शेष का सन्तुलन आवश्यक नहीं होता है। आयातों की मात्रा निर्धातों की तुलना में कम भी हो सकती है और अधिक भी। दूसरे शब्दों में, व्यापाराशेष अनुकूल अथवा बनात्मक (Favourable or Positive) भी हो सकता है और प्रतिकूल अथवा ऋणात्मक (Adverse or Negative) भी। यदि निर्धातों की कीमत आयातों को कीमत से अधिक है तो व्यापाराशेष अनुकूल होगा, परन्तु यदि आयातों की कीमत निर्धातों की कीमत से अधिक है तो व्यापाराशेष प्रतिकूल होगा। शोधनाशेष सदा ही सन्तुलित होता है, परन्तु व्यापाराशेष का सन्तुलित होना आवश्यक नहीं है, यद्यिप संयोग से भले ही वह सन्तुलित हो जाय।

# प्रतिकल व्यापाराशेष को ठीक करने की रीतियाँ—

धभी-ग्रभी हमने यह बताया है कि व्यापाराशेष में भारी ग्रसन्तुलन हो सकता है। यदि व्यापाराशेष अनुकूल है तो यह देश के लिए अच्छा ही सभमा जाता है, क्योंकि विदेशियों को स्वर्ण अथवा वस्तुओं के निर्यात बढ़ा कर इसका निस्तारण करना पड़ता है, परन्तु यदि व्यापाराशेष प्रतिकूल है तो इसके कारण देश के सम्मुख काफी गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्वर्ण का निर्यात तथा विदेशी ऋण एक निश्चित सीमा के परे नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण निस्तारण में कठिनाई होती है। ऐसी दशा में प्रतिकूलता को दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं:—

(१) निर्यातों को म्रार्थिक सहायता तथा म्रायातों पर प्रतिबन्ध— इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्यात व्यापारियों को कम कीमत पर विदेशों में माल वेचने के लिए घाटे को पूरा करने हेतु म्रनुदान, ऋगा, निर्यात करों की छूट म्रादि बिसे जा सकते हैं। विभिन्न रीतियों द्वारा, जैसे—म्रायात प्रशुल्क, म्रम्यंश इत्यादि द्वारा भायातों की मात्रा को सीमत किया जाता है।

(२) मूल्य-ह्रास—इस रीति के अनुसार सरकार देशी चलन की बाह्य अथवा विदेशी विनिमय कीमत में कमी करती है। इसका परिएाम यह होता है कि

विदेशों में देशी माल की कीमत गिर जाती है और इसके विपरीत आयातों की कीमतें ऊँची हो जाती हैं। देश के निर्यातों की विदेशों में माँग बढ़ने और देश में आयातों को माँग घटने से व्यापाराशेष फिर से सन्तुलित हो जाता है।

- (३) मुद्रा-विस्फीति—बहुत बार ऐसा होता है कि एक देश अपने चलन की बाह्य कीमत में क्मी करना नहीं चाहता है। ऐसी दशा में व्यापाराशेष की त्रुटियों को दूर करने के लिए वह देश के भीतर मुद्रा-संकुचन कर सकता है। इसका परिगाम यह होता है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घट जाती हैं, विदेशी माल महिगा पड़ता है और इस कारण आयातों की माँग गिर जाती है और इसके विपरीत देशी माल विदेशियों को कम कीमत पर मिल जाता है, जो उसे अधिक मात्रा में मँगाने लगते हैं।
- (४) मुद्रा-स्रवसूल्यन—इसके द्वारा भी देशी मुद्रा की विदेशी विनिमय क्रयः शक्ति को कम कर दिया जाता है। परिग्णाम यह होता है कि निर्यात प्रोत्साहित होते हैं और श्रायातों की माँग घटती है।
- (५) विनिमय नियन्त्रण्—यह व्यापाराशेष सम्बन्धी असन्तुलन को रोकने की एक व्यापक तथा विस्तृत विधि है। साधारण्तया मुद्रा-संकुचन नीति के फलस्वरूप देशी अर्थ-व्यवस्था पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं, अवमूल्यन तथा मूल्य-ह्रास के कारण् देश के सम्मान को ठेस पहुँचती है और प्रशुल्क कर, अभ्यंश आदि प्रतिकार को जन्म देते हैं, इसिलए इन सभी उपायों का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाता है। उपरोक्त नीतियों के दुष्परिणामों से बचने के लिये विनिमय नियन्त्रण् किया जाता है। इसके अन्तर्गत आयातों और निर्यातों पर इस प्रकार का नियन्त्रण् लागू किया जाता है कि वे सरकारी आज्ञा के बिना नहीं किये जा सकते हैं। निर्यातकत्ताओं को सारा का सारा विदेशी विनिमय सरकार को सौंपना पड़ता है, जो उसे आयातकत्ताओं में बाँट देती है। इसका परिणाम यह होता है कि आयातों की कीमत निर्यातों की कीमत के भीतर ही रहती है।

## विदेशी विनिमय दरों के उचावचन (Fluctuations in the Rate of Exchange)

यह हम पहले ही देख चुके हैं कि विनिमय दरों की स्थिरता आवश्यक नहीं होती है। स्वर्णमान पद्धित में भी उनमें उच्चावचन होते रहते हैं और स्वतन्त्र पत्र-मुद्रा अगाली में तो उच्चावचन काफी गम्भीर होते हैं। साधारणतया विनिमय दरों की स्थायी अथवा दीर्घकालीन प्रवृत्ति तो स्थिरता की ज्योर होती है, परन्तु अल्पकालीन विनिमय दर काफी तेजी के साथ घटती-बढ़ती रहती है। विनिमय दरों के इन परि-वर्तनों के देश के किदेशी व्यापार तथा देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था पर काफी गम्भीर प्रभाव पड़ते हैं। उच्चावचन अनिश्चितता को जन्म देते हैं और अनिश्चितता मनेक बुराइयों को उत्पन्न करती है। प्रत्येक देश यही प्रयत्न करता है कि यथासम्मव

उचावचनों को कम करके एक सीमा के भीतर रखा जाय । इस कारण उन सभी कारणों की व्याख्या का काफी महत्त्व होता है जो विनिमय दरों के उचावचनों को उत्पन्न करते हैं। ये कारणा तीन भागों में वाँटे जा सकते हैं:—(१) विदेशी मुद्राम्रों की माँग भीर पूर्ति की स्थिति, (२) चलन सम्बन्धी दशायें भीर (३) राजनैतिक दशाएँ। इनका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है:—

(१) विदेशी मुद्राश्रों की माँग श्रीर पूर्ति की स्थिति—विदेशी मुद्राश्रों की माँग श्रीर पूर्ति के परिवर्तनों का विदेशी विनिमय दर पर सबसे श्रधिक प्रभाव पड़ता है। यदि विदेशी विनिमय की माँग उसकी पूर्ति से कम या श्रिधिक होती हैं तो उसकी कीमतों में भी घटत बढ़त हो जाती है। श्रत्पकाल में तो माँग श्रीर पूर्ति के श्रसाम्य की सम्भावना काफी श्रधिक होती है। इसी कारण श्रत्पकाल में विनिमय दरों के उच्चावचन काफी विस्तृत होते हैं। विदेशी मुद्राश्रों की माँग श्रीर पूर्ति पर निम्न तीन बातों का श्रभाव पड़ता है:—

(क) व्यापार की दशाएँ (Trade Conditions)—विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति एक वड़े ऋंश तक आयात और निर्यात की माजा पर निर्मर होती है। यदि हमारे निर्यात हमारे ग्रायातों की तुलना में ग्राधिक हैं तो विदेशों में हमारे देश की चलन की माँग ग्राधिक होगी और इसके विपरीत हमारे लिए विदेशी मुद्राओं की माँग कम रहेगी, जिसके फलस्वरूप विनिमय दर हमारे पक्ष में हो जायगी। इसके विपरीत, यदि आयात निर्यात से ग्राधिक हैं तो विनिमय दर हमारे लिए प्रतिकूल हो जायगी। विदेशी व्यापार में हश्य और अहश्य (Visible and Invisible) दोनों प्रकार के आयात-निर्यात सम्मिलत होते हैं।

(ख) सट्टा बाजार का प्रभाव (Stock Exchange Influences)—
सट्टा बाजार में विदेशी विनिमय बिलों का क्रय-विक्रय तथा विदेशी मुद्राश्रों की खरीद
श्रीर बेच होती रहती है। यदि किसी समय सट्टे बाज किसी विदेशी मुद्रा को श्रिषंक
मात्रा में खरीदते हैं तो उस मुद्रा की माँग के बढ़ जाने के कारण उसकी विनिमय
दर उपर चढ़ जायगी। इसके विपरीत यदि सट्टे बाज किसी मुद्रा को बेच रहे हैं
तो उसकी विनिमय दर काफी नीचे गिर सकती है। इसी प्रकार ऋणों के भुगतान
श्रीर प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के कारण भी विनिमय दरों में डचावचन हो सकते हैं।

(ग) श्रिधकोषएा प्रभाव (Banking Influences)—विनिमय दरों पर बैंकिंग नीति के प्रभाव दो प्रकार पड़ते हैं:—(i) बैंक दर में परिवर्तन करके देश की केन्द्रीय बैंक विदेशी श्रष्टणों को प्रोत्साहित श्रथवा हतोत्साहित कर सकती है। यदि बैंक दर ऊँची है तो श्रिषक ब्याज के लोभ में विदेशी लोग श्रिषक ऋए। देते हैं, जिसके कारए। देशी मुद्रा की विदेशी विनिमय बाजार में माँग बढ़ जाती है भौर उसकी विनिमय दर भी अपर उठ जाती है। बेंक दर को नीचा करने का परिएाम

इसके विपरीत होता है। (ii) बैंक विभिन्न प्रकार के साख-पत्रों की निकासी की मात्रा में पिरेवर्तन करके भी विनिमय दरों के उचावचन उत्पन्न कर देती हैं। जब एक बैंक अपनी विदेशी शाखा अथवा किसी विदेशी बैंक के ऊपर ड्राफ्ट अथवा अन्य किसी प्रकार का साख-पत्र निकालती है तो विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है और विनिमय दर गिर जाती है।

- (घ) मध्यस्थों की किया (Arbitrage operations)—जब प्रतियुतियाँ संसार के व्यापारिक केन्द्रों ने सट्टे लाभ के लिये सरीदी और बेची जाती हैं
  तो इन कियाओं को मध्यस्थों की कियायें कहते हैं। इन कियाओं का भी विनिमय
  दर पर प्रभाव पड़ता है। मान लो कलकत्ते में इस समय स्टॉलग का मूल्य १५ पेंस प्रति
  हमया और लन्दन में १६ पेंस प्रति हाया है। यदि कोई बेंक (या व्यक्ति) तार के
  द्वारा लन्दन में १ हाये के बदले में १६ पेंस क्रय कर ले और फिर तत्काल ही कलकत्ते
  में १८ पेंस प्रति हाये पर विक्रय कर दे तो उसे १ पेंस प्रति हपया लाभ होगा। इन
  कियाओं से लन्दन में स्टॉलग की माँग इसकी पूर्ति से ग्रधिक और कलकत्ते में स्टॉलग
  की पूर्ति उसकी माँग से ग्रधिक हो जायगी। फलस्वरूप लन्दन में १ हरया के बदले
  कम पेंस और कलकत्ते में १ ह० के बदले ग्रधिक पैंस मिलने लगेंगे। ग्रयांत् भारत में
  विनिमय दर ग्रधिक ग्रीर इंगलैंण्ड में कम हो जायगी।
- (२) चलन सम्बन्धी दशायें चलन की कयः शिक्त के परिवर्तनों का विनिमय दरों के उचावचनों पर काफी प्रभाव पड़ता है। क्रयः शक्ति समानता सिद्धान्त तो प्रत्यक्ष रूप में यही बताता है कि दो विभिन्न देशों के चलन की क्रयः शक्ति के तुलानात्मक परिवर्तनों के कारण ही विनिमय दर में परिवर्तन होते हैं। यदि किसी देश की मुद्रा की प्रत्यिक निकासी होती है अथवा होने की सम्भावना है, जिसके कारण उस मुद्रा के मूल्य-हास का भय है तो ऐसी दशा में विदेशी पूँजी का आयात नहीं होगा और पहले से लगाई गई विदेशी पूँजी को भी देश से निकाल लेने का प्रयत्त किया जायगा। ऐसी दशा में यह कहा जाता है कि लोग उस चलन से भाग रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि उस देश की चलन की बाह्य कीमत कम हो जायगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी कारण किसी देश की मुद्रा के मूल्य की वृद्धि होती है तो विनिमय दर देश के लिये अनुकूल हो जाती है।
- (३) राजनीतिक दशाएं विदेशी विनिमय का सष्टा तथा विदेशी पूंजी का आवागमन एक बड़े श्रंश तक सरकार की राजनीतिक नीति श्रोर उसके राजनीतिक दृष्टिकोण पर निर्भर होते हैं। यदि सरकार स्थाई तथा टिकाऊ है, शान्ति श्रोर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था है, व्यक्तिगत सम्मित की रक्षा की जाती है, सरकारी नीति निर्पक्ष है तथा श्रमिकों श्रोर मिल-मालिकों के सम्बन्ध श्रच्छे हैं तो ऐसे देश में अपनी पूँजी का लगाना, उसके साथ व्यवसाय करना श्रोर उस देश की साख पर विश्वास करना श्रीष्ट उस देश की साख पर विश्वास करना श्रीष्टक विस्तृत रूप में पाया जायगा। ऐसी दशा में विनिमय दर देश के पक्ष में हो

बायगी। इसके अिंतिरिक्त सँरक्षरा, विदेशी पूँजी सम्बन्धी प्रतिबन्ध, प्रशुल्क, परिकल्पना वेत्त तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी सरकारी नीति पर भी बड़े अंश तक विनिमय दर गौर उसके परिवर्तन निर्भर होंगे।

### वेतिमय दरों के उच्चावचनों की सीमाउँ—

विनिमय दरों में परिवर्तन तो होते रहते हैं, परन्तु देखना यह है कि क्या इन ।रिवर्तनों की कोई सीमा होती है ?(१) स्वर्णमान के अन्तर्गत उचावचनों की सीमाएँ वर्णा बिन्दुत्र्यों द्वारा निश्चित भी जाती हैं । उच्चावचनों का क्षेत्र सीमित होता है भीर वर्ण के निर्यात द्वारा भुगतान करने की स्विवा के कारण विनिमय दर में प्रधिक से प्रिषक स्वर्ण निर्यात व्यय के बराबर भ्रन्तर होता है एक म्रोर विनिभय दर स्वर्ण नेयाति बिन्दु (Upper Specie Point) (टंक समता + स्वर्ण निर्यात न्यय) से क्रेची नहीं जाती है। क्योंकि इस ग्रवस्था में व्यापारियों को विदेशी मुद्रा या इसके बेल खरीदने के बजाय स्वर्णं क्रय करके विदेशों को भेजना स्रधिक सस्ता रहेगा। (सरी श्रोर विनिमय दर स्वर्ण श्रायात बिन्दु (Lower Specie Point) ( टंक अमता - स्वर्ण निर्यात व्यय ) से नीचे नहीं गिरती है, क्योंकि इस दशा में विदेशी श्यापारियों को हमारी मुद्रा या इसके बिल खरीदने के बजाय स्वर्ण कय करके हमारे श्च के व्यापारियों को भेजना अधिक सस्ता रहेगा। ग्रतः स्पष्ट है कि दो स्वर्णमान श्वों के बीच विनिमय दर टंक समता के चारों ग्रीर स्वर्ण ग्रायात विन्दू ग्रीर स्वर्ण निर्यात बिन्दू के नीचे ही घटती-बढ़ती रहती है। जितनी ही विनिमय दर स्वर्ण श्रायात बिन्दुओं के अधिक निकट होगी उतनी ही वह देश के अधिक **ँ**पद्म में होगी। इसके विपरीत जितनी विनिमय दर स्वर्ण निर्यात विन्दु के पास होती है उतनी ही वह देश के विपक्त में होती है।

इसके विपरीत यदि देश में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्राओं का चलन है तो विनिमय दर की सामान्य दीर्घंकालीन प्रवृत्ति कयः शक्ति समानता बिन्दु पर रहने की होगी। इस दशा में स्वर्ण निर्यात द्वारा तो विदेशी मुद्रा को खरीदने का प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए विनिमय दरों के उच्चावचनों पर कोई प्राकृतिक प्रतिबन्ध नहीं होता है। उनके उच्चावचन इस बात पर निर्भर होते हैं कि सरकार उनकी स्थिरता के लिये क्यान्था प्रयत्न करती है और किस अंश तक उनमें सफल होती है। यही कारण है कि इस दशा में विनिमय दरों के उच्चावचनों की कोई भी सीमा नहीं होती है।

# विनिमय दरों के उचावचनों को रोकने के उपाय-

यह हम ऊपर ही देख चुके हैं कि विनिमय दरों के उच्चावचनों पर किन-किन बातों का प्रभाव पड़ता है। इन सब बातों को देखते हुए यह निश्चय करना सरल होता है कि उच्चावचनों को रोकने के क्या-क्या उपाय किए जायें। विनिमय दर की स्थिरता सबसे पहले व्यापाराशेष के ज्यसन्तुलन पर निर्भर होती है। वे सभी उपाय जिनसे व्यापाराशेष के सन्तुलन को दूर किया जाता है, जैसे—ज्यायात प्रशुल्क,

मुद्रा-ह्रास, विस्कीति, विनिमय नियन्त्रण, त्रादि इस दिशा में भी लाभदायक हैं। इनके त्रितिरक्त बैंक दर के समुचित नियन्त्रण, समुचित नियमों तथा सुरज्ञा की व्यवस्था करके भी बड़े त्रंश तक विनिमय दर की स्थिरता स्थापित की जा सकती हैं।

श्रनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दरें—

विनिमय की दर दो प्रकार से व्यक्त की जा सकती हैं-

- (i) स्वदेश की मुद्रा में —जब किसी देश में विनिमय की दर उस देश की अपनी ही मुद्रा में प्रगट की जाती है, तो गिरती हुई (Falling) विनिमय दर उसके अनुकूल या पद्म में होती हैं और बढ़ती हुई दर (Rising Rate) उसके प्रतिकूल या निपद्म में होती हैं। उदाहरण के लिये, मान लो, १ पौंड = १५ रुपये है। यदि यह विनिमय दर घट कर १ पौंड = १२ रु० हो जाती है, तो यह हमारे देश के लिये अनुकूल है, क्योंकि अब हमें १ पौंड का सामान कय करने के हेतु पहले की तुलना में कम रुपये देने पड़ते हैं। इसके विपरीत यदि विनिमय दर बढ़कर १ पौंड = १० हो जाय, तो वह हमारे देश के लिये 'प्रतिकूल' कही जावेगी, क्योंकि अब हमें १ पौंड का सामान क्रय करने के हेतु पहले की अपेक्षा अधिक रुपये देने पड़ते हैं।
- (ii) विदेश की मुद्रा में -- जब किसी देश में विनिमय की दर विदेश की मुद्रा में प्रगट की जाती है तो बढ़ती हुई दर (Rising Rate) स्वदेश के पद्म में होती है और गिरती हुई दर (Falling Rate) स्वदेश के विपद्म में होती है। जैसे, प्राज विनिमय की दर है १ ६० = २१ सैंट। यदि विनिमय दर १ ६० = ३० २२५ सेंट हो जाय, तो यह विनिमय दर स्वदेश के पक्ष में होगी, क्योंकि ग्रव हम १ ६० के बदले में अधिक सेंट (या ग्रधिक विदेशी सामान) क्रय कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि विनिमय दर घट कर १ ६० = २० सेंट हो जाय, तो यह हमारे देश के विपक्ष में होगी, क्योंकि ग्रव हम १ ६० के बदले में कम सेंट (या कम विदेशी मान) खरीद सकते हैं।

जब विनिमय दर अनुकूल होती है तो स्वदेश की एक मुद्रा इकाई के बदले में विदेश की मुद्रा पहले से अधिक मात्रा में मिलने लगती है, जिससे आयात को प्रोत्साहन और निर्यात को अप्रोत्साहन होता है। आयातकर्ताओं व उपभोक्ताओं को लाभ होगा। निर्यातकर्ताओं को हानि होगी। इससे निर्यात उद्योग बन्द हो जायेंगे और धीरे-घीरे देश में बेरोजगारी फैल जायगी। दूसरी ओर, जब विनिमय दर प्रतिकूज होती है तो स्वदेश अपनी एक मुद्रा इकाई के बदले में कम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है। ऐसी दशा में निर्यात को प्रोत्साहन और आयात को अप्रोत्साहन होता है। निर्यातकर्ताओं व निर्यात-उद्योगों के उत्पादकों को लाभ तथा आयातकर्ताओं व उपभोक्ताओं को नुकसान रहता है। उद्योगों की उन्नति से श्रमिकों को खूब रोजगार मिलता है, लेकिन निश्चित आय वाले लोगों को हानि उठानी पड़ती है।

त्रातः स्पष्ट है कि यह कहना कि कोई विनिमय दर किसी देश के लिये ब्रमुकूल है या प्रतिकूल, एक विरोधाभास (Contradiction) है, क्योंकि प्रत्येक रूर में किसी न किसी वर्ग को लाभ श्रीर हानि होती है।

### मावी विनिमय द्र (Forward Exchange)—

विनिमय दर दो प्रकार की होती है-तत्काल ऋथवा प्रस्तुत दर (Spot Rate) ऋौर भावी दर | स्वतन्त्र पत्र-मुद्रा-चलन प्रगालियों में विनिमय दरों के उचावचनों की कोई सीमा नहीं रहती है, इस कारण यह सदा ही अनिश्चित रहता के भविष्य में विनिमय दर क्या होगी । इसका परिखाम यह होता है कि व्यापारियों हो विदेशियों से माल मँगाने तथा उनको माल बेचने के वायदे करने में संकोच होता है। भविष्य में विनिमय दरों के परिवर्तनों के कारए। हानि होने का भय रहता है. प्रस्तु त्र्राष्ट्रनिक व्यवसायिक जगत में निर्यात व्यापारी विनिमय दरों के परिवर्तनों में सम्वन्धित जोखिम से बच सकते हैं। यह कार्य उनके लिये सट्टोबाज कर देते हैं | एक म्रायात म्रथवा निर्यात व्यापारी जब भविष्य में माल खरीदने म्रथवा बेचने का वायदा करता है तो इस वायदे के साथ-साथ वह द्वेध-र ज्ञाग-नायदा (Hedging Contract) भी कर लेता है, जिसमें वह किसी भावी तिथि पर वर्तमान दरों पर विदेशी विनिमय खरीदने या बेचने का किसी सट्टेबाज से वायदा ले लेता है। अब यदि भविष्य में विनिमय दर में परिवर्तन होते हैं तो उनका प्रभाव व्यापारी पर न पड़ कर सट्टेबाज के ऊपर पड़ता है, क्यों कि व्यापारी को तो एक पूर्व निश्वित दर पर ही बंदेशी विनिमय मिल जाता है। यदि भविष्य में विनिमय दर ऊँची हो जाती है तो विने का वायदा करने वाले सट्टोबाज को हानि होती है ग्रौर खरीदने का बायदा करने वाले सट्टोबाज को लाभ होता है। इसके बिपरीत यदि विनिमय दर गिरती है तो खरीदने का वायदा करने बाले सट्टेबाज को द्दानि होती है और वेचने का वायदा

भी इस ग्रनिश्चितता के प्रभाव से बच जाते हैं। भी किया किया में विदेशी विनिमय खरीदने श्रीर बेचने का कार्य 'भावी विनिमय' कहलाता है। विदेशी व्यापार में इसका भारी महत्त्व होता है। एक सुसंगठित भावी विनिमय बाजार विनिमय दरों के परिवर्जनों से सम्बन्धित ग्रनिश्चितता को एक खड़े ग्रंश तक दूर कर देता है, परन्तु स्वयं विनिमय दरों के उच्चावचनों पर भी इस स्वयस्था का काफी प्रभाव पड़ता है। यदि भविष्य में विनिमय दर के ऊपर जाने की प्राशा है तो ग्रभी से विदेशी विनिमय को खरीदना ग्रारम्भ कर दिया जाता है, जिसके हारए। उसमें ग्रकस्मात् परिवर्तन नहीं होने पाते हैं। उच्चावचनों की गति नियमित

हरने वाले को लाभ होता है। दोनों ही दशाग्रों में ग्रायात तथा निर्यात व्यापारी दरों

ाथा सुगम हो जाती है। अवस्था कि वर्तमान दर ग्रीर भावी दर में क्या सम्बन्ध होता

है। भावी दर सदेव वर्तमान दर पर आधारित होती है। विनिमय व्यवसायी विदेशी विनिमय खरीदते और वेचते समय देश के भीतर और विदेश में अल्पकालीन ऋगों के ब्याज की दरों की सावधानीपूर्वंक तुलना करता है। यदि विदेशों में ऐसे ऋगों पर ब्याज की दर देश की अपेक्षा अधिक है तो भावी विनिमय वर्तमान से कटौती (Discount) पर बेचा जाता है। इसके विपरीत, यदि विदेश में देश की अपेक्षा ब्याज की दर कम हैं तो भावी विनिमय लाभ (Premium) पर बेचा जाता है। इसके अतिरिक्त भावी दर इस बात पर भी निर्भर होती है कि भविष्य में विदेशी विनिमय का माँग और पूर्ति सम्बन्धी अनुमान कैसा है और भविष्य में विभिन्न मुद्राओं की मूल्य वृद्धि अथवा मूल्य हास की सम्भावना किस प्रकार है?

#### QUESTIONS

1. इंग्रः शिक्त समता सिद्धान्त को समस्ताइये और स्पष्ट कीजिए कि व्यवहारिक रूप से यह सिद्धान्त कहाँ तक लागू हो सकता है। (Agra, B. A, 1958)

2. What do you understand by the Purchasing Power Parity
Theory relating to foreign exchange? When does the rate
deviate from this parity? (Agra, B. Com., 1958)

3. Discuss the 'Purchasing Power Parity Theory' (सम कयः शक्ति सिदान्त) and state its defects. (Raj., B. A., 1958)

4. Critically examine the Purchasing Power Parity Theory (स्म कथ: शक्ति सि: । নে). (Raj., B. Com, 1958)

5. State and explain the Purchasing Power Parity Theory of Foreign Exchange and indicate its limitations.

(Sagar, B. A., 1958; Alid., B. A., 1954)

6. Write a note on :- Gold Points.

(Agra, B. A., 1956 Supp; Sagar B. Com., 1957)

7. Write a note on :- Mint Par.

(Agra, B. A., 1956, 1954; B. Com, 1955; Raj., B. A., 1954; Sagar, B. A., 1958)

8. Examine briefly the factors that cause fluctuations in the exchange rates. Are there any limits to these fluctuations?

(Raj., B. Com., 1955; Agra, B. Com., 1957)

9. विनिमय को टङ्क समत (Mint Par of Exchange) का क्या अर्थ है ? विदेशी विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव रखने वाले कारगों की विवेचना कीजिए।

(Sagar, B. Com., 1958)

 Discuss the main factors which influence the rate of foreign exchanges. (Aligarh, B. A., 1956)

11. Show how the foreign exchange value of a country's currency is determined.

किसी देश के चलार्थ की विनिमय अर्हा किस प्रकार निर्धारित होती है। Agra, B. A., 1959)

### अध्याय २६

# विनिमय नियन्त्रण

(Exchange Control)

### विनिमय नियन्त्रण का ऋर्थ-

स्वतन्त्र अथवा अनियन्त्रित विदेशी विनिमय व्यवस्था में एक देश के निवासियों को किसी भी मात्रा में विदेशी विनिमय खरीदने और बेचने का पूरा-पूरा अधिकार होता है, परन्तु यदि सरकार देश की विदेशी विनिमय कमाई के किसी निश्चित वितरण के लिए अथवा विदेशी विनिमय कोपों द्वारा कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हस्तद्धे प करती है तो इसे विनिमय नियन्त्रण कहा जाता है। विस्तृत अयं में विनिमय नियन्त्रण का अभिप्राय अधिकारियों द्वारा किये गये उस सभी प्रकार के प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप से होता है जो विनिमय दरों अथवा उनस सम्बन्धित व्यापार को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार विस्तृत रूप में विदेशी विनिमय वाजार में किये गये किसी भी सरकारी हस्तद्धे प को विनिमय नियन्त्रण कहा जा सकता है, जिसमें विनिमय दरों की प्राकृतिक प्रवृत्ति, पूँजी के आवागमन, स्थिरता कोषों के संचालन, व्यापारिक तथा समाशोधन समभौते आदि सभी को सम्मिन्ति किया जा सकता है। किन्तु आजकल इस शब्द का अर्थ अधिक निश्चित तथा सक्वित हो गया है और इसका आश्रय केवल उन हस्तद्धे पों और प्रतिबन्धों से होता है जो निजी विदेशी विनिमय व्यवसाय (Private Foreign Exchange Transaction) के सम्बन्ध में किये जाते हैं।

### विदेशी विनिम्य नियन्त्रण की विशेषताएँ —

विनिमय नियन्त्रण का विकास मुख्यतया प्रथम महायुद्ध के पश्चात् हुमा है। स्वर्ण के पिरत्याग के पश्चात् तो विनिमय दरों के उच्चावचनों के कारण किठनाई इतनी बढ़ गई थी कि लगभग सभी देशों को इस प्रणाली का प्रयोग करना पड़ा था। एक विकसित विनिमय नियन्त्रण प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार दी जा सकती हैं:—(i) इस प्रणाली में सभी प्रकार के विदेशी विनिमय व्यवसायों का केन्द्रीयकरण हो जाता है भौर उनका संचालन देश की वेन्द्रीय बेंक भ्रथवा सरकार द्वारा नियुक्त की हुई किसी अन्य संस्था द्वारा किया जाता है। (ii) देशवासियों द्वारा जितना भी विदेशी विनिमय प्राप्त किया जाता है वह सब का सब इसी केन्द्रीय सत्ता को सींप देना भ्रावश्यक होता है। (iii) सभी प्रकार की विदेशी विनिमय सम्बन्धी भावश्यकतार्थे एक केन्द्रीय कोष में पूरी की जाती हैं भौर यही कोष उनके वितरस्

तथा व्यय की कार्यविधि निश्चित करता है। (iv) इस प्रकार इस प्रणाली में विदेशी विनिमय व्यवसाय पर सरकारी एकाधिकार होता है।

'विनिमय नियन्त्रण' व 'सरकारी हस्तक्तेप' में भेद—

इस सम्बन्ध में विनिमय नियन्त्रण तथा विदेशी विनिमय में किये गये सरकारी हस्तक्षेप (Intervention) में भेद करना आवश्यक है। यदि किसी निश्चित विनि-मय दर को स्थापित करने ग्रथवा बनाये रखने के लिए सरकार विदेशी विनिमय को खरीदती है भ्रथवा बेचती है तो यह सरकारी हस्तक्षेप होगा। ऐसी दशा में व्यक्तिगत व्यवसायियों द्वारा उनकी इच्छा के अनुसार विदेशी विनिमय खरीदने और बेचने पर किसी प्रकार की बाधा नहीं की जाती है। दोनों महायुद्धों के बीच के काल में स्वर्ण-मान के परित्याग के पश्चात् इस प्रकार के हस्तक्षेपों का काफी रिवाज था। उदाहररा-स्वरूप, इङ्गलैंड ने विनिमय समानीकरणा कोष इसी उद्देश्य से स्थापित किया था, परन्त् विनिमय नियन्त्रण इससे बहुत व्यापक होता है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत व्यवसायियों की विदेशी विनिमय खरीदने श्रीर बेचने की स्वतन्त्रता भी समाप्त कर दी जाती है।

विनिमय नियन्त्ररा पूर्णं भी हो सकता है ग्रौर ग्रांशिक भी। पूर्णं विनिमय नियन्त्रसा में सभी विदेशी मुद्रामों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं, परन्त म्रांशिक नियन्त्रसा में केवल किसी एक म्रथवा कुछ मृद्राम्रों के ऋय-विक्रय पर ही इस प्रकार की रुकावटें लगाई जाती है। व्यवहारिक जीवन में ग्रांशिक विनिमय नियन्त्रण का ही चलन ग्रधिक रहा है।

### विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्य-

विनिमय नियन्त्रण प्रणाली का उपयोग बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं --

- (१) विनिमय दर की स्थिरता-इसका उद्देश्य विनिमय दर को एक पूर्व निश्चित बिन्दु पर बनाय रखना हो सकता है। यदि देश में अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा चालू है तो म्रनियन्त्रित विदेशी विनिमय व्यवसाय के कारए। विनिमय दरों में म्रत्यिक उच्चावचन हो सकते है। पूँजी के देश से बाहर जाने को रोक कर विनिमय नियन्त्रण विनिमय टर को गिरने से रोक सकता है, परन्तु साधाररातया पूँजी के श्रावागमन पर प्रतिबन्ध लगाने से ही काम नहीं चल पाता, क्यों कि पूँजी को ग्रहश्य रूप में भी बाहर निकाला जा सकता है. इसलिए बहुवा सभी प्रकार के भुगतानों पर प्रतिबन्ध लगाना स्रावश्यक होता है।
- (२) व्यापाराशेष की त्रुटियों को दूर करना—विनिमय नियन्त्रण का दूसरा उद्देश्य व्यापाराशेष के अन्तरों का समायोजित करना होता है। व्यापारिक प्रतिबन्धों तथा संरक्षरा के सम्बन्ध में किये गये कार्यों के फलस्वरूप न्यापाराशेष का श्रसन्तुलन इतना बढ़ सकता है कि उसके श्रन्तरों का समायोजन कठिन हो जाय। ऐसी दशा में विदेशी भूगतानों के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाना तथा विनिमय कमाई का

नियन्त्रित वितरण श्रावश्यक हो जाता है श्रौर विनिमय नियन्त्रण का उपाय किया जाता है।

(३) सरकारी आय—विनिमय नियन्त्रसा का उद्देश्य सरकार द्वारा आय प्राप्त करना हो सकता है। यदि नियन्त्रसा द्वारा विदेशी विनिमय की विक्री की कीमत और खरीद की कीमतों में अन्तर रखा जाता है तो विनिमय नियन्त्रसा निर्यात करीं का स्थान ग्रहसा कर लेता है और सरकार को इससे आय प्राप्त होती है।

(४) व्यापार भेद-भाव—विनिमय नियन्त्र का उपयोग व्यापारिक भेद-भाव के लिए भी किया जा सकता है। किसी एक देश को व्यापार में छूट दी जा सकती है। कुछ देशों के साथ व्यापार के लिए अथवा कुछ वस्तुओं के आयात-निर्यात के सम्बन्ध में विशेष विनिमय दरें रखी जा सकती हैं। इस प्रकार विनिमय नियन्त्र गा द्विदेशीय व्यापार विभेद (Bilateral Trade Discrimination) का एक अच्छा साधन हो सकता है।

(५) उद्योग संरक्षरा — इसका उपयोग उद्योग संरक्षरा के लिए भी किया जा सकता है। विदेशी आयातों को रोकने और विदेशी प्रतियोगिता का अन्त करने के लिए विनिमय नियन्त्ररा एक बड़ा सप्रभाविक उपाय है।

(६) निषेध — इसका उद्देश्य कुछ विशेष देशों के ग्रायातों ग्रौर निर्यातों को पूर्णतया रोक देना भी हो सकता है।

पूर्णतया राक दना भा हा सकता ह ।
(७) पूँजी का निर्यात रोकना—इसका उद्देश्य देश से पूँजी के निर्यातों
को रोकना ग्रीर विदेशी ऋगों के भुगतानों को रोकना भी हो सकता है ।

इस प्रकार विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्यों में काफी भिन्नता होती है। प्रत्यैक देश ग्रपनी श्रावश्यकताओं श्रौर परिस्थितियों के श्रनुसार ही उद्देश्य को निश्चित करता है, परन्तु विनिमय नियन्त्रण का प्रमुख उद्देश्य किसी ऐसी विनिमय दर की स्थापना होता है जो मुक्त बाजार की दर से भिन्न हो।

विनिमय नियन्त्रण के उपाय-

रें, परन्तु प्रत्यक्ष उपाय अधिक सफल र् माँग श्रीर पूर्ति को प्रसावित करने के उद्देश्य से त्रता पूर्णतया समाप्त कर देते हैं। शिवत की जाती है। १००० इस प्रणाली का आरम्भ परीच्च उपायों में दो का भिलने के कारण हुपा है। यह एक अधिक कठोर, प्रत्यक्ष सरें, ज्याज की दरें। प्रशुलक से पहले सन् १६३१ में जर्मनी ने इस प्रणाली को प्रहण ही पूर्ति को घटाने तथा विदेश

मु॰च॰म्र॰, (२६) १य: अर्थशास्त्र के मूलाधार, पृष्ठ ४६८, दूसरा संस्कर्या।

हैं । आयातों के घटने के कारण विदेशी भुगतानों में भी कमी होती है, ग्रतः देश के चलन की मूल्य-वृद्धि हो जाती है, परन्तु इस नीति की सफलता इसी बात पर निभंद होती है कि सभी देश समान अनुपात में प्रशुल्क करों में वृद्धि न करें, ग्रन्यथा सभी चलनों की तुलनात्मक क्रयः शक्ति में समान वृद्धि हो जाने के कारण विनिमय दर में परिवर्तन नहीं होंगे। निर्यात करों का परिणाम इसके विपरीत होता है। इनमें निर्यातों की मात्रा घटती है और देशी चलन की माँग घटने के कारण उसका अवमूल्यन हो जाता है।

व्याज की दरों का प्रभाव पूँजी के आयात-निर्यात पर पड़ता है। यदि देश में ब्याज की दरें ऊँची कर दी जाती हैं तो पूँजी का आयात होता है, क्योंकि विदेशी ऋगा आकर्षित होते हैं और इस प्रकार देशी चलन की माँग बढ़ने के कारण विदेशी बाजार में उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। ब्याज की दरों के गिरा देने से पूँजी विदेशों को जाने लगती है और देशी चलन की माँग घटती है।

जैसा कि ऊपर संकेत किया गया था, परोच्च उपायों की सफलता का च्लेत्र सीमित होता है, इसलिए सङ्कट काल में शिक्तशाली प्रत्यद्ध उपाय करना आव-श्यक हो जाता है। प्रत्यक्ष उपायों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं — (i) हस्तक्षेप (Intervention) और (ii) विनिमय प्रतिबन्ध (Restriction)। हस्तक्षेप प्रतिमृत्यन, प्रवमृत्यन प्रथवा विनिमय दरों की स्थिरता के लिए किया जाता है। इसकी सफलता के लिए मुद्रा नियन्त्रक के पास देशी चलन, विदेशी चलन प्रथवा सोना पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ताकि विदेशी विनिमय की माँग और पूर्ति में प्रावस्यकतानुसार समायोजन (Adjustment) किया जा सके। इस उपाय का सबसे बड़ा गुण् इसकी सरलता है। स्वर्णमान परित्याग के पश्चात् इङ्गलैंड ने विनिमय दर की स्थिरता के लिए इसी का उपयोग किया था।

# विनिमय समानीकरण कोष (The Exchange Equalisation Account)-

यह कोष ब्रिटेन ने सन् १६३२ में स्थापित किया था, तत्पश्चात् अमरीका, उचावचन हा सकते हैं। पूजी भी ऐसा ही किया था। विनिमय नियन्त्रण की इस रीति विनिमय दर को गिरने से रोक सकती स्विए हम ब्रिटिश विनिमय समानीकरण कोष का पर प्रतिबन्ध लगाने से ही काम नहीं चल फे.

बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए बहुधा सर्ते ऐसा अनुभव किया कि स्टर्लिंग की लगाना आवश्यक होता है। रहे थे। इन उच्चावचनों को रोकने

(२) व्यापाराशेष की त्रुटियों की दूर कर गा खाता खोल दिया। इस कोष दूसरा उद्देश्य व्यापाराशेष के अन्तरों को समायोजित कर यह कार्य एजेन्ट के रूप में बैंक प्रतिबन्धों तथा संरक्षण के सम्बन्ध में किये गये कार्यों के पी में सरकार द्वारा प्रचलित असन्तुलन इतना बढ़ सकता है कि उसके अन्तरों का समायोजने न्द्रीय बैंकों से खरीदा हुआ दशा में विदेशी भुगतानों के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाना तथा को लगभग १७ ५ करोड़

पौंड के कोषागार-विपत्र दिए थे, परन्तु सन् १६३७ तक यह राशि ५७ ५ करोड़ पौंड तक पहुँच गई थी। कोषागार-विपत्रों को प्रत्येक ३ महीने पीछे नया करा लिया जाता था। ग्रारम्भ में कोष की कोई पूँजी विदेशों में नहीं थी, परन्तु कुछ समय परचात् कोष ने विदेशों में पूँजी जमा कर ली थी। कोष का प्रवान उद्देश्य स्टर्लिंग के बदले में विदेशों मुद्राग्रों को खरीद कर ग्रथवा वेच कर विनिमय दरों की स्थिरता बनाए रखना था। यदि विदेशी विनिमय बाजार में स्टर्लिंग की माँग घटती-बद्दी थी तो कोष उसे यथेष्ठ मात्रा में बेच या खरीदकर विनिमय दर को बढ़ने-घटने से रोकता था।

सरकार इस कोष का उपयोग इस रीति से नहीं करती थी कि विनिमय बाजार की स्थायी और दीर्घकालीन प्रवृत्तियों में हस्तक्ते प करे, परन्तु यह प्रयत्न अवश्य किया जाता था कि पूँजी लगाने वालों की घवराहट और सट्टे बाजों की कार्यवाहियों का विदेशी विनिमय दर पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़ सके । इसका उद्देश्य बेंकिंग व्यवस्था को विदेशी विनिमय वाजार से ग्रना रखना और साथ ही दीर्घकालीन प्रवृत्तियों को घ्यान में रखकर विनिमय दरों को दृढ़ बनाना था। इस कोष की कार्य-प्रणाली को गृत रखा गया था। वह बहुत जिटल भी थी। संक्षेत्र में, केवल इतना कहा जा सकता है कि विदेशी विनिमय और मुद्रा-वातुग्रों के बाजार पर नियन्त्रण रखने के लिए एक संतोषजनक प्रणाली बना ली गई थी। इस प्रणाली ने विनिमय दरों के अल्पकालीन उच्चावचनों को भज्ञी-भाँति रोक दिया था, परन्तु यह प्रणाली विभिन्न देशों के बीच कीमतों और आय का समायोजन करने का प्रयत्न नहीं करती थी।

श्चारम्भ में कोष स्टॉलिंग के बदले में डालर खरीदता था, क्योंकि सन् १६३३ तक डालर स्वर्ण में परिवर्तनशील था, इसलिये उसके द्वारा सभी विनिमय दरों पर नियन्त्रण रखा जाता था। सन् १६३३ में श्चमरीका द्वारा स्वर्णमान छोड़ देने पर कोष ने फ्रेंक खरीदना श्चारम्भ कर दिया था, परन्तु सन् १६३६ में फ्रांस द्वारा स्वर्णमान छोड़ देने के पश्चात् कठिनाई हुई। इस कठिनाई को दूर करने के लिये इङ्गलेंड, श्चमरीका और फ्रांस के बीच एक श्चापसी मौद्रिक समभौता किया गया, जिसके श्चनुसार प्रत्येक देश को यह श्चिकार मिला कि वह दूसरे देश की प्राप्त मुद्रा को २४ घन्टे के भीतर उस देश की केन्द्रीय बैंक से सोने में बदल ले।

विनिमय प्रतिबन्ध का तार्ल्य "मुद्रा अधिकारियों की उन कियाओं से हैं जिनके द्वारा विनिमय बाजारों में माँग और पूर्ति को प्रभावित करने के उद्देश्य से विनिमयों की अबाधता प्रतिबन्धित की जाती हैं।" इस प्रणाली का आरम्भ हस्तक्षेप से पूर्ण सफलता न मिलने के कारण हुपा है। यह एक अधिक कठोर, प्रत्यक्ष और सार्थंक नीति है। सबसे पहले सन् १६३१ में जर्मनी ने इस प्रणाली को ग्रहण किया था और बाद को अर्जेन्टाइना तथा मध्य यूरोप के देशों ने भी इसे अपनाया था।

महता तथा अन्य : अर्थशास्त्र के मूलाधार, पृष्ठ ४६८, दूसरा संस्करण ।

सन् १६३६ के पश्चात् भारत तथा बहुत से देशों ने युद्ध-कालान अथ-व्यवस्था की सफलता के लिए इसका काफी उपयोग किया है। इस प्रएगली की कार्य-विधि को सम-भने के लिए जर्मन प्रएगली का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है।

### जर्मनी का विनिमय प्रतिवन्ध—

जर्मनी में यह प्रणाली इस कारण ग्रपनाई गई थी कि सन् १६३१ में जर्मनी में चलन का ग्रवमूल्यन होने के कारण महान् ग्राधिक संकट पैदा हो गया था। ग्रपती युद्धकालीन ग्रथं-व्यवस्था को सुधारने के लिए जर्मनी ने बहुत से ग्रत्पकालीन ऋण दिये थे। इन ऋणों को लौटाने के लिए जर्मन मार्क की पूर्ति बहुत बढ़ाई गई थी, परन्तु जर्मनी का निर्यात व्यापार लगभग शून्य के बराबर था, जिसके कारण विदेशों में मार्क की माँग बहुत ही कम थी। ऋणदाताग्रों को यह ग्राशङ्का थी कि जर्मन ग्रथं-व्यवस्था टूट जायगी, इसलिये उन्होंने मार्क में भुगतान लेने से इन्कोर कर दिया था। स्थित इतनी विगड़ गई थी कि मार्क की बाह्य कीमत के शून्य तक गिर जाने का भय था। इस किटनाई को दूर करने के लिए जर्मनी ने कृत्रिम ग्रितमूल्यन की नीति ग्रहण की ग्रीर जर्मन मार्क की पूर्ति को इस प्रकार नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया कि वह उसकी मांग के बराबर बनी रहे।

इसके लिए जर्मनी ने कठोर उपाय किये—सर्वं प्रथम, सारा विदेशी विनिमय एक केन्द्रीय सत्ता द्वारा रोक लिया गया धौर विदेशी विनिमय व्यवसाय के लिए अनुज्ञापन प्रणाली का आरम्भ किया गया । दूसरा कार्य यह किया गया कि सभी नागरिकों को सभी विदेशी मुद्राएँ, विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा बौंड सरकार को सौंपने का आदेश दिया गया और इस प्रकार एक निश्चित दर पर सरकार ने सारी विदेशी विनिमय सम्पत्ति प्राप्त कर ली । इस सम्पत्ति का एक भाग तो सरकार ने स्वयं रख लिया और शेष को खरीदने की दर से ऊँची कीमत पर उन नागरिकों को वेच दिया कि जिन्हें विदेशी विनिमय की आवश्यकता थी । विदेशी यात्राओं के लिये बहुत ही कम मात्रा में जर्मन प्रथवा विदेशी मुद्रायें दी जाती थीं । आयातों के लिए एक प्राथमिकता का क्रम निश्चित कर दिया गया था और कुछ अनावश्यक वस्तुओं के आयात पूर्णतया बन्द कर दिये गये थे । प्रत्येक आयात व्यापारी को अनुज्ञापन लेना होता था और विदेशी व्यापारी उसे उस समय तक माल नहीं भेजते थे जब तक कि उन्हें यह विश्वास नहीं हो जाता था कि आयातकत्तिओं ने आवश्यक सरकारी आज्ञा प्राप्त कर ली है ।

ग्रन्त में जर्मनी ने ग्रवरुद्ध खाता (Blocked Account) नीति भी ग्रपनाई थी। इसके ग्रनुसार विदेशियों को ग्रपनी सम्पत्ति, प्रतिभूतियाँ तथा मुद्राएँ जर्मनी से बाहर ले जाने का ग्रधिकार नहीं दिया गया था। यह सब सम्पत्ति सरकार के 'ग्रवरुद्ध खाता' नामक ग्रन्म कोष में जमा कर दी जाती थी। प्रत्येक जर्मन ऋग्गी ग्रपना विदेशी ऋगा सरकार को चुकाता था ग्रौर सरकार इस राशि को विदेशी के नाम पर मनरुद्ध खाते में जमा कर देती थी, परन्तु यह राशि विदेशी मुद्राशों में परिवर्तनशील न

थी। विदेशियों को इस प्रकार अपनी मुद्राग्रों में भुगतान नहीं मिलता था और वे विवश होकर या तो जर्मनी से माल खरीद कर अपना भुगतान लेते थे या इस राशि को कम दाम पर वेच देते थे। प्रत्येक दशा में जर्मनी को लाभ होता था। इस व्यवस्था ने विदेशी विनिमय में चोर बाजारी को जन्म दिया, जिसे बहुत बार 'ब्लैंक बोर्स' (Black Bourse) के नाम से पुकारा जाता है।

जर्मनी की यह नीति महान् श्राधिक जादूगर डा० शाट (Schacht) के मस्तिष्क की उपज थी श्रीर इसे 'नयी योजना' कहा जाता था। इन उपायों के परि-एगामस्वरूप जर्मनी का तेजी के साथ ग्राधिक विकास हुग्रा। क्राउथर के अनुसार—"जर्मनी का उद्योग-घन्चा बाहर से खरीद कर मँगाये गये कच्चे माल पर निर्भर करता है श्रीर नाजी सरकार को जर्मन उद्योग-घन्चों पर ग्रावश्यक सामानों के राशनिंग करने के कड़े विनिमय नियन्त्रण के कारण जो अपरिमित शासन शक्ति मिल गई थी, वह उसके हाथ में साघारण श्रीद्योगिक नियन्त्रण का एक जबरदस्त ग्रस्त्र था, परन्तु इसके श्रतिरिक्त जर्मनी की चेष्टा इस दिशा में लगी हुई थी कि श्रायातकृत कच्चे माल की श्रीष्ठक से श्रीष्ठक पूर्ति करे।"\*

### विनिमय नियन्त्रण के श्रन्य रूप-

विनिमय नियन्त्रण तीन ऋलग-ऋलग रूपों में देखने में ऋाया है—एक-देशीय, द्वि-देशीय तथा बहु-देशीय । इनमें से दूसरे और तीसरे रूप में तो केवल ग्रंश का ही अन्तर होता है, परन्तु प्रथम रूप ग्रलग ही प्रकार का होता है। एक-देशीय विनिमय नियन्त्रण एक ही देश के व्यक्तिगत कार्यों का परिणाम होता है, द्वि-देशीय नियन्त्रण में दो देश मिल कर अन्योन्य विनिमय प्रवन्ध करते हैं और बहु-देशीय नियन्त्रण में कई देश सम्मिलित होते हैं। एक-देशीय विनिमय नियन्त्रण के प्रमुख रूप विनिमय समानीकरण कोष, अवरुद्ध खाते, विनिमय राशनिंग तथा आयात-अन्यंश हैं। विनिमय समानीकरण कोष तथा अवरुद्ध खाता प्रणाली का विस्तृत वर्णन ऊपर किया जा चुका है। नीचे अन्य दो प्रणालियों का वर्णन किया जाता है:—

(१) विनिमय रार्शानंग—इस प्रगाली का उपयोग स्वतन्त्र रूप में प्रथवा अवरुद्ध खातों के साथ मिलाकर किया जा सकता है। इस प्रगाली में विदेशी विनिमय कमाई को इस प्रकार रखा जाता है कि वह त्रावश्यक त्रायातों के लिए पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाय। सरकार सभी प्रकार के विदेशी विनिमय के खरीदर्भ और बेचने का कार्य अपने हाथ में ले लेती है और विनिमय दरों को स्वयं निश्चित करती है। विनिमय के स्वतन्त्र व्यवसाय को रोक दिया जाता है। केन्द्रीय बेंक प्राप्त विदेशी विनिमय प्राय को एक निश्चित प्राथमिकता के क्रम के अनुसार आयातकर्ताओं में बाँट देती है। इस प्रकार केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात हो पाता है जिन्हें मेंगाना आवश्यक समक्षा जाता है और प्रत्येक के आयात की मात्रा भी निश्चत हो जाती है।

(२) श्रायात अभ्यंश—विनिमय राशनिंग के साथ-संाय कभी-कभी श्रायात अभ्यंश तथा अनुज्ञापत्र प्रगाली को भी अपनाया जाता है। विदेशी विनिमय का नियन्त्रण श्रायातों और निर्यातों की मात्राओं को निश्चित करके किया जाता है। साधारणतया निर्यातों को तो प्रोत्साहन दिया जाता है, परन्तु अनावश्यक आयातों को या तो कम कर दिया जाता है या पूर्णतया वर्जित कर दिया जाता है। निर्धारण अभ्यंश प्रगाली के अनुसार ही आयात और निर्यात के अनुज्ञापन प्रदान किये जाते हैं और क्योंकि बिना अनुज्ञापन के कोई माल न तो बाहर भेजा जा सकता है और न बाहर से मंगाया जा सकता है, इसलिए पूरे निर्यात और आयात व्यापार पर समुचित नियन्त्रण स्थापित हो जाता है।

# विनिमय उद्बन्धन अथवा पेगिंग (Exchange Pegging)—

यह रीति साधारएतः युद्ध के काल में विनिमय दरों के उच्चावचनों को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। मुद्रा-स्फीति अथवा मुद्रा-संकुचन के कारए। देश की मुद्रा का आन्तरिक मूल्य नीचे गिर सकता है अथवा ऊपर जा सकता है, परनु विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए सरकार उसका बाह्य मूल्य एक निश्चित विन्दु पर बनाये रख सकती है। इस प्रकार विनिमय दर देशी मुद्रा की आन्तरिक क्रयः शक्ति के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं हो पाती है। यदि मुद्रा को क्रयः शक्ति समानता स्तर से अधिक मूल्य दिया जाता है तो इसे दर का 'ऊपर टाँकना' (Pegging Up) कहा जाता है और यदि उद्देश्य अवमूल्यन होता है वो देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य घटाकर विनिमय दर का नीचे अटकाना (Pegging Down) किया जाता है।

दोनों महायुद्धों के काल में इङ्गलैंड ने इस प्रणाली को अपनाया था। सन् १९१६ और सन् १९१६ के बीच कृत्रिम रीति से स्टॉलङ्ग का मूल्य ४'७३५ डालर रखा गया था, यद्यपि यह मूल्य वास्तिवक मूल्य से ऊँचा था। इसी प्रकार दूसरे महा-युद्ध के काल में भारत सरकार ने विनिमय दर १ रुपया = १ शिंतिग ६ पेंस ही बनाये रखी, यद्यपि क्रयः शक्ति समानता के आधार पर यह बहुत नीचे होनी चाहिए थी। इस प्रणाली में विनिमय दर को एक खूँटे से बाँघ कर रखा जाता है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है।

### द्धि-देशीय विनिमय नियन्त्रण की रीतियाँ—

द्धि-देशीय विनिमय नियन्त्रण का प्रचलन भी काफी रहा है, परन्तु अपेक्षतन बहु-देशीय नियन्त्रण का रिवाज कम ही रहा है। बहु-देशीय नियन्त्रण का प्रमुख उदाहरण विनिमय समानीकरण कोषों के सहयोग के रूप में प्रकट हुआ है। द्धि-देशीय नियन्त्रण के दो रूप महत्त्वपूर्ण हैं:—

(१) शोधन समभौते (Payments Agreements)—इस प्रकार का समभौता विनिमय राशनिंग का हो एक रूप होता है। समभौता करने वाले एक देश को विदेशी विनिमय के राशनिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे दूसरे

देश को आवश्यक भुगतान किये जा सकें। शोधन समभौते में एक ऋगी देश ऋगुदाता देश के लिए मूलधन चुकाने, ब्याज देने तथा लाभांश बांटने की व्यवस्था करता है। साधारणतया ऋगी देश ऋगुदाता देश को यह धमकी देकर कि वह उससे माल खरीदना बन्द करेगा, विनिमय राशनिंग व्यवस्था लागू करने पर बाध्य करता है।

(२) निकासी समभौते (Clearing Agreements)—जब दो देश कोई ऐसा समभौता कर लेते हैं जिसके अनुसार अन्योन्य भुगतानों को इस प्रकार एक दूसरे के द्वारा चुकती कर दिया जाता है कि उन्हें विदेशी विनिमय बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती तो इसे निकासी समभौता कहते हैं। इन समभौतों के अनुसार दो देश ऐसी व्यवस्था करते हैं कि प्रत्येक अपने निर्यातकर्ताओं को अपने ही चलन में उन शोधनों में से भुगतान करना तय कर लेता है जो देश के आयातकर्ताओं को प्राप्त होते हैं। ऐसे समभौते द्वारा विदेशी विनिमय बाजार का साधारणा कार्यवाहन पूर्णतया स्थिगत कर दिया जाता है। विदेशी मुद्राओं का उपयोग किये बिना ही भुगतान हो जाते हैं। निकासी समभौते दो देशों के व्यापार का समानीकरण कर देते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को एक प्रकार का वस्तु-विनिमय रूप दे देते हैं।

इन दो रूपों के ग्रतिरिक्त इस प्रकार के विनिमय नियन्त्रण के दो रूप श्रौर भी देखने में ग्राये हैं, जो निम्न प्रकार हैं:—

- (३) विलम्ब-काल हस्तान्तरण (Transfer Moratoria)—इसका उद्देश्य यह होता है कि विदेशियों को उनके द्वारा भेजे हुए माल श्रथवा पूँजी का भुगतान तत्काल न करके कुछ समय पश्चात् किया जाय । श्रायातकर्ता शों को अपने ऋणों का भुगतान देश ही की मुदा में किसी अधिकृत बेंक में जमा करने का भादेश दे दिया जाता है। यह जमा राशि सुरक्षित रखी जाती है और विदेशियों को निश्चित भविष पश्चात् भुगतान किया जाता है। विलम्ब काल (Moratorium) की समाप्ति पर यह राशि विदेशियों को भेज दी जाती है। इस काल में देश की सरकार को विदेशी विनिमय सम्बन्धी श्रावश्यक समायोजन करने का श्रवसर मिल जाता है। साधारणतया विदेशियों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है कि विदेशी प्राप्त का किस प्रकार उपयोग करेंगे, किन्तु कुछ समभौतों में इस सम्बन्ध में भी विदेशियों को श्रादेश दे दिये जाते हैं।
- (४) यथास्थिर प्रथवा निश्चित समभौते (Standstill Agreements)— इस पद्धित का उपयोग सन् १६३१ की आधिक मन्दी के पश्चात् जर्मनी में हुग्रा था। इसमें समभौता करने वाले देशों के बीच पूँजी के हस्तान्तरए। पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं श्रौर विदेशी ऋगों को धीरे-धीरे किश्तों में चुकाने का समभौता किया जाता है। साधारणतया ग्रन्थकालीन ऋगों का भुगतान स्थिगत कर दिया जाता है शौर उनका दीर्घकालीन ऋगों में परिवर्तन कर लिया जाता है।

उपरोक्त व्यवस्था का परिस्माम यह होता है कि ऋगी देश को ग्रपनी ग्रायिक स्थिति में सुधार करने तथा पूँजी के ग्रावागमन को रोक कर विनिमय दर पर नियन्त्रस जगाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।

## भारत में विनिमय नियन्त्रण

### युद्धकालीन विनिमय नियन्त्रण-

भारत में भी संसार के बहुत से दूसरे देशों की भाँति विनिमय नियन्त्रण लागू है। यह नियन्त्रण दूसरे महायुद्ध के काल में ग्रावश्यक हो गया था। महायुद्ध के काल में भारतीय सुरक्षा विधान के ग्रन्तगंत ऐसी व्यवस्था की गई थी कि रिजर्व बेंक ग्रांफ इण्डिया की ग्राज्ञा के बिना विदेशी विनिमय का उपयोग नहीं किया जा सकता था ग्रीर बेंक केवल कुछ स्वीकृत कार्यों के लिए ही उसके उपयोग की ग्राज्ञा देती थी। विनिमय नियन्त्रण का कार्य ग्रारम्भ से रिजर्व बेंक को सींपा गया था ग्रीर इसका संचालन बेंक का विनिमय नियन्त्रण विभाग (Exchange Control Department) करता था। वैसे विदेशी विनिमय व्यवसाय बेंकों द्वारा किया जाता था, परन्तु वे रिजर्व बेंक से ग्रनुज्ञापन प्राप्त करते थे ग्रीर उसी के नियन्त्रण में कार्य करते थे।

### सन् १६४७ का विनिमय नियन्त्रण विधान-

मार्च सन् १६४७ में भारतीय सुरक्षा विधान समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर सन् १६४७ का विनिमय नियन्त्रण अधिनियम (Foreign Exchange Regulation Act, 1947) जो उस वर्ष के फरवरी मास में पास किया गया था, लाग्न किया गया था। अधिनियम के अनुसार केवल रिजर्व बेंक द्वारा अधिकृत विनिमय बेंक ही विदेशी विनिमय व्यवसाय कर सकती है और कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था केवल रिजर्व बेंक के आज्ञा-पत्र (Permit) पर ही विदेशी विनिमय खरीद सकती है। इस सम्बन्ध में स्टिलिङ्ग क्षेत्र के लोगों को कुछ छूट दी गई है। उनके लिए आज्ञा-पत्र आवश्यक नहीं है और इसके अतिरिक्त वे १५० पींड प्रति मास तक अपने कुटुम्ब के व्यय के लिए भी भेज सकते हैं। विनिमय नियन्त्रण का अमुख उद्देश यह है कि देश से सोने के निर्यात, विदेशी पूँजी के आयात तथा विदेशी मुद्राओं के क्रय-विक्रय पर नियन्त्रण रखा जाय। नियम की अन्य व्यवस्थायें निम्न प्रकार हैं:—

(१) भारत में रहने वाले विदेशी एक सीमा तक ही मुद्रा देश से बाहर भेज सकते हैं। साधारएतिया जीवन निर्वाह व्यय की उचित मात्रा को कुल आय में से घटाकर केवल शेष को ही बाहर भेजने की आज्ञा दी जाती है। इसीलिए यदि कोई फर्म, व्यक्ति अथवा संस्था किसी विदेशी व्यक्ति की सेवायें प्राप्त करना चाहती है तो उसे रिजर्व वैंक से आज्ञा लेनी पड़ती है।

- (२) ग्रंशों, प्रतिभूतियों तथा जमा के स्वामी को लाभाँश भौर ब्याज की । ाश देश से बाहर भेजने की पूरी स्वतन्त्रता है ग्रौर इसी प्रकार विदेशी मुद्राग्रों में बीमे की किश्तें भी बिना किसी प्रतिबन्ध के भेजी जा सकती हैं।
- (३) स्वदेश लौटने वाले विदेशी व्यक्ति को वेतन की बचत, प्रावधान कोष राशि तथा निजी सम्पत्ति की कीमत देश से बाहर ले जाने की पूरी स्वतन्त्रता है, यदि यह ४,००० पौंड से ग्रधिक नहीं है।
- (४) यदि आयात कत्तां ने आयात अनुज्ञापन प्राप्त कर रखा है तो वह विदेशों से मंगाई गई वस्तुओं की कीमत स्वतन्त्रतापूर्वक चुका सकता है। बिना अनु-ज्ञापन के मंगाई हुई वस्तुओं के लिए (यदि वे खुले सामान्य अनुज्ञापन के अन्तर्गत नहीं आती हैं) विदेशी विनिमय नहीं दिया जाता है।
- ( ५ ) विदेशी व्यापार संस्थायें ग्रपने लाभ को प्रधान कार्यालयों को मेज सकती हैं।
- (६) कुछ विशेष परिस्थितियों के म्रतिरिक्त पूँजी का स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के वाहर निर्यात नहीं किया जा सकता है।

# श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा विनिमय स्थायिस्व---

धन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना के पश्चात् भारत भी कोष के सदस्यों में सिम्मिलित हो गया है। इस कोष ने भारत तथा ग्रन्य सदस्य देशों की मुद्राग्नों की कीमत स्वर्ण ग्रथवा ग्रमरीकन डालर में परिभाषित करके ग्रौर सदस्य देशों को व्या-पाराशेष के घाटों को पूरा करने के लिए ऋए। देकर विनिमय दरों की स्थिरता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। कोष विदेशी विनिमय तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी प्रतिबन्धों के विरुद्ध है। सदस्य होने के नाते भारत को भी मुद्रा-कोष के ग्रादेशों का गालन करना पड़ता है।

#### **QUESTIONS**

- 1. विनिमय नियन्त्रण के क्या उद्देश्य हैं ? विनिमय नियंत्रण के साधनों का वर्णन कीजिए। (Agra, B. A., 1957)
- 2. श्राप 'विनिमय नियंत्रण' का क्या तात्पर्य सममते हैं ? वह क्यों श्रावश्यक हो गया हैं। (Sagar, B. Com., 1954)
- What should be the object of exchange control? Describe the various methods of exchange control. Do you support them?
  (Bihar, B. A., 1957; Patna, B. A., 1957)

6.

 Explain the chief aims and methods of exchange control illustrating the same from its working in India.

(Raj., B. Com., 1954, 1957)

- 5. Write short note on :—Exchange Control.

  (Agra, B. A., 1958, 1956 Supp.; Agra, B. Com, 1958;

  Alld, B. A., 1956)
  - Write a note on: Exchange Equalisation Account.
    (Agra, B. A., 1956; Raj., B. Com., 1957, 1955)
- 7. Explain the objectives, nature and limitations of Exchange Equalisation Account. (Agra, B. A., 1955)
- 8. Write a note on :- Exchange Pegging.

(Agra, B. Com., 1957).

9. Discuss the objects and methods of exchange control, with special reference to methods employed in India. भारत में प्रयुक्त पद्धतियों का विशेष उल्लेख करते हुए विनिमय नियमन के उद्देश्यों श्रीर पद्धतियों का विवेचन करिये। (Agra, B. Com., 1959)

### प्रध्याय २७

# भारतीय चलन का इतिहास

( सन् १६२५ से पूर्व )

(The History of Indian Currency)

## प्राचीन भारत में मुद्रा एवं चलन (द्विधातुमान पद्धति)—

भारत में मुद्रा का उपयोग ग्रतीत काल से होता ग्राया है। सभी प्राचीन ग्रन्थों से इसका प्रमाण मिलता है। वेद, मनुस्मृति तथा बौद्ध साहित्य में ग्रनेक स्थानों पर मुद्रा तथा चलन के उपयोग का वर्णन मिलता है। इसके ग्रतिरिक्त ग्रनेक पुराने सिक्के, शिला लेख तथा ऐतिहासिक प्रमाण ऐसे प्राप्त होते हैं जिनसे मुद्रा के उपयोग की प्राचीनता सिद्ध होती है। ऋगवेद में गाय को मूल्य की सामूहिक माप के रूप में उपयोग करने का वर्णन ग्रनेक स्थानों पर पाया जाता है। मुस्लिम काल में तो सम्राट द्वारा सिक्कों ग्रीर मुहरों का निकालना ग्रीर चालू करना एक साधारण सी घटना बन गई थी।

मुस्लिम-काल में मुहम्मद तुगलक ने सांकैतिक सिक्के तथा पत्र-मुद्रा का निगंमन करके एक अनुपम तथा महत्त्वपूर्ण प्रयोग किया, परन्तु यह प्रयोग सफल न हो सका । १७ वीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी अपनी शिल्पशालाओं तथा अपनी आधीन बस्तियों के लिए सिक्कों का ढालना आरम्भ कर दिया था। इसके पश्चात् जैसे-जैसे कम्पनी वा अधिकार अधिक भू-भाग पर होता गया, इन सिक्कों ना प्रचलन बढ़ता ही गया, परन्तु इस काल में सबसे बड़ी कठिनाई सिक्कों की भारी विविधता ही थी। अनेक धातुओं के सिक्के प्रचलित थे और स्वयं एक ही धातु के सिक्कों में भी रूप, मूल्य वजन तथा शुद्धता में अत्यधिक अन्तर होता था। ऐसी दशा में व्यापार में अमुविधा होती थी, क्यों कि सिक्कों की परख आवश्यक होती थी और विभिन्न सिक्कों का विनिमय उनकी शुद्धता की परख के पश्चात् तोल कर किया जाता था। सन् १८३५ तक द्वि-धातुमान पद्धति चालू थी तथा सोने और चांदी दोनों के सिक्के विधि ग्राह्य थे। ईस्ट इगिडया कम्पनी का आवगमन एवं इसके पश्चात् (रजत मान की स्थापना)—

सन् १६३५ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सर्वप्रथम अपने अधीन क्षेत्रों में प्रचलित सिक्कों में ग्रनुरूपता स्थापित करने का प्रयत्न किया। कम्पनी की राज्य सीमाग्रों के भीतर चाँदी के रुपये को जिसका भार एक तोला भ्रथवा १८० ग्रेन होता था ग्रौर जिसमें चाँदी की मात्रा १६५ ग्रेन थी. प्रामाणिक सिक्का घोषित कर दिया गया ग्रौर यह भी ग्रादेश निकाला गया कि भविष्य में कम्पनी के राज्य क्षेत्र में सोने का सिक्श कहीं भी विधि-ग्राह्म नहीं होगा । इस प्रकार रजतमान के रूप में देश में एक-घातुमान स्थापित किया गया । चाँदी को स्वतन्त्र मुद्रण प्रदान किया गया ग्रौर उसकी ढलाई ग्रारिमित रखी गई। सोने में रुपये की कीमत चाँदी के स्वर्ण मुल्य पर निर्भर होने लगी। सन् १८६४ में भारतीय रुपए का स्वर्ण मृत्य सावरेन में दस रुपया प्रति सावरेन ग्रथवा १ रुपया = २ शिलिंग रखा गया, परन्त्र इस समय तक चाँदी की बहुत सी नई खानों का पता लग जाने तथा स्रधिकाँश देशों द्वारा चाँदी के विमुदीकरण के कारण स्वर्ण में चाँदी की कीमत भी अधिक घट चुकी थी। सन् १८७३ में लेटिन संघ (Latin Union) देशों ने फ्रांस का ग्रन्करण करके द्वि-घात्मान को समाप्त कर दिया ग्रीर चाँदी के सिक्कों को चलन से निकाल कर स्वर्ण मुद्रा तथा एक-घातुमान को स्वीकार किया स्रौर यूरोप के देशों में स्वर्णमान पद्धित का प्रचार हुमा। सन् १८७४ में फांस, इटली तथा स्विटजरलैंड ने चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण स्थिगत कर दिया । जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, नार्वे तथा हालैंड ने पहले से ही चाँदी का विमुद्रीकरण कर दिया था। इसका परि-गाम यह हुम्रा कि स्वर्ण की कीमत निरन्तर गिरती ही रही। सन् १८७१ में यह २ शिलिंग के बराबर थी, परन्तु सन् १८६२ में यह केवल १ शिलिंग ३ पेंस रह गई थी।

चाँदी की कीमतों के इस भारी पतन का कारए। यह था कि माँग की तुलना में चाँदी की पूर्ति अधिक बढ़ गई थी। अधिकाँश यूरोपीय देशों द्वारा स्वर्णमान प्रहरण करने के कारए। चाँदी के सिक्कों को गला कर घातु के रूप में बेचा जाने लगा था। चौदी की नई खानों की खोज तथा चाँदी निकालने की विधियों के सुघार ने भी चौदी के उत्पादन में अत्यिधक वृद्धि की। सन् १८६१ में चाँदी की उत्पत्ति सन् १८७६ की अपेक्षा दूनी हो गई थी। इसके विपरीत स्वर्णमान की प्राह्मता के कारण सोने की मांग अधिक बढ़ गई थी, यद्यपि उसका उत्पादन घट रहा था।

### परिणाम-

- (१) चाँदी की स्वर्ण में कीमतों के गिर जाने का परिणाम यह हुम्रा कि भारत में चाँदी के भ्रायातों में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिसके कारण मुद्रा-प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो गई ग्रीर कीमतों बढ़ने लगीं। सन् १८७३ ग्रीर सन् १८६३ के बीच कीमतों में २६% की वृद्धि हो गई थी।
- (२) इसके अतिरिक्त सोने में चाँदी की कीमतों के गिर जाने का देश के विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा और विदेशी पूँजी की सहायता से भारत के आर्थिक जीवन का विकास करने में कठिनाई होने लगी, क्योंकि पूँजी के आयात अधिक घट गये थे।
- (३) साथ ही, ग्रुह खर्चों का भार बढ़ गया और ब्रिटिश अफसरों के वेतन तथा उत्तर-वेतन चुकाने के लिए घन भेजने में भारत सरकार को भारी किठनाई होने लगी। इन । सबकी कीमत स्टिलिंग में निश्चित की जाती थी और रुपये की कीमत के प्रत्येक पतन के साथ इन दायित्त्वों को चुकाने के लिए अधिक मात्रा में रुपयों की आवश्यकता पड़ने लगी थी।
  - (४) सरकार को करों में भारी वृद्धि करनी पड़ी और बजटों के सन्तुलन में भारी कठिनाई भ्रतुभव होने लगी।

कई वर्षों तक भारत सरकार ने म्नन्तर्राष्ट्रीय द्वि-घातुमान की स्थापना का प्रयत्न किया। सन् १८६७ तथा सन् १८६२ के बीच इस कार्य के लिए चार बड़े-बड़े भन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुए, परन्तु जब सफलता प्राप्त न हो सकी तो भारत सरकार ने स्थिति की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्ति की।

# हरशैल समिति (The Herschell Committee)—

यह सिमिति सन् १८६२ में लार्ड हरशैल की ग्रध्यक्षता में नियुक्त की गई थी भौर सिमिति को भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्तावों पर विचार प्रकट करने का आदेश दिया गया था:—(१) क्या भारत में चाँदी का स्ततन्त्र मुद्रंण समाप्त कर दिया जाय भौर स्वर्णमान ग्रह्ण कर लिया जाय, (२) क्या भारत में सोने के सिक्के चालू किए जायें और (३) क्या रूपया की स्टर्लिंग विनिमय दर घटा कर १ रू० = १ बिलिंग ६ पेंस कर दी जाय?

समिति का विचार था कि भारत में सोने के सिक्कों का चालू करना ग्रनावश्यक तथा ग्रनुपयुक्त था, क्योंकि बिना सोने के सिक्कों को चलाये भी स्वर्णमान स्थापित हो सकता था। साथ ही, यह भी कहा गया कि इसके ग्रहण करने से सोने में चाँदी की कीमतों के और अधिक गिर जाने की सम्भावना थी। सिमिति ने १ शिलिंग ६ पैंस की विनिमय दर को भी इस कारण अनुपयुक्त बताया कि इसका देश के व्यापार, उद्योग तथा आधिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सिमिति ने दो मुक्ताव दिए:—(१) चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण बन्द होना चाहिये, परन्तु सरकार यह घोषणा करे कि यद्यपि जनता का यह अधिकार नहीं रहेगा कि वे चाँदी की सिलों को रुपयों में ढलवा सके, परन्तु सरकार अपनी टकसालों में १ शिलिंग ४ पैंस प्रति रुपया की कीमत पर चाँदी के रुपयों को ढालने का काम बराबर करती रहेगी। (२) सरकारी खजानों में सभी प्रकार के लोक दायित्वों के भुगतान में सोना इसी दर पर स्वीकार होता रहेगा।

इन सिफारिशों के तीन परिणाम हुए:--

- (१) सोना तथा चाँदी दोनों का स्वतन्त्र मुद्रग् समाप्त कर दिया गया।
- (२) रुपया एक साँकेतिक सिक्झा बन गया, क्योंकि एक ग्रोर तो इसकी विनिमय कीमत इसकी निहित कीमत से ग्रीवक रखी गई थी ग्रीर दूसरी ग्रोर उसका मुद्रग्र समिति ग्रीर प्रतिबन्धित था।
- (३) इन सिफारिशों में स्वर्णमान की स्थापना की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की गई थी, यद्यपि यह विचार प्रकट किया गया था कि भविष्य में स्वर्णमान स्थापित किया जायगा।

भारत सरकार ने हरशैंन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करके भारतीय मुद्रण एक्ट सन् १८६३ पास कर दिया । तत्पश्चात रुपये की विनिमय दर चाँदी की कीमतों के प्रभाव से विमुक्त हो गई भ्रौर चांदी का मूल्य के मान के रूप में उपयोग बन्द हो गया, यद्यपि चलन हेतु प्रमुख घातु अभी भी चांदी ही रही। स्वर्ण को अब भी विधि-ग्राह्य स्थान प्रदान नहीं किया गया था.। अतः हरशैल समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में एक अपूर्ण द्वि-धातुमान अपनाया गया, जिसमें चाँदी और सोने के सिकों का मुद्रण जनता द्वारा नहीं कराया जा सकता था और केवल चाँदी के रुपये ही असीमित विधि याह्य थे।

चाँदी के स्वतन्त्र मुद्रग्ण को समाप्त करने का उद्देश्य रुपये की विदेशी विनिमय दरों को उँ वा करना था। सन् १८६३ में रुपये की विनिमय दर केवल १ शिलिंग रई पैंस थी और सरकार ने उसे बढ़ा कर १ शिलिंग ४ पैंस कर देने का प्रयत्न किया। इसके लिए रुपयों की कुल मात्रा में कभी की गई। मुद्रा संकुचन ने लोगों को भयभीत कर दियो। गाढ़ कर रखे हुए रुपये चलन के लिए निकलने लगे और जेवरात बनाने में रुपयों का उपयोग घटने लगा। परिग्णाम यह हुआ कि रुपयों का प्रचलन घटने के स्थान पर बढ़ गया। १ शिलिंग ४ पैंस की विनिमय दर बनी न रह सकी और सरकार को १ शिलिंग १ मैं पैंस की दर पर रुपये बेचने पड़े। जनवरी सन् १८६६ में यह दर गिर कर १ शिलिंग ६ पैंस ही रह गई, परन्तु तत्पश्चात् यह घीरे-घीरे बढ़ कर सन् १८६६ में १ शिलिंग ४ पैंस हो गई. क्योंकि अब चाँदी की कीमतों का विनिमय

दर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। रुपये की यह कीमत सन् १६१६ तक स्थित्या स्थायी रही। केवल सन् १६०७-०६ में कुछ आर्थिक संकटों के कारण यह थीं समय के लिए नीचे गिर गई थी।

भारत में स्वर्ण-विनिमय मान (सन् १=६६-१६१६)—

विनिमय दर के १ शिलिंग ४ पैंस पर स्थिर हो जाने के पश्चात् भारत सरका ने मार्च सन् १८६८ में भारत सचिव से भारत में पूर्ण स्वर्णमान स्थापित करने कं फिर प्रार्थना की, अतः सर हेनरी फाऊलर (Sir Henry Fowler) की अध्यक्षत में एक और समिति नियुक्त की गई। फाऊलर समिति के प्रमुख सुम्नाव निम्प्रकार थे:—

- (१) भारतीय टक्सालों में चाँदी का स्वतन्त्र मुद्रण नहीं होना चाहिए क्चोंकि भारत का रूँ व्यापार स्वर्णमान देशों के साथ ही था।
- (२) ब्रिटिश सावरेन को भारत में अपिरिमित विधि-ग्राह्य मुद्रा घोषित के देना चाहिए और उसका भारत में प्रचलन होना चाहिए। भारत हे सोने की स्वतन्त्र ढलाई होनी चाहिए। सावरेन की ढलाई और उसक
- प्रचलन इङ्गलैंड ग्रौर भारत दोनों देशों में होना चाहिए।
  (३) रुपया सांकेतिक सिक्का रहते हुए भी ग्रपरिमित विधि ग्राह्य बन
  रहना चाहिए।
  - (४) रुपये ग्रौर स्टर्लिङ्ग की विनिमय दर १ शिलिंग ४ पैंस प्रति रुपय रहनी चाहिये। (५) क्योंकि स्वर्ण कोष का सबसे महत्त्वपूर्ण उपयोग यही था कि विदेश
  - भुगतानों के लिये वे स्वतन्त्रतापूर्वक प्राप्त होते रहें, इस कारण भारत सरकार को स्वर्ण निर्यात के लिये सोने का संचित कोष रखन चाहिए, जिससे कि विनिमय दर की स्थिरता स्थापित की जा सके।
  - (६) भारत सरकार को सोने के बदले में रुपये देने की प्रथा को बनारं रखना चाहिये, परन्तु नये रुपये के सिक्कों की ढलाई उस समय ता बन्द रहनी चाहिये जब तक कि चलन में स्वर्ण का अनुपात जनत की स्वर्ण आवश्यकता से अधिक न हो जाय।
  - (७) निर्यात के लिये जनता को पर्याप्त स्वर्ण देने के लिए सरकार कं स्वर्ण कोष रखने चाहिये। रुग्यों के मुद्रण पर जो भी लाभ प्राप्त हं उसे सरकार की साधारण भ्राय में हस्तान्तरण नहीं करना चाहि
    - ग्रौर न ही उसे सरकार की साधारण जमा (Balances) के रू में रखना चाहिए। इस लाभ को सोने में एक विशेष सुरक्षित कोष ने रूप में रखना चाहिए ग्रौर यह सुरक्षित कोष साधारण पत्र-मुद्र निधि तथा सरकार की साधारण कोषागार जमा (Treasur)

Balances) से पूर्णतया अलग होना चाहिये।

### परिणाम-

भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और इन्हें कार्य रूप देने का प्रयत्न किया। सितम्बर सन् १८६६ में सावरेन को विधि-ग्राह्म मुद्रा घोषित किया गया, परन्तु रुपया भी अपरिमित विधि-ग्राह्म बना रहा। ब्रिटिश कोषागार की स्वीकृति न मिलने के कारण भारत में सोने के सिक्कों की ढलाई के लिये शाही टक-साल की शाखा खोलने की योजना रह कर दी गई। इस प्रकार देश में जो मौद्रिक मान स्थापित हुन्ना उसे स्वर्ण-विनिमय-मान कहा गया। यह एक ऐसा स्वर्णमान था जिसमें सोने के सिक्कों का प्रचलन न था। इस मान की चार प्रमुख विशेषताएँ थीं :—(१) इसमें देश के भीतर सोने के सिक्कों का प्रचलन न था। (२) देश की भीतरी आवश्यकताओं के लिए रुपये को सोने में परिवर्तन करना आवश्यक न था। (३) केन्द्रीय सरकार द्वारा देशी मुद्रा के बदले में एक निश्चित अधिकतम् विनिमय दर पर विदेशी विप्रेषों (Remittances) को सोने में भेजने की व्यवस्था की गई थी। (४) इन विप्रेषों के लिये मुरक्षित कोषों का एक आवश्यक भाग इक्कलंड में रखा जाता था।

इस मौद्रिक मान की देश में कड़ी त्रालोचना हुई :—

- (१) यद्यपि इसके श्रन्तर्गत विनिमय दरों की स्थिरता तो प्राप्त हो गई थी, परन्तु कीमतों की स्थिरता प्राप्त न हो सकी। सन् १८६३ घौर सन् १६२३ के बीच संसार के ग्रन्य देशों की तुलना में भारत में ही कीमतों के सबसे ग्रधिक उच्चा-वचन हो रहे थे। सन् १६०७-०८ के सङ्कटकालीन वर्षों में यह मुद्रा प्रगाली टूटते-टूटते बची ग्रीर सन् १६१६-२० में तो यह एक दम टूट ही गई।
- (२) कीमतों के इन भारी उचावचनों ने स्त्रार्थिक जीवन में स्त्रानिश्चितता उत्पन्न करके देश के व्यापार स्त्रीर पूँजी विकास के मार्ग में बाघाएँ उपस्थित कर दीं।
- (३) इसके अतिरिक्त यह मौद्रिक मान प्रवन्धित मान था और इसके सफल संचालन के लिए पग-पग पर सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती थी। यह एक जटिल प्रगाली थी और कैनन के शब्दों में मूर्ख-सिद्ध तथा मकार-सिद्ध न थी। चैम्बरलेन आयोग (The Chamberlain Commission)—

सन् १८६६ के पश्चात् भारत में जो मौद्रिक प्रणाली स्थापित हुई थी उसकी भारत में कड़ी ग्रालोचना हुई थी। इसके ग्रितिरक्त इस प्रणाली की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा भारत सचिव के बीच भी भारी मतभेद था। इन ग्रालोचनाओं तथा इस मतभेद की जाँच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अप्रैल सन् १९१३ में मिस्टर चैम्बरलेन की ग्रध्यक्षता में एक शाही ग्रायोग नियुक्त किया। इस ग्रायोग ने ग्रपनी रिपोर्ट फरवरी सन् १९१४ में प्रस्तुत की, जिसके प्रमुख सुक्ताव निम्न प्रकार थे:—

- (१) आयोग ने स्वर्गा-विनिमय-मान को चालू रखने की सिफारिश की, क्योंकि आयोग का विचार था कि इस मान ने सन् १६०७-०८ के आर्थिक संकट का सफलतांपूर्वंक सामना किया था और वैसे भी इसका विकास अनेक प्रकार के प्रयोगों के पश्चात् हुआ था।
- (२) सोने के सिक्कों की ढलाई के लिए भारत में टकसाल का खोलना अनावश्यक था। इसके विपरीत भारत में बम्बई की टकसाल को स्पर्य देकर बराबर सोना खरीदना चाहिए।
- . (३) स्वर्णमान निधि में वृद्धि होनी चाहिए और इन कोषों को लन्दन में ही रखा जाना चाहिए। सिक्कों की ढलाई पर जो भी लाभ हो वह सबका सब इसी निधि कोष में जाना चाहिए।
  - (४) भारत सरकार को यह गारन्टी देनी चाहिए कि ग्रावश्यकता पड़ने पर विशेष रूप से विनिमय दरों के गिरने की दशा में, वह १ शिलिंग ३ड्डें पैंस प्रति रुपया की दर पर भारत में लन्दन पर बिल बेच देगी।
  - (५) पत्र-मुद्रा प्रसाली को भ्रधिक लोचदार बना देना चाहिए और स्वर्सा मुद्रा के स्थान पर सोने के उपयोग को भ्रधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए।
- ( ६ ) स्वर्णमान की रजत शाखा (Silver Branch) को बन्द कर देना चाहिए ।

त्रभी चैम्बरलेन त्रायोग की सिफारिशों को कार्यरूप देने का त्रावसर भी न त्राया था कि प्रथम महायुद्ध त्रारम्म हो गया।

### प्रथम महायुद्ध और भारतीय चलन-

युद्ध के ग्रारम्भ में ग्रन्य देशों की भाँति भारतीय मुद्रा-प्रगाली पर युद्धकाल की पिरिस्थितियों का जो त्र्यसर पड़ा तथा बिगड़ती हुई दशा के सुधार के लिए परकार द्वारा जो प्रयत्न किये गये थे उनका संद्यित व्योरा इस प्रकार हैं:—

- (१) भारत में भी भय की स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसके कारण व्यापार प्रीर व्यवसायों में भारी अस्थिरता तथा अनिश्चितता आ गई। इस भयपूर्ण स्थिति के लक्षण विनिमय दरों के पतन, सेविङ्ग बैंक जमा निकालने, कागज के नोटों को रुपये के सिक्कों अथवा सोने में बदलने तथा भारत सरकार के स्वर्ण-कोषों से सोना मांगने के रूप में प्रकट हए।
- (२) विनिमय दर के पतन को रोकने के लिए ६ अगस्त सन् १९१४ तथा २८ जनवरी सन् १९१५ के बीच भारत सचिव को ८७,०७,००० पौंड की कीमत के

प्रति परिषद् विपन्न (Reverse Council Bills) वैनने पड़े। लोगों का पन्नमुद्रा पर से निश्वास उठने लगा और १० करोड़ रुपये की कीमत के कागजी नोट
कोषागार को लौटा दिये गये। लोगों ने रुगयों और सोने के सिक्कों को, जमा करके
रखना आरम्भ कर दिया और कागज के नोटों को रुपये के सिक्कों और सोने में बदलने
की माँग बहुत बढ़ गई। बैंकों में से भी भारी मात्रा में जमा का निकालना आरम्म
हो गया।

- (३) नोटों को सोने में बदलने की माँग इतनी बढ़ गई कि पहिली और चौथी अगस्त सन् १६१४ के बीच में ही भारत सरकार को १८,००,००० पींड की कीमत का सोना देना पड़ा। ५ अगस्त सन् १६१४ को भारत सरकार ने प्राइवेट व्यक्तियों को सोना देना बन्द करने की घोषणा कर दी। इस प्रकार कुछ काल के लिए संवर्णमान स्थगित कर दिया गया।
- ्रं (४) सन् १६१५ के अन्त तक भारत का निर्यात व्यापार फिर उन्नति करने लगा, जिसका कारए। यह था कि विदेशों में अच्छी कीमतों पर भारतीय माल की माँग अधिक बढ़ गई थी। इसके विपरीत भारत के आयात व्यापार का संकुवन हुया, क्योंकि बाहर के देश युद्धकालीन परिस्थितियों के कारए। भारत को पर्यात मात्रा में माल भेजने में असमर्थ थे। इस प्रकार व्यापाराशेष काफी अंश तक भारत के पक्ष में हो गया।
- (१) साधारण परिस्थितियों में भारत के अनुकूल व्यापाराजेष का निस्तारण विदेशों द्वारा भारत को सोना भेजकर तथा भारत सचिव द्वारा परिषद् विपत्र (Council Bills) बेच कर किया जाता था, परन्तु युद्धकाल में सुरक्षा की कमी तथा यातायात सम्बन्धी किठनाइयों के कारण बहुमूल्य धातुओं के निर्यात सम्भव न हो सके। इसके विपरीत भारत सचिव की परिषद् विपत्र वेचने की क्षमता इस बात पर निर्भर होती थी कि वह भारत सरकार के लिए रुपयों की मात्रा बढ़ाने के लिए कितनी चाँदी खरीद सकता था। इस सम्बन्ध में भारत सचिव को यह किठनाई अनुभव हुई कि युद्धकाल में चाँदी की माँग बढ़ने और उसकी पूर्ति के घट जाने के कारण चाँदी की कीमतें निरन्तर बढ़ती गई और अन्त में ऐसी स्थिति आ गई कि १ शिलिंग ४ है पेंस प्रति रुपया के भाव पर भारत सचिव के लिए परिषद् विपत्र बेचना लाभदायक

१. प्रति परिषद् विपत्र इक्तेंड में स्टिलिंग में बेचे जाते थे। इनका उद्देश्य यह होता था कि स्टिलिंक में ऋगा प्राप्त करके विदेशो विनिमय बाजार में स्टिलिंक की मात्रा को बढ़ाया जाय, तािक स्टिलिंक की पूर्ति कम होने से रुपयों में उनकी कोमत बढ़ने न पाये। यह भारत सिचय की श्रोर से जारी किये हुये ऋगु-पत्र थे।

२. परिषद् विपन्न प्रति परिषद् विपन्न के विपरीत भारत में रुपयों के बदले में बेचे जाते थे, ताकि रुपयों की पूर्ति बढ़ाकर विनिमय बाजार में रुपये की कीमत को बढ़ने से रोका जाय।

मु०च०ग्र० (३०)

न रह सका। अगस्त सन् १६१६ तक चाँदी की कीमत बढ़ कर ४३ पैंस प्रति औंस हो गई और दिसम्बर सन् १६१६ में तो यह बढ़ते-बढ़ते ७६ पैंस प्रति औंस तक पहुँच गई। चाँदी की कीमतों की वृद्धि के साथ-साथ परिषद् विपत्रों की बिक्री दर भी बराबर बढ़ाई गई और दिसम्बर सन् १६१६ में वह १ शिलिंग ४ पैंस प्रति रुपया कर दी गई।

(६) उक्त स्थिति को सुघारने के लिए सरकार ने निम्न उपाय किये—
(म्र) निजी व्यक्तियों द्वारा चाँदी के ग्रायात बन्द कर दिये गये ग्रौर रुपये के सिक्कों की माँग को पूरा करने के लिए सरकार ने भारी मात्रा में चाँदी खरीदी। ग्रकेले ग्रमरीका से ही २० करोड़ ग्रौंस चाँदी खरीदी गई। (ब) इसी काल में भारत सरकार ने एक ग्रौर दो रुपए के नोट भी चालू किये तथा गिलट के ग्रौर ग्रधिक सिक्के ढाले, जिससे कि चाँदी के उपयोग में बचत की जा सके। नोटों को रुपयों में बदलने पर भी प्रतिबन्ध लगाये गये। (स) इस काल में जितने सोने का ग्रायात हुम्रा उसे सरकार ने खरीद लिया। इसके ग्राघार पर नोटों का प्रकाशन किया, जिससे नोटों के प्रचलन में भारी वृद्धि हुई। (द) युद्धकाल में स्वयं इङ्गलेंड ने भी स्वर्णमान का संचालन स्थानिक कर दिया था, जिसके कारण स्टर्लिङ्ग का भी स्वर्ण में सूल्य-ह्रास हो गया था, इसिलए परिषद विपत्रों की दर थोड़ी ग्रधिक ऊँची रखी गई, जिससे कि स्टर्लिङ्ग के इस मूल्य-ह्रास के लिये भी गुङ्डायश हो सके। इस प्रकार युद्धकालीन परिस्थितियों की गहरी चोट के कारण स्वर्ण-विनिमय मान पूर्णतया टूट गया।

## बैबिंगटन-स्मिथ समिति (The Babington-Smith Committee)—

सन् १६१६ में लड़ाई तो समाप्त हो गई, परन्तु युद्धकालीन किठनाइयां बराबर बनी रहीं । व्यापाराशेष की अनुकूलता भारत के लिए अभी तक भी काफी रहीं, यद्यपि युद्ध कार्यों के लिए भारतीय माल की मांग धर्ब शेष नहीं रही थी, परन्तु शान्ति स्थापना के परनात् यूरोप के युद्ध विघ्वंश देशों में भारतीय माल की मांग पर्याप्त मात्रा में अभी तक भी बनी रही । इस कारण चाँदी की कीमतें बराबर बढ़ती रहीं और नोटों को चाँदी में बदलना किठन हो गया । भारत सरकार ने ऐसा अनुभव किया कि सम्पूर्ण स्थित की जाँच करने के लिए एक और समिति नियुक्त की जाय, अतः मई सन् १६१६ में बैंबिगटन-स्मिथ की अध्यक्षता में एक नई समिति नियुक्त की गई, जिसे उसके अध्यक्ष के नाम के पीछे बैंबिगटन-स्मिथ समिति कहा जाता है ।

#### सुभाव-

इस समिति ने १ रुपया = २ शिलिंग की विनिमय दर को स्थापित करने का सुभाव दिया। समिति का विचार था कि स्वर्णों में रुपये की कीमत २ शिलिंग के बराबर रखने से कई प्रकार के लाभ होने की आशा थी:—

( ग्र ) चौदी की कीमर्ते ग्रभी कुछ ग्रौर वर्षों तक ऊँची ही रहने का ग्रनुमान लगाया गया था ग्रौर समिति का विचार था कि ऊँची दर नियत किये बिना रुपये की सांकेतिक प्रकृति को बनाये रखना सम्भव न था।

(व) समिति का यह भी विचार था कि एक ऊँची विनिमय दर इस कारए। भी उपयुक्त थी कि उसके द्वारा कीमतों की ऊपर उठने की प्रवृत्ति एक जायगी।

(स) गृह-लर्ची (Home Charges) में भी बनत हो जायगी।

(द) समिति का मत था कि इस नीति द्वारा भारतीय व्यापार के घटने का भय न था, क्योंकि संसार में कच्चे मालों और खाद्य पदार्थों की माँग बहुत प्रधिक

होने के कारण ऊँची विनिमय दर पर भी भारतीय निर्यातों की ग्रच्छी कीमत मिल सकेगी। इसके श्रतिरिक्त युद्धकालीन विनाश के कारण विदेशों में उत्पादन व्यय इतना ऊँचा बना रहेगा कि वे ऊँची विनिमय दर का कुछ भी लाभ नहीं उठा सर्कों। समिति

केपा बना रहना कि व केपा विनिमय दर का कुछ भी लाभ नहीं उठा सकेंगे। सिमिति ने यह भी सुभाव दिया कि विनिमय दरों के पतन की दशा में भारत सरकार को प्रति परिषद विपत्र बेचने चाहिए। सिमिति के स्त्रन्य सुभाव निम्न प्रकार थे:—
(१) सावरेन के बदले में रुपये देने की सरकारी जिम्मेदारी बन्द होनी

चाहिए।
(२) भारत में स्वर्ण के ग्रायात श्रौर निर्यात स्वतन्त्र होने चाहिए ग्रौर सरकारी नियन्त्रण का ग्रन्त होना चाहिए।

(३) स्वर्णं कोषों का श्रविक से श्रविक ग्रावा भाग भारत में रखा जाय श्रोर शेष ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रखा जाय।

(४) भारतीय पत्र-मुद्रा प्रणाली में लोच उत्पन्न करने के लिए देश में अनु-पातिक निधि प्रणाली ग्रहण की जाय।

( प्र ) पत्र-चलन का विश्वासाश्रित भाग कुल चलन के ६०% से **प्रधिक नहीं** रहना चाहिए।

(६) रुपये की विनिमय दर स्टर्लिङ्ग के स्थान पर स्वर्ण में नियत की जाय श्रीर भारत सरकार को भारत सचिव की श्राज्ञा के बिना भी प्रति परिषद् बिल जारी करने का श्रीवकार दिया जाय।

सर दादीबा दलाल, जो आयोग के एक मात्र भारतीय सदस्य थे, समिति के बहुमतीय विचारों से सहमत न थे। उन्होंने समिति के सामूहिक वृत्तलेख (Report) में अपने विरोधी विचार प्रकट किये, जिसमें उन्होंने भारत सचिव की चलन तथा विदेशी विनिमय नीति की कड़ी आलोचना की। उनका विचार था कि विनिमय दर

विदेशी विनिमय नीति की कड़ी ग्रालोचना की । उनका विचार या कि विनिमय दर स्वर्ण में १ शिलिंग ४ पेंस ही रहनी चाहिए थी और भारत में स्वर्ण विनिमय मान के स्थान पर पूर्ण स्वर्णमान स्थापित होना चाहिए था। उन्होंने बताया कि विनिमय दरों को ऊँचा उठाने का भारतीय व्यापार, उद्योग तथा समस्त ग्राथिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने का भय था।

(१) समिति की बहुमतीय सिफारिशें भारत सचिव ने स्वीकार कर लीं धौर श्री दलाल के विरोध पर ध्यान नहीं दिया गया।

- (२) सन् १६२० के भारतीय मुद्रण (संशोधन) एक्ट के स्रनुसार भारत ्र सावरेन को १०) की दर पर विधि-प्राह्म घोषित कर दिया गया।
- (३) परन्तु समिति की रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही लन्दन को विषेष भेवने की माँग एक दम बढ़ गई। भारत सरकार ने विनिमय दर को १ रुपया = २ शितिंग पर बनाए रखने का प्रयत्न किया, परन्तु इससे सरकार को भारी हानि हुई ग्रौर प्रयत्न सफल न हो सका।
- (४) ब्रिटिश सरकार ने डालर और स्टॉलिंग की विनिमय दर पर से नियन्त्रण उठा लिया और क्योंकि बाजार में चाँदी की कीमत २ शिलिंग सोने से अधिक थी, सरकार ने बाजारी दर पर प्रति परिषद विपन्न बेच कर विनिमय दर को स्थिर रखने का प्रयत्न किया. परन्तु सट्टें के विकास तथा सरकारी और वास्तविक दर के अन्तर के कारण प्रति परिषद विपन्नों की माँग इतनी अधिक हो गई कि उनकी सरकारी तथा बाजारी दर में भारी अन्तर हो गया। इसके कारण मुद्रा बाजार में अत्यधिक उथव-पुथल होने लगी।
- (५) भारतीय आयात व्यापारियों ने विदेशों से माल मँगाने के भारी आदेश भेजे, जिससे प्रति परिषद विपत्रों की माँग और भी बढ़ गई।
- (६) निर्यात व्यापार का मारी संकुवन हुपा और भारत का व्यापारा के प्रतिकृत हो गया। इसके कारण तुरन्त हो विनिमय दरें नीचे गिर गई और जून सन् १६२० के अन्त तक वे १ शिलिंग = पैंस पर आ गईं। कुछ समय तक भारत सरकार ने विनिमय दर को २ शिलिंग (स्टिलिंग) पर बनाये रखने का प्रयत्न किया, परन्तु इससे सरकारों कोषागार को और भी हानि हुई। भारतीय जनता की ओर हे इस प्रकार देश के साधनों का अपव्यय करने के विषद्ध काफी अन्दोलन किया गया। भारत सरकार भी ५ करोड़ पौंड की कीमत के प्रति परिषद विपन्न बेच चुकी थी, परन्तु विनिमय दर स्थिर नहीं हो सकी थी। भारत सरकार ने विनिमय दर को ऊपर चढ़ाने के लिए मुद्रा-संकुचन का भी प्रयत्न किया, परन्तु यह प्रयोग भी असफत रहा। जब सभी प्रयत्न असफत रहे तो सरकार ने विनिमय दर के नियन्त्रण की नीति ही छोड़ दी और उसका स्वतन्त्र निर्धारण होने दिया। जून सन् १६२० तक विनिमय दर गिर कर १ शिलिंग ५ पैंस रह गई।
- (७) वैधानिक दृष्टिकोण से तो विनिमय दर २ शिलिंग ही बनी रही, परनु सितम्बर सन् १६२० के परचात् यह वैद्यानिक दर कभी भी सप्रभाविक न रह सकी। सन् १६२३ से परिस्थितियों ने दूसरा ही रुख पलटा और विनिमय दर बढ़ कर १ शिलिंग ४ पेंस (स्टिलिङ्ग) हो गई। ग्रन्टूबर सन् १६२४ में यह बढ़ कर १ शिलिंग ६ पेंस (स्टिलिङ्ग) अथवा १ शिलिंग ४ पेंस (स्वर्ण) हो गई। इस काल से मार्च सन् १६२६ तक विनिमय दर ऊपर को ही चढ़ती रही। इसी बीच में सन् १६२४ में इङ्ग्लैंग्ड ने स्वर्णमान ग्रहुण करके स्टिलिङ्ग और स्वर्ण की कीमतों में

समानता उत्पन्न कर दी थी और तब से रुपये की कीमत निरन्तर १ शिलिंग ६ पैंस के मास-पास ही बनी रहीं। संसार की म्राथिक दशाओं में भी मिन निरिचतता और स्थिरता उत्पन्न हो गई। वास्तविकता यह है कि सन् १६१६ और सन् १६२५ के बीच का काल समायोजन का काल था। इस काल में युद्धकालीन वैभव का मन्त होने के परचात् मन्दी का म्राना म्रावश्यक था भीर म्रान्त में म्राथिक जीवन ी सामान्यता एक एक बार फिर स्थापित हो गई। भारत सरकार ने बहुत समभ से काम नहीं लिया था और उसकी मौद्रिक नीति के कारण देश को म्राधिक हानि हुई थी।

वास्तव में भारत सरकार ने जरूदी में वैबिंगटन स्मिथ-समिति की सिफा-रिशों को स्वीकार करने में भारी भूल की थी। जिस समय समिति की किकारिशों को कार्य-रूप दिया गया था, संसार की त्रार्थिक त्रोर राजनैतिक परिस्थितियाँ बहुत ही त्रिनिश्चित थीं। सरकारी नीति के फलस्वरूप व्यापारी तथा व्यवसायी वर्ग को भारी हानि हुई। "एक ऐसी नीति ने, जिसका उद्देश विनिमय दरों की स्थिरता थी, एक ग्रारोग्य ग्रर्थ-व्यवस्था में विनिमय दरों के भारी उचावचन उत्पन्न कर दिये, व्यापार में उथल-पुथल पैदा की, सरकार को भारी ग्राधिक हानि पहुँचाई ग्रीर सैकड़ों बड़े बड़े व्यापारियों का दिवाला निकाल दिया।"

# QUESTIONS Questions

- Give an account of the working of Gold Exchange Standard in India. (Agra, B. Com, 1950)
- 2. Describe briefly the history of Indian Currency from the closing of the mint till 1914. (Agra, B. Com., 1949)
- 3. Describe the main features of the Gold Exchange Standard. Trace the circumstances that led to its adoption. Indicate the causes of its break down during the first World War.

(Raj., B. Com., 1952)

4. Examine critically the working of the Gold Exchange Standard in India before the first World War-

(Agra, B. Com., 1957)

5. Give a critical estimate of the findings of the Fowler Committee. (Sagar, B. Com., 1950)

#### अध्याय २८

# भारतीय चलन का इतिहास (क्रमशः)

( सन् १६२५-३६ )

(The History of Indian Currency Contd.)

#### प्रारम्भिक-

प्रथम महायुद्ध के बाद का काल अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारी आर्थिक अस्थिरता और अनिश्चितता का काल था। वह संक्रान्ति काल (Transitional Period) था, जिसमें युद्ध-कालीन अर्थ-व्यवस्था शान्ति-कालीन अर्थ-व्यवस्था में बदल रही थी। संसार की आर्थिक दशाओं के विषय में किसी भी प्रकार का निश्चित अनुमान सम्भव न था। इस कारण भारत सरकार ने २ शिलिंग प्रति क्यया की विनिमय दर स्थिगत करके अच्छा ही किया था। रुपए को अपनी सही विनिमय दर हुँ ढ़ने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया गया। साथ ही, युद्ध-काल में स्टिलिंग का स्वर्ण सम्बन्ध हुट गया था और इक्कलेंड हारा मुद्रा-विस्तार के कारण स्टिलिंग की कीमत गिर गई थी। सन् १६२१ के अन्त तक इक्कलेंड ने स्वर्णमान फिर प्रह्णा कर लिया था। इसके कारण रुपए की कीमत स्टिलिंग तथा स्वर्ण दोनों में समान ही हो गई, प्रर्थात् १ शिलिंग ६ पेंस के बराबर हो गई थी। संसार की आर्थिक दशाओं में भी स्थिरता आ गई थी। संक्रान्ति-काल समाप्त हो चुका था और युद्धोत्तर कालीन उद्धार (Recovery) ने काफी उन्नति कर ली थी। भारत सरकार ने भी ऐसा अनुभव किया कि ऐसी दशा में रुपये की नई स्थिति के निर्धारण की आवश्यकता थी।

## हिल्टन-यङ्ग श्रायोग (The Hilton-Young Commission)—

सन् १६२५ के ग्रन्तिम काल में श्री हिल्टन-यंग की ग्रध्यक्षता में एक नया शाही भ्रायोग नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य:—"भारतीय चलन भ्रौर विनिमय प्रगाली तथा व्यवहार की जांच करना भ्रौर उस पर भ्रपना मत प्रकट करना था।" भ्रायोग ने सम्पूर्ण मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय प्रगाली की विस्तृत जांच करके जुनाई सन् १६२६ में भ्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह एक बहुमतीय रिपोर्ट थी, क्योंकि भ्रायोग के एक मात्र भारतीय सदस्य श्रा पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास इससे सहमत न थे। स्पिर्ट की प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार थीं:—

(१) त्र्रब तक भारत सरकार जिस स्वर्ण-विनिमय-मान को चला रही थी वह समाप्त होना चाहिए त्र्रौर चलन के प्रति जनता का विश्वास प्राप्त करने के खिये मुद्रा का स्वर्ण से ऐसा सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए जो वास्तविक त्र्रौर

प्रहश्य (Visible) हो । इस उद्देश्य से स्वर्ण पाटमान को यहरण करना उपयुक्त होगा । इस मान की विशेषताएँ निम्न प्रकार होती हैं :—

- ( ग्र ) सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता है।
- ( ब ) मुद्रा सं वालक का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह नियत कीमतों पर असीमित मात्रा में सोना खरीदे और बेचे ।
- (स) सरकार प्रत्येक व्यक्ति को अपरिमित मात्रा में नोटों के बदले में सोना देने की गारन्टी देती है।
- (द) इस सम्बन्ध में कोई भी शर्त नहीं लगाई जाती है कि मुद्रा-संचालक से सोना किस उद्देश्य के लिए खरोदा जायगा।
- (२) रुपए तथा स्टर्लिङ्ग ऋथवा रुपये ऋौर स्वर्ण की विनिमय दर को ? शिलिंग ६ पैंस पर स्थिर रहना चाहिए।
- (२) भारत में एक केन्द्रीय वैंक की स्थापना होनी चाहिए, जिसका प्रमुख कार्य देश में चलन और साख पर नियन्त्रण रखना हो तथा जो रुपए की विदेशी विनिमय दर का भी प्रवन्त्र करे। इस बैंक के कार्य निम्न होंगे:—
  - ( प्र ) इसे २५ वर्ष के लिए नोट निर्गमन का एकाधिकार होगा।
  - ( ब ) बैंक के द्वारा निकाले हुए नोट अपरिमित विवि-प्राह्म होंगे और उन पर भारत सरकार की गारन्टी होगी।
  - (स) वर्तमान नोट तो रुपयों में परिवर्तनीय रहेंगे लेकिन जनता को आगे के लिए नए नोटों के बदले में रुपये के सिक्के प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार त होगा। इसके विपरीत मुद्रा-संचालक के रूप में केस्द्रीय वैंक का यह कर्त्तंव्य होगा कि वह नोटों को विधि-ग्राह्म मुद्रा सर्थात् छोटी की मतों के नोटों और रुपयों के सिक्कों में बदल दे।
- (४) श्रब तक स्वर्णमान निधि तथा पत्र-चलन निधि को श्रलग-श्रलग रखने की जो प्रथा थी वह समाप्त की जाय श्रीर इन दोनों कोषों को मिला कर एक कर दिया जाय। इस निधि में स्वर्ण तथा स्वर्ण प्रतिभूतियाँ ४०% से कम नहीं हों और बाकी ६०% भारत सरकार की रुपये प्रतिभृतियों में तथा व्यापारिक बिलों में होना चाहिए।
- (५) भारत सरकार द्वारा एक रूएये के जो नोट निकाले गये थे उनका केन्द्रीय बैंक ऋर्थात् रिजर्व बैंक द्वारा पुनः निर्गमन होना चाहिए।
- (६) देश में निश्चित असुरक्षित नोट निर्गम प्रणाली (Fixed Fiduciary System) के स्थान पर आनुपातिक पद्धति (Proportional Reserve System) अपनाने की सिफारिश की थी।

ये भ्रायोग के बहुमत की सिफारिशें थीं। श्री पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, जो भ्रायोग के एक सदस्य थे, इनसे सहमत नहीं थे। उनका विरोध दो बातों के विषय में था:—(१) उनका मत था कि देश में खण्डवान स्वर्णं विनिमय-मान के स्थान पर पूर्णं स्वर्णमान स्थापित किया जाय, जिसमें सोने के सिक्के प्रचनन में हों। (२) वे चाहते थे कि विनिमय दर १ शिलिंग ६ पैंस के स्थान पर १ शिलिंग ४ पैंस होनी चाहिये। उनका तक इस बात पर आधारित था कि १ शिलिंग ६ पैंस की विनिमय दर प्रवास्तविक थी, क्योंकि यह उस सम्पन्नता के कारण स्थापित हुई थी जो एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में लगातार चार अच्छी फसलों के होने से उत्पन्न हो गई थी, परन्तु यह सम्पन्नता बहुत समय तक बनी नहीं रह सकती थी। यह फसलें अच्छी न हुई तो रुपये का अतिमूल्यन होने का भय था, जिसका भारत पर बुरा प्रभाव पड़ना आवश्यक था। श्री ठाकुरदास का यह भी मत था कि क्योंकि आयोग की सुमाई हुई दर वास्तविक न थी, देश के उद्योगों को उसके अनुसार समायोजन करना आवश्यक था और यह कार्यं काफी दुखदाई तथा कठिन होता है। ऊँची दर के कारण विदेशी स्पर्धा के बढ़ने और देश के उद्योग-धन्धे ठप्प हो जाने, बेरोजगारी फैनने और देश के सोने का निर्यात होने का भी भय था।

श्रायोग के बहुमतीय सुफाव भारतीय घारा-सभा ने स्वीकार कर लिए श्रीर मार्च सन् १६२७ में करेंसी बिल पास कर दिया गया। इस बिल ने विनिमय दर को १ शिलिंग ६ पेंस नियत किया। इसने भारत सरकार का यह भी उत्तरदायिहा रखा कि वह प्रत्येक बेचने वाले से २१ हपया ७ श्राना १० पाई प्रति तोला की दर से सोना खरीदे श्रीर इसी प्रकार ४०-४० तोले की छड़ों में प्रत्येक खरीदने वाले को सोना बेचे। सोना बेचने के बदले में सरकार ऐसा भी कर सकती थी कि विदेशी व्यापार के लिए १ शिलिंग ६ पेंस की दर पर विदेशी विनिमय प्रदान कर दे। साथ ही साथ सावरेन तथा श्रद्ध-सावरेन का, जिन्हें पहले विधि-प्राह्म घोषित किया था, विमुद्रीकरण (Demonetisation) कर दिया गया। इस प्रकार श्रारम्भ में भारत सरकार ने श्रायोग के सुमावों को केवल विनिमय दर तथा स्वर्ण-पाटमान के सम्बन्ध में ही स्वीकार किया। रिजर्व बेंक की स्थापना के प्रश्न को कुछ समय के लिए स्थिगित कर दिया गया।

# विनिमय दर सम्बन्धी वाद-विवाद—

विनिमय दर के प्रश्न ने एक लम्बे वाद-विवाद को जन्म दिया। यह वाद-विवाद ग्रायोग की सिफारिशों के प्रकाशित होते ही ग्रारम्भ हो गया था ग्रौर दूसरे महायुद्ध के बाद तक भी चलता रहा था। सन् १६२७ में भारत सरकार के वित्त-सदस्य सर बासिल ब्लैकेट (Sir Basil Blackett) ने १ शिलिंग ६ पैंस की विनिमय दर के पद्म में निम्न तर्क रखे थे:—

(१) यह कि इस दर पर रुपया पिछले दो वर्षों से स्थिर था, जिससे स्पष्ट था कि यही प्राकृतिक दर थी, जो भारत तथा संसार की आर्थिक दशाओं के समायोजन ने उत्पन्न की थी।

- (२) यह कि कीमतों, उत्पादन व्यय और लगभग सारी ही धर्थ व्यवस्था का इस दर से समायोजन हो चुका था। इन कारण इसमें परिवर्तन करने की दशा में फिर से समायोजन की धावश्यकता पड़ेगी, जिससे उद्योग और व्यवतायों को कठिनाई होगी।
- (३) यह कि केन्द्रीय और प्रान्तीय (राज्य) बजट इस दर के आघार पर पहले से ही बनाये जा चुके थे। दर को बदलने का ग्रथं था कि बजटों का सन्तुलन भंग हो तथा बजटों के घाटों को पूरा करने के लिए और ग्रिषक करारोपण की ग्रावश्यकता पड़े।
- (४) यह कि यदि १ शिलिंग ४ मेंस की दर स्वीकार की गई तो दूसरे देशों की तुलना में भारत में कीमतें नीची हो जायेंगी, जिन्हें ऊपर उठाने के लिए मुद्रा-प्रसार आवश्यक हो जायगा।
- (५) यह कि क्योंकि १ शिलिंग ४ पेंस की दर कृत्रिम होगी, इसका बनाये रखना केवल मुद्रा-प्रसार द्वारा हो सम्भव होगा, जिससे श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी घटेगी और श्रौद्योगिक श्रशान्ति फैलेगी।

सरकारी दृष्टिकोणा के विरुद्ध गैर-सरकारी वर्गों ने भी बहुत से तर्क रखे । इनमें से मुख्य-मुख्य निम्न प्रकार हैं :—

- (१) यह कि पिछले २० वर्षों से रुपए की कीमत १ शिलिंग ४ पैंस पर बनी हुई थी।
- (२) यह कि भारत में सन् १६२६ तथा सन् १६१४ के तुलनात्मक कीमत-स्तर समान ही थे। इससे स्पष्ट था कि सन् १६२७ में भी सन् १६१४ की भाँति विनिमय दर १ शिलिंग ४ पेंस ही रहनी चाहिए।
- (३) १ शिलिंग ६ पैंस की दर कृत्रिम थी और पिछले २ वर्षों की चार अच्छी फसलों पर ग्राघारित थी ग्रीर कीमतों, उत्पादन व्यय तथा ग्राधिक जीवन का ग्रभी तक इसी दर से समायोजन नहीं हो पाया था।
- (४) इस नीति का परिएगन यह होगा कि सरकार ने विवेचनात्मक उद्योग संरक्षण (Discriminating Protection) की जो नीति अपनाई है उसका आर्थिक जीवन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ पायेगा, क्योंकि ऊँची विनिमय दर एक प्रकार विदेशी उद्योगपितयों के लिए आर्थिक सहायता होगी, अतः विदेशी स्पर्घा के कारण देश के उद्योग नष्ट हो जायेंगे।
- (५) क्योंकि भारतीय निर्यातों की कीमत उसके आयातों की कीमत से अधिक थी, ऊँची दर के प्रहण करने से यह स्थिति बदल जायगी और देश को हानि होगी।

- (६) १ शिलिंग ६ पैंस की नई दर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मुद्रा-संकुचन की ग्रावश्यकता पड़ेगी, जिसके कारण मजदूरी, उत्पादन तथा ग्राधिक उन्नति का वेग कम हो जायगा।
- (७) संसार में सोने की कीमतों के नीचे गिरने की सम्भावना के कारण १ शिलिंग ६ पैंस की दर को बनाए रखना कठिन होगा।
- ( प ) इस बात का अधिक भय था कि इस दर को केवल स्वर्ण का निर्यात करके ही स्थिर किया जा सकता था और इस प्रकार देश के स्वर्ण कोषों में भारी कमी की आशंका थी।
- ( ६ ) ऊँ वी विनिमय दर का अभिप्राय एक प्रकार का अहरय मुद्रा-प्रसार होता है, जो परोक्ष और अहरय करारोपण होगा।

जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि सरकार ने गैरे-सरकारी दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं दिया और मार्च सन् १६२७ में ही एक बिल के द्वारा १ शिलिंग ६ पैंस विनिमय दर को लागू कर दिया। तब से दिखाने को तो यह दर स्थिर रहीं थी, परन्तु वास्तव में इसे बनाये रखने के लिए अधिक मान्ना में मुद्रा-संकुचन किया गया था और मुद्रा-बाजार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। दर को बनाये रखने के लिए भारत सरकार को स्टलिंक ऋएण भी लेना पड़ा था।

# भारत में स्वर्ण-पाट-मान ( सन् १९२७ से सन् १९३१ तक )

हिल्टन-यङ्ग श्रायोग ने भारत के सम्बन्ध में लगभग सभी मौद्रिक मानों की जाँच की थी। श्रायोग को स्वर्ण-विनिमय-मान, स्टर्लिङ्ग-विनिमय-मान, स्वर्ण-मान मुख्य तथा स्वर्ण-पाट-मान में से किसी एक को चुनना था। सभी मानों के गुर्ण और दोषों की जाँच करने के पश्चात् आयोग ने स्वर्ण-पाट-मान के प्रहर्ण करने का सुमाव दिया था।

स्वर्ण-विनिमय-मान के सम्बन्ध में आयोग का विचार था कि यद्यपि यह मान स्वर्ण में रुपये की कीमत की स्थिरता ला सकता था, परन्तु इसमें कई गम्भीर दोष थे:—

- ( i ) इसकी कार्य-विधि जटिल थी ग्रौर जन-साधारण की समफ से परे थी।
- (ii) इस प्रणाली में मुद्रा का विस्तार तथा संकुचन मौद्रिक कारणों द्वारा स्वयं ही नहीं हो जाता था, उसे परिषद् तथा प्रति परिषद् विपन्नों के क्रय-विक्रय द्वारा घटाया जाता था।
- (iii) इस प्रणालों में लोच का ग्रमाव था और यह विनिमय दरों के लिए प्राकृतिक सुघारक (Curatives) उपलब्ध नहीं करती थी।
- (iv) इस प्रणाली में मुद्रा और साख के नियन्त्रण की विभाजित जिम्मेदारी थी, जिससे यह कार्य ठीक प्रकार से नहीं होने पाता था।

- ( v ) रिजर्व किसी एक जगह न रखा जाने से यह प्रगाली व्ययपूर्ण ग्रीर श्रदूरदर्शी थी। यद्यपि इस प्रगाली में सोने का उपयोग कुछ मितव्ययिता के साथ होता था तथापि फिर भी बहुत सा सोना व्यर्थ वैवा पड़ा रहता था।
  - ( vi ) यह प्रणाली रुपये के मूल्य में स्थिरता लाने में ग्रसफल रही है।
- ( vii ) यह प्रसाली इङ्गलैण्ड पर निर्भर है, जिससे उस देश के परिवर्तनों का प्रभाव भारत पर भी पड़ता था।

इसी प्रकार शायोग ने स्टर्लिङ्ग-विनिमय की भी जाँच की, परन्तु श्रायोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह भी देश के लिये उपयुक्त नहीं है। उस प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा श्रविकारी रुपयों को स्टर्लिङ्क के बदले बेचते हैं और स्टर्लिङ्क को रुपयों के बदले खरीदते-बेचते हैं। इस तरह इसमें स्वर्ण विनिमय मान के तो सब दोष विद्यमान हैं ही किन्तु साथ में यह प्रणाली इङ्गलैण्ड की मुद्रा-प्रणाली पर अपेक्षतः अधिक निर्भर थी, जिससे यह भारत के लिये श्रविक हानिकारक प्रनाणित हो सकती है।

स्वर्णमान मुस्य के विरुद्ध आयोग ने दो तर्क रखे थे:—(i) यह कि भारत के लिए इसके संचालन हेनु पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण प्राप्त करना लगभग असम्भव था। (ii) इसमें यह भय था कि स्वर्ण में चांदी को कीमतें गिरेंगी, जिसके कारण भारतवासियों को भारी हानि होगी, क्योंकि उनके रजत कोषों को कीमत रखे रखे गिर जायगी।

इन सभी कारणों से ब्रायोग ने स्वर्ण-पाट-मान की स्थापना का सुक्राव दिया।
यहाँ पर यह कहना ब्रसंगत न होगा कि यद्यपि हिल्टन-यङ्ग ब्रायोग ने स्वर्ण-विनिमयमान को समाप्त करने ब्रौर भारतीय रुपये का प्रत्यक्ष रूप में स्वर्ण से सम्बन्ध स्थापित
करने का सुक्राव दिया था, परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं किया गया था। ब्रब भी
रुपये का सम्बन्ध विदेशी मुद्राब्रों से स्वर्ण के स्थान पर स्टिलङ्ग के माध्यम से ही बना
रहा था। यहाँ तक कि जब स्टिलङ्ग का स्वर्ण में ब्रबम्लयन भी हो गया तो रुपए
ब्रौर स्टिलङ्ग की विनिमय दर ज्यों की त्यों बनी रही। चू कि वास्तव में कमीशन की
सिफारिशों के ब्रनुसार जनता को सोना तो नहीं मिला वरन स्वर्ण मिलना या स्टिलङ्ग
मिलना सरकार की मर्जी पर निर्भर था, इसिलये इसे स्वर्ण-पाट-मान न कह कर
स्टिलङ्ग विनिमय मान कहना ब्रधिक उपयुक्त न होगा। इस प्रकार जिस स्टिलङ्ग
विनिमय मान को दोषयुक्त बता कर कमीशन ने रद्द कर दिया था उसी को दूसरे शब्दों
में अपनाया गया।

प्रत्यच्च स्टर्लिंग विनिमय मान ( सन् १९३१ से सन् १९४७ तक )

भारत में स्टर्लिङ्ग विनिमय-मान की प्रत्यक्त रूप से स्थापना-

सन् १९२७ ग्रौर पन् १९२८ के वर्ष भारत तथा ग्रन्य देशों के लिए **ग्रायिक** 

स्थिरता भीर सन्तूलन के वर्ष थे. परन्तु सन् १९२६ के म्रन्तिम महीनों में विश्वव्यापी अवसाद (Depression) आरम्भ हुआ। इस मन्दी का सबसे बूरा प्रभाव कृषक देशों पर पड़ा। भारत में इसके दृष्परिगाम सन् १९३० में प्रथम बार दृष्टिगोचर हुए। भारतीय निर्यातों में कमी होने लगी और उसके व्यापाराशेष की ग्रनकलता घटने लगी। इस नारण विनिमय दर की स्थिरता को बनाये रखना कठिन हो गया। सन् १६३३ के मध्यकाल तक युरोप के देशों की आर्थिक अवस्थाएँ अधिक विगढ गई थीं। जिन विदेशियों ने भारतीय कोषागार विपन्नों में अपना रुपया लगा रखा था उन्होंने उसे वापस लेना आरम्भ कर दिया। इसके कारएा भारत में विदेशी महाधों की माँग काफी बढ गई और इसके विपरीत विदेशी विनिमय बाजारों में रुपये की माँग में कमी आ गई। परिस्थितियों के रूप में २१ सितम्बर सन् १६३१ के पश्चात जबिक इङ्गलैण्ड ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया, ग्रीर भी परिवर्तन हो गया। २२ सितम्बर सन् १९३१ को भारत सरकार ने सन् १९२७ के करेन्सी एक्ट के कार्यवाहन को स्थगित कर दिया, परन्तु इसके तीन ही दिन परचात् अर्थात् २५ सितम्बर सन १६३१ को रुपये का स्टर्लिङ्ग से सम्बन्ध पुनः स्थापित कर दिया गया। भारतीय रुपये की स्वर्णों में परिवर्तनशीलता समाप्त कर दी गई. क्योंकि स्टर्लिङ्क का अब स्वर्ण से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा था। भारत का मौद्रिक मान स्वर्ग-पाट-मान तो क्या स्वर्ण-विनिमय-मान भी न रह सका। रुपये की केवल स्टर्लिङ में ही परिवर्तनशीलता रखी गई थी. इसलिए हमारा मौद्रिक मान केवल स्टलिङ्ग विनिमय-मान ही रह गया।

रुपये का स्टर्लिंग से जो सम्बन्ध जोड़ा गया था उसके पक्ष-विपक्ष में इस प्रकार तर्क दिये गये थे:—

### पत्त में---

- (i) इससे विनिमय दर में बहुत घट-बढ़ न हो पावेगी, जिससे विदेशी ब्यापार को लाभ पहुँचेगा :
- (ii) इङ्गलैंड में स्वर्णमान टूट गया था और स्टर्लिंग का अन्य स्वर्णमान वाले देशों की मुद्राओं के सम्बन्ध में अवमूल्यन हो गया था। यदि रुपये का स्टर्लिंग से सम्बन्ध रखा गया, तो रुपये का अवमूल्यन भी करना पड़ेगा, जिससे विदेशी व्यापार को लाभ होगा; तथा
- (iii) भारत को प्रति वर्ष इङ्गलैंड एक बड़ी राशि गृह खर्चों के रूप में भेजनी पड़ती है। इस हिंछ से भी रुपये ग्रीर स्टर्लिंग का गठबन्धन लाभप्रद रहेगा। विपद्ध में—
- (i) इस गठबन्धन से भारत सदा के लिए राजनैतिक दासता के साथ-साथ आर्थिक पराधीनता में भी फैंस जायगा, क्योंकि स्टॉलग के मूल्य के परिवर्तनों के साथ-साथ रुपये के मूल्य में भी परिवर्तन हुआ करेंगे।

- (ii) स्वर्णमान देशों से म्रायात का हमें म्राधिक पूर्य चुकाना पड़ेगा, क्योंकि स्टालिंग का २०% म्रवपूर्वन हो गया है।
- (iii) इस गठवन्यन के कारण राये का स्वर्ण मूल्य कम हो जायेगा, जिससे भारत से स्वर्ण का भारी मात्रा में निर्यात होने लगेगा। ऐसा ही वास्तव में हुआ भी।
- (iv) यह गठवन्घन हिल्टन यंग कमीशन की निकारिशों के विरुद्ध था। कमीशन रुपये को किसी भी विदेशी मुद्रा से गठवन्घत करने के पक्ष में न था।

सन् १६२१ और सन् १६२६ के मध्य मुद्रा प्रशाली के च्रेत्र में जो ऋन्य घटनायें हुई वे संचोप में इस प्रकार हैं :—

- (१) विनिमय नियन्त्रग् स्वर्गमान के स्थिगत करने का तत्काल परिगाम यह हुआ कि स्वर्ग में स्टिलिंग की कीमत घटने लगी और साथ ही साथ भारतीय रुपये का स्वर्ग मूल्य भी तेजी के साथ गिरने लगा। इस मूल्य पतन को रोकने के लिए भारत सरकार ने िनिमय नियन्त्रण लागू कर दिया। इसका परिगाम यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति भारत के साथ विदेशी विनिमय व्यवसाय केवल भारत सरकार द्वारा ही कर सकता था। भारत में विनिमय-नियन्त्रण का प्रमुख उद्देश विनिमय दरों में होने वाले सट्टे को रोकना था, परन्तु अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि विनिमय नियन्त्रण अनावश्यक था और इसलिए जनवरी सन् १६३२ के अन्त तक इसे समाप्त कर दिया गया। वास्तविकता यह है कि सितम्बर सन १६३१ और मार्च सन् १६३० के बीच रुपया स्टिलिंग विनिमय दर में साधारणतया काफी स्थिरता रही थी। केवल सन् १६३० में कुछ उथल-पुथल हुई थी। अन्त में सन् १६३६ में दूसरे महायुद्ध के आरम्भ हो जाने पर भारत सरकार ने देश में कड़ा विनिमय नियन्त्रण लागू कर दिया, जिसके फलस्वरूप देश में भारी मुद्रा-प्रसार के फैलने पर भी विनिमय दर की स्थिरता बराबर बनी रही।
- (२) स्वर्गा-निर्यात—इसका अर्थ यह नहीं है कि सन् १६३८ तक विनिमय दर की स्थिरता का कारण यह था कि १ शिलिंग ६ पैंस की विनिमय दर समुचित तथा वास्तविक थी। यथार्थ में सन् १६३१ और सन् १६३८ के बीच के काल में इस विनिमय दर को ग्रहण करने की बुद्धिहीनता पूर्ण रूप से स्पष्ट हुई थी। इस स्थिरता का प्रमुख कारण यह था कि भारत बरावर भारी मात्राओं में सोने का निर्यात कर रहा था, क्योंकि:—
- (i) महान् श्रवसाद (The Great Depression) के काल में हमारे व्यापाराशेष की श्रनुकूलता पहले ही कम हो गई थी। केवल इसी के कारएा विनिमय दरों की स्थिरता को बनाये रखना कठिन हो सकता था, यदि वस्तुश्रों के निर्यात की कमी स्वर्ण निर्यात द्वारा पूरी न की जाती;
- (ii) सन् १६३१ के मध्य में सोने का भाव २१ रुपये १३ आर्ने ३ पाई प्रति तोला था, जो उसी वर्ष के अन्त तक २६ रुपए २ आने हो गया था। सोने की

कीमतों के बढ़ने के कारण लोगों ने उसे संचित कोषों तथा जेवरात में से निकाल कर बेचना ग्रारम्भ कर दिया ;

(iii) इसके श्रितिरक्त श्रवसाद के काल में कीमतों के गिरने के कारण देश में उत्पादकों श्रीर व्यापारियों को काफी हानि हुई थी श्रीर उनके पास पैसे की कमी थी। इस कमी को उन्होंने भी सोना बेच कर पूरा करने का प्रयत्न किया। सितम्बर सन् १६३१ श्रीर दिसम्बर सन् १६३२ के बीच लगभग ५० करोड़ रुपये का सोना देश से बाहर भेजा गया। सन् १६३५ में सोने का भाव ३५ रुपये प्रति तोला हो गया श्रीर सोने का निर्यात ग्रीर भी बढ़ा। सन् १६३८ के मध्य तक लगभग ३५० करोड़ रुपये का सोना भारत से बाहर चला गया था। इस प्रकार विदेशी सरकार की घृणित तथा बुद्धिहीन नीति के कारण भारतीय जनता की युगों की कमाई कुछ ही वर्षों में समात हो गई।

यह ऐसा समय था जबिक संसार का प्रत्येक देश सोने का संचय करने में लगा हुआ था, परन्तु भारत सरकार सोने का निर्यात करके ही प्रसन्न थी। भारतीय जनता की सोने के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की प्रार्थना ठुकराई जाती थी और उत्तर में यह कहा जाता था कि (i) सोने का निर्यात इसलिए हो रहा था कि एक और तो भारतवासियों के पास सोना बहुत था और दूसरी और उन्हें उसकी भ्रच्छी कीमत मिल रही थी; (ii) स्वर्ण निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देने से कुषकों को बहुत किनाई उठानी पड़ती, क्योंकि स्वर्ण बेच कर ही वे ग्रपने सङ्कृट के दिनों का सामना कर सके; (iii) देश से जितना सोना बाहर गया, स्टर्लिंग की पूर्ति में उतनी ही वृद्धि हो गई, जिससे देश ग्रपने स्ट्रिंग दायिस्थों को सरलता से चुका सका; (iv) स्वर्ण के निर्यात द्वारा भारतीय विदेशों से ग्रधिक वस्तुएँ खरीदने में समर्थ हो गया और इस प्रकार देश का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पहले से काफी बढ़ गया; (v) स्वर्ण को बेच कर लोगों ने अपना संचित घन व्यापार में लगाया, जिससे देश का ग्रार्थिक विकास हुआ।

इस काल में भारत सरकार ने सोने को स्वयं खरीदने का काम भी नहीं किया, क्योंकि इसका वैद्यानिक मूल्य २१ रु० ३ ग्राने १० पा० था, जबिक बाजार मूल्य बढ़ता ही जा रहा था। सरकार इस ग्रन्तर के ग्राधार पर सोना स्वयं खरीद कर 'सट्टा' करने को तैयार न थी। स्वर्ण-पाट-मान तथा १ शिलिंग ६ पेंस की विनिमय दर ने, जिसे हमने स्थिर रखने का प्रयत्न किया था, हमें कितने मुन्दर फल प्रदान किये थे।

स्वर्ण-निर्यात के विरोध में जन-नेताओं के तर्क इस प्रकार थे:—(i) स्वर्ण के निर्यात से देश के स्वर्ण साधनों का लाभहीन प्रयोग हुआ ; (ii) युगों की कमाई बाहर चली गई, जिससे स्वर्णमान अपनाना असम्भव हो गया ; तथा (iii) अन्य देश स्वर्ण का आयात करके अपने स्वर्ण साधनों को मजबूत बना रहे थे, किन्तु भारत उन्हें कमजोर बना रहा था।

- (३) रिजर्व बैंक की स्थापना—हिल्टन-यङ्ग म्रायोग की एक सिफारिश रिजर्व बैंक की स्थापना के सम्बन्ध में थी, जिसे केन्द्रीय बैंक का रूप देने का सुमाव दिया गया था। सन् १६२७ में इसकी स्थापना को स्थगित कर दिया गया था, परन्तु केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति (सन् १६३१) ने फिर इसकी स्थापना पर जोर दिया, मतः ६ म्रगस्त सन् १६३४ को भारत सरकार ने रिजर्व बैंक म्रांफ इंज्डिया एक्ट पास किया, जिसके अनुसार १ भ्रप्रेल सन् १६३४ को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इस बैंक की स्थापना से भारतीय चलन प्रगाली में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए:— (i) नोटों की निकासो का एकाधिकार इसी बैंक को प्रदान किया गया; (ii) पहली बार भारतीय चलन पद्धित, साख नियन्त्रण एवं मुद्रा संचालन सभी कार्य एक ही मौद्रिक संस्था कौ सौपे गये; (iii) पत्र-मुद्रा चलन कोप, स्वर्ण कोप तथा प्रविकोषण कोष इन तीनों का केन्द्रीयकरण कर दिया गया ग्रौर (iv) रुपये की विनिमय दर का प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय बैंक को सौंपा गया।
- (४) चाँदी का निर्यात—सन् १६३१ भीर सन् १६३६ के बीच सोने के निर्यात के साथ-साथ भारत सरकार ने भारी मात्रा में चाँदी भी विदेशों को बेची। चांदी के निर्यातों के भी कई प्रमुख कारए। थे:—
  - ( i ) विदेशों में चांदी की कीमत भारत की अपेक्षा ऊँची थी।
- (ii) हिल्टन-यंग आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार ने नोटों को रूपयों में बदलने का दायित्व हटा लिया था, जिससे रजत कोषों की अब कोई आव-ध्यकता नहीं रह गई थी। सरकार ने भी चाँदी के निर्यातों के विरोध का कोई प्रयत्न नहीं किया, था और ३१ मार्च सन् १६३४ तक लगभग २ करोड़ औंस चाँदी बाहर भेज दी गई।
- (iii) जुलाई सन् १९३३ में एक अन्तर्राष्ट्रीय रजत समभौता हुआ था, जिसके अनुसार अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, मैनिसको तथा पीरू की सरकारों ने प्रति वर्ष ३ करोड़ औंस चाँदी खरीदने का निर्णय किया था। इस प्रकार सोना ही नहीं, चिँदी भी भारत से बराबर बाहर जाती रही। इन निर्यातों के दुष्परिणाम दूसरे महा-युद्ध के काल में भारत सरकार के सम्मुख आये, जबिक उसे चाँदी को फिर से खरीदने पर बाध्य होना पड़ा।
- (iv) सन् १९३५ में अमरीका ने बहुत ही अधिक मात्रा में चाँदी खरीदना आरम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप चाँदी की कीमतें बढ़ कर ३६% पैंस प्रति औं सतक पहुँच गई। भारत से चाँदी के निर्यात को और भी प्रोत्सहन मिला, परन्तु चाँदी की कीमतों की इस अत्यधिक बृद्धि का परिगाम यह हुआ कि चीन के लिए रजतमान का सञ्चालन कठिन हो गया और उसने भी रजतमान का परित्याग कर दिया। भारत सरकार ने भी ऐसा अनुभव किया कि संकट का समय दूर न था और उसने एक-एक रूपये के नोट छाप कर रख लिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर रुपयों की मांग को

पूरा करने में कठिनाई न हो, किन्तु चीन द्वारा रजतमान के परिस्याग करने का परि-एगाम यह हुम्रा कि ग्रमरीका ने भी श्रमनी चांदी खरीदने की नीति बदल दी ग्रीर चांदी की कीमतें फिर गिरने लगीं। भारत सरकार को एक एक रुपये के नोटों को प्रचलन में लाने की ग्रावस्थकता नहीं पड़ी। सन् १६३६ में चांदी के भाव १६ पैंस ग्रीर २२ पैंस प्रति ग्रांस के बोच रहे, परन्तु फिर भी सन् १६३६ तक चांदी का निर्यात होता ही रहा। चांदी का ग्रधिक निर्यात हो जाने से ही भारत सरकार को द्वितीय महायुद्ध काल में चांदी का ग्रभाव ग्रनुभव हुम्रा ग्रौर उसे मुद्रएग के लिये चांदी खरीदनी पड़ी। क्या भारतीय चलन पद्धति का विकास हिल्टन-यंग ग्रायोग की सिफारिशों के ग्रनुसार हुन्ना हैं?—

इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा कठिन है कि भारतीय चलन पद्धित का विकास हिल्टन-यंग ग्रायोग की सिफारिशों के ग्रनुसार किस ग्रंश तक हुग्ना है। इसमें तो सन्देह नहीं कि भारत सरकार ने ज्यायोग की सभी सिफारिशों स्वीकार कर ली थीं ज्योर उनके ज्यनसार चलन पद्धित का संचालन करने का भी प्ररा प्रयत्न किया था।

- (१) भारत में सैद्धान्तिक रूप में स्वर्ण-पाट-मान की स्थापना भी कर दी गई थी।
  - (२) विनिमय दर को १ शिलिंग ६ पैंस पर बनाये रखने के पीछे सरकार ने देश का सम्पूर्ण सोना-चांदी विदेशों को भेज दिया था तथा देश के ग्रार्थिक जीवन को विदेशी स्पर्धा से बचाने का कोई महत्त्वपूर्ण प्रयत्न नहीं किया था।
- (३) सन् १६३५ में रिजर्व बैंक झॉफ इण्डिया की स्थापना करके साल, चलन और विदेशी विनिमय के नियन्त्रएा की एकाकी संस्था भी स्थापित कर दी गई। इस प्रकार सभी दिशाओं में आयोग की सिफा-रिशों को कार्य-रूप देने का प्रयत्न किया गया था।

परन्तु यह समभना भूल होगी कि आयोग की सिफारिशों का वास्तविक उद्देश पूरा हो गया था—(१) आयोग ने स्वर्णमान की स्थापना का सुभाव देकर हारे और स्वर्ण के बोच स्पष्ट और प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने की सिफारिश की थी, परन्तु व्यवहार में भारत सरकार ने रुपये का सोने से सम्बन्ध परोक्ष रूप में स्टॉलग के माध्यम से ही रखा। विदेशी बाजार में रुपये को कोई स्वतन्त्र स्थिति प्राप्त न थी। उसे सभी लोग केवल स्टॉलङ्ग के माध्यम द्वारा ही जानते थे। यही कारण है कि जिस मान को भारत में स्वर्ण-पाट-मान का नाम दिया गया था वह वास्तव में स्टॉलङ्ग विनिमय-मान ही था, क्योंकि जब स्टॉलङ्ग का मूल्य-हास भी होता था तो तब भी रुपये और स्टॉलङ्ग की विनिमय दर स्थिर ही रखी जाती थी। सन् १६३१ के पश्चात् तो यह मान प्रत्यक्ष रूप में ही स्टॉलङ्ग-विनिमय-मान रह गया था। सचे अर्थ में भारत में स्वर्ण-पाट-मान कभी स्थापित ही नहीं हुआ था। (२) जहाँ तक विनिमय दर का प्रवन है, आयोग ने १ शिक्षिंग ६ पैंस की दर को स्थापित करने तथा

उसके बनाये रखने का सुफाव अवश्य दिया था, परन्तु आयोग ने यह नहीं सोचा कि निकट भविष्य में ही इङ्कलैंड स्वर्णमान का परित्याग कर देगा। आयोग का यह भी विचार न था कि स्टिलिङ्ग के मूल्य-हास की दशा में भी रुग्ये और स्टिलिङ्ग की विनिमय दर में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। आयोग ने तो रुपये का सम्बन्ध स्वर्ण में स्थापित करने की सलाह दी थी। वह रुपये और स्टिलिङ्ग की विनिमय दर को स्थायी रखने के पक्ष में न था। इस प्रकार भारत की चलन पद्धित यथार्थ में आयोग के सुमावों के अनु। सार विकसित न हो सकी। इस प्रकार आयोग के सुमाव केवल आंशिक रूप में कार्य- रूप में परिणित किए जा सके।



- Enumerate the principal recommendations of the Hilton-Young Commission. Did the currency system of India after 1926 develop along the lines indicated in the report of the Commission? (Agra, B. A., 1950)
- 2. Explain the case for 18d. exchange value of the rupee as against 12 d. exchange value. (Agra, B. Com., 1949)
- 3. Discuss the main recommendations of Hilton-Young Commission and indicate the extent to which the same were accepted by the Government. (Raj. B, Com., 1956)
- Give a brief history of the Indian currency system since 1926.
   What difficulties were experienced during the last Great War. (Bombay, B. Com., 1951)
- 5. Trace the history of Indian currency system since 1926.

  (Agra, B. Com., 1948)

#### अध्याय २६

# भारतीय चलन का इतिहास ( क्रमशः )

( सन् १६३६--१६६० )

(The History of Indian Currency Contd.)

#### प्रारम्भिक--

३ सितम्बर सन् १६३६ को द्वितीय महायुद्ध की घोषणा की गई। उस समय भारत में स्टिलिङ्ग विनिमय मान प्रचलित था। भारत की प्रामाणिक मुद्रा रुपया था और रुपए के सिक्के, प्रठिशी तथा नोटों को असीमित विधिग्राह्यता प्राप्त थी। रुपए की स्टिलिङ्ग में विनिमय दर १ रुपया = १ शिलिंग ६ पेंस थी और सरकार इस दर पर स्टिलिङ्ग खरीदने और बेचने के लिए उत्तरदायी थी। रुपये के सिक्के, अठिशी तथा कागज के नोटों के अतिरिक्त देश में चाँदी और गिलट की चवन्नी, दुम्ननी, इकन्नी और ताँबे के पैसे प्रचलित थे। देश का व्यापाराशेष साधारणतया अनुकूल रहता आया था। यद्यपि भारतीय रुपये को कोई स्वतन्त्र बाजार प्राप्त न था, किन्तु स्टिलिङ्ग के माध्यम से संसार के सभी देश उससे परिचित थे। ब्रिटिश साम्राज्य का एक ग्रंग होने के कारण भारत की भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लेना पड़ा। युद्ध में सम्मिलित अन्य देशों की गाँत भारत सरकार को भी युद्धकालीन स्थिति का सामना करने के लिए समय-समय पर देश की प्रर्थ-व्यवस्था में आवश्यक समायोजन करने पड़े। युद्ध के काल में देश की ग्रर्थ-व्यवस्था में अधिक तनाव रहा। अधिक मुद्रा-प्रसार के कारण जनता को कष्ट हुमा और अविश्वतास के कारण मुद्रा-प्रणाली टूटते-टूटते बची।

# द्वितीय महायुद्ध में भारतीय मुद्रा-प्रणाली

ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध के ग्राघात के ग्रारम्भिक प्रभाव ग्रंथं-व्यवस्था के लिए हितकारी सिद्ध हुए थे। देश में उत्पादन तथा व्यापार का विस्तार हुग्ना, वस्तुन्नों भीर सेवाग्नों की कीमतें बढ़ीं ग्रीर वर्षों के पश्चात कृषकों की ग्राधिक दशा में सुवार हिग्नाचर हुग्ना। ग्रारम्भ में ऐसा प्रतीत हुग्ना कि देश की ग्रंथं-व्यवस्था ने युद्ध की टक्कर की बिना किसी विशेष ग्रातंक के सह लिया था। रुपया स्टॉलङ्ग की विनिमय दर १ शिलिंग ६ पेंस पर ही जमी रही ग्रीर इसी दर पर रिजर्व वेंक ने देश की विदेशी विनिमय सम्बन्धी ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति के लिए भारी मात्रा में स्टिलङ्ग खरीदा, परन्तु डालर तथा येन ( Yen ) में रुपए का मूल्य-पतन हो गया। ब्रिटिश सरकार ने स्टिलङ्ग ग्रीर डालर की विनिमय दर १ पीण्ड = ४ २०३ डालर रखी ग्रीर इस ग्राधार पर रुपए तथा डालर की विनिमय दर १ पीण्ड = ४ २०३ डालर रखी ग्रीर इस

में व्यापार की तेजी तथा कीमतों के बढ़ने के कारए। चलन की माँग में नाफी वृद्धि हुई। इस माँग की सन्तृष्टि के लिए सिक्कों तथा कागज के नोटों का प्रचलन बढ़ाया गया। कागज के नोटों का प्रचलन सितम्बर सन् १६३६ में १८० ६ करोड़ रुपए से बढ़ाकर जून सन् १६४५ में १,०३४ करोड़ रुपया हो गया। पत्र-मुद्रा का यह भ्रत्य- धिक विस्तार भारत सरकार ने स्टॉलग प्रतिभूतियों तथा कोपागार विश्तों की सहायता से किया था।

द्वितीय महायुद्ध के भारतीय मुद्रा पर जो विशेष प्रभाव पड़े उनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं:—(१) नोटों को परिवर्तित करने की दौड़, (२) रुपए के िक्कों का नियन्त्रित वितरण, (३) एक रूपये के नोट का प्रकाशन, (४) कम चाँदी की श्रठन्नी, चवन्नी व रुपए के सिक्कों का टंकन, (५) पुराने सिक्कों का प्रचलन बन्द करना, (६) नई रेजगारी का टंकन, (७) मुद्रा प्रसार व कीमतों में वृद्धि। प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है:—

- . (१) नोटों को परिवर्तित करने की दौड़—इसरे महायुद्ध के काल में भारतीय चलन पद्धित की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि रुपए के सिक्कों में प्रचलन से निकलने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई ग्रीर एक-एक रुपये के नोट चालू किए गए। युद्ध के ग्रारम्भ काल में पत्र-मुद्रा के प्रति जनता का विश्वास बना रहा था, परन्तु फाँस के फतन के पश्चात् मई ग्रीर जून सन् १६४० में कागज के नोटों को रुपये के सिक्कों में बदलने की माँग बहुत बढ़ गई ग्रीर क्योंकि रिजर्व बैंक का यह वैद्यानिक उत्तरदायित्त्व था कि वह नोटों के बदले में रुपये के सिक्के उपलब्ध करे, जनता ने नोटों को रुपयों में तेजी के साथ भुनाना ग्रारम्भ कर दिया। साधाररणतया नोटों को रुपयों में वदलने की माँग एक करोड़ रुपया प्रति सप्ताह से भी कम रहती थी, परन्तु मई सन् १६४० में यह एकदम ४५ करोड़ रुपया प्रति सप्ताह तक पहुँच गई। जून सन् १६४० के प्रथम सप्ताह तक रिजर्व बैंक का संचित रुपया कोष युद्ध के ग्रारम्भ में ७५५४७ करोड़ रुपया से घट कर केवल ३२ करोड़ रुपया रह गया। भारतीय टकसालों के लिए रुपयों के सिक्कों को उतनी तेजी के साथ ढालना ग्रसम्भव था जितनी तेजी से कि वे प्रचलन से निकल कर संचित कोषों में एकत्रित हो रहे थे, यद्यपि भारत सरकार के पास चाँदी के स्टॉकों का ग्रभाव न था।
- (२) रुपये के सिक्कों का नियन्त्रित वितरण इस कारण १५ जून सन् १६४० को भारत सरकार ने एक ग्रध्यादेश द्वारा रुपयों का व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक ग्रावश्यकता से ग्रधिक मात्रा में जमा करना दण्डनीय बना दिया। कुछ समय तक रुपये के सिक्के की कीमत नोटों से ग्रधिक रही ग्रीर रुपये के सिक्कों ग्रीर खेरीज के छोटे-छोटे सिक्कों की भारी कमी ग्रनुभव हुई।
- (३) एक रुपये के नोट का प्रकाशन—इस परिस्थित का सामना रिजवं बेंक ने एक रुपये का नोट निकाल कर किया, जिसे अपरिमित विधि-ग्राह्म घोषित

किया, परन्तु इसे चाँदी के रुपयों में बदलने का किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व न था।

- (४) कम चाँदी की चवली, ग्रठली व रुपये के सिक्कों का मुद्र ए-चाँदी के उपयोग में बचत करने का दूसरा उपाय भारत सरकार ने यह किया कि सभी चाँदी के सिक्कों की प्रमाणित शुद्धता (Fineness) में कमी कर दी। ग्रप्रैंस सन् १६४० में केन्द्रीय घारा सभा ने भारत सरकार को यह ग्रधिकार प्रदान किया कि वह चवली की शुद्धता देने से घटा कर ने कर दे। तत्परचात् २६ जुलाई सन् १६४० को ग्रठली की शद्धता भी देने से घटा कर ने कर दी गई। २३ दिसम्बर सन् १६४० को यह कमी रुपये के सिक्के पर भी लागू कर दी गई। ये सभी उपाय इसलिए किये गये थे कि भारत सरकार चाँदी के प्रस्तुत स्टाँकों से ग्रधिक काम लेना चाहती थी।
- (५) पुराने सिक्कों का प्रचलन वन्द करना—सरकार ने चाँदी के पुराने रुपयों का प्रचलन भी वन्द कर दिया। ११ अक्टूबर सन् १६४० को एक आदेश निकाला गया, जिसके द्वारा महारानी विकटोरिया के छापे के रुपयों और अठिक्रियों का विमुद्रीकरण कर दिया गया तथा सरकार ने १ अप्र ल सन् १६४१ तक उन्हें वापस माँग लिया। ४ नवम्बर सन् १६४१ को एडवर्ड के छापे वाले रुपये और अठिक्रियों भी बन्द कर दी गई और ये सिक्के ३० सितम्बर सन् १६४२ तक सरकारी खजाने तथा रेलवे स्टेशनों पर वापिस माँगे गये। १ नवम्बर सन् १६४३ से जार्ज पंचम तथा जार्ज पष्टम के वे रुपये और अठिक्रियाँ भी बन्द कर दिए गए जिनकी शुद्धता के प्रे थी। इस प्रकार पुराने सिक्कों को बन्द करके तथा नये सिक्के चला कर, जिनमें चाँदी की मात्रा वस्म रखी गई थी, चाँदी के उपयोग में बचत को गई।
- (६) नई रेजगारी का टंकन—सन् १६४२-४३ में छोटे-छोटे सिकों का भी स्रभाव स्रिक्त स्रनुभव हुया। लोगों ने ताँव के पैसों तथा स्रन्य छोटे-छोटे सिकों को गलाना और जोड़कर रखना स्रारम्भ कर दिया था। बड़े-बड़े शहरों में छोटे-छोटे सिक्कों के स्थान पर डाकखाने के टिकट खेरीज के रूप में चलने लगे। भारत सरकार ने भारत सुरक्षा विधान के सन्तर्गत रेजगारी का सवय दण्डनीय घोषित कर दिया। रेजगारी की कमी को दूर करने के लिए बम्बई और कलकत्ते की टक्सालों ने पैसा ढालना स्रारम्भ कर दिया। छोटे सिक्कों की ढलाई के लिए लाहौर में भी एक नई टक्साल खोलो गई। जनवरी सन् १९४२ में गिलट का स्रधन्ना चालू किया गया। इकन्नी और दुसन्नी में भी गिलट की मात्रा बढ़ा दी गई। सन् १९४३ में छेद वाला पैसा निकाला गया, परन्तु इसका वात्रर (Washer) के रूप में इतना स्रधिक उपयोग होने लगा कि योड़े ही समय में सरकार को इसकी ढलाई बन्द करनी पड़ी। सरकार ने तेजी के साथ छोटो कीमत के सिक्के निकालने स्रारम्भ कर दिये स्रौर सन् १९४४ में ऐसे सिक्कों का उत्पादन २१ करोड़ ६० लाख प्रति मास तक पहुँच गया। इस प्रकार धीरे-घीरे रेजगारी की कमी दूर हो गई।

(७) मुद्रा-विस्तार, मुद्रा-स्फीति तथा कीमतों की वृद्धि—भारतीय चलन के इतिहास में दूसरे महायुद्ध के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना चलन और साख-मुद्रा का अत्यधिक विस्तार और उसके कारण उत्पन्न होने वाली कीमत-वृद्धि थी। इस काल में सरकार की सामान्य नीति अधिक से अधिक पत्र-मुद्रा निकाल कर युद्ध- अपय को पूरा करना थी। सन् १६३६ और सन् १६४५ के बीच गोटों का प्रचलन १६० करोड़ हाये से बढ़कर १,०३४ करोड़ हपए तक पहुँच गया। इसी काल में साख-मुद्रा की मात्रा भी दुगुनी से ऊरर पहुँच गई थी। पत्र-मुद्रा की इस वृद्धि के साथ कीमत-स्तर भी वरागर ऊरर उठता गया। निम्न आँकड़े स्थिति का अच्छा अनुमान प्रदान करते हैं:—

वर्षं	नोटों की संख्या (करोड़ रुपयों में)	त्र्राधिक सलाहकार का मूल्यांक (१६३६ = १००)	
3 5 3 9	१८०	₹00	
<b>\$</b> 8%0	२३८	<b>१</b> ३३	
१४३१	२४४	<b>११</b> ४	
<b>१</b> १४ <b>२</b>	<b>३</b>	<b>\$</b> 84	
१९४३	₹3×	\$6X	
<b>\$</b> £&&	<b>५</b> ५२	<b>२</b> ३२	
१६४५	१,०३४	२५०	

ग्राधिक सलाहकार के मूल्याँक से स्थिति का वास्तिविक ग्रनुमान नहीं मिलता हैं, क्योंकि ये केवल सरकार द्वारा नियन्त्रित कीमतों के ग्राघार पर बनाये गये हैं। वास्तव में ग्रनियन्त्रित वस्तुग्रों ग्रौर चोर-बाजार की कीमतें बहुत ऊँची थीं ग्रौर सन् १९४५ का मूल्यांक ४०० से भी ऊरर होना चाहिए था।

कीमतों की इस ग्रत्यधिक वृद्धि ने सन् १६४३ से ही मुद्रा-स्फीति की दशाएँ उत्पन्न कर दी थीं। रिजर्व बेंक ने भी यह स्वीकार किया कि मुद्रा-स्फीति वढ़ रही थीं, परन्तु रिजर्व बेंक ने इसे रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। सन् १६४३ की वार्षिक रिपोर्ट में रिजर्व बेंक ने यह स्वीकार कर लिया था कि जीवन-रक्षक वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने के कारण स्फीति को ग्रौर भी श्रिषिक प्रोत्साहन मिला था। वेंक की सन् १६४४ की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया था:—''मुद्रा-स्फीति को दूर करने के लिए सरकार ने जनता से ऋण लेना ग्रारम्भ कर दिया है ग्रौर नये-नये कर लगाये हैं। यदि इन दोनों कामों में सरकार को सफलता न मिली तो देश में कीमतों को बढ़ने से रोकना ग्रौर जीवन निर्याह व्यय को कम करना ग्रसम्भव हो जायगा।''

कीमतों की इस भारी वृद्धि के अनेक कारण थे, परन्तु प्रमुख कारण चलन भीर साख-मुद्रा का अत्यधिक विस्तार था । युद्ध-काल में चलन की कुल वृद्धि १,१६८:६४ करोड़ रुपया थी, जिसका ८२:५% पत्र-मुद्रा की वृद्धि, ११:८% रुपए के सिक्कों की वृद्धि तथा ५:६% छोटे सिक्कों की मात्रा की वृद्धि के कारण हुआ था। अनुकूल व्यापाराशेय—

युद्ध के काल में भारत का व्यापाराशेष भी निरन्तर ग्रनुकूल ही बना रहा। युद्धकालीन व्यापाराशेष की स्थिति निम्न प्रकार थी:—

वर्षं	व्यापाराशेष की भ्रनुकूलता ( करोड़ रुपयों में )
3538	<del> </del> १७·५६
08-3539	<u> </u>
88x0-88	+ 88.88
9888-89	+ 98.40
१६४२—४३	<del> </del>
४४—५४३}	+ 68.25
\$688 <del></del> 88	┼ २६•०⊏

इस अनुकूल व्यापाराशेष के बदले में न तो भारत को सोना ही प्राप्त हुप्र शौर न वस्तुयें ही । ब्रिटिश सरकार ने इसके बदले में हमें केवल स्टिलिङ्ग प्रतिभृतियाँ ही दीं, जिनको रिजर्व बैंक ने निधि के रूप में उपयोग करके कागज के और अधिक नोट छाप दिये । युद्ध के काल में सोना तो देश से बाहर भी भेजा गया । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अकेले सन् १६४० में लगभग ३४ करोड़ रुपये का सोना देश के बाहर भेजा गया । इस सोने के बदले में भी हमें स्टिलिङ्ग प्रतिभृतियाँ ही प्राप्त हुई तथा उनके बाधार पर पत्र-मुद्रा में और भी वृद्धि की गई । इस काल में भारत सरकार का रक्षा व्यय भी बहुत अधिक रहा था । स्टिलिङ्ग प्रतिभृतियों के अतिरिक्त भारत सरकार ने कोषागार विपत्रों के आधार पर भी नोट छापे । सन् १६३६-४० में ऐसे कोषागार विपत्रों की मात्रा, जिनके आधार पर नोट छापे गये थे, केवल ३७ करोड़ रुपया थी, परन्तु सन् १६४१-४२ में यह ७५ करोड़ रुपया हो गई थी और सन् १६४१-४३ में १३६ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी ।

# द्वितीय महायुद्ध काल में भारत में विनिमय नियन्त्रण

युद्ध का आरम्भ होते ही भारत रक्षा अध्यादेश (Defence of India Ordinance) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक को सिक्कों, घातुओं, प्रति-

स्टिलिंग प्रतिभूतियाँ उन हुिएडयों को कहते हैं जो ब्रिटिश सरकार ने उस माल की कीमत के रूप में लिखकर दी थीं जो भारत से उधार खरीदा गया था।

<sup>2.</sup> See The 14th Annual Report, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries, 1940.

भतियों तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवसायों के नियन्त्रण और इस नियन्त्रण के शासन का काम सौंप दिया । आरम्भ से ही देश में कडा विनिमय नियन्त्रण लागू किया गया। विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवसाय केवल कुछ स्वीकृत फर्मो तथा संस्थामी द्वारा ही किये जा सकते थे और इस उद्देश्य से कुछ भारतीय सिम्मलित पूँजी बैंकों तथा विदेशी विनिमय बैंकों को अनुजारन (Licenses) प्रदान कर दिये गये थे। विनिमय नियन्त्रण की सामान्य नीति यह थी कि नावाररातवा साम्राज्य देशों की मुद्राम्रों के कय-विकय पर कोई प्रतिवन्घ नहीं लगाया जाता था. परन्तू साम्राज्य से बाहर के देशों की मुद्राम्नों के क्या विकय को वास्तविक व्यापार आवश्यक्तामों के मनुसार सीमित रखा जाता था। किर भी यात्रा-व्यय तथा व्यक्तिगत विप्रेपों (Personal Remittances) के लिए कुछ ग्रवकाश रखा जाता था। भारतीय विनिमय नियन्त्रण श्रिधिकारियों की नीति यही थी कि भारत में सभी प्रकार के विदेशी विनिमय व्ययसाय उन विनिमय दरों के ग्राधार पर किये जायें जो समय-समय पर लन्दन विनिमय नियन्त्रण द्वारा घोषित की जाती थीं और साथ ही हाये और स्टिलिङ की विनिमय दर १८ पेंस पर स्थिर रखी जाय । विना रिजर्व वैंक से म्राज्ञा प्राप्त किये कोई भी व्यक्ति न तो विदेशियों से प्रतिभृतियाँ खरीद सकता या ग्रौर न उनका निर्यात ही कर सकता या। प्रतिबन्धों का प्रमुख उद्देश्य पूँजी के निर्यात और विदेशी दरों में होने वाले सट्टे को रोकना था। विनिमय नियन्त्रण के दृष्टिकीए। से साम्राज्य तथा समधन (Commonwealth) देशों को एक ही चलन इकाई अर्थात स्टर्लिङ्ग का क्षेत्र मान लिया गया था। इस क्षेत्र के भीतर कोषों के हस्तान्तरए। पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये थे. परन्तू इस क्षेत्र के बाहर चलनों के क्रय-विक्रय पर कडा नियन्त्रण रखा जाता था। इन विनिमय नियन्त्रणों को तीन वर्गों में इस प्रकार रखा जा सकता है:---

- (१) ग्रायात नियन्त्रण्—ग्रारम्भ में तो बेंकों को विदेशी विनिमय के बेचने के विषय में काफी छूट दी गई थी, परन्तु जैसे-जैसे युद्ध बढ़ता गया, बेंकों के ग्रिषकारों में निरन्तर कमी की गई। ग्रन्त में ऐसी व्यवस्था की गई कि बेंक रिखर्व बेंक से ग्राज्ञा प्राप्त करके ही कुछ ग्रनुज्ञापित ग्रायातों तथा व्यक्तिक विप्रेषों का भुगतान करने के लिये विदेशी विनिमय बेच सकती थीं। इस प्रकार एक कड़ा ग्रायात नियन्त्रण् स्थापित किया गया ग्रीर बिना ग्रनुज्ञापन के स्टीलङ्ग क्षेत्र के बाहर के देशों ग्रर्थात् दुर्लभ मुद्रा देशों (Hard Currency Countries) से कोई भी माल नहीं मगाया जा सकता था। इस नियन्त्रण् के दो उद्देश्य थे:—प्रथम, विदेशी व्यापार के ग्रसन्तुलन को रोकना ग्रीर दूसरे, ऐसे ग्रायातों को प्राथमिकता (Priority) देना जिनका युद्ध ग्रथवा ग्रन्य ग्रावश्यक कार्यों के लिए ग्रिषक महत्त्व था।
- (२) निर्यात नियन्त्रण् विनिमय नियन्त्रण् के साथ ही साथ बह भी आवश्यक समभा गया कि स्टिनिङ्ग क्षेत्र से बाहर भारत से जो भी माल भेजा जाय इससे प्राप्त कीमत पर भी नियन्त्रण् रखा जाय। इस उद्देश्य को पूरा करने के ज़िए

रिजवं बेंक ने एक निर्यात नियन्त्रए। योजना भी लागू की। इस योजना के भी दो उद्देश्य थे:—प्रथम, यह कि निर्यातों की कीमत विदेशों में न रहे, प्रत्युत भारत में आ जाय। दूसरे, यह कि निर्यातों की कीमतों का भुगतान एक निश्चित रीति से हो, जिससे उनका अधिकतम् मूल्य प्राप्त हो सके। भारत द्वारा अपरीका को किये जाने वाले निर्यातों से जो भी मूल्य प्राप्त किया जाता था वह ब्रिटिश सरकार को दे दिया जाता था, जो उसे साम्राज्य डालर कोष में रखकर उसका उपयोग युद्ध सम्बन्धी सामानों के खरीदने के लिए करती थी। इस योजना का उद्देश्य युद्ध का सफल संचालन था।

(३) ग्रन्य नियन्त्रण् — विदेशी विनियय के नियन्त्रण् की नीति को सफल बनाने के लिये भारत में निम्न नियन्त्रण् व प्रतिबन्ध लगाये गये :— (i) नवम्बर सन् १६४० से भारतीय मुद्रा को रिजर्व बैंक के लाइसेन्स बिना बाहर भेजने का निषेव कर दिया गया । सन् १६४३-४४ से भारतीय मुद्रा, ईरानी, रायल, ग्रफगानी, तथा लङ्का की मुद्राग्रों को छोड़ कर ग्रन्य मुद्राग्रों के ग्रायात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया। (ii) सन् १६४१ से विदेशी मुद्रा में भुगतान करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। (iii) शत्रु राष्ट्रों के भारतीय बैंकों में जमा धन के भुगतान पर भी रोक लगा दी गई। (iv) स्वर्णं के ग्रायात-निर्यात के लिये लाइसेन्स लेना ग्रावश्यक हो गया। (v) भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति से प्रतिभृति खरीदना मना कर दिया गया।

#### साम्राज्य डालर कोष (The Empire Dollar Pool)-

सन् १९३६ में ही बिटिश सरकार ने स्टॉलङ्ग क्षेत्र के विदेशी विनिमय कोशों का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया था। क्षेत्र के किसी देश का ब्रिटेन के साथ ज्यापाराशेष जितना भी अनुकूत होता था उसका निस्तारण ब्रिटेन स्टॉलङ्ग देकर किया करता था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश के स्टॉलङ्ग क्षेत्र के बाहर के देशों के ज्यापाराशेष का निस्तारण भी ब्रिटेन ने इसी प्रकार करना आरम्भ कर दिया। ह मार्च सन् १९४० को भारत में एक नई योजना चालू की गई, जिसका उद्देश्य दुलंभ मुद्रा देशों को भेजे जाने वाले निर्यातों से प्राप्त कीमत को सुरक्षित रखना था। इन देशों में संयुक्त राज्य अमरीका, स्विटजरलेंड, हॉलेंड, बेलजियम आदि सम्मिलत थे, जिनकी मुद्राण गाँग की तुलना में दुर्लभ हो गई थीं। योजना के दो उद्देश्य थे:—प्रथम, दुर्लभ मुद्राओं की प्राप्त मात्राओं पर नियन्त्रण रखना, तािक युद्ध के सफल संवालन के लिए उनका समुचित उपयोग किया जा सके और दूसरे, दुर्लभ मुद्राओं को नियत दरों पर खरीदने और बेचने की योजना को सफल बनाना।

युद्ध से पूर्व यह प्रथा प्रचलित थी कि स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के ग्रधिकांश देश ग्रपने लगभग सभी विदेशी विनिमय कोषों को लन्दन में स्टर्लिङ्ग के रूप में रखते थे। उस समय स्टर्लिङ्ग को ग्रन्य सभी मुद्राग्नों में स्वतन्त्र परिवर्तनशीलता प्राप्त थी, जिसके फलस्वरूप उसके बदले में कोई भी मूद्रा प्राप्त की जा सकती थी। युद्ध का ग्रारम्भ होते ही स्टर्लिङ्ग की यह परिवर्तनशीचना कठिन हो गई। इस कारण स्टिलिङ्ग क्षेत्र के कुछ देशों ने अपनी विदेशी विनिमय आय को अपने ही मंरक्षरण में रखना आरम्भ कर दिया। क्षेत्र के कुछ देशों ने युद्ध के मफन संचालन हेन् अपनी विदेशी विनिमय ग्राय के व्यय पर प्रतिबन्ध लगाने ग्रारम्भ कर दिये। स्टीलङ्ग क्षेत्र की सारी की सारी विदेशी विनिमय ग्राय एक सामृहिक कीप में रखी गई, जो बैंक अाँक इङ्गलैंड तथा ब्रिटिश कोपानार के संरक्षण में रखा गया था। इस कोष की सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्रा स्रमरीकन डालर थी। इसी कारण इस व्यवस्था का नाम साम्राज्य डालर कोप (Empire Dollar Pool) पड़ा। इस कोप में से स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के ग्रलग-ग्रलग देशों को व्यय के लिए कोई निविवत ग्रम्यंश (Q.20ta) नहीं दिया जाता था। क्षेत्र के सभी देशों ने यह स्वीकार किया था कि उनमें से कोई भी विदेशी विनिमय का अनादश्यक व्यय नहीं करेगा। काकी समय तक केथ ने विदेशी विनिमय देने के लिए युद्ध का संवालन तथा नागरिक ग्रर्थ-व्यवस्था को युद्ध-कालीन आधार पर बनाये रखना ही समुचित उद्देश्य स्वीकार किया, परन्त् ग्रावश्यकता का निर्णय सदस्य देश के ऊरर ही छोड़ा गया था श्रीर यदि सदस्य देश यह प्रमाणित कर देता था कि व्यय स्रावश्यक था तो कोप कभी भी उसके निर्एाय का विरोध नहीं करता था। युद्ध का अन्त हो जाने के पश्चात् कीप ने अपनी नीति को अधिक उदार बना दिया था।

ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सन् १६३६ और सन् १६४६ के बीच भारत ने लगभग ४०.५ करोड़ रुपये की कीमत का डालर प्राप्त किया था, जो सारा का सारा इस कीष में जमा कर दिया गया था, परन्तु इस काल में भारत का डालर व्यय केवल २०४ करोड़ रुपये की कीमत का था और इसके अतिरिक्त भारत द्वारा ५१ करोड़ रुपये की कीमत का अन्य दुर्लंभ मुद्राओं का व्यय किया गया था। इस प्रकार सब कुछ देखते हुए भारत की ओर से कोष को ११४ करोड़ रुपये का डालर अधिक दिया गया था।

मई सन् १६४० में भारत सरकार ने आयातों के अनुजापन की एक नई प्रिणाली ग्रहण की, जिससे कि विदेशी विनिमय के उपयोग में बचत हो सके और कुछ प्रकार के मालों के आयात बन्द हो जायें। आरम्भ में तो वस्तुष्रों की एक छोटी सी सूची पर ही प्रतिबन्ध लगाये गये थे, परन्तु सन् १६४१ में वस्तुष्रों की सूची का इस प्रकार विस्तार किया गया कि उसमें विदेशों से आने वाली सभी वस्तुष्रों को सम्मिलत किया गया। केवल कनाडा से आने वाले कुछ प्रकार के मालों को इस सम्बन्ध में छूट दी गई थी। ऐसा करने का केवल यही उद्देश्य न था कि विदेशों विनिमय के व्यय को कम किया जाय, बिल्क इसके द्वारा जहाजों के भीतर के स्थान (Tonnage) में बचत करने का तथा अमरीका की उत्पादन शक्ति की रक्षा करने का भी प्रयत्न किया गया। जापान के युद्ध में सम्मिलत होने के पश्चात् जलयानों के यातायात में और भी

श्रिष्ठिक किठनाई अनुभव होने लगी, परन्तु सन् १६४२--४३ में उघार-पट्टा प्रणाली (Lend-lease System) के विकास ने डालर में भुगतान करने की आवश्यकता काफी कम कर दी। इस प्रणाली के अन्तर्गत भारत में भारी मात्रा में मशीनरी, इस्पात तथा अन्य सामानों का आयात किया गया, परन्तु इनकी की मत आयात व्यापारियों ने भारत सरकार को केवल रुपयों में ही चुकाई और क्यों कि भारत सरकार के लिए डालर में भुगतान करने की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिये विदेशी विनिमय खरीदने का प्रस्त ही नहीं उठता था। जैसे-जैसे युद्धकालीन स्थिति का तनाव कम होता गया, आयातों के अनुज्ञापन प्रदान करने में अधिक उदारता दिखाई गई। देश में मुद्रा-स्फीति को रोकने तथा अनाज की कमी को दूर करने के लिये भारत सरकार ने अमरीका से भारी मात्रा में खाद्य ज्ञ तथा उपभोगीय वस्तुओं के आयात किये, जिसके कारण अमरीका के साथ हमारा व्यापाराशेष प्रतिकृत हो गया। अन्त में भारत सरकार ने स्टर्शिङ्क क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रतिबन्धों को ढोला किया और डालर के उपयोग में मितव्यियता लाने के लिए डालर क्षेत्र के आयातों पर और भी कड़े नियन्त्रण लगाये।

सोने के सम्बन्ध में ब्रिटिश भारत के भीतर इसके हस्तान्तरण पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये थे, परन्तु बिना रिजर्व बैंक से आज्ञा-पत्र प्राप्त किये सोने के निर्यात नहीं हो सकते थे। स्वर्ण आयात के आज्ञा-पत्र तो सरलतापूर्वक प्रदान कर दिये जाते थे, परन्तु निर्यात अनुज्ञापन तभी दिये जाते थे जबिक सोना या तो बैंक आफ इङ्गलैंड को भेजा जाता था, अथवा बैंक आफ इङ्गलैंड द्वारा माल खरीदने के लिए उपयोग किया जाता था। युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण यह आवश्यक था कि भारत तथा ब्रिटेन के उपयोग के लिए सभी स्वर्ण कोजों की बचत की जाय।

# हमारे पौर्ण्ड पावने (The Sterling Balances)

भारतीय चलन के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना हमारे पौंड पावना ऋणों का जमा होना भी था। युद्ध से पूर्व भारत के ऊपर इङ्गलैंड का साम्राज्यवादी ऋण लदा हुम्रा था, परन्तु युद्ध के काल में यह सब ऋण चुका दिया गया भ्रीर इसके भ्रति-रिक्त भारत का इङ्गलैंड पर अरबों रुपयों का ऋण चढ़ गया। इस ऋण के चढ़ने की कहानी इड़ी मर्मस्पर्शी है, क्योंकि यह ऋण भारतवासियों के भ्राघा-पेट खाने तथा नंगे तन रहने का परिणाम था। भारत ने इङ्गलैंड के युद्ध व्यय को चलाने भ्रीर इङ्गलैंड को भ्रावश्यक माल भेजने में भारी सहायता पहुँचाई, जिसके लिए भारी मात्रा में इगलैंड को ऋण दिया गया। भारत के इस ऋण को माप स्टिलिंग में की जाती थी भ्रीर इसी कारण इसका नाम पौंड पावना भ्रथवा स्टिलिंग पावना पड़ा।

रिजर्व बैंक ग्रॉफ इण्डिया एक्ट सन् १९३४ की घारा ३३ के ग्रनुसार रिजर्व बैंक को स्टॉलिंग प्रतिभूतियों की ग्राड़ पर नोट निकालने का ग्रिधकार था। युद्ध-काल में भारत सरकार ने इस घारा की ब्यवस्थाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाया। इङ्गलैंड भारत से जो भी माल खरीदता या उसके बदले में बिटिश सरकार रिजर्व वैं कि को स्टॉलिंग प्रतिभूतियाँ दे देती थी और इन प्रतिभृतियों को निधि के क्य में उपयोग करके रिजर्व बैंक बराबर नोट छापती रहती थी, जिनके हारा भारत में भुगतात दे दिए जाते थे। पहले तो भारत सरकार ने इन प्रतिभूतियों का उपयोग प्रकृते स्टॉलिंग ऋगों के चुकाने के लिए किया, परन्तु शीरे-शीरे जब उस ऋगा का भुगतान हो गया तो पींड पावने ब्रिटिश ऋगों के रूप में जमा होते गये। ये पावने उस व्यय का फल हैं जो भारत ने इक्क लैंड की स्रोर से किया था। इनकी वृद्धि के तीन कारण उक्क खनीय है—

- (१) भारत सरकार ने इङ्गलैंड की ग्रोर से भारत में जो सामग्री खरीदी उसकी कीमत स्टर्लिंग प्रतिभूतियों में चुकाई गई ग्रीर इस प्रशर पौंड पावनों की मात्रा बढ़ती गई। सरकार ने यह सभी माल नियन्त्रित कीमतों पर खरीदा था ग्रीर भारतवासियों के लिए इसका वेचना बहुघा ग्रनिवार्य होता था। परिखामस्वरूप देश में सन् १६४३ का बंगाल दुभिक्ष ग्राया था ग्रीर मुद्रा-प्रसार के कारण जनता को घोर कष्ट उठाने पड़े थे।
- (२) भारत ने युद्ध के सफल संचालन के लिए अन्य मित्र राष्ट्रों को भी माल भेजा। उन्होंने भी भुगतान स्टर्लिंग में किया, जो कि इङ्गलैंड में जमा हो जाताथा।
- (३) भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के खाते पर मुद्रा-संचालन के लिये जो व्यय किया था उसकी राशि ने भी पौंड पावनों को बढ़ाया, क्योंकि इसके बदले में भी हमें स्टॉलिंग प्रतिभृतियाँ ही मिली थीं।
- (४) युद्ध काल में अमेरिकी सेनायें भी भारत में रही थीं। इन पर होने वाले व्यय के बदले जो डालर प्राप्त हुए वे भी साम्राज्य डालर कोष में जमा कर दिए जाते थे और इङ्कलैंड बदले में भारत सरकार के खाते में स्टॉलग प्रतिभूतियाँ जमा कर देता था, जिससे पौंड पावनों में बुद्धि होती गई।
- (५) यही नहीं, भारत के अनुकूल व्यापाराजेष तथा डालर कोप में जमा किए हुए विदेशी विनिमय के बदले में भी स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ ही दी गई थीं और उन्होंने भी ऋगा की मात्रा को बढ़ाया था।

सन् १६४७ में ये पींड पावने लगभग १,७०० करोड़ रुखे की कीमत के आँके गये थे। युद्ध के विभिन्न वर्षों में ये निम्न प्रकार जमा हुए थे:—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)		
\$636-80	१४४		
१ <b>६</b> ४० <b>-४</b> १	१४८		
१ <b>६४१-४</b> २	२६४		

१९४२-४३	788
88-583	६६४
१६४४-४५	<b>१,</b> ४७२
१६४५-४६	१,६८०

### पौड पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में वाद-विवाद-

पौंड पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में युद्धकाल से ही बात चीत चल रही थी। इङ्गलैंड की स्रोर से बहुत बार यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा या तो इन ऋगों को पूर्णतया रह कर दिया जाय, प्रथवा इनकी मात्रा में भारी कमी कर दी जाय।

इस विचार के पक्ष में बहुधा यह कहा जाता था कि (१) युद्ध के सफल संचालन श्रौर शत्रु को परास्त करने में भारत का भी उतना ही हित था जितना कि इङ्गलैंड का। इङ्गलैंड द्वारा किया गया व्यय भारत की रक्षा से भी सम्बन्धित था, इसलिए इसके चुकाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। (२) कुछ व्यक्तियों ने यह तर्क रखा कि इतने बड़े ऋगों का चुकाना इङ्गलैंड की शौधनक्षमता से बाहर था, जिसके कारण इसमें कमी करना आवश्यक था। (३) पौंड पावनों को युद्ध सम्बन्धी ऋण समभते हुए भारत को चाहिए कि इन्हें अमेरिका की भाँति माफ कर दे। (४) युद्ध काल में राये की विनिमय दर कृत्रिम रूप से ऊँची रखी गई थी, जिससे पौंड पावनों में इतनी बृद्धि हो गई है।

इत तर्नों में कटु सत्यता थी, परन्तु भारत की ग्रोर से यह कहा गया था कि (१) भारत ने यह ऋए स्वेच्छा से नहीं दिया था। यह उससे जबरदस्ती लिया गया था। ग्रन्थथा इतने बड़े ऋएों का देना भारत की क्षमता से बाहर था। (२) इसके श्रितिरिक्त इस ऋएा के पीछे भारतवासियों का महान् त्याग तथा उनके घोर ग्राथिक कष्ट छिपे हुए थे, इसलिये इसका रद्द करना ग्रथवा कम कर देना न्यायपूर्ण नहीं था। (३) भारत को ग्रमेरिका की तरह इङ्गलैंड से पौंड पावनों का भुगतान नहीं मांगना चाहिए। यह तर्क भी न्यायरहित है, क्योंकि भारत ग्रौर ग्रमेरिका की ग्राधिक स्थित में जमीन ग्रासमान का ग्रन्तर है। (४) रुपये का मूल्य भले ही ऊँचा रखा गया हो, लेकिन इङ्गलैंड व मित्र राष्ट्रों को तो सामान नियन्त्रित मूल्यों पर ही सप्लाई किया गया था। (५) पौंड पावने हमारी सबसे बड़ी पूँजी है, क्योंकि इसके ग्राघार पर हम स्टिलिंग क्षेत्र से मशीनें ग्रादि मँगा सकते हैं, जो कि हमारे ग्राधिक विकास के लिए बहुत ग्रावश्यक हैं।

काफी लम्बे काल तक इस विषय पर तर्क वितकं चलता रहा और अनेक रीतियों से इङ्गलैंड इस ऋगा के भुगतान को टालता रहा। भारत ने पौंड पावनों का प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा परिषद् (International Monetary Conference) के सम्मुख भी प्रस्तुत किया, परन्तु उसने इस पर विचार करने से इन्कार कर दिया। इसी परिषद् में इङ्गलैंड के प्रतिनिधि लार्ड कीन्ज ने बड़े स्तर्ट गव्दों में यह विश्वास दिलाया धा कि इङ्गलैंड अपने उत्तरदायित्त्व को पूर्या रूप में निभाने को नैयार था और पींड पावनों के घटाने अथवा रह करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। इङ्गलैंड ने इस दायित्त्व को भली-भांति निभाया है और अब हमारे पींड पावने धीरे-धीरे जनात हो रहे है।

## युद्धोत्तर काल सन् १९४४-४६-{९४८-४६

भारतीय चलन पद्धति की युद्धकालीन प्रवृत्तियाँ युद्धोत्तर काल में भी बनी रहीं ग्रीर इस काल का इतिहास साधारएतया पुराने ही इतिहास का एक अगला पृष्ठ है। चलन पद्धति के सम्बन्ध में भारत की प्रमुख घटनाएँ मृद्रा-कोप की सदस्यता, भारत सरकार की मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति, रुपये का अवमूल्यन, रिजर्ब बैंक और इन्नीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरएा, व्यापाराशेष का सन्तुलन, कीमतों में धर्मा की प्रवृत्ति और हीनार्थ प्रबन्ध (Deficit Financing) है। इसी काल में दो और भी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं, अर्थात पाँड पावनों का भुगतान और भारत की पच-वर्षीय योजनाएँ। प्रथम योजना के आरम्भ में यह अनुमान लगाया गया था कि इस मद से २६० करोड़ रुपये निकाल जायाँगे। वास्तव में पाँड पावनों का उपयोग बहुन कम हो पाया है और दूसरी योजना में इस मद से लगभग २०० करोड़ रुपया निकाल लेने का अनुमान है। प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है:—

#### (1) रुपये का अवमूल्यन और उसके प्रभाव-

भारतीय रुपए के भ्रवमूल्यन का संक्षिप्त भ्रध्ययन भ्रध्ययन द में किया जा चुका है। प्रस्तुत भ्रध्याय में इसके परिगामों का विस्तृत भ्रध्ययन किया जायगा। १८ सितम्बर सन् १९४६ को ब्रिटिश सरकार ने भ्रकस्मात् ही स्टर्निंग का भ्रवमूल्यन कर दिया, जिसके कारण उसका डालर मूल्य ४.०३ डालर प्रति पौंड से घटकर केवल २.८० डालर रह गया। ब्रिटेन ने यह निर्गाय इतनी बीध्रतापूर्वक किया था कि राष्ट्रमन्डल (Common wealth) देशों को इसका पहले से कुछ पता नहीं लग पाया था। ब्रिटेन ने भ्रवमूल्यन प्रधानतया इस कारण किया था कि डालर देशों के साथ उसके व्यापाराशेष का घाटा बहुत ही भ्रधिक था। सन् १९४६ में इस घाटे का भ्रनुमान ६० करोड़ पौंड प्रति वर्ष लगाया गया था। इस घाटे को पूरा करने के लिये लगभग सभी प्रयत्न भ्रसफल रहे थे। विवश होकर इङ्गलैंड ने घाटे को दूर करने के लिए एक मात्र उपाय के रूप में स्टर्लिङ्ग का भ्रवमूल्यन कर दिया।

स्टॉलिंग के अवमूल्यन ने भारत सरकार के सम्मुख एक बड़ी जटिल समस्या उपस्थित कर दी, जिसने उसे शीघ्रतापूर्वक अवमूल्यन के सम्बन्ध में निर्णय करने पर बाध्य किया। रुपये और स्टॉलिंक्ज का सम्बन्ध इतना पुराना हो चुका था कि उसे अकस्मात् ही तोड़ देना सरल न था। भारत सरकार को यह भय था कि अवमूल्यन न करने का उसके विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय रुपये कौ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोई स्वतन्त्र स्थिति प्राप्त न थी। दूसरे, अवमूल्यन न करने से

यह भी भय था कि इससे हमारे पींड पावना ऋ एए की कीमत में श्रिषक व मी ग्रा जायगी। इसके विपरीत अवमूल्यन कर देना भी भय से स्वतन्त्र न था, विशेष कर ऐसी दशा में जब कि देश में पहले से ही मुद्रा-प्रसार था। श्रवमूल्यन के कारए वस्तु श्रों श्रीर सेवा श्रों के निर्यात बढ़ जाते हैं, जिससे देश में वस्तु श्रों श्रीर सेवा श्रों की कमी श्रीर भी बढ़ जाती। बहुत सोच-विचार के पश्चात् भारत सरकार ने श्रवमूल्यन का ही निर्णाय किया, यद्यपि पड़ौसी देश पाकिस्तान ने यह निश्चय किया कि श्रवमूल्यन नहीं किया जायगा।

बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत का निर्णय ठीक ही था:-

- (१) व्यापाराशेष की स्थिति में सुधार—श्री चिन्तामिए देखमुख का विचार है कि सन् १६४६ के पश्चात् हमारे व्यापाराशेष में जो सुवार हुआ उसका प्रमुख कारए अवसूल्यन ही है। सितम्बर सन् १६४६ और जून सन् १६४० के बीच के काल में व्यापाराशेष का घाटा १७२ करोड़ रुपया कम हो गया था, परन्तु वास्त-विकता यह है कि इस सुधार का एकमात्र कारएा अवसूल्यन ही नहीं था, प्रत्युत आयातों पर लगाये हुए प्रतिबन्ध भी थे। सन् १६५०-५१ में तो व्यापाराशेष का घाटा केवल ४ करोड़ रुपया ही रह गया, परन्तु अगले वर्षों में घाटे में फिर वृद्धि हुई और सन् १६५२-५३ में यह २३२'६२ करोड़ रुपये तक पहुँच गया। हाल के वर्षों में घाटे की वृद्धि का प्रमुख कारएा यह रहा है कि कोरिया की लड़ाई के उपरान्त व्यवसायिक मन्दी आरम्भ हो गई और कच्चे मालों की कीमतों के गिरने के कारए हमारा निर्यात व्यापार अधिक कम हो गया। सन् १६५६-५७ के वर्ष में व्यापाराशेष का घाटा २४० करोड़ रुपया रहा था। सम्पूर्ण स्टॉलङ्ग क्षेत्र को तो अवसूल्यन से लाभ ही हुआ है। भारत के व्यापाराशेष का घाटा डालर देशों के साथ सन् १६४६ में ५३ करोड़ के बराबर था, परन्तु सन् १६५० में इसके विपरीत उसे २६ करोड़ रुपये की बचत रही थी।
- (२) ग्रान्तरिक मूल्य-स्तर में उठान—ग्रवमूल्यन के पश्चात् कीमतें ऊपर उठनी शुरू हुई। सितम्बर में सन् १९४६ में थोक कीमतों का निर्देशांक ३६० था, जो अप्रैल सन् १९५१ में ४५ द तक पहुँच गया था, परन्तु अप्रैल सन् १९५१ में ४५ द तक पहुँच गया था, परन्तु अप्रैल सन् १९५३ में यह गिर कर फिर ३४३ पर आ गया था और तब से फिर इसकी प्रवृत्ति गिरने की ओर ही रही थी। यद्यपि सितम्बर सन् १९५६ से अब तक कीमतें फिर निन्तर बढ़ रही हैं।
- (३) भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक सम्बन्धों में खिचाव— अवमूल्यन का एक बड़ा परिणाम भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक सम्बन्धों के खिचाव के रूप में भी प्रकट हुआ। अवमूल्यन न करने के कारण पाकिस्तानी रुपये की कीमत २ शिलिंग १'६ पेंस या १'४४ भारतीय रुपये के बरावर हो गई। भारत सहकार ने पाकिस्तानी रुपये की इस नई दर को स्वीकार करने से अस्वीकार कर

दिया, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच व्यापार स्थिगत हो गया, परन्तु जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप ने पाकिस्तानी रुपये की इस नई दर को स्वीवार कर लिया तो भारत सरकार ने भी सन् १६५१ में इस दर पर पाकिस्तान से एक लम्बा-बौड़ा व्यापार समभौता कर लिया। सब कुछ होते हुए भी दोनों देशों वा पारस्परिक व्या-पार उन्नति न कर सका। यह स्थिति अब तक भी बनी हुई है, यद्यपि अब पाकिस्तान ने भी अपने रुपये का अवसूल्यन कर दिया है।

- (४) डालर देशों से निर्यात व्यापार में वृद्धि—विगत वर्षों में डालर देशों से हमारा निर्यात व्यापार बरावर बढ़ता गया है और व्यापाराशेष में सन्तुनन ही नहीं, ग्राधिक्य की भी थोड़ी सी प्रवृत्ति है। एक बड़े ग्रंश तक यह स्थिति प्रवमूल्यन का ही परिगाम है, यद्यपि इस पर ग्रन्य वातों का भी प्रभाव पड़ा है।
- (५) पौंड पावने के मूल्य में कमी—भारत ने ब्रवमूल्यन के पश्वात् अपने पौंड पावनों का जितना भाग डालर क्षेत्र में व्यय किया उसका मूल्य ० ५०० कम हो गया।
- (६) विदेशी ऋगों के भार में वृद्धि—भारत ने विश्व वेंक से जो ऋगा लिया है उसका रुपया-मूल्य अवमूल्यन के कारण वढ़ गया है।
- (७) ग्राथिक विकास में वाधा देश के ग्राथिक विकास के लिए हम डालर क्षेत्र से मुख्यतः पूँजीगत वस्तुयें मँगाते हैं। इनके लिये हमें ग्रय ३० ५०% ग्राधिक देना पड़ता है। इस प्रकार हमें विवश होकर अपनी कुछ विकास योजनायें स्थागत करनी पड़ी हैं।

यद्यपि श्रव श्रवमूल्यन श्रौर उसकी वांछनीयता से सम्बन्धित वाद-विवाद पुराना पड़ चुका है, किन्तु फिर भी कभी-कभी रुपए के पुनमू क्यन के प्रश्न को उठा कर इसे फिर से जीवित कर दिया जाता है।

(II) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना और रुपया-स्टर्लिङ्ग का सम्बन्ध विच्छेद---

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्धोत्तर काल की सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण मौद्रिक घटनाएँ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुर्नानर्माण और विकास बैंक की स्थापना है। मुद्रा-कोष ने मार्च सन् १६४७ से अपना कार्य आरम्भ कर दिया। भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-परिषद् के सम्मुख, जिसकी सिफारिशों के फलस्वरूप उपरोक्त दोनों संस्थाएँ स्थापित हुई थीं, दो प्रस्ताव रखे थे:—एक तो, यह कि उसे मुद्रा-कोष की कार्यकारिग्णी में एक स्थाई जगह दी जाय और दूसरी, यह कि पौंड-पावना ऋग्ण का भुगतान मुद्रा-कोष के कार्यों में सम्मिलित कर लिया जाय। परिषद् ने दोनों ही प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये थे, अतः भारत में काफी लम्बे समय तक वाद-विवाद चलता रहा है कि मुद्रा-कोष की सदस्यता ग्रहग्ण करना कहाँ तक उपयुक्त था, परन्तु अन्त में भारत सरकार ने मुद्रा-कोष की योजना में सम्मिलित होकर उसकी प्रारम्भिक सदस्यता प्राप्त

कर ली। भारतीय निर्णय पर सबसे बड़ा प्रभाव इस बात का पड़ा था कि मुद्रा कोष की सदस्यता के द्वारा विश्व बैंक की सदस्यता का ग्रवसर मिलता था।

मुद्रा-कोप की सदस्यता के कारण भारत सरकार को रुपये की कीमत स्वर्णं में घोपित करनी पड़ी। द अप्रैल सन् १९४७ की रुपये और स्टर्लिंग का वैधानिक सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया और रुपए की कीमत स्वतन्त्र रूप में ० २६६६०१ ग्राम सोना रखी गई। परन्तु स्मरण रहे कि स्वर्णं में रुपए की यह कीमत १ शिलिंग ६ पैंस प्रति रुपया की विनिमय दर के ग्राधार पर ही निर्धारित की गई थी। व्यवहार में रुपये और स्टर्लिङ्ग का पुराना गठबन्धन पहले की भाँति ही बना रहा है।

# (III) रिजर्व वैंक और इम्पीरियल वैंक का राष्ट्रीयकरण-

रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की माँग बहुत पुरानी है। जब इस बैंक की स्था-पना पर विचार ही किया जा रहा था तो उस समय भी कुछ लोगों ने ग्रारम्भ से ही इसे एक सरकारी बैंक के रूप में खोलने के सुभाव दिये थे, परन्तु सन् १६३४ के एक्ट में बैंक को एक व्यक्तिगत बैंक के रूप में स्थापित करने का निश्चय किया गया। सन् १६४६-४७ में इसके राष्ट्रीयकरण की माँग फिर रखी गई ग्रौर अन्त में सन् १६४७-४० के बजट में राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था को सम्मिलित कर लिया गया ग्रौर १ जनवरी सन् १६४६ से रिजर्व बैंक एक राष्ट्रीय संस्था बन गई। ग्रंशधारियों के अंश सरकार ने खरीद लिए ग्रौर प्रत्येक १०० रुपये के ग्रंश के बदले ११८ रुपये १० ग्राने देना स्वीकार किया। इस राशि का भुगतान इस प्रकार किया गया कि १८ रुपये १० ग्राने तो नकद दे दिये गये ग्रौर ग्रगले १०० रुपये के लिए ३% ब्याज का सरकारी बाँड (Bond) दे दिया गया। राष्ट्रीयकरण के साथ ही साथ बैंक सम्बन्धी नियमों में भी श्रावश्यक संशोधन कर दिये गये।

पहले रिजर्व बैंक का यह कर्त्त व्य था कि वह निश्चित दरों पर रुपये के बदलें में स्टर्लिङ्ग खरीदा और बेचा करती थी, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की सदस्यता के पश्चात् यह स्थिति बदल गई और बैंक सम्बन्धी नियमों में ऐसा परिवर्तन कर दिया गया है कि मुद्रा-कोष द्वारा निश्चित दरों पर रिजर्व बैंक रुपये के बदले में कोई भी विदेशी मुद्रा खरीद और बेच सकती है।

इम्पोरियल वंक के राष्ट्रीयकरएा की माँग भी श्रन्त में स्वीकार कर ली गई श्रोर उसे १ जुलाई सन् १९५५ से सरकारी श्रधिकार में ले लिया गया है। श्रव उसका नया नाम स्टेट बैङ्क श्रॉफ इण्डिया है। राष्ट्रीयकरएा के पश्चात् इसका सङ्गठन एक नये श्राधार पर किया गया है।

### (IV) व्यापाराशेष का सन्तुलन श्रौर कीमतों की कमी-

सन् १६४८ तथा उसके पहले काल में भारत का व्यापाराशेष अधिक असन्तु-लित रहा है। युद्धोत्तर काल में देश में खाद्यान्न की भारी कमी को दूर करने और मुद्रा प्रसार की स्थिति को सुधारने के लिए आयातों के सम्बन्ध में उदारता की नीति अपनाई गई थी। साथ ही, देश के आधिक जीवन की उन्नति तथा चालू विकास योजनाओं की सफलता के लिए भी सरकार को मशीनरी, आवश्यक कच्चे माल तथा अन्य वस्तुएँ विदेशों से मँगानी पड़ी थीं। यही कारएा है कि भारत को व्यापारानेष पर घाटा होने लगा, यद्यपि युद्ध-काल में वरावर वचत हो रही थी। सन् १६४६ में अवभूल्यन के पश्चात् इस स्थिति में कुछ नुधार हुआ और अगले वर्ष अर्थात् सन् १६५० में डालर देशों के साथ होने वाल व्यापार में थोड़ी सी बचत हुई। भारत सरकार ने आयातों पर प्रतिबन्ध लगाना तथा निर्यातों को प्रोत्साहन देना आरम्भ कर दिया। वर्तमान स्थिति यह है कि कोरिया युद्ध समाप्त होने के पश्चात् कीमतें फिर गिरी हैं और सन् १६५३ में हमारा व्यापाराशेष फिर प्रतिकृत हो गया था। सन् १६५३-५४ में भी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हो पाया है। वाद के वर्षों में यह घाटा कम होता गया है। मार्च सन् १६५६ में इसका अनुमान केनल ६२ लाख रुपया था। सितम्बर सन् १६५६ का अनुमान यह है कि घाटे की मात्रा बहुत वढ़ गई है और ६ महीने में ३५५ करोड़ रुपये हैं। दूसरी योजना के काल में घाटा फिर वराबर बढ़ रहा है।

विगत वर्षों की एक महत्त्वपूर्ण घटना कीमतों में बढ़ने की एक सामान्य प्रवृत्ति रही है। सन् १९५०-५१ में बचत का बजट बनाने का कार्य ग्रारम्भ हो गया था ग्रौर ग्रमरीका से प्राप्त हुग्रा गेहूँ भारत ने बेच दिया था। इसके ग्रितिरक्त सन् १९५१ में रिजर्व बेंक ने दैंक दर को ३% से बढ़ा कर ३५% कर दिया था। इन सबका परिग्णाम यह हुग्रा था कि सोने ग्रौर चाँदी की कीमतों में भारी परिवर्तन हुए। मार्च सन् १९५२ में सोने की कीमत ११४ रुपये प्रति तोला से घट कर ७७ रुपए पर पहुँच गई। इसी प्रकार मार्च सन् १९५१ ग्रौर सन् १९५२ के बीच चाँदी की कीमतों १९६५ रुपया प्रति तोला से गिरकर १९३६ रुपया प्रति तोला रह गई। राष्ट्रीयकरण के परचात् रिजर्व बेंक साख तथा कीमतों के नियन्त्रण का कार्य ग्रधिक सप्रभाविक रीति से कर रही है। दूसरी पंच-वर्षीय योजना में सरकार ने कीमतों की स्थिरता बनाये रखने की नीति ग्रपनाई है। योजना में हीनार्थ प्रबन्व के कारण मुद्रा-प्रसार का भय है। भागत सरकार की नीति यह भी है कि योजना काल में कृषि उपज की कीमतों को घटने न दिया जाय, चाहे इसके लिए कृष्टिम उपाय ही क्यों न किए जाएँ। दूसरी योजना के काल में कीमतों निरन्तर ऊपर की ग्रोर जा रही हैं ग्रौर मुद्रा-प्रसार का भय पुनः सम्मुख है।

## (V) पौराड पावना ऋरा का भुगतान-

युद्धोत्तर काल की एक महत्त्वपूर्ण घटना ब्रिटिश सरकार द्वारा पौण्ड पावना ऋगा का भुगतान भी है। समय-समय पर किये गये समभौते इस प्रकार हैं:—

(ग्र) जनवरी सन् १६४७ का समभौता—ग्रारम्भ में भारत ग्रौर ब्रिटेन मु०च०ग्र०, (३२)

के बीच जनवरी सन् १९४७ में यह समभौता हुन्ना कि भारत अपनी आवश्यकता की वस्तुए रिटिल क्षेत्र से खरीद सकता था और यदि उसे डालर क्षेत्र से भी वस्तुए मैंगाने की आवश्यकता पड़े, तो वह पौंड पावनों को डालर में परिवर्तित कर सकता था। परन्तु शीघ्र ही इङ्कलैंड और अमरीका के बीच एक नवीन आर्थिक समभौता हो गया, जिसने स्थिति में इतना परिवर्तन कर दिया कि उपरोक्त समभौते के अनुसार कार्यन हो सका।

(ग्रा) ग्रगस्त सन् १६४७ का समभौता—१४ ग्रगस्त सन् १६४७ को भारत और इङ्गलैंड के बीच एक नया समभौता हुग्रा, जिसके ग्रनुसार हमारे पौंड पावनों के दो खाते खोले गये:—प्रथम, चालू, खाता और दूसरा स्थिर खाता। चालू खाता ६६ ६ करोड़ रुपए से खोला गया, जिसमें से केवल ३ करोड़ रुपए दुर्लभ मुद्रा की प्राप्ति के लिए किया जा सकता था। नये पौण्ड पावनों की कमाई भी इसी में जमा होनी थी। स्थिर खाते में शेष १,४६६ ६ करोड़ रुपए जमा किये गये। इसका उपयोग विदेशी पूँजी, प्रावीडेन्ट फण्ड ग्रौर पैंशन ग्रादि का भ्रुगतान करने के लिए किया जायगा। परन्तु कोई निश्चित ग्रायात योजना न होने के कारण भारत इस काल में पूरी राशि को निकालने में ग्रसमर्थ ही रहा।

- (इ) जुलाई सन् १९४८ का समभौता—पहिले समभौते का प्रन्त होते ही एक नवीन समभौता किया गया, जिसकी शर्ते १५ जुलाई सन् १९४८ को प्रकाशित की गई। इस समभौते की प्रमुख व्यवस्थाएँ इस प्रकार थीं:—
  - (१) अप्रैल सन् १६४७ को भारत सरकार ने इङ्गलैंड द्वारा छोड़े हुए कुल फौजी सामान को अपने अधिकार में ले लिया। इसकी कीमत १३३'३ करोड़ रुपया तय की गई और यह राशि हमारे पौंड पावनों में से घटा दी गई। इस प्रकार इस माल की कीमत का भुगतान हमने अपने पौंड-पावना ऋगा में समायोजन करके कर दिया।
  - (२) भारत सरकार द्वारा इङ्गलैंड को पुराने ग्रंगरेज ग्रधिकारियों के उत्तर-वेतन के रूप में जो राशि दी जाती थी उसके चुकाने के लिए भारत सरकार ने इङ्गलैंड की सरकार से एक वार्षिकी (Annuity) खरीद ली। इस प्रकार व'र्षिकी के रूप में इन उत्तर-वेतनों का मूल्य १६। करोड़ रुपया निश्चित किया गया। यह राशि भी पौंड पावनों में से निकाल दी गई। इसी प्रकार प्रान्तीय सरकारों के ग्रधिकारियों के उत्तर-वेतनों की वार्षिकी की कीमत २७ करोड़ रुपया तय हुई, ग्रत २२४ करोड़ रुपया इस मद पर पौण्ड पावनों में से कम किया गया।
  - (३) पिछले समभौते के अनुसार भारत को १६१ करोड़ रुपयों के पौंड पावने लेने का अधिकार मिला था, परन्तु वास्तव में केवल ४ करो। रुपयों का ही माल लिया गया। नये समभौते में भारत सरकार कं

शेष १०७ करोड़ रुपये के पींड-पावने निकालने का अधिकार फिर से दे दिया गया । इनके अतिरिक्त अगले ३ वर्षो अर्थात् ३० जून सन् १६५१ तक इङ्गलैंड ने इतनी ही कीमत के पींड-पावने और देने का वचन दिया । इस प्रकार हमें तीन साल के भीतर कुल मिला कर २१४ करोड़ रुपए निकालने का अधिकार दिया गया । इस समभौते के समय पीण्ड पावना ऋरण की कुल कीमत १,५५० करोड़ रुपया आंकी गई थी, जिसमें से १३३ करोड़ रुपया फीजी सामानों, २१४ करोड़ रुपया उत्तर-वेतनों की वार्षिकी तथा १२६ करोड़ रुपया पाकिस्तान के हिस्से के रूप में निकाल दिया गया था । इस प्रकार कुल १,०६७ करोड़ रुपए के पींड-पावने वचे थे, जिसमें से २१४ करोड़ रुपए की राशि अगले तीन वर्षों में निकाली जा सकती थी ।

समफौते में यह भी तय किया गया कि एक वर्ष में केवल २० करोड़ रुपए की राशि ही डालर तथा दूसरी दुलंभ मुद्राओं में ली जा सकती थी।

- (ई) जुलाई सन् १६४६ का समभौता—उपरोक्त समभौते के जीवन-काल में ही एक नए समभौते की ग्रावश्यकता ग्रनुभव हुई, क्योंकि विटेन के पास डालर का ग्रामाव ग्रिषक था। इस समभौते में भारत को सन् १६४०-४६ के लिए प्रति वर्ष ५ करोड़ पौंड दिए गये ग्रौर सन् १६४६-५० तथा सन् १६५०-५१ के लिए प्रति वर्ष ५ करोड़ पौंड मिलना निश्चित हुना। इसके ग्रातिरक्त खुली ग्रनुज्ञापन व्यवस्था (Open General License) के ग्रन्तर्गत मंगाये गये पिछले माल की कीमत चुकाने के लिए ५ करोड़ पौंड ग्रौर दिये गये। डालर की कमी को दूर करने के लिए भारत को केन्द्रीय कोष (Central Reserves) में से १४ या १५ करोड़ डालर लेने का ग्रावकार दिया गया ग्रौर यह भी ग्राज्ञा मिली कि वह विश्व बेंक से डालर ऋण लेकर कितना भी माल खरीद सकता था, परन्तु भारत सरकार से यह वचन ले लिया गया कि ग्रगले वर्षों में भारत सरकार ग्रपने डालर ग्रायातों में २५% की कमी कर देगी। इस समभौते की शर्तें भारत के हिष्टकोण से काफी उदार थीं, जिसके कारण इङ्गलैंड में वहाँ की लेबर सरकार की ग्रालोचना भी हुई थी।
- (उ) सन् १६५२ का समभौता— क फरवरी सन् १६५२ की अन्तिम जाँच के परचात् यह ज्ञात हुआ था कि उस समय हमारे पास ५७ करोड़ पाँड अथवा ७६१ करोड़ रुपयों के पाँड-पावने शेष रहे थे। उस समय ब्रिटिश सरकार से एक नया समभौता किया गया, जिसके अनुसार यह निश्चय हुआ कि ३० जून सन् १६५७ तक ब्रिटिश सरकार प्रति वर्ष ३ ५ करोड़ पाँड चुकायेगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गई है कि ६१ करोड़ पाँड की एक ऐसी राशि खाता नं० १ में रखी जायगी जिसे भारत केवल संकट-काल में ब्रिटिश सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके निकाल सकेगा। व्यवस्था इस प्रकार थी कि इस समभौते की अविध समाप्त होते ही सन्

१९५७ में शेष राशि के लिए नया समभौता किया जाय। प्रथम पंच-वर्षीय योजना में भारत सरकार ने पौंड-पावना खाते से २६० करोड़ की राशि निकाल कर योजना-काल म्रर्थात् सन् १९११-५६ में योजना पर व्यय करने का निश्चय किया था । वास्तव में बहुत ही कम राशि प्रथम योजना काल में इस मद में से निकाली गई थी। जून सन् १९५४ में ७४४ करोड़ रुपए के पौंड पावने शेष थे, जिसके स्राधार पर सन् १६५५-५६ में भी कोई ७४८ करोड़ रुपए की राशि इस मद में बची हुई थी। दूगरे पंच-वर्षीय आयोजन में इस मद से २०० करोड़ रुपए को राशि निकाल लेने का म्रनुमान है।

पिछले वर्षों में रिजर्व वेंक्र के पास पौंड-पावने की रकम के खाते में निम्न शेष रहे हैं :--

मार्च	सन	१६५२	७२३	करोड़	रुपये
		१९५३	७२५	,,	,,
मार्च	सन्	-	७४४		
जून	सन्	१९५४		;;	"
दिसम्बर	सन्	१९५५	७३५	"	"
मार्च	सन्	<b>१</b> ९५६	<b>७</b> ४६	7.7	33
नवम्बर	सन्	१९५६	४४३	12	77
जनवरी	सन्	१९५७	प्ररह	22	22
मई	सन्	१९५७	४६९	"	- 22

इस प्रकार भ्रभी तक हमारे पौंड-पावना खाते में काफी रकम शेष है। स्मरण रहे कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना के काल में पाँच वर्षों में इस खाते में २०० करोड़ रुपये की राशि को निकालने का प्रस्ताव है, जिस ग्राधार पर लगभग ४० करोड़ रूपये की राशि प्रति वर्ष निकाली जायगी। वास्तिविकता यह है कि हम ग्रपने पौंड-पावने शेषों का भन्नी-भाँति उपयोग नहीं कर पाये हैं। प्रथम योजना वाल में निर्घारित २६० करोड़ रुपये की राशि निकालने के स्थान पर केवल ४३ करोड़ रुपये की राशि निकाली . गई थी । दूसरी योजना के प्रथम ३ वर्षों का ग्रनुभव भी कुछ इसी प्रकार का है ।

# (VI) भारत विभाजन का मुद्रा व चलन पर प्रभाव—

१५ म्रगस्त सन् १६४७ को स्वतन्त्रता के साथ-साथ भारत का भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में बँटवारा हो गया । इस बँटवारे में देश की चलन का भारत ग्रीर पाकिस्तान में १३ और ३ के अनुपात में विभाजन किया गया। विदेशी ऋर्गों के भुगतान की समस्त जिम्मेदारी भारत ने अपने ऊपर ली और पाकिस्तान ने अपने हिस्से की राशि भारत को किश्तों में चुकाने का वचन दिया, परन्तु पाकिस्तान है वायदा पूरा करने की ग्रभी तक तो कोई श्राशा नहीं हो पाई है, उस देश का सामान ध्यवहार शत्रुता का है भौर वह उचित तथा भ्रनुचित रीति से भारत को हानि पहुँचान चाहता है। ग्रविभाजित भारत के ऋगा को चुकाने का उत्तरदायित्व भारत ने ग्रपने कपर लिया था, परन्तु पाकिस्तान ने ग्रभी तक भी श्रपने हिस्से की किश्त नहीं चुकाई है। इसके ग्रतिरिक्त पाकिस्तान को जो पानी ग्रौर विजली सप्ताई की गई है उसकी कीमत भी उसने नहीं चुकाई है।

## (VII) भारतीय रुपये के पुनमू ल्यन का प्रश्न (Revaluation)-

१६ सितम्बर १६४६ को स्टिंतिंग और रुपये का तया अन्य स्टिंतिंग क्षेत्रीय मुद्राभ्रों का अवमूल्यन किया गया था। इसके एक वर्ष वाद ही रुपये के पुनर्मुल्यन की चर्चा होने लगी। पुनर्मुल्यन के पक्ष एवं विपक्ष में निम्न तर्क दिये गये थे:—

## पुनम् ल्यन के पच में तर्क-

पिछले कुछ दिनों से कुछ व्यक्तियों ने यह विचार प्रकट िया है कि भारतीय हिपये का पुनम् ल्यन करके उसकी विदेशी कीमत में वृद्धि करनी चाहिए। इस मत के पक्ष में निम्न तकं प्रस्तृत किये जा सकते हैं—

- (१) ग्रायात वस्तुत्रों के मूल्य में कमी होगी—इसके द्वारा ग्रावश्यक श्रायातों, जैसे— खाद्यान्न, मशीनों ग्रौर जरूरी कचे मालों की कीमत घट जायगी।
- (२) निर्यात व्यवहार बढ़ेगा-—इससे हमारे निर्यातों का पहले से अधिक मूल्य प्राप्त होगा। इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि हमारे अधिकांश निर्यात ऐसे हैं कि उनकी मांग लगभग बेलोच है और कीमतों की वृद्धि के कारण उनकी मांग में कोई विशेष कमी हो जाने का भय नहीं है।
- (३) स्रान्तरिक मूल्य-स्तर में कमी—यह कहा जाता है कि सन् १६४६ में रुपये के अवमूल्यन के कारण देश में कीमतें ऊपर चढ़ गई थीं। पुनमूं ल्यन द्वारा ये कीमतें फिर नीचे गिर जायेंगी।
- (४) पाकिस्तान से सम्बन्धों में सुधार—इससे भारत बौर पाकिस्तान के व्यापारिक, ग्राधिक तथा राजनैतिक सम्बन्ध सुधर जार्येगे ग्रौर दोनों को ग्राधिक विकास का ग्रन्छ। ग्रवसर प्राप्त होगा।
- ( ५) मुद्रा प्रसार पर रोक—ऐसा कहा जाता है कि यदि देश में मुद्रा-प्रसार को नहीं रोका जाता है तो हमारी आर्थिक विकास योजनाओं के संवालन में कठिनता होगी, क्योंकि इसके कारए। एक और तो देश के भीतर औद्योगिक ध्रुंसम्बन्धों में तनाव बना रहेगा और दूसरे, इसके कारए। मशीनों, स्थिर यन्त्रों तथा कच्चे मालों की कीमत ऊँची हो जायगी, जिससे सरकारी तथा व्यक्तिगत योजनाओं का संवालन कठिन हो जायगा। साथ ही, यह भी कहा जाता है कि कीमतों की स्थिरता को बनाये रखना स्वयं योजना की सफलता के लिए भी आवश्यक है। योजना के अन्तर्गत जो व्यय किया जा रहा है वह स्वयं ही स्फीतिक प्रवृत्तियाँ रखता है।

संक्षेप में, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि रुपये का पुनमूं ल्यन देश की मान्तरिक ग्रर्थ-व्यवस्था की रक्षा हेतु उपयुक्त बताया जाता है और मान्यता यह है कि इसका देश की बाह्य ग्रर्थ-व्यवस्था पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## पुनमू ल्यन के विपत्त में तर्क-

पुनमूं त्यन के आलोचकों के तर्क भी महत्वपूर्ण हैं, जोकि निम्न प्रकार हैं:-

- (१) आयात वस्तुओं के मूल्य में कमी आना आवश्यक नहीं है—
  हपये की मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप आयात की वस्तुओं में जो कमी होने की आशा की
  जाती है उसका होना आवश्यक नहीं हैं, क्योंकि विदेशी निर्यातकर्ता उनकी कीमतों
  में वृद्धि कर सकते हैं अथवा देशी आयातकर्ता ऐसा कर सकते हैं। जिन अधिकांश
  आवश्यक वस्तुओं का भारत द्वारा आयात किया जाता है ( जैसे खादान्न, मशीनरी
  आदि ) उनकी पूर्ति माँग से कम है और उनकी बिक्री साधारएत्या एकाधिकारी संघों
  द्वारा की जाती है। भारत के साथ मूल्य-विभेद सम्भव है। यह कहना अनुपयुक्त न
  होगा कि हमारे आयातों की समस्या उनकी ऊँची कीमत की समस्या नहीं है, बिक्रः
  उनके मिल जाने की समस्या है।
- (२) अन्य देशों के प्रतिरोध का भय—भारत द्वारा पुनर्मू ल्यन का परिगाम यह हो सकता है कि प्रतिरोध में पाकिस्तान, लङ्का, बर्मा आदि भी ऐसा ही करें।
- (३) निर्यात में कमी होने का भय—यह समभना भी भूल होगी कि हमारे श्रविकांश निर्यातों की माँग बेलोच है। कुछ वस्तुओं, जैसे मैंगनीज श्रीर श्रवरक मे तो हमें एक बड़े श्रंश तक एकाधिकार अवश्य प्राप्त है, परन्तु अन्य सभी में काफी प्रतियोगिता है। जूट के माल की कीमतों को भी बहुत ऊँचा कर देना सम्भव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी प्रतियोगिता के अतिरिक्त स्थानापन्नों का प्रचलन बढ़ जाने का भय है। चाय के विषय में भी ऐसा ही कहा जा सकता है।
- (४) व्यापाराशेष का घाटा भारत के भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्रो चिन्ता-मिए देशमुख ने लोक सभा में बताया था कि उनके श्रनुमानों के श्रनुसार यदि रुपये की कीमत में १५% की भी वृद्धि की गई तो इसके कारए देश के व्यापाराशेष का घाटा ५० करोड़ रुपया हो जायगा श्रीर यदि वृद्धि ३०% होती है तो घाटे की मात्रा १३५ करोड़ रुपये तक पहुँच जायगी।
- (५) राष्ट्रीय सम्मान को चोट—समय-समय पर थोड़ा सा लाभ उअने के लिए विनिमय दर में परिवर्तन करना दीघंकालीन हिष्टकोएा से बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय सम्मान को चोट लगती है। जहाँ तक पूनमूं ल्यन द्वारा निर्यात से लाभ प्राप्ति का प्रश्न है, वह तो निर्यात कर से भी प्राप्त किया जा सकता है।
- (६) स्टॉल इक्षेत्र के देशों से स्पर्धा में बृद्धि—यदि केवल भारत ही रुपये का पूनमू ल्यन करता है, तो वह निर्यात व्यापार में स्टॉल इक्ष के क्षेत्र के मन्य देशों के साथ स्पर्धा नहीं कर सकेगा। इससे उसका निर्यात व्यापार स्टॉल इक्षेत्र में व मिरिका में भी कम हो जायगा।

(७) खुद्रा-प्रसार रोकने के अन्य साधन भी हैं—मुद्रा-प्रसार के हुष्प्रभावों को दूर करने का एक मात्र उपाय काये का पुतर्मू ल्यन हो, ऐसी बात नहीं है। वरन इसके अन्य उपाय भी हैं, जैसे बचत को विकसित करना, करों में बृद्धि, मूल्य नियन्त्रए। आदि। अतः जब चाहे तद विनिमय दर से खिलवाड़ करना नहीं चाहिए।

श्री देशमुख ने कड़े र.वरों में पुनमू ल्यन का विरोध किया था। उनका विचार था कि हमारे लिए इस समय विदेशों मुद्राओं का प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि हमारे व्यापाराशेष के सन्तुलन के अतिरिक्त आवश्यक आयातों का अभाव भी दूर हो जाय, परन्तु विदेशों विनिमय प्राप्त करने का एक मात्र उपाय यही है कि निर्यात बढ़ाये जायें और इसकें लिए पुनमू ल्यन वाँछनीय नहीं है। पिछले कुछ समय से तो देश में बस्तुओं की कीमतें फिर बढ़ने लगी है और इसलिये पुनमू ल्यन का महत्त्व बहुत ही कम रह गया। श्री देशमुख ने सरकारी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था:— "अभी हम पुनमू ल्यन न करने का निश्चय कर चुके हैं, क्यों कि देश का हित इसी में है, परन्तु इस निर्णय को अन्तिम तथा स्थाई नहीं कहा जा सकता है। यदि परिस्थितियों में अनुकूल परिवर्तन होते हैं तौ सम्भव है, भविष्य में हमें इस पर विचार करना पड़े।"

इस समय तो स्थिति बिल्कुल ही बदल गई है। ग्रव तो सरकार की नीति कृषि उपज की कीमतों में कमी रोकने की है। पाकिस्तान ने ग्रपने राये का पुनमूं ल्यन करके भारतीय रुपये के पुनमूं ल्यन की ग्रावश्यकता लगभग समाप्त ही कर दी है। (VIII) ग्राधिक नियोजन और हीनार्थ-प्रवन्धन (Economic Planning and Deficit Financing)—

सन् १६५१ से भारत में ग्रांथिक नियोजन को कार्यशील किया गया है। प्रथम पंच-वर्षीय ग्रायोजन में कुल विकास व्यय २,२४६ करोड़ रुपया रखा गया था। सरकार का ऐसा ग्रनुमान था कि इस व्यय का ग्रियंकों से पूरा हो जायगा, परन्तु कुछ ग्रंश व्यक्तिगत बचत तथा इसी प्रकार के दूसरे शीर्षकों से पूरा हो जायगा, परन्तु कुछ ग्रंश तक घाटे के बजटों ग्रीर विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा। ग्रनुमान यह था कि २६० करोड़ रुपये के हीनार्थ-प्रबन्धन से काम चल जायगा ग्रीर लगभग १६५ करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की ग्रावश्यकता पड़ेगी। इस हीनार्थ-प्रबन्धन के कारण किसी विशेष कठिनाई ग्रथवा भय का ग्रनुमान नहीं लगाया गया था, क्योंकि इस राशि के पौंड पावना मद से प्राप्त होने की ग्राशा थी। बाद के ग्रनुभव से सिद्ध हुग्रा है कि ग्रनुमान गलत थे। ग्राशा के ग्रनुसार ग्राय प्राप्त न होने के कारण घाटा ग्रधिक रहा है। सन् १९५४ के ग्रन्त में ही घाटे का सरकारी ग्रनुमान २५० करोड़ रुपये के लगभग था, यद्यपि गैर सरकारी ग्रनुमान ४००-५०० करोड़ रुपए के ग्रास-पास था। ग्रथम पञ्च-वर्षीय योजना काल में ४०० करोड़ रुपए के ग्रास-पास हीनार्थ-प्रबन्धन हुग्रा है।

दूसरे पंच-वर्षीय ग्रायोजन में सार्वजिनिक क्षेत्र में ४, ५०० करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें से ५०० करोड़ रुपया विदेशी सहायता के रूप में मिलने का ग्रनुमान लगाया गया है। १,२०० करोड़ रुपए के हीनार्थ-प्रबन्धन का ग्रनुमान है ग्रीर ४०० करोड़ रुपये के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस राशि पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि शायद हीनार्थ-प्रबन्धन १,६०० करोड़ रूपए से भी उपर रहेगा। इसमें से कोई २०० करोड़ रुपए की राशि तो पौंड-पावना मद से प्राप्त होने का ग्रनुमान है ग्रीर यदि ४०० करोड़ रुपए का घाटा ग्रन्य सूत्रों से पूरा भी हो जाय तो पाँच वर्ष में फिर भी १,००० करोड़ रुपये के हीनार्थ-प्रबन्धन की ग्रावश्यकता होगी।

यह विषय विवादग्रस्त है कि ही नार्थ-प्रबन्धन के फलस्वरूप की मतों में किस हद तक वृद्धि हुई है। १५ ग्रगस्त सन् १६४७ से ३१ मार्च सन् १६५४ तक ६८१ करोड़ रुपयों का ही नार्थ-प्रबन्धन हुग्रा था। इसमें से २५२ करोड़ रुपया ऐसा था कि उसके कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं हुई थी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस प्रकार की मदों को निकाल देने के बाद भी इस काल में कोई ५० करोड़ रुपए का प्रति वर्ष ही नार्थ-प्रबन्धन रहा है। निम्न तालिका ही नार्थ-प्रबन्धन के प्रभाव को स्पष्ट करती है:—

वर्ष	बजट घाटा (—) बचत (- <del> </del> -)	हीनार्थ-प्रबन्धन	मुद्रा की पूर्ति	थोक कीमतों का निर्देशांक
<u> </u>	<u>११०*६</u> =	१६०-१७	१ <b>६</b> •६४	<u> ग्रगस्त १६३६ = १००</u> ३०५ <sup>,</sup> २
38-28	হংখ্ড	१४७ : ६६	१८ ५४	, ,
9888-40	<del></del> ४३ <b>°</b> ५०	- ६६.३२	१८.६४	३८४.४
१६५०-५१	+ 85.88	- 80.8X	१८.३४	8089
१६५१–५२	+ 0.88	+ २०.08	१७ ६३	४३४"६
१९५२-५३	६३"५४	— ४२ <b>.</b> ७६	१६" द ३	३८० ६
<b>१</b> ६५३–५४	— ४ <b>५</b> °२६	39.08	१७-१५	४.७३६
१९५४-५५	Supherical District Control of the C			३५७'४
१९५५-५६	1		१०"5	३४४.०
१६५६-५७			—	४१६'द

इस प्रकार इसमें तो सन्देह नहीं है कि हीनार्थ-प्रबन्धन नीति के फलस्वरूप मुद्रा की मात्रा तथा कीमतों में वृद्धि है, परन्तु इस प्रकार हमारे देश में इसकी सम्मा-वना स्रधिक नहीं है। योजना कमीशन का अनुमान है कि प्रथम पंच-वर्षीय आयोजन में पाँच वर्षों में ५० करोड़ रुपया प्रति वर्ष का हीनार्थ प्रबन्धन हुआ है, जिसमें से ३५ से ४७ करोड़ रुपए तक के हीनार्थ-प्रबन्धन में मुद्रा-प्रसार की प्रवृत्ति न थी। रिजर्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार प्रथम पंच-वर्षीय आयोजन में घाटा लगभग २५० करोड़ रुपए का ही रहा है। दूसरी पंच वर्षीय योजना के लगभग २०० करोड़ रुया प्रति वर्ष के हीनार्थ-प्रबन्धन की आवश्यकता दिखलाई गई है। यह घाटा और भी बढ़ सकता है, यदि योजना व्यय में ४०० करोड़ हवर के बाटे को पूर्ण करने का कोई दूसरा उपाय सफल नहीं होता।

# दूसरी योजना में हीनार्थ-प्रवन्धन-

दूसरी पंच-वर्षीय योजना के आरम्भ में ही कीमतों ने ऊवर उठना आरम्भ किया। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि दसरी योजना के प्रस्तावित लढ्यों की पूरा करने के लिए अब ४ ५०० करोड़ रुपये के स्थान पर लगभग ५ ५०० करोड़ रुपये की मावश्यकता पडेगी । इस प्रकार वित्तीय घाटा और भी वढ जायगा । उघर हीनार्थ-प्रबन्धन नीति के फलस्वरूप मद्रा-प्रसार का भय भी पैदा हो गया है, जिसकी गम्भीरता इस कारण और भी बढ गई है कि हमारा खाद्यान उत्पादन कार्यक्रम स्रावश्यकतानुसार सफल नहीं हो पाया है। दिसम्बर सन् १९५६ में राटीय विकास परिपद् ने हीनार्थ-प्रबन्धन को घटाने का सुभाव दिया था। परिषद का विचार था कि दूसरी योजना के पहले तीन वर्षों में शायद २५० करोड रुपए प्रति वर्ष के हिसाव मे हीनार्थ-प्रवन्धन निभ जाय किन्तु ततपश्चात मुद्रा-प्रसार का दबाव इतना बढ जायगा कि ग्रीर प्रधिक हीनार्थ-प्रवन्धन शायद उचित न रहे । वास्तविकता यह है कि मार्च सन् १९५८ तक. ग्रर्थात योजना के पहले दो वर्षों में लगभग ६०० करोड रुपये का हीनार्थ-प्रबन्ध हो चका है। सन १९५८-५१ के लिए २०५ करोड रुपए के हीनार्य-प्रवन्ध की व्यवस्था की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हीनार्थ-प्रवन्य से उताल मुद्रा-प्रसार का आरम्भिक दबाव ग्रपना वेग समाप्त कर चुका है। ग्राजा यह है कि जायद भविष्य में नियन्त्रित तथा सीमित हीनार्थ-प्रबन्ध दुखदायी न हो. किन्तु यह ग्राशा इस विश्वास पर ग्राधारित है कि सरकार दूसरी योजना के लिए ग्रन्य सुत्रों से ग्रावश्यक वित्त प्राप्त करने में सफत रहेगी। भ्रव तक योजना की जो प्रगति हुई है उससे तो यही स्पष्ट है कि भ्रन्य सूत्रों से भावश्यक मात्रा में ग्राय प्राप्त न होने के कारण हीनार्थ-प्रबन्धन की ग्रीर ग्रधिक सहायता ली गई है। यही कारण है कि कीमतें भी निरन्तर ऊपर की घोर उठ रही हैं।

#### **QUESTIONS**

What difficulties were experienced by the Government of India in respect of currency and exchange during the last Great War? How did the Government meet the situation?

(Agra, B. Com, 1958)

- Discuss the effects of World War II on the Indian Currency System. (Agra, B. Com., 1955 Supp., 1957 Supp.)
- 3. Trace the history of Indian Currency System since the establishment of the Reserve Bank of India.

(Agra, B. Com., 1958)

- 4. Examine critically the present currency system in India. Does it meet the needs of economic expansion that is taking place in the country? Discuss. (Raj., B. Com., 1955)
- 5. नोट लिखिए—घाटे की अर्थ-पूर्ति (Deficit-Financing)।

(Sagar, B. Com., 1958)

- 6. द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) के भारतीय मुद्रा पर पड़ने वाले प्रभावों का पूर्ण विवेचन की जिए। (Sagar, B. Com., 1957)
- 7. भारत की वर्तमान चलार्थ पद्धति की तर्क सहित परीचा (Critically Examine) कीजिए। (Sagar, B. Com., 1954)
- सितम्बर सन् १६४६ में किन कारगों से भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ! इस अवमूल्यन से भारतीय आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्टतया समम्माइये। (Agra, B. Com., 1958)
- 9. Write a note on Devaluation of Currency.
  (Agra, B. Com., 1954, 56, 58)
- 10. How is the exchange value of the rupee determined? Was the devaluation of the Indian rupee in September 1949 justified? Give reasons for your answer.

(Raj., B. A., 1954)

11. Indicate the circumstances leading to the devaluation of the Indian rupee in 1949 and discuss its economic effects.

(Raj., B. Com., 1956; Sagar, B. Com., 1955)

12. मुद्रा का अवमूल्यन क्या है ? वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के पन्न एवं विपन्न के तकों की परीन्ना कीजिए। (Sagar, B. Com., 1958)

#### ऋध्याय ३०

# भारतीय पत्र-चलन का इतिहास

(The History of Indian Paper Currency)

#### प्रारम्भिक-

भारतीय पत्र चलन के इतिहास को तीन कालों (Pericds) में बाँट कर अध्ययन किया जा सकता है। ये काल निम्नलिखित हैं:—(I) प्रेसीडेन्सी बेंकों द्वारा नोट प्रकाशन (सन् १००६ से सन् १०६१ तक); (II) सरकार द्वारा निश्चित असुरक्षित नोट चलन पद्धित के अनुसार नोटों का प्रकाशन (सन् १०६१ से सन् १९३४ तक); (III) रिजर्व बेंक ऑफ इण्डिया द्वारा आनुपातिक कोप-निधि-प्रगाली की स्थापना (सन् १९३४ से सन् १९४६ तक); (IV) न्यूनतम् मुटा-कोप-प्रगाली की स्थापना (सन् १९४६ से सन् १९४६ तक); (V) वर्तमान नोट निर्णम अगाली।

# (1) प्रेसीडेन्सी बैंकों द्वारा नोट प्रकाशन (१=०६-१=६१)—

इस काल की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं:-

- (१) १६ वीं शताब्दी से पूर्व भारत में पत्र-मुद्रा चलन का प्रचलन नहीं था।
- (२) सबसे पहले बैंक ग्रॉफ बङ्गाल ने, जिसकी स्थापना सन् १८०६ में हुई थी, सरकारी ग्राज्ञानुसार नोटों की निकासी ग्रारम्भ की। तत्पश्चात् सन् १८४० में बैंक ग्रॉफ बम्बई तथा सन् १८४३ में बैंक ग्रॉफ मद्रास को भी यह ग्रविकार दिया गया। इस प्रकार सन् १८६१ के पूर्व इन तीनों प्रेसोडेन्सी बैंकों को नोट निकालने का ग्रविकार था।
- (३) इन बेंकों द्वारा नोटों का वाहक की मांग पर भुगतान करना आवश्यक होता था। इन नोटों के प्रचलन का क्षेत्र भी साधारणतया कलकत्ते, वस्वई तथा मद्रास के शहरों तक ही सीमित था। सरकार द्वारा प्रत्येक बेंक के लिए नोट निर्गमन की अधिकतम् सीमा निश्चित की गई थी और प्रत्येक बेंक को नोट निर्गम का एक-तिहाई (जो बाद को है कर दिया गया था) धातु-निधि के रूप में रखना पड़ता था। इन बेंकों द्वारा निकाले हुए नोटों को विधि-ग्राह्मता भी प्राप्त न थी।
- (४) तीनों प्रेनीडेन्सी बेंक ग्रंशघारियों की बेंक थीं ग्रौर व्यक्तिगत संस्थायें थीं, परन्तु इनमें सरकार के भी ग्रंश रहते थे ग्रौर इनके प्रबन्घ में भी सरकार का हाथ रहता था।

(II) सरकार द्वारा निश्चित, श्रसुरिचत नोट चलन पद्धित के श्रनुसार नोट प्रकाशन (सन् १८६१-१९३६)—

सन् १८६१ में सरकार ने इन नोटों के प्रचलन को बन्द कर दिया भ्रोर नोट निर्गमन का कार्य भ्रपने हाथ में ले लिया। उपरोक्त वर्ष में पत्र-चलन एक्ट ( $P_{aper}$  Currency Act) पास किया गया। इसकी मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित थीं:—

- (१) सरकार ने १०,२०, ४०, १००, १,००० तथा १०००० रुपए के नोट चालू किए।
- (२) ग्रारम्भ में देश को कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के तीन निर्मम क्षेत्रों (Issue Circles) में विभाजित किया गया ग्रौर प्रत्येक क्षेत्र में निकाले हुए नोट केवल उसी क्षेत्र के भीतर विधि-ग्राह्य होते थे। सन् १६१० तक क्षेत्रों की संख्या बढ़ा कर ७ कर दी गई। क्षेत्र विशेष के भीतर ये नोट ग्रारिमित विधि-ग्राह्य होते थे। ऐसे नोटों को प्रत्येक क्षेत्र के केवल प्रधान कार्यालय पर ही रुपयों के सिक्कों में बदला जा सकता था, परन्तु सरकारी भुगतानों को चुकाने के लिए किसी भी क्षेत्र के नोटों में भुगतान किया जा सकता था। इस क्षेत्रवर्ती प्रगाली ने नोटों की लोकप्रियता में कमी कर दी, ग्रतः शनै:-शनै: इसे तोड़ने का प्रयत्न किया गया।
- (३) सन् १६०३ में ५ रुपये का नोट सभी क्षेत्रों में श्रपरिमित विधि-ग्राह्म बनाया गया। तत्पश्चात् सन् १६१० में १० तथा ५० रुपये के नोटों ग्रौर सन् १६११ में १०० रुपए के नोटों को सभी क्षेत्रों में विधि-ग्राह्म कर दिया गया।
- (४) इङ्गलेंड की नोट निर्गमन प्रणाली के ग्राघार पर सन् १८६१ के नियम में निश्चित विश्वासाश्चित निर्गम प्रणाली (Fixed Fiduciary System of Note Issue) की स्थापना की गई थी। ४ करोड़ रुपये की कीमत तक के नोट सरकारी प्रतिभूतियों के ग्राघार पर निकाले जा सकते थे, परन्तु इससे ऊपर के प्रत्येक नोट के पीछे रुपये के सिक्कों, घातुग्रीं ग्रथवा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों की १००% निधि ग्रावश्यक होती थी। ग्रागे चल कर विभिन्न संशोधनों द्वारा धीरे-घीरे विश्वासाश्चित निर्गम की मात्रा बढ़ा दी गई थी ग्रीर सन् १६१६ में यह २० करोड़ रुपया हो गई थी। सन् १८६८ के एक नियम के ग्रनुसार भारत सरकार को यह ग्राधकार दे दिया गया था कि वह निधि का एक भाग सोने में रख ले। इसी प्रकार सन् १६०० के एक नियम के ग्रनुसार सरकार निधि का कोई भी भाग लन्दन में रखने की ग्राधकारी हो गई थी, परन्तु रुपये के सिक्कों को लन्दन में रखने का ग्राधकार नहीं दिया गया था। विश्वासाश्चित सीमा के परे १००% निधि की जो व्यवस्था की गई थी उसने पत्र-मुद्रा प्रणाली को ग्रत्यधिक सुरक्षा तो ग्रवश्य दे दी, परन्तु इसके कारण यह प्रणाली व्ययपूर्ण हो गई, क्योंकि निधि के ग्राधकांश भाग को ग्रनुत्रादक रूप में रखना ग्रावश्यक था।

भारत में सन् १८६१ से सन् १८३८ तक सपनाई गई निश्चित असुरित्तत नोट निर्गम प्रणाली के गुण-दोष —

इस प्रणाली के प्रमुख ग्रुण—-(१) सुरक्षा, (२) परिवर्तनशीलता तथा (३) ग्रिति-निर्गमन विरोधी रोक थी। साथ ही, इस प्रगाली में कुछ गम्भीर दोष भी थे।

- (१) स्व-चालकता का श्रभाव इसमें स्व-चालकता का गुरा न था श्रीर समय-समय पर विश्वासाश्रित निर्गमन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए नये-नये कानूनों की श्रावश्यकता पड़ती थी।
- (२) निधि में धातु का भाग ग्रधिक—इसमें बातु निधि का ग्रंश काफी ग्रधिक था और उसका ग्रधिकाँश भाग देश के बाहर ही रखा जाता था।
- (३) कोष-निधि का काषागार में व्यर्थ पड़े रहना केन्द्रीय वैंक के न होने के कारण सरकार को अपनी कोष-निधि कोषागारों में बन्द करके रखनी पड़ती थी, जिसके कारण व्यस्त व्यवसायिक काल में घन की कमी अनुभव होने लगती थी।
- (४) बेलोच चलन—इसने देश की चलन प्रगाली को पूर्णतया बेलोच बना दिया था। भारत में बैंकिंग विकास, मौद्रिक बाजार तथा विल बाजार के अभाव के कारण यह प्रगाली विशेष रूप में असुविधाजनक थी और आवश्यकता के काल में चलन की मात्रा में परिवर्तन करना कठिन होता था। चैम्बरलेन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पत्र-मुद्रा चलन की लोच तथा लोकप्रियता को बढ़ाने के कुछ सुभाव रस्ने थे, परन्तु इस दिशा में बहुत सुधार नहीं हो पाया था।

#### प्रथम महायुद्ध का पत्र-मुद्रा-चलन पर प्रभाव-

प्रथम महायुद्ध काल में भारतीय मुद्रा प्रणाली ने अत्यिष्ठि ग्रांकर्षण का अनुभव किया। पहले से ही कागजी नोट बहुत लोकप्रिय न थे। युद्ध का आरम्भ होते ही विश्वास में और भी अधिक कमी होने लगी। लड़ाई के पहले द महीनों में ही १० करोड़ रुपये की कीमत के नोट खजाने को लौटा दिये गये थे, क्यों कि नोटों को रुपये के सिक्कों में बदलने की मांग में भी वृद्धि हुई थी। सन् १६१४ में सरकार ने विश्वा-साश्रित निर्गमन की मात्रा को बढ़ा कर १४ करोड़ रुपया कर दिया और सन् १६१६ में वह २० करोड़ रुपया कर दी गई। इसी काल में रुपये के सिक्कों के स्थान पर एक तथा दो रुपए के नोट निकाल गये और सरकार ने नोटों को रुपयों में परिवर्तित करने के उत्तरदाबित्व को स्थिगत कर दिया।

# सन् १६१६ की बैविंगटन-सिमथ कमेटी की सिकारिशें—

युद्ध के पश्चात् बैविंगटन-स्मिथ समिति ने भारतीय चलन प्रणाली की फिर जाँच की। इस समिति का विचार था कि भारतीय पत्र मुद्रा चलन में लोच का भारी सभाव था। समिति ने इस कमी को दूर करने के लिए दो सुकाव रखे—प्रथम, यह कि विश्वासाधित निर्गमन के ऊरर ५ करोड़ रुपए के नोटों की और अधिक व्यवस्था होनी चाहिए और यह राशि प्रेसीडैन्सी बैंकों को निर्यात बिलों की आड़ पर ऋगों के रूप में मिलनी चाहिए और दूसरे, यह कि निधि का घातु भाग कुल पत्र-मुद्रा चलन का कम से कम ४०% रहना चाहिए। समिति के सुभाव सरकार ने स्वीकार कर जिए और उनके आवार पर नोटों को रुपयों में परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी हटा दिये।

#### पत्र-चलन एक्ट सन् १६२३ —

सन् १६२० के कई छोटे-छोटे नियमों द्वारा भारत की पत्र-मुद्रा प्रणाली में कुछ परिवर्तन किये गये थे। इन सभी संशोधनों को एक सामूहिक बिल में सिम्मिलित करके भारत सरकार ने सन् १६२३ का एक्ट पास किया। इस एक्ट ने पत्र-मुद्रा निषि सम्बन्धी नियमों में निम्निलिखित परिवर्तन किए:—

- (१) कुछ निधि का कम से कम ५०% घातु-निधि के रूप में रखना ग्राव-स्यक बनाया गया।
  - (२) शेष निधि को २० करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों के रूप में भारत में रखा जा सकता था और इससे ऊपर की सारी निधि को अल्पकालीन प्रतिभूतियों में, जिनकी समय अविध १२ मास से अधिक न हो, लन्दन में रखना आवश्यक कर दिया गया।
  - (३) सरकार को यह अधिकार मिला कि ५ करोड़ रुपए की कीमत तक के नोट ऐसे भुनाये हुए विनिमय बिलों की आड़ पर निकाल दे, जिनकी परिपक्कता (Maturity) ६० दिन से अधिक न हो।
  - (४) भारत सचिव लन्दन में ५० लाख शौंड के मूल्य से स्त्रिविक स्वर्णा नहीं रख सकता था।

सन् १६२१ में तीनों प्रेसीडेन्सी बेंकों को मिला कर इम्पीरियल बेंक बना दिया गया और इसे ही इस प्रकार की (विनिमय बिलों की भ्राड़ पर) मुद्रा के निगम का अप्रधिकार दिया गया। यह स्मरण रहे कि बाद में यह एक्ट संशोधित रूप में ही कार्योन्वित किया गया।

#### हिल्टन-यंग कमीशन (सन् १६२६)—

हिल्टन-यंग आयोग ने भी पत्र-मुद्रा-प्रगाली में सुधार के कुछ सुफाव रखे थे। आयोग के सुफाव चार प्रकार के थे:—(१) एक केन्द्रीय बैंक स्थापित की जाय, जिसे 'नीट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त हो, (२) नोटों को रुपयों में बदलने की जिम्मेदारी का अन्त होना चाहिए। (३) पत्र-चलन निधि तथा स्वर्गमान निधि का संवनन (Consolidation) होना चाहिए और (४) भारत में अनुपातिक निधि निर्गम प्रगाली की स्थापना होनी चाहिए।

#### सन् १६२७ का करेन्सी एक्ट-

सन् १६२७ के करेन्सी एक्ट में सरकार ने इनमें से कुछ सुभावों को कार्य रूप

दे दिया:—(१) देश में स्वर्ग-शतुमान स्थापित किया गया, (२) रुपये की विनिमय दर १ शिलिंग ६ पैस तय की गई, (३) इङ्गलैण्ड ने सन् १६३१ में स्वर्गमान छोड़ दिया, तब से देश में स्टिलिङ्ग विनिमय मान कायम हो गया ग्रीर नोटों के बदले स्वर्ग-पाट देना बन्द कर दिया, (५) किन्तु केन्द्रीय वैंक की स्थापना का प्रश्न स्थिपित कर दिया गया, ग्रीर (६) देश में ग्रव भी निश्चित ग्रमुरिक्त नोट निर्गम प्रगाली से ही काम चलता रहा, उसे बदला नहीं गया।

(III) रिजर्व देंक श्रॉफ इशिंडया द्वारा श्रनुपारिक कोष निधि प्रणाली की स्थापना (सन् १९३४-१९५६)—

सन् १६३४ में रिजर्व वेंक आँफ इण्डिया एक्ट पास हम्रा. जिसने १ अप्रैल सन् १६३५ से कार्यं आरम्भ किया। इस अविध के नोट निर्गम की निम्न मुख्य विशेषतायें हैं:-(१) म्रानुपातिक कोप निधि प्रसाली का जन्म सन् १६३४ के रिजर्व बैंक श्रॉफ इण्डिया एक्ट पर श्राधारित था। (२) एक्ट के श्रनुसार नोट निर्गमन का एकाधिकार केवल रिजर्व वैंक के ही पास है। ग्रन्य किसी व्यक्ति भ्रथवा वैंक को ऐसे नोटों के निकालने का ग्रधिकार नहीं है जो वाहक (Bearer) को माँग पर शोधनीग हों। रिजर्व बैंक द्वारा निकाले हए नोट अपरिमित विधि-ग्राह्म होने हैं श्रीर इन पर भारत सरकार की गारन्टी रहती है। दो रुपए के ऊपर के सभी नोटों को रिजर्व बैंक रुपए के सिक्कों अथवा छोटो कीमत के नोटों में बदलने की गारन्टी देती थी। बैंक के दो विभाग हैं: - ग्रिधिकोषण विभाग तथा निर्गमन विभाग। दोनों विभागों को एक-दसरे से पूर्णत्या अलग-अलग रखा जाता है और नोटों की निकासी केवल निर्णमन विभाग ही करता है। १ अप्रेल सन् १६३५ से भारत सरकार ने नोटों का प्रकाशन बन्द कर दिया है। (३) सन् १९५६ तक निर्गमन विभाग के लिए यह आवश्यक था कि वह कूल नोटों की कीमत की ४०% निधि सोने के सिक्कों, सोने अथवा विदेशी प्रतिभृतियों या विदेशी मुद्राग्रों के रूप में रखे । सन् १९४८ के संशोधन के पूर्व विदेशी मुद्राम्रों का म्रभिप्राय केवल स्टर्लिङ्ग से होता था, परन्त्र तत्पश्चात् मुद्रा-कोप के किसी भी सदस्य देश की मुद्रा को निधि के रूप में रखा जाने लगा। कुल निधि में से कम से कम ४० करोड रुपये के मृत्य का स्वर्ण रखना ग्रावश्यक है। शेष ६०% पत्र-चलन के पीछे निम्न प्रकार की आड़ हो सकती है:-

- (१) रुपये के सिक्के तथा सरकारी प्रतिभूतियाँ।
- (२) स्वीकृत विनिमय बिल तथा प्रतिज्ञा-पत्र।

विधान के प्रनुसार सरकारी प्रतिभृतियों की मात्रा कुल ग्रादेयों के २५% ग्रयवा ५० करोड़ रुपये की कीमत से अधिक नहीं हो सकती है, परन्तु विशेष परि-स्थितियों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय गर्गाराज्य के राष्ट्रपित की पूर्व स्वीकृति से इस मात्रा में १० करोड़ रुपए की वृद्धि की जा सकती है। जहाँ तक विनिमय बिखों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों का प्रश्न है, रिजर्व बैंक केवल उन्हीं बिलों मथवा

पत्रों को खरीद सकता था जिन पर किसी अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) की गारन्टी हो और कम से कम एक और आदरखीय पार्टी के हस्ताक्षर हों। प्रतः रिजर्व बैंक ने करेन्सी सिद्धान्त के स्थान में बैंकिंग सिद्धान्त को अपनाया और सन् १९५६ तक आनुपातिक कोष निधि प्रशाली के अनुसार नोटों का निर्गम किया।

व्यवस्था इस प्रकार की गई कि विशेष परिस्थितियों में रिजर्व बैंक के निर्गम सम्बन्धी नियमों में ढील दी जा सकती है, परन्तु यह केवल निम्न दशाओं में किया जा सकता था:—(i) राष्ट्रपति से याज्ञा प्राप्त करना यावश्यक है। (ii) नियमों को केवल ३० दिन तक के लिए तोड़ा जा सकता है, यद्यपि इसमें राष्ट्रपति की याज्ञा से १४ दिन की और वृद्धि की जा सकती है और (iii) नियत निर्गम के ऊपर के प्रत्येक निर्गम पर वैंक को एक बिशेष कर देना होता है, जिसकी दर ऐसे निर्गमन की प्रत्येक वृद्धि के साथ बढ़ती रहती है। (iv) जहाँ तक भारत में प्रचलित कागज के नोटों का प्रश्न है, इस समय १ रुपया, २ रुपया, ५ रुपया, १० रुपया, १०० रुपया और १,००० रुपए के नोट चालू हैं। १,०००, ४,००० और १०,००० रुए के नोट भी ग्रिषक समय तक स्थिगत रहने के पश्चात् १ ग्रप्रेल सन् १६५६ से फिर श्रारम्भ किये गये हैं।

## श्रानुपातिक कोष प्रणाली के गुण-

भारत की यह पत्र-मुद्रा चलन प्रगाली श्रमरीका के संघ निधि बैंक एक्ट (Federal Reserve Bank Act) पर श्राधारित थी। इस प्रगाली के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार थे—

- (१) देश में अनुपातिक निधि निर्गमन प्रगाली प्रचलित है, क्योंकि कुल निर्गमन का कम से कम ४०% सोने, सोने के सिक्कों अथवा विदेशी प्रतिभूतियों में रखा जाता है।
- (३) विदेशी प्रतिभृतियों को निधि के रूप में उपयोग करने की व्यवस्था ने प्रणाली में प्रधिक लोच उत्पन्न कर दी है। इस व्यवस्था के कारण विनिमय नियन्त्रण भी सरल हो जाता है।
- (३) देश की चलन निधि को एक ही कोष में एकत्रित कर दिया गया है। कई प्रकार के कोषों को रखने की पुरानी ग्रपव्ययी प्रसाली समाप्त कर दी गई है, जिसमें कई प्रकार के सुरक्षित कोष रखे जाते थे।
- (४) स्वीकृत विनिमय विलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों की आड़ पर नोट निर्गमन की व्यवस्था करके नोट निर्गमन प्रणाली में और भी अधिक लोच उत्पन्न कर दी गई है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इस व्यवस्था का महत्त्व अधिक है, क्योंकि इसके कारण कृषि की फसलों के वेचने के अर्थ-प्रबन्ध के लिए सामाजिक वित्त (Seasonal Finance) मिलता रहता है।

(१) निथि सम्बन्धी नियमों में छूट मिल जाने की सम्भावना के कारण संबदकालीन परिस्थितियों के लिए समुचित व्यवस्था हो जाती है, परन्तु अतिरिक्त निर्गमन पर बढ़ती हुई दरों में कर लगाने की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण एक सीमा के परे रिजर्व वैंक के लिए नोट निर्गमन अधिक महाना हो जाता है।

#### प्रणाली के दोष-

यह प्रणाली दोपों से विमुक्त हो, ऐसी बात नही है :--

- (१) नोट निर्गमन में अत्यधिक प्रसार का भय—इसका एक दोष तो यही है कि भारत सरकार अस्थायी प्रतिभूतियाँ उत्तन्न करके नोट निर्गमन को बढ़ा सकती है, जिसके विरुद्ध कोई समुचित उपचार भी प्राप्त नहीं है।
- (२) परिवर्तनशीलता का स्रभाव—साथ ही, नोटों की परिवर्तनशीलता स्टिलिङ्ग पर निर्भर है। स्टिलिङ्ग की कीमतों के उचावचनों का काए की कीमत पर प्रभाव पड़े विना नहीं रह सकता है। इसके स्रतिरिक्त क्योंकि स्वयं स्टिलिङ्ग की भी सोने-चाँदी में परिवर्तनशीलता नहीं है, इसलिए भारतीय कागर्जा नोट प्रपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा मात्र हैं।
- (३) स्वयं संचालन का अभाव इस प्रणाली में व्यवसायिक आवश्यक-ताओं और विकास की अर्थ-व्यवस्था के अनुसार विस्तृत होने तथा सिकुड़ने का गुण नहीं है। सभी दृष्टिकोणों से यह एक कृत्रिम तथा प्रबन्धित प्रणाली है, जिसके सँचालन के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है।
- (४) स्रान्तरिक मूल्य-स्तर में स्थिरता नहीं रहती—हमारी पत्र-मुद्रा प्रणाली का उद्देश्य केवल विदेशी विनिमय में स्थिरता ही रहा है। यह प्रणाली भ्रान्त-रिक कीमतों में स्थिरता स्थापित करने में सफल नहीं रही है।
- (५) समुचित लोच का स्रभाव—इस प्रणाली में समुचित लोच का भी स्रभाव है। निधि व्यवस्थाएँ बहुत ही कड़ी हैं। प्रणाली का देश की स्रान्तरिक तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी मौद्रिक स्रावश्यकताओं से कोई भी प्रत्यक्ष तथा धनिष्ट सम्बन्ध नहीं है। स्टर्लिङ्क ही इस प्रणाली का प्राण्ण है। इसमें देशी ग्रर्थं-व्यवस्था की ग्रावश्यकता के मनुसार मुद्रा की मात्रा को घटाने-बढ़ाने का गुण्ण नहीं है।
- (६) आर्थिक विकास के लिए अनुपयुक्त—यह प्रणाली इस प्रकार संवा-लित है कि इसमें देश की समस्त प्रचलित मुद्रा तथा देश की आर्थिक आवश्यकता, उत्पादन शक्ति एवं दितरण सम्बन्धी आवश्यकताओं में किसी प्रकार का भी समन्वय नहीं रहता है। इस दृष्टिकीण से आर्थिक विकास के हेतु यह प्रणाली बहुत उपयुक्त नहीं हो सकती है।

# (IV) न्यूनतम निधि प्रणाली की स्थापना ( सन् १९५६-१९५९ )-

भारतीय पत्र-मुद्रा चलन पद्धति के सम्बन्ध में विगत वर्षों में कुछ ग्राधारमत परिवर्तन किये गये हैं। नई प्रगाली की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—(१) रिजर्व बैंक ग्रॉफ इण्डिया (संशोधन ) सिन्नयम सन् १९५६ ने भारत में नोट निर्गमन की प्रचलित अनुपातिक निधि पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान पर न्यूनतम् निधि प्राणाली की स्थापना की है। (२) इस व्यवस्था के अनुसार बैंक को अपने नोट निर्गन विभाग में नोट निर्गम के विरुद्ध कम से कम ४०० करोड़ रुपए विदेशी प्रतिभूतियों में तथा ११५ करोड़ रुपये सोने के सिक्के या सोने के रूप में संचित करना पड़ताथा। इस अधिनियम की कार्यशीलता से पूर्व रिजर्व वैंक के लिए निर्गमित नोटों के कूज मूल्य का ४० प्रतिशत विदेशी प्रतिभूतियों, स्वर्गा एवं स्वर्गा टंकों में रखना प्रनिवार्य था तथा शेष के लिए चाँदी, चाँदी के सिक्के एवं देशी बिल रखे जा सकते थे। ग्रब तक नोट निर्गमन विभाग में रक्षित स्वर्ण का मूल्य १ रुपया = ६ ४७५१२ ग्रेनस् (स्वर्गा) अर्थात् २१ रुपए १३ आने १० पाई प्रति तोला की दर से लगाया जाता था। संशोधित नियम के लागू होने के समय इस दर पर रिजर्व बैंक के पास ४० ०० २ करोड़ रुपयों के मूल्य का स्वर्ण था। संशोधन इस प्रकार हुआ है कि ग्रब उक्त स्वर्ण का मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष द्वारा निर्घारित दर अर्थात् ३५ डालर प्रति औंस [ १ रुपया = २'८६ ग्रेनस् (स्वर्णं) ] ग्रथवा ६२'५० रुपया प्रति तोला की दर हे किया गया। इस दर पर बेंक के पत्र-मुद्रा कोष में स्थित सोने का मूल्य ४० ०२ करोड रुपए से बढ़कर ११५ करोड़ रुपए हो गया । (३) सन् १८५६ के रिजर्व वैंक एक्ट संशोधन के अनुसार बैंक के नोट निर्गम विभाग द्वारा रखे जाने वाले सोने के सिक्के व सोना तथा विदेशी प्रतिभृतियों की अनुमानित राशि कभी भी २०० करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए श्रीर इसमें भी सोने के सिक्के व सोने के कोष की कीमत ११% करोड से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार अब विदेशी प्रतिभृतियों की मात्रा ४०० करोड़ रुपए से घटाकर १५ करोड़ रुपए कर दी गई है। इसका कारए। यह था कि दूसरी योजना के आरम्भ होने से विदेशी विनिमय की अधिक आवश्यकता हुई, जिससे बैंक के विदेशी कोषों में कमी होने की प्रवृत्ति रही। संक्षेप में, इस नई प्रणाली का उद्देश्य भारतीय मुद्रा प्रगाली में लोच और नितव्यधिता लाना तथा विदेशी विनिमय के संकट को दूर करना था।

# (V) वर्तमान नोट निर्गम प्रसाली के गुस-दोष-

वर्तमान नोट निगम प्रणाली में एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली के कई ग्रण पाये जाते हैं:--

(१) लोच—यह अनुपातिक प्रसाली की तुलना में भ्रष्टिक लोचदार है, क्यों कि इसके अन्तर्गत विदेशी प्रतिभूतियों की मात्रा ४०० करोड़ रुपये से घटा कर ५५ करोड़ रुपये कर दी गई है।

- (२) विदेशी मूल्य की स्थिरता-भारत का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से संबंध स्थापित हो जाने से भारतीय मुद्रा का विदेशी मूल्य स्थिर रहने लगा है, जिससे विदेशी विनिमय कार्य में सुगमता हो गई है।
- (३) मितव्ययिता—जब कि पुरानी प्रगाली,में कई प्रकार के सुरक्षित कोष रखे जाते थे किन्तु इतमें सबको मिला कर एक कर दिया गया है, जिससे बड़ी मित-व्ययिता हो गई है।
- (४) परिवर्तनशीलता—इस प्रगाली में न्यूनाविक परिवर्तनशीलता है, जिससे जनता का इसमें हड़ विश्वास बना रहता है।
- (५) संकट-काल में ढील—भारत के गए। राज्य के राष्ट्रगति की पूर्व स्वीकृति से इस प्रएगली में संकट-काल में कोप सम्बन्धी नियमों में छूट मिल सकती है, किन्तु इस छूट के लिये बैंक को बढ़ती हुई दरों पर 'कर' देना पड़ता है। इससे एक सीमा के पश्चात् बैंक के लिये नोट निर्गम करना में हगा रहता है।

# इस प्रगाली के निम्न दोष पाये जाते हैं :--

- (१) स्रान्तरिक मूल्य-स्तर में स्रस्थिरता—यह प्रणाली रुपये के स्रान्तरिक मूल्य को स्थिर रखने में स्रसफल रही है।
  - (२) सांकेतिक मुद्रा इस व्यवस्या के अन्तर्गत तमाम मुद्रा सांकेतिक है।
- (३) स्वयं-संचालकता का ग्रभाव यह एक कृत्रिम प्रणाली है, जिसके संचालन के लिये सरकारी हस्तक्षेप ग्रति ग्रावश्यक रहता है।
- (४) एक स्पष्ट मान का अभाव—यह प्रणाली सभी देशों के पारस्परिक समभौते पर निभंर है; अतः एक स्वतन्त्र प्रणाली नहीं है। इसे प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-मान, स्वर्ण समता मान और बहु मुद्रा मान के नाम से सम्बोधित करते हैं।
- (१) जिंदलता—एक कृत्रिम व प्रबन्धित प्रगाली होने के कारण जन साधारण इसे सरलता से नहीं समभ सकता।
- (६) परिवर्तनशीलता की कमी—नोटों के बदले में वास्तव में सोना-चांदी नहीं मिलता, ग्रतः इसमें वास्तविक परिवर्तनशीलता का ग्रभाव पाया जाता है।

#### QUESTIONS

What principles should govern the note-issue in a country?
 In this connection examine the provisions of the Reserve Eank of India Act. (Agra, B. A., 1956)

2. Explain the various systems of note-issue. Which of these systems has been adopted in India?

(Agra, B. Com., 1954 and 57)

- 3. Explain the characteristics of an ideal system of note-issue and indicate how far does the Indian paper money possess the same? (Raj., B. Com., 1958)
- 4. Examine critically the present paper currency system in India. Does it meet the needs of the economic expansion that is taking place in the country? Discuss.

(Raj., B. Com., 1955)

- 5. What are the essentials of a good currency system? How far does the Indian Currency System satisfy the requirements of a good system? (Agra, B. Com., 1953, 56)
- 6. Point out the salient features of Indian Paper Currency System as it exists at present. (Raj., B. Com., 1952)
- 7. Discuss clearly the main features of the Fiduciary issue system and the minimum reserve method of note issue as adopted by India. Give your arguments in support of them. भारत की विश्वासाश्रित पत्र-मुद्रा संचालन एवं न्यूनतम कीय-पद्धति की विशेषताओं का विवेचन करिए। उनकी पृष्टि के लिए अपनी युक्तियाँ दोजिए।

  (Agra, B. Com., 1959)

#### ऋध्याय ३१

# भारत में दशमिक मुद्रण की समस्या

(The Problem of Decimal Coinage in India)

#### प्रारम्भिक-

स्वतन्त्रता के परवात् हमारे देश के सामने अनेक समस्यायें उपस्थित हुई हैं, जिन्हें हमने घीरे-घीरे सुलभाने का प्रयास किया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् का काल राजनीतिज्ञों. अर्थ-शास्त्रियों तथा वैज्ञानिकों के लिए इतना अधिक व्यस्त काज रहा है कि छोटी-छोटी समस्याओं की ओर विशेष घ्यान नहीं दिया गया है. परन्तु देश की मनेक समस्याएँ ऐसी हैं जो देखने में साधारण ज्ञात होती हुई भी देश के आर्थिक मौर सामाजिक जीवन में भारी महत्त्व रखती हैं। दशमलवीय मूद्रण की समस्या ऐसी ही समस्याओं में से एक है। लम्बे काल तक देश की मुद्रए प्रशाली में रुखा, म्राना मीर पाई का चलन रहा है। जैसा कि विदित है कि एक रुपये में १६ आने होते हैं और एक ग्राने में १२ पाई । विद्यार्थियों, विशेषकर छोटे-छोटे विद्यार्थियों के लिए, रुप्ये. माने और पाई का हिसाब कितना कठिन होता है, इसका म्रनुभव तो स्वयं पाठकों को भी होगा, परन्तु हममें से बहुत ने किचित यह कभी न सोचा होगा कि इस कठिनाई को मुद्रा प्रणाली में थोड़ा सा ही सुधार करके दूर किया जा सकता है। यह भी हमने कभी न सोचा होगा कि रुपये, आने और पाई की वर्तमान प्रणाली में कितना राष्ट्रीय श्रम ग्रौर कितनी राष्ट्रीय शक्ति बेकार व्यय होते हैं। कठिनाई को दूर करने का सबसे सरल उपाय यही था कि देश में दशमिक मुद्रण क्रम (Decimal Coinage System) स्थापित किया जाता, अतः १ अप्रैल सन् १९५७ से भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया। दशमिक क्रम से हमारा अभिप्राय एक ऐसी मुद्रा प्रणाली से होता है जिसमें प्रत्येक मुद्रा इकाई अपने से ऊपर की मुद्रा इकाई का दसवां भाग होती है। ऐसी प्रणाली फान्स में काफी लम्बे काल से प्रचलित है। इस प्रणाली में एक मुद्रा इकाई को ्० से गुएग करके या १० से भाग देकर दूसरी मुद्रा इकाई निकाली जा सकती है। उदाहरए।स्वरूप, यदि एक रुपया १० ग्राने के बराबर बना दिया जाय और १ म्राना १० पैसे के बराबर तो किसी दी हुई रुपये की संख्या के मागे केवल बिन्दी लगा देने से आने निकल आयेंगे और एक और बिन्दी लगाने से पैसे। नये पैसे चालू करके भारत सरकार ने देश की मुद्रा-प्रणाली में एक ऐसा ही सुवार किया है। संसार में १४० प्रकार के मुद्रामान हैं, जिनमें १०५ दशमलव प्रशाली पर माबारित हैं। म्रन्य देशों में मुद्रा के सौवें भाग को सैन्ट (Cent) कहते हैं, जो कि स्याममें सितांग (संस्कृत के शतांश शब्द का स्रपश्चंश) कहलाता है। पर भारत में सौवें भाग को नया पैसा कहा गया है।

# भारत में दशमिक क्रम की आवश्यकता-

ऐसे विद्वानों का अभाव नहीं है जो यह कहते हैं कि भारत में प्राचीन रुपए, मन, गज झादि के आधार पर प्रमापीकरण (Standardisation) सम्भव था और यद्यपि दशिमक कम इस काम के लिए अधिक उपयुक्त है, परन्तु इस समय इसके ग्रह्मण करने से भारी असुविधा हुई है। इसिलए यही अच्छा बताया जाता है कि प्राचीन प्रमाणी को ही प्रमापीकृत आधार पर बनाये रखा जाता, क्योंकि उससे सभी लोग भली-भाँति परिचित थे, जबिक नई प्रमाणी को समभने और उसके अनुनार काम करने में अधिक समय लगेगा। यह बात तो सत्य है, परन्तु इस समय देश के विभिन्न भागों में बजन और जम्बाई आदि की नाप के पैमानों में इतने अन्तर हैं कि प्राचीन आधार पर प्रमापीकरण करने में भी कुछ कम असुविधा न होगी। तो फिर दशिमक कम पर ही प्रमापीकरण करने में भी कुछ कम असुविधा न होगी। तो फिर दशिमक कम पर ही प्रमापीकरण क्यों न किया जाय, जिसकी श्रेष्ठता को सभी स्वीकार करते हैं। यदि प्राचीन प्रणाली में परिवर्तन ही करना था तो ऐसा परिवर्तन क्यों न किया जाता कि जो स्थाई हो तथा जिससे कुशंलता और सुविधा बढ़ सके। निम्न कारणों से भारत में दशिमक कम की आवश्यकता रही है:—

- (१) संसार के सभी सभ्य देशों में गिएति के चिन्ह (Notations) दशमलवीय ग्राघार पर ही बनाये गये हैं। नाप और तोल की कोई भी ऐसी इकाई सुविघाजनक न होगी जिसमें इस दशमलवीय ग्राघार को ग्रहण न किया जाय। संसार के लगभग सभी देशों में बहुमत दशमिक क्रम के ही पक्ष में हैं, क्योंकि इसकी श्रेष्ठता को सभी मानते हैं। यह निश्चय है कि यदि इस समय हम इस क्रम को ग्रहण न भी करते तो भविष्य में ऐसा ग्रवश्य करना पड़ता। फिर इसको ग्रभी से क्यों न ग्रारम्म किया जाय।
- (२) संसार के ५० देशों ने, जिनमें सारे संसार की तीन-चौथाई जन-संख्या रहती है और जिनमें विभिन्न जलवायु और संस्कृति के लोग शामिल हैं, इस क्रम को पहिले से ही ग्रहण कर लिया था। व्यवहारिक अनुभव इस क्रम के ही पक्ष में है, क्योंकि यह भी निश्चय है कि जिस देश ने इस प्रणाली को एक बार ग्रहण कर लिया है उसने ग्रागे चलकर इसे छोड़ना ग्रावश्यक नहीं समभा है। कुछ समय पश्चात् भारत को भी धन्य देशों का अनुकरण करना ही पड़ता।
- (३) भारत में दशिमक कम के पक्ष में यह भी कहा जा सकता है कि इस कम का अन्तर्राष्ट्रीय आधार होने के कारण देश के सभी भागों में इसे बिना विरोध प्रहण कर लिया गया है। किसी दूसरी प्रणाली को ग्रहण करने का परिणाम यह हो सकता था कि कुछ क्षेत्रों में भारी असन्तोष रहता, क्योंकि उत्तर और दक्षिण में पैमाने एक ही आधार पर नहीं हैं।

(४) दशमिक कम को प्रह्गा करके भारत भी उन देशों की उस लम्बी मूर्वी में शामिल हो गया है जिन्होंने नाप के सामूहिक याघार को मान लिया है। ऐना करने से भारत अपनी अन्तर्राष्ट्रीय भावनाओं को कार्य रूप दे सकेगा और साथ ही उन जज्जीरों को भी तोड़ सकेगा जिन्होंने अब तक उसकी उन्नति में स्कावटें उगस्थित की हैं।

क्या भारत के लिये दशमिक मुद्रा व्यवस्था को स्थगित करना उपयुक्त होता ?—

इस सम्बन्य में एक और प्रश्न का उत्तर भी आवश्यक प्रतीत होता है। दश-मिक क्रम के कुछ ग्रालोचक ऐसे भी हैं जो भारत के लिए इसकी उपयुक्तता को स्वीकार करते है, परन्तु उनका विचार है कि इसका कार्यरोपरा १५-२० वर्ष के जिए स्थिगत रखा जाना चाहिए था। यह कहा जाता है कि हमने ग्राधिक नियोजन का मार्ग ग्रय-नाया है। सरकार और जनता दोनों ही निर्माण-कार्यों में व्यक्त है। ग्रभी कुछ समय तक और रुके रहने की आवश्यकता थी, क्योंकि इस प्रणाली को ग्रहण करके हम इक्स तेंड जैसे देश से अलग हो जाते हैं, जिसते हमारा वाणिजियक सन्बन्ध बड़ा ही घनिष्ट है। ऐसे आलोचकों को जानना चाहिए कि यब समय या गया था कि इस क्रम के लागू करने में ग्रौर ग्रधिक विलम्ब न किया जाय । क्रम को तत्हाल ग्रहरा करने के पक्ष में अनेक तर्क रखे जा सकते हैं: - (i) इस समस्या को इतने लम्बे काल तक टाला गया है कि अब इसको और अधिक टालना किसी भी प्रकार उचित नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय हित इसी में है कि ग्रन्तस्थानीय व्यापार ग्रौर वास्पिज्य की उलक्कत को और म्रधिक समय तक न बना न रहने दिया जाय। जितनी जल्दी इसे दूर किया जायगा उतना ही अच्छा होगा। ( ii ) यह कहना असङ्गत प्रतीत होता है कि जब तक इक्स लैंड में यह प्रस्माली नहीं अपनाई जाती है, भारत में भी इसके प्रहस्म करने का विचार स्थगित किया जाय । बात यह है कि इस देश को काफी लम्बे काल से पैमानों के प्रमापीकररण का लाभ प्राप्त है. जबकि भारत में मुद्रा के सम्बन्ध में हमने इसे समी-भभी स्थापित किया है श्रीर दूसरी दिशाओं में हम श्रभी तक भी स्थापित नहीं कर पाये हैं। इस सम्बन्ध में सन् १९५४ में सर एडवर्ड बुलर्ड (Sir Edward Bullard) ने, जो इङ्गलैंड की नेशनल फिजीकल लेबोरेट्री (National Physical Laboratory) के संचालक हैं, ठीक ही कहा था — "यदि निर्णय यही है कि भारत में दशमिक क्रम को ग्रहण किया जाय तो इसे तुरन्त ही किया जाय, पहिले इसके कि श्रौद्योगीकरण इस सीमा तक श्रागे बढ़ जाय कि इस प्रकार का परिवर्तन करना कठिन हो जाय ।" श्रतः यह ग्रावश्यक था कि ग्रौद्योगीकरण की समृत्वित प्रगति के पूर्व ही इस आवश्यक परिवर्तन को सम्पन्न कर दिया जाय। ( iii ) स्थिगत करने से किसी समस्या या कठिनाई के सूलक जाने की भी कोई ग्राशा नहीं हो सकती थी। जैसे-जैसे समय व्यतीत होता जायगा. इस प्रकार का परिवर्तन करने का व्यय बढ्ता ही जायगा, क्योंकि सभी प्रकार की शिलाक, ग्रीचोगिक ग्रीर व्यवसायिक शिक्षा, जो प्राचीन प्रशालों के घ्राचार पर दी जाती, बेकार हो जायगी। (iv) ग्रानिहिंचतता जनित के मार्ग में बाघक होती है। यदि ग्रानिहिंचतता बनी रहती है तो उद्योगों को ग्रापनी दीर्घकालीन योजनाएँ बनाने में किठनाई होती है। (v) यह तर्क भी बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है कि क्योंकि भारत का दो-तिहाई व्यापार ऐसे देशों से है जिनमें यह प्रशाली प्रचलित नहीं है, इसिलए ग्रभी कुछ समय तक भारत में भी इसे लागू न किया जाय। बात यह है कि स्वयं इङ्गलेंड ग्रीर ग्रमरीका का ग्राघा-ग्राघा व्यापार दशिमक कम तथा ग्रन्य देशों से होता है ग्रीर इन्हें इसमें कोई किठनाई भी नहीं है, ग्रतः यही ग्रन्छा था कि यदि हम इस प्रशाली को ग्रह्ण करना चाहते थे तो इसे शीघ्र ही ग्रह्ण करते। मुद्रा के सम्बन्ध में तो सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय कर ही लिया है, ग्र य दिशाग्रों में भी इसकी ग्रावश्यकता है।

## भारत में दशमिक क्रम का इतिहास-

भारत में दशिमक क्रम की स्थापना के प्रयत्न का इतिहास ग्रधिक प्राचीन है। इस दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रयत्न सन् १८६७ ग्रौर सन् १८७१ के बीच के काल में किया गया था। सम्पूर्ण सम्भावनाओं की जांच के परचात भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची थी कि सभी किठनाइयों का एक मात्र हल दशिमक क्रम की स्थापना थी, यद्यिप यह स्थापना घीरे-घीरे होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में सन् १८७० में दशिमक एक्ट (Metric Act of 1870) पास किया गया, जिसकी व्यवस्थाओं में भारत सचिव के ग्रादेश पर कुछ संशोधन किए गए। तब से ग्रब तक ६० वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु एक्ट को लागू नहीं किया जा सका है। सन् १९३६ में भारत सरकार ने वजन प्रतिमान सन्नियम (Standard of Weight Act) को पास करके तो सन् १८७० के एक्ट की व्यवस्थाओं को समाप्त ही कर दिया। इसके बाद सन् १६४० में भारतीय दशिमक सभा (Indian Decimal Society) स्थापित हुई। इस संस्था ने बराबर दशिमक क्रम की स्थापना पर जोर दिया है ग्रौर सरकार तथा समाज को इसके विषय में उपयुक्त ज्ञान प्रदान किया है।

# दशमिक मुद्रा विधेयक, सन् १९४६—

फरवरी सन् १९४६ में भारत सरकार ने घारा सभा के सामने एक बिल प्रस्तुत किया, जिसमें दशिमक मुद्रा प्रणाली के लागू करने की व्यवस्था की गई थी और रुगए को प्रामाणिक सिक्का मान कर उसे १०० सेंट में विभाजित करने का सुमाव दिया गया था। जन मत प्राप्त करने के लिए बिल पर जनता की राय मांगी गई। सभी श्रोर से बिल के पक्ष में ही राय श्राई। फरवरी सन् १९४७ में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को श्रादेश दिया कि वे दशिमक नाप श्रीर तोल के ग्रहण करने के प्रश्न पर विचार करें। वाणिज्य श्रीर व्यापार संघों तथा वैज्ञानिक संस्थाओं ने सरकारी नीति का समर्थन किया श्रीर इस श्रावश्यक सुधार को लागू करने का श्रनु- रोष किया।

## भारतीय प्रतिमान संस्था विशेष समिति की शिकारिय-

तराश्चात् सन् १६४५ में भारतीय प्रतिमान संस्था विजेष समिति (Indian Standards Institution Special Committee, 1949) को स्थापना की गई, जिनकी रिपोर्ट सन् १६४६ में प्रकाशित हुई। इस मिति ने देश में दशिमक कम की स्थापना सम्बन्धी सभी समस्याओं को जांच की। समिति ने देश के विभिन्न हितों और देश की विभिन्न संस्थाओं की राय जमा की। समिति प्रन्न में इस निष्कर्ष पर पहुँची कि दशिमक कम की सभी और माँग थी, परन्तु इस प्रणानी को घीरे-घीरे स्थापित किया जाय। विभिन्न राज्य सरकारों ने कम को घीरे-घीरे लागू करने के लिये थे से लेकर १५ वर्ष तक की समय अविध रखी थी। केच्न विदार और मध्य-प्रदेश दशिमक कम के ग्रहण करने के पक्ष में न थे। समिति ने चर्च और अमुविधा को घ्यान में रखते हुये यह सुभाव दिया था कि दशिमक कम को घीरे-घीरे १०-१५ वर्ष में सभी दिशाओं में लागू कर दिया जाय। सिमिति के प्रमुख मुभाव निम्न प्रकार थे:—

- (१) पहिले ३ से लेकर ५ वर्षों तक कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन न किया जाय। इस काल में लोगों को समुचित सूचना ग्रीर शिक्षा दी जाय। फिर धीरे-घीरे दशमिक क्रम ग्रयनाया जाय।
- (२) भारत सरकार दशमिक मुद्रा-प्रशाली स्थापित करे, जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई उससे पहिली इकाई का दसवाँ ग्रंग हो।
- (३) इस सम्बन्ध में गहरा प्रचार होना चाहिए और शिक्षा संस्थाओं और प्रचार की भनेक विधियों का पूरा-पूरा उपयोग किया जाय।
- (४) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार प्रारम्भिक तैयारी आरम्भ कर दें और नई प्रगाली को लागू करने के खर्च का अनुमान लगायें।
- (५) सरकार नियमित बाजारों (Regulated Markets) के दैनिक कार्यों में यथासम्भव दशमिक क्रम के उपयोग को प्रोत्साहन दें, इत्यादि।

समिति की रिपोर्ट से सिद्ध होता है कि ग्रन्य दिशाशों में दशिम कम को लागू करने में, चाहे कठिनाई रही हो, मुद्रा के सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण कठिनाई न थी, क्योंकि मुद्रा की इकाइयों का प्रमापीकरण बहुत पहिले से ही हो चुका है। सिमिति ने सिफारिश की थी कि भारत सरकार शीघ्र ही लोक सभा में दशिमक मुद्रण सम्बन्धी नियम प्रस्तुत करे और दशिमक कम की स्थापना का श्रारम्भ मुद्रण प्रणाली के परिवर्तन द्वारा करे।

#### भारतीय मद्रण संशोधन प्रस्तात-

भारतीय मुद्रगा एक्ट, सन् १६०६ में संशोधन करने का ठोस प्रस्ताव एक नये बिल के रूप में सन् १६४६ में रखा गया था। प्रस्ताव यह था कि भारत में दशमिक प्रसाली लागू की जाय, जिसमें एक रुपए को १६२ पाई में विभाजित करने के स्थान पर १०० सेंट (Cents) में विभाजित किया जाय। प्रस्ताव निम्न प्रकार था:—

-	रुप			वर्तमा	<b>7</b>	इपये है	h i	प्रनुस	र					रुपया
४०	संट					7,							d.	रुपया
२५	,,					11							9	रुपया
१०	"		]											
	,,		1			_	_		_					
?	77	(5)	}	वर्तमान	욯	रुपये	से	क्म	कीमत	के	सिक्कों	के	स्थान	पर
ξ	,,	(पीतल)	!											
3	: 2	(सम्भावितं)	J											

यह विभाजन क्रम श्री लङ्का की मुद्रा प्रगाली के आधार पर बनाया गया था। हपए का सिक्का, श्रठश्रो और चवन्नी की शक्त, वजन और आकार ज्यों का त्यों रहेगा, परन्तु इससे नीचे के सिक्के नये रहेंगे और उनके पुनः मुद्रगा की आवश्यकता पड़ेगी। दशमलव प्रगाली के लाभ-

भारत सरकार के वित्त विभाग ने दशमलवीय प्रिणाली के स्थाई लाभ की गराना निम्न प्रकार कराई है:—

- (१) एक सरल तथा शीघ्र लेखा विधि का निर्माण।
- (२) व्यय तया मूल्य निर्घारण की एक सही और सप्रभाविक रीति।
- (३) घरेलू कामों और उपभोगीय वस्तुग्रों की कीमतों को नापने का एक सरल उपाय।
- (४) श्रनावश्यक तथा विविध प्रकार की मुद्रा इकाइयों को समाप्त करना श्रौर नई इकाइयों को दशमलवीय ग्राधार पर परिभाषित करना।
- (५) कीमतों के छोटे-छोटे परिवर्तनों की ग्रधिक सही नाप करना, जिससे कि मुद्रा का व्यय ग्रधिक उपयुक्त रीति से किया जा सके।
- (६) शिक्षा संस्थायों में समय ग्रौर परिश्रम की बचत करना।

# दशमलव प्रणाली को कार्यान्वित करने में कठिनाइयाँ—

भारत सरकार नई मुद्रा के चालू करने के सम्बन्ध में होने वाली कठिनाइयों को भी भली-भाँति समभती थी। तीन कठिनाइयाँ विशेष रूप में महत्त्वपूर्ण हैं:—

- (१) आरम्भ में यह नई प्रणाली अरुचिकर तथा जटिल प्रतीत होगी। वर्तमान प्रणाली लम्बे काल से एक परम्परागत प्रणाली के रूप में चालू है और लोग भावनायुक्त रूप में नई प्रणाली का विरोध करेंगे, परन्तु सरकार ने इस कठिनाई को दूर करने के लिए रुपया, अठशी और चवशी के सिक्कों में परिवर्तन न करने का निश्चय किया है।
- (२) कुछ काल तक नवीन एवं प्राचीन मुद्राएँ साथ ही साथ चालू रहेंगी। इससे ग्रनावश्यक उलभन होगी। ग्रौर भोले-भाले लोगों के ठगे जाने की सम्भावना

भ्रधिक रहेगी, परन्तु यदि नई प्रणाली चानू करनी है तो यह कठिनाई बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है। गड़बड़ चवन्नी से नीचे के ही सिक्कों में होगी और वह भी थोड़े ही समय तक ।

(३) वर्तमान दशा में सभी दरें जिस आधार पर है वह आधार ही बदल जायगा, जिससे असु विधा होगी। रेल्वे और डाकखाने की नई दरें कुछ और ही रहेंगी, परन्तु यह कठिनाई भी अस्थाई होगी। अन्त में तो नई मुद्रा ही स्थाई रूप में चालू रहेगी।

## भारतीय मुद्रा (संशोधन ) नियम सन् १९५६—

भारत सरकार द्वारा विचार-परामर्श तथा सोच-विचार क वाद सन् १६५५ का भारतीय मुद्रा (संशोधन ) नियम सन् १६५६ में पास किया गया है। नियम की प्रमुख व्यवस्थायें निम्न प्रकार हैं:—

- (१) इस एक्ट का नाम भारतीय मुद्रा (संशोधन) सन्नियम (Indian Currency Amendment Act) रखा गया है।
- (२) एक्ट के अनुसार भारत की मुख्य मुद्रा इकाई रुपया रहेगी। सबसे छोटी मुद्रा इकाई का नाम पैसा रहेगा, परन्तु उसे कुछ समय तक (उस समय तक जब तक कि वर्तमान पैसा भी चालू रहेगा) नया पैसा कहा जायगा। एक रुपया १०० नये पैसों के बराबर होगा।
- (३) रुपए और पैंसे के अतिरिक्त ५० पैंसे और २५ पैंसे के दो सिक्ते भौर होंगे। वर्तमान ग्रठिशी भीर चविश्वों की कीमत जमशः ५० और २५ नये पैसों के बरा-बर होगो।
- (४) इन सिक्झों के अतिरिक्त वर्तमान दुग्रन्नी, इकन्नी, दो पैसे ग्रौर एक पैसे के सिक्झों के स्थान पर १०, ५, २ ग्रौर एक नये पैसे के सिक्झे बनाये जायेंगे।
- (५) वर्तमान दो आने, एक आने, दो पैसे और एक पैसे के सिवके भी साथ-साथ चालू रहेंगे, परन्तु घीरे-घीरे इनका विमुद्रीकरण होगा। तीन वर्ष के पश्चात् अन्त में पूर्ण रूप में नई मुद्रा चालू हो जायगी, यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर इस अविष को बढ़ाया जा सकता है।
- (६) एक्ट की व्यवस्थाओं को १ अप्रैल सन् १६५७ से लागू किया गया है। रुपया, अठली और चवली के सिक्के गिलट (Nickle) के हैं, एक नया पैसा ताँबे का है और अन्य सिक्के ताँबे और गिलट की मिलावट के।

#### मुद्रा प्रशाली का नया रूप-

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, १ अप्रैंन सन् १६५७ से सरकार ने नये सिक्कों को चालू कर दिया है। ३ वर्ष तक, अथवा यदि आवश्यकता समभी गई तो और आगे तक, नये और पुराने दोनों ही प्रकार के सिक्के साथ-साथ चलेंगे। कुन मिलाकर सात नये सिक्के होंगे, जिनमें कपये का वर्तमान रूप ज्यों का त्यों रहेगा।

अन्तर केवल इतना होगा कि रुपए की पीठ पर "सौ नये पैसे" लिखा रहेगा। रुपए के अविरिक्त ५० पैसे (रुपए का आधा भाग), २५ पैसे (रुपए का चौथा भाग), १० पैसे (रुपए का दसवाँ भाग), ५ पैसे (रुपये का बीसवाँ भाग), दो पैसे (रुपए का पचासवाँ भाग) और १ पैसे (रुपए वा सौवां भाग) के भी सिक्के होंगे। कुछ काल के लिए भारत सरार ने रुपये के नये सिक्कों और ५० तथा २५ नए पैसों के सिक्कों को न निकालने का फैसला किया है। रुपए वा वर्तमान सिक्का तथा अठिशी और चवित्ती इसके स्थान पर चालू रहेंगे। वर्तमान और नये दोनों ही सिक्कों में लेन-देन हो सकेगा। इन सिक्कों को ग्रहण करने को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति नए, पुराने अथवा नए और पुराने सिक्के मिलाकर, जो भी उसके पास हों, अगतान कर सकता है। घ्यान देने योग्य बात यह है कि रुपए के आधारभूत मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उसके नोचे के सिक्के ही मूल्य में बदल गये हैं। निम्न तालिका में नए और पुराने सिक्कों की परिवर्तन दर दिखाई गई है:—

ग्राने	पाई	नये पैने	ग्राने	पाई	नये पैसे	ग्रान	पाई	नये पैसे	ग्राने	पाई	नये पैसे
0	ş	२	४	ą	<i>ټر</i> ن	5	₹	५२	१२	3	७७
0	Ę	¥	४	६	२ ८	দ	६	५३	१२	ξ.	৩5
. 0	3	¥	ጸ	3	३०	5	3	ሂሂ	१२	è	50
\$	0	Ę	¥	0	₹ १	3	0	५६	१३	0	58
. \$	¥	5	ሂ	ą	३३	3	ą	५५	१३	Ŗ	53
\$	Ę	3	X	Ę	३४	3	Ę	४६	१३	Ę	<b>5</b> لا
8	3	११	¥	3	३६	3	3	६१	१३	è	द६
₹	0	<b>१</b> २	Ę	0	३७	१०	0	६२	१४	0	50
?	₹	१४	Ę	₹	38	१०	३	६४	१४	ą	58
२	६	१६	६	Ę	४१	१०	Ę	६६	१४	Ę	83
२	3	१७	Ę	3	४२	१०	3	६७	१४	3	£ ?
3	0	38	હ	0	४४	११	0	६ ६	१५	0	83
3	¥	२०	૭	ą	<b>አ</b> ጀ	११	३	७०	१५	ą	દય
3	Ę	२२	હ	६	४७	११	Ę	७२	१५	Ę	89
₹	3	२३	હ	3	४५	११	è	৬ ই	१५	3	६६
8	0	२५	5	0	५०	<b>१</b> २	0	७५	१६	0	₹0 <b>•</b>

अधिक संक्षित रूप में परिवर्तन सारिग्छी निम्न प्रकार दी जा सकती है:— १ रुपया १०० नए पैसे २ ग्राने १२ नये पैसे म् ग्राने ५० ,, ,, १ ग्राना ६ ,, ४ ,, २५ ,, ,, २ पैसे ३ ,, ३ ,, १६ ,, ,, १ पैसा २ ,, नवीन सिक्कों को चलते हुए ग्रव तीन वर्ष बीत चुके हैं। ग्राशा यह की जाती थी कि एक साल में नये सिक्कों की लोकप्रियता इतनी बढ जायगी कि पुराने सिक्के किसी विशेष सीमा तक समाप्त हो जायेंगे, किन्तु ग्रनुभव इसके विपरीत है, क्योंकि ग्रभी तक पुराने सिक्कों के प्रचलन में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ी है।

तोल की दशमलवीय प्रणाली (The Metric System of Weights) —

इस समय भारत में तोल और माप की कोई भी एक प्रगाली देगव्यामें नहीं है। देश में कम से कम १८३ प्रगालियाँ प्रचलित है। इतनी अधिक प्रगालियों के कारण धोले का अवकाश भी पर्यात रहता है। यदि देश में माप और तोन की दश-मलवीय प्रणाली आरम्भ कर दी जाय तो हिसाब लगाने में अधिक आमानी हो जायगी, मुख्यतया जबिक देश में दशमलवीय मुद्रण प्रगाली पहले से हो चालू है। इस दिशा में सन् १९५६ के तोल और माप परिमान सिन्नयम ने दशमलवीय प्रणाली की आधारभूत इकाइयाँ निश्चित कर दी हैं। भारत सरकार ने अक्टूबर सन् १९५८ से माप और तोल की दशमलवीय प्रणाली चालू करने का निश्चय किया है। नई प्रणाली को घीरे-घीरे लागू किया जायगा और ३ साल तक नई और पुरानी माप-तोल साथ-साथ चलेगी। तोल की नई आधारभूत इकाई किलोग्राम (Kilogram) रखी गई है, जिसकी तोल १ सेर ६ तोला अथवा ६ तोला अथवा २ पोंड ३ ग्रींस होगी। पूरी प्रणाली निम्न प्रकार रहेगी:—

१०	मिलीग्राम	?	सेन्टीग्राम
१०	सेन्टीग्राम	٤	डेसीग्राम
१०	डेसीग्राम	१	ग्राम
१०	ग्राम	१	डेकाग्राम
१०	<b>डेकाग्राम</b>	१	है <b>क्टोग्राम</b>
१०	हैक्ट्रोग्राम	१	किलोग्राम
१००	<b>किलोग्राम</b>	₹	कुइन्टल
१००	कुइन्टल		•
	<b>ग्र</b> थवा		
१,०००	<b>क्लोग्राम</b>	?	मेट्रिक टन

#### QUESTIONS

1. दशमिक सदा पर नोट लिखिए।

(Agra, B. A., 1956, 58)

2. What is 'decimal coinage'? Give the advantages and disadvantages of this system under Indian conditions.

(Raj., B. A., 1956)

3. नोट लिखिए—दशमिक टंक्रन (Decimal Coinage).

(Jabalpur, B. A., 1958)

- Briefly explain the main provisions of the Indian Coinage (Amendment) Act, 1955.
- 5. Why has decimal coinage been introduced in the Indian Currency System? What are its advantages and disadvantages to the country? भारतीय मुद्रा प्रशाली में दशमलव-प्रशाली का क्यों समावेश किया गया है? हमारे समाज को इसके क्या लाभालाभ हैं? (Agra, B. Com., 1959)

Kamerik Kune Tynd

#### अध्याय ३२

# भारतीय बेंकिंग-उसका विकास एवं उसकी समस्यारें

(Indian Banking—its Development and Problems)

भारतीय वैंकिंग का आरम्भिक इतिहास —

प्राचीन ग्रन्थों से इस बात का पर्याप्त प्रमाग मिलता है कि भारतवर्ष में वैंक प्रथा बहुत लम्बे काल से प्रचिलत रही है। वैदिक काल में भी रुपया उधार लेने और देने की प्रथा थी और चाए। क्य के अर्थशास्त्र से तो ऐसा स्पष्ट होता है कि उस काल में बैंकिंग व्यवस्था का विस्तृत महत्त्व था। महाजन लोग जनता के रुपये को जमा भी करते थे और उधार रुपया भी देते थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के काल में भारत की देशी बैंकिंग प्रथा टूटने लगी, क्यों कि देशी बैंकर अंग्रेजी भाषा तथा विदेशी बैंकिंग प्रणाली से परिचित न थे। वैसे भी अंग्रेजों ने भारतीय बैंकरों की सेवाओं का लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं किया था, बिल्क अपना काम चलाने के लिए इङ्गलिश एजेन्सी-गृह स्थापित किये थे। भारत की आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का इतिहास वास्तव में इन्हीं एजेन्सी गृहों की स्थापना से आरम्भ होता है। ये गृह अपने अन्य व्यवसायों के साथ-साथ जनता से निक्षेप भी स्वीकार करने का कार्य भी करते थे और उनकी ऋण सम्बन्धी व्यापारिक तथा औद्योगिक आवश्यकताओं को भी पूरा करते थे। इन गृहों के पास आरम्भ में कोई निजी पूँजी न थी और वे कम्पनी के नौकरों द्वारा जमा की हुई राशि से ही व्यवसाय करते थे, यद्यपि आगे चलकर इन्होंने धारे-धीरे अपनी निजी पूँजी नी

प्राप्त कर ली थी। भारत में सम्मिलित पूँजी बैंक प्रणाली का ग्रारम्भ इन्हीं एजेन्सी ग्रहों द्वारा हुन्ना।

सन् १६१३ में भारत के विदेशी व्यापार पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का एकािष्ठकार समाप्त हो गया, जिससे एजेन्सी गुहों को गहरी चोट पहुंनी और सन् १६३२
तक जनका अन्त हो गया। इनमें से दो एजेन्सी गुहों ने अपने रूप में परिवर्तन करके
सिम्मिलित पूँ जी के आधार पर अपने को संगठित करने का प्रयत्न किया और इस
प्रकार सर्वप्रथम सन् १७७० में 'दी वैंक आँफ हिन्तुस्तान' के नाम से भारत में सबसे
पहली योरोपियन वैंक स्थापित हुई, जो सन् १६३२ में ठप्प हो गई। इसी प्रकार
बंगाल वैंक भी स्थापित की गई थीं, जो एजेन्सी गुहों से मिन्न थी और पत्र-मुदा का
निर्गम भी करती थी। सन् १८६६ में 'दी जनरल वैंक ऑफ इण्डिया' स्थापित की गई
थी, परन्तु आरम्भिक कल की सभी वैंक आगे चलकर हूव गई और इस दिशा में
किये गये पहले सभी प्रयत्न असफल ही रहे।

तत्परचात् प्रेसीडेन्सी बैंकों की स्थापना के साथ भारत में ब्राधृनिक बैकिंग विकास के जीवन का दूसरा युग आरम्भ हुआ। सन् १८०६ में ईस्ट इण्डिया कम्मनी के आज्ञा-पत्र के अनुसार 'वैंक ग्रॉफ कलकता' नाम की पहली वैंक स्थापित की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य अवमूल्यन चलन पद्धित के दोषों को दूर करना था। इसके परचात् सन् १८४० में 'वैंक ग्रॉफ बम्बई' एवं सन् १८४३ में 'वैंक ग्रॉफ मद्रास' की स्थापना हुई। ये तीनों 'प्रेसीडेन्सी वैंक' ईस्ट इण्डिया कम्पनी की तित्तीय आवश्यकन्ताओं को पूरा करने तथा आन्तरिक व्यापार का अर्थ-प्रबन्च करने के लिए स्थापित की गई थीं और इन्हें नोट निगम का अधिकार भी दिया गया था, जो सन् १८६२ में छीन लिया गया था। किन्नाइयों के होते हुये भी ये तीनों बैंक सन् १६२० तक सफलता-पूर्वक चालू रहीं। सन् १६२१ में इन तीनों को मिजाकर 'इम्पीरियल वैंक ऑफ इण्डिया' स्थापित किया गया, जिसका अब 'स्टेट बैंक ग्रॉफ इण्डिया' के रूप में फिर से पुनर्संङ्गठन किया गया है।

सन् १८६० से भारतीय बैंकिंग के इतिहास का तीसरा युग आरम्भ होता है। इस वर्ष से योरोपियन प्रबन्ध के अन्तर्गत अनेक बैंकों की स्थागना हुई और सन् १८७४ तक सीमित उत्तरदायित्त्व बैंकों की संख्या १४ तक पहुँच गई। भारतीय प्रबन्ध के अन्तर्गत संचालित सबसे पहली बैंक 'अवध कॉर्माशयल बैंक' थी, जो सन् १८६१ में स्थापित की गई थी। तत्पश्चात् और भी कई बैंक, जिनमें 'पजाब नेशनल बैंक' (१८६४) भी सम्मिलित है, स्थापित हुई। सन् १६०५ के स्वदेशी आन्दोलन ने तो इस प्रवृत्ति को और भी प्रोत्साहन दिया।

सन् १६०५ भ्रौर सन् १६१३ के बीच ऐसी बैंकों की संख्या, जिनकी परिदत्त पूँजी तथा सुरक्षित निधि मिलकर ५ लाख रुपये से ऊपर थी, ६ से बढ़कर १८ हो गई। इन १८ बैंकों की परिदत्त पूँजी भ्रौर निधि ४ करोड़ रुपये तक पहुँच गई भ्रौर जमाधन २२ करोड़ रुगए के ब्रास-पास पहुँच गया। इस काल में स्थापित होने वाली बड़ी-बड़ो बैंक दी बैंक ब्रॉफ इन्डिया, सेन्ट्रन बैंक ब्रॉफ इन्डिया, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, वैंक ब्रॉफ बड़ौदा, बैंक ब्रॉफ मैंसूर तथा दी इन्डियन बैंक हैं। इनमें से प्रथम ५ अभी तक भी भारत की पाँच महान बैंकों में से गिनी जाती हैं। इन बड़ी-बड़ी बैंकों के ब्रातिरिक्त इस काल में बहुत सी छोटी-छोटी बैंक भी खोशी गई, जिनकी संख्या सन् १६१३ में ५०० तक पहुँच गई थी। ब्रिश्कांश बैंक बिना समुचित ब्रौर हढ़ ब्राधिक ब्राधार के ही खेल दी गई थीं, जिसका परिशाम यह हुमा कि सन् १६१३-१७ के बैंकिंग संकट के काल में वे ब्रिधिक संख्या में फेल हो गई। इस संकट में फेल होने वाली प्रमुख बैंक निम्न प्रकार थीं—दी इण्डियन स्थीशी बैंक, दी बंगाल नेशनल बैंक, केडिट बैंक ब्रॉफ इण्डिया, दी स्टेंडर्ड बैंक, दी वॉम्बे मर्चेन्ट्स बैंक ब्रौर बैंक ब्रॉफ ग्रपर इण्डिया लिमिटेड।

## सन् १६१३-१७ का वैंकिंग संकट—

बेंक का जीवन जनता के विश्वास पर निर्भर रहता है। यह तो एक साधारण सत्य है कि प्रत्येक बैंक की देन उसके कोष में उपस्थित धन की तुलना में बहुत अधिक होती है। किसी भी बैंक के लिए अपने सभी जमाधारियों को एक ही साथ नकदी में भगतान करना सम्भव नहीं होता है. यद्यपि वैंक अपने प्रत्येक जमाधारी को माँग पर तत्काल नकदी में भूगतान करने का विश्वास देती है। कभी-कभी साधारण नकदी सम्बन्धी माँग की तुलना में कम नकदी अपने पास रखने के कारण बैंक को जमाधारियों को नकदी में भुगतान करने में कठिनाई होती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी-किसी बैंक के दिवालिया हो जाने की निराधार अफवाहें फैल जाती हैं, जिसके कारए सभी जमाधारी तुरन्त नकदी की माँग करने लगते हैं श्रीर बैंक के लिए इस माँग को पूरा करना असम्भव हो जाता है। कुछ दशाओं में आधिक परिस्थितियाँ ही इस प्रकार की उत्पन्न हो जाती हैं कि लोग बैंक से नकदी में भगतान लेने के लिए दौड़ते हैं। ऐसा काल बैंक के लिए बड़ी कठिनाई का काल होता है। यदि बैंक के आदेय अतरल हैं और उसे केन्द्रोय बैंक अथवा अन्य बैंकों से यथासमय सहायता नहीं मिलती है तो उसके लिए जमाधारियों की नकदी की माँग को पूरा करना ग्रसम्भव हो जाता है। स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि यदि कोई बैंक जमाधारियों को नकदी में भुगतान करने से इन्कार करती है अथवा असमर्थ रहती है तो उस पर से जनता का विश्वास उठ जाता है। सभी जमाधारी एक दम नकदी की माँग करने लगते हैं और ऐसी दशा में बेंक पर दौड़ होती है (There is a run on the bank)। अब तो बैंक की स्थिति चिन्ताजनक हो जाती है। यदि इधर-उधर से धन प्राप्त करके वह नकदी की माँग को पूरा कर देती है तो घीरे-घीरे उस पर विश्वास फिर से जम जाता है, परन्तु यदि ऐसा सम्भव नहीं होता है तो बैंक को ग्रपने फाटक बन्द करके दिवालिया हो जाने पर बाध्य होना पड़ता है। व्यवसायिक भाषा में ऐसी स्थिति को बैंकिंग संकट कहते हैं। व्यवहारिक जीवन में ऐसा देखने में म्राता है कि एक बैंक पर से विश्वास उठने के कारण श्रन्य वेंकों के प्रति भी विश्वास में कमी श्रा जाती है श्रीर वैकिंग संकट एक सामान्य रूप धारण कर लेता है।

भारत में इस प्रकार के बैंकिंग संकट अनेक बार ग्रांथे है। सन् १६०५ के परवात् देश में बैंकिंग का विकास इतनी तेजी के माय हुआ था कि उसमें किसी प्रकार का स्थायित्व न ग्रा सका था। वैसे भी भारतीय मुद्रा-वाजार की ग्रस्थायी प्रकृति के कारण बैंकिंग संकट के लिए उपयुक्त दशायें विद्यमान थीं। सन् १६१२-१३ में ही संकट के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे थे। शीष्ट्रजापूर्वक स्थापित होने वाली वेंक युद्धकालीन परिस्थितियों का ग्राघात न सह सकीं। भारतीय मुद्रा-वाजार के विभिन्न ग्रंगों के बीच संगठन का ग्रभाव था, जो एक बड़ी भारी दुर्वलता थी। इसके ग्रतिरक्त भारत की साख प्रणाली में लोच का भी ग्रभाव था। परिखाम यह हुण कि भारतीय बैंकों के लिए एक दूसरे से सहायता प्राप्त कर लेना ग्रौर ग्रावश्यकता के ग्रनुजार निकेपों को घटाना-बढ़ाना कठिन हो गया।

प्रथम महायुद्ध के आरम्भ में ही प्रेसीडेन्सी वेंकों की ब्याज की दर ७-६% थी। युद्ध का आरम्भ होते ही सरकार ने ऋ ए। लेना प्रारम्भ कर दिया। देश मे मुद्रा का विस्तार हुआ और एक प्रकार की सामान्य अभिवृद्धि दृष्टिगोचर हुई। व्यापारियों तथा उद्योगपतियों ने भी ऋगा प्राप्त करके प्रपने व्यवसायों का विस्तार किया । सभो ग्रोर से ऋगों की माँग बढ़ने लगी। परिगानस्वरूप मुद्रा ग्रीर सास की कमी हुई भौर ब्याज की दर ऊपर चढ़ने लगी। वैंकों ने ऊँचे ब्याज का लाभ उठाने के लिए साख-मुद्रा का विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया। निक्षेप वढ़ने लगे और उनकी तुलना में नकद कीण कम रह गये। यह सब एक ऐसे काल में हो रहा था जबिक युद्धकालीन अनिश्चितता के कारए। लोगों का बैंकों के प्रति विश्वास घट रहा था और निक्षेपों को निकालने की मांग बढ़ रही थी। सबसे पहले 'पीपूर्स वैंक ग्रॉफ इण्डिया' पर संकट श्राया और सितम्बर सन् १६१३ में ही वह दिवालिया हो गई। इसका सारो वैंकिंग प्रणाली पर ब्रुरा प्रभाव पड़ा और घीरे-घीरे एय-एक करके बहुत बैंक फेल होने लगीं। . सन् १६१७-१८ तक बैंकों के डूबने का क्रम बराबर चलता रहा और इस काल में ८७ बैंक, जिनकी सामृहिक परिदत्त पूँजी श्रौर निधि १७५ लाख रुग्या थी. बुद गईं। यह पूँजी इस समय की कुल वैंकों की पूँजी का ५०% थी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सन् १६१३ ग्रीर सन् १६२४ के बीच १६१ वें को का विलीयन हुआ है। तत्परचात् सन् १६३१ ग्रीर सन् १६३६ के बीच के काल में ग्रीसत रूप में प्रति वर्ष ६४ बैंक ठण होती रही हैं। सन् १९३८ में 'ट्रावनकोर कोचीन एण्ड किलों बैंक' के निस्तारण ने तो समस्त दांक्षणी भारत में ग्रातंक मचा दिया था।

#### वैंक विलीयन के कारण-

इस संकट के काल में बैंकों के फेल होने के श्रनेक कारण थे। इन कारणों में मुज्य • अब् (३४) से कुछ तो इस प्रकार के थे जो उसी काल से सम्बन्धित थे, परन्तु कुछ कारण ऐसे भी थे जो भारतीय वैंकिंग प्रणाली के दोषों के रूप में ग्रभी तक विद्यमान हैं श्रीर भविष्य के लिए भी संकट से खाली नहीं हैं। प्रमुख कारण निम्न प्रकार थे:—

- (१) म्रिति शीघ्र विकास—स्वदेशी म्रान्दोलन के फलस्वरूप बैंक घास की भाँति उगने लगी थीं। बहुत सी बैंक ऐसे व्यक्तियों द्वारा खोली गई थीं और चलाई गई थीं जिन्हें न तो इस व्यवसाय में किसा प्रकार का म्रनुभव था ग्रौर न ही बैंक संकटों का ज्ञान था। ऐसा कहा जाता है कि 'क्रेडिट बैंक भ्रॉफ इन्डिया' का मैनेजर 'बिल' शब्द का अर्थ तक नहीं जानता था। ऐसी बैंकों का फेल हो जाना स्वभाविक ही था।
- (२) धोखेबाजी—बहुत सी बैंकों ने घोलेबाजी की नीति अपनाई थी। वे अपनी अधिकृत पूँजी को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाती थीं और प्राथित पूँजी तथा परितत पूँजी को, जो अनुपात में बहुत कम रहती थी, छुपा कर रखती थीं। वास्तव में उनके पास कार्यवाहक पूँजी की भारी कमी रहती थी, जिसके कारण संकट की छोटी सी चोट भी उन्हें हुवा देती थी। प्रो० मुरझन ने पता लगाया है कि 'पूना बेंक, पूना' ने अपनी अधिकृत पूँजी १० करोड़ रुपया दिखाई थी, जबिक उसकी प्राथित पूँजी केवल ५० लाख रुपया थी और इसमें से भी प्रत्येक १०० रुपया के अंश पर केवल १५ रुपमें लिये गये थे और इस प्रकार परिवत्त पूँजी केवल ७५ लाख रुपया थी। इसी प्रकार अमृतसर बैंक, पायोनियर बैंक तथा हिन्दुस्तान बैंक जैसी छोटी-छोटी बैंकों ने थोड़े से ही काल में अनावश्यक रूप में अनेक शाखायें खोली थीं।
- (३) निक्षेपों की अधिक वृद्धि—इन बैंकों को पूँजी प्राप्त करने के लिये निक्षेपों पर निर्भर रहना पड़ता था और इसी कारए। ये निक्षेपों पर ऊँचा ब्याज देकर उन्हें अधिक मात्रा में आकर्षित करने का प्रयत्न करती थीं। इस प्रकार इनके ऋए। लेने और ऋए। देने की ब्याज की दरों का अन्तर कम रहता था। अधिक लाभ कमने के लिए उन्होंने नकद कोषों पर समुचित ध्यान दिए बिना निक्षेपों को बढ़ाना आरम्भ किया। बहुत-सी दशाओं में निक्षेपों के पीछे केवल १०-११% नकद कोष रखे गये थे।
- (४) अतरल आदेय—-कुछ बैंकों ने दीर्घकालीन विनियोगों में रूपया लगाने की नीति अपनाई थी। इनके आदेयों में तरलता नहीं रह पाई थी, इस कारण जब निक्षेप-वारियों ने नकदी में माँग की तो बहुत सी बैंक उसे पूरा करने में असमर्थ रहीं। पील्पुस बैंक ऑफ लाहौर, टाटा इण्डस्ट्रियल तथा अमृतसर बैंक के फेल होने का प्रमुख कारण यही था।
- (५) सट्टा व्यवसाय—बहुत सी वैकों ने सट्टा व्यवसाय में भी घ्रपना घन लगाया और व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धी ग्रनेक ऐसे कार्य किए जो किसी भी बैंक

<sup>\*</sup> See S. K. Muranjan: Modern Banking in India, 358-62.

के लिए अवाँछनीय होते हैं। इण्डियन स्पीशी बैंक के फेल होने का प्रमुख कारण मोने, चाँदी श्रीर मोती में स्ट्टेबाजी करना था। इस बैंक ने श्रीर भी बहुत से अनुप्युक्त ऋण दिए थे। प्रो० मुरञ्जन के अनुसार इस बैंक को निम्न प्रकार हानि हुई थीं :---

<del>-</del>	64. 18
चांदी में सट्टा करने से हानि	(लाख रायों में)
	१११
मोती व्यवसाय के सट्टे से हानि	३६
बदला व्यवसाय से हानि	٤٤
भ्रवांछनीय ऋगों से हानि	٧.
कुल हानि	१६५

प्रो० मुरञ्जन ने पता लगाया है कि इस वेंक ने ग्रपने सट्टा व्यवसाय को वरावर ग्रुप्त रखा और यद्यपि इसे सन् १६०६ के पश्चात् लाभ बिलकुल नहीं हुआ था, परन्तु इसने ग्रपनी पूँजी में से २२ लाख रुपये की राशि लाभ के रूप में बाँटी, जो एक बहुत ही अनुचित कार्यवाही थी।

- (६) अनुपयुक्त संचालक—बहुत सी वैंक अनुभवहीन, स्वार्थी तथा घोले-बाज संचालकों के हाथों में थीं। संचालक अपने लिए तथा ऐसे उद्योगों के लिए ऋएा प्राप्त करते रहते थे जिनमें उन्हें रुचि थी अथवा जिनमें उनका निजी स्वार्थ था। भूठे बेखों को तैयार करना, श्रंकेक्षरा को भूठी रिपोर्ट तैयार करना आदि अनेक अनियमित तथा घोलेवाजी के कार्य किये जाते थे। उदाहरसा के लिए, काठियावाड़ एण्ड अहमदाबाद कॉरपोरेशन की लेखा पुस्तकों भी नहीं थीं। पायनियर बेंक की तो परिदत्त पूँ जी भी करानात्मक थी, क्योंकि अंश पूँ जी अंशवारियों को ऋरा के रूप में दी हुई दिखाई गई थी।
- (७) दुर्भाग्य कम से कम दो बैंक केवल अपने दुर्भाग्य के कारण फेल हुईं। किसी न किसी कारण इन पर से जनता का विश्वास उठ गया और इन्हें अपने द्वार वन्द करने पड़े। ऐसी बैंकों में बैंक ऑफ अपर इण्डिया, मेरठ का नाम उल्लेखनीय है। इस बैंक पर पर पीपुल्स बैंक के फेल होते ही सङ्कट आया और इसे ८० लाख रुपये की निक्षेपों का नकदी में भुगतान करना पड़ा, परन्तु बैंक सङ्कट को फेल गई। सन् १६१४ में फिर सङ्कट आया और वैंक हूब गई। ऐसा पता लगा था कि इस बैंक द्वारा दिए हुए सभी ऋणा सुरक्षित थे और विलीयन के पश्चात् भी इसके अंशधारियों तथा निक्षेपधारियों को पूरी राशि मिली थी। इसी प्रकार की दूसरी बेंक एलायंस बैंक आफ शिमला थी। यह बैंक इस कारण फेल हुई कि इसकी बदनामी की फूठी अफवाहें फैल गई थीं और नकनी की माँग असाधारण रूप में इतनी अधिक हुई थी कि उसे किसी भी बैंक द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था।

बें कों के विलीयन से सम्बन्धित उपरोक्त सभी कारण समय विशेष से

<sup>\*</sup> Ibid, p. 353.

सम्बन्धित थे, परन्तु कुछ कारण भारतीय वैंकिंग के श्राधारभूत दोषों के रूप में भी कार्यशील रहे हैं, जो निम्न प्रकार हैं:—

- (१) नकद कोषों का कम अनुपात में रखना—बहुत सी भारतीय बैंक नकद कोप कम अनुपात में रखती हैं। १०-११% नकद कोष रखने पर थोड़ा सा भी संकट आने पर नकदी की माँग को पूरा करना कठिन हो जाता है। ऐसी बैंक की सुरक्षा सदैव सन्देहपूर्ण रहती है।
- (२) म्रपर्याप्त पूँजी—भारतीय बेंकों में भ्रिषकृत तथा स्वीकृत पूँजी की तुलना में परिदत्त पूँजी बहुत ही कम रहती है।
- (३) योग्य प्रबन्धकों तथा निपुरा संचालकों की कमी—यह कमी इतनी अधिक है कि बहुत सी बेंकों को विदेशी प्रबन्धक और कर्मचारी रखने पड़ते हैं।
- (४) अव्यवसायिक व्यवहार—ऐसे अनेक व्यवहार प्रचलित हैं जो व्य-वसायिक दृष्टिकोए से अनुचित हैं, जैसे—निक्षेपों पर ऊँचे व्याज देना, पूँजी में से लाभांश बाँटना, इत्यादि । इस सबका परिएाम यह होता है कि दीर्घकाल में बैंक को घाटा होता है । कृत्रिम लाभों द्वारा निक्षेपदाताओं तथा अंशधारियों को कुछ ही काल तक घोखा दिया जा सकता है । अन्त में पोल खुल ही जाती है ।
- (५) म्रादेयों में तरलता का स्रभाव—कभी-कभी बैंक को कार्य ग्रहक पूँजी का काफी बड़ा भाग म्रतरल म्रादेयों तथा ऐसी प्रतिभृतियों में लगा दिया जाता है जो न तो बहुत विश्वासजनक होती हैं ग्रौर न शीघ्र बेची जा सकती हैं, जैसे—भूमि, बिल्डिङ्ग म्रादि।
- (६) प्रबन्ध की स्वार्थी नीति बहुन सी दशाश्रों में मैंनेजरों श्रौर संचा-लकों के घोखेपूर्ण व्यवहार के कारण भी बैंक फेल हुई हैं। भूतकाल में मैंनेजिंग एजेन्ट इस सम्बन्ध में काफी गड़बड़ किया करते थे।
- (७) बैंकिंग विधान का स्रभाव—देश में समुचित बैंकिंग विधान का स्रभाव रहा है, जिसके कारणा बैंकों को मनमानी कार्यवाहियाँ करने का स्रवसर मिल जाता था। सन् १६४६ के बैंकिंग विधान से यह कमी काफी संश तक दूर हो गई है।
- (८) केन्द्रीय बैंक का ग्रभाव—देश में केन्द्रीय बैंक के न होने से भी विलीयन प्रवृत्ति को रोकना सम्भव न हो सका। प्रतियोगिता के भय से तथा अपना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंक सङ्कट के काल में एक दूसरी को सहायता नहीं देती हैं। ग्रव रिजर्व बैंक की स्थापना ने यह दोष दूर कर दिया है। वैंकिंग संकटों का परिणाम—

प्रथम महायुद्ध के प्रथम अर्द्ध भाग में वैंकिंग संकट के कारण वैंकों पर से जनता का विश्वास हट गया था, परन्तु दूसरे अर्द्ध भाग में स्थिति सुघरने लगी थी।

सबसे अच्छा परिएाम यह हुआ था कि सरकार और जनता दोनों के सम्मुख यह स्पष्ट हो गया कि देश में वैंकिंग के समुचित विकान के लिए उस पर नियन्त्रए आवश्यक था। यह सत्य तो स्वीकार कर लिया गया था, किन्तु किर भी सरकार इस समस्या के प्रति उदासीन ही बनी रही। सन् १६२६ तक इम दिया में लगभग कुछ भी कार्य नहीं किया गया था। महान अवसाद के प्रारम्भ होने पर सन् १६३० में सरकार ने केन्द्रीय वेंकिंग जाँच समिति नियुक्त की। इस समिति को देश के वैंकिंग संगठन की जाँच करने के पश्चात् सुघार के मुक्तव देने का आदेश दिया गया था। समिति ने दो महत्त्वपूर्ण सुक्ताव प्रस्तुत किये—प्रदन्त, इसने केन्द्रीय वेंक की स्थापना पर जोर दिया भीर हुसरे, इसने वैंकिंग विधान बनाने और लागू करने की सिक्तारिश की। परिएगम यह हुआ कि एक और तो १ अप्रैल सन् १६३५ से रिजर्व वेंक ऑक इण्डिया की स्थापना की गई और दूसरो और सन् १६३६ में सन् १६१३ के भारतीय कम्मनीच एक्ट में संशोधन किये गये, जिससे कि वैंकिंग कम्मनियों से सम्वन्यत नियमों में सुधार हो जाय।

प्रथम महायुद्ध के अन्तिम भागों में युद्ध-क्तालीन मुद्रा-क्कीति के कारण जनता के पास अधिक घन पहुँच गया था। फलतः वेंकों के निक्षे में में। वृद्धि होने लगी। इसके कारण वेंकों पर फिर से विश्वास जमने लगा। पहले से स्थापित वेंकों ने अपने व्यवसाय का विस्तार करना आरम्भ कर दिया और कितनी ही नई वेंक चुलने लगीं। इस काल में औद्योगिक वेंकों की स्थापना पर अविक जोर दिया गया और यह कम सन् १६२३ तक चलता रहा, जिस वर्ष 'टाटा इण्डस्ट्रियल वेंक' फेन हो गई। मन्हें१६२१ तक ऐसी वेंकों की संख्या जिनकी परिवत्त पूँजी और सुरक्षित निधि भ लाख काये से बाहर थी, २५ हो गई थी। सभी वेंकों की परिवत्त पूँजी और निधि वढ़ कर कमशः ११ और ७१ करोड़ रुपये हो गई थी। इसी काल में सन् १६२१ में तीनों प्रेसीडेन्सी वेंकों को मिला कर इम्पीरियल वेंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई, जिसकी परिवत्त पूँजी और निधि उस समय ६ ७ करोड़ रुपया थी और जिसके निक्षे में की कुल राशि ७३ करोड़ रुपया थी। सन् १६५५ में इस वेंक का राष्ट्रीयकरण हो गया है और इसका नया नाम स्टेट वेंक ऑफ इण्डिया है।

सन् १६२१ के बाद फिर एक मन्दी का काल ग्राया। सरकार ने भी विस्फीतिक नीति ग्रहण की। एक बार फिर बैंकों की स्थिति डाँवाडोल हो गई ग्रीर विलीयन का क्रम ग्रारम्भ हो गया। जनता की ग्राय के घट जाने के कारण बैंकों के जमाधन में भी कभी ग्राने लगी। सन् १६२१ ग्रीर सन् १६२४ के वीच में बेंकों का जमाधन द० करोड़ रुपये से घट कर केवल ५५ करोड़ रुपया रह गया। इस काल में कुला मिला कर छोटी-बड़ी ४४७ बैंकों का दिवाला निकल गया। फेल होने वाली बैंकों की कुल परिदत्त पूँजी द करोड़ रुपया थी। सन् १६२४ के पश्वात् स्थिति फिर सुबरने लगी ग्रीर सन् १६२५ में ग्राथिक जीवन में सामान्यता ग्रा गई, परन्तु सन् १६३० तक

कोई विशेष प्रगति दृष्टिगोचर न हो सकी । सन् १६३० के पश्चात् वें कों के विलीयन का कम फिर आरम्भ हुआ, जो सन् १६३६ तक चलता रहा । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यद्यपि सन् १६२२ और सन् १६३६ के बीच बेंक भारी संख्या में फेल हुई थीं परन्तु इस काल में बेंकों की कुल शाखाएँ मिल कर तीन गुनी हो गई थीं । सन् १६३७ में दूसरा बेंकिंग सङ्कट आया था, परन्तु उसका प्रभाव दक्षिणी भारत की बेंकों पर ही अधिक पड़ा । अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि सन् १६३६ का विधान भी विलियन प्रवृत्ति को रोकने में अभिकल ही रहा था। इसी कारण सन् १६४२ तथा सन् १६४४ के युद्धकालीन वर्षों में विशेष उपाय किये गये और प्रन्त में सन् १६४६ में विस्तृत बेंकिंग विधान लागू किया गया।

# दोनों महायुद्धों के बीच वैकिंग विकास की विशेषताएँ —

दोनों महायुद्धों के बीच के काल में भारतीय बैंकिंग में एक ही साथ दो बातें स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ती हैं। इस काल में नई बेंकों के खुलने स्रौर पूर्व स्थापित बेंकों के फेल होने का क्रम बरावर चलता रहा है। साधारए।तया मन्दी के स्राते ही देंक फेल होने लगती थीं और सामान्यता के म्राते ही उनकी फिर से स्थापना होने लगती थी। बहुत सी दशास्रों में तो एक ही साथ बैंकों के खुलने स्पीर ठप्त होने का कार्य चलता रहता था था। इस काल के विषय में शायद ऐसा कहना अनुपयक्त न होगा कि भारत का बैंकिंग विकास सब कुछ देखते हुए बड़ा ही अव्यवस्थित रहा है। देश में यथेष्ठ अनुभव, पूँजी तथा साहस को अभाव था। अधिकाँश बेंक बिना भावी विकास की सम्भावनाओं पर विचार किये ही खोल दी जाती थीं। शाखाएँ खोलने के विषय में तो प्रत्येक बैंक उसी स्थान पर शाखा खोलने का प्रयत्न करती थी जहाँ पहले से ही किसी न किसी बैंक की शाखा खुली हुई थी। इस सम्बन्ध में सभी बैंक देश की पाँच बड़ी-बड़ी बैंकों का अनुकरए। करती थीं। जहाँ तक इन पाँच बड़ी-बड़ी बैंकों का प्रश्न थीं. ये भी शाखा खोलने में इम्पीरियल बैंक का अनुकरण करती थी और इस बात की जाँच नहीं करती थीं कि स्थान विशेष में व्यवसाय का अवकाश कितना था। म्राधृतिक बैंकों के साय-साथ देशी बैंकर भी म्रपने कार्यों में व्यस्त थे। इनका माघृतिक बैंकों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा है। म्राधूनिक बैंकों ने उन्हें म्राप्ते साथ मिलाने का कोई प्रयत्न भी नहीं किया था भौर अधिकांश बेंकों ने बड़े-बड़े श्रीद्योगिक श्रीर व्यापा-रिक केन्द्रों पर ही भ्रपनी शाखाएँ खोली थीं।

इस ग्रन्थविस्थित विकास के कारण देश के विभिन्न भागों के बीच बैंकिंग सेवाग्रों का समुचित वितरण न हो सका। उत्तर-प्रदेश, बम्बई, मद्रास, बङ्गाल और पंजाब में बेंकों की संख्या बर बर बढ़ती गई, परन्तु बिहार, उड़ीसा और मध्य-प्रदेश को इनकी सेवाग्रों से लाभ प्राप्त न हो सके। श्री पनानडिकर का विचार है कि लगभग सभी बैंक देशी राज्यों में शाखाएँ खोलने में संकोच करती थीं और यदि इम्पीरियल बेंक ने विशेष सुविधा न दी होती तो शायद ये क्षेत्र बैंकिंग सेवाग्रों से बंचित ही

रहते। \* शाखायें खोलने का कार्य इउनी अनियमित तथा आघारहीन रीति में हुया कि बहुत से छोटे-छोटे नगरों में अनावश्यक ही अनेक शाखाएँ खुन गईं और कितने ही महत्त्वपूर्णं स्थानों को वैंकिंग सेवाएँ प्राप्त न हो सकीं।

इस प्रकार के अव्यवस्थित विकास का दूसरा परिणाम निक्षेत्रों के केन्द्रीयकरण के रूप में दृष्टिगोचर होता है। सन् १६२२ और सन् १६३६ के बीच वेंकों की निक्षेप राशि ७० करोड़ रुपए से बढ़कर ११० करोड़ रुपया हो गई थी, परन्तु हुन उमायन का ५३% इम्पीन्यिल बेंक, विनिमय वेंक तथा सात अन्य वड़ी-बड़ी वेंकों के पास था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सात महान् वेंकों के पास कुल जमायन का ७१% था, जिसमें से ६७% केवल पाँच वेंकों के पास था। इससे स्पष्ट होता है कि छोटी-छोटो बेंक निक्षेपों को आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाई थीं। इस स्थित के प्रमुख कारण निमन प्रकार हैं:—

- (१) छोटी-छोटी बेंकों ने अपना व्यवसाय छोटे-छोटे नगरों में आरम्भ किया था और शाखाएँ भी ऐसे ही नगरों में खोली थीं। इन स्थानों में व्यवसाय की कमी थी और लोगों के पास घन का भी अभाव था। इस कारण इन बेंकों के पास निक्षेप राशि सदा ही कम रही।
- (२) बड़ी-बड़ी बैंकों की शाखाएँ छोटी बैंकों से प्रतियोगिता करती थीं। वे केवल उनका व्यवसाय ही छीनने में सफल नहीं होती थीं, वरन् अपनी ऊँची साख के कारण नीची ब्याज की दरों पर भी अधिक निक्षेप प्राप्त कर लेती थीं।
- (३) बड़े-बड़े ग्रौद्योगिक ग्रौर व्यापारिक केन्द्रों में शाखाएँ खोलने के कारए। बड़ी बैंकों को घनी लोगों का संरक्षण मिलता था ग्रौर इसी कारए। छोटी बैंकों की तुलना में उनकी निक्षेप राशि ग्रविक रहती थी।
- (अ) इम्पीरियल बेंक की प्रतियोगिता के कारए। बड़ी-बड़ी वेंकों को ऐसे व्यापार केन्द्रों से दूर भागना पड़ता था जहां इम्मीरियल बेंक की शाखाएँ थीं। उन्होंने देश के सभी भागों में शाखाएँ खोल कर छोटी बैंकों से प्रतियोगिता की और उनका व्यवसाय छीनने का प्रयत्न किया।
- (५) जिन क्षेत्रों में ब्याज की दरें ऊँची रहने के कारण छोटो-छोटी बेंक लाभ कमाने में सफल हो जाती थीं वहाँ भी बड़ी बैंकों ने शाखाएँ खोल कर उनके व्यवसाय को चौपट कर दिया।
- (६) भारत में शाखा बेंकिंग प्रणाली श्रपनाई गई थी, जिसने निक्षेत्रों के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को श्रौर भी बलवान बना दिया।

<sup>\*</sup> See G. S. Panandikar: Banking in India-

# द्वितीय महायुद्ध श्रीर भारतीय वैंकिंग

द्वितीय महायुद्ध का भारतीय वैंकिंग पर प्रभाव—

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, सन् १६३६ में भारतीय वेकिंग प्राणाली एक संकट के काल से गुजर रही थी। सितम्बर सन् १६३६ में दूपरा महायुद्ध आरम्भ हमा। इस महायुद्ध के भारतीय वैंकिंग पर निम्न प्रभाव पड़े:—

- (i) निक्षेपों में दृद्धि—तत्काल परिगाम यह हुआ कि जनता ने भारी मात्रा में निक्षेपों को निकाला, क्योंकि युद्ध के आरम्भ ने भय की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। थोड़े ही काल में ५.१२ करोड़ रुपये का जमाधन निकाल लिया गया, परन्तु धीरे-धीरे विश्वास का स्रभाव दूर हुआ और निक्षेपों में वृद्धि होने लगी। युद्धकाल में केवल सन् १.३६ और सन् १६४३ के बीच निक्षेपों की मात्रा २४६ ४५ करोड़ से बढ़ कर ६४५.०१ रुपया हो गई।
- (ii) शाखाओं का विस्तार व नई बैंकों की स्थापना युद्धकाल के प्रथम दो वर्षों में तो बैंकिंग की प्रगित धीमी रही, परन्तु तत्परचात् बैंकों ने अपनी शाखाओं का विस्तार किया और अनेक नई बैंक भी खोली गईं। सन् १६४२ और सन् १६४६ के बीच तो बड़ी तेजी के साथ विकास हुआ। सन् १६३६ और सन् १६४६ के बीच के काल में बैंकों की कुल संख्या १,६५१ से बढ़ कर ५,५२१ हो गई। इस काल में खुलने वाली बैंकों में यूनाइटेड कॉमिशियल बैंक, हिन्दुस्तान वॉमिशियल बैंक. हबीब बैंक तथा हिन्दुस्तान मर्केनटायल बैंक के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सभी दृष्टिकोशों से इस काल में उन्नित हुई थी। परिगिणित बैंकों की संख्या सन् १६४६ में ६३ हो गई थी और बैंकों के कार्यालयों की संख्या ३,१०६ तक पहुँच गई थी। जमाधन में भी अधिक वृद्धि हुई और सन् १६४६ में इसकी मात्रा १,०६७ करोड़ रुपया हो गई।
- (iii) महायुद्ध का वैंकों के श्रादेयों श्रीर उनकी लेनों पर प्रभाव—
  युद्धकाल में बेंकों की स्थिर निक्षेपों (Fixed Deposits) में कमी हुई थी। व्यापार
  ऋगों की श्रिष्ठक मांग के कारण याचना ऋगों पर ब्याज की दर ऊँची रही थी।
  सोने-चाँदी की कीमतों में अत्यिषिक परिवर्तन होते रहने के कारण चालू खातों की
  जमा का विस्तार हुआ था। इसके ग्रितिरक्त बैंकों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार
  के ऋगों के अनुपात में भी कमी हुई थी। युद्ध से पहले सम्पत्ति का ६२% तक
  ऋगों में दे दिया जाता था, जो युद्धकाल में घट कर २५% रह गया था। इम्पीरियल
  बैंक में तो यह अनुपात ५५% से घट कर २०% रह गया था। बैंकों के आदेयों में
  तरलता का ग्रंग भी बढ़ गया था। सरकारी प्रतिभृतियों में घन का विनियोग बढ़ा था।
  सभी परिगणित बैंकों के ऐसे विनियोगों का प्रतिशत ५४ से वढ़ कर ६१ हो गया
  श्रीर इम्पीरियल बैंक का ४३ से बढ़ कर ६१, परन्तु इसका ग्रर्थ यह नहीं है कि इस
  परिवर्तन के कारणा बैंकों की लाभ स्थिति में किसी प्रकार की कमी ग्राई थी।

- ( iv ) व्यापार श्रौर व्यवसाय की उन्नति के कारण लाभ का सामान्य स्तर  $\vec{s}$  चा ही बना रहा !
- ( $\nabla$ ) युद्धकाल में बैंकों के नकद कोप भी अधिक हुड़ हो गए। परिगिरात बैंकों के नकद कोप ११% से बड़कर २५% हो गए और उम्मीरियल बैंक के १५% से बड़कर २४%। सभी हिंदिकोणों से युद्धकालीन विकास की स्थिति अधिक सन्तोप-जनक दिखाई पड़ती है। युद्धकाल में बेंकों की दशा इतनी अच्छी हो गई थी। कि उन्हें रिजर्व बैंक से सहायता की भी कम ही आवश्यकता पड़ी थी, परन्तु माँगने पर सहायता भी मिल जाती थी। इस काल में रिजर्व बैंक ने १ करोड़ से लेकर ४ करोड़ रायै तक की वार्षिक सहायता दी थी।
- (vi) देश में वैंकिंग का विकास इतनी तेजी से हुम्रा या कि स्रनुभवी भीर योग्य कर्मचारियों की कमी ऋनुभव हुई। यह कमी एक ग्रंश तक भ्रभी तक भी दूर नहीं हो पाई है।

# युद्धकालीन वैंकिंग प्रसार के कारण-

- (१) मुद्रा-प्रसार—सरकार ने मुद्रा-प्रसार की नीति ग्रह्ण की थी। युद्ध-काल में पत्र-मुद्रा की कुल मात्रा लगभग साड़े छ: गुनी हो गई थी। जनता के पास घन था। व्यापारियों ग्रौर उद्योगपितयों ने ग्रविक लाभ कमाया था। इस घन में से बैंकों को भी जमाधन प्राप्त हुग्रा ग्रौर उनके नकद कोपों का पर्याप्त विस्तार हुमा, जिनके कारण उनकी साख निर्माण शक्ति बहुत बढ़ गई।
- (२) कीमतों के अत्यधिक परिवर्तन—युद्धकाल में सोने-चाँदी और स्थायी सम्पत्ति की कीमत में घोर उच्चावचन हो रहे थे। इनमें रुपया लगाने में जोखिम थी, इसलिए जनता ने फालतू घन को बैंकों में जमा करना ही अधिक उग्युक्त समक्षा।
- (३) ऋरगों की माँग में वृद्धि—युद्धकाल में ऋगों की माँग में भारी वृद्धि हुई। स्वयं भारत सरकार अपनी और ब्रिटिश सरकार की ओर से ऋग ले रही थी। सरकार की सामान्य नीति यही थी कि पत्र-मुद्रा के साथ-साथ साख-मुश का भी विस्तार हो, ताकि युद्धकालीन वित्त सुगमता से प्राप्त हो जाय।
- (४) अभिवृद्धि—युद्धकालीन अभिवृद्धि ने व्यापार तथा उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया था। कीमतों के निरन्तर बढ़ते रहने तथा युद्धकालीन माँग के कारए। लाभ अधिक था। इसने विनियोगों को प्रोत्साहन दिया और ऋगों की माँग को बढ़ा दिया। ऐसी दशा में बैंकिंग व्यवसाय की उन्नति स्वभाविक ही थी।
- (५) मुद्रा के प्रचलन-वेग में वृद्धि— व्यवसायिक तेजी के कारण रुपए का प्रचलन वेग बढ़ गया था और बेंकों के पास बरावर रुपया आता-जाता रवता था। इसने आदेशों में तरलता उत्पन्न कर दी और बेंकों को साख का अधिक विस्तार करने का अवसर दिया।

(६) रिजर्व वैंक की उदार नीति—रिजर्व वैंक ने भी साख विस्तार को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई और वैंकों द्वारा नई शाखाएँ खोलने तथा नई वैंकों की स्थापना का विरोध नहीं किया, विलक्ष उत्टा प्रोत्साहन दिया।

इस काल में परिगिए।त वैंकों के विकास के साथ-साथ अपरिगिए।त वैंकों की भी चन्नित हुई ग्रीर सन् १६३६ तथा अन् १६४६ के बीच उनकी भी संख्या २३१ से बढ़ कर २८८ हो गई, परन्तु इस सारी उन्नित का अर्थ यह नहीं होता है कि इस विकास में किसी प्रकार का दोष नहीं था। यद्यपि रिजर्व बैंक के खुल जाने तथा सन् १६३६ के कम्पनीज एक्ट में किए गए संशोधनों ने वैंकों के विलीयन का भय काफी अंश तक दूर कर दिया था, परन्तु फिर भी सन् १६३६ ग्रीर सन् १६४० में कुछ वैंक फेल हो गई थीं। सन् १६४१ में लड़ाई सुदूरपूर्व के क्षेत्र में फैल गई थी, जिसके कारए। विनिमय बैंकों के प्रति अविश्वास उत्पन्न हुआ श्रीर उसके निक्षेप घटने लगे, यद्यपि अन्य बैंकों के निक्षेप बराबर बढ़ रहे थे।

# भारत में युद्धकालीन वैंकिंग विकास के दोष-

साधारणतया द्वितीय महायुद्ध के काल में भारतीय बैंकिंग का ग्राधार सुदृढ़ रहा है, परन्तु यह भी पूर्णतया दोषरिहत नहीं रह पाया है। इस काल में बैंकों की संख्या में ग्रीर उनकी शाखाग्रों में भारी वृद्धि हुई है। ग्रिधकांश शाखाएँ ऐसे स्थानों में खुली हैं जहां पहले से ही बैंकिंग सेवाएँ विद्यमान थीं। इसका परिणाम यह हुग्रा है कि बैंकों के बीच पारस्परिक प्रतियोगिता बढ़ी है, जो बहुत सी दशाग्रों में ग्रनाथिक हो गई है। यह स्वयं बैंकों के लिए नहीं, बित्क राष्ट्रीय ग्रर्थ-व्यवस्था के लिए भी महितकर है। इस विकास के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं:—

- (१) देश में अधिकोष सेवाओं का असमान तथा अनाधिक वितरण हुआ है। कितने ही स्थान ऐसे हैं जहाँ आवश्यकता होते हुए भी वैंकिंग सेवाएँ स्थापित नहीं हो पाई हैं। इसके विपरीत बहुत से स्थानों पर इन सेवाओं की अनावश्यक दोबारगी हुई है।
- (२) म्रानार्थिक प्रतियोगिता बढ़ी है म्रोर सेवाम्रों की दोगरगी के कास्सा संचालन व्यय भी बढ़ा है।
- (३) युद्धकाल में अधिकोषगा लाभ और लाभांश इतने बढ़े थे कि बैंकों के अशों तथा अन्य प्रतिभूतियों में सट्टा होने लगा था।
- (४) सहकारी हुण्डियों की कीमत बढ़ जाने के कारए। लाभों का उपयोग सुरक्षित कोष को बढ़ाने के स्थान पर लाभाँश बाँटने के लिये ग्रधिक हुन्ना था।
- (५) युद्धकालीन विकास का सबसे बड़ा दोष यह है कि बैंकिंग व्यवसाय का संचालन ऐसे व्यक्तियों के हाथ में चला गया है जिनका मुख्य व्यवसाय व्यापार अथवा उद्योग है। यूनाइटेड कॉर्माशयल बैंक बिड़ला ब्रादसं ने खोली है। इसी प्रकार हिन्दुस्तान कॉर्माशयल बैंक सिंघानिया ने और भारत बैंक जिसका श्रव पंजाब नेशनल बैंक में

विलय हो चुका है, डालिमिया ने। यह एक ब्रत्यधिक दोषपूर्ण प्रवृत्ति है, जो वैकिंग ब्यवसाय को ब्रत्य व्यवसायों पर आश्रित कर देती है ब्रौर उसके सहिचत ब्रायार को समाप्त कर देती है।

- (६) जितनी तेजी के साथ वैकिंग का विस्तार हुम्रा है उसकी तुलना में योग्य भौर म्रनुभवी वर्मचारी बहुत ही कम संस्था में उत्पन्न हुए है।
- (७) शाखार्ये खोलने में बहुषा प्रव्यवसायिक हिन्तीरा अपनाया गण है। कुछ बेंकों ने ऐसे क्षेत्रों में शाखार्ये खोली हैं जिनसे उनका व्यवसायिक सम्बन्ध वित्कृत नहीं था। शाखा खोलने में व्यवसाय खोजने के स्थान पर अन्य वंकों से प्रतियोगिता करने का हिन्तिरा अधिक महत्त्वपूर्ण रहा है।
- ( प्र) लेखों में हेर फेर करने और व्यवसाय की सही स्थिति को खियाने की प्रवृत्ति बलवान हो गई है। युद्धकालीन श्रभिवृद्धि का नाभ उठाने के लिए अनुचित रीतियों का भी उपयोग बढ़ा है।
- ( ६ ) विलीयन का क्रम युद्धकाल में भी चलता रहा है। सन् १६३६ में ६० ग्रीर सन् १६४० में १०२ वैंक फेल हुई थीं। उसके परचात् ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध की प्रगति के साथ इस प्रवृत्ति का बल घटता गया है, यद्यि कुछ वैंक वराबर दिवालिया होती गई हैं। सन् १६४१ में ७७, सन् १६४२ में ४६, सन् १६४३ में ५१, सन् १६४४ में २२, सन् १६४५ में २६ ग्रीर सन् १६४६ में २७ बैंक फेल हुई हैं। इस प्रकार सन् १६३६-४६ के काल में ४४४ बैंक फेल हुई हैं, जिनमें कुछ छोटी-छोटी बैंक सम्मिलित नहीं हैं, जो इनके श्रतिरिक्त हैं।

#### भारत के वँटवारे का प्रभाव-

युद्ध का अन्त होने पर भी भारतीय वैंकिंग का सुदृढ़ आघार बना ही रहा है। युद्धोत्तर काल में बेंकों की ऋरणदान शक्त में वृद्धि हुई है और उनके नकद कोपों का अनुपात घटा है। कीमतों की वृद्धि हो जाने के कारण कार्य-व्यय भी बढ़ा है, परन्तु बेंकों के लाभ में कोई विशेष कमी नहीं आई है। इस काल में चालू निक्षेत्रों में कमी आई है और स्थायी निक्षेप बढ़े हैं। उपयुक्त कर्मचारियों की कमी के कारण सन् १६४६ के अन्त में एक छोटा सा वैंकिंग संकट फिर आया था, जिसका मुख्य प्रभाव बंगाल में दृष्टिगोचर हुआ था। बंगाल की कुछ बेंकों ने अंशों की आड़ पर अधिक ऋरण दिये थे, जिसके कारण रोक निधि का अभाव हो गया और उन्हें भुगतान रोकने पड़े। इससे बहुत सी छोटी-छोटी बैंक दिवालिया हो गई। रिजर्व बेंक को एक ऐसा आदेश भी निकालना पड़ा है कि सट्टा व्यवहार के लिए ऋरण न दिए जार्ये। सन् १६४६ में ही रिजर्व बेंक ने शाखा विस्तार पर नियन्त्रण रखने के लिए सरकार से नियम पास करा लिए थे।

१५ ग्रगस्त सन् १६४७ को देश का विभाजन हुग्रा । विभाजन के साथ ही साम्प्रदायिक भगड़े हुए ग्रौर पंजाब तथा बंगाल में पूरी ग्रराजकता रही । देश में श्रायात-निर्यात, ज्रुत्पादन तथा सम्पत्ति का भारी विनाश हुया। पंजाब की वैंकों को हानि श्रिष्ठिक हुई, जिसका सही अनुमान श्रभी तक भी नहीं लगाया जा सका है। विभाजन के फलस्वरूप करोड़ों की संख्या में लोगों को अपने घर-वार छोड़ने पड़े। इसके श्रितिरिक्त श्रिनिश्चितता ने सट्टा व्यवसाय को भी प्रोत्साहन दिया। सन् १६४७ में ३० श्रपरिगिएत बैंकों का विलीयन हुमा और इस विलीयन के कारण श्रन्य बैंकों के लिए भी कठिनाई हो गई। विभाजन होने से पहले ही पंजाब की कुछ बैंकों ने अपने कार्यालयों को दिल्ली तथा पूर्वी पंजाब को स्थान्तरित करना और पश्चिमी पंजाब में ऋगों का कम मात्रा में प्रदान करना श्रारम्भ कर दिया था, परन्तु व्यवहार में ऐसा कम ही हो पाया था। विभाजन के होते ही बहुत सी बैंकों को श्रपनी पश्चिमी पंजाब की शाखाएँ वन्द करनी पड़ीं। ऋगु वसूल न हो सके और श्रादेयों का भारत को हस्तान्तरण श्रसम्भव हो गया। तुरन्त ही रिजर्व बैंक ने सहायता की योजना लागू की भीर श्रन्य बैंकों को विलीयन प्रभाव से बचाने का प्रयत्न किया। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने निम्न कार्य किए:—

- (१) रिजर्व बैंक एक्ट में ऐसा संशोधन किया गया कि उपयुक्त प्रतिभूतियों की म्राड़ पर अपरिगिएत बैंकों को भी रिजर्व बैंक से ऋगा प्राप्त करने का मधिकार दिया गया।
- (२) एक ऐसा म्रादेश निकाला गया जिसके म्रनुसार दिल्लो तथा पूर्वी पंजाब राज्यों में स्थित बैंकों के विरुद्ध तीन मास तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती थी। यह नियम बनाया गया कि स्थगित शोधन काल में ये बैंक म्रपने भारत स्थित चल निक्षेपों का केवल १०% म्रथवा २५० रुपये का (जो भी कम हो) भुगतान कर सकती थीं।
- (३) ऐसी बंकों के पुनर्वास के लिए सरकार ने १ करोड़ रुपये की सहा-
- (४) रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों के निरीक्षण और उसके सम्बन्ध में सरकार को रिपोर्ट देने का भी अधिकार प्राप्त किया ।

इस प्रकार बँटवारे के दुष्परिसामों से बैंकिंग प्रसाली की रक्षा करने का प्रयत्न किया गया। आगे की घटनाओं में सन् १९४९ का बैंकिंग विद्यान तथा सन् १९५५ का संशोधन नियम महत्त्वपूर्ण हैं। इनका विस्तृत अध्ययन अगले अध्याय में किया जायगा।

### विलीयन प्रवृत्ति को रोकने के उपाय —

बैंकों की विलीयन प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि बैंकों के संचालन के सामान्य मान को ऊपर उठाया जाय। छोटी बैंकों के सम्बन्ध में तो यह बहुत ही आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न सुफाव दिये जा सकते हैं —

(क) शिक्षा—वैंकिंग सिद्धान्त तथा व्यवहार सम्बन्धी शिक्षा इस सम्बन्ध

में काफी लाभदायक हो सकती है। साथ ही साथ, यह भी श्रावश्यक है कि वंकों में पारस्परिक सहयोग की भावना उत्पन्न की जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् १६२५ में 'इण्डिया इन्स्टीट्यूट ग्रॉफ वेंकसें' स्थापित की गई थी। यह इन्स्टीट्यूट भाषणों की व्यवस्था करती है, परीक्षायें लेती है ग्रौर ग्रपनी एक तिका भी निकालती है। इसके श्रतिरिक्त कुछ राज्य सरकारें भी वेकिंग शिक्षणा की व्यवस्था करती हैं, परन्तु ग्रावश्यकता इस बात की है कि ऐसी संस्थाग्रों की क्रियाग्रों का विस्तार किया जाय। देश में योग्य प्रवन्त्रकों ग्रौर कर्मचारियों का ग्राज भी बहुत ग्रभाव है।

- (ख) वैधानिक व्यवस्थायें बैंकों के समुचित संवालन के लिए समय-समय पर भारत सरकार वैधानिक व्यवस्थाएँ करती रही है। तन् १६३६ के वैकिंग कम्पनीज एक्ट में इस सम्बन्ध में कुछ प्रकार की व्यवस्थायें की गई थी। विना समु-चित पूँजी के कार्य करने और अशिक्षित संचालकों तथा मैनेजिंग एजेन्टों के प्रभाव को दूर करने के लिए सन् १६४६ के वैकिंग कम्पनीज एक्ट में काकी विस्तृत व्यवस्थायें की गई हैं। इन व्यवस्थायों द्वारा बैंकों के विजीयन का भय बहुत कुछ दूर हो जाने की ग्राशा है।
- (ग) रिजर्व बैंक का नियन्त्रग्—यह आवश्यक है कि सभी बैंकों पर कड़ा नियन्त्रण रहे, जिसके कारण उनके अनुचित व्यवहार हो रहें। इन कार्य के लिए सन् १६४६ के एक्ट में रिजर्व बैंक को महत्त्वपूर्ण अधिकार दिये गये है। सिछले वर्षों में सभी बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ने ऋणों, अग्रिमों तथा व्यवसायों के सम्बन्व में आदेश निकाले हैं, जिनका पालन वास्तव में बैंकों को फेल होने से रोक सकता है, परन्तु इस सम्बन्ध में इस महत्त्वपूर्ण कथन को याद रखना आवश्यक है कि अच्छे नियम एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो केवल अच्छे बैंकरों द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

## भारतीय वैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ वनाने के उवाय-

समय-समय पर रिजर्व बैंक भारतीय वैकिंग को स्थिति की जाँच करती रहती है ग्रौर इस सम्बन्ध में वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करती है। जो दोप सामने ग्राये हैं उन्हें दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने कुछ सुभाव रखे है। विभिन्न विषयों से सम्बन्धित सुभाव निम्न प्रकार है:—

(१) प्रबन्ध के विषय में — भारत की वैंकों को कुशल, शिक्षण प्राप्त तथा अनुभवशाली प्रबन्धकों की सेवाओं के बहुत ही कम लाभ प्राप्त हैं। इसी प्रकार बहुत सी बैंकों में भीतरी निरीक्षण तथा श्रंकेक्षण प्रणाली भी दोपपूर्ण होती है। संवालकों को न तो श्रपने कार्य का ज्ञान होता है और न उसके करने की योग्यता। बैंक के कुशल संवालन के लिए यह श्रावश्यक होता है कि संवालक न केवल उसके कार्य में रुचि लें बिल्क समय-समय पर सप्रभाविक निरीक्षण भी करते रहें। इस कारण रिजवं बैंक ने

कर्मचारियों के शिक्षरा, उनकी नियुक्ति में सावधानी तथा उनकी कार्य-विधि में सुवार के सुभाव दिये हैं।

- (२) विनियोग नीति—इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा किये गये ग्रध्ययन से पता चलता है कि बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में कम धन को लगाती हैं ग्रीर उनके विनियोगों का तरलता ग्रनुपात कम रहता है। ग्रपरिगिएत (Non-Scheduled) बैंकों में ऋणों की मात्रा तो घ्रधिक रहती है, परन्तु कुल निक्षेपों की तुलना में सरकारी प्रतिभूतियों में उनका विनियोग बहुत कम रहता है। ऐसा पता लगाया गया था कि १२३ बैंकिंग कम्पनियाँ या तो सरकारी प्रतिभूतियों में धन लगाती ही नहीं थीं या उनका ऐसी प्रतिभूतियों में विनियोग कुल निक्षेपों के १% से भी कम था। सन् १६५१ से रिजर्व बैंक प्रत्येक बैंक से ऐसा विवरण मांग रही है कि उसने सरकारी प्रतिभूतियों में कितना धन लगा रखा है। बैंकों को यह समभाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है कि वे ऐसी प्रतिभूतियों में विनियोग की मात्रा को बढ़ावें, ताकि उनके ग्रादेयों की तरलता बढ़े ग्रीर उन्हें जन-साधारण से ग्रधिक विश्वास प्राप्त हो सके।
- (३) ऋरग नीति—इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। बहुत सी बंक अपनी क्षमता के बाहर भी ऋग् दे देती हैं और ऋग लेने वाले की साख की समुचित जांच किये बिनः तथा बिना उपयुक्त प्रतिभूतियों के भी ऋग दे दिए जाते हैं। अधिकत्यम् लाभ कमाने के लिए बैंक अपने ऋगों की मात्रा को बढ़ाती जाती है। सन् १६४६ के नियम में समय और मांग देन के २०% को तरल आदेयों में रखने की व्यवस्था की गई है, जो बहुत लाभदायक हो सकती है, परन्तु यह आवश्यक है कि ऋग देने से पहले लेने बाले की शोधनक्षमता की समुचित जाँच की जाय। अचल सम्पित की आड़ पर कम ऋग दिये जायें और जोखिम में विविधता प्राप्त करने के लिए यथासम्भव विभिन्न प्रकार के ऋग दिये जाएँ।
- (४) लाभाँश नीति—लाभांश घोषित करने से पहले बैंकों को अबिक्री साध्य आदेयों, अशोध्य ऋणों तथा विनियोगों के अवसूत्यन के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में नकद शेषों का भी पर्याप्त मात्रा में रखना आवश्यक है। इस विषय में सन् १६४६ के एक्ट की व्यवस्थाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। कोई भी बैंक अपने लाभों के २०% से अधिक को उस समय तक नहीं बांट सकती है जब तक कि उसका सुरक्षित कोष परिदत्त पूँजी के बराबर न हो जाय, परन्तु और अधिक कोषों की व्यवस्था से स्थित और भी सुबर सकती है। इसलिए बैंकों को केवल न्यूनतम् वैद्यानिक सीमा पर संतोष नहीं करना चाहिए, बिलक अपने नकद कोषों को और अधिक बढ़ाना चाहिए।
- (५) शाखा नीति—बिना सोचे-विचारे शाखाओं के बढ़ाने से बैंक, बैंकिंग प्रणाली तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को काफी हानि हो सकती है। ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने इस बात का प्रनुरोव किया है कि नई शाखाएँ खोलने के स्थान पर

वर्तमान दशाश्चों के प्रस्तुत व्यवसाय के आघार को मुद्द बनाना प्रधिन उपयुक्त होगा। यद्यपि यह आवश्यक है कि अच्छी-अच्छी वैंक प्रामीगा क्षेत्रों तथा छोटे-छोटे नगरों में शाखाएँ खोलें, परन्तु शाखायें इस प्रकार न खोली जायें कि पारस्परिक प्रतियोगिता बढ़े। रिजर्व वैंक का यह कर्त्तव्य है कि वह इस दिशा में सतर्क रहे।

(६) वैंकिंग रीतियों में सुधार—यह भी ब्रावस्यक है कि रार्व-विधयों में सुधार हों और सनुचित वैंकिंग सिद्धान्तों के ब्राधार पर कार्य को चलाया नाय। भूत काल में ब्रनेक वैंकों ने समुचित वैंकिंग सिद्धान्तों के ब्रनुसार कार्य नहीं किया है।

## वैंकिंग का राष्ट्रीयकरण

#### (Nationalisation of Banking)

ग्राधुनिक संसार में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के ममर्थक बहुद है। ऐसा कहा जाता है कि ये महत्त्वपूर्ण संस्थायें सरकार के हाथ में रहती चाहिए, जिससे कि इनका संचा-लग राष्ट्रीय हितों को उन्नत करने के लिए किया जा सके। इसके प्रतिरिक्त यह भी भ्रमुभव किया गया है कि बैंकिंग सेवाओं के उपयुक्त नियन्त्रण का सबसे महत्त्वपूर्ण उपाय उनका राष्ट्रीयकरण ही है।

#### वैंकिंग के राष्ट्रीयकरण की ऋावश्यकता—

बैंकों की प्रकृति ऐसी है कि उनका राष्ट्र के श्रायिक श्रीर सामाजिक जीवन में भारी महत्त्व रहता है । बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण की श्रावश्यकता निम्न प्रकार बताई जाती है:—

- (१) समुचित साख नियन्त्ररा बैंकों का प्रमुख व्यवसाय साख-निर्माण होता है, जो वर्तमान श्राधिक जीवन की प्रमुख श्रावश्यकता है, परन्तु साख एक ऐसा श्रस्त्र है जिसका कत्यारा तथा विनाश दोनों ही उद्देशों के लिए उपयोग किया जा सकता है। साख का नियन्त्ररा बहुत ही श्रावश्यक है, जिससे कि उसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ बढ़ाने के लिए न होकर राष्ट्रीय कत्यारा के लिए हो सके। श्रनुभव वताता है कि साख तथा राष्ट्रीय आवश्यकताश्रों का ठीक ठीक समायोजन केवल वैकिंग के राष्ट्रीयकररा द्वारा ही सम्भव हो सकता है।
- (२) व्यापार चकों से बचाव—व्यापार चकों के काल में वैंक-मुद्रा तथा बैंकिंग नीति का भारी महत्त्व होता है। वैंकों की बुद्धिहीनता के कारण तो व्यापार चक्र उत्पन्न होते ही हैं, परन्तु यदि कोई समुचित वैंकिंग नीति अपनाई जाय तो आधिक संकटों की कूरता बहुत ग्रंश तक दूर की जा सकती है। यद्यपि व्यापार-चक्कों को पूर्णतया समाप्त करना तो कठिन होता है, परन्तु साख-मुद्रा के समायोजनों द्वारा उनकी कूरता एक बड़े ग्रंश तक घटाई जा सकती है। समाजवादी देशों में, जहां वैंकिंग का राष्ट्रीयकरण ही एक सामान्य नियम है, व्यापार-चक्र दृष्टिगोचर ही नहीं होते है।
  - (३) बैंकिंग सेवाभ्रों का पर्याप्त विकास -- आधुनिक युग में राष्ट्रीय व्यानार

तथा वािराज्य के अर्थ-प्रवन्ध के लिए बैंकों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। इस कारण यह उचित होगा कि बैंकिंग सेवाएँ ऐसे उद्देशों के लिए तथा उस ग्रंश तक उपलब्ध की जायें कि राष्ट्रीय हितों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय-करण ही एक मात्र उपाय है।

- (४) लाभों का लोक कल्याण हेतु उपयोग— वेंक लोक-धन तथा जनता के विश्वास में व्यवसाय करती हैं, इसलिए अच्छा यही है कि उनके लाभ भी जनता को प्राप्त हों, न कि निजी व्यक्तियों को । राष्ट्रीयकरण द्वारा ये लाभ सरकारी कोष में पहुँचते हैं और इनका उपयोग लोक कल्याण की उन्नति के लिए किया जा सकता है। भारत में तो वेंकिंग के राष्ट्रीयकण्ण की आवश्यकता कई कारणों से और भी बढ़ गई है।
- (५) भारतीय पूँजी परम्परा से ही शर्मीली है—इस दोष को दूर करना देश के भावी विकास के लिए बहुत मावश्यक है। देश में एक छोर तो बचत ही कम हो पाती है और दूसरी छोर बचत का अधिकाँश भाग आसंचित कोषों में चला जाता है, जिससे पूँजी के निर्माण में बाघा पड़ती है।
- (६) देश में बैंकों का विकास कुछ इस प्रकार हुआ है कि कुछ स्थातों में बैंकों की संख्या आवश्यकता से बहुत श्रिधक है और उनके बीच हानिशूर्ण और अनुचित प्रतियोगिता है, जबकि सामान्य रूप में देश के भीतर बैंद्धिंग सेवाओं की कमी है।

इसी प्रकार कई अन्य कारणों से भी भारतीय बेंक्किंग जनता में विश्वास उत्पन्न नहीं कर पाई है। आरम्भ में अनेक बैंकों का प्रबन्ध विदेशियों के हाथ में था, जिसके कारण बैंक बराबर विदेशी संस्थाएँ समभी जाती थीं। दूसरे, भारत में बेंकिंग का विकास भी आयोजित रीति से नहीं हुआ है। तीसरे, बैंकों के विलीयन की संख्या बहुत अधिक रही है। सन् १६१३ मे ५०-५५ बैंक फेल हो गई थीं। सन् १६१३ और सन् १६३६ के बीच २३० बैंक ठप्प हो गई, सन् १६३६ और सन् १६३८ के बीच ६४ बैंक प्रति वर्ष फेल होने का औसत रहा है और सन् १६४६ तथा सन् १६५१ के बीच में भी ४० बड़ी बैंक फेल हो गई थीं।

हमारी वैंकिंग प्रिणाली की एक विशेषता यह है कि ग्राधिक हिष्टिकीस से रिजर्व बैंक साख नीति के नियात्रस में ढीली रही है। यद्यपि ग्रावश्यकता पड़ने पर सरकार रिजर्व वैंक को ग्रावश्यक ग्रधिकार दे देती है, परन्तु इसमें विलम्ब होता है। इस समस्या का महत्त्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि युद्धोत्तर-काल में सरकार सभी साख नियन्त्रस उपायों का उपयोग करने पर भी कीमतों में स्थायित्त्व लाने में सफल नहीं हो पाई है। पिछले कुछ दिनों से दशाएँ कुछ बदलती हुई ग्रवश्य दीख रही हैं।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली की दो 'श्रीर भी विशेषताएँ घ्यान देने योग्य हैं। प्रयम, देश में साधारणत्या व्यापार बैंकों की ही प्रधानता है श्रीर श्रीदोगिक तथा कृषक वित्त का भारी श्रभाव है। यह एक-दिशाई विकास ठीक नहीं है। दूसरे, भार-

तीय वाकग का एक महत्त्वपूर्ण भाग सभी तक भी विदेशियों द्वारा चलाया जाता है। लगभग सभी विविमय बैंक विदेशी हैं।

जपरोक्त विवेचन से पता चलता है कि भारतीय बैंक का समुचित नियन्त्रण्य आवश्यक है। दूसरे महायुद्ध के काल में यह भी सिद्ध हो गया है कि समुचित नियन्त्रण्य द्वारा भारतीय वैकिंग प्रणाली का किसी भी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपरोग करना सम्भव है। इस नियन्त्रण् के लिए तथा वैकिंग के अन्य दोषों को दूर करने के लिए राष्ट्रीयकरण् ही उपयुक्त है।

जहाँ तक भारत में वैकिंग के राष्ट्रीयकरण के व्यवहारिक रूप का प्रश्न है, प्रथम जनवि सन् १६४६ से भारत सरकार ने रिजर्व वैंक का तो राष्ट्रीयकरण कर ही लिया है और साथ ही में इम्पीरियल वैंक के राष्ट्रीयकरण को भी सम्मन्न किया है। सारी वैंकिंग प्रणाली के राष्ट्रीयकरण का कोई विचार ज्ञात नहीं होता है। राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हम केवल इतना कह सकते हैं कि सरकारी व्यवसायों में व्यक्तिगन सम्पर्क, लोच, मितव्ययिता, शासन की कुशलता, समायोजन आदि गुण कम अंग तक प्राप्त हो पाते हैं। इधर भारत सरकार ने जीवन वीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके वैंकों के राष्ट्रीयकरण की सम्भावना को बढ़ा दिया है।

### राष्ट्रीयकरण के विरोध मं-

राष्ट्रीयकरण के विरोध में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। भारत में विरोधी पक्ष ने तीन महत्त्वपूर्ण तकों को अपने दृष्टिकोण का आधार बनाया है—(१) यह कि भारत में सरकारी उद्यांगों का कार्य बहुत सराहनीय नहीं रहा है। इनका कार्य अकुशल, विलम्बपूर्ण तथा बहुधा अपन्ययी रहा है। भय यही है कि राष्ट्रीयकरण के द्वारा बेंकिंग सेवाओं की कुशलता मारी जायगी। (२) उद्योगपितयों और व्यवसायिओं को यह भय है कि उनके व्यवसायों की गोपनीयता समाप्त हो जायगी। राष्ट्रीयकृत बैंकिंग सभी के साथ मन-मानी कर सकती है। (३) राष्ट्रीयकृत बैंकिंग व्यवसाय को चलाने के लिए सरकार के पास योग्य और निपुण कर्मचारी नहीं है, जिससे व्यवसाय का समुचित संचालन कठिन हो जायगा।

इन सभी तकों को देखने से पता चलता है कि ये बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। इसमें तो सन्देह नहीं है कि राष्ट्रीयकरण की भी अपनी समस्याएँ होती है, परन्तु यह कहना उचित न होगा कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों की कुशलता अवश्य ही व्यक्तिगत उद्योगों से कम रहती है। इसी प्रकार कर्मचारियों की कमी तो व्यक्तिगत स्वामित्त्व के अन्तर्गत भी रहेगी।

## भारतीय वैंकिंग की नदीन प्रवृत्तियाँ—

भारतीय वैकिंग का वर्तमान स्वरूप उन सरकारी नीतियों द्वारा निश्चित होती हैं जो स्वतन्त्रता के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने ग्रहण की हैं। इस काल में सरकार ने मु०च० प्र० (३५)

वेंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के अनेक उपाय किये हैं। इस दिशा में प्रमुख सरकारी कार्य निम्न प्रकार हैं:---

- (१) रिजर्व वैंक का राष्ट्रीयकरणा—यह इस दिशा में सबसे पहला महत्त्वपूर्ण कार्य था। प्रथम जनवरी सन् १६४६ से रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है। उद्देश्य यह था कि देश की केन्द्रीय वैंक की शक्ति और सप्रभाविकता में वृद्धि की जाय। राष्ट्रियकरण द्वारा यह आशा की गई है कि रिजर्व बैंक सरकार की आर्थिक नीति और देश के आर्थिक विकास में अधिक सहयोग दे सकेगी। वास्तव में आर्थिक नियोजन को आरम्भ करने से पहले यह राष्ट्रीयकरण उपयुक्त ही था। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् का ऋनुभव भी यह स्पष्ट कर देना है कि राष्ट्रीयकरण लाभदायक ही रहा है।
- (२) नया बैंकिंग कम्पनी विधान—मार्च सन् १६४६ से देश में बैंकिंग कम्पनी विधान लागू कर दिया गया है। उद्देश्य यह है कि देश की बैंकिंग व्यवस्था का समुचित वैद्यानिक नियमन किया जा सके और उसका विकास आरोग्य रूप में हो। इस विधान में रिजर्व बैंक के अधिकारों में अधिक वृद्धि की गई है। अब केन्द्रीय बैंक देश की बैंकों का समय-समय पर निरोक्षरण कर सकती हैं, बिना अनुज्ञापन प्राप्त किये कोई नई बैंक नहीं खोली जा सकती है, जन-साधारण के हित में रिजर्व बैंक बैंकों की किसी भी अनुचित कार्यवाही को रोक सकती है और निक्षेपधारियों के हितों की रक्षा का विशेष उत्तरदायित्व केन्द्रीय बैंक के अपर रखा गया है।
- (३) एकीकरण को प्रोत्साहन—ऐसा अनुभव किया गया है कि बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का उपाय उनका एकीकरण भी है। एकीकरण की नीति को सरकार और केन्द्रीय बैंक दोनों ने स्वीकार किया है। यह कम सन् १६५० में बङ्गाल की चार बैंकों को मिला कर आरम्भ किया गया और तत्वश्चात् सन् १६५१ में भारत बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। स्टेट बैंक की पुनर्संगठन योजना के अन्तर्गत ऐसी दस बैंकों को जो राज्य सरकारों के अधिकार में थीं, स्टेट बैंक में मिलाया जा रहा है।
- (४) स्टेट बैंक ग्रॉफ इण्डिया का निर्मागा—१ जुलाई सन् १६५५ से इम्पीरियल बेंक ग्रॉफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है ग्रौर उसे स्टेट वेंक ग्रॉफ इण्डिया के नाम से एक नये ग्रावार पर संगठित किया गया है। उद्देश यह है कि ग्रामीण ग्रौर पिछड़े हुए क्षेत्रों को ग्रीधक वैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध की जायें। इसके ग्रीतिरक्त सहकारी बेंकिंग के विकास में भी इससे काफी सहायता मिलेगी। स्टेट वैंक को सन् १६६० तक ४०० नई शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे-छोटे नगरों में खोलने का भी ग्रादेश दिया गया है।
- (४) निस्तारण विधि में सरलता—सन् १६५० में प्रथम बार यह अनुभव किया गया था कि भारत में बेंकों की निस्तारण व्यवस्था (Process of

Liquidation) बहुत जटिल और दिलम्बपूर्ण थी। एक नियम हारा इसको सरन भौर सीव्रगामी बनाने का प्रयत्न किया गया है।

(६) वैंक शिक्षा का स्रायोजन — वैकिंग शिक्षा की कमी हमारे देश के समुचित वैकिंग विकास के मार्ग में एक भारी व घा है। विगत वर्षों में रिजर्व वैंक ने इस ग्रोर भी घ्यान दिया है। इण्डिया इन्स्टीट्यूट श्रॉफ वेंटमंके कार्यों का विस्तार किया गया है। साथ ही, रिजर्व बैंक द्वारा एक ऐसा कॉलिज स्थापित किया जा रहा है जहाँ वैंकों के प्रबन्धकों ग्रौर कर्मचारियों को ग्रावश्यक सैंडान्तिक ग्रौर व्यवहारिक शिक्षा दी जायशी।

## बैंकों का एकीकरण

## एकीकरण का अर्थ-

एकी करए। का श्रभिप्राय विलय श्रथवा मिल जाने से होता है। जब दो यादो से प्रविक बैंक इस प्रकार एक दूसरे से मिल जाती हैं कि इन सबका व्यक्तिगत प्रस्तित्त्व मिट जाता है और एक ऐसी संस्था का निर्माण हो जाता है जो सामूहिक रूप में सबका काम करती है तो हम कहते हैं कि इन बेंकों का एकीकरए। हो गया है। इसी प्रकार जब एक बैंक का दूसरी में इस प्रकार विलय हो जाता है कि दोनों मिलकर एक हो जाती हैं तो इसे भी हम एकी करगा ही कहते हैं। उद्योग श्रौर व्यवसायों सभी में आधु-निक युग में एकी करए। की प्रवृत्ति का अधिक जोर है। एकी करए। द्वारा एक श्रोर तो पारस्परिक प्रतियोगिता को समाप्त किया जा सकता है और दूसरी श्रोर बड़े पैमाने के संगठन के लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं।

## एकीकरण के कारण-

भारत में बैंकों का एकीकरए। थोड़े ही काल से अधिक प्रचलित हुआ है। इसके कई कारण हैं :---

- ( i ) दूसरे महायुद्ध के काल में भारतीय बैंकों ग्रौर उनकी शाखाग्रों का भारी विस्तार हुआ, जिसके कारए। यह विकास भ्रारोग्यहीन न रह सका। अधिकाँश बैंकों ने ग्रनावश्यक शाखाएँ खोलीं और वे ग्रपने कार्यालय की कुशलता तया शोघनक्षमता की सुदृढ़ता प्राप्त करने में ग्रसमर्थ ही रहीं। सेवाओं की कुशलता बढ़ाने के लिए बहुत सी बैंकों ने ऊँचे वेतनों का लोग देकर योग्य ग्रौर ग्रनुभवी कर्मचारियों को, जिनका देश में भारी म्रभाव है, म्रपने पास खींचने का प्रयत्न किया, जिससे उनका कार्य-व्यय बढ़ गया है। बहुत सी बेंकों ने शीघ्र लाभ कमाने के लिए सट्टा व्यवसाय में भी धन लगाया है।
- ( ii ) युद्धकालीन अभिवृद्धि का अन्त होते ही दहुत सी वैंकों ने ऐसा अनुभव किया कि व्यवसाय का संकुवन हो रहा था और उन्होंने अपनी शाखाओं को बन्द करना आरम्भ किया । फिर भी सन् १६४६ और सन् १६५१ के पाँच वर्षों में १८३ वें कों का विलीयन हुम्रा।

- (iii) व्यवसाय की मन्दी के फलस्वरूप वैंकों ने अपनी आर्थिक नींव हढ़ करने का प्रयत्न किया।
- (iv) रिजर्व बैंक ने भी विलीयन प्रवृत्ति को रेशेकने के प्रयत्न आरम्भ किये। ऐसा अनुभव किया गया है कि बलहीन और अव्यवस्थित बैंकों को बड़ी और शक्तिशाली बैंकों के साथ जोड़ देने से हानिकारक प्रतियोगिता समाप्त हो जायगी, कार्यक्षमता बढ़ेगी और बैंकों के फेल होने का भय घट जायगा।
- (  $\nabla$  ) सन् १६४६ के बैंकिंग दिधान में एकीकरण का आयोजन किया गया है।

#### बेंकों के एकीकरण के लाभ-

उद्योग और व्यवसाय के एकीकरण की भाँति बैंकों के एकीकरण से भी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं:—

- (१) प्रवन्ध का केन्द्रीयकरण हो जाने के कारण उसकी कुशलता बढ़ती है ग्रीर व्यय कम हो जाता है।
- (२) इसके द्वारा बैंकों के म्राधिक साधन हुक हो जाते हैं अप्रैर ऐसे साधनों का माकार भी बढ़ जाता है।
- (३) छोटी बैंकों के बड़ी बैंकों में मिल जाने के कारण छोटी बैंकों को भी कुशल ग्रीर ग्रनुभवी कर्मचारियों की सेवाग्रों के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। इसके द्वारा बड़ी बैंकों को शाखा बैंकिंग प्रखाली के सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं ग्रीर उनमें ग्रापिक संकटों का सामना करने के लिए ग्राधिक शक्ति ग्राजाती है।
- (४) एकीकरसा निक्षेप प्राप्त करने के लिए ब्याज की दरों को बढ़ाने की प्रवृत्ति को रोकता है और विलीयन की सम्भावना कम कर देता है।
- (५) इसके द्वारा बैंक को बड़े पैमाने के व्यवसाय के सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं।
- ्रं (६) विशाल संगठन के कारएा वैंक के लिए विशेषज्ञों का रखना सम्भव हो जाता है, जिससे व्यावसायिक कुशलता और लाभ दोनों ही बढ़ते हैं।
- (७) नकद कोषों के उपयोग में मितव्ययिता आती है, क्योंकि एक शासा से दूसरी को घन का हस्तान्तरण होता रहता है।
- (८) बैंकिंग सम्बन्धी जोखिम का प्रादेशिक वितरण हो जाता है ग्रीर किसी क्षेत्र विशेष के सङ्कटों का सारे बैंकिंग व्यवसाय पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है।
- ( ६ ) एकीकरण केन्द्रीय बैंक की निरीक्षण तथा नियन्त्रण क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे मुद्रा-बाजार में अनुरूपता आ जाती है और बैंकिंग व्यवसाय की कार्य-कुशनता भी बढ़ती है।
  - ( १० ) एकीकरण एकाधिकार से सम्बन्धित सभी लाभों को उत्पन्न करता है।

#### एकीकरण की हानियाँ—

उपरोक्त अनेक लाभों के साथ-साभ एकीकरना के दोप भी निम्न प्रकार हैं:-

- (१) एकीकरए। वैंकों की सेवाओं और सायतों का केन्द्रिय रुग्य करता है, जिससे विशाल आर्थिक शक्ति थोड़े से क्वक्तियों के पास आ जाती है और जनता के शोषगा की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। इसमें एकाविकार के सभी दोष पाये जाते हैं।
- (२) इसके बैंकिंग कलेवर में श्रत्यविक विस्तार, श्रष्टाचार तथा सट्टा-ब्बवहार के दोष ग्रा जाते हैं :
- (३) इससे बहुता रोजगार का संकुचन होता है और कर्मचारियों की छटनी होती है। एकोकरण के पश्चात् पहले की नुलना में कम कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है।
- (४) एकीकरण में बड़े पैमाने तथा शाखा बेंकिंग प्रसाली के सभी दोष पाये जाते हैं।
- (५) इसके द्वारा बैंक सेवाग्रों और स्थानीय व्यापार तथा वाणिज्य दशाग्रों के बीच घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता है, क्योंकि वड़ी वैंकों की शाखाएँ व्याक्तिगत छोटी-छोटी स्थानीय बैंकों की भाँति स्थानीय हितों से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकती हैं।

#### भारत में बैंकों का एकीकरण-

इङ्गलैंड में एकीकरण की प्रवृत्ति प्रथम महायुद्ध के पश्चात् ग्राने वाली मन्दी के काल में ब्रारम्भ हुई थी । (i) भारत में इसका सबसे पहला उदाहरए। सन् १६२१ में तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल वैंक की स्थापना द्वारा प्रस्तृत किया गया है। (ii) दूसरे महायुद्ध के पश्चात् भारत में भी एकीकरण के लिए उपयुक्त दशाएँ उत्पन्न हो गईं। (iii) भारत सरकार ने सन् १६५० में बैंकिंग विचान में इस प्रकार के संशोधन किए कि समुचित तथा वांछित एकीकरए। को प्रोत्साहन मिले। (iv) इससे पहले रिजर्व बैंक ने सन् १६३७ और सन् १६४५ में दो बार एकीकरण किया में सहायता दी थी। (ए) सन् १९५० में बङ्गाल की चार वैंकों को, जिनका देश के विभाजन के कारण विलीयन का भय था. एकीकरण की सलाह दी गई। फलतः कोमिल्ला बैंकिंग कॉर्पोरेशन. कोमिल्ला यूनियन बैंक. हगली बैंक तथा बङ्गाल सेन्ट्ल बैंक को मिलाकर युनाटेड बेंक भ्रॉफ इण्डिया लिमिटेड का निर्माण हमा। (vi) सन् १९५१ में भारत बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुन्ना। (vii) इसी प्रकार राजस्थान की तीन बैंकों ग्रर्थात दी बैंक ग्रॉफ जयपूर, दी वैंक ग्रॉफ बीकानेर, दी बैंक आँफ राजस्थान को मिलाकर राजस्थान बैंक लिमिटेड में परिवर्तित किया गया है। (viii) सरकार की नई योजना के अनुसार लगभग ४०० छोटी-छोटी बैंकों को स्टेट बैंक आँफ इण्डिया में मिला दिया जायगा।

#### भारतीय वैंक की वर्तमान स्थिति—

इस समय भारत में अनुस्चित बैंकों की कुल संख्या ६१ है, जिनमें से १५ विनिमय बेंक हैं। सन् १६५५ के अन्त में कुल संख्या ६६ थी। इन ६६ वेंकों की कुल पूँजी और निधि ६३ १० करोड़ रुपये की थी। इन वैंकों की कुल देय (Liabilities) १,०३४ ६७ करोड़ रुपए थी और कुल सम्पत्ति ७४० २० करोड़ रुपया। सन् १६५६ के आरम्भ में सभी प्रकार की कुल बेंकों की संख्या ४७२ थी, जिनकी पूँजी और निधि १,२४६ ६७ करोड़ रुपया थी। सभी बैंकों के पास नकदी, ऋग्, अप्रिम, विनियोग, बिल आदि के रूप में १,२११ ६३ करोड़ रुपये थे।

सन् १६५० के सम्बन्ध में बैंकिंग की प्रगित की जो रिपोर्ट रिजर्व बेंक द्वारा मई सन् १६५० में प्रकाशित की गई है उससे पता चलता है कि सन् १६५० के वर्ष में देश में विस्फीतिक प्रवृत्तियाँ ही बलवान रही हैं। इस वर्ष में साख के विस्तार के कम में शिथिलता रही है। वर्ष विशेष में साख की कुल मात्रा ५३० ६ करोड़ रुपया रही है। वर्ष विशेष में बंक साख की मात्रा को कुल वृद्धि केवल ११.१ करोड़ रुपये की हुई, जब कि सन् १६५७ में यह वृद्धि ७४ ६ करोड़ रुपया धीर सन् १६५६ में १५१ ३ करोड़ रुपया धी। इस वर्ष में बेंकों के जमाधन में संतोषजनक वृद्धि हुई है और उनके ब्रादेयों की तरलता भी बढ़ी है। जमावन की कुल वृद्धि २१६ करोड़ रुपये की राशि लगाई हैं। बैंकिंग प्रणाली के संगठन में भी इस प्रकार के सुधार हुए हैं कि बेंक देश की विकासशीन अर्थ-व्यवस्था में अधिक योग देने के योग्य हो गये हैं। इस वर्ष में उद्योगों को दिये जाने वाले ऋरणों की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भागतीय बैंकिंग की स्थिति आशाप्रद है और भविष्य में और अधिक प्रगति की आशा की जा सकती है।

जनवरी सन् १६५१ और नवम्बर सन् १६५८ के बीच भारत में परिगि एत और गैर अनुसूचित (Non-scheduled) सभी प्रकार की बेंकों के कार्यानयों की संख्या ४,११६ से बढ़कर ४,५१८ हो गई है। इस काल में स्टेट बैंक के कार्यानय ५६१ से बढ़कर ६६६, विनिमय बैंकों के कार्यानय ६४ से ६७ और भारतीय परि-गिएत बैंकों के २,१६१ से २,५४१ हो गये हैं, जबिक गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या १,४७३ से घट कर केवल ६१४ रह गई है।

यद्यपि इस्रावात का निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है कि भारत में बैंकिंग सेवाग्रों का विकेन्द्रीयकरण हो, किन्तु वैंकिंग सेवाग्रों का फिर भी कुछ विशेष क्षेत्रों में ही केन्द्रीयकरण होता दिखाई दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैंकिंग सेवाग्रों का विकास नहीं हो रहा है। इन क्षेत्रों में वैंकिंग सुविधाग्रों के विस्तार के ग्रभाव के दो कारण हैं—(१) जोखिम की समस्या ग्रौर (२) जनता में वैंकिंग ग्रादत का ग्रभाव। सिम-लित पूँजी वैंक, जिनका संचालन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएँ खोलने को तैयार नहीं हैं। किन्तु यह निश्चय है कि देश के ग्राधिक विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ इन कारणों की शक्ति को घटा रही हैं। भारतीय बैंकिंग का भविष्य—

इस अध्याय में भारतीय वैकिंग के विकास और उसकी समस्याओं का विवेचन किया गया है। देश में वैकिंग का भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है, क्यों कि अभी विकास की सम्भावनाएँ बहुत हैं। रिजर्व वेंक की स्थानना, इमीरियन वेंक के राष्ट्रियररा तथा समुचित वेंकिंग विकास द्वारा सुदृढ उसित की आशा और भी वड़ जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि कर्मचारियों के शिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाय और प्रवन्ध में कुशलता प्राप्त की जाय। औद्योगिक वित्त की कमी को पूरा करने के लिए हमने विशेष प्रयत्न किया है। घीरे-घीरे उन सेवाओं का भी विकास होता जा रहा है जो वैकिंग कार्यों में सहायक होती हैं। ऐनी आशा की जादी है कि आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत वैकिंग सेवाओं का भी समुचित विकास एवं सुधार होगा। डा॰ जॉन मथाई ने, जो स्टेट वेंक ऑफ इण्डिया के नये गवर्नर बनाए गए थे, कहा है— "शक्ति और कार्यश्च मता में भारतीय बैंकिंग प्रणाली इङ्गलैंड एवं प्रमरीका से कम नहीं है। " असित वित्नान स्थित आशावद्व के है।"

सन् १६५६ की वैंकिंग प्रगति सम्बन्धी रिगोर्ट में रिजर्व वैंक ने देश में वैंकिंग विकास और वैंकों के कार्यों के विस्तार पर संतोष प्रकट किया है। रिपोर्ट के अनुभार भविष्य आशाजनक है, किन्तु रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि वेंकों को जन-साधारण में वैंकिंग आदत (Banking habit) को बढ़ाने का अधिक प्रयत्न करना चाहिए और अपनी कार्य-विधि में इस प्रकार के परिवर्तन करने चाहिए कि विकासशील अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।

"इस समय भारतीय बैंकिंग न्यवस्था निश्चय ही चौराहे पर है। इसके लिए यह सम्भव नहीं है कि भूतकाल की भाँति ग्रपना प्रधान कार्य वाणिज्य साख की पूर्ति ही रख सके। एक ऐसे देश में जिसका शीन्नता के साथ ग्रायिक विकास हो रहा है, यह ग्रावश्यक ही है कि बैंक ग्रपनी ऋण-दान नीति में ऐसा परिवतन करें कि विवेकशील तथा उपयक्त निर्वाचन के ग्रन्तर्गत उद्योगों को दीर्घ जालीन ऋण दिये जा सकें।"\*

#### भारतीय वैंकिंग का भावी स्वरूप-

यह प्रश्न ग्रभी ग्रनिश्चित सा ही है कि भारतीय वैंकिंग का भावी स्वरूप क्या

<sup>\*&</sup>quot;The Indian Banking System is clearly at the cross-roads. It cannot cling to the traditional pattern of supplying commercial credit as its predominant activity. Employment of its funds in term loans to industry by a prudent and careful selection of applicants emerges as a reasonable and essential change in its policy of employment of funds in a rapidly industrialising economy."—The Eastern Economist.

रहेगा ? भविष्य के बारे में दो विचारघारायें महत्त्वपूर्ण हैं—प्रथम, क्या भारतीय वेंकिंग का राष्ट्रीयकरण किया जाय और दूसरे, क्या भावी प्रगति एकीकरण के अन्तर्गत हो ? एकीकरण के ग्रुणों और दोषों का सविस्तार अध्ययन तो हम पहले कर ही चुके हैं, अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि भारतीय वेंकिंग का राष्ट्रायकरण कहाँ तक उचित होगा। इस सम्बन्ध में यह समक्षना आवश्यक है कि राष्ट्रोयकरण वेंकों की केवल अंशधारियों के लाभ के लिए काम करने की प्रवृत्ति को रोक देगा और वेंकिंग को चन-साधारण के हितों की उन्नति का साधन बनाने में भी सफन होगा। राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं:—

- (१) क्योंकि हमने तमाजवादी ढंग की समाज स्थापना का लद्द्य निश्चित किया है. इसलिए राष्ट्रीयकरण श्रावश्यक ही होगा।
- (२) साख निर्माण ही बैंकों का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है और साख का उपयोग जन-साधारण के हितों को उन्नत करने के लिए भी किया जा सकता है और समाज का शोषण करने के लिए भी। राष्ट्रीयकरण इस सम्भावना को बढ़ा सकता है कि साख एक राष्ट्रीय-सेविका ही वनकर रहे। साख और राष्ट्रीय आवश्यकताओं का समायोजन सबसे अच्छी प्रकार राष्ट्रीयकरण द्वारा हो हो सकता है।
  - (३) राष्ट्रीयकृत बैंकिंग व्यापार चक्रों के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रतिबन्व है।
- (४) म्रार्थिक नियोजन की सफलता बड़े म्रंश तक इस बात पर निर्भर होगी कि बैंकिंग नीति का उद्देश्य म्रार्थिक विकास में सहायता देना हो। राष्ट्रीयकरण समु-चित वित्त प्रदान करने के प्रतिरिक्त मुद्रा-प्रसार के विरुद्ध भी भ्रच्छा उपचार रहेगा।
- (५) वैंकों के लाभ लोक घन और लोक विश्वास के कारण पैदा होते हैं,
   इसलिए वे व्यक्तियों के स्थान पर राज्य जैसी लोक संस्था को ही प्राप्त होने चाहिए।
- (६) बैंकिंग सेवाओं के रोगहीन विकास के लिए राष्ट्रीयकरण ही अविक उपयुक्त है।
  - (७) राष्ट्रीयकरण सरकारी नियन्त्रण का सबसे सप्रभाविक उपाय है।
- ( प्र ) व्यक्तिगत वैंकिंग के सभी दोष राष्ट्रीयकरण द्वारा दूर किए जा सकते हैं।

इसमें तो सन्देह नहीं है कि राष्ट्रीयकरण हम।रे बैंकिंग कलेवर की लगभग सारी कठिनाइयों को दूर कर देता है, परन्तु राष्ट्रीयकरण के मार्ग में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ अवश्य हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयकरण बैंकिंग प्रणाली की लोच को समाप्त कर देता है और व्यक्तिगत रुचि के अभाव के कारण उत्साह और कार्य-कुश-लता को कम कर देता है। भारत में राष्ट्रीयकृत उद्योगों का अनुभव बहुत उत्साहवर्द के नहीं है, यद्यपि सरकार द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण की सम्भावना अधिक बढ़ गई है।

#### QUESTIONS

- What are the defects of the Indian Banking Organisation?
   Suggest lines of improvement. (Agra, B. Com, 1950)
- Discuss the main trends in the development of Indian Banking since 1947 and point out their lesson for the future. (Raj., B. A., 1956)
- 3. Point out the main defects of the present banking organisation in India. Indicate further lines of improvement.

(Bombay, B. Com., 1948)

4. What were the issues involved in the nationalisation of the Imperial Bank of India? Do you favour nationalisation of commercial banking in India?

(Agra. B. A., 1956 Supp.)

- 5. Examine the case for the nationalisation of Commercial banking in India. (Raj., B. Com., 1957)
- 6. What important changes have taken place in the banking organisation in India during recent years and why?

(Agra, B. Com., 1956 Supp)

 Describe the developments that have taken place in the banking system in India since 1926 and discuss their effects. (Agra, B. Com., 1955 Supp)

#### श्रध्याय ३३

# भारतीय मुद्रा बाजार

(The Indian Money Market)

#### मुद्रा बाजार का ऋर्थ-

साधारए। भाषा में बाजार अथवा मन्डी का अभिप्राय उस स्थान से होता है जहाँ पर वस्तुम्रों का क्रय-विक्रय होता है। म्राथिक दृष्टिकोगा से वाजार शब्द ऐसी वस्तु की म्रोर संकेत करता है जिसके ग्राहकों ग्रौर विक्रेताग्रों के बीच इस प्रकार की प्रतियोगिता रहे कि सभी स्थानों पर वस्तु विशेष के दामों के समान रहने की ही प्रवृत्ति रहे। कूछ भी सही, बाजार शब्द सदा ही कय-विकय से ही सम्बन्धित होता है, परन्तु क्या इस सम्बन्ध में गुद्रा बाजार भी हो सकता है ? क्या-मुद्रा का भी क्य-विक्रय होता है ? सवसे बड़ी कठिनाई यह है कि क्य-विक्रय के अन्तर्गत प्रत्येक वस्तू की कीमत मुद्रा में चुकाई जाती है, परन्तु यदि मुद्रा का क्रय-विकय होता है तो उसकी कीमत किस वस्तु में चुकाई जायगी ?यह कहना थोड़ा विचित्र सा लगता है कि मुद्रा को भी खरीदा ग्रयवा बेचा जा सकता है, परन्तु वास्तविकता यह है कि ऐसा दिन प्रति दिन ही होता रहता है। मुद्रा को बेच कर बदले में जो कुछ प्राप्त किया जाता है वह केवल भविष्य में उसके लौटाने का वचन ही होता है। दूसरे शब्दों में, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि कय-विक्रय का ग्रर्थ केवल मुद्रा के उधार लेने तथा उधार देने से होता है। ग्रब हमें मुद्रा की की मत का अर्थ सम भने में भी किटनाई नहीं होगी, क्यों कि मुद्रा की कीमत केवल उस पोरितोषए। की ग्रोर संकेत करती है जो मुद्रा को भविष्य में उसके लौटाने के वायदे में बदलने के लिए प्राप्त होती है। इस प्रकार मुद्रा की कीमत उसके ऋणों पर मिलने वाजी ब्याज की दर को कहते हैं। अतः मुद्रा-बाजार से हमारा अभिश्राय मुद्रा के उधार लेने-देने तथा इस उधार से सम्बन्धित अन्य क्रियाओं से होता है। प्रस्तुत भ्रघ्याय में मुदा-बाजार से हमारा श्रभिप्राय यही होगा।

इस सम्बन्ध में मुद्रा बाजार (Money Market) तथा पूँजी बाजार (Capital Market) का भेद समक्ष लेना भी भ्रावश्यक है। दोनों ही बाजारों का मुद्रा के उधार लेने-देने से सम्बन्ध होता है। भ्रन्तर केवल इतना है कि मुद्रा-बाजार शब्द का उपयोग केवल ग्रल्पकालीन ऋग् बाजार के लिए किया जाता है, जबिक पूँजी बाजार दीर्घकालीन ऋगों की लेन-देन की भ्रोर संकेत करता है। मुद्रा-बाजार में काम करने वाली संस्थायें भी साधारणत्या पूँजी बाजार से भिन्न होती हैं, परन्तु विस्तृत

<sup>\*</sup> मुद्रा बाजार के स्थान पर मुद्रा-विपिए। शब्द का भी उपयोग हो सकता है।

प्रशं में मुद्रा-वाजार में पूँजी को सम्मिलित किया जाना है ग्रीर सभी प्रकार के ऋगों का बाजार मुद्रा-वाजार कहलाता है। वैने भी मुद्रा-वाजार ग्रीर पूँजी बाजार में विनष्ट सम्बन्ध होता है, क्योंकि ग्रन्थकातीन तथा दीर्घनातीन ऋगों को एक दूसरे से पूर्णतया ग्रन्थ नहीं किया जा सकता है। दोनों ही बाजारों में व्यापारिक तथा ग्राधिक ग्रावश्यक तथा ग्राधिक तथा ग्राधिक ग्रावश्यक तथा ग्राधिक ग्रावश्यक तथा ग्राधिक ग्रावश्यक तथा ग्राधिक ग्रावश्यक विषय ग्राधिक तथा ग्राधिक ग्रावश्यक विषय ग्राधिक ग्राध

भारतीय मुद्रा-वाजार के श्रङ्ग (The Constituents of the Indian Money Market)—

भारतीय मुद्रा-बाजार को दो भागों स्रथीत् भारतीय संग तथा यूरोपियन संग में बाँटने की प्रथा चली आई है। योरोपियन भाग में रिजवे बेंक बाँक इण्डिया, स्टेट बंक ग्रॉफ इण्डिया तथा विदेशो विनिमय वैंकों को सम्मितिन किया जाना या ग्रीर भारतीय भाग में स्वदेशी अधिकीष (देशी बैंकर ), सहकारी वें हों तथा संयुक्त-स्कन्व वैंकों (Joint-stock Banks) को सम्मिलित किया जाना था। देश के मार्थिक जीवन में अधिक महत्त्व देशी बैंकरों तथा सहकारी वैंकों का ही होता है। योरोपियन भाग को ग्रारम्भ से ही सरकारी नियन्त्रण तथा संरक्षण के लाभ प्राप्त रहे हैं, परन्तु भारतीय भाग प्राय: अनियन्त्रित तथा अनियमित ही रहा है। सन् १६३५ तक अर्थात् रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व दोनों ग्रंगों में किसी प्रकार का सम्बन्ध भी नहीं था, परन्तु तत्पश्चात् सम्पर्क को स्थापित करने का भारी प्रयत्न किया गया है। स्वतन्त्रता के पश्चात् इस स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया है और इस समय रिजर्व वेंक का राष्ट्रीयकरण हो चुका है तथा इम्पीरियल वैंक जैसी विशाल संस्था का भारतीयकरण (Indianisation) हो चुका है। भारत सरकार ने उसका भी राष्ट्रीयकरण कर लिया है ग्रौर उसका 'स्टेट बेंक ग्रॉफ इन्डिया' के रूप में पुनर्सङ्गठन कर दिया है. ग्रतः भारतीय और योरोपियन अंगों का ग्रलग-ग्रलग महत्त्व बहुत ही कम रह गया है। इस समय तो हम भारतीय मुद्रा-वाजार का वर्गीकरए। एक दूसरी ही रीति से कर सकते हैं, मर्थात् (१) देशी वैंकर (Indigenous Bankers) और (२) म्राष्ट्रिक वेंक (Modern Bank)। प्रथम प्रकार के बैंक भारत में लम्बे काल से भनते आ रहे हैं ग्रौर भारतीय पद्धति के ग्रामार पर कार्य करते हैं। ग्राधुनिक वैंक ब्रिटिश शासन काल ग्रथवा उसके पश्चात् स्थापित हुए हैं ग्रौर उनकी कार्य विधि योरोपियन वैंकों की भाँति है। इनका कार्य भी भारतीय भाषाध्रों में न होकर इङ्गलिश भाषा में होता है।

हमारे देश में यूरोप के देशों की भाँति वोई सुसंगठित मुद्रा-वाजार नहीं है। मुद्रा-वाजार के भी छोटे-छोटे टुकड़े हैं और उनमें से अधिकाँश केवल स्थानीय बाजार हैं, जैसे— कलकत्ता तथा वम्बई के महान् मुद्रा-बाजार तथा दिह्नों, कानपुर आदि के छोटे मुद्रा-बाजार। अभी तक भी हमारे देश में कोई अखिल भारतीय मुद्रा-बाजार उत्पन्न नहीं हो पाया है। भारतीय मुद्रा-बाजार के प्रमुख अंग निम्न प्रकार है:—

(१) रिजर्व बैंक झॉफ इण्डिया, (२) स्टेट बैंक झॉफ इण्डिया, (३) संयुक्त स्कन्ध बैंक, (४) धौद्योगिक बैंक, (५) सहकारी बैंक, (६) भू-प्राधि बैंक, (७) विनिमय बैंक झौर (६) स्वदेशी ध्रिक्षकोष झथता देशी बैंकर। भारतीय मुद्रा-बाजा के इन झलग-झलग झंगों का विस्तृत झध्ययन आगे चल कर किया जायगा। प्रस्तुत झध्याय में तो मुद्रा-वाजार सम्बन्धी सामान्य परिस्थितियों तथा सामान्य समस्याप्नों का ही झध्ययन पर्याप्त होगा। संगठन तथा नियन्त्रण के दृष्टिकोण से भारतीय मुद्रा-वाजार स्वयं एक समस्या है। इसके विभिन्न झंगों के बीच समचय न होने के कारण नियन्त्रण का कार्य कठिन ही होटा है।

भारतीय मुद्रा बाजार के दोष (Defects of the Indian Money Market)—

भारतीय मुद्रा-बाजार के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :---

- (१) संगठन का स्रभाव—यह एक गम्भीर दोष है। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, देस में कोई अखिल भारतीय मुद्रा-बाजार है ही नहीं। अधिकाँश मुद्रा-बाजार स्थानीय हैं, जिनके बीच सम्पर्क तथा सम वय का भारी स्रभाव है। स्रभी तक भी भारतीय मुद्रा-बाजार के दो लगभग पूर्णतया स्वतन्त्र भाग प्रयात स्राधृतिक मुद्रा बाजार तथा देशी मुद्रा-बाजार विद्यमान है। प्रथम भाग में रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, व्यापार बैंक, विनिमय बैंक, सहकारी बैंक ख़ादि सम्मिलित हैं और दूसरे में साहकार, महाजन, देशी बैंकर आदि । मुद्रा बाजार के इन विभिन्न अंगों के बीच सह-योग तो दूर रहा, सम्पर्क भी नहीं है। श्राधुनिक वैंकिंग प्रगाजी तथा देशी मुद्रा-बाजार के बीच निरन्तर हानिकारक और अपव्ययी प्रतियोगिता होती रहती है, परन्तु स्वयं अध्यतिक मुद्रा-बाजार के विभिन्न सदस्यों में भी सहयोग और समचय की भारी कमी है। स्टेट बैंक, व्यापार बैंक तथा विदेशी विनिमय बैंक एक दूसरी को प्रपना प्रतिद्वन्दी समभती हैं और ठीक यही दशा विभिन्न देशी महाजनों और वेंकरों की भी है। प्रत्येक एक दूसरे का व्यवसाय छीन लेने का प्रयत्न करती है। इस दोष की गम्भीरता इस कारए। ग्रीर भी वढ़ जाती है कि भारत में बैंकिंग सेवाग्रों की सामान्य कमी है। कुछ समय से रिजर्व बैंक इस दोष को दूर करने में लगी हुई है, परन्तु श्रभी तक सफलता बहुत ही कम मिल पाई है। इस दोष के कारण देश में बैंकिंग के सम्चित विकास में बाधा पड़ती है और केन्द्रीय बैंक की साख नियन्त्रण नीति को कम सफलता मिल पाई है।
  - (२) ब्याज की दरों में भिन्नता—यह दोष मुख्यतया संगठन तथा समचय के भ्रभाव से ही उत्पन्न होता है। इक्क्लैंड में मुद्रा-बाजार का समुचित संगठन होने के कारण सभी प्रकार के ब्याजों की दरें बैंक दर पर निर्भर होती हैं, परन्तु भारतीय मुद्रा-बाजार के विभिन्न ग्रंगों में समुचित नियन्त्रण, समचय तथा विष्ट सम्बन्ध न होने के कारण बैंक दर, बाजारी ब्याज की दर, स्टेट बैंक की दर तथा बट्टा

दर (Discount Rate) में भारी अन्तर होते हैं। अलग-अलग स्थानों पर ब्याज की दरों में भारी अन्तर होते हैं और इन दरों की सामान्य प्रकृति ऊँचों रहने की धोर होती हैं। बैंक दर की अमफलता का मुख्य कारण यही है और इनी कारण रिजर्व बैंक को निधन्त्रण कार्य में भारी कठिनाई होती है। अधिक जमा आकर्षित करने के लिए बैंक अपनी-अपनी ब्याज दरों तो बढ़ाती रहते कहें। ब्याज की दरों को इस भिन्नता के कारण देश के मुद्रा-बाजार में ब्रिचित्र परिस्थितियाँ उत्तम्म हो जाती हैं। केन्द्रीय वैकिंग जाँच समिति के अनुसार ब्याज की दर कुं में लेकर १००० तक रहती है।

(३) एक अच्छे बिल बाजार का अभाव—देश के मुता-यहार का एक बहुत बड़ा दोष व्यापारिक विलों अथवा हुण्डियों के द्भुजार का अभाव है। लग्दन के मुद्रा-बाजार में वैंकों के आदेयों का एक महत्त्वपूर्ण भाग विलों के रूप मे होता है और विदेशों में तो वे अपने कोषों का अधिकांश भाग बिलों में ही लगती है। भार-तीय मिश्रित पूँजी बैंक अपनी गुल निक्षेतों का केवल ३ से ६% तक ही विनों के मुनाने में लगाती हैं। लगभग सभी केन्द्रीय वैंकिंग जाँच समितियों तथा वैकिंग विशेष्कों का मत है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली सुहढ़ तथा मुध्यवस्थित बनाने के लिए व्यापारिक बिलों के उपयोग में वृद्धि तथा सुसंगठित सहे बाजार की स्थापना आवश्यक है।

विलों के उपयोग के अभाव के अनेक कारण हैं, यद्यपि घीरे-घीरे अब इन कारणों में भी कमी होती जा रही है। प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं:—

- (क) अधिकांश विनियोग परम प्रतिभूतियों में करना— शारन्भ से ही भारतीय वेंकों को नक्तद कोप अधिक मात्रा में रखने पड़े हैं और इसी कारण वे अपने अधिकांश विनियोग परम प्रतिभूतियों (Guiltedged Securities) में ही करती आई है, ताकि आदेयों की तरलता बनी रहे। परन्तु क्योंकि आय के दृष्टिकोण से बिलों का अपहरण (Discounting) परम प्रतिभृतियों की अपेक्षा अधिक लाभदायक होता है, इसलिए अब घीरे-घीरे यह परिस्थित बदल रही है।
- (ख) निर्गस गृहों का स्रभाव—बिलों के उपयोग की कमी का एक कारण यह भी है कि देश में निर्गम गृहों (Issue Houses) जैसी वित्तीय संस्थायों का स्रभाव है, जो बिलों को स्वीकार (Accept) करके लिखने वाले को ग्राहक की स्थायिक स्थिति का सही ज्ञान दे सकती है। इस कारण बैंक विलों का स्थन्हरण करने में संकोच करती हैं, क्योंकि बहुत सी दशायों में स्वीकार करने वाले की साख वन्देहपूर्ण हो सकती है।

- (ग) विलों को पुनः भुनाने वाली संस्था का अभाव—सन् १६३५ से पूर्व देश में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जिससे विलों को फिर से भुनाया जा सके। इम्पीरियल बैंक इस कार्य को अवश्य करती थी, परन्तु वह अन्य बैंकों से प्रतियोगिता करती थी, जिस कारण दूसरी बैंक इसे संदेह की दृष्टि से देखती थीं।
- (घ) व्यापारिक तथा अर्थ बिलों में स्पष्ट भेद का अभाव—भूकाल में भारत में व्यापार दिलों तथा अर्थ-बिलों में भी कोई अन्तर नहीं होता था और सन्देह के कारण बैंक विलों के अपहरण में संकोच करती थीं, क्योंकि भुनाने वाली बैंक के लिए बिल की सही प्रकृति का पता लगाना कठिन होता था।
- (ङ) हुन्डियों में विविधता भारत में हुन्डियों की भाषा, रूप तथा प्रकृति में स्थानान्तर के अनुसार इतने गम्भीर अन्तर होते हैं कि बैंक उलक्षन में पड़ जाती है कि कौनसी हुण्डी ठीक है और कौनसी नहीं।
- (च) नगद ऋर्ग देने को अच्छा मानना—िवलों को भुनाने की अपेक्षा भारतीय बैंक नकद ऋगों का देना श्रविक पसन्द करने हैं, क्योंकि ऐसे ऋगों को बैंक कभी भी रद्द कर सकती है और ग्राहक को भी ब्याज कम देना पड़ता है।
- (छ) कोषागार नियमों का निर्गमन—लम्बे काल से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को कोषागार-विपत्रों द्वारा पूरा करती आई हैं। इनमें विनियोग अधिक सुरक्षित समक्ता जाता है और बिलों का उपयोग कम होता है। यही कारगा है कि पूर्णतया विश्वासजनक बिल कम ही मात्रा में रहते आये हैं।
- (ज) अत्यधिक मुद्रांक कर—बहुत काल तक भारत में मुद्रांक करीं (Stamp Duties) की दर भी अधिक ऊँची रही है। इन ऊँची दरों के कारण बिलों के अपहरण की लाभदायकता कम हो जाती थी। सन् १६४० के पश्चात् इनमें कुछ कमी अवश्य हुई थी।
- (४) घन की कमी—यह भी एक गम्भीर दोष है। उद्योग-घन्धों ग्रौर व्यापार के लिए ग्रावश्यक पूँजी उपलब्ध करने तथा साल की मांग पूर्ति करने के लिए भारत में पर्याप्त घन की कमी है। इस ग्रभाव के तीन मुख्य कारण हैं:—पर्याप्त विनियोग के साधनों की कमी, बैंक प्रणाली का ग्रपर्याप्त विकास तथा बैंकों के बराबर टूटते रहने के कारण उनके प्रति श्रविश्वास। इसके ग्राविश्विक देश में ग्राय तथा बनत की कमी, बचतों की गाड़ कर रखने की प्रवृत्ति, ग्राय के वितरण की ग्रसमानता ग्रौर जन-साधारण की ग्रविक्षा भी बैंकों के पास घन की कमी उत्पन्न कर देती है। देहातों

में तो ऐसी संस्थाओं की भी भारी कमी है जो वचत को एकत्रित कर सकें। भाज-कल बचतों को प्रोत्साहन देने तथा एकत्रित करने की दिशा में विशेष प्रयत्न किया जा रहा है। इस कारणा निकट भविष्य में इस दोष के दूर हो जाने की काफी सम्भावना है।

- (५) मुद्रा बाजार में लोच तथा स्यायित्व का ग्रम् इ—रिटर्ड बैंक की स्थापना से पूर्व साख पर तो इम्नीरियल वैंक नियन्त्रण रखती थी, जो एक बहुत ही अनुत्रयुक्त साधन थी और मुद्रा पर सरकारी नियन्त्रण रहता था। उन दना में मुद्रा बाजार में लोच तथा स्थायित्व का प्रश्त कम ही उठता था, परन्तु नोट निर्गम के एकाधिकार तथा खुले बाजार व्यवसाय नीति की सहायता से रिजर्व वैंक ने एक अंग तक इस कमी को दूर कर दिया है। फिर भी भारतीय वैंकों के साधन आज भो बहुत सीमित हैं, उनके कोष भी सीमित हैं। और देश में चैंक प्रथा का प्रवार भी बहुत कम है। इस कारण मुद्रा बाजार देश की वड़ती हुई मुद्रा और साख की आवव्यकता को पूरा करने में असमर्थ रहता है।
- (६) ब्याज की दरों के मौसमी परिवर्तन—देश की कृषि प्रधानता के कारण देश में विभिन्न मौसमों की ब्याज की दरों में भारी ग्रन्तर होते हैं। नवम्बर से जून तक के मौसम में बन की ग्रावच्यकता अधिक रहती है ग्रौर ब्याज की दरें अपर चढ़ जाती हैं। शेप काल में वे नीची रहती है। यह परिस्थित ग्रभी तक भी ठीक नहीं हो पाई है।
- (७) साहूकारों तथा देशी बैंकरों का प्रभाव—ग्राधुनिक वैकिंग का विकास भी इनके महत्त्व को कम नहीं कर पाया है। कृषि वित्त तथा ग्रातरिक व्यापार में ग्राज भी साहूकारों ग्रौर देशी बैंकरों का ही बोजवाला है। इनके बीच समचय तथा सहयोग का भारी ग्रभाव है और इसके कारण मुद्रा-वाजार में काफी उथल-पुथल होती रहती है। कठिनाई यह भी है कि इन पर समुचित नियन्त्रण रखना कठिन है। देश के विभिन्न भागों में इनकी कार्य विधियाँ ग्रलग-ग्रजग हें ग्रौर ये वैकिंग के साथ-साथ ग्रौर भी कार्य करते हैं।
- ( द ) बैंकिंग सुविधात्रों की सामान्य कमी—यह कमी ग्रामीए क्षेत्रों में तो बहुत ही ग्रधिक है। जन-संख्या के ग्राबार पर हमारे देश में प्रत्येक १ लाख ३० हजार व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है, जब कि ग्रमरीका में प्रत्येक ३,७३७ व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है। परिएए। यह होता है कि न तो बचत प्रोत्साहित होती है, न वह एकत्रित हो पाती है और न ही देश के विभिन्न भागों की ग्राधिक दशाओं में समानता भाने पाती है। निम्न तालिका में यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि बैंकिंग सुविधाओं के हिष्कोए। से संसार के छुछ महत्त्वपूर्ण देशों की तुलना में भारत कितना पीछे है। ग्रांकड़े सन् १६४६ से सम्बन्धित है:—

देश	क्षेत्र (हजार वर्ग मील मे)	जन-संख्या (करोड़ में)	वैिंग कार्यालयों के संख्या	एकलाख जन संख्या के पीछे कार्यालयों की संख्या	प्रत्येक बैंकिंग कार्यालय का स्रौसत क्षेत्र (वर्ग मील में)
ब्रिटेन संयुक्त राज्य	58	¥	११,४६१	३२.६	5
भ्रमरीका	३,६७४	१४.७	१८,६७५	३२.६	१६४
कनाडा	३,६६०	<b>१ -</b> ३	३,३२३	२४.६	१,११०
म्रास्ट्रे लिया	२,६७५	•ជ	334,8	४४.0	<b>द</b> २७
भारत	१,२२४	३४२	४,२७७	१५-५	२३१

- (६) देशी बैंकरों श्रौर साहूकारों की समस्या—भारत में श्रिषकाँश बैंकिंग व्यवसाय देशी बैंकरों श्रौर साहूकारों के हाथ में रहा है। मुख्यतया कृषि श्रौर श्रान्तिरिक व्यापार के श्रथं प्रबन्ध में तो इन्हीं का बोल-बाला रहा है। किन्तु इनका न तो श्राधुनिक बैंकों से किसी प्रकार का सम्बन्ध है श्रौर न इन पर रिजर्व बैंक का ही किसी प्रकार का निवन्त्रण है ये बैंकर श्रौर साहूकार श्रपनी-श्रपनी बांसुरी श्रलग-श्रलग बजाते हैं श्रौर श्रपनी कार्यवाहियों से कभी-कभी मुद्रा-बाजार में काफी उथलपुषल मचा देते हैं।
- (१०) शाखाएँ खोलने की दोषपूर्ण नीति—ग्रतीत में भारतीय बैंकों की शाखाएँ बहुत कम थीं। छोटे-छोटे नगरों, कस्बों ग्रीर ग्रामीण क्षेत्रों में तो बैंकिंग सुविधाग्रों का ग्रभी तक भी भारी ग्रभाव है। दूसरे महायुद्ध के काल में तथा उससे उपरान्त वैंकों ने तेजी के साथ शाखाग्रों का खोलना ग्रारम्भ किया है। किन्तु ये शाखार्य ग्रिष्ठकतर बड़े बड़े नगरों तथा मुख्य व्यापार केन्द्रों में ही खोली जाती हैं। परिणाम यह हुग्रा है कि कुछ स्थानों पर तो लगभग सभी बेंकों की शाखार्यें हैं ग्रीर कुछ स्थानों पर किसी भी बेंक की शाखा नहीं है। शाखाएँ खोलने का उद्देश साधारणतया ग्रविकस्ति क्षेत्रों का विकास करना न होकर दूसरी बैंकों से प्रतियोगिता करना रहा है। वैसे भी उपयुक्त कर्मचारियों की कमी के कारण ग्रनेक शाखाग्रों का कार्यवाहन संतोषजनक नहीं रहा है। यह एक ग्राशाजनक बात है कि स्टेट बैंक ग्रांक इण्डिया ने सन् १६६० तक ग्रामीण तथा ग्रह ग्रामीण (Semi-urban) क्षेत्रों में ४०० नई शाखाएँ खोलने का संकल्प किया है।

## दोषों को दूर करने के उपाय—

रिजर्व बेंक की स्थापना, उसके राष्ट्रीयकरणा तथा सन् १६४६ के बैकिंग कम्पनो विघान द्वारा भारतीय मुद्रा बाजार के बहुत से दोप दूर हो गये हैं धौर बैंकिंग सेवाधों के विकास, सरकारी बचत प्रोत्साहन नीति तथा वैघानिक उपायों द्वारा शेष दोषों को घीरे-घीरे दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे मुद्रा-बाजार का सबसे गम्भीर दोष उसका असंगठन है, जो उसी दशा में दूर हो सकता है जबकि देशी

बैंकरों का रिजर्व बैंक से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाय, जैसा कि केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने भी सुभाव दिया है। परन्तु इसके लिए देशी बैंकरों की कार्य-विधि में महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों की आवश्यकता है। मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों मे सम्बन्धित दोषों को दूर करने के उपायों का सिवस्तार अध्ययन आगे के अध्यायों में किया जायंगा। सामान्य रूप में केवल इतना कहा जा सकता है कि देश में वैकिंग सुविधाओं के विस्तार की भारी आवश्यकता है, परन्तु यह विकास एक निर्धारित योजना कम के अनुसार होना चाहिए, जिससे कि समचय स्थापित हो जाय, सेवाओं की दोबारगी समात हो जाय और हानिकारक प्रतियोगिता दूर हो सके। विल-वाजार के विकास की आवश्यकता बहुत है और इस दिशा में विशेष प्रयत्न होने चाहिए। इनके बिना बैंकिंग प्रशाली का समुचित विकास भी कठिन होगा। सामान्य रूप में भारतीय मुद्रा-बाजार के दोषों को दूर करने के निम्न सुभाव दिये जा सकते है:—

- (१) हुँडियों का प्रमापीकरण (Standardisation of Hundis)— यह ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है कि देश भर में हुण्डियों की भाषा, रूप, लेखन-विश्व ग्रादि में अनुरूपता लाई जाय। यदि हुण्डियों का कोई प्रमापीकृत रूप निकाला जाय तो ग्रविक अच्छा होगा। इससे एक ग्रोर तो हुण्डी के समभने के लिए समय की बचन होगी ग्रीर दूसरी ग्रोर बैंकों के लिए हुण्डी की सही प्रकृति को समभने में भी मुविवा होगी।
- (२) साख-पत्रों के पुनर्ग्रपहरण की सुविधाओं का विस्तार(Increase of Rediscounting Facilities)—इस प्रकार की सुविधायें रिजर्व वेंक द्वारा प्रदान की जाती हैं। स्टेट वेंक भी कुछ प्रकार की सुविधायें देती है। इन सुविधायां के ग्रीर बढ़ाने की भारी ग्रावश्यकता है। मुख्यतया मुद्दती हुण्डियों के पुनर्श्वरूरण की सुविधायों बढ़नी चाहिए।
- (३) अनुज्ञापित भण्डार-गृहों की स्थापना (Establishment of Licensed Warehouses)—मान की आड़ पर ऋरण देने में भारतीय वेंकों की एक महान् कठिनाई यह है कि अधिकांश वेंकों के पास अपने निजी गोदाम नहीं हैं और अन्य भण्डार बहुत विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है. कि केन्द्रीय बेंक अनुज्ञापित भण्डार-गृह स्थापित करने में सहायता दे और राज्य सहकारें भी ऐसे भण्डार खोलें। पिछने कुछ वर्षों से सहकार भण्डार-गृह योजना लागू की गई है, जिससे काफी लाभ की आशा की जा सकती है।
- (४) विप्रेष सुविधाओं की वृद्धि (Increase in the Remittances Facilities)—देश में घन का एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरए। करने की सुविधायों बहुत मंहगी हैं। डाकखाना और कोष।गार दोनों ही इस कार्य के लिए अनुपयुक्त संस्थायें हैं। रिजर्व वैंक को सस्ती विप्रेप सुविधाओं का आयोजन करना चाहिए।

मु॰च०प्र०, (३६)

- (५) देशी बैंकरों पर नियन्त्रगा (Control over Indigenous Bankers)—देशी बैंक्कर भारतीय मुद्रा बाजार में काफी उथल-पुथल मचाते रहते हैं। साह्कारों की तो कार्यविधि भी काफी दोषपूर्ण है। ऐसे बैंक्करों और साह्कारों का पंजीयन होना चाहिए और उन्हें उचित शर्तों पर रिजर्व बैंक्क से जोड़ देना चाहिए।
- (६) समाशोधन गृहों का पुनर्सङ्गठन (Reorganisation of Clearing Houses) बेंकिंग सेवाओं के समुचित विकास के लिए यह भी आग- इयक है कि समाशोधन सम्बन्धी सुविधायें बढ़ाई जायें। इसके लिये एक ओर तो ऐसे गृहों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए और दूसरी ओर इन गृहों का नवीन रीति से संगठन होना चाहिए, ताकि वे उतनी कुशलता प्राप्त कर सकें जितनी कि योख्य के समाशोधन गृहों को प्राप्त है।
- (७) अखिल भारतीय बैंकर्स संघ के कार्यों का विकास (Expansion of the Activities of the All-India Bankers Association)—यह संघ सन् १६४६ में बम्बई में स्थापित हुआ था, यद्यपि इसकी स्थापना का सुभाव सन् १६२६ की केन्द्रीय बैङ्किंग जांच समिति ने दिया था। यह विभिन्न बैङ्करों के लिए मिल जुलकर काम करने और सुभाव देने का महत्त्वपूर्ण कार्य करता है। आवश्यकता इस बात की है कि संघ के कार्यों का अधिक विस्तार हो, ताकि वह मुद्रा-बाजार के संगठन में अधिक योग दे सके।

### बिल बाजार नियोजन के सुकाव—

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति के सुफाव निम्न प्रकार हैं: -

- (१) केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाय। (यह सुफाव सन् १६३५ में कार्य-रूपित किया जा चुका था)।
- (२) बैंकों को व्यापारियों की ऋार्थिक स्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान हो, जिसके लिए ऐसी संस्थायें स्थापित की जायें जो इस प्रकार का ज्ञान दे सकें।
- (३) बट्टा ग्रथना अपहरसा दर (Discount Rate) यथासम्भव नम रखी जाय।
- (४) राज्यों में बिलों के पारस्परिक मुगतान के लिए समाशोधन गृहों (Clearing Houses) स्थापित किये जायँ, जो विलों के मुगतान में उसी प्रकार की सहायता दें जैसी कि धनादेशों के भुगतान में दी जाती है। इस समय देश में २६ ऐसी संस्थायें हैं, परन्तु उनसे यथेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वे बिलों के भुगतान का काम कम करती है।
- (५) विपत्रों के मुद्रांक कर (Stamp Duty) में कमी की जाय। सन् १६४० में इस प्रकार की कमी की भी गई थी।
- (६) एकरूपता लाने के लिए बिलों की भाषा और लिपि सम्बन्धी भिन्नतायें

दूर की जायें। देशी हुण्डियों में भी इसी प्रकार के सुमार किए जायें।

(७) खड़ी फसलों की ग्राड़ पर बिलों की स्वीकृति ग्रीर उनका उपयोग बढ़ाया जाय ग्रीर ऐसे बिलों के ग्राबार पर ऋणा दिए जायें जो खड़ी फसलों की ग्राड़ पर लिखे गये हों।

इनके ग्रतिरिक्त ग्रौर भी ग्रनेक सुभाव दिए जा सकते है, जो निम्न प्रकार हैं:—

- (क) भण्डार ग्रहों (Warehouses) की स्थापना ऐसे गोदामों में जमा किए हुए माल की रसीद विलों के साथ लगा देने से उनकी साख बढ़ जायगी। इसी प्रकार राज्य सरकारें भी राज्यों में गोदामों की स्था-पना कर सकती हैं।
- (ख) भारत जैसे ऋषि प्रधान देश में कृषिज वस्तुम्रों की प्रतिभूति पर लिखे हुए बिलों में भी व्यवसाय होना चाहिए। इस सम्बन्ध में यूरोप के अर्थ बिलों (Finance Bills) का उपयोग लाभदायक रहेगा।
- (ग) यह अच्छा होगा कि बिल अनादरण पर उनका आलोकन (Noting) तथा प्रमाणन (Protesting) सरकारी संस्थाओं के स्थान पर वैंकों के संघों द्वारा ही किए जायें।

# रिजर्व बैंक की बिल बाजार संगठन की योजना-

बिल बाजार के नियोजन के ग्रविकांश सुफाव रिजर्व वैंक ने मान लिए हैं। जनवरी सन् १६५२ में बिल बाजार के निर्माण हेतु एक योजना को कार्य-रूप दिया गया था। योजना के ग्रन्तगंत रिजर्व बैंक्क ने बैंक्कों की साविध विजों (Time Bills) पर ऋण देने में है% ब्याज की छूट दी थी और माँग बिल (Demand Bill) को साविध बिल में परिवर्तित करने के ग्राधे मुद्रांक कर को स्वयं चुकाने की सुविधा दी थी। यह योजना प्रयोगात्मक ग्राधार पर चलाई गई थी। सन् १६५३ में योजना को और ग्रधिक विस्तृत किया गया था और जुलाई सन् १६५४ में ऋण की निश्चित सीमा का भी विस्तार किया गया था। योजना ४ साल तक चालू रही और इसे १ मार्च सन् १६५६ से समाप्त कर दिया गया है।

चार वर्ष की अविध में योजना में भाग लेने वाली बैंक्कों की संख्या २७ से बढ़कर ४५ हो गई थी। प्रदान किए गये अग्निमों की रािश्त भी सन् १६५२ में ६१ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी। इससे सिद्ध होता है कि योजना को पर्याप्त सफलता मिली थी। इस वाल में वंकों के साधन, जो ३१ दिसम्बर सन् १६५१ में ६१८ करोड़ रुपये जमा और ३४६ करोड़ रुपये के विनियोग के थे, बढ़कर अन्दूबर सन् १६५५ को क्रमशः १,०७४ और ४४४ करोड़ रुपये हो गये थे।

भारतीय पूँजी वाजार (The Indian Capital Market)-

पूँजी बाजार से हमारा ग्रिभिप्राय दीर्घकालीन ऋगों के वाजार से होता है। इस बाजार का सम्बन्ध राष्ट्रीय पूँजी को दीर्घकालीन प्रतिभूतियों, बाँडों ग्रीर ग्रंकों ग्रादि में विनियोग करने से होता है ग्रीर तत्पश्चात् इस बाजार में इसी प्रकार की प्रतिभूतियों का व्यवसाय होता है। सरकार तथा उद्योगों की दीर्घकालीन वित्तीय ग्रावश्यकताओं की पूर्ति इसी बाजार द्वारा की जाती है। ऐसे वाजार में एक ग्रोर तो जनता, बीमा कम्पनियाँ तथा ट्रस्ट संघ होते हैं, जो ऋगादाता का कार्य करते हैं और दूसरी ग्रोर उद्योग ग्रीर व्यवसाय होते हैं, जो ऋगा लेने का काम करते हैं। ग्राधकांश ऋगा ग्रंशों ग्रीर ऋगा-पत्रों को खरीदने के रूप में दिए जाते हैं। ऋगादाताओं तथा ऋगायों के बीच ग्रंशों के दलाल तथा ग्रभिगोगन गृह (Underwriting Houses) होते हैं। दलाल लोग उद्योगों ग्रीर विनियोगियों के बीच सम्पर्क स्थापित करते हैं ग्रीर ग्राभिगोपन गृह ग्रंशों ग्रीर ऋगा-पत्रों तर हस्ताक्षर करके उनके प्रति विश्वास को बढ़ाते हैं तथा उनकी बिक़ी का प्रश्न्य करते हैं। ये सबके सब पूँजी बाजार के ही ग्रङ्ग होते हैं।

## भारत में पूँजी का निर्माण

#### प्राक्तथन--

भारत में भूतकालीन पूँजी निर्माण के सम्बन्ध में कोई सही तथा निश्चित् ग्रांकडे प्राप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में डा॰ लोकनाथन का यह अनुमान है कि सन् १६१३ तथा सन् १६३२ के बीच वार्षिक राष्ट्रीय बचत ७५ करोड़ रुपया रही है। इसके विपरोत डा॰ जैन (m L.~C.~Jain) के अनुसार सन् १९२६ और सन् १९३२ के बीच राष्ट्रीय बचत में लगभग २१० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है ग्रौर इस प्रकार वार्षिक राष्ट्रीय बचत २३ करोड़ रुपये के श्रास पास बैठती है। ऐसा श्रनुमान लगाया जाता है कि दूसरे महायुद्ध के काल में बचत में काफी वृद्धि हुई, क्योंकि गृह निर्माण तथा स्वर्ण ग्रायात पर प्रतिबन्ध लगा दिए गये थे। युद्धोत्तर के काल के विषय में ईस्टर्न इकॉनॉमिस्ट (Eastern Economist) ने जो अनुमान लगाये हैं वे वहत ही निराशाजनक हैं । उपरोक्त पत्रिका के अनुसार सन् १६४६-४७, १६४७-४= तथा सन् १६४८-४६ में बचत अधिक नहीं हुई है और इन वर्षों में वह केवल १ % की दर पर हो पाई है। योजना कमीशन के अनुसार प्रथम पंच वर्षीय योजना के काल में कुल व्यक्तिगत बचत का अनुसान ५१५ - करोड़ रुपये का लगाया गया है. जिसमें से ११५.० करोड़ रुपया जनता से ऋरग के रूप में प्राप्त करने का ब्रनुमान लगाया गया है. २७०'० करोड़ रुपया छोटी बचतों तथा ग्रन्य ऋगों के रूप में मिलने भौर शेष १३०' करोड़ रुपया जमाधन कोष तथा अन्य विविध साधनों से प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। योजना की प्रगति की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि वास्तविक बचत ग्रनुमान से बहुत कम रही है। यह सन्देहर्र्ण है कि क्या दूसरी

योजना से सम्बन्धित कमीशन द्वारा निर्धारित लच्य पूरा हो सकेगा? वास्तिविकता यह है कि पूँजी निर्माण की समस्या भारत की इस समय एक बड़ी कठिन परन्तु महत्त्वपूर्ण समस्या है। सन् १९५०-५१ में पूँजी निर्माण कुल राष्ट्रीय आय का ५ २० वा, जो बढ़कर सन् १९५३-५४ में ६ ६० हो गया था। सन् १९५५-५६ के लिए इसका अनुमान ७% है। योजना कमीशन का अनुमान है कि दूसरे पं उ-वर्षीय आयोजना के अन्त तक यह १२% हो जायगा। इससे देश में पूँजी के निर्माण की गति पर्याप्त हो जायगी।

पूँजी का निर्माण यथार्थ में एक दीर्वकालीन किया है और इसकी नीन बड़ीबड़ी सबस्थायें होती हैं। सर्वप्रथम तो, बचत होनी चाहिए, जो मुख्यतया जनता की
बचत करने की शिक्त, बचत करने की इच्छा तथा बचत करने की मुविधाओं पर
निर्भर होती है। दूसरे, इन बचतों को विनियोग साध्य कोषों में परिवर्तित किया
जाता है। यह कार्य बैंकिंग संस्थाओं द्वारा सम्पन्न किया जाता है। अन्त में, इस प्रकार
के कोषों से पूँजीगत वस्तुएँ प्राप्त की जाती हैं, जो देश के औद्योगिक विकास की
स्थित पर निर्भर होता है। सारी की सारी बचत पूँजी का निर्माण नहीं करनी है।
उसका एक भाग श्रासंचित कोषों (Hoards) श्रयवा विदेशी निर्यातों में चला जाता
है। इसके श्रतिरिक्त पूँजीगत माल को खरीदने में समय लगता है और इस प्रकार
बचत तत्काल ही पूँजी का निर्माण नहीं कर सकती है। पूँजी निर्माण का कार्य तभी
पूरा होता है जबिक एक निश्चित योजना के श्रनुसार एकत्रित वनतों को उपयुक्त
विनियोगों में लगा दिया जाता है।

वर्तमान संसार में यह भी एक सन्तोपजनक स्थिति समभी जाती है, यदि किसी देश के निवासी अपनी आय का ५% भी बचा सकते हैं, यद्यि कुछ देशों ने विभिन्न कालों में राष्ट्रीय आय का १५-२०% भी बचाया है। शायद वर्तमान दशाओं में हमारे लिए इतनी अधिक बचत सम्भव न हो सके, परन्तु यदि हम राष्ट्रीय आय का ५% भी बचाने में सफल हो जाते हैं तब भी हमारी वार्षिक बचत कम से कम ४५० करोड़ ख्या होनी चाहिए। वर्तमान स्थिति यह है कि हमारी बचत इससे भी बहुत कम है। अनुमान इस प्रकार है कि दूमरे पंच-वर्षीय आयोजन के अन्त तक यह बढ़कर ४०० करोड़ ख्या प्रति वर्ष तक हो जायगी।

## मारत में पूँ जी निर्माण की धीमी प्रगति के कारण-

पूँजी निर्माण की शिथिलता के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :---

(१) नीचा स्राय-स्तर एवं विनियोग सुविधाओं का स्रभाव—देश में स्राय-स्तर काफी नीचा है स्रौर यद्यपि जनता की बचत करने की इच्छा काफी बलवान है, परन्तु वैकिंग सेवास्रों तथा उद्योगों के समुचित विकास के स्रभाव के कारण बचत करने की सुविधा बहुत कम है। यही कारण है कि बचत, जो कि पूँजी निर्माण का

- (२) देश-विभाजन, जमींदारों व राजाओं का अन्त—देश के विभाजन ने पूँजी निर्माण की गित को काफी शिथिल कर दिया है और इसी प्रकार युद्धो- तर काल की दूसरी घटनाओं ने, जिनमें देशी राज्यों का अन्त तथा जमींदारी उन्मूलन भी सिम्मिलित हैं, बचत तथा पूँजी निर्माण दोनों की प्रगति घीमी कर दी है। पञ्जाब के हिन्दू व्यापारी, देशी राज्यों के राजा तथा जमींदार बचत करने वाले वर्गों में सबसे महत्त्वपूर्ण लोग थे और इनका अन्त होने से बचत में भारी कमी हो गई है।
- (३) करारोपएा की ऊंची दर—कुछ ब्रथंशास्त्रियों का मत है कि युद्धो-त्तर काल में करारोपएा स्तर के ऊँचा रहने के कारएा विनियोग हतोत्साहित हुए हैं। सन् १६४७-४८ के बजट ने पूँजी निर्माएा पर सबसे बड़ा ग्राघात किया था। उसके पश्चात् विभिन्न प्रकार की छूट देकर सरकार ने स्थिति की सुधारने का प्रयत्न किया है ग्रीर ग्रब इस सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायत शेष नहीं रह गई है।
- (४) राष्ट्रीयकरण का भय—उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के भय ने पूँ जी-पितयों को भयभीत कर दिया है। सन् १६४= में सरकार ने राष्ट्रीयकरण को देश की भौद्योगिक नीति का भ्राधार घोषित कर दिया था। तत्पश्चात् सरकार ने १० वर्ष के लिए राष्ट्रीयकरण को स्थिगित रखने का बचन दिया भ्रौर संविधान में यह स्पष्ट किया गया कि सरकार दिना मुभावजा दिए किसी उद्योग को भ्रपने भ्रधिकार में नहीं लेगी, परन्तु सरकार की उद्योग राष्ट्रीयकरण घोषणा ने भारी अनिश्चितता उत्पन्न कर दी और पूँजी निर्माण के मार्ग में बाधायें खड़ी कर दी।
- (५) सट्टो बाजार की कार्यवाहियाँ—भारत में सट्टो बाजार का संचालन कुछ इस प्रकार हुआ कि उसने विनियोग साध्य कोषों के स्वतन्त्र प्रवाह को रोका है। सट्टो बाजार में जुप्रारी प्रकृति का जोर रहा है, जिसके कारए। कीमतों में अकारए ही भारी उच्चावचन हुए हैं और वास्तविक विनियोगी हतोत्साहित हुए हैं।
- (६) मैंनेजिंग एजेन्टों की दोषपूर्ण तथा घोलेवाजी की नीति के कारण कितने ही उद्योग या तो चौपट हो गए हैं या अंशघारियों के लिए किसी प्रकार का लाभ नहीं कमा पाए हैं। इन एजेन्टों ने अपने स्वार्थ हेतु विनियोगियों को हानि पहुँ चाई है भौर पूँजी निर्माण के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न कर दी है।
- (७) धन का दोषपूर्ण वितरमा द्वितीय महायुद्ध काल तथा युद्धोत्तर काल में देश के भीतर ग्राय के वितरमा में इस प्रकार के परिवर्तन हुए है कि राष्ट्रीय ग्राय का प्रिषक बड़ा भाग उन वर्गों के पास चला गया है जो बचत तथा विनियोग करना जानते ही नहीं हैं। साथ ही, उद्योगों में रुपया लगाने वाले वर्गों की बचत बरावर घटती जा रही है।
- (प) मृत्यु कर, निर्यात कर एवं बिकी-कर—ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु-करों में बचत तथा पूंजी निर्माण को ह्तोत्साहित करने की प्रवृत्ति होती है,

विदेशों के अनुभव से यह बात सिद्ध तो नहीं होती है, परन्तु इन करों का वचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारत में निर्यात करों भीर बिक्री करों ने औद्योगिक विनियोगों से प्राप्त होने वाली आय घटा दी है और इस प्रकार पूँजी के निर्माण को हतोत्साहित किया है। उररोक्त तीनों प्रकार के कर बचत भीर विनियोग दोनों को ही घटाने की प्रवृत्ति रखते है।

- (६) युद्धोत्तरकालीन तनाव युद्धोत्तर काल में भी युद्धकालीन तनाव समाप्त नहीं हो पाया है। लगभग सभी देशों ने ग्रावश्यक मालों को जमा करने तथा सशस्त्रीकरण की नी ते ग्रपनाई है। इसके ग्रतिरिक्त भारत सरकार को तो बहुत से मुद्रा प्रसार विरोधी उपाय भी करने पड़े है। परिणामस्वरूप पूँजी के निर्माण में शिथिलता ग्राई है।
- (?०) पूँजी निर्गम नियन्त्रग् भारत में पूँजी निर्गम नियन्त्रग् (Capital Issue Control) का नार्यवाहन कुछ इस प्रकार हुग्रा है कि कोप लाभदायक विनियोगों की ग्रोस प्रवाहित नहीं हो पाये हैं।
- (११) उद्योग (विकास तथा नियन्त्ररण) एक्ट—बहुत से म्रर्थशास्त्रियों का मत है कि सन् १९५१ का उद्योग (विकास तथा नियन्त्ररण) एक्ट व्यक्तिगत विनियोगों को हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति रखता है।
- (१२) लाभ का विदेशों को निर्यात—भारतीय उद्योगों के लाभों का एक बहुत बड़ा भाग, जिसका साधारणतया पूँजी के रूप में उपयोग होना चाहिए था, विदेशी पूँजी के ब्याज श्रौर लाभ के रूप में देश से बाहर चला जाता है। ऐसी राशि का वार्षिक श्रनुमान लगभग ३६ करोड़ रुपया है।
- (१३) निजी क्षेत्र पर प्रतिबन्ध—ऐसा कहा जाता है कि ग्राधिक नियोजन के ग्रन्तर्गत निजी क्षेत्र पर जो प्रतिबन्घ लगाए जा रहे हैं उन्होंने पूँजी के विनियोग को घटाया है।

## भारत में पूँजी निर्माण प्रोत्साहन के सुभाव--

भारत में देश के श्रौद्योगिक विकास के लिए इस समय घोर प्रयत्न किया बा रहा है। प्रथम पंच-वर्षीय योजना अपना जीवन-काल समाप्त कर चुकी है श्रीर दूसरी योजना के तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं, परन्तु देश का श्रौद्योगिक तथा सामान्य धार्थिक विकास अभी वहुत पीछे है। इस विकास के मार्ग में अनेक वाघाएँ हैं, परन्तु सबसे बड़ी बाघा वित्तीय कमी है। यह निश्चय है कि जब तक देश की बचतों में वृद्धि न होगी श्रौर यह बचत उद्योगों में नहीं लगाई जायेंगी तब तक कोई महत्त्वपूणं प्रगित सम्भव नहीं है। इस कारण इस समय हमारी सबसे बड़ी श्रावश्यकता पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन देना है। इसमें सन्देह नहीं है कि सरकार इस दिशा में भरसक प्रयत्न कर रही है, परन्तु अभी तक स्थित सन्तोषजनक नहीं हो पाई है। भविष्य तो श्राशाजनक दिखाई पड़ता है, क्योंकि श्रौद्योगीकरण राष्ट्रीय ग्राय को बढ़ा कर स्वयं बचत तथा

पूँजी निर्माण को उन्नत करता है, परन्तु श्रारम्भ में तो पूँजी निर्माण की उन्नति करकें ही शौद्योगिक निकास सम्पन्न किया जा सकता है। यह तो सत्य है कि कुछ श्रंश तक हम निदेशी सहायता और हीनार्थ प्रवन्धन का सहारा ले सकते हैं, परन्तु इनकी भी एक सीमा होती है। श्रन्तिम दशा में देश में पूँजी का निर्माण ही एक मात्र उपाय है। इस निर्माण को प्रोत्साहित करने के सुभाव निम्न प्रकार हो सकते हैं:—

- (१) सरकारी व्यय में वचत सबसे पहली आवश्यकता यह है कि देश में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की शासन-व्यवस्था में इस प्रकार के सुधार किये जाए कि अपव्यय समात हो और व्यय में बचत हो सके। इस सम्बन्ध में सन् १२४६-५० की सरकारी व्यय वचत समिति की सिफारिशें महत्त्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही सरकार के व्यय में जो बचत की जाय उससे प्रत्त राशि का इस प्रकार उपयोग किया जाय कि वर्तमान काल में औद्योगिक विकास हो और भविष्य के लिए पूँजों के निर्माण की नींव पडें।
- (२) स्रासंचित कोषों को तोड़ना—इस बात की भारी स्रावश्यकता है कि स्रासंचित कोषों को तोड़ा जाय, जिससे कि उनका लाभदायक उपयोग हो सके। इसके लिए दो बातों की स्रावश्यकता है:—प्रथम, इस सम्बन्ध में सप्रभाविक प्रचार करके लोगों को गढ़े हुए घन के उपयोग का महत्त्व समभाया जाय ग्रीर दूसरे, विनियोगों के लाभ प्रथवा ऋएगों के ब्याज की दरें ग्राकर्षक रखी जायें। ऐसा स्रनुमान लगाया जाता है कि यदि स्वर्ण स्रासंचित कोषों को ही निकाल देने में सफलता मिल जाती है तो पाँच वर्ष तक राष्ट्रीय स्राय का लगभग २% पूँजी के रूप में प्राप्त हो सकता है। पिछले दिनों सरकार ने स्वर्ण तथा बहुमूल्य जेवरात की ग्राड़ पर ऋएग देने का बो स्रादेश बेंकों को दिया है उससे काफी लाभ की ग्राशा है।
- ्रे (३) ग्रल्प बचत को प्रोत्साहन—छोटी ग्राय वर्गों को तथा ग्रामीए क्षेत्रों में बचत को प्रोत्साहन देने के लिए प्रचार की ग्रधिक ग्रावश्यकता है ग्रौर यह भी ग्रावश्यक है कि बैंकिंग सेवाग्रों तथा सेविंग बैंकों का विकास किया जाय। इस सम्बन्ध में ब्याज की दरों में वृद्धि करना लाभदायक हो सकता है। वर्तमान दरें बहुत ग्राकर्षक नहीं हैं।
- (४) स्टॉक एक्सचेन्ज सुविधायों अधिक आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए बचत प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं का अभाव नहीं है। उनके लिए तो केवल यही पर्याप्त है कि उन्हें उपभोग घटाने तथा बचत को लाभदायक कार्यों में लगाने की प्रोत्साहित किया जाय। मध्यम आय वर्गों की बचत उनके लिए स्टाक् इक्सचेन्ज सुविधाएँ उपलब्ध करके बढ़ाई जा सकती है। छोटी आय वर्गों में प्रचार की भारी आवश्यकता है।
- (५) लाभ पर- करों में छूट उद्योगों तथा कम्पनियों की बचत को श्रोत्साहन देने के लिए यह उपयुक्त होगा कि लाभ पर लगाये जाने वाले करों में

खूट दी जाय ग्रौर मशीनों की घिसावट ग्रादि के लिए ग्राधिक छूट की व्यवस्था की जाय। ऐसी बचत ग्रौद्योगिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण सावन बन सकती है।

(६) पूँजी के निर्यात पर प्रनिवन्य और आयान को प्रेन्नहम् यह आवश्यक है कि पूँजी के निर्यात पर प्रतिबन्य लगाये जार्य और विदेशी पूँजी-पतियों से यह अनुरोध किया जाय तथा उन्हें ऐनी मुविधायें दी जार्य कि दे लाभ का अधिकांश भाग भारतीय विनियोगों में लगायें। विदेशी पूँजी के आयात के लिए अधिक प्रयत्न किया जाय।

### सरकारी उपायों का संचित्र वर्णन-

टपरोक्त सभी दिशाशों में भारत की राष्ट्रीय सरकार प्रयत्नशील है। योजना कमीशन ने प्रथम पञ्च-वर्षीय योजना के लिए २,२५० करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था,की थी। योजना कमीशन के अनुसार इस राधि में मे १,२५५ करोड़ रुपया बचत द्वारा प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से ७२५ करोड़ रुपया लोक बचतों से और शेष ५२० करोड़ रुपया व्यक्तिगत बचत ने प्राप्त होने का अनुमान था। १५६ करोड़ रुपया विदेशी ऋणों के रूप में मिल चुना है तथा भविष्य में और भी ऐसे ऋणों के मिलने की प्राथ्ता है। २६० करोड़ रुपये की राधि पींड पावना मद से प्राप्त हो सकती थी। शेष वित्तीय ग्रावश्यकता करों की बृद्धि,ऋणा तथा हीनार्थ प्रवन्धन (Deficit Financing) द्वारा पूरा होने की सम्भावना थी। वास्तविक व्यय २,००० करोड़ रुपये से भी कम रहा है। हीनार्थ प्रवन्ध की ग्रावश्यकता ग्रहमान से ग्राविक रही है, क्योंकि पींड पावना मद से तो नाम मात्र राधि ही निकाली गई है। बचत के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सरकारी उपाय छोटी बचतों से सम्बन्धित हैं।

## छोटी बचत योजना—

इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक छोटो बचत योजना ( $Small\ Saving\ Scheme$ ) का निर्माण किया है, जिसके अन्तर्गत इस प्रकार की पहले से चालू योजनाओं के विस्तार के अतिरिक्त कुछ नई योजनाएँ भी चालू की गई हैं। इस प्रकार की योजनाएँ निम्न प्रकार हैं:—

(१) डाकखानों के सेविंग बैंक—यह योजना काफी लम्बे काल मे चालू है, परन्तु इसमें विगत दर्षों में कुछ महत्त्वपूर्ण सुघार तथा संशोधन किये गये है। ये बैंक सभी डाकखानों में खोली गई हैं। इनमें कोई भी वयस्क रुत्रया जमा कर सकता है। किसी भी ग्रत्यवयस्क की ग्रोर से भी उसके संरक्षक द्वारा खाता खोला जा सकता है। जमा करने वाले को एक सप्ताह में एक बार खाते में से कभी भी रुत्रया निकालने का ग्रिषकार होता है; कम से कम २ रुपया जमा करके खाता खोला जा सकता है और इस प्रकार के खाते में ग्रिषक से ग्रिषक १५,००० रुपये तक जमा किया जा सकता है। जमा की हुई राशि पर २% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज दिया जाता है, परन्तु १०,००० रुपये से ऊतर की राशि पर ब्याज की दर केवल १५% है, शर्त यह

हैं कि यदि किसी महीने में जमा की रक्म २५ रुपये से कम होती है तो उस महीने का ब्याज नहीं दिया जाता है। ऐसी जमा से प्राप्त ब्याज ग्राय-कर तथा ग्राति-करसे मुक्त है।

- (२) वारह-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (The 12-Years National Savings Certificates)—इस प्रकार के प्रमाण-पत्र भी डाक्खानों द्वारा ही बेचे जाते हैं। ये प्रमारा-पत्र ५, १०, ५०, १००, ५००, १,००० तथा ४,००० रुपये के होते हैं और उन जमा करने वालों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं जो मूलघन तथा ब्याज की प्राप्ति के लिए कुछ साल तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। एक व्यक्ति ग्रपनी ग्रोर से ग्रथवा बचों की ग्रोर से प्रमारा-पत्र खरीद सकता है, परन्तु इस प्रकार के प्रमारा-पत्रों में एक व्यक्ति अधिक से अधिक २५,००० रुपये तक लगा सकता है. जिसमें वह राशि भी सम्मिलित की जाती है जो ज्यक्ति विशेष ने पहले चालू किये गये पञ्च-वर्षीय तथा सप्त-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमागा-पत्रों में लगा रखी है। दो व्यक्ति सेम्मिलित रूप में ग्रधिक से ग्रधिक ५०,००० रुपया ऐसे प्रमाग्त-पत्रों में लगा सकते हैं। इन पत्रों में ब्याज की दर इस प्रकार रखी गई है कि परिपक्कता पर ग्रर्थातु १२ वर्ष पश्चात १०० रुपये के १६५ रुपये मिल जाते हैं। इस प्रकार ब्याज की ग्रौसत वार्षिक दर x'४२% निकलती है, परन्तु इनमें रुपया लगाने वालों को परिपक्कता से पूर्व भी रुपया निकाल लेने का ग्रधिकार दिया गया है। कम से कम एक वर्ष पीछे स्वया निकाला जा सकता है, परन्तु उस दशा में ५ रुपये के प्रमागा-पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी राशि के प्रमारा-पत्र पर ब्याज नहीं मिलता है। जैसे-जैसे समय ग्रवधि बढ़ती जाती है, ब्याज की दर भी बढ़ती है। ब्याज से प्राप्त राशि आय-कर तथा अति-कर से विमक्त है श्रीर श्राय-कर की दर निर्धारित करने के लिए भी उसे कुल श्राय में सम्मिलित नहीं किया जाता है।
- (३) पश्च-वर्षीय तथा सप्त-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाग्ग-पत्र इन प्रमाग्ग-पत्रों के नियम १२-वर्षीय प्रमाग्ग-पत्रों की ही भाँति हैं, ग्रन्तर केवल इतना है कि इन पर ब्याज की दर कम होती है। पञ्च-वर्षीय प्रमाग्ग-पत्रों पर ३% तथा ७-वर्षीय पत्रों पर ३ ५% ब्याज की दर रहती है। इनसे प्राप्त ब्याज पर भी करों में छूट दी गई है।
- (४) बचत मुद्राङ्क (Saving Stamps)—यह सबसे छोटी बचतों की योजना है। जो लोग ५ रुपये के भी प्रमारा-पत्र नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे समय-समय पर डाकखाने से ४ ग्राने, द ग्राने ग्रथवा एक रुपये के बचत-मुद्रांक खरीद लें। ऐसी टिकटें डाकखाने से दी गई एक पास-बुक पर चिपका दी जाती हैं और जब उसकी कीमत ५ रुपये ग्रथवा १० रुपये तक हो जाती हैं तो उनके बदले में बचत प्रमारा-पत्र खरीदने का ग्रधिकार दे दिया जाता है।

लगभग सभी प्रकार के प्रमारा-पत्रों के सम्बन्ध में कुछ विशेष रूप में सुविधा-

जनक नियम बनाये गये है, जैसे—कोये हुए प्रमासा-पत्र के स्थान पर स्वामी की घोषसा को स्वीकार कर लिया जाता है, सरकारी करों को चुक्तने में इन्हें स्वीकार कर लिया जाता है और उपकारी संस्थाओं, सबीं अर्दि को इनमें अधिक धन लगाने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में सरकार इन्हें स्वीकार कर लेती है और नकद प्रतिभूति पर अनुरोध नहीं करती है।

- (४) दस-वर्षीय कोपागार वचत निक्षेप (The 10-Years Treasury Savings Deposits)—यह जमा १०० रुपये से कम की नहीं हो सकती है ग्रौर इसके लिए १००-१०० रुपये के ही प्रमासा-पत्र होने है । एक व्यक्तिः ग्रघिक से ग्रधिक २५,००० रुपया इस जमा में लगा सकता है। दो व्यक्ति मिलकर ५०,००० रुपये लगा सकते हैं और दानी सस्यायें १ लाख रुपये तक लगा सकती है। इन निक्षेपों की विशेषता यह होती है कि जमा करने वाले की पूँजी ज्यों की त्यों दनी नहती है. परन्तु उसे नियमित रूप में प्रति वर्ष ३ $\frac{50}{5}$  की दर पर ब्याज मिलता रहता है, इस कारण यह योजना उन लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है जो अपनी बचत मे एक निय-मित आय प्राप्त करना चाहते हैं। रुपया रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक अथवा सरकारी कोपा-गार में जमा किया जा सकता है। ग्रत्य-वयस्कों की ग्रोर मे भी मरझकों को रूपया जमा करने का अधिकार दिया गया है। एक साल पश्चानु कभी भी जमा की राशि को निकाला जा सकता है, परन्त्र १० वर्ष से पूर्व रुपया निकालने की दशा में विभिन्न दरों पर बट्टा लगाया जाता है। ब्याज की शुद्ध दर प्रति वर्ष इस प्रशार बढ़ती जाती हैं कि १० वर्ष पीछे वह ३º५% हो जाती हैं। ऐसी जमा के प्रमास-पत्र भी प्रति-भूतियों के रूप में स्वीकार किये जाते हैं और इनके ब्याज की राशि भी सरकारी करों से मुक्त होती है और आय-कर की दरों के निर्धारण में भी उसे कूल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है।
- (६) वेतन बचत योजना (Salary Savings Scheme)—यह योजना सन् १९५० में चालू की गई है और विशेषतया उन व्यक्तियों के लिए लाभ-दायक है जिन्हें निश्चित रूप में प्रति मास आय प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति प्रति मास १०, २०, २५, ५० अथवा १०० रुपये प्रति मास डाकखाने में जमा कर सकता है और ५ अथवा १० वर्ष तक इस प्रकार की जमा को चालू रख सकता है। जमा की राशि को जमा करने वाले द्वारा घोषित जमा के अनुसार ५ अथवा १० वर्ष पश्चात् निकाला जा सकता है। जमा पर ब्याज मिलता है और निर्धारित अवधि के पश्चात् ब्याज और मूलधन की राशि निकालने का जमाधारी को अधिकार होता है, यद्यपि कुछ निश्चित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत समय अवधि के पूरा होने से पूर्व भी धन निकाला जा सकता है। व्याज की राशि आय-कर से विमुक्त होती है।

विगत वर्षों में सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके अनुसार सोने, चाँदी, हीरे, जवाहरात, आभूषणा आदि की आड़ पर राष्ट्रीय ऋणों में घन लगाने के लिए बेंकों को ऋए। देने का अधिकार दिया गया है। इसका परिएाम अधिक महत्त्व-पूर्ण होगा, क्योंकि इस योजना के अनुसार देश के अनुत्पादक आसंचित कोणों का भी लाभदायक उपयोग हो सकेगा। १५ अक्टूबर सन् १६५३ से भू-सम्पत्ति कर (Estate Duties) के रूप में भारत सरकार ने मृत्यु-कर भी लागू कर दिया है, जिससे प्राप्त होने वाली समस्त आय को पूँजी के रूप में आर्थिक योजनाओं की वित्तीय आव-स्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग करने का निश्चय किया गया है। प्रवार हारा बचत को प्रोत्साहन देने का भी काफी प्रयत्न किया जा रहा है और काफी मात्रा में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें वार-वार लोक ऋर्गों को जारी करती रहती हैं। विदेशों से पूँजी प्राप्त करने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में कुछ विशेष प्रकार की छूटें भी दी गई हैं।

सन् १९५७ के ग्रन्त में देश के पूँजी बाजार की स्थिति निम्न तालिका द्वारा स्वित की जाती है:—

(करोड़ रुपयों में )

=	सभी अनुसूचित		कोषागार	(१) का	(३) का
म्रन्तिम शुक्रवार	बैङ्कों के	चलन	विपत्र	(३) से %	(२) से %
man grant	निक्षेप		बकाया	श्रनुपात	म्रनुपात
	(१)	(२)	(३)		
जनवरी	१,१२२'२६	१,४=५.४२	७०७:२५	७४•७२	४७•६१
फरवरी	१,१५१'६४	१,५०६"२५	७३८.४७	७६ ४८	४६.०३
मार्च	१,१७५.३०	१,५२६.०६	८ इंर.७०	9000	५४ ७६
भ्रप्रैल	१,२२० ५२	१,५६१-६१	<b>८५१</b> °८६	७८. १८	<b>ሂ</b> ሄ"ሂሄ
मई	१,२३८७१	१,५७०"००	६१४.७५	03.50	४ द"२७
जून	१,२६२•३१	१,५४२ १७	१४१ ७५	द <b>१</b> °द४	६१°०ँ७
जुलाई	१,२८८'०८	१,४८६"५३	१५ ३ १ १ ७ ३	<b>८४</b> .६८	६४.६३
श्रगस्त	१,२५५'०४	१,४७०'६३	६१२"४२	<b>দ</b> ७*খ্ৰ	६२"०४
सितम्बर	१,३१० ६५	१,४७१ ११	६४३'७३	30-32	६४•१५
ग्रक्टूबर	१,३६५'४०	१,४५६"२०	१,००१'२७	६१.५७	६७•३७
नवम्बर	१,३६५'१६	१,४७=*६६	१,०५= २६	६२•३३	७१-५७
दिसम्बर	१,३६६°०४	१,५०६ ७६	१,०५५ २६	६०°६६	६६.६१

#### **QUESTIONS**

1. What are the main constituents of the Indian Money

- Market? What control does the Reserve Bank exercise over them? (Agra, B. Com., 1956 Supp & 1954)
- 2. Are you convinced that an organised Money Market does not exist in India? If so, discuss the conditions under which it can come into existence.

(Agra, B. Com., 1951 & 1945)

3. What are the defects of the Indian Money Market? Suggest any measures of reform you consider necessary.

(Agra, B. Com., 1957 Supp)

- 4. Discuss the salient features of the Indian Money Market and show to what extent its main defects have been remedied since independence. (Raj., B Com., 1956)
- i. Discuss the causes responsible for the absence of a bill market in India. Suggest measures to remove them.

  (Rai. B. Com., 1952)
- 6. Discuss the impurtance of a well-organised Bill Market as an instrument of economic progress. Account for the absence of a bill market in India. What steps have been taken in this respect in recent times? (Raj., B. Com., 1954)
- 7. भारतीय मुद्रा-वाजार के मुख्य दोषों का उल्लेख कीजिए और उन्हें दूर करने के लिए निश्चित सुमाव दीजिए। (Sagar, B. Com., 1954)
- Write note on—Main features of the Indian Money Market. (Raj., B. Com., 1956)

Indian Money Market—its defects and the way out.

(Raj., B. Com, 1957)

#### अध्याय ३४

# रिजर्व बेंक ऑफ इन्डिया

The Reserve Bank of India)

#### वारमा

भारत में १ अप्रैल सन् १६३५ में एक अंश्वारियों की बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ने अपना कार्य आरम्भ किया। इससे पहले सन् १६३४ में रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया एक्ट पास हो चुका था। ऐसी बैंक की स्थापना की सिफारिश हिल्टन-यंग आगोग ने की थी, जिसका विचार था कि भारत में एक केन्द्रीय बैंक की अधिक आवश्यकता थी और ऐसी बैंक का नाम भी रिजर्व बैंक होना चाहिए, परन्तु कुछ दिनों तक सरकार ने इस समस्या पर विचार करना स्थिगत करके रखा। सन् १६३४ का एक्ट पास होने से पहले बहुत समय तक यह वाद-विवाद चलता रहा था कि क्या इम्पीरियल बैंक को ही केन्द्रीय बैंक नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि पहले से ही वह बैंक केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी कुछ कार्य करती चली आ रही थी। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी बहुत सोच-विचार किया गया कि क्या रिजर्व बैंक को अश्वारियों की बैंक बनाया जाय, अथवा उसे आरम्भ से ही सरकारी स्वामित्व में रखा जाय।

## ं बैंक की श्रावश्यकता

#### मुद्रा व साख का समुचित प्रवन्ध—

ऐसा अनुभव किया गया था कि केन्द्रीय बैंक्क के का में इम्पीरियल बैंक का कार्य सन्तोषजनक नहीं था और मुद्रा पर सरकार और इम्पीरियल बैंक का दोहरा नियन्त्रण रहता था, इसलिए यह आवश्यक था कि इन दोषों को दूर करने के लिये एक केन्द्रीय बैंक स्थापित की जाय। हिल्टन यंग आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि एक ऐसी प्रणाली में दोषों का रहना आवश्यक था जिसमें मुद्रा तथा साख पर दो अलग-अलग संस्थाओं का नियन्त्रण रहता हो, क्योंकि दोनों की नीतियों में भारी अन्तर का रहना सम्भव है। आयोग का विचार था कि केन्द्रीय बैंक की व्यवस्था द्वारा यह कमजोरी दूर हो जायगी। साथ ही, यह भी अनुभव किया गया था कि सन् १६३५ के नये विधान की सफलता एक बड़े अंश तक इस बात पर निभंर थी कि देश की वित्तीय स्थित सुदृढ़ रहे और उसकी साख भी बनी रहे। इसके लिए भी केन्द्रीय बैंक की स्थापना आवश्यक समभी गई।

इम्गीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक बनाना इस काररा उपयुक्त नहीं समक्ता गया था कि पहले से ही इम्पीरियल बैंक देश की अन्य बैंकों से प्रतियोगिता करती चली आ रही थी, इसलिए अन्य बैंकों का उस पर पूरा विश्वाम न रहने के कारण उसके लिए केन्द्रीय वैकिंग के कार्य को सन्तोपजनक रीति से चलाना कठिन था। केन्द्रीय वैंक के अधिकार मिल जाने का अर्थ यह था कि इम्गीरियल बैंक अन्य बैंकों की संरक्षक तथा ऋरण का अन्तिम सहारा बन जाती, जिससे वह अपने साधारण टैकिंग व्यवसाय को चालू नहीं रख सकती थी। अन्य बैंकों पर उसका प्रभाव न होने के धारण उसकी कार्यक्षमता पर कम विश्वास रहने का भी भय था। वैंसे भी इम्पीरियल बैंक का संचालक-मण्डल बैंक द्वारा साधारण बैंकिंग व्यवसाय को छोड़ने के पक्ष में नहीं था। अतएव यह निश्चित किया गया कि भारत में एक रिजर्व बैंक स्थापित की जाय जो नये सिरे से अपना कार्य आरम्भ करके अपनी नई परम्परा बनाये।

रिजर्व वेंक को राजकीय संस्था बनाने के पक्ष ग्रौर विपक्ष में भी बहुन कुछ कहा गया था। ऐसा विचार था कि ग्रंशघारियों की संस्था के रूप में यह वैंक देश के हित में कार्य नहीं कर पायगी, क्योंकि प्रशासारी अपने प्रधिकारों का उपयोग निहित हितों (Vested Interests) को उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं स्रीर इस प्रकार प्राप्त शक्ति का उपयोग राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा उनकी अपनी स्वार्थ पूर्ति में किया जा सकता है। इसी प्रकार यह भी कहा गया था कि एक अधिकतित देश होने के कारण भारत में जतता को ग्रथनी बचत उत्पादक कार्यों में लगाने का अभ्यास नहीं है, इसलिए ऐसी दशास्रों में कोई भी श्रंशघारियों की बैंक वचत को प्रोत्साहित करने में सफल नहीं हो सकती थी। इस बैंक को एक राजकीय संस्था बनाने के विरुद्ध भी कुछ गम्भीर तर्क रखे गये थे, क्योंकि उस समय सरकार विदेशी थी, इसलिए यह कहा गया था कि सरकार द्वारा इस संस्था का एक भेद-भाव के साधन के रूप में विदेशी हितों को लाभ पहुँचाने के लिए उपयोग किया जा सकता था। यह भी प्रकट किया गया था कि राजकीय संस्था बन जाने पर रिजर्व बेंक भारतीय व्यापारियों के स्रनुभवों स्रीर उनकी सलाहों के लाभ से बंचित रहेगी। केवल ग्रंगवारियों की बैंक रहने की दशा में ही ये लाभ उसे प्राप्त हो सकते हैं। अतः यह निरुचय हुआ कि रिजर्व बेंक को एक अंशघारियों की वैंक बनाया जाय ग्रीर १ ग्रप्रैल सन् १६३५ तथा ३१ दितम्बर सन् १९४५ के बीच यही व्यवस्था बनी भी रही। १ जनवरी सन् १९४९ से रिजर्व वैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया है । ग्रब यह पूर्णातया एक सरकारी बैंक है, क्योंकि मुग्रावजा देकर ग्रंशधारियों को समाप्त कर दिया गया है।

## वैंक का विधान—

ग्रारम्भ में रिजर्व बैंक ने ग्रंशधारियों की बैंक के रूप में कार्य शुरू किया। इसकी कुल ग्रंश पूँजी ५ करोड़ रू० रखी गई थी, जिसे १००-१०० राये के पूर्णतया तथा शोधित (Fully paid-up) ग्रंशों में बाँटा गया था, परन्तु प्रयत्न यह किया गया था कि रिजर्व बैंक की संवालक शक्ति कुछ थोड़े से हाथों में केन्द्रित न होने पाये। इसके लिए एक योजना बनाई गई थी, जिसके श्रमुसार देश को कलकत्ता, बम्बई,

मद्रास, दिल्ली तथा रंगून के पांच क्षेत्रों में बाँटा गया और प्रत्येक क्षेत्र के ग्रंशघारियों को निश्चित कीमत के ग्रंश बेचे गये, परन्तु घीरे-घीरे हस्तान्तरएा द्वारा ग्रंघिकांश ग्रंश बम्बई क्षेत्र में केन्द्रित होने लगे। इसके कारएा सन् १६४० में सरकार को यह नियम बनाना पड़ा कि यदि किसी व्यक्ति के पास २० हजार रुपये की कीमत से ग्रंघिक ग्रंश हो जायें तो उसका नाम ग्रंशयारियी की सूची में प्रविष्ट नहीं हो सकता था, परन्तु यह नियम भी ग्रंशों को बम्बई क्षेत्र में केन्द्रित होने से रोक न सका। केवल राष्ट्रीयकरण द्वारा ही यह दोष दूर हो सका है।

### वर्तमान विधान-

सन् १६४८ के रिजर्व बेंक (लोक स्वामित्त्व हस्तान्तररा) एक्ट द्वारा रिजर्व बेंक का राष्ट्रीयकररा किया गया। बेंक के सभी ग्रंशों की प्रत्येक १०० रुग्ये के ग्रंश की ११८ रुपये १० ग्राने कीमत चुका कर सरकार ने प्राप्त कर लिया है। बेंक का वर्तमान विधान निम्न प्रकार है—

- (क) पूर्णी—बैंक की वर्तमान पूँजी पहले की ही भाँति ५ करोड़ हाया है, परन्तु अब उसके सभी अंश सरकार के पास हैं।
- (ख) प्रवन्ध-—वैंक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय संचालक सिमिति द्वारा किया जाता है, जिसमें १४ सदस्य होते हैं। इन १४ सदस्यों में से एक गवर्नर तथा २ उप-गवर्नर सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, ७ संचालक केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद किये जाते हैं ग्रौर ४ सञ्चालक स्थानीय सिमितियों (Local Boards) से खंटि जाते हैं।

गवर्नर तथा उप-गवर्नर वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। ये पाँच साल की ग्रविष के लिए नियुक्त किये जाते हैं और इनका वेतन केन्द्रीय सरकार से परामर्श लेकर केन्द्रीय बोर्ड निश्चित करता है। स्थानीय बोर्डों द्वारा नियुक्त संवालक भी पांच वर्ष तक के लिए नियुक्त किये जाते हैं, यद्यपि उनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है। ग्रन्य संचा-लक बारी-बारी से एक, दो तथा तीन वर्ष पश्चात् निवृत (Retire) होते रहते हैं।

इनके स्रतिरिक्त केन्द्रीय बोर्ड में सरकार द्वारा एक सरकारी कर्मचारी भी नियुक्त किया जाता है, जो केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार काम करता है। इस कर्म-चारी को बोर्ड की बैठकों में सम्मिलित होने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का तो स्रिष्कार होता है, परन्तु इसे मतदान का स्रिष्कार नहीं होता।

विधानानुसार केन्द्रीय बोर्ड की एक वर्ष में कम से कम छः और तीन मास में कम से कम एक बैठक अवश्य होनी चाहिए। गवर्नर को बोर्ड की बैठक बुलाने का अधिकार है और किन्हीं तीन संचालकों की माँग पर भी बैठक बुलाना आवश्यक होता है।

(ग) कार्यालय—इस समय बैंक के पाँच मुख्य कार्यालय हैं, जो बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास भौर कानपुर में हैं। बैंक का प्रधान कार्यालय स्थाई रूप से बम्बई है। रिजर्व बंक की विदेशी शाखायें कराँ वी, लाहौर और लन्दन में हैं। केन्द्रीय सरकार की आज्ञा पर रिजर्व बंक को किसी भी स्थान पर शाखा खोलने का अधिकार है। इस समय यह व्यवस्था की गई है कि जिन स्थानों पर रिजर्व बंक की शाखा नहीं है, परन्तु स्टेट बंक की शाखायें हैं, स्टेट बंक्क रिजर्व बंक की अभिकर्त्ता (Agent) का कार्य करती है।

स्थानीय समितियों के ३-३ सदस्य होते हैं, जो विभिन्न प्रादेशिक तथा प्राधिक हितों का प्रतिनिधित्त्व करते हैं और इन हितों में सरकारी बैंक तथा देशी बैंक्करों को भी सम्मिलित किया जाता है।

राष्ट्रीयकरएा से पूर्व केन्द्रीय संचालक मण्डल में १६ सदस्य होते थे, जिनमें से १ गवर्नर तथा १ उप-गवर्नर सरकार नामजद करती थी, ४ संचालक सरकार नामजद करती थी, द संचालक विभिन्न क्षेत्रों के ग्रंशधारी निर्वाचित करते थे ग्रीर एक सरकारी ग्रंधिकारी सरकार द्वारा नामजद किया जाता था। इसी प्रकार स्थानीय मण्डलों में द-द सदस्य होते थे, जिनमें से ५ वहाँ के ग्रंशधारी निर्वाचित करते थे ग्रीर ३ सदस्य केन्द्रीय सरकार नामजद करती थी।

(घ) नीति—रिजर्व बेंक की नीति तथा कार्यवाहन पूर्णतया केन्द्रीय सर-कार के हाथ में है, जो समय-समय पर गवनर से सलाह करके बेंक को आदेश देती रहती है।

(ङ) विभाग — बै्ङ्क के दो प्रमुख विभाग हैं: — निगंम विभाग तथा अधि-कोषण विभाग। यही व्यवस्था बैंक आँफ इङ्गलैंड में भी है। निगंम विभाग का सम्बन्ध केवल नोट निगंम से है, अन्य सभी कार्य अधिकोपण विभाग द्वारा किये जाते हैं।

निर्गम विभाग के दो उप-विभाग हैं—(१) कोषाध्यक्ष विभाग तथा (२) साघारण विभाग । प्रथम उपविभाग नोटों के निर्गम तथा पत्र-मुद्रा को प्रधान तथा गौरा मुद्राओं में बदलने का कार्य करता है। साधारण उप-विभाग चलन विभाग की व्यवस्था करता है। स्वर्ण निधि का संरक्षण इसी के पात है। इतके अतिरिक्त यह उप-विभाग नोटों को जाँचने, नोटों को रद्द करने, नोटों के हिसाब रखने तथा आंतरिक अनेक्षण (Internal audit) का भी कार्य करता है।

ग्रिंघकोषणा विभाग के भी कई उप-विभाग हैं, जो निम्न प्रकार है :--

(१) कृषि साख विभाग — (Agricultural Credit Department)—यह विभाग कृष तथा ग्रामीए। वित्त सम्बन्धी सभी प्रकार के कार्य करता है। देश में कृषि वित्त की कमी को दूर करने के लिए ब्रारम्भ से ही इस विभाग का निर्माण किया गया था।

मु०्च०ग्र० (३७)

100 Th p.

- (२) विनिमय नियन्त्रग् विभाग (The Exchange Control Department)—इस विभाग का कार्यं विनिमय नियन्त्रग् नियमन सम्बन्धी शासन को चलाना होता है।
- (३) बैंकिंग कार्य विभाग (The Department of Banking Operations)—यह विभाग ग्रन्य बैंकों के नियन्त्रण तथा निरीक्षण का कार्य करता है। यह विभाग १ ग्रगस्त सन् १६४५ को खोला गया था ग्रौर इसके तीत उप-भाग हैं:—(ग्र) संवालन विभाग (Operation Division), (ब) निरीक्षण विभाग (Inspection Division) तथा (स) निस्तारण विभाग (Liquidation Divsion)। प्रथम विभाग उन सब कार्यों को करता है जो रिजर्व बैंक्क को एक बैंक होने के नाते करने पड़ते हैं। निरीक्षण विभाग यह देखता है कि ग्रन्य बैंक समुचित बैंकिंग कार्यवाहन के लिए सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा निकाले हुए ग्रादेशों का कहाँ तक प'लन करती हैं। निस्तारण विभाग का कार्य बैंकों को बन्द कर देने से सम्बन्धित ग्रावश्यक कार्यवाहों का करना होता है।

इनके ग्रितिरिक्त बें ह का एक ग्रीर भी विभाग है ग्रथात् ग्रन्वेषणा तथा समांक विभाग (Department of Research and Statistics) । इस विभाग का कार्य मौद्रिक, साख ग्रीर वित्तीय समस्याग्रों के ग्रन्वेषणा तथा ग्रनुसन्धान से सम्बन्धित है । यह इन विषयों से सम्बन्धित ग्रांकड़ों का भी प्रकाशन करता है । यह विभाग मुद्रा ग्रीर वित्त के सम्बन्ध में एक वार्षिक रिपोर्ट भी निकालता है ।

रिजर्व बैंक के कार्य (The Functions of the Reserve Bank)-

रिजर्व बैंक भारत की केन्द्रीय बैंक है, इसलिए वह उन सभी कार्यों को सम्पन्न करती है जो एक साधारए केन्द्रीय बैंक द्वारा किए जाते हैं। इन कार्यों का विस्तृत वर्णान एक पिछले अध्याय में किया जा चुका है। प्रस्तुत अध्याय में रिजर्व बैंक के कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यों का संक्षिप्त वर्णान किया जायगा। बैंक के कार्य निम्न प्रकार है:—

(१) सरकारी बैंकर का कार्य—केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सभी नकद शेष (Cash Balances) रिजर्व बेंक में रखी जाती हैं ग्रीर इन शेषों पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। भारत के लोक ऋएा (Public Debts) का प्रबन्ध भी यही बेंक करती है। ऋएगों का हिसाब, उनका जमा करना तथा उनका चुकाना रिजर्व बैंक के ही कार्य हैं। इसके ग्रतिरिक्त सरकारी बैंकिंग व्यवसाय, जिनमें सरकारी करों ग्रादि से प्राप्त ग्राय को जमा करना, सरकारी कोषों का एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना, सरकारी ज्रादिका स्थान से ऋएग दे सकती है, परन्तु ऐसे ऋएग या तो मांग पर तुरन्त शोधनीय होते हैं ग्रथवा मार्गापाय ग्रिग्रमों (Ways and Means Advances) के रूप में होते हैं, जो एक निश्चित ग्रविध के भीतर, जो ग्रधिक से ग्रधिक ६० दिन हो सकती है, शोधनीय होते हैं। बैंक्क को विदेशी सर-

कारों की श्रोर से भी कार्य करने का श्रिविकार है। यह वैद्ध सरकार को सलाह भी देती है। सरकार की श्रोर से रिजर्व बैद्ध जो कार्य करती है उसके लिए उने कि प्रशास का पारितोषरण नहीं दिया जाता है, क्योंकि बैद्ध को सरकारी शेषें विना बगाज के प्राप्त होती हैं। केवल सरकारी हुण्डियों की विक्री का कभीशन इसे मिलता है। इस कमीशन की दर प्रति एक लोख के विल पर दो हजार रुपया होती है। रिजर्य बैद्ध सदा हो समुचित प्रतिभूति के श्रावार पर देती है।

(२) नोटों का निर्गम—रिजर्व वैंक को भारत में नोट निर्गम का एका-घिकार प्राप्त है। इस कार्य के लिए बैक्क का एक प्रयक्त विभाग है, जिसे निर्गम विभाग कहा जाता है। कारएा यह है कि नोट निर्गम को एक प्रकार से बैंड्रिंग कार्य नहीं कहा जा सकता है, परन्तु आधुनिक विचारघारा ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध है। वर्तमान काल में करेंसी नोट तथा बैक्क के जमाधन में कोई आधारभूत भेद नहीं होता है और दोनों ही मुद्रा होते हैं। इस कारएा दोनों विभागों के भेद का कोई सैद्धान्तिक आधार नहीं रह जाता है। केन्द्रीय बैक्क को नोट निर्गम तथा बैंक्किंग व्यवसाय दोनों में ही प्रतियो-गिता का कोई भय नहीं होता है।

भारत में नोट निर्गम प्रिणाली पर जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए यहं व्यवस्था की गई थी कि जितने नोटों का निर्गम हो उसके ४०% के बराबर सोने के सिक्के, स्वर्ण-पाट प्रथवा स्टिलिं होने चाहिए, जिसमें २१ राया ३ ग्राना १० पाई प्रित तोला की दर पर किसी भी समय ४० करोड़ रुग्ये से कम कीमत का सोना नहीं रहना चाहिए। शेष ६०% नोटों के पीछे रुपया प्रतिभूतियाँ, विनिमय बिल भादि हो सकते हैं, परन्तु भारत सरकार ने रुपया प्रतिभूतियों की ग्रविकतम् मात्रा ४० करोड़ रुपया अथवा कुल की एक-चौथाई (जो भी अधिक हो) रखी थी, परन्तु बाद के संशोधनों द्वारा यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया है, जिसके कारण रुपया प्रतिभूतियों की राशि बराबर बढ़ती गई है। यह संशोधन सन् १६४६ में हुग्रा था।

सन् १६५६ में यह पुरानी व्यवस्थायें समाप्त कर दी गई हैं। नये नियम के अनुसार नोट निर्गमन विभाग में सोने और सोने सिक्के अब न्यूनतम् ११५ करोड़ रुपये के मूल्य में रखे जा सर्कों। इसके अतिरिक्त नोट निगम विभाग में कम से कम ४०० करोड़ रुपये ( जो विशेष परिस्थितियों में ३०० करोड़ रुपये तक घटाई जा सकती है) के मूल्य की विदेशो प्रतिभृतियाँ रहेंगी। इस प्रकार कुल मिलाकर कम से कम ११५ करोड़ रुपये का कोष इस विभाग में रखना आवश्यक है। रिजर्व बंद्ध के पास जो सोना है उसका मूल्यां हन अब २१ रुपये ३ आने १० पाई प्रति तोला के स्थान पर अन्तर्श्योय मुद्रा-कोष द्वारा निर्घारित दर अर्थात् ३५ डालर प्रति खोंस [१ रुपया = २ ६६ ग्रेन (स्वर्गा)] अथवा ६२ ५० रुपया प्रति तोला की दर पर किया जाता है।

(३) विनिमय दर के स्थायित्त्व को बनाये रखना—सन् १९३४ के एक्ट के अनुसार यह रिजर्व बैङ्क का एक वैधानिक कार्य है कि वह स्पये की बाह्य

कीमत को एक निश्चित बिन्दु पर बनाये रखे । मुद्रा-कोष (I. M. F.) की स्थापना से पूर्व रिजर्व बैंक की निर्धारित रुपए की कीमत १ शिलिंग ६ पैंस के बराबर थी । सन् १९४७ से इस नियम में संशोधन किया गया है । ग्रब रिजर्व बैंक्क विदेशी विनिमय केवल उन दरों पर खरीद तथा बेच सकती है जिनको सरकार समय-समय पर निर्धारित करती है। पहले की भौति ग्रब एक निश्चित दर पर स्टर्लिंग का क्रय-विक्रय करना ग्रनिवार्य नहीं रहा है। मुद्रा-कोप द्वारा निश्चित दरों पर रिजर्व बैंक्क कोई भी विदेशी मुद्रा खरीद सकती है।

- (४) वैं ड्विंग कार्य रिजर्व बैङ्क सरकारों के निक्षेपों को स्वीकार करती है. परन्तु इन निक्षेपों पर ब्याज दिया जा सकता है। बैङ्क को विनिमय बिलों, प्रतिज्ञा-पत्रों मादि के क्रय-विक्रय तथा फिर से भुनाने का भी मधिकार है, परन्तु इसमें यह शर्त लगाई गई है कि ऐसे साख-पत्रों पर दो हस्ताक्षर होने चाहिए, जिनमें से एक किसी अनुसूचित अथवा राज्य सहकारी बैङ्क का हो और इनकी परिपक्कता अविध है। दिन से ग्रधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे कृषक बिलों पर जो कृषि के मौसमी व्यवसायों की वित्तीय व्यवस्था के लिए लिखे जाते हैं, परिपक्षता श्रवधि १५ महीने की रखी गई है। परन्तु रिजर्व बैंक द्वारा अपहरए। के लिए ऐसे विलों पर भी दो अच्छे हस्ताक्षर होने चाहिए, जिसमें से एक ग्रनुस्चित बैंक ग्रथवा राज्य सहकारी बैंक का होना चाहिए। बैंक को विदेशी विनिमय खरीदने और बेचने का भी अधिकार है और वह किसी भी ऐसे देश पर लिखे हुये विदेशी विनिमय बिल का भी क्रय-विक्रय कर सकती है जो ग्रन्त-. र्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का सदस्य हो । बेङ्क राज्यों, स्थानीय सरकारों, ग्रनुसूचित बैङ्कों तथा राज्य सहकारी बैंड्कों को ऋगा भी दे सकती है, यदि ऐसे ऋगा माँग पर तूरन्त शोध-नीय हैं अथवा ६० दिन के भीतर शोधनीय हैं और प्रसंविदित प्रतिभूति (Trustee Security), स्वर्ण अथवा चाँदी, स्वीकृत विषत्र तथा प्रतिज्ञा-पत्रों पर दिये गये हैं श्रथवा ग्रनुसूचित या राज्य सहकारी बैङ्कों द्वारा लिए गये हैं ग्रौर माल के ग्रविकार-पत्रों के रहन (Pledge) द्वारा स्रक्षित हैं। रिजर्व बैङ्क विदेशी केन्द्रीय बैङ्क के साथ एजेन्सी व्यवस्था भी कर सकती है।
- (५) बैड्कों की बैड्क-रिजर्व बैड्क का यह कर्तव्य है कि वह भारत में समुचित वैंकिंग प्रणाली को बनाये रखे। सन् १९४६ के विधान में उसे महत्त्वपूर्ण प्रधिकार दिये गये है। देश की बैंक-निधि का केन्द्रीयकरण करने तथा निक्षेपदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए यह निश्चित किया गया है कि सभी अनुज्ञापित बैंक अपने माँग दायित्वों का ५% तथा समय दायित्वों का २% रिजर्व बैंक में रखें। समय-समय पर प्रत्येक बैंक को रिजर्व बैंक के पास अनेक प्रकार की रिपोर्ट भेजनी पड़ती हैं और प्रत्येक सप्ताह अपनी लेन-देन का विस्तृत विवरण भी भेजना पड़ता है। रिजर्व बैंक किसी भी अनुज्ञापित बैंक के लेखों का निरोक्षण कर सकती है, यह बैंकों को ऋण दे सकती है, उन्हें उनकी ऋण नीति के सम्बन्ध में भादेश दे सकती है और

उनके अनुचित व्यवहारों को वीजत कर सकती है। इसके अतिरिक्त मनाकोत्रन-गृहीं की सेवाएँ उपलब्ध करके वह बैंकों के पारस्परिक भुगतानों को चुकाने में मुविधा देती है।

- (६) साख नियन्त्रएा—साख नियन्त्रए का उद्देश्य यह होता है कि साख की मात्रा का व्ययसायों की साख सम्बन्धी माँग के साथ समायोत्रन किया जाय। साख की मात्रा बहुघा बैंकों की ऋगा नीति पर निर्भर होती है। इस कारगा साख नियन्त्रण का अर्थ बेंकों की ऋगा नीति पर नियन्त्रण करने से होता है। रिजर्व बेंक इस कार्य के लिए बें ह दर के परिवर्तनों, खुले बाजार व्यवसाय तथा वैघानिक अधि-कारों का उपयोग करती है। साधाररात्या. रिजर्व वेंक को जनता के साथ सीधे-सीधे व्यवसाय काने का अधिकार नहीं है, परन्तु यदि केन्द्रीय मण्डल की कोई विशेष समिति ग्रयवा गवर्नर ऐसा अनुभव करता है कि विशेष परिस्थिति अथवा संकट का काल उत्तन्न हो गया है और वाि्एज्य तथा व्यापार के हितों की रक्षा के लिए साख पर नियन्त्रण रखना आवश्यक है तो अनुसूचित वैंक के हस्ताक्षर विना भी रिजर्व बैंक बिलों को भूनाने तथा खरीदने और बेचने का कार्य कर सकती है। साख नियन्त्रण की इस प्रभावशाली रीति का रिजर्व बैंक ने पूरा-पूरा लाभ उठाया है. परन्तु इस अधिकार की भी कुछ सीमायें हैं। भारतीय मुद्रा-बाजार के असंगठित तथा अविकसित होने के कारण यह नीति बहुत सफल नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक केवल कुछ विशेष प्रकार के ही साख-पत्रों का क्रय-विक्रय कर सकती है और क्यों कि ये साख-पत्र सरकारी होते हैं, इसलिए इनके सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता भी नहीं होती है। सरकार की साख नष्ट हो जाने के भय से उन्हें भारी मात्रा में नहीं बेचा जा सकता है।
- (७) कृषि वित्त व्यवस्था—रिजवं बेंक कृषि साख से सम्बन्धित सभी समस्याग्रों का ग्रध्यम करने के लिए विशेषज्ञों को रखती है। बेंक का एक पृथक विभाग ही ऐसा है जिसका कार्य कृषि वित्त की उन्नित ग्रौर सुविधाग्रों के लिए उपाय करना होता है। इसके ग्रातिरिक्त यह विभाग राज्य सरकारों तथा राज्य सहकारी बेंकों को सलाह भी देता है। श्रारम्भ में यह विभाग केवल रिपोर्ट प्रकाशित करता था ग्रौर कृषि साख के पुनर्संगठन के सम्बन्ध में ग्रन्य कोई भी कार्य नहीं करता था। पिछले तीन वर्षों से बेंक ने इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया है। सन् १६४६-५० की ग्रामीए। बेंकिंग जाँच समिति को सिफारिशों पर इसने देश भर में कृषि साख व्यवसाय की जांच का काम पूरा किया है।

## रिजर्व वैंक के वर्जित कार्य-

सन् १६३४ के रिजवं बेंक भ्रॉफ इण्डिया एक्ट के भ्रनुसार, जिसमें तत्पश्चात् संशोधन भी किये गये हैं, इस समय रिजवं बेंक को निम्न कार्यों के करने से विजत किया गया है:—

(१) कुछ निश्चित काल के लिए अपनी लेन को वसूल करने के लिए ही

रिजर्व बैंक व्यापार, वाििंग प्रथवा उद्योग में भाग ले सकती है, ग्रन्यथा सामान्य रूप में उसे इन कार्यों के करने से वींजत किया गया है।

- (२) वह किसी बैंक अथवा कम्पनी के अंश नहीं खरीद सकती है और ऐसे अंशों की आड़ पर ऋए। भी नहीं दे सकती है।
- (३) वह अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति पर ऋरण नहीं दे सकती है और प्रपत्ने व्यवसायिक कार्यालयों के निर्माण के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश से ऐसी सम्पत्ति प्राप्त भी नहीं कर सकती है।
- (४) वह उसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दे सकती है।
- (५) वह न तो ऐसे बिल लिख सकती है स्रौर न भुना सकती है जो माँग पर शोधनीय न हों।

स्मरण रहे कि रिजर्व बैंक के कार्यों की ये सीमार्थे इस कारण निश्चित की गई हैं कि एक श्रोर तो रिजर्व बैंक श्रन्य बैंकों से प्रतियोगिता न कर सके श्रौर दूसरी श्रीर बैंक का व्यवसायिक श्राधार हढ़ रहे।

# रिजर्व वैंक व्यवहार में (The Reserve Bank in Action)—

रिजर्व बेंक इस समय ग्रपने जीवन-काल का २५ वाँ वर्ष व्यतीत कर रही है भीर बहुत बार यह प्रश्न रखा जाता है कि क्या यह ग्रपने उद्देश में सफल रही है? रिजर्व बेंक के कार्यवाहन को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि दोषों के रहते हुए भी इस संस्था ने देश की भारी सेवा की है ग्रौर देश की मुद्रा तथा साख नीति को एक समुचित ग्राधार प्रदान किया है।

नोट के निर्गम का कार्य पूर्णतया सन्तोषजनक रहा है। बैंक ने सोने के सिक्कों तथा स्वर्णपाट की मात्रा कभी भी ४० करोड़ रुपये से कम कीमत की नहीं होने दी है, बिल्क सन् १६४८-४६ तक यह इससे अधिक रही है। इसी प्रकार रुपया प्रतिभूतियाँ भी कुल देयवन के है से अधिक नहीं रही हैं। केवल सन् १६४६ में इनसे सम्बन्धित नियम में संशोधन के पश्चात ही यह अनुपात घटा है।

नोट निर्गम के सम्बन्ध में सबसे बड़ा दोष यही रहा है कि दूसरे महायुद्ध के काल में उनकी मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सन् १६३८-३६ में २११ करोड़ रुपयों से बढ़ कर सन् १६४४-४६ में उनकी मात्रा १,१७६ करोड़ रुपया हो गई थी। यह परिस्थित रिजर्व बैंक की भूल के कारण उत्पन्न नहीं हुई थी, विल्क ब्रिटिश सरकार को उस नीति का परिगाम है जिसके अन्तर्गत उसने रिजर्व बैंक विधान की उस व्यवस्था से लाभ उठाया था जिसके अनुसार रिजर्व बैंक को स्टिलिङ्ग प्रतिभूतियों की आड़ पर नोट निर्गम का अधिकार दिया गया था। रिजर्व बैंक का दोष यही था कि उसने जनता को ब्रिटिश सरकार की इस नीति की यथासमय सूचना नहीं दी थी।

स्वतन्त्रता के उपरान्त मुद्रा-प्रसार का रोकने के लिए चलन में आए हुए नोटों की संख्या को आवश्यकतानुसार घटाने में भी रिजर्व वें हु असफन रही है।

सरकारी बें कर के दृष्टिकोए। से रिजव वें क ने जिस प्रकार कार्य किया है उसके प्रति भी सरकार अथवा जनता को कभी अनन्तोप प्रकट करने का अवसर नहीं मिला है। यही बात रिजव वें के द्वारा विदेशी विनिमय दर के स्थायित्व को बनाए रखने के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है।

रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी मालोचना इस सम्बन्ध में हुई है कि वह मन्य बैंकीं को फेल होने से बचाने में मसमर्थ रही है। मन्य वैंकीं की संरक्षण तथा ऋणों का मन्तिम सहारा होने के कारण रिजवं वैंक का यह कर्त्वय हो जाता है कि वह पाव-ध्यक सहायता देकर वैंकों के विलीयन की सम्भावना को कम करे। इस सम्बन्ध में रिजवं बैंक के श्रिष्ठकारियों का कहना है कि मिक्तांश दशाओं में फेन होने वाली संस्थाओं की बिगड़ती हुई दशा का उसे पता नहीं चलता था। भूतकाल में ऐसी बैंकों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने का उसे प्रषिकार न था और फेन होने वाली बहुत सी संस्थाओं की सम्पत्ति ब्रिटिश भारत के बाहर थी, जिसके कारण उन्हें सहा- यता नहीं दी जा सकती थी। परन्तु ये तर्क सारहीन हैं, क्योंकि एक भ्रोर तो भाव-ध्यकता पड़ने पर रिजवं बैंक सरकार द्वारा भावश्यक नियम बनवा सकती थी भीर दूसरी भीर सही सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए एक भ्रंश तक रिजवं बैंक स्वयं भी दोषी थी।

सन् १६४६ के बैंकिंग विद्यान ने निरीक्षण, जानकारी तथा नियन्त्रण के विस्तृत अधिकार रिजर्व बैंक को दिए हैं। इन अधिकारों का वर्णन एक पिछले अध्याय में किया जा चुका है। बिना रिजर्व बैंक की आज्ञा के कोई भी न्यायालय अब किसी बैंक के विलीयन की योजना स्वीकार नहीं कर सकता है। अब रिजर्व बैंक अन्य बैंकों का नियमित रूप से निरीक्षण करती है। इस सम्बन्ध में मार्च सन् १६५१ से एक विस्तृत योजना लागू की गई थी और सन् १६५२ के अन्त तक ही २५१ बैंकों का निरीक्षण समात कर दिया गया था। इस का ए स्थित में सुधार दृष्टिगोचर हो रहा है। 'भारत बैंक' तथा बङ्गाल की चार बैंकों को इबने से बचाकर रिजर्व बैंक ने प्रशंसनीय कार्य किया है। बैंकिंग प्रणाली के सुधार का कार्य दीर्घकालीन कार्य है, परन्तु समुचित निरीक्षण द्वारा इस दिशा में काफी उन्नित होती दिखाई पह रही है।

## रिजर्व बैंक श्रीर साख नियन्त्रण-

सन् १६४६ के विधान में सभी प्रकार का बका का एए एए प्रवास कर विधान में सभी प्रकार का बका का एए एए प्रवास कर दिया गया है और सन् १६५१ से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी बैंकिंग कम्पनियाँ अपने चालू तथा निश्चितकालीन देयधन (Demand and Time Liabilities) का २०% नकदी, स्वर्ण अयवा अन्य स्वीकृत प्रतिभृतियों में रखे। तत्पश्चात् संशोधनों द्वारा रिजर्व बैंक को अन्य बैंकों की कुछ छूटें देने का भी अधिकार दिया गया है। विधान में रिजर्व बैंक को विस्तृत अधि-

कार प्रदान किए गए हैं, परन्तु यह अधिक अच्छा होगा कि आवश्यकता पड़ने पर देय-धन के उपरोक्त प्रतिशत को तुरन्त बदला जा सके। रिजर्व बैंक को खुले बाजार में व्यवसाय करने का भी अधिकार दिया गया है, जो साख-नियन्त्रण का एक महत्त्वपूर्ण साधन है, परन्तु अभी तक इस अधिकार का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है। भार-तीय मुद्रा-बाजार की अविकसित तथा असंगठित प्रकृति और उन प्रतिभूतियों को सीमितता, जो कि रिजर्व बैंक द्वारा खरीदी और बेची जा सकती हैं, इस कार्य में भारी बाधा उत्पन्न करती हैं। इस दिशा में रिजर्व बैंक को आशानुकूल सफलता नहीं मिली है।

# भारत में बैंक दर—

ग्रारम्भ में बैंक दर नीति सफल न हो सकी थी, क्योंकि परिस्थितियों के कारण रिजर्व बैंक को ही बैंक दर ३% बनाए रखनी पड़ी थी। इस कारण इस साधन का लाभपूर्ण उपयोग न हो सका। वास्तविकता यह है कि बैंक की कमजोर ग्राथिक स्थिति तथा ग्रसंगठित मुद्रा बाजार के कारण शायद यह नीति बहुत लाभदायक हो भी नहीं सकती थी।

युद्धोत्तर-काल में सभी देशों में बैंक दर के परिवर्तनों की एक सामान्य लहर सी ग्राई थी। इस कारएा साख-संकूचन नीति के अन्तर्गत १५ नवम्बर सन् १९५१ को रिजर्व बैंक ने बैंक दर ३% से बढ़ा कर  $\frac{1}{2}$ % कर दी । मार्च सन् १९५७ में यह बढ़ा कर ४% कर दी गई है। बैंक दर को सप्रभाविक बनाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा व्या-पार बैंकों को वित्तीय सहायता देने की नीति में भी भारी परिवर्तन किया गया है। पहले यह रीति अपनाई जाती थी कि रिजर्व बैंक बाजार भाव पर अनुसूचित बैंकों तथा सहकारी बैंकों से ऋगा-पत्र म्रादि खरीद लिया करती थी। इससे इन बैंकों को सरलतापूर्वक तथा सस्ते ब्याज पर ऋगा मिल जाता था। इसके ग्रतिरिक्त कोई बैंक सरकारी ऋगा-पत्रों तथा अन्य स्वीकृत बिलों को भूना कर भी ऋग प्राप्त कर लेती थी, परन्तु इस प्रकार लिए जाने वाले ऋ ए। कम ही रहते थे। बैंक दर को बढाते ही रिजर्व बेंक ने यह घोषणा की कि वह बेंकों की सामयिक ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति के लिए ऋगु-पत्र नहीं खरीदेगी. परन्तू सरकारी तथा ग्रन्य स्वीकृत ऋगु पत्रीं पर बैंक, दर के अनुसार ऋगा देगी। सन् १९५० में अनुसूचित बैंकों तथा सहकारी बैंकों ने रिजर्व बैंक से क्रमकः १३% करोड़ रुपया तथा २% करोड़ रुपया उघार लिया था। सन् १९५१ में ये राशियाँ ७६३ करोड़ रुपया तथा ५३ करोड़ रुपया हो गई थीं श्रीर नीति में परिवर्तन करने से यह बढ़कर सन् १९५२ में १६% करोड़ रुपया तथा ३ करोड़ रुपया हो गई थीं। नीचे की तालिका द्वारा ऋ एा के अन्तिम सावन के रूप में रिज़र्व बैंक का महत्त्व स्पष्ट होता है :---

अनुस्चित तथा सहकारी वेंकों द्वारा प्राप्त ऋण (करोड कार्यों में )

वर्प	श्रनुसूचित वैंक	राज्य सहकारी बैक	योग	
38-239	२१•२६	₹° {\o }	२२.8८	
०४-३४३१	₹ 8 * 9 €	४•७३	38.08	
१९५०-५१	१४.३२	२•३०	१५*७१	
१६५१-५२	७६-५७	४.५६	द१'द६	
१९५२-५३	१६४ २५	3₺₽	१६७' <b>८१</b>	
१९५५-५६	<b>१</b> २३ <b>.००</b>	¥*00	२२८°००	

ऋरण देने के सम्बन्ध में रिजवं वेंक ने अपनी नीति में जो परिवर्तन किये हैं उनके तीन लाभ बताये जाते हैं:— (१) यह कहा जाता है कि इसमे वेंक दर की सप्रभाविकता बढ़ जाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात से मिलता है कि नीति का परिवर्तन होते ही इम्पीरियल बेंक ने तुरन्त अपनी सभी प्रकार की ब्याज की दरों में सामान्य रूप में है% की वृद्धि कर दी थी। (२) यह रीति ऐशी है कि मुद्रा की पूर्ति में लोच रहती है। व्यवस्त व्यवसायिक काल में पूर्ति बढ़ती है, परन्तु इस काल के पश्चात् ऋरण पत्र लौट आते हैं और इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति स्वयं ही घट जानी है। (३) इस रीति से रिजवं बेंक का अन्य वैंकों पर अच्छा नियन्त्रण स्यापित हो जाता है।

उपरोक्त परिवर्तन की कई हानियाँ भी हैं:—(१) समुचित फल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि खुले बाजार व्यवसाय की नीति को ग्रम रखा जाय, परन्तु इस रीति के कारण यह नीति गोपनीय नहीं रह पाती है। (२) पहले ऋण-पत्रों की कीमत में काफी स्थायित्व रहता था, क्योंकि रिजर्व बेंक उन का क्रय-विक्रय करती रहती थी, परन्तु इस नीति के फलस्वरूप इन पत्रों की कीमत गिरी है। नीति का परिवर्तन होते ही तीन सप्ताह के भीतर इन ऋण-पत्रों की कीमत में ५.३% की कमी हो गई थी। सरकारी ऋण-पत्रों की कीमत में ऐसा परिवर्तन उचित नहीं होता है। (३) यह रीति बेंकों के लिए मंहगी तथा कष्टदायक है। इससे वित्त की प्रगति तथा मद्रा-बाजार के विकास के मार्ग में बाघा पड़ती है।

जनवरी सन् १९५२ से रिजर्व बैंक ने हुण्डियों के क्रय-विक्रय की भी एक योजना चालू की थी। इस योजना के अनुसार रिजर्व बैंक ने अकेले सन् १९५२ में कुल मिलाकर ८७ ६५ करोड़ रुपये के ऋगा दिये थे, जिनमें से ८१ ५५ करोड़ रुपया अनु-सूचित बैंकों को दिया गया था और शेष ६ ५० करोड़ रुपया सहकारी बैंकों को। लम्बे काल से रिजर्व बैंक के विरुद्ध यह कड़ी आलोचना की जा रही थी कि वह देश में हुँडी बाजार का विकास नहीं कर रही थी। उपरोक्त कार्यवाही द्वारा शंघ ही यह भी दोष दूर हो जायगा। इस प्रगाली को लोकप्रिय बनाने तथा हुण्डी बाजार का शोघ्र विकास करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा इस योजना के भ्रनुसार अनुसूचित वैंकों को वैंक दर से कै कम दर पर ऋगा दिये जाते हैं। ऋगा को मुद्ती हुण्डी में बदलने के लिए जितने रुपये के मुद्राँक लगाये जाते हैं उनका भ्राधा व्यय स्त्रयं रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाता है।

जून सन् १६५४ से नवीन बिल योजना रिजर्व वैङ्क ने सभी अनुसूचित वैङ्कों पर लागू कर दी है। वर्तमान का में इस योजना के अन्तर्गत ऋरण प्राप्ति को न्यूनतम् रवम १० लाख रुपया रखी गई है और प्रत्येक ऐसे बिल की रकम जो रिजर्व वैङ्क से भुनवाया जो सकता है, १ लाख रुपये घटाकर ५० हजार रुपया कर दी गई है। योजना के कार्यवाहन का ग्यारहवाँ वर्ष आरम्भ हो गया है, क्योंकि यह जनवरी सन् १६५२ से चालू है। योजना की सफलता काफी रही है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायगा:—

# रिजर्व बैंक के श्रियम

(करोड़ रुपयो में)

वर्ष	सरकारी प्रतिभूतियों के ग्राधार पर	कुल का प्रतिशत	बिलों के ग्राधार पर	कुल का प्रतिशत	कुल
₹ <i>2</i> + 7 + 3	१६४	ξξ'⊏	52	₹₹•२	२४६
8843-48	३०	६६.३	६६	३३.७	\$39
१९५४-५५	१८६	५६•२	१४७	४३.च	₹ ₹
१९५५-५६	२६६	48.8	२२८	४४.६	880

यह निश्चय है कि श्रव रिजर्व बैंक बिलों के श्राघार पर श्रिषक ऋ एा दे रही है। इससे दो स्पष्ट लाभ हैं—प्रथम, रिजर्व बैंक को बैंकों को साख नीति को नियन्तित करने का श्रिषक श्रच्छा ग्रवसर मिल रहा है श्रीर दूसरे, रिजर्व बैंक के लिए यह श्रिष- कार सरल हो गया है कि व्यापार की ग्रावश्यकता के लिए श्रिषक साख का निर्माण कर सके।

देशी बेंकिंग प्रणाली पर नियन्त्रण रखने में भी रिजर्व बेंक स्रभी तक स्रयफल ही रही है। यह प्रयत्न काफी वर्षों से चल रहा है कि इस प्रणाली पर भी रिजर्व बेंक का ग्राधिपत्य स्थापित किया जाय। इस सम्बन्ध में रिजर्व बेंक वही सुविधाएँ देने को तैयार है जो साधारण अनुसूचित बेंकों को दी जाती हैं, परन्तु यह अनुरोध किया जाता है कि सहायता प्राप्त करने के लिए देशी बेंकरों को अपना व्यापार व्यवसाय छोड़ना पड़ेगा। यह धर्त किसी भी देशी बेंकर को मान्य नहीं है और अभी तक केवल ७ देशी बेंकिंग संस्थाएँ ही योजना में सम्मिलित हो पाई हैं।

## रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण—

सन् १६४८ के रिजर्व बैंक ( लोक स्वामित्त्व हस्तान्तररा ) नियम द्वारा रिजर्व

वैंक का राष्ट्रीयकररण हो गया है भीर अब यह एक सरकारी संस्था है। रिजबं वेंक की स्थापना से पूर्व ही यह वाद विवाद चला था कि क्या इन संस्था को एक सरकारी संस्था के रूप में स्थापित किया जाय, परन्तु इस नमय इने एक अंश्राधारियों की वेंक बनाना ही अधिक उपयुक्त समक्षा गया था। कालान्तर में इस व्यवस्था के पक्ष में दिये जाने वाले तकों का महत्त्व शेष नहीं रह पाया है। इस समय निम्न कारणों पर राष्ट्रीयकरण का समर्थन हुआ है:—

- (१) अन्य देशों की केन्द्रीय वैंकों के भी राष्ट्रीयकरण का तर्क युद्धोत्तर-काल में संसार के अनेकों देशों में केन्द्रीय वैंक का राष्ट्रीय-करण हो चुका है और यह एक विश्ववयानि प्रान्तेत्रन बन चुका है। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का भी यही आधार है।
- (२) युद्धकालीन अनुभव यही है कि उस काल में रिजर्व वैंक की स्वतन्त्रता की वास्तविकता खुल गई थी और वह एक नग्कारी विभाग की भांति कार्य कर रही थी। राष्ट्रीयकरण ने इस स्थिति को केवल वैद्यानिकता ही प्रदान की है।
- (३) रिजर्व वेंक के अंशों का केन्द्रीयकरए। होता जा रहा या और व्यक्तिक अधिकारों के दुरुपयोग का काफी भय था। सन् १९४६ के नियम ने तो रिजर्व वेंक को इतने विस्तृत अधिकार दे दिये हैं कि अब इमका निजी संस्था रहना अनुचित ही था।
- (४) आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए भी यह आवश्यक है कि सर-कार तथा रिजर्व बैंक का निकटतम् सम्वन्घ रहे। विना राष्ट्रीय गरण के इसकी आसा कम ही थी।

इसके विपरीत राष्ट्रीयकरएं के विरुद्ध भी भ्रतेक तर्क हैं—(१) यह कहा जा सकता है कि यह भारत सरकार की वर्तमान सामान्य भौद्योगिक नीति के विरुद्ध है। सन् १६४० में उद्योग राष्ट्रीयकरएं की जिस नीति की घोषणा की गई थो उसे सरकार बदल चुकी है भौर इसलिए केवल रिजर्व वैंक की ही राष्ट्रीयकरणं के लिए चुनना उचित नहीं कहा जा सकता है। ग्रांभिक नियोजन की पूरी मफनना के लिए तो समस्त बैंकिंग श्रणाली का राष्ट्रीयकरणं ग्रधिक उपयुक्त होगा। (२) राष्ट्रीयकरणं के कारणं भ्रव रिजर्व वेंक योग्य और अनुभवी व्यापारियों की सेवाभों के लाम से बंचित हैं, क्योंकि इसकी परिपदों के सभी सदस्य सरकार नामबद्द करती है और उननें कोई भी वित्त सम्बन्धी विशेष अनुभव प्राप्त गैर-सरकारी व्यक्ति नहीं है। (३) भ्रव यह भय काफी बढ़ गया है कि वेंक के संवालन पर राजनीतिक दलों तथा सरकार की वित्तीय नीति का अनुचित प्रभाव पड़ सकता है। इस समय रिजर्व वेंक पूर्णतया वित्त मन्त्रालय के हाथों में है, जो उसका किसी भी प्रकार उपयोग कर सकता है।

जैसा कि ऊपर भी बताया जा चुका है, १ जनवरी सन् १६४६ से रिन्वं बैंक

को सरकारी ग्रधिकार में ले लिया गया श्रीर इसके पुराने सभी ग्रंशधारियों को १०० रुपये के लिए ११८ रुपये १० श्राने मुश्रावजे के रूप में दे दिये गए हैं। मु.
की यह दर ग्रंशों की मार्च सन् १६४७ ग्रीर फरवरी सन् १६४८ के बीच के काल की ग्रीसत मासिक कीमत के बराबर रखी गई है। मुग्रावजे का एक भाग नकदी में चुकाया गया है ग्रीर शेष के लिए ३% ब्याज के प्रतिज्ञा-पत्र दे दिये गये हैं। राष्ट्रीयकररण के पश्चात् श्रब तक बहुत समय नहीं हो पाया है, जिसके कारण यह निर्णय किठन है कि इस व्यास्था द्वारा कितना लाभ हुग्रा है, परन्तु सरकारी ग्रधिकारियों का मत है कि इसके कारण रिजर्व बैंक की उपयोगिता तथा सप्रभाविकता बढ़ गई है।

ऐसा अनुभव किया गया है कि कृषि साख के सम्बन्ध में रिजवं बैंक समुचित सेवा नहीं कर पाई है। इन सम्बन्ध में एक ग्राम्य साख जाँच समिति नियुक्त की गई थी, जिसने मार्च सन् १६५६ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार कर ली है। १६ अप्रैल सन् १६५६ को वित्त मन्त्री ने एक बिल लोक-सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा रिजवं बैंक एक्ट सन् १६३४ में संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य एक राष्ट्रीय कृषक साख कोच (National Agricultural Credit 'Long Term Operations' Fund) स्थापित करना है। इस कोच का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जायगा—

- (१) राज्य सरकारों को सहकारी साख समितियों के ग्रंश खरीदने के लिए ऋरण दिये जायँगे, जिससे कि इन समितियों की ग्रंश पूँजी में वृद्धि की जा सके।
- (२) राज्य सहकारी बैङ्कों को मध्यकालीन ऋरण दिये जायँगे, जिनका वे कृषि वित्त की व्यवस्था करने के लिए उपयोग करेंगी।
- (३) केन्द्रीय भू-प्राधि बैङ्कों को दीर्घकालीन ऋ ए। श्रौर श्रिप्रम दिए जायेंगे।

विल में यह भी व्यवस्था की गई है कि एक ग्रौर भी कोष ग्रर्थात् राष्ट्रीय साख (स्थरता) कोष (National Agricultural Credit 'Stabilization' Fund) स्थापित किया जाय। इस कोष में जो घन रखा जायगा उसका उपयोग केवल मध्यकालीन ऋगों ग्रौर ग्रिग्रमों के प्रदान करने के लिए किया जायगा। ये ऋग राज्य सहकारी बैंड्रों को मिल सकेंगे ग्रौर इन बेंकों को यह ग्रधिकार होगा कि यदि ग्रकाल, बाढ़, सूखा तथा ग्रन्य प्राकृतिक ग्रापत्तियों के कारण मध्यकालीन वित्त की कमी पड़ती है तो वे ग्रपने ग्रल्पकालीन ऋगों को भी मध्यकालीन ऋगों में बदल लें। रिजर्व वैंक ग्रौर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष—

भारत ने मुद्रा-कोष की प्रारम्भिक सदस्यता प्राप्त की थी। मुद्रा-कोष के प्रादेश पर भारत ने रुपए का मूल्य स्वर्ण में द'४७५१२ ग्रेन के बराबर निर्घारित किया था, परन्तु सितम्बर सन् १९४६ में रुपए का अवसूल्यन किया गया और डालर ( अथवा स्वर्ण) में रुपए के मूल्य में ३०'५% की कमी कर दी गई है। मुद्रा-कोष की सदस्यता

से पहले रिजर्व वैङ्क स्टिलिङ्ग प्रतिभूतियाँ रखती थी भ्रौर विदेशी विनिमय के रूप में उसी का क्रय-विक्रय करती थी। अब रिजर्व बैङ्क मुद्रा-कोप के सभी सदस्य देशों की मुद्राभ्रों का क्रय-विक्रय कर सकती है। इन मुद्राभ्रों को वेचने की दर सरकार भपने मुद्रा-कोप सम्बन्धी दायित्त्वों को ध्यान में रखकर समय-समय पर निश्वित करती है। रिजर्व बैंक की लोन और देन—

निम्न तालिकाओं में रिजर्व बैङ्क की लेन और देन सम्बन्धी स्थिति दिखाई गई है। निर्गम और श्रिधकोषणा विभागों की ग्रलग-ग्रलग स्थिति निम्न प्रकार है —

तिर्रोम विभाग

				(क	रोड़ कार्यों में
वर्ष	नोट प्रचलन में	कुल नोट निर्गम	घातु	विदेशी प्रतिभूतियाँ	रुपया प्रतिभूतियां
35-2538	. १ <b>५२</b> *३६	२१०.६४	88.55	६६.६४	३२.१६
<b>१६४७–४</b> 5	१,२२७"४=	१,२७४:६४	४४:२२	१,१३५-२२	६२* ः४
<b>१६५१</b> —५२	१,१५६'५४	<b>१</b> ,२१७ <sup>.</sup> २२	80.05	६२५.१७	४८८ <sup>.</sup> ३ <b>६</b>
१६५३-५४	१,१३३ ६५	१,१५६'६७	४०:०२	५६४"०२	830.68
<b>१</b> ६५४–५५	१,१६६ १६	१,२१६ १=	80.05	६५४°५१	४२८'०६
१६५५-५६	3,388.38	१,३५६•४७	80.05	६५६•५२	५३३:२०
१६५६–५७	१,४७५-७७	१,४६४ ५२	४०" ५२	५४५ ६१	७५५.५२

## अधिकोषण विभाग

वर्ष	निक्षेप	ग्रन्य देन	नोट	विदेशों मे शेप	विनियोग
35-2538	३१:८४	१'२=	२८ ३८	8.58	€.3€
28-6838	५२०"४०	१४.४४	४७.५४	४०६°६५	न <b>१</b> .४३
,8e48-42	३३५-१५	१८ ६२	२७.६२	१८७"१४	६४.६०
१६५२-५३	२६५.०५	२३"६१	र्ड'०३	१६३ ५६	ee•3≓
8 <u>£</u> ¥३—4४	२३२"=0	१३'६१	२३•२२	१२३•२१	۲۶.۲ ت
8E48-44	२०१ २८	२३•६२	२३"२४	<b>८७</b> ,१३	20.85
१६५५-५६	१५२ २३	३५"५६	१७•२१	६६°१६	४६•३६
१६५६–५७	१४३•३८	१५-१३	१द-६१	६४•७७	५१:5२

## रिजर्व बैंक का महत्त्व-

सन् १६३५ में रिजर्व बैङ्क ने प्रपता कार्य धारम्भ किया था। ग्रव इस संस्था को काम करते हुए २५ वर्ष से भी ऊपर हो चुके हैं। ग्रव तक का कार्य काफी सराह-नीय रहा है। इस बैङ्क ने भारत की बैङ्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ भौर समृचित धाषाद प्रदान करने का प्रयत्न किया है। वैङ्क की सफलताओं की सूची काफी लम्बी है। वैङ्क के कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यों को निम्न प्रकार गिनवाया जा सकता है:—

- (१) सुलभ मुद्रा नीति-ग्रारम्भ से ही बैङ्क ने सुलभ मुद्रा नीति (Cheap Money Policy) अपनाई थी। बैङ्क दर को नीचा रखकर रिजर्व वैंक ने व्यापार, उद्योग ग्रीर कृषि सम्बन्धी वित्तीय ग्रावश्यकताग्रों की ग्रधिक से ग्रधिक पूर्ति करने का प्रयत्न किया है। नवम्बर सन् १९५१ तक बैंक दर ३% रही है, परन्तु उपरोक्त मास से वह बढ़ा कर ३५% कर दी गई है ग्रीर सन् १९५७ में ४%। भारतीय मुझाबाजार में ब्याज वी दरों को नीचे गिराने का प्रमुख श्रेय रिजर्व बैंक को ही है।
- (२) ब्याज की दरों में परिवर्तन रिजर्व बैंक ने देश में प्रचलित ब्याज की सामयिक दरों के उच्चावचनों को भी कम करने में सफलता प्राप्त की है। बैंकों की तत्कालीन ब्याज की पारस्परिक दरें साधारणतया है और है के ही बीच रही है।
- (३) विप्रेष सुविधाम्नों में वृद्धि विप्रेष सुविधाम्नों (Remittances Facilities) में भारी वृद्धि की गई है। इस समय ये दरें मुद्रा-बाजार की स्थिति को देखते हुए बहुत कम हैं। ५,००० रुपये तक यह दर  $\frac{9}{3}\%$  ( न्यूनतम् एक रुपया) म्रीर ५,००० रुपये से ऊपर  $\frac{9}{3}\%$  (१ रुपया ६ म्राने, नई मुद्रा १ रुपया ५६ नये पैसे) है।
- (४) सार्वजिनिक ऋगों का प्रबन्ध—लोक ऋगों के प्रबन्ध ग्रीर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सस्ते ऋगा प्रदान करने में बैंक ने ख्याति प्राप्त की है।
- ( ধু ) बैं किंग विधान का निर्मारण—बैंकिंग विधान के निर्माण में रिजरं बेंक का कार्य काफी सराहनीय रहा है।
- (६) बैंकों को आर्थिक सहायता—आर्थिक संकटों के काल में रिजर्व बैंक ने दूसरी बैंकों की काफी सहायता की है। कितनी ही बैंकों को केवल रिजर्व बैंक के ही ऋगों ने डूबने से बचाया है।
- (७) विनिमय दर में स्थिरता—देश की विनिमय दर की स्थिरता वनाये रखने का प्रमुख श्रेय इसी को है।
- (द) ग्रौद्योगिक वित्त-श्रौद्योगिक वित्त की उन्नति में भी ग्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल को रिजर्व बैंक से काफी सहायता मिली है।
- ( ६ ) कृषि ग्रर्थ-व्यवस्था—बैंक के कृषि साख विभाग के कार्य की सभी ने प्रशंसा की है।
- (१०) रिजर्व बैंक का खोज और अनुसन्वान विभाग बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य करता रहा है।
- (११) मुद्रा, साख व वैंकिंग पर उचित नियन्त्रग्।-विभिन्न ग्रधिकारों के द्वारा रिजर्व वैंक ने मुद्रा, साख ग्रोर वैंकिंग व्यवस्था पर श्रच्छा नियन्त्रण रखा है।

देश की वैंकिंग व्यवस्था के युद्धकालोन संचालन में रिजर्व वैंक का ऊँचा स्थान रहा है।

(१२) ग्राँकड़ों का संग्रह व प्रकाशन-ग्रांकड़ों के जमा करने ग्रौर उपयुक्त सलाह देने में रिजर्व बैंक का भारी महत्त्व है।

रिजर्व बेंक द्वारा मुद्रा पर नियन्त्र ॥—

केन्द्रिय बैंक होने के कारए। रिजर्व बैंक का यह कर्त्तव्य है कि मुद्रा और साख दोनों की निकासी पर समुचित नियन्त्रण रखे । मुद्रा के नियन्त्रण में माधाररात्या सिक्कों स्रौर पत्र-मुद्राका नियमन किया जाता है। कागत्र के नोटों की निकासी तो रिजर्ववैंक का ही एकाविकार है ग्रौर उनकी निकासी के सम्बन्ध में समृत्रित नियम भी बनाये जा चुके हैं, जिनका अध्ययन पिछले अध्यायों में किया जा चुका है। नोटों के निर्गमन के लिए रिजर्व बेंक का एक ग्रलग ही विभाग है। कागज के नोटों के पीछे रिजर्व बैंक सोने, सोने के सिक्कों, रूपये के सिक्कों, विदेशी मुद्राएँ, स्टॉलग प्रतिसूतियों, रुपयों की प्रतिभूतियों तथा सरकारी हुण्डियों की ग्राड़ रखतो है। इस ग्राड़ की मात्रा को घटा बढ़ाकर रिजर्व बेंक पत्र-मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कर सकती है। यदि रिजर्व बेंक पत्र-मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना चाहती है तो वह अपने अधि रोपग् विभाग में से रुपये की प्रतिभूतियाँ अथवा विदेशी प्रतिभूतियाँ अथवा दोनों निर्गम विभाग को हस्तान्तरित कर देती है श्रौर तब निर्गम विभाग हस्तान्तरित प्रतिभूतियों के मूल्य के बराबर पत्र-मुद्रा का निर्गमन कर देता है। इसके विपरीत यदि रिजर्व वेंक पत्र-मुद्राकी मात्राकम करना चाहर्ता है तो प्रतिभूतियों को निर्गम विभाग से ग्राधि-कोषरा विभाग को हस्तान्तरित कर िया जाता है और उनके मूल्य के बराबर पत्र-मुद्रा को रद्द कर देती है। इस सम्बन्ध में बहुधा यह कहा जाता है कि रिजर्व बें क मुद्रा पर नियन्त्रए। रखने में पर्यात ग्रंश तक सफल रही है, किन्तु वास्तविकता यह है कि यद्यपि म्रावश्यक मंत्रा तक चलन की मात्रा का विस्तार तो रिजर्व बैंक करती रही है. परन्तु देश में प्रचलित नोटों की मात्रा को घटाकर मुद्रा-प्रसार को दूर करने में वह पूर्णतया ग्रसफल रही है।

# रिजर्व बैंक द्वारा साख नियन्त्रण-

रिजर्व बेंक का यह एक महत्त्वयूर्ण कार्य है कि देश में साख की मात्रा पर नियन्त्रण रखे। इसके लिए रिजर्व बेंक वे सभी उपाय करती है जो प्रत्येक केन्द्रीय बेंक को करने पड़ते हैं। विधानानुसार यह अनिवार्य है कि प्रत्येक बेंक अपनी समय देन (Time Liabilities) का २% और माँग देन (Demand Liabilities) का ५% रिजर्व बेंक में जमा करे। इससे रिजर्व बेंक को बेंकों की जमा सम्बन्धी आवश्यक सूचना मिलती रहती है। साख नियन्त्रण की दिशा में रिजर्व बेंक के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:—

(१) नकद कोषों सम्बन्धी नियम—सन् १६४६ के वैंकिंग विवान के

अनुसार देश की प्रत्येक बैंक को अपने कुल निक्षेपों का २०% अपने पास नकदी, स्वर्ण अथवा स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। रिजर्व बैंक का यह कर्त्तं व्य है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि अन्य वैंक इस नियम का उलंघन न करें। यद्यपि, यदि आवश्यक हो, रिजर्व बैंक किसी भी बैंक को इस सम्बन्ध में छूट दे सकती है। इससे साख का निर्माण एक निश्चित सीमा के ही भीतर रहता है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि उत्पर बताया जा चुका है, प्रत्येक बैंक को अनिनो मांग तथा समय देन का क्रमशः ५ श्रौर २% रिजर्व बैंक में जमा करना होता है। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योय्य है कि रिजर्व बैंक को इन प्रतिशतों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। व्यवहार में इन व्यवस्थाओं से अधिक लाभ नहीं हो पाता है, क्योंकि सब कुछ होने पर बैंक के लिए साख निर्माण के लिए पर्याप्त सामग्रो रहती है।

- (२) बैंक दर—श्रन्य केन्द्रीय बैंकों की भाँति रिजर्व बैंक भी बिलों को फिर से भुनाने (Rediscounting) श्रीर श्रावश्यकता के काल में ग्रन्य बैंकों को ऋग देने का कार्य करती है। किन्तु भारत में रिजर्व बैंक की बैंक दर नीति बहुत सफल नहीं रही है, क्योंकि (i) श्रन्य बैंक रिजर्व बैंक से कम मात्रा में ही ऋग नेती हैं श्रीर (ii) स्वयं रिजर्व बैंक के साधन भी तथा (iii) वे प्रतिभूतियाँ जिनकी श्राह पर ऋग दिए जाते हैं, भी सीमित हैं। ग्रारम्भ में रिजर्व बैंक ने सुलभ मुद्रा नीति (Cheap Money Policy) ग्रपनाई थी। मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए सन् १६५१ से नीति में परिवर्तन किया गया है। सन् १६५१ से पहले बैंक दर ३% रहती थी। उस वर्ष उसे बढ़ाकर ३५% किया गया था श्रीर फरवरी सन् १६५७ में ४%। यहाँ पर यह कहना ग्रसंगत न होगा कि बैंक दर नीति को ग्रावश्यक सफलता नहीं मिली है।
- (३) खुले बाजार कियायों— खुले बाजार कियायों का अभिप्राय यह होता है कि केन्द्रीय बैंक जनता को सरकारी प्रतिभूतियों का क्रयः-विक्रय करने लगती है और उस पर से जनता के साथ प्रत्यक्ष व्यवसाय न करने का प्रतिवन्घ हटा लिया जाता है। रिजर्व बैंक के सम्बन्ध मे यह नीति भी बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं रही है। सन् १६५१ तक सदस्य बैंकों को यह अधिकार था कि वे आवश्यकता के समय रिजर्व बैंक को असीमित मात्रा में स्वीकृत प्रतिभूतियाँ बेच कर घन प्राप्त कर सकती थीं। सन् १६५१ से इस नीति में भी परिवर्तन किया गया है। अब रिजर्व बैंक केवन विशेष परिस्थितियों में ही इस प्रकार की प्रतिभूतियों को खरीदती है, अन्यथा स्वीकृत प्रतिभूतियों को खाइ पर बैंक दर के अनुसार ऋगा देने तक ही सीमित रहती है। नीति के परिवर्तन का यह परिणाम हुआ है कि (i) अब बैंक दर अधिक सप्रभाविक हो गई है, (ii) मुद्रा की पूर्ति में पहले से अधिक लोच आ गई है और (iii) साख नियन्त्रण की सप्रभाविकता बढ़ गई है। किन्तु इससे बैंकों की असुविधा बढ़ गई है।

(४) बिल बाजार योजना - देश में बिल बाजार का विकास करने के लिए सन् १६५२ मौर सन् १६५६ के बीच रिजर्व बैंक ने एक बिल बाजार योजना साम्न की थी। इस योजना और इसके परिगामों का सविस्तार वर्णन पीछे किया जा चुका है।

(५) अन्य उपाय — अन्य उपायों में रिजर्व वैंक के दृष्टिकोण से दो का महत्त्व अधिक है:—(१) प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action) और (२) साख का राशिनग (Rationing of Credit)। इन दिशाओं में सन् १६४६ के विधान ने रिजर्व वैंक को अधिकार दिए हैं। नये विधान के अनुसार रिजर्व वैंक अन्य वैंकों को किसी भी विशेष प्रकार की लेन देन से रोक सकती है। उसे वैंक के निरीक्षण का अधिकार है। वह किसी भी वैंक के व्यवसाय को कुछ काल के लिए स्थागित कर सकती है। उसे यह भी अधिकार है कि किसी वैंक के विलय अध्वा निस्तारण की सिफारिश करे। ये सब साख नियन्त्रण सम्बन्धी प्रत्यक्ष कार्यवाहियाँ हैं। माख राशिनग के अन्तर्गत रिजर्व वैंक वैंकों की नीति निर्धारत कर सकती है और उन्हें कुछ विशेष प्रकार के ऋणा देने यान देने के आदेश दे सकती है।

## रिजर्व वैंक की विफलताएँ—

इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि रिजर्व बैंक की सफलताओं की सूची काफी लम्बी है और इघर कुछ समय से इस सूची का विस्तार और भा बढ़ता जा रहा है, परन्तु कुछ दशाओं में इसका कार्य अभी सन्तोषजनक नहीं रह पाया है। वास्तिवकता यह है कि रिजर्व बैंक की सफलता बड़े अंश तक सरकार द्वारा यथासमय आवश्यक कार्यवाहियाँ कर देने पर निर्भर रही है। विफलता की प्रमुख दिशाएँ निर्मन प्रकार हैं:—

प्रथम, रिजर्व बेंक अभी तक भी देश की देशी बैंकिंग प्रसाली से ऐसा सप्रमाविक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाई है जिससे कि लाभदायक फल प्राप्त हो सकें।

दूसरे, यद्यपि रिजर्व वैंक ने यथासमय सहायता देकर कितनी ही वैंकों को फेंब होने से बचाया है, परन्तु यह धभी तक वैंकिंग संकटों को पूर्णतया दूर नहीं कर पाई है।

तीसरे, अभी तक भी रिजवं बैंक भारतीय सम्मिलित पूँजी बैंकों को विदेशी विनिमय व्यवसाय में उनका समुचित हिस्सा प्रदान नहीं कर पाई है। यद्यपि विदेशों में कुछ शाखाएँ खुली हैं और कुछ प्रगति भी हुई है।

चौथे, रिजर्व बेंक भारतीय चलन के ग्रान्तरिक मूल्य में स्थिरता स्थापित नहीं कर पाई है। भूतकाल में इसका कारण शायद यह रहा है कि विदेशी शासनकाल में रिजर्व बेंक को इतनी स्वतन्त्रता न थी। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इस दिशा में श्रिषक सफलता प्राप्त हुई है।

पाँचवें, रिजर्व बैंक देश में समुचित बिल-बाजार के विकास में असमर्थ ही रही है। सन् १९५४ से कुछ सुविभाएँ अवस्य बढ़ा दी गई हैं।

मु०च स्म० (३८)

छठे, भारतीय मुद्रा बाजार में प्रचलित ब्याज की दरों में भी बैंक की म्रनुरूपता स्थापित करने में कम सफलता मिली है।

### निष्कर्ष --

इन सब विफलताओं के रहते हुए भी इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि रिजवं बेंक की स्थापना ने देश में बित्तीय स्थिरता और बेंकिंग सुधार के एक नये युग का ब्रारम्भ किया है। इसने संकट के दो भयंकर कालों, अर्थात् द्वितीय महायुद्ध वःल तथा देश के विभाजन के समय देश की बेंकिंग प्रणाली की अनुपम सेवा की है। बेंक ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि ब्राधिक नियाजन और ग्राम्य वित्त के दृष्टिकोण से इसकी सेवाओं का भारी महत्त्व है। दूसरी योजना के काल में १,२०० करोड़ रुपए के हीनार्थ प्रबन्धन (Deficit Financing) और विदेशी विनिमय सम्बन्धी ग्राव- रुयकताओं के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर जो खिचाव पड़ेगा उसमें रिजवं बेंक की उपयोगिता और भी स्पष्ट हो जायगी।

रिजर्व बैंक श्रॉफ इन्डिया (संशोधन) एक्ट सन् १६४६ (Reserve Bank of India (Amendment) Act, 1956)—
नोट निर्गमन पद्धति में परिवर्तन—

द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के लिए श्रावश्यक धन-राश व्यवस्थित करते समय श्रायोजकों ने १,०००-१,२०० करोड़ रुपयों के हीनार्थ प्रवन्ध (Deficit Financing) का उल्लेख किया था। स्वभावतः रिजर्व बैंक ग्रांक इन्डिया पर दायित्व ग्रा गया कि वह उक्त राशि की व्यवस्था नोट निर्गमित करके करे और इस प्रकार जो साख प्रसार हो, उसके लिए भी उचित नियमन करे, श्रतः बैंक को इस दिशा में कुछ विशेषा- विकार सौंपने ग्रावश्यक हुए ग्रीर इसलिए रिजर्व बैंक ग्रॉफ इन्डिया एक्ट में संशोधन करने पड़े। संशोधन इस प्रकार हैं:—

- (१) बैंक अपने नोट-निर्गमन विभाग में विदेशी प्रतिभूतियाँ अब कम से कम ४०० करोड़ रुपए के मूल्य की रख सकेगी और यदि आवश्यक हुआ तो इसकी न्यूनातिन्यून राशि ३०० करोड़ रुपये भी की जा सकेगी। उस स्थित में केन्द्रीय तरकार बैंक से दण्ड स्वरूप कोई कर नहीं वसूल करेगी।
- (२) नोट-निर्गमन विभाग में सोना तथा सोने के सिक्के अब न्यूनातिन्यून ११५ करोड रुपए के मुल्य में रखे जा सकेंगे।

इस प्रकार बैंक द्वारा चलाए जाने वाले नोटों के लिए पत्र-मुद्रा कोष में भ्रव कम से कम ४०० करोड़ रूपए के मूल्य की विदेशी प्रतिभृतियाँ तथा ११५ करोड़ रूपए का सोना व सोने के सिक्के रखना भ्रनिवार्य होगा। कुल मिलाकर ५१५ करोड़ रूपए का न्यूनातिन्यून कोष नोट निर्गमन विभाग में रखा जा सकेगा।

स्मरए। रहे कि अब तक हमारे देश में पत्र-मुद्रा का चलन अनुपातिक निषि पद्धति (Proportional Reserve Method) के अनुसार, होता था, जिसके म्नन्तर्गत निर्गमित नोटों के कुल मूल्य का ४०० ते विदेशी प्रतिभूत्यों, सोना व सोने के सिक्कों में रखना श्रनिवार्य था तथा होप के लिए चांदी व चांदी के सिक्के व देशी बिल रखे जा सकते थे। इस संशोधन के द्वारा देश की श्रनुपातिक कोप प्रशाली को हटाकर उसके स्थान पर न्यूनातिन्यून कोप प्रशाली को श्रपना लिया गया है।

- (३) अब तक नोट-निर्गमन विभाग में रक्षित सोने का मूल्य १ रुपया = दार ४७५१२ ग्रेनस् (स्वर्ण) अर्थात् २१ रु० १३ आना १० पाई प्रति तोला की दर से लगाया जाता था। इस दर पर बेंक के पास अब ४० ००२ करोड़ रुपए के मूल्य का सोना था। संशोधन किया गया कि अब से बाद उक्त सोने का मूल्याङ्कन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित दर अर्थात् ३५ डालर प्रति औंस [१ रु० = २ प्टम प्रेनस् (स्वर्ण)] या ६२ रु० = आने प्रति तोले की दर से किया जायणा। इस दर पर बेंक के पत्र-मुद्रा कोष में स्थित सोने का मूल्य वर्तमान ४० ०२ करोड़ रुपए से बड़कर ११५ करोड़ रुपए हो गया।
- (४) रिजर्व बेंक को अविकार मिला है कि वह अनुसूचित वेंकों द्वारा उसके पास जमा की जाने वाली राशि में बढ़ोत्तरी कर सकेगी। अब तक सभी तालिकावद्ध बेंक अपनी-अपनी मांग-देनदारी का ५% और काल-देनदारी का २% रिजर्व बेंक के पास जमा रखती हैं। संशोधन के अनुसार रिजर्व बेंक अब तालिकावद्ध वेंकों से उनकी माँग देनदारी का ५% से २०% तक और काल देनदारी का २% से ५% तक राशि जमा ले सकती हैं।

इस प्रकार रिजर्व बेंक को तालिकाबद्ध वेंकों की साख नीति का समुचित नियमन करने का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया है।

(१) रिजर्व बैंक को यह भी श्रिषकार सौंप दिया गया है कि वह अपने राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घंकालीन कोष) में से सहकारी बैंकों को ऋण दे सकेगी, ताकि वे सहकारी बैंक उस राशि को छोटे तथा मध्यम कृषकों को उचार दे सकें और फिर वे उससे सहकारी संस्थाओं के श्रंश खरीद सकें।

इस प्रकार रिजर्व बेंक ग्रॉफ इन्डिया एक्ट में संशोधन करके देश की नोट-निगंमन पद्धित में ग्रामूल परिवर्तन कर दिया गया है। सोने के मूल्याङ्कन का ग्राधार बदल दिया गया है तथा बेंक को साख नियन्त्रण का एक विशेषाधिकार भी सौंप दिया गया है।

## रिजर्व बैंक और भारत की विदेशी विनिमय दर-

भारत की केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक को भारतीय रुपए की विदेशी विनिमय दर का भी प्रबन्ध करना पड़ता है। द अप्रैल सन् १६४७ तक रिजर्व बैंक का यह वैधानिक उत्तरदायित्व था कि वह निश्चित दरों पर, यदि प्रस्तुत किया जाता है, असीमित मात्रा में स्टिलिंग खरीदे और, यदि मांगा जाता है तो, स्टिलिंग बेचे कारण यह था कि भारत में स्टिलिंग विनिमय मान (Sterling Exchange

Standard) कार्यशील था थ्रौर भारतीय रुगये का केवल स्टलिङ्ग के माध्यम द्वारा ही अन्य चलनों से सम्बन्ध स्थापित होता था। मुद्रा-कोष (I. M. F.) की सदस्यता के पश्चात भारतीय रुगये का मुद्रा-कोष के सदस्य देशों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो गया है। विनिमय दरें मुद्रा-कोष द्वारा निश्चित की जाती हैं थ्रौर रिजर्व वैंक का यह कर्त्तंच्य है कि इन विनिमय दरों को बनाये रखे। निश्चित दरों पर रिजर्व वैंक विदेशी मुद्राग्रों को खरीद कर अथवा वेचकर विनिमय दरों के स्थायित्व को बनाये रखने का प्रयत्न करती है। इस समय विभिन्न देशों की मुद्राग्रों में भारतीय रुगये की विनिमय दरें निम्न प्रकार हैं:—

# भारतीय रुपये का मूल्य : विभिन्न देशों की मुद्राश्चों में—

		आ ग—
देश	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा
१. पाकिस्तान	१०० रु० ३५ न० पै०	१०० पाकिस्तानी <b>र</b> ०
ेर लंका	१०० रु० ४५ न० पै०	१०० लंका के रु०
	१०० रु० ३० न० पै०	१०० क्यात
- 8. अमेरिका	४७६ रु० ४१ न० पै०	१०० डालर
र्. कनांडा	४६० रु० ४ न० पै०	
्रद्{- म्लाया	१५६ रु० ५५ न० पै०	१०० डालर
<b>ं. हां</b> ग्कांग	दर ह० ६० न० पै०	१०० डालर
<b>-र्फ</b> , ब्रिटेन	१ ह०	१०० डालर
ं हैं. न्यूजीलैण्ड	१ रु०	१ शि० ५३२ पैंस
<b>४०. भास्ट्रे</b> लिया		१ शि० ५ <del>३ २</del> पैंस
११. दक्षिणी अफीका	१ <b>रु</b> ०	१ शि० १० वृह पेंस
श्रे. पूर्वी ग्रफीका	₹ <del>5</del> 0	१ शि० ५ ने हे पैंस
१३% मिस्र	ं ६७ रु० १३ न० पै०	१०० शि०
१४. फ्र <del>ांस</del>	१३ रु० म१ न० पै०	१ पौंड
	१०० रु०	१०२३ हैवी फ्रांक
१५८ बेलजियम	१०० रु०	१०४५ <sub>डें</sub> फांक
१६८ स्विटजरलैण्ड	१०० रु०	६०  इं फांक
क्रिं. पश्चिमो जर्मनी	१०० ₹०	प्रकृहें सार्क
१५% नीदरलैण्ड	१०० रु०	७६ व <mark>ह</mark> गिल्डर
१६. नारवे	\$00 £0	१४६ <u>३</u> ७ क्रोनर
२० स्वीडन	8-0 €0	१०५ <sub>५ ह</sub> क्रोनर
२१ डेनमार्क	१०० रु०	१४४ <del>६</del> डेनमार्क क्रोनर
र्द्रेर. इटबी	१०० रु०	१२६६२ <mark>ई</mark> लीरा
<b>२३. जापान</b>	<b>₹ ₹</b> 0	७४ ३ येन
	•	०५ ५ पन

२४. फिलिपाइन २३८ २० ७८ न० पै० १०० पीमो २४. ईर<sup>ा</sup>क १,३३८ २० १०० दीनार

(ये विनिमय दरें फरवरी सन् १६५६ में भारतीय रिजर्व बैंक के झनुमार हैं।)

सन् १६५७ में रिजर्व बैंक एक्ट में संशोधन—

तीन संशोधन महत्त्वपूर्ण है:—(१) रिजर्व बैंक ऐसी संस्थाओं की पूँजी में प्रिभिदान दे सकती है जो मध्यकालीन ऋ एग देंगी, (२) सन् १६४६ में जिन पत्र-मृद्राओं का विमुद्रीकरण किया गया था उनकी बिना भुनाई रागि के सम्बन्ध में रिजर्व बेंक की देनदारी समाप्त कर दी गई है, और (३) रिजर्व बेंक की घारा ४२ में संशो- धन किया गया है और बैंक की दूसरी सूची में कुछ नई संस्थायें शामिल की गई हैं।

#### QUESTIONS

- रिजर्व बैंक एक्ट पर श्रालोचनात्मक टिप्पणी दीजिए। सन् १६५६ के रिजर्व बैंक संशोधन एक्ट के क्या उद्देश्य हैं ? (Agra, B. A., 1917 Supp.)
- . रिजर्व बैंक के कार्यों पर प्रकाश डालिए। (Alta, B. A., 1957)
  - What part does the Reserve Bank of India play in the banking system of this country? How does it control currency and credit?

    (Agra, B. Com., 1956)
- भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की विवेचना कीजिए।
  - (Alld., B. A., 1956)
- 5. What is credit? How does the Reserve Bank of India control it. (Alld., B. A., 1954)
- How does the Reserve Bank of India control and regulate the supply of currency and credit.

(Raj., B. Com., 1957)

- 7. Describe the central banking functions of the Reserve Bank of India. How does it control the volume of currency and credit in the country and maintain the exchange value of the ruppe?

  (Agra, B. Com., 1955 Supp.)
  - How does the Reserve Bank of India control and regulate the supply of currency and credit? Indicate your answer in the light of the recent ordinance.

(Raj, B. Com., 1958)

9. Explain briefly the constitution and functions of the Reserve

Bank of India.	How does it exercise	control	over	currenc
and credit in the	e country ?	(Agra,	B. C	om•, 1954

10. Give a critical estimate of the working of the Reserve Bank of India during the last decade of its working.

(Raj., B. Com., 1955)

11. Write short notes on: Open Market Operations of the Reserve Bank of India. (Agra, B. Com., 1957)

Agricultural Credit Department of the Reserve Bank.

(Agra, B. Com., 1955)

Nationalisation of the Reserve Bank of India.

(Raj., B. Com., 1954) (Agra, B Com., 1954)

Rebate on Bills discounted.

12. Indicate the chief defects in the working of the Reserve Bank of India and suggest methods of over-coming them.

(Raj., B. Com., 1951)

## अध्याय ३५

# समाशोधन-गृह अथवा निकासी गृह

(The Clearing Houses) 4 3 2

श्चर्य-समाशोधन-गृह ऐसी संस्था अथवा संगठन है जी बेंकों को पारस्परिक मुगतान की

समाशोधन-गृह ऐसी संस्था अथवा संगठन है जो बेंकों को पानस्तरिक भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। टाउजिंग के शब्दों में— "समाशोधन-गृह किसी एक स्थान की बेंकों का एक सामान्य संगठन है, जिसका आधारमूत उद्देश्य घनादेशों द्वारा निर्मित पारस्परिक दायिस्वों का प्रतिसाद अथवा भुगतान करना होता है।" यह साधाररण-त्या एक महान् बेंद्ध होती है, जो विभिन्न बेंद्धों की लेन-देन का इस प्रकार हिसाब करती है कि पारस्परिक लेन-देन की चुकती कम से कम नकदी देकर केवल खातों में आवश्यक परिवर्तन करके ही की जा सके।

ऐतिहासिक दृष्टिकोरा से समाशोधन-गृहों का ग्रारम्भ सर्वप्रथम इङ्गलैंड में हुगा था क्योंकि उस देश में धनादेशों द्वारा भूगतान करने की प्रथा अधिक लम्बे काल से महत्त्वपूर्ण रही है। सबसे पहला समाशोधन-गृह लन्दन में सन् १७७५ ई० में स्थापित किया गया था। अमरीका में यह संस्था सर्वप्रथम सन् १८५३ में खोली गई थी और धनादेशों के उपयोग के बढ़ने के साथ-साथ इसका महत्त्व श्रीर विस्तार बराबर बढ़ते गये हैं। समाशोधन-गृहों की स्थापना देश की बैंड्डिंग प्राणाली की एक भारी कमी को परा करती है। घनादेशों के उपयोग की विस्तृत सामान्य प्रथा न होने के कारए। भारत में ऐसी संस्थाओं की ग्रावश्यकता काफी देर में ग्रनुभव हुई है. क्योंकि यहाँ वैद्धिग प्रगाली का विकास ही देर में हुन्ना है भीर धनादेश का उपयोग सभी तक भी बहुत कम है, परन्तु सन् १६२० में इम्पीरियल बैङ्क आँफ इण्डिया की स्थापना हुई, जिसने देश की मधिकीय प्रणाली को एक समुचित भाषार प्रदान कर दिया। कलकता बम्बई. दिल्ली और मद्रास में समाशोधन-गृह स्थापित हए, जो इम्बीरियल बैंड्स के निरीक्षण में कार्य करने लगे। सदस्य बैङ्कों का पारस्परिक भूगतान इम्पीरियल बैङ्क की स्थानीय शाखाओं पर लिखे हुए घनादेशों द्वारा होने लगा। रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात सन १६३५ से अनुस्चित बैंकों को रिजर्व बैंक में अपने खाते खोलने पड़े और उनका पारस्परिक भूगतान इन खातों पर लिखे हुए घनादेशों द्वारा होने लगा। साथ ही. रिजर्व बैंड्र को यह भी ग्रधिकार दिया गया कि वह समाशोधन गृहों के समृचित कार्य-

<sup>\*&</sup>quot;Clearing House is a general organisation of banks of a given place having for its main purpose the off-setting of cross obligations in the form of cheques."—Taussig.

वाहन के लिए नियम वनाये। रिजर्व बैंड्स इन ग्रहों की व्यवस्था करती है, यद्यपि उनके सम्बन्ध में समुचित विधान स्रभी तक भी नहीं बन पाया है। इस समय भारत में कुल २७ समाशोधन-ग्रह हैं।

# समाशोधन गृह की काये प्रणाली-

समाशोधन-गृहों के सदस्यों में बहुत सी वैंक होती हैं, जिन्हें समाशोधन वैंक (Clearing Banks) कहा जाता है। एक निश्चित समय पर प्रति दिन प्रत्येक सदस्य बैङ्क के लिपिक (Clerk) समाशोधन-गृह में एकत्रित होते हैं। समाशोधन-गृह में एक विशेष प्रकार के प्रपत्रों पर प्रत्येक सदस्य बैंक का प्रतिनिधि वैक विशेष की लेन-देन का हिसाब बनाता है। तैयार किये हुए प्रपन्नों को वहिंप स्त (Out Book) तथा उन्हें तैयार करने वाले लिपिकों को वहिर्शोधक (Out Clearers) कहा जाता है, परन्तु उपरोक्त प्रपत्रों के अतिरिक्त 'अन्तपु स्त' (In Book) भी होती है और उनसे सम्बन्धित अन्तर्शोधक (In Clearers) भी होते हैं। समाशोधन गृह के अन्य कर्मचारियों में संघावक (Runners) भी होते हैं। इनका कार्य प्रत्येक बेंक के छैंटे हुए घनादेशों को लाना तथा उनका वर्गीकरण करके यथास्थान रखना होता है। वहिर्पस्त तथा ग्रन्तर्पस्त की लिखाई के पश्चात् दोनों की तुलना करके प्रत्येक बैंक का लेन देन निकाली जाती है। इस लेन-देन का ब्योरा विशेष छपे हुए प्रपन्नों पर लिखा जाता है और इनमें सदस्य बैंक की समस्त लेन-देन को सविस्तार दिखाया जाता है। इस विस्तृत लेखे से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक बैंक को कितना लेना-देना है। भूगतान को विधि यही होती है कि जिस बैंक को देना है वह लेने वाली बैंक के नाम भ्रपने केन्द्रीय बैंक के समाशोधन-गृह पर देन राशि का धनादेश लिखती है और फल-स्वरूप सदस्य बैंकों के समाशोधन-गृह खातों में ग्रावश्यक समायोजन हो जाते हैं। इस प्रकार दिन के अन्त में प्रत्येक बैंक के समाशोधन-गृह लेखे की लेन-देन सन्तुलित हो जाती है और सदस्य बेंक में से एक-दूसरे पर कुछ भी शेष नहीं रहता है। समाशोबन-गृह एक बैंक से प्राप्त राशि दूसरे को चुकती दे देता है। वास्तविकता यह है कि समा-शोवन-गृह प्रणाली व्यक्तिगत व्यवहार के स्थान पर सामूहिक व्यवहार प्रणाली को प्रतिपादित करती है। नीचे की तालिका में यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि समाज्ञोधन-गृह किस प्रकार विभिन्न बेंकों की लेन-देन को छाँटता है :--

	_	, कुल दंन				
सदस्य बैङ्क	कुल देन	क	ख	ग	घ	
क	40,000	20,000	२४,०००	20,000	84,000	
ख	80,000	५,०००	१५,०००	8,000	३,०००	
ग	30,000	१५,०००	6,000	११,०००	8,000	
घ	२०,०००	8,000	१२,०००	9,000		
क्ल	8,80,000	88,000	£8,000	37,000	२२.०००	

इस तालिका से प्रत्येक सदस्य वेंक की लेन-देन साफ साफ ग्रनग-प्रत्य दिखाई पड़ बाती है।

## समाशोधन-गृह के लाभ-

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, समाशोधन-गृह बैकिंग प्रसाली की एक महान् श्रावश्यकता को पूरा करते हैं। उनके प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं:—

- (१) बैंकों के पारस्परिक भुगतान में सरलता—सभी सदस्य बैंकों की लेन-देन का भुगतान व्यक्तिगत रूप से न होकर सामुदायिक प्रथवा सामूहिक रूप में होता है, जिसके कारएं पारस्परिक भुगतान शीझतापूर्वक तथा सुविधाजनक रीति से हो जाते हैं। समाशोधन-गृह की सेवायों का लाभ केवल सदस्य बेंकों को ही नहीं, वरन् अन्य बैंकों को भी प्राप्त होता है। ऐसी दशा में सेवायें प्रदान करने के लिए गैर-सदस्य बेंकों से शुल्क लिया जाता है।
- (२) मुद्रा के उपयोग में मितव्ययिता—सभी सदस्य बेंकों के पारस्परिक दायित्वों का आपसी निबटारा होने के कारण एक बंक पर लिखे गए तथा दूसरी बेंक में जमा किए गए सभी चैकों का भुगतान नकदी में करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल लेन और देन के अन्तर का ही इस प्रकार भुगतान आवश्यक होता है। अन्तर का भुगतान भी बेंक विशेष की केन्द्रीय बेंक में जमा की हुई राशि पर घनादेश लिखकर किया जा सकता है। इस प्रकार नकदी के उपयोग में बचत होती है।
- . (३) नकद कोष कम रखने की सुविधा—समाशोधन-गृहों की स्थापना के कारण बैंकों को नकद कोष कम मात्रा में रखने पड़ते हैं और वे अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर सकती हैं। इस प्रकार इनके द्वारा देश के व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग की उन्नति होती है।

## भारतीय समाशोधन-गृह—

भारतीय समाशोधन-गृह स्वतन्त्र रूप में कार्य करते हैं और उनके नियम भी स्वतन्त्र हैं। सभी प्रकार की अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks) इनकी सदस्य होती हैं। नई सदस्यता प्रस्तुत सदस्यों के हु बहुमत से ही प्रदान की जाती है और इसे प्रदान करने से पूर्व प्रार्थी बैंक के स्थिति-विवरण की सावधानीपूर्व के और सविस्तार जाँच की जाती है। कुछ समाशोधन-गृहों की सदस्यता प्राप्त करने के लिए परिदत्त पूँ जी की एक न्यूनतम् सीमा भी रखी जाती है। कनकत्ते और बम्बई के समाशोधन-गृहों की सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रार्थी बैंक के पास कम से कम ५ लाख रूपये की परिदत्त पूँ जी होनी चाहिए। इससे कम पूँ जी वाली बैंक सदस्यों की सिफारिश पर केवल उप-सदस्य ही बनाई जा सकती हैं और उन ही गारन्टी उनकी सिफारिश करने वाले सदस्य को देनी पड़ती है। सिफारिश करने वाली बैंकों को प्रवेशक बैंक (Sponsorer Bank) कहा जाता है। भारत में विभिन्न स्थानों के समाशोधन-गृहों की सदस्यता सम्बन्धी नियमों में काफी अन्तर होते हैं।

समाञोधन-गृहों का प्रबन्ध व्यवस्थापक समितियों (Management Committees) द्वारा किया जाता है, जिसमें रिजर्व बेंक और स्टेट बेंक की स्थानीय शाखाओं का एक-एक प्रतिनिधि होता है और अन्य सदस्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि रहते हैं। इन गृहों का निरीक्षण रिजर्व बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा किया जाता है भीर प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार की निरीक्षक बैंक के पास एक निश्चित राशि जमा करनी पड़ती है, जिस पर घनादेश लिखकर पारस्परिक भुगतान चुकाये जाते हैं। जिन स्थानों पर समाशोधन-गृह नहीं हैं वहाँ उनका कार्य स्टेट बैंक करती है। ऐसे गृह कलकत्ते और बम्बई में काफी उन्नति कर चुके हैं। कलकत्ते में दो समाशोधन-गृह हैं—एक कलकत्ता समाशोधन बैंक संघ (Calcutta Clearing Banks Association) श्रौर दूसरा मेट्रोपोलिटन समाशोधन-गृह । प्रथम गृह केवल उन बड़ी-बड़ी बेंकों को ही पारस्परिक भुगतान सुविधायें प्रदान करता है जिनकी परिदत्त पूँजी १० लाख रुपया ग्रथवा उसके ऊपर है। दूसरा गृह सन् १९३६ से कायंशील है भीर उन बेंकों द्वारा खोला गया है जो श्रनुसूचित बेंक नहीं हैं। इसके ग्रतिरिक्त कलकत्ते में पिछले १०-१२ वर्षों से एक और भी समाशोधन प्रगाली प्रचलित है, जिसे हम अग्रगामी समाशोधन प्रणाली (Pioneer Clearing System) कहते हैं, जिसमें पारस्परिक भुगतानों को समकौतों द्वारा चुकाया जाता है। वास्तविकता यह है कि भारत में समाशोधन-गृहों की कार्य विधि में किसी प्रकार की ग्रनूरूपता नहीं है भौर उनके सम्बन्घ में कोई समुचित विधान भी नहीं है।

इस समय भारत में निम्न स्थानों पर समाशोधन-गृह स्थापित हो चुके हैं:— बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, ग्रहमदाबाद, ग्रमृतसर, कोयम्बदूर, कोभीकर, लखनऊ, बंगलौर, मदुरा, नागपुर, शिमला, पटना, इलाहाबाद, मंगलौर, जालन्बर, ग्रागरा, देहरादून, श्रप्रैला, राजकोट, गया, पूना, नई दिल्ली ग्रौर मुजफरपुर।

भारत के समाशोधन-गृह स्वतन्त्र रूप में कार्य करते हैं श्रौर उनके नियम भी स्वतन्त्र हैं। विनिमय बेंकों, श्रनुसूचित संयुक्त स्कन्य बेंकों को समाशोधन-गृहों की सदस्यता प्राप्त होती है। श्रन्य बेंक सदस्यों के हु बहुमत की सिफारिश पर सदस्य बनाई जा सकती है, यदि वह पूँजी सम्बन्धी नियमों को पूरा करती है। सदस्यता प्रदान करने से पहले प्रार्थी बेंक के स्थिति-विवरण की विशेषज्ञों द्वारा जांच करा की जाती है। पूँजी सम्बन्धी शतें श्रलग-श्रलग स्थानों पर अलग-श्रलग है। कलकत्ते और बम्बई के समाशोधन-गृह ५ या १० लाख रुपये की चुकती पूजी पर श्रनुरोध करते हैं। इससे कम पूँजी वाली बेंक सदस्य बेंकों की सिफारिश पर केवल उप-सदस्य बनाई जा सकती हैं।

#### प्रवन्ध-

प्रत्येक समानोधन-गृह का प्रबन्ध एक प्रबन्ध समिति करती है, जिसमें रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा का एक-एक सदस्य होता है श्रीर श्रन्य सदस्य बेकों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। नवीन सदस्यों के प्रवेश की आज्ञा यह प्रवन्ध समिति ही देती है। समाशोधन-गृहों का निरोक्षण रिजर्व बेंक करती है, यदि उसकी वहाँ शाखा है, प्रत्यथा यह कार्य स्टेट वेंक द्वारा किया जाता है। प्रत्येक सदस्य बेंक को समाशोधन गृह के संच लन के लिए निरोक्षक बेंक के पास एक निश्चित राशि जमा करती होती है, जिस पर समाशोधन-गृह के घनादेश आदि लिखकर भुगतान किया बाता है। जिन स्थानों पर समाशोधन-गृह नहीं है वहाँ पारस्परिक भुगतान स्टेट बेंक के माध्यम से घनादेशों द्वारा किया जाता है। समाशोधन-गृहों के लिए लिपिकों की पूर्ति स्टेट बेंक तथा रिजर्व वेंक द्वारा की जाती है।

## भारतीय समाशोधन-गृह प्रणाली के दोष-

यह कहना अनुचित न होगा कि भारत में अभी तक भी बैंकों की पारस्परिक क्षेत्र-देन के भुगतान को सुलभाने की व्यवस्था सन्तोपजनक नहीं है। इसके प्रमुख दोष निम्न प्रकार है:—

- (१) बाह्य धनादेश का भुगतान प्राप्त करने में कठिनाई—वर्तमान व्यवस्था में ऐसे भुगतान केवल स्थानीय घनादेशों के सम्बन्ध में निवटाये जा सकते हैं। बाहर के स्थानों के घनादेशों का भुगतान स्थानीय रूप में प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण अनावश्यक विलम्ब और व्यय होता है तथा इस प्रणाली में अमुविधा भी काफी रहती है।
- (२) समाशोधन-गृहों की कमी—ऐसे ग्रनेक बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्र हैं बहाँ पर काफी बैंकों के रहते हुए भी ग्रभी तक समाशोधन-गृह स्थापित नहीं हो पाये हैं। इससे व्यापारिक उन्नति में भारी बाबा पड़ती है।
- (३) नियमों में श्रन्तर—देश के विभिन्न स्थानों के समाशोधन-गृहों के नियमों तथा उनकी कार्य-प्रणालियों में भी भारी भ्रन्तर है, जिसके कारण बहुधा काफी उलभन उत्पन्न होती है।
- (४) सदस्यता के कड़े नियम—देश में समाशोधन-गृहों की सदस्यता के नियम बहुत कड़े हैं, जिसके कारण बहुत सी ग्रच्छी बैंकों को भी उन शी सदस्यता का भवसर नहीं मिल पाता है।
- (१) रिजर्व बैंक की उपेक्षा—हम यह भी कह सकते हैं कि समाशोधन-ग्रहों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने ग्रपने वैद्यानिक उत्तरदायित्व को भली-भाँति निभाने का प्रयत्न नहीं किया है। इस दिशा में ग्रभी बहुत कुछ करना शेष है।

#### QUESTIONS

1. What is a clearing house? Describe its mechanism and

## [ 80}

- operation and point out its advantage to the banker and the community. (Agra, B. Com., 1945)
- 2. Describe the working of the Clearing House System and point out its advantages. Will the growing popularity of the clearing house, other things being equal, lead to the expansion or contraction money? (Nag., B. Com., 1945)
- Write a note: —
   The Clearing House System.
   (Agra, B. A., 1955 & 1954;
   Raj., B, A., 1955; Raj., B. Com., 1955 & 1954;
   Sagar, B, A., 1958 & 1957)
- 4. नोट लिखिए—समाशोधन गृह (Clearing House)
  (Sagar, B. Com., 1957)

# अध्याय ३६ भारत में मिश्रित पूँजी वेंक

(Joint-Stock Banks in India)

## इतिहास-

भारत में व्यापारिक बैंकों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के समय देश में आधुनिक प्रकार की बैंकिंग संस्थायें नहीं थीं। सबसे पहले देश में कुछ एजेन्सी गृह स्थापित किए गए थे, जो देशी व्यापार के अर्थ-प्रवन्ध के साथ-साथ कुछ प्रकार के बैंकिंग कार्य भी करते थे। सन् १०३० के बाद पीरे-धीरे ये संस्थायें समाप्त हो गईं, क्योंकि इनका कार्यवाहन लगभग कभी भी सन्तोपजनक नहीं रहा था। एजेन्सी गृह साधारएतया कलकत्ता और उसके आस-पास खोले गये थे। सन् १७६२ में इनकी संख्या १६ थी, जो सन् १०३४ तक ५० हो गई थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी से व्यापार का एकाधिकार छिन जाने के पश्चात् इनकी आर्थिक दशा काफी खराब हो गई थी। सन् १०३० के पश्चात् कुछ व्यापारिक बैंक भी खुली थीं, परन्तु इनकी संख्या बहुत कम थी। व्यापारिक बैंक मिश्रित पूँजी ब्राधार पर खोली गई थीं, इसलिए व्यापारिक बैंकों का अध्ययन हम मिश्रित पूँजी बैंक शीर्षंक के ही अन्तर्गत करेंगे।

इस प्रकार की बैंकों के खुलने का ग्रारम्भ प्रेसीडेण्सी बैंकों के खुलने से हुमा। सन् १८०६ में 'बैंक ग्रॉफ बङ्गाल', सन् १८४० में 'बैंक ग्रॉफ वम्बई' ग्रौर सन् १८४३ में 'बैंक ग्रॉफ मद्रास' की स्थापना हुई। सन् १८२३ से इन प्रेसीडेन्सी बैंकों को पत्रमुद्रा नोट निकालने का ग्रधिकार दिया गया था, जो सन् १८६२ में समाप्त कर दिया। सन् १८६० के ग्रास-पास वास्तविक ग्रथ्य में भारत में मिश्रित पूँजी ग्राघार पर व्यापारिक बैंक खुलनी ग्रारम्भ हुई। सन् १८६३ में 'ग्रपर इण्डिया बैंक' तथा सन् १८६५ में 'इलाहाबाद बैंक' स्थापित हुईं। सन् १८६८ तक बैंकों की संख्या २५ तक पहुँच गई, परन्तु सन् १६०० तक बैंकिंग विकास की प्रगति घीमी रही। इसके कई कारण थे— प्रथम, ग्रमरीकन गृह युद्ध के कारण सट्टे बाजी को प्रोत्साहन मिला था ग्रौर बैंकों ने सट्टे बाजी में भाग लेकर ग्रपने व्यवसाय को चौपट कर लिया था। दूसरे, इस काल में विनिमय दर की घोर ग्रस्थिरता के कारण प्रगति में वाघा पड़ी थी। बहुत सी बैंक ठप्प हो गई थीं ग्रौर सन् १८६४ तक मिश्रित पूँजी बैंकों की संख्या घटकर केवल ६४ रह गई थी, परन्तु इसी काल में तीन बड़ी-बड़ी बैंक स्थापित हुईं — सन् १८५४ में 'एलायन्स बैंक', सन् १८६४ में 'ग्रवघ कॉर्माशियल बैंक' ग्रौर सन् १८६४ में 'पंजाब

नशनल बैक'। ये सब मिश्रित पूँजी बैंक थीं भ्रौर इनमें से 'भ्रवध कॉर्माशयल बैक' पूर्णतया भारतीय बैंक थी।

बीसवीं शताब्दी का आरम्भ होते ही बैंक तेजी के साथ खुलने लगीं। सन् १६०५ के स्वदेशी आन्दोलन ने तो भारतीय मिश्रित पूँजी बैंकों की स्थापना को बहुत ही प्रोत्साहन दिया और पश्चिमी-भारत, पंजाब और उत्तर-प्रदेश में तो बैंकों की बाढ़-सी आ गई। सन् १६०५ और सन् १६१३ के बीच ऐसी बैंकों के निक्षेपों में ११ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। प्रथम महायुद्ध का आरम्भ होते ही कितनी ही और बैंक खोली गईं, परन्तु अधिकांश बैंक युद्ध का आघात न सह सकीं और युद्ध का अन्त होने से पहले ही समाप्त हो गईं। सन् १६१३ और सन् १६१७ के बीच ही ६५ बैंक फेल हो गईं और युद्धोत्तरकालीन मन्दी ने तो हालत और भी खराब कर दी। सन् १६१७ और सन् १६२४ के बीच ६६ बैंक और बैंठ गईं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सन् १६१३ ३६ के बीच के काल में कुल मिलकर ४५१ बैंक फेल हो गईं थीं। सन् १६३६ में दूसरे महायुद्ध के आरम्भ ने बैंकों की स्थापना और पुरानी बैंकों द्वारा शाखा खोलने के क्रम को फिर प्रोत्साहन दिया, परन्तु युद्ध का अन्त होने पर देश के विभाजन के कारण पंजाब और बंगाल की बहुत सी बैंक ठप्प हो गईं।

मिश्रित पूँ जी (व्यापारिक) बैंकों के कार्य-

एक व्यापारिक बैंक एक साधारण बैंक के लगभग सभी प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करती है। इनके प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:—

- (१) निश्चितकालीन, चालू अथवा सर्विग बैंक निक्षेपों का स्वीकार करना। इन निक्षेपों पर साधारणतया ब्याज दिया जाता है।
- (२) देशी व्यापार से सम्बन्धित विनिमय बिलों का भुनाना, स्वीकार करना, खरोदना और बेचना।
- (३) देश के ग्रायात-निर्यात व्यापार के ग्रर्थ-प्रबन्ध में सहायता देना ।
- (४) ग्रंशों, समुचित प्रतिभूतियों, कृषि उपज श्रौर तैयार तथा ग्रर्द्ध तैयार माल की जमानत पर ऋरण देना ।
- ( ५ ) व्यक्तिगत जमानत तथा प्रतिज्ञा-पत्रों पर ऋ ए। देना ।
- (६) नकद साख तथा ऋधि-विकर्ष की सुविधाएँ प्रदान करना।
- (७) विप्रेषों का भेजना, धन का एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरस्य करना ग्रौर कमीशन के ग्राधार पर बहुमूल्य वस्तुग्रों का संरक्षस्य करना।
- ( ८ ) ग्राहकों के ग्रिभिकर्त्ता के रूप में कार्य करना ।
- (६) बैंकिंग व्यवसाय सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की सेवाएँ सम्पन्न करना।
- (१०) अपने ग्राहकों की ग्राधिक स्थिति का संदर्भ (Reference) देना और उसकी अन्य देंकों को गुप्त सूचना देना।

व्यापारिक वैंकों के प्रकार—

भारतीय व्यापारिक वैकों को चार भागों में वाँटा जा मकता है—(१) वे जिनकी पूँजी ग्रौर सुरक्षित कोष मिला कर ५०,००० रुपये ने कम है, (२) वे जिनकी पूँजी ग्रौर सुरक्षित कोष ५० हजार ग्रौर १ लाख रुपये के भीतर है, (३) वे जिनकी इस प्रकार की पूँजी १ लाख तथा ५ लाख रुपये के भीतर है ग्रौर (४) वे जिनकी पूँजी ५ लाख रुपये से उपर है। प्रथम प्रकार की वैंक सन् १६३६ से पहले स्थापित हुई थीं। नवीन कम्पनी एक्ट के अनुसार ग्रब ५०,००० रुपये से कम पूँजी वाली बैंक नहीं खोली जा सकती है। इनकी संख्या सन् १६४५ में १४४ थी, जो बराबर घट रही है। इनमें से ग्रियकाँश की ग्रायिक स्थिति भी इतनी कमजोर है कि उन्हें बैंक कहना उचित न होगा। ऐसी बैंकों को रिजर्व वैंक की भी सदस्यता प्राप्त नहीं है। सन् १६५४ में उनकी संख्या घट कर ६९ रह गई थी।

परिगिएत वैंक (Scheduled Banks) ग्रथवा ग्रनुमूचित वैंक ग्रौर ग्रपरिगिएत वैंक (Non-Scheduled Banks)—

देश की व्यापारिक बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रगा रहता है । नियन्त्रगा की सरलता के लिए ऐसी बेंकों को परिगिएत और अपरिगिएत वर्गों में बाँट दिया गया है। ऐसी वैंकों को जिनकी परिदत्त पूँजी श्रीर सुरक्षित कोप मिलाकर ५ लाख रुपया या इससे अधिक है, रिजर्व बैंक की दूसरी सूची (Second Schedule) में सम्मिलित कर दिया गया है भ्रौर इसी कारए। इन्हें परिगिए न वंक कहा जाता है। ऐसी बैकों को अपनी तत्कालीन देन (Demand Liability) का ५% और समय देन (Time Liability) का २% रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, जिसमें सन १९५६ में वृद्धि कर दी गई है। ऐसी बैंकों के लिए प्रति सप्ताह रिजर्व बैंक के पास रिपोर्ट भेजना ग्रावश्यक है। जमा की राशि में कमी हो जाने ग्रथवा समय पर रिपोर्ट न भेजने की दशा में रिजर्व बैंक इनसे जुर्माना वसूल करती है। इन प्रतिबन्बों के साथ-साथ रिजर्व बैक ने इन्हें कुछ विशेष सुविघाएँ दे रखी हैं। ग्रावश्यकता पडने पर ये समुचित प्रतिभूति देकर रिजर्व बैक से ऋ ए। प्राप्त कर सकती हैं अपवा भ्रपनी खरीदी और भुनाई हुई हुण्डियों को फिर से भुना सकती हैं। इसके भ्रतिरिक्त रिजर्व वैंक इनसे ऐसे प्रतिज्ञा-पत्रों ग्रीर विनिमय विलों को खरीद लेती है जिनकी परिपक्कता ग्रवधि ६० दिन से ग्रधिक नहीं है। रिजर्व बैंक ऐसी वैंकों के रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाने की भी सुविधा देती है।

उन बैंकों को भी जिन्हें रिजर्व बैंक की दूसरी सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता है, रिजर्व बैंक कुछ प्रवार की सुविधाएँ देती है। यदि कोई बैंक रिजर्व बैंक में कम से कम १० हजार रुपया जमा करके खाता खोलती है तो इसे अपरिगिणित बैंक कहा जाता है। ऐसी बैंकों को भी कुछ निर्धारित सुविधाएँ दी जाती हैं।

## ध्यापारिक वैंकों के ऋगा-

इन बैंकों के ऋए प्रदान करने की रीति सरल होती है। ऋए लेने वाले से एक प्रतिज्ञा-पत्र लिखवा लिया जाता है और समुचित जमानत लेकर ऋए दे दिया जाता है। नकदी में ऋए देने की प्रथा नहीं है, बिल्क ऋए की राशि के लिये ऋएी के नाम खाता खोल दिया जाता है, जिसमें से वह चैक द्वारा रुपया निकालता रहता है। चालू खाते के निक्षेपधारियों को अधि-विकर्ष की भी सुविधाएँ दी जाती हैं। ऋए की शोधनावधि साधारएतया कम रखी जाती है। व्यापारिक बैंक दीर्घकालीन ऋए वहुत ही कम देती हैं। अल्पकालीन ऋएों में तरलता अधिक होती है, व्याज की दर ऊँची रहती है और रुपया जल्दी-जल्दी वसूल होता रहता है, जिससे कि धन की कमी मालूम नहीं होती है। वैसे भी व्यापारिक बैंकों की अधिकांश जमा चालू खाते की जमा होती है, जिसके आधार पर अल्पकालीन ऋएों का दान देना ही अधिक उपयुक्त होता है।

जहाँ तक जमानतों का प्रश्न है, व्यापारिक बैंक तरल जमानत ही ग्रधिक पसन्द करती हैं। भूमि, मकान तथा अन्य अचल सम्पत्तियों की जमानत साधारए।तया अच्छी नहीं समभी जाती है। यह प्रसिद्ध है कि एक कुशल बैंकर वही है जो विनिमय बिल तथा प्राधि (Mortgage) का भेद स्पष्टता के साथ जानता है। बात यह है कि अचल सम्पत्ति को बेच कर घन प्राप्त करने में भारी कठिनाई होती है और यथासमय घन प्राप्त कर लेना कठिन होता है, जिससे बैंक के डूब जाने का भय रहता है। इसी कारए। वे प्रतिभूतियाँ पसन्द की जाती हैं जो तुरन्त बिक्री साध्य होती हैं।

भारतीय व्यापारिक बैंक सावधि जमा को प्राप्त करने का विशेष प्रयत्न करती हैं, जिसके लिए ऐसी जमा पर अधिक ब्याज दिया जाता है। चालू खाते में जमा रुपए पर साधारणतया या तो नाम-मात्र ब्याज दिया जाता है या बिना ब्याज की जमा स्वीकार की जाती है। विनियोग के दृष्टिकोण से सरकारी हुण्डियाँ अधिक पसन्द की जाती हैं, जिसका प्रमुख कारण बिल व्यवसाय की कमी है।

## भारत में व्यापारिक बैंकों के विकास की शिथिलता के कारएा—

भारत में बैंकिंग का विकास ग्रभी बहुत पीछे है। प्रत्येक २,७६,००० व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है, जबिक इङ्गलैण्ड में प्रत्येक ३,६०० श्रीर स्विटजरलैंन्ड में १,३३३ व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है। बेंकिंग विकास की इस घीमी प्रगति के कारण निम्न प्रकार हैं:—

- (१) भारत में बचत कम हो पाती है, क्योंकि लोगों की ग्राय कम है, परन्तु बचत को जमीन में गाढ़ कर रखने का रिवाज भी काफी ग्रिधिक है। परिगाम यह होता है कि बेंकों में कम रुपया जमा हो पाता है।
- (२) सन् १६०५ और सन् १६३६ के बीच बैंक नियमित रूप में भारी संस्था मे फेल हुई हैं, जिसने जनता के विक्वास पर गहरा स्राघात किया है।

- (३) घोमी प्रगति का एक कारण वैंकिंग शिक्षण का ग्रभाव है। इसके कारण लाभ कम होते हैं ग्रीर जनता के विश्वास में वैंकों के फेव होते रहने के कारण कमी ग्रा जाती है।
- (४) भारत सरकार ने वैंकिंग के प्रोत्साहन का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है।
- (५) भारत का विदेशी व्यापार ग्रिषिकतर विदेशियों के हाथ में रहा है, जिन्होंने भारतीय बेंकिंग के साथ श्रनुचित व्यवहार किया है ग्रीर उसके विकास में बाघा डाली है।
- (६) विदेशी विनिमय बैंकों ने, जो विदेशी संस्थाएँ हैं, भारतीय वेंकों के साथ देशी व्यापार, साधारण बैंकिंग तथा निक्षेप प्राप्ति में भी प्रतियोगिता की है, जिससे व्यवसाय की कमी रहती आई है।
- (७) बैंकिंग के प्रति जनता की उदासीनता रही है, जिसके कारएा प्रधिकाँग बैंकों के पास पूँजी की कभी रही है। इसी कभी के कारएा न तो बैंकिंग व्यवसाय लाभदायक ही रहा है और न उसमें कुशलता तथा संकटों के श्राघात सहने की शक्ति ही श्राई है।
- ( द ) व्यापारिक बैंकों का उद्देश्य ऊँचे लाभांश बाँट कर ग्रंशचारियों को सन्तुष्ट करना रहा है । इन्होंने सुरक्षित कोष जमा करके ग्रपनी स्थिति को टढ़ करने का प्रयत्न कम ही किया है।
- ( ६ ) ग्रँग्रेजी भाषा के उपयोग तथा पाश्चात्य लेखा-विघि के कारण देशी व्यवसायियों से बहुत निकट सम्बन्ध नहीं बन पाया है । यही कारण है कि देशी वैंकरों की भी प्रतियोगिता बराबर बनी रही है ।
- (१०) ग्रधिकांश दशाश्रों में ऊँचे पदों पर विदेशियों को रखने की प्रथा चलती ग्राई है। ये लोग न तो देशी व्यापारियों से निकट सम्बन्ध ही स्थापित कर सके हैं, न उनका विश्वास ही प्राप्त कर सके हैं।
- (११) इम्पीरियल वैंक की प्रतियोगिता ने ग्रन्य वैंकों को पनपने का मौका कम ही दिया है। यह दोष ग्रव स्टेट वैंक के निर्णाण ने दूर कर दिया है।
- (१२) पूर्व विकसित बिल बाजार के न होने के कारण वैकिंग के विकास में बाघा पड़ी है, क्योंकि सुरक्षित विनियोग के साघन कम रहे हैं।
- (१३) बैंकों की शाखाओं की कमी के कारण जोखिम का प्रादेशिक वितरण नहीं हो पाया है और जनता में बैंकिंग भ्रादत भी पैदा नहीं हो सकी है।
- (१४) वैधानिक प्रतिबन्ध कुछ इस प्रकार के रहे हैं कि बेंकों को घन वसूल करने में भारी कठिनाई रही है। ग्रचल सम्पत्ति की ग्राड़ पर ऋरण देने में तो फंफट बहुत ही रहता है। इसने ऋरण व्यवसाय के समुचित विकास में वाधा डाली है।

- (१५) भारतीय व्यापारिक बैंकों के जमानत सम्बन्धी नियम कड़े हैं, जिनके कारणा देशी बैंकर और साहूकार उनके व्यवसाय को छीनने में सफल हो जाते हैं।
- (१६) सरकारी सहायता की काफी कमी रही है। स्थार के सुभाव---

च्यापारिक बैंकों के दोषों को दूर करना आवश्यक है, जिससे कि बैंकिंग के समुचित विकास द्वारा देश की आर्थिक उन्नति सम्भव हो सके। सुधार के प्रमुख सुभाव निम्न प्रकार हैं:—

- (१) सरकारी नीति में परिवर्तन करने की भ्रावश्यकता है, जिससे कि सरकार वैकिंग के विकास को प्रोत्साहन दे सके।
- (२) पारस्परिक प्रतियोगिता को मिटाने के लिए बेंकों का ग्रिखल भारतीय संघ बनना चाहिए।
- (३) विदेशी विनिमय बैंकों की अनुसूचित कार्यवाहियों को रोकना चाहिए और उनका कार्य-क्षेत्र इस प्रकार निश्चित होना चाहिए कि वे व्यापारिक वैंकों के साथ प्रतियोगिता न कर सकें।
- (४) सहकारी बैंकों की भांति छोटी-छोटी बैंकों को भी श्राय-कर श्रौर मुद्रांक करों में छूट मिलनी चाहिए।
- ( ५) छोटे नगरों तथा ग्रामीरण क्षेत्रों में शाखा खोलने के लिए रिजर्व वैंक द्वारा सहायता मिलनी चाहिए।
- (६) बैंकों के प्रबन्ध ग्रौर उनकी कार्य-विधि में सुधार की भारी ग्राव-रयकता है।
  - (७) बैंकिंग सम्बन्धी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ।
- ( ८ ) भूमि बन्धक बैंकों, श्रौद्योगिक बैंकों श्रौर सहकारी बैंकों का विकास होना चाहिए श्रौर उनका व्यापारिक बैंकों से निकट का सम्बन्ध रहना चाहिए।
  - ( ६ ) ग्रंगे जी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाग्रों का उपयोग होना चाहिए।
- (१०) ऐसी संस्थाय्रों की स्थापना की भारी ग्रावश्यकता है जो वैंकों ग्रौर व्यापारिजों के सम्बन्ध में ग्रुप्त, परन्तु विश्वनीय सुचनाएँ एकत्रित करती रहें।
  - ( ११ ) हिसाब रखने की रीतियों में सुधार होना चाहिए।
- (१२) देशी बैंकरों तथा छोटी-छोटी बैंकों को मिला कर परिगिएत बैंकों में परिवर्तित कर देना चाहिए।
- (१३) संकट के समय सहायता देने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की नीति अधिक उदार होनी चाहिए।
  - (१४) स्टेट बेंक को प्रतियोगिता के स्थान पर सहायता और प्रोत्साहन की नीति अपनानी चाहिए। राष्ट्रीयकरण द्वारा इसकी सम्भावना बढ़ जाती है।

(१५) वें भ के ऋगा साधारगातया उत्पादक कार्यों के निए होने चाहिए ग्रौर जमानत सम्बन्धी नियम भी ग्रधिक उदार होने चाहिये।

#### वर्तमान स्थिति-

सन् १६५४-५५ में अनुस्चित बैंकों की कुल संख्या ८८ थी. जो सन १६५६-५७ में ८६ तक पहुँच गई थी। सन् १६५४-५५ के वर्ष में शालाओं की कुल संख्या २.०८७ तक पहुँच गई थी। योजना के अन्तर्गत लोक-क्षेत्र में व्यय की जो वृद्धि हुई है उसका बैंकों के साधनों पर भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडा है। सन् १६५७ में अनुमुचित बैंकों की संख्या ६१ थी, जो सन् १६५८ में ६३ हो गई थी। वास्तविकता यह है कि सन् १९५८ में ५ नई बैंकों को परिगिएत बैंकों की सची में सम्मिलित किया गया था, परन्त ३ बैंकों को सूची में से निकाल दिया गया था। इसी वर्ष में उनकी शासाओं की कूल वृद्धि २०५ थी, जिसमें ६६ शाखाएँ स्टेट बैंक की थीं। इस वर्ष में सभी अनुसूचित बेंकों की शाखाएँ कुल मिला कर ३,५७० तक पहुँच गई थीं। सन् १९५६-५७ में इन बैंकों की कुल जमा १,१४८ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी। इसके फलस्वरूप बैंकों की साख सुविधायों में ६६ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । सन् १९५ के वर्ष में बैंकों के जमाधन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। परिगिएत वैंकों की कुल शुद्ध जमा देन (Net deposit liability) में २०६ द करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। समय देन में २१४ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, किन्तु माँग देन में ७ २ करोड़ रुपये की कमी रही। २ वर्ष के काल में ही परिगिएत बैंकों की जमा में ४३% की वृद्धि हुई है ग्रौर समय देन में तो लगभग १००% वृद्धि हो गई है। यद्यपि साख के विस्तार का क्रम इस वर्ष भी चलता रहा, किन्तु उसकी वृद्धि केवल ८ ७ करोड़ रुपया थी। निम्न तालिका में अनुसूचित बेंकों की सन् १९५६-५७ तक की सम्पूर्ण स्थिति दिखाई गई है :---

ਕਥੰ

बेंकों की

संख्या

सभी अनुसूचित बैंकों की लेन और देन

कोष

कुल जमा

परिदत्त सूरक्षित

पँजी

			7// 4			भनग म	विनियोग
१९५०-५१	£\$	३५"५५	२६•६५	६२५१३	४६•७५	<b>55'</b> 97	३६४•५१
9 <b>2.</b> 9239	६२	३४•४५	२७•३३	६१८ ०६	४६•६२	६३.३३	786.84
१९५२-५३	83	३३•७१	२६•६५	८६१"८७	₹ १.3 €	द <b>६</b> °१७	385.88
१९५३-५४	32	३२•७५	२६•७२	१०५"५५	३६•६७	૭૪.૬૭	३२५°२०
१९५४-५५	55	३२*६६	२६•६९	०७:४३३	३८*८०	१००७३	३४६•६३
१९५५-५६	<b>५</b> ६	३२`द५	२६•७३	१,०७१"७३	४२•१३	१२•६३	३५२*५१
१६५६-५७	<u> جو</u>	33.5	२७.६६ १	,१४५,०७	83.68	६२.००	३६३•७२
	-						
المتعدد	محتنتهم مسم	The Control of the State of the		THE REPORT OF THE PARTY OF THE			SIX TO DESCRIPTION OF THE PARTY OF
वर्ष	ग्रन्य विनियोग	याचना राशि	ऋरण श्र ग्रग्रिम	ौर खरीदे बि	ग्रौर भुनार ाल	मे शुद्ध लाभ	कार्यालयों को संस्या
वर्ष 	1 1			हि 		•	
	विनियोग		श्रग्रिम	हि  ० ६!	ाल	लॉभ	की संख्या
१९५०-५१	विनियोग ४६ <b>'</b> ४०	राशि 	श्रप्रिम ४४०*४०	ि ० ६: ४ ७:	ाल  ५ <b>.</b> ०४	लॉभ ७ <b>°</b> ४३	की संख्या २,७६४
<b>१</b> ६५०-५१ १६५१-५२	विनियोग ४६ <b>'</b> ४० ४६ <b>'</b> ५० ४६ <b>'</b> ३०	राशि 	श्रमि ४४०'४। ४४५'११	हि ० ६' ४ ७ ० ६	ाल ५ <b>*</b> ०४ ३ <b>*</b> ७७	लॉभ ७*४३ द*६५	की संख्या २,७६५ २,६४६
<b>१</b> ६५०-५१ १६५१-५२ १६५२ ५३	विनियोग ४६ '४० ४६ '५८ ४६ '३० ४७ '६६	राशि  	श्रमि ४४०'४१ ४४५'११ ४७४'०४	ि ० ६' ४ ७ ० ६' ० द	ाल ५ <b>.</b> ०४ ३.७७ ०.७७	लॉम ७*४३ ८*६४ ७•२६	की संख्या २,७६४ २,६४६ २,६४६

जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, सन् १६५ में परिगणित बेंकों द्वारा साख का निर्माण नाम-मात्र ही रहा है। श्रायातों पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों तथा रिजब बेंक की साख संकुचन नीति के कारण ऋणों की माँग ही कम रही है। यही कारण है कि बेंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में श्रधिक धन लगाना पड़ा है। ऐसे विनियोगों में २०४ शकरोड़ रुपये, श्रर्थात् ४७% की वृद्धि हुई है। इस काल में बेंकों के साधनों में भी दृढ़ता ग्राई है और उन्होंने रिजर्व बेंक से पहले की तुलना में कम ऋण लिए हैं। निम्न तालिका में सन् १६५६, ५७ और ५० की स्थित दिखाई गई है:

53°3

7.888

१९५६-५७ ५५.६४ १४.३६ ६४०.६० १,७६.४१

	१९५६	9838	१९५५	विस्थ	<b>गरिवर्तम</b>
	के श्रन्त में	के श्रन्त में	के प्रन्त में	१९५७ में	१९५व में
मृत देन	६०.००४.४	કુમું અફ દ , ફ	३८.४०४.१	7६६,७य	+ 305.0c
माग देन	9%.EX3	७०१.वर	\$ \$ \$ \$ \$ \$		
समय देन	४५७.१८	S 3. X 3. S	८५ <mark>.</mark> ५५	+ २०५.४३	+ 283.84
वैंकों के पारस्परिक ऋसा	<b>११</b> " ५७	34.8%	हें <b>१</b> हें हैं		
रिजर्व वैंक से ऋसा	୬୦.ଅର	8.8.8 8.8.8.8	80°08	हेर. ४४ —	
स्टेट बेंक से ऋसा	ჭე <b>.</b> ე	୭୭.୬	<b>አ</b> ድ. ୭	33.0	
रिजर्ब बैंक के पास नकद शेष	हर.०३	<b>३ ५.</b> ๑० <b>३</b>	888.88	+ 88.84	23.88 -
सरकारी हण्डियों में विनियोग	88.838	E2.2E2	୭୪.୭୫३	+ 84.88	
वेंक साख	<b>७</b> ५५ - ४३	0 % O % S	नह्भु '७व	64.60	

गेर अनुसूचित वैक (Non-Scheduled Banks)-

गैर श्रनुसूचित वैकों में ऐसी सभी वैकों को धामिल किया जाता है जिनकी पश्दिस पूँजी (Paid-up Capital) श्रीर मुरिशत कोप मिलकर थूं लाख रुपये से कम होते हैं। ऐसी वैकों को चार वर्गों में बाँटा जाता है— (१) ऐसी वैक जिनको परिस्त पूँजी तथा मुरक्षित कोप मिलकर थे लाख रुपये से श्रधिक होते हैं, किंसु जिन्हें अन्य कारगों से अनुस्नित वैकों में शामिल नहीं किया जाता है। (२) ऐसी बेकों की कुल संख्या सन् १९५६-५७ में ३३४ थी श्रीर कुल जमा ७३'७५ करोड़ स्पया। गैर अनुमूचित बेकों की संख्या निगत वर्षी में ऐसी बेंक जिनकी परिदत्त पूँजी शौर सुरक्षित निधि मिलकर १ शौर ४ जाख रूपये के भीनर है। (३) ऐसी बेक जिनकी परिदत्त पूँजी श्रीर निधि ५० हजार श्रीर १ लाख रुपये के भीतर है श्रीर (४) ऐमी बैक जिनकी पन्दित पूँजी श्रीर निधि ५० हजार म्पये से कम है।

बराबर घटी है, यद्यपि जमा में कोई विशेष कमी नहीं हुई है। सन् १९५१ ग्रौर सन् १९५८ के बीच इनकी संख्या १,४७३ से घटकर ९१४ रह गई है। निम्न तालिका सम्पूर्ण स्थिति को दिखाती है:—

गैर-अनुसूचित बैंकों की लेन और देन

(करोड़ रुपयों में) परिदत्त पूँजी सुरक्षित वैंकों की मुंख्या वर्ष नकदी नकदी कुल जमा कोष हाथ में वैंकों में **१**६५०-५१ 288 १०"२६ 3.88 ७३•६७ ६•दद ४'६८ 9849-42 ४७४ 38.3 ३.६ ट 33.37 ७.७४ ३.४४ 82-5X38 880 38.3 8.53 ७२.७स ६"२८ ३•५६ 8EX3-X8 ४३२ 00'3 ४•६५ ६३"५४ ६•१४ 3.63 **१**६५४-५५ ४१० দ\*দ০ ४•५१ ६६"५३ ६•१७ 8.83 १६५५-५६ ३६६ **द**'११ ४°६७ \$\$°0€ ६"४८ 30" € १६५६-५७ 238 ७.६४ 8.88 प्रथ•इंश ६•६० ३४४६

वर्ष	सरकारी हुण्डियों में विनियोग	श्रन्य विनियोग	ऋगा तथा ग्रग्रिम	बिल स्रपहरण	शुद्ध लाभ	कार्यालयों की संख्या
११४०-५१	<i>₹</i> 8.88	8.80	४४ •७७	१ द७	<del></del>	१,५४५
१६५१-५२	३२•७६	३•५३	४१•७६	१•६६	<del>, ,</del> <del>, ,</del>	१,४६६
१६५२-५३	२०१६७	3.48	४२:०१	१•६ द	५२	१,३३o
१६५३-५४	३०"४६	४.६४	४१"६०	१ ६४	<b>?</b> `\ & ?	१,२६२ १,२६२
१९५४-५५	२१•६६	33'8	४० ७१	१ <sup>५</sup> ६५	५२ ६२	339,8
१९५५-५६	२५.५४	१•६१	३७. ३२	30.8	4 7 5 3	-
१६५६-५७	२४.६७	६.५८	३६•५२	२.७२	५२ ७१	१,१४२ १,१०१

## व्यापार बैंकों का भविष्य-

इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि भारतीय व्यापारिक बैंकों के कार्यवाहन में अनेक त्रुटियाँ हैं और सुघार की आवश्यकता तथा गुंजायश भी बहुत काफी है, परन्तु विगत वर्षों में सुघार के अनेक प्रयत्न हुए हैं। श्राशा यही है कि भविष्य में वैकिंग का आघार अधिक हढ़ हो सकेगा। इस सम्बन्ध में प्रमुख सुघार निम्न प्रकार रहे हैं:—

(१) सन् १६३६ के कम्पनी एक्ट के अनुसार कोई भी बैंक बिना ५०,००० रुपये की पूँजी के नहीं खोली जा सकती है।

- (२) सन् १६४६ के विघान के अनुसार कोई वैंक गैर वैकिंग कार्य नहीं कर सकती है।
- (३) नये विधान के अनुसार रिजर्व वैंक से आज्ञा प्राप्त किये विना कोई वैंक न तो कई शाखा खोल सकती है और न अपने कार्य का कुछ विशेष दशाओं में विस्तार ही कर सकती है । प्रत्येक वैंक को अपने कार्य-संचालन के लिए रिजर्व वैंक से अनुजापन प्राप्त करना होता है ।
- (४) रिजर्व वैंक की नीति भ्रव अधिक उदार तथा सहानुस्तिपूर्ग है भीर वह समय पर सहायता देने में संकोच नहीं करती है।
- (१) दूसरे महायुद्ध का वैंकों की आर्थिक स्थिति नथा जमा गिंश पर ग्रच्छा प्रभाव पड़ा है।
- (६) सभी वैंकों को अपनी देन का एक निश्चित भाग रिजर्व वैंक में रखना पड़ता है। इससे आदेयों की तरलता बनी रहती है और जनता का विश्वास भी बना रहता है।

#### **QUESTIONS**

- 1. What are the main points of difference between a joint-stock bank and cooperative bank. (Agra, B. Com., 1957)
- 2. Discuss briefly the functions of commercial banks. How far Indian Commercial Banks perform these functions?
  (Raj., B. A., 1957)
- 3. Examine the case for the nationalisation of commercial banking in India. (Raj., B. Com., 1957)
- 4. Examine the recent trends in the organisation, capital structure and investment of Indian Joint-stock banks.
  - (Raj., B. Com., 1952)
- 5. Discuss the functions performed by joint-stock banks in India. Do you agree that the joint-stock banks in India are conservative in their dealings? If so, what suggestions would you offer to make them useful to trade and industry? (Agra, B. Com., 1950)

## श्रध्याय ३७

# इम्पीरियल बैंक एवं स्टेट बेंक ऑफ इगिडया

(The Imperial Bank and The State Bank of India)

इम्पीरियल बैंक का प्रारम्भ-

इम्पीरियल बैंक श्रॉफ इन्डिया एक्ट सन् १६२० के श्रनुसार तीनों प्रेसीडेन्सी बैंक का विलय करके इम्पीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। इस बैंक की श्रिधकृत पूँजी ११'२५ करोड़ रुपया रखी गई थी, जिसमें से श्राधी पूँजी परिदत्त पूँजी थी श्रौर शेष श्रंशधारियों के निधि देयधन (Reserve Liability) के रूप में थी। इस बैंक का सुरक्षित कोष (Reserve Fund) ६'३३ करोड़ रुपया था श्रौर इसका लाभांश १% से ऊपर रहता था। वर्तमान स्टेट बैंक का पुराना नाम इम्पीरियल बैंक ग्रॉफ इण्डिया ही था।

सन् १६२० के नियम के अनुसार इस संस्था का प्रबन्ध एक केन्द्रीय गवर्नर मण्डल तथा कलकत्ता, बम्बई श्रीर मद्रास के तीन स्थानीय मण्डलों द्वारा किया जाता था। दो संचालक गवर्नर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे श्रौर चलन नियन्त्रक (Controller of Currency) भी अपने पदाधिकार द्वारा इसका सदस्य होता था। सरकार को यह भी अधिकार था कि वह ऐसे सभी मामलों में इम्पीरियल वैंक को ग्रादेश दे जो कि सरकार की वित्तीय नीति तथा सरकारी कोषों की सुरक्षा पर प्रभाव जालते हों। इस प्रकार आरम्भ में इम्पीरियल बैंक का दोहरा कार्य था। देश की केन्द्रीय बैंक के रूप में यह सरकारी शेषों का संरक्षण करती थी, देश के लोक ऋण का प्रबन्ध करती थी, बैंकों की बैंक का कार्य करती थी, समाशोधन-गृहों का प्रबन्ध करती थी, कोषों का एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरए। करती थी ग्रीर ग्रपने लन्दन कार्यालय द्वारा भारत सरकार के लिए अन्य बैंड्डिंग सेवाएँ प्रसादित करती थी। एक साधारए। ग्रंशधारियों की बैंक के रूप में यह व्यापार बैंकों के सभी कार्यों को भी सम्पन्न करती थी, परन्तु ऋगा देने के सम्बन्ध में स्वीकृत प्रतिभृति सम्बन्धी कुछ प्रति-बन्घ लगाये गये थे। भूमि. बांघों तथा विदेशी विनिमय के व्यवसाय इसके लिए वर्जित थे। ग्रारम्भ में इसे यह भी ग्रादेश दिया गया था कि देश में बैंकिंग सुविधाओं के विकास के लिए यह कम से कम १०० नई शाखाएँ खोले।

इम्पोरियल बैंक की इन व्यवस्थाग्रों की काफी ग्रालोचनाएँ की गई हैं। केन्द्रीय बैंक के रूप में इसका कार्य सदा ही दोषपूर्ण रहा है। स्थापना के समय इसका सारा प्रबन्ध योरोपियनों के हाथ में था, जो साधारणतया भारत विरोधी भावनाएँ रखते थे और संकट काल में भारतीय वैंकों को किसी प्रकार की सहायता नहीं देते थे। भारतीयों के शिक्षण के लिए भी यह किसी प्रकार की सुविधाएँ नहीं देती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इसने अपनी नई शाखाएँ ऐसे स्थानों पर खोली थीं जहाँ पर पहले से अन्य वैंकों की शाखाएँ मौजूद थीं और इस प्रकार वैंकिंग नेवाओं के विस्तार के स्थान पर भारतीय वैंकों से प्रतियोगिता करने का प्रयत्न किया था।

रिजर्व बैंक की स्थापना पर सन् १६३४ के इम्बीरियल वैंक आंक इण्डिया (संशोधन) एक्ट द्वारा इस बैंक के केन्द्रीय वैंकिंग कार्यों को समान कर दिया गया और इसके दूसरे कार्यों पर से प्रतिवन्ध हटा लिये गये। प्रवन्ध पर से सरकारी नियन्त्रण हटा लिया गया था, परन्तु फिर भी सरकार को केन्द्रीय मण्डल में दो गवर्नर नामजद करने का अधिकार था।

इम्पीरियल वैंक का रिजर्व वैंक तथा ग्रन्य वैंकों से सम्वन्ध-

सन् १६५१-५२ के नए समभौते के अनुसार जून सन् १६५३ के अन्त तक इम्पीरियल बैंक ने ३० नई शाखाएँ खोलने तथा अपने कोपागार शोधन कार्यालयों को शाखाओं में परिवर्तित करने का वायदा किया था । ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जून सन् १६५१ के बाद खोली गई शाखाओं के सरकारी व्यवसाय पर इम्पीरियल बैंक को  $\frac{2}{48}$ % की दर पर कमीशन मिलता ।

इम्पीरियल बैंक देश की सबसे बड़ी व्यापार वैंक थी। इसकी साख भी वहुत थी, इस कारएा इसे स्थानीय सरकारों से बिना ब्याज निक्षेप प्राप्त हो जाते थे। इसके अतिरिक्त यह अन्य बैंकों को ऋरण देती थी और विनिमय बिलों को किर से भुनाने का भी कार्य करती थी। देश में साख नियन्त्रएा की सफलता भी एक वड़े अंश तक इम्पीरियल वैंक के सहयोग पर निर्भर रहती थी। इस वैंक का महत्त्व इसी बात से सफट है कि सन् १९४९ में भारत में इसकी ३७० शाखाएँ थीं और इसके कुल निक्षेप ७०० करोड़ रुपये के थे, जब कि अन्य सभी वैंकों के निक्षेप, जिनमें विनिमय बैंक भी सिम्मिलत है, सामूहिक रूप में ६३३ करोड़ रुपये की कीमत के थे। अभी तक भी

देश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इम्पीरियल बैंक (स्टेट बैंक ) की शाखा ही एक मात्र बैंकिंग संस्था है।

इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न-

यद्यपि भारतीय वैकिंग प्रगाली में इम्पीरियल बैंक का भारी महत्त्व था, परन्तु काफी समय से इसके कार्य-संचालन की कड़ी ग्रालोचना की गई थी। इन ग्रालोचना श्रों के दो प्रमुख ग्राधार थे। एक ग्रोर तो यह बुरा बताया जाता था कि इम्पीरियल बैंक स्वतन्त्रतापूर्वक सरकार के कोषों का उपयोग करती रहती थी। किसी भी एक व्यापार बैंक के हाथ में सारे सरकारी घन को दे देना उचित नहीं हो सकता था, क्योंकि इससे एक ऐसा शक्तिशाली एकाधिकार उत्पन्न हो जाता है जो वैंकों तथा जनता के हितों की ग्रालोचना करता रहे, इसलिए बहुधा यह कहा जाता था कि इम्पीरियल बैंकों के उन सब विशेष ग्राधिकारों ग्रीर सुविधाग्रों का ग्रन्त होना चाहिए जो रिजर्व बैंक के स्थापित हो जाने पर भी उसको प्राप्त थे। दूसरी ग्रोर यह कहा जाता था कि ग्रारम्भ से ही इम्पीरियल बैंक भारत विराधी नीति का पालन करतो रही है। विदेशियों के प्रबन्ध में होने के कारण इसने भारतीय कर्मचारियों को ऊँचे स्थानों पर नियुक्त करने तथा शिक्षणा प्रदान करने का कभी प्रयत्न भी नहीं किया था। व्यवहार में भी वह भारतीयों के साथ बराबर भेद-भाव करती चली ग्राई है। भारत में ब्रिटिश व्यापार हितों का तथा इम्पीरियल बैंक का गठबन्धन बराबर बना रहा है।

उपरोक्त आलोचनाओं के अतिरिक्त यह भी कहा जाता था कि इस बैंक ने भारी मात्रा में नकद साख प्रदान करके देश में बिल बाजार के विकास में बाधायें उत्पन्न की हैं और देश के दूर-दूर के भागों से निक्षेप एकत्रित करके बड़े-बड़े व्यापार केन्द्रों का विकास किया है।

इन सभी ब्रालोचनाओं की ग्रामीए। बैंकिंग जांच समिति सन् १९५१-५२ ने विस्तृत जांच की थी | इस समिति का विचार था कि इम्पीरियल बैंक में दीप ब्रवश्य थे, परन्तु उनके कारए। उसका राष्ट्रीयकरए। उचित न था । समिति ने सुधार के निम्न रूमुभाव दिये थे:—

- (१) यह कि इम्पीरियल बैंक पर लगाये गये वर्तमान प्रतिबन्ध पर्याप्त थे श्रौर वह श्रन्य व्यापार बैंकों से किसी प्रकार की श्रनुचित प्रतियोगिता नहीं कर रही थी।
- (२) बैंङ्क में शीव्रतापूर्वक भारतीय ग्रिधिकारियों की संख्या बढ़नी चाहिए। इम्पीरियल बैंङ्क ने सन् १९४५ के अन्त तक ऐसा करने का विश्वास भी दिलाया था।
- (३) बैंद्ध के विशेष अधिकारों का रहना उचित नहीं था और उनका अन्त होना चाहिए।

(४) सभी बैङ्कों को कोपानारों द्वारा सस्ते दामों पर विश्रेष भेजने की सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे इम्बीरियल बैङ्क के विशेष लाभ का अन्त हो जाय।

रिजर्व वैङ्क के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ इम्मीरियल वैङ्क के राष्ट्रीयकरण का भी प्रश्न उठाया गया । इम्पीरियल बैंद्ध का देश के आर्थिक जीवन में इतना भारी महत्त्व ग्रौर बैङ्क द्वारा श्रपने अधिकारों का दुरुपयोग देखकर सरकार ने सैद्धान्तिक रूप में उसके राष्ट्रीयकरण की वांछनीयता स्वीकार कर ली थी, परन्तु राट्रीयकरण को व्यवहारिक रूप देने के कार्य को भविष्य के लिए स्थिगत कर दिया था। दो कारराों से सरकार ने बैंङ्क के तुरन्त राष्ट्रीयकरण को उचित नहीं समभा या :---प्रयम, विदेशों में भी इसकी शाखायें थी, जिनकी संख्या सन् १९५० के अन्त में ४८ थी। ये शाखायें बटिल समस्या उत्पन्न करती थीं। दूसरे, सरकार का विचार था कि राट्टीयकरए। के परचात् वैक वािराज्य कार्य नहीं कर सकेगी और ऐसी दशा में बैकिंग सेवाओं के अभाव भौर इम्पीरियल बेंक के भारी महत्व के कारए। राष्ट्रीय भ्रर्थ-व्यवस्था को काफी हानि पहुँचने का भय था। सरकार ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब कभी भी इसका राष्ट्रीयकरणा किया जायगा, अंशघारियों को मुत्रावजा अवश्य दिया जायगा। इस प्रकार उस समय म्रनिश्चित काल के लिए राष्ट्रीयकरण का प्रश्न स्थगित कर दिया गया था। वैसे भी अन्य वैंकों के सम्बन्ध में सरकारी नीति राष्ट्रीयकरए। की स्रोर नहीं थी। सन् १९५५ में सरकार ने नीति को बदल दिया। इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीय-करण करके उसे स्टेट बैंक के रूप में संगठित किया गया है।

## स्टेट वैंक के कार्यों का विस्तृत ग्रध्ययन-

स्टेट बैंक के कार्यों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—केन्द्रीय वैंक के हप में कार्य श्रीर व्यापार बैंक के कार्य। सन् १६२१ से सन् १६३५ तक इम्पीरियल बैंक दोनों ही प्रकार के कार्यों को एक ही साथ करती रही है। सन् १६३५ के पश्चात केन्द्रीय बैंक के श्रिधकांश कार्य रिजर्व बैंक ग्रॉक इण्डिया को सौंप दिये गये, परन्तु कुछ केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धित कार्य ऐसे श्रवश्य रहे जिन्हें इम्पीरियल बैंक द्वारा सम्पन्न किया जाता है। बाद को उसके व्यापार बैंकिंग सम्बन्धी कार्य ही श्रिधक महत्वपूर्ण रहे हैं। प्रमुख केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्य निम्न प्रकार थे:—

(१) यह बैंकों की बैंक के रूप में कार्य करती रही है। म्रावश्यकता पड़ने पर इम्पीरियल बैंक व्यापार बैंकों को ऋएा देती रही है। भ्रौर उनके द्वारा भुनाये हुए बिलों को फिर से भुनातो रही है। इसके म्रातिरक्त यह बैंक भूतकाल में बैंकों की देख-भाल करती थी भौर देश में बैंकिंग की उन्नति का प्रयत्न करती थी। देश की मन्य व्यापार बैंक तथा विनिमय बैंक इम्पीरियल बैंक में भ्रपना खाता खोलती थीं। इसी कारए। दूसरो बैंक इसका निकासी भ्रथवा समाशोधन-गृह (Clearing House) के रूप में भी उपयोग करती रही हैं। इस कार्य का महत्व मभी तक शेष है। साथ ही,

इम्पीरियल बैंक ग्रन्य बैंकों के घन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य भी करती रही है। इसका प्रमुख कारणा यह रहा है कि देश भर में इम्पीरियल बैंक की शाखाओं का जाल सा बिछा हुग्रा था। इम्पीरियल बैंक ने देश की बैंकों को उनके बैंकिंग कार्यों में सहायता पहुँचाने का भी कार्य किया है। यह काम स्टेट बैंक भी करती है।

- (२) स्टेट बैंक सरकारी बैंक का कार्य करती रही है। रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले तो यह कार्य केवल इम्पीरियल बैंक ही करती थी, परन्तु बाद में भी उन सभी स्थानों में जहाँ पर रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है, श्रिभिकर्ता के रूप में स्टेट बैंक ही राज्य बैंक (State Bank) का कार्य करती रही है। भारत सरकार श्रीर राज्य सरकारों का सारा बैंकिंग सम्बन्धी कार्य इम्पीरियल बैंक ही करती रही है। सरकार की श्रीर से रूपया वसूल करने श्रीर रूपये का भुगतान करने का कार्य यही बैंक करती थी श्रीर एक ग्रंश तक ग्रभी भी करती है। कर श्रादि की रकम इसमें जमा की जाती हैं। लोक ऋगों का एकत्रग, हिसाब श्रीर शोधन भी पहले यही बैंक करती थी। ग्रभी तक भी सरकारी शेष इसी बैंक में रहती है, यद्यपि श्रब श्रिधकाँश दशाश्रों में रिजर्व बैंक इस कार्य को सम्पन्न करती है।
- (३) विश्रेषों (Remittances) म्रर्थात धन को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने का कार्य स्टेट बैंक श्रारम्भ से ही करती रही है। ग्रब भी इस कार्य का महत्त्व कम नहीं हुम्रा है। केन्द्रीय बैंक की भाँति स्टेट बैंक को सरकारी खजाने के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजने की सुविधा दी गई है, जो काफी महत्त्व-पूर्ण है।
- (४) सन् १६२१ से पहले भारत सरकार के लन्दन सम्बन्धी सभी बैंकिंग, विनिमय तथा अन्य मौद्रिक कार्य बैंक आँफ इङ्गलैण्ड द्वारा किये जाते थे। सन् १६२१ और सन् १६३५ के बीच ये कार्य इम्पीरियल बैंक द्वारा किये जाते थे। रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् अब ये कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किये जाते हैं। इन कार्यों में लन्दन को रुपया भेजना, शोधन करना आदि सम्मिलित होते हैं।

## व्यापार बैंक सम्बन्धी कार्य-

जैसा कि विदित है कि इम्पीरियल बैंक तीनों प्रेसीडेन्सी बैकों के विलय से बनी थी। ये तीनों बैंक व्यापार बैंक थीं, इस कारण इनके कार्यों को इम्पीरियल बैंक ने करना आरम्भ कर दिया था। व्यापार बैंक के रूप में इम्पीरियल बैंक (स्टेट बैंक) के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:—

(१) भारत सरकार की प्रतिभूतियों, रेल्वे प्रतिभूतियों, राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, स्थानीय सरकारों की प्रतिभूतियों, लोक सत्ताओं, जैसे— पोर्ट ट्रस्ट (Port Trust), कॉरपोरेशन ग्रादि की प्रतिभूतियों पर कोषागार विपत्रों में घन का विनियोग करना ग्रीर उसकी ग्राड़ पर

ऋरण देना। ये कार्य वित्कुल व्यापारिक बैंकों के कार्य हैं ग्रीर लगभग सभी वेंकों द्वारा किये जाते हैं, परन्तु स्टेट वेंक की प्रमुख विशेषता सरकारी ग्रीर ग्रर्द्ध-सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजन ग्रीर व्यवसाय करना है।

- (२) तैयार माल, माल के अधिकार-पत्रों तथा अन्य उपयुक्त पत्रों और प्रति-भूतियों पर ऋण देना।
- (३) स्वीकृत प्रतिज्ञा-पत्रों, बाँड्स तथा-विनिमय बिलों पर ऋग्। देना ।
- (४) चल सम्पत्ति की ख्राड़ पर ऋ ए देना और ऐसी कम्पनियों के ग्रंशों की जमानत पर ऋ ए देना जिसमें ग्रंशघारियों का दायिस्व सीमित है।
- (१) ऐसे बिलों का निकालना, बेचना ग्रौर स्वीकार करना जो भारत में पहले भी भुनाये जा चुके हों।
- (६) अपने ग्राहकों को साख प्रमाण-पत्र प्रदान करना।
- (७) बहुमूल्य घातुर्ये ग्रौर सोने-चाँदी के सिक्के खरीदना ग्रौर वेचना।
- ( ८ ) जनता से निक्षेप प्राप्त करना ।
- (६) जनता की बहुमूल्य वस्तुग्रों के सुरक्षित संरक्षण की व्यवस्था करना।
- (१०) अपने व्यवसाय के लिये भारत में ऋग लेना।
- ( ११ ) ऐसी चल श्रौर श्रचल सम्पत्ति को बेचना जिस पर बेंक ने श्रिषिकार प्राप्त कर लिया हो ।
- (१२) पारितोषगा के ग्राघार पर ग्राहकों के ग्रिभिकर्ता का कार्य करना।
- (१३) बैंक की लन्दन शाखा अपनी व्यवसायिक आवश्यकताओं के लिए लन्दन में ऋए। प्राप्त कर सकती है।
- (१४) साधारण व्यापारिक बैंकों सम्बन्धी ग्रन्य प्रकार के कार्य करना।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेट बैंक देश के आर्थिक जीवन में तीन रूपों में आती रही है—(१) केन्द्रीय बैंक, (२) राज्य बैंक और (३) व्यापार वैंक । इसमें सन्देह नहीं कि सरकारी संरक्षण के कारण स्टेट बैंक की साख और प्रतियोगिता शक्ति अन्य व्यापार बैंकों की तुलना में बहुत अधिक रही है। सरकारी धन के जमा रहने के कारण स्टेट बैंक की आर्थिक स्थिति भी अधिक हढ़ रही है। इस बात का आरम्भ से ही भय था कि कहीं अन्य बैंकों से होड़ करके इम्पीरियल बैंक देश में बैंकिंग के विकास के मार्ग में बाधा न बन जाय। यही कारण है कि आरम्भ से ही इसके कार्यों पर कुछ प्रकार के प्रतिवन्ध लगा दिये गये हैं।

स्टेट वैंक पर लगाये हुए प्रतिबन्ध—

स्टेट बैंक के कार्य पर प्रमुख प्रतिबन्ध निम्न प्रकार हैं:--

(१) पहिले इम्पीरियल बैंक ६ माह से अधिक काल के लिए ऋ एा नहीं दे

सकती थी, परन्तु कृषि साख की उन्नति के लिए ग्रब स्टेट बैंक पर से यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया है।

- (२) इस बैंक को स्वयं अपने अंशों और अचल सम्पत्ति की जमानत पर ऋगा देने का अधिकार नहीं है।
- (३) किसी व्यक्ति अथवा संस्था को दिये जाने वाले ऋगा की अधिकतम् सीमा निश्चित कर दी गई है।
- (४) इस बैंक को ऐसे बिलों को भुनाने तथा उनकी आड़ पर ऋगा देने की अनुमित नहीं थी जिनकी परिपक्कता अविध ६ मास से अधिक हो, परन्तु कृषि साख की उन्नित के लिए अब इसमें छूट दी जा सकती है।
- (५) बैंक को विदेशी विनिमय व्यवसाय की आज्ञा नहीं है।
- (६) बेंक द्वारा अचल सम्पत्ति खरीदने पर भी प्रतिबन्ध है।

वैसे तो इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक का कार्य करती रही है, परन्तु इसे पत्र-मुद्रा निर्गम का अधिकार नहीं दिया गया था। आरम्भ में इस बात पर भी विचार किया गया था कि इम्पीरियल बैंक को पूर्ण रूप में केन्द्रीय बैंक ही क्यों न बना दिया जाय, परन्तु कुछ कारणों से ऐसा उपयुक्त नहीं समभा गया था:—प्रथम, यह कहा गया था कि कोई भी केन्द्रीय बैंक इतनी शाखायें नहीं खोल सकती है जितनी कि इम्पीरियल बैंक ने खोल रखी थीं। यदि इम्नीरियल बैंक को और अधिक शाखायें खोलने का अधिकार न दिया जाता अथवा कुछ शाखायें बन्द करने की आज्ञा दी जाती तो इसका देश की बैंकिंग व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने का भय था। दूसरे, केन्द्रीय बैंक के नाते देश के चलन का प्रबन्ध भी इम्पीरियल बैंक के पास रहता, जिस दिशा में अधिकारों के दुरुपयोग का भारी भय था। तीसरे, केन्द्रीय बैंक बन जाने की दशा में इम्पीरियल बैंक एक साधारणा व्यापार बैंक की भाँति लाभ के ही उद्देश्य से काम नहीं कर सकती थीं, क्योंकि ऐसी दशा में उससे केन्द्रीय बैंकिंग में सफलता की आशा नहीं हो सकती थीं। अन्त में, बैंक के अशिधारी व्यापारिक बैंक सम्बन्धी कार्यों को पूर्णतया बन्द करने के पक्ष में न थे। स्टेट बैंक के निर्माण के पश्चात् भी यह पुरानी व्यवस्था बनाये रखी गई है।

#### बैंक की स्थापना से भारत को लाभ-

इम्पीरियल बैंक का देश के आर्थिक जीवन में भारी महत्व रहा है। बैंकिंग जगत में तो इसका अपना विशेष स्थान है। देश को इसकी स्थापना से निम्न प्रकार लाभ हुए हैं:—

(१) इसने देश में बैंकिंग सुविधाओं का प्रसार किया है। इस समय बैंक की ५०० से भी ऊपर शाखायें है, जो देश के कौने-कौने में फैली हुई हैं। बहुत से स्थानों पर तो स्टेट बैंक की शाखा के अतिरिक्त कोई बैंक हैं ही नहीं।

- (२) इस बैंक ने देश में व्याज की दर को कम किया है। बैंक के पाम काफी घन रहा है, जिसके कारएा यह काफी मात्रा में नीची दर पर ऋएा देने में सफल रही है। साहुकारों और दूसरी बैंकों को भी ब्याज की दरों को घटाने पर बाब्य होना पड़ा है।
- (३) बहुत सी शाखार्ये होने के कारण इसने एक स्थान से दूसरे स्थान को धन हस्तान्तरित करने की सस्ती और सुविधाजनक सेवाएँ उपलब्ध की हैं।
- (४) इस वैंक की डिस्कान्उट दर में काफी स्थिरता रही है, जिसके कारए। देश भर में ऐसी दर स्थिर रहती है।
- (५) यह वैंक कृषि की उपज की म्राड़ पर ऋगा देती रही है। परिगाम यह हुम्रा है कि ऐसे माल की विक्री भौर यातायात में काफी सुविधा रही है।
- (६) यह वैंक सहकारी बैंकों को ग्रधि-विकर्प की मुविधा देकर काफी मह-त्त्वपूर्ण कार्य करती रही है।
- ( प्र ) देशी बैकरों और साधारण वैंकों को इससे ऋण प्राप्ति की भारी सुविधायें मिली हैं।
- ( ६ ) इस बैंक ने समाशोधन ग्रहों को श्रायोजित करके देश की वैंकिंग प्रगाली की काफी सेवा की है।

## इम्पीरियल बैंक के कार्यवाहन में दोप-

इन सव लाभों के साथ-साथ बैंक के कार्यवाहन में कुछ गम्भीर दोष भी रहे हैं। इम्पीरियल बैंक के विरुद्ध अनेक शिकायतें रही हैं:—

- (i) इसने अपने उच्च पदों पर गैर भारतीयों को ही नियुक्त किया है। भारतीय स्वतन्त्रता के पश्चात् धीरे-धीरे पदों का भारतीयकरण आरम्भ हुआ है।
- (ii) इसके अंशधारियों में विदेशियों की संख्या श्रधिक रही है और उन्हीं का इसकीं नीति और कार्यवाहन पर श्रधिक सप्रभाविक नियन्त्रण रहा है।
- (iii) इसने भारतीय व्यापारियों के प्रति भेद-भाव किया है और विदेशियों के हिलों को प्रधानता दी है।
- (iv) इसने देश में व्यापार बेंकों के विकास में बाघा डाली है। यह उनकी घोर प्रतियोगी रही है और बहुत बार तो इसने व्यापार बेंकों को अना-

थिक दरों पर ऋगा देने पर बाध्य किया है। सम्मानित वैंक होने के कारगा इसने निक्षेप प्राप्त करने में भी अन्य वैंकों से होड की है।

( v ) इस बैंक ने व्यापार बैंकों की अपेक्षा विनिमय बैंकों के प्रति अधिक उदारता की नीति अपनाई है, मुख्यतया इस कारएा कि वे विदेशी बैंक थीं। विनिमय बैंकों ने सदा ही भारतीय हितों की अबहेलना की है और भारतीय व्यापारियों के साथ घृिणत व्यवहार किया है।

सन् १६५५ में इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण ग्रौर स्टेट वैंक ग्राँफ इण्डिया का निर्माण—

१६ म्रप्रैल सन् १६५५ को सरकार ने लोक-सभा में एक बिल प्रस्तुत किया था, जिसे स्टेट बैंक म्रॉफ इण्डिया बिल का नाम दिया गया था। इस बिल का उद्देश इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण था। इस प्रकार बिल को प्रस्तुत करने का विचार सरकार काफी दिन पहले से कर रही थी, परन्तु म्रखिल भारतीय ग्राम्य साख जाँच सिमित (Rural Credit Survey Committee) की सिफारिशों ने राष्ट्रीयकरण की विचारधारा को काफी बल प्रदान किया है। वित्त मन्त्री ने बिल को प्रस्तुत करते समय बताया था कि सरकार का ऐसा इरादा नहीं है कि व्यक्तिगत वाण्यिष्य भौर व्यवसाय में अनुचित हस्तक्षेप करे। इसी कारण इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का यह भ्रथं नहीं होता है कि सभी व्यापारिक बैंकों को सरकारी भ्रधिकार में ले लिया जायगा। इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य उन सब शिकायतों को दूर करना जो कि लम्बे काल से भारतीयों को इसके विरुद्ध थीं तथा ग्राम्य साख की समु-चित व्यवस्था करना बताया गया है। सबसे पहले वित्त मन्त्री ने २० दिसम्बर सन् १९५४ को इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का विचार प्रकट किया था। बिल की प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं:—

- (१) बैंक के अंशधारियों को मुआवजा देने का सिद्धान्त मान लिया गया है। मुआवजे की दर निश्चित करने के लिए इम्पीरियल बैंक के लिए इम्पीरियल बैंक के श्रंशों की २० दिसम्बर सन् १९५३ और २० दिसम्बर सन् १९५४ के १२ मास के बीच की औसत मासिक कीमत निकाली गई है। इस आधार पर एक ५०० रुपए के पूर्णतया शोधित अंश की कीमत १,७६५ रुपये और आँशिक शोधित की ४३१ रुपया १२ आने ४ पाई होती है और यही रकम मुआवजे के रूप में दी जायगी।
- (२) मुझावजे की रकम में से १०,००० रुपए तक का भुगतान नकदी में किया गया है श्रौर शेष के लिये सरकार ने बाँड दी हैं, जिनके सम्बन्ध में ब्याज की दर ग्रौर परिपक्कता ग्रविध सम्बन्धी बातें बाद को निश्चित की जायँगी।
- (३) ऐसी व्यवस्था की गई है कि कम से कम ५५% ग्रंश रिजर्व बैंक द्वारा लिये जायेंगे श्रौर शेष ४५% जनता द्वारा प्राप्त किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में इम्पी-

रियल बैंक के पुराने अंशघारियों को नई संस्था के अंश खरीदने का पूर्व अधिकार दिया गया है।

- (४) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इम्मीरियल वैंक का नया नाम स्टेट वैंक भ्रॉफ इण्डिया रखा गया है।
- (५) सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ एक नये ग्राम्य साख संगठन का निर्माण करना है, जिसके लिए रिजर्व वैंक ग्राँक इण्डिया एक्ट में भी ग्राव-क्यक संशोधन किये गये हैं।
- (६) इस वात की व्यवस्था की गई है कि स्टेट वेंक ग्रांक इन्डिया की स्थापना के पश्चात् खण्ड ख राज्यों की १० ऐसी वेंकों को जो राज्य सरकारों के नियन्त्रण ग्रीर संरक्षण में कार्य कर रही हैं, इस वेंक के साथ मिला दिया जायगा। साथ ही, सरकार का यह भी विचार है कि ग्राम्य साख जाँच सनिति की सिकारिशों को कार्य रूप देने के लिए कुछ गैर-अनुसूचित (Non-Scheduled) वंकों को भी समुचित जाँच के पश्चात् स्टेट वेंक में सम्मिलित कर लिया जायगा।
- (७) बिल के पास होने पर इम्पीरियल वेंक के सभी ग्रंगों को रिजर्व वेंक को हस्तान्तिरत कर दिया गया है, परन्तु इन ग्रंगों के ग्रंघिक से ग्रंघिक ४ $\chi_0^0$  घीरे- घीरे प्राइवेट व्यक्तियों को बेच दिये जायँगे।
- ( ू ) सरकार व्यक्तिगत व्यवसायियों और वाणिज्य हितों को भी स्टेट वेंक से सम्बन्धित रखेगी, परन्तु इस बात का पूरा-पूरा घ्यान रखा गया है कि बैंक पर सर-कार का ही पूर्ण रूप में नियन्त्रण रहे।
- ( ६ ) स्टेट बैंक ग्रॉफ इण्डिया का प्रबन्घ २० संचालकों के एक मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसमें से १४ सरकार द्वारा नामजद किये जाते हैं ग्रौर शेप ६ व्यक्तिगत ग्रंशघारी निर्वाचित करते हैं। लोक सभा ग्रथवा घारा सभा के सदस्य बैंक के संचालक नहीं बन सकते हैं।
- (१०) राष्ट्रीयकरएा के पश्चात् इम्पीरियल बैंक के व्यापारिक वैंकिंग कार्यं बन्द नहीं हुए हैं। स्टेट बैंक ग्रॉफ इण्डिया देश की सबसे बड़ी व्यापार वैंक के रूप में कार्यं करेगी ग्रीर देश की ग्रनुसूचित वैंकों को बराबर सहायता देती रहेगी।
- (११) इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का यह ग्राशय नहीं है कि घीरे-घीरे ग्रन्य व्यापार वैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा। इस सम्बन्ध में सरकारी नीति सामान्य रूप में बैकिंग के राष्ट्रीयकरण की नहीं है।
  - ( १२ ) स्टेट बैंक की ग्रधिकृत पूँजी २० करोड़ रुपया रहेगी।

#### म्रालोचनात्मक मध्ययन-

स्टेट बैंक ग्रॉफ इण्डिया एक्ट का घारा सभा तथा जन-साघारण ने साघार एतया स्वागत ही किया है। देश में ग्राम्य साख की समुचित व्यवस्था की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण पग है। सरकार ने ऐसा भी ग्राक्वासन दिलाया है कि शीघ्र ही ५ वर्ष के

भीतर स्टेट बेंक की ४०० नई शाखायें खोली जायेंगी, लो उन ४७२ शाखाओं के अतिरिक्त होंगी जो इम्पीरियल बेंक ने पहले से ही खोल रखी थीं । ये शाखाएँ साधारणतया ग्रामीए अथवा अर्द्ध-नागरिक (Semi-urban) क्षेत्रों में खोली जायेंगी, जहाँ पहले से बैंकिंग सेवाएँ मौजूद नहीं हैं। इस सम्बन्ध में रिजर्व वेंक एक्ट में आवश्यक संशोधन करने का बिल पास हो चुका है।

स्टेंट बैंक बिल को लोक सभा में प्रस्तुत करते समय वित्त विभाग के उप मन्त्री ने ठीक ही कहा था कि भारत जैसे देश में, जहाँ देश की ७०% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ग्राम्य साख की समुचित व्यवस्था का भारी महत्त्व है। ग्रामीण जनता साख की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ऋगों के भार से दबी हुई है। ऐसा प्रनुमान लगाया गया है कि ग्रामीण ऋगु-भार की मात्रा ७५० करोड़ रुपये से भी ऊरर है। सन् १६५४ में केन्द्रीय श्रम जांच से पता चला था कि ग्रामीण जन-संख्या में ३०% भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं। इन श्रमिकों ग्रीर ग्रीद्योगिक श्रमिकों की ग्राय में भारी ग्रन्तर है। बङ्गाल, बिहार, उड़ीसा ग्रीर बम्बई राज्यों में खेतिहार श्रमिक को वार्षिक ग्राय केवल १६०, ११६, ६६ तथा ६८ रुपये थी, जबकि इन्हीं राज्यों में ग्रीद्योगिक श्रमिकों की वार्षिक ग्राय क्रमशः २६८, ३३२, १४५ तथा ३६८ रुपया थी। इस घोर ग्रन्तर का कारण ग्रामीण जनता का ऋगु-भार ही था। ऐसी स्थित में ग्राम्य साख के विकास का महत्त्व ग्रीर भी बढ़ जाता है।

इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के द्वारा उन सब शिकायतों का भी अन्त हो जाता है जो इस बैंक के प्रति काफी समय से चली आ रही थीं, यद्यपि अब इन शिका-यतों का कोई विशेष महत्त्व नहीं रह गया था । उस समय बैंक के लगभग सभी अधि-कारी भारतीय ही थे, परन्तु फिर भी राष्ट्रीयकरण उन सब दोषों को दूर कर देता है जो सरकारी संरक्षण के कारण इम्पीरियल बैंक में पैदा हो गये थे । अब भारतीय हितों की अवहेलना का प्रश्न ही नहीं उठता है । जहाँ तक इम्पीयिल बैंक के कर्मचारियों का प्रश्न है, ऐसा विश्वास दिलाया गया था कि मैनेजिंग डाइरेक्टर, डिप्टी मैनेजिंग डाइरेक्टर और दो डाइरेक्टरों को छोड़ कर शेष के वेतनों और सेवामों की दशाओं में किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं किया जायगा ।

बिल की घ्रालोचना साधारणतया मुम्रावजे के दृष्टिकोण से ग्रंश की कीमत निश्चित करने के सम्बन्ध में हुई है। ग्रंशधारियों का विचार है कि मुग्रावजे की रकम बहुत कम है, यद्यपि इसमें बहुत सत्य दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि पूर्णतया शोधत ग्रंशों की कीमत सन् १६५१, सन् १६५२ ग्रीर सन् १६५३ के बीच निर्धारित कीमत के ग्रास-पास ही रही है। लोक सभा के ग्रधिकांश सदस्यों ने ऐसा विचार प्रकट किया है कि मुग्रावजा ग्रधिक दिया जा रहा है, क्योंकि ग्रंशों की ऊँची कीमत का एक महत्त्वपूर्ण कारण सरकारी संरक्षणों तथा सरकारी व्यवसायों का इम्नीरियल बैंक द्वारा सम्पन्न करना रहा है। कुल मुग्रावजे की रकम का ग्रनुमान १६९६ करोड़ रुपया

लगाया गया है, जिसका ६१.७% भारतवासियों को मिलेगा और शेष विदेशी ग्रंश-

इस सम्बन्ध में भी काफी आलोचना हुई है कि प्रस्तावित शाखाओं की संख्या कम रखी गई है। श्री तुलसीदास किलाचन्द के अनुसार ४०० शाखाओं के स्थान पर ४,००० शाखायें खुलनी चाहिये। कुछ सदस्यों ने यह भी विचार प्रकट किया है कि स्टेट वैंक की अधिकृत पूँजी, जो २० करोड़ रुपया रखी गई है, वास्तव में कम है और फिर इसके भी ४५% पर प्राइवेट व्यक्तियों का अधिकार होगा। सब कुछ होते हुए भी इस बिल से काफी लाभ की आशा की जाती है।

## स्टेट बैंक के कार्य-

स्टेट वेंक ग्रॉफ इण्डिया प्रामीए। साख की वृहत् योजना का ही एक ग्रंग है। इस वक की स्थापना द्वारा प्रामीए। क्षेत्रों में सहकारी साख ग्रौर सहकारी विक्री व्यवस्थाग्रों को वढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। इस के ग्रतिरक्त ग्रामीए। वेंकिंग तथा सामान्य रूप में सभी प्रकार की वेंकिंग को सहयोग देने का भी उद्देश है। स्टेट वेंक के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार रहेंगे:—

- (१) इम्पीरियल वैंक की भाँति यह भी उद्योग, व्यापार और वारिएज्य को साख सुविधायें प्रदान करेगी।
- (२) यह बैंकों के समुचित विकास में सहायक होगी।
- (३) यह सन् १६६० तक ४०० नई शाखाएँ खोलेगी।
- (४) यह वक अधिक बड़ी विप्रेष सुविधाएँ प्रदान करेगी और प्रामीए। बचत के संग्रह करने का प्रयत्न करेगी।
- (५) ग्रामीएा साख की यह शक्तिशाली एजेन्सी होगी ग्रीर सहकारी विक्री तथा गोदाम व्यवस्था को बढायेगी।

## स्टेंट बेंक के वर्जित कार्य-

स्टेट बेंक को निम्नांकित कार्य करने से वर्जित किया गया है:-

- (१) यह स्कन्ध, अपने अंश अथवा स्थायी सम्पत्ति की आड़ पर ६ मास से अधिक काल के लिए ऋणा अथवा अग्रिम नहीं दे सकती है।
- (२) यह निश्चित प्रतिभूति के म्रितिरिक्त किसी व्यक्ति म्रथवा फर्म के विनि-मय-पत्रों को एक निश्चित राशि से ऊपर की रकम के लिए नहीं भुना सकती है।
- (३) बैंक केवल ऐसे विनिमय विलों को भुना सकती है अथवा उसकी आड़ पर ऋगा अथवा अग्निम दे सकती है जिन पर कम से कम दो व्यक्तियों अथवा फर्मों का उत्तरदायित्व हो।
- (४) यह १५ मास से अधिंक परिपक्कता ग्रविध के कृषि बिलों अथवा ६ मास से अधिक के बिलों को नहीं भुना सकती है।

(५) यह अपनी इमारत के अतिरिक्त अन्य कोई अचल सम्पत्ति प्राप्त नहीं कर सकती है।

#### लाभ का बँटवारा--

स्टेट बैंक एक एकीकरए एवं विकास कोष (Integration and Development Fund) रखती है, जिसमें रिजवं बैंक को दिया जाने वाला लाभाँश और दूसरे चन्दों की रकम जमा होती रहेगी। इस कोष का उपयोग बैंक की हानि को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। इसके ग्रतिरिक्त एक ग्रौर भी कोष रहेगा, जिसमें इम्पीरियल बैंक के निधि कोष की राशि के साथ-साथ बाद की वह राशि रहेगी जिसे निधि कोष में रखा जायगा।

## स्टेट बैंक की प्रगति—

१ जुलाई सन् १६५५ से स्टेट बैंक झॉफ इण्डिया ने अपना काम शुरू कर दिया। श्री जॉन मथाई बैंक के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किये गये थे। इम्पीरियल बैंक की सारी लेन-देन स्टेट बैंक को हस्तान्तरित कर दी गई है। स्टेट बैंक की अधिकृत पूँजी २० करोड़ रुपया है और निर्गमित पूँजी ५,६२,५०,००० रुपया। सारी की सारी निर्गमित पूँजी का रिजर्व बैंक को हस्तान्तररण कर दिया गया है। पिछले अंश-धारियों के प्रत्येक पूर्णत्या शोधित अंश के लिए १,७६५ रुपये १० आने और आंशिक शोधित अंश के लिए ४३१ रुपये १२ आने ४ पाई मुआवजे के रूप में दिये गये हैं।

सन् १६५५-५६ के लिए वित्त मन्त्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट छपी है उसमें बताया गया है कि स्टेट बैंक के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य यह था कि राज्य की साफेदारी में एक शक्तिशाली व्यापार बैंक खोली जाय, जिसकी शाखायें देश भर में फैनी हों तथा जो सहकारी और अन्य प्रकार की बैंकों की विप्रेष सुविधाओं का विस्तार करके देश में बैंकिंग के विकास को प्रोत्साहन दे । इम्पीरियल बैंक के कुल मिलाकर १०,७२० अंशधारी थे, जिन्हें कुल १६,७१,०७,५०० रुपये का मुआवजा मिलना था। ३१ दिसम्बर सन् १६५५ तक के मुआवजे के लिए ६,५६० अंशधारियों ने प्रार्थना-पत्र भेजे थे, जिनमें १८,६५,२४,००० रुपये की माँग की गई थी। इस काल में ६,४६१ अंशधारियों को १८,३५,००० रुपये मुआवजे के रूप में दिये जा चुके हैं।

स्टेट बेंक ने ५ साल में ४०० नई शाखाएँ खोलने का लक्ष्य निर्घारित किया है। ३१ दिसम्बर सन् १६५५ तक अर्थात् पहले ६ महीनों में बेंक ने २० नई शाखायें खोली थीं। सन् १६५५ के अन्त तक स्टेट बेंक निर्घारित ४०० नई शाखाओं में से २६२ शाखायें खोल चुकी है। ३१ साल में यह प्रगति पर्याप्त अंश तक सन्तोषजनक है। वास्तविकता यह है कि सन् १६५१ और सन् १६५५ के बीच स्टेट बेंक के कार्यालयों की संख्या ३६१ से बढ़कर ६६६ हो गई है। अन्य दिशाओं में भी प्रगति हुई है। स्टेट बेंक ने छोटे-छोटे उद्योगों की सहायता का कार्य आरम्भ कर दिया है। इसने विदेशी विनिमय के कार्य में भी आगे कदम बढ़ाया है। पाकिस्तान में स्थित करांची, चिटगांव

ग्नीर नारायरागंज की शाखायों के स्रतिरिक्त स्रन्य विदेशी शाखाएँ ३० जून सन १९५६ को बन्द कर दी गई हैं। प्रथम ६ मास में ही बैंक का युद्ध लाभ ६० करोड़ रूपया रहा था स्रौर इसने ७६% लाभांश घोषित किया था।

प्रथम फरवरी सन् १६५७ को स्टेट वैंक ने यह निश्चय किया था कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा शीर्ष वैंकों को सप्ताह में एक बार ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाग्रों को कोषों को भेजने में निःशुल्क विश्रेष सुविधाएँ दी जार्येगी। स्टेट वैक रियायनी दरों पर सहकारी संस्थाग्रों को ट्रस्टी प्रतिभूतियों, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ऋग्-पत्रों ग्रौर ग्रंशों, माल, विनिमय विलों, प्रतिज्ञा-पत्रों ग्रादि पर ऋग् तथा नकद साख (Cash Credit) सुविधाएँ भी उपलब्ब करेगी। ग्रारम्भिक ग्रवस्था में सहकारी संस्थाग्रों को ग्रंश पूँजी को बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी ऋग् दिये जाने लगे हैं। इस सम्बन्ध में स्टेट वैंक जो योग देती है वह उसके ग्रादि रिक्त होता है जो कि रिजर्ब वैंक द्वारा दिया जाता है।

सन् १६५० के सम्बन्ध मे वैंकिंग की प्रगति की जो रिपोर्ट रिजर्व बैंक ने प्रकाशित की है कि सन् १६५० के वर्ष में स्टेट वैंक ने परम प्रतिभृतियों में घन का विनियोग करके देश में वैंकिंग विनियोग की मात्रा बढ़ाई है। इस वर्ष में कुछ ग्रौर राज्य सम्बन्धित बैंकों का स्टेट बैंक में विलय हुग्रा है। इस वर्ष स्टेट बैंक ने १०५ नई शाखाएँ खोली हैं, जो विशेषतया उन स्थानों पर खोली गई हैं जहाँ वैंकिंग मुविधाग्रों का अत्यधिक ग्रभाव था। बैंक ने सरकारी वैंकों को विश्रेष (Remittances) मुविधाएँ देने में उदारता अपनाई है ग्रौर सरकारी विक्री तथा उत्पादन समितियों को अल्पकालीन ऋरण भी दिये हैं। छोटे उद्योगों को ऋरण देने की योजना ग्रव स्टेट वैंक की सभी शाखाग्रों पर लागू कर दी गई है।

## स्टेट बैंक का महत्त्व-

स्टेट बैंक की स्थापना भारतीय बैंकिंग के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। इस बैंक की सहायता से ग्रामीण वित्त की समस्या के बहुत ग्रंश तक सुलभ जाने की ग्राशा है। यह बैंक विधानानुसार सन् १६६० तक ४०० नई शाखाएँ खोल कर ग्रामीण तथा श्रद्ध-नागरिक क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाश्रों का प्रसार करेगी। साथ ही, राज-कीय कोषों को बैंकिंग कोषों में परिवर्तित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकेंगा ग्रीर ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती ग्रीर सुविधाजनक वैंकिंग तथा विश्रेष सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को श्रोत्साहित करने ग्रीर इन वचतों को एकिंतित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य भी सम्पन्न हो सकेंगा।

श्रारम्भ से ही कुल बेंकों की जमा का एक-चौथाई भाग स्टेट बेंक के पास है। इससे इस बेंक में जन-विश्वास की कमी न रहेगी श्रौर साथ ही, रिजर्व बेंक को भी साख नियन्त्रण में श्रिधिक सुविधा रह सकेगी। छोटो-छोटी सरकारी बेंकों के स्टेट बेंक में मिला देने के कारण बेंक की कार्यक्षमता एवं सप्रभाविकता श्रौर भी वढ़ गई

है। सारांश यह है कि उद्योग, व्यापार श्रौर वािि ज्य सभी दिशाश्रों में देंक से भारी लाभ की श्राशा है। वैसे भी इसने बेंकिंग के राष्ट्रीयकरण के महान् क्रम का सूत्रपात किया है।

स्टेट बैंक ग्राँफ इन्डिया की लेन-देन स्थिति\* (लाख रुपयों में)

वर्षं	परिदत्त पूँजी	सुरक्षित कोष	ा कुल जमा	नकदी हाथ में	नकदी बैंकों में	विनियं कारी	ोग (सर- हुन्डियाँ)
१६५०	४,६३	६,३३	२३१,३७	७,१७	२१,१०	१,०	७,१५
9 E X 8	५,६३	६,३५	२३०,६१	६,७१	२२,८६	: 6	६५,६३
१६५२	४,६३	६,३५	२०५,५५	३,६५	२१,६०	7	50,48
११४३	४,६३	६,३५	२०६,६७	३,६९	१५,६५		<b>२०,</b> ६५
१६५४ -	५,६३	६,३४	२३१,१३	३,०७	३२,६७	, ,	દે૪,દેધ
१९४५	४,६३	६,३४	२१६,५०	३,४३	२४,६६	१,	०४,०६
१६५६	६,६३	६,३८	२३४,४७	3,38	२४,३६	. 6	32,53
	म्रन्य विनियोग	याचना राशि	ऋग तथा ग्रग्रिम	भुनाये ध खरीदे हु		शुद्ध लाभ	कार्यालयों की संख्या
१६५०	१४,४०		£8,88	७,४	१	१,२५	३८२
१६५१	१६,२३	••••	<i>₹,</i> ₹ <i>₹</i> ,	۵,5	१	१,३०	३६३
१६५२	१६,६१	••••	१,०७,१२	६,०	ሂ	१,३३	४१०
१९५३	३३,१६	••••	६२,०३	१४,२	<u>ح</u>	१,२७	४२४
१६५४	०७,६१	••••	६६,१५	६,१	৩	१,३७	<i></i> ጸሂሂ
१९४५	१२,०२	१,५३	58,08	१६,८	0	१,३६	४६४
१९५६	१४,२८	१,०७	१,०७,४२	३२,७	8	१,५६	४३८

#### **QUESTIONS**

1. With what objects has the Imperial Bank of India been converted into the State Bank of India? How do you think it will develop the Banking habit in the rural areas?

(Agra, B. Com., 1956)

<sup>\*</sup> Vide: Statistical Tables relating to banks in India.

- 2. What were the issues involved in the nationalisation of the Imperial Bank of India? Do you favour nationalisation of commercial banking in India? (Agra, B. A., 1956 Supp.)
  - 3. स्टेट वैक ग्रॉफ इण्डिया के कार्यों पर प्रकाश डालिये।

(Agra, B. A., 1957 Supp.)

- 4. What part did the Imperial Bank of India play in the credit organisation of the country? Was the nationalisation of Imperial Bank desirable? (Bombay, B. Com., 1956)
- 5. What part does the Imperial Bank of India play in the banking system of the Country? (Agra, B. Com., 1955)
  - 6. Write a note on:—State Bank of India.
    (Sagar, B, Com., 1957 and Agra, B. Com., 1957 Supp.)

# श्रध्याय ३८ भारत में विदेशी विनिमय वैंक

(Foreign Exchange Banks in India)

## परिभाषा एवं इतिहास-

विदेशी विनिमय बैंकों से हमारा श्रभिप्राय उन बैंकों से होता है जो विदेशी विनिमय में व्यवसाय करती हैं। भारत के विदेशी व्यापार का श्रयं-प्रवन्ध करती हैं। भारत में ऐसी बैंकों का विकास विदेशी शासन की उन्नति से सम्बन्धित है। श्रारम्भ से ही ब्रिटिश सरकार ने विदेशियों को भारत में विनिमय बैंक खोलने की पूरी पूरी नुविधाएँ प्रदान की थीं, जिसके फलस्वरूप शीघ ही उनकी उन्नति होती गई। भारतीय बैंकों ने समय-समय पर विदेशी विनिमय व्यवसाय में प्रवेश करने के प्रयत्न किये। उदाहररण्-स्वरूप, सबसे पहले 'एलायंस बैंक श्रॉफ शिमला' ने यह कार्य श्रारम्भ किया, परन्तु यह सन् १६२३ में दिवालिया हो गई। सन् १६३६ में 'सेन्ट्रल बैंक श्रॉफ शिमला' ने वह कार्य श्रारम्भ किया, परन्तु यह सन् १६२३ में उसे भी 'बारकले बैंक' के साथ विलय करना पड़ा। इस प्रकार भारतीय बैंकों द्वारा विदेशी विनिमय में प्रवेश करने के सभी प्रयत्न श्रसफल रहे। श्रभी तक भी इस व्यवसाय का एकाधिकार विदेशियों के पास है, यद्यपि स्वतन्त्रता के उपरान्त एक बार फिर भारतीय बैंकों ने इस दिशा में श्रागे बढ़ने का प्रयत्न किया था।

भारतीय विनिमय बैंकों की ग्रसफलता के ग्रनेक कारण हैं, जिनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं:—(१) कार्य का ग्रारम्भ करने तथा ग्रारम्भ काल की हानियों को सहन करने के लिए पूंजी की कमी, (२) ऐसे योग्य तथा निपुण कर्मचारियों का ग्रभाव जो विदेशी विनिमय व्यवसाय से परिचित हों, (३) विदेशों में शाबाएँ खोलने से सम्बन्धित कठिनाइयाँ, (४) प्रस्तुत विदेशी विनिमय बैंकों की प्रतियोगिता। इन कारणों का परिणाम यह हुग्रा है कि कुछ थोड़े से विदेशी विनिमय व्यवसाय को छोड़ कर, जो भारतीय सम्मिलत पूंजी बैंकों द्वारा किया जाता है, ऐसा लगभग सारा का सारा व्यवसाय विदेशियों के हाथ में है।

इस समय भारत में जो विदेशी विनिमय बैंक कार्य कर रही हैं उन्हें हम दो भागों में बाँट सकते हैं। कुछ बैंक तो ऐसी हैं जिनका व्यवसाय अधिकांश मात्रा में भारत में ही है, जैंसे—'नेशनल बैंक श्रॉफ इण्डिया', 'चार्टर्ड बैंक ग्रॉफ इण्डिया, ग्रास्ट्रे लिया, चाइना', इत्यादि। दूसरी वे बैंक हैं जो केवल बड़ी-बड़ी विदेशी बैकों की भारतीय शाखाएँ हैं, जैसे—'लाइडस् बैंक', 'नेशनल सिटी बैंक ग्रॉफ न्यूयार्क' इत्यादि। सब मिला कर इस समय भारत में १५ विनिमय बैंक हैं, जिनके ६५ कार्यालय हैं।

## विनिमय बैंकों के कार्य-

विनिमय बैंक का प्रधान कार्य विदेशी व्यापार का वित्तीय प्रबन्ध करना होता है । इनके कार्य निम्न प्रकार हैं :—

(१) निर्यात व्यापार का ग्रर्थ-प्रबन्ध-जब एक भारतीय व्यापारी माल का निर्यात करता है तो वह अपने विदेशी ग्राहक अथवा उसकी बैंक पर बिल लिखता है। इस प्रकार के बिल साधारएातया प्रस्तुत करने के ३ मास के भीतर शोधनीय होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं--स्वीकृति पर प्रपत्र (Document on Acceptance or D. A.) तथा शोधन पर प्रपन्न ( Document on Payment or D. P.) । इस प्रकार के बिल और विकर्ष सदा ही विनिमय बेंकों द्वारा खरीद लिए जाते हैं, जो इस सम्बन्ध में अपने प्रधान कार्यालय अथवा अन्य ऐसी आर्थिक संस्थाओं से स्वीकृति प्राप्त कर लेती हैं जिनमें भारतीय माल के निर्यातकर्ताग्रों ने ग्रपने खाते खोल रखे हैं। इस प्रकार भारतीय निर्यात व्यापारी अपने बिल को विनिमय बैंक के भारतीय कार्यालय से भुनाकर तुरन्त धन प्राप्त कर लेता है। विनिमय बैंक बिल को विदेशी केन्द्र में भेज देती है श्रीर या तो उसकी परिपक्कता पर श्रायात व्यापारियों से धन प्राप्त कर लेती है अथवा उसे लन्दन के मुद्रा बाजार में फिर से भुना लेती है। इस प्रकार विनिमय बैकों को उनके द्वारा रुपयों में किये गए शोधनों की कीमत स्टर्लिंग में मिल जाती है। साधारणतया विनिमय बैंक इससे बहुत अधिक कीमत के बिल खरीदती हैं, जितने कि वे परिपक्कता के समय तक ग्रपने पास रख सकती हैं। इस कारण प्रधिकाँश बिलों को, विशेषकर (D. A.) बिलों को, फिर से भुना लिया जाता है। इस प्रकार ब्रिटिश बैंकों के ग्रल्पकालीन कोष भारत के विदेशी व्यापार का मर्थ- प्रबन्ध करने के लिए उपयोग किये जाते हैं। बहुत बार निर्यातकर्ता धन एकत्रित करने के लिए विनिमय बैंक के पास बिल भेज देता है। ऐसी दशा में वैंक को बिल की परिपक्कता की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक मन्दी के काल में भी विनिमय बैंक बिजों को अपने पास जमा करके रख सकती है।

जब भी एक बिटिश विनिमय बैंक किसी निर्यात विल को खरीदती है तो वह भारत में रुपयों में शोधन करती है श्रीर बाद में लन्दन में स्टॉलग प्राप्त कर लेती है । इस प्रकार कोपों का भारत से लन्दन को हस्तान्तरण होता है । इन कोपों को भारत में वापिस लाने के लिए विनिमय बैंक रिजर्व बैंक, व्यापारियों तथा लन्दन को विप्रेष भेजने वालों को स्टॉलग वेचती है । इसके अतिरिक्त श्रायात विलों के खरीदने से भी लन्दन से भारत को कोषों का हस्तांतरण होता है, परन्तु यदि इन सब रीतियों से भी पूरे कोषों का हस्तान्तरण नहीं हो पाता है तो बैंक सोने श्रीर चाँदी का श्रायात करती है ।

(२) श्रायात व्यापार का श्रर्थ-प्रबन्ध—श्रायात व्यापार के श्रर्थ-प्रवन्ध की दो रीतियाँ हैं। यदि श्रायात व्यापारी कोई योरोपियन है, जिसकी लन्दन में एजेन्सी है तो यह एजेन्सी एक बिल लिखती है, जिसे गृह-पत्र (House Paper) कहा जाता है श्रीर इसे विनिमय बेंक की लन्दन शाखा स्वीकार करती है। माल को बेचने वाला व्यापारी बिल को लन्दन मुद्रा-बाजार में भुना कर कीमत प्राप्त कर लेता है। परिपक्कता काल तक विनिमय बैक बिल को अपने पास रखती है श्रीर तब भारतीय शाखा द्वारा निर्यातकर्ता से धन वसूल कर लेती है। इस प्रकार के सभी बिल साधारएतया २ मास की श्रवधि की परिपक्कता के होते हैं।

ग्रन्य सभी निर्यातकर्ताश्रों के लिए माल के बेचने वाला ग्रायात व्यापारी के ऊपर ६० दिन की परिपक्तता का बिल लिखता है । ये विल विनिमय बैंकों द्वारा भुनाये जाते हैं, जो इन्हें माल की प्राप्ति से पूर्व घन एकत्रित करने के लिए अपने भारतीय कार्यालयों को भेज देते हैं। कुछ दशाग्रों में निर्यात व्यापारी बेंक के साथ शोधन से पूर्व माल प्राप्त करने की भी उपयुक्त व्यवस्था कर सकता है। इसके लिए प्रसंविदा रसीद (Trust Receipt) दी जाती है ग्रौर पूरे भुगतान तक के काल के लिये व्याज दिया जाता है। साघारणतया भारत में ग्रायात विलों को फिर से भुनाने कर कार्य नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में विनिमय बैंक ग्रौर भी महत्त्वपूर्ण कार्य करती हैं। वे विदेशी निर्यात व्यापारियों को भारतीय ग्रायातकर्त्ता की साख तया ग्राधिक स्थित का समुचित ज्ञान प्रदान करती हैं।

भारतीय व्यापार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि घ्रायात घीर निर्यात दोनों ही प्रकार के बिल साधाररणतया स्टर्लिंग में लिखे जाते हैं। घ्रायात बिलों पर उनके लिखने की तिथि से लन्दन में पहुँचने की तिथि तक  $\mathfrak{t}^{\circ}_{0}$  व्याज लिया जाता है । साधाररणतया लन्दन डिस्काउण्ट बाजार की दर इससे बहुत नीची होती है। परिस्णाम यह होता है कि भारतीयों की तुलना में विदेशियों को सदा ही लाभ होता है। मुद्रा-

कोष की स्थापना के बाद अब निर्यात श्रीर श्रायात बिल कुछ दूसरी चलनों में भी लिसे जाने लगे हैं।

- (३) स्रान्तिरिक व्यापार का स्रर्थ-प्रबन्ध—यह विनिमय बेंकों का प्रधान कार्य नहीं है, परन्तु वहुत सी विनिमय बेंक भारत के झान्तिरिक व्यापार में भाग लेती हैं, विशेषकर माल के एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने तथा बन्दरगाहों पर उसके एक वित करने श्रथवा वहां से माल के बाँटने के सम्बन्ध में। भारत में विनिमय वेंकों की विशेष परिस्थिति ने उन्हें इस योग्य बना दिया है कि वे देश के भीतरी वाणिज्य में भी भारतीय बेंकों से प्रतियोगिता कर सकें। कुछ दशास्रों में तो झान्तिरिक व्यापार की वित्तीय व्यवस्था बड़े श्रंश तक विनिमय बेंकों पर निर्भर होती है। कानपुर के चमड़ा व्यापार तथा दिल्ली के सूती कपड़ा व्यापार का यही हाल है।
- (४) साधारण बैंकिंग व्यवसाय—बहुत सी विनिमय बैंक ग्रन्य प्रकार के बैंकिंग व्यवसायों में भी भाग लेती हैं। वे निक्षेपों को स्वीकार करती हैं, ऋण देती हैं, बिलों को भुनाती हैं ग्रौर ग्रिभिकत्ती का कार्य करती हैं ग्रौर इस प्रकार सभी दिशाग्रों में भारतीय बैंकों से प्रतियोगिता करती हैं। वे साधारणतया निक्षेपों पर ग्रधिक ब्याज देती हैं ग्रौर जलयान रसीदों (Shipping Documents) पर भी ऋण दे देती हैं। विगत वर्षों में विनिमय बैंकों के इन कार्यों में काफी कमी हो गई है।
- (५) बिलों में व्यवसाय—-विदेशी विनिमय बैंक श्रान्तरिक तथा विदेशी विनिमय बिलों में भी व्यवसाय करती हैं । मारवाड़ी बैंकरों के लगभग सभी बिल इन्हीं के द्वारा भुनाये जाते हैं।

## भारत में विनिमय बैंकों का महत्व-

भारत में विनिमय बैंक काफी लम्बे काल से कार्यशील हैं और इन्होंने देश में बैंकिंग के विकास तथा विदेशी व्यापार की उन्नति में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। सन् १६५० में ऐसी बैंकों की संख्या १५ थी और इनके पास १५७५ करोड़ रुपये की पूँजी तथा सुरक्षित कोष थे, इनके निक्षेप १६२,४७ करोड़ रुपये के थे और इनके नकद कोष २३,६७ करोड़ रुपये के थे। देश के निर्यात व्यापार के ७०% और आयात व्यापार के ६०% का इन्हों के द्वारा अर्थ-प्रबन्ध किया जाता है। व्यापार बैंकिंग के क्षेत्रों में भी ये सम्मिलित पूँजी बैंकों की भारी प्रतियोगी हैं। भारतीय मुद्रा वाजार में विनिमय बैंकों का यह महत्त्वपूर्ण स्थान होने के अनेक कारण हैं:—

- (१) ये वेंक काफी समय से इस व्यवसाय को कर रही हैं ग्रौर इन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली है।
- (२) इन बैंकों के पास वित्तीय साधनों की प्रचुरता है ग्रीर क्योंकि इन्हें लन्दन मुद्रा-बाजार की सेवाग्रों की सुविधा प्राप्त है, जिससे इनकी शक्ति ग्रीर भी बड़ गई है।

- (३) इन बैंकों ने निपुरा तथा अनुभवी कर्मचारियों को रखकर प्रबन्ध तथा कार्यवाहन की भारी कुशलता प्राप्त कर ली है।
- (४) भारत सरकार ने, इनके विदेशी संस्था होते हुए भी, इन पर कभी भी किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाये हैं। वास्तविकता यह है कि बहुत बार तो परोक्ष रूप में सरकार ने इनको सहायता भी दी है।
- (५) भारत का विदेशी व्यापार ग्रधिकतर विदेशियों के हाथ में है, जो भ्रपना सभी व्यवसाय इन विदेशी संस्थाश्रों को सौंपते हैं श्रौर श्रन्य व्यापारियों को भी ऐसा ही करने का प्रोत्साहन देते हैं।

## विनिमय बैंकों के कार्यवाहन की ग्रालोचना-

भारत में कुछ ऐसी विदेशी बैंकों का रहना जिनके हाथ में विदेशी विनिमय बिल व्यवसाय का एकाधिकार हो, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक गम्भीर दोप है। इन बैंकों के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें निम्न प्रकार हैं:—

- (१) इन बैंकों की व्यवसायिक विधि इस प्रकार की रही है कि भारत के विदेशी व्यापार का अर्थ-प्रवन्ध लन्दन मुद्रा वाजार के अल्पकालीन कोषों द्वारा होता रहा है। कीन्ज ने बहुत पहले ही यह चेतावनी दी थी कि भारत की वित्तीय व्यवस्था के लिए यह भय से खाली न था, परन्तु हाल में यह स्थिति काफी वदल गई है। विनिमय बैंकों ने भारत में भी काफी निक्षेप प्राप्त कर लिए हैं और अब इस धन से वे अपना कार्यं चलाती हैं।
- (२) भारतीय विदेशी व्यापार में भारतीयों का हिस्सा केवल १५:२०% है। इसका प्रमुख कारण विनिमय बैंकों की भाग्त विरोधी नीति बताया जाता है। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति के सम्मुख बहुत सी व्यापार संस्थाओं ने बताया था कि विनिमय बेंक विदेशियों को भारतीय व्यापार-गृहों की आर्थिक स्थिति का भूठा और असन्तोपजनक हवाला देती हैं, वे भारतीय निर्यात व्यापारियों को D. A. विलों की वे सुविधाएँ नहीं देती हैं जो योरोपियनों को दी जाती हैं और साखपत्र खोलने से पहले भारतीय आयात फर्मों को माल की कीमत का १५ से लेकर २०% तक जमा करने पर बाध्य करती हैं।
- (३) विनिमय बेंक भारतीय बीमा कम्पिनयों, जलयान कम्पिनयों तथा दलालों के साथ भेद-भाव करती हैं। ये बहुघा यह अनुरोध करती हैं कि उनके भारतीय ग्राहक सभी कार्यों के लिये विदेशी सेवाओं का उपयोग करें।
- (४) इन वैंकों में ऊपर की श्रेणी के सभी कर्मचारी विदेशी होते हैं और इन्होंने भारतवासियों के शिक्षण के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया है।

- (५) पूँजों को प्रचुरता तथा लन्दन मुद्रा-बाजार के निकट सम्बन्धों के कारण भारतीय मौद्रिक ग्रधिकारी इन पर ठीक-ठीक नियन्त्रण रखने में ग्रस-फल रहते हैं। इन बैंकों की भारत-विरोधी नीति राष्ट्रीय हितों को भारी हानि पहुँचा सकती है।
- (६) विनिमय बैंक भारतीय व्यापार बैंकों की भारी प्रतियोगी हैं। वे भ्रषिक ब्याज देकर निक्षेपों को भ्राकर्षित करती हैं श्रौर कुछ समय पहले तक तो कोई ऐसा नियम भी नथा जिसके द्वारा इन बैंकों के भारतीय निक्षेपदाताश्रों के हितों की रक्षा हो सकती। भारतीय व्यवसायी इनकी नीति को भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं।
- (७) विनिमय बैंक संघ के नियमों ग्रीर उसकी कार्यवाहियों को ग्रुप्त रखा जाता है। भारतीय व्यापारियों से न तो इस सम्बन्ध में सलाह ली जाती है ग्रीर न उन्हें सूचना दी जाती है।
- ( प ) विनिमय समभौतों के पूरा होने में देर होने पर अनुचित रूप में ऊँचा हर्जाना लिया जाता है।
- ( ६ ) दिन प्रति दिन के प्रत्येक व्यवसाय में भारतीय व्यापारियों के साथ भेद-भाव किया जाता है।
- (१०) यह कहा जाता है कि इन बैंकों ने भारतीय पूँजी को विदेशी ग्रौद्यो-गिक व्यवसायों तथा परम प्रतिभूतियों की ग्रोर हस्तान्तरित करने का बराबर प्रयत्न किया है।
- (११) ये बैंक उन देशों की मुद्राग्नों को बदलने के लिये बहुत ग्रधिक कमी-शन लेती हैं जिनकी बैंकों की शाखाएँ भारत में नहीं हैं ग्रौर ग्रन्य विदेशी बैंकों को भारत में ग्राने से रोकती हैं।
- (१२) इन बैंकों पर यह आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने सदा ही भार-तीय हितों और दृष्टिकोगा का विरोध किया है और विदेशों में भारत विरोधी वातावरगा उत्पन्न किया है।

## दोषों को दूर करने के उपाय-

विनिमय बैंकों के उपरोक्त दोषों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इनके कार्यों पर नियन्त्रण रखने की भारी ग्रावश्यकता है। सन् १६३१ की केन्द्रीय वैंकिंग जाँच सिमिति ने यह सिफारिश की थी कि विनिमय बैंकों को ग्रनुज्ञापन लेने के लिए बाध्य किया जाय, जो एक सीमित काल के लिए हों ग्रीर ऐसी शर्तों पर फिर से दिये जायें कि भारतीय व्यापारियों की कठिनाइयाँ दूर हो सकें ग्रीर ये बैंक भारत में ग्रपनी लेन-देन का वार्षिक विवरण देती रहें।

सन् १६४६ के विधान को ग्रन्य बैंकों की भाँति विनिमय बैंकों पर भी लागू किया गया है। इनके लिए भी रिजर्व बैंक से अनुज्ञापन प्राप्त करना ग्रावश्यक होता है श्रौर

विभिन्न प्रकार के विवरण तथा रिपोर्टें भेजना ग्रनिवार्य है । भारत के बाहर स्थापित होने वाली सभी वैकिंग कम्पनियों को कम से कम १५ लाख रुपये की परिवत्त पूँजी रखनी पड़ती है और यदि उनकी शाखाएँ कलकत्ते अथवा वम्बई में हैं तो २० लाख हमए की परिदत्त पूँजी स्रावश्यक है तथा यह राशि नकदी तथा स्वीकृत प्रतिसृतियों के रूप में रिजर्व बैंक में जमा करनी पड़ती है। सन् १९४९ के विधान की विस्तृत व्यवस्थाएँ एक पीछे के म्राच्याय में दी जा चुकी हैं। विनिमय वैंकों को म्रापनी समय तथा मांग देनों का का ७५% ऐसे म्रादेशों में रखना पड़ता है जो भारत में स्थित हों। इन वैघानिक व्यवस्थाओं से काफी लाभ की स्राशा है।

भारत में सबसे बड़ी म्रावश्यवता इस बात की है कि भारतीय विदेशी विनिमय बैंक सोली जायें। स्रारम्भ में शायद यह उपयुक्त होगा कि स्रच्छी भारतीय वैंक विदेशों सेसम्बन्घ कायम करें, जिससे कि विदेशों में शाखाएँ खोलने का भारी व्यय वच जाय । श्रभी तक भारतीय बैंकों ने विदेशी विनिमय व्यवसाय से झलग ही रहने का प्रयन्न किया है। इससे भारत को श्राय की हानि तो हुई है, परन्तु साथ ही उसे विदेशी व्यापार में कठिनाइयाँ भी बहुत सहनी पड़ती हैं। यह एक ग्राशाजनक बात है कि हाल में भारतीय बैंकों ने इस दिशा में प्रयत्न किया है। सन् १६५१ के ग्रन्त में भार-तीय बैकों की विदेशों में ११ शाखाएँ तथा १६ कार्यालय थे। अप्रतेल सन् १६५२ में इन विदेशो कार्यालयों की कुल देन १०१ करोड़ रुपया थी। सन् १९५४ में इनकी संस्या तो १६ ही रही थी, परन्तु इनकी कुल देन १७८ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थीं। सन् १६**५६**-५७ में इनकी संख्या १७ थी ग्रौर कुल जमा १८६ ३४ करोड़ ष्पया । नए विधान के अनुसार अब विदेशी विनिमय बैंक को अपनी लेन का ७५<mark>०</mark>० म्रादेयों के रूप में भारत में रखना पड़ता है।

## विनिमय बैंकों की वर्तमान स्थिति—

सन् १९५६ में भारत में कुल १५ विनिमय बैंक थीं, जिनको ६३ शाखाएँ देश भर में फैली हुई थीं। इन बैंकों का प्रारम्भन विदेशों में हुन्रा है। भूतकाल में इन पर भारतीय बैंकिंग संविधान की व्यवस्थायें लागू नहीं होती थीं, परन्तु नवीन वैंकिंग नियमों में रिजर्व बैंक को इनके कार्यों पर नियन्त्रगा रखने का ग्रधिकार दिया गया है। इन बैंकों की ग्रधिकांश शाखाएँ बड़े-बड़े नगरों में स्थित हैं। इस समय ६३ शासाम्रों में से २० कलकत्ते, १५ बम्बई, १० दिल्ली और १० मद्रास में है। विनिमय वैंक भारत में निक्षे पों को जमा करने ग्रौर देश में ग्रान्तरिक व्यापार की तित्त व्यवस्था का भी काम करती हैं। मार्च सन् १९५६ में इनकी जमा देन १६० करोड़ रुप्या थी, जबिक उसी समय भारत में इनके ऋगों श्रीर श्रिग्रमों की कुल राशि १६२ करोड़ रुपया थी। ग्रगले वर्ष ग्रर्थात् सन् १६५६-५७ में इनकी कुल जमा घट कर १८७ करोड़ रुपया रह गई थी, जो सन् १९५७-५८ में बढ़कर २०४ करोड़ रुपये तक पहुंच गई, यद्यपि इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। निम्न तालिका इनकी प्रगति की स्थिति दिखाती है ----

## भारत में विदेशी विनिमय बैंकों की स्थिति

(करोड़ रुपयों में)

তা	बेंकों की संख्या	कुल जमा	नकदी हाथ में	नकदी बेंकों में	सरकारी हुन्डियों में विनियोग	प्रन्य विनियोग	ऋएा तथा भ्रप्रिम	बिलों का श्रपहरसा	गुद्ध लाभ
१६५२	१५	१७६"५०	२•५६	१४,५७	४३.३४	8.08	१३१.००	\$8.38	8.20
१६५३	१६	१६५ -८४	२•२५	१२•३४	४४.६७	8.03	११०.७१	२० ४४	3€"}
१९५४	१६	३४.५०%	२•२२	१३•८३	४६.३६	१.स४	83.828	२५.७५	8.54
१९५५	१७	१६४.८६	३•२२	१४•५८	४६.०१	३.६६	'१३६"०७	३१ प्र	१•६८
१९५६	१७	१८७.३४	२•द१	१४.०२	३६•२७	२•८७	१६१.५२	४० १४	१•६६
१६५७	<u> </u>	२०४"१४	२•६२	१७•५३	३५°६१	४:३६	१४३.८७	४०.८५	4.65

सही स्थिति का पता लगाने के लिए यह जनना भ्रावश्यक है कि स्वतन्त्रता के पश्चात भी विदेशी विनिमय बैंकों के व्यवसाय में शिथिलता का कोई चिन्ह हिष्टिगोचर नहीं होता है, यद्यपि ये सभी बैंक निदेशी संस्थाएँ हैं। ऐसी वैंकों की संख्या लगभग स्थिर रही है। सन् १६२० में यह १५ थीं और अब १७ हैं। इनकी कुल जमासन १६२० में केवल ७५ करोड़ रुपया थी, जो सन् १९४० में ५५ करोड़ रुपया हो गई थी । किन्तु युद्धकाल में इसमें तेजी के साथ वृद्धि हुई श्रीर सन् १६४८ में यह १६० करोड रुपये तक पहुँच गई। तत्पश्चात् यह बरावर बढ़ रही है श्रीर सन् १९५७ में २०४ करोड रुपये तक आ गई थी । ऋगा, अग्रिम तथा बिल अपहरणा की राशि पहले घटती हुई दिखाई पड़ती है। सन् १९४० में यह २१० करोड़ रुपया थी, जो युद्धकाल में घटते-घटते सन् १९४० में ११४ करोड़ रुपये पर ग्रा गई थी। उसके परचात् यह फिर बरावर बढ़ती गई है भीर सन् १९५६ में लगभग २०२ करोड़ रुपया थी भीर सन १९५७ में १९४ करोड़ रुपया । विनिमय वैंकों के कार्यालयों की संख्या सन् १९५३ से लगभग बराबर सी रही है। उपरोक्त वर्ष में यह ६८ थी, जो सन् १९५४ में घट कर ६६ रह गई थी। तत्पश्चात् सन् १९५८ तक यह ६७ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कुछ वर्षों से इन बैंकों ने भी अपने आदेयों की तरलता को बढ़ाने का प्रयत्न किया है। इनकी याचना राशि की मात्रा का निरन्तर विस्तार होता हुआ प्रतीत होता है।

<sup>\*</sup>The following are the foreign exchange banks in India:—
National Bank of India; Llyods Bank; Chartered Bank
of India, China and Australia; Grindlays Bank; Hongkong and
(Cont. on next page)

देश में भारतीय विनिमय वैंक क्यों नहीं हैं ?—

यह प्रश्न बड़ा ही स्वाभाविक है कि भारतीय विनिमय वैक स्थापित क्यों नहीं हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि म्रान्तरिक व्यापार के वित्त प्रवन्धन में विदेशी व्यापार की तुलना में लाभ म्रधिक रहता है। यही कारए। है कि भारतीय सिम्मितित पूँजी वैंक म्रपने कोपों की सीमितता के कारए। उसी पर सन्तोप कर लेती हैं। विदेशी व्यापार सम्बन्धी विलों में रुपया तीन मास से भी म्रधिक काल के लिए फँम जाना है, जो इन बैंकों के लिए काफी म्रसुविधाजनक हो जाता है, परन्तु इस सम्बन्ध में यह याद रखना मावस्थक है कि भारतीय सिम्मिलित पूँजी वैंक म्रपने फालतू धन को या तो सरकारी प्रतिभूतियों में लगा देती हैं या उन्हें रिजर्व वैंक में जमा कर देती हैं। यदि यह धन इसके विपरीत विदेशी व्यापार के वित्त प्रवन्ध में लगाया जाय तो लाभ म्रधिक हो सकता है।

इसी प्रकार बहुत बार यह भी कहा जाता है कि भारत में विदेशी विनिमय व्यवसाय के संचालन के लिए पर्याप्त निपुरा तथा योग्य कर्मचारियों की कभी है। यह तर्क भी बहुत सारयुक्त प्रतीत नहीं होता है। इम्पीरियल बैंक के गवर्नर ने केन्द्रीय बैंकिंग जाँच सिमिति के समक्ष अपने बयान में कहा था कि आवश्यक कर्मचारियों को तो कभी भी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है।

विगत वर्षों में भारतीय सम्मिलित पूँजी बैंकों ने ग्रियिक ग्रंश तक विदेशी विनिमय व्यवसाय में हिस्सा लेने की चेटा की है। ग्रियिक बैंकों ने विदेशों में शाखाएँ खोलने ग्रथवा ग्रियिक की नियुक्त करने का प्रयत्न किया है। सन् १६५४ में भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाग्रों की संख्या १०७ तक पहुँच गई थी।

## भारतीय वैंकों का विदेशों में व्यवसाय-

भारतीय सम्मिलित पूँजी बैंकों द्वारा विदेशी विनिमय व्यवसाय आरम्भ करने में मार्ग में प्रमुख रुकावट विदेशों में शाखाएँ खोलने और उन्हें सफलतापूर्वक चलाने की किठनाई रही है। इस सम्बन्ध में अनेक राजनीतिक और चलन सम्बन्धी किठनाइयाँ पैदा होती हैं। विदेशी शाखा तभी कोपों को आकर्षित कर सकती हैं जबिक उसे बहु-मात्रा में पूँजी, अनुभव और सम्मान के लाभ प्राप्त हों। पाकिस्तान के निर्माण के परचात् बहुत सी भारतीय बैंकों की वे शाखाएँ जो उन क्षेत्रों में थीं जो पाकिस्तान में सम्मिलित किए गए हैं, विदेशी शाखाएँ बन गई हैं। सन् १६४६ में अनुस्चित वैंकों की विदेशी शाखाओं की संख्या ६२६ थी, जो सन् १६४४ में केवल १०७ रह गई थी।

Shanghai Banking Corporation; Mercantile Bank of India; Eastern Bank; National City Bank of New York; Bank of Tokyo; British Bank of Middle East; Netherlands Trading Society; American Express Co.; Comptoir National D'Escompte de Paris and Bank of China,

गैर अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं में भी कमी हुई है। इस समय कुल विदेशी शाखाओं में से ६६ अकेले पाकिस्तान में हैं। इनके अतिरिक्त बर्मा में ६, मलाया में १२, ब्रिटेन में ५ और ब्रिटिश पूर्वी अफीका में ७ शाखाएँ हैं। विदेशी शाखाएँ अधिकतर पाँच बड़ी-बड़ी बेंकों, अर्थात् बैंक ऑफ बड़ौदा, दी इण्डियन ओवरसीज बैंक (The Indian Overseas Bank), दी अपर कलकत्ता बैंक, दी बैंक ऑफ इण्डिया और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की ही हैं।

भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं को देखने से पता चलता है कि इन शाखाओं में कुल देन के अनुपात में भारतीय शाखाओं की तुलना में अधिक बड़े नकद कीष रखे जाते हैं। इसका प्रमुख कारण शायद यह है कि एक अग्रेर तो सम्मान प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है और दूसरी ओर आरम्भ में सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। विभाजन के पश्चात् देश की वैंकों ने विदेशी ब्यवसाय बढ़ाने का प्रयत्न किया है, परन्तु अभी विदेशी विनिमय ब्यवसाय में वे बहुत पीछे हैं।

#### नये विधान में विनिमय बैंकों का नियन्त्ररा-

सन् १६४६ के विधान के लागू हो जाने के पश्चात् विनिमय बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण, काफी हद तक स्थापित हो चुका है। इस नियम में भारतीय हितों की रक्षा के लिए इन बैंकों पर निम्न प्रतिबन्ध लगाये गये हैं:—

- (१) जिन बैंकों का प्रारम्भन भारत से बाहर हुग्रा है उन्हें कम से कम १५ लाख रुपया रिजर्व बैंक में जमा के रूप में रखना पड़ता है ग्रौर यदि उनकी शास्ताएँ कलकत्ता ग्रथवा बम्बई में भी हैं तो कम से कम २० लाख रुपया रखना होता है।
- (२) यदि ऐसी बैंक भारत में व्यवसाय बन्द करती है तो रिजर्व बैंक में जमा की राशि पर बैंक के लेनदारों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जायगी।
- (३) प्रत्येक तृतीय मास के अन्तिम दिन पर किसी भी ऐसी बैंक के भारत में स्थित आदेय उसकी माँग तथा समय देन के मूल्य के ७५% से कम नहीं होने चाहिए ।
- (४) प्रत्येक वर्षं के अन्त में इन बैंकों को भारतीय व्यवसाय का ग्रपना-ग्रपना चिट्ठा ग्रौर लाभ-हानि लेखा बनाना पड़ता है। इस चिट्ठे का प्रकाशन ग्रौर समु-चित ग्रंकेक्षरण होता है।

#### उपसंहार---

विनिमय बैंकों का मुख्य व्यवसाय भारत के विदेशी व्यापार का वित्तीय प्रबन्ध है। देश की सभी विदेशी बैक विदेशी संस्थायें हैं। वे विदेशी चलनों में बिलों को खरीदती हैं ग्रौर जहाजी रसीदों तथा श्रन्य पत्रों की श्राड़ पर ऋग् देती हैं। ये बैंक देश के श्रान्तरिक व्यापार में भी हाथ वैंटाती हैं, विशेषतया निर्यात श्रौर श्रायात के मालों को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने के सम्बन्ध में। विगत वर्षों में इन वैंकों ने

देश में अपने व्यवसाय के विस्तार का वरावर प्रयत्न किया है। इन्होंने सेविंग और बालू खातों पर निक्षेप स्वीकार करना भी आरम्भ कर दिया है और आन्तरिक व्यापार के अर्थ-प्रवन्ध में अधिक दिलचसी दिखाई है। सन् १६४६ के वैंकिंग कम्पनीज अधिनियम के अनुसार इन वैंकों को अपनी देन का ७५% आदेयों के रूप में भारत में रखना आवश्यक है, अतः इनके द्वारा देश के आन्तरिक व्यवसाय में अधिक हिस्सा लेने की प्रवृत्ति बरावर बढ़ रही है। भारत में ऐसी वक्षों का प्रारम्भ मन् १५४२ ने हुआ है। यही विदेशी व्यापार और वास्तिज्य की महत्त्वपूर्ण कड़ियाँ हैं।

#### **QUESTIONS**

1. What part do Exchange Banks paly in financing the external trade of India? What charges have been levelled against them and how does the Indian Government try to control their activities? (Agra, B. Com., 1956)

2. Discuss the main functions performed by the Exchange Banks in India and point out how far their defects have been remedied after Independence. (Raj., B. Com., 1956)

3. The exchange banks as a separate limb of the Indian banking system have not played their part in the best interests of Indian trade. Discuss. (Bombay, B. Com., 1950)

- 4. Examine the various complaints against the working of the foreign exchange banks in India. What has the Government of free India done to remove these complaints? Discuss.
  - (Raj., B. Com., 1954)
- 5. Describe the operations of the Exchange Banks in connection with the financing of India's foreign trade. What objections have been raised against them and how far have they been removed by the Indian Banking Companies Act, 1949?

(Agra, B. Com., 1956 Supp.)

6. Write a note on:

Exchange Banks

(Agra, B. Com., 1957 Supp., 1956 Supp. and 1954)

Importance of Exchange Banks in India.

(Raj., B. Com., 1957)

D/A and D/P Bills. (Agra, B. Com., 1957, 1955 Supp., 1954)

# श्रध्याय ३६ भारत में देशी बैंकर

(Indigenous Bankers in India)

#### परिभाषा--

भारतीय मुद्रा बाजार में देशी बैंकरों तथा महाजनों का भारी महत्त्व है। भारतीय केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति के अनुसार देशी बैंकर प्रथवा बैंक वह व्यक्ति या निजी फर्म है जो निक्षे पों को स्वीकार करने, हुण्डियों में व्यवसाय करने ग्रथवा ऋण देने का कार्य करे। देश के विभिन्न भागों में इनके अलग-अलग नाम हैं। बङ्गाल में इन्हें महाजन कहा जाता है, उत्तर-प्रदेश में साहुकार, पंजाब में खत्री, बम्बई में सर्राफ, मारवाड़ में सेठ, मद्रास में चेट्टी, इत्यादि, परन्तु एक देशी बैंकर तथा साहूकार (Money lender) में यह महत्त्वपूर्ण अन्तर होता है कि बैंकर निक्षे पों को स्वीकार करता है, परन्तु साहूकार ऐसा नहीं करता है। इनकी बैंकिंग सुविधाएँ देश को बड़े लम्बे काल से प्राप्त हैं और सभी प्रकार के परिवर्तन हो जाने पर भी, इस समय भी देश के आर्थिक जीवन में इनका भारी महत्त्व है। छोटे-छोटे नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों और देश के आन्तरिक व्यापार तथा कृषि वित्त में ग्रभी तक ग्राधुनिक बैंक इनके महत्त्व को कम नहीं कर पाई हैं।

देशी बैंक ग्रौर ग्राधुनिक बैंकों में ग्रन्तर—

देशी बैंक आधुनिक बैंकों से अनेक प्रकार भिन्न होती हैं:--

- (१) ग्राधुनिक बैंकों की तुलना में देशी बैंक निक्षे पों द्वारा ग्रपनी पूँजी का एक बड़ा ही तुच्छ भाग प्राप्त करती हैं ग्रौर ग्रंश पूँजी द्वारा तो यह कुछ भी वन एक-त्रित नहीं करती हैं।
- (२) देशी वैंकिंग प्रशाली में धनादेशों का चलन नहीं है, सभी भुगतान नकदी में किये जाते हैं।
- (३) देशी बैंकर बैंकिंग व्यवसाय के साथ-साथ व्यापार म्रादि म्रन्य व्यवसाय भी करते हैं।
- (४) देशी बैंकर अचल सम्पत्ति की आड़ पर भी ऋगा दे-देते हैं और इनके ऋगा दीर्घकालीन भी होते हैं, यद्यपि इनकी ब्याज की दरें आधुनिक बैंकों की तुलना में काफी ऊँची होती हैं।
- (५) ये बैंक व्यापार बैंकों श्रीर श्रीद्योगिक बैंकों की भाँति दीर्घकालीन तथ श्रल्पकालीन ऋगों में भेद नहीं करती हैं श्रीर दोनों प्रकार के ऋगा एक साथ देती हैं।

- (६) इन बैंकरों पर सन् १६४६ के विधान की व्यवस्थाएँ लागू नहीं होती हैं भौर इनका विदेशी व्यापार से लगभग कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है।
- (७) इनकी कार्य-विधि अलग होती है और इनका कार्य साधारस्त्रस्य प्रादे-शिक भाषाओं में होता है।

## देशी बैंकरों के कार्य-

देशी बैंकरों के कार्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ग्रर्थात् वैकिंग व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य तथा ग्रन्य प्रकार के कार्य। प्रथम प्रकार के कार्य निम्न प्रकार हैं:—

- (१) निक्षोपों का स्वीकार करना—ये वैंकर माँग पर तुरन्त शोधनीय तिक्षेपों प्रथवा ऐसी निक्षोपों को स्वीकार करते हैं जो एक निश्चित काल पीछे शोधनीय हों। साधारणतया इनकी ब्याज की दर ग्राधुनिक वैंकों की निक्षेप दर में ऊँची रहती है, परन्तु बम्बई की कुछ संस्थाग्रों को छोड़कर ये चैंक द्वारा शोधन नहीं करती हैं।
- (२) ऋरगों का देना—यह देशी वेंकरों श्रीर साहूकारों का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस सम्बन्ध में ये संस्थायें लगभग सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार
  करती हैं, जिनमें ऋरग लेने वाले की व्यक्तिगत जमानत भी सम्मिलित है। श्रञ्छी
  प्रतिभूतियों पर ब्याज की दर ६% से लेकर १६% तक होती है, परन्तु ग्रग्याप्त
  प्रतिभूतियों ग्रथवा किश्तों पर चुकाये जाने वाले ऋगों पर ब्याज की दर कभी-कभी
  ४४% तक होती है। ये संस्थायें कृषि, उद्योग तथा व्यापार का काम करती हैं।
  साहूकार भूमि, फसल, जेवरात श्रादि की प्रतिभूतियों पर ऋगा देने हैं। कुछ ऋगा
  वस्तुश्रों ग्रथवा माल के रूप में भी दिये जाते हैं ग्रीर वसूल भी माल में ही किये जाते
  हैं। इसी प्रकार कारीगर के इस वायदे पर कि वे तैयार माल को उन्हीं के हाथ वेचेंगे,
  ऋगा दे दिए जाते हैं। कभी-कभी त्ये ऋगा कच्चे मालों और ग्रन्य ग्रावश्यक सामानों
  के रूप में भी दिये जाते हैं। वड़े-बड़े उद्योगों के पास निक्षेप जमा करके उनका ग्रर्थप्रवन्ध किया जाता है, परन्तु गोदामों में रखे हुए माल की ग्राड़ पर देशी वेंकर ऋगा
  नहीं देते हैं।
- (३) हुण्डियों का व्यवसाय—देशी वैंकर विभिन्न प्रकार की हुण्डियों की निकासी, उनके क्रय-विक्रय तथा उनके भूनाने का कार्य करते हैं।

देशी बैंकरों तथा साहूकारों के गैर वैंकिंग व्यवसायों में व्यापार तथा दुकान-दारी का सबसे ग्रधिक महत्त्व है । ग्राघुनिक बैंकों की प्रतियोगिता के कारण बैंकिंग व्यवसाय में जो हानि हुई है उसकी कमी इन्होंने गैर-वैंकिंग व्यवसायों को बढ़ा कर पूरी की है। इसके ग्रतिरिक्त यह सट्टा व्यवसाय में भाग लेते हैं ग्रौर व्यापार कर्मों के ग्रभि-कर्त्ता के रूप में कार्य करते हैं। व्यापार वैंकों के साथ भो इनका सम्बन्ध रहता है। वैसे तो ये संस्थाएं साधारणतया ग्रपनी तथा ग्रपने कृटुम्ब के सदस्यों ग्रौर रिश्नेदारों की पूँजो से काम चलाती हैं परन्तु आवश्यकता पड़ने पर व्यापार बैकों से ऋण भी लेती हैं और कभी-कभी अपने फालतू कोषों को उनमें जमा भी करती हैं, परन्तु आधुनिक वैंक केवल ऐसे साहूकारों तथा देशी बैंकरों को ऋण देती हैं जो उनकी स्वीकृत सूची पर होते हैं। ऐसी ही संस्थाओं को अग्रिम तथा डिस्काउन्ट सुविधाएँ भी दी जाती हैं। इनकी हुन्डियाँ व्यापार बैंकों द्वारा भुनाई जाती हैं और स्टेट बैंक तथा हाल में रिजर्व बैंक उनकी हुन्डियों को फिर से भुनाने का भी कार्य करती हैं। आधुनिक बैंक इन्हें विश्रेष (Remittance) सुविधाएँ भी प्रदान करती हैं। इनके दोष—

इस प्रगाली के दोष कई प्रकार के हैं:--

- (१) ये संस्थाएँ वैकिंग व्यवसाय के साथ साथ श्रीर भी श्रनेक प्रकार के व्यवसाय करती हैं, जो बैंक के रूप में इनकी उपयोगिता को कम कर देते हैं श्रीर विशेष समस्याएँ उत्पन्न करते हैं।
  - (२) इनके ब्याज की दरें बहुत ऊँची होती हैं।
- (३) इनके पास कोषों की कमी है, क्योंकि इनका निक्षेप व्यवसाय बहुत ही सीमित है। इसी कारगा हुन्डियों का व्यवसाय भी ये कम अंश तक ही कर पाते हैं।
- (४) इनकी कार्य-विधियों में भारी भिन्नता है स्त्रीर ये साधारणतया पर-म्परागत स्त्राधारों पर काम करते हैं। इसके कारण इनके निरीक्षण स्त्रीर स्रकेक्षण का कार्य बहुत कठिन है।
- ( ५ ) ये समुचित बैंकिंग सिद्धान्तों पर कार्यं नहीं करते हैं श्रीर बहुघा अप-र्याप्त प्रतिभृतियों पर ऋगा देकर जोखिम के श्रंश को बढ़ाते हैं।
- (६) इनमें पारस्परिक सहयोग का ग्रभाव है, ग्राधुनिक बैंकों के साथ भी इनकी प्रतियोगिता चलती ग्रा रही है।
  - (७) ये भ्रपने लेखों भौर विवरगा-पत्रों को प्रकाशित नहीं करते हैं।
- ( द ) ग्रन्त में, साहूकारों की कार्य-विधि साधारएतया घोलेबाजी श्रौर श्रनुचित व्यवहारों से भरी रहती है। श्रनेक प्रकार की कटौतियाँ, ऋएा की मात्रा को बढ़ाकर लिखना, रसीद न देना श्रादि इनके भारी दोष हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रपने ऋएा को ऋएा से मुक्त होने का ग्रवसर ही कम देते हैं।

उपरोक्त दोषों के कारण हाल के वर्षों में इन्हें व्यवसाय की काफी हानि हुई है। ग्राधुनिक बेंकों की निरन्तर प्रतियोगिता ने भी इन्हें गैर-बेंकिंग व्यवसाय को ग्राधिक ग्रंग तक ग्रहण करने पर बाध्य किया है। साथ ही, रूढ़िवादी प्रथाग्रों ने भी इनके व्यवसाय को काफी चौपट किया है।

स्घार के सुभाव-

सुघार की तीन दिशाओं में भारी श्रावश्यकता है :— (१) कार्य-विघि में

सुधार, (२) आर्थिक स्थिति में सुधार और (३) अनुचित व्यवहारों का अन्त । लगभग सभी बैंकिंग जाँच समितियों ने यह स्वीकार किया है कि इन संस्थाओं की सेवाएँ काफी महत्त्वपूर्ण हैं और इनका अन्त कर देना उचित न होगा, परन्तु इनके कार्यं-बाहन में सुधार की भारी आवश्यकता है। सुधार के मुक्ताव निम्न प्रकार हैं:—

- (१) ऐसी संस्थाओं के सट्टा और व्यानार व्यवसायों पर प्रतिवन्य लगाकर उनका सम्बन्ध रिजर्व वैंक से स्थापित किया जाय, जिससे कि उन क्षेत्रों को भी समुचित वैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध हो जाएँ जहाँ उनका स्रभाव है। इस सम्बन्ध में पूँजी, निक्षेत्र, कार्यवाहन स्रादि के सम्बन्ध में उपयुक्त नियम बना कर इन्हें श्रिप्रम, विश्रेप तथा पुन-स्रपहरण (Rediscount) की सुविधाएँ दी जायँ।
- (२) ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि व्यापार वैंक इनकी हुन्डियों का स्वतन्त्रतापूर्वक अपहरण करती रहें।
- (३) स्टेट बैंक तथा रिजर्व बैंक द्वारा समुचित वार्तों पर इन्हें वही विश्रेष सुविधाएँ दी जायें जो श्रन्य बैंकों को प्राप्त हैं।
- (४) कार्य-विधि में भ्रावश्यक सुधार करके इन्हें भ्राधुनिक भ्राधार पर संग-ठित किया जाए भ्रौर इनके भ्रंकेक्षण तथा नियन्त्रण की भी समुचित व्यवस्था की जाय।
- (५) ग्रनुज्ञापित बैंकों की स्थापना, विलय तथा देशी बैंकरों के संघ बना कर इनकी कुशलता बढ़ाई जाय ग्रौर पारस्परिक डाह को समाप्त किया जाय।
- (६) बिल व्यवसाय को इन बैंकों का महत्त्वपूर्ण कार्य समक्ता जाय और इन्हें स्रसीमित उत्तरदायित्त्व स्राधार पर संगठित किया जाय ।
- (७) साहूकारों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा इम प्रकार विधान बनामें जायँ कि उनके अनुचित व्यवहारों का अन्त हो और व्याज की दरों में कमी हो । छोटे नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी साख का विकास इस सम्बन्ध में लाभदायक हो सकता है। विभिन्न राज्य सरकारों ने ऋणी वर्गों की रक्षा के लिए जो नियम बनाए हैं उनका कार्य-वाहन सन्तोपजनक नहीं है। यह कमी दूर होनी चाहिए। साहुकारों के हिसाब-किताब की जाँच की भारी आवश्यकता है, जिससे कि उनके अनुचित व्यवहार कम हो जायँ।

## देशी बैंकर श्रौर रिजर्व बैंक-

देशी बैंकर ग्रामीए। क्षेत्रों की लगभग समस्त मौद्रिक ग्रावरयकता ग्रें की पूर्ति करते हैं ग्रौर नगर क्षेत्रों में भी उनका काफी महत्त्व है। इस कारए। यह ग्रावरयक है कि उनका ग्राधुनिक बैंकिंग प्रणाली से समुचित सम्बन्ध रहे। इस समय रिजर्व वैंक

का इन पर लगभग कुछ भी प्रभाव नहीं है ग्रीर उसकी किसी भी नीति का इन पर ग्रसर नहीं पड़ता है। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति की सिफारिशों के ग्राघार पर सन् १६३७ में रिजर्व बैंक ने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके ग्रनुसार कुछ निश्चित शर्तों पर देशी बैंकर रिजर्व बैंक की स्वीकृत सूची में सम्मिलित किये जा सकते हैं। ये शर्तें निम्न प्रकार हैं:—

- (१) केवल ऐसे देशी बैंकरों को रिजर्व बैंक की सूची में सिम्मिलित किया जा सकता है जो कम से कम दो लाख रुपये से ब्यवसाय करते हों ग्रीर ५ वर्ष में उसे ५ लाख रुपये तक बढ़ाने को तैयार हों।
- (२) ऐसी बैंकों को सभी प्रकार के गैर-बैंकिंग व्यवसाय बन्द करने होंगे।
- (३) ऐसे बैंकर श्रपने लेखों को एक निश्चित रूप में रखें, उनका ग्रंकेक्षण करायें ग्रीर रिजर्व बैंक को निरीक्षण का ग्रधिकार दें।
- (४) ये रिजर्व बैंक को समय-समय पर ग्रावश्यक विवरण भेजते रहें ग्रौर ग्रपने विवरण-पत्रों को प्रकाशित करें।
- (५) जो देशी बैंकर उपरोक्त व्यवस्थाओं के अन्तर्गत रिजर्व बैंक से सुविघाएँ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं वे भी अपने संघ बनाकर ये सुविघाएँ प्राप्त कर सकते हैं।

बदले में रिजर्व बैंक ने देशी बैंकरों को ग्रग्रिम, विप्रेष तथा विलों के भुनाने के सम्बन्ध में वही सुविधाएँ प्रदान करने की व्यवस्था की है, जो ग्रन्य वैंकों को प्राप्त हैं, परन्तु देशी बैंकरों ने उपरोक्त सुभावों तथा शतों को उपयुक्त नहीं समभा है, जिसके कारण भारतीय बैंकिंग के देशी ग्रीर ग्राधुनिक ग्रंगों के बीच ग्रावश्यक समचय स्थापित नहीं हो पाया है। वे वल ७ संस्थाग्रों ने ही रिजर्व बैंक की सुविधाग्रों का लाभ उठाने का प्रयत्न किया है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि देशी बैंकर ग्रपने लाभदायक व्याप्तर व्यवसाय की छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उसके द्वारा एक बार फिर इस दिशा में प्रयत्न किया गया है ग्रीर समस्त ग्रामीण वित्त व्यवस्था की इस दृष्टिकोण से जाँच भी की गई है। ऐसी ग्राशा की जाती है कि भविष्य में ऐसी योजना बनाई जायगी जिसमें इन संस्थाग्रों का ग्रिक सप्रभाविक उपयोग हो सकेगा। स्मरण रहे कि सन् १९४६ का विधान देशी वैंकरों तथा साहूकारों पर लागू नहीं होता है। यदि ये संस्थाएँ ग्रपने नाम के साथ बैंक ग्रथवा बैंकर शब्द का प्रयोग नहीं करती हैं तो इस विधान के ग्रनुसार इनके कार्यों में भी कोई हस्तक्षेप रिजर्व बैंक नहीं कर सकती है।

देशी बैंकर तथा ग्राधुनिक बैंकर का दृष्टिकोगा—

कार्यों के दृष्टिकोएा से दोनों प्रकार के बैंकरों में कोई विशेष ग्रन्तर नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही बैंकिंग सम्बन्धी कार्य करते हैं, परन्तु दोनों की कार्य-विधि में भारी श्रन्तर होता है। निम्न तालिका में दोनों का भेद दिखाया गया है:—

- (१) ये बेंकर साधार एतिया श्रपनी, श्रपने परिवार की तथा श्रपने रिस्तेदारों की पूँजी से व्यवसाय करते हैं।
- (२) ये साधारएा निक्षेप ग्रथवा जमाधन स्वीकार नहीं करते हैं यद्यपि कुछ देशी बैंकर जमा भी रखते हैं।
- (३) ये घनादेशों द्वारा भुगतान नहीं करते हैं। लेन-देन साधारणतया नकदी में ही किया जाता है।
- (४) इनकी शाखायें नहीं होती हैं।
- (प्र) बैंकिंग के साथ-साथ ये ग्रन्य कारो-बार भी करते हैं, जैसे—व्यापार, उद्योग ग्रादि।
- (६) जमानतों के सम्बन्ध में इनकी नीति काफी उदार होती है । बहुत बार तो बिना जमानत के ही ऋरण दे दिये जाते हैं । जोखिम का ग्रंश ग्रधिक रहता है ग्रौर ब्याज की दर ऊँची रहती है ।
- (७) इनके कारोबार का क्षेत्र बहुघा स्था-नीय होता है श्रीर श्रधिकांश ऋण कृषकों, छोटे-छोटे उत्पादकों तथा कारीगरों को दिये जाते हैं।
- (प) अधिकांश देशी बैंकरों की पूँजी के साधन सीमित होते हैं।

- (१) ये साधाररणतया सम्मिलित पूँजी कम्पनी के रूप में होते हैं **भौर** श्रंशों को बेच कर धन प्राप्त करते हैं।
- (२) निक्षेपों का प्राप्त करना इनको महत्त्वपूर्ण कार्य होता है। इनकी पूँजी का काफी वड़ा भाग जमा घन से प्राप्त होता है।
- (३) इनमें घनादेशों का चलन होता है। सभी प्रकार की लेन देन चैकों द्वारा ही की जाती है।
- (४) इनकी शाखायें दूर-दूर तक फैली रहती हैं। भारत में शाखा वैकिंग प्रगाली ही अधिक प्रचलित है।
- (५) बैंकिंग व्यवसाय के अतिरिक्त ये अन्य कार्य नहीं करते हैं।
- (६) ये लगभग सभी ऋ एों पर समुचित जमानत लेते हैं। इससे जोखिम का ग्रंश कम हो जाता है ग्रौर व्याज की दर भी नीची रहती है।
- (७) कारोबार का क्षेत्र विस्तृत होता है। दूर-दूर तक इनका व्यवसाय फैला रहता है। इनके ग्राहकों में व्यापारी, उद्योगपति ग्रादि छोटे बड़े सभी प्रकार के लोग रहते हैं।
- (द) इनकी पूँजी के साधन देशी बैंकरों की तुलना में विशाल हैं।

देशी वैंकरों की उधार देने की रीतियाँ—

देशी बैंकरों द्वारा उधार देने की भ्रनेक रीतियाँ हैं। प्रमुख रीतियाँ निम्न प्रकार हैं:—

- (१) प्रतिज्ञा-पत्र पर ऋगा—जब ऋगी और साहूकार के बीच ब्याज की दर और ऋगा की अन्य शर्तें तय हो जाती हैं तो साहूकार ऋगा लेने वाले से एक प्रतिज्ञा-पत्र लिखा लेता है, जिसमें वह एक निश्चित अविधि के पश्चात ब्याज और मूल-धन लौटाने का वायदा करता है। इस प्रतिज्ञा-पत्र पर ऋगी के अतिरिक्त दो और जमानती हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं और शर्त यह होती है कि ऋगी द्वारा स्पया न लौटाने की दशा में वह जमानत देने वालों को लौटाना पड़ेगा। बहुत बार प्रतिज्ञा-पत्र में यह भी लिखा लिया जाता है कि समय पर स्पया न लौटाने की दशा में ऊँची दर पर ब्याज लगाया जायगा।
  - (२) रसीद अथवा टीप—इसमें प्रतिज्ञा-पत्र के स्थान पर ऋगी से केवल एक रसीद लिखवा ली जाती है, जिसमें ब्याज की दर भी लिखी रहती है।
  - (३) दस्तावेज ग्रौर तमस्सुक—ये सरकारी स्टाम्प के कागजों पर लिखे जाते हैं। ऋगी एक निश्चित ग्रविध के पश्चात् मूलधन को एक निश्चित ब्याज की दर के ग्रनुसार लौटाने का वचन देता है।
  - (४) टिकट वही—इसमें ऋगा की रकम लिख कर टिकट के ऊपर ऋगी के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। ऋगा के चुकाने की समय श्रवधि तथा ब्याज की दर लिखी नहीं जाती है। वे श्रापसी बात-चीत द्वारा मौखिक तय कर ली जाती हैं। ऐसी बही को न्यायालयों में भी स्वीकार किया जाता है।
  - (५) किश्त, बनज, ग्रथवा रेहती—इस प्रणाली में ऋण को किश्तों में चुकाने का वायदा लिया जाता है ग्रौर पहली किश्त ऋण देते समय ही काट ली जाती है।
  - (६) रूजही—यह भी एक प्रकार की किश्त प्रगाली है। ऋगी ३०) का उधार लेता है, जिसमें से २) रुपये पहली किश्त के रूप में तुरन्त काट लिए जाते हैं। बाकी २८) रुपये ऋगी को मिलते हैं, जो उन्हें १-१ रुपया करके ३० दिन में चुकाता है।
  - (७) हाथ-उधार—ऐसे उधार में किसी प्रकार की लिखा-पढ़ी नहीं की जाती है। बिना किसी लिखित पत्र के रुपया दे दिया जाता है, परन्तु कुछ दशाश्रों में उधार लेने वालों से अपथ ले ली जाती है।
    - ( $\varsigma$ ) गिरवी—इसमें ऋग के लिये सोना, चाँदी, जेवरात अथवा अन्य गेमती वस्तुओं की ग्राड़ ली जाती है। साधारणतया यह कोशिश की जाती है कि तिसूति कीमत के  $\frac{3}{3}$  श्रथवा  $\frac{3}{8}$  से श्रधिक ऋग के रूप में न दिया जाय।
      - ( ६ ) रेहन-इसे प्राध (Mortgage) भी कहते हैं। रेहन ग्रौर गिरवी में

केबल इतना अन्तर होता है कि रेहन में भूमि, मकान आदि अचल सम्पत्ति आड़ में ली बाती है और गिरवी में केवल चल सम्पत्ति ।

(१०) माल में ऋगा—िकसानों को ग्रनाज के रूप में ऋगा दिये जा सकते हैं, जो फसल तैयार हो जाने पर सवाये (१३) ग्रीर ज्यौढ़े (१३) करके लौटाये जाते हैं। कारीगरों को कच्चे माल के रूप में ऋगा दिया जाता है ग्रीर उनसे एक निश्चित कीमत पर तैयार माल ऋगादाता के हाथ वेचने का वायदा ले लिया जाता है। देशी वैंकरों के विकास के सुभाव—

भारत में देशी बैंकरों के महत्त्व को सभी ने स्वीकार किया है। देश के ग्रान्तिक व्यापार तथा कृषि वित्त व्यवस्था में ग्राज भी उनका एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। लगभग ६०% ग्रामीए। साख की पूर्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। लगभग किसी भी समिति ने इनके समाप्त करने का सुभाव नहीं दिया है, यद्यपि मभी ने इनके मुधार पर जोर दिया है। सुधार की ग्रावश्यकता तीन दिशाओं में ग्राधिक है—(2) इनकी कार्य-प्रएगाली में सुधार, (2) इनकी ग्राधिक स्थिति में सुधार ग्रौर (2) इनके ग्रमुचित कार्यों का ग्रन्त। विकास के लिए निम्न सुभाव दिये जा सकते हैं:—

- (१) इन बैंकरों को सट्टा व्यवसाय में घन लगाने से रोका जाय।
- (२) इनका रिजर्व बैंक से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहना चाहिए। यहाँ पर यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि रिजर्व बैंक को इस बात पर अनुरोध नहीं करना चाहिए कि देशी बैंकर अपने व्यापार कार्यों को छोड दें।
- (३) इनके सम्मान को बढ़ाने तथा ग्रामीए। क्षेत्रों में वैकिंग सुविधाएँ बढ़ाने के लिए इन्हें उन सभी स्थानों पर जहाँ रिजर्व बैंक ग्रौर स्टेट वैंक की शाखाएँ नहीं हैं उन संस्थाग्रों का ग्राभिकर्त्ता नियुक्त किया जाय।
- (४) उपयुक्त संशोधनों के साथ बैंकिंग विधान की व्यवस्थाएँ इन पर भी लागू होनी चाहिए।
- (५) व्यापार बैंकों द्वारा इनकी हुण्डियों को भुनाने का काम करना चाहिए ।
- (६) रिजर्व बैंक को चाहिए कि इन्हें आधुनिक रीतियों पर संगठित होने के लिए प्रेरित करे और इनके निरीक्षण तथा अंकेक्षण का भार अपने ऊपर ले।
- (७) इन बैंकरों को भी वही विप्रेष सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो गैर-म्रनु-सूचित बैंकों को प्राप्त हैं।
  - ( ८ ) इनका व्यवसाय भी अनुज्ञापित होना चाहिये ।
- ( ६ ) इन बैकरों को बिलों की दलाली के व्यवसाय का विस्तार करने का प्रोत्साहन देना चाहिये, तािक एक भ्रोर तो देश में बिल बाजार की उन्नति हो भ्रौर दूसरी भ्रोर देशी बैंकरों की भ्राधिक स्थिति में सुधार हो ।
  - (१०) छोटी-छोटी संस्थाग्रों का एकीकरण कराया जाय।
  - (११) राज्य सरकारों को इनके अनुचित व्यवहारों को रोकने के लिये नियम

बनाने चाहिए । कुछ राज्यों ने ऐसे नियम बनाये भी हैं, परन्तु उनका समुचित कार्य-रोपरा नहीं हो पाया है ।

(१२) श्रच्छे-श्रच्छे देशी बैंकरों को भी बैंकिंग संघों की सदस्यता प्राप्त करने का श्रवसर मिलना चाहिये।

#### **QUESTIONS**

- 1. Write an essay on indigenous bankers (देशी बेंकर) and their working. What improvements will you suggest to remove their defects. (Raj., B. A., 1958)
  - 2. Write a note on-Indigenous Banker.

(Agra, B. Com., 1957 Supp., and 1955 Supp.)

3. Describe the part played by the indigenous Bankers in financing agriculture and internal trade in India. Will you, in view of their various defects, recommend an outright abolition of such Bankers or suggest some measures to improve their woking?

(Raj., B. Com., 1952)

- 4. What action, if any, has been taken by the Roserve Bank of india for the control of indigenous banking in this country and with what success? What are the main defects in the way of bringing about such a control?

  (Agra, B. Com., 1950)
- 5. What is the place of the indigenous banker in Indian economy? What measures should be adopted to make him a more useful member of the society? (Raj., B. Com., 1951)
- 6. Describe the part played by indigenous bankers in financing inetrnal trade. Point out their main defects and give your suggestions to link them up with the general banking system.

(Agra, B. Com., 1950 and 1947; Bombay, B. Com., 1943)

## अध्याय ४०

# भारत में ग्राम्य वित्त

(The Rural Finance in India)

# ग्रामीए। वित्त का महत्त्व-

भारतीय किसान सम्पन्न नहीं है और साथ ही देश में कृपक वित्त काफी महेंगा है। किसान को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन तीनों ही प्रकार के ऋरोों की आवश्यकना पड़ती है। उसे बीज, खाद आदि खरीदने तथा फसल को बेचने के लिए अल्पकालीन ऋरण चाहिए, मवेशो तथा औजारों के लिए मध्यकालीन ऋरण और भूमि में स्थाई सुधार करने के लिए दीर्घकालीन ऋरण। देश की लगभग ७५% जन-संख्या कृषि पर निर्भर है और बिना कृपक उद्धार के देश में किसी भी प्रकार की उन्नति सम्भव नहीं है। यदि कृषि वित्त की कोई विचारयुक्त प्रणाली अपनाई जाय तो निस्संदेह उससे कृषि जैसे महत्त्वपूर्ण उद्योग में उत्पादन-क्यय घट जायगा और देश की जन-संख्या के अधिकांश भाग का भला होगा, परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ वास्तविक किनाइयाँ हैं। हमारे देश का किसान निर्धन और निरक्षर है। वह न तो वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं और उनके नियमों से परिचित है और न उसके पास उपयुक्त प्रतिभूति अथवा जमानत ही है। साधारणतया किसान सदा ही जमींदारों तथा साहूकारों से ऋरण लेता है, परन्तु कुछ वर्षों से ऋरण के ये स्रोत सूखते जा रहे हैं। जमींदारी उन्भूलन तथा महाजनों को समाज-विरोधी वर्ष घोषित करके उन पर जो प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं वे ऋरण के साधनों को और भी कम करते जा रहे हैं।

# ग्रामीए। वित्त के साधन ग्रीर उनके दोष-

भारतीय किसान ऋणी उत्पन्न होता है, इसी रूप में जीवन व्यतीत करता है ग्रीर अन्त में इसी दशा में मरता है। उसकी आय कम है, इसिलए वह ऋण के भार से मुक्त होने में असमर्थ रहता है। उसे ऋण अधिक ब्याज पर प्राप्त होते हैं। अधिक ब्याज देने से उसकी आय और भी घटती है और इस कारण ऋणों की आवश्यकता तथा उसका भार और भी बढ़ता जाता है। सरकार की ओर से कभी-कभी तकावी ऋण दिये जाते हैं, परन्तु ऐसे ऋण सङ्कट-काल के लिए होते हैं। साधारण परिस्थितियों में उनका लाभ प्राप्त नहीं होता है। वैसे भी यह प्रणाली लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि इन ऋणों को विशेष रीतियों से प्राप्त किया जाता है। ये निश्चित उद्देशों के लिए दिए जाते हैं और इन्हें बिना किसी रियायत के सख्ती के साथ वसूल किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम्य विक्त के अन्य साधन सहकारी संगठन, व्यापारिक वैंक, भू-प्राध

वैंक (Land Mortgage Bank) भ्रौर साहूकार हैं, परन्तु साहूकारों को छोड़कर अन्य सभी साधनों का कार्य-क्षेत्र बहुत ही सीमित है। विगत वर्षों में सहकारी समितियों तथा भू-प्राधि वैंकों ने कुछ प्रगति अवश्य की है, परन्तु जमींदारी उन्भूलन के कारण ग्राम्य-वित्त की जो कभी उत्पन्न हो गई है वह इनके इस विकास से भी पूरी नहीं हो पाई है। दूसरे महायुद्ध के काल में कृषि की उपज की कीमतों में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है, जिससे कृषक की वित्तीय अवस्था पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा है, परन्तु इससे समस्या हल नहीं हो जाती है। वर्तमान प्रवृत्ति कीमतों के बढ़ने की है, जो समस्या की गम्भी-रता को और भी बढ़ा देती है। व्यापार बैंक तो प्रत्यक्ष रूप में ग्राम्य वित्त के सम्बन्ध में कुछ भी कार्य नहीं करती हैं। उनका कार्य तो कृषि उपज की बिक्री करने वाले व्यापारियों को अग्रिम प्रदान करने तक ही सीमित है।

कृषि वित्त के ग्रधिकाँश भाग की पूर्ति साहूकार ही करता है। साहूकार कृषक की सभी प्रकार की वित्तीय श्रावश्यकताश्रों को पूरा करते हैं। मद्रास राज्य में कुल कृषक ऋरों के ६३% साहूकारों द्वारा दिये जाते हैं, ६% सहकारी समितियों द्वारा श्रीर केवल १% तकावी ऋरों के रूप में, परन्तु साहूकारों द्वारा दिये हुए ऋरण साधारणतया श्रत्पकालीन होते हैं श्रीर वे ऋरों के श्रतिरिक्त किसान को कुछ उपयोगी वस्तुयें भी उधार देते हैं श्रीर उसकी फसल को कुछ नीची कीमत पर खरीद लेते हैं। श्रनेक रीतियों से वे किसान का शोषण करते हैं। एक बार साहूकार के चंगुल में फँस जाने के पश्चात् निकल जाना कठिन ही होता है। सबसे श्रच्छा उपाय यही होगा कि किसान को साहूकार के फन्दों से छुड़ा कर उसके लिए सस्ती संस्थागत साख की व्यवस्था की जाय।

। साहूकारों के शोषएा को कम करने के उपाय---

कृषि वित्त के पुनर्संङ्गठन के लिए यह ग्रावश्यक है कि सन् १६४५ की गैंडगिल सिमिति की सिफारिशों के अनुसार किसानों के पुराने और पुश्तैनी ऋगों में कमी की जाय और सहायक उपायों के रूप में साहूकारों के कार्य को सीमित तथा नियन्त्रित किया जाय। कांग्रे स कृषि सुधार सिमित का विचार है कि सभी राज्यों में साहूकारों के कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाने के नियम ग्रसफल रहे हैं। इन नियमों द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों का वास्तविक दरों से लगभग कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा है। साहूकारों की शक्ति को कम करने के लिए निम्न सुभाव दिये जा सकते हैं:—

- (१) साहूकारों का पंजीयन होना चाहिए।
- (२) बिना अनुज्ञापन प्राप्त किये कोई भी ऋरण देने का कार्य न कर सके। प्रत्येक साहूकार के लिए अनुज्ञापन लेना आवश्यक रहे।
- (३) साहूकारों को अपने क्षेत्र की भाषा का उपयोग करने श्रौर एक निश्चित रूप में हिसाब-किताब रखने पर बाध्य किया जाय, जिससे हिसाब में की जाने वाली गड़बड़ कम हो जाय।

- (४) ऋरण की मात्रा को बढ़ाकर लिखने के लिए कड़ी सजा रखी जाय।
- (५) साहूकार को कानून द्वारा समय-समय पर ऋगी को उसके ऋग का विस्तृत ब्यौरा भेजने पर वाच्य किया जाय।
- (६) साहूकार प्रत्येक प्राप्त शोधन के जिए रतीद दे।
- (७) ब्याज की दरों को एक सीमा के भीतर रखा लाय।
- ( द ) साहूकारों को ऋगों के सम्बन्ध में होने वाले सर्चों के वसूल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वह केवल मूलधन और ब्याज का ही
- श्रिविकारी रहे। (६) ऋगी को ऋगा की कुल रकम श्रथवा उसके किसी भाग को किसी भां
- समय न्यायालय में जमा करने का ग्रिषकार होना चाहिए।
  (१०) ऐसे समभौते ग्रवैष होने चाहिए जिनके द्वारा ऋग की राशि को
  किसी दूसरे राज्य में चुकाने की व्यवस्था की गई हो।
- (११) ऋ गी को यह ग्रधिकार मिलना चाहिए कि वह न्यायालय द्वारा साहू-कार को ऋ गा का हिसाब देने पर वाघ्य कर सके। साथ ही, न्याया-लयों को यह निर्धारित करने का भी ग्रधिकार मिलना चाहिए कि
- ऋरण की कितनी रकम ऋरणी के ऊपर बाकी हैं।
  (१२) साहूकार के दबाव तथा अनुचित अत्याचारों से ऋरणी की रक्षा की जाय।
- (१३) नियमों का पालन न करने वाले साहूकारों के लिए जुर्माने तथा जेल जाने की सजा रखी जाय।

व्यवहारिक जीवन में नियमों को कार्यशील करने के लिए एक निरीक्षण विभाग ज्ञानिर्माण होना चाहिए, जो समय-समय पर साहूकारों के हिसाब की अकस्मात जाँच ज्ञारता रहे। भूतकाल में इन नियमों की कमी यही थी कि निरीक्षण का अभाव था।

ह शायद बहुत ही लाभदायक होगा, यदि साहूकारों को ग्रामीए। बैंकिंग प्रणाली का क ग्रावश्यक ग्रंग वना दिया जाय। इस व्यवस्था की सम्भावना के विषय में जाँच की ग्रावश्यकता है। इसी सम्बन्ध में दो ग्राँर भी सुभाव दिये जा सकते हैं—(i)

ब्याज की अधिकतम् दरे निश्चित करने के स्थान पर, जैसा कि सभी निथमों में किया गया है, अधिकतम दरों की एक विस्तृत सूची बनाई जाय, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों की दशाओं के अनुसार अधिकतम् दरों में अन्तर रहे। यह प्रएगाली न्यायपूर्ण भी होगी और व्यवहारिक भी। (ii) व्यक्तिगत सूत्रों से जो प्राधि किये जाते हैं उनमें से ऐमे फ्लोपभोगी (Ususfructuary Mortgages) जिनमें २० साल के भीतर स्वयं

फलोपभोगी (Ususfructuary Mortgages) जिनमें २० साल के भीतर स्वयं मन्त हो जाने की व्यवस्था न हो, नियम द्वारा अवैध होने चाहिए। साथ ही, साधारण प्राधि में बिक्री द्वारा भूमि का हस्तान्तरण नियम द्वारा बन्द होना चाहिए।

परन्तु इस सम्बन्ध में यह बात विचारणीय है कि केवल नियन्त्रक नियमों द्वारा स्थिति के सुधरने की आशा नहीं है। सबसे बड़ा भय यह है (यह रिजर्व बैंक की जांच से मी सिद्ध होता है) कि ये नियम साख का संकुचन करते हैं। इस कारण इनका समुचित पालन संस्थागत साख (Institutional Credit) के विस्तार पर भी निर्भर है। साथ ही, ग्रामीए। क्षेत्रों से पूँजी के हटने के कार्यों को रोकना भी श्रावश्यक है, क्योंकि इससे वित्तीय कमी और भी बढ़ जायगी। डा॰ राघाकमल मुकर्जी ने जमींदारी उन्मूलन समिति को एक स्मरएा-पत्र में बताया था कि उत्तर-प्रदेश में ग्रामीए। वित्त का ४०% जमींदारों द्वारा दिया जाता था और श्रव जमींदार अपने कोषों का नगरों को हस्तान्तरए। कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कृषि सुघार समिति (Agrarian Reforms Committee) इस बात के पक्ष में न थी कि सरकार ग्रामीए। क्षेत्रों में राष्ट्रीय बचत प्रमाएा-पत्र बेचकर घन प्राप्त करे। ग्रावश्यकता तो इस बात की है कि ग्रामीए। क्षेत्रों में बचत को प्रोत्साहित करके ग्रामीए। बहुमुखी सहकारी समितियों और ऊपर की ग्रामीए। वित्त संस्थाग्रों के जमाघन को बढ़ाया जाय।

## सहकारिता का महत्त्व-

ग्रामीण वित्त तथा कृषि साख की सभी कठिनाइयों को दूर करने का सबसे उपयुक्त तथा स्थायी उपाय सहकारी साख आन्दोलन का विकास है। नानावती समिति ने कृषि साख के सम्बन्ध में सहकारी आन्दोलन की उपयोगिता की विस्तृत जाँच की थीं भ्रौर इस आन्दोलन के कुछ दोषों का पता लगाया था। बड़ी कठिनाई यह है कि ऋगों को प्रदान करने में सहकारी समितियाँ बहुत समय लगाती हैं, जो कृषकों के लिए बड़ा असुविधाजनक होता है। इस दोष भी दूर करने के लिए समिति ने निम्न सुभाव दिए थे:—

- (१) प्रत्येक सदस्य तथा सहकारी समिति के लिए हर वर्ष ऋगु लेने की सीमाएँ निश्चित होनी चाहिए।
- (२) ग्रच्छे प्रबन्ध वाली समितियों को ग्रपनी साख-संस्थाओं के साथ नकद साख खोलने का ग्रधिकार मिलना चाहिए।
- (३) अच्छी समितियों को छोटे-छोटे ऋरण प्रदान करने के लिए अपने पास नकद कोष रखने की आज्ञा मिलनी चाहिए।
- (४) इस सम्बन्ध में मद्रास राज्य की चालू प्राधि बाँध (Continuity Mortsage Bond) प्रगाली की लाभपूर्णता की जाँच होनी चाहिए और उसके उपयोग का प्रयत्न होना चाहिए।
- (५) यथासम्भव चालू साख (Running Credit) प्रगाली का उपयोग होना चाहिये ।
- (६) सिमितियों के उपयुक्त अधिकारियों को विशेष परिस्थितियों में निश्चित सात्राओं में विशेष ऋगों के प्रदान करने का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि कुछ दशाओं में तुरन्त ऋगा दिये जा सके।

इस सम्बन्ध में मिस्र देश की प्रशाली लाभदायक हो सकती है, जहां पर क फसल के उत्पादन व्यय के आधार पर ऋशा की मात्रा की सीमा निश्चित की

गई है। उस देश में वस्तुम्रों के रूप में ऋ एा देने के लिये सहकारी बैंक देश के विभिन्न क्षेत्रों में बीज और खाद के गोदाम रखती हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत ऋ एा के प्रार्थना-पत्र की समुचित जाँच की जाती है और म्रावस्थक छान-बीन के पश्चान् बहुत सी दशामों में बैंक के उप-मिकर्त्ता द्वारा बिना उच्च म्रधिकारियों से म्राज्ञा लिये ही ऋ एा प्रदान कर दिया जाता है।

भारत में सहकारी आन्दोलन का एक दोप यह भी है कि सहकारी सिमतियों के ब्याज की दरें ऊँची होती हैं। भारत में यह दर ७% से लेकर १५% तक
है। इसे कम- करने की आवश्यकता है और साथ ही यह भी आवश्यक है कि महतारी
सिमितियों और बैंकों के कार्यवाहन में मितव्यियता लाई जाय और उनके बीच समुचित
समचय तथा सहयोग स्थापित किया जाय। सहकारी सिमितियों के लिये यह भी आवध्यक है कि वे अपने ऋरों में फेर-बदल करके आदेयों में तरलता लायें। शायद यह
कहना भी अनुपयुक्त न होगा कि ऐसे नियम बनाये जायें जिनके द्वारा ऋरण लेने वालों
को समय पर भुगतान करने के लिये बाध्य किया जा सके। मद्रास राज्य में 'नियन्त्रित
साख' प्रगाली से अच्छे लाभ प्राप्त हुये हैं। इस प्रगाली की विशेषता यह है कि
सदस्यों को स्वीकृत ऋरा आवश्यकतानुसार किश्तों में दिये जाते है और ऋरा की
राशि उस आय में से प्रान्त कर ली जाती है जो ऋरा-राशि के उपयोग से उत्पन्न होती
है। आवश्यक परिवर्तन के साथ अन्य राज्यों में भी इसका उपयोग हो सकता है।

ग्रामीगा बेंकिंग जाँच समिति (The Rural Banking Enquiry Committee)—

यह सिमिति सन् १६४६ में नियुक्त की गई थी। इसने यह सिफारिश की है कि गैंडगिल सिमिति की सिफारिशों में आवश्यक परिवर्तन करके कृषि वित्तीय प्रमण्डल (Agricultural Finance Corporation) की स्थापना पर विचार किया जाय। सिमिति का विचार है कि केवल ग्रामीण साख व्यवस्था के उद्देश्य में ग्रामीण बेंकिंग प्रणाली का निर्माण करना उपयुक्त न होगा। सिमिति के अनुसार ग्रामीण मिक्कोषण को संस्थागत रूप देना आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की बचत का उपयोग किये विना ग्रामीण अधिकोषण की कोई समुचित योजना नहीं वनाई जा सकती है। सिमिति ने ऐसे उपायों का भी सुभाव दिया है जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डाकखाने के सेविंग वेंकों की उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए डाकखानों की शाखाओं का खोलना, अधिक जमा प्राप्त करने वाले डाक अधिकारियों को विशेष पारितोषण देना तथा समुचित विज्ञापन की सिफारिशों की गई हैं। सिमिति ने यह भी सुभाव दिया है कि ऐसे स्थानों पर स्टेट बैंक को अपनी शाखार्ये खोलने में सहायता दी जाय जहाँ ग्राभी तक कोषागारों द्वारा नकदी में लेन-देन की जा रही है। सिमिति ने इस सम्बन्ध में ५ साल के भीतर २०० शाखार्ये खोलने का प्रस्ताव रखा था। इस सम्बन्ध में स्टेट बैंक के विधान में भी कुछ प्रकार के परिवर्तनों के प्रस्ताव रखे गये थे। सम्बन्ध में स्टेट बैंक के विधान में भी कुछ प्रकार के परिवर्तनों के प्रस्ताव रखे गये थे।

#### वर्तमान स्थिति एवं भविष्य-

ग्रामीण बैंकिंग जाँच सिमिति की सिफारिशों का संक्षिप्त वर्णन ऊपर किया जा चुका है, परन्तु इस सिमिति ने ग्रामीण साख व्यवस्था के पुनसंङ्गठन के लिए कुछ भ्राधारभूत सिद्धान्तों का निर्माण किया है, इसिलिये इसकी सिफारिशों की विस्तृत समीक्षा श्रावश्यक प्रतीत होती है। ये सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं:—

- (१) यह विचार प्रकट किया गया है कि ग्रामीए। क्षेत्रों की बचत को एकदित करने तथा उनके लिए साख व्यवस्था करने के कार्यों को एक-दूसरे से ग्रलग नहीं किया जा सकता है, ग्रतः दोनों कार्यों के लिए एक ही संस्था का रहना ग्रावश्यक है।
- (२) इस समय सबसे बड़ी समस्या ग्रामीरण साख संस्थाओं का ग्रभाव है।
- (३) ग्रल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घंकालीन वित्तीय व्यवस्था के लिये श्रलग-ग्रलग संस्थायें होनी चाहिये, परन्तु उन सबका ग्राधार सहकारी ही होना चाहिये।
- (४) भूमि और ऋगों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाये हुये सभी नियम व्यवहारिक होने चाहिये और इन नियमों को बनाने से पहले इनके साख संस्थाओं और उनके विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का साव-धानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए।

समिति ने पता लगाया था कि व्यापारिक श्रीर सहकारो बैंकों का विकास नगरों तथा कस्बों तक ही सीमित है। व्यापारिक बैंकों को ग्रामीए क्षेत्रों में व्यवसाय बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन मिलना चाहिये। समिति का विचार है कि ग्रामीएा यातायात साधनों के विकास, ग्रामीएा शाखाओं के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कम व्याज पर ऋएए देने तथा गोदामों की व्यवस्था द्वारा इस प्रकार का प्रोत्साहन उपलब्ध हो सकेगा। दीर्घकालीन ऋएएों के सम्बन्ध में समिति ने सुभाव दिया है कि ऐसे सभी ग्रामीएा क्षेत्रों में जहाँ ग्रारम्भिक ग्रथवा केन्द्रीय भू-प्राधि बैंक नहीं हैं, इस प्रकार की बैंक खोली जायाँ। समिति ने देश के लिए कृषि वित्त प्रमण्डल का सुभाव रह् कर दिया है, क्योंकि नकद सहायता श्रीर शासन के दृष्टिकोएा से यह उपयुक्त नहीं समभा गया है। इसी प्रकार समिति ने जमाधन बीमे (Doposit Insurance) तथा चलायमान बैंकों (Mobile Banks) की व्यवस्था को भी ठीक नहीं समभा है।

समिति के प्रस्तावों की तीन प्रमुख ग्रालोचनायें की गई हैं:-

- (१) यहा कहा जाता है कि शायद समिति द्वारा प्रस्तावित योजना सहकारी प्रिषिकोषणा में सहायक न हो सकेगी, क्योंकि समिति ने ग्रामीणा क्षेत्रों को वित्तीय सहस्यता देने के स्थान पर उनकी बचत को जमा करने पर ग्रिधिक जोर दिया है। भय यह;है कि यह जमाधन स्थानीय सहकारी संस्थाग्रों के काम नहीं ग्रा पायगा।
  - (२) दीर्घकालीन ऋर्यों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये

ऋरण किन सूत्रों से प्राप्त होंगे और किस प्रकार । भू प्राधि वैंकों की स्थापना का सुभाव देते समय उससे सम्बन्धित कठिनाइयों पर घ्यान नहीं दिया गया है । ऐसा भी प्रतीत होता है कि कृषि वित्त प्रमण्डल के सुभाव को विना समुचिन विचार किये ही ठुकरा दिया गया है।

(३) ग्रल्पकालीन ऋरों की पूर्ति का साघन सहकारी मिमितियों को मान कर तो समिति ने ठीक ही किया है, परन्तु समिति ने यह नहीं वताया है कि इन समितियों की कुशलता और सफलता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है।

योजना हायोग ने ग्रामीस वित्त सहायता के लक्ष्य निर्धारित किये हैं और इस सम्बन्ध में ग्रह्मकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार की वित्तीय सहायता के सुकाव भी रखे हैं। प्रथम पंचवर्षीय-योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि योजना काल में सरकारी तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि वित्त के निमित्त १०० करोड़ रूपये का वार्षिक वितरस किया जाय, परन्तु पहले दो वर्षों में इस दिशा में प्रगति कार्यक्रम से बहुत पीछे रही थी। योजना के ग्रन्तिम तीन वर्षों में ग्रायोग ने कृषि वित्त की पूर्ति करने वाले साधनों को १ करोड़ रुपया और ग्रधिक देने की व्यवस्था की थी। ग्रारम में इन संस्थाओं की सहायता के लिए २१ करोड़ रुपये की वार्षिक सहायता का प्रस्ताव था। ऐसा प्रतीत होता है कि योजना ग्रायोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य इतना ऊँचा है कि उसे ग्रवास्तविक कहा जा सकता है। सन् १९५२-५३ में रिजर्व वैक केवल ११०५ करोड़ रुपये की ग्रह्मकालीन वित्तीय सहायता दे सकी थी।

ग्रामीए। साख-संगठन के शासन में कुशलता प्राप्त करने के लिए योजना श्रायोग ने सरकारी श्रिष्ठिकारियों के शिक्षए। के लिए तीन क्षेत्रीय काँनेजों की स्थापना का सुभाव रखा है, जिन पर केन्द्रीय सरकार १० लाख रुपया ज्यय करेगी, परन्तु यह ज्यय कम है। साथ ही, श्रभी तक राज्य सरकारों ने इस योजना के महत्त्व को भी नहीं समभा है, जिसके कारए। श्रभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं हो पाया है।

दूसरे पंच-वर्षीय श्रायोजन में श्रारम्भिक सहकारी साख समितियों की सदस्यता को ५० लाख रुपये से बढ़ा कर १५० लाख रुपया कर देने का सुम्हाव रखा गया है। योजना काल में सहकारी श्रान्दोलन द्वारा श्रल्पकालीन ऋगों की मात्रा ३० करोड़ रुपये से बढ़ा कर १५० करोड़ रुपया, मध्य-कालीन ऋगों को १० करोड़ रुपये से ५० करोड़ रुपया और दीर्घकालीन ऋगों की मात्रा ३ करोड़ रुपये से २५ करोड़ रुपया कर दी जायगी। ग्रामीरण साख के लक्ष्य निम्न प्रकार रखे गये हैं:—

समितियों की संख्या १०,४०० ग्रन्पकालीन साख १५० करोड़ रुपये मध्यकालीन साख ५० ,, ,, दीर्घकालीन साख २५ ,, ,,

इस कार्य में रिजर्व बेंक जो सहायता देगी उसके ग्रतिरिक्त ४८ करोड़ रुपये की सरकारी सहायता ग्रौर भी दी जायगी। ग्रामीरण साख के सम्बन्ध में तीन महत्त्वपूर्ण नीतियों का निर्मास किया गया है—

- (i) कुछ विशेष दशास्रों को छोड़ कर, जो कि कृषि उत्पादन से सम्बन्धित होंगी, सहकारी संस्थाएँ केवल व्यक्तिगत काश्तकारी के ही सम्बन्ध में ऋग देंगी।
- (ii) ऐसे किसानों को जिनका भूमि सुघार नियमों के अन्तर्गत सरकार से सीघा सम्बन्ध हो गया है, दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋगों की सुविधाएँ देने के लिए भूमि को सहकारी वित्त संस्थाओं को हस्तान्तरित करने का अधिकार दिया जाय।
- (iii) उन भूभागों के सम्बन्ध में जो सहकारी वित्त संस्थाओं के पास आ जाते हैं, भू-सीमा, काश्तकारों के रखने अथवा पट्टों पर उठाने से सम्बन्धित नियमों को लागू न किया जाय । सहकारी समितियों को इस प्रकार प्राप्त होने वाली भूमि को हस्तान्तरित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए । शर्त केवल यही रहनी चाहिए कि खरीदने वाला उस पर स्वयं खेती करे और इस प्रकार प्राप्त की जाने वाली भूमि की मात्रा नियम द्वारा निर्धारित अधिकतम् मात्रा से अधिक नहीं रहनी चाहिए।

## रिजर्व बैंक ग्रौर ग्रामीगा वित्त-

- (i) रिजर्व बैंक का एक भ्रलग विभाग ग्रामीरा तथा कृषि साख से सम्बन्धित है, जिसके कार्यों का वर्णन पिछले एक भ्रष्याय में किया जा चुका है।
- (ii) रिजर्व बेंक केवल अल्पकालीन ऋगा ही दे सकती है, जिनकी अविष अधिक से अधिक १५ महीने की होती है ।
  - (iii) ये ऋरण राज्य सहकारी बैंकों को ही दिये जा सकते हैं।
- (iv) रिजर्व बैंक को कृषक बिलों, हुण्डियों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों के क्रय-विक्रय का ग्रिधकार है, परन्तु ऐसे पत्रों पर दो हस्ताक्षर ग्रावश्यक होते हैं, जिनमें से एक या तो किसी ग्रनुसूचित बैंक का होना चाहिए या राज्य सहकारी बैंकों का।
- (v) सहकारी बैंकों के लिए ब्याज की दर में ५०% की कमी भी १ सितम्बर सन् १६५१ से कर दी गई है।
- (vi) ग्रामीए। साख विस्तार हेतु इम्पीरियल बैंक को ३० नई शाखाएँ खोलने का ग्रधिकार दिया गया था ग्रीर समस्त ग्रामीए। साख व्यवस्था की विस्तृत जांच का कार्य ग्रारम्भ कर दिया गया था, परन्तु फिर भी सन् १९५० में सहकारी बैंकों ने केवल ५ ३३ करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त की थी ग्रीर सन् १९५२ में ११ करोड़ रुपये की।
- (vii) तत्पश्चात् रिजर्वं बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को दी जाने वाली सहा-यता को मात्रा बराबर बढ़ती गई है। ग्रल्पकालीन ऋगों के लिए सन् १९५४-५६ में १७ राज्य सहकारी बैंकों के लिए २८-७९ करोड़ रुग्ये के ऋगों की राशि की सीमा निविचत की गई थी, जो सन् १९५६-५७ के लिए १८ राज्य सहकारी बैंकों के लिए ३३-१९४ करोड़ रुपया कर दी गई थी। इसी काल में इन बैंकों द्वारा निकाली हूं

राशि २२.६५ करोड़ रुपये से बढ़कर ३१.६२ करोड़ रुपया हो गई थी। मार्च सन् १६५७ कं अन्त में राज्य सहकारी बैंकों के वकाया ऋगा २०.५ करोड़ रुपये के थे, जब कि ऐसे ऋगा मार्च सन् १६५६ और मार्च सन् १६५५ में क्रमशः १२.३४ और ६.१४ करोड़ रुपये थे। अस् सन् १६५७ ५ के वर्ष में राज्य सहकारी बैंकों के लिए सामयिक कृषक कार्यों और फसलों की विक्री की अर्थव्यवस्था के लिं। ४६.४२ करोड़ रुपये के ऋगों की सीमा निश्चित की गई थी, जब कि गत वर्ष की ऐसी राशि ३५.१५ करोड़ रुपये के ऋगा लिए जा चुके थे, जबकि गत वर्ष की ऐसी राशि २३.३२ करोड़ रुपया रही थी। इस वर्ष में सहकारी बुनकर संघों के लिए २५% ब्याज की दर पर २०५.७ वलाल रुपये के और ऋगों की स्वीकृति दी गई थी।

मध्य-कालीन वित्त के सम्बन्ध में सन् १६५५.५६ में द राज्य सहकारी बैंकों को ६६ ६७ लाख रुपये के ऋगों की स्वीकृति दी गई थी, जो सन् १६५६-५७ में बढ़ाकर १५७ लाख रुपया कर दी गई थी। इस वर्ष इन बैंकों ने १२२ २१ लाख रुपये की राशि इस मद में से निकाली, यद्यपि गत वर्ष में केवल ४१ ३४ लाख रुपये की राशि निकाली गई थी। सन् १६५७-५६ में ६ राज्य सहकारी बैंकों को १ ६७ करोड़ रुपयों के मध्यकालीन ऋगों की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से वर्ष के अन्त में १ ५८ करोड़ रुपये की राशि शेष थी। सन् १६५८-५६ में १२ राज्य सहकारी बैंकों के लिए ७ ७ करोड़ रुपये की राशि के ऋगा स्वीकार हुए थे और वर्ष के अन्त में इनमें से अभी ३ ४२ करोड़ रुपये की राशि निकालने को शेष थी।

ग्रंगैल सन् १६५५ में रिजर्व बैंक एक्ट में संशोधन करने का बिल पास हो गया था। इसके अनुसार किसानों को खड़ी फसल पर रुपया उधार लेने और फसल को गिरवी रख कर उधार लेने की व्यवस्था की गई है। बिल में १० करोड़ रुपये के राष्ट्रीय कृषि ऋगा कोष की स्थापना की व्यवस्था की गई है और यह कोष सहकारी समितियों को ऋगा देने के लिए राज्य सरकारों को ऋगा देगा। कोप से भूमि बन्धक बैंकों को भी ऋगा दिया जा सकेगा। बिल में रिजर्व बैंक को १ करोड़ रुपये का एक ग्रंर कोष, राष्ट्रीय कृषि स्थायित्व कोष (National Agricultural Stabilization Fund) खोलने का भी ग्रधकार दिया गया है। इसमें से राज्य सहकारी बैंकों को इसलिए ऋगा दिया जायगा कि वे ग्रल्यकालीन ऋगों को मध्य ग्रविष ऋगों में बदल सकें। धीरे-घीरे इन कोषों की रकम को बढ़ाया जायगा। किसान फसल को सरकारी गोदामों में जमा करके ऋगा ले सकता है और कीमतों के उनर चढ़ने की दशा में उसे बेचकर ऋगा चुका सकता है। सन् १६५५-५६ में रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन कार्यवाहन) कोष भी स्थापित किया था, जिसमें ग्रारम्भ में १० करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी। जून सन् १६५६, १६५७ ग्रीरसन् १६५६ में

<sup>\*</sup> Report on Currency and Finance, 1956-57.

इस राशि में ४-५ करोड़ रुपये और जोड़ दिए गए थे। कोष की स्थापना राज्य सरकारों को दीर्घ और मध्यकालीन ऋगा देने के लिए की गई है, तािक वे राज्य सहकारी बैंकों और मू-प्राधि बैंकों के ग्रंश खरीद सकें। इस कोष में से मार्च सन् १६५७ तक ११ राज्यों को २६६. २० लाख रुपये के ऋगों की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से उस समय तक १६०. २५ लाख रुपये की राशि उधार ली गई थी। जून सन् १६५८ तक इस कोष में से १४ राज्य सरकारों को सहकारी साख समितियों के ग्रंश खरीदने में सहायता देने के लिए ६. ४ करोड़ रुपये के ऋगों की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से उस समय तक १३ राज्यों ने ५ ६३ करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया था। राष्ट्रीय कृषि स्थायित्व कोष में से ग्रंभी कोई ऋगा नहीं दिया गया है।

जून सन् १६५६ में कृषि उपज (विकास और गोदाम व्यवस्था) प्रमण्डल अधिनियम (Agricultural Produce 'Development and Warehousing' Corporations Act, 1956) भी पास हुआ था, जिसके अनुसार सितम्बर सन् १६५६ में राष्ट्रीय सहकारी विकास और गोदाम मण्डल (National Cooperative Development and Warehousing Board) स्थापित किया गया है। यह परिषद् कृषि उपज के लिए गोदामों की व्यवस्था करती है और उसकी विक्री का भी प्रबन्ध करती है।

## कृषि साख की प्रगति-

प्रथम फरवरी सन् १६५७ को स्टेट बैंक ने यह निश्चय किया था कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा शीर्ष बैंकों को सप्ताह में एक बार ग्रामीए क्षेत्रों की शाखाओं को कोषों के भेजने में निशुल्क विश्रेष सुविधाएँ दी जायेंगी। स्टेट बैंक रियायती दरों पर सहकारी संस्थाओं को ट्रस्टी प्रतिभूतियों, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत ऋएा-पत्रों और ग्रंशों, माल, विनिमय बिलों, प्रतिज्ञों-पत्रों ग्रादि ऋएा तथा नकद साख सुविधायें भी प्रदान करेगी। ग्रारम्भिक ग्रवस्था में सहकारी संस्थाओं को ग्रंश पूँजी को बढ़ाने तथा ग्रामीए क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी ऋएा दिए जायेंगे। नवम्बर सन् १९५ तक रिजर्व बैंक ने २४४ नई शाखाएँ भी खोल दी हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम बोर्ड ने १७ राज्यों में सहकारी विकास की योजनाएँ स्वीकार की हैं और उनके लिए १२.०६ करोड़ रुपये ऋग तथा ३६.६२ करोड़ रुपये की ग्रायिक सहायता दी है। गोदामों के निर्माण के हेतु १० करोड़ रुपर की पूँजी से केन्द्रीय भण्डार गृह प्रमण्डल (Central Warehousing Corporation) की स्थापना की जा चुकी है। इस प्रमण्डल ने ६ गोदाम बनाए हैं। ११ राज्यों में राज्य भण्डार गृह प्रमण्डल भी स्थापित हो चुके हैं। बोर्ड ने सन् १९५६-५७ विकास के लक्ष्य निम्न प्रकार निश्चित किये थे:—

बड़ी सहकारी साख सिमितियों की स्थापना केन्द्रीय सहकारी बैंक ग्रारम्भिक भू-प्राधि वैंक

3,00E 295

94

सहकारी समितियों के वित्त का प्रमुख साधन ग्रभी तक रिजर्व वंक ही रही है, रद्यपि रिजर्व देंक की सहायता के लक्ष्य निश्चित नहीं किए गये हैं। ेम प्रमुमन लगाया गया है कि अब तक रिजर्व वंक ने राज्य सहकारी वंकों को ६-३१ करोड़ रुपए के ऋगा दिए हैं, जो अल्पकालीन ऋगा हैं। इसी प्रकार १-१२ करोड़ रुपये के मध्य-कालीन ऋगा भी दिए गए हैं। रिजर्व वंक से राज्य सहकारी वंकों को ६-७४ करोड़ रुपये के ऋगा दे एउस करोड़ रुपये के ऋगा दे एउस सहकारी वंकों को ६-७४ करोड़ रुपये के ऋगा दे उद्देश्य से भी दिये गये हैं कि वे राज्य में दूसरी सहकारी संस्थाओं की ग्रंग पूँजी में वृद्धि कर सकें।

म्रखिल भारतीय ग्राम्य साख म्रनुसन्धान समिति (All India Rural Credit Survey Committee)—

सन् १९५१ में रिजर्व बैंक ने देश में प्रामीण साल ग्रीर सहकारी ग्रान्दोलन की विस्तृत जाँच की। यह जाँच देश के ७५ जिलों के ६०० गाँवों में की गई थी ग्रीर १,२७,३४३ परिवारों तक फैली हुई थी। समिति के ग्रघ्यक्ष श्री गोरवाना थे। समिति ने पता लगाया है कि किसानों के ऋण व्यवसायों में सरकार ग्रीर सहकारी भ्रान्दोलन का हाथ क्रमशः केवल ३.३ ग्रीर ३.१% था। लगभग ७०% ऋण साहुकारों ग्रीर ग्रामीण व्यापारियों द्वारा दिये जाते हैं। सहकारी समितियों को केन्द्रीय ग्रीर राज्य बैंकों से जो सहादता मिलती है वह ग्रपर्याप्त है। समिति का विचार है कि कृषि ग्रीर ग्राम्य साल के समुचित विकास के लिए सहकारी ग्रान्दोलन का विकास ही एक मात्र उपाय है, इसिंगए ग्राम्य साल की एक समचययुक्त प्रणाली का निर्माण ग्रावश्यक है। समिति ने पता लगाया है कि ग्राम्य वित्त के सम्बन्ध में विभिन्न साल संस्थाओं का महत्त्व निम्न प्रकार है—

्साख संस्था	कुल ऋगा का प्रतिशत	************
(१) सरकार	₹,\$	
(२) सहकारी साख समितियाँ ग्रौर बेंक	₹-१	
(३) व्यापार बैंक	3.0	
(४) नातेदार तथा सम्बन्धी	१४•२	
(५) जमींदार ग्रौर ग्रन्य भू-स्वामी	<b>१-</b> ४	
(६) किसान साहूकार	3*8	
( ७ ) व्यवसायी साहूकार	४४*प	
( ८ ) व्यापारी ग्रौर ग्राढ़ितया	<b>⊼</b> •X	
( ६ ) ग्रन्य	१.⊏	-
कुल	<b>१००</b> °०	

समिति के प्रमुख सुभाव निम्न प्रकार हैं :---

- (१) सहकारी संस्थाओं में प्रत्येक अवस्था में सरकार की साभेदारी रहनी चाहिए और सरकार तथा रिजर्व बैंक के बीच अधिक सहयोग रहना चाहिए।
- (२) राज्य सहकारी बैंकों श्रीर भू-प्राधि बैंकों की पूँजी का विस्तार होना चाहिए श्रीर उनके ५१% ग्रंश राज्य सरकारों के पास रहने चाहिए। इसी प्रकार की साभेदारी केन्द्रीय सहकारी बैंकों श्रीर बड़ी-बड़ी श्रारम्भिक समितियों में भी रहनी चाहिए।
- (३) यथासम्भव इस साभेदारी के लिए रिजर्व बैंक से राज्य सरकारों को राष्ट्रीय कृषि साख कोष में से ऋरग मिलना चाहिए। यह कोष रिजर्व बैंक ५ करोड़ रुपये से शुरू करे और फिर हर साल इसमें ५-५ करोड़ रुपया बढ़ाती जाय।
- (४) इस कोष में से राज्य सहकारी बैंकों को मध्यकालीन ऋण और भू-प्राधि बैंकों को दीर्घकालीन ऋण भी दिये जायें। इसका घन सिंचाई की योजनाम्रों के विशेष विकास ऋग्-पत्र खरीदने में भी काम में लाया जाय।
- (५) सहकारी बिक्री श्रीर गोदाम व्यवस्था में भी सरकार की इसी प्रकार की साभेदारी रहनी चाहिये।
- (६) एक महत्त्वपूर्ण सुभाव स्टेट बैंक के निर्माण के सम्बन्ध में है, बो ४०० नई शाखाएँ ग्रामीए ग्रीर ग्रर्ड-नागरिक क्षेत्रों में खोतेगी। राज्यों से सम्बन्धित बैंकों, जैसे—सौराष्ट्र बैंक, पटियाला बेंक, बीकानेर बैंक, जयपुर बैंक, राजस्थान बैंक, इन्दौर बैंक, बड़ौदा बैंक, मैसूर बैंक, हैदराबाद बैंक ग्रौर त्रिवांकुर बैंक का स्टेट बैंक से एकीकरण कर दिया जाय।
- (७) सहकारी संस्थाओं के प्रबन्धकों श्रीर कर्मचारियों की शिक्षा की व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा रिजर्व बेंक तीनों को ही श्रिषक उदार नीति श्रपनानी चाहिये श्रीर इस शिक्षा में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवाग्रों से सम्बन्धित श्रावश्यकताश्रों को ध्यान में रखने की श्रावश्यकता है ।
- ( प ) सरकार को ग्रामी एव बचत को एकत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिये,
  परन्तु इस बचत का उपयोग केवल ग्रामी एा साख की उन्नित के लिये
  किया जाय ग्रीर क्यों कि ग्रामी एा बचत कम है, इस लिये नगरों की
  बचत के एक भाग को भी ग्रामी एा साख विस्तार के लिये उपयोग
  किया जाय।
- ( ६ ) ग्रामी ए क्षेत्रों में ब्याज की दरों की घटाने के लिये साहू कारों के कार्यों

पर नियन्त्रण आवश्यक है। इस सम्बन्ध में ऋगा और कृषि सम्बन्धी नियम बनने चाहिये।

- (१०) कृषकों के हितों को सुरक्षित करने के लिये भात्री बाजारों (Forward Markets) पर समुचित नियन्त्रण रखा जाय।
- (११) सरकारी नीति का आधार कृषि उपजों की कीमतों में स्थिरता बनाये रखना होना चाहिये।
- (१२) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दुर्गिक्ष कोष स्थापित करें श्रौर उसकी व्यवस्थाओं का विस्तार करें।
- (१३) साहूकारों को उनका कार्य करने दिया जाय, यद्यपि उनके वर्तमान महत्त्व में कमी होनी चाहिए।
- (१४) व्यापार बैंकों की वर्तमान कृषि साख व्यवस्था बनी रहनी चाहिये। इन बैंकों को माल के गोदाम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।
- (१५) ग्रामीरा कुटीर उद्योगों को भी वित्तीय सहायता मिलनी चाहिये, जिसके लिये राज्य वित्त प्रमण्डलों, रिजर्व बैंक तथा कुटीर उद्योग प्रमण्डलों की विशेष व्यवस्था करनी चाहिये।
- (१६) ग्रमीएा यातायात श्रौर सम्वादवाहन के साघनों का विस्तार श्रौर विकास होना चाहिये।
- (१७) राज्य द्वारा उचित सहायता देकर सहकारी भ्रान्दोलन को सुदृढ़ बनाना चाहिए।

## सहकारी कार्य की संक्षिप्त समीक्षा-

ग्रिखल भारतीय ग्रामीए। साख ग्रनुसन्धान सिमित की सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है श्रीर उनके ग्राधार पर ग्रामीए। व्यवस्था को संगठित करने का प्रयत्न किया है।

- (१) सरकार ने अप्रैल सन् १९५५ में ही इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी नियम पास कर दिया था। पुनर्संङ्गठन रूप में इम्पीरियल बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के रूप में १ जुलाई सन् १९५५ से अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। सभी राज्य सम्बन्धी बैंकों को स्टेट बैंक में मिला देने का कार्यक्रम भी चालू है।
- (२) अप्रैल सन् १६५५ में रिजर्व वैंक आँफ इण्डिया एक्ट में संशोधन किये गये हैं। वैंक को राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन कार्यवाहन) कोप (National Agricultural Credit 'Long-term Operations' Fund) और राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरता) कोष (National Agricultural Credit 'Stabilisation' Fund) स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया है। प्रथम कोष १० करोड़ रुपये की राजि से आरम्भ किया गया है और इसमें से राज्य सहकारी

बैंकों ग्रौर केन्द्रीय भू-प्राधि बैंकों को ऋरण दिये जायेंगे। दूसरे कोष में जून सन् १६५६ से रिजर्व बैंक ने १ करोड़ रुपया प्रति वर्ष देना ग्रारम्भ कर दिया है ग्रौर इसमें से राज्य सहकारी बैंकों को मध्यकालीन ऋरण दिये जा रहे हैं।

- (३) सरकार ने यह मान लिया है कि श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल श्रौर राज्य वित्त प्रमण्डलों के श्रंश श्रौर भूमि-बन्धक बैंकों के ऋग्ग-पत्र रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के समक्ष समभे जायेंगे।
- (४) रिजर्व बैंक द्वारा यह बात भी विचाराधीन है कि क्या ग्रंशों ग्रीर 'ऋरण पत्रों' के ग्रभिगोपन (Underwriting) का कार्य रिजर्व बैंक ग्रास्म कर दे।
- ( ५) स्टेट बैंक को यह ऋदिश दिया गया है कि वह ग्रामीए। तथा ऋदं-नागरिक क्षेत्रों में ४०० नई शाखाएँ स्थापित करे।
- (६) सितम्बर सन् १९५४ से बम्बई में बैंकिंग प्रशिक्षण कॉलेज खोल दिया है, ताकि कुशल श्रौर योग्य प्रबन्धक तथा कर्मचारी प्राप्त हो सकें।
- (७) मार्च सन् १६५७ में केन्द्रीय गोदाम प्रमण्डल (Central Ware-housing Corporation) भी स्थापित कर दिया गया है। इस प्रमण्डल की अधिकृत पूँजी २० करोड़ रुपया तथा ग्रंश पूँजी १० करोड़ रुपये रखी गई है। यह कृषि उपज के लिए गोदामों तथा बिक्री की व्यवस्था करती है।

ग्रामीए। वित्त के ग्रन्य साधन-

भारत में ग्रामीए वित्त के साधन निम्न प्रकार हैं :—(१) महाजन ग्रथवा साहूकार, (२) व्यापार बैंक, (३) रिजर्व बैंक ग्रॉफ इण्डिया, (४) स्टेट बैंक द्यांफ इण्डिया, (५) सरकारी समितियां श्रीर सहकारी बैंक, (६) सू-प्राधि बैंक, (७) सरकार ग्रौर (८) देशी बैंकर। इनमें से महाजनों, देशी बैंकरों, रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक का अध्ययन पिछले अध्यायों में किया जा चुका है। ग्रामीए। वित्त के हिष्टिकोएा से व्यापार बैंकों का महत्त्व बहुत कम है। ये बैंक कृषकों को ऋएा नहीं देती हैं। इनके ऋ एा या तो उन व्यापारियों को मिलते हैं जो कृषि की उपज में व्या-पार करते हैं या महाजनों ग्रौर देशी बैंकरों को । कृषक को ये ऋगा उपरोक्त सूत्रों के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। सहकारी समितियाँ ग्रामीएा साख का एक महत्त्वपूर्ण साधन हैं श्रीर वर्तमान काल में इनका महत्त्व बराबर बढ़ता ही जा रहा है। इनका विस्तृत अध्ययन अगले अध्याय में किया जायगा। भू-प्राधि बैंक कृषकों की दीर्घ-कालीन ऋ सों से सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करती हैं । इनकी संख्या देश में ब हुत कम है। इनका भ्रध्ययन भी एक भ्रगले भ्रध्याय में किया जायगा। जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, प्रत्यक्ष रूप से सरकारी ऋए। केवल संकटकालीन परिस्थितियाँ में ही दिये जाते हैं ग्रौर इन्हें तकावी ऋगा (Taccavi Loans) कहा जाता है। इन ऋगों पर ब्याज की दर बहुत नींची होती है ग्रौर इन्हें कठोरता के साथ वसूब ाजाता है। इनके मिलने में भी बहुघा विलम्ब होता है और ये कृपक को बड़ी गई से मिल पाते हैं। परोक्ष रूप में रिजवं वंक, स्टेट वंक तथा अन्य सरकारी आमें के द्वारा सरकार कृषि वित्त की व्यवस्था भली भांति करती है। इस सम्बन्ध ग्रं यह नहीं भूलना चाहिए कि ग्रामीग्रा वित्त का प्रमुख साघन महाजन ही है, जो त ६०% ऋगों की पूर्ति करता है।

### **QUESTIONS**

1. Comment on the problem of rural credit in India and how the Reserve Bank of India is trying to solve it. Has the ion of the State Bank, in any way helped in this work?

(Raj., B. A., 1956)

- 2. What efforts has the Reserve Bank of India made to faciliural credit during the past three years? Show how far these is have been successful? (Raj., B. A., 1954)
- 3. Make out a case for the extension of modern banking facito the rural sector of India. What is being done by the State is respect? (Aligarh, B. A., 1956)
- 4. What are the agencies of rural finance in India? How is the cooperative movement succeeded in replacing the village jan? (Agra, B. Com., 1957)
- 5. In what ways has the Reserve Bank of India helped in ig the problem of Agricultural finance in India?

(Raj., B. Com., 1952)

#### अध्याय ४१

# भारतीय सहकारी साख संगठन

(The Indian Co-operative Credit Organisation)

सहकारी ग्रान्दोलन का प्रारम्भ--

सहकारी ब्रान्दोलन का ब्रारम्भ जर्मनी से हुआ श्रीर वहाँ से यूरोप के दूसरे देशों में फैलता गया है। भारत में भी सहकारी प्रणाली द्वारा ग्रामवासियों को ऋणों के भार से मुक्त करना एक उपयुक्त उपाय समभा गया है। भारत में भी यह ब्रान्दोलन सन् १८६१ के भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिशों पर आरम्भ हुआ। सबसे पहला सहकारी साख समिति एक्ट सन् १६०४ में पास हुआ, जिसका उद्देश्य रेफेसेन ग्रामीण सहकारी साख समितियाँ स्थापित करके ग्रामीण वित्त की व्यवस्था करना था। बाद को यह आवश्यकता अनुभव हुई कि सहकारिता के नियमों में साख व्यवस्था के ब्रितिरक्त अन्य उद्देश्यों को भी सम्मिलित किया जाय, इसलिए सन् १६१२ में एक विस्तृत सहकारी समिति नियम पास किया गया। सन् १६१६ में सहकारिता एक प्रान्तीय विषय बना दिया गया और आन्दोलन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने संशोधक नियम बनाने आरम्भ किये।

भारत में सहकारी बैंक प्रणाली संघीय आधार पर संगठित की गई है। सबसे नीचे छोटी ग्रामीण और नगर समितियां हैं, उनके ऊपर केन्द्रीय समितियां और केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं और सबसे ऊपर राज्य सहकारी बेंक हैं, जिन्हें शीर बेंक अथवा सर्वोच्च बेंक (Apex Bank) भी कहा जाता है। छोटी समितियां कृषि कार्यों के लिए कृषकों को ऋण देती हैं और अपनी पूँजी का एक भाग केन्द्रीय बैंकों से ऋण के रूप में प्राप्त करती हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की पूँजी अंशों को बेच कर, निक्षेणें द्वारा, शीर्ष बैंकों के ऋण तथा रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के ऋणों से प्राप्त होती हैं। आरिम्भक समितियों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के बीच केन्द्रीय समितियों होती हैं, जो आरिम्भक समितियों और केन्द्रीय बैंकों के बीच सम्बन्ध स्थापित करती हैं, निरीक्षण का कार्य करती हैं, अथवा बैंकिंग संघ के रूप में होती है। केन्द्रीय संव (Central Union) स्वयं ऋण नहीं देता है, बिल्क छोटी सहकारी समितियों का संबंव केन्द्रीय सहकारी बैंकों से जोड़ देता है। सहकारी आन्दोलन की प्रगति का अनुमान निम्न तालिका से प्राप्त हो सकता है:—

वर्ष	समितियों की संख्या	सदस्यता ( लाखों में )	कार्यवाहक पूँजी (करोड़ रुपयों में)
११०-१३१	98,300	१॰६०	o*{¤
१६२०-२१	२,५४,५००	37"78	१५.१=
<b>१</b> ६३०–३१	٥٥٧,3٤,۶	३६"८०	3e"8e
१६४०-४१	११,६८,६००	५०'७७	१०४°६=
१९५०—५१	१७,३०,६००	१२५•६१	२३३-१०
\$ <b>£</b> \$\$-\$\$	१,५१,१८६	Birtheologi	२७४-⊏४
\$ & 4 - 5 × 3 \$	१,६५,६५०	3.€! ₹ \$	३०६•३४
824-48	१,६५,५६५	<i>१५१•७६</i>	30.8 18
\$£48-44	२,१६,२ ज ज	१६२•००	३६० ५ ५२
१६५५-५६	२,३५,६०७	१७४ <b>-</b> २ <b>५</b>	४०६.६६
१६५६–५७	२,४४,७६६	£8.£3\$	४६७-६७

'ग्रारम्भिक सहकारी साख समितियों का संगठन—

भारत में सहकारी आन्दोलन कृषकों की आरिम्भिक सहकारी समितियों की स्थापना से आरम्भ हुआ। इस समय भी ऐसी समितियाँ कुल समितियों की  $\varepsilon$  % हैं। इन समितियों का संगठन निम्न प्रकार होता है:—

- (१) कोई भी १० व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति खोल सकते हैं। अधिक-तम् सदस्यता १०० होती है । इन समितियों का सहकारी समितियों के रिजस्ट्रार से पंजीकरण कराया जाता है।
- (२) साधारं एा नियम यह है कि एक गाँव के लिए एक सिमिति होती है। सदस्यों द्वारा पारस्परिक नियन्त्र एा प्रबन्ध तथा निरीक्ष एक लिये आवश्यक समभा जाता है, परन्तु हाल के संशोधनों से इस नियम में कुछ परिवर्तन कर दिये गये हैं।
- (३) एक सहकारी सिमिति का प्रबन्ध प्रजातन्त्रात्मक तथा नि:शुल्क होता है ग्रीर दो मण्डलों द्वारा किया जाता है। ऊपर तो एक साधारण सभा होती है, जो नीति का निर्माण करती है ग्रीर जिसमें सभी ग्रंगधारी रहते हैं। दिन प्रति दिन के प्रबन्ध के लिए एक प्रबन्धक सिमिति होती है, जिसमें १ से लेकर ६ तक सदस्य होते हैं ग्रीर जिनका निर्वाचन उपरोक्त सभा द्वारा किया जाता है। सिमिति का एक सिचव भी होता है, जो बहुधा वेतनभोगी कर्मचारी होता है ग्रीर उसके नीचे भ्रन्य वेतनभोगी कर्मचारी रहते हैं।
- (४) भारत में इन समितियों के सदस्यों का उत्तरदायित्व साधारणतया असीमित होता है, परन्तु विशेष दशाओं में सरकार सीमित उत्तरदायित्व समितियों

की स्थापना की आज्ञा देती है। बहुमुखी सरकारी समितियों के लिए, जो एक ही साय कई प्रकार के कार्य करती हैं, सीमित उत्तरदायित्व सिद्धान्त को मान लिया गया है।

- (५) ब्रारम्भिक सहकारी साख समिति की पूँजी के साधन दो प्रकार के होते हैं:— ब्रान्तरिक तथा बाह्य । ब्रान्तरिक साधनों में ब्रंश पूँजी, नये सदस्यों के प्राप्त प्रवेश शुल्क, सदस्यों के निक्षेप तथा सुरक्षित कोष सम्मिलित होते हैं। भारत में ब्रंश पूँजी की मात्रा बहुत ही कम रहती है, क्योंकि ब्रंशों को बेचे बिना भी समितियां स्थापित की जा सकती हैं। इसी प्रकार सदस्यों के निक्षेप तथा प्रवेश शुल्क की रामि भी नाम मात्र ही होती है। ब्रान्तरिक साधनों से पर्याप्त पूँजी प्राप्त नहीं होती हैं और समितियां ब्रध्विकतर बाह्य साधनों पर ही निर्भर रहती हैं। इन साधनों में सरकारी ऋरगों, गैर-सदस्यों के किश्चेपों तथा केन्द्रीय ब्रौर राज्य सरकारी बेंकों से प्राप्त ऋरगों को सम्मिलित किया जाता है। सरकारी समितियां केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी बेंकों के ऋरगों पर निर्भर रहती हैं।
- (६) ये समितियाँ केवल सदस्यों को ऋरण दे सकती हैं। इनके ऋरण तीन प्रकार के होते हैं:—(क) उत्पादक ऋरण, (ख) अनुत्पादक ऋरण और (म) पिछले ऋरण चुकाने के लिये दिये हुये ऋरण। उत्पादक ऋरणों में चालू कृषि व्यवसायों को दिये गये अल्पकालीन ऋरण तथा करों के चुकाने और कृषि के स्थायी सुधार हेतु दिए गये दीर्घकालीन ऋरण सिम्मिलत होते हैं। अनुत्पादक ऋरणों को (जैसे विवाह आदि के लिए) उचित नहीं समभा जाता है, परन्तु बहुत बार साहूकार से ऋरण लेने की प्रवृत्ति का अन्त करने के लिये वे भी दिये जाते हैं। सभी प्रकार के ऋरणों पर व्याव की दर नीची रहती है और उन्हें किश्तों में चुकाने की सुविधा दी जाती है। साधारण-तथा दो या अधिक सदस्यों की जमानत ली जाती है, परन्तु कभी-कभी सहायक प्रतिभूति के रूप में चल अथवा अचल पूँजी भी माँगी जाती है।
- (७) सभी सहकारी सिमितियों को एक निश्चित रूप में लेखों को रखना पड़ता है ग्रीर इन लेखों का सरकारी श्रकेक्षरण किया जाता है। कभी-कभी स्वीकृत प्राइवेट ग्रकेक्षक भी इस कार्य के लिये रखे जाते हैं।
- ( द ) सभी सहकारी समितियों के लिये अपने लाभ के एक भाग को सुरक्षित कोष में जमा करना अनिवार्य होता है। जिन समितियों में अंश पूँजी नहीं होती है वहां सारा का सारा लाभ सुरक्षित कोष में जमा किया जाता है। लाभों का एक भाग शिक्षा तथा परोपकारी कार्यों के लिये भी खर्च किया जा सकता है।
- (६) सहकारी सिमितियों के रिजस्ट्रार को यह अधिकार होता है कि वह ऐसी सिमितियों को बन्द कर दे जो अकुशल हैं, जिनका प्रबन्ध ईमानदार नहीं है अथवा जिन्हें घाटा होता रहता है।

ाज्य श्रौर सहकारी साख ग्रान्दोलन-

सरकार निम्न रीतियों से सहकारी साख श्रान्दोलन की सहायता करती है:-

- (क) सहकारी समितियों को मुद्रांक करों, पंजीयन करों इत्यादि के सम्बन्ध में छूट दी गई है।
- (स्त) इन समितियों को सरकार बहुत ही कम व्याज पर ऋ एा देती है। सहकारी बैंकों के लिये रिजर्व बैंक की ब्याज की दर केवल १३% है जबकि ग्रन्य बैंकों से ४% ब्याज लिया जाता है।
- (ग) सरकार ऋगों में सहकारी समितियों को प्राथितकता देती है भीर सहा-यता के लिए तैयार रहती है। साधारणतया रिजर्व वेंक ६० दिन से अधिक काल के लिए ऋगा नहीं देती है, परन्तु कृपि विलों पर १५ महीने के लिए ऋगा दे देती है।
- (घ) रिजर्व वैंक के कृषि साख विभाग का यह कर्त्तंव्य है कि वह कृषि साख की सारी समस्याओं का अध्ययन करे और सहकारी वैंकों के बीच सम्पर्क स्थापित करे।
- (इ) बहुत सी सरकारें प्राम सुघार तथा सहकारी साख के विकास-के लिए वार्षिक अनुदान देती हैं। 🕊 🌿
- (च) सहकारी विभाग के अधिकारियों की सहायता से सहकारी समितियों के कार्यवाहन का निरीक्षण करती है, उनके लेखों का अंकेक्षण करती है तथा उन्हें आवश्यक सलाह देती है।

### बंक (Apex Bank)-

भारत में सभी खण्ड क राज्यों में एक-एक शीर्ष बैंक थी ग्रौर ग्रासाम राज्य में इनकी संख्या २ थी। सन् १९५६-५७ में देश के सभी राज्यों में ऐसी बैकों की संख्या २३ थी, जिनकी प्रधान कार्यालयों सहित १५० के ऊनर शाखाएँ हैं। भारत में शीर्ष बैंक दो प्रकार की हैं अर्थात् अमिश्रित (Pure) तथा मिश्रित (Mixed) । प्रथम प्रकार की बैंकों के ग्रंश केवल सहकारी बैंकों द्वारा ही खरीदे जा सकते हैं, परन्तू दूसरी प्रकार की बैंकों के ग्रंश सहकारी समिति तथा निजी व्यक्ति दोनों ही को बेचे जाते हैं। केवल पश्चिमी वङ्गाल तथा पंजाब की शीर्ष बेंकें समिश्रित हैं, अन्य सभी राज्यों में मिश्रित वैंक स्थापित की गई हैं। इस समय ऐसी कुल बैंकों के ४०% अंश निजी व्यक्तियों के पास हैं और ६०% प्रश सहकारी समितियों तथा प्रन्य प्रकार की बैंकों के पास हैं। सन् १९५६-५७ में ऐसी बैंकों की संख्या २४ थी। सदस्यों की संस्था ३३,४४० थी । भ्रंश पूँजी भ्रौर सुरक्षित कोष ५ ३१ भ्रौर ३ ४८ करोड़ रुपये के थे। उपरोक्त वर्ष में इन संस्थाग्रों ने सहकारी बैंकों ग्रौर समितियों तथा व्यक्तियों को १२३ ७१ करोड़ रुपयों के ऋ ए। दिये थे, जबिक इससे पिछले वर्ष में ऋ एगों की मात्रा केवल ५५ २७ करोड़ रुपया थी । कुल कार्यवाहक पूँजी ७६ ५४ करोड़ रुपया थी, इसमें १३ ७% निजी घन, ८० ६% जमा तथा २५ ५% अन्य सावनों से प्राप्त ऋण थे।

स्थित इस प्रकार दृष्टिगोचर होती है कि सन् १९५४-५५ में इन शीर्ष बेंकों का ग्राधे से ग्रांविक जमाधन विभिन्न व्यक्तियों की निक्षेपों से प्राप्त हुग्रा था ग्रीर शेष (लगभग ४०%) बराबर-बराबर मात्राग्रों में सहकारी बैंकों ग्रीर छोटी छोटी समितियों से प्राप्त हुग्रा था। कुल प्राप्त ऋगों का ३८% व्यापार बेंकों से मिला था ग्रीर ६२% रिजर्व बेंक तथा सरकार से। दिये हुए कुल ऋगों का ५२% सहकारी बेंकों तथा समितियों को दिया गया था ग्रीर शेष व्यक्तियों को। सन् १९५१-५२ के वर्ष में ३८ २ करोड़ रुपये के ऋगा लौट ग्राये थे ग्रीर ४२ १ करोड़ रुपये के कुल ऋगा दिये गये थे। शीर्ष बैंकों के बकाया ऋगा सन् १९५६-५७ वर्ष के ग्रन्त में ४६ ६२ करोड़ रुपये के थे।

# केन्द्रीय सहकारी बैंक--

केन्द्रीय समितियों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं:—(१) केन्द्रीय बैंक तथा बैंकिंग संघ ग्रीर (२) केन्द्रीय गैर-साख समितियाँ। केन्द्रीय सहकारी बैंकों का प्रमुख कार्य ग्रपनी सदस्य सहकारी समितियों के लिए सन्तुलन कारक उपस्थित करना तथा कोषों को ग्रारम्भिक सहकारी समितियों की ग्रीर प्रवाहित करना होता है। ऐसी बैंक शीर्ष बैंकों ग्रीर ग्रारम्भिक सहकारी समितियों के बीच मध्यस्थ के रूप में होती हैं।

सन् १६५३-५४ में केन्द्रीय बैंकों की संख्या ४६६ थी ग्रौर सदस्यता २,४७,६०५, किन्तु ग्रमले वर्ष ग्रर्थात् सन् १६५४-५५ में यह घट कर ४६५ रह गई, यद्यपि सदस्यों की संख्या २,४७,६०५ से बढ़ कर २,७२,००० हो गई थी। सदस्यों में ५२% बैंक तथा सहकारी समितियाँ थीं। कुल चालू पूँजी ग्रर्थात् ७३ ६८ करोड़ रुपए में में १७.७% निजी पूँजी, ६२ ६% जमाधन तथा शेष ग्रन्य प्रकार के ऋगों के रूप में थी। इन बैंकों का कार्य काफी गड़बड़ है ग्रौर इनकी जमा पूँजी ग्रावश्यकता से बहुत कम है। इन बैंकों के जमाधन का ६७% व्यक्तियों से ग्रौर शेष सहकारी समितियों में प्राप्त हुग्रा था। कुल ऋगों में से सहकारी बैंकों, सरकार तथा रिजर्व बैंक ग्रौर व्यापार बैंकों का हिस्सा क्रमशः ६१, ११ ग्रौर द प्रतिशत था। उपरोक्त वर्ष में इन बैंकों ने ६६ १७ करोड़ रुपये के ऋगा दिए थे। वर्ष के ग्रन्त में कुल बकाया ४२ ६६ करोड़ रुपये की थी।

इन बैंकों की संख्या में घटने की प्रवृत्ति बराबर बनी हुई है। सन् १६५६-५७ में इनकी संख्या ४५१ थी, किन्तु सदस्यता में निरन्तर वृद्धि हुई है। उपरोक्त वर्ष में सदस्यता ३,१०,५५५ तक पहुँच गई थी। इस वर्ष कार्यवाहक पूँ जी भी बढ़कर ११० २६ करोंड़ रुपए तक हो गई थी, जिसका १६ ५% निजी कोषों, ५३.०% जमाधन ग्रीर ३० २% ऋरणों से प्राप्त हुन्ना था। वर्ष विशेष में १०० ५० करोड़ रुपये की राशि के ऋरण दिए गए थे। परिदत्त ग्रंश पूँजी ११ ११ करोड़ रुपया थी ग्रीर सुरक्षित कोष

७ ३४ करोड़ रुपया । वर्ष के अन्त में इन वैंकों के कुल विनियोग २६ ० ४ करोड़ रुपयें के थे, जिनमें से १४ ६४ करोड़ रुपए सरकारी तथा प्रयान्सी हुन्डियों में लगे हुए थे। कृषि-श्रीर अ-कृषि साख समितियाँ—

भारत में सहकारी साख समितियों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—
(१) कृषि सहकारी साख समितियाँ (Agricultural Credit Societies)
गौर (२) ग्र-कृषि सहकारी साख समितियाँ (Non-agricultural Credit Societies) । कृषि सहकारी समितियाँ ही देश के सहकारी साख संगठन का ग्राधार हैं । ऐसी समितियों की संख्या सन् १६५६-५७ में १,६१,५१० थी गौर इनकी सदस्यता तथा कार्यवाहक पूँजी क्रमशः ६१,१६,८४६ तथा ६८-३० करोड़ रूपया थी। इन्होंने इस वर्ष ६७ ३३ करोड़ रूपया के ऋग् दिए थे। ऐसी समितियों को पूँजी के लिए साधारणतया केन्द्रीय वित्त संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। उपरोक्त वर्ष में ऋग्, निजी पूँजी तथा जमा कुल कार्यवाहक पूँजी के क्रमशः ५८-१, ३३-६ गौर ८-१% थे। यह स्थित बहुत ग्र-छी नहीं है, इसलिए बचतों गौर जमाधन को ग्राक-र्षित करने की ग्रावश्यकता बहुत है। निम्न तालिका में कृपि सहकारी साख समितियों की समस्त स्थिति दिखाई गई है:—

( रुपयों में )

	(11111)	
	१६५१-५२	१६५६—५७
भ्रौसत सदस्यता	88	¥ E
ग्रौसत ग्रंश पूँजी प्रति समिति	द२७	१,२२=
श्रीसत श्रंश पूँजी प्रति सदस्य	38	२२
श्रौसत जमा प्रति समिति	805	88=
भौसत जमा प्रति सदस्य	8	2
भौसत कार्यवाहक पूँजी प्रति समिति	8,860	६,०=६
भौसत कार्यवाहक पूँजी प्रति सदस्य	EX.	200

आरम्भ से ही सहकारी साख आन्दोलन का उद्देश्य किसानों को इतनी नीची ब्याज की दरों पर ऋगा देना रहा है जितना कि वे दे सकते हैं, किन्तु इस दिशा में अभी सफलता कम ही मिली है। सहकारी समितियों की ब्याज की दर बराबर ऊँची ही रही है (१२३ से २१% तक)। उन राज्यों में भी जहाँ सहकारी आन्दोलन उन्नत प्रवस्था में है, ब्याज की दरें ४ और १२% के बीच रही हैं।

अ-कृषि सहकारी साख समितियों में मजदूरों और नौकरी पेशा लोगों की सह-कारी साख समितियों तथा नागरिक सहकारी बेंक सम्मिलित होती हैं। सन् १६५४-५५ में ऐसी कुल समितियों की संख्या ६,३४५ थी। इनकी सदस्यता और कार्यवाहक पूँजी कमश: २५,४७,६४४ और ७५°३२ करोड़ रुपया थी। ऐसी समितियों का जमाधन कुल पूँजी का ६२°४% था। वर्ष विशेष में ऐसी सिमितियों ने ६२°१२ करोड़ रुपए के ऋगा दिये थे। सन् १९५६-५७ के श्रन्त में इनका जमाधान ६४°४६ करोड़ रुपया था, जो कुल कार्यवाहक पूँजी का ६४°३१% था।

रिजर्व बैंक तथा सहकारी साख-ग्रान्दोलन-

यह तो निश्चय है कि बिना ग्रामीण साख के नियन्त्रण तथा उसकी व्यवस्था के रिजर्व बैंक ग्रपने उद्देशों में सफल नहीं हो सकती है। रिजर्व बैंक के सम्बन्न में यह महत्त्वपूर्ण सत्य सभी ने स्वीकार किया है। रिजर्व बैंक कृषि व्यवसायों के लिये लिखे गए बिलों को खरीद सकती है, बेच सकती है तथा उनको फिर से भुना सकती है, यदि ऐसे बिलों पर किसी अनुसूचित बैंक ग्रथवा राज्य सहकारी बैंकों के हस्ताक्षर होते हैं। कृषि बिलों को १५ महीने तक की परिपक्कता पर भी स्वीकार किया जाता है। सरकारी पत्रों तथा स्वीकृत ऋरण-पत्रों पर रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को ६० दिन तक के-लिए ऋरण भी दे सकती है, परन्तु इस कार्य के लिए सहकारी बैंक को समय-समय पर रिजर्व बैंक के पास विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। नए संशोधित एक्ट के श्रनुसार रिजर्व बैंक कृषि साख में ग्रौर भी सहायता देगी।

श्रप्रैल सन् १६३५ में ही रिजर्व बैंक ने एक कृषि साख विभाग स्थापित किया था, जो इस विषय से सम्बन्धित ग्रनेक प्रश्नों का ग्रध्ययन करता है ग्रीर ग्रावश्यकता पड़ने पर सहकारी बैंकों को सलाह भी देता है । साधारणतया व्यवहार में सहकारी बैंकों तथा ग्रन्य बैंकों के बीच रिजर्व बैंक किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं करती है । उल्टी सहकारी बैंकों को प्राथमिकता दी जाती है । सन् १९५५ के संशोधन नियम ने सहकारी श्रान्दोलन के प्रोत्साहन के लिये दो ग्रलग कोषों की स्थापना की व्यवस्था की है ।

विगत वर्षों में राज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक से मिलने वाली सहायता में बराबर वृद्धि हुई है। ग्रत्यकालीन ऋगों के लिए सन् १६५६-५७ में १८ राज्य सहकारी बैंकों के लिये रिजर्व बैंक ने ऋगा की ग्रधिकतम् सीमा ३३.६४ करोड़ रुपया रखी थी, जबिक सन् १६५५-५६ में १७ राज्य सहकारी बैंकों के लिए ऋग सीमा २६.७६ करोड़ रुपया थी। मध्यकालीन वित्त के निमित्त स्वीकृत राशि सन् १६५६-५७ में १५७ लाख रुपया थी। मध्यकालीन वित्त के निमित्त स्वीकृत राशि सन् १६५६-५७ में १५७ लाख रुपया थी, जबिक गत वर्ष में यह केवल ६६.६७ करोड़ रुपया थी। सन् १६५५-५६ के वर्ष में रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि साख ( दीर्घकालीन ) कोष (National Agricultural Credit 'Long-term' Fund) स्थापित किया था, जिसमें ग्रारम्भ में १० करोड़ रुपये जमा किए गए थे। जून सन् १६५६ में ५ करोड़ रुपया ग्रीर भी दिया गया था। इस कोष का उद्देश्य यह है कि राज्य सरकारों को सहकारी संस्थाग्रों के ग्रंश खरीदने के लिए दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन ऋगा दिए जार्ये। मार्च सन् १६५७ के ग्रन्त में इस कोष में से ११ राज्यों को २६६-२० लाख रुपए के ऋगों की स्वीकृति दी गई थी। सन् १६५६-५७ में रिजर्व

वैंक ने १ करोड़ रुपए की पूँजी से राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरता) कीय (National Agricultural Credit 'Stabilisation' Fund) भी स्थापित किया ५. " सहकारी आ्रान्दोलन की प्रगति के क्षेत्र में अन्य महत्त्वपूर्ण घटना मार्च सन् १९४७ में केन्द्रीय गोदाम प्रमण्डल की स्थापना है।

सहकारी साख ग्रान्दोलन के दोष-

सहकारी श्रान्दोलन के ५५ वर्ष के कार्यवाहन में कुछ ऐसे दोप किल्लेटर हुए हैं जिन पर घ्यान देना श्रावश्यक है:—

- (१) अभी तक इस आन्दोलन ने ग्रामीए। ऋगों की समस्या का एक छोर हो।
  - (२) समितियों के बकाया ऋ गों की मात्रा बहुत अधिक रहती है।
  - (३) लेखे समुचित रूप में नहीं होते हैं।
  - (४) नियन्त्रम् तथा प्रबन्ध म्रकुशल है।
  - (५) अनुचित व्यवहारों की संख्या काफी अधिक है।
- (६) उन सरकारी अधिकारियों के शिक्षण की ग्रभी तक भी भारी कमी है जिनके संरक्षण में यह ग्रान्दोलन चल रहा है।
- (७) भारतीय सहकारी साख ग्रान्दोलन का एक गम्भीर दोष यह है कि यह लोगों पर ऊपर से थोगा गया है, उनके हृदय में स्वयं सहकारी प्रेरणा उत्पन्न नहीं हुई है ग्रौर सरकारी हस्तक्षेप की ग्रधिकता के कारण इस पर जनता का ग्रावश्यक विश्वास नहीं जम पाया है।
- ( ज ) एक सहकारी समिति की सफलता कुछ विशेष शर्तों पर निभंर होती है, जैसे—सदस्यों का समुचित निर्वाचन, पारस्परिक सहयोग, उच्च चरित्र, ईमानदारी, समुचित श्रंकेक्षरा तथा निरीक्षरा। व्यवहार में ये शर्ते शायद ही पूरी हो पाती हैं।

भारत में सहकारी समितियों के ब्याज की दर भी साधारएतया ऊँची रहती है। इसके कई कररए। हैं :—(i) सहकारी समितियों साधारएतया पर्याप्त स्थानीय निक्षेप जमा करने भीर जनता में बचत प्रवृत्ति को उत्पन्न करने में भसफल रही हैं, जिसके कारए। उन्हें श्रधिकतर ऋएों पर निर्भेर रहना पड़ता है।(ii) मद्रास तथा बम्बई राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में केन्द्रीय सहकारी वेंक साधारएतया छोटी संस्थाएँ होती हैं। इस कारए। व्यवहार में यह होता है कि शीर्ष वेंक उससे अधिक दर पर ब्याज देती हैं जिस पर स्वयं उन्हें ऋए। मिलता है, केन्द्रीय सहकारी वेंक ऋए। देते समय दर को और बढ़ा देती है तथा तत्परचात भारिमक समितियाँ उनमें भौर भी वृद्धि कर देती हैं। इस स्थिति को दूर करने के लिए रिजवं वेंक ने चार सुमाव दिये हैं:—(१) केन्द्रीय सहकारी वेंक की कुशलता को बढ़ाना, (२) प्रामीए। वचतों का एकत्रित करना, (३) केन्द्रीय बेंकों का संघीकरए। तथा (४) राज्य सरकारों द्वारा प्रिक्ष वित्तीय सहायता।

## दोषों को दूर करने के उपाय-

सहकारी श्रान्दोलन के दोषों को दूर करने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के निम्न सभाव विचारणीय हैं:—

- (१) सहकारी समितियों को ग्रपने सुरक्षित कोषों को बढ़ाना चाहिए।
- (२) ऋगों के प्रदान करने में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।
- (३) ग्रारम्भिक सहकारी समितियों को बहुमुखी समितियों में परिवर्तित कर देना चाहिए, जिससे कि उनका वित्तीय ग्राधार हढ़ हो, उनकी लोकप्रियता बढ़े ग्रौर वे किसान की ग्रियंक ग्रावश्यकताओं को पूरा कर सकें।
- (४) सहकारी ग्रान्दोलन की कुशलता को बढ़ाने के लिए उनके कर्मनारियों के शिक्षरा की व्यवस्था की जाय।

#### सहकारी साख ग्रान्दोलन की सफलता ग्रौर उसका सुधार-

किमयों के रहते हुए भी सहकारी आन्दोलन से निम्न फल प्राप्त हुए हैं :-

- ( क ) इसने सभी दिशाम्रों में ब्याज की दरों को कम किया है।
- ( ख ) इसने बचत तथा विनियोग प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया है।
- (ग) इसने अनुत्पादक ऋगों की मात्रा को काफी कम कर दिया है।
- ( घ़ ) इसने किसानों और कारीगरों के चरित्र को बलवान किया है, सहयोग की भावना को बढ़ाया है श्रीर उन्हें स्वतन्त्र दृष्टिकोएा प्रदान किया है।
- (ङ) इसने नगर के पूँजीपितयों तथा श्रिमिकों में ग्रामीए। क्षेत्रों के प्रति ग्रिमिक दिलचस्पी उत्पन्न की है।

सहकारी साख श्रान्दोलन के सुधार के सम्बन्ध में कुछ सुभाव ऊपर दिये जा चुके हैं, परन्तु कुछ श्रौर सिफारिशें नीचे दी जाती हैं:—

- (१) बकाया ऋणों तथा दीर्घंकालीन ऋणों को घ्रत्पकालीन ऋणों से पृथक रखना चाहिए। किश्तों में भुगतान लेकर बकाया ऋणों को वसूल करना चाहिए तथा वस्तुओं में नए ऋणा देने चाहिए।
- (२) यथासम्भव ऋगा उत्पादक कार्यों के ही लिए होने चाहिए, परन्तु इस सम्बन्ध में यह ग्रावश्यक है कि नियम इतने कड़े न हों कि कृषक को साहकार की शरगा लेनी पड़े।
- (३) केन्द्रीय तथा राज्य सहकारी बेंकों का पुनर्संगठन होना चाहिए श्रीर बड़ी-बड़ी बेंकों को ऐसी संस्थाओं में संगठित करना चाहिए जिनमें प्रबन्ध की कुशलता तथा कार्यवाहन की शीघ्रता हो।
- (४) केन्द्रीय संस्थाओं में घीरे-घीरे निजी व्यक्तियों की सदस्यता समाज होनी चाहिए ।
- ( प्र ) भूमि सुघार हेतु एक ऐसी केन्द्रीय संस्था स्थापित की जाय जो दीर्ष-

कालीन ऋए। दे, भूमि बन्धक वेंकों के ऋए। पत्रों का अभिगोयन करे तथा उन्हें विशेष कार्यों के लिए ऋए। दे।

- (६) सहकारी बैंकों को विश्रेप मुविघाएँ प्रदान करने की दर साघारण दर से कम रखी जाय।
- (७) सहकारी समितियों द्वारा डाकखानों में जमा किए जाने वाले धन के जमा करने और निकालने के नियमों को ढीला किया जाय।
- ( प्र) सहकारी सिमितियों तथा बैंकों को राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों के बेचने के लिए अभिकर्ता अधिकार दिये जायें।

# च-वर्षीय योजनाएँ श्रौर सहकारी साख—

- (१) सहकारी साख के विकास को सहकारी आन्दोलन की प्रारम्भिक प्रवस्था मात्र समभा जाय और फिर घीरे-घीरे आर्थिक जीवन की ग्रन्य शास्त्राओं में उसे फैलाया जाय।
- (२) प्रत्येक गाँव के हर एक परिवार को कम से कम एक सहकारी समिति का सदस्य होना चाहिए।
- (३) सहकारी भ्रान्दोलन के विकास का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीए। परिवार की साख बढ़ाना होना चाहिए।

प्रथम पंच-वर्षीय योजना में रिजर्व बैंक की सहायता से सहकारी झान्दोलन का काफी विकास हुआ है। प्रथम योजना के अन्त में देश में १८ राज्य सहकारी बैंक, ४६६ केन्द्रीय बैंक और संघ, १,२६,६५४ आरिम्भिक साख समितियाँ और ६ केन्द्रीय तथा २६१ अन्य भू-प्राधि बैंक थीं। आरिम्भिक कृषि सहकारी साख समितियों की सदस्यता ५८ लाख थी। दूसरे पंचवर्षीय आयोजन में आन्दोलन का बहुत सिक विकास होगा और देश की कम से कम २०% जन-संख्या किसी न किसी सहकारी समिति की सदस्य रहेगी।

सहकारी साख संगठन के विकास के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य निम्न प्रकार हैं:--

बड़े ग्राकार की सिमितियों की संख्या	१०,४००
अल्पकालीन साख का लक्ष्य	१५० करोड़ रुपया
मध्यकालीन साख का लक्ष्य	١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١
दीर्घकालीन साख का लक्ष्य	રય ,, ,,

## **QUESTIONS**

1. Explain the difference between the two: - Primary Cooperative Credit Society and a Cooperative Central Bank.

(Agra, B. Com., 1958, 1956 Supp., 1954)

2. What are cooperative banks? Indicate their importance in a country like India and explain the nature of the different types of cooperative banks working in the country.

(Agra, B. Com., 1955)

3. How far have the Cooperative Banks succeeded in their objectives and indicate the help that the Reserve Bank of India does and should render to them in this connection?

(Raj., B. Com., 1956)

4. Discuss the nature, constitution and functions of cooperative banks in India. Give a brief critical estimate of their work in India as rural financiers. (Raj., B. Com., 1954)

5. What are the agencies of rural finance in India? How far has the cooperative movement succeeded in replacing the village Mahajan? (Agra, B. Com., 1957)

6. Write a note on :--

Cooperative Central Bank.

(Agra. B. Com., 1957 Supp. and 1955 Supp.) Primary Cooperative Credit Societies.

(Agra, B. Com., 1955)

7. Write short note on: Agricultural Credit Department रिजर्व बेंक का कृषि साख विभाग

Blom

(Agra, B. Com., Pt. I, 1959)

#### अध्याय ४२

# भारत में भूमि-बन्धक वैंक

(The Land Mortgage Banks in India)

#### परिभाषा--

कृषकों की वित्तीय आवश्यकतायें तीन प्रकार की होती हैं। अपनी फसलों की विक्री के लिए उन्हें अल्पकालीन ऋगों की आवश्यकता होती है। फसल को वेच कर धन तुरन्त प्राप्त नहीं होता, जबिक लगान तथा अन्य प्रकार के कर तुरन्त हो चुकाये जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिस समय फसल तैयार होती है, उपज्की कीमत नीची रहती है और किसान के लिये थोड़ी प्रतीक्षा करना लाभदायक होता है। ऐसी दशा में सहकारी समितियों तथा व्यापारिक बैंकों से अल्पकालीन ऋगों लिये जाते हैं। मध्यकालीन ऋगों की आवश्यकता बीज, खाद आदि के लिए पड़ती है, जो साध रगान्त्रया सहकारी समितियों और साहकारों से लिये जाते हैं। इन दोनों प्रकार के ऋगों के अतिरिक्त कृषकों को दीर्घकालीन ऋगों की भी आवश्यकता होती है। ऐसे ऋगों के अतिरिक्त कृषकों को दीर्घकालीन ऋगों की भी आवश्यकता होती है। ऐसे ऋगों के अतिरिक्त कृषकों को दीर्घकालीन ऋगों की भी आवश्यकता होती है। ऐसे ऋगों के अतिरिक्त कृषकों को दीर्घकालीन ऋगों की भी आवश्यकता होती है। ऐसे ऋगों के आमीग्ग महाजन हैं, परन्तु विगत वर्षों में भूमि-बन्धक बैंक ऐसे ऋगों का प्रमुख स्रोत आमीग्ग महाजन हैं, परन्तु विगत वर्षों में भूमि-बन्धक बैंक ऐसे ऋगों की व्यवस्था करने लगी हैं।

भूमि बन्धक प्रथवा भू प्राधि बैंकों से हमारा अभिप्राय ऐसी बैंकों से होता है जो भूमि की आड़ पर कृषकों को दीर्घंकालीन ऋएए प्रदान करती हैं। साधारएएतया भारत में आधुनिक बैंक अचल सम्पत्ति की आड़ पर ऋएए नहीं देती हैं। भूमि की आड़ पर ऋएए देना तो और भी अनुपयुक्त समभा जाता है, क्योंकि उसके स्वामित्त्व का सही-सही पता लगा लेना अधिक कठिन होता है। इस प्रकार की जमानत स्वीकार करने में बैंकों के आदेयों की तरलता भी समाप्त हो जाती है। इसके अविरिक्त भूमि की कीमत का सही-सही अनुमान केवल विशेषज्ञों द्वारा ही लगाया जा सकता है, जिनका रखना प्रत्येक बैंक के लिए सम्भव नहीं होता है। भूमि बन्धक बैंक अपना संगठन इस प्रकार बनाती हैं कि उन्हें भूमि की आड़ पर दीर्घंकालीन ऋएए देने में कठिनाई नहीं होती है। भारत में भूमि-बन्धक बैंकों का महत्त्व—

यह तो सभी स्वीकार करते हैं कि भारत में कृषक वित्त काफी मेंहगा है। ग्रामीए। बैंकिंग जाँच समिति ने पता लगाया है कि ग्रामीए। क्षेत्रों में ब्याज की दर २०% से लेकर ७५% तक है। सवाया ग्रीर ड्यौड़ा, जिसके ग्रन्तगंत कृषक को

क्रमशः २५ तथा ५०% ब्याज देना पड़ता है, बहुत प्रचलित है। ऊँची ब्याज की दरों के ग्रनेक कारए। हैं। कृषक की साख नीची होती है, क्योंकि उसके पास कोई उपयुक्त प्रतिभूति नहीं होती है। साहूकार व्यक्तिगत प्रतिभूति पर ऋए। देकर जोखिम उठाते हैं ग्रीर इसी कारए। ग्रधिक ब्याज लेते हैं। कृषक की वित्तीय ग्रावश्यकतायें भी महान् हैं। ग्रपनी निर्धनता के कारए। दूषित सामाजिक रीति-रिवाजों के कारए। ग्रीर पहले से ही ऋए। होने के कारए। कृषक को सदा ही ऋए। की ग्रावश्यकता पड़ती रहती है। ग्रामीए। क्षेत्रों में उन संस्थाग्रों की भी भारी कमी है जो दीर्घकालीत ऋए। को प्रदान कर सकें। हमारी साख समितियों का विकास ग्रभी बहुत पीछे है ग्रीर ग्रे समितियाँ दीर्घकालीन ऋए। को प्रदान कर सकें। हमारी साख समितियों का विकास ग्रभी बहुत पीछे है ग्रीर ग्रे समितियाँ दीर्घकालीन ऋए। को देने में संकोच करती हैं। ऐसा ग्रनुमान लगाया गया है कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् ऋए। प्राप्ति के स्रोत ग्रीर भी सूखते जा रहे हैं। इस दिशा में भूमि-बन्धक बैंकों का विकास ही एकमात्र सहारा हो सकता है।

साधार एतिया भूमि-प्राधि बैंक ऋ एा -प्राथियों तथा ग्रन्य व्यक्तियों के ऐसे संब होती हैं जो सदस्यों को पिछले ऋ एों को चुकाने तथा भूमि सम्बन्धी सुधारों के बिए ऋ एा देते हैं। ऐसी बैंकों से भारत में निम्न लाभों की ग्राशा की जाती है:—

- (१) इनके द्वारा कृषक वर्ग का ऋगा भार घट जायगा, जिससे उनकी दिर-द्वता दूर हो जाने के कारगा भविष्य में आय की वृद्धि की सम्भावना उत्पन्न हो जायगी।
- (२) भारतीय कृषक को कृषि की सीमा का विस्तार करने का ग्रवसर मिलेगा, जिसके फलस्वरूप देश में कृषि उपज की वृद्धि होगी।
- (३) भूमि में स्थायी सुधार होने के कारण कृषि उत्पादन की प्रकृति पर निर्भरता कम हो जायगी। इससे कृषक का आर्थिक आधार हढ़ होगा और उसकी भ्राय की अस्थिरता कम हो जायगी।
  - (४) इन बैंकों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज की दर नीचे गिरेंग्री।
- (१) कृषकों के लिए समुचित प्रतिभूति देने की व्यवस्था हो जायगी, जिस्का उनकी साख पर श्रच्छा प्रभाव पड़ेगा।
- (६) भूमि-बन्धक बैंक कृषकों की साहूकारों पर निर्भरता कम कर देगी, जिसका सहकारी साख संगठन के विकास पर भी अच्छा प्रभाव पढ़ेगा।
- (७) इन बैंकों की स्थापना से ग्रामीए। क्षेत्रों में सहकारिता ग्रीर सहयोग की नई जागृति उत्पन्न होगी, क्योंकि भारत में भूमि-बन्धक बैंक भी साधारणतया सहकारी भाषार पर संगठित किये जा रहे हैं।

भूमि-बन्धक बैंकों के प्रकार-.

भूमि-बन्धक बैंकों का संगठन कई प्रकार किया जाता है। कभी-कभी इन बैंकों को पूर्णतया सहकारी बैंक बनाया जाता है, परन्तु शुद्ध वाि व्य ध्राधार पर भी ऐसी बैंक खोली जाती हैं। ऐसी बैंकों के निम्न तीन रूप अधिक प्रचितत हैं:—

- (१) सहकारी भूमि-बन्धक वैंक—इस प्रकार की बैंक शुद्ध सहकारी आधार पर स्थापित की जाती हैं। ऋगु के इच्छुक व्यक्ति आपस में मिलकर एक संध बनाते हैं। पूँजी प्राध बाँध (Mortgage Bond) निकाल कर प्राप्त की जाती है, जिस पर ब्याज दिया जाता है और जो वाहक को शोधनीय होते हैं। इसके अतिरिक्त ऋगों के रूप में भी पूँजी प्राप्त की जा सकती है। ऐसी मू-प्राध वेंकों की साधारगान्त्रया निजी पूँजी नहीं होती, सभी पूँजी (Bonds) द्वारा प्राप्त की जाती है। ऐसी बैंकों का उदाहरगा जर्मनी में मिलता है, जो ऋगी व्यक्तियों के सहकारी संघ के रूप में होती हैं। अमरीका में भी संघीय फार्म ऋगा बैंक (Federal Farm Loans Banks) सहकारी आधार पर स्थापित की गई हैं।
- (२) वारिएाज्यिक भू-प्राधि बैंक—ऐसी बैंक शुद्ध वारिएज्यिक ग्राधार पर कार्यं करती हैं। सहकारी भू-प्राधि बैंक की निजी पूँजी नहीं होती। वह न तो लाभ कमाती है ग्रौर न लाभांश घोषित करती है। वारिएज्यिक भू-प्राधि बैंकों के पास मिश्रित पूँजी बैंकों की भाँति निजी पूँजी होती है, वे लाभ के उद्देश्य से कार्यं करती हैं । इनकी एक मात्र विशेषता कृपकों को भूमि की ग्राइ पर दीर्घंकालीन ऋएए देना होती है। व्यवहार में ऐसी बैंकों पर किसी न किसी ग्रंश तक सरकारी नियन्त्रएए रहता है। सरकार इस बात का प्रयत्न करती है कि प्रधिक लाभ कमाने के लिए ऊँची व्याज न लें ग्रौर ग्रपने ऋएए-पत्रधारियों के प्रति धनुचित व्यवहार न करें। भारत में इस प्रकार की भू-प्राधि बैंक नहीं हैं, परन्तु यूरोप के लगभग सभी देशों में मिश्रित पूँजी भू-प्राधि बैंक पाई जाती हैं। ऐसा ग्रनुभव किया गया है कि ऐसी बैंक उन्हीं देशों में सफल होती हैं जहाँ ग्रन्य प्रकार की बैंकिंग सुविधाएँ प्रदुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं।
- (३) स्राभास-सहकारी भू-प्राधि वैंक (Quasi-Co-operative Land Mortgage Banks)—इस प्रकार की प्रूमि-वन्चक वैंक प्रथम दो प्रकार की बेंकों का मिश्रित रूप है। ऐसी बैंक ऋरण लेने वालों के संघ द्वारा स्थापित की जाती हैं। इनकी पूँजी ग्रंशों की बिक्री, ऋरण-पत्रों की निकासी तथा ऋरणों द्वारा प्राप्त की जाती है। इन संस्थाओं में ग्रंशघारियों को मतदान ग्रंघिकार होता है, यद्याप मतदान शक्ति का ग्रंशों की संख्या से सम्बन्ध नहीं होता है। ये बेंक मिश्रित पूँजी कम्पनियों की भाँति सीमित उत्तरदायित्व के ग्राधार पर कार्य करती हैं। भारत में इसी प्रकार की भू-प्राधि बेंकों का ग्रंघिक प्रचलन है। शुद्ध सहकारी भू-प्राधि बेंकों का विकास ग्रंभी कम हुआ है, यद्यपि सभी भू-प्राधि बेंकों में सहकारिता का ग्रंश काफी रहता है।

ऐसी बैंक भी दो प्रकार की हो सकती हैं—शुद्ध और मिश्रित। शुद्ध बैंक वह होती है जिनके ग्रंश केवल ऋगा-इच्छुक सदस्यों को बेचे जाते हैं, मिश्रित बैंकों में ऋगी के ग्रितिरक्त. ग्रन्य व्यक्ति भी ग्रंश खरीद सकते हैं। भारत में ग्रिधिकांश भूषाधि बेंक मिश्रित प्रकार की हैं। बहुधा इस बात पर जोर दिया जाता है कि बाहरी व्यक्तियों

को भू-प्राधि बैंकों की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, परन्तु पूँजी के ग्रभाव के कारण हमारे देश में ऐसा करना उपयुक्त नहीं है।

## भू-प्राधि बैंकों के कार्य-

भारत में भू-प्राधि बैंक केन्द्रीय बैंक और ग्रारम्भिक बैंक के रूप में होती हैं। भू-प्राधि बैंक की प्रमुख इकाई ग्रारम्भिक बैंक ही होती है। केन्द्रीय बैंक ग्रारम्भिक बैंकों के संघ के रूप में होती है। एक ग्रारम्भिक भू-प्राधि बैंक के कार्य निम्न प्रकार होते हैं:—

- (१) अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को उन्नत करना, जिसके लिए मुख्य-तया अचल सम्पत्ति की प्राधि पर कुछ, उद्देश्यों के लिए ऋण दिये जाते हैं, जैसे — (क) गिरवी रखी हुई भूमि और मकानों तथा पुराने ऋणों को चुकाने के लिए ऋण देना, (ख) कृषि की रीतियों में सुधार करने के लिए और भूमि सम्बन्धी सुधार के लिए ऋण देना, (ग) कृषि सम्बन्धी यन्त्रों के खरीदने के लिए ऋण देना, (घ) भूमि खरी-दने, भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा नई भूमि तोड़ने के लिए ऋण देना।
- (२) सदस्यों में सहयोग ग्रौर सहकारिता की भावना उत्पन्न करना ग्रौर उनमें बचत ग्रौर उनसे सम्बन्धित ग्रुगों का उत्पन्न करना।
- (३) सदस्यों को भूमि ग्रौर उसके उपयोग सम्बन्धी समस्याग्रों के लिए ग्रावश्यक सलाह देना।

भारतीय भू-प्राधि बैंक अधिक से अधिक २० वर्ष के लिए ऋगा देती हैं। इनके ऋगा पत्रों की परिपक्कता अविध भी इससे अधिक नहीं होती है। अधिकांश राज्यों में भूमि की कीमत के ५० प्रतिशत तक ऋगा दिये जाते हैं। कुछ राज्यों के लगान के तीस गुने तक ऋगा देने का चलन है। ऋगा देने से पहले आड़ में रखी जां वाली भूमि के स्वामित्त्व तथा प्रार्थी की शोधनक्षमता की जाँच की जाती है। ब्याक की दर अलग-अलग राज्यों में ६ प्रतिशत से लेकर १० प्रतिशत तक रहती है।

श्रिषकाँश ऋगा पुराने ऋगाों को चुकाने के लिए दिये गये हैं। विगत वर्षों राज्य सरकारों ने ऋगा निवारगा उपाय किये हैं। फलतः पुराने ऋगाों का भार का हुआ है और भू-प्राधि बैंक श्रिषक रचनात्मक उद्देश्यों के लिए ऋगा देने लगी हैं विभिन्न राज्यों की भू-प्राधि बैंकों के कार्यों और उनकी ऋगा-दान नीति में काप अन्तर रहा है। श्रलग-अलग राज्यों में सरकारी संरक्षण का ग्रंश भी अलग-अलग स् है। मद्रास और बम्बई राज्यों में ऐसी बैंकों की उन्नति अधिक हुई है।

# भारत में भू-प्राधि बैंकों का ग्रारम्भ—

भारत में सबसे पहली इस प्रकार की बैंक सन् १६२० में पंजाब में स्रोत गई थी, जो कुछ समय पीछे फेल हो गई। तत्पश्चात् मद्रास में 'सेन्ट्रल लैंड मोटेंगे बैंक' सन् १६१६ में स्थापित किया गया। इस बैंक के २ ५ लाख रुपये की कीमत ग्राधे ऋगा-पत्र मद्रास सरकार ने ले लिये थे, जिसने समस्त ऋग्-एकों के निर्गम पर १% ब्याज देने की भी जिम्मेदारी ली थी। यह बैंक प्रारम्भिक भू-प्राधि बैंकों की संघ के रूप में थी। सन् १९५० में प्रारम्भिक बैंकों की संख्या १२६ थी।

बम्बई में ऐसी बैंकों का संगठन सन् १६३५ में किया गया और निरोक्षरण स्वा सहायता के लिये उसी वर्ष बम्बई राज्य सहकारी भू-प्राधि बैंक स्वारित की वर्ष बम्बई राज्य सहकारी भू-प्राधि बैंक स्वारित की वर्ष बम्बई सरकार ने ५० लाख रुपये की राशि तक बैंक द्वारा जारी हुए ऋरण-पत्रों के मूलघन तथा ब्याज को चुकाने की गारन्टी दी। सन् १६५० में बम्बई में १६ प्रारम्भिक भू-प्राधि संस्थाएँ थीं। इसी प्रकार सन् १६५० में मैसूर में ७६ और मध्य-प्रदेश में ऐसी १४ संस्थाएँ थीं। अन्य राज्यों में सहकारी संस्थाओं के अभाव के कारण भू-प्राधि बैंकों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। उपरोक्त वर्ष में पिनमी बंगाल में २, उत्तर प्रदेश में ६, आसाम में २ तथा अजमेर में १२ प्रारम्भिक भू-प्राधि बैंक थीं। इस प्रकार पूरे भारत में सन् १६५३-५४ में २६१ आरम्भिक भू-प्राधि बैंक तथा ६ केन्द्रीय भू-प्राधि बैंक थीं, इनमें से २११ मद्रास, आन्ध्र और मैंनूर के तीन राज्यों में थीं। सन् १६५४-५५ में भी केन्द्रीय बैंकों की संख्या ६ ही रही, यद्यपि आरम्भिक बैंकों की संख्या बढ़ कर २६२ हो गई थी।

केन्द्रीय बैंकों की अधिकाँश पूँजी ऋरा-पत्रों की निकासी से प्राप्त होती है, जिन पर राज्य सरकार की गारन्टी रहती है। सन् १६५३-५४ के अन्त में ११ ४५ करोड़ रुपये के ऋरा-पत्र चालू थे, जिनमें से केवल मद्रास और आन्छ्र केन्द्रीय भू-प्राधि बैंकों के ऋरा-पत्र ७ २० करोड़ रुपये के थे। सन् १६५४-५५ के अन्त में १२ ७१ करोड़ रुपये के ऋरा-पत्र थे, जिनका ६३% मद्रास और आन्छ्र में था। आरम्भिक बैंकों की संख्या जून सन् १६५५ के अन्त में २६२ थी, जिन्होंने १४५ लाख रुपये के ऋरा उपरोक्त वर्ष में दिये थे। कृषकों के लिए ब्याज की दर ३ और ६ अपिशत के बींच थी। कुल २६२ आरम्भिक बैंकों में से २१२ आन्छ्र, मद्रास और मैसूर के तीन राज्यों में केन्द्रित थीं।

जून सन् १६५५ के ग्रन्त में भूमि-बन्घक बैंकों की सामान्य स्थिति निम्न प्रकार थी:—

	केन्द्रीय भूमि-बन्धक बेंक	ग्रारम्भिक भूमि- वन्धक वैक
<b>स्या</b>	3	२६२
दस्यता	६५,५६३	\$ <i>\$ 3, 0 3, 5</i> <i>\$ 0 3, 7 0, 8 8, 8</i>
र्एदान (रुपयों में) ग्यंवाहक पूँजी ( ,, )	२,४३,४८,४७६ १४,७८,८१,६८७	१०,४१,६७,४२२
144164 7 41 ( 1)		

सन् १९५६-५७ के अन्त में देश की ३२६ आरम्भिक भू-प्राधि वेकों में से ४० और कुल की ७३ ६१% आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर के तीन राज्यों में

केन्द्रित थीं। इनकी सदस्यता ३,३३,४६६ थी। इन बैंकों की कार्यवाहक पूँ बी १२'७० करोड़ रुपया थी ग्रीर इन्होंने वर्ष विशेष में २'०५ करोड़ रुपये के ऋग् दिर्वे थे। इन ऋगों पर ब्याज की दर ५ $\frac{1}{2}$  ग्रीर १०% के बीच थी। केवल बम्बई राज्य में कुछ प्रकार के ऋगों पर ३ $\frac{1}{2}$ % ब्याज लिया गया था। निम्न तालिका में समस्त देश से सम्बन्धित ग्रारम्भिक भू-प्राधि बैंकों की स्थिति दिखाई गई है:—

( लाख रुपयों में 🎙

शीर्षंक	१६५१-५२	१९४६-५७
ऋग दान	१३०	२०४
ऋग की वसूली	४५	54
बकाया ऋगा	६९६	१,१५१
ग्रन्य ग्रादेय, जैसेविनियोग तथा नकद शेषें	৬३	१२३
परिदत्त श्रंश पूँजी	४८	33
सुरक्षित-कोष	१३	38
शोधन कोष (Sinking Fund)		२
भ्रन्य कोष	ሂ	११
ऋरा प्राप्ति	६७५	१,१३२
ऋग -पत्र (Debentures)	3	<b>G</b>
-कार्यवाहक पूँजी	७,६०	ू १,२७०

## स्थिति में सुधार के सुभाव-

सन् १९२६ के सहकारी रिजस्ट्रार सम्मेलन में भू-प्राधि बैंकों की समस्या पर विचार किया गया था। बाद को इन संस्थाओं का विकास इसी सम्मेलन द्वारा निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार हुआ है।

उपरोक्त सम्मेलन के प्रमुख सुभाव निम्न प्रकार हैं:--

- (१) प्रबन्ध का सुधार—इन बैंकों का संगठन सहकारिता सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत हो और इनका कार्य-क्षेत्र इस प्रकार निश्चित किया जाय कि वह न तो आर्थिक हिष्टकोगा से अनुपयुक्त हो और न प्रबन्धि के हिष्टकोगा से कठिन हो।
- (२) ऋरगों के उद्देश्य—भू-प्राधि वैंक किसानों को कुछ विशेष कार्यों के लिए ही ऋरग दे सकती हैं, जो इस प्रकार हैं:—(ग्र) गिरवी रखी हुई मूमि ग्रथवा मकान को छुड़ाने के लिये, (ब) भूमि तथा कृषि के साधनों में स्थायी सुधार करने के लिए, (स) पुराना ऋरग चुकाने के लिये ग्रीर (द) भूमि खरीदने के लिये। प्रत्येक बेंक के लिए यह ग्राव-श्यक हैं कि वह यह स्पष्ट कर दें कि प्रत्येक प्रकार के ऋरग की न्यूनतम ग्रीर ग्रधिकतम सीमाएँ क्या होंगी ? सम्मेंलन ने सुभाव दिया हैं

कि ऋएा की राशि सम्पत्ति की कीमत के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- (३) ऋरण का भुगतान—ऋरण चुकाने की अवधि निश्चित करने में बैंक को ऋरण के उद्देश्य तथा ऋरणी की आधिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। अनुत्पादक कार्यों के लिए साधाररणतया ऋरण नहीं देने चाहिए।
- (४) सरकारी गारन्टी—सरकार को ऋगा-पत्रों के मूलघन और व्याज के चुकाने की गारन्टी देनी चाहिए। स्नारम्भ में सरकार उन्हें भाषिक सहायता दे, मुद्रांक करों में छूट दे तथा प्राधि के सम्बन्ध में कुछ विशेष सुविधायें दे।

इनके म्रतिरिक्त भूमि-बन्धक बैंकों की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए निम्न भ्रौर भी दिए जा सकते हैं:—

- (५) सुरक्षित कोषों में वृद्धि—इन बैंकों के लिए यह ग्रावश्य के प्रतीत होता है कि वे ग्रपनी ग्रार्थिक स्थिति की दृढ़ता के लिए ग्रपने सुरक्षित कोषों का विस्तार करें। इन्हें ग्रपने लाभ का ग्रिषकांश भाग ऐसे कोषों के ही निर्माण पर व्यय करना चाहिये।
- (६) बन्धक सूमि बेचने का अधिकार—ऋए के वसूल न होने की दशा में भू-प्राघि बैंकों को ऐसी भूमि बेचने का अधिकार होना चाहिए जो उनके पास गिरवी रखी गई है।
- (७) निक्षे पों पर रोक—भू-प्राघि बैंकों के जमा घन स्वीकार करने परं भी प्रतिबन्ध रहने चाहिए। या तो इन्हें इस प्रकार की जमा स्वीकार करने से रोकना चाहिए या फिर यह जमा ग्रधिक लम्बे काल के लिए होनी चाहिए।
- ( प्र ) लम्बे काल के लिए ऋग्ण—भारतीय भू-प्राधि बैंक केवल २० साल के लिए ऋग् देती हैं। यह अवधि कुछ दशाओं में बहुत ही कम रहती है । संसार के अन्य देशों की भाँति कुछ दशाओं में भारतीय भू-प्राधि बैंकों को भी ३०-४० वर्ष तक की अवधि के ऋग् देने चाहिए।
- (६) सहकारी सहायता—िवना सरकारी सहायता के भू-प्राधि वैकों की सफलता सम्भव नहीं है। ऐसी सहायता ऋएा-पत्रों की गारन्टी, कुछ ग्रंश तक ऋएा-पत्रों को खरीद कर, करों में विशेष रियायत देकर तथा ग्रारम्भ में सहायक अनुदानों द्वारा दी जा सकती है।
- (१०) विशेषज्ञ सेवायें—भूमि की सही कीमत को झाँकने के लिए भू-प्राघि बैंकों को सरकारी सूत्रों से विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करने का अधि कार होना चाहिए।

भ-प्राधि बैंकों की समस्यायें-

भू-प्राधि बैंकों की सफलता एक बड़े ग्रंश तक इस बात पर निर्भर होती है कि प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई भूमि की कीमत का सही ग्रनुमान लगाया जा सके ग्रीर ऋगा की वार्षिक किस्तों ठीक समय पर मिलती रहें। ग्रपनी एक वार्षिक रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने यह बताया था कि भारत में भू-प्राधि बैंक भूमि में स्थायी सुधार की अपेक्षा पुराने ऋगों के निस्तारण का ही कार्य ग्रधिक करती हैं। कोषों के प्राप्त करते तथा ऋगा-पत्रों के निस्तारण की रीतियाँ भी दोषपूर्ण हैं। केवल उन्हीं राज्यों में इन बैंकों ने पर्याप्त कोष एकत्रित किए हैं जहां की सरकारों ने इनके ऋगों की गारत्टी दी है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ऐसी बैंकों का महत्त्व निस्सन्देह महान् है, परन्तु यह समफना भूल होगी कि ग्रामीण वित्त की सभी कठिनाइयाँ इनके द्वारा दूर हो जायेंगी।

भू-प्राधि बैंकों के मार्च सन् १६५४ के सम्मेलन में यह बताया गया था कि इन बेंकों के पास घन की कमी है, ऋण देने में देर होती है, ब्याज की दर ऊंची होती है और उनकी वसूली में कठिनाई होती है। भारतीय भू-प्राधि बैंकों की ७७१ करोड़ रुपये की पूँजी में से ६ ७५ करोड़ रुपया केवल ऋण-पत्रों से प्राप्त होता है। कार्यविधि के सुधार के लिए तीन सुभाव दिये जा सकते हैं—(१) प्रथम ऋण के पश्चात् प्रत्येक अगले ऋण के लिए ब्याज की दर अधिक रखी जाय, (२) ऋण थोड़े समय के लिए दिए जायें, जिससे थोड़े कोषों द्वारा अधिक ऋण दिए जा सकें और (३) ऋणों के उपयोग से प्राप्त आय केवल ऋणों के भुगतान के लिए उपयोग की जाय। स्मरण रहे कि भू प्राधि बंक सारे कृषि ऋणों को अपने ऊपर तो नहीं ले सकती हैं, परन्तु ब्याज की दरों को गिराकर तथा किश्तों में शोधन की व्यवस्था करके वे ऋणों के भार को अवक्य घटा सकती हैं। दूसरे पच-वर्षीय आयोजन में भारत सरकार ने इनके सम्बन्ध में अखिल भारतीय ग्राम्य साख अनुसन्धान समिति की सिफारिशों को पूरा करने की नीति अपनाई है। योजनाकाल में सहकारी आधार पर इनके भारी विकास की आशा की जाती है।

### **QUESTIONS**

- 1. What are the credit needs of the Indian agriculturist? How are they met to day? (Raj., B. Com., 1949)
  - 2. What part is played by the Land Mortgage Banks in the rural economy in India? What are the difficulties in the development of this branch of banking in India?

- 3. Discuss the development of land-mortgage banks in India. How will you improve their efficiency.
- 4. Discuss the importance of land mortgage banks for agriculturists in India. What are your suggestions to improve upon their position?

भारतवर्ष के कृषकों के लिए मूमि-बन्धक ग्रिधकोषों का क्या महत्त्व है ? उनकी दशा सुधारने के लिए ग्रिपने सुभाव प्रस्तुत की जिए।

(Agra, B. Com, Pt. I, 1959)

### श्रध्याय ४३

## भारत में श्रीद्योितक वित्त

(Industrial Finance in India)

ग्रौद्योगिक पू<sup>\*</sup>जी के साधन---

भौद्योगिक कम्पनियों को दो प्रकार के कोषों की भ्रावश्यकता पड़ती है। दिन प्रति दिन का कार्य चलाने के लिए उन्हें अल्पकालीन ऋगों की भ्रावश्यकता होती है, जैसे—क्या माल खरीदने के लिए, मजदूरी चुकाने के लिए और तैयार माल को बिक्री करने के लिए, परन्तु इन कम्पनियों को मशीनों तथा स्थिर भ्रादेयों के खरीदने के लिए दीवकालीन ऋगों की भी भ्रावश्यकता होती है। इन दोनों प्रकार की पूँजी के प्रमुख साधन निम्न प्रकार हैं:—

(१) कार्यवाहक ग्रथवा ग्रल्पकालीन पूँजी—यदि कोई कम्पनी ऐसा भनुभव करती है कि दिन प्रति दिन का कार्य चलाने के लिए भी उसकी ग्रंश पूँजी अपर्याप्त है तो वह अल्पकालीन कोषों को उघार लेती है। इसके तीन साधन हैं:—(भ) कम्पनी के गोदामों और कारखानों के भीतर रखे हुए माल की आड़ पर व्यापारिक बेंक थोड़े समय के लिए ऋगा दे देती हैं, (ब) मैनेजिंग एजेन्टों (प्रबन्ध भिकर्ताओं) से ऋगों और अग्रिमों की प्राप्ति और (स) जन-साधारण से प्राप्त निक्षेप की राशि । कुछ उद्योगों में यह प्रथा है कि जनता से निक्षेपों को स्वीकार किया जाता है। बम्बई की सूती कपड़े की मिलों में इसका रिवाज बहुत है, परन्तु यह व्यवस्था बहुधा उद्योग के लिए धातक होती है। संकः अथवा मन्दी के काल में निक्षेप-

दाता अपने घन को निकालने लगते हैं और इस प्रकार कम्पनी की बिगड़ती हुई स्थित को और भी खराब कर देते हैं।

(२) स्थिर पूँ जी (Fixed Capital)—काफी समय से चालू उद्योग मशीनों, स्थिर यन्त्रों तथा अन्य प्रकार के स्थिर पूँ जीगत माल के खरीदने के लिए ऋगों को प्राप्त करते रहे हैं। बहुत बार पुरानी मशीनों को बदलने अथवा उद्योग विस्तार हेतु नये यन्त्र खरीदने के लिए भी दीर्घकालीन ऋगों की आवश्यकता पड़ी है। सम्पन्न उद्योग दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति या तो अपने जमा किये हुए सुरक्षित कोषों में से करते हैं या ऋगु-पत्रों की निकासी द्वारा धन प्राप्त करते हैं। नये उद्योगों तथा ऐसे उद्योगों को जिनकी साख नहीं बन पाई है, यह सुविधा प्राप्त नहीं होती है। देश में औद्योगों को जिनकी साख नहीं बन पाई है, यह सुविधा प्राप्त नहीं होती है। देश में औद्योगों के जिनकी साख नहीं बन पाई होती है। व्यापारिक बैंक दीर्घकालीन ऋगु नहीं देती हैं, वे अचल सम्पत्ति अथवा प्राधियों की प्रतिभूति पर ऋगु नहीं देती हैं। स्टेट बैंक तथा विनिमय बैंक भी साधारगात्या ऐसे ऋगों में व्यवसाय नहीं करती हैं। विदेशों में बीमा कम्पनियाँ अपने आदेथों का एक काफी बड़ा भाग उद्योगों में लगाती हैं, परन्तु भारत में इसका चलन भी नहीं है।

### दीर्घकालीन वित्त के साधन-

भारतीय उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त के सम्बन्ध में भारी कठिनाई होती है। ऐसे वित्त के प्रमुख साधन निम्न प्रकार हैं:—

- ( ग्र ) देशी बैंकर, साहूकार तथा व्यक्तिगत ऋग्गदाता फर्में—ये दीर्घंकालीन विक्त का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं, परन्तु ये बहुत सन्तोषजनक नहीं हैं, क्योंकि इनके ऋगों पर ब्याज की दर काफी ऊँची होती है।
- (ब) राजकीय ऋगा—यह दीर्घकालीन वित्त का दूसरा साधन है। बहुत सी राज्य सरकारें नियमानुसार छोटे-छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। श्रौद्योगिक कम्पनियों के दिष्टिकोगा से सरकारी ऋगा बहुत सुविधाजनक नहीं होते हैं, क्योंकि इनके मिलने में बहुधा विलम्ब होता है और ऋगा लेने वाली कम्पनियों को कई दफ्तरों श्रौर सूत्रों में से प्रार्थना-पत्र भेजने पड़ते हैं। वैसे भी ऐसे ऋगा एक निश्चित अंश तक ही प्राप्त होते हैं। इस कारणा ऋगों का यह साधन बहुत लोकप्रिय नहीं है। साथ ही साथ, सरकारी ऋगा साधारणतया छोटे अथवा मध्यम श्रेगी के उद्योगों को ही दिये जाते हैं।
- (स) श्रौद्योगिक बैंक से ऋग्।—भारत में ऐसी बैंकों को बहुत ही कम सफलता मिली है। समय-समय पर श्रौद्योगिक वित्त व्ययस्था करने के लिए बहुत सी श्रौद्योगिक बैंक खोली गई थों, परन्तु वे कुछ ही समय पश्चात या तो व्यापार बैंकों में विलय करने पर पर बाध्य हुई श्रथवा ठप्प हो गई। ऐसी बैंकों की श्रसफलता के प्रमुख

कारए। ग्रीद्योगिक बेंकिंग सम्बन्धी ज्ञान ग्रीर ग्रनुभव का ग्रभाव तथा प्रबन्ध की ग्रमुशलता ग्रीर बेईमानी थे।

(द) श्रौद्योगिक वित्त प्रमन्डल से प्राप्त ऋग् इस प्रमण्डल की सेवाए सन् १६४० से प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकारों ने भी राज्य श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल स्रोले हैं। ऐसी श्राशा की जाती है कि भविष्य में इस सूत्र से काफी सहायता मिल सकेगी, परन्तु इन प्रमन्डलों का कार्य इस समय तक बहुत सन्तोषजनक नहीं रहा है। श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल (Industrial Finance Corporation)—

भारत में श्रौद्योगिक वित्त की कमी को तो सभी स्वीकार करते हैं, परन्तु युद्धोत्तर काल में सरकार तथा रिजर्व बैंक ने ऐसा अनुभव किया है कि श्रौद्योगिक विकास तथा पुनर्वास की प्रगति के लिए विशेष व्यवस्था की श्रावश्यकता थी। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने समस्या को सुलभाने के लिए एक श्रिखल भारतीय श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल तथा राज्य वित्त प्रमन्डलों की स्थापना का सुभाव दिया था। एक विशेष नियम पास करके भारतीय लोक सभा ने १ जुलाई सन् १९४५ से श्रौद्योगिक वित्त प्रमन्डल की स्थापना की है। इस प्रमन्डल की प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं:—

(१) पूँजी—इस प्रमन्डल को १० करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी की म्राज्ञा दी गई है और इसकी मंत्र पूँजी ४ करोड़ रुपया रखी गई है, जिसे ४-४ हजार रूपये के पूर्णतया परिदत्त अंशों में बाँटा गया है। प्रमंडल के अंश केन्द्रीय सरकार तथा अन्य उल्लेखित संस्थाओं द्वारा निम्न अनुपात में खरीदे जा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार २०%, रिजर्व बैंक २०%, परिगिएत बैंक २५%, बीमा कम्पनियाँ, विनियोग ट्स्ट तथा इस प्रकार की अन्य संस्थाएँ २५% और सहकारी वैक १०% । प्रमन्डल के ग्रंशों का हस्तान्तरए। नहीं किया जा सकता है, परन्तु ऊपर के विभिन्न वर्गों के बीच एक म्रश तक हस्तान्तररा की म्राज्ञा दी गई है, किन्तु यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी वर्ग के पास उसके निश्चित हिस्से के १०% से ग्रंघिक ग्रंश एकत्रित न होने पार्ये। इन ग्रंशों पर सरकार की गारन्टी है। यदि प्रमन्डल फेल होता है तो ग्रंशघारी को उसके ग्रंश की कीमत सरकार द्वारा चुकाई जायगी। सरकार ने यह भी विश्वास दिलाया है कि न्यूनतम लाभांश २ $rac{1}{2}\%$  की दर पर ग्रवश्य दिया जायगा । यदि कोई वर्ग अपने हिस्से के अंश को नहीं खरीदता है तो ऐसे अंशों को सरकार अथवा रिजर्व वैंक प्राप्त कर सकते हैं ग्रीर बाद को उपयुक्त संस्थाओं के हाथ वेच सकते हैं। ग्रन्थ सभी संस्थाओं ने तो अपने हिस्से से अधिक के अंश खरीदे हैं, परन्तु सहकारी बैंक अपने कुल अभ्यंश को नहीं खरीद पाई हैं। उनके हिस्से के ३ ६५ लाख रुपये के अंश रिजर्व बेंक ने प्राप्त किये हैं।

(२) प्रबन्ध—प्रमन्डल का प्रबन्ध १२ सदस्यों के संचालक मन्डल द्वारा किया जाता है। ३ संचालक भारत सरकार द्वारा नामजद किए जाते हैं, २ संचालक

रिजर्व बैंक द्वारा नामजद किये जाते हैं, २ ग्रंशधारी बैंकों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं, २ का निर्वाचन सहकारी बैंक करती हैं, २ ग्रंग्य ग्रंशधारियों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं श्रौर १ प्रबन्ध संचालक (Managing Director) सरकार नियुक्त करती हैं। निर्वाचित संचालकों का कार्य-काल ४ वर्ष होता है ग्रौर नामजद सदस्य नामजद करने वाली संस्था की इच्छा के ग्रनुसार बदले जा सकते हैं। प्रबन्ध संचालक एक वेतनभोगी सदस्य होता है ग्रौर साधारणतया ४ वर्ष तक कार्य करता है, यद्यपि उसकी फिर से नियुक्त किया जा सकता है। इस मण्डल की सहायता के लिए ५ सदस्यों की एक कार्यकारिगी समिति होती है, जिसके दो सदस्य निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं ग्रौर १ सरकार नामजद करती है, प्रबन्ध संचालक इस समिति का ग्रध्यक्ष होता है। इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि ग्रावश्यकता पड़ने पर कुछ सलाहकार समितियों को भी नियुक्त किया जा सके। प्रमण्डल का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है।

(३) कार्य-प्रमण्डल के लिये सरकारी ग्रादेशों का पालन करना ग्रनिवार है। यदि संचालक समिति ऐसा नहीं करती है तो उसका कार्यवाहन स्थगित किया जा सकता है। प्रमण्डल का उद्देश्य श्रौद्योगिक कम्पनियों के लिये दीर्घकालीन तथा मध्य-कालीन ऋ गों की व्यवस्था करना है। प्रमन्डल व्यक्तियों, साभेदारियों तथा निजी श्रीद्योगिक कम्पनियों को सहायता नहीं दे सकता है। प्रमण्डल को निम्न प्रकार के प्रिधिकार दिये गये हैं—(१) ग्रौद्योगिक कम्पनियों द्वारा लिए जाने वाले ऋगों की गारन्टी देना, यदि ऐसे ऋगा २५ वर्ष के भीतर शोधनीय हैं। (२) स्कन्ध, ग्रंश. बाँध अथवा ऋगा-पत्रों का अभिगोपन करना। (३) ऊपर बताई गई कम्पनियों को ऋग देना। प्रमण्डल केवल समुचित प्रतिभूतियों पर ही ऋगा देता है और ऐसे ऋगों को २५ वर्ष के भीतर चुकाना आवश्यक होता है। ऋगा भारतीय मुद्रा अथवा किसी विदेशी मुद्रा में भी दिये जा सकते हैं। प्रमण्डल को ऋगी के लिए शर्तें निश्चित करने के विस्तृत श्रिधकार दिये गये हैं श्रीर वह ऋरण लेने वाली कम्पनी की संचालक सिमित में एक सदस्य नियुक्त कर सकता है। किसी एक कम्पनी अथवा संस्था के लिए ऋण की ग्रधिकतम् मात्रा ५० लाख स्पया रखी गई है। (४) प्रमण्डल को यह भी ग्रिध-कार है कि वह स्वयं ऋगा-पत्र जारी करे और विश्व बैंक से विदेशी ऋगा प्राप्त कर ले। (५) प्रमण्डल जनता से ५ वर्ष के निश्चित-कालीन निक्षेप भी स्वीकार कर सकता है, परन्तु ऐसे निक्षेपों की कुल राशि १० करोड़ रुपये से ग्रिषक नहीं होनी चाहिये। (६) प्रमण्डल को भारतीय स्राय-कर विधान के अनुसार एक कम्पनी घोषित किया गया है और इसलिए इस पर आय-कर तथा अति-कर लगाया जा सकता है।

फरवरी सन् १६५२ तक प्रमण्डल के ब्याज की दर ५३% थी, जिसमें ब्याज और ऋगा की किश्त को समय पर चुकाने की दशा में ५% की छूट दी जाती थी, परन्तु उपरोक्त मास से ब्याज की दर बढ़ा कर ६३% कर दी गई है और छूट की दर यथास्थिर रखी गई है।

प्रमण्डल का कार्यवाहन एवं उसकी ग्रालोचनाएं-

सन् १९५२ तक का प्रमण्डल के सम्बन्ध में जो अनुमान लगाया गया था उसके अनुसार अपने ४ वर्ष के जीवन-काल में इसने ऋगा की ६४ प्रार्थनाएँ स्वीकार करके १४ ०३ करोड़ रुपयों के ऋगा दिये थे। प्रमण्डल ने काफी मात्रा में प्रार्थना न्यों के अस्वीकार किया है। प्रमण्डल के कार्य का घीरे-घीरे बरावर विस्तार होता गया है, परन्तु पहले ४ वर्षों में उसके लाभ इतने कम रहे थे कि निश्चित लाभांश बाँटना भी सम्भव न हो सका और इस काल में इसके लिए सरकार को २६ ६ लाख हाये की सहायता देनी पड़ी। प्रमने कोषों को बढ़ाने के लिये प्रमण्डन ने बाँड की निकासी द्वारा धन प्राप्त किया है। जून सन् १६५२ के अन्त तक ऐसी निकासी की मात्रा ५ ६ करोड़ रुपया थी।

३० जून सन् १६५५ तक श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल ने १२५ उद्योगों को कुल मिलाकर २८ करोड़ रुपये के ऋएा दिये थे, जिसमें से १५,२२,५०,००० रुपये नये उद्योगों को दिये गए थे और १२,५५,२५,००० रुपए पुराने उद्योगों के नकीनीकरस्प, श्राद्युनिकरस्प तथा विस्तार के लिए दिए गये थे। ३० जून सन् १६५५ तक प्रमण्डल ने.६.६ लाख रुपए का लाभ कमाया था, जो सब प्रकार के खर्चे चुकाने ग्रौर १५ लाख रुपए का सुरक्षित कोष रखने के बाद बचा था। ३० जून सन् १६५४ तक प्रमण्डल ने वाटे को पूरा करने और ५ करोड़ रुपए की परिदत्त पूँजी पर २३% बयाज चुकाने के लिए सरकार से ३०.६५ लाख रुपए की सहायता प्राप्त की थी। पहले ७ वर्ष के काल में प्रमण्डल से सबसे बड़ा ऋस्ए (४.४३ करोड़ रुपया) चीनी उद्योग को मिला था, दूसरा नम्बर सूती कपड़ा उद्योग (४.११ करोड़ रुपया), तीसरा सीमेंट (३.१५ करोड़ रुपया), चौथा कागज (३.११ करोड़ रुपया) ग्रौर पाँचवां रसायन (२.५१ करोड़ रुपया) का रहा था।

३० जून सन् १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रमण्डल ने कुल १५.१३ करोड़ रुपये के ऋगा दिए थे, जो गत वर्ष में दिए हुए ऋगों की मात्रा के दो गुने से भी ग्रधिक थे। इस वर्ष में २७.७० करोड़ रुपए के ऋगों के दूर प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे, जबिक गत वर्ष में ११.२७ करोड़ रुपए के ऋगों के केवल ४६ प्रार्थना-पत्र प्राये थे। ग्रपने जीवन-काल के द्रवर्षों में प्रमण्डल ने कुल ४३.२१ करोड़ रुपए के ऋगों की स्वीकृति दी थी, जिसमें १६.७३ करोड़ रुपयों के ऋगा दिये जा चुके थे। भुगतान में से लगभग २१.६% बकाया था। द्रवर्ष के काल में प्रमण्डल की ब्याज की श्राय २,८०,८८,६२२ रुपया रही है, जिसमें से २,६२,६१,२५७ रुपया वसूल हो चुका था।

सितम्बर सन् १९५५ में श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल के नियमों में कई संशोधन किए गए थे। एक संशोधन द्वारा प्रमण्डल को गिरवी रखी हुई सम्पत्ति को बेचने के श्रितिरक्त पट्टे पर उठाने का भी अधिकार दिया गया था, ताकि अपना मुगतान पा नेने के पश्चात् प्रमण्डल ऋगी को उसकी सम्पत्ति लौटा सके। दूसरे संशोधन द्वारा

भ्रौशिक-समय वेतन-रहित भ्रध्यक्ष के स्थान पर पूर्ण-समय वेतन-भोगी भ्रध्यक्ष रखने की व्यवस्था की गई है। तीसरे संशोधन द्वारा प्रमण्डल को केन्द्रीय सरकार से ऋणु लेकर भ्रपने कोषों का निर्माण करने का श्रिधकार दिया गया है।

३० सन् जून १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में झौद्योगिक वित्त प्रमण्डल को ४३'०६ लाख का सकल लाभ और ११'२५ लाख रुपए का शुद्ध लाभ रहा है। वर्ष विशेष के अन्त में कुल ऋगा २१'६० करोड़ रुपये के रहे हैं। वर्ष विशेष में १'७१ करोड़ रुपए के ऋगों का वितरण हुआ है, जबिक सन् १६५५-५६ में ऐसी राम्न केवल २'२० करोड़ रुपया थी। इस वर्ष में कुल ११'६१ करोड़ रुपये के ऋगों की स्वीकृति दी गई थी। सहकारी समितियों के लिए १०'७३ करोड़ रुपए के ऋगा स्वीकार किए गए हैं। वर्ष विशेष की महत्त्वपूर्ण घटना यह रही है कि प्रमण्डल को १५ करोड़ रुपए की पूँजी और प्राप्त हो गई है, जिसके फलस्वरूप यह सन् १६५७-५६ रे २० करोड़ रुपए तक के ऋगा दे सकेगा। सन् १६५७ में एक नये संशोधक नियम द्वारा प्रमण्डल को अपनी परिदत्त पूँजी और सुरक्षित कोष के १० गुने तक ऋगा लें का अधिकार दिया गया है।

निम्न तालिका में श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल द्वारा दिए हुए ऋगों के सम्बन्ध । सम्पूर्ण स्थिति दिखाई गई है:—

	,			स्वीकृत ऋगों की कुल राशि (रुपयों में)	दिये हुए ऋगों की कुल राशि (रुपयों रे
-ইত	जून	सन् १६४६	के ग्रन्त में	४,४२,२४,०००	१,३२, <i>५</i> ६,५ <b>१</b>
	,,	,, १९५०	;; ;; ;;	७,१६,२५,०००	३,४०,७४,३१
	,,	,, १६५१	11 11 11	६,५८,२०,०००	४,७८,६४,००
	7 <b>2</b>	,, १६५२	(1 1) 11	१४,०३,४४,०००	७,५७,०३,८०
	,,	,, १९५३	11 11 11	१४,४६,७०,०००	१०,०६,७६,५४
, ,	11	,, १६५४	11 11 11	२०,७३,७४,०००	१२,८८,६४,७३
	"	्र,, १९५५	11 11 11	२८,०७,७४,०००	१४,५२,६६,३०
í	,	,, १६५६	11 11 1>	४३,२०,७४,०००	१६,७३,१६,६१
•	,,	,, १६५७	11 11 11	४८,३६,००,०००	२६,४४,१६,६१
,	,,	,, १६५८	11 11 11	५७,४२,००,०००	३२,०३,००,००

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि जून सन् १९४७ और जून सन् १९ के बीच प्रमण्डल ने ६ ०६ करोड़ रुपये के नये ऋगों की स्वीकृति दी है, जबकि काल में उद्योगों ने ५ ५६ करोड़ रुपये के ऋगा वास्तव में लिए हैं। दूसरी पंच-वर योजना के काल में केन्द्रीय सरकार की श्रोर से प्रमण्डल को १३ ५० करोड़ रुपये ऋण देने का निश्चय किया गया था। अब यह राशि बढ़ाकर २२.२५ करोड़ हागा कर दी गई है। श्रीद्योगिक वित्त प्रमण्डल (संशोधन) श्रिधिनियम, सन् १६५७ (The Industrial Finance Corporation 'Amendment' Act, 1957) ने प्रमण्डल के साधनों श्रीर उनकी कार्यवाहियों दोनों का विस्तार किया है। इस संशोधन के फलस्वरूप नये उद्योग तथा बहुत से ऐसे उद्योग भी जो समुचित प्रतिभृति देने में श्रसमर्थ हैं, परन्तु जिनके विकास का राष्ट्रीय महत्त्व है, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, परिगणित बैंक श्रयवा राज्य सहकारी बैंक की गारन्टी पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

### म्रालोचनाएँ —

प्रमण्डल के विधान तथा कार्यवाहन के विरुद्ध दो आलोचनाएँ की गई हैं:--

- (१) प्रमण्डल केवल बड़े-बड़े उद्योगों को सहायता देता है। यह छोटे उद्योगों के लिए हानिकारक है श्रौर पूँजी का केन्द्रीयकरण करने की प्रवृत्ति रखता है।
- (२) प्रमण्डत वो निजी अंशधारियों की संस्था बनाया गया है । इससे यह भय उत्पन्न होता है कि इसकी सुविधाओं का व्यक्तिगत, क्षेत्रीय अथवा वर्गीय हितों को उन्नत करने के लिए उपयोग हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रमण्डल पिछड़े हुए उद्योगों को सहायता दे और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखे। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात प्रमण्डल के ४०% अश्व सरकार के हाथ में आ गये हैं और इस कारण अब राष्ट्रीय हितों की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आशा है। बीमा व्वयसाय के राष्ट्रीयकरण ने सरकार के हाथ और भी मजबूत कर दिए हैं।

कार्यवाहन के सम्बन्ध में चार और भी ग्रालोचनाएँ की जा सकती हैं:-

- (३) प्रमण्डल ने अपना कार्य रूढ़िवादी रीति से चलाया है, जिससे यह पर्याप्त सहायता नहीं दे सका है। आपवेदन-पत्रों को छोटे-छोटे टैक्नीकल कारणों पर रह कर देना उचित न था।
- (४) प्रमण्डल ने सहायता बहुत ही कम दी है। ६ वर्षों में केवल २६ करोड़ रुपए के ऋगा दिये गए हैं। इन ऋगों के देने में काफी विलम्ब किया है। ऋगा देने के अतिरिक्त अंशों की गारन्टी, ऋगा-पत्रों के खरोदने तथा अभिगोपन का कार्य इसने अभी नहीं किया है।
- (५) प्रमण्डल के ब्याज की दर बहुत ऊँची है, जिसके कारण बहुत ही कम कम्पनियाँ इससे ऋगा लेने को इच्छुक रहती हैं।
- (६) यह कहा जाता है कि प्रमण्डल ने ग्रमी तक केवल ऐसे राज्यों तथा उद्योगों को सहायता दी है जो पहले से ही विकसित तथा मजबूत हैं।

गत वर्ष में प्रमण्डल का कार्यवाहन ग्रिष्ठिक सन्तोष जनक रहा है श्रीर प्रदान किए हुए ऋगों की मात्रा में भी काफी वृद्धि हुई है। सितम्बर सन् १६५६ में प्रमण्डल की वार्षिक बैठक में प्रमण्डल के श्रद्धक्ष श्री मैनन ने बताया था कि गत वर्ष में प्राण्डित

तथा स्वीकृत दोनों ही प्रकार के ऋगों की मात्रा सब वर्षों से अधिक रही है। अध्यक्ष का विचार था कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना में प्रमण्डल द्वारा १५ करोड़ रुपये की राशि के ऋगा देने की जो व्यवस्था की गई है वह आवश्यकता से कम है। श्री मैनन का विचार था कि दो बातों का प्रमण्डल के कार्यवाहन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। एक ओर तो राज्य सरकारें औद्योगिक इकाइयों को सीधा ऋगा दे रही हैं, इसके स्थान पर ऋगा प्रमण्डल द्वारा दिये जाने चाहिए। दूसरी ओर प्रमण्डल के खातों का अंकेक्षण अनेक एजेन्सियों द्वारा हो रहा है, जिसमें किसी अधिक विचार-युक्त नीति अपनाने की आवश्यकता है। उनका विचार था कि अभी ब्याज की दर को ६ ५५% से नीचे घटाने की सम्भावना नहीं है, बिल्क हो सकता है कि प्रमण्डल को न्यूनतम् निर्धारित लाभांश बाँटने के लिए सरकार से सहायता लेनी पड़े। श्री मैनन ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को ऐसा नियम बना देना चाहिए कि औद्योगिक विकास सम्बन्धी सभी ऋगा प्रमण्डल द्वारा ही दिए जायें। उनका यह भी विचार था कि कोशों को बढ़ाने के लिए प्रमण्डल को बाजार से ऋगा प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ सकती है। सन् १६५७ में प्रमण्डल का कार्यवाहन बहुत सन्तोषजनक रहा है और सन् १६५६ में इसके कार्य का काफी विस्तार भी हुआ है।

राज्य वित्त प्रमन्डल-

श्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल का कार्य-क्षेत्र काफी सीमित है, इस कारए उसके कार्यों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने राज्य वित्त प्रमण्डलों की स्थापना की माँग रखी। सितम्बर सन् १६५१ में लोकसभा ने राज्यों को ऐसे प्रमण्डल खोलने का म्रधिकार दिया । इन प्रमण्डलों में यह व्यवस्था की गई है कि उन उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता दी जा सके जो केन्द्रीय प्रमण्डल से सहायता पाने के प्रघिकारी नहीं हैं। विघान तथा कार्यों में ये संस्थायें केन्द्रीय प्रमण्डल से बहुत भिन्न नहीं हैं। ये प्रमण्डल केवल २० वर्ष तक के लिए ऋ ए। दे संकते हैं और इनकी ग्रंग पूँजी ५० लाख तथा ५ करोड़ रुपयों के बीच होगी । कुल ग्रंश पूँजी का ७५% सरकार, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों, बीमा कम्पनियों, विनियोग ट्रस्ट तथा अन्य वित्तीय संस्थाम्रों द्वारा देने की व्यवस्था की गई है म्रौर शेष २५% व्यक्तियों द्वारा। ऐसे प्रमण्डल एक उद्योग को ग्रिधिक से ग्रिधिक १० लाख रुपये का ऋगा दे सकते हैं। कुछ राज्यों ने ऐसे प्रमण्डल स्थापित कर लिए हैं स्रौर शेष केन्द्रीय सरकार के स्रादेश की प्रतीक्षा में हैं। पंजाब, मध्य-प्रदेश तथा उत्तर-प्रदेश राज्यों के वित्तीय प्रमण्डल की प्रगति के ग्राँकड़े प्राप्त हुए हैं। शेष की स्थिति का ग्रभी पता नहीं है। इनसे छोटे तथा मध्यम-श्रेणी के कारखानों को सहायता मिलेगी । ३० जून सन् १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष के म्रन्त में देश में कुल राज्य वित्त प्रमण्डलों की संख्या १३ हो गई थी ्रग्रीर ग्रगले दो वर्षों में भी उनकी संख्या १३ ही रही है। जून सन् १६५८ के ग्रन्त में . इन प्रमण्डलों के कुल बकाया ऋगा और अग्रिम ६ ५१ करोड़ रुपया थे।

केन्द्रीय स्रीर राज्य वित्त प्रमण्डलों के कार्य-क्षेत्रों को एक-दूसरे से बिल्कुल स्नलग कर दिया गया है। यह तय किया गया है कि १० लाख रुपये तक के ऋगों के प्रार्थना पत्र स्रथवा राज्य प्रमण्डल की पिरदत्त पूँजी के १०% तक के ऋगों के प्रार्थना-पत्र राज्य वित्त प्रमण्डल के पास जाने चाहिए। ये प्रमण्डल मध्यम तथा छोटे रखोगों को ऋगा देते हैं।

राज्य वित्त प्रमण्डल (संशोधन) ग्रिधिनियम, सन् १६५६ द्वारा, जो १ अक्टूबर सन् १६५६ से लागू कर दिया गया है, ऐसे प्रमण्डलों के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्थाएँ की गई हैं:—(१) दो या ग्रिधिक राज्य मिल कर सम्मिलित वित्त प्रमण्डल बना सकते हैं। (२) ये प्रमण्डल केन्द्रीय ग्रीर राज्य सरकारों तथा ग्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डल के ग्रिभिक्त का कार्य कर सकते हैं। (३) प्रमण्डल ग्रब किसी उद्योग को राज्य सरकार, ग्रमुसूचित वैंक ग्रथवा राज्य सहकारी बैंक की जमानत पर ऋगा दे सकते हैं (४) प्रमण्डल सरकारी हुन्डियों की ग्राड़ पर रिजर्व वैंक में ग्रह्मकालीन ऋगा ले सकते हैं ग्रौर (५) रिजर्व वैंक को प्रमण्डलों के निरीक्षण का अधिकार दे दिया गया है।

राष्ट्रीय श्रीद्योगिक विकास निगम लि॰ (The National Industrial Development Corporation Ltd.)—

श्रौद्योगिक विक्त निगम के श्रीतिरिक्त दो श्रौर निगम देश के श्रौद्योगिक विकास के लिए स्थापित किये गये हैं। इनमें से राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम की स्थापना अक्टूबर सन् १६५४ में १ करोड़ रुपए की पूँजी से की गई है। कमानी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी बनाया गया है, यद्यपि सारी श्रंश पूँजी सरकार द्वारा दी गई है। निगम को पूँजी बढ़ाने के लिये श्रंशों श्रौर ऋएग-पत्रों की निकासी का श्रीयकार दिया गया है। निगम को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, बैंकिंग कम्पनियों तथा व्यक्तियों से ऋएग श्रौर जमा प्राप्त करने का भी श्रीयकार दिया गया है। निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य लोक श्रौर निजी क्षेत्रों में संतुलित श्रौद्योगिक विकास को श्रीत्साहन देना, नई श्रौद्योगिक योजनाश्रों की जाँच करना तथा उनका संवालन करना श्रीर श्रौद्योगिक विकास की किमयों को दूर करना है। निगम के कार्यों का उल्लेख निम्न प्रकार है:—

- (१) सरकारी उद्योगों, कम्पनियों, फर्मों ग्रौर व्यक्तियों को पूँजी साख ग्रौर यन्त्रों सम्बन्धी सहायता देना।
- (२) उद्योगों को ऋ ए। देना।
- (३) उद्योगों के भ्रंशों भ्रौर ऋग्-पत्रों का म्रभिगोपन करना भौर उनकी गारन्टी लेना तथा उन्हें दक्ष भ्रौर विशेषज्ञीय सेवाएँ प्रदान करना।
- (४) भौद्योगिक विकास हेतु नये उद्योगों को सहायता देना।
- (५) व्यापारिक संस्थाओं में सामेदारी के रूप में शामिल होना।

- (६) सम्बन्धित उद्योगों के लिए संचालकों स्रोर सलाहकारों को नियुक्त करना।
- (७) ग्रौद्योगिक विकास के लिए ग्रपनी ग्रोर से नई योजना चालू करना।

निगम के लिए वित्तीय प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ऋगों और अनुदानों द्वारा करती है। सन् १६५६-५७ के बजट में इसके लिए १ ४६ करोड़ रुपये और सन् १६५७-५८ के बजट में ४ ५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। मार्च सन् १६५७ तक निगम ने ६ सूती कपड़ा मिलों को लगभग १ ६५ करोड़ रुपये के ऋग दिये थे। इसके अतिरिक्त २ जूट की मिलों को ५५ लाख रुपये के ऋग दिये थे। निगम के ऋगों पर ब्याज की दर ४ ५% रखी गई है और वे १२ किरतों में शोधनीय हैं। निगम के द्वारा सरकार सूती कपड़ा और जूट उद्योगों को उद्योगों के पुनर्वासन तथा आधुनिकरण के लिए ऋगा देती है। जून सन् १६५८ तक निगम को इस कार्य के लिए २ २६ करोड़ रुपये के ऋगा दिये जा चुके थे।

भारतीय श्रौद्योगिक साख श्रौर विनियोग निगम लि॰ (Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.)—

इस निगम ने मार्च सन् १९५५ में अपना कार्य आरम्भ किया है। निगम की स्थापना भारतीय कम्पनी विधान के अन्तर्गत की गई है और उद्देश्य निजी क्षेत्र के उद्योगों को सहायता देना है। निगम के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:—

- (१) भ्रौद्योगिक इकाइयों को मध्यकालीन भ्रौर दीर्घकालीन ऋए। देना।
- (२) नई कम्पनियों के ग्रंशों ग्रौर ऋग्ग-पत्रों का ग्रिभिगोपन।
- (३) ऋगों को भ्राकर्षित करने के लिए निजी क्षेत्रों से भ्राये हुए ऋगों की फिर से गारन्टी लेना।
  - (४) भारतीय कम्पनियों को प्रबन्ध के बारे में तान्त्रिक सलाह देना।
  - ( ५ ) उद्योगों के विकास भीर नये स्राविष्कारों की व्यवस्था करना।
  - ः (६) नये व्यवसायों तथा विनियोगों को प्रोत्साहन देना।

निगम की कुल पूँजी २५ करोड़ रुपया रखी गई है, जिसे १००-१०० रुपये के ग्रंशों में बाँटा गया है। ग्रंभी तक केवल ५ करोड़ रुपये की पूँजी की निकासी की गई है, जिसमें से २ करोड़ रुपया भारतीय बीमा कम्पनियों, ५० लाख रुपया ग्रंमरीका की वित्त निगम, १ करोड़ रुपया इंगलैंड की बीमा कम्पनियों ग्रीर १-३ करोड़ रुपया जनता द्वारा दिया गया है। कम्पनी के ग्रंशों के हस्तान्तरण पर सरकारी नियंत्रण है। सरकार निगम को ७.५ करोड़ रुपये का ब्याज रहित ग्रंग्रिम देगी, जिसका भुगतान स्थापना के १५ वर्ष पीछे १५ किस्तों में किया जायगा। विस्व बैंक ने निगम को लगभग १ करोड़ रुपये की कीमत का डालर में विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान किया है। निगम ने ५ करोड़ रुपया ग्रंशों की बिक्री द्वारा ग्रीर ७.५ करोड़ रुपया सरकार से प्राप्त कर लिया है।

सन् १६५६ के अन्त तक निगम ने १५ प्रार्थियों के ६ ०१ करोड़ रुपये के ऋगों की स्वीकृति दी थी। इसमें से २ ६५ करोड़ रुपए ऋगा के रूप में थे, २ ३ ६ करोड़ रुपये अभिगोपन (Underwriting) के रूप में और ६ ६ लात रुपया अंगों के चन्दों के रूप में। २ ६५ करोड़ रुपये के स्वीकृत ऋगा में से वास्तव में सन् १६५६ के अन्त तक केवल ५४ लाख रुपये लिए गए थे। सन् १६५७ के अन्त तक निगम ने कागज, रसायन और औषि, विद्युत सामान, वस्त्र, चीनी, घानु, चूना, सीमेंट, कांच आदि उद्योगों के लिए ११ ६५ करोड़ रुपये के ऋगों की स्वीकृति दी थी। किन्तु वास्तव में उद्योग इस काल तक केवल १ ६५ करोड़ रुपये की राशि ही निकाल पाये हैं।

निगम का प्रारम्भिक उद्देश्य भारत में निजी क्षेत्र के उद्योगों की सहायता करना है। उद्देश्य यह है कि ऐसे उद्योगों के निर्माण, विस्तार और आधुनिकरण का वित्त प्रवन्ध किया जाय और देशी तथा विदेशी पूँजी को औद्योगिक विनियोगों की ओर प्रेरित करके निजी क्षेत्र के औद्योगिक विकास की उन्नति की जाय । निगम द्वारा दीर्घकालीन और मध्य-कालीन ऋणा दिये जाते हैं और यह औद्योगिक कम्पनियों को दिये जाने वाले ऋणों की गारन्टी भी लेता है।

राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम लि॰ (National Small Industries Cor-

poration Ltd.)—

इस निगम की स्थापना भारत सरकार ने फरवरी सन् १६५५ में की है। उद्देश्य यह है कि छोटे उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन, संरक्षरण और सहायता प्रदान की जा सके। निगम केवल ऐसे उद्योगों को सहायता दे सकता है जिनमें यदि विद्युत शक्ति का उपयोग नहीं होता है तो श्रमिकों की संख्या १०० से कम हो, यदि विद्युत शक्ति का उपयोग होता है तो श्रमिकों की संख्या ५० से कम हो और जिनकी पूँजी ५ लाख रुपये से अधिक न हो। कम्पनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप से १० लाख रुपये की पूँजी से आरम्भ किया गया है। पूँजी को १००-१०० रुपयों के अंशों में बाँटा गया है।

इस निगम द्वारा छोटे उद्योगों के विकास में सहायता मिलेगी, जिससे कि उपभोगीय वस्तुश्रों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:—

(१) छोटे उद्योगों के लिए माल सप्लाई के सरकारी ग्रादेश प्रप्त करना।

(२) जिन उद्योगों को सरकारी ग्रादेश मिलते हैं उनके लिए ग्रायिक ग्रोर शैल्पिक सहायता प्रदान करना, ताकि वे इन ग्रादेशों को पूरा करने के निए -प्रावब्धक माल तैयार कर सर्वे।

(३) छोटे ग्रीर बड़े उद्योगों के बीच समचय ग्रीर सम्बन्ध स्थापित करना,

ताकि दोनों एक दूसरे के विकास में सहायक हो सर्के ।

मशीनों के खरीदने और श्रौद्योगिक इकाइयों के माल की बिक्री के विकेन्द्रीय-करणा के हेतु निगम के श्रन्तगैत ४ उप-निगम दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई श्रौर मद्रास में सन् १९५७ से स्थापित किए गये हैं, म्रर्थात् राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम, दिल्ली; राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, बम्बई; राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, कलकत्ता; तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, मद्रास ।

उद्योगों का पुनर्वित्त निगम प्राइवेट लि॰ (Refinance Corporation for Industry Private Ltd.)—

इस निगम की स्थापना जून सन् १६५ में की गई है, ताकि निजी क्षेत्र में मध्यम श्रेणी के उद्योगों के वित्तीय साधनों को बढ़ाया जाय । निगम का प्रमुख उद्देश उद्योगों को ऋगा देने में बैंकों की सहायता करना है। निगम निजी क्षेत्र के उन उद्योगों को जिन्हें पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है, बैंकों द्वारा दिए हुए ऋगों को पुनः उधार (Relending) की सुविधाएँ देता है। निगम की ग्रिधकृत पूँजी २५ करोड़ रुपया है और निर्गमित पूँजी (Issued Capital) १२ ५ करोड़ रुपया। पूँजी रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम तथा १५ बड़ी-बड़ी परिगणित बैंकों द्वारा उपलब्ध की गई है।

निगम केवल ऐसे ही ऋगों का पुनर्ग्रपहरण (Rediscount) कर सकता है जो ३ ग्रौर ७ वर्ष के बीच के काल के लिए दिए गए हों ग्रौर जिनकी राशि ५० लाख रुपयों से ग्रधिक न हो । निगम केवल उन्हीं उद्योगों को सहायता देता है जिनकी गरिदत्त पूँजी ग्रौर सुरक्षित कोष मिल कर २.५ करोड़ रुपये से ग्रधिक न हों। पौद्योगिक वित्त में सुधार के सुभाव—

भारत में ऐसी उपयुक्त संस्थाश्रों की भारी कमी है जो श्रौद्योगिक वित्त की स्ववस्था करती हों। देश में व्यापार बैंकों की ही प्रधानता है, जो उद्योगों की श्रथेक्षा यापार को श्रल्पकालीन ऋग्। देना श्रधिक उपयुक्त समभती हैं। श्रौद्योगिक वित्त की स्नित के लिए निम्न प्रकार के सुभाव दिये जा सकते हैं:—

- (१) भारत में ग्रभिगोपन-गृहों तथा निर्गम गृहों का विकास होना चाहिए। केन्द्रीय तथा राज्य श्रौद्योगिक वित्तीय प्रमन्डलों को यह कार्य शीझता-पूर्वक ग्रपने हाथ में ले लेना चाहिए।
- २) बहुत सी श्रौद्योगिक बेंकों की स्थापना से यह कमी काफी ग्रंश तक पूरी हो सकती है। इस समय वे बहुत से कारण शेष नहीं रहे हैं, जिन्होंने भूतकाल में ऐसी बेंकों को सफलता नहीं मिलने दी थी। इसके श्रति-रिक्त ऐसी संस्थाओं को सरकार श्रारम्भ में सुविधायें तथा उपयुक्त सहा-यता देकर प्रोत्साहित कर सकती है।
- ३) यूरोप के देशों की भाँति भारत में भी श्रौद्योगिक प्राधि बैंक (Industrial Mortgage Banks) खोली जा सकती हैं, जिनका ठीक वही श्राधार होगा जो भू-प्राधि बैंकों का है।

ا للكليانية

- (४) विनियोग ट्रस्टों की स्थापना द्वारा लोगों में विनियोगों के प्रति दिल-चस्पी उत्पन्न करना ग्रावश्यक है, परन्तु साथ ही साथ उत्पुन्त मंन्यप्रघें की सहायता से बचत के एकत्रित करने तथा बढ़ाने का भो कार्य बढ़ाना चाहिए ।
- (५) श्रौद्योगिक कम्पनियों द्वारा माल खरीदने श्रौर बेचने के लिए सरकारी प्रेरणा पर सरकारी बिक्री संगठनों का निर्माण होना चाहिए।
- (६) व्यापारिक बैंकों के व्यवहार में भी परिवर्तन की म्रावश्यकता है। उन्हें उद्योगों की जरूरत की म्रोर म्रधिक व्यान देना चाहिए। यह भी विचारणीय है कि जर्मन प्रणाली के म्राघार पर भारत की व्यापार बैकों को वर्तमान कार्य के म्रतिरिक्त मौद्योगिक बैंकों के कार्य के लिए संग-ठित करना कहाँ तक उपयुक्त होगा।
- (७) भारतीय बैंकों को उपयुक्त दशाओं में व्यक्तिगत प्रतिभूतियों पर विना प्रतिभूति अग्रिम (Clean Advances) देने पर भी तैकार रहना चाहिए । परन्तु इसमें-भारी सावधानी की आवश्यकता है।
- ( द ) ग्रौद्योगिक वित्त प्रमण्डलों के कार्यवाहन का विस्तार होना चाहिए ग्रौर उनकी कार्य-प्रणाली में ऐसे सुधार होने चाहिए कि ग्रौद्योगिक वित्त की ग्रावश्यकता ग्रीधक ग्रंश तक पूरी हो सके।
- ( ६ ) विदेशी पूँजी का समुचित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आयात करना तो आवश्यक है, परन्तु इस सम्बन्ध में भारत को केवल अमरीका पर निर्भर रहना ठीक न होगा। जहाँ कहीं से भी उचित शर्तों पर आवश्यक पूँजी मिलती हो, उसका स्वागत करना चाहिए।

### ग्राथिक नियोजन श्रौर श्रौद्योगिक वित्त-

प्रथम पञ्च-वर्षीय योजना में श्रौद्योगिक विकास पर १७६ करोड़ रुपये के व्यय की योजना सार्वजिनक क्षेत्र के लिए बनाई गई थी। दूसरे ग्रायोजन में ६६१ करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा गया है। श्रौद्योगिक वित्त के क्षेत्र में प्रथम योजना के काल में चार महत्त्वपूर्ण कार्य हुए हैं:—(१) श्रौद्योगिक वित्त प्रमन्डल के संचालन में सुघार, (२) राज्य वित्त प्रमन्डलों की स्थापना, (३) राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास प्रमन्डल (National Industrial Development Corporation) का निर्माण और (४) श्रौद्योगिक साख श्रौर विनियोग प्रमन्डल (Industrial Credit and Investment Corporation) की स्थापना। दूसरे श्रायोजन के काल से इन संस्थाओं से पर्याप्त फल प्राप्त होने की श्राशा है।

प्रथम पंच-वर्षीय योजना में ग्रौद्योगिक विकास के लिए लोक क्षेत्र में १७६ करोड़ रुपए ग्रौर निजी क्षेत्र में ४६३ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था थी। वास्त-विक व्यय ग्रनुमान से कम रहा है ग्रौर निजी क्षेत्र का विनियोग केवल ३४० करोड़ रुपये का रहा है। दूसरी दोजना में श्रौद्योगिक विकास पर लोक क्षेत्र में ८६०, जिसमें से लगभग १०० करोड़ रुपया घातु उद्योग के विकास के लिए रखा गया है, श्रौर निजी क्षेत्र में २,४०० करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था है। इसमें से वित्तीय साधनों से निजी क्षेत्र के लिए ६२० करोड़ रुपया मिलने का श्रनुमान लगाया गया है। वित्तीय साधनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

( करोड़	ह रुपयों में )
(१) श्रौद्योगिक वित्त प्रमन्डल, राज्य वित्त प्रमन्डलों तथा श्रौद्योगिक साख श्रौर विनियोग प्रमन्डल से ऋगा (२) प्रत्यक्ष ऋगा, परोक्ष ऋगा श्रौर साफेदारी के रूप में मिलने वाले ऋगा	80
पाल ऋण (३) विदेशी पूँजी (४) नई निकासी	۶۰ <b>۱۰۰</b>
( ४ ) विनियोग के लिए प्राप्त ग्रान्तरिक साधन	ू ३००
(६) श्रन्य साधन, जैसे—भैनेजिंग एजेन्टों से ऋगा, श्रतिरिक्त लाभ कर की वापिसी, इत्यादि	۲٥

### कुल ६२०

### सर्राफ समिति के सुभाव-

सन् १६५३ में रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्रों के उद्योगों के वित्तीय साधनों में वृद्धि के सुभाव देने के लिए श्री हर्राफ की ग्रध्यक्षता में एक सिमिति नियुक्त की थी, जिसकी रिपोर्ट जून सन् १६५४ में प्रकाशित हुई थी। सिमिति ने पता लगाया है कि श्रौद्योगिक वित्त के साधन श्रभी तो श्रपर्याप्त हैं। बड़े उद्योगों और पुराने उद्योगों को नवीनकरए। के लिए श्रावहयक पूँजी नहीं मिल रही है श्रौर मध्यम श्रेणी तथा छोटे उद्योगों के पास पूँजी की भारी कमी है। सिमिति ने इस सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूण सिफारिशों की हैं। प्रमुख सुभाव निम्न प्रकार हैं:—

- (१) सरकार को समुचित वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को अभी स्थिगित रखा जाय और श्रमिकों का पारितोषण उनकी उत्पादन-शक्ति के अनुसार रखा जाय।
- (२) निजी क्षेत्र के विकास के लिए यह स्रावश्यक है कि राष्ट्रीय बचत का एक भाग मुद्रा स्रौर पूँजी बाजार में जाता रहे। सरकार को नियोजन हेतु सारी बचत संग्रह करने की नीति छोड़ देनी चाहिए।
- (३) अनुसूचित बैंक उद्योगों को जो अल्पकालीन और दीर्घंकालीन सहायता देती हैं उन्ने बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए समिति ने तीन सुफाव दिये हैं— बैंकों को औद्योगिक कम्पनियों के अंशों और ऋग्ग-पत्रों में विनियोग करने के लिए

प्रोत्साहन, ऐसे ग्रंशों श्रौर ऋग्-पत्रों पर ग्रग्रिम प्रदान करने की ग्राज्ञा ग्रौर बैंकों को ग्रीबोगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निगमों के ग्रंशों ग्रौर बांघों को खरीदने के लिए प्रोत्साहन।

- (४) समिति ने सुफाव दिया था कि नये उद्योगों के ग्रंशों का ग्रिमिगोपन करने के लिए स्टेट बैंक ग्रौर बीमा कम्पनियों का एक संघ बनाया जाय।
- (१) रिजर्व बैंक की बिल बाजार योजना के ग्रन्तर्गंत ऐसी सभी सदस्य बैंकों को सहायता मिलनी चाहिए जिनकी जमाएँ १ करोड़ रुपये से ग्रधिक हैं।
- (६) जमाधारियों के हितों की रक्षा के लिए देश में जमा दीमा प्रमन्डल स्रोला जाय।
  - (७) एक अखिल भारतीय बैंकिंग संघ खोला जाय ।
- ( प्र) ग्रौद्योगिक वित्त प्रमन्डल ग्रौर राज्य वित्त प्रमन्डल के कार्यों का विस्तार किया जाय ग्रौर उन्हें ऋगा-पत्रों के ग्राधार पर भी ऋगा देना चाहिए।
- (१) श्रौद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए सरकार श्रौर उद्योगपितियों के सहयोग द्वारा एक श्रौद्योगिक विकास प्रमन्डल खोला जाय।
- ( १० ) बीमा कम्पनी विधान में ऐसा संशोधन किया जाय जिससे वे ५०% के स्थान पर ४५% ही सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करने के लिए बाध्य हों।
- (११) प्रत्येक कस्बे भ्रौर बड़े गाँव में कम से कम बैंकिंग कार्यालय भ्रवश्य रखा जाय, जिसके लिए रिजर्व बैंक ऐसे स्थानों में कार्यालय स्थापित करने वाली बैंकों को सहायता दे।
- ( १२ ) ग्रामीरण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ बढ़ाने के लिए चल-वैंकें (Mobile Banks) स्थापित की जायँ।
- (१३) ऋ गों की निकासी के लिए केन्द्रीय भीर राज्य सरकारों को ऐसा समय चुनना चाहिए कि वैंकों भीर मुद्रा दाजार पर भावश्यकता से भिषक खिचाब न पढ़ने पाये।
- (१४) रिजर्व बैंक को देशी बैंकों के नियमन का फिर से प्रयत्न करना चाहिए और जब तक ऐसा सम्भव न हो तब तक बैंकों को देशी बैंकों द्वारा भुनाये हुए बिलों को फिर से भुनाने का अधिकार दिया जाय।
- (१५) बैंकों की विश्रेष सुविधायें बढ़ाई जायें। इसके लिये समिति ने निम्न सम्मान विए हैं:—
  - (क) रिजर्व बैंक और उसकी एजेन्सियों के कार्यालय में टेलीप्रिन्टर रहने चाहिए।
  - (ख) कार्यालयों के बीच राशि भेजने ग्रीर मेंगाने के तारों को एक्सप्रेस तारों पर भी प्राथमिकता दी जाय।
  - (ग) सप्ताह में कम से कम दो बार निःशुल्क गति विप्रेष की सुविधाएँ रिजर्व बैंक को देनी चाहिए ।

सिमिति के बहुत से सुफाव सरकार ने स्वीकार कर लिये हैं। ग्रौद्योगिक विकास प्रमण्डल ग्रारम्भ कर दिया गया है। इम्पीरियल बैंक ग्रीर जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण ने बहुत सी सिफारिशों के महत्त्व को समाप्त कर दिया है। विप्रेष सुविधाओं में भी काफी वृद्धि की गई है। रिजर्व बैंक की बिल बाजार विकास सम्बन्धी योजना में समिति की सिफारिश को ध्यान में रखा गया है।

### नया उद्योग एक्ट---

भारत सरकार ने १५ फरवरी सन् १६५७ से नये उद्योग एक्ट को लागू करने की घोषणा की है, जिसमें उद्योग (विकास और नियमन) एक्ट सन् १६५१ में संबोध्यन किये गये हैं। नये विधान में ३४ उद्योगों को नियम के अन्तर्गत लाने का प्रयत्न किया गया है, जिनका विकास सरकार की सन् १६५६ की औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार किया जायगा। निम्न उद्योगों को संबोधित नियम के अनुसार सरकारी कार्य के क्षेत्र में लाया गया है:—

Ferro-alloys and special steels, electrical furnaces, earth moving machinery, typewriters and calculating machines, air conditioner and refrigerators, plastic moulding industries, paints, varnishes and enamels, staple fibre, pulp, food processing industries and cigarettes.

पंजीयन तथा अनुज्ञापन प्रगालियों में भी कुछ छोटे-छोटे परिवर्तन किये गये हैं। सरकार ने जनमत प्राप्त करने के लिए एक्ट की व्यवस्थाओं को गजट में छाप दिया था।

### भ्रौद्योगिक वित्त में सुधार के सुभाव—

इस समय देश में ग्रीद्योगीकरण की शीघ्रतापूर्वंक प्रगति का प्रयत्न किया जा रहा है। वास्तव में देश में ग्राधिक नियोजन की सफलता बड़े ग्रंश तक इसी बात पर निर्भर है कि कृषि ग्रीर उद्योगों का किस ग्रंश तक विकास हो पायेगा। वैसे तो देश की ग्रीद्योगिक उन्नति के मार्ग में ग्रनेक बाधायें हैं, परन्तु ग्रीद्योगिक वित्त की समुचित व्यवस्था का ग्रभाव एक महान् बाधा है। देश में पूँजी के निर्माण की गित धीमी है ग्रीर जनता में बैंकिंग ग्रादत ग्रभी बहुत कम है। ग्रीद्योगिक वित्त की पूर्ति के साधन तो बड़े ही ग्रपर्याप्त ग्रीर कुछ दशाग्रों में बड़े ही ग्रसन्तोषजनक हैं। श्रीद्योगिक वित्त की कमी ने देश में दो ऐसी प्रथाग्रों को महत्त्वपूर्ण बना दिया है जो भारत की ही विशेषताएँ हैं, ग्रर्थात् मैनेजिंग एजेन्सी प्रगाली तथा उद्योगों द्वारा जन-साधारण से निक्षेपों को स्वीकार करना। इसमें वो सन्देह नहीं है कि ग्रारम्भ में इन दोनों प्रथाग्रों ने भारतीय ग्रर्थं-व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण सेवा की है, परन्तु कालान्तर में इनके दोष इतने बढ़ गये हैं कि ग्रव इनका न रहना ही ग्रच्छा होगा। देश की ग्रधिकांश बैंक व्यापार बैंक हैं, जो ग्रल्पकालीन ऋगा देती हैं ग्रीर उद्योगों के हिण्टकोग से बहुत लाभ-दायक नहीं हैं। विगत वर्षों में भारत सरकार ने ग्रीद्योगिक वित्त की पूर्ति को बढ़ाने

के अनेक प्रयत्न किये हैं और देश में विदेशी पूँजी को भी निमन्त्रित किया है, परन्तु अभी भी पूर्ति आवश्यकता से कम है।

श्रीद्योगिक वित्त की पूर्ति को बढ़ाने श्रीर श्रीद्योगिक ऋगों पर ब्याज की दरों को घटाने के लिए निम्न सुभाव दिये जा सकते हैं :—

- (१) अभिगोपन-गृहों का विकास (Development of Underwriting houses)—देश की एक महान् कमी यह है कि अभिगोपन-गृह जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का अभाव है। ये संस्थायें कम्मनियों के अंगों और ऋग्य-पत्रों (Debentures) का अभिगोपन करके उनके प्रति विश्वास को बढ़ा देती हैं और जनता को अपने धन का उद्योगों में विनियोग करने को प्रेरित करती हैं।
- (२) ग्रीद्योगिक बैंकों की स्थापना—देश में ग्रीद्योगिक बैंकों के विकास की महान् ग्रावश्यकता है। भूतकाल में ऐसी बैंक बहुत सफल नहीं हो पाई हैं, परन्तु इनके महत्त्व को सभी ने स्वीकार किया है। भारत सरकार को विशेष मुविधायें देकर इनके विकास का प्रबन्ध करना चाहिए। ग्रीद्योगिक वित्त प्रमण्डल तथा ग्रन्थ ग्रीद्योगिक वित्त सम्बन्धी प्रमण्डलों की स्थापना ने इस ग्रभाव को कुछ ग्रंश तक दूर ग्रवश्य कर दिया है।
- (३) ग्रौद्योगिक प्राधि बैंकों की स्थापना (Establishment of Industrial Mortgage Banks)—जिस प्रकार कृपकों की दीर्घकालीन ऋए की मावश्यकताग्रों की पूर्ति के लिए भू-प्राधि बैंक लाभदायक होती हैं। ठीक इसी प्रकार ऐसी बैंक उद्योगों के लिए बहुत उपयोगी होंगी जो मशीनों तथा भन्य स्थिर भौद्योगिक सम्पत्ति की ग्राड़ पर ऋए। दे सकें।
- (४) व्यापार बैंकों का पुनर्सङ्गठन—एक महत्त्वपूर्ण मुक्ताव यह भी हो सकता है कि जर्मनी की भाँति भारत में भी व्यापार बेंकों को उद्योगों को दीर्घका-बीन ऋगा देने की आज्ञा दी जाय। ऐसी दशा में यह एक ही बैंक एक ही साथ व्यागर बैंक तथा औद्योगिक बैंक दोनों होगी।
- (१) वितियोग ट्रस्टों की स्थापना (Establishment of Investment Trusts)—धन के विनियोग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तथा भारतीय पूँजी की परम्परागत लज्जा को दूर करने के लिये विनियोग ट्रस्टों की स्थापना से अपिक लाभ हो सकता है।
- (६) सर्राःफ सिमिति के सुभावों को कार्य-रूप देना—जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, श्रौद्योगिक वित्त के सुघार हेतु सर्राफ सिमिति ने श्रनेक महत्त्व पूर्णं सुभाव प्रस्तुत किये हैं। इन सुभावों को श्रावश्यक संशोधनों के साथ कार्यं-रूप दे देना चाहिये।
- (७) विदेशी पूँजी के ग्रायात को प्रोत्साहन—इसमें तो सन्देह नहीं है कि विदेशी पूँजी प्रत्येक दशा में ग्रच्छी नहीं होती है। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में इससे हमें ग्रधिक सहायता मिल सकती है। पूँजी के ग्रायात में हमें यह नहीं देखना

चाहिए कि वह किस देश से मिल रही है। समुचित शतों, समुचित नियन्त्रसात्य राजनीतिक दबाव के अभाव की दशा में हमें प्रत्येक देश से आने वाली पूँजी क स्वागत करना चाहिए।

(८) ऋगा सम्बन्धी प्रतिभूतियों में उदारता—साधारणतया हमारे के में व्यापार बेंकों की ऋगा के सम्बन्ध में प्रतिभूति सम्बन्धी शर्तें बहुत कड़ी होती है पारचात्य देशों में व्यक्तिगत प्रतिभूतियों पर पर्याप्त ऋगा मिल जाते हैं। सुरक्षा के ध्यान में रख कर भारतीय बेंक कुछ ऐसे उपाय अवश्य निकाल सकती हैं जिससे कि प्रतिभूति सम्बन्धी शर्तें अधिक उदार हो जायें।

### **QUESTIONS**

1. Wrire a short essay on 'Industrial Finance' in India.

(Raj., B. A., 1957

2. Discuss fully the objects, constitution and functions of the Industrial Finance Corporation in India.

(Agra, B. Com., 1950

3. To what extent do commercial banks in India provide financial assistance to private industries? How far would the Industrial Credit and Investment Corporation of India solve the problem of industrial finance?

(Agra, B. Com., 1956)

4. What are the sources from which industries get their finance in India? Discuss the recent measures adopted to remove the defect of industrial finance in India.

(Raj., B. Com., 1950)

5. Give the chief features of the Industrial Finance Corporation of India and critically examine its working.

B. Com., 1952

# भारत में विदेशी पूँजी की समस्या

(The Problem of Foreign Capital in India)

समस्या का रूप-

विदेशी पूँजी की समस्या स्वतन्त्र भारत की एक महत्त्वपूर्ण समस्या है। इस पूँजी के प्रति दो प्रकार के विरोधी मत पाये जाते हैं। ग्राधिक विद्वानों का मत है कि इस समय हमारी सबसे बड़ी ग्रावश्यकता देश का ग्राधिक विकास है ग्रौर क्योंकि हमारे पास इस कार्य के लिए यथेष्ठ पूँजी नहीं है, हमें विदेशी पूँजी का स्वागत करना चाहिए। इसके विपरीत राष्ट्रीयता के पुजारियों का तथा उन व्यक्तियों का जो विदेशी पूँजीपतियों को शङ्का की हष्टि से देखते हैं, मत यह है कि ग्राधिक विकास को शीघ्रतम सम्पन्न करने के लिए देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता को सकट में डाल देना उचित नहीं है। विदेशी हमारे कल्याएा के लिए हमारे देश में नहीं ग्राते हैं, उनका उद्देश्य तो उचित ग्रौर ग्रमुचित रीति से हमारे देश के साधनों का शोषए करके ग्रपनी जेवें भरना होता है। सामान्य ग्रमुभव यही है कि देश की ग्राधिक दासता ग्रन्त में राजनीतिक दासता का कारए। बन जाती है।

ये दोनों हिण्डिकोरा एक दूसरे के पूर्णतया विरोधी हैं। इनमें से एक मुद्ध राष्ट्रीयवाद पर आधारित है और दूसरा भौतिक बुद्धिमानी पर। सत्य शायद दोनों के बीच में है। विदेशी पूँजी के प्रति अविश्वास को छोड़ देना किसी प्रकार भी उचित नहीं हो सकता है, परन्तु यह समभना भी भूल होगी कि प्रत्येक दशा में विदेशी पूँजी बुरी होती है। समुचित नियन्त्ररा द्वारा विदेशी पूँजी के दोषों को दूर करना सम्भव है और उसके उपयोग से पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सकता है।

भारत में विदेशी पूँजी के प्रवेश का इतिहास-

भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों (Portugese) ने सन् १५०० में कालीकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित करके विदेशी पूँजी देश में उपस्थित की। बाद को डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी, ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा फांसीसी कम्पनियों ने पुर्तगालियों का अनुकरण किया। ऐतिहासिक हिण्टिकोण से भारत में विदेशी पूँजी के विकास के तीन अलग-अलग युग हिण्टिगोचर होते हैं: आरम्भ में १८ वीं शताब्दी के अन्त तक व्यापारी पूँजी का जोर रहा, दूसरी अवस्था में औद्योगिक पूँजी आई, जिसने देश के साधनों का शोषण करने का प्रयस्त किया। इस प्रकार की पूँजी अभी तक भी देश में

म्राती रहती है। म्रन्तिम प्रकार की पूँजी ऋगा पूँजी है, जिसका प्रवेश थोड़े ही काल से म्रारम्भ हुम्रा है म्रौर जो म्रधिकांश विदेशी पूँजी सम्बन्धी दोषों से साधारणतया विमुक्त होती है।

१७ वीं शताब्दी के अन्त तक ब्रिटिश व्यापारियों की नीति यह थी कि भारतीय उद्योगों की तैयार उपज को यूरोप के देशों में बेचकर लाभ कमाएँ। इन व्यापारियों ने ग्रारम्भ में भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया श्रौर उनके विकास के लिए ग्रार्थिक सहायता दी । इङ्गलैंड में ग्रौद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् इस नोति में परिवर्तन हुआ और विदेशी व्यापारियों ने भारत से कच्चे माल का निर्यात तथा देश में इङ्कलैंड के उद्योगों के तैयार माल का आयात आरम्भ किया। फिर भी १८ वीं शताब्दी के अन्त तक देश में लगाई हुई अधिकाँश पूँजी व्यापारी पूँजी ही रही। आगे चलकर १८ वीं शताब्दी के अन्त में इंगलैंड की निर्वाधावादी नीति के फलस्वरूप विदेशियों को भारत में ग्रपने उद्योग-धन्धे खोलने की पूर्ण स्वतन्त्रता मिली। भारतीय पूँजी तो ग्रारम्भ से ही शर्मीली थी ग्रौर लोग उद्योगों में बचत को लगाने के स्थान पर असे सोने-चाँदी तथा जेवरात के रूप में रखना अधिक पसन्द करते थे, म्रतः विदेशियों ने भारत में म्रपने उद्योग ग्रौर उपक्रम खोल दिये ग्रौर इस प्रकार भीद्योगिक पूँजी देश में भाने लगी। पूँजी के इस प्रवाह को दो बातों ने ग्रौर भी प्रोत्साहित किया । एक ग्रोर तो देश में ग्रान्तरिक शान्ति ग्रौर सुरक्षा की व्यवस्था सूधर गई थी और दूसरी ओर विदेशी व्यापारियों ने ऐसा ग्रनुभव किया था कि भारत में उद्योग खोलने से कच्चे माल को भारत से ले जाने ग्रौर तैयार माल को फिर भारत में लाने का यातायात व्यय बचाया जा सकता था । इस ग्रौद्योगिक पूँजी ने रेलों, सङ्कों, नहरों ग्रादि के विकास में श्रधिक सहायता दी। २० वीं शताब्दी के ग्राग्मा में ग्रौद्योगिक पूँजी ने देश में निर्माण उद्योगों का भी विकास ग्रारम्भ किया।

इसी काल में ऋण पूँजी भी देश में आने लगी, यद्यपि औद्योगिक पूँजी का आयात बराबर होता रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने निर्यात व्यापार के घाटे की बिटिश व्यापारियों ने अपने भारतीय औद्योगिक विनियोगों से अधिक आय प्राप्त करके पूरा करने का प्रयत्न किया था। ऋण पूँजी का महत्त्व हाल ही के वर्षों में बढ़ा है। इस पूँजी को केवल ब्याज कमाने के लिए भारत में भेजा जाता है और विदेशो पूँजीपित का स्वार्थ केवल मूलधन तथा ब्याज का अगतान प्राप्त करने तक ही सीमित रहता है। औद्योगिक पूँजी की तुलना में भारत में ऋण पूँजी की मात्रा बहुत कम है। इस प्रकार की पूँजी साधारणतया दोष-मुक्त समभी जाती है, क्योंकि यह अपने साथ राजनीतिक प्रभाव नहीं लाती है। भूगरत में विदेशी पूँजी की आवश्यकता—

यह अनुमान कठिन है कि भारतीय अर्थं-व्यवस्था में विदेशी पूँजी का विभिन्न कालों में कितना महत्त्व रहा है। भूतकाल के सम्बन्ध में तो विदेशी पूँजी की मात्रा सम्बन्धी आँकड़े भी विश्वसनीय नहीं हैं । गैर-सरकारी अनुमानों में इतनी अधिक भिन्नता है कि किसी निश्चित बात का पता नहीं चल सकता है। सन् १६४= में रिजर्व बैंक ने यह अनुमान लगाया था कि उस समय भारत में कुल विदेशी पूँजी की मात्रा ५६६ करोड़ रुपया थी, जिसमें से ३७६ करोड़ रुपए की ब्रिटिश पूँजी थी, ३० करोड़ रुपए की अमरीकन, २१ करोड़ रुपए की पाकिस्तानी और ६ करोड़ रुपए की क्वाडियन (Canadian) पूँजी थी। विगत वर्षों में हमने विश्व बैंक और मुद्रा-कोष से भी ऋएा लिए हैं और इसी प्रकार अमरीका, रूस, चैंकोसलोवेकिया, स्वीडन आरि देशों से ऋएा लिए हैं । इसी प्रकार कुछ अन्य सूत्रों से भी ऋएा मिले हैं।

भारत में विदेशी पूँजी की । आवश्यकता इस कारण उत्पन्न होती है कि हमारे देश में प्रचुरता के बीच भी निर्धनता है। देश के विभिन्न प्रका के नाधन पूँजी के स्रभाव के कारण वेकार पड़े हुए हैं। साथ ही, देश में पूँजी का निर्माण प्रावश्यक तेजी के साथ नहीं हो रहा है। आधिक नियोजन की सफतता के लिए हमें आन्तरिक और बाहरी दोनों ही सूत्रों से पूँजी की पूर्ति बढ़ानी पड़ेगी। देश में पूँजी निर्माण की धीमी प्रगति के कारण तो हम पिछले अध्याय में देख ही चुके हैं। इसके अभिरिक्त हमारे अधिकांश निर्यात बेलीच प्रकृति के हैं और वर्तमान दशाओं में हमें कच्चा माल, मशीनरी, कारीगर और भोजन सभी वस्तुएँ अधिक मात्रा में विदेशों से मँगानी पड़ते हैं। यही कारण है कि देश की विदेशी विनिमय तथा ऋण सम्बन्धी आवश्यकता महान् है।

भारत में विदेशी पूँजी की आवश्यकता उसके निम्न लाभों के कारण उत्यन्त होती है:—

- (१) श्रीद्योगीकरए। में सहायता—विदेशी पूँजी ने भारत के श्रीद्योगीकरए। में सहायता दी है। राष्ट्रीय सरकार को भावी विकास योजनाश्रों में इससे श्रीर भी श्रिषक लाभ की श्राशा है। विदेशी पूँजी के उपयोग द्वारा हम देश के वेकार ५ ड़े हुए साधनों का उपयोग करके राष्ट्रीय धन श्रीर सम्पन्नता में वृद्धि कर सकते हैं।
- (२) प्रारम्भिक जोखिम का सामना—साधारण तथा, श्रौद्योगिक विकास की प्रारम्भिक श्रवस्था में जोखिम का श्रंग श्रविक रहता है। यह सम्भव है कि प्रारम्भिक जोखिम विदेशी पूँजीपित उठाएँ श्रौर तत्पश्चात् स्थापित उद्योग देशवासियों द्वारा प्राप्त कर लिया जाय।
- (३) शिक्षा ज्ञान का सह आयात—विदेशी पूँजी अपने साथ उत्पादन की नई-नई कलायें और रीतियाँ लेकर आती है। इससे देश में उत्पादन की शिल्प-क्षमता बढ़ जाती है।
- (४) स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा—विदेशी पूँजी एक आरोग्य प्रति-योगिता उत्पन्न करती है। देशी उद्योगपितयों को नींद से जगाया जा सकता है, क्योंकि विदेशो उत्पादकों से प्रतियोगिता करने के लिए उन्हें भी सुघार का मार्ग अपनाना पड़ता है और कुशलता प्राप्त करनी पड़ती है।

म्राती रहती है। म्रन्तिम प्रकार की पूँजी ऋगा पूँजी है, जिसका प्रवेश थोड़े ही काल से म्रारम्भ हुम्रा है भ्रौर जो म्रधिकांश विदेशी पूँजी सम्बन्धी दोषों से साधारणतया विमुक्त होती है।

१७ वीं शताब्दी के ग्रन्त तक ब्रिटिश व्यापारियों की नीति यह थी कि भारतीय उद्योगों की तैयार उपज को यूरोप के देशों में बेचकर लाभ कमाएँ। इन व्यापारियों ने ग्रारम्भ में भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया श्रौर उनके विकास के लिए ग्रार्थिक सहायता दी । इङ्गलैंड में ग्रौद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् इस नोति में परिवर्तन हुआ और विदेशी व्यापारियों ने भारत से कच्चे माल का निर्यात तथा देश में इङ्गलैंड के उद्योगों के तैयार माल का आयात आरम्भ किया। फिर भी १८ बीं शताब्दी के अन्त तक देश में लगाई हुई अधिकाँश पूँजी व्यापारी पूँजी ही रही। आगे चलकर १८ वीं शताब्दी के अन्त में इंगलैंड की निर्बाधावादी नीति के फलस्वरूप विदेशियों को भारत में अपने उद्योग-धन्धे खोलने की पूर्ण स्वतन्त्रता मिली। भारतीय पूँजी तो ब्रारम्भ से ही शर्मीली थी और लोग उद्योगों में बचत को लगाने के स्थान पर उसे सोने-चाँदी तथा जेवरात के रूप में रखना अधिक पसन्द करते थे. अतः विदेशियों ने भारत में अपने उद्योग और उपक्रम खोल दिये और इस प्रकार श्रीद्योगिक पूँजी देश में श्राने लगी। पूँजी के इस प्रवाह को दो बातों ने श्रीर भी प्रीत्साहित किया । एक श्रोर तो देश में श्रान्तरिक शान्ति श्रीर सुरक्षा की व्यवस्था सुघर गई थी और दूसरी ओर विदेशी व्यापारियों ने ऐसा अनुभव किया था कि भारत में उद्योग खोलने से कच्चे माल को भारत से ले जाने ग्रौर तैयार माल को फिर भारत में लाने का यातायात व्यय बचाया जा सकता था। इस ग्रौद्योगिक पूँजी ने रेलों. सङ्कों, नहरों आदि के विकास में अधिक सहायता दी। २० वीं शताब्दी के आगम्भ में स्रौद्योगिक पूँजी ने देश में निर्माण उद्योगों का भी विकास स्रारम्भ किया।

इसी काल में ऋग् पूँजी भी देश में आने लगी, यद्यपि श्रीद्योगिक पूँजी का श्रायात बराबर होता रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने निर्यात व्यापार के घाटे की ब्रिटिश व्यापारियों ने अपने भारतीय श्रीद्योगिक विनियोगों से अधिक आय प्राप्त करके पूरा करने का प्रयत्न किया था। ऋग् पूँजी का महत्त्व हाल ही के वर्षों में बढ़ा है। इस पूँजी को केवल ब्याज कमाने के लिए भारत में भेजा जाता है श्रौर विदेशो पूँजीपित का स्वार्थ केवल मूलधन तथा ब्याज का भुगतान प्राप्त करने तक ही सीमित रहता है। श्रौद्योगिक पूँजी की जुलना में भारत में ऋग् पूँजी की मात्रा बहुत कम है। इस प्रकार की पूँजी साधारणतया दोष-मुक्त समभी जाती है, क्योंकि यह अपने साथ राजनीतिक प्रभाव नहीं लाती है। भूमरत में विदेशी पूँजी की आवश्यकता—

यह अनुमान कठिन है कि भारतीय ग्रर्थं-व्यवस्था में विदेशी पूँजी का विभिन्न कालों में कितना महत्त्व रह्या है। भूतकाल के सम्बन्ध में तो विदेशी पूँजी की मात्रा सम्बन्धो आँकड़े भी विश्वसनीय नहीं हैं । गैर-सरकारी अनुमानों में इतनी अधिक भिन्नता है कि किसी निश्चित बात का पता नहीं चल सकता है। सन् १९४० में रिजर्व बेंक ने यह अनुमान लगाया था कि उस समय भारत में कुल विदेशी पूँजी की मात्रा ५६६ करोड़ रुपया थी, जिसमें से ३७६ करोड़ रुपए की ब्रिटिश पूँजी थी, ३० करोड़ रुपए की अमरीकन, २१ करोड़ रुपए की पाकिस्तानी और ६ करोड़ रुपए की कनाडियन (Canadian) पूँजी थी। विगत वर्षों में हमने विश्व बंक और मुद्रा-कोष से भी ऋण लिए हैं और इसी प्रकार अमरीका, रूस, चैकोसलोवेकिश, स्वीडन आरि देशों से ऋण लिए हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य सूत्रों से भी ऋण मिले हैं।

भारत में विदेशी पूँजी की । आवश्यकता इस कारण उत्पन्न होती है कि हमारे देश में प्रचुरता के बीच भी निर्धनता है। देश के विभिन्न प्रकार के माधन पूँजी के अभाव के कारण वेकार पड़े हुए हैं। साथ ही, देश में पूँजी का निर्माण आवश्यक तेजी के साथ नहीं हो रहा है। आधिक नियोजन की सफतता के निए हमें अपनिरक और बाहरी दोनों ही सूत्रों से पूँजी की पूर्ति बढ़ानी पड़ेगी। देश में पूँजी निर्माण की धीमी प्रगति के कारण तो हम पिछले अध्याय में देख ही चुके हैं। इसके अनिरिक्त हमारे अधिकांश निर्यात बेलीच प्रकृति के हैं और वर्तमान दशाओं में हमें कच्या मान, मशीनरी, कारीगर और भोजन सभी वस्तुएँ अधिक मात्रा में विदेशों से मँगानी पड़ती हैं। यही कारण है कि देश की विदेशी विनिमय तथा ऋण सम्बन्धी अवश्यकता महान् है।

भारत में विदेशी पूँजी की आवश्यकता उसके निम्न लाभों के कारण उत्यन्त होती है:—

- (१) स्रौद्योगीकरए। में सहायता—विदेशी पूँजी ने भारत के सौद्योगीकरए। में सहायता दी है। राष्ट्रीय सरकार की भावी विकास योजनाओं में इससे सौर भी सिवक लाभ की स्राशा है। विदेशी पूँजी के उपयोग द्वारा हम देश के वेकार ५ डे हुए साघनों का उपयोग करके राष्ट्रीय धन सौर सम्पन्नता में वृद्धि कर सकते हैं।
- (२) प्रारम्भिक जोखिम का सामना—साधाररातवा, श्रौद्योगिक विकास की प्रारम्भिक श्रवस्था में जोखिम का श्रंश श्रविक रहता है। यह सम्भव है कि प्रारम्भिक जोखिम विदेशी पूँजीपित उठाएँ श्रौर तत्पश्चात् स्थापित उद्योग देशवासियों द्वारा प्राप्त कर लिया जाय।
- (३) शिक्षा ज्ञान का सह आयात—विदेशी पूर्णे अपने साथ उत्पादन की नई-नई कलायें और रीतियाँ लेकर आती है। इससे देश में उत्पादन की शिल्प-असमता बढ़ जाती है।
- (४) स्वस्थ प्रतियोगिता को वढ़ावा—विदेशी पूँजी एक प्रारोग्य प्रति-योगिता उत्पन्न करती है। देशी उद्योगपितयों को नींद से जगाया जा सकता है, क्योंकि विदेशी उत्पादकों से प्रतियोगिता करने के लिए उन्हें भी सुघार का मार्ग अपनाना पड़ता है और कुशलता प्राप्त करनी पड़ती है।

4

- (४) लाभदायक सम्पत्तियों का निर्माण—विदेशों पूँजपित देश में ऐसे उपक्रमों, ग्रादेयों ग्रीर साधनों तथा ऐसी सम्पत्ति का निर्माण कर सकते हैं जो विदेशियों के चले जाने के पश्चात् भी देश के लिए लाभ तथा ग्राधिक उन्नति का साधन बने रहें। भारतीय रेलें, जिनका निर्माण विदेशों पूँजी की सहायता से हुग्रा है, इसका एक बहुत ग्रच्छा उदाहरण हैं।
- (६) ग्रार्थिक नियोजन में सफलता—श्रार्थिक नियोजन की सफलता में भी विदेशी पूँजी से पर्याप्त सहायता मिल सकती है। ग्रार्थिक नियोजन के सम्बन्ध में हमारा पिछले = वर्षों का ग्रनुभव यही सिद्ध करता है कि शीघ्रतम् ग्रार्थिक विकास के लिए विदेशी पूँजी ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है।
- (७) पूँजीगत माल का ग्रभाव इस समय हमारी सबसे महान् श्रावश्य-कता पूँजीगत माल के श्रायात की है। इसके लिए दो ही उपाय हो सकते हैं: प्रथम तो यह कि हम उन देशों को श्रपने निर्यात बढ़ायें जो हमें बदले में पूँजीगत माल दे सकते हैं श्राँर दूसरा यह कि ऐसे देशों से ऋगा लेकर पूँजीगत माल को खरीदें। निर्यातों के सीमित होने के कारगा विदेशी पूँजी का प्राप्त कर लेना ही हमारे लिए हितकर होगा।

विदेशी पूँजी की हानियाँ ग्रथवा उसके दोष-

विदेशो पूँजी के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :--

- (१) राजनीतिक प्रतिबन्ध—सबसे बड़ा दोष राजनीतिक प्रकृति का है। "भण्डा व्यापार के पीछे-पीछे चलता है।" दूसरे शब्दों में, ग्राधिक ग्रधिकार राजनीतिक ग्राधिपत्य उत्पन्न करता है। विदेशी पूँजी देश की ग्राधिक ग्रौर राजनीतिक स्वतन्त्रता को मिटा देती है। चीन ग्रौर ईरान का ग्रनुभव तो ऐसा ही है। इसीलिए विदेशी पूँजी से डरना चाहिए।
- (२) स्रिधिकांश लाभ विदेशियों को—विदेशी पूँजी द्वःरा देश के साधनों का विदेशियों द्वारा शोषण होता है। लाभ का स्रिधिकाँश भाग विदेशियों की ही सम्पन्नता को बढ़ाता है। देश के निवासियों को केवल सीमित मात्रा में ही लाभ प्राप्त हो पाता है।
  - (३) रक्षा स्रौर स्राधार उद्योग—रक्षा स्रौर स्राधार उद्योगों में तो विदेशी पूँजी का उपयोग संकट से खाली नहीं होता है।
  - (४) भारतवासियों के प्रति भेद-भाव—भारत में विदेशी पूँजीपितयों ने भारतवासियों के प्रति भेद-भाव किया है। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध काम किया है श्रीर भारतीय कर्मचारियों को शिक्षरा तथा श्रनुभव प्राप्त करने से वैचित रखा है। वे देश में विदेशी सरकार के महान् समर्थंक रहे हैं।
- ( १) ग्रन्य विदेशियों के साथ पक्षपात—विदेशी पूँजीपितयों ने भारतीय व्यापारियों की ग्रपेक्षा सदा ही दूसरे विदेशियों के साथ रियायत की है । उन पर भारत के हितों के विरुद्ध कार्य करने के ग्रनेक ग्रारोप लगाये गये हैं।

(६) देशी पूंजी के निर्माण को अप्रोत्साहन—विदेशी पूँजी के बने रहने के कारण देश में पूँजी का निर्माण पूरी तेजी से नहीं होने पाया है। स्वश्वरणन्य सभी उद्योगपित अपने लाभ के एक भाग को पूंजी के रूप में उपयोग करके उसका विनियोग कर देते हैं, परन्तु भारत से प्रति वर्ष लगभग ३६ करोड़ रुपये की राशि विदेशी उपक्रमों के लाभ के रूप में देश से बाहर चली जाती है।

विदेशी पूँजी के दोषों को घ्यानपूर्वंक देखने से पता चलता है कि वे दोष काफो गम्भीर हैं। इधर पिछले १०-१५ वर्षों का ग्रनुभव भी कट्ठ है। कितने ही देश विदेशी पूँजी के कारण अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता भी खो बैंटे हैं। विदेशी पूँजी देश में विदेशी निहित हितों (Foreign vested interests) को उत्पन्न करती है, जिनकी रक्षा के लिए विदेशी सरकारें अपनी पूरीशक्ति लगा देती हैं। विदेशी पूँजीपतियों द्वारा संचालित उद्योग और व्यवसाय देश में विदेशी प्रभाव और षडयन्त्र के अहु बन जाते हैं। इन कारणों से विदेशी पूँजी के प्रति शंका का बना रहना स्वामाविक ही है, परन्तु इस सम्बन्ध में यह बात घ्यान देने योग्य है कि विदेशी पूँजी से सम्बन्धित अधिकाँश दोष उसके नियन्त्रण से सम्बन्धित हैं। स्वयं विदेशी पूँजी में दोष नहीं हैं। दोष इस कारण उत्पन्न होते हैं कि राष्ट्रीय सरकार उस पर उचित नियन्त्रण नहीं रख पाती है। अनुभव बताता है कि समुचित नियन्त्रण के अन्तगंत विदेशी पूँजी देश की महान् सेवा कर सकती है। इस दिशा में केवल एक ही कठिनाई है कि किसी देश के लिए अपनी ही शतोँ पर विदेशी पूँजी का प्राप्त कर लेना कठिन होता है।

भारत सरकार की विदेशी पूँजी सम्बन्धी नीति-

विदेशी पूँजी के गम्भीर दोषों के कारण उसके नियन्त्रण की आवश्यकता ग्रिषिक है, परन्तु प्रश्न यह है कि हमें किस प्रकार की विदेशी पूँजी पर नियन्त्रण रखना चाहिए। यदि विदेशी पूँजी भारतीय उद्योगों तथा व्यवसायों को ऋण के रूप में मिलती है तो उससे किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता है। सबसे अधिक दोष साहसी ग्रथना ग्रौद्योगिक पूँजी में होता है और इसी प्रकार की पूँजी की भारत में प्रधानता है। हमारे लिए ग्रावश्यकता इस बात की है कि हम ऋण पूँजी को समुचित प्रोत्साहन दें ग्रौर साहसी पूँजी पर समुचित नियन्त्रण रखें।

भारतीय स्वतन्त्रता के पूर्व विदेशी पूँजी के दोषों की गम्भीरता पर लगमग कभी भी विचार नहीं किया गया था। ब्रिटिश सरकार की सामान्य नीति उल्टी विदेशी पूँजीपतियों को विशेष सुविधायें देने की श्रोर थी। सन् १६२२ के ग्राधिक ग्रायोग को इस समस्या पर विचार प्रकट करने के लिए कहा गया था, परन्तु ग्रायोग के बहुकत को ऐसी पूँजी में कोई दोष दृष्टिगोचर न हो सका। इसके विपरीत ग्रायोग के ग्रत्पमत का विचार था कि विदेशी पूँजी के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए उस पर निम्न प्रतिबन्ध ग्रावश्यक थे:—

(१) विदेशी कम्पनियों को भारत सरकार से कार्याधिकार तथा पंजीयन

(Registration) प्राप्त करना चाहिए और प्रपनी पूँजी को रूपमें में लगाना चाहिए, न कि विदेशी मुद्राओं में।

- (२) ऐसी कम्पनियों के संचालक-मण्डल में भारतवासियों का समुचित प्रति-निधित्त्व रहना चाहिए।
- (३) इन कम्पनियों को भारतवासियों के लिए शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध करनी चाहिए।

सन् १६२५ की विदेशी पूँजी समिति ने भी उपरोक्त सुक्षावों का अनुमोदन् । कया था । इस समिति का विचार था कि ऐसी विदेशी कम्पनियों के संचालक मण्डल में भारतवासियों के प्रतिनिधि अवश्य रहने चाहिए, जिन्हें भारतीय साधनों के शोषण का विशेष अधिकार दिया गया था । इन सिफारिशों के रहते हुए भी भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ भी प्रयत्न नहीं किया था । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि दोनों महायुद्धों के बीच के काल में प्रति वर्ष लगभग ४०-५० करोड़ रुपया विदेशी विनियोगों के लाभ के रूप में या तो देश से बाहर जाता रहा है या उसे फिर से भारत में ही विनियोगों में लगा दिया गया है । राष्ट्रीय नियोजन समिति (National Planning Committee) ने भी विदेशी पूँजी की समस्या पर विचार किया था । समिति के निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:—

- (१) विदेशी पूँजी ने स्राधिक स्रौर राजनीतिक दोनों ही हष्टिकोगों से राष्ट्रीय विकास में बाघा डाली है ।
  - (२) राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगों में विदेशी ग्रधिकार तथा प्रबन्ध नहीं रहना चाहिए। ऐसे उद्योगों में विदेशी पूँजी का केवल ऋ ए। के रूप में ग्रहण करना ही उपयुक्त हो सकता है।
  - (३) विदेशी पूँजीपतियों के विशेषाधिकार समाप्त होने चाहिए।
  - (४) सभी महत्त्वपूर्ण उद्योगों में सरकार को चाहिए कि मुग्रावजा (Compensation) देकर विदेशी पूँजी का घीरे धीरे निस्तारण करे।

भारत सरकार की वर्तमान नीति-

प्रश्नेल सन् १६४८ को ग्रौद्योगिक नीति प्रकथन (Industrial Policy Statement) में भारत सरकार की विदेशी पूँजी सम्बन्धी नीति की घोषणा की गिर्देशी। इस प्रकथन में विदेशी पूँजी के ग्रायात की ग्रावश्यकता को तो स्वीकार कर जिल्या गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में निम्न शर्ते लगा दी गई हैं:—

(१) विदेशी पूँजीपितयों को भारत सरकार की श्रौद्योगिक नीति के श्रनुसार कार्य करना पड़ेगा। भारत सरकार देशी श्रौर विदेशी पूँजी के बीच भेद-भाव नहीं करेगी श्रौर दोनों के बीच सहयोग का श्राषार स्थापित करने का प्रयत्न करेगा।

- (२) विदेशिया क लाम तथा मूलघन भारत स ानकाल ले उतने हा ग्राहिक कार रहेगा, किन्तु कुछ निश्चित शतों के म्रन्तगंत ही। (३) विदेशी कर्मचारी उन पदों पर रखे जा सकते हैं जिनके निए उपयुक्त योग्यता तथा अनुभव प्राप्त भारतवासी उपलब्ब नहीं हैं, परन्तु विदेशी कम्पनियों को भारतवासियों के शिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी श्रौर घीरे-घीरे श्रपनी सेवाश्रों का भी भारतीयकरण (Indiani-
- sation) करना पड़ेगा। (४) विदेशी कम्पनियों को सरकारी ग्रिथिकार में लेने समय उनके मालिकों को उचित मुग्रावला दिया जायगा।
- (५) जब तक विदेशी कम्पनियाँ रचनात्मक तथा सहयोगी कार्यं करतो रहेंगी, भारत सरकार उन्हें किसी प्रकार की हानि नही पहुँचाएगी।
- जून सन् १६५० में इस नीति को स्पष्ट करते हुए प्रधान मन्त्री नेहरू ने कहा शाः "प्रथम जनवरी सन् १६५० के पश्चात् लगाई गई विदेशी पुँजी कौ, यदि वह
- ऐसे उपक्रमों में लगाई है जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया है, प्रारम्भिक विनि-योग तथा उसके लाभ की मात्रा तक की राशि भारत के बाहर ले जाने की पूर्ण स्वतन्त्रतो होगी ।'' सन् १६४६ में केन्द्रीय उद्योग सलाहकार समिति ने भी सिफारिश
- की थी—"भारत सरकार को श्रमरीकंन तथा ग्रन्य विदेशी पूँजी को भारत में निय-ंन्त्रित करने के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिए।" सन् १९५०-५१ के बजट भाष्या में भारत के वित्त मन्त्री ने घोष्या की थी कि भारत सरकार सम्मिलित
- हिस्सेदारी के श्राधार पर, यदि उसके साथ राजनीतिक शर्ते जुड़ी हुई नहीं हैं, विदेशी पूँजी का स्वागत करेगी, परन्तु भारत सरकार की सामान्य नीति इस प्रकार है कि
- ंप्रत्येंक ऐसे व्यवसाय में जहाँ विदेशी पूँजी लगी है, स्वामित्त्व तथा नियन्त्रगा में भारतवासियों का बहुमत रहेगा श्रौर भारतवासियों के शिक्षण की समुचित व्यवस्था ंकी जायगी। सरकारी नीति का परिएाम यह हुआ है कि विदेशी पूँजी का आयात
- ंबराबर होता रहा है। सन् १६४६ में ६ ३५ करोड़ रुपये की पूँजी विदेशों से भारत में ग्राई थी। इसी प्रकार सन् १६५० में २ ५७ ग्रीर सन् १६५१ में ६ ६६ करोड़
- स्पये की पूँजी भारत को प्राप्त हुई। अधिकांश पूँजी ब्रिटेन से आई है। मार्च सन् १६५४ तक भारत सरकार का कुल विदेशी ऋरण (लोक) १३५.६६ करोड़ कार्य ं का था, जिसमें ११२.०४ करोड़ रुपये के मूल्य का डालर ऋगा भी सम्मिनित या।
- े प्रथम पंच वर्षीय योजना में ३०० करोड़ रुपएके विदेशी ऋगों की ग्रावस्यकता बताई ाई थी, यद्यपि यह अनुमान वास्तव में अधिक रहा है। अप्रैल सन् १९५३ और जून
- सन् १९५४ के बीच भारत को १६२ द लाख रुपये के विदेशी विनियोग प्राप्त हुए, ं परन्तु इसी काल में ५४ २४ लाख रुपये की विदेशी पूँजी लौटा दी गई है। प्राप्त · विनियोग में से इङ्गलैंड से १३७°८५ लाल, ग्रमरीका से १६'०० लाल तथा स्टिटजर-

लैंड से २२°१५ लाख, रुपये की कीमत के ऋगा प्राप्त हुए हैं। सन् १९५७ में विदेशी पूँजी का कुल अनुमान १,०३६ करोड़ रुपये का था। दूसरी योजना में सन् १९५६-६१ के काल में ८०० करोड़ रुपये की विदेशी पूँजी की आवश्यकता दिखाई गई है।

सामान्य रूप में हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि हमारे लिए विदेशी पूँजी की आवश्यकता है और यदि वह समुचित शतों पर मिलती है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, परन्तु हमें विदेशी पूँजी के प्रति पूर्णतया निर्भीक होना उचित नहीं है। अनुभव बताता है कि लगभग प्रत्येक दशा में ऐसी पूँजी के साथ ग्रहश्य राजनीतिक बन्धन लगे रहते हैं। यह भी आवश्यक है कि समुचित शतों के अन्तर्गत हमें किसी भी देश से पूँजी के आयात स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। भय यहीं है कि शायद मुँह माँगी शतों पर हमें आवश्यक मात्रा में विदेशी पूँजी न मिल सके।

दूसरा पंच-वर्षीय स्रायोजन स्रौर विदेशी पूँजी-

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रथम पंच वर्षीय आयोजन के काल में ३०६ करोड़ रुपये की विदेशी पूँजी मिली है, जिसमें विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त राजि भी सम्मिलित है। इस पूँजी का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमरीका से प्राप्त हुआ है। उस देश से २३६ करोड़ रुपये की पूँजी मिली है, जिसमें १२६ ६० करोड़ रुपया ऋगा के रूप में मिला है और शेष सहायता के रूप में। कुल प्राप्त विदेशी पूँजी में से लगभग २०४ करोड़ रुपये का ही प्रथम योलना-काल में उपयोग हो सका है। शेष को दूसरी पंच-वर्षीय योजना के अर्थ प्रवन्ध में सम्मिलित कर लिया गया है। विभिन्न सूत्रों से प्राप्त राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—अमरीका २६ ४० करोड़ डालर, ग्रूजीलेंड १६ ४० लाख पौंड, फोर्ड फाउन्डेशन ८० लाख डालर, नॉरवे १ करोड़ क्रेनर और विश्व बैंक ६ १० करोड़ डालर।

नई योजनाग्रों में फाँस, ईरान, पश्चिमी जर्मनी, इटली, स्विटजरलैंड, बिटेन, रूस, जापान तथा चैकोस्लोवेकिया से भी सहायता प्राप्त हुई है। साधारएतया व्यक्तिगत विदेशी फर्में भारतीय उद्योगों में साफेदारी के ग्राधार पर पूँजी लगा रही हैं। ग्रमरीका का ग्रायात-निर्यात बैंक (Import Export Bank of U. S. A.) भी ऋएों के रूप में सहायता दे रही है। दूसरे ग्रायोजन में १६० करोड़ रूपया प्रति वर्ष की विदेशी पूँजी के ग्रायात का ग्रनुमान है ग्रौर इस प्रकार ५ वर्ष में ६०० करोड़ रूपया इस मद से मिलने की ग्राशा है। ग्रायोजन कमीशन का विद्वास है कि इस ग्रंश तक विदेशी सहायता ग्रवश्य मिल जायगी। दूसरे ग्रायोजन में ४०० करोड़ रूपये का घाटा दिखाया गया है, जिसका ग्रविकांश भाग भी विदेशी ऋएों से प्राप्त होने की ग्राशा है। इस सम्बन्ध में कुछ ग्राशाजनक घटनाएँ ग्रभी से सामने ग्राई हैं। व्यक्तिगत विदेशी ऋएों की मात्रा बराबर बढ़ रही है। विद्व बैंक से ग्रौर ग्रविक ऋएा प्राप्त हुए हैं। इनके ग्रतिरिक्त पश्चिमी जर्मनी, चैकोस्लोवेकिया, रूस ग्रौर स्वीडन से भी

ऋग् मिले हैं और अधिक ऋग् मिलने की आशा है। पिछले तीन वर्षों से व्यापारा-क्षेत्र सम्बन्धी स्थिति में कुछ सुधार हुटा है और ऐसी आशा की जाती है कि विदेशी विनिसय सद पर भी कुछ अधिक बचत हो जायगी। भारत सरकार ने लगभग १७० इरोड़ रुपया रिजर्व बैंक के विदेशी विनिसय संचय में मे निकालने का भी निश्चय किया है। हमारी भावी नीति समुचित शर्तों के अन्तर्गत और अधिक मात्रा में विदेशी ऋग् प्राप्त करने की है।

दूसरी योजना के काल में सन् १६५७ के अन्त तक ४८० करोड़ रुपया विदेशी इत्या के रूप में प्राप्त करने का अनुमान रखा गया था। सन् १६५८ का लक्ष्य ३२५ करोड़ रुपये वा था। हाल में १०७ करोड़ रुपया अमरीका से, ६० करोड़ रुपया रूस से, २८ करोड़ रुपया फांस से, २४ करोड़ रुपया जापान से और ६६ करोड़ रुपया पहिचमी जर्मनी से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त कनाडा में मार्च सन् १६५८ तक २८० लाख डालर का ऋगा मिला था। मार्च सन् १६५८ में अमरीका ने २२० करोड़ रुपया मिलने की आशा है। इस प्रकार सन् १६५८-५६ में विदेशी ऋगा सम्बन्धी अनुमान काफी आशा जनक रहे हैं।

### **QUESTIONS**

- 1. Examine critically the policy of the Government of India with regard to foreign capital in India.
- 2. Bring out a case for foreign capital in India. What steps have been taken during recent years in India to encourage the flow of foreign capital in the country?
- 3. Do you think that foreign capital is necessary for the success of economic planning in India? How far does the Second Plan depend for its success on the availability [of foreign capital?]
- 4, Discuss the role played by foreign capital in the economic development of India.

### श्रध्याय ४४ भारत में बैंकिंग विधान

(Banking Legislation in india)

भारत में बैंकिंग विधान की श्रावश्यकता—

पुरानी विचारघारा के अनुसार बैंकिंग विधान आवश्यक नहीं है। स्वर्णमान की स्वचालक प्रकृति इस बात का आश्वासन थी कि साख का अत्यिक विस्तार न होने पाए। इसके अतिरिक्त स्वर्णामान के अन्तर्गत केवल बैंक दर में परिवर्तन करके ही देश की सरकार साख निर्माण को नियन्त्रित कर सकती थी, किन्तु धीरे-धीरे बैंक दर की सप्रभाविकता घट गई और स्वर्णामान का भी अन्त हो गया। बीसवीं शताब्दी में बैंकिंग विधान की आवश्यकता सभी देशों ने अनुभव की। इङ्गलैंड ने भी अपनी परम्परागत निर्वाधावादी नीति में परिवर्तन किया और अन्त में तो बैंक ऑफ इगलैंड का राष्ट्रीयकरण भी कर लिया। भारत में बैंक दर नीति की सप्रभाविकता सदा ही अनिश्चित रही है और बैंकों का विलीयन इतना अधिक हुआ कि लम्बे काल से बैंकिंग विधान की दिशा में किसी उपयुक्त नीति की आवश्यकता अनुभव की गई। इः महत्त्वपूर्ण कार्णों से भारत में बैंकिंग विधान की आवश्यकता है:—

- (१) देशी श्रीर श्राधुनिक बैंकों के बीच समचय—भारत में देशी बैंकरों श्रीर महाजनों की संख्या काफी श्रधिक है। साल संगठन पर एकाकी नियन्त्रण स्थापित करने के लिए देशी बैंकिंग का सिम्मिलित पूँजी बैंकिंग से सम्बन्ध स्थापित करना श्रावश्यक है। समचय की श्रावश्यकता इस कारण श्रीर भी बढ़ जाती है कि वर्तमान दशा में दोनों प्रणालियों के बीच प्रतिस्पर्धा है, जबिक देश में बेंकिंग सेवाश्रों का सामान्य ग्रभाव है। श्रनुभव बताता है कि बिना वैधानिक व्यवस्था के समचय स्थापित नहीं हो सकता है। समचय द्वारा दोनों ही प्रणालियों का भला होगा और साथ ही समाज तथा राष्ट्रीय श्रर्थंव्यवस्था को भी लाभ होगा।
  - (२) विलीयन प्रवृत्ति को रोकना— भारत में बैंक भारी संख्या में छेल हुई हैं। बैंकिंग विकास समुचित ग्राघार पर नहीं हो पाया है। ग्रनावश्यक विस्तार तथा शाखायें खोलने के सम्बन्ध में किसी उपयुक्त नियन्त्रण की ग्रावश्यकता है। बैंकिंग विघान द्वारा ग्रारोग्यहीन बैंकों का विकास रोका जा सकता है ग्रीर बेंकों को समुचित साख विकास तथा विनियोग नीति ग्रपनाने पर बाध्य किया जा सकता है।
  - (३) रिजर्व बैंक की शक्ति बढ़ाना—रिजर्व बैंक कुछ कारणों से कमज़ीर रही है। ग्रारम्भ में ही यह स्पष्ट हो गया था कि विस्तृत वैधानिक ग्रधिकारों के बिना रिजर्व बैंक सरकार की मुद्रा, साख तथा विदेशी विनिमय नीति को कार्य रूप नहीं दे

क्ल्मी। रिजर्व बैंक के पास बैंक दर श्रीर खुले बाजार व्यवसाय के दो महत्त्वपूर्ण श्रस्त्र हैं, परन्तु वे श्रपर्याप्त हैं। रिजर्व बैंक की सफलता का प्रमुख कारण उसके विस्तृत वैधा-कि श्रिषकार हैं।

- (४) विवेकहीन शाखा विस्तार पर प्रतिवन्ध—विगत वर्षों में भारतीय क्षेम की एक और विशेषता दृष्टिगोचर हुई है। प्रत्येक वैंक यही प्रयत्न करती है कि क्षी स्थानों पर अपने व्यवसाय का विस्तार करे। शाखाएँ बिना विस्तार को संभान्ता की जाँच किये ही खोल दी जाती हैं और उनके द्वारा अन्य वैंकों से प्रतियोगिता करने का प्रयत्न किया जाता है। कुछ नगरों में तो वैंकिंग सेवाएँ आवश्यकता से बद्धत अधिक हैं और कुछ उनकी सेवाओं से पूर्णत्या बंचित हैं। ऐसी अवस्था देश के लिए हिंकारी नहीं हैं, इसलिए शाखा खोलने के सम्बन्ध में कुछ वैधानिक व्यवस्थाओं की भारी आवश्यकता है।
- (५) ग्रामीरा क्षेत्रों में वैकिंग का विकास—ग्रामीरा क्षेत्रों को वैकिंग क्षेत्रों प्रदान करने के लिए तथा सहकारी साख ग्रान्दोलन को प्रोत्साहित करने के लिए वैकिंग विधान ग्रावश्यक है।
- (६) एक-दिशायी प्रकृति का निवारण—भारतीय बैंकिंग की एक-दिशायी प्रकृति भी समुचित विधान द्वारा रोकी जा सकती है। भारत में देशी बैंकिंग विधान का नियन्त्रण—

भारत में देशी बैंकिंग के नियन्त्रण का कार्य काफी देर में आरम्भ हुआ। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व इस दिशा में लगभग कुछ भी प्रयत्न नहीं किया गया था। रिजर्व बैंक श्रॉफ इंडिया एक्ट सन् १६३४ की घारा १५ (१) ग्र के अनुसार रेजर्व बैंक का यह कत्तंच्य है कि वह देशी बैंकिंग प्रणाली के सुघार के प्रस्ताव प्रस्तुत हरे। मई सन् १६३७ में रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में परिगणित बैंकों और देशी बैंकरों से विचार-परामर्श किया श्रौर एक योजना तैयार की। इस योजना में सन् १६३१ की केन्द्रीय बैंकिंग समिति की सिफारिशों को पूरा करने का प्रयत्न किया गया था। यह स्वीकार किया गया कि देशी बैंकरों का रिजर्व बैंक से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखा जाय, परन्तु सहायता तथा स्वीकृति प्राप्त करने के लिए देशी वैंकरों के लिए निम्न पाँच शर्तों का पूरा करना आवश्यक बनाया गया है:—

- (१) केवल ऐसे देशी बैंकरों को जो कम से कम २ लाख रुपये की पूँजी से व्यवसाय करते हों श्रीर ५ साल के भीतर श्रपनी पूँजी की मात्रा को ५ लाख रुपये तक बढ़ाने को तैयार हों, रिजर्व बैंक से स्वीकृति मिल सकती है।
- (२) ऐसे बैंकरों को बैंकिंग के म्रतिरिक्त ग्रन्थ व्यवसाय एक निश्चित अविधि के भीतर बन्द करने होंगे।
- (३) ऐसे बैंकरों के लिए समुचित लेखे रखना आवश्यक है और रिजर्व बेंक को इन लेखों के निरीक्षण का अधिकार होगा ।

- (४) उन्हें श्रपने चिट्ठे प्रकाशित करने चाहिए श्रौर समय-समय पर निश्चित रिपोर्ट रिजर्व बैंक को भेजनी चाहिए।
- (५) बदले में ऐसी बैंकों को रिजर्व बैंक से बिल भुनवाने का ग्रिधकार विका गया है। उन्हें वही सुविघाएँ प्राप्त होंगी जो ग्रपरिगिएत बैंकों (Non-scheduled Banks) को प्रदान की गई हैं।

देशी बैंकरों को ये शर्तें कड़ी ग्रनुभव हुई हैं। उन्होंने व्यापार ग्रौर सोना, चौदी तथा हीरे-जवाहरात का व्यवसाय छोड़ना स्वीकार नहीं किया है। सन् १९५० के ग्रन्त तक केवल ७ देशी बैंकरों ने शर्तों को स्वीकार किया था।

सम्मिलित पूँजी बैंकिंग का नियन्त्रग्-

सन् १९०५-०६ के बैंकिंग संकट ने बैंकिंग विधान की आवश्यकता स्पष्ट कर दी थी, इसलिए सन् १९१३ के कम्पनीज एकट में बैंकिंग कम्पनियों के सम्बन्ध में अलग व्यवस्थायें की गईं। इस एक्ट में बैंकिंग कम्पनियों को एक निश्चित रीति से चिट्ठे तैंथार करने का आदेश दिया गया था और उन्हें एक निर्धारित रूप में ६ मासिक विवरण पत्र प्रकाशित करना पड़ता था, परन्तु इस नियम की व्यवस्थायें अपर्याप्त थीं और इसका क्षेत्र बहुत सीमित था। प्रथम यहायुद्ध के काल में तथा उसके उपरान्त भी बेंक विलीयन का क्रम बराबर चलता रहा। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सन् १६२७ में हिल्टन यंग आयोग ने और सन् १६३१ में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने केन्द्रीय बैंक की स्थापना का सुफाव दिया था।

केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने समस्त भारतीय बैंकिंग प्रणाली की विस्तृत जाँच की थी। इसने एक ऐसे विशेष बेंकिंग विधान के निर्माण की सिफारिश की थी जिसमें सन् १६१३ के कम्पनीज एक्ट की व्यवस्थाओं को उचित संशोधनों सिहत सिम्मिलत किया जाय। सिमिति का विचार था कि इसके अतिरिक्त निम्न विषयों से सम्बन्धित क्यावस्थायों भी विधान में रखी जायें:—(१) बैंकिंग संगठन, (२) प्रबन्ध, (३) अंकेक्षण तथा निरीक्षण और (४) निस्तारण तथा विलय। सन् १६३६ में रिजवं बैंक को स्थापित करके तथा इन्डियन कम्पनीज (संशोधन) एक्ट, सन् १६३६ द्वारा सरकार ने सिमिति के अधिकाँश सुभावों को कार्य-रूप दिया। सन् १६३६ के नियम की प्रमुख व्यवस्थायें निम्न प्रकार थीं:—

- (१) परिभाषा—बैंकिंग कम्पनी की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि बैंकिंग कम्पनी साधारण कार्यों के अतिरिक्त, जैसे—रुपए का लेन-देन, बिलों का भुनाना, बहुमूल्य वस्तुओं का संरक्षण साख-पत्रों की निकासी इत्यादि, साथ-साथ अपना प्रमुख व्यवसाय चालू खातों पर अथवा अन्य किसी रूप में निक्षेपों का स्वीकार करना तथा घनादेश, ड्राफ्ट अथवा आदेश द्वारा रुपया निकालने का अधिकार देना, रख सकती है।
- (२) पूँजी—वैंकिंग कम्पनी के पास कम से कम ५० हजार रुपए की पूँजी होनी चहिए, जो अशों को वेचकर प्राप्त हुई हो।

- (३) सुरक्षित कोष—इसके पास एक सुरक्षित कोष होना चाहिए, जिसमें नाम का कम से कम २०% उस समय तक जमा किया जाय जब तक कि मुरक्षित कोष परिदत्त पूँजी के बराबर न हो जाय।
- (४) नकद कोष बैंकिंग कम्पनियों के लिए समय देन का १६% तथा  $\pi$  देन का ५% नकद कोष में रखना ग्रावश्यक रखा गया था ।
- (५) संचालन भविष्य में बैंकिंग कम्पनी का संचालन मैनेजिंग एकेन्टों द्वारा नहीं किया जा सकता था।
- (६) गौरा व्यवसाय—वैंकिंग कम्पनियों को किसी गौरा कम्पनी के अंश प्राप्त करने का ग्रिधिकार नहीं दिया गया था, जब तक कि गौरा कम्पनी कोई ऐसा अवसाय नहीं करती हो जो मुख्य कम्पनी के ही कार्यं से सम्बन्धित हो।
- (७) व्यवसाय क्षेत्र—वैंकिंग कम्पनी का व्यवसाय क्षेत्र उन कार्यों तक ही सीमित किया गया था जिनका रिजस्ट्रार के सम्मुख पंजीकरण के लिए पार्यंद सीमा- नियम (Memorandum of Association) में उल्लेख किया गया हो।
- (द) भुगतानों की सुविधा—कोई भी बेंकिंग कम्पनी थोड़े काल के लिए भुगतानों को स्थिगत कर सकती है, यदि रिजस्ट्रार इसकी सिफारिश करता है भीर स्थाशलय को विश्वास है कि कम्पनी की कठिनाई श्रस्थाई है।

एकट में बैंकिंग कम्पनियों के लिए की गई कुछ म्रन्य व्यवस्थाएं निम्न प्रकार हैं:---

- (१) नियम में बैंकिंग कम्पनी की विस्तृत परिभाषा की गई थी।
- (२) यह व्यवस्था की गई थी कि परिभाषा में वरिंगत कार्यों के अतिरिक्त कम्मनी अन्य कार्यंन करे।
- (३) एक दूसरी बैंकिंग कम्पनी के श्रतिरिक्त बैंक को अन्य किसी प्रकार के भैनेजिंग एजेन्ट रखने की आज्ञा नहीं दी गई थी।
- (४) अपरिदत्त पूँजी पर किसी प्रकार के खर्चे लगाना वर्जित किया गया था।
- (५) गैर-ग्रनुस्चित बैंकों के लिये सुरक्षित कोष तथा नकद कोषों के रखने की व्यवस्था की गई थी।
- (६) किसी भी बैंक को ग्रपनी पूँजी के ४०% से श्रिषक किसी एक कम्पनी में लगाने से वर्जित किया गया था।

उपरोक्त विघान की बहुत सी किमयों को सन् १६३४ के रिजर्व बैंक झाँक इण्डिया एक्ट ने भी पूरा कर दिया, जिसने बैंकिंग विधान को एक समुचित झाधार प्रदान कर दिया । रिजर्व बैंक एक्ट की एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि सभी बैंकों के लिए अपने निक्षेपों का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक में रखना अनिवार्य किया गया था । इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक को विधान के सम्बन्ध में और सुकाब

देने का भी श्रादेश मिला था। थोड़े ही काल में यह स्पष्ट हो गया कि सन् १६३६ का एकट श्रस्पष्ट तथा शासन के हिण्टकोगा से किठन था। इसके श्रितिरक्त एकट के पास होते ही बैंकों के फेल होने का वेग बढ़ गया था। इस कारण रिजर्व बैंक ने समस्त स्थिति की विस्तृत जांच की ग्रीर नवस्वर सन् १६३६ में विधान में कुछ ग्रावश्यक संशोधन करने के मुभाव प्रस्तुत किये। उस समय युद्ध की किठनाइयों के कारण इन सिफारिशों को कार्य रूप देना सम्भव न हो सका, परन्तु सन् १६४३-४४ में इंडियन कम्पनीज (द्वितीय संशोधन) एकट पास किया गया, जिसके श्रमुसार प्रत्येक ऐसी कम्पनी को बैंकिंग कम्पनी घोषित कर दिया गया जो श्रपने नाम के साथ बैंक ग्रथवा बैंकर शब्द का प्रयोग करती हो, परन्तु इसी काल में मुद्रा-प्रसार के कारण बैंकों की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगी ग्रीर उनमें से बहुत सी बैंकों की शासन तथा प्रबन्ध-व्यवस्था ठीक-ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए सन् १६४४ में एक ग्रीर संशोधक एकट पास हुग्रा, जिसमें मैनेजिंग एजेन्टों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाये गए।

दूसीरे महायुद्ध के काल में भारतीय बैंकिंग का विकास बड़ी तेजी के साथ हुआ, परन्तु इस विकास का प्रमुख कारए। देश में मुद्रा-प्रसार था। इस कारए। इसमें कुछ दोष दृष्टिगोचर हुए और कुछ अनुचित प्रवृत्तियां भी उत्पन्न हो गईं। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विधान में आवश्यक, संशोधन करा कर बैंकिंग प्रएगाली तथा साख विकास पर नियन्त्रए। रखने का प्रयत्न किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बैंक की वार्षिक सभा में युद्धकालीन विकास की निम्न अनुचित प्रवृत्तियों पर जोर दिया था:—

- (१) बिना विचारे शाखाएँ खोलने की प्रवृत्ति, जिससे कि बिना जोखिम पर
  - . . घ्यान दिये निक्षेपों को आकर्षित किया जा सके।
- (२) निक्षेपदाताओं के धन का प्रबन्धकों के लाभ के लिए उपयोग करना, इसके लिए अन्य कम्पनियों के श्रंश खरीदे गये, उद्योगों के क्षंश प्राप्त किये गए और विनियोग प्रन्यास (Investment Trusts) की स्थापना की गई, जिससे बेंकों के आदेय अधिक अतरल बन गये।
- (३) चिट्ठों में अदला बदली करने की प्रवृत्ति, जिससे कि बैंक की आर्थिक स्थिति का सही अनुमान न लगाया जा सके।
- (४) सट्टेबाजी की प्रवृत्ति, जो ग्रंशों, सरकारी हुण्डियों तथा चल ग्रौर ग्रचल सम्पत्ति में सट्टा करने तक विस्तृत थी।
- (५) लाभों को लाभाँश के रूप में बाँटने की प्रवृत्ति और सुरक्षित कोष की ग्रीर ध्यान न देने की प्रवृत्ति ।

सन् १६४५ के बैंकिंग कम्पनीज विल में इन प्रवृत्तियों को रोकने की व्यवस्था की गई थी, परन्तु यह बिल सन् १६४ द तक संसद के सम्मुख नहीं रख़ा जा सका था। बीच के काल में ग्रार्टीनेन्सों द्वारा रिजर्व बैंक को विशेष ग्रधिकार दिये गये। सन् १६४६ -के ग्रष्ट्यादेश (Ordinance) ने रिजर्व बैंक को किसी भी बैंक के लेखों के निरीक्षण

का ग्रधिकार दिया। रिजर्व बैंक के ग्रादेशों का पालन न करने पर किसी भी बैंक को बिरगिएत बैंकों की सूची में से निकाला जा सकता था, ग्रथवा कुछ कान के लिए इसका व्यवसाय बन्द किया जा सकता था । सन् १६४७ के ग्राडीनेन्स द्वारा रिजर्व के को ऐसी बैंकों को आर्थिक सहायता देने का अधिकार दिया गया जिन पर देश के विभाजन के कारण संकट म्रा गया था। इसी प्रकार दो और नियमों द्वारा कुछ प्रकार के प्रतिज्ञा-पत्रों की निकासी पर रोक लगाई गई और प्रत्येक बैंक के लिए नई शासा होलने के लिए रिजर्व वैंक से ग्राज्ञा प्राप्त करना ग्रावश्यक वनाया गया। ग्रन्त में, मार्च सन् १६४८ में एक नया बैकिंग बिल पास किया गया, जिसे १६ मार्च सन् १६४६ से लागू किया गया है।

बैंकिंग कम्पनीज एक्ट सन् १६४६—

यह एक्ट जम्मू और काश्मीर राज्य की छोड़ कर भारत के सभी राज्यों पर साग्र होता है। इस एक्ट का उद्देश्य भारतीय वैंकिंग प्रशाको को निम्न दोषपूर्ग प्रवृत्तियों को दूर करना बताया गया है।

- (१) ग्रचल सम्पत्ति की ग्राड़ पर ग्रधिक मात्रा में ऋरण देना।
- (२) ऐसी कम्पनियों को जिनमें बैंक के संचालकों अयदा उनके सम्बन्त्रियों का स्वार्थ हो, अपर्याप्त प्रतिभूतियों पर ऋग देना।
  - (३) बिना सोचे-बिचारे बैंक की शाखाग्रों को खोलते रहना।
- (४) बेंक के धन को ऐसी फर्मों में फंसा देना जिनमें बैंक के संचालकों को दिलचस्पी हो।
- (५) कुछ प्रबन्धकों द्वारा बैंक के कोषों का अनुचित उपयोग करके इसरी श्रौद्योगिक कम्पनियों पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करना ।
- (६) बैंक की वास्तविक स्थिति को छिपाने के लिए प्रकाशित होने वाल मांकड़ों में फेर-बदल करके जनता को धोखा देना।
- (७) कुछ छोटी-छोटी बैंकों का ग्रपने साधनों की तुलना में बहुत ग्रधिक मात्रा में ऋशों का प्रदान करना।

उपरोक्त एक्ट की प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं:--

- (१) परिभाषा- 'उधार देने ग्रथवा विनियोग करने हेतु जनता से मुद्रा के ऐसे निक्षेपों का स्वीकार करना जो या तो मांग पर अथवा अन्य किसी प्रकार शोधनीय हों एवं धनादेश. विकर्ष ब्रादेश ब्रथवा ब्रन्य प्रकार निकाली जा सकती हों'. वैिकग कहलाता है। एक बैंकिंग कम्पनी वह है जो भारतीय कम्पनीज एक्ट के अनुसार स्यापित हुई हो ग्रीर बैंकिंग का व्यवसाय करती हो। वे श्रीद्योगिक कम्मनियां जो भपनी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए निक्षेपों को स्वीकार कर लेती हैं, बैं किंग कम्पनियाँ नहीं हैं।
- (२) बैंक का व्यवसाय-इसके लिये एक विस्तृत सूची दी गई है, जिसमें वे सब व्यवसाय उल्लेखित किये गये हैं जो एक बैंकिंग कम्पनी कर सकती है। रुपये

का उधार लेना श्रीर देना, विनिमय बिलों का भुनाना, हुनिंडयों का भुनाना, विनिमय-साध्य साख पत्रों का जमा करना, सोने चाँदी तथा विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय, साख प्रमारा-पत्रों का प्रदान करना, मूल्यदान वस्तुश्रों का संरक्षरा करना, इत्यादि बहुत से कार्यों को बैंक के व्यवसाय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, परन्तु अपने ऋरा को वसूल करने के ग्रांतिरक्त ग्रन्य किसी भी उद्देश्य से बैंकिंग कम्पनी को प्रत्यक्ष व्यापार का ग्राधकार नहीं है। व्यवसायिक कार्यालय की बिल्डिंग को छोड़कर ग्रन्य कोई भी अचल सम्पत्ति बैंक ७ साल से श्रीधक काल के लिये प्राप्त नहीं कर सकती है। प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी के लिए रिजर्व बैंक से अनुज्ञापन प्राप्त करना ग्रावश्यक है। बिना ऐसा किये कोई भी कम्पनी अपने नाम के साथ बैंक अथवा बैंकर शब्द नहीं लगा सकती है ग्रीर वैकिंग व्यवसाय करने दाली सभी फर्मों के लिए इन शब्दों का उपयोग ग्रावश्यक है।

यह भी व्यवस्था की गई है कि बैंकिंग कम्पनी कुछ थोड़ी सी दशाओं को छोड़कर भीगा कम्पनियाँ स्थापित नहीं कर सकती है। इसी प्रकार एक बैंकिंग कम्पनी किसी अन्य कम्पनी में अपनी निर्गमित अश पूँजी के २०% अथवा अपनी परिदत्त पूँजी के ३०% से (जो भी कम हो) अधिक कीमत के अश प्राप्त नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त एक बैंकिंग कम्पनी ऐसी किसी भी कम्पनी के अश प्राप्त नहीं कर सकती है जिसमें उसके संचालक अथवा प्रवन्धक स्वार्थ रखते हो।

(३) प्रबन्ध— बैंकिंग कम्पनियों के लिए मैंनेजिंग एजेन्टों की नियुक्ति की भ्राज्ञा नहीं दी गई है। ऐसे व्यक्ति बैंकिंग कम्पनी का प्रबन्ध करने योग्य नहीं हैं जो भ्रन्य कम्पनियों के संचालक हैं, अन्य बैंकों का प्रबन्ध करते हैं अथवा कोई दूसरा व्यवसाय करते हैं। कोई भी बैंक ऐसे व्यक्तियों को नौकर नहीं रख सकती जो दिवालिया हो चुके हैं अथवा किसी फौजवारी के अपराध में जल काट चुके हैं। इसी प्रकार किसी भी कर्मचारी को कमीशन अथवा अंदा के आधार पर किसी प्रकार का पारितोषण नहीं दिया जा सकता है।

(४) परिदत्त पूँजी तथा निधि—यदि कोई भारतीय बैंकिंग कम्पनी भारत के राज्यों के बाहर स्थापित की जाती है तो उसकी परिदत्त पूँजी और मुरक्षित कोष मिलकर १५ लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए और यदि उसकी शाखा कलकत्ते अथवा बम्बई में भी है तो ऐसी पूँजी कम से कम २० लाख रुपया होनी चाहिए । यह राशि रिजर्व बैंक में जमा की जायगी। जिन कम्पनियों की स्थापना भारत में हुई है उनके लिए परिदत्त पूँजी और निधि की निम्न व्यवस्थाएँ की गई हैं।

(क) यदि इस कम्पनी की शाखार्थे कलकत्ते प्रथवा बम्बई में हैं तो पूंजी कम से कम १० लाख रुपया होनी चाहिए ।

(ख) यदि इसकी शाखायें एक से श्रिधिक राज्यों में हैं तो ५ लाख रुपा।

(ग) यदि इनकी बालायें एक ही राज्य में हैं तथा कलकत्ते और बम्बई में

नहीं हैं तो इसके प्रधान कार्यालय में १ लाख ग्रौर प्रत्येक शाखा में कम से कम १० हजार रुपये (यदि वे एक ही जिले में हैं) तथा २५ हजार रुपये (यदि वे ग्रलग-ग्रलग जिलों में हैं) होने चाहिये।

कम्पनी की निर्गमित पूँजी (Subscribed Capital) अधिकृ : पूँजी की कम से कम आधी होनी चाहिये और परिदत्त पूँजी इसी प्रकार निर्गमित पूँजी की कम से कम ५०% होनी चाहिए।

- (५) मतदान अधिकार—प्रत्येक ग्रंशघारी का मतदान अधिकार उसके द्वारा दी गई पूँजी के अनुपात में होगा, परन्तु किसी भी ग्रंशघारी को कुल मतदान अधिकार के ५% से अधिक मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- (६) नकद कोष व सुरक्षित कोष— बैंकिंग कम्पनी के लाभों का २०% उस समय तक सुरक्षित कोष मे जमा करना ग्रावश्यक है जब तक कि सुरक्षित कोष की राशि परिदत्त पूँजी के बराबर न हो जाय । साथ ही, प्रत्येक गैर-अनुसूचित बैंक को ग्रपनी समय देन का २% तथा गाँग देन का ५% रिजर्व बैंक में जमा करना होता है। अनुसूचित बैंकों के लिए इस प्रकार की जमा की व्यवस्था पहले से ही रिजर्व बैंक ग्राँफ इण्डिया एक्ट में कर दी गई थी। प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को ग्रपनी समय एवं गाँग देन का कम से कम २०% प्रत्येक दिन नकदी, स्वर्ग ग्रथवा स्वीकृति प्रति-भूतियों में रखना ग्रावश्यक है और भारतीय बैंकिंग कम्पनियों को उपरोक्त देनों की कीमत के कम से कम ७५% ग्रादेय भारत में रखने चाहिए।
- (७) रिजर्व बैंक के ग्रिधिकार—सभी बैंकिंग कम्पनियों पर रिजर्व बैंक को नियन्त्र एा तथा निरीक्षरण के विस्तृत ग्रिधिकार दिए गए हैं। एक्ट की कुल ५५ धाराएँ हैं, जिनमें से २७ केवल रिजर्व बैंक के ग्रिधिकारों के सम्बन्ध में हैं।
  - (i) रिजर्वं बैंक को यह ग्रधिकार दिया गया है कि संकट काल में वह बैंक के सब ग्रथवा कुछ, व्यवसायों को स्थगित करने की सिफारिश कर सकती है।
  - (ii) इसी प्रकार रिजर्व बैंक की अनुमित पर बैंकिंग कम्पनी ७ वर्ष से अधिक काल के लिए अचल सम्पत्ति रख सकती है।
  - (iii) रिजर्व बैंक प्रवन्धकों को अस्यिधक पारितोषण प्राप्त करने से रोक सकती है।
  - (iv) अस्थाई रूप में रिजर्व बैंक परिदत्त पूँजी तथा सुरक्षित कोषों सम्बन्धी व्यवस्था में छूट दे सकती है।
  - ( v ) गौरा कम्पनी की स्थापना के लिए भी रिजर्व बैंक की आजा लेनी आवश्यक होती है।
  - (vi) इस बात का निरीक्षण भी रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है कि अन्य बैंक एक्ट की व्यवस्थाओं का ठीक-ठीक पालन करती हैं या नहीं।

- (vii) साथ ही, यह भी रिजर्व बैंक का ही कर्त्तव्य है कि वह यह देख ले कि ऋ गों तथा अग्निमों के सम्बन्ध में बैंक कोई समुचित नीति अपनाती हैं या नहीं।
- (viii) रिजर्व बेंक की ग्राज्ञा के बिना कोई भी अम्पनी नई शाखा नहीं खोल सकती है।
  - (ix) इसी प्रकार रिजर्व बैंक को सभी बैंकिंग कम्पनियों के निरीक्षण और श्रावश्यकता पड़ते पर उनके बन्द करने की सिफारिश करने का भी श्रिवकार दिया गया है।
  - (x) रिजर्व बैंक उन्हें कुछ प्रकार के व्यवसायों को करने से भी रोक सकती है ग्रौर यदि उचित समभे तो प्रबन्ध में किए जाने वाले परिवर्तनों को भी रोक सकती है।
  - (xi) बैंकों को एकीकरएा के लिए भी आज्ञा का लेना आवश्यक होता है।
- (xii) म्रनेक प्रकार के विवरणों तथा रिपोर्टों को रिजर्व बैक को मेजा जाता है ग्रीर उसकी ग्राज्ञा के बिना एक बैंक तथा उसके ऋणदाताम्रों के बीच किसी प्रकार का समभौता नहीं हो सकता है।
- ( xiii ) रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार किसी बैंक को सवा के लिए अथवा कुछ समय के लिए एक्ट की कुछ अथवा समस्त व्यव-स्थाओं से मुक्त भी कर सकती है।
- ( ८ ) निस्तारएा—ऐसी व्यवस्था की गई है कि बेंक के निस्तारएा का कार्य की झितापूर्वक किया जा सके। बेंक के निस्तारएा का अधिकार केवल उच्च न्यायालयों की ही दिया गया है, जिन्हें इस विषय में कुछ प्रकार के विशेष अधिकार दे दिये गये हैं।
- (६) ग्रन्य व्यवस्थायें—ग्रंकेक्षरा, खातों, विवररा-पत्रों के प्रकाशन तथा कम्पनी के बन्द करने के सम्बन्ध में सिवस्तार नियम बनाये गए हैं ग्रौर नियमों का उलङ्घन करने वाली बेंकिंग कम्पनियों के लिए दण्ड रखा गया हैं।

#### म्रालोचनाएँ—

इस एवट की व्यवस्थाग्रों की दो प्रकार की ग्रालीचनाएँ की गई हैं। जो लोग व्यापार बेंकों के राष्ट्रीयकरण को उचित समभते हैं उनके विचार में यह एक्ट पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत जो लोग ऐसा समभते हैं कि बैंकिंग व्यवसाय में स्वतन्त्रता रहनी चाहिए उनके विचार में यह वहुत से ग्रानावश्यक प्रतिबन्ध लगाता है ग्रौर देश में बैंकिंग विकास के मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न करता है। सरकार के सामने इन दोनों विचारों के बीच समायोजन करने की समस्या थी। एक्ट की बहुत सी व्यवस्थाएँ कड़ी श्रवस्य हैं, प्रस्तु वे बैंकिंग व्यवस्था को काफी सुरक्षा प्रदान करती हैं। एक्ट की व्यवस्था में का ग्रासन, रिजर्व बैंक को सौंपा गया है। इसी कारण उसी की कुशलता तथा

ईमानदारी पर उनके कार्यरोपएग के परिएगाम निर्भर रहेंगे। स्मरएग रहे कि रिजर्व बैंक की स्थापना को २४ वर्ष हो चुके हैं और अब उससे बहुत आ़शा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त एक्ट में दो भारी त्रुटियां और भी हैं:—(१) इसमें देशी बैंकरों के सम्बन्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है और (२) ऐसा नियम बनाकर कि एक्ट के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सरकार के द्वारा की जाने वाली अनुचित बातों के लिए भी बैंक कुछ न कर सकेंगी, बैंकों के साथ अन्याय किया गया है। बैंकिंग विधान में किए गए संशोधन—

सन् १६४६ के नियम में दो संशोधन किए गए हैं। सन् १६५० में प्रबन्ध के सम्बन्ध में एक्ट की व्यवस्थाओं की कुछ किमयों को दूर किया गया है और सन् १६५३ का एक्ट बैंक के निस्तारण से सम्बन्धित है और निस्तारण प्रविक सरल, वैज्ञानिक तथा उचित बनाने का प्रयत्न करता है।

सन् १६५१ में रिजर्व बैंक के विधान में कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए कि वह बैंकिंग कम्पनियों की कार्य-प्रगाली पर अधिक नियन्त्रगा रख सके और उन्हें उपर्युक्त सहागता दे सके। इन परिवर्तनों के अनुसार प्रत्येक बैंक को रिजर्व बैंक के पास भेजे हुए विवरण में यह दिखाना होता है कि उसकी कितनी पूँजी सरकारी प्रतिभूतियों में लगी हुई है, अन्य बैंकों में कितनी पूँजी जमा है और तत्कालीन देयघन (Money at short notice) कितना है। विवरण के रूप में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं और बैंक की शाखाएँ विदेशों में भी हैं तो उसे अपनी विदेशी शाखाओं का भी विवरण भेजना पड़ता है।

#### सन् १६५१ का संशोधन-

सन् १९५१ के संशोधन द्वारा रिजर्व बेंक को कुछ ग्रौर भी ग्रधिकार दिए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं:—

- (१) रिजर्व बैंक किसी बैंक को किसी समय विशेष में यह छूट दे सकती है कि वह रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम् वैधानिक शेष (Minimum Statutory Balance) न रखे।
- (२) रिजर्व बैंक किसी भी बैंक को यह छूट दे सकती है कि वह किसी विशेष समय से सम्बन्धित लेखे उसके पास न भेजे।
- (३) रिजर्व बैंक को यह ग्रधिकार दिया गया है कि वह राज्य सहकारी बैंकों से विवरगा तथा लेखा पुस्तकों निरीक्षगा के लिए मांग सके।
- (४) रिजर्व बैंक को विदेशी सरकारों और सरकारी आज्ञा पर व्यक्तियों के भी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अधिकार दे दिया गया है।
- (५) रिजर्व बैंक को समभौतों द्वारा राज्य सरकारों और व्यक्तिगत पक्षों के मौद्रिक ऋगा सम्बन्धी प्रबन्ध का भार स्वीकार करने का भी ग्रधिकार मिल गया है।

सन् १६५० का संशोधन-

इससे पूर्व सन् १६५० में बैंकिंग विधान में निम्न चार संशोधन पहले ही किये जा चुके थे:—

- (क) प्रत्येक बैंक के लिए देश श्रथवा विदेश में शाखा खोलने के लिए रिजर्व बैंक की श्रनुमति श्रावश्यक है।
- (ख) एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के नियम बनाये गये।
- (ग) विलीन होने वाली बैंकिंग कम्पनियों की समस्त लेनदारी पूर्ण रूप में नई कम्पनियों को हस्तान्तरित हो जाती है।
- (घ) बैंक श्रौर उसके ऋग्।-दाता के बीच होने वाला ऐसा कोई भी समभौता श्रवैधानिक न होगा जो रिजर्व बैंक को मान्य न हो।

#### निस्तारग व्यवस्था—

सन् १६५० के संशोधक नियम द्वारा बैंकों के निस्तारण (Liquidation) का जो क्रम निश्चित किया गया था वह काफी जिटल था और नियम के पास होते ही उसकी किमयों का अनुभव होने लगा था। सन् १९५२ की एक सिमिति ने बताया था कि ३२१ बैंकों के निस्तारण का कार्य सन् १९२६ से चल रहा था और अभी समाप्त नहीं हुआ था, अतः दिसम्बर सन् १९५३ में बैंकिंग कम्पनीज निस्तारण नियम पास किया गया। इस एक्ट में निस्तारण के ब्यय को कम किया गया है, छोटे निक्षेप-दाताओं को अधिक सुविधा दी गई है और निस्तारण की कार्य-विधि को अधिक सरल बनाया गया है।

निस्तारण सम्बन्धी नियम की प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं :--

- (१) बचत और चालू खातों के ऐसे निक्षेपदाताओं को जिनकी जमा छोटी है, एक निश्चित राशि तक के भुगतान में प्राथमिकता दी जायगी।
- (२) निस्तारक (Liquidator) को बैंक के बन्द हो जाने के ६ महीने के भीतर ही ऐसे ऋगी ग्राहकों की सूचना न्यायालय को देनी होगी, जिनके मामलों का निबटारा न्यायालय को करना होगा।
- (३) न्यायालय को अधिकार होगा कि वह निस्तारक की डिग्री की राशि वसूल करने के लिए लगान वसूली की विधियों के उपयोग के आदेश देसके।
- (४) यदि उचित समक्ते तो न्यायालय बैंक के संचालकों की भी जाँच कर सकता है और अयोग्य सिद्ध होने पर संचालक को ५ वर्ष तक के लिए बैंक का संचालक बनने से बंचित कर सकता है।
- (५) न्यायालय ग्रौर सरकार दिवालिया बैंक का रिजर्व बैंक से निरीक्षण करा सकते हैं।
- (६) बैंकों के निस्तारण के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में भ्रदालती निस्ता-रण नियुक्त किया जा सकता है।

बंकिंग कम्पनीज (संशोधन) ग्रिधिनियम, सन् १६५२-

इस नियम को दिसम्बर सन् १९५३ में वैक्तिंग ग्रिधिनियम में सिम्मिलित कर दिया गया है। इस ग्रिधिनियम ने मुख्यतया वैंकों के निस्तारण की व्यवस्था की है। प्रमुख व्यवस्थायों निम्न प्रकार हैं:—

- (१) उच्च न्यायालय का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, जिससे कि उसी क्षेत्र का उच्च न्यायालय निस्तारए। का कार्य कर सके, जिसमें कि बेंक स्थित है।
- (२) उच्च न्यायालय (High Court) को वैंकिंग कम्मनी के संवालकों के विरुद्ध दावों के लिए समय अविध निश्चित कर सकता है।
- (३) संचालकों की देनदारी को शीघ्र निपटाने के लिए वैंकिंग कम्मियों के व्यवहारों की ग्रनिवार्य सार्वजनिक जाँच की जायगी।
- (४) उच्च न्यायालय को स्रिषकार दिया गया है कि यदि निस्तारक (Liquidator) बाह्य प्रमाण द्वारा सिद्ध कर देता है तो न्यायालय बेंकिंग कम्मनी के प्रवर्तक (Promoter), स्रिषकारी, संचालक स्रथवा व्यवस्थापक से बेंक की राभि प्रथवा सम्पत्ति का भुगतान प्राप्त कर सके।
- (५) केन्द्रीय सरकार को बैंकों के श्रदालती निस्तारक नियुक्त करने का श्रिष्ठिकार दिया गया है।
- (६) ऐसी व्यवस्थायें की गई हैं कि वैकिंग कम्पनियों के ऋिए।यों के विरुद्ध ग्रादेश ग्रथवा कुर्की की कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक की जा सके।
- (७) उच्च न्यायालय अथवा सरकार के आदेश पर रिजर्व बैंक को निस्तारक बैंक के परीक्षरण और उससे विवरण तथा सूचनायें माँगने का अधिकार दिया गया है।
- ( प्र) नियमानुसार कम्पनी के ऐसे जमाधारियों को भुगतान में प्राथमिकता दी गई है जिनकी बचत स्रौर चालू खातों में कम राशि जमा है।
- ( ६ ) निस्तारित बैंक के लिए यह ग्रनिवार्य किया गया है कि काम को बन्द करने के ६ मास के भीतर निस्तारक को ऐसे ऋिए।यों की सूची प्रदान करे जिनका कि उच्च न्यायालय को भुगतान करना है।

बैंकिंग कम्पनीज ( संशोधन ) श्रिधनियम, सन् १६५६-

रिजर्व बैंक सम्बन्धी नियम के परिवर्तन के पश्चात् बैंकिंग कम्पनीज एक्ट में भी कुछ प्रकार के संशोधन स्रावश्यक हो गये थे। दिसम्बर सन् १९५६ में इसी स्राशय से उपरोक्त नियम पास किया गया। यह नियम १४ जनवरी सन् १९५७ से लागू किया गया है। इस नियम की व्यवस्थायें निम्न प्रकार हैं:—

- (१) रिजर्व बैंक को जन-साधारण तथा बैंकिंग कम्पिनयों के हितों की रक्षा के लिए बैंकों तथा बैंकिंग कम्पिनयों को म्रादेश देने का म्रविकार दिया गया है।
  - (२) बैंकों के लिए यह ग्रनिवार्य किया गया है कि वे ग्रपने प्रमुख ग्रधिका-

रियों श्रौर प्रबन्ध-संचालकों की नियुक्ति श्रौर नियुक्ति की शर्तों के विषय में रिजवं बैंक से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करें।

(३) किसी भी बैंक के संचालक मण्डल ग्रथवा ग्रन्य समिति ग्रथवा ग्रन्य संगठित सभा की कार्य-पद्धित की जाँच के लिए रिजर्व बैंक ग्रपने ग्रधिकारियों को भेज सकती है ग्रथवा ऐसी जाँच ग्रौर बैंक की स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए ग्रपने निरीक्षक (Observers) नियुक्त कर सकती है ।

भारतीय बैंकिंग विधान में त्रुटियाँ (Defects in the Indian Banking Legislation)—

सन् १६४६ से भारतीय बैंकिंग विधान को समुचित श्राधार प्रदान करने का फ्रम निरन्तर चल रहा है। समय-समय पर जो दोष दृष्टिगोचर हुए हैं उनको दूर करने का भी प्रयत्न किया गया है। संचालकों की स्वार्थी कार्यवाहियों को रोकने, व्यवसाय का विस्तार करने तथा शाखाओं के खोलने के सम्बन्ध में श्रव बैंकों पर रिजर्व बैंक का श्रधिक सप्रभाविक नियन्त्रण रहता है। एकीकरण तथा निस्तारण की क्रियाओं को भी श्रव श्रधिक सरल तथा श्रधिक शोझगामी बना दिया गया है। रिजर्व बैंक श्रव श्रधिक सतक रहती है श्रीर उसका निरीक्षण भी श्रव श्रधिक विस्तृत तथा श्रधिक सूक्ष्म रहता है। परन्तु बैंकिंग विधान श्रभी तक भी भारतीय बैंकिंग के कुछ महत्त्वपूर्ण दोषों को दूर नहीं कर पाया है। किचित यह सत्य ही है कि श्रच्छी बैंकिंग व्यवस्था श्रच्छे नियमों पर निर्भर नहीं रहती है, बल्कि श्रच्छे बैंकिरों पर निर्भर होती है। देश में कुशल प्रवन्धकों श्रीर कर्मचारियों की श्रभी तक भी श्रधिक कमी है। बैंकिंग विधान की प्रमुख किमियाँ निम्न प्रकार हैं:—

- (१) देशी बैंकरों पर नियन्त्रण का ग्रभाव—नये बैंकिंग विधान में देश की बैंकिंग प्रणाली का एक बहुत बड़ा भाग ग्रर्थात् देशी बैंकर ग्रछ्ता ही रह गया है। देशी बैंकरों का देश के ग्रान्तरिक व्यापार ग्रीर ग्रामीण साख में इतना ग्रधिक महत्त्व है कि उनकी कार्यवाहियों का समस्त बैंकिंग कलेवर पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता है। मुद्रा-बाजार के इस महत्त्वपूर्ण ग्रंग के नियन्त्रण के बिना मुद्रा-बाजार के संगठन की ग्राशा निर्मुल ही रहेगी।
- (२) सहकारी बैंकिंग पर नियन्त्रग् का स्रभाव—देश में सहकारी साख और उसके विकास के महत्त्व को तो सभी स्वीकार करते हैं और विगत वर्षों में उसके शीघ्रतापूर्वंक विकास का भी प्रयत्न किया गया है। परन्तु यह द्यावश्यक है कि सहकारी बैंकिंग का विकास समचययुक्त हो। वर्तमान दशास्रों में उसका विकास प्रतियोगी रूप में भी हो रहा है। न्याय और कुशलता दोनों ही के दृष्टिकोग्गों से सहकारी बैंकिंग का भी नियन्त्रित विकास होना चाहिये, किन्तु बैंकिंग विधान सहकारी बैंकिंग पर लागू महीं होता है।
  - (३) विज्ञियोगों की तरलता का श्रभाव—बैंकिंग विधान इस दिशा में मी श्रसफल रहा है कि उसके द्वारा बैंकों के श्रादेयों में तरलता नहीं श्रा पाई है। ऐसा

ग्रावश्यक प्रतीत होता है कि विधान में ऐसी व्यवस्था की जाय कि भारतीय वैक केवल विशेष प्रकार की ही सम्पत्ति रख सकें। ग्रादेशों की तरलता प्राप्त करने के हेनु बैंकिंग विधान द्वारा बैंकों पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं हैं।

(४) केन्द्रीयकरण को रोकने में ग्रसफलता:—भारतीय वैकिंग विधान देश में वैंकिंग सेवाग्रों के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को रोकने में भी ग्रसफल ही रहा है। रिजर्व वैंक की सन् १६५० की रिपोर्ट से भी यही सिद्ध होता है कि यह प्रवृत्ति घटने के स्थान पर उन्हीं दढ़ ही रही है। ग्रामीण क्षेत्रों ग्रीर छोटे नगरों में वैंकिंग सेवाग्रों का ग्रभाव बरावर है ग्रीर वैंकिंग सेवाएँ कुछ क्षेत्रों में केन्द्रित होती जा रही हैं। वैंकिंग विधान का महत्त्व—

बेंकिंग विधान का उद्देश्य बेंकिंग विकास की दोषपूर्ण प्रवृत्तियों को रोकना ग्रीर बेंक की अनुचित तथा जन-हित विरोधी कार्यवाहियों को बन्द करना होता है। बेंकिंग विधान की सफलता भी उसकी इन महत्त्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने की क्षमता पर निभर होती है। भारतीय बेंकिंग विधान का भी उद्देश्य यही रहा है। वास्तव में व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम् करने के लिए बेंक बहुधा सतर्कता ग्रौर सुरक्षा के मार्ग को छोड़ देती हैं तथा जन-हित की अवहेलना करने लगती हैं। इस घातक प्रवृत्ति को समुचित विधान द्वारा रोका जा सकता है। भारत में वर्तमान बेंकिंग विधान काफी सोच-समक्त कर बनाया गया है। सरकार की नीति यह भी रही है कि आवश्यकता पड़ने पर विधान में उपयुक्त दिशाओं में आवश्यक संशोधन भी किए जायें। एक नवीन संशोधन द्वारा बेंकों की रिजर्थ बेंक जमा सम्बन्धी प्रतिशत को भी घटाया गया है, ताकि दूसरी पंच-वर्षीय योजजा के वित्तीय साधन सुलभ हो जायें। हमारे बेंकिंग विधान के दोदोष अवश्य हैं। प्रथम, यह भय है कि वैधानिक जिल्लता प्रगति में बाधक हो सकती है। दूसरे, रिजर्व बेंक के अधिकार इतने बढ़ गए हैं कि उनका दुश्पयोग सम्भव है। विशेषकर, राजनीतिक आधार पर।

#### **QUESTIONS**

- 1. Discuss the main defects of the Indian Banking Organisation. How far has the recent banking legislation in India removed them? Explain. (Raj., B. Com., 1955)
- 2. Indian Banking Act has been welcomed by some, while some have criticised it. In the light of this statement, examine some of the provisions of the Act. (Agra, B. Com., 1950)

3. Enumerate the main provisions of the Indian Banking Companie's Act with regard to the employment of banker's funds.

(Raj., B. Com., 1950)

4. Critically examine the essential features of the Indian Banking Companie's Act.

( Raj., B. Com.; 1956; Bombay, B. Com., 1950)

# <sup>ऋघ्याय ४६</sup> राष्ट्रीय आय

(The National Income)

#### प्रायकथन--

यह तो विदित ही है कि मनुष्य की सारी क्रियाओं का उद्देश्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना ही होता है । उत्पत्ति करने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पत्ति के साधन मिल कर काम करें। उत्पत्ति सदा ही विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयत्न का परिग्णाम होती है, इसलिए कुल उत्पत्ति में से उत्पत्ति के साधनों को हिस्सा मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति की आर्थिक सम्पन्नता और उसका आर्थिक कल्याण इस बात पर निर्भर होते हैं कि उसे अपने प्रयत्न के बदले में उत्पत्ति में से कितना हिस्सा मिलता है। इसी प्रकार किसी राष्ट्र के भौतिक कल्याण का स्तर भी इस बात पर निर्भर होता है कि उसे, उसके सदस्यों के उपभोग के लिए कितनी वस्तुएँ और सेवायें प्राप्त होती हैं। किसी देश का धन, जिसे आर्थिक भाषा में राष्ट्रीय लाभांश कहा जाता है, देश के निवासियों के अधिकार में रहने वाली वस्तुओं और सेवाओं के संचय पर निर्भर होता है।

# राष्ट्रीय लाभांश की कुछ परिभाषाएँ —

(१) प्रोफेसर का पीगू का विचार—पीगू का विचार है,—''राष्ट्रीय े लागाँश किसी समाज की भौतिक श्राय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त श्राय भी सम्मिलित होती है, जिसकी कि मुद्रा में माप हो सकती है।'' इसरे शब्दों में,

<sup>\* &#</sup>x27;National Dividend is that part of the objective income of the community, inculding of course income derived from abroad, which can be measured in money."—A. C. Pigou: Economics on Welfare.

देश में उत्पन्न की गई कुल ग्राय का केवल वही भाग राष्ट्रीय लाभाँश को सूचित करता है जिसका उपभोग तथा विनियोग हो सकता है। इसी ग्राधार पर किसी देश की राष्ट्रीय ग्राय से हमारा ग्राभिप्राय ग्राय की उस घारा से होता है जो देश के सभी निवासियों के वस्तुग्रों ग्रीर सेवाग्रों के संचय से प्राप्त होती है। यह विषय विवादग्रस्त है कि राष्ट्रीय ग्राय में किन किन चीजों को शामिल किया जाय ग्रीर किन-किन को शामिल न किया जाय :

- (२) प्रोफेसर मार्शल का विचार—मार्शल ने देश के समस्त उत्पादन से प्राप्त होने वाली श्राय को, चाहे वह उत्पादन भौतिक वस्तुओं के रूप में हो ग्रथवा ग्रभौतिक वस्तुओं के रूप में, राष्ट्रीय श्राय में शामिल किया है। पीग्न ने उन सेवाओं ग्रीर वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय लाभाँश में नहीं जोड़ा है जिनकी कीमत की मौद्रिक माप नहीं होती है, उदाहरणस्वरूप, माता, मित्र श्रथवा पत्नी की निःशुल्क सेवायें। कुछ श्रथंशास्त्री सरकारी श्रधिकारियों की सेवाओं को राष्ट्रीय श्राय में सम्मिलित नहीं करते हैं श्रीर कुछ दूसरे श्रथंशास्त्री ऐसी कुल श्राय को राष्ट्रीय श्राय में से निकाल देने के पक्ष में हैं जिसके बदले में कोई सेवा प्रस्तुत नहीं की गई है, जैसे—दान श्रथवा उपहार से प्राप्त श्राय, वृद्धावस्था उत्तर-वेतन श्रादि।
- (३) प्रो० फिशर का विचार—(१) फिशर का विचार है "राष्ट्रीय लाभाँश ग्रथवा ग्राय में केवल सेवायें जैसी कि वे उपभोक्ताओं को प्राप्त होती हैं, शामिल की जाती हैं, चाहे वे सेवायें भौतिक परिस्थितियों से उत्पन्न हुई हैं ग्रथवा मानवीय कारगों से ।" (२) वर्तमान ग्रथंशास्त्र में राष्ट्रीय ग्राय को मुद्रा में नापने का ही ग्रधिक प्रचलन है।

इसी हिष्टिकोग्। पर प्रो० कॉलिन क्लार्क ने राष्ट्रीय भ्राय की निम्न परिभाषा की है—

(४) प्रो० कॉलिन क्लार्क का विचार—"किसी समय विशेष में राष्ट्रीय ग्राय उन वस्तुग्रों ग्रौर सेवाग्रों के मौद्रिक मूल्य द्वारा सूचित की जाती है जो समय विशेष में उपभोग के लिए उपलब्ध होती हैं, ऐसा मूल्य उसकी वर्तमान बिक्री कीमत पर निकाला जाता है। इसमें पूँजी की उस वृद्धि को जोड़ा जाता है जिसका मूल्य नये पूँजीगत माल की कीमत के रूप में चुकाया जा चुका है। इसमें से प्रस्तुत पूँजीगत माल के ग्रवक्षयरा (Depreciation) ग्रौर पुराने पड़ने (Obsolescence) के व्यय को निकाल दिया जाता है तथा इस प्रकार की जोड़ ग्रौर घटा।

<sup>\* &</sup>quot;National dividend or income consists solely of services as received by ultimate consumers, whether from their material or from their human environment."—Fisher: The Nature of Capital and Income, p. 104.

की कीमत भी चालू कीमतों के आधार पर आंकी जाती है।" प्रो० क्लार्क का विचार है कि ऐसी सेवाओं की कीमत जो राज्य द्वारा बिना लाभ के आधार पर प्रस्तुत की जाती हैं, जैसे— डाक-तार सम्बन्धी सेवाएँ आदि, वास्तविक भाड़ों की दर पर निकाली जाती हैं। जब कुछ वस्तुओं पर कर लगाए जाते हैं तो उन वस्तुओं की कीमत निकालते समय इन करों की आय की मात्रा को बिक्री मूल्य में शामिल नहीं किया जाता है।

(५) डा० राव के विचार—डा० राव ने भी इसी से मिलता-जुलता हिन्हकोण अपनाया है। उनका विचार है कि राष्ट्रीय श्राय वस्तुओं श्रीर गेवाश्रों की घारा के मौद्रिक मूल्य द्वारा सूचित होती है। डा० राव का विचार है कि सभी कीमतें चालू कीमतों के श्राधार पर श्रांकी जाती हैं और उन श्रायातों की कीमत शामिल नहीं की जाती हैं जो बिक्री के लिए प्राप्त हैं श्रथवा जो वेचे जा सकते हैं। इस प्रकार वस्तुओं श्रीर सेवाश्रों का मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है उसमें से निम्न मदों को निकाल दिया जाता है:— (१) समय विशेष में पूँजीगत माल के श्रवक्षयण व्यय का मौद्रिक मूल्य, (२) ऐसी वस्तुओं श्रीर सेवाश्रों का मौद्रिक मूल्य जो उत्पादन कार्य में व्यय की गई हैं, (३) ऐसी वस्तुओं श्रीर सेवाश्रों का मौद्रिक मूल्य जो वर्तमान पूँजी स्टॉक को बनाये रखने के लिए उपयोग की गई हैं, (४) राज्य को परोक्ष करों से प्राप्त होने वर्ती श्राय, (५) व्यापाराशेष की श्रनुकूलता की मौद्रिक कीमत श्रीर (६) देश के विदेशी ऋण की शुद्ध वृद्ध। व

राष्ट्रीय ग्राय को नापने की रीतियाँ--

राष्ट्रीय श्राय की माप निम्न चार रीतियों से की जाती है:-

(१) उत्पत्ति गर्गाना प्रगाली (Census of Production Method)—इस प्रगाली का उपयोग सन् १६०७ की ब्रिटिश उत्पत्ति गर्गाना में किया गया था। किसी एक उद्योग ग्रथवा फर्म की सकल उपज (Gross Produce) की कीमत में से यदि हम कच्चे माल तथा दूसरे ऐसे पदार्थों की कुल कीमत तथा वह रकम जो दूसरी फर्मों को काम करने के लिए दी जाती है, निकाल दें तो उद्योग ग्रथवा फर्म की शुद्ध उपज (Net Product) निकल ग्राती है। सारी फर्मों ग्रथवा सारे उद्योगों की शुद्ध उपज का योग हमें राष्ट्रीय शुद्ध उपज वतायेगा। यह शुद्ध उपज

<sup>1.</sup> The national income for any period consists of the money value of goods and services becoming available for consumption during that period, reckoned at their current selling value, puls additions to capital reckoned at the prices actually paid for the new capital goods, minus depreciation and obsolescence of existing capital goods and adding the net accretion of, or deducting the net drawings upon stocks, also reckoned at current prices."—Colin Clark: the National Income, pp. 1-2.

<sup>2.</sup> See Dr V. K. R. V. Rao: National Income of British India.

हमें निर्माण (Manufacture) द्वारा वस्तुओं और पदार्थों में उत्पन्न किये गये मूल्य को बतायेगी। एक उद्योग की शुद्ध उपज उस कोष को सूचित करेगी जिसमें से वेतन, लगान, ब्याज, कर, अवक्षयण, लाभ तथा धन्य प्रकार के खर्चे चुकाये जायेगे। राष्ट्रीय श्वाय को निकालते समय कुल राष्ट्रीय शुद्ध उपज में से वार्षिक अवध्ययण तथा मकीनों की मरम्मत और उनके बदलने का ब्यय निकाल देना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरे साधनों की क्षयता (Exhaustion) का खर्च भी घटा देना पड़ेगा। खनिज उद्योग में यह खर्च अधिकार-शुल्क (Royalties) द्वारा सूचित होता है। उदाहरणस्वरूप, यदि एक मशीन १० साल तक काम दे सकती है तो वार्षिक राष्ट्रीय आद निकालते समय उसकी शुद्ध उपज की कीमत में से मशीन की कीमत का कुट निकाल देना चाहिये।

- (२) ग्राय गर्गाना प्रगाली (Census of Incomes Mcthcd)— इस रीति के अनुसार देशवासियों की ग्राय का योग निकाला जाता है। उन सभी ब्यक्तियों की जो ग्राय-कर देते हैं ग्रीर जो ग्राय-कर नहीं देते हैं, ग्रायों का योग कुन राष्ट्रीय ग्राय को सूचित करता है। यह कार्य देश में सभी परिवारों की ग्राय की ग्रलग-ग्रलग गर्गाना करके किया जा सकता है। केवल इसी बात का घ्यान में रखना ग्रावश्यक होता है कि एक ग्राय को दो बार न गिना जाय। उदाहररास्वरूप, यदि एक वकील की ग्राय साल में कुल ६,००० रुपये की है, जिसमें से वह १,२०० रुपया प्रति वर्ष ग्रपने मुन्शी को दे देता है तो मुन्शी की ग्राय को राष्ट्रीय ग्राय में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वकील की ग्राय को जोड़ते समय यह पहले ही गिनी जा चुकी है।
- (३) व्यवसायिक गर्गाना प्रगाली (Occupational' Census Method)—इस प्रगाली में लोगों की ग्राय की उनके व्यवसायों के ग्रनुसार गर्गाना की जाती है। विभिन्न प्रकार के उत्पादक कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों की ग्रायों को ग्रांका जाता है ग्रीर इन सबका जोड़ राष्ट्रीय ग्राय को दिखाता है। इसमें भी यही सावधानी ग्रावश्यक होती है कि एक ही ग्राय को एक से ग्रधिक बार न गिना जाय। स्टाम्प का विचार है कि इस प्रकार की गर्गाना में वृद्धावस्था उत्तर-वेतन (Old age pensions) ग्रौर युद्ध के विशेष भत्ते शामिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि वे व्यवसायिक ग्राय नहीं होते हैं।
- (४) उत्पादन गराना श्रौर श्राय गराना प्रगालो का सामूहिक उपयोग—इस प्रणाली में श्राय गराना श्रौर उत्पादन गराना दोनों ही कामों को एक ही साथ किया जाता है। डा॰ राव ने भारत में इसका उपयोग वड़ी सफलनापूर्वक किया है। उन्होंने कृषि उपज के सम्बन्ध में सरकारी श्रौकड़ों का उपयोग किया है श्रौर देश में खनिज, उद्योग, दूध तथा दूसरी वस्तुश्रों के उत्पादन का श्रृनुम न लगाया है श्रौर साथ ही साथ श्राय-कर सम्बन्धी श्रौकड़ों, सरकारी कैर्मचारिशों के वेतनों, श्रौद्योगिक श्रमिकों की मजदूरियों श्रौर श्रन्य प्रकार की श्रायों का भी पता लगाया है।

सबसे उत्तम रीति कौनसी है ?—

यह विषय विवाद-ग्रस्त है कि राष्ट्रीय ग्राय को नापने की कौनसी रीति ग्रिषिक उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है कि उत्पत्ति गर्णना प्रणाली ग्रीर व्यवसायिक गर्णना प्रणाली ग्रीर व्यवसायिक गर्णना प्रणाली ग्रीर व्यवसायिक गर्णना प्रणाली ग्रीषक व्यवहारिक हैं, क्योंकि ग्राय गर्णना प्रणाली में एक ही ग्राय को एक से ग्रीषक बार गिनने की सम्भावना बराबर रहती है, जिसको दूर नहीं किया जा सकता है। इंगलैंड का ग्रनुभव यह है कि प्रथम तीनों रीतियों में से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है। यदि सावधानी से काम लिया जाता है तो प्रत्येक से एक से ही फल प्राप्त होते हैं, किन्तु सबसे ग्राधिक रिवाज उत्पत्ति गर्णना प्रणाली का है।

राष्ट्रीय ग्राय की गराना का महत्त्व-

राष्ट्रीय श्राय श्रीर झाथिक कल्याए। के बीच बड़ा घिनिष्ट सम्बन्ध है। साधा-रणतया हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि श्रन्य वातें यथास्थिर रहें तो जितनी ही राष्ट्रीय श्राय अधिक होगी उतना ही देश के आर्थिक कल्याए। का स्तर भी ऊँचा होगा, यद्यपि प्रत्येक दशा में राष्ट्रीय श्राय श्रीर आर्थिक कल्याए। में एक ही दिशा में तथा एक ही अनुपात में वृद्धि होना श्रावश्यक नहीं है। राष्ट्रीय श्राय के श्रष्ट्ययन के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं:—

- (१) राष्ट्रीय स्राय से सम्बन्धित आँकड़े हमें देश के भीतर जीवन स्तर के बारे में महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। इनकी सहायता से यह पता चल जाता है कि देश की स्थ-व्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में कालान्तर में क्या परिवर्तन हुए हैं स्रौर सामान्य आर्थिक परिस्थितियों का रख किस दिशा में तथा किस स्रंश तक बदल गया है।
- (२) राष्ट्रीय ग्राय सम्बन्धी ग्राँकड़ों को देखकर हम यह भी जान सकते हैं कि क्या देश का विकास समुचित ग्राधार पर हो रहा है ? यद्यपि राष्ट्रीय ग्राय भौतिक कल्याएा की पूर्णतया निश्चित माप तो नहीं होती है, परन्तु इसके द्वारा उसकी सामान्य प्रवृत्ति का पता ग्रवश्य लगाया जा सकता है।
- (३) राष्ट्रीय श्राय देश की श्रथं व्यवस्था के दोषों को स्पष्ट कर देती है शौर उनके दूर करने के उपाय दर्शाती है। राष्ट्रीय श्राय के श्राँकड़े हमें यह बता दते हैं कि वितरण के रूप में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। ये हमारे लिए देश की श्रार्थिक, वािणाज्यिक, प्रशुल्क तथा श्रौद्योगिक नीति के निर्माण में सहायक होते हैं। भारत में राष्ट्रीय श्राय का श्रनुमान—

भूतकाल में भारत की राष्ट्रीय श्राय के श्रनेक श्रनुमान लगाने गये हैं। सर्वप्रथम श्री दादा भाई नौरोजी ने सन् १८६७-७० के काल के लिए राष्ट्रीय श्राय का श्रनुमान २० रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगाया था। तत्पश्चात् सन् १६४२-४३ तक १८-२० श्रीर भी श्रनुमान लगाए गए, परन्तु सभी श्रनुमान गैर-सरकारी थे श्रीर इनमें श्रापस

में भारी अन्तर थे। लार्ड कर्जन का अनुमान सन् १६०० में ३० रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था। सन् १६२१ में फिडले शिराज (Findlay Shirras) का अनुमान १०७ रुपया प्रति वर्ष था। इसी प्रकार सन् १६३१-३२ में डा० राव ने ६५ रुपया और सन् १६३७-३५ में सर जेम्स गिग्र (Sir James Grigg) ने ५६ रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का अनुमान लगाया था। सन् १६४२-४३ का कॉमसं (Commerce) पित्रका का अनुमान १२४ रुपया था। इन सभी अनुमानों में आपस में भारी अन्तर हैं और यह जानने के लिए कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है, हमें सामान्य कीमतों की वृद्धि को घ्यान में रखना पड़ेगा। डा० राव का अनुमान अधिक विश्वसनीय माना जाता है। उन्होंने ग्रामीरा क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय ५१ रुपया और नागरिक क्षेत्रों की १६६ रुपया ग्राँकी थी और इस आधार पर ग्रीसत प्रति व्यक्ति आय ६५ रुपया निकलती है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार ने राष्ट्रीय आय की गराना का अधिक संगठित श्रीर वैज्ञानिक उपाय किया है। वाग्गिज्य मन्त्रालय ने राष्ट्रीय अ.य का निक्ष्त अनुमान लगाया था:—

(करोड़ रुपयों में )

top companied SSF of the large year of a Line Advance and the Cyph Plan in the Advance grammer state, and advance makes	ब्रिटिश भारत	भारत संघ	प्रान्त (राज्य)
शीर्षंक	१९४५-४६		१६४६-४७
(१) प्रारम्भिक उत्पादन—			
े (क) कृषि स्रौर पशु-पालन उद्योगा	5 10 di	0 053	• 2 C C •
की शुद्ध उपज	२,७४५	१,६६३	२,२६१
(ख) जंगलों की शुद्ध उपज	१२	3	४६
(ग) खनिज उद्योगों की शुद्ध उपज	३८	३७	<b>- </b>
कुल शुद्ध ग्रारम्भिक उत्पादन	२,७६५	300,5	२,३६ म
(२) गैर-म्रारम्भिक उत्पादन— (क) ग्राय-कर चुकाई हुई म्राय । (ख) म्राय, जिस पर कर नहीं दिया	४७६	४३४	५६६
गया है	२,८६०	२,३८७	२,६१६
कुल राष्ट्रीय श्राय	६,२३४	8,638	<u>ሂ, ሂ</u> ടo
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय श्राय	१६५	२०४	२२६

# राष्ट्रीय ग्राय समिति—

विगत वर्षों में राष्ट्रीय आय की गएना के महत्त्व को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अगस्त सन् १६४६ में सरकार ने राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित आँकड़ों में सुधार के सुफाव देने और अधिक वैज्ञानिक रीति से राष्ट्रीय आय•का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आय सिमिति नियुक्त की थी। अप्रैल सन् १६५१ में सिमिति ने अपनी प्रथम

रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें सन् १६४८-४६ से सम्बन्धित राष्ट्रीय आय का अनुमान दिया गया था । सिमिति की अन्तिम रिपोर्ट सन् १६५४ में प्रकाशित हुई है और उसमें सन् १६५३-५४ तक के अनुमान निम्न प्रकार दिये गये हैं :—

#### भारत की राष्ट्रीय ग्राय

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR AND A PROPERTY AND A P	and a second second second		(करोड़	रुपयों में )
शीपंक	-8E 8E8=	9E X 8	-x3	-7.8 8.6.7.3
(१) कृषि, वन ग्रौर मछली उद्योग (२) खनिज निर्माग्य ग्रौर हस्त उद्योग (३) वाग्गिज्य ग्रौर परिवहन (४) ग्रन्य सेवायें शुद्ध देशी न्रत्पादन विदेशों से प्राप्त शुद्ध ग्राय कुल राष्ट्रीय ग्राय जन-संख्या (करोड़ों में) प्रति व्यक्ति ग्राय (स्पयों में)	8,7%       8,850       8,800       5,800       5,800       5,800       5,800       5,800       70	8,980 8,980 8,400 80,080 70 80,080 80,080 80,080 80,080 80,080 80,080	8,680 8,980 8,480 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 -	₹, %00 ₹, 500 ₹, 500 ₹0, 500 ₹0, 500 ₹0, 500 ₹0, 500 ₹0, 500

इन आँकड़ों के देखने से पता चलता है कि सन् १६४६-४६ और सन् १६५३-५४ के बीच में कुल राष्ट्रीय आय ८,६५० करोड़ रुपये से बढ़कर १०,६०० करोड़ रुपया हो गई है, अर्थात् उसमें २२.५% की वृद्धि हुई है। इस काल में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि केवल १५% रही है (२४६.६ रुपये से २८३.६ रुपया)। इसका कारण यह है कि जन-संख्या में भी ६.६ की वृद्धि हो गई है। (३५ करोड़ से ३७.३ करोड़)। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि अगस्त सन् १६३६ — १०० के आधार पर सन् १६४८-४६ का थोक कीमतों का निर्देशांक ३७६ था, जो सन् १६५३-५४ में ३६८ तक पहुँच गया था। इस आधार पर सन् १६४८-४६ और सन् १६५३-५४ के काल में कीमतों में ६% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार वास्तविक प्रति ब्यक्ति आय की वृद्धि केवल ८.५% निकलती है।

### राष्ट्रीय श्राय श्रीर ग्रार्थिक नियोजन-

योजना स्रायोग ने राष्ट्रीय स्राय की वृद्धि का दीर्घकालीन लक्ष्य सन् १९७५-७६ तक सन् १९५०-५१ की तुलना में कुल राष्ट्रीय स्राय को तीन गुना तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय श्राय को दुनुना कर देना निश्चित किया है। श्रनुमान यह है कि इस काल में देश की जन संख्या में भी ५०% की वृद्धि हो जायगी। लक्ष्य निम्न प्रकार हैं:—

शोर्षक	1	दूसरी योजना ५६–६१			पाँचवीं योजना ७१-७६
(१) राष्ट्रीय ग्राय योजना काल के ग्रन्त में (करोड रुपये) (२) जन-संख्या (करोड़ों में ) (३) प्रति व्यक्ति ग्राय (रुपये)	१०,८०० ३८.४ २८१	१३,४८० ४०'८ ३३१	۶۶ <b>.۶</b>	४६.४	X0.0

प्रथम पंच-वर्षीय योजना पूरी हो चुकी है। इस योजना के काल में कुल राष्ट्रीय आय में १६% की वृद्धि हुई है, जो अनुमान से बहुत अधिक है। योजना काल में वास्तिविक आय भी बराबर बढ़ी है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि योजना के अन्त में कीमतें योजना के आरम्भ के काल की तुलना में १३% नीची थीं। साथ ही, योजना काल में जन-संख्या भी बराबर बढ़ती रही है। परिग्णाम यह हुआ है कि प्रति व्यक्ति औय में ११% की वृद्धि हो गई है, जबिक अनुमान केवल ७% की वृद्धि का था और क्योंकि कीमतें नीचे गिरी हैं, इसलिए वास्तिविक आय में भी वृद्धि हुई है।

प्रथम योजना की प्रगति राष्ट्रीय भ्राय की वृद्धि के दृष्टिकोगा से इतनी सन्तोष-जनक रही है कि राष्ट्रीय ग्राय की वृद्धि के लक्ष्यों को पहले से ऊँचा कर दिया गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान वृद्धि दर पर देश की कुल राष्ट्रीय म्राय सन् १६७३-७४ तक ही तीन गुनी हो जायगी म्रीर प्रति व्यक्ति म्राय दो गुनी । दूसरी पंच-वर्षीय योजना में सन् १९५६-६१ के काल में राष्ट्रीय आय में २५ ६% वृद्धि का लक्ष्य निश्चित किया गया है और वयों कि पाँच वर्ष के इस काल में जन-संख्या .३८ ३७ करोड़ से बढ़कर ४० ६७ करोड़ हो जायगी, इसलिए प्रति व्यक्ति ग्राय में १५% की वृद्धि हो जायगी:। योजना कमीशन का अनुमान इस मान्यता पर आधारित है कि योजना काल में की मतों की स्थिरता बनी रहेगी, की मतों के बढ़ने की दशा में लक्ष्यों में संशोधन भ्रावस्यक हो सकते हैं। वास्तविकता यह है कि दूसरी योजना के लागू करते ही कीमतों के ऊपर जाने की प्रवृत्ति आरम्भ हो गई है। दिसम्बर सन् १६५६ में ही योजना कमीशन को दूसरी योजना के प्रस्तावित व्यय (४,८०० करोड़ रुपये) में ४०० करोड़ रुपये की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखना पड़ा था। वित्त मन्त्री ने अपनेक ऐसे नए कर भी लगाए हैं जिनसे एक श्रोर तो मुद्रा-प्रसार का दबाव घटेगा और दूसरी स्रोर सरकार को लगभग १०० करोड़ रुपये की वार्षिक स्राय प्राप्त हो जायगी। योजना काल में राष्ट्रीय ग्राप की वृद्धि-

सन् १६५५-५६ के लिए भारत में राष्ट्रीय ग्राय का ग्रनुमान ६,६६० करोड़ रुपया रखा गया है, जब कि सन् १६४ द-४६ में इसका ग्रनुमान द,६५० करोड़ रुपया था। उपरोक्त काल में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय ग्राय २४६ ६ रुपये से बढ़कर २६० द रुपया हो गई है। इस प्रकार चालू कीमतों (Current Prices) के ग्राधार पर

इस काल में कुल राष्ट्रीय आय में १५.५% वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में ५.६ प्रतिशत वृद्धि। निम्न तालिका में चालू तथा स्थिर कीमतों पर कुल राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि का क्रम दिखाया गया है:---

राष्ट्रीय आय की वृद्धि

Company of the School Section	राष्ट्रीय ग्राय (करोड़ रुपयों मे)		प्रति व्यक्ति ग्राय (रुपयों मे)	
	चालू कीमतों के ग्राघार पर	सन् १६४८–४६ की कीमतों पर	चाल कीमतों के	
38-2838	८,६५०	८,६५०	२४६.६	3.385
१६४६-५०	६,०१०	८,८२०	३५३-६	२४५ ६
१६५०–५१	<b>६,५३</b> ०	८,८५०	२६५.२	२४६•३
१६५१–५२	०७३,३	6,800	२७४'०	* <b>२</b> ५०•१
<b>१</b> ६५२—५३	६,८२०	६,४६०	२६६.४	२५६•६
१९५३ ५४	१०,४५०	१०,०३०	२५०.७	२६५७
१६५४-५५	६,६१०	१०,२५०	२५४.५	३७१•६
१९५५-५६	033,3	१०,४५०	२६०•=	२७३-६
१६५६–५७	११,४१०	११,०१०	२९४•३	२६४'०

उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि वास्तविक ग्राघार (Real Terms) में सन् १६५१-५२ श्रौर सन् १६५५-५६ के पांच वर्षों में, श्रर्थात् प्रथम पंच-वर्षीय योजना के काल में कुल राष्ट्रीय श्राय में १८ ४% वृद्धि हुई है श्रौर सन् १६५६ ५७ में, श्रर्थात् द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में, ५.१% की वृद्धि । इसी प्रकार इस काल में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय श्राय में क्रमश ११.१ श्रौर ३.८ प्रतिशत वृद्धि हुई है। कीमतों के परिवर्तन के कारण चालू कीमतों पर राष्ट्रीय श्राय की वृद्धि स्थिर कीमतों की तुलना में श्रष्टिक रही है।

क्या हमारे राष्ट्रीय ग्राय सम्बन्धी लक्ष्य पर्याप्त हैं ?—

इसमें तो सन्देह नहीं है कि पिछले वर्षों से हमने आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के प्रयत्न किए हैं और इसमें हमें काफी सफलता भी मिली है, परन्तु अभी हमारी प्रगति बहुत पीछे है। एक औसत अमरीकन की आय एक औसत भारतीय से लगभग ३१ ग्रुनी है और एक औसत अंग्रेज की लगभग १४ ग्रुनी है। हमारे देश में जन-संख्या की वृद्धि उत्पादन की वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है। नीचे की तालिका में भारत की राष्ट्रीय आय की तुलना दूसरे देशों से की गई है:

देश	वर्षं	जन-संख्या करोड़ में	कुल राष्ट्रीय स्राय (करोड़ रुपयों में)	प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय ग्राय (रुपयों में)
ग्रास्ट्रे लिया	१९५३	०'दद	3,898	४,४६०
वर्मा	१९५३	<b>१</b> •००	<b>\$8</b> \$	२०६
बनाडा	8848	१•५२	339,3	६,०५६
लङ्का	१६५३	0.26	४४१	५४१
फ्रान्स	१६५४	४.५७	१४,७४०	३,६६६
जापान	१६५४	द"द२	5,१२६	६२२
गूजील <sup>ै</sup> प्ड	१९५४	० २१	१,०५=	४,०६२
पाकिस्तान	8EX3XX	<b>७</b> •७=	₹,€₹१	२४५
स्विट <b>ज</b> रलैण्ड	8878	০'४५	7,800	४,५ <b>१</b> २
ब्रिटेन	१९५४	7.55	२०,७२०	४,०५७
संयुक्त राज्य ग्रमरीका	१९५४	१६ २४	१,४२,६५७	इ,७७४
भारत	१९५६५७	े ३८'७४	1 - 28,080	? द४

#### राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि करने के उपाय-

राष्ट्रीय म्राय में वृद्धि करने के लिये नियोजित प्रयत्न करने की अति म्रावस्य-कता है।

(i) इस स्थित को सुधारने का सबसे महत्त्वपूर्ण उपाय यही हो सकता है कि सभी दिशाओं में उत्पादन की वृद्धि की जाय। (ii) साथ ही, हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारे देश में आय के वितरए में भी घोर असमानतायें हैं। उपयुक्त नीति यही है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि और वितरए की असमानताओं को घटाने के प्रयत्न एक ही साथ किये जायें। (iii) यह भी आवश्यक है कि जन-संख्या की वृद्धि पर कुछ प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जायें। (iv) पूँजी के विनियोजन में वृद्धि की जाय। (v) देश में चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य अनेक प्रकार की सामाजिक सेवाओं का समुचित प्रबन्ध किया जाय। यह एक आशाजनक बात है कि आर्थिक नियोजन के द्वारा राष्ट्रीय आय की इसी कमी को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

# √श्रध्याय ४७

# बचत, विनियोग और पूर्ण वृत्ति

(Savings, Investments and Full Employment)

ग्राय किसे कहते हैं ?—

यह तो सभी जानते हैं कि हम उस समय तक कुछ भी ग्रामदनी प्राप्त नहीं कर सक्तं, हैं जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज को प्राप्त कर लेने के लिए तैयार न हो जो कि हम बेचना चाहते हैं, ग्रथवा जब तक कि कोई व्यक्ति हमारे श्रम को वेतन ग्रथवा मजदूरी के बदले में खरीदने को तैयार न हो। कीन्ज ने ठीक ही कहा है कि एक व्यक्ति का व्यय दूसरे की आय होती है। इस प्रकार सारे समाज की मौद्रिक आय सारे समाज के मौद्रिक व्यय के बराबर होती है। हम जो कुछ भी काम करते हैं भथवा जो कुछ भी हम उत्पन्न करते हैं वह उसे येच लेने की संभावना के श्राधार पर किया जाता है। श्राय को उत्पन्न करने का उपाय यही होता है कि हम सामाजिक उपज के स्टॉक में वृद्धि कर देते हैं। ग्राय के उत्पन्न होने की विधि ही यह है कि कोई व्यक्ति सामा-जिक उपज की मात्रा में वृद्धि करता है ग्रीर इस प्रकार वह उत्पत्ति के साधनों को भुगतान करता रहता है। सामाजिक उपज में वृद्धि करने के कार्य के अन्तर्गत ग्राय की एक घारा को उत्पन्न किया जाता है, जो उत्पत्ति के साधनों को किये गये भुगतान की मात्रा के बराबर होती है। इस सम्बन्ध में यह जानना ग्रावश्यक है कि जिस व्यक्ति को म्राय प्राप्त होती है वह भी उसे व्यय करता है ग्रीर दूसरों की ग्राय को उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है, किन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक बार जब एक व्यक्ति अपनी आय को व्यय करता है, आय का एक भाग भावी उनयोग के लिए बचा लिया जाता है। उदाहरएास्वरूप, यदि एक व्यक्ति को महीने के ग्रारम्भ में २०० रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं ग्रौर वह इसमें से १०% बचा कर शेष को खर्चं कर देता है तो उसकी स्थिति निम्न प्रकार होती है---२०० रुपया ग्राय = १८० रुपया उपभोग - २० रुपया बचत । जिन १८० रुपयों का व्यय किया गया है, मान लीजिए कि वे किसी दूकानदार को मिल जाते हैं। दूकानदार की आय १८० रुपया े हुई ग्रौर यदि वह भी १०% बचा कर शेष को व्यय कर देता है तो स्थिति निम्न प्रकार होगी-१८० रुपया ग्राय = १६२ रुपया उपभोग + १८ रुपया बचत। ठीक इसी प्रकार यह १६२ रुपये का व्यय किसी ग्रन्य व्यक्ति की ग्राय उत्पन्न करेगा ग्रौर यदि वह भी इसके १०% की बचत करता है तो स्थिति इस प्रकार होगी:--१६२ रुपया आय = १४५' द रुपया उपभोग + १६'२ रुपया बचत । यही क्रम बराबर

मागे चलता रहेगा और यदि इस प्रकार १० बार यह स्थिति पैदा होती है तो प्रत्येक बार माय, उपभोग और बचत की मात्रा घटती जाती है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार ब्यय के जो दस चक्र पूरे हो जाते हैं उन सबका जोड़ २०० रुपये की यारिम्भिक श्राय का १० गुना होना चाहिए, जिसका आर्थ यह होता है कि २०० रुपये के प्रारम्भिक व्यय के फलस्वरूप कुज २,००० रुपये का ब्यय हो जायेगा। यहाँ पर महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यदि कुल व्यय बचत का १० गुना है तो कुल उत्पन्न की गई श्राय प्रारम्भिक श्राय का १० गुना ही देगा।

उपभोग की वस्तुओं पर किया जाने वाला कुल व्यय दो बातों पर निर्भर होता है:—(i) व्यक्ति की कुल ग्राय तथा (ii) उपभोग की प्रवृत्ति (Propensity to Consume) । उपभोग की प्रवृत्ति का ग्रथं कुल ग्राय का वह भाग है जो उपभोग पर व्यय किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि आय की वृद्धि के साथ-साथ उपभोग पर किया गया खर्च भी बढ़ता जाता है, क्योंकि उपभोग की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है । उपभोग की प्रवृत्ति के कारए। आय में परिवर्तन नहीं होते हैं, बल्कि विनियोग (Investment) में परिवर्तन होने से श्राय में परिवर्तन हो जाते हैं। जितनी ही विनियोग में वृद्धि होती है उतनी ही आय में भी वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि श्राय की वृद्धि की व्याख्या करने के लिए उन कारणों को समझना पड़ता है जो विनियोग को प्रभावित करते हैं। विनियोग के ऊपर दो बातों का प्रभाव पड़ता है :--(i) ब्याज की दर तथा (ii) पूँजी की सीमान्त कुशनता (The Marginal Efficiency of Capital)। पूँजी की सीमान्त क्ञलता का ग्रर्थं उस लाभ की दर से होता है जिसके प्राप्त होने की ग्राशा की जाती है। यह निश्चय है कि उस समय तक विनियोग बराबर बढ़ते रहेंगे जब तक कि विनियोगों पर प्राप्त की हुई लाभ की दर पूँजी पर प्राप्त होने वाले ब्याज की दर से ऊँची रहती है, किन्तु जैसे-जैसे विनि-योग बढ़ते हैं, उन पर लाभ की सीमान्त दर घटती जाती है ग्रीर ग्रन्त में वह ब्याज की दर के बराबर हो सकती है। यहाँ पर ग्राकर विनियोगों का बढ़ना रक जाता है। साथ ही, विनियोगों के बढ़ाने के लिए ग्राय का बढ़ाना भी ग्रावश्यक है, ताकि बचत भी उसी अनुपात में बढ़ती रहे जिस अनुपात में कि विनियोग बढ़ रहा है। हमारा म्रन्तिम निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी समय विशेष में देश की म्राय इस बात पर निर्भर होती है कि उस देश में विनियोग की दर क्या है ग्रौर उस समय में देश के लोगों की विनियोग करने की प्रवृत्ति क्या है।

### बचत (Savings)-

बचत की साधारएा सी परिभाषा यह हो सकती है कि यह आय और व्यय के अन्तर के बराबर होती है। प्राप्त आय में से उपभोग पर व्यय करने के पश्चात जो कुछ बचता है वह बचत को सूचित करता है। देश में बचत की मात्रा वहाँ के लोगों की बचत करने की प्रवृत्ति पर निर्भर होती है। यदि देश के लोग अपनी आय का ६०% व्यय करने के खादी हैं तो बचत खाय का १०% होगी। साधारणतया बचत को बढ़ाने-घटाने के लिए श्राय की मात्रा में परिवर्तन करना खावरुयक होता है, क्योंकि उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तन कम ही होते हैं। जब कोई व्यक्ति बचत करता है तो इसका यह खर्थ नहीं होता है कि उसने खपना उपभोग बन्द कर दिया है। वह केवल उपभोग को स्थिगित कर देता है और ऐसा करने में वह खाय के उस भाग को, जिसकी बचत कर ली गई है, भविष्य में व्यय करने का खिकार प्राप्त कर लेता है।

बचत के अनेक रूप सम्भव हैं:—(i) बचत करने वाला व्यक्ति श्राय के एंक भाग को ग्रपने पास नकदी के रूप में रख सकता है, ताकि उसे भविष्य में उपयोग कर सके, (ii) इसी प्रकार बचाई हुई ग्राय को बैंक के जमा के रूप में रखाजा सकता है, (iii) इसे सरकार को ऋगा के रूप में दिया जा सकता है। इसके लिए बींड खरीदा जा सकता है, (iv) यह राशि किसी कम्पनी श्रथवा फर्म को उधार दी जा सकती है, ग्रथवा ( v ) इसके बदले में भूमि, मकान ग्रथवा ग्रन्य सम्पत्ति खरीदी जा सकती है, इस प्रकार की सारी वचत व्यक्तिगत बचत होती है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा बचत करने का सदा ही यह अर्थ नहीं होता है कि समाज ने भी बचत की है। वास्तव में यह सम्भव है कि जनकि एक व्यक्ति बचत करता है तो दूसरा इसकी विप-रीत दिशा में कार्य करे। उदाहरणस्वरून, यदि एक व्यक्ति मकान खरीदता है तो कोई दूसरा उसे वेचता है। थहाँ पहले व्यक्ति ने तो बचत की है, परन्तु दूसरे ने विपरीत दिशा में कार्य किया है। ऐसी दशा में एक व्यक्ति की बचत दूसरे व्यक्ति की विराधी कार्यवाही द्वारा रद्द हो जाती है ग्रीर समाज के दृष्टिकी स कुछ भी बनत नहीं हो पाती है। समाज द्वारा बचत तभी हो सकेगी जबकि एक व्यक्ति की बचत किसी दूसरे की विरोधी कार्यवाही से रद्द न होने पाये। यही कारण यह है कि व्यक्ति-गत बचत और सामाजिक बचत में ग्रन्तर होता है।

#### विनियोग (Investment)—

जब समाज बचत करता है, ग्रर्थात् जब समाज ग्रपने उपभोग को स्थाित करता है तो बचत के फलों का ग्रनेक रूपों में उपयोग हो सकता है। यह सम्भव है कि सरकार नये ऋगों की निकासी करे श्रीर ऋगों से प्राप्त रकम के द्वारा नई नहरों श्रीर नये पुलों का निर्माण करे। यह भी सम्भव है कि किसी नई कम्पनी की स्थापना हो, नये ग्रंशों की निकासी की जाय, नये मालों का उत्पादन हो ग्रथवा नये मकानें का निर्माण हो। इस बचत का उपभोग लोक तथा व्यक्तिगत उपक्रमों की कार्यवाहक पूँजी में वृद्धि करने ग्रथवा कच्चे, ग्रद्ध तैयार ग्रीर तैयार मालों के स्टॉक् बनाने के लिए भी किया जा सकता है। जब कभी भी सामाजिक बचत होती है तो इससे पूँजी के स्टॉक में वृद्धि होती है, ग्रथित पूँजी का नया निर्माण (Formation) होता है। पूँजी के इस नए निर्माण को ही हम विनियोग कह सकते हैं। साधारण भाषा में जब कभी भी हम यह कहते हैं कि हमने ग्राय का विनियोग किया है तो हमारा ग्रीभन्नाय

गह होता है कि हमने भविष्य में ग्राय प्राप्त करने का ग्रधिकार प्राप्त कर लिया है। स प्रकार के विनियोग में, जो स्वभाव से ही व्यक्तिगत है, यह सम्भावना बरावर गि रहती है कि एक व्यक्ति के विनियोग के साथ साथ दूसरे के द्वारा ग्रविनियोजन (Dis-investment) हो रहा हो। सामाजिक विनियोग में ऐसी सम्भावना नहीं रहती है। ऐसा विनियोग सदा ही घनात्मक होता है ग्रौर यह भी ग्रावश्यक नहीं है कि सामाजिक विनियोग के साथ-साथ व्यक्तिगत विनियोग भी हो ही।

व्यक्तिगत विनियोग की मात्रा एक बड़े ग्रंश तक सरकारी नीति पर निर्मंर होती है। घन का विनियोग करते समय विनियोगी लाभ की दर पर सावधानी के साथ विचार करता है। बचत करने वाले के पास बचत के लाभदायक उपयोग के दो उपाय होते हैं—बचत को ब्याज पर उठा देना ग्रोर बचत का विनियोग कर देना। दोनों में से उसी को चुना जायगा जो ग्रधिक लाभदायक होगा। इस ग्राधार पर हम यह कह सकते हैं कि जहाँ पर पूँजी की सीमान्त कुशलता ग्रथवा लाभ की दर ब्याज की दर के बराबर हो जाती है, वहीं पर विनियोग की सीमा ग्रा जाती है। जो कारण लाभ की दर को बढ़ा देते हैं वे विनियोग को भी प्रोत्साहन देते हैं और इसके विपरीत जिन कारगों से ब्याज की दरें बढ़ती हैं वे विनियोगों को हतोत्साहित कर देते हैं।

भारत में पूर्णी का निर्माण (Capital Formation in India)—

पूँजी निर्माण श्रौर विनियोग में कोई विशेष श्रन्तर नहीं होता है। पूँजी निर्माण बचत कोषों के जमा करने की क्रिया है श्रौर ये बचत कोष के विनियोग की मात्रा निश्चित करते हैं। एक दूसरे हिंदिकोण से पूँजी निर्माण का श्रीभप्राय बचत कोषों को नये निर्माण, पूँजीगत माल के उत्पादन श्रथवा विदेशों में विनियोग करने से होता है। किसी भी देश की श्राधिक सम्पन्नता वहाँ पर पूँजी के निर्माण की दर पर निर्मर होती हैं। ग्राधिक विकास के लिए यह श्रावश्यक है कि देश में बचतों को बढ़ाया जाय श्रौर इन बचतों का श्रिधक श्रंश तक उद्योग, कृषि तथा विकास कार्यों में विनियोग किया जाय।

भारत में पूँजी के निर्माण की गित घीमी ही रही है। इसके कई कारण हैं:—(i) इसमें तो सन्देह नहीं कि भारतवासी स्वभाव से ही बचत करने के इच्छुक होते हैं, परन्तु ग्राय के कम होने के कारण बचत करने की क्षमता कम रहती है। (ii) पिछले कुछ वर्षों से तो यह क्षमता ग्रीर भी कम रह गई है, क्योंकि कीमतें काफी ऊँची चली गई हैं ग्रीर :(iii) करारोपण की वृद्धि हुई है। वैसे भी केवल बचत की दर ही पूँजी निर्माण के हिण्टकोण से महत्त्वपूर्ण नहीं है, बिल्क बचतों का विनियोग भी ग्रावश्यक है। (iv) इघर कुछ वर्षों से भारतवासियों को बचतों का विनियोग करने के स्थान पर उनका उपभोग करने पर बाघ्य होना पड़ा है। (v) साथ ही, जमींदारों ग्रीर राज्य दरबारों के उन्मूलन तथा ग्रन्य सामाजिक सुघारों के फलस्वरूप उच्च ग्राय वर्ग के लोगों की बचत करने की क्षमता में काफी कमी हो गई

है। (vi) बचत की दर के नीचा रहने का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि बचते करने की सुविधाएँ बहुत कम हैं। मुख्यतया छोटी-छोटी बचत करने वाले व्यक्तियों के लिए। ऐसी मुविधाएँ ग्राम तौर पर डाकखानों के सेविंग बैंक द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। देश की विनियोग संस्थाएँ साधारणतया बड़ी-बड़ी बचत करने वालों के हिष्कोण से विनियोग मुविधाएँ उपलब्ध करने के लिए बनाई गई हैं, परन्तु वर्तमान काल में छोटी बचतों का महत्त्व ग्रिधिक बढ़ गया है।

भारत में ग्राय, बचत तथा विनियोग की प्रगति-

भारत में प्रथम पंच-वर्षीय योजना का उद्देश्य बचत और विनियोग की दरों को बढ़ाना था। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि बचत की दर, जो सन् १६५०-५१ में राष्ट्रीय ग्राय का ५% थी, सन् १६५५-५६ में ६ ७५% हो जायगी। इसका परिगाम यह होता है कि देश में पूँजी निर्माण इस काल में ४५० करोड़ रुपया प्रति वर्ष से बढ़ कर ६७५ करोड़ रुपया प्रति वर्ष हो जाता। प्रथम पंच-वर्षीय योजना के काल में प्रगति इससे भी श्राधक ग्राशाजनक रही है। देश की राष्ट्रीय ग्राय में योजना-काल में १८% को वृद्धि हुई है, ग्रर्थात् वह सन् १६५०-५१ में ६,११० करोड़ रुपये से बढ़ कर सन् १६५५-५६ में १०,८०० करोड़ रुपया हो गई है। विनियोग की मात्रा ४५० करोड़ रुपये प्रति वर्ष से बढ़कर ७६० करोड़ रुपया प्रति वर्ष हो। विनियोग की मात्रा भाग कि स्वद्ध कर राष्ट्रीय ग्राय के ४ ६% से बढ़ कर ७ ३% हो गई है। निम्न तालिका सन् १६५२-५३ की कीमतों के ग्राधार पर राष्ट्रीय ग्राय, विनियोग तथा उपभोग की प्रगति दिखाती है:—

( करोड़ रुपयों में )

<u>হীর্</u> षक	सन् १६५०-५१	सन् १९४४-४६
(१) राष्ट्रीय ग्राय	6,880	१०,५००
(२) विनियोग ४५०		030
(३) विनियोग का राष्ट्रीय ग्राय से	प्रतिशत ४'६	७•े३ 🐇
(४) राष्ट्रीय ग्राय निर्देशांक	१००	११८
(५) प्रति व्यक्ति ग्राय निर्देशांक	8'00	१११
(६) प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय नि	र्देशांक १००	308

सन् १६५२-५३ में, जबिक प्रथम पंच-वर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया गया तो योजना कमीशन ने पता लगाया था कि दूसरी और इसके बाद की योजनाओं से पूँजी निर्माण को बराबर बढ़ाते रहने की सम्भावना रहेगी। लक्ष्य यह रखा गया था कि सन् १६५६-५७ के बाद बचत की दर को इस प्रकार बढ़ाया जाय कि अति-रिक्त उत्पादन के ५०% की बचत हो जाय। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि सन् १६६०-६१ तक राष्ट्रीय आय के ११% तक बचत हो जायगी और सन् १६७७-७८ तक यह २०% तक पहुँच जायगी । यह अनुमान लगाया गया था कि इस प्रकार सन् १६७७-७८ तक कुल राष्ट्रीय आय ३ गुनी हो जायगी और प्रति व्यक्ति आय २ गुनी ।

ग्रब ऐसा श्रनुमान लगाया गया है कि ये लक्ष्य ग्रावश्यकता से ऊँचे हैं श्रीर इन पर ग्रनुरोध करते से जनता को काफी कष्ट हो सकता है, इसलिए दूसरी पच-वर्षीय योजना में दिष्टिकोएा बदल दिया गया है। ऐसा ग्रनुमान लगाया गया है कि विनियोग की दर सन् १६५४-५६ में ७% से बढ़ कर सन् १६६०-६१ में ११%, सन् १६६४-६६ में १४% ग्रीर सन् १६७०-७१ में १६% तक पहुँच जायगी। इसके पश्चात् इसके यहीं पर रुके रहने की ग्राशा है, ग्रीधक से ग्रीधक यह सन् १६७४-७६ तक १७% हो सकती है। नीचे की तालिका सम्पूर्ण स्थिति को दिखाती है:—

़ शीर्षक	E 3	दूसरी योजना काल १९५६-६१		चौथी योजना काल ',६६६-७१	पाँचवीं योजना काल १६७१-७६
राष्ट्रीय ग्राय योजना काल क	-			•	
ग्रन्त में (करोड़ रुपये में )	१०,500	१३,४५०	१७,२६०	२१,६८०	२७,२७०
कुल शुद्धे विनियोग (करोड़	-				
रुपये में )	30,200	६,२०४	003,3	१४,८००	२०,७००
विनियोग का राष्ट्रीय श्राय से					
प्रत्येक योजना कोल के अन्त में					
प्रतिशत	७•३	१०•७	१३-७	१६०	<i>१७</i> °०
	<u>~</u>	2	S - 110/	-f>	

दूसरी पंच-वर्षीय योजना में कुल राष्ट्रीय ग्राय में २५% वृद्धि करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है ग्रीर विनियोग दर को १०७% तक बढ़ा दिया जायगा। ग्रालोचकों का कहना है कि ये दोनों ग्रनुमान ग्रवास्तिवक प्रतीत होते हैं। राष्ट्रीय ग्राय इकाई (National Income Unit) तथा करारोपण जाँच ग्रायोग (Taxation Enquiry Commission) ने राष्ट्रीय ग्राय, बचत ग्रीर विनियोग की प्रगति का जो ग्रनुमान लगाया है वह इतना ग्राशाजनक नहीं है। भारत में इस प्रगति का सही ग्रर्थ समफने के लिए यह ग्रावश्यक होगा कि संसार के कुल दूसरे देशों की प्रगति से इसकी तुलना कर दी जाय। नीचे की तालिका में इसी का प्रयत्न किया

गया है:--सकल देशी पंजी-निर्माग सकल देशो उपज के प्रतिशत के रूप में-

देश	सन् १६४८	सन् १६५०	सन् १६५२
म्रास्ट्रे लिया भार्द्रे लिया	२०•७	२४'=	३५.६
आर्द्रारायाः बर्मा	१५•१	8.0.₹	१५.२
लेना लेना	ે ૬∙૦	१०-४	१३.३
<sub>प्रा</sub> यरलैंड	१२.८	१४.४	१६.४
ब्रावरसप् ब्रिटेन	<b>१२·१</b>	<b>१३.</b> १	१३.४
भारत	<b>5</b> *3	F'3	\$0.0

भारत में प्रजी-निर्माण प्रोत्साहन के सुभाव-

देश में राष्ट्रीय ग्राय तथा पूँजी-निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए यह ग्राव-रयक है कि मुद्रा-प्रसार को रोका जाय और इसका सबसे अच्छा उपाय यही हो सकता है कि कम से कम काल में उत्पादन को इतना बढ़ा दिया जाय कि जनता के हाथ में श्राधिक नियोजन के अन्तर्गत जितनी तेजी के साथ क्रय: शक्ति पहुँच रही है उतनी ही तेजी के साथ बाजार में वस्तुश्रों की पूर्ति बढ़ सके । सरकार की मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति, जिसके ग्रन्तगंत चलन ग्रौर साख-मुद्रा का संकुचन किया जाता है, बहुत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे उद्योगों और व्यवसायों के लिए वित्तीय साधनों की कमी पैता हो जाती है। यदि हम अपने आर्थिक नियोजन का लक्ष्य दीर्घकालीन रखते हैं तो सर-कार के लिए यह आवश्यक हैं कि उत्पादकों के लिए बैंकों तथा इसी प्रकार की दूसरी संस्थान्त्रों से वित्तीय स्विधार्ये उपलब्ध करके निकट भविष्य में ही वस्तुम्रों की पति को बढ़ाने का प्रयत्न करे। साथ ही साथ, यह भी आवश्यक है कि छोटी बचतों को और भी अधिक प्रोत्साहन दिया जाय तथा उनके जमा करने की व्यवस्था को बढाया जाय । इसके लिए सहकारी बैंकों श्रौर व्यापार बैंकों को छोटे कस्बों तथा बढ़े-बढ़े गाँवों में शाखायें खोलने के लिए सहायता देना उचित होगा। हाल में सरकार ने रिजर्व बैंक की ब्याज की दर में वृद्धि करके तथा सन् १९५१ के उद्योग (विकास श्रौर नियमन ) एक्ट में संशोधन करके तो श्रौद्योगिक उत्पादन को श्रौर भी हतोत्सा-हित कर दिया है।

# रोजगार (Employment)

'पर्गा रोजग्रार का अर्थ-

श्राधुनिक युग में समाज की एक बड़ी गम्भीर समस्या बेरोजगारी की समस्या होती हैं। बेरोजगारी का रहना देश के ग्राधिक ग्रीर सामाजिक जीवन के लिए काफी घातक हो सकता है। श्रल्यकाल में देश में श्रम की पूर्ति लगभग निश्चित ही होती है। यही कारण है कि श्रम की माँग में कमी होते ही बेरोजगारी फैलती है। बेरोजगारी को दूर करना ग्रीर देश के सभी नागरिकों के लिए समुचित रोजगार सुविधाग्रों की व्यवस्था करना प्रत्येक श्राधुनिक राज्य का महत्त्वपूर्ण कर्तां व्य समभा जाता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना सभी के लिए रोजगार की सुविधाग्रें स्थापित किये बिना हो ही नहीं सकती है। पूर्ण वृत्ति ग्रथवा पूर्ण रोजगार तब सम्पन्न होता है जबकि देश के प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को रोजगार मिल जाय जिसे उसकी ग्रावश्यकता है। पूर्ण वृत्ति का यह ग्रथं नहीं होता है कि देश में बेरोजगारी ग्रथवा बेकारी पूर्णत्या समाप्त हो जाती है। प्रत्येक ग्रथं-व्यवस्था में कुछ ग्रंश तक बेरोजगारी का बना रहना ग्रानिवार्य ही होता है। इस प्रकार बेरोजगारी के बने रहने के निम्न कारण हो सकते हैं:—

(१) काम करने के अनिच्छुक व्यक्ति—प्रत्येक समय में समाज में

कुछ ऐसे व्यक्ति ग्रवश्य होते हैं जो किसी न किसी कारण से काम करना ही नहीं चाहते हैं। इन्हें कोई भी प्रलोभन काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकता है।

- (२) ग्रस्थायी बेरोजगारी—कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक काम को छोड़कर दूसरा ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ काल के लिए बेरोजगार रह सकते हैं, क्योंकि एक काम को छोड़ते ही तुरन्त दूसरे का मिल जाना निश्चित नहीं होता है।
- (३) प्रशिक्षरण काल—कुछ व्यक्ति ऐमे भी होते हैं जो एक काम को छोड़ देने के पश्चात् दूसरे को सीखने पर समय बिताते हैं और प्रशिक्षरण के इस काल में इस हिण्टकोएं से बेकार रहते हैं कि प्रशिक्षरण के काल में उन्हें मजदूरी नहीं मिलती हैं।
- (४) ग्राकस्मिक बेकारी—कुछ ग्रंश तक बेकारी ग्राकस्मिक (Casual) हो सकती है, जैसे जहाजों पर मान लादने ग्रथवा उतारने वाले श्रमिक कुछ समय तक के लिए बेकार रह सकते हैं।
- (५) मौसमी बेकारी—कुछ उद्योगों, जैसे—चीनी उद्योग में काम मौसमी (Seasonal) होता है श्रौर जिन महीनों में चीनी की मिलें बन्द रहती हैं उनमें काम करने वाले श्रिधकाँश श्रमिक बेकार रहते हैं।
- (६) व्यापार चक्र—व्यापार चक्रों के फलस्वरूप भी व्यवसायिक मन्दी के काल में बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है, जो उस समय तक बनी रहती है जब तक कि मन्दी का प्रभाव शेष रहता है।
- (७) शैलिपक परिवर्तन—शैलिपक परिवर्तन भी कुछ काल के लिए बेरोजगारी पैदा कर सकते हैं । मशीनों, उत्पादन विधियों और इस प्रकार के दूसरे परिवर्तनों के कारण कुछ श्रमिक कुछ काल के लिए बेरोजगार हो जाते हैं।

इस प्रकार के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कुल जन-संख्या का तीन से लेकर ५% तक साधारणतया रहती हैं। ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों को छोड़कर होप सभी के लिए रोजगार सुविधाएँ रहनी चाहिए। पूर्ण वृत्ति अथवा पूर्ण रोजगार का अभिप्राय यही होता है कि देश की शेष ६५ से लेकर ६७% जनता के लिए रोजगार उपलब्ध हो। साधारणतया युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था में इस दृष्टिकोण से पूर्ण वृत्ति की दशाएँ पैदा हो जाती हैं। शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्था की समस्या यही होती है कि जन संख्या के इतने बड़े भाग के लिए समुचित रोजगार सम्बन्धी सुविधाएँ उत्पन्न की जार्ये।

पूर्ण वृत्ति स्थापना के सिद्धान्त-

इस सम्बन्ध में सबसे पहले यही जानना भ्रावश्यक होगा कि रोजगार की मात्रा किन बातों पर निर्भर होती है ? यदि सरकार द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और स्वतन्त्र बाजार व्यवस्था रहती है तो श्रम और पूँजी को प्राप्त होने वाले रोजगार की मात्रा व्यवसायियों भौर उद्योगपितयों के इस निर्णय पर निर्मर होती है कि वे नये व्यापारों तथा उद्योगों में कितना विनियोग करने का निर्ण्य करतें हैं। इन्हीं निर्ण्यों पर कुल रोजगार की मात्रा निर्भर रहेगी, इसलिए इस बात का श्रध्ययन बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है कि विनियोग सम्बन्धी निर्ण्य किन बातों पर निर्भर होते हैं?

प्रतिष्ठित ग्रर्थंशास्त्रियों का विचार था कि ये निर्णाय ब्याज की दर पर निर्भर होते हैं ग्रर्थात् इस बात पर कि नई पूँजी की पूर्ति की कीमत क्या है ? इस हिट-कोग से ब्याज की दर की प्रत्येक कमी विनियोगों को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखती है ग्रीर इसके विपरीत ब्याज की दर के बढ़ाने से विनियोग हतोत्साहित होते हैं । इन प्रयंशास्त्रियों के ग्रनुसार रोजगार की मात्रा को बढ़ाने के लिए ब्याज की दरों को घटाना ग्रावश्यक है । व्यवहारिक ग्रनुभव ने इस यिचारघारा की पुष्टि नहीं की है। ग्रवसाद के काल में ब्याज की दरों को घटाने से भी विनियोग प्रोत्साहित नहीं हो पाये हैं।

वास्तिविकता यह है कि व्यवसायी तथा उद्योगपित इस कारण ऋण नहीं लेते हैं कि ब्याज की दरें नीची हैं। ऋण प्राप्त करने का प्रोत्साहन इस बात से प्रभावित होता है कि भविष्य में विनियोगों पर अधिक लाभ प्राप्त होने की आशा की जाती है। साम्य की दशा में ऋणों के व्याज की दर विनियोगों की सम्भावित सीमान्त लाभ दर के बराबर होनी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि रोजगार में उस समय तक वृद्धि होने की सम्भावना नहीं होगी जब तक कि भावी लाभों की दर बढ़ने की सम्भावना नहीं। जब तक ऊँचे लाभों की आशा न होगी, ब्याज की दरों के नीचे गिरने से रोजगार के बढ़ने की कोई सम्भावना नहीं रहेगी। इसी प्रकार यदि भावी लाभ की आशा उज्ज्वल नहीं है तो विनियोग हतोत्साहित होगे और रोजगार की मात्रा घटेगी। रोजगार को बनाये रखन अथवा उसका विकास करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप के बिना काम नहीं चल सकता है। मन्दी के काल में बेरोजगारी को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार को अपनी आय से अधिक व्यय करना चाहिए। इसी प्रकार अभिवृद्धि (Boom) के काल में सरकार को आय से कम व्यय करना चाहिए। सरकारी नीति पर ही एक बड़े अंश तक रोजगार का विस्तार अथवा संकुचन निर्भर होता है।

जहाँ तक पूर्ण वृत्ति को प्राप्त करने के सिद्धान्तों का प्रश्न है, वे सरकारी हस्तक्षेप की ग्रावश्यकता पर ही ग्राधारित होंगे। इस सम्बन्ध में तीन सिद्धान्तों का उल्लेख किया जा सकता है:—

(१) समुचित विनियोग नीति अपनाना—सरकार को समुचित विनियोग नीति द्वारा अवसाद को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके विपरीत अभिवृद्धि के काल में सरकार को लोक व्यय में कमी करनी चाहिए और मँहगी मुद्रा नीति का पालून करना चाहिए। दोनों ही दशाओं में सट्टा बाजार पर समुचित नियन्त्रण भी आवश्यक है।

- (२) काम को श्रमिकों तक ले जाना—सरकार को उद्योगों की स्थिति इस प्रकार म्रायोजित करनी चाहिए कि उन क्षेत्रों के बेरोजगार व्यक्तियों को जिनमें मन्दी म्रा गई है उन्हीं क्षेत्रों में रोजगार मिल सके । दूसरे शब्दों में, काम को श्रमिकों तक ले जाने की नीति भ्रपनाई जानी चाहिए।
- (३) समुचित ग्रार्थिक नीति—यह ग्रावश्यक है कि सरकार ऐसी ग्रार्थिक नीति को ग्रहण करे जिससे कि देश के उद्योगों ग्रौर निर्यातों के स्तर बनाये रखे जा सकें। इन सब रीतियों से रोजगार स्तर को बनाये रखना तथा उनका ऊँचा उठाना सम्भव हो जायगा।

राज्य ग्रौर पूर्ण वृत्ति —

काफी लम्बे समय तक ग्रर्थशास्त्री ग्राधिक जीवन में राजकीय हस्तक्षेप को बुरा

समभते आये हैं। महान् अवसाद ने इस विचारघारा को काफी बदल दिया। इस काल में संसार ने प्रचुरता के बीच निर्धनता और अति-उत्पादन के साथ भुखमरी के विचित्र हथ्य देखे थे। इस विचित्र परिस्थित का कारणा यह था कि एक और तो उत्पादन और उपभोग के बीच समायोजन नहीं रहा था और दूसरी ओर बचत और विनियोगों की भी दरों में अन्तर था। सभी अर्थशास्त्रियों को यह मानने पर बाध्य होना पड़ा था कि उत्पादन और उपभोग तथा बचत और विनियोग के बीच समचयं स्थापित किए बिना इस परिस्थित से छुटकारा सम्भव न था। समचय और समायोजन की स्थापना आर्थिक नियोजन द्वारा ही सम्भव थी, इस लिए महान् अवसाद के बाद संसार भर में आर्थिक नियोजन की एक विश्वव्यापी लहर सी आई थी। नियोजन की सफलता ने इस विचारघारा को और भी अधिक बल प्रदान किया।

ग्राधिक नियोजन की सफलता के लिए सरकारी नियन्त्रण ग्रौर नियमन ग्रावरयक हो जाता है। पूर्णं वृत्ति सम्बन्धी नीति को तो उस समय तक कार्यं रूप दिया ही नहीं जा सकता है जब तक कि सम्पूर्णं ग्र्थंव्यवस्था का पुनर्सङ्कठन ग्रथवा पुनर्निर्माण न कर दिया जाय। ग्राधिक नियोजन का एक सर्वस्वीकृत उद्देश्य पूर्णं वृत्ति की व्यवस्था करना ही होता है। इस नीति की सफलता उपयुक्त सरकारी संगठन ग्रीर राज्य प्रारम्भन पर ही निर्भर होती है।

# एक पूर्ण रोजगार का कार्यक्रम-

एक पूर्ण रोजगार के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुभाव विचार-गीय हैं:—

(१) कृषि विकास का कार्यक्रम—भारत में जनसंख्या का भूषि पर दबाव बहुत है और जनसंख्या की वृद्धि के साथ निरन्तर बढ़ता जा रहा है। कृषकों को कुछ महीनों तक अनिवार्य रूप से बेकार रहना पड़ता है, कृषि अनाधिक हो गई है, प्रति एकड़ पैदावार अति कम है और उत्पादन बिना किसी योजना के होता रहा है। सव-एकड़ पैदावार अति कम है और उत्पादन बिना किसी योजना के होता रहा है। सव-पृष्ण मुच ही भारतीय कृषि केवल जीने भर की अर्थ व्यवस्था पर निर्भर है। अतः पूर्ण रोजगार के जीवन-स्तर की रचना करने के लिये श्रम की अन्तर्व्यवसायी गतिशीलता (Inter-occupational movements) को बढ़ावा देना होगा, ताकि कृषि पर जन-संख्या का भार घटे। हमें प्रामीग अर्थ व्यवस्था का श्रामूल परिवर्तन करना होगा और उसे शहरी या श्रीद्योगिक अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित करना होगा।

(२) ग्रौद्योगिक विकास का कार्यक्रम—वर्तमान मसंतुलित एवं दोषपूर्ण

ग्रौद्योगिक ढाँचे को सुधारने के लिये निम्न उपाय करने चाहिये—(i) ग्रौद्योगिक इका इयों की विविधता ग्रौर उनका विकेन्द्रीयकरण, (ii) श्रम बाजारों को स्थायी बनाने के लिये उद्योगों के स्थानीयकरण पर नियन्त्रण रखना, (iii) क्षेत्र के ग्रौद्योगिक विकास ग्रौर उसके सामान्य ग्रार्थिक विकास में समन्वय स्थापित करना, (iv) उद्योगों के उत्पादन के लिये क्षेत्रीय बाजारों का विकास करना, (v) मजदूरी के उतार-चढ़ाव का इस प्रकार प्रबन्ध करना कि पूर्ण रोजगार का जीवन-मान बना रहे, (vi) निर्माण रीति में ग्रैल्पिक विकास, (vii) क्षेत्र के विशिष्ट उद्योगों का नियंत्रित पुनर्निर्माण, (viii) ग्रौद्योगिक उत्पादों के ग्रन्तर्कोत्रीय व्यापार का नियमन, (ix) क्षेत्रीय उद्योगों में विनियोजन का नियमन करना ग्रादि।

- (३) यातायात के विस्तार का कार्यक्रम—पूर्ण रोजगार के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये एक ग्रन्छी यातायात प्रिणाली श्रित आवश्यक है। इसके सुधार का निम्न कार्यक्रम है:—(i) यातायात प्रणाली का विकेदी-करण और क्षेत्रीकरण होना चाहिये; (ii) यातायात प्रणाली की सेवा की सार्वजितक उपयोगिता के स्तर को ऊँचा उठाना चाहिये; (iii) विभिन्न यातायात के साधनों में समन्वय होना चाहिये; (iv) मार्ग सम्बन्धी या किराये सम्बन्धी प्रतियोगिता को घटाने के लिये विभिन्न यातायात प्रणालियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये; (v) श्रम की गतिशीलता और वस्तुश्रों के व्यापार का युक्तिसंगत नियंत्रण होना चाहिये, जिससे कृषि और उद्योग में मूल्य सम्बन्धी उपयुक्त ढांचे की रचना करना सुविधाजनक हो जाय; (vi) देश की यातायात प्रणाली को बहुत लोचदार बनाना चाहिये, तािक वह पूर्ण रोजगार वाले कार्यक्रम को लागू करने के फलस्वरूप बढ़े हुए ग्रसाधारण व्यापार की ग्रावश्यकता को पूरा कर सके; (vii) एक विस्तृत व सहयोगपूर्ण सड़क यातायात प्रणाली की भी व्यवस्था करनी चाहिये।
- (४) द्रव्य बाजार की उचित व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यक्रम—पूर्णं रोजगार की श्राय के ढांचे (Full Employment Income Structure) की रक्षा के हेतु मूल्यों में स्थिरता होना श्रावश्यक है। इस हेतु बेंकों की जमा, श्राकिषत करने की शक्ति पर श्रौर समाज की क्रय शक्ति को प्रभावित करने वाले घटकों पर नियंत्रए होना चाहिये। भारतीय मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करने के लिये केन्द्रीय बैंकिंग में कुछ सीमा तक विकेन्द्रीयकरए किया जाय, देश में छोटी-छोटी परन्तु स्वतंत्र बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की जाय, बैंकिंग कार्य पर नियंत्रए किया जाय श्रौर विदेशी विनिमय के कार्यों का नियमन होना चाहिये।
- (५) विदेशी व्यापार की उचित व्यवस्था का कार्यक्रम—विदेशी व्यापार की नीति को भी ग्रामूल परिवर्तित करना होगा, जिसके लिए मुख्य मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:—(i) ग्राधिक नियोजन की पूर्ति के लिए वित्तीय व्यवस्था करने तथा ग्रन्तर्राब्द्रीय पूँजी के लाभों को प्राप्त करने के हेतु द्विपक्षी (Bilateral) समभौतें किये जायें, (ii) ब्रिटिश राष्ट्र मंडल के देशों के बीच बहुमुखी ग्रुट (Block Multilateralism) बनाने चाहिये, ताकि उसका बाहरी ग्राधिक सम्बन्धों का ढांचा मजबूत हो जाय ग्रीर ग्रान्तरिक कार्यक्रम में विश्व की ग्रन्य ग्राधिक शक्तियाँ बाधा न इंडालने पार्यें, (iii) स्टिलिंग ग्रुट की एक इकाई के रूप में भारत विश्वव्यापी बहुपक्षीय क्यापार में भाग ले। विशेषज्ञ ग्रयंशास्त्रियों का सुभाव है कि पूर्ण रोजगार के ग्रादर्श को प्राप्त करने के लिये ससार के सभी राष्ट्रों को चाहिये कि विश्व व्यापार को संतु-

ौर विस्तृत रूप दें । इस सम्बन्ध में भ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैक बहुत हो सकते हैं ।

में पूर्ण वृत्ति

भारत सरकार ने रोजगार की मुविधाओं को बढ़ाने के महत्त्व को भली भाँति लिया है। आधिक नियोद्धन का एक महान् उद्देश्य पूर्ण रोजगार की स्थिति करना है। इससे पहले ही पूर्ण रोजगार व्यवस्था का उत्पन्न करना देश के न में राज्य नीति का अमुक्त उद्देश्य बताया गया था। योजना कमीशन ने प्रथम शिय योजना का निर्माण करते समय ही देश में बेरोजगारी के अंश और उसके का पता लगाने का प्रयत्न किया था तथा योजना के अन्तर्गत समुचित रोज- विधाओं की व्यवस्था करने का लक्ष्य बनाया था। कमीशन का विचार है कि र मुविधाओं के विकास के कार्य के तीन पहलू हैं: (i) पहले से ग्रामीण तथा क क्षेत्रों में बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हैं, जिनके लिए रोजगार उपलब्ध की ग्रावश्यकता है। (ii) इस बात की जरूरत है कि जन संख्या की प्राकृतिक क्ष्यरण जो नये काम करने वाले पैदा हो जाते हैं, उनके लिए रोजगार पैदा जाय। ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगभग २० लाख प्रति वर्ष है।(iii) कृपि तथा थाँ में लगे हुए व्यक्तियों के लिए रोजगार की मुविधाएँ बढ़नी चाहिए, क्योंकि वल ग्रांशिक रोजगार ही प्राप्त है।

प्रथम पंच वर्षीय योजना में सरकार का अनुमान था कि लगभग १ करोड़ यों को लोक और निजी क्षेत्रों में अधिक रोजगार की सुविधायें मिल सकेंगी। नुमान गलत रहा है। सन् १६५३ में ही सरकार को पंच वर्षीय योजना में कुछ शोधन करने पड़े हैं जिनसे कि रोजगार की सुविधायें प्रधिक तेजी के साथ बढ़ प्रथम योजना-काल का सामान्य अनुभव यही रहा है कि आर्थिक विकास की के साथ-साथ बेरोजगारी घटने के स्थान पर उलटी बढ़ी है। मार्च सन् १६५१ सेवा योजनालयों (Empolyment Exchanges) के रजिस्टरों में ऐसे यों की संख्या जिन्हें रोजगार नहीं दिया जा सका था, वेवल ३ ३७ लाख थी, सम्बर सन् १६५३ में ५ २२ लाख हो गई थी और मार्च सन् १६५६ में ७ ०५। योजना कमीशन ने आदेश पर राष्ट्रीय सैम्पल जाँच (National Sample vey) ने पता लगाया था कि सन् १६५४ में नगर क्षेत्रों में २२ ४ लाख व्यक्ति गार थे और प्रामीगा क्षेत्रों में २८ लाख व्यक्ति वेरोजगार थे । प्रामीगा और एक क्षेत्रों में कुल बेरोजगारी का अप्रैल सन १६५६ का अनुमान क्रमशः २८ और । स्था रखा गया है।

ो पंच-वर्षीय योजना में रोजगार की व्यवस्था-

दूसरी पंच वर्षीय योजना में रोजगार सुविधाओं को बढ़ाने के कार्य को विशेष । दिया गया है । योजना कमीशन का अनुमान है कि देश में दूसरी योजना के में बेरोजगारी को पूर्णतया दूर करने के लिए १५३ लाख व्यक्तियों के लिए हे रोजगार की आवश्यकता होगी । कमीशन का अनुमान है कि क्रमशः २५ और जाख व्यक्ति तो नागरिक और ग्रामीण क्षत्रों में पहले से ही बेकार हैं और इस बेकारी की मात्रा ५३ लाख है । इसके अतिरिक्त दूसरी प्च-वर्षीय योजना के में १ करोड़ और व्यक्ति काम करने वालों की संख्या में शामिल हो जायेंगे । शन का अनुमान है कि दूसरी योजना के काल में बेरोजगारी को पूर्णतया स्थाप्त

कर देना स भव न हो सवेगा, परन्तु बेरोजगारी को बढ़ने से रोका जा सवेगा, इस लिए दूसरी पंच-वर्षीय योजना का लक्ष्य १ करोड़ नई रोजगार सुविधाएँ उत्पन्न करना बताया गया है। इसका परिएगाम यह होगा कि पाँच वर्ष में श्रम की पूर्ति में होने वाली वृद्धि के लिए रोजगार का प्रबन्ध हो जायगा। लोक क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यों में निम्न प्रकार रोजगार सुविधायों के विकास का अनुमान लगाया गया है:—

ग्रिधिक रोजगार का अनुमान

	(लाखों में)
	(वालाम)
(१) निर्माण	58.00
(२) सिचाई ग्रीर शक्ति	०.४४
(३) रेल्वे	२•५३
( ४) भ्रन्य यातायात एवं सम्वादवाहन	१*≂०
(५) उद्योग भ्रौर खनिज	७.४०
(६) कुटीर तथा छोटे उद्योग	४.४०
( ७ ) वन, मछली उद्योग, राष्ट्रीय प्रसार तथा सम्बन्धित	
े सेवायें	8.53.
( ५ ) शिक्षा	8 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
(६) स्वास्थ्य	0.0c
	१.१६
The state of the s	१*४२ 🖔
(११) सरकारी नौकरी	४•३४
( १२ ) ग्रन्य	२७"०४ 🐧
कुल	\$0.30

इस प्रवार लगभग ५० लाख व्यक्तियों के लिए लोक क्षेत्र में ही रोजगार की व्यवस्था हो जायगी। शेष २० लाख व्यक्तियों में से २'४ लाख व्यक्तियों को इस कारण रोजगार मिल जायगा कि पाँच वर्ष के काल में इतने सरकारी नौकर वृद्धावस्था के कारण स्थान खाली कर देंगे। शेष के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो जायगा। इस प्रकार दूसरी योजना के अन्त में भी बेरोजगारी की स्थिति में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन न हो सकेगा। इतना अवस्य हो जायगा कि सन् १६५६ की तुलना में बेरोजगारी बढ़ने नहीं पायेगी। शायद तीसरी योजना के समाप्त होने पर ही पूर्ण वृत्ति की अवस्था पैदा हो सके और तत्पश्चात् आर्थिक नियोजन का उद्देश्य इस पूर्ण वृत्ति की अवस्था को बनाये रखना होगा।

दूसमें तो सन्देह नहीं है कि दूसरी योजना ं हमने पूर्ण वृत्ति की व्यवस्था का कार्यक्रम ग्रारेम्भ कर दिया है ग्रीर शायद हम धीरे-धीरे इस लक्ष्य की ग्रोर ग्रागे बढ़ सकें। भय केवल यही है कि कहीं प्रथम योजना की भाँति दूसरी योजना से सम्बन्धित रोजगार सम्बन्धी लक्ष्य ग्रवास्तविक न रहें।

#### **QUESTIONS**

1. Are savings and investments in an Economy always equal? If not, how can this condition be brought about?

किसी देश मे ''बचत'' तथा ''कार्य मे लगा हुम्रा द्रव्य'' व्या हर परिस्थिति में बराबर ्रोने हैं ? भूगर बराबर नहीं है तो किस प्रकार बराबर किये जा सकते हैं। (Agra, B. A., 1959)